Table of Contents

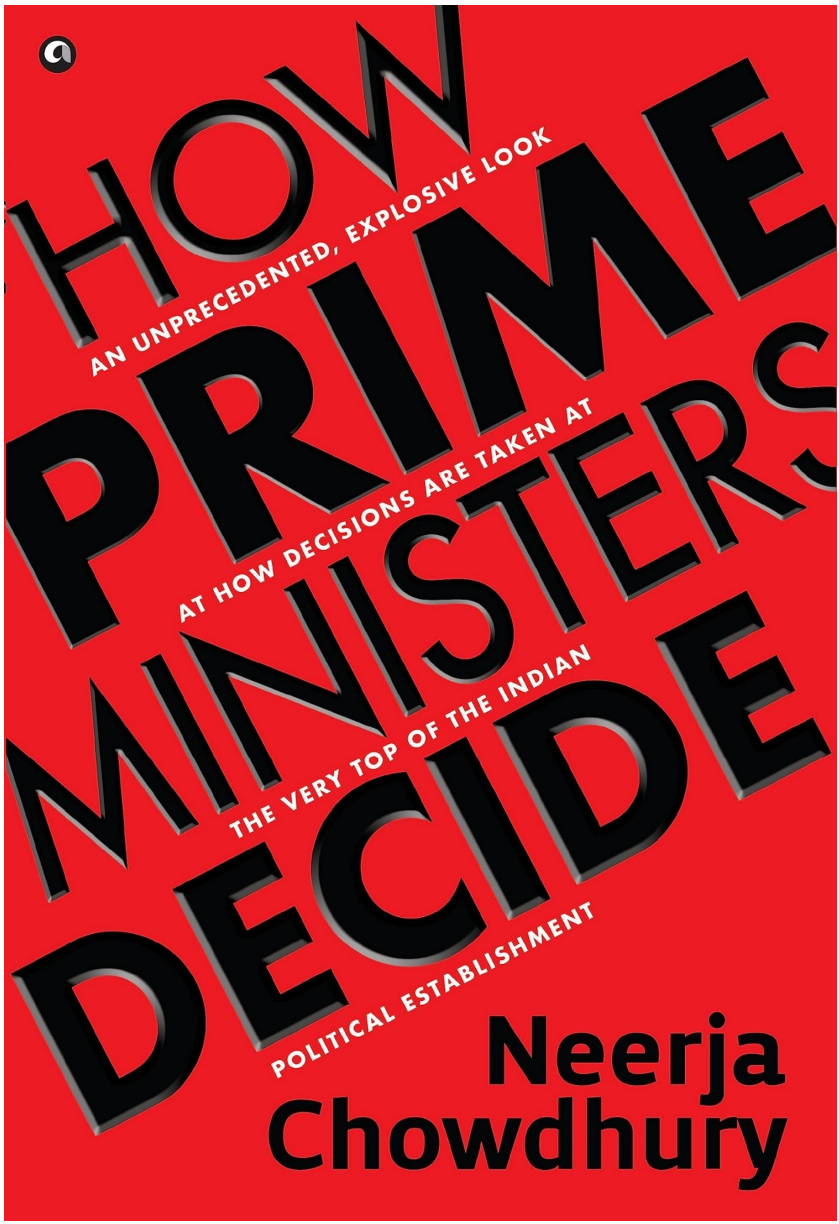

HOW PRIME MINISTERS DECIDE

HOW PRIME MINISTERS DECIDE

Neerja Chowdhury

ALEPH

एलेफ बुक कंपनी
एक स्वतंत्र प्रकाशन फर्म
रूपा पब्लिकेशन्स इंडिया द्वारा प्रायोजित

भारत में पहली बार 2023 में प्रकाशित हुआ।
एलेफ बुक कंपनी द्वारा
7/16 Ansari Road, Daryaganj
नई दिल्ली 110 002

कॉपीराइट © नीरजा चौधरी 2023

सर्वाधिकार सुरक्षित।

लेखिका ने अपने नैतिक अधिकारों का दावा किया है।

इस पुस्तक में व्यक्त किए गए विचार और मत लेखिका के हैं और तथ्य उन्हीं के द्वारा बताए गए हैं, जिनकी यथासंभव पुष्टि की गई है, और प्रकाशक इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशक ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है कि इस पुस्तक में संदर्भित बाहरी वेबसाइटों के यूआरएल प्रकाशन के समय सही और सक्रिय हों। हालांकि, प्रकाशक वेबसाइटों के लिए उत्तरदायी नहीं है और यह गारंटी नहीं दे सकता कि कोई साइट सक्रिय रहेगी या उसकी सामग्री उपयुक्त है या भविष्य में उपयुक्त रहेगी।

एलेफ बुक कंपनी से लिखित अनुमति के बिना इस प्रकाशन का कोई भी भाग किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से पुनरुत्पादित, प्रसारित या किसी पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है।

ISBN: 978-93-90652-45-7

1 3 5 7 9 10 8 6 4 2

यह पुस्तक इस शर्त के अधीन बेची जाती है कि इसे व्यापारिक रूप से या किसी अन्य तरीके से, प्रकाशक की पूर्व सहमति के बिना, इसके प्रकाशन के समय प्रयुक्त कवर या बाइंडिंग के अलावा किसी अन्य रूप में उधार नहीं दिया जाएगा, पुनर्विक्रय नहीं किया जाएगा, किराए पर नहीं दिया जाएगा या प्रसारित नहीं किया जाएगा।

मेरे जीवन के दो पुरुषों के लिए

अरुण
और
नकुल
ᔑ

अंतर्वस्तु

अर्ध-शीर्षक पृष्ठ

शीर्षक पेज

कॉपीराइट पृष्ठ

समर्पण

अंतर्वस्तु

परिचय

1. राख से उठकर आए प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी की वापसी

2. धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री जिन्होंने कमजोर किया
धर्मनिरपेक्षता
शाह बानो के मामले में राजीव गांधी का ढुलमुल रुख

3. भारत को नया रूप देने वाला धूर्त प्रधानमंत्री
राजनीति
वी. पी. सिंह की मंडल चाल

4. वह प्रधानमंत्री जिसने निर्णय लेने से इनकार कर दिया
पी.वी. नरसिम्हा राव और बाबरी मस्जिद का विध्वंस

5. शांतिप्रिय प्रधानमंत्री जिन्होंने गर्जना की
ए. बी. वाजपेयी ने परमाणु उपकरणों के परीक्षण को अधिकृत किया

6. कम आंका गया प्रधानमंत्री जिसने विजय प्राप्त की
मनमोहन सिंह और भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता

उपसंहार

स्वीकृतियाँ
नोट्स

ग्रन्थसूची

परिचय

शीर्ष पर हमेशा अकेलापन होता है। किसी कंपनी के सीईओ के लिए भी यह अकेलापन भरा होता है।
किसी भी सरकार के मुखिया के लिए अकेलापन और बढ़ जाता है, एक गलत कदम का यही परिणाम होता है।
पीढ़ियों तक कायम रहता है। लेकिन उससे भी अधिक अकेला वह व्यक्ति होता है जो शीर्ष पर होता है।
भारत में, प्रधानमंत्रियों की तमाम शक्तियों और असंख्य लोगों के बावजूद,
उनके चारों ओर मंडराते चापलूसों की संस्कृति। 'जी हुजूरी' की संस्कृति।
(नीचे से अनुपालन और ऊपर वालों के प्रति सम्मान) अलग-थलग कर देता है
प्रधानमंत्री तो और भी ज्यादा।
प्रधानमंत्रियों के निर्णय लेने के तरीके को देखते हुए, मुझे अलग-अलग बातें पता चलीं।
प्रधानमंत्रियों ने अपने-अपने तरीके से इस अकेलेपन की भावना को व्यक्त किया।
'अंतिम जिम्मेदारी आपकी है...यह शानदार हो सकता है,' भारत के
विवादास्पद प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह ने मुझसे कहा, जब वे इलाज करवा रहे थे।
1999 में अपोलो अस्पताल में डायलिसिस। 'जिम्मेदारी जितनी अधिक होगी,
स्वतंत्रता कम हो जाती है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ, पार्टी में जा रहा हूँ, या
मैं अपने परिवार से मिलने के लिए एक सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूँ। शीर्ष पर, नेता हैं
इन मानवीय भावनाओं से वंचित। यह एक बेहद भावनात्मक और
व्यक्तिगत भावना।' अदम्य चंद्र शेखर, प्रधानमंत्री
1990-91 में पांच महीने, और लगातार दरबारियों से घिरे रहना।
उन्होंने उपराष्ट्रपति की बात को दोहराया। 'हाँ, शीर्ष पर अकेलापन होता है... इस अर्थ में कि आपके पास
जब कोई और मौजूद न हो, तब वहां मौजूद रहना, खासकर तब जब "अत्यंत

महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ"
निर्णय लेने होंगे।
‘The space to yourself is just not there, milne walon ka taanta laga
रहता है (आपसे मिलने के इच्छुक लोगों की लगातार भीड़ लगी रहती है),
1997-98 में प्रधानमंत्री रहे आई. के. गुजराल ने कहा, 'हमारे सामंती रवैये के कारण...'
दर्शन जैसा है वैसा ही है।
जैसे-जैसे कोई राजनेता शिखर के करीब पहुंचता है, अकेलापन बढ़ता जाता है और यह
यह बात एक से अधिक प्रधानमंत्रियों ने भी कही थी। इनमें से एक प्रधानमंत्री ने कहा था।
अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कई कविताओं को मार्मिक ढंग से लिखा था।
‘आप जितना ऊपर जाते हैं, उतना ही अकेलापन महसूस करते हैं।’ उन्होंने शिखर पर होने के दर्द को व्यक्त करते हुए कहा, ‘राजनीति में आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी।’
इसने मेरे जीवन में एक अजीब तरह का खालीपन ला दिया है।
शीर्ष पर मित्रों की कमी तब और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है जब
हालात बिगड़ने लगे। जब मनमोहन सिंह के खिलाफ घोटाले उजागर हुए।
सिंह की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में, यहां तक कि उनके दोस्तों और
अनुयायियों ने उससे मुंह फेर लिया। उसे देखा जाएगा
संसद में, उनकी आँखों में कोई भाव नहीं था, वे एक घर से दूसरे घर की ओर चलते रहे।
अन्य। राजीव गांधी, जिन्हें अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त था
आठवीं लोकसभा में 414 संसद सदस्यों (सांसदों) के पास बहुत कम विकल्प थे।
1988 में अपनी संकटग्रस्त सरकार को बचाने की कोशिश करते समय वह इसका सहारा ले सकता था।
89.
एक प्रधानमंत्री केवल कुछ ही लोगों पर भरोसा कर सकता है, यदि
कोई भी। जो भी उससे मिलने आता है, अधिकतर किसी न किसी मकसद से आता

है।
उनमें से सर्वश्रेष्ठ लोग कुछ मांगने आते हैं। 'जैसे ही कोई
इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था, 'जब वह मेरे कमरे में आती है, तो मुझे ठीक-ठीक पता होता है कि क्या होने वाला है।'
वे यही मांगेंगे।' उसने वर्षों से यह बात सहज रूप से सीख ली थी।
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन लोगों में से एक थे जिन्होंने
उच्च पद से प्राप्त एकांत का उन्होंने सदुपयोग किया।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उन्होंने अपनी जेल की कोठरी में पढ़ना और लिखना शुरू किया।
वहां लंबे समय तक रहने के दौरान उन्होंने विपुल लेखन किया; उनके लेखन
इसमें उनकी आत्मकथा और उनकी महत्वपूर्ण कृति 'द डिस्कवरी ऑफ' शामिल थी।
लेकिन भारत में बिताए अपने आखिरी दिनों में नेहरू का अकेलापन स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था।
मई 1964 में देहरादून में। वह कपूर के पेड़ के नीचे बैठे थे, लगभग चुप।
नेहरू 26 मई को दिल्ली लौट आए। चौबीस घंटे से भी कम समय में, नेहरू ने
आगे बढ़ गया—एक अज्ञात ब्रह्मांड में। उसके बिस्तर के पास एक किताब पड़ी थी।
रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता, जिसकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं: 'जंगल सुंदर हैं,
अंधेरा और गहरा, / लेकिन मुझे अपने वादे निभाने हैं, / और मीलों का सफर तय करना है इससे पहले कि मैं...
नींद...।'
चाहे वे चाहें या न चाहें, सर्वोच्च पद नेता को दूसरों से दूर कर देता है।
लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए कुछ प्रधानमंत्रियों ने अलगाव की नीति अपनाई है।
अजेयता का एक आभास। इंदिरा गांधी स्वभाव से संयमित थीं, लेकिन वह
वह पहुंच से बाहर हो सकती थी; इसने उसे एक ऊंचे स्थान पर बिठा दिया, और
लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि वह क्या करने वाली है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्ताव रखा।
मंत्री की 'अकेली' स्थिति को राजनीतिक लाभ सृजित करने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इससे उन्हें खुद को एक मजबूत नेता के रूप में चित्रित करने में मदद मिली, जो तटस्थ

रहने में सक्षम था।
राष्ट्र के प्रति समर्पित, 'मैं हूँ ना' (मैं वहाँ हूँ) के सिद्धांत को सुदृढ़ करते हुए।
आप) छवि। उनके जनसंपर्क तंत्र ने लगातार ऐसी तस्वीरें जारी कीं जो अकेले होने की
इस छवि पर जोर देती थीं। रुद्रा में मोदी अकेले थे।
केदारनाथ की गुफा में, केसरिया शॉल ओढ़े हुए, सत्रह मिनट तक ध्यान करते हुए।
2019 के चुनाव प्रचार के अंत में, कुछ घंटों बाद, मोदी वहां मौजूद थे।
सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के सामने अकेले खड़े होकर, या
दक्षिण अफ्रीका में एक खाली रेलवे कोच में अकेले बैठे हुए, वह बाहर की ओर देख
रहे थे।
भविष्य। या मोदी एयर इंडिया वन से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, साथ में
उनके पीछे कोई अधिकारी या मंत्री नजर नहीं आए।
उन्होंने जिस अंडरपास का उद्घाटन किया था।
■

प्रधानमंत्री की देखभाल करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है।
जरा सी भी जरूरत हो, अधिकारियों को किसी भी निर्णय के फायदे और नुकसान
स्पष्ट रूप से बताने चाहिए।
खुफिया एजेंसियां आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगी। प्रधानमंत्री
नीति निर्माण में सहायता के लिए पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए
विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकती हैं।
निर्णय। और अब नवीनतम संचार तकनीक उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री के संदेश को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना
कुछ सेकंड। एक ऐसी प्रणाली में निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल होता है जहां
प्रधानमंत्री को सर्वोपरि माना जाता है—लेकिन
इसका अभ्यास करना उससे कहीं अधिक है।
पिछले कुछ वर्षों में, मैंने खुद से पूछा कि अंतिम जिम्मेदारी मुझे क्यों इतनी महत्वपूर्ण
लगती है?
भारतीय प्रधानमंत्री के साथ और भी अधिक आराम करने के लिए। क्या ऐसा इसलिए

है क्योंकि हम हैं?
क्या यह अब भी काफी हद तक सामंती समाज है? या इसलिए कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी
एक सामंती व्यवस्था पर आधारित और प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा की जाती है कि
क्या वह माई-बाप (माता-पिता) होंगे? या इसलिए कि हमारा लोकतंत्र नहीं है
फिर भी इसने एक मजबूत संस्थागत ढांचा विकसित किया ताकि
क्या यह जिम्मेदारी वास्तव में सामूहिक है? या यह इसलिए भी है क्योंकि हम एक हैं?
गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था से जूझते हुए, अंततः एक पिता तुल्य व्यक्ति की ओर रुख करना।
हमारे लिए फैसले? इसने इंदिरा गांधी को 'एकमात्र व्यक्ति' बनने के लिए मजबूर किया।
मंत्रिमंडल में अपने पुरुष सहयोगियों की तुलना में अधिक सख्त रुख अपनाते हुए, उन्होंने अमेरिका को उकसाया।
विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने कामना की कि अमेरिकी
सत्ता प्रतिष्ठान के पास एक ऐसा व्यक्ति था जो इंदिरा गांधी जितना ही शक्तिशाली था!
इन सवालों के कोई सरल जवाब नहीं हैं।
मैंने पुस्तक की शुरुआत प्रधानमंत्रियों के अकेलेपन से करने का निर्णय लिया।
क्योंकि वे भी अन्य लोगों की तरह ही इंसान हैं, और वे इस तरह से काम नहीं करते हैं।
सारगर्भित। लेकिन इतिहास अधिकतर घटनाओं को ही दर्ज करता है, प्रक्रियाओं को शायद ही कभी।
दुविधाएँ, भावनात्मक उथल-पुथल जिनके बीच एक प्रमुख
मंत्री को निर्णय लेने होते हैं।
■

शीर्ष पर होना एकांत का स्थान है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धात्मक दबावों से भरा हुआ है।
राष्ट्रीय राजनीति को कवर करते समय जिन चीजों ने मुझे आकर्षित किया, उनमें से

एक यह थी...
प्रधानमंत्रियों (पीएम) और प्रधानमंत्रियों के कार्यालयों (पीएमओ) के बारे में लिखना।
राजनीतिक दलों और संसद में चालीस से अधिक वर्षों तक पत्रकार के रूप में काम करना मेरे लिए एक अनुभव रहा है।
प्रधानमंत्रियों द्वारा लिए गए प्रतीततः सीधे-सादे निर्णय किस प्रकार वास्तव में
कितना सरल है। एक आम आदमी को तो ऐसा लगता है कि सिर
सरकार जो चाहे कर सकती है। लेकिन असलियत अक्सर कुछ और ही होती है।
बहुत अलग—क्योंकि यह दांव-पेच, साजिशों और एजेंडों में उलझा हुआ है।
—यहां तक कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों के समय में भी।
कभी-कभी अहंकार होता था, हमेशा धूर्तता रहती थी, और कभी-कभार
पूर्वाग्रह, लेकिन साथ ही बुद्धिमत्ता की झलक भी। सबसे बढ़कर, वहाँ था...
प्रधानमंत्री की जीवित रहने और राजनीतिक रूप से विजयी होने की प्रबल आवश्यकता।
भारत के नौवें प्रधानमंत्री, विद्वान पी. वी. नरसिम्हा राव,
शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को 'व्यापक हितों के जाल' के रूप में संक्षेप में बताया गया।
तुच्छ दृष्टिकोण और वास्तविक विचार। निहित स्वार्थों का यह 'जाल' राव
जिन बातों पर चर्चा हुई उनमें कार्यस्थल, देश और विदेश में मौजूद शक्तिशाली लॉबियां शामिल थीं।
एक अत्यंत विविधतापूर्ण समाज में जाति और समुदाय को संतुष्ट करना आवश्यक था।
भारत जैसे बहुधार्मिक राष्ट्र में; विरोधियों की साजिशें...
खाली; और विदेशी पूंजी से ध्यान भटकाने का दबाव।
इसके लिए कौशल, अनुभव, निर्ममता और सबसे बढ़कर विशुद्ध दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है।
भारतीय राजनीति में व्यक्तियों की सफलता के लिए भाग्य आवश्यक है।
शीर्ष पर पहुंचने वाले सभी लोगों में सहज प्रवृत्ति बहुत प्रबल थी।
निर्णय लेने की प्रक्रिया, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, इससे अलग नहीं है।

यह जिस ऐतिहासिक संदर्भ में घटित होता है। न ही प्रधानमंत्री को कोई पद विरासत में मिलता है।
जब वह पदभार ग्रहण करेगा/करेगी तो सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा।
अगले पृष्ठों में, मैंने कुछ आकर्षणों और
प्रधानमंत्रियों पर पड़ने वाले दबाव और पर्दे के पीछे की घटनाएं
दृश्य, उथल-पुथल भरे, अक्सर रहस्यमय नाटक जो इसके साथ थे
भारत के कुछ प्रधानमंत्रियों द्वारा लिए गए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय।
मैं छह प्रधानमंत्रियों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ— इंदिरा Gandhi, Rajiv Gandhi, V. P. Singh, P. V. Narasimha Rao, Atal Bihari
वाजपेयी और मनमोहन सिंह। मैंने उन प्रधानमंत्रियों पर लिखने का फैसला किया जो पूरे पांच साल के कार्यकाल तक शासन करने में सक्षम रहे—कुछ अपवादों के साथ।
जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख नहीं किया गया, हालांकि उन्होंने भारत के सत्रह वर्षों तक शासन किया था।
सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण वर्ष। हालाँकि एक महान व्यक्तित्व जिसने रचना की।
आधुनिक भारत की संरचना में, मैंने नेहरू को शामिल न करने का निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऐसा है
उसकी आलोचना करना फैशन बन गया है, लेकिन क्योंकि मेरा अपना
उनके शासनकाल की समाप्ति के बाद ही भारतीय राजनीति के प्रति जागरूकता का संचार शुरू हुआ।
मैंने वी.पी. सिंह को शामिल किया है, हालाँकि उनकी सरकार केवल कुछ ही समय तक चली।
ग्यारह महीने। वह इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उनके प्रधानमंत्रित्व काल ने बदलाव ला दिया।
उत्तर भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया; और उन्होंने एक करारा झटका दिया
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई—से
जिससे पार्टी अभी तक उबर नहीं पाई है।

जिन प्रधानमंत्री को नजरअंदाज करना मुश्किल था, वे थे नरेंद्र मोदी—
देश की चेतना में यह बात इतनी गहराई से समाई हुई थी। बहुत कुछ के बाद
विचार-विमर्श के बाद, मैंने किसी विशिष्ट निर्णय की गहन जांच न करने का निर्णय लिया।
मैंने छह अन्य प्रधानमंत्रियों के साथ जैसा किया है, वैसा ही उनके साथ भी किया है, हालांकि उनसे अधिक
मोदी द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में से एक, जिसमें कई चीजों का विमुद्रीकरण शामिल है,
देश की मुद्रा का पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 को समाप्त करना उचित था।
सूक्ष्मदर्शी से जांच की जानी चाहिए। हालाँकि, जब मैंने शोध शुरू किया तो
जिस तरह से मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने विवादास्पद निर्णय लिए, मुझे जल्द ही
मुझे आने वाली कठिनाइयों का एहसास हो गया था। सबसे पहले, वर्तमान पदाधिकारी होने के नाते
जिस समय यह पुस्तक लिखी जा रही थी, उस समय के प्रधानमंत्री, उनका प्रधानमंत्रित्व काल
अभी भी काम चल रहा था। (लिखते समय वह तैयारी कर रहा था।)
(तीसरे कार्यकाल के लिए बोली लगाने के लिए।) मुझे इसका लाभ नहीं मिला।
अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह, मुझे भी अतीत से मिली जानकारी से सहायता मिलेगी। अधिक
भारत में, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री के करीबी कुछ ही लोग हैं, जिन्हें अंदरूनी मामलों की जानकारी है।
सरकार के उच्चतम स्तर पर, खुलकर और स्पष्ट रूप से बात करें
प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पर्दे के पीछे वास्तव में क्या हुआ था?
पद पर रहते हुए। जिन लोगों ने मुझसे अन्य प्रधानमंत्रियों के बारे में बात की थी।
उन्होंने ऐसा तब किया जब उनके करीबी प्रधानमंत्री ने पद छोड़ दिया था।
मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए, पीछे छूट जाने का भी खतरा था।
घटनाएँ और उनका पुराना हो जाना।
मैं मोदी की निर्णय लेने की शैली की बात कर रहा हूँ, जो बाकी लोगों से बिल्कुल

अलग है।
किसी अन्य प्रधानमंत्री की तरह, पुस्तक के उपसंहार में, इस उम्मीद में कि मैं
भविष्य में हम उन पर अधिक विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे।
मोदी की घटना अतीत से पूर्णतः अलग है, और एक
भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव।
■

मैंने मुंबई स्थित एक अखबार के लिए काम करके पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया।
समाचार साप्ताहिक हिम्मत, जिसने आपातकाल (1975-77) का विरोध किया था, जब
इंदिरा गांधी सर्वशक्तिमान थीं। उसके बाद के वर्षों में, काम करते हुए
स्टेट्समैन में नागरिक अधिकार संवाददाता के रूप में, और राजनीतिक संपादक के रूप में...
इकोनॉमिक टाइम्स में काम करने के बाद, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में दस वर्षों तक राजनीतिक संपादक के रूप में काम किया।
कई वर्षों तक, और बाद में राजनीति पर लिखने वाले एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में, मुझे एक अवसर मिला।
देश के सभी प्रधानमंत्रियों और उनके साथियों का प्रत्यक्ष अवलोकन।
इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, वे महिलाएं जिन्होंने भारत का शासन चलाया।
इससे पहले कि मैं प्रधानमंत्री के उन निर्णयों पर बात करूं जिनका मैंने अध्ययन किया है, एक
भारत पर शासन करने वाले सभी प्रधानमंत्रियों की संक्षिप्त समीक्षा, और
उनके द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का उल्लेख पाठक को कुछ संदर्भ प्रदान करने में सहायक होगा।
स्वतंत्रता के बाद के पचहत्तर वर्षों में, भारत में चौदह*
प्रधानमंत्रियों की संख्या पंद्रह होगी, यदि गुलज़ारी लाल नंदा
सूची में शामिल किया गया था। सियालकोट (अब) के एक पंजाबी खत्री को भी शामिल किया गया था।

पाकिस्तान) उन्होंने दो बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, एक बार मृत्यु के बाद
जवाहरलाल नेहरू ने 1964 में और फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद दोबारा ऐसा किया।
1966 में उनका निधन हो गया। दोनों ही मौकों पर उन्होंने तेरह दिनों तक देश पर शासन किया।
यदि ऐसा होता है तो अंतरिम प्रधानमंत्री के कार्यभार संभालने की परंपरा स्थापित करना
पद पर आसीन व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया। प्रणब मुखर्जी ने इसी नियम का पालन किया।
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के समय उनका जिक्र किया गया था, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था।
राजनीतिक रूप से दंडित किया गया। नंदा को 27.5-
नेहरू जिस हेक्टेयर में फैले विशाल भवन, तीन मूर्ति हाउस में रहते थे, उसे एक नए भवन में बदल दिया गया।
उनके लिए स्मारक। शास्त्री के रहने आने से पहले ही उन्होंने यह निर्णय ले लिया था।
अन्यथा, यह प्रधान मंत्री का आधिकारिक निवास बन जाता।
मंत्री।
भारत के प्रधानमंत्रियों की कहानी कुलीन वर्ग से शुरू होती है और
अपने विशिष्ट लाल गुलाब को अचकन में लगाए हुए परिष्कृत जवाहरलाल नेहरू।
भारतीय जनता द्वारा बेहद प्रिय। देश के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति के रूप में।
1947 से 1964 तक देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री ने देश का निर्माण किया।
वे संस्थाएँ जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी—
चुनाव आयोग, योजना आयोग, भारतीय संस्थान
प्रौद्योगिकी (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान
परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), भाभा परमाणु जैसे संस्थानों से सीखना
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (BARC), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

(ISRO), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), और ऐसे ही कई अन्य संस्थान।
अधिक।
नेहरू को महात्मा गांधी ने चुना था, न कि कांग्रेस पार्टी ने।
1946 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए, और फिर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने के लिए।
1947 में प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें चुना गया था।
उनकी गतिशीलता और जनता पर पकड़, युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता,
अल्पसंख्यकों के बीच स्वीकृति और उनके साथ बातचीत करने की उनकी क्षमता
ब्रिटिश चाहते थे कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष बनें और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करें।
गुस्सा।
लाल बहादुर शास्त्री, जो नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने,
सन् 1964 में जन्मे व्यक्ति, शुरुआत में 'शास्त्री' नहीं थे। उनका नाम लाल बहादुर था।
वर्मा और वह एक कायस्थ परिवार से थे। उन्होंने शास्त्री को अपने नाम के साथ जोड़ा।
जब उन्हें शास्त्री की उपाधि प्रदान की गई, तब उनका नाम क्या था?
वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जैसा
दसवीं कक्षा का छात्र लाल बहादुर महात्मा गांधी का प्रवचन सुनने गया था।
और मदन मोहन मालवीय वाराणसी में भाषण देते हैं। अगले दिन वह
वह स्थानीय कांग्रेस कार्यालय गए और घोषणा की कि अब वह
देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्णकालिक काम करने जा रहे थे। उनका परिवार—वह थे
एक गरीब स्कूल शिक्षक का बेटा, जिसकी मृत्यु तब हो गई थी जब लाल बहादुर
अठारह महीने का बच्चा बहुत गुस्से में था। लेकिन उसकी माँ के शब्दों ने उसे शांत किया।
ये बातें जीवन भर उनके साथ रहेंगी: 'सही मार्ग के बारे में गहराई से सोचें।'
उसने उससे कहा, और '...अपने फैसले पर दृढ़ रहो।'
नेहरू ने अपने जीवनकाल में पर्याप्त संकेत दिए थे कि वे
उन्होंने कद में छोटे और कम चर्चित शास्त्री को अपना उत्तराधिकारी माना।

उन्हें एक कमज़ोर प्रधानमंत्री समझा जाता था—उन्हें अक्सर 'छोटा' कहा जाता था।
गौरैया'। जब पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर हमला किया, तो उसने पासा पलट दिया।
उन्होंने उन पर हमला किया और सियालकोट और लाहौर पर आक्रमण करके युद्ध जीत लिया।
एक 'साधारण' प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नायक बन गए, जिन्होंने एक मुहावरा गढ़ा।
लोकप्रिय नारा 'जय जवान, जय किसान'। उन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
पाकिस्तान के ताशकेंट में, और उसके कुछ ही घंटों के भीतर, उनकी मृत्यु हो गई।
केवल उन्नीस महीनों तक चलने वाला प्रधानमंत्रित्व काल।
शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली इंदिरा गांधी ने...
1966 में जिनका निधन हो गया, वे शासन करने वाली पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं।
देश। समाजवादी विचारक द्वारा इसे 'गूंगी गुड़िया' कहा जाता है।
राम मनोहर लोहिया, उनके प्रतिद्वंद्वी मोरारजी द्वारा 'यह छोकरी' (लड़की की चिट)
देसाई, और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा 'बुढ़िया चुड़ैल' कही जाने वाली इंदिरा गांधी
गांधी को 'दुर्गा' के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भू-राजनीतिक परिदृश्य बदल गया।
असाधारण साहस, राजनीतिक सूझबूझ और एक
जोखिम उठाने की क्षमता। लेकिन उन्होंने 1975 में आपातकाल भी लागू किया था।
नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करना—केवल चुनाव कराने के आह्वान के लिए
1977 में उसने खुद को मार डाला। 1984 में उसके अपने ही सुरक्षा गार्डों ने उसकी हत्या कर दी।
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर मौजूद सेना को आदेश देते हुए,
सिख उग्रवादियों।
मोरारजी देसाई मार्च 1977 में प्रधानमंत्री बने जब वे
इक्यासी वर्ष के। एक स्कूल शिक्षक के पुत्र, देसाई अनाविल परिवार से आए थे।

गुजरात का ब्राह्मण परिवार। ईमानदार लेकिन दृढ़ निश्चयी देसाई, एक
गांधीवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक, जिन्होंने 1977 में जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व किया, जो पहली बार थी
केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार सत्ता में आएगी।
इसका महत्व इंदिरा गांधी के सत्तावादी शासन को समाप्त करने में निहित था।
गांधी जी। उनकी सरकार ढाई साल तक चली लेकिन अंततः गिर गई।
इसके विरोधाभासों का भार और इसके नेताओं के विशाल अहंकार।
चरण सिंह पहले किसान प्रधानमंत्री थे, जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे।
भारत में मध्य जातियों का उदय; इस उछाल के कारण ही इनका गठन हुआ।
1967 में पटना से अमृतसर तक नौ राज्य सरकारें थीं। हालाँकि
उत्तर प्रदेश में, सिंह के उत्तरी मैदानी इलाकों में भारी जनसमर्थन था। लेकिन
विडंबना यह है कि वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने पद को साबित नहीं कर सके।
सदन में बहुमत। इंदिरा गांधी ने उन्हें समर्थन दिया था।
28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सरकार को गिरा दिया।
मोरारजी देसाई को समर्थन देने के बाद, उन्होंने तेईस दिनों के भीतर ही अपना समर्थन वापस ले लिया।
जनवरी 1980 में वे फिर से सत्ता में आए।
आकर्षक, तकनीक-प्रेमी, चालीस वर्षीय राजीव गांधी थे
भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री ने एक अभूतपूर्व बदलाव का प्रतिनिधित्व किया।
अतीत। उन्होंने नेताओं की एक नई पीढ़ी के आगमन की घोषणा की।
भारतीय परिदृश्य। इंदिरा गांधी के मिलनसार बड़े बेटे एक पायलट थे।
जब उनके छोटे भाई संजय, जो इंडियन एयरलाइंस में थे, तब वे वहीं पढ़ रहे थे।
इंदिरा गांधी द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किए गए एक व्यक्ति की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई।
अनिच्छुक राजीव के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने राजनीति में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि
'मम्मी की किसी न किसी तरह मदद करनी होगी।' वह एक नया और
आधुनिक भारत का निर्माण करना और देश को इक्कीसवीं सदी के लिए तैयार करना।

मतदान की आयु घटाकर अठारह कर दी, दूरसंचार क्रांति ला दी
भारत में कम्प्यूटरीकरण को प्रोत्साहित किया गया, सार्वजनिक कॉल कार्यालयों (पीसीओ) को बंद कर दिया गया।
गांवों तक जाकर उन्होंने प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किए। लेकिन यह जाति और समुदाय द्वारा शासित प्राचीन भारत था, जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे।
समझ में आया कि यही बात उसके पतन का कारण बनी।
विश्वनाथ प्रताप सिंह निकटवर्ती एक छोटे से रियासत के राजा थे।
इलाहाबाद (प्रयागराज) में रहने वाले, लेकिन अंततः एक शाही और अधीनस्थ व्यक्ति निकले।
एक ही व्यक्ति में समाहित। राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री, वे
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजीव से मतभेद हो गया—विशेष रूप से कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर।
155 मिमी की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए अवैध रिश्वत का भुगतान
स्वीडिश हथियार कंपनी बोफोर्स की हॉवित्जर तोपें। उपराष्ट्रपति गए।
उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक नई विचारधारा विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने यह विचारधारा विकसित की।
लगभग पूरी कांग्रेस विरोधी ताकतों की टुकड़ी एक साथ
देश में दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यमार्गी दलों के साथ-साथ क्षेत्रीय दलों के भी दल शामिल हैं।
यह सब ढाई साल के भीतर हुआ—और उन्होंने चुनाव में राजीव को हरा दिया।
1989 में उन्होंने राजीव गांधी का स्थान लेकर प्रधानमंत्री का पद संभाला।
'भारत जिस प्रधानमंत्री से वंचित रहा'—चंद्रमा ने इसी तरह से अपनी बात रखी।
शेखर का अक्सर वर्णन किया जाता था। वी. पी. सिंह के बाद, उन्होंने एक नेतृत्वकर्ता का पद संभाला।
जनता दल के एक अलग हुए गुट के नेतृत्व वाली सरकार, जिसे समर्थन प्राप्त है
राजीव गांधी के नेतृत्व वाली अधिक प्रभावशाली कांग्रेस।
1950 और 60 के दशक में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख व्यक्ति,
चंद्र शेखर कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें एक 'युवा नेता' के रूप में सराहा गया।
इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में समाजवादी विचारधारा का समर्थन करने के

कारण उन्हें 'तुर्क' कहा गया।
कारण। लेकिन आपातकाल के दौरान वह उससे अलग हो गया और था
जेल में डाल दिया गया। हालांकि वे एक व्यावहारिक व्यक्ति थे, फिर भी वे लगातार विरोध करते रहे।
अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। उन्होंने कन्याकुमारी से एक यात्रा का नेतृत्व किया।
1983 में दिल्ली में, उन्होंने चप्पलों में 4,260 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को प्रेरित किया।
कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष। महिलाएं उसका इंतजार करती थीं।
वे अपने शिशुओं को लेकर रास्ते में रुक गईं और उनसे अपने बच्चों का नाम किसी एक के नाम पर रखने का अनुरोध करने लगीं।
स्वतंत्रता संग्राम के नायकों। प्रधानमंत्री के रूप में, वे समस्या के समाधान के करीब पहुंचे।
अयोध्या विवाद हिंदुओं और उनके बीच बातचीत के जरिए सुलझाया गया।
मुसलमानों। लेकिन समझौते को अंतिम रूप देने से पहले, कांग्रेस
उन्होंने अपनी सरकार को भंग कर दिया, जो केवल सात महीने तक चली।
और मई 1991 में आम चुनाव की घोषणा की गई।
जून 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव के सत्ता संभालने के साथ ही, सत्ता का हस्तांतरण हुआ।
भारतीय इतिहास में पहली बार विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में
गणतंत्र। राव पुजारी बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद, वे प्रधानमंत्री बने।
मंत्री। एक कम आंका गया प्रधानमंत्री, विद्वान राव ने उदारीकरण किया।
अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी के लिए खोलकर, पंजाब और जम्मू में जाति और धार्मिक संघर्ष से भड़की स्थितियों को शांत किया।
कश्मीर। अनुभवी और दूरदर्शी, लेकिन एक मृत व्यक्ति के आकर्षण से रहित।
'मछली'—वह जन नेताओं की तरह नहीं थे। फिर भी वह एकमात्र ऐसे नेता थे।
नेहरू-गांधी कांग्रेस के अलावा कोई अन्य प्रधानमंत्री 1996 तक अपना पूरा कार्यकाल संभालेगा।

नरसिम्हा के उत्तराधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी का महत्व
मई 1996 में राव की जीत का कारण उनका व्यक्तित्व था—एक उदारवादी नेता जो सफल रहे।
दक्षिणपंथी, हिंदू समर्थक राष्ट्रवादी विचारधारा के पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित रहना
स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)। वाजपेयी एक गरीब कान्यकुब्ज से आते थे
ग्वालियर रियासत में एक ब्राह्मण परिवार। उनके दादाजी थे।
उत्तर प्रदेश के बटेश्वर से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आकर बस गए।
मेरे पिता एक स्कूल शिक्षक और कवि भी थे—एक ऐसा वातावरण जिसने उन्हें
वाजपेयी में कवि का जन्म हुआ। वर्षों बीतने के साथ, उन्होंने एक सहजता प्राप्त कर ली।
उनके भाषणों में अक्सर विराम होते थे, और वे अपने शब्दों को शब्दों में बयां करते समय एक अनोखा संतुलन बनाए रखते थे। यही होना था।
राजनीति में सफलता का उनका पासपोर्ट। उनकी पहली सरकार केवल कुछ ही समय तक चली।
1996 में तेरह दिनों तक। 1998 में, वाजपेयी ने सरकार का गठन किया।
नेशनल डेमोक्रेटिक नामक चौबीस दलों के गठबंधन के प्रमुख
इस बार उनकी सरकार ने NDA गठबंधन के साथ काम किया। इस बार उनकी सरकार तेरह महीने तक चली।
अप्रैल 1999 में फिर से संकट आ गया, जब वाजपेयी अविश्वास प्रस्ताव हार गए।
एक वोट। लेकिन आम चुनाव में वे तीसरी बार सत्ता में वापस आए।
उन्होंने 1999 में चुनाव जीते और 2004 तक प्रधानमंत्री बने रहे।
हरदनहल्ली डोड्डेगौड़ा देवेगौड़ा पहले शूद्र थे
1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने। स्कूली छात्र के रूप में, देवेगौड़ा
वह गांव में ब्राह्मण परिवारों को दूध पहुँचाती थी, और वे
इसे अंदर ले जाने से पहले इस पर पानी छिड़क दें। उसकी जाति, वोक्कालिगा, एक कृषि समुदाय को 'पिछड़ा वर्ग' की श्रेणी में रखा गया है। उनके पिता
वह अपने चार बच्चों में से केवल एक को ही स्कूल भेजने का खर्च उठा सकता था।
और उन्होंने देवे गौड़ा को चुना, जो अपने समय में पहली पीढ़ी के साक्षर व्यक्ति बने।
परिवार से संबंध होने के कारण वे सिविल इंजीनियर बन गए। आज भी उनके घर के

लोग उन्हें जानते हैं।
हसन जिले के लोग उनके द्वारा निर्मित पुलियों को याद करते हैं। 1996 में, देवे गौड़ा
उन्होंने जनता दल के गठबंधन से बनी संयुक्त मोर्चा (यूएफ) सरकार का नेतृत्व
किया।
और क्षेत्रीय दल, जिन्हें कांग्रेस द्वारा सत्ता में बनाए रखा गया था (ठीक उसी तरह जैसे
कि
(उन्होंने 1990 में कुछ महीनों के लिए चंद्र शेखर का समर्थन किया था)।
जिसे आम तौर पर 'मुख्यमंत्रियों की सरकार' के रूप में जाना जाता है—ये सरकारें थीं
क्षेत्रीय दलों के प्रमुख और निर्णायक भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री (सीएम)
यूएफ सरकार में। देवे गौड़ा की पदोन्नति के साथ, सत्ता हाथ में आ गई थी।
एक बार फिर दक्षिण की ओर चले गए।
दस साल के लड़के के रूप में इंदर कुमार गुजराल की शुरुआती यादों में से एक यह
थी:
जवाहरलाल नेहरू को भीड़भाड़ वाली सड़कों पर सफेद घोड़े की सवारी करते हुए
देखना
लाहौर की गलियों में। उनके माता-पिता उन्हें ऐतिहासिक सत्र में ले गए थे।
1929 में लाहौर में कांग्रेस की बैठक हुई, जहाँ नेहरू ने कांग्रेस की बागडोर संभाली।
राष्ट्रपति ने पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) की घोषणा की।
पार्टी का लक्ष्य। इससे गुजराल और उनके पंजाबी माता-पिता पर गहरा असर पड़ा।
झेलम के खत्री. गुजराल अपने कॉलेज के दौरान कम्युनिस्ट बन गए
वर्षों बाद, परिवार भारतीय पक्ष में आ गया।
देश के विभाजन के बाद, उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए। वे एक प्रमुख नेता बन
गए।
1966 में इंदिरा गांधी की 'किचन कैबिनेट' की सदस्य, फिर एक राजनयिक,
जो वी. पी. सिंह सरकार में विदेश मंत्री के पद तक पहुंचे और
देवेगौड़ा के नेतृत्व में और अंततः 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बने।
देवेगौड़ा की जगह। उनके द्वारा प्रतिपादित 'गुजराल सिद्धांत' में परिकल्पना की गई थी।
भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार।
अति सतर्क और तकनीकी विशेषज्ञ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह,

अप्रत्याशित घटनाक्रम में, सोनिया गांधी ने 2004 में वाजपेयी का स्थान लिया।
गांधी प्रधानमंत्री बनने की कगार पर थे, लेकिन फिर उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया।
उन्होंने मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति नियुक्त किया। सिख धर्म को मानने वाले मनमोहन सिंह सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले पहले व्यक्ति थे।
अल्पसंख्यक समुदाय को राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला। सिंह भी आगे बढ़े।
साधारण शुरुआत से। बचपन में उन्हें लंबी दूरी पैदल चलकर तय करनी पड़ती थी।
स्कूल। वह मिट्टी के तेल के दीपक की मंद रोशनी में पढ़ाई करता था—लेकिन
आगे चलकर वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अर्थशास्त्री बने। 'मैं
वे अक्सर कहते थे, ‘मैं जो कुछ भी हूँ, शिक्षा की बदौलत हूँ।’ वे हमेशा शीर्ष पर रहे।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख के रूप में दस वर्षों तक मंत्री रहे।
(यूपीए), कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन।
2014 में नरेंद्र मोदी के उदय ने भारत में गठबंधन युग का अंत कर दिया।
जो वी. पी. सिंह, चंद्र शेखर के प्रधानमंत्रित्व काल तक फैला हुआ था,
देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह।
यहां तक कि पी.वी. नरसिम्हा राव ने भी शुरुआत में अल्पमत सरकार का नेतृत्व किया था।
और उन्हें छोटी पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा। गठबंधन युग
ये सरकारें 1989 से 2014 तक, यानी पच्चीस वर्षों तक चलीं।
यह भारतीय राजनीति में हो रहे परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता था।
कांग्रेस, जिसने 1989 तक उनतीस वर्षों तक देश पर शासन किया था।
स्वतंत्रता के बाद के बयालीस वर्षों में से, बाकी वर्षों में गिरावट देखी गई।
राजनीतिक ताकतें इसके द्वारा खाली किए गए स्थान पर कब्जा जमा रही थीं। भाजपा इसका प्रभाव बढ़ रहा था, लेकिन यह अकेले कांग्रेस की जगह लेने में असमर्थ था।
1998 और 2014 के बीच, दो दलों के गठबंधन (न कि दो दलों के गठबंधन) के इर्द-गिर्द एक खंडित राजनीतिक व्यवस्था मजबूत हुई। कांग्रेस ने एक गठबंधन का नेतृत्व किया।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) और भाजपा, राष्ट्रीय

लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए)। जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए थे।
भाजपा की जीत के साथ मोदी ने मई 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला।
देश के इतिहास में पहली बार, उसने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। वह था
उन्हें बढ़ी हुई सीटों (282 से बढ़कर 303 सीटें) के साथ सत्ता में पुनः चुना गया।
2019. एक ध्रुवीकरण करने वाले प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ने एक 'नई भाजपा' को आकार दिया, जो पहले से अलग थी।
वाजपेयी और एल. के. आडवाणी के नेतृत्व वाली पार्टी से अलग होकर, उन्होंने भाजपा की राह पर आगे बढ़े।
पार्टी के मूल, हिंदू समर्थक एजेंडे को आगे बढ़ाया और पार्टी के सामाजिक आधार को व्यापक बनाया।
मोदी के उदय के साथ, सत्ता उन समूहों के हाथों में जाने लगी जो पहले सत्ता में नहीं थे।
देश की सत्ता संरचना के हाशिये पर। जवानी में एक चायवाला, एक
जाति से घांची (तेल चक्की मालिक) मोदी, अन्य ओबीसी (अन्य) समुदाय से आने वाले दूसरे व्यक्ति थे।
देवे गौड़ा के बाद, पिछड़े वर्गों के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति को
भारत। लेकिन वह अपने सभी पूर्ववर्तियों से अलग थे।
■

एक बार प्रधानमंत्रियों के पदभार संभालने के बाद, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे
क्षेत्र, जाति या भेदभाव की परवाह किए बिना पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना।
जिस समुदाय से वे आते हैं। हालाँकि, इस पर गौर करना शिक्षाप्रद है।
भारत के प्रधानमंत्रियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करके देखें कि क्या इससे हमें कुछ पता चलता है।
भारत के लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण, या इसके विपरीत, के बारे में कुछ भी।
विभिन्न पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व करते हुए—कुलीन और ग्रामीण, उत्तरी और दक्षिण, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, ब्राह्मण और पिछड़ा, पुरुष और

भारत की प्रधानमंत्रियों ने भारत की अविश्वसनीय क्षमताओं का प्रतीक रही हैं।
विविधता।
पंद्रह प्रधानमंत्रियों में से छह ब्राह्मण थे, जो शीर्ष पर थे।
social ladder (Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Morarji Desai, Rajiv
गांधी, हालांकि वे माता की तरफ से आधे ब्राह्मण थे,
नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी)। वी. पी. सिंह और चंद्र
Shekhar were Rajputs, Shastri a Kayastha, and Gulzari Lal Nanda and
आई. के. गुजराल पंजाबी खत्री थे—सभी उच्च जाति के लोग थे।
इनमें से दो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली किसान जातियों (और शूद्रों) से थे।
चरण सिंह, एक जाट, और एच. डी. देवे गौड़ा, एक वोक्कालिगा। हालाँकि एक
शक्तिशाली और समृद्ध किसान नेता चरण सिंह की चिंता
उच्च जाति से संबंधित न होने का अर्थ स्पष्ट था। 'मैं...'
मैं एक जाट परिवार में पैदा हुआ था। मैं मुसलमान बन सकता हूँ... लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता... राजपूत नहीं बन सकता... और न ही... वैश्य बन सकता हूँ,' उन्होंने 1977 में कहा था। 'और अगर मैं चाहूँ तो
हरिजन बनना भी असंभव है, क्योंकि संविधान के अनुसार ऐसा संभव नहीं है।
इसकी अनुमति नहीं देता।
अभी तक कोई दलित, मुस्लिम, आदिवासी या ईसाई नहीं मिला है।
प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। लेकिन स्पष्ट रूप से, जो समुदाय इसमें शामिल थे,
समाज के हाशिये पर रहने वाले लोग अब मुख्यधारा में आ रहे हैं और शीर्ष स्थान पर पहुंच रहे हैं।
सत्ता संरचना।
भारत के तीन प्रधानमंत्रियों में से एक पंजाब से थे (गुलज़ारी लाल)।
उत्तर में नंदा, इंदर कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह) दो
पश्चिम में गुजरात से (मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी), दो अन्य देशों से
दक्षिण (एच. डी. देवेगौड़ा और पी. वी. नरसिम्हा राव) में, रहा है

अभी तक पूर्वी या उत्तरपूर्वी भारत से कोई नहीं। इनमें से आठ
चौदह प्रधानमंत्रियों में से सभी उत्तर प्रदेश से थे—नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी
Gandhi, Charan Singh, Rajiv Gandhi, V. P. Singh, Chandra Shekhar,
और अटल बिहारी वाजपेयी (जिनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश से था, वहीं बस गए थे)
मध्य प्रदेश में, लेकिन उन्होंने लखनऊ से कई चुनाव लड़े।
सबसे बड़ा राज्य होने के नाते, उत्तर प्रदेश (यूपी) ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है।
भारतीय राजनीति में कांग्रेस की भूमिका। कांग्रेस का पतन अपरिवर्तनीय हो गया।
उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित होने में असमर्थता के कारण भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर सफल हुई।
मोदी के नेतृत्व में खिलाड़ी ने 2014 और 2019 में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, क्योंकि
इसे उत्तर प्रदेश का समर्थन मिला। 2014 में, मोदी ने स्वयं अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया।
गुजरात के वडोदरा से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक।
यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन चौदह प्रधानमंत्रियों में से पांच थे
इलाहाबाद से—नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, राजीव और वीपी, जिनके
मांडा की जमींदारी जागीर इलाहाबाद के बहुत करीब थी।
आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि इलाहाबाद स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था, लेकिन साथ ही
क्योंकि यह नेहरू परिवार का घर था, जिन्होंने देश को प्रभावित किया।
आजादी के बाद आधी सदी से भी अधिक समय तक राजनीति।
■

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जे. आर. जयवर्धने ने एक बार कहा था कि
(अपने देश के मुख्य कार्यकारी के रूप में) उनके पास कुछ भी करने की शक्ति थी।
किसी व्यक्ति का लिंग बदलने के अलावा! हालाँकि भारत एक

ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र,
सरकार का मुखिया, प्रधानमंत्री, सर्वशक्तिमान होता है। उसकी शक्ति
यह स्थिति बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों ने तो इसे संसदीय लोकतंत्र के भीतर प्रधानमंत्री की तानाशाही तक कह दिया है। व्यवहार में,
प्रधानमंत्री की शक्तियां उन्हें प्रदत्त शक्तियों से कहीं अधिक होती हैं।
संविधान के अनुसार। यह विशेष रूप से ऐसे प्रधानमंत्री के मामले में सच है जिनकी पार्टी
जिसे बहुमत प्राप्त है और जो लोकप्रिय है।
जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है
वास्तव में, एक मजबूत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभा अपने कार्यों के लिए उनका अनुसरण करती है।
प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार। प्रधानमंत्री ही अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं।
मंत्रियों को हटा दें। जब प्रधानमंत्री एक लोकप्रिय व्यक्ति हों जो...
पार्टी के लिए चुनाव जीतने में सक्षम होने पर, कैबिनेट मंत्री और भी अधिक रियायतें देते हैं।
उनकी शक्ति प्रधानमंत्री पर निर्भर हो जाती है। वे चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री पर निर्भर हो जाते हैं।
उनके लिए चुनाव—जैसा कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के मामले में हुआ था।
मोदी। उन्होंने सीधे संबंध स्थापित करके अपनी पार्टियों से आगे बढ़कर सफलता हासिल की।
जनता से जुड़ें।
■

प्रधानमंत्री अपने माध्यम से शासन की पूरी व्यवस्था को नियंत्रित कर सकते हैं।
वह जिन नियुक्तियों को करता है—अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय ब्यूरो में भी—
केंद्रीय जांच आयोग (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), संघ
लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
भारत सरकार (सीएजी), भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई), और वित्त मंत्रालय

आयोग।
उदाहरण के लिए, संविधान में यह प्रावधान है कि नियुक्ति
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148 के अधीन),
केंद्र सरकार के आधिकारिक लेखा परीक्षक द्वारा यह कार्य किया जाएगा।
राष्ट्रपति। लेकिन इसके बारे में और कुछ नहीं कहा गया है। राष्ट्रपति,
जो मंत्रिमंडल की सलाह से बंधा हुआ है, उसे अंततः उसी के अनुसार चलना होगा।
प्रधानमंत्री यही चाहते हैं। अन्य पदों पर नियुक्तियों के मामले में भी यही स्थिति है।
यूपीएससी जैसे संवैधानिक निकाय जो भर्ती प्रक्रिया का ध्यान रखते हैं
नौकरशाही और चुनाव आयोग, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
निष्पक्ष चुनाव।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) को यह कार्य करना होता है।
संवैधानिक रूप से अनिवार्य पदों के लिए सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर निर्णय लें
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर जैसे वैधानिक निकाय।
'दरअसल, नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री ही करते हैं,' भुवनेश ने कहा।
चतुर्वेदी, जो नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (MoS) थे।
वह अपनी विशिष्ट स्पष्टवादिता के साथ कहा करते थे, '....एसीसी इसे पूर्वव्यापी प्रभाव देता है।' अपने अस्तित्व के अधिकांश समय तक, एसीसी में प्रधानमंत्री शामिल थे।
गृह मंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री। लेकिन इसके बाद
मोदी सरकार सत्ता में आई, केवल प्रधानमंत्री और
गृह मंत्री इस मामले पर बने रहेंगे।
सीवीसी और सीबीआई के प्रमुखों का चयन एक प्रक्रिया होनी चाहिए
दिशा-निर्देशों के कारण स्थिति थोड़ी भिन्न है, जिन्हें के निर्देश पर तैयार किया गया था।
1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीवीसी और सीबीआई के निदेशकों को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री और एकल विधानसभा के नेता सहित एक समिति द्वारा चयनित।
भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की एक समिति।

समिति के समक्ष तीन नाम रखे गए हैं। हालाँकि, यहाँ भी कुछ कमियाँ हैं।
यह सुनिश्चित करने के तरीके कि चयनित सभी नामों को प्रधानमंत्री द्वारा मंजूरी मिल गई हो
पहले। या विपक्ष के नेता (एलओपी) और मुख्य न्यायाधीश अनौपचारिक रूप से
प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार चलने के लिए राजी हो गए। एक बार फिर, चतुर्वेदी के अनुसार
कहा करता था, 'अनौपचारिक स्तर पर बहुत सी चीजें संभव हो पाती हैं।'
हालांकि, यह कार्मिक और लोक प्रबंधन मंत्रालय है, जिसका नाम सुनने में नीरस लगता है।
शिकायतें और पेंशन, जो हर प्रधानमंत्री के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।
लगभग हर प्रधानमंत्री ने इस पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का विकल्प चुना है।
मंत्रालय। क्योंकि यह सीबीआई की निगरानी करता है, जो लगातार जांच कर रही है।
विपक्षी नेताओं से जुड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले—एक तलवार जो
प्रधानमंत्री पद का खतरा विरोधियों के सिर पर मंडराता रह सकता है। मई 2013 में,
सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि
सीबीआई ने शीर्ष पदों के दुरुपयोग के लिए उसे 'पिंजरे में बंद तोता' और 'उसके मालिक की आवाज' बताया।
कोयला क्षेत्र लाइसेंसों के आवंटन में जांच एजेंसी। जबकि प्रत्येक
सरकार ने अपने विरोधियों के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, मोदी सरकार ने भी ऐसा ही किया है।
सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अतिरिक्त विभाग के रूप में शामिल किया है।
अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने का साधन।
कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
और पेंशन का प्रबंधन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अंतर्गत आता है।
जो भारतीय जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जिम्मेदार है
प्रशासनिक सेवा (आईएएस)। प्रधानमंत्री, प्रभारी मंत्री के रूप में,
तबादलों के माध्यम से संपूर्ण नौकरशाही के कामकाज को नियंत्रित करना।
और नियुक्तियाँ। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में, गृह
मंत्रालय पहले विभाग एवं सेवा विभाग की देखरेख करता था। उनके तीखे मतभेदों के

बाद
इंदिरा गांधी ने इसे अपने गृह मंत्री वाई.बी. चव्हाण के अधीन लाया।
1970 में प्रधानमंत्री का नियंत्रण। यही वह समय था जब प्रधानमंत्री कार्यालय सर्वशक्तिशाली हो गया।
जब चरण सिंह 1977 में गृह मंत्री बने, तब विभाग
यह गृह मंत्रालय को वापस सौंप दिया गया था। राजीव गांधी ने ही इसे एक नए मंत्रालय के अधीन लाकर सीधे प्रधानमंत्री के प्रभार में वापस लाया था।
उन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग बनाए। जब अटल
बिहारी वाजपेयी ने अपने उप प्रधानमंत्री एल.के. को सत्ता सौंप दी।
आडवाणी ने उन्हें विभागाध्यक्ष का कार्यभार संभालने की अनुमति दी। इससे आडवाणी को एक
सरकार में एक प्रभावशाली व्यक्ति।
हालांकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं होता,
संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को, यदि वह चाहे तो, ऐसा करने में सक्षम बनाते हैं।
राज्यों की शक्तियों को सीमित करने का निर्णय लेता है। केंद्र सरकार काम कर सकती है।
वित्त आयोग के माध्यम से (अनुच्छेद 280-282 के तहत)
अनौपचारिक रूप से केंद्र-राज्य हिस्सेदारी के अनुपात को प्रभावित करना
वित्तीय बंटवारा—मुख्यमंत्रियों को नियंत्रित करने का एक तरीका। संविधान भी।
अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की स्थिति लागू करने का प्रावधान है।
देश में या उसके किसी भाग (अर्थात्, राज्य) में, जो इसकी अनुमति देगा
किसी राज्य को यह निर्देश देने के लिए एक केंद्र नियुक्त किया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए।
फिर अनुच्छेद 356 है जिसका बहुत दुरुपयोग किया गया है, जो इसके लिए प्रावधान करता है।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है, जब राज्यपाल (जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है)
केंद्र सरकार संवैधानिक व्यवस्था की विफलता का तर्क प्रस्तुत करती है।

'तंत्र'। इससे राज्य की बर्खास्तगी का रास्ता खुल सकता है।
जनता सरकार को सीधे केंद्र के नियंत्रण में लाना।
1977 में सत्ता में आने पर सरकार ने नौ सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था।
कांग्रेस द्वारा चलाई गई सरकारों ने इंदिरा गांधी को इसका प्रतिफल दिया।
1980 में सत्ता में आने पर भी स्थिति वैसी ही थी।
■

संविधान के अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था।
राष्ट्रपति (अर्थात सरकार) द्वारा मुख्य अधिकारी के साथ 'परामर्श' के द्वारा
भारत का न्याय। लेकिन शुरुआती वर्षों में, सरकारें केवल सूचित करती थीं।
उनके फैसले के मुख्य न्यायाधीश। यह 1993 में पी.वी. के दौरान बदल गया।
नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्रित्व काल। सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ।
न्यायालय ने 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' के रूप में व्याख्यायित किया।
पिछले कुछ वर्षों में, न्यायपालिका ने सुरक्षा उपाय बनाने में कामयाबी हासिल की है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसे बाद में इस रूप में जाना जाने लगा,
कॉलेजियम प्रणाली जो उच्च न्यायालयों और न्यायाधीशों के चयन का कार्य करती है
सर्वोच्च न्यायालय। 1999 में, मुख्य न्यायाधीश सहित कॉलेजियम ने
भारत और सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे
इसका विस्तार किया गया, जिसमें पांच न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई, जिनसे सामूहिक रूप से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई थी। न्यायाधीशों द्वारा नियुक्ति पर निर्णय लेने के साथ
साथी न्यायाधीशों के बीच, न्यायपालिका को कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।
प्रक्रिया में पारदर्शिता।
2014 में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक निकाय की स्थापना की।
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा।
इसे 2015 में रद्द कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि

कॉलेजियम प्रणाली की बहाली।
सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में हमेशा देरी कर सकती है।
मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नामों पर कई बार वर्षों तक विचार-विमर्श चलता रहता है।
जिसे '360 डिग्री' प्रक्रिया कहा जाता है, उसकी आड़ में छिपना।
'उचित सावधानी', क्योंकि सरकारी एजेंसियां किसी व्यक्ति के पूर्ववृत्त की जांच करती हैं
न्यायाधीश के चयन से पहले उम्मीदवार की उपयुक्तता का निर्धारण करना।
अंतिम रूप दिया गया है। इस पुस्तक के पूरा होने के दौरान एक युद्ध चल रहा था।
सरकार और न्यायपालिका के बीच, सरकार के साथ
न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रत्यक्ष भूमिका निभाने की मांग।
■

इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों ने यह विकल्प चुना है कि...
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के माध्यम से शासन। पीएमओ इस प्रकार है:
प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार शक्तिशाली। तमाम चुनौतियों के बावजूद
एक नए राष्ट्र को स्थापित करने और उसे सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी का सामना करते हुए, जवाहरलाल नेहरू के पास सीमित संसाधन थे।
प्रोफ़ाइल: प्रधानमंत्री सचिवालय (पीएमएस), जिसे अब पीएमओ के नाम से जाना जाता है।
नेहरू की प्रधानमंत्री सेवा समिति में केवल एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी ही प्रमुख था—एम.ओ.
मथाई, जो नेहरू के निजी सचिव थे। मथाई प्रसिद्ध हुए।
बाद में जब उनका नेहरू परिवार से मतभेद हो गया, तो उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा करने वाली किताब लिखी।
परिवार के बारे में किताब। हालाँकि नेहरू को उनके विचारों को लेकर कोई खास चुनौती नहीं मिली।

1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद, उन्होंने सत्ता संभालने के बाद काम करना पसंद किया।
अपने मंत्रिमंडल मंत्रियों के माध्यम से। अपने आप में नेता
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, वे अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते थे।
बाद के वर्षों में भी यही स्थिति रही।
यह अधिक संकोची लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की।
एक वरिष्ठ अधिकारी को उनके कार्यालय की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया और एल. के. झा को नियुक्त किया गया।
पीएमएस में सचिव, आईसीएस अधिकारी झा, सभी पहलुओं की देखरेख करते थे।
प्रधानमंत्री के कामकाज में दखल देने लगा और उसने सरकार से भी अधिक शक्ति हासिल कर ली।
मंत्रिमंडल सचिव, जो नौकरशाही के प्रमुख होते हैं। यह झा ही थे जिन्होंने यह पद संभाला था।

शास्त्री को पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए ताशकेंट जाने के लिए राजी कर लिया गया।
दोनों देशों के बीच 1965 का युद्ध।
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सेवा समिति को सर्वशक्तिशाली बनाने वाली पहली नेता थीं।
उन्होंने सबसे पहले उप मंत्री दिनेश सिंह को इसका प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया।
1967 में, उन्होंने शक्तिशाली पी. एन. हक्सर को सचिव के रूप में नियुक्त किया।
पीएमएस; 1971 में, वह उनके प्रधान सचिव बने। वामपंथी झुकाव वाले
हकसर केवल उसके निर्देशों का पालन करने वाला ही नहीं था, बल्कि वह और भी बहुत कुछ था।
बैंक से प्रेरित होकर, उन्होंने 1967-72 के बीच अपने सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया।
राष्ट्रीयकरण से लेकर बांग्लादेश जैसे नए राष्ट्र के निर्माण में सहायता तक।
हकसर, जो इंदिरा को इलाहाबाद के दिनों से जानता था, उसे इसी नाम से पुकारता

था।
निजी जीवन में इंदु एक आदर्श थीं। लेकिन सार्वजनिक रूप से वह प्रधानमंत्री थीं।
मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में पीएमएस, पीएमओ बन गया।
आत्मनिर्भर देसाई को इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई; उन्होंने इसे महत्वहीन बना दिया।
और इसमें मुख्य रूप से गठबंधन प्रबंधन की समस्याओं से निपटा गया।
चतुर पी.वी. नरसिम्हा राव को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई।
एक अधिकारी या एक गुट। हालांकि अमर नाथ वर्मा उनके प्रमुख थे।
सचिव के रूप में, राव ने नरेश चंद्र को अपरंपरागत कार्यों के लिए इस्तेमाल किया—जैसे कि
अयोध्या प्रकोष्ठ के प्रमुख को मंदिर विवाद से निकलने का रास्ता खोजने का निर्देश दिया गया है, और
फिर उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ परमाणु परीक्षण की तैयारी के लिए अपने संपर्क व्यक्ति के रूप में काम किया।
1995.
स्वतंत्रता के बाद से, दो वास्तव में शक्तिशाली प्रमुख सत्ताधारी रहे हैं।
सचिव जिन्होंने निस्संदेह प्रधानमंत्रियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित किया।
वे मंत्री पी. एन. हक्सर और ब्रजेश मिश्रा थे, जो वाजपेयी के मंत्री थे।
प्रधान सचिव मिश्रा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे,
वाजपेयी को अक्सर सरकार का वास्तविक मुखिया कहा जाता था।
वह निर्णय लेने की प्रक्रिया की बारीकियों में खुद को शामिल करता है। उसने इन्हें छोड़ दिया।
मिश्रा को।
मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाला प्रधानमंत्री कार्यालय 'साधारण' और 'संयमित' था।
अपने व्यक्तित्व के अनुरूप। सिंह शायद ही कभी बोलते थे।
उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकें कीं और मंत्रियों के समूहों के माध्यम से अपनी सरकार चलाई।
मंत्रियों के सरकारी समूह (जीओएम) और मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम), जिनमें से कई

इन टीमों का नेतृत्व अनुभवी प्रणब मुखर्जी कर रहे थे। लेकिन सोनिया गांधी ने ही यह काम किया।
गांधी जी यूपीए सरकार में सत्ता के वास्तविक केंद्र थे।
सिंह ने नेतृत्व किया; उन्होंने अपने राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के माध्यम से काम किया।
नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से शासन करते हैं, जो कई गतिविधियों की देखरेख करता है।
प्रत्येक मंत्रालय के कामकाज का कार्यप्रणाली प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता है।
मंत्रालय—मंत्री उन कार्यक्रमों को लागू करते हैं जिनके लिए उन्हें निर्देश दिए जाते हैं।
इसका अपवाद गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो एक अलग भूमिका निभाते हैं।
शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका। मोदी का मुख्य उद्देश्य।
सचिव, नृपेंद्र मिश्रा, जिन्हें दोस्त निप्पी कहते थे, ने पदभार संभाला।
प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के पहले कार्यकाल के पहले पांच साल (2014-19), और फिर पी.के.
उनके स्थान पर आए मिश्रा, न तो पी. एन. हक्सर जितने शक्तिशाली थे और न ही
बृजेश मिश्रा भी उतने दिखाई नहीं देते थे—और वे अपनी पहचान गुप्त रखना पसंद करते थे।
प्रोफ़ाइल। मोदी के प्रधानमंत्री कार्यालय में एक शक्तिशाली व्यक्ति, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास था
प्रधानमंत्री के विश्वास के प्रतीक उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत थे।
डोवाल। लेकिन डोवाल भी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं।
■

प्रधानमंत्रियों को प्रदत्त आधिकारिक शक्तियों के अलावा,
संविधान के अनुसार, ऐसे कई अनौपचारिक तरीके हैं जिनसे वे
जो उनका विरोध करते हैं, उन्हें मात दे दो।
प्रधानमंत्रियों द्वारा अपने विरोधियों पर फाइलें रखने की बात जगजाहिर है।

प्रतिद्वंद्वी और संभावित चुनौती देने वाले। कुछ प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया कि ये फाइलें मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने तुरंत यह भी जोड़ा कि उन्होंने खुद कभी ऐसा नहीं किया।

उन्होंने इस जानकारी का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ किया। 'हां, फाइलें मौजूद हैं।'

चंद्र शेखर ने मुझे बताया था, 'मैंने उनका कभी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे तो बस मिल गया था।'

सूचना सूचना ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार, मुझे बताया गया था कि इंदिरा गांधी के समय में भी,

उनका उपयोग नहीं किया गया। उनकी उपस्थिति मात्र ही काफी थी।'

प्रधानमंत्री कार्यालय में राजनेताओं और प्रमुख नौकरशाहों से संबंधित फाइलें मौजूद हैं।

और कई अन्य महत्वपूर्ण लोग। उन्हें ताला लगाकर सुरक्षित रखा जाता है।

पी.वी. राज्य मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी ने खुलासा किया, 'प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ।'

नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यालय में। 'इनमें भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी है।'

महिलाओं और हर तरह के कुकर्मों से संबंधित था।' उन्होंने आगे कहा: 'यह प्रथा थी

इंदिरा गांधी के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह अनुसंधान और

विश्लेषण विंग (आर एंड एडब्ल्यू) - हालांकि इसका उद्देश्य बाहरी डेटा एकत्र करना था

बुद्धि—(जिसने) इसे समझने में मदद की...। वह आशंकित थी।

उनकी स्थिति के बारे में। अधिकांश प्रधानमंत्रियों ने ऐसा करना चाहा होगा।

उन्होंने अपने विरोधियों को लगाम में रखा हुआ है।

■

मुझे एक मंत्री याद हैं जो किसी भी घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर मुझे फोन करते थे।

प्रधानमंत्री के साथ साक्षात्कार समाप्त हो गया था। 'तो बैठक कैसी रही?' वह पूछता। पूछो। मुझे आश्चर्य होता कि उसे इतनी जल्दी इसके बारे में कैसे पता चल गया। वह

स्पष्ट रूप से मुझे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह कितना अंदरूनी व्यक्ति था।

हरियाणा के दिवंगत मुख्यमंत्री भजन लाल—उनका नाम तो बस इतना ही है

उदाहरण प्रस्तुत करने की कला में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। जब भी वे इंदिरा से मिलने जाते थे,

गांधी अपने घर में चपरासियों, गार्डों, माली और अन्य कर्मचारियों को टिप दिया करते थे।

अन्य लोग उन्हें भरपूर धन देते थे। वे उन्हें प्रतिदिन आने-जाने की जानकारी देते रहते थे।

और प्रधानमंत्री आवास में होने वाली गतिविधियों के बारे में।

इंदिरा गांधी के सहयोगियों आर. के. धवन को प्राप्त शक्ति, जिन्होंने

उन्होंने उसे स्टेनोटाइपिस्ट के रूप में काम पर रखा था, और माखन लाल फोतेदार, जिन्होंने

प्रधानमंत्री आवास (पीएमएच) स्थित उनके कार्यालय में तैनात कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक थी।

हर घंटे उसके निकट रहना। धवन का प्रभाव इतना अधिक था।

अपने पिता की मृत्यु के बाद, भारत के लगभग सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उस शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।

उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने आए थे।

प्रधान मंत्री अपनी इच्छा अनुसार किसी से भी मिल सकते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली

सहायक प्रधानमंत्री तक पहुंच को नियंत्रित कर सकता है; वह चाहे तो पहुंच प्रदान कर सकता है।

उन लोगों की नियुक्तियाँ जो प्रधानमंत्री को आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री को जो हासिल करना चाहता है, इसीलिए नेता अपना नेटवर्क बनाते हैं।

खुफिया एजेंसियों और आधिकारिक चैनलों से स्वतंत्र रूप से,

प्रतिक्रिया प्राप्त करना। वे मीडियाकर्मियों, दोस्तों, नौकरशाहों से संबंध बनाते हैं।

और पार्टी के सहयोगी जो उन्हें इस बारे में जानकारी देते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है

चल रहा है।

■

अब, प्रधानमंत्री के उन निर्णयों पर आते हैं जिनका मैंने अध्ययन किया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

भारतीय राजनीति के पचास वर्ष। मैंने ऐसे निर्णय चुने जिन्होंने राजनीति को प्रभावित किया।

और समाज में इनके बनने के बहुत समय बाद भी ये मौजूद रहते हैं।

इंदिरा गांधी के मामले में, मैं इस बात पर गौर करता हूँ कि उन्होंने ऐसा आह्वान करने का निर्णय क्यों लिया।

जनवरी 1977 में हुए चुनाव—जिसमें मित्र और शत्रु दोनों ही शामिल थे—

आश्चर्य की बात है—और यह चालीस वर्षों से अधिक समय से विश्लेषकों को लुभाता आ रहा है।

बाद में, मैं 1977-80 के बीच उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर गौर करता हूँ।

उन्हें सत्ता में वापस लाया। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपने समर्थकों को कैसे जीता?

कट्टर विरोधी, जनता पार्टी के विद्रोही नेता राज नारायण, जिन्होंने

सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? वही था जिसने उसे अयोग्य घोषित करवाया था।

उन्होंने 1975 में संसद में उनका प्रतिनिधित्व किया और 1977 में उन्हें हराया, लेकिन उन्होंने उनका इस्तेमाल किया।

जनता सरकार को ध्वस्त कर दिया। उसने जयप्रकाश को कैसे बेअसर किया?

नारायण (जेपी)—जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने के आंदोलन का नेतृत्व किया था,

किस बात ने उन्हें 1975 में आपातकाल लागू करने के लिए उकसाया? उन्होंने दलित नेता जगजीवन राम को कैसे नुकसान पहुंचाया, जो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उन्हें बचा सकते थे?

क्या इसने 1980 में उनकी सत्ता में वापसी को रोका? और समर्थन खोने के बाद

आपातकाल के दौरान मुसलमानों के साथ जो हुआ, उसने किस प्रकार अपने शरीर का

हिंदूकरण किया?
राजनीति में, 1980 में हिंदुओं को अपने पीछे एकजुट करने में सफल रही—
क्या यह ऐसा कदम था जिसका भारतीय राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने वाला था?
उनकी वापसी की कहानी में ये तत्व शामिल थे: इंदिरा गांधी ने इनका इस्तेमाल किया।
saam, daam, dand, bhed (persuasion, bribery, punishment, and
चाणक्य के राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र के शब्दों में, विभाजन के रूप में
सत्ता में वापसी के लिए उसने अपनी कूटनीति के औजारों का इस्तेमाल किया—
भीतर
उत्तर भारत में कांग्रेस के पूरी तरह से सफाए होने के तैंतीस महीने
भारत। इसी दौरान वह वास्तव में एक उस्ताद के रूप में उभरीं।
वास्तविक राजनीति। 'किसी भी कीमत पर सत्ता' को राजनीतिक मान्यता मिली, और उसे
सभी दलों के राजनेताओं की पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बनें जो
उसके पीछे आए। उन्होंने उसकी जीत की नकल करने की कोशिश की।
विरोधियों से भी बड़ी होकर, अपनी पार्टी से भी बड़ी बनकर, और राजनीतिक रूप से सफल होकर
सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए विरोधाभासों का सहारा लेना।
राजीव गांधी के शुरुआती प्रधानमंत्री कार्यकाल में उनकी नासमझी झलकती थी।
गांधी जी। गंभीर और नेक इरादे वाले, शाह बानो के प्रति उनकी प्रतिक्रिया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अप्रैल 1985 में दिया गया फैसला, जिसमें गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था।
एक व्यथित मुस्लिम महिला के प्रति उनका व्यवहार ही उनके पतन का कारण बना।
उसने ऐसी ताकतों को बेकाबू कर दिया जिन्होंने उसकी क्रूरता के बावजूद उसे ही पराजित कर दिया।
संसद में बहुमत।
अगर कुछ ऐसे फैसले थे जिन्होंने भाजपा को गति प्रदान की, तो वे ये थे...

राष्ट्रीय स्तर पर विकास के संदर्भ में, राजीव ने दो निर्णय लिए थे।
शाह बानो का फैसला। उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बनाने का फैसला किया।
शाह बानो अधिनियम को निरस्त करने के लिए (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986।
उत्तेजित मुस्लिम समुदाय को शांत करने के लिए निर्णय लिया। फिर, जल्दबाजी में, उसने
जब वे सड़कों पर उतरे तो उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को शांत करने की कोशिश की।
विरोध प्रदर्शन। उन्होंने विवादित बाबरी किले के ताले खोलने में मदद की।
मस्जिद में हिंदुओं को नमाज अदा करने की अनुमति है। हालांकि
न्यायिक आदेश से ढांचा खोला गया, इसके पीछे राजीव का हाथ नजर आ रहा था।
इस बात पर बहस अभी भी जारी है कि अंततः इसके लिए कौन जिम्मेदार था।
ताले खोलने का फैसला। क्या यह राजीव गांधी का अपना फैसला था? या
क्या उनके चचेरे भाई अरुण नेहरू, जो उस समय अपने क्षेत्र के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, ने ऐसा किया?
सरकार, उसे अंधेरे में रखे और उसके सामने एक झूठ पेश करे।
क्या आरएसएस ने प्रधानमंत्री के 1 फरवरी 1986 को संविधान को अनलॉक करने के फैसले को प्रभावित किया ताकि वह सत्ता में आ सकें?
'हिंदुओं के दिलों का राजा'?
राजीव गांधी के दो निर्णयों ने ऐसी शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने भविष्य में समाज का स्वरूप निर्धारित किया।
अगले तीन दशकों की राजनीति। अंततः इसके परिणामस्वरूप स्थापना हुई।
2014 में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी।
एक साल से भी कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे वी. पी. सिंह ने राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया।
मंडल प्रणाली को लागू करने के उनके निर्णय से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया।
आयोग की रिपोर्ट। बी. पी. मंडल द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में एक

सरकार में 27 प्रतिशत नौकरियां सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित लोगों के लिए आरक्षित करने का तर्क
शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिन्हें आम तौर पर 'अन्य' के रूप में जाना जाता है।
पिछड़े वर्ग। भारत की कुल जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत है।
1931 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या। इसके बाद, मंडल शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।
ओबीसी के लिए सकारात्मक कार्रवाई के पक्ष में। उपराष्ट्रपति के इस फैसले से भाजपा का दबाव बढ़ गया।
'मंदिर' के लिए आंदोलन—यह मांग को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त शब्द है।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और भाजपा राम मंदिर निर्माण के लिए
उस स्थान पर जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी।
क्या 'मंदिर' 'मंडल' का जवाब था, जैसा कि व्यापक रूप से माना जाता है? या फिर...
मंडल भाजपा की मंदिर राजनीति का प्रतिवाद है—जैसा कि वी. पी. सिंह ने प्रयास किया था।
आक्रामक भाजपा को हराने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक नया निर्वाचन क्षेत्र तैयार करना।
संकटग्रस्त सरकार?
इस फैसले और इसके विरोध ने एक नए ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को जन्म दिया।
वह नेतृत्व जिसने भारत और उसके राज्यों पर पच्चीस वर्षों तक शासन किया
afterwards. They included Lalu Prasad Yadav, Mulayam Singh Yadav,
Nitish Kumar, Kalyan Singh, Uma Bharati, Akhilesh Yadav, Shivraj
चौहान, अशोक गहलोत और कई अन्य। नरेंद्र मोदी को...
2014 में भारत के एक शक्तिशाली ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में उभरे।
जाति और धर्म के बीच के संघर्ष में मंडल और मंदिर शामिल हैं।
जिसकी शुरुआत हुई, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नुकसान हुआ—और हुआ है

तैंतीस साल बाद भी उबरना बाकी है। वी. पी. सिंह सरकार
अल्पकालिक होने के बावजूद, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण एक
यह एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता है जिसे उपराष्ट्रपति के बाद कोई भी सरकार नहीं बदल सकती।
भारतीय राजनीति का मंडलीकरण तेजी से जारी है, क्योंकि हाशिए पर पड़े
सभी दलों द्वारा लुभाए गए समूह अपने वोट के महत्व को समझते हैं।
6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक
भारत के इतिहास का निर्णायक क्षण। पी. वी. नरसिम्हा राव की विफलता।
संरचना की रक्षा करना बैठक में लिया गया अंतिम अनिर्णय था।
प्रधानमंत्री। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की शक्तिशाली एजेंसियां हिंसक घटनाओं को बेबसी से देखती रहीं।
भीड़ बाबरी मस्जिद पर चढ़ गई और उसे ध्वस्त कर दिया।
रस्सियाँ, फावड़े और कुल्हाड़ी।
विध्वंस के दशकों बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं।
क्या नरसिम्हा राव ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार को गिराने की साजिश रची थी?
क्या यह बाबरी मस्जिद थी, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं? या उन्होंने बस इमारत को बनने की अनुमति दे दी थी?
विध्वंस शुरू होने के बाद नीचे आ जाओ, इस उम्मीद में कि इससे एक
भारत की राजनीतिक व्यवस्था में पनप रहे गहरे घाव को मिटाकर, भाजपा के प्रयासों को विफल किया जा सकता है।
महत्वाकांक्षाएं? क्या राव विध्वंस को रोकने के लिए और कुछ कर सकते थे—जो
यह भारतीय राज्य की किसी पूजा स्थल की रक्षा करने में विफलता का प्रतिनिधित्व करता है।
हालांकि इस पर विवाद था।
प्रधानमंत्री बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर मजाक करते थे।
वह भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद के लिए प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति थे। वाजपेयी
11 और 13 मई 1998 को हुए परमाणु परीक्षणों के लिए याद किया जाएगा,

जिन्होंने दुनिया को खतरे में डाल दिया था।
भारत परमाणु हथियार संपन्न देशों की बड़ी लीग में शामिल है।
1964 में कट्टरपंथी रहे वे 1979 में विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नरमपंथी बन गए।
मोरारजी देसाई ने परमाणु परीक्षण का विरोध किया था। लेकिन, 1998 में उन्होंने तुरंत कार्रवाई की।
इन उतार-चढ़ावों का कारण क्या था जिसने अंततः भारत को इस पथ पर अग्रसर कर दिया?
वैश्विक उच्च मंच तक पहुंचने का मार्ग? वाजपेयी को ऐसा कदम उठाने के लिए किसने प्रेरित किया?
इंदिरा गांधी को छोड़कर अन्य प्रधानमंत्रियों ने इसके खिलाफ फैसला किया था।
क्या वाजपेयी ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया था?
वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैसले के बाद की स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं थे।
उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर इसके दुष्परिणामों को नियंत्रित किया और सूर्यास्त की ओर चले गए।
अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनके बीच एक अनोखी केमिस्ट्री थी।
भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत-अमेरिका संबंधों को संभव बनाया।
2008 में हस्ताक्षरित नागरिक परमाणु समझौता। यह एकमात्र ऐसा निर्णय था जिस पर
सिंह ने अपनी प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री पद को दांव पर लगा दिया, और एक अप्रत्याशित प्रदर्शन किया।
उसने जो चाहा उसे पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अमेरिका भारत को एक 'आधार' के रूप में देखता था।
एशिया में स्थिरता लाने और चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य से। भारत के लिए, इस समझौते ने एशिया में स्थिरता लाने और चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य को समाप्त कर दिया।
1974 और 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद से उसे जिस परमाणु भेदभाव का सामना करना पड़ा था—
और इसने परमाणु व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया।

शांत स्वभाव वाले 'डॉक्टर साहब' ने विपक्ष का सामना कैसे किया?
शक्तिशाली सोनिया गांधी से, जो उनके कार्यकाल में 'आधी प्रधानमंत्री' थीं।
उनका कार्यकाल कैसा रहा? उन्होंने उन वामपंथी पार्टियों को कैसे पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने उनका समर्थन किया था?
सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः अपना समर्थन वापस ले लिया? वे कौन थे?
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मध्यस्थ, स्वयं को राजनीति से परे बताने वाले मनमोहन सिंह
क्या सिंह ने दिल्ली और वाशिंगटन डीसी में समर्थन जुटाने के लिए लामबंदी की?
मनमोहन सिंह ने समझौते को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया।
उसने जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डाली, उससे उसकी वह हत्यारा प्रवृत्ति स्पष्ट हो गई जिसके बारे में कुछ ही लोगों ने सोचा था।
इस जीत ने अमेरिका के साथ एक नई और रणनीतिक साझेदारी का मार्ग प्रशस्त किया।
■

जैसा कि अक्सर कहा जाता है, यदि कोई संस्था किसी व्यक्ति की लंबी परछाई है,
प्रधानमंत्री के निर्णय लेने की प्रक्रिया से इस बात पर दुर्लभ प्रकाश पड़ता है कि कैसे हमारी बहुदलीय, विखंडित लोकतंत्र में सरकारें काम करती हैं। क्योंकि वे
वे न केवल सत्ता के पिरामिड के शीर्ष पर बैठे हैं, बल्कि वे केंद्र में भी हैं।
विचारों, दबावों से निपटने, परस्पर विरोधी दावों को संतुलित करने और संघर्ष करने के बीच संतुलन बनाना।
जमीनी स्तर की ताकतों के बढ़ते दबाव के साथ, जो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं।
प्रधानमंत्रियों ने इन चुनौतियों का अपने-अपने विशिष्ट तरीके से जवाब दिया।
शैली—भारत के लोकतंत्र को आकार देने और नया रूप देने के लिए।
यह पुस्तक सत्ता और सत्ता पर काबिज लोगों द्वारा उसके प्रयोग के बारे में है।
सर्वोच्च सार्वजनिक पद। यहां तक कि गठबंधन सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री भी।

आई. के. गुजराल, जिन्हें सबसे कमजोर प्रधानमंत्रियों में गिना जाता है, बहुत शक्तिशाली हैं।
वह अक्सर ऐसा कहते थे। ये अध्याय इस बात को स्पष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री की शक्ति किस प्रकार है।
बहुमत शासन के तहत और गठबंधन सरकार में भी इसका क्रियान्वयन हुआ।
और नियंत्रण एवं संतुलन किस हद तक इसे रोकने में सक्षम थे
इस शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग।
आज के समय में यह बात और भी अधिक प्रासंगिक है। तत्काल के बावजूद
संचार और 24x7 स्ट्रीमिंग, समाचारों तक अभूतपूर्व पहुंच
अभूतपूर्व संख्या में चक्र, जो अभी भी पर्दे के पीछे छिपा है
इस प्रकार प्रधानमंत्री उच्चतम स्तर पर निर्णय लेते हैं। अध्याय जो
आइए, एक-एक प्रधानमंत्री के बारे में खुलासा करें और जानें कि कैसे...
गतिशील पुर्जे काम करते हैं।
■

एक व्यक्तिगत टिप्पणी: नेहरू, शास्त्री और गुलज़ारी लाल नंदा को छोड़कर, मैं
मुझे सभी प्रमुख हस्तियों से मिलने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
इस पुस्तक में मंत्रियों और उनमें से कई के साथ मेरे साक्षात्कारों से प्राप्त जानकारी का योगदान है।
जब मैं नौ साल का था, तब मैंने अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में नेहरू का भाषण सुना था।
विभिन्न देशों की अपनी यात्राओं के बारे में बात करें—विवरण अस्पष्ट हैं,
केवल चाचा नेहरू का हमारे साथ होना ही काफी था।
यह पुस्तक एक तरह से मेरी चार दशकों की दैनिक रिपोर्टिंग पर आधारित है।
स्तंभ लेखन, घटनाओं का विश्लेषण—उन शुरुआती वर्षों में घर-घर जाकर लोगों से मिलना, प्रतीक्षा कक्षों में बैठना, सरकार में शामिल लोगों का इंतजार करना।
और राजनीतिक दल। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरे 'सूत्र'—
अनदेखे, गुमनाम और अनसुने, जिनमें से कई लोग बड़े जोखिम में हैं—

उन्होंने मुझे पर्दा उठाने में मदद की। इनमें वे महिलाएं और पुरुष शामिल थे जिन्होंने आनंद लिया।
प्रधानमंत्री का विश्वास, मंत्रीगण, सांसदगण, पार्टी नेता, मेरे साथी यात्री।
मीडिया में, नौकरशाहों में, उद्योगपतियों में, और अनगिनत अन्य लोगों में जो
प्रधानमंत्रियों के चारों ओर लगातार बढ़ते दायरे में घूमते रहे।
कई बार मुझे घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव मिला, तो कई बार यह एक अलग नजरिया था।
पीछे की बेंच से देखें। कभी-कभी प्रधानमंत्रियों ने उच्च स्तर की रणनीति अपनाई।
वहीं दूसरी ओर, उनके कार्यों ने समाज के कुरूप पक्ष को उजागर कर दिया।
भारतीय राजनीति। लेकिन लगभग एक दृढ़ विश्वास के रूप में, मैंने लिख डाला।
आज की कहानी के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से की जाने वाली औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत।
इसे बाद के लिए रखा जाए, इस उम्मीद में कि मैं एक किताब लिखूंगा।
भूली हुई अलमारियों में अनगिनत नोटबुक पड़ी हुई हैं; हजारों
दस्तावेजों, अध्ययनों, समाचार रिपोर्टों और पुस्तकों के पृष्ठ; से मुक्त
पत्रकारिता की समयसीमा के अत्याचार से बचने के लिए, मैंने गहराई में गोता लगाया और फिर से उभर कर सामने आया।
मेरे पास ऐसे खजाने थे जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था। इनमें मैंने और भी साक्षात्कार जोड़े।
और इस पुस्तक को लिखने के लिए आगे अध्ययन किया।
कोविड काल के दौरान, मैंने जिन सभी पात्रों के बारे में लिखा है
अचानक हलचल मच गई और मेरे अध्ययन कक्ष में भीड़ जमा हो गई। जैसे ही मैंने अपनी बातचीत पर दोबारा गौर किया, मुझे
उच्च ध्वनि वाले नाटक के रोमांच को पुनः खोज लिया—जीवंत,
निरंतर परिवर्तनशील, हमेशा आश्चर्यजनक। अंततः, इसने मुझे एक रचना लिखने में मदद की।
एक अनकही कहानी। भारत के प्रधानमंत्रियों की सोच की कहानी।
और निर्णय लेना—एक ऐसी कहानी जो वयस्कता के आगमन को दर्शाती है, और सभी के लिए

इसकी कमजोरियाँ, भारत के अविश्वसनीय लोकतंत्र का परिपक्व होना।

*विभिन्न स्रोतों में प्रधानमंत्रियों की संख्या अलग-अलग बताई गई है। पीएम इंडिया की वेबसाइट पर गुलज़ारी लाल नंदा सहित पंद्रह प्रधानमंत्रियों का उल्लेख है, लेकिन यह पुस्तक विधिवत निर्वाचित प्रधानमंत्रियों की गिनती करने की अधिक प्रचलित परंपरा का अनुसरण करती है—अब तक चौदह व्यक्तियों ने यह पद संभाला है। इनमें से पांच—जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी—ने एक से अधिक कार्यकाल तक पद संभाला है। ऐसे भी कई व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा कार्यकाल नहीं निभाया।

अध्याय 1

राख से उठकर आए प्रधानमंत्री

इंदिरा गांधी की वापसी

मैं

इंदिरा गांधी ने सोचा, ‘मुझे लगता है मैं पहाड़ों पर जाकर वहीं रिटायर हो जाऊंगी।’
सफदरजंग रोड स्थित अपने घर पर आए कुछ मेहमानों से उन्होंने कहा, 'शायद मैं ले जाऊंगी।'
हिमाचल प्रदेश में कहीं एक छोटी सी कुटिया में रहूँ, और अपनी कहानी लिखूँ। संस्मरण।'
‘आखिर मेरी ज़रूरतें क्या हैं?’ वह सोच-विचार करते हुए बोली। ‘मेरा’
मुझे जीने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है? मैं बहुत आराम से रह सकता हूँ। बस।
वह कपिल मोहन और अनिल बाली से बात कर रही थीं, जो वहीं से थे।
प्रसिद्ध मोहन मीकिन शराब निर्माण कंपनी,

अपने ओल्ड मोंक रम के लिए। 1970 के दशक में, वे अपने
प्रधानमंत्री से निकटता। मोहन परिवार, व्यापक नेटवर्क के साथ।
राजनीतिक हलकों में मौजूद सभी दलों ने 1960 के दशक के उत्तरार्ध से ही श्रीमती गांधी का समर्थन किया था।
वह उनके साथ घर के पीछे वाले लॉन में जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गई।
विशाल बंगला। बगीचा हरा-भरा और जीवंत रंगों से भरा हुआ था।
दिल्ली की छोटी सी वसंत ऋतु में। लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी खुशनुमा नहीं था।
वह देख रही थी
बगीचे के चारों ओर के पेड़ों को देखकर—उसे पेड़ बहुत पसंद थे—लंबे, प्रहरी जैसे दिखने वाले पेड़।
दाईं ओर कदम और अकेला चीड़ का पेड़, अपनी एक अलग ही सुंदरता के कारण मनमोहक लगते हैं।
ऊपर पत्तियों का एक असामान्य गुच्छा था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उनसे उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा था।
सांत्वना। अप्रैल 1977 की इस सुबह, ऐसा लग रहा था कि शायद ही कुछ सांत्वना दे पाएगा।
दो सप्ताह पहले तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं।
भारत। आज वह संसद सदस्य भी नहीं थीं। कांग्रेस
उनकी पार्टी मार्च 1977 के आम चुनाव हार गई थी।
यह एक बहुत बड़ा झटका था। वह अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में हार गई थी।
रायबरेली में मिली हार—एक ऐसे नेता के लिए चौंकाने वाला झटका, जिनकी प्रशंसा की गई थी
1971 में बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र के निर्माण में सहायता करने के बाद उन्हें 'दुर्गा' नाम दिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने उन्हें 'भारत की साम्राज्ञी' कहा था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने देश को सत्ता दिलाई थी
उन्हें आजादी मिली और उन्होंने तीस वर्षों तक बिना किसी रुकावट के इस पर शासन किया।
उत्तर भारत में स्वतंत्रता लगभग पूरी तरह से मिटा दी गई थी। जनता

पार्टी और उसके सहयोगियों ने चुनावों में शानदार जीत हासिल करते हुए सभी 345 सीटों पर कब्जा कर लिया था।
उत्तरी राज्य। 22 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दे दिया था।
प्रधानमंत्री, एक ऐसा पद जिसे उन्होंने ग्यारह वर्षों तक संभाला था।
अपनी इस करारी हार से निराश होकर, वह अब गंभीरता से विचार कर रही थी कि...
पहाड़ियों में जाकर बसने और राजनीति से संन्यास लेने के विचार के साथ। 'मैं
यह किसी जगह पर स्थित होगा, शायद जहाँ चारों ओर पेड़ हों।
और एक झरना। मैं अपना बाकी जीवन वहीं बिता सकता हूँ। और मैं पढ़ भी सकता हूँ।
किताबें।
'महोदया, क्या आप एक किताब लिखेंगी?' उनतीस वर्षीय बाली ने पूछा।
उसने उत्तेजित होकर उससे पूछा।
उन्होंने कहा, 'शायद, लेकिन फिर मेरी आत्मकथा कौन पढ़ना चाहेगा?'
वह उदास थी। उसे पता था कि वह नफरत की पात्र बन चुकी है। देश ने
उसके खिलाफ हो गए।
'कृपया मेरे लिए एक कॉटेज ढूंढ दीजिए,' उसने मोहन और बाली से कहा। 'मैं
अब मैं बहुत थक गया हूँ। और मैं इस राजनीति से तंग आ चुका हूँ।
अचानक उसने कहा, 'मुझे पहले से ही आभास हो गया था कि मैं हार सकती हूँ।' उन्होंने देखा
आश्चर्यचकित। क्योंकि वे जानते थे कि उसे यह प्रतिक्रिया मिली थी कि वह
जीत। दरअसल, खुफिया एजेंसियों ने उसे बताया था कि वह 340 वोट जीतेगी।
सीटें। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें बताया था कि वह वापस आ जाएंगी।
सत्ता। लखनऊ में, नतीजों से दो दिन पहले, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश के एन. डी. तिवारी ने उन्हें विश्वासपूर्वक आश्वासन दिया था, 'हम हैं'
यहां (85 में से) 70 सीटें जीतना।
आप जानते हैं, जब मैंने अपना आवेदन दाखिल करने के बाद उस कार्यालय से बाहर आया
मैंने नामांकन पत्र (रायबरेली में) तैयार किए और लोगों से बात करना शुरू कर दिया।
वहां जो लोग जमा थे, उन्हें देखकर ही मुझे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है,'

उसने बताया।
मोहन और बाली। 'मुझे वह उत्साह महसूस नहीं हो रहा था जो पहले हुआ करता था।'
पहले ही।' उसे यह भी आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है।
अभियान। एक बार जब बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके लिए प्रचार करने आए लोग पैदल चलने लगे।
उन्होंने अपना भाषण समाप्त करने के बाद तुरंत ही बाहर निकल गए, प्रधानमंत्री के बोलने का इंतजार नहीं किया।
उन्होंने अपना भाषण शुरू किया।
उस सुबह जब मोहन और बाली कमरे 1 में दाखिल हुए थे,
सफदरजंग रोड पर, उन्हें सीधे ले जाया गया देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए।
पीछे वाले बगीचे में आरामकुर्सियाँ रखी हुई थीं। सुबह के 11 बज रहे थे।
अप्रैल की शुरुआत थी और दिन गर्म होने लगे थे। आमतौर पर वे मिलते थे।
उसे सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए बैठक कक्ष में बिठाया गया जहाँ वह विदेशी आगंतुकों से मिलती थी।
गणमान्य व्यक्ति, राजनेता और अन्य महत्वपूर्ण आगंतुक। पूछताछ करने पर,
उन्हें पता चला कि अपनी हार के बाद से वह आगंतुकों से मिलने लगी थी।
बगीचे में। उसे शक था कि सत्ताधारी जनता पार्टी की सरकार,
मोरारजी देसाई के नेतृत्व में घर में जासूसी उपकरण लगाए गए थे। उसे यह भी नहीं पता था कि क्या हुआ था।
अमेरिकी क्या कर रहे थे। वह तब से 'शक करने लगी थी'।
मैंने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के परिसर में जासूसी उपकरणों की निगरानी के बारे में सुना है।
अमेरिकियों द्वारा। अन्य राजनेताओं की तरह, उन्हें भी कुछ समर्थन मिला था।
उपग्रह निगरानी को रोकने के लिए छत पर एक उपकरण स्थापित किया गया है।
इन एहतियाती उपायों के बावजूद, वह अपने घर पर ही रही।
रक्षक।
इंदिरा के विपरीत, जिसे अपने जीवन का अंत नजर आ रहा था।
राजनीतिक दृष्टि से कपिल मोहन इसे इस तरह नहीं देखते थे। मोहन मीकिन
परिवार का इंदिरा के साथ लंबे समय से संबंध था। मोहन का भी उनसे पुराना रिश्ता

था।
आपातकाल के दौरान वह अपने छोटे बेटे संजय के बेहद करीब रहीं।
उनके जैसे उद्योगपतियों ने राजनीति में इतने उतार-चढ़ाव देखे थे कि अब वे
वह स्थायी जीत या हार में विश्वास करते थे। लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा।
उसका विरोध करना; उसके लिए बाद में पर्याप्त समय होगा।
उसने अपने लिए चाय और चिकन सैंडविच लाने को कहा।
आगंतुकों से पूछा, 'मुझे नहीं पता कि मैं अपने इन कालीनों का क्या करूं।'
उसने झुंझलाहट भरी आवाज में कहा। हस्तशिल्प और हथकरघा
ये उनके पसंदीदा शौक थे। उनके खूबसूरत कश्मीरी कालीनों की बहुत कद्र की जाती थी।
उसने अपनी संपत्ति से घर के हर कमरे को सजाया था।
भोजन कक्ष बहुत ही अनोखा था और लगभग कमरे जितना ही बड़ा था। उसने कहा,
ये ज्यादातर मेरे माता-पिता ने दिए थे, मुझे नहीं पता कि मैं इन्हें कहाँ रखूँ।
उन्हें... यह सरकार,' उसने थोड़ी कड़वाहट के साथ कहा, 'नहीं करेगी।
मुझे अभी एक घर भी आवंटित कर दो... यह ऐसी शिष्टाचार की बात नहीं है जो वे मुझे दिखाएंगे।
एक पूर्व प्रधानमंत्री।' कुछ दिनों बाद—11 अप्रैल 1977 को—
वह 12, विलिंगडन क्रिसेंट में रहने लगी, जो एक सरकारी संपत्ति थी।
पारिवारिक मित्र मोहम्मद यूनुस द्वारा उनके लिए खाली कराया गया। जनता
सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई।
'महोदया, कृपया चिंता न करें,' मोहन ने तुरंत उन्हें आश्वस्त किया। 'मैं
हम मोहन नगर से बढ़ई और पैकर भेजेंगे ताकि इन्हें ठीक से पैक किया जा सके। हम
यह सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें कोई नुकसान न पहुंचे।' उन्होंने आगे कहा, 'हम
जब तक आप उन्हें वापस नहीं मांग लेते, हम उन्हें मोहन नगर में आपके लिए सुरक्षित रखेंगे।
इंदिरा को राहत मिली। फिर उसने असलियत का जिक्र किया।
उसके मन में कई बातें खटक रही थीं। उसने कहा, 'मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है।'
मोहन। 'मुझे संजय और उसकी सुरक्षा की चिंता है। मुझे नहीं पता क्या होगा।'
वे उसके साथ क्या करेंगे... मैं उसकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हूँ?' उसकी

आवाज़ में यह भाव था...
अपने संभावित राजनीतिक उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हुए वह थोड़ी उत्तेजित लग रही थीं।
कुछ ही दिन पहले तक, उससे लोग डरते थे—एक तानाशाह के रूप में, उसके पास
नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला, और
आपातकाल के दौरान उसने प्रेस पर सेंसरशिप लागू की थी।
1975 से 1977 तक उन्नीस महीने। अचानक वह कमजोर दिखने लगी।
वह बार-बार दोहरा रही थी, 'मुझे संजय की जान की बहुत चिंता है।'
उसे डर था कि जनता पार्टी की सरकार उसे जीने नहीं देगी।' उसे डर था कि जनता पार्टी की सरकार
उसे 'नुकसान पहुंचाएंगे' और उसे 'जेल में डाल देंगे'।
बाली ने बाद में कहा, 'उसने मुझे यह बात एक से अधिक बार बताई थी।'
मोहन ने एक बार फिर उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। 'चिंता मत कीजिए, महोदया, हम सब ठीक कर देंगे।'
उसका ध्यान रखना।
उसने जिज्ञासा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा।
सोलन में हमारा एक गेस्ट हाउस है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर एकांत स्थान पर स्थित है।
जगह अच्छी है। वहां से नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। वह वहां जाकर रह सकता है। मैं व्यवस्था कर दूँगा।
सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा।'
उन्होंने आगे कहा, 'आप मुझे बता दीजिए कि आप उसे कब भेजना चाहेंगे।'
‘अनिल यहाँ है,’ मोहन ने बाली की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘वह उसके साथ जा सकता है और उसे ले जा सकता है।’
हर चीज का ख्याल रखना।
वह अनिश्चित लग रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बैठी हुई
उस दिन बगीचे में, उसने बताया कि सब कुछ कितना अजीब लग रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।

अचानक, जाने के लिए कोई ऑफिस नहीं था। न ऑफिस की गाड़ी थी, न कोई कर्मचारी।
कार। उन्हें वापस ले लिया गया था। उसके पास खुद की कार भी नहीं थी।
उसके पास कोई टेलीफोन ऑपरेटर नहीं था जो उसे लोगों से संपर्क करने में मदद कर सके।
वह जिनसे बात करना चाहती थी। उसे उनके फोन नंबर भी याद नहीं थे।
उसके दोस्त। इन सब चीजों का ख्याल उसके लिए दूसरों ने इतने समय से रखा था।
कई साल बीत गए। रातोंरात, उसे कोई फाइल नहीं भेजी जा रही थी। कम से कम उस समय तो नहीं।
वह इसमें व्यस्त रहती।

द्वितीय

20 मार्च 1977 को, जैसे ही रात हुई, दिल्ली में चुनाव परिणामों को लेकर हलचल मच गई।
लगातार संदेश आ रहे थे। यह स्पष्ट था कि कांग्रेस हार रही थी। इंदिरा गांधी के निजी सहायक आर. के. धवन दौड़कर आए और उन्हें बताया कि
वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में पिछड़ रही थी। फिर वह असहज होकर रुक गया।
और कहा कि हार का अंतर बढ़ता जा रहा था। जब उसकी दोस्त
और जीवनीकार पुपुल जयकर रात करीब 8 बजे अंदर आईं, इंदिरा
बिल्कुल अकेली बैठी हुई। 'पुपुल, मैं हार गई,' उसने अपनी सहेली से उदास स्वर में कहा।
वे बिना कुछ और कहे साथ बैठे रहे।
इंदिरा गांधी ने उस दिन देर शाम मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई थी।
रात हो चुकी थी। बाहर सड़कों पर जश्न की आवाजें सुनाई दे रही थीं।
वह 'जंगली उल्लास की रात' होने वाली थी। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे।
इंदिरा गांधी की हार का जश्न मनाने के लिए मिठाई वितरण। मंत्रिमंडल की बैठक।
इस बार सुनवाई उनके आवास पर हुई, जो 1, सफदरजंग रोड स्थित है।
छोटे कमरे जहाँ वह आगंतुकों से मिलती थी—और यह मुलाकात संक्षिप्त होती थी।
इंदिरा और उनके कई मंत्री सहयोगियों को पता था कि वे हार चुके हैं।
उसने अपने सहयोगियों को बताया कि वह अपना इस्तीफा भेज रही है, और

मंत्रिपरिषद की ओर से राष्ट्रपति को। मुख्य एजेंडा
बैठक में आपातकाल हटाने के संबंध में निर्णय लिया जाना था। अधिकांश
मंत्रिमंडल के मंत्रियों का मानना था कि इसे तत्काल रद्द कर देना चाहिए।
उन्हें डर था कि जनता सरकार इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकती है। 25 जून को
1975 में जब उन्होंने आपातकाल लागू किया था, तब उन्होंने जनता से परामर्श नहीं किया था।
मंत्रिमंडल को इसकी सूचना बाद में दी गई। इस बार, पराजित इंदिरा गांधी।
उन्होंने मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने का विकल्प चुना—इससे पहले कि वह निर्णय लेतीं आपातकाल रद्द करें।
बहुत जल्द ही, कैबिनेट सचिव बी. डी. पांडे और गृह सचिव एस.
एल. खुराना बगल वाले कमरे में चले गए। वे तैयारी करने के लिए बैठ गए।
कार्यवाहक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बी. डी. जट्टी के हस्ताक्षर के लिए अधिसूचना।
राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे।
उसी साल 11 फरवरी को फखरुद्दीन अली अहमद को यह नोट मिला। पांडे को यह नोट मिला।
21 मार्च को सुबह 1 बजे के बाद इंदिरा गांधी द्वारा अनुमोदित। इसके बाद वह तुरंत उपाध्यक्ष के पास पहुंचे।
राष्ट्रपति भवन, 6, मौलाना आजाद रोड। जब वह वहाँ पहुँचा तब तक रात के 2 बज चुके थे।
किया गया।
सफदरजंग रोड स्थित नंबर 1 पर, थकी-हारी इंदिरा गांधी ने अपने बेटे को फोन किया।
राजीव और बहू सोनिया। उसने उन्हें तुरंत चले जाने को कहा।
और कुछ दिनों के लिए दोस्तों के साथ रहने चली गई; उसे उनकी सुरक्षा का डर था।
उन्होंने अपने दो नींद में डूबे बच्चों, राहुल और प्रियंका को उठाया और चले गए।
उनका छोटा बेटा संजय और उसकी पत्नी मेनिका उस समय अमेठी में थे।
दिन बीत गया। वे देर रात दिल्ली लौटे। बी. डी. पांडे ने जब उन्हें लेने गए तो उन्होंने गलियारे में उन्हें इंदिरा गांधी से बात करते हुए सुना।

उन्होंने आपातकालीन कागजातों पर हस्ताक्षर किए। वे 'स्पष्ट रूप से परेशान' दिख रहे थे।
उसने हताशा से संजय से कहा, 'मैंने जो कर सकती थी, वह कर दिया। अब मैं...'
'हम शांति से जीना चाहते हैं,' संजय के करीबी सहयोगी कमल नाथ ने याद करते हुए कहा।
जो उसके साथ ही लौट आया था।
22 मार्च 1977 को सभी परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित हो गए। इंदिरा गांधी
उन्होंने अपना इस्तीफा बी.डी. जट्टी को सौंपने के लिए 6, मौलाना आजाद रोड तक गाड़ी चलाई।
वहाँ मौजूद संगम्मा (जट्टी की पत्नी) लगातार रोती रही।
बैठक। जट्टी ने इंदिरा के इस्तीफे का पत्र वाला लिफाफा ले लिया।
अनमने ढंग से। लेकिन उसने उसे खोला नहीं। यह तब हुआ जब इंदिरा उठीं।
यह बात उनके प्रधान सचिव पी. एन. धर ने फुसफुसाकर कही थी।
कार्यवाहक राष्ट्रपति ने कहा कि वह संवैधानिक रूप से क्या उचित है, यह भूल गए थे।
आवश्यक है—प्रधानमंत्री से वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कार्य जारी रखने का अनुरोध करना।
व्यवस्था कर दी गई थी। 'हाँ, हाँ, हाँ,' जट्टी ने कहा और जल्दी से कर दिया।
जो आवश्यक था।
इसके कुछ ही समय बाद इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण शुरू किया।
मेरे सहयोगी और मैं जनता के फैसले को बिना किसी शर्त के और पूर्णतः स्वीकार करते हैं।
उन्होंने देश से कहा, 'विनम्रता की भावना रखो।'
आपातकाल के विद्रोही संजय गांधी, जिन्होंने भी
अमेठी से संसदीय सीट हारने के बाद उन्हें खलनायक कहा जाने लगा था।
उसकी हार के पीछे का कारण। लोगों का कहना था कि बछड़े ने गाय को खा लिया था।
(गाय)। (उस समय कांग्रेस पार्टी का प्रतीक गाय और बछड़ा था।)
अखबारों की सुर्खियों में खबर छपी, 'संजय सक्रिय राजनीति छोड़ेंगे'

अगले दिन, असामान्य रूप से शांत संजय ने पत्रकारों से कहा कि
मुझे खेद है अगर मैंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जो किया उससे मुझे नुकसान पहुंचा हो।
वह मां जिसका जीवन निस्वार्थ सेवा में व्यतीत हुआ।
शुरू में इंदिरा गांधी अपनी हार से स्तब्ध रह गई थीं। लेकिन,
पहले की तरह, संकट के समय भी वह अडिग रही। लेकिन उसके बाद, उसे अवसाद हो गया।
कई दिनों तक, अकेली और अलग-थलग पड़ी, उसने लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। यह बहुत दर्दनाक था।
अचानक खलनायक के रूप में देखा जाना। वह जानती थी कि लोग लिख रहे थे।
उसे दूर भगाना; यही बात उसे सबसे ज्यादा दुख पहुँचा रही थी।
अपनी हार के बाद के दिनों में, चिंतित इंदिरा गांधी ने अपनी
बहुएं सोनिया और मनेका, और उनके पोते राहुल
और प्रियंका को पहाड़ों पर भेज दिया गया ताकि उन्हें किसी भी खतरे से बचाया जा सके। वे वहीं रहे।
अपनी एक दोस्त सुमन दुबे के घर पर। उसने अपने बड़े बेटे राजीव को भेज दिया।
मुंबई में यह देखने के लिए कि क्या परिवार को बाहर निकालने के लिए एक निजी विमान किराए पर लिया जा सकता है।
भारत। जब राजीव मुंबई में थे, तब दिल्ली स्थित खुफिया ब्यूरो के संयुक्त निदेशक वी.वी. नागरकर को उनके खुफिया ब्यूरो के सहयोगियों से सूचना मिली।
राजीव की मुंबई यात्रा के बारे में। मुंबई से होने के कारण, नागरकर को अच्छी जानकारी थी।
महानगर में खुफिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ। 'मैंने यह सुना है।'
'नागरकर से ही,' रवि नायर ने याद किया, जो उस समय वहां थे।
जॉर्ज फर्नांडीस के राजनीतिक सचिव। (आपातकाल के नायक,
फर्नांडीस जनता पार्टी में संचार मंत्री बने ही थे।
पार्टी सरकार—हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया।
उद्योग मंत्रालय।) नागरकर ने तुरंत यह जानकारी आगे पहुंचा दी।
to Prime Minister Morarji Desai. A worried Desai rang up

Jayaprakash
नारायण, एक समाजवादी से गांधीवादी बने व्यक्ति थे जिन्होंने इसके निर्माण में मदद की थी।
जनता पार्टी। वे दिल्ली में गांधी शांति फाउंडेशन में मिले, जहाँ
जेपी वहीं रुक रहे थे। दोनों नेताओं ने फैसला किया कि 'इस मामले को सुलझाना होगा'।
'देखभाल'। सरकार दुर्व्यवहार का आरोप लगने का जोखिम नहीं उठा सकती थी।
पराजित प्रधानमंत्री और उनका परिवार।
रवि नायर ने खुलासा किया, ‘जेपी और प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की।’ ‘उन्होंने
उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। और उन्हें इसकी आवश्यकता है।
उनकी शारीरिक सुरक्षा की चिंता न करें।
उन्होंने मोरारजी देसाई से कहा, 'मैं हिमालय में रिटायर होना चाहती हूं।'
केवल एक ही गारंटी है, और वह है संजय की सुरक्षा।
अफवाहें हैं कि राजीव और सोनिया अपने बच्चों राहुल और
प्रियंका भारत छोड़कर इटली जा सकती हैं।
नागरकर को यह भी पता चला था कि इंदिरा गांधी के कुछ ही घंटों के भीतर...
हार के बाद, दो ‘दस्तावेजों से भरे बक्से’ 1 से चुपके से ले जाए गए थे।
सफदरजंग रोड से होते हुए, छतरपुर स्थित उनके फार्महाउस तक ले जाया गया और वहीं उन्हें दफना दिया गया।
नागरकर ने इस विषय पर सरकार के लिए एक नोट तैयार किया। उन्होंने इसकी एक प्रति सरकार को दी।
इसे जॉर्ज फर्नांडीस को सौंप दिया गया, जिन्होंने रवि नायर को रेकी करने के लिए कहा। नायर और एक
आई.बी. के उप अधीक्षक (डी.एस.पी.) वहां पहुंचे।
फार्महाउस। 'मुझे याद है कि डीएसपी के साथ एक गैजेट भी आना था।
नायर ने कहा, 'जो हैदराबाद से आना था।' यह हैंडहेल्ड डिवाइस
यह जमीन के नीचे धातु का पता लगा सकता था। लेकिन डीएसपी इसके बिना आया

था।
फार्महाउस में कुछ नहीं मिला। लगभग एक महीने बाद, उपकरण
पहुँच गए। इस बार नायर एक अन्य अधिकारी के साथ इंदिरा गांधी के घर गए।
छतरपुर में फार्महाउस। एक बार फिर, प्रयास व्यर्थ गया।
माली ने हमें बताया कि संदूक (पेड़ों के तने) खोदकर निकाल लिए गए थे।
'इस बीच दूर रहो,' नायर ने कहा। ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा को इस बात का डर सताता था।
जनता सरकार संजय के साथ क्या कर सकती है, इस बारे में जनता नेताओं को गहरा संदेह था और उन्हें इस बात का भी डर था कि संजय नए शासन को पलटने के लिए क्या कदम उठा सकती है।
सरकार।
■

जनता सरकार के सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद, मंत्रिमंडल ने—उकसाया
गृह मंत्री चरण सिंह द्वारा कांग्रेस को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।
नौ राज्यों की सरकारों में। इसने फैसला किया कि इन राज्यों ने भी हार मान ली है।
राष्ट्रीय चुनाव में इंदिरा गांधी की हार के बाद उन्हें शासन करने का जनादेश मिला।
चुनाव। मंत्रिमंडल ने राज्य भंग करने की सिफारिश भेजी।
कार्यवाहक अध्यक्ष जत्ती से मुलाकात। जत्ती ने उसे रोकने का फैसला किया
एक बार नहीं बल्कि दो बार सहमति दी। उन्होंने सरकार को इसकी जानकारी दी—
29 अप्रैल 1977—कि उन्हें इस मामले पर विचार करने के लिए और समय चाहिए।
इससे सरकार में अफरा-तफरी मच गई। आखिरकार, जट्टी तो सिर्फ एक रस्म थी।
सिर। वह स्पष्ट रूप से जानबूझकर निर्णय में देरी कर रहा था। उसका इनकार
हस्ताक्षर करने से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता था, जिससे बाधा उत्पन्न हो सकती थी।
चुनी हुई सरकार के शासन करने का आदेश।
चिंतित प्रधानमंत्री देसाई ने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई।
30 अप्रैल 1977 को। मंत्रियों की घबराहट स्पष्ट थी; वे

उन्हें इस बात की चिंता थी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। वे जानते थे कि जट्टी इंदिरा गांधी का वफादार था और उसकी तरक्की इंदिरा गांधी की वजह से ही हुई थी। हालाँकि ऐसा कोई सबूत नहीं है।
मंत्री ने इसे स्पष्ट रूप से कहा, सवाल वहीं अनसुलझा रह गया, 'क्या ऐसा हो सकता है?'
सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में जट्टी ने सेना को बुलाया।
और नई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे?' ऐसी फुसफुसाहटें चल रही थीं।
चुनाव से कुछ दिन पहले सत्ता के गलियारों में यह बात सामने आई कि प्रमुख
सेना के अधिकारियों ने इंदिरा गांधी को एक प्रस्ताव दिया था कि वे 'लाएंगे'
चुनाव हारने की स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए नई दिल्ली में सेना भेजी गई।
विपक्ष ने उसके घर के खिलाफ मार्च निकालने का फैसला किया। भीड़
उसने कथित तौर पर कहा था कि हालात बेकाबू हो सकते हैं और वे उसके घर पर हमला कर सकते हैं।
बताया था।
इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था, 'मेरी चिंता मत करो। मैं बस इतना पूछती हूँ कि...'
बात यह है कि आप मेरे बच्चों की देखभाल करें।
आर. एन. काओ, आरएंडएडब्ल्यू के प्रमुख, जो देश की बाहरी गतिविधियों की देखरेख करते हैं।
खुफिया विभाग ने भी उसे इसी तरह का प्रस्ताव दिया था। 'मेरे पास कई सशस्त्र लोग हैं।'
मेरे अधीन अर्धसैनिक बल हैं और मैं उन्हें दिल्ली लाना चाहता हूं।
हिंसा होने की आशंका में।

लेकिन 30 अप्रैल 1977 को रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया।
उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को आशंका थी। उन्होंने कहा कि सेना द्वारा उठाया गया कोई भी कदम
संभावना कम है। हालांकि, उन्होंने यह खुलासा किया कि आपातकाल के दौरान, रक्षा मंत्री बंसी लाल ने सेना प्रमुख से मुलाकात की थी और उनसे इस बात का समर्थन

करने का अनुरोध किया था।
आपातकाल। लेकिन सेना प्रमुख, जनरल तपेश्वर नारायण
राम ने बताया कि रैना ने मना कर दिया था। जनरल रैना एक पेशेवर अधिकारी थे।
उनके सहकर्मी। और सेना एक ऐसी ताकत थी जिसकी व्यावसायिकता
इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। राम के आश्वस्त करने वाले शब्दों के बावजूद, कई
उस दिन मंत्रियों को एक अजीब सा डर महसूस हुआ।
उस रात देर से, जॉर्ज फर्नांडीस को खुफिया विभाग से फोन आया।
अधिकारी फिर से स्थानांतरित हो गया. फर्नांडिस की तरह नागरकर भी समाजवादी थे
पृष्ठभूमि और आपातकाल का विरोध किया था। 'कुछ तो गड़बड़ है।'
'पैदल चल रहा है,' उन्होंने फर्नांडेस को चेतावनी दी। आईबी में उनके सहयोगी थे
वह कांग्रेस नेताओं के फोन कॉल की निगरानी कर रहा था। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है।
योजना बनाई जा रही थी, लेकिन उसने जॉर्ज से 'सावधान रहने' को कहा। उसने ऐसा कहा नहीं।
लेकिन यह इशारा तख्तापलट की संभावना की ओर था। जैसा कि फर्नांडीस ने कहा।
रिसीवर नीचे रखते ही फोन फिर बज उठा। यह उनके समाजवादी सहकर्मी का फोन था।
मधु लिमाये लाइन पर हैं। उन्हें भी सतर्क कर दिया गया था।
नागरकर और लिमाये के फोन आने के बाद, जॉर्ज फर्नांडीस ने भेजा
रवि नायर नई दिल्ली के उच्च सुरक्षा वाले इलाकों का चक्कर लगाएंगे।
दिल्ली। फर्नांडीस की आधिकारिक गाड़ी दिन भर के लिए रवाना हो चुकी थी। इसलिए, नायर ने अपनी गाड़ी से काम किया।
उधार के दोपहिया वाहन पर चक्कर लगाते हुए। वह लुटियंस के दिल्ली में घूम रहा था।
उस रात, उसके दिमाग में कप्प पुत्श का वह सिलसिला चल रहा था जिसके बारे में उसने पढ़ा था,
जर्मनी में राष्ट्रीय सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तख्तापलट का प्रयास किया गया।
1920, जिसने नवजात वीमर गणराज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, और

इसके स्थान पर निरंकुश सरकार स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन नायर को कोई समाधान नहीं मिला।
सेना मुख्यालय या सेंट्रल टेलीग्राफ के आसपास असामान्य गतिविधि
कार्यालय या ऑल इंडिया रेडियो या संसद भवन। वह वापस आया और
फर्नांडेस को 'सब ठीक है' की सूचना दी गई।
अगले दिन, 1 मई 1977 को, जॉर्ज ने हममें से 200-300 समाजवादी लोगों का नेतृत्व किया।
रवि नायर ने याद करते हुए बताया, 'युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया। हम राष्ट्रपति भवन तक मार्च करते हुए गए।'
भवन में जाकर जट्टी के इस्तीफे की मांग की। पर्दे के पीछे,
जनता सरकार ने जट्टी को कड़ी चेतावनी दी। उसने कुख्यात 42वें संशोधन को लागू कर दिया।
आपातकाल के दौरान पारित संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत
इसमें यह शर्त रखी गई थी कि राष्ट्रपति को परिषद की सलाह का पालन करना होगा।
मंत्रियों के बीच। अंततः, जट्टी मान गया। उसी रात, उसने हस्ताक्षर कर दिए।
नौ राज्य विधानसभाओं को बर्खास्त करने का आदेश। देसाई सरकार ने 11 जून 1977 को इन राज्यों में नए चुनावों की घोषणा की। जनता
पार्टी इनमें से सात राज्यों - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश - में सत्ता में आई।
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार और उड़ीसा। दो गैर-
पश्चिमी राज्यों में कांग्रेस, सीपीआई (एम) और अकाली दल विजयी रहे।
बंगाल और पंजाब। कांग्रेस को हर जगह करारी हार का सामना करना पड़ा।
■

इंदिरा गांधी और उस अड़ियल नेता के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था।
मोरारजी देसाई, जो 1967 में उनके अधीन उप प्रधानमंत्री थे।
वर्षों से चली आ रही उनकी तमाम प्रतिद्वंदिताओं के बावजूद, देसाई उस पर मुकदमा चलाने के लिए अनिच्छुक थे।
आपातकाल और उसकी ज्यादतियों के लिए। लेकिन वह भारी दबाव में था।

गृह मंत्री चरण सिंह के दबाव के कारण, जॉर्ज
फर्नांडिस और अन्य मंत्रिस्तरीय सहयोगियों।
चरण सिंह ने उसके खिलाफ नूर्नबर्ग तर्ज पर मुकदमे की मांग की।
जनता पार्टी के नेता माफ करने या भूलने के मूड में नहीं थे। प्रधानमंत्री
मंत्री ने इंदिरा गांधी से वादा किया था कि उनका परिवार सुरक्षित रहेगा।
उन्होंने तर्क दिया कि शारीरिक रूप से सुरक्षित, न कि संजय गांधी को बरी कर दिया जाएगा।
आपातकाल के दौरान किए गए उनके अपराधों का आधार।
अप्रैल 1977 तक, जनता सरकार ने आठ स्थापित करने का निर्णय लिया।
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में जांच आयोगों का गठन किया गया ताकि जांच की जा सके।
इंदिरा गांधी, संजय गांधी और वरिष्ठ अधिकारियों के कथित कुकर्म
Congress leaders like Bansi Lal, V. C. Shukla, and Pranab Mukherjee.
न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना को संसाधनों के दुरुपयोग की जांच करनी थी और
संजय द्वारा मारुति कंपनी में स्थापित सरकारी एजेंसियों में उनकी हिस्सेदारी थी।
एक जनमानस कार का उत्पादन करने के लिए। एक अन्य आयोग को इस बात की जांच करनी थी कि जेपी ने कैसे
आपातकाल के दौरान जेल में उनका इलाज किया गया था, जिसके कारण यह हुआ।
उनकी किडनी खराब हो गई। सरकार ने इसकी जांच करने का भी फैसला किया।
समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का 1967 में निधन! (पिछले कुछ वर्षों में,
इससे समाजवादियों में चिंता पैदा हो गई थी, जिन्हें किसी साजिश का संदेह था। लेकिन माँ
सभी जांचों की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जे.सी. ने की थी।
शाह। उन्हें 'अति, कुप्रथाओं और दुर्व्यवहार' की जांच करने का काम सौंपा गया था।
आपातकाल के दौरान, यहाँ तक कि 'सर्वोच्च राजनीतिक प्राधिकरण' द्वारा भी, 'सर्वोच्च राजनीतिक'
'अधिकार'। इंदिरा ने आयोग को केवल एक सत्ता बताया।
‘राजनीतिक प्रतिशोध’ के आरोप में, दो बार पूछे जाने पर भी वह उसके समक्ष पेश

नहीं हुआ।
अंततः, जब उन्होंने जनवरी 1978 में ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि यह सामूहिक प्रयास था।
उन्होंने इसे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी बताया और इसके बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया।
अतिरेक।
■

जून 1977 में, चिंतित इंदिरा गांधी ने कपिल मोहन को अपने साथ ले जाने का फैसला किया।
उसके प्रस्ताव पर। उसने संजय को सोलन भेजने का फैसला किया ताकि उसे इस मामले से दूर रखा जा सके।
सार्वजनिक निगाहों के सामने। वह वहां गुप्त रूप से गया और मोहन मीकिन में ठहरा।
कंपनी के गेस्ट हाउस में अनिल बाली उनके साथ गए थे। बाली एक कंपनी के गेस्ट हाउस में रह रहे थे।
अपने चाचा वी. आर. मोहन के समय से ही वे इंदिरा गांधी के कट्टर वफादार रहे हैं।
कपिल मोहन के बड़े भाई और मोहन मीकिन के प्रमुख, जब तक कि वह
उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने 1969 में उन्हें प्रधानमंत्री से मिलवाया था। उन्होंने बताया था कि
घबराई हुई इक्कीस वर्षीय बाली को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि 'जानकारी ही सब कुछ है'
शक्ति'।
इसके बाद, उन्हें इंदिरा गांधी के बारे में जानकारी मिलती थी।
विरोधियों ने जो किया, वह सही था।
सोलन गेस्ट हाउस के केयरटेकर, किनू राम ने देखभाल की।
संजय अपने साथ दिल्ली से एक निजी सहायक भी लेकर आए थे।
इकत्तीस वर्षीय संजय को शाकाहारी भोजन पसंद था। सोलन में उनका आहार
इसमें मशरूम, सब्जियां, फल और दूध शामिल थे। उसे ये नहीं दिया गया था।

कार्बोनेटेड पेय पीने के मामले में, संजय पहले जैसा नहीं रहा था। यह संजय का बिल्कुल अलग रूप था।
एक किशोर जो अपने उग्र और मनमौजी स्वभाव के लिए जाना जाता था।
कभी-कभी वह पढ़ता था। या फिर बैठे-बैठे पुराने पियानो को बजाने की कोशिश करता था।
गेस्ट हाउस की पहली मंजिल पर स्थित कमरा।
अनिल बाली ने उनसे पूछा था, 'क्या आपको पियानो बजाना आता है?'
पहले दिन बातचीत शुरू करते हुए संजय ने सिर्फ एक शब्द कहा, 'नहीं'।
संजय ज्यादा बात नहीं करता था। उसके जवाब या तो सीधे-सीधे होते थे।
एक-शब्दीय या, ज़्यादा से ज़्यादा, एक-लाइनर के जवाब। वे अभी-अभी मेहमान के घर पहुँचे थे।
घर। हरे और सफेद रंग की कुटिया के अंदर के कमरे—जिनके पास
कालका से शिमला जाने वाली पहाड़ी ट्रेन गुजरी—मैंने उस पर कई तस्वीरें खींचीं।
दीवारें—उनमें से एक दुर्जेय दिखने वाले परिवार के मुखिया की थी।
नरेंद्र मोहन दीवार पर टंगी बाघ की खाल को देख रहे हैं।
बगल वाले कमरे में 1820 के दशक की एक बिलियर्ड्स टेबल थी जो बनी हुई थी प्रसिद्ध बर्मा सागौन।
सोलन अपने स्वास्थ्यवर्धक वातावरण के लिए जाना जाता था। कभी-कभी,
संजय टहलने के लिए बाहर निकलता था। लेकिन इससे बाली घबरा जाता था। 'मैं
मैंने उसे एक बंदर टोपी पहना दी, ताकि लोग उसे पहचान न सकें।
अंततः संजय गांधी अपने बंदी जीवन से अधीर हो गए।
सोलन पहुंचने के सोलह दिन बाद, उन्होंने दिल्ली लौटने का फैसला किया।
वह अपनी कार में वापस लौट गया, जबकि बाली दूसरे वाहन में उसके पीछे-पीछे आ रहा था।
कालका में संजय की कार खराब हो गई। वह यह देखने के लिए बाहर निकला कि क्या हुआ है।
हालात बिगड़ गए। लोग गाड़ी के चारों ओर जमा हो गए और वह
तुरंत पहचान लिया गया। भीड़ आक्रामक हो गई। 'लॉग मारने के
लोग उसे पीटने के लिए तैयार थे। इससे पता चलता है कि

बाली ने कहा, 'उस समय उनके प्रति शत्रुता की सीमा कितनी थी?'
मुझे उसे जल्दी से अपनी कार में बिठाना पड़ा और तेजी से वहां से निकलना पड़ा।
सोलन में अपने प्रवास के दौरान, एकांतप्रिय संजय चुपचाप
युद्ध की तैयारी में। वह अपनी माँ का सबसे करीबी राजनीतिक सलाहकार था।
आपातकाल के वर्षों के दौरान उसकी विश्वासपात्र। अब उसने उसकी योजना बनाना शुरू कर दिया।
वापस आओ।
अगर जनता पार्टी ने संजय को अकेला छोड़ दिया होता, तो इंदिरा गांधी शायद...
'राजनीतिक रूप से सब कुछ खत्म हो चुका है,' कमल नाथ ने कहा, जो संजय के करीबी थे और
इंदिरा गांधी ने वर्षों बाद यह बात कही।
लेकिन जनता पार्टी के लोगों ने संजय गांधी के पीछे पड़ने का फैसला किया। और इंदिरा गांधी
उसने पलटवार करने का निश्चय कर लिया। तभी उसके मिजाज में अचानक बदलाव आया।
एक बड़ा बदलाव। उनकी पहली इच्छा तो सेवानिवृत्त होने की थी। अब उन्होंने फैसला किया कि...
जवाबी हमला करना।
उन्होंने सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक गुरु श्री मां आनंदमयी से मुलाकात की।
हरिद्वार में जाकर वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करेंगी। राज्य चुनावों के मद्देनजर
जून 1977 के लिए घोषित होने पर, उन्होंने खुद को चुनाव अभियान में झोंक दिया।
पार्टी के सहयोगी उनकी ऊर्जा देखकर अचंभित रह गए।
कार या हवाई जहाज में थोड़ी देर झपकी लें और एकदम तरोताजा दिखें।
लड़ाई का अगला दौर।
‘अपने चेहरे से रोने वाला भाव हटाओ,’ उसने एक युवक को फटकार लगाई।
अंबिका सोनी, जिन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था
संजय द्वारा लिखित 'द इमरजेंसी'। 'तुम्हें अपने बत्तीस दांत दिखाने होंगे और'
हर समय खुश दिखो। आपको सहनशील बनना होगा, पुरानी बातों को भूल जाना

होगा।
और आगे बढ़ो।'
'या फिर,' उसने बड़ी गंभीरता से कहा, 'आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए।'
24 जुलाई 1977 को उन्होंने सर्वोदय नेता विनोबा भावे के लिए उड़ान भरी
महाराष्ट्र के पौनार स्थित आश्रम में तीन दिवसीय यात्रा के दौरान,
stay there, she had seven sittings with Vinoba Bhave the 'sarkari sant'
आपातकाल के समर्थन के बाद मीडिया ने उन्हें यही नाम दिया था। उन्होंने आपातकाल को 'अनुशासन पर्व' कहा था।
जिसने उसके इस कृत्य को वैधता प्रदान की थी।
जब इंदिरा गांधी पौनार से रवाना हुईं, तो भावे ने पत्रकारों से कहा कि वे
उन्होंने राजनीति पर कोई बात नहीं की। इंदिरा ने अपने एक कार्यक्रम में कहा, 'मैं कभी बातचीत के लिए नहीं आई।'
भाग, 'मैं बस उनसे (विनोबाजी से) मिलने आया था।'
जुलाई 1977 में अनिल बाली के साथ अपनी एक मुलाकात में उन्होंने उनसे कहा, और
यह बात लगभग एक आदेश के रूप में कही गई थी, 'मोरारजी देसाई, चरण सिंह,
और जगजीवन राम बड़े अहंकारी हैं, उनके अहंकार का फायदा उठाओ।' उसने निर्देश दिया।
कपिल मोहन जनता पार्टी के शीर्ष तीन नेताओं के बीच मतभेदों को और बढ़ाएंगे।
नेताओं; उन सभी के साथ उनके व्यापक संबंध थे। इंदिरा जानती थी कि वह
उन्हें तीनों पक्षों की असुरक्षाओं का फायदा उठाना पड़ा और उनकी स्थिति को और बिगाड़ना पड़ा।
मतभेद थे। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जल्द ही वे
खुलेआम झगड़ा करना। वह यह दिखाना चाहती थी कि उसके विपरीत,
जनता सरकार देश पर शासन करने में असमर्थ थी। उसका मानना था कि
उसकी पुरानी ऊर्जा वापस लौट रही थी।
■

1977 में उन्होंने जो सबसे बड़ा फैसला लिया, वह था उसी व्यक्ति से संपर्क करना।
उसके पतन के लिए जिम्मेदार—विद्रोही समाजवादी नेता, राज
नारायण। उन्होंने 1971 में रायबरेली से उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था।
संसदीय चुनाव। उसने उसे हरा दिया। उसने उसकी जीत को चुनौती दी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ चुनावी कदाचार के आरोप में मुकदमा दायर किया गया है।
जून 1975 में, अदालत ने चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया, जिससे एक नई प्रक्रिया शुरू हुई।
घटनाओं की वह श्रृंखला जो 25 जून 1975 को आपातकाल की स्थिति में परिणत हुई।
1977 के चुनावों में, नारायण ने रायबरेली में उन्हें हराया और उन्हें एक सफल नेता के रूप में सराहा गया।
विशाल हत्यारा।
शुरू में इंदिरा गांधी उनसे बातचीत करने में बहुत अनिच्छुक थीं।
संजय ही वह व्यक्ति था जिसने उसे अपनी झिझक दूर करने के लिए राजी किया।
श्रीमती गांधी के सत्ता से बाहर होने के बाद उनमें परिपक्वता आई थी,' उन्होंने टिप्पणी की।
जगमोहन मल्होत्रा एक निजी बातचीत में। एक शक्तिशाली नौकरशाह।
अपने पहले नाम से लोकप्रिय—वे संजय के समूह के सदस्य थे।
यह गुट, जो कई विवादास्पद कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार था
आपातकाल।
कपिल मोहन ने इंदिरा गांधी और राज के बीच सेतु का काम किया।
नारायण। खुफिया ब्यूरो के दो लोगों ने भी इसमें भूमिका निभाई।
राज नारायण और संजय गांधी के बीच बैठकों को सुविधाजनक बनाने में मुंबई के कुछ उद्योगपतियों ने भी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद के महीनों में,
नारायण को उसका एकमात्र विध्वंस दस्ता बनना था, जिसके परिणामस्वरूप यह हुआ:
जनता पार्टी का आंतरिक पतन।

इस मामले में, इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए अन्य कदमों की तरह, संजय ही मुख्य भूमिका में थे।
मुख्य वास्तुकार। उसने अपनी माँ को मना लिया था कि उन्हें यह कदम उठाना चाहिए।
शत्रु के क्षेत्र में घुसकर युद्ध करना और विरोधियों की सेनाओं को विभाजित करना।
पहले वह उसे धैर्य और शिष्टाचार का पालन करने की सलाह देती थी। उसका मानना था कि
अधीरता या रूखेपन की तुलना में इनसे बेहतर परिणाम प्राप्त हुए। लेकिन,
1977 के मध्य में, संजय ने ही इंदिरा को यह विश्वास दिलाया था कि उन्हें झुकना चाहिए।
जीतना।
शायद जगजीवन राम, अगर वे प्रधानमंत्री बन जाते तो...
मोरारजी देसाई संजय गांधी के बराबर के उम्मीदवार हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं था।
इतिहास के उन अनसुलझे सवालों में से एक बनकर रह जाना। इंदिरा गांधी यह जानती थीं।
दलित होने और एक चतुर प्रशासक होने के नाते, राम उसे रोक सकता था।
अगर वह जनता समूह में एक वैकल्पिक ध्रुव के रूप में उभरता है तो उसकी वापसी संभव है।
—एक ऐसी संभावना जिसे नकारा नहीं जा सकता था। वह यह नहीं भूल सकती थी कि उसका
2 फरवरी 1977 को एच. एन. बहुगुणा के साथ कांग्रेस से बाहर निकल गए।
नंदिनी सतपथी और उन्होंने देश में जोश भर दिया था और इस प्रक्रिया को गति प्रदान की थी।
जनता पार्टी के पक्ष में स्थिति।
जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी (सीएफडी) का गठन किया था, बाद में
जनता पार्टी में विलय करने के लिए। उन्हें प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद थी।
जनता सरकार के मुखिया मंत्री, लेकिन प्रतिष्ठित
यह पद मोरारजी देसाई को मिला। लेकिन वे सही मौके का इंतजार करते रहे।
शीर्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करने का यही सही समय था। वह जानती थी

कि उसे ऐसा करना होगा।
उसके खतरे को कम करो। और हमला करने के अनुकूल समय की प्रतीक्षा करो।
वह यह भी जानती थी कि उसे जयप्रकाश नारायण को मनाना होगा।
जिसने दो साल पहले ही उसे 'तानाशाह' कहा था। यही वह आदमी था।
उसे 25 जून 1975 को सत्ता पलटने की कोशिश करने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था।
उनकी सरकार। उन्होंने बिहार में युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया था।
1974 में भ्रष्टाचार और बढ़ती कीमतों ने स्थिति को इतना गंभीर बना दिया था कि पुलिस बल को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
जिसकी वजह से अंततः उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा।
1977 के मध्य तक, जेपी की तबीयत खराब हो गई थी। थकावट और कमजोरी के कारण, अब उन्हें डायलिसिस पर रखा गया था।
जीवन भर के लिए। लेकिन वह नैतिक अधिकार का प्रयोग करता रहा। वह जानती थी कि वह
जनता सरकार से पहले से ही निराश, जिसके वे जनक थे;
यह एक ऐसी चीज थी जिसका वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती थी।
वह यह भी जानती थी कि उसे अपनी राजनीति को हिंदू रंग देना होगा। वह इस बात से अवगत थी कि
1977 के चुनावों में मुसलमानों ने उनका साथ छोड़ दिया था। संजय के जबरन नसबंदी कार्यक्रम ने समुदाय को नाराज कर दिया था।
मुस्लिम समुदाय के नुकसान की भरपाई के लिए एक वैकल्पिक आधार तैयार करना होगा।
support. The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) had made overtures
आपातकाल के दौरान हर समय उनके साथ। आरएसएस प्रमुख बालासाहेब देवरस ने
मैंने उन्हें कई बार पत्र लिखा। कुछ आरएसएस नेताओं ने भी उनसे संपर्क किया था।
संजय कपिल मोहन के माध्यम से। अब, 1977 में, उसे देखना होगा कि कैसे
जवाब देने के लिए। लेकिन उसे इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी होगी।
उसने राजनीतिक शतरंज की बिसात पर अपने मोहरे सावधानीपूर्वक बिछाए—अब

वह अपने विरोधियों द्वारा दिए गए अवसरों का इंतजार करती थी ताकि वह उनका फायदा उठा सके।
कब्जा कर लो। वह उन्हें दिखाएगी कि इंदिरा गांधी क्या करने में सक्षम थीं।

तृतीय

इससे पहले कि मैं इस बात पर चर्चा करूं कि इंदिरा गांधी ने 1977 में चुनाव कराने का निर्णय क्यों लिया,
जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और उन्होंने वापसी के लिए किस तरह की रणनीति बनाई।
महज तैंतीस महीनों में सत्ता में आने के बाद, पीछे मुड़कर देखना मददगार होगा।
यह समझना मुश्किल है कि उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को किस बात ने आकार दिया। पाँच पुरुष थे।
जिनके अनुसार इंदिरा गांधी के जीवन और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा।
इतिहासकार रामचंद्र गुहा: उनके पिता और भारत के पहले प्रधानमंत्री
मंत्री जवाहरलाल नेहरू; उनके पति फिरोज गांधी; और उनकी
प्रधान सचिव सह राजनीतिक सलाहकार पी. एन. हक्सर ने उनका मार्गदर्शन किया।
1967-73 के बीच का समय, जिसे राजनीति में उनके सर्वश्रेष्ठ वर्ष माना जाता है।
फिर आया...
जयप्रकाश नारायण ने उनके शासन का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें सत्ता थोपनी पड़ी।
आपातकाल। लेकिन सबसे ज्यादा दबदबा उनके बेटे संजय के हाथ में था।
उस पर उसका पूरा नियंत्रण था। वह उसका 'कमजोर पहलू' था, और उस पर उसका 'बहुत कम नियंत्रण' था।
उससे ऊपर'।
ये वे पुरुष थे जिन्होंने अलग-अलग समय पर वैचारिक रूप से उन पर प्रभाव डाला।
उसके जीवन में। एक लड़की के रूप में, और बाद में 1930 के दशक में इंग्लैंड में एक छात्रा के रूप में,
अपने पिता और पति के प्रभाव में, उसकी संवेदनशीलता
स्पष्ट रूप से उदारवादी और वामपंथी झुकाव वाली। 1950 के दशक के अंत में, उन्होंने अपना झुकाव बदला।

संयुक्त राष्ट्र जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के प्रभाव में दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर अग्रसर।
नेहरू की समाजवादी नीतियों से नाखुश ढेबर और जी.बी. पंत,
वह साम्यवादी समर्थक नीतियों का समर्थन करता था और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने का जरिया मानता था।
1960 के दशक के उत्तरार्ध और 1970 के दशक के आरंभ में, उन्होंने पी. एन. के साथ एक बार फिर वामपंथी रुख अपनाया।
हकसर और उनके मार्क्सवादी सहयोगियों ने उनकी सरकार का मार्गदर्शन किया।
1973-74 के बाद से, उनका दक्षिणपंथी झुकाव फिर से स्पष्ट हो गया जब उग्र रूप से
साम्यवाद-विरोधी संजय ने मामलों में एक प्रमुख भूमिका निभाना शुरू कर दिया।
कांग्रेस पार्टी और सरकार। 1980 के दशक की शुरुआत में, वह थीं
हालांकि उन्होंने समाजवादी बयानबाजी जारी रखी, फिर भी वे विकास के राज्य-नियंत्रित मार्ग से हटकर 1 मार्च को लोकसभा में यह बात कही।
1982: 'विनियम, जिनका एकमात्र गुण उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना है, वे ऐसा करते हैं'
इससे हम और अधिक समाजवादी नहीं बनेंगे।
जैसे-जैसे इंदिरा गांधी का राजनीतिक व्यक्तित्व विकसित होता गया, उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि
अपने पिता के विपरीत, वह वास्तविक राजनीति की माहिर थी। वह वास्तव में
उसके कार्यों को निर्देशित करने के लिए एक वैचारिक दिशा-निर्देशक होना चाहिए। उसने स्वीकार किया था
1963 में, एक स्पष्टवादिता के क्षण में, 'मेरे पास वास्तव में कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है।'
मैं यह नहीं कह सकती कि मैं किसी भी विचारधारा में विश्वास करती हूँ।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं यह नहीं कहूँगी कि मैं किसी विचारधारा में विश्वास करती हूँ।'
मुझे समाजवाद में सिर्फ समाजवाद के रूप में दिलचस्पी है। मेरे लिए, यह सिर्फ एक साधन है।'
लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि 'धार्मिकता और राष्ट्रवाद'

उनके प्रधानमंत्रित्व काल के 'मार्गदर्शक सिद्धांत' बन गए। जब उनसे पूछा गया
वॉशिंगटन पोस्ट की संवाददाता ने बताया कि किस चीज़ ने उन्हें इन मुश्किलों से उबरने में मदद की।
उन्होंने कहा कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पड़े दबावों के बारे में उनका यही मानना था।
'हिंदू दर्शन और भारत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता' में। हालाँकि एक 'डी-
एक विचारधारा से प्रेरित नेता के रूप में, महत्वपूर्ण क्षणों में, उसे उन गुणों का प्रदर्शन करना था।
एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार, अचूक समयबोध और अपार क्षमता के साथ
साहस, जोखिम उठाने की क्षमता—और सबसे बढ़कर, एक समझ
सत्ता की राजनीति का, जिसका उसने लाभ उठाया। बार-बार उसने
उनका उद्देश्य अपने से कहीं अधिक अनुभवी और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों को मात देना था।
वह पहले से कहीं अधिक थी।
■

जैसा कि अपेक्षित था, यह उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ही थे, जिन्होंने
वह पहला व्यक्ति था जिसने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसे उससे उम्मीद थी।
हमेशा मजबूत रहना। शुरुआत में नेहरू ने ही उन्हें मुश्किलों से निपटना सिखाया था।
एक संकट में। अप्रैल 1931 में, जब नेहरू, उनकी पत्नी कमला और चौदह अन्य बच्चे संकट में थे।
12 वर्षीय इंदिरा श्रीलंका के सीलोन (सीलोन) की यात्रा पर थीं, तभी एक घटना घटी।
एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे बहुत प्रभावित किया। एक खड़ी पहाड़ी पर सवारी करते समय।
पहाड़ी ढलान पर, उनकी कार फिसलकर एक खाई के किनारे पर जा गिरी। इंदिरा
उसने अपने पिता और

माँ अंदर थी। लेकिन ड्राइवर की फुर्तीली प्रतिक्रियाओं के कारण, बाकी सब कुछ संभव नहीं था।
कार में सवार लोग नीचे गिरकर मर जाते। नेहरू
उसे बताया कि उसने जो किया वह गलत था। 'गहराई से शर्मिंदा होकर, इंदिरा ने कभी नहीं
खतरे का सामना करने पर वह फिर से घबरा गई। बाद में जीवन में, उसके पिता की सलाह ने उसे सहारा दिया।
इससे उसे संकट की स्थिति में जिम्मेदारी संभालने में मदद मिलेगी। इन्हीं परिस्थितियों में वह
उसने विपरीत परिस्थितियों का सामना करना सीख लिया।
उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था और उनका पालन-पोषण यहीं हुआ था।
विशाल आनंद भवन, वह हवेली जो नेहरू परिवार का निवास स्थान थी,
इंदिरा का पूरा बचपन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था।
आनंद भवन महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रेरित था।
जब उसके पिता को पहली बार जेल भेजा गया था तब वह सिर्फ दो साल की थी। जब राजकुमार ने
वेल्स ने 1921 में भारत दौरे के दौरान इलाहाबाद का दौरा किया था, और इंदिरा गांधी के समय
उनके दादा, मोतीलाल नेहरू ने विरोध में हड़ताल का आयोजन किया, जिसके लिए उन्होंने
जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो तीन साल की इंदिरा उसकी गोद में बैठी रही क्योंकि उसने मना कर दिया था।
अदालत में अपना बचाव करना।
1929 में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला।
उन्होंने कांग्रेस पार्टी अपने पिता मोतीलाल से प्राप्त की थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा,
नेहरू पूर्ण स्वराज को पार्टी का लक्ष्य घोषित करने वाले थे। उन्होंने इसके लिए घंटों मेहनत की।

प्रस्ताव का मसौदा तैयार करते हुए, उन्होंने अपनी बारह वर्षीय बेटी को फोन किया। वह कमरे में आया और उससे इसे पढ़कर सुनाने को कहा। वह सुनना चाहता था कि यह कैसा है।
आवाज आएगी।
जैसे-जैसे वह इसे पढ़ती गई, उसने हर शब्द पर ज़ोर दिया: 'हमारा मानना है कि यह है अन्य किसी भी जनसमूह की तरह, भारतीय जनसमूह का भी यह अविभाज्य अधिकार है कि उसे
स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपनी मेहनत का फल भोगने तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने का अधिकार।
जीवन, ताकि उन्हें विकास के पूर्ण अवसर मिल सकें।'
उन्होंने आगे कहा, ‘भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल
इसने भारतीय जनता को उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया है, लेकिन इसने स्वयं को इस पर आधारित किया है।
जनता का शोषण किया है और भारत को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया है।
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से।
यहाँ वह रुकी। फिर सोच-समझकर आगे बोली, 'हम'
इसलिए मेरा मानना है कि भारत को अंग्रेजों से संबंध तोड़ लेना चाहिए और
पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना।
प्रस्ताव पढ़कर इंदिरा गांधी पहली महिला बनीं
भारतीय भारत की स्वतंत्रता की शपथ लेंगे।
हालांकि इंदिरा कई स्कूलों में पढ़ीं और उनके कई शिक्षक भी थे,
नेहरू ही उनके असली गुरु बने रहे। उन्होंने उन्हें ढेरों पत्र लिखे।
उन्होंने अपने जीवन के कई वर्षों के दौरान अपनी बेटी से हर तरह के विषयों पर बात की।
जेल में। अगर उनका जीवन स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित न हुआ होता, तो वे
वह एक शानदार शिक्षक बन सकता था। उसने अपने अंदर के अपराधबोध को कम करने की कोशिश की।
उसे इस बात का बहुत दुख था कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ देकर उसके साथ समय नहीं बिता सका।

दिमाग।
इंदिरा के पिता ने उनके दिमाग का विस्तार किया और उन्हें धैर्य सिखाया।
नेतृत्व; उनकी मां, कमला, जिनके साथ इंदिरा ने अपना एकाकी बचपन का अधिकांश समय बिताया, ने उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं को आकार दिया—जैसे कि उनका विश्वास।
बंगाली आध्यात्मिक गुरु मां आनंदमयी से प्रेरणा मिली।
अपनी अक्सर बीमार रहने वाली माँ की देखभाल करते-करते, इंदिरा को कई बातों का एहसास होने लगा।
नेहरू परिवार में उनकी मां को जिन अपमानों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से उनकी मौसियों, नेहरू की बहनों, विजया लक्ष्मी पंडित और कृष्णा से।
नेहरू हुथीसिंग।
स्वतंत्रता, संकट में प्रतिक्रिया करने की क्षमता और उसे अपने पास रखने की क्षमता
अपनी भावनाओं को दबाकर रखने के कारण वह अंतर्मुखी और यहाँ तक कि अलग-थलग रहने लगी।
इंदिरा ने बताया कि वह उम्र में बड़ी थी, और उसने किस तरह एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाया।
वह एक ऐसी जगह में पीछे हट सकती थी, जिससे उसे खुद को मजबूत करने में मदद मिलती।
ऊर्जा और सहनशक्ति। 'मेरा बचपन बेहद असुरक्षित था,' इंदिरा ने कहा।
बाद में कहना था, 'क्योंकि हमें दिन-प्रतिदिन यह नहीं पता होता था कि कौन क्या करेगा।'
'कौन जीवित होगा, घर में कौन होगा और आगे क्या होगा?'
उनके बचपन के सबसे महान शिक्षकों में से एक स्वतंत्रता थी।
वह जिस आंदोलन से गुज़री, उसी में उसने अपना जीवन व्यतीत किया। 'मैं जुलूसों का हिस्सा थी और
बैठकें और जो कुछ भी हुआ।' 1930 का दांडी नमक मार्च,
जिसके दौरान महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक उठाया।
अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर के विरोध ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी।
देश भर में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया।

संख्याएँ। नेहरू परिवार की महिलाओं ने भी ऐसा ही किया। एक ही झटके में,
गांधी ने महिलाओं को मुक्ति दिलाई और महिलाओं को प्रधानता प्रदान करना संभव बनाया।
छत्तीस साल बाद मंत्री।
कमला नेहरू ने जिस तरह से खुद को समर्पित किया, उससे उनका परिवार दंग रह गया।
संघर्ष में उतरते हुए। उन्होंने प्रभावशाली भाषण देना शुरू किया, और वह
अपने पति की परछाई से कहीं अधिक। एक दिन, एक युवक, झुकते हुए...
लखनऊ में अपने कॉलेज की दीवार के सहारे खड़े होकर, उन्होंने कमला को भाषण देते हुए देखा।
बोलने में दिक्कत हो रही थी। वह बेहोश हो गई। वह उसकी मदद के लिए दौड़ा।
इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई छोड़ दी और
वह उस महिला के प्रति समर्पित हो गए। उनका नाम फिरोज गांधी था।
फिरोज भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य के प्रति समर्पित हो गए। 1932 में,
उन्होंने इंदिरा के सोलहवें जन्मदिन से एक महीने पहले उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया।
इस प्रस्ताव ने उसे झकझोर दिया। कमला ने अपने पति से कहा कि वह यह प्रस्ताव नहीं चाहती।
इंदिरा ने उससे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वह 'अस्थिर था'।
हालांकि, कमला की मृत्यु के बाद इंदिरा और फिरोज के बीच संबंध और भी घनिष्ठ हो गए।
1936 में, कमला की मृत्यु के समय वे नेहरू परिवार के साथ थे। और बाद में, इंदिरा गांधी के समय भी।
वह अपनी मां के निधन से दुखी थी और उसके बाद के महीनों में उसे टीबी हो गया।
जैसा कि उन्होंने वर्षों बाद कहा, फ़िरोज़ 'हमेशा मेरे लिए मौजूद थीं'।
1930 के दशक में ब्रिटेन में रहते हुए, फ़िरोज़ ने लंदन स्कूल में अध्ययन किया।
अर्थशास्त्र और ऑक्सफोर्ड में इंदिरा, दोनों एक ऐसे समूह का हिस्सा बन गए
विद्रोही राजनेता वी. के. कृष्ण मेनन के इर्द-गिर्द वामपंथी, जो एक प्रमुख चेहरा हैं।
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की स्वतंत्रता के लिए पैरवी करने वाली इंडिया लीग के बारे में।

राजनीतिक गलियारों में, फ़िरोज़ और इंदिरा विचारों की एक रोमांचक दुनिया में रहते थे।
और क्रांतिकारी जोश।
1941 में वे भारत लौट आए। उसने अपने पिता को बताया कि उसने फैसला कर लिया है।
फिरोज से शादी करने के लिए। इससे नेहरू बहुत परेशान हुए; उन्हें इसमें बहुत अंतर दिखाई दिए।
उनके पृष्ठभूमि में। उन्होंने फ़िरोज़ को 'ज़ोरदार, उद्दंड और एक महान' पाया।
अपशब्दों का प्रयोग करने वाले नेहरू मृदुभाषी, सूक्ष्म और गाली-गलौज न करने वाले व्यक्ति थे।
यहां तक कि क्रोधित होने पर भी।
उन्होंने इंदिरा से आग्रह किया कि वे कोई भी कदम उठाने से पहले रिश्तेदारों और दोस्तों से सलाह लें।
इस निर्णय के बाद, नेहरू ने गांधीजी को पत्र लिखकर उनका मार्गदर्शन मांगा।
दिलचस्प बात यह है, और यह उन अज्ञात छोटी-छोटी जानकारियों में से एक है...
इतिहास के अनुसार, नेहरू का गांधी को लिखा पत्र गांधी के सचिव के पास ही रहा।
महादेव देसाई ने इस पर वर्षों तक लिखा था, ‘केवल मेरे या नेहरू के लिए’।
'आँखें'। महादेव देसाई की मृत्यु के बाद, उनके बेटे नारायण देसाई ने खोज की।
घर पर मिला पत्र—वह उन कागजों में शामिल नहीं था जो सौंपे गए थे।
भारत सरकार द्वारा संकलित रचनाओं के संकलन हेतु
गांधी। नारायण देसाई ने तुरंत नेहरू को पत्र लिखकर उनसे मिलने का अनुरोध किया।
नेहरू—उन्हें वर्षों पहले युवा नारायण बहुत पसंद थे और उन्होंने भेजा था
उन्हें विश्व इतिहास की झलकियाँ नामक पुस्तक की एक प्रति और इंदिरा की कुछ पुस्तकें दीं।
कक्षा चार और पांच के छात्रों ने अपने हाथ से लिखकर जवाब दिया, 'बड़ौदा में मुझसे मिलो'।
वह जिस स्टेशन पर रुकने वाला था, वह अपने एक दौरे के दौरान वहां ठहरना चाहता था।
नारायण देसाई ने लिफाफा नेहरू को सौंपते हुए कहा, ‘यह मेरा था।’

उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, 'इसे आप तक पहुंचाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है।'
पत्र का विषय रहीं इंदिरा गांधी, नेहरू के बगल में बैठी थीं।
वह चुपचाप डिब्बे में बैठकर दोनों पुरुषों के बीच हो रही बातचीत सुन रहा था।
अब तक वह प्रधानमंत्री की आधिकारिक मेजबान और दो बच्चों की मां बन चुकी थीं।
उसके बेटे हैं—और वह अपने पति से अलग रहती है।
लेकिन नवंबर 1941 में, नेहरू का पत्र मिलने के बाद, गांधी
इंदिरा को फिरोज से शादी करने के अपने फैसले से पीछे हटने के लिए समझाने की कोशिश की थी। उसे ऐसा करना चाहिए था।
शादी में जल्दबाजी न करें। अंत में, वह मान गया लेकिन इस शर्त पर कि
वह और फिरोज नेहरू की सहमति के बिना कुछ भी नहीं करते थे।
अंततः नेहरू भी झुक गए।
उन्हें घोर आश्चर्य हुआ जब गांधी ने उन्हें एक साधारण से काम के खिलाफ सलाह दी।
समारोह। अगर समारोह छोटा होता, तो लोगों को शक होता कि परिवार इस समारोह को मंज़ूरी नहीं देता। इसलिए, शादी सबके सामने हुई।
इंदिरा और फिरोज का विवाह राम नवमी के अवसर पर 26 मार्च 1942 को हुआ था।
यह समारोह आनंद के बरामदे में लगे शामियाने के नीचे आयोजित किया गया था।
भवन। इंदिरा सुबह 9 बजे अपने कमरे से हल्के रंग के कपड़े पहने नीचे आईं।
गुलाबी खादी की साड़ी। इसे नेहरू द्वारा बुने गए धागे से बुना गया था।
वह जेल में था। उसने सोने के गहने नहीं पहने थे, केवल फूलों की माला पहनी थी।
कांच की चूड़ियाँ।
गांधी इंदिरा गांधी के विवाह में शामिल नहीं हो सके। वे यात्रा पर थे।
दिल्ली में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स से सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा के लिए मुलाकात होगी।
ब्रिटेन से भारत। क्रिप्स ने ब्रिटिश विश्व युद्ध के लिए भारत का समर्थन मांगा।
चुनाव और पूर्ण छूट के वादे के बदले द्वितीय विश्व युद्ध के प्रयासों को जारी रखा गया।
युद्ध के बाद प्रभुत्व का दर्जा देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने खारिज कर दिया।
पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए; गांधी ने इस प्रस्ताव को 'अप्रचलित' बताया।
'एक विफल बैंक पर चेक'। इसी के चलते 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ।
उस दौर की उथल-पुथल की तरह, फ़िरोज़-इंदिरा का विवाह भी उथल-पुथल भरा था।
यह भी उथल-पुथल भरा था; यह ज्यादा समय तक नहीं चला। नेहरू के डर—और

कमला के भी—
आशंकाएं सच साबित हुईं। फिरोज के कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ संबंध बनने लगे।
अन्य महिलाओं के साथ। इंदिरा ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया। उनके पास
उन्होंने यॉर्क रोड के 17 नंबर पर स्थित छोटे से घर से स्थानांतरित होने का निर्णय लिया (अब
मोतीलाल नेहरू मार्ग), जहां वे प्रधानमंत्री के रूप में अपने शुरुआती कार्यकाल में रहे थे, से
भव्य तीन मूर्ति भवन, जहाँ सेनापति विराजमान हैं।
ब्रिटिश भारतीय सेना वहां रहती थी। उनके बेटे, राजीव और संजय, उनके साथ चले गए।
उसकी।
1952 में फिरोज के सांसद बनने के बाद, वे अक्सर अपने समर्थकों की आलोचना करते थे।
प्रधानमंत्री के ससुर। वे अक्सर अपने बेटों से मिलने आते थे।
तीन मूर्ति हाउस में नाश्ते के समय। कभी-कभी वह उन्हें ले जाता था।
उसका घर, और उन्हें उसका बगीचा, उसके शिकार के ट्राफियां, उसकी मछली पकड़ने की जगहें दिखाओ।
उन्होंने उन्हें लकड़ी काटना सिखाया। संजय अपने पति के बहुत करीब थे।
पिता और फ़िरोज़ संभवतः अपने छोटे बेटे को अधिक पसंद करते थे, 'संभवतः'
क्योंकि दोनों को अपने हाथों से काम करना पसंद था। एक बार, जब
ये लड़के दून स्कूल से दिल्ली की यात्रा पर आए थे, जहाँ वे
पढ़ाई करते हुए, फ़िरोज़ ने उनसे संसद में मिलने के लिए आने को कहा।
दर्शक दीर्घा में संजय ने अपने पिता का एक प्रेरक भाषण सुना।
फिरोज ने उन्हें देखते ही तुरंत उनकी ओर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया।
एक साथ, प्रत्येक बांह के नीचे एक।
नेहरू भी अपने पोतों से बहुत स्नेह रखते थे। एक बार उन्होंने उनके साथ दो घंटे बिताए थे।

संजय ने अपने एक दोस्त के घर पर एक इलेक्ट्रिक खिलौना ट्रेन देखी थी और उसे खरीदने पर जोर दे रहा था। रात में फोन पर बात करके उस ट्रेन को खरीदने की कोशिश कर रहा था।

दूर चले गए। हालाँकि तब तक सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं, नेहरू किसी तरह वहाँ पहुँचने में कामयाब रहे।

आधी रात तक उसके लिए इसे ले आओ। लेकिन अपने बाद के वर्षों में, 'संजय और राजीव...

उन्होंने अपने दादा को परिवार के टूटने के प्रमुख कारणों में से एक माना।

उनका पारिवारिक जीवन...

1960 में फिरोज को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी उम्र मात्र अड़तालीस वर्ष थी।

फ़िरोज़ की मौत से संजय के मन में द्वेष पैदा हो गया; उसने इसके लिए अपनी माँ को दोषी ठहराया।

'अपने पिता की उपेक्षा और मृत्यु'। धीरे-धीरे, वह खुद पर नियंत्रण खोती जा रही थी।

उसे। 'मनमौजी' और 'जंगली', और अक्सर मुसीबत में पड़ने वाला, वह था

पुपुल जयकर के अनुसार, यह उनकी माँ के लिए एक मुश्किल काम था। लेकिन इंदिरा

वह एक स्नेहशील मां बनी रहीं।

■

अपने पिता की आधिकारिक मेज़बान के रूप में, इंदिरा गांधी की राजनीति में भागीदारी

1950 के दशक में यह किसी भी औपचारिक पदनाम से कहीं अधिक था।

उन्होंने सुझाव दिया। वह नेहरू की प्रमुख सलाहकार थीं। 'लोगों को यह एहसास नहीं होता कि कैसे

'पापू मुझ पर कितना निर्भर थे,' उन्होंने एक बार कहा था, अपनी उस भूमिका का जिक्र करते हुए जो उन्होंने निभाई थी।

उन्होंने उनके प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान खेला था। 1955 में, वह सदस्य बनीं।

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी), पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था-
शरीर का निर्माण करना—और सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के लिए उनका आधार बनना।
कई लोग इंदिरा को उनके पिता तक पहुंचने का एक सुविधाजनक माध्यम मानते थे—
जैसे जी.बी.
जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, पंत और यू.एन. ढेबर इसके विरोधी थे।
नेहरू की वामपंथी राजनीति। उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी इसे नियंत्रित करने में सक्षम होंगी।
समाजवादियों और कम्युनिस्टों से उनकी निकटता। पंत एक संघवादी थे।
मंत्री और ढेबर 1955-59 तक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके थे। दोनों
उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजी किया गया। उन्होंने पदभार संभाला।
ढेबर, 1959 में।
उन्होंने नेहरू को कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने के लिए राजी कर लिया।
जुलाई 1959 में केरल में अशांति फैली हुई थी। यह वह समय था जब राज्य में अशांति का माहौल था।
यह पहली बार था जब केंद्र सरकार ने किसी राज्य को भंग किया था।
यह इंदिरा गांधी की 'निर्दयता' का पहला प्रदर्शन भी था।
लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति उनकी उदासीनता। 'केरल में अशांति...ने प्रभावित किया।
उनकी जीवनीकार कैथरीन फ्रैंक ने लिखा, 'उनकी नसें हमेशा भेदी थीं।'
समझदारी से। 'इंदिरा नेहरू के इस विश्वास से सहमत नहीं थीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहेगी।'
संस्थाएँ अस्थिर परिस्थितियों में भी जीवित रहेंगी।
संघर्ष और अस्थिरता के बीच, उसकी सहज प्रवृत्ति व्यवस्था को प्राथमिकता देने की थी।
प्रजातंत्र।'
वह हमेशा अपने पिता से सहमत नहीं होती थी। इंदिरा का अपने पिता से अक्सर मतभेद होता था।
उन्हें बंबई राज्य के गुजरात और अन्य राज्यों में विभाजन को लेकर आपत्ति थी।

महाराष्ट्र। नेहरू इसके खिलाफ थे। वह अधिक दृढ़ निश्चयी थीं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की।
4 दिसंबर 1959 को, इसने राज्य को विभाजित करने की सिफारिश की और
बॉम्बे को महाराष्ट्र को दे दिया गया। उसकी यही इच्छा थी।
इंदिरा अपने पिता को बहुत 'नरम' मानती थी। उसने कहा कि वह 'एक संत' थे जो
राजनीति में भटक गई थी। वह खुद को एक 'कठोर राजनीतिज्ञ' मानती थी। 'मेरा
baap sant thaa, main nahin hoon (My father was a saint, but I am not),'
उन्होंने 1969 में यूपी कांग्रेस नेता बनारसी दास को बताया, उन्हें अपने पास रखते हुए
वह खड़ी थी, उसकी ओर देखे बिना। संदेश चंद्र के लिए था।
उत्तर प्रदेश के शक्तिशाली मुख्यमंत्री भानु गुप्ता, जिन्होंने अपना रुख बदल दिया था,
उसके खिलाफ होड़ लगाई और विरोधियों के 'सिंडिकेट' के साथ हाथ मिला लिया।
उसे।
■

जब 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हुआ, तो सिंडिकेट ने लाल बहादुर को चुना।
शास्त्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जब शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था,
तब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था।
1963 में कामराज योजना को लेकर ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि नेहरू इस
योजना को लेकर चिंतित थे।
उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1963 में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के.
कामराज ने छह कैबिनेट मंत्रियों को पद से हटाने की योजना बनाई थी, जिनमें शामिल थे
शास्त्री और स्वयं समेत छह मुख्यमंत्रियों ने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया।
संगठन। लेकिन शास्त्री को शुरू से ही यकीन था कि नेहरू चाहते थे
उनकी बेटी को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाना था, हालांकि नेहरू इस पर अस्पष्ट
बने रहे।

जब इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनीं, तब नेहरू का रवैया कुछ हद तक सकारात्मक था।
'अस्वीकारात्मक'; वह भाई-भतीजावाद के आरोप को आमंत्रित नहीं करना चाहता था या
वंशवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना।
जब शास्त्री ने इंदिरा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, तो शुरू में वह
वह अनिच्छुक थी। लेकिन जब उसने सुना कि वह उसकी चाची को भी शामिल कर सकता है, तो वह सहमत हो गई।
इसके बजाय विजया लक्ष्मी पंडित। वह विदेश मंत्री बनना चाहती थीं; वह
उन्होंने उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पेशकश की। उन्होंने उन्हें
मंत्रिमंडल में चौथे नंबर पर होना—जो उनके दृढ़ स्वभाव को दर्शाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसे खुश करने के लिए, उसने कई मौकों पर उससे तीखी बहस की, अक्सर

उनका उपहास करते हुए। 'क्या आपको लगता है कि यह सरकार कर सकती है?'
एक बार उन्होंने तिरस्कारपूर्वक कहा था, 'अगर मैं आज इस्तीफा दे दूं तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगी?'

चतुर्थ

11 जनवरी 1966 को इंदर कुमार गुजराल के बेडरूम में फोन की घंटी बजी।
रात के 3 बज रहे थे। इंदिरा गांधी के सहायक यशपाल कपूर लाइन पर थे। 'लाल
कपूरी ने बताया, 'बहादुर शास्त्री का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है।'
गुजराल दंग रह गए। प्रधानमंत्री उस समय ताशकेंट में थे जब यह घटना घटी।
अंत आ गया। उन्होंने अभी-अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
Yahya Khan.
'श्रीमती गांधी चाहती हैं कि आप तुरंत आ जाएं,' कपूर ने कहा।
अत्यंत आवश्यक। गुजराल वामपंथी 'बैकबेंचर्स क्लब' के सदस्य थे।
इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान राजनीतिक रूप से सलाह देने वाले झुकाव वाले

सांसद
सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल—बाद में वे उनकी 'रसोई' बन गईं अलमारी'।
जब गुजराल इंदिरा गांधी के आवास पर पहुंचे, तो वह उनका इंतजार कर रही थीं।
वे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जल्द ही, उनके साथ प्रकाशक भी शामिल हो गए।
सेमिनार, रमेश थापर। गुजराल की तरह, वह भी उनके करीबी दोस्त थे।
इंदिरा गांधी की। 'श्रीमती गांधी काफी उत्साहित थीं।' उन्हें लगा कि अब वह ऐसा कर सकती हैं।
'विदेश मंत्री' बनो। गुजराल और थापर ने एक-दूसरे की ओर देखा।
वह अचंभित रह गई। उन्होंने उससे कहा कि वह 'प्रधानमंत्री चुनी जा सकती है'।
इंदिरा के साथियों की अगली सुबह फिर मुलाकात हुई। इस बार दूसरे लोग भी शामिल थे— यूपी के लोग।
कांग्रेस नेता उमा शंकर दीक्षित, जिन पर उन्हें भरोसा था, और दिनेश
सिंह, कलाकंकर के पूर्व राजा, जो एक सौम्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और आगे चलकर राजा बनने वाले थे।
उनकी पहली कैबिनेट में राज्य मंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने फैसला किया
उन्हें अपनी उम्मीदवारी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें एक
अनिच्छुक खिलाड़ी—गैर-प्रतिबद्ध और आत्म-त्यागी। ये लोग थे
राजनीति के एक सुस्थापित सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए—कि जिन्होंने फेंका
जो लोग शुरुआत में ही मैदान में उतर गए थे, वे ही सबसे पहले दौड़ से बाहर हो गए।
हमेशा की तरह, उनके विरोधियों को संगठित होने का अवसर मिल जाता था
उनके खिलाफ ताकतें।
यह रणनीति कारगर साबित हुई।
अगले दिन, 12 जनवरी 1966 को, काले रंग की साड़ी और गहरे रंग के कपड़े पहने हुए
चश्मा पहने, शोकग्रस्त इंदिरा गांधी पालम हवाई अड्डे पर इंतजार कर रही थीं।
शास्त्री का पार्थिव शरीर ताशकेंट से आने वाला है। वहां एक राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद है।

इंदिरा गांधी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पत्रकार निखिल से कहा
चक्रवर्ती ने कहा कि इलाहाबाद से 'हैट्रिक' लगाने वाली वह महिला वहीं बैठी थी। वह भविष्यवाणी कर रहे थे कि वह नेहरू की तरह अगली प्रधानमंत्री बनेंगी।
शास्त्री, वह भी इलाहाबाद से थीं।
19 जनवरी 1966 को कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) ने चुनाव जीता।
इंदिरा गांधी इसकी नेता थीं—वह आगे चलकर प्रधानमंत्री बनीं।
सैंतालीस वर्ष की आयु में। उन्होंने मोरारजी देसाई को हराया, जिन्होंने कड़ा विरोध किया था।
उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को आगे बढ़ाया। आत्मधर्मी देसाई वैसे भी नहीं थे।
सांसदों के बीच लोकप्रिय। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के. कामराज
इंदिरा के पक्ष में सर्वसम्मति बनाने में सफलता मिली। उन्हें 355 वोट मिले।
देसाई के 169 वोटों के मुकाबले। जीत के तुरंत बाद, उन्होंने देसाई को फोन किया।
उनकी कृपा प्राप्त करें।
‘यह एक शानदार जनसंपर्क अभियान था,’ नटवर सिंह ने याद करते हुए कहा।
जो 1966 से 1971 तक उनके सचिवालय का हिस्सा थीं और बाद में बनीं
विदेश मंत्री।
शुरू में, उनके राजनीतिक विरोधियों ने यह गलती की कि
उन्हें कम आंकना। मोरारजी देसाई ने जल्द ही उन्हें 'यह छोकरी' कहकर पुकारा था।
सीपीपी द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए जाने के बाद
जनवरी 1966। कुछ महीनों बाद, प्रधान मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद।
मंत्री, और संसद में खुद को चुप पातीं, समाजवादी
नेता राम मनोहर लोहिया ने उन्हें 'गूंगी गुड़िया' कहा। अन्य लोग थे
उतना ही तिरस्कारपूर्ण रवैया। दिल्ली की एक पत्रिका ने उन्हें 'एक' के रूप में वर्णित किया था।
एक निर्दोष व्यक्ति' के रूप में भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करना।
जब लोग उससे मिलने आते थे तो वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। वह एक अच्छी श्रोता थी।
वह अक्सर अपने सामने रखी राइटिंग पैड पर कुछ न कुछ बनाती रहती थी। सालों बीतने के साथ-साथ, उसने

उसने मौन को एक ऐसे उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना सीख लिया जिसका वह सदुपयोग कर सकती थी। इससे उसे समय मिला।
अपने आगंतुकों के स्वभाव का अंदाजा लगाने और उन्हें इस बारे में अनुमान लगाते रहने के लिए कि आगे क्या होगा।
वह ऐसा करेगी।
■

उनके प्रधानमंत्री पद की शुरुआत काफी उतार-चढ़ाव भरी रही। देश की स्थिति
दो मौसमों तक मानसून के विफल रहने से भीषण सूखे की चपेट में।
1965 और 1966 में लगातार गिरावट आई। खाद्य उत्पादन में भारी कमी आई थी।
तस्वीरों में...
दुबली-पतली टांगों, उलझे बालों और खाली आँखों वाले कंकालनुमा बच्चे।
देश के पूर्वी हिस्से में 1966-67 के अकाल के शिकार लोग,
यह खबर अक्सर मीडिया में दिखाई देती थी। संकट को और भी गंभीर बनाने वाला कारक था...
1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता का निलंबन
दोनों देश।
उसने अमेरिका जाने का फैसला किया और पत्रकार इंदर से इस बारे में बात की।
मालहोत्रा ने बताया कि उनका उद्देश्य 'भोजन और विदेशी मुद्रा दोनों प्राप्त करना' था।
बिना मांगे ही। मार्च 1966 के अंत में, वह वहाँ पहुँची।
वाशिंगटन डीसी में एक तूफानी सुबह। उनका रेड कार्पेट पर स्वागत किया गया।
राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन और उनकी पत्नी लेडी बर्ड द्वारा स्वागत किया गया।
विदेश यात्राओं के दौरान इंदिरा गांधी हमेशा सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहनने पर विशेष ध्यान देती थीं।
यहां तक कि ग्लैमरस अंदाज में भी, अपने 'नए, ऊंचे हेयरस्टाइल, फुल मेकअप और आभूषण'। जॉनसन को वह 'अति आकर्षक' लगीं।
उन्हें लगा कि यह दौरा बहुत सफल रहा। जॉनसन ने कहा था कि
यह सुनिश्चित करना चाहता था कि 'इस लड़की को कोई नुकसान न पहुंचे' और 'तीन'

का वादा किया।
‘लाखों टन भोजन’ और ‘90 लाख डॉलर की सहायता’। इंदिरा गांधी ने अपनी ओर से वियतनाम में अमेरिका के हस्तक्षेप पर हमला नहीं किया। केवल एक ही बात
उसने जो करने से इनकार किया वह था 'डांस फ्लोर पर चारों ओर घूमना'
अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में भोज में शामिल हुए। उन्होंने जॉनसन से कहा कि इससे वह अपने गृह नगर में अलोकप्रिय हो जाएगी।
हालांकि देश को इस संकट से उबरने में मदद के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
जिस संकट का सामना इसे करना पड़ा, विश्व बैंक और आईएमएफ की जो शर्तें थीं लागू किए गए प्रतिबंध कठोर थे। इनमें रुपये का अवमूल्यन शामिल था—और
उन्होंने रुपये का मूल्य 36.5 प्रतिशत तक कम कर दिया।
आधिकारिक घोषणा 6 जून 1966 को की गई थी।
यह एक निर्णायक क्षण बन रहा है।
उनके प्रधान सचिव एल. के. झा ने ही उन्हें प्रभावित किया था।
अवमूल्यन पर निर्णय,’ नटवर सिंह ने वर्षों बाद कहा था।
उन्हें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने ही देश के प्रति समर्पण का दिखावा किया था।
अमेरिका। उनकी अपनी पार्टी—कांग्रेस वर्किंग कमेटी—
उसने उसके इस कृत्य की निंदा की। परेशान कामराज ने अपने फैसले पर खेद व्यक्त किया।
उसे सिंहासन पर बिठाओ: 'एक बड़े आदमी की बेटी, एक छोटे आदमी की गलती।'
कामराज और पुराने नेताओं के साथ उनकी समस्याएं शुरू हुईं...
मुद्रा का अवमूल्यन। साथ ही उनका वामपंथी झुकाव भी, जो 1973 तक जारी रहा।
उनकी ‘किचन कैबिनेट’ के सदस्य—आई. के. गुजराल, उमा शंकर दीक्षित,
दिनेश सिंह और नंदिनी सतपथी समेत अन्य लोगों ने उनसे ऐसा करने का आग्रह किया।
वह अपने फैसलों को वैचारिक रंग देती है ताकि इस धारणा का खंडन कर सके कि वह
अमेरिका की ओर से दबाव बढ़ रहा था। उसने अमेरिका पर हमला करना शुरू कर

दिया।
वियतनाम नीति को 'साम्राज्यवादी आक्रमण' करार दिया गया। जॉनसन बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने इसे स्थगित कर दिया।
पीएल 480 कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की आपूर्ति - इसका भुगतान किया गया था
रुपयों में—कड़ी लगाम के साथ। हालांकि मुद्रा अवमूल्यन ने लगभग एक दशक तक उनके राजनीतिक पथ को प्रभावित किया, लेकिन 1966 में उनकी अमेरिकी यात्रा ने उन्हें
खूब सोचो।
अलाबामा के एक अखबार ने उनकी यात्रा को 'नई भारतीय नेता' शीर्षक दिया था।
भीख मांगने आता है। उन्हें एहसास हुआ कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा।
भोजन को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की आवश्यकता है। उसने प्रोत्साहन देना शुरू किया।
ऐसी नीतियां और अनुसंधान जो देश के खाद्य उत्पादन में सुधार लाएंगे
उत्पादन। अंततः इसी से हरित क्रांति का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य था...
भारत को खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बनाना—लेकिन बाद में इससे कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हुईं।
रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से जुड़ी समस्याएं।
■

फरवरी 1967 में रायबरेली में आम चुनाव प्रचार के दौरान ही यह घटना घटी थी।
elections, that Indira Gandhi reached out to Parameshwar Narayan
हकसर, जो खुद को मार्क्सवादी मानते थे, भारत के उप उच्चायुक्त थे।
उस समय वह लंदन में थी। उसने उसे पत्र लिखकर दिल्ली आने का अनुरोध किया।
उसके साथ काम करें। उसने स्वीकार किया कि उसका निमंत्रण समय से पहले था क्योंकि उसने
चल रहे चुनावों के परिणाम ज्ञात नहीं हैं।

‘जी हां, बिल्कुल हां,’ पी. एन. हक्सर ने तुरंत जवाब दिया।
हक्सर में, वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही थी जो व्यक्तिगत रूप से
उसके प्रति वफादार रहना, नए विचार उत्पन्न करना और उसकी बातों को सुनने वाला सलाहकार बनना। हक्सर के पास था।
मैं इंदिरा को तब से जानता था जब वह दो साल की थी और वह खुद दस साल का लड़का था, और वह
मुझे बड़ी-बड़ी आंखों वाली वह छोटी बच्ची याद आ गई। हमारा रिश्ता कायम रहा।
वह उनके बेटों, राजीव और संजय के स्थानीय संरक्षक थे, जब वे
वे 1960 के दशक के मध्य में लंदन में थे। हक्सर प्रधानमंत्री के साथ जुड़ गए।
1967 में सचिवालय में सचिव के रूप में नियुक्त हुए। 1971 में, वे इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव बने।
सचिव। उन्हें देश का सबसे शक्तिशाली नौकरशाह माना जाता था।
उन्हें स्वतंत्रतोत्तर युग का 'प्रधानमंत्री का जनक' माना जाता है।
'कार्यालय'। हक्सर को कई प्रमुख निर्णयों का श्रेय दिया जाता है।
1967-72 के बीच इंदिरा के साथ उनका संबंध था, हालांकि उन्होंने कभी इस बात को ज़ाहिर नहीं होने दिया। न ही उन्होंने
कभी भी उनका श्रेय मत लेना। कोई राजनीतिक निर्णय नहीं था।
आर्थिक या विदेश नीति से संबंधित, जिसमें हक्सर का कोई हित शामिल नहीं था।
टिकट।
इंदिरा गांधी ने 9 जुलाई को सिंडिकेट के खिलाफ अपना पहला कदम उठाया।
1969 में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में एक नोट प्रसारित किया।
बेंगलुरु में हुई बैठक में राज्य के नेतृत्व वाली आर्थिक व्यवस्था की वकालत की गई।
परिवर्तन, जिसमें बैंकों का ‘सामाजिक नियंत्रण’ भी शामिल है। क्योंकि उसने नोट का अंत इस वाक्य से किया था, ‘ये कुछ बिखरे हुए विचार हैं जो मैंने जल्दबाजी में लिखे हैं।’
'बोलकर लिखवाई गई' इस नोट को बाद में उसके 'अस्त-व्यस्त विचार' कहा जाने लगा।
दस दिन बाद, 19 जुलाई 1969 को, उसने अपने एक 'भटके हुए' साथी को धर्म

परिवर्तन के लिए प्रेरित किया।
विचारों को वास्तविकता में बदला—और एक आश्चर्यजनक कदम में उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया
चौदह निजी बैंक। लेकिन उससे ठीक पहले, एक और त्वरित कदम में,
अपने निर्णय लेने के विशिष्ट स्वरूप के अनुसार, उन्होंने मोरारजी देसाई से पद छीन लिए।
वित्त मंत्रालय। निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उनका निर्णय
‘भारत सरकार के सबसे गुप्त रहस्यों में से एक’, जिसे कोई नहीं जानता
हक्सर समेत 'चार-पांच लोगों को छोड़कर' बाकी सभी को इसके बारे में पता था।
अब उसने शत्रु के क्षेत्र में युद्ध छेड़ने का फैसला किया।
सिंडिकेट ने नीलम संजीवा के चयन में अपनी मनमानी कर ली थी।
रेड्डी को कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में इस पद के लिए नामित किया गया है।
गणतंत्र की राष्ट्रपति। लेकिन इंदिरा गांधी, जिन्हें डर था कि उन्हें हटा दिया जाएगा।
यदि रेड्डी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो उन्होंने 'अंतरात्मा के मत' का अनुरोध किया था।
पार्टी नेताओं द्वारा। उन्होंने उपाध्यक्ष वी.वी. गिरि का समर्थन किया।
राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थीं।
मौन समर्थन। 20 अगस्त को, गिरी ने मामूली अंतर से चुनाव जीता, और
भारत के राष्ट्रपति बने।
अंततः, कांग्रेस अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया।
12 नवंबर 1969 को 'अनुशासनहीनता' के आरोप में उन्हें पद से हटा दिया गया।
उन्होंने अपना खुद का भारतीय संघ बनाया।
राष्ट्रीय कांग्रेस (अधिग्रहण), या कांग्रेस (आर) जैसा कि यह बाद में बनी
यह ज्ञात है कि मूल पार्टी का नाम बदलकर कांग्रेस कर दिया गया था।
(संगठन) या कांग्रेस (ओ)। पुराने नेताओं ने सोचा था कि वह ऐसा करेगी।
1966 में जब उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री चुना तो वे लचीली थीं। लेकिन
उन्होंने पासा पलट दिया। यह इंदिरा गांधी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।

गांधी की राजनीतिक यात्रा; यह 1969 में पार्टी में विभाजन के बाद ही शुरू हुई थी।
कि उसने अपनी पहचान बना ली।
अपने प्रगतिशील उपायों को जारी रखते हुए, सितंबर 1970 में, उन्होंने
उन्होंने एक और कदम उठाया जिससे उन्हें लोकप्रियता मिली—दास प्रथा का उन्मूलन।
पूर्व राजकुमारों के निजी कोष और विशेषाधिकारों से संबंधित। ये कर थे।
उस समय के 278 राजकुमारों को दिए गए मुफ्त विशेषाधिकार और भत्ते।
केंद्र सरकार—संवैधानिक गारंटी के माध्यम से जब वे
स्वतंत्र भारत में अपनी रियासतों को एकीकृत करने पर सहमति व्यक्त की।
स्वतंत्रता। 26वें संवैधानिक संशोधन के पारित होने के साथ।
संशोधन अधिनियम के तहत, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया—हालांकि उनका निर्णय हो सकता है
दो साल की कानूनी लड़ाई के बाद ही इसे लागू किया गया।
1971 में हुए चुनावों में उन्होंने पूरे देश को रोमांचित कर दिया।
उन्होंने 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ कांग्रेस का नेतृत्व किया।
(आर) ने लोकसभा में 352 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की, जो निचले सदन के समान है।
संसद के सदन में। आने वाले समय में, वह मुख्य बन जाएगी
कांग्रेस पार्टी। (लेकिन कांग्रेस (ओ), जो कि काफी हद तक बदल गई थी)
1971 के बाद कद में गिरावट आई, एक आखिरी शानदार प्रदर्शन किया, हालांकि वह अल्पकालिक था।
1977 में जनता पार्टी के साथ विलय होने और सत्ता हथियाने के बाद भी यह पार्टी अस्तित्व में रही।
(आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी से।)
हालांकि, इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर का चरम बिंदु 1980 में आया।
1971 में उन्होंने भू-राजनीतिक इतिहास रचा। उनकी शानदार जीत के बाद
मार्च 1971 के आम चुनाव में उन्होंने और भी बड़ी जीत हासिल की।
उसी वर्ष के अंत में उन्हें तब विजय प्राप्त हुई जब उन्होंने युद्ध में पाकिस्तान को परास्त कर दिया, और

स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने साहसिकता का प्रदर्शन किया।
दिसंबर 1971 में बांग्लादेश में। यह हक्सर ही थे जिन्होंने नट्स का आविष्कार किया था।
और रणनीति के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया—और उसे सलाह दी कि उसे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।
पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप की जल्दबाजी। कोई सैन्य हस्तक्षेप नहीं।
यह तभी काम करेगा जब पूर्वी पाकिस्तान में कोई विद्रोह न हो जाए।
भारत जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान कर सकता था। भारत ने प्रशिक्षण दिया और सहायता प्रदान की।
मुक्ति वाहिनी (स्वतंत्रता सेनानी) ने अपनी सेना भेजने से पहले।
बांग्लादेश के गठन से पहले भी, हक्सर के साथ-साथ,
राजनयिक डी. पी. धर—वे उस समूह का हिस्सा थे जिसे 'कश्मीर' कहा जाता था।
उसके आसपास मौजूद माफियाओं ने उसे भारत-सोवियत संघ संधि में शामिल होने की सलाह दी।
भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए शांति, मित्रता और सहयोग के सिद्धांत।
पाकिस्तान, चीन और अन्य देशों के बीच बढ़ते गठजोड़ को देखते हुए हितों का ध्यान रखना होगा।
अमेरिका। जिस क्षण अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर गए थे
इंदिरा गांधी पाकिस्तान से चीन की गुप्त और अचानक यात्रा पर आईं, इंदिरा गांधी ने तुरंत कार्रवाई की।
और भारत-सोवियत संघ शांति, मैत्री और सद्भाव संधि पर हस्ताक्षर किए।
9 अगस्त 1971 को सहयोग की स्थापना हुई।
अमेरिका भारत और उसके प्रधानमंत्री से बेहद नाराज था। राष्ट्रपति
रिचर्ड निक्सन ने उन्हें 'बुढ़िया चुड़ैल' कहा था। उनकी मुलाकात उनसे 4 नवंबर को हुई थी।
1971 में उन्होंने उसे सेना वापस बुलाने के लिए मनाने की असफल कोशिश की।
भारत-पाकिस्तान सीमा पर। वह अपनी 'सर्वोत्तम जुझारू क्षमता' में थी और उसने 'हर संभव प्रयास किया'।
'निक्सन के साथ बातचीत'। उन्होंने बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका का सामना

किया।
संघर्ष में, अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के प्रवेश करने पर भी वह जरा भी विचलित नहीं हुआ।
धमकी भरे प्रदर्शन के तौर पर बंगाल की खाड़ी में घटना को अंजाम दिया गया।
पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला किया। तीन दिन बाद, इंदिरा गांधी ने
गांधी ने बांग्लादेश को नवराष्ट्र के रूप में मान्यता दी। उनके प्रतिद्वंदी, दक्षिणपंथी भारतीय जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी सराहना की।
'दुर्गा' के रूप में।
हालांकि, बांग्लादेश के खिलाफ उनकी अभूतपूर्व जीत के बाद, समीकरण बदल गया।
हकसर के दोस्त उसे 'इंदुजी' और 'बाबूजी' कहकर पुकारते थे, उनके बीच में...
उसमें बदलाव आने लगा। अब वह उड़ने के लिए स्वतंत्र हो गई थी और खुद ही उड़ सकती थी।
अपने आप में एक जन नेता के रूप में देखी जाने वाली, उन्होंने उस टैग को पीछे छोड़ दिया था...
नेहरू की बेटी होने के नाते, उन्हें अब किसी मुखर हक्सर की आवश्यकता नहीं थी।
हर विषय पर अपनी राय रखने वाली उसकी कोहनी। निर्णायक मोड़।
दोनों के बीच विवाद दिसंबर 1972 में हक्सर की तीखी आलोचना के कारण शुरू हुआ।
संजय गांधी के बारे में। उन्होंने उससे कहा कि प्रधानमंत्री के बेटे को नहीं होना चाहिए।
व्यवसाय करते हुए—उन्होंने मारुति का नेतृत्व किया, जो एक छोटी 'लोगों की' कंपनी बनाने की परियोजना थी।
प्रधानमंत्री आवास से 'कार'। 'आपको अपना मन बनाना होगा।'
हकसर ने अपने विशिष्ट सीधे-सादे अंदाज में कहा, 'आप या तो माँ बन सकती हैं।'
(संजय से) या प्रधानमंत्री। आप दोनों नहीं हो सकते।'
'हक्सर ने मुझे यह बात खुद बताई थी,' नटवर सिंह ने खुलासा किया, जिन्होंने
प्रधानमंत्री सचिवालय में रहने के कारण हक्सर तक प्रतिदिन पहुंच संभव थी।
1966–71.
संजय ने हक्सर को उसकी आलोचना करने के लिए कभी माफ नहीं किया। दोनों के

बीच दरार पड़ चुकी थी।
यह काफी समय से चल रहा था। संजय को इसका जबरदस्त प्रभाव पसंद नहीं था।
हकसर और उसके वामपंथी विचारधारा वाले दोस्तों ने उसकी माँ पर दबाव बनाया।
उसने उसे ले लिया।
खुद को साम्यवाद-विरोधी कहने में उन्हें गर्व होता था। वे कहा करते थे कि
अनिल बाली ने याद दिलाते हुए कहा, 'कम्युनिस्टों को समुद्र में फेंक देना चाहिए।'
इंदिरा
उन्होंने हक्सर को, जो अब एक 'मौन आलोचक' बन चुका था, को उकसाकर संघर्ष को शांत करने का प्रयास किया।
1973 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल जारी रखा।
उन्हें अनौपचारिक रूप से सलाह दी, और यहां तक कि संवेदनशील कार्य भी हाथ में लिए।
उसकी ओर से।
हकसर ने इंदिरा गांधी के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित किया था।
एक प्रगतिशील, वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत और धर्मनिरपेक्ष भारत की परिकल्पना।
1967-73 के दौरान इंदिरा गांधी के 'वैचारिक मार्गदर्शक' कहे जाने वाले उन्होंने उन्हें देखा।
अपने पिता की प्रगतिशील नीतियों को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन 1973 के बाद, इंदिरा गांधी ने
वह उस दिशा से अलग दिशा में आगे बढ़ गई थी जिसकी हक्सर ने उम्मीद की थी।
पैदल चलेगा।
जब वह 1980 में दोबारा चुनी गईं, तो हक्सर ने उन्हें एक हार्दिक पत्र लिखा।
बधाई का व्यक्तिगत पत्र, जिसमें एक सत्य का प्रतिपादन किया गया था जिसने
राजनीति में सफलता के लिए: 'युद्ध की तरह ही, शांति में भी कला हमेशा इसमें निहित होती है'
या तो दुश्मन पर विजय प्राप्त करके या उसे पूरी तरह से नष्ट करके।' लेकिन, वह
उन्होंने आगे कहा, 'ऐतिहासिक अनुभव से पता चलता है कि सुलह की कला विनाश की कला से कहीं अधिक फलदायी होती है।' उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए।
उन्होंने उसे उसके उपनाम (बाबूजी) से पुकारा। उसने उसके पत्र को स्वीकार किया।

लेकिन वह
उन्होंने उन्हें औपचारिक रूप से श्री हक्सर कहकर संबोधित किया। और उन्होंने पत्र पर 'इंदिरा' लिखकर हस्ताक्षर किए।
गांधी', न कि इंदु या इंदिरा जैसा कि वह पहले के वर्षों में किया करती थीं।
उन्हें पीएन, पीएनएच या बाबूजी कहकर संबोधित किया जाता था। एक बार हक्सर को मजबूर किया गया।
जब संजय बाहर हो गए, तो उन्होंने अपनी माँ के मुख्य सलाहकार के रूप में पदभार संभाला। संयोगवश या
परिणामस्वरूप, इंदिरा की मुश्किलें उनके चले जाने से और भी बढ़ गईं।
हक्सर और संजय का उदय।
वी
इंदिरा गांधी के सोलह वर्षों के शासनकाल में तीन महत्वपूर्ण चरण थे।
प्रधानमंत्री थे। इनमें से दो चरण, 1966-73 और मध्य से...
1980-84—जब उसने पंजाब के स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी थी,
जिसकी परिणति उनकी हत्या में हुई—ये घटनाएँ संजय के बिना हुईं।
प्रभाव। वास्तव में, 1972-73 तक वह राजनीतिक परिदृश्य में नहीं थे।
हालांकि वे 1967 में ब्रिटेन से भारत लौट आए थे। यह उस दौरान हुआ था।
सन् 1973 से 1980 तक की मध्य अवधि, जिसमें संजय ने प्रमुख भूमिका निभाई, और उन्हें सत्ता के पीछे की असली शक्ति के रूप में देखा जाता था। उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया।
आपातकाल के चरम पर पहुंचने तक इंदिरा गांधी शक्तिशाली थीं, लेकिन उस समय उन्होंने दावा किया कि वह
मुझे उसके द्वारा किए जा रहे कुछ कामों के बारे में और अधिक जानकारी नहीं है।
बचपन से ही एनीमिया से पीड़ित होने के कारण इंदिरा गांधी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
संजय के साथ गर्भावस्था के दौरान, उसे जन्म देते समय वह लगभग मरते-मरते बची।
जब वह संजय के गर्भ में थी तब वास्तव में वह एक लड़की चाहती थी, और
उन्होंने उसका नाम भी चुन लिया था। उनकी कुलदेवी (कुलदेवी) थी
उसका नाम शारिका था और वह अपनी बेटी का यही नाम रखना चाहती थी।

यदि उसे बेटी होती, तो बाद में उसका नाम सारिका रखा जाता।
पारिवारिक मित्र और कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा की बेटी।
संजय को एक ऐसे विद्रोही के रूप में जाना जाता था जिसका कोई उद्देश्य नहीं था, और उसका जीवन एक ऐसे मोड़ पर चल पड़ा था जहाँ उसे एक अलग ही राह पर चलना पड़ा था।
उथल-पुथल भरी राह। बचपन में वह अपने घर में फूलों के गमले तोड़ा करता था।
तीन मूर्ति भवन में दादाजी के घर पर जाकर, उनके कान खींचो।
कुत्ते। वह एक जिद्दी बच्चा था, पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था, और अक्सर
मुसीबतों में पड़ना। इंदिरा ने पहले उसे दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में भेजा।
पहले उन्होंने उसकी पढ़ाई पूरी की और फिर उसे दून के प्रतिष्ठित आवासीय स्कूल में भेज दिया।
देहरादून। लेकिन उसे स्कूल से नफरत थी और उसे वहाँ से स्थानांतरित करना पड़ा क्योंकि
और उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की।
एक दुर्लभ क्षण में, इंदिरा गांधी ने एक बार स्पष्टवादिता से कहा था...
उनकी दोस्त पुपुल जयकर ने कहा: 'राजीव विनम्र, अच्छे व्यवहार वाला और निष्पक्ष व्यक्ति था।'
छात्र संजय विद्रोही, विध्वंसक, स्कूल की सभी गतिविधियों में अरुचि रखने वाला, अपने शिक्षकों के प्रति असभ्य और कुल मिलाकर अनियंत्रित था। वह बड़ा हुआ।
एक बेपरवाह, मनमौजी युवक, जो अक्सर मुसीबतों में फंसता था, कारों से छेड़छाड़ करता था।
संदिग्ध दोस्तों को आकर्षित करना।
संजय को बचपन से ही मेकानो सेट में रुचि थी।
कारें और हवाई जहाज। इसीलिए उसने उसे इंटर्नशिप के लिए भेजा।
इंग्लैंड के क्रू में स्थित रोल्स-रॉयस कंपनी में उन्होंने काम किया। हालाँकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया।
तीन साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया और दो साल में वापस लौट आए।
साल।
वापस लौटने के बाद, उन्होंने एक छोटा सा उपकरण बनाने में रुचि दिखाई,

सस्ती, स्वदेशी रूप से निर्मित कार। इंदिरा गांधी ने इसे प्रोत्साहित किया।
वह उम्मीद करती थी कि उसका बेटा इस परियोजना के माध्यम से अपने जीवन में कुछ सार्थक करेगा।
जिस वाहन को बनाने के लिए वह इतना दृढ़ था, उसका निर्माण करना। सरकार ने अनुमति दी।
1971 में उसे इसके निर्माण का लाइसेंस दिया गया। इसने उसे कई लाभ प्रदान किए।
परियोजना को शुरू करने में मदद करने के लिए। मारुति मोटर्स लिमिटेड नामक एक कंपनी।
जून 1971 में संजय गांधी को पहले प्रबंधकीय पद पर नियुक्त करके इसकी स्थापना की गई थी।
निर्देशक। हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल ने 297 लोगों की मदद की।
कारखाने के लिए एकड़ जमीन बहुत कम कीमत पर दी गई थी।
संजय और उसकी माँ की इच्छा पूरी करने की उसकी उत्सुकता ने लाल को निर्दयतापूर्वक बेदखल कर दिया।
किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। चूंकि वह प्रधानमंत्री के बेटे थे, इसलिए...
ये कार डीलर थे जो एक-दूसरे से होड़ करते हुए भारी रकम देने के लिए होड़ करते थे।
उन वाहनों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में जो वह उन्हें देने वाला था। पचास
हजार कारों का उत्पादन किया जाना था—अक्टूबर 1973 तक 10,000 और 25,000
1974 में, और बाकी बाद में। हालाँकि, एक भी कार का निर्माण नहीं हुआ।
संजय की मृत्यु के बाद ही इंदिरा ने जापान में सुजुकी के साथ समझौता किया था।
आज भारतीय सड़कों पर दिखाई देने वाली मारुति कारों के उत्पादन के लिए। 14 तारीख को
दिसंबर 1983 में, जब एक छोटी सी सफेद मारुति 800 एक कारखाने से निकली...
गुड़गांव में, उन्होंने नए उद्यम के अधिकारियों को संबोधित करते हुए ऐसी आवाज में बात की कि
भावनाओं से चूर हो गया।

जब छोटी कार परियोजना सफल नहीं हुई, तो संजय ने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ दिया।
राजनीति पर ध्यान देना। अट्ठाईस साल की उम्र में, उन्होंने कहा कि वह बदलाव लाना चाहते हैं।
देश। इंदिरा गांधी ने उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने वस्तुतः उन्हें पूरी छूट दे दी।
1975 से कांग्रेस संगठन के। लेकिन यह केवल तभी संभव हुआ जब
जून 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद संजय का
राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भागीदारी वास्तव में स्पष्ट होने लगी।
■

12 जून 1975 वह दिन था जब इंदिरा गांधी और पूरा देश...
उसे लंबे समय तक याद रहा। 11 जून को पूरे दिन वह बेचैन रही थी।
और वह थकी हुई लग रही थी। उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी थी।
संसद सदस्य के रूप में उनके चुनाव को चुनौती देना अगले महीने होने वाला था।
दिन। इससे मुसीबत खड़ी हो सकती है।
दिन की शुरुआत अशुभ संकेत के साथ हुई थी। सुबह 6 बजे के कुछ देर बाद, वह
उन्हें डी. पी. धर के निधन की खबर मिली। वे तुरंत गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल पहुंचीं।
जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। वे इंदिरा के दल का हिस्सा थे।
कोर टीम के सदस्य के रूप में, उन्हें मॉस्को में भारत के राजदूत के पद पर तैनात किया गया था, और वे एक
अंत के समय वह दिल्ली गई थीं। अस्पताल में उन्होंने कार्यभार संभाला।
उन्होंने स्वयं अंतिम संस्कार के बारे में निर्देश दिए। सुबह 10:05 बजे
वह खबर जिसका वे सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंदिरा के सूचना सलाहकार एच. वाई.
शारदा प्रसाद प्रधान सचिव पी. एन. धर के कमरे में जबरदस्ती घुस गए।
साउथ ब्लॉक। 'इलाहाबाद का फैसला आ गया है और प्रधानमंत्री

उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, 'मंत्री को पद से हटा दिया गया है।' धर दौड़कर चले गए।
प्रधानमंत्री आवास। खबर पहले ही फैल चुकी थी; कांग्रेस नेताओं ने शुरुआत कर दी थी।
1, सफदरजंग रोड पर इकट्ठा होने के लिए। जो लोग पहले से वहां मौजूद थे, वे बंट गए थे।
उन्होंने खुद को दो समूहों में बांट लिया। एक समूह कानूनी निहितार्थों पर चर्चा कर रहा था।
फैसले के राजनीतिक नतीजों पर चर्चा हो रही थी। दूसरा समूह इस फैसले के राजनीतिक नतीजों पर चर्चा कर रहा था।
दबी हुई आवाज़ में।
कानून मंत्री एच. आर. गोखले के नेतृत्व में कानूनी समूह गहन अध्ययन कर रहा था।
प्रख्यात वकील नानी के साथ फैसले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।
पालखीवाला और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय,
जिन्हें इंदिरा गांधी ने एक दिन पहले दिल्ली बुलाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय
अदालत ने उन्हें चुनाव में धांधली का दोषी ठहराया था।
1971 के चुनाव में रायबरेली लोकसभा सीट; उनकी पराजित प्रतिद्वंदी,
दिग्गज समाजवादी राजनेता राज नारायण ने उनकी जीत को चुनौती दी थी।
न्यायालय ने उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।
1951 में, उसने एक सरकारी कर्मचारी, यशपाल कपूर, जो एक अधिकारी था, का इस्तेमाल किया था।
प्रधानमंत्री सचिवालय में विशेष कर्तव्य (ओएसडी) के रूप में, उनके चुनाव के बाद
एजेंट। फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति जगनमोहन सिन्हा ने कहा था कि
इसके अलावा, उन्हें संसद में भाग लेने और किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया।
छह साल। अब इंदिरा को इस फैसले के खिलाफ अपील करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट।
कांग्रेस अध्यक्ष डी. के. बरुआ ने इस बात पर विस्तार से चर्चा की कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए।
राजनीतिक परिणाम। इंदिरा गांधी दोनों समूहों के बीच घूम रही थीं, देख रही थीं

‘असंवादी और अलग-थलग’। सुबह करीब 10:30 बजे, वह संजय और आर.के. धवन के साथ एकांत में बातचीत करने लगीं। इसके बाद धवन बाहर आ गए।
मीटिंग के बाद वह पूरी तरह से सक्रिय हो गया। उसने फोन पर खूब काम किया—और
उन्होंने पार्टी नेताओं को अपने समर्थन में प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया। जल्द ही
बंसी लाल भी उनके साथ शामिल हो गया। उसने भी फोन करना शुरू कर दिया और अपने डिप्टी को आदेश देने लगा।
हरियाणा में जनभावना जुटाने के लिए आयुक्तों को नियुक्त किया गया है।
पार्टी के कुछ नेताओं ने उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दी। 'जिस दिन
इलाहाबाद का फैसला आ गया... मैंने उससे कहा कि शायद यह अच्छा होगा
उनके लिए यह सुझाव दिया गया कि वे इस्तीफा दे दें और अपना इस्तीफा राष्ट्रपति फखरुद्दीन को भेज दें।
‘अली अहमद,’ अनुभवी सांसद करण सिंह ने मुझे बताया।
उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति हमेशा उनके प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं और पूछ सकते हैं
उन्हें 'सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने तक' पद पर बने रहने की अनुमति दी गई है।
इससे उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। 'उसने एक शब्द भी नहीं कहा (सचमुच)।
प्रतिक्रिया),’ सिंह ने याद किया। ‘लेकिन (स्पष्ट रूप से) उसे यह बहुत पसंद नहीं आया।’
अगर उन्होंने कभी इस्तीफा देने के बारे में सोचा भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला सुलझ जाएगा।
अपना फैसला सुनाते ही उसने इसे तुरंत खारिज कर दिया। दो समूह थे जो
वे नहीं चाहते थे कि वह इस्तीफा दे। एक समूह का नेतृत्व मोनूदा (सिद्धार्थ) कर रहे थे।
शंकर राय) सहित, और इसमें डी. के. बरुआ और एच. आर. गोखले शामिल थे,’ करण
सिंह ने कहा, ‘दूसरा समूह संजय का था, जिसमें खुद संजय शामिल थे।’
V. C. Shukla, Om Mehta, and Bansi Lal.’

जनता पार्टी के नेता शांति भूषण, जो राज नारायण के भी समर्थक थे
वकील ने बाद में आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने न्यायाधीश को प्रभावित करने की कोशिश की थी।
सिन्हा। फैसले से कुछ दिन पहले, मुख्य न्यायाधीश ने
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी.एस. माथुर अपनी पत्नी के साथ गए थे।
न्यायमूर्ति सिन्हा से मिलें। उन्होंने सिन्हा को बताया कि इंदिरा ने पदोन्नति देने का फैसला किया था।
मामले का फैसला सुनाने के बाद उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में भेजा गया। मुख्य न्यायाधीश
माथुर को यह संदेश उनके रिश्तेदार डॉ. के. पी. माथुर ने दिया था।
जो इंदिरा गांधी के निजी चिकित्सक थे। हालाँकि, न्यायमूर्ति सिन्हा का मजबूत
भूषण ने खुलासा किया, 'उनकी अंतरात्मा ने उन्हें प्रलोभन में आने की अनुमति नहीं दी।'
भूषण ने कहा कि उन्हें यह बात खुद जस्टिस सिन्हा ने बताई थी, जब वे
कई साल बाद दोनों इलाहाबाद में गोल्फ खेल रहे थे।
12 जून 1975 के समाप्त होने से पहले एक तीसरा झटका अभी आना बाकी था।
शाम को, राज्य में हाल ही में हुए चुनावों के परिणाम घोषित किए जाएंगे।
गुजरात विधानसभा में सभा में उपस्थित होने वालों की भीड़ उमड़ने लगी। कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा।
जनता मोर्चा, विपक्षी दलों का एक अनौपचारिक संयुक्त गठबंधन है।
यह खबर इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ा झटका थी। इससे पता चला कि वह अपना प्रभाव खो रही थीं।
■

किसी अदालती फैसले से इतिहास का परिवर्तन होना असामान्य और दुर्लभ है।
देश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने यही किया। इंदिरा
उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अवकाशकालीन न्यायाधीश ने...
न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर ने न्यायमूर्ति सिन्हा के फैसले पर सशर्त रोक लगा दी।

आदेश। इसने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी। लेकिन वह
संसदीय कार्यवाही में भाग लेने या मतदान करने से प्रतिबंधित
संसद सदस्य का वेतन।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को फैसले पर रोक लगा दी। एक दिन बाद,
25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की।
संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश को इस आधार पर कि
आंतरिक अशांति ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया—और वह
स्थिति से निपटने के लिए उसने कुछ शक्तियां ग्रहण कर लीं। उसी रात देर से, उसने
उन्होंने अपने सहायक आर. के. धवन को राष्ट्रपति भवन में एक मसौदा लेकर भेजा।
राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाला दस्तावेज।
राष्ट्रपति ने रात 11.45 बजे आपातकालीन आदेश पर हस्ताक्षर किए।
मंत्री ने इसे मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया;
यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। मंत्रिमंडल ने अगली सुबह इसकी पुष्टि कर दी।
न तो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने और न ही कैबिनेट सचिव, बी. डी.
पांडे और उनके प्रधान सचिव पी. एन. धर को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि
क्या हुआ था।
वह यही करने की योजना बना रही थी। उन्हें तड़के बुलाया गया था।
26 जून 1975 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सुबह का समय।
पांडे ने वर्षों बाद याद करते हुए बताया कि बैठक 'सुबह 5 या 6 बजे' हुई थी।
जहां उन्हें आपातकाल के बारे में बताया गया।
उन्हें आपातकालीन विकल्प चुनने की सलाह देने वालों में से सबसे महत्वपूर्ण
आवाज संजय गांधी की थी। 'संजय का मुझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव था।
करण सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा, 'आपातकाल का विकल्प चुनने का उनका निर्णय।'
25-26 जून की रात को इंदिरा गांधी ने अधिकांश लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं में जयप्रकाश भी शामिल थे।
Narayan, Morarji Desai, Charan Singh, Atal Bihari Vajpayee, L. K.
आडवाणी, चंद्र शेखर और कई अन्य। इनमें से कई लोगों के पास
उन्होंने आज शाम दिल्ली के राम लीला मैदान में एक रैली को संबोधित किया।

25 जून। उनके इस्तीफे की मांग करते हुए जेपी ने गरजते हुए कहा था, 'सिंहासन खाली'।
karo ki janata aati hai (Vacate the throne, the people are now here)'—
प्रसिद्ध हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों का उद्धरण देते हुए।
जेपी ने पुलिस और सशस्त्र बलों से अपील की थी कि वे आदेश का पालन न करें।
सरकार के 'अवैध और अनैतिक' आदेशों के खिलाफ पुलिस जेपी को पकड़ने आई थी।
सुबह 3 बजे। वह गांधी शांति फाउंडेशन में ठहरे हुए थे और बहुत देर से सोए थे। उन्हें जगाकर बताया गया कि पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद हैं।
उसे ले जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। जवाब में, उसने केवल चार शब्द कहे—
quoting the Chanakya niti: 'Vinash kale vipreet buddhi (When the
विनाश का समय आ जाता है, मन गलत दिशा में काम करने लगता है
दिशा)।'
इंदिरा गांधी ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू की और उसके सदस्यों के निलंबन का आदेश दिया।
नागरिक स्वतंत्रताएँ। उन्होंने अनेकों कानून और संवैधानिक प्रावधान लागू किए।
मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए संशोधन। इनमें आदेश शामिल था।
कठोर आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम, 1971 के तहत,
(एमआईएसए) जिसके तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए आधार बताने की आवश्यकता नहीं होती है।
इसके अलावा संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 भी था।
जिसने आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया और किसी भी चीज़ को प्रधानमंत्री से संबंधित मामले न्यायालयों के दायरे से बाहर हैं।
अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करने वाला राष्ट्रपति का आदेश था
पारित हो गया, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार निलंबित कर दिया गया।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। लोकसभा का कार्यकाल था।

इसे दो बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया, पहली बार फरवरी 1976 में, और फिर दोबारा
नवंबर 1976 (मार्च 1978 तक)।
इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए कदम कठोर और निरंकुश थे।
'जब मैं तानाशाह नहीं था, तब भी आप मुझे तानाशाह कहते रहे हैं। अब हां, मैं तानाशाह हूं।'
उन्होंने 22 जुलाई 1975 को संसद में यह बात कही। उनका बयान भेजा गया था।
समाचार एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)। लेकिन इसमें पांच लोगों की मौत हो गई।
कुछ मिनट बाद सेंसर द्वारा।
आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने उनकी ओर से सारी बागडोर संभाली।
चापलूसी करने वाले मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महत्वाकांक्षी नेता आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।
एक-दूसरे को उसकी चापलूसी करने के लिए मजबूर करते थे। वही सब कुछ नियंत्रित करता था और सबके साथ कठोर व्यवहार करता था।
लेकिन अधिकांश कांग्रेसी सदस्य अपमान सहते रहे और चुपचाप उसे बर्दाश्त करते रहे।
धक्का-मुक्की की गई।
संजय ने युवा कांग्रेस के सदस्यों को अपनी आक्रामक सेना के रूप में इस्तेमाल किया।
His core team included Kamal Nath, Jagmohan, V. C. Shukla, Bansi Lal,
ओम मेहता, जगदीश टाइटलर, और नवीन चावला; अकबर डम्पी अहमद
बाद में उनसे जुड़ने वाला था। संजय की मनमानी ने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित किया।
नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वित्त मंत्री सी. सुब्रमण्यम का पदावनति कर दिया।
जो 1969 के विभाजन के दौरान इंदिरा गांधी के साथ रहे थे। उन्होंने एक भाषण दिया।
इसके बजाय उन्होंने अपने कनिष्ठ प्रणब मुखर्जी को आगे बढ़ाया, जिन्होंने समर्थन

किया।
आपातकाल। (हालांकि, मुखर्जी ने बाद में कहा कि आपातकाल
(इसे टाला जा सकता था।)
इंदिरा गांधी के लंबे समय से वफादार रहे आई. के. गुजराल के प्रति उनका व्यवहार इस उद्देश्य से था कि
यह अन्य पार्टी नेताओं के लिए एक संदेश होना चाहिए। इलाहाबाद के तुरंत बाद
फैसले के बाद, संजय ने गुजराल को तलब किया, जो सूचना अधिकारी थे और
उस समय के प्रसारण मंत्री। 'ऑल इंडिया रेडियो नहीं है'
'आप इंदिरा गांधी को काफी हद तक पेश कर रहे हैं,' उन्होंने गुजराल को तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। 'आप...
ऑल इंडिया रेडियो का सही ढंग से संचालन नहीं हो रहा है। सभी (AIR) समाचार बुलेटिन
संजय ने गुजराल को निर्देश दिया, 'इसे पहले मेरे पास भेजा जाना चाहिए।'
मैं इन्हें तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा, मैं इन्हें तुम्हारी माँ के पास भेजूंगा।
गुजराल ने पलटवार किया। उन्होंने आगे कहा, ‘आप मेरे बेटे की उम्र के हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए।’
तो फिर आपको मुझसे सम्मानपूर्वक बात करनी होगी।'
लेकिन इंदिरा ने अपने बेटे का साथ दिया। उन्होंने गुजराल से कहा, ‘सूचना एवं प्रसारण एजेंसी अब नहीं रही।’
आपको पसंद आएगा। प्रेस को सख्ती से संभालना होगा।' जिस दिन
आपातकाल लागू किया गया, गुजराल को सूचना विभाग से बर्खास्त कर दिया गया और
प्रसारण मंत्री वी.सी. शुक्ला ने पदभार संभाला; बाद में उन्हें पदभार ग्रहण करना था।
शाह आयोग द्वारा गुजराल को 'मध्ययुगीन तानाशाह' करार दिया गया था।
कम महत्वपूर्ण योजना मंत्रालय में निर्वासित कर दिया गया और बाद में भेज दिया गया
मॉस्को में राजदूत।
Sanjay then sent Congress leader K. D. Malviya—Bhaiji as he was

सर्वत्र बुलाया गया—लखनऊ में एच. एन. बहुगुणा से बात करने के लिए, जो इसके लिए जाने जाते हैं
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पर उनकी पकड़। 'संजय आपको भेजना चाहता है।'
ambassador to Australia,’ Bhaiji told Bahuguna. Bahuguna was
क्रोधित। 'जब मैंने कुमाऊं में अपना गांव छोड़ा, तो मैं यह करने के लिए आया था।'
बहुगुणा ने पलटवार करते हुए कहा, 'किसी की नौकरी करना राजनीति है, न कि काम करना।' अगला
अगले दिन संजय ने उसके पास एक और दूत भेजा, इस बार एक होटल का मालिक।
क्रोधित बहुगुणा का जवाब वही था। 'उनसे कह दो कि मैं गुजराल नहीं हूँ।'
उसके बाद, बहुगुणा को पार्टी में दरकिनार कर दिया गया।
संजय का अंदाज़ दबंग था। उन्होंने तारिक अनवर को बुलाया था।
वे बिहार से दिल्ली आए हैं, जहाँ वे एक युवा पत्रिका 'यूथ कांग्रेस' का संपादन करते थे।
chala sakoge kya (Can you run the Youth Congress)?’ he asked Anwar
उसके आते ही अचानक।
तारिक ने सिर हिलाया।
मैं आपको युवा कांग्रेस का राज्य सचिव बनाना चाहता हूँ।
बिहार।
अनवर ने याद करते हुए कहा, ‘मीटिंग दो मिनट तक चली। उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं।’ ‘
मुझे बैठने के लिए कहो।'
अनवर अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बिहार लौट आया।
संजय का स्वभाव भी गुस्सैल था—इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह क्या था।
किसी वरिष्ठ मंत्री या कनिष्ठ पदाधिकारी से निपटना। एक बार, वह और वीर
संजय सिंह के वफादार बहादुर सिंह, जो बाद में मुख्यमंत्री बने।
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से होते हुए गाड़ी चला रहे थे। संजय गाड़ी चला रहा था।
कई गलत मोड़ लेने के बाद, वे बुरी तरह से रास्ता भटक गए थे।

‘अब हम किस तरफ जाएं?’ चिड़चिड़े संजय ने पूछा।
‘मुझे नहीं पता,’ अनिश्चित भाव से वीर बहादुर ने उत्तर दिया।
संजय ने गाड़ी रोक दी। उसने वीर बहादुर को बाहर निकलने को कहा।
दरवाजा बंद करके वह गाड़ी चलाकर चला गया, और वीर बहादुर को सदमे में वहीं छोड़ गया।
ऐसा निर्जन जंगल जहां दूर-दूर तक कोई मानवीय बस्ती नजर नहीं आती।
उसका नाम ही भय पैदा करता था, क्योंकि वह राज्य की क्रूर शक्ति का प्रयोग करता था।
संजय गांधी ने ‘सुधार’ के लिए पांच सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
देश—परिवार नियोजन, दहेज उन्मूलन, वृक्षारोपण, वयस्क
शिक्षा और जाति व्यवस्था का उन्मूलन। हर जगह
लोगों को संदेश देने वाले होर्डिंग्स लगाए गए थे: 'कम बोलो और काम करो'
और भी बहुत कुछ। उन्होंने राजधानी में निर्मम 'सुंदरीकरण अभियान' शुरू किए।
इनमें सबसे कुख्यात घटना अप्रैल 1976 में तुर्कमान गेट के पास हुई थी।
प्रतिष्ठित जामा मस्जिद। बुलडोजरों ने 150 पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया, जिससे लोग विस्थापित हो गए।
परिवार, जिनमें महिलाएं चीख रही थीं और बच्चे रो रहे थे।
उन्हें उनके जीवन भर के घरों से 24 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया।
जानें चली गईं। लोग जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात करने से भी डरते थे।
प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, मीडिया में शायद ही कुछ प्रकाशित होता था।
संजय गांधी की परिवार नियोजन नीति को लेकर भारी असंतोष था।
यह कार्यक्रम जबरन नसबंदी का एक नरम पर्याय है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1976 में 70 लाख से अधिक पुरुषों की नसबंदी की गई थी।
किसानों को दबाव में बंध्याकरण कराने के मामले सामने आए थे;
उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी पानी और बिजली काट दी जाएगी।
इसके आगे झुकना नहीं था। पिताओं को बताया गया कि उनके बच्चों को इससे कोई लाभ नहीं होगा।

यदि वे नसबंदी कराने से इनकार कर देते थे तो उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ट्यूबेक्टॉमी की जाती थी।
यह प्रयोग महिलाओं पर भी किया गया।
जल्द ही लोगों की निराशा और भय गुस्से में बदलने लगे।
1976 के अंत तक, जब मैंने दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र का दौरा किया और
लोग दबी आवाज़ में कहने लगे थे, 'पुनर्वास बस्तियाँ', 'चलो
चुनाव होने दो और हम उन्हें सबक सिखाएंगे।' लेकिन फिर भी
आपातकाल शासन के विरोधियों को तब गहरा सदमा लगा जब इंदिरा गांधी
18 जनवरी 1977 को अचानक चुनावों की घोषणा की गई—देश
मार्च के तीसरे सप्ताह में मतदान होगा।
छठी

इंदिरा गांधी का जनवरी में चुनाव घोषित करने का अप्रत्याशित निर्णय
1977 का वह दौर, जिसके कारण उन्हें भयावह हार का सामना करना पड़ा, आज भी पर्यवेक्षकों को उत्सुक बनाए रखता है।
चार दशक से भी अधिक समय बाद। यह एक ऐसे विवाद का विषय है जो अभी तक जारी है।
मामला शांत हो गया। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो उसके लिए ऐसा करने का कोई ठोस कारण नहीं था।
उन्होंने चुनाव का विकल्प तब चुना जब उन्होंने चुना। वह पूरी तरह से सत्ता में थीं। कानूनी तौर पर,
इसके अलावा, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने में अभी पंद्रह महीने बाकी थे।
समाप्त।
संजय गांधी अपनी मां के फोन करने के फैसले के सख्त खिलाफ थे।
चुनाव। जनता पार्टी की व्यापक जीत के पांच दिन बाद,
संजय ने अपने दोस्त को बताया, "298 सीटें और 43.4 प्रतिशत मत।"
और विश्वासपात्र डम्पी अहमद ने कहा, 'इसमें शामिल होना कितनी बड़ी गलती साबित हुई है!'
चुनाव।' चुनाव कराना न केवल एक गलती थी, बल्कि यह

मार्च 1977 में उन्हें आयोजित करना और भी बड़ी गलती थी।
'संजय मैटाडोर चला रहा था और मैं आगे की सीट पर बैठा था।'
डम्पी ने याद करते हुए कहा, 'हम मारुति फैक्ट्री से आ रहे थे।'
हरयाणा।'
‘मैंने मम्मी से कहा था,’ संजय ने डम्पी से कहा, ‘कि इन लोगों को छोड़ दें।’
(जेल से) फरवरी में रिहा हों और फिर मानसून के बाद चुनाव कराएं।
या तो अक्टूबर में या नवंबर में। मैंने कहा था कि तब तक वे लड़ रहे होंगे।
बिल्लियों और कुत्तों की तरह... लेकिन मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी।'
संजय जिन 'लोगों' का जिक्र कर रहे थे, वे विपक्ष के लोग थे।
वे नेता जिन्हें इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिया था—
और चुनाव की घोषणा के बाद इसे जारी किया गया।
संजय और डम्पी दून स्कूल में साथ पढ़ते थे। उनकी मुलाकात हुई थी।
फरवरी 1977 में लखनऊ में एक संयोग हुआ। कुछ ही दिनों में डम्पी वहाँ पहुँच गया।
अमेठी में, जहाँ से संजय लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे।
मैं लखनऊ के हजरतगंज स्थित खादी भंडार गया और मैंने खरीदा
तीन सफेद पायजामा और तीन सफेद कुर्ते।
पजामा ग्यारह रुपये का था और कुर्ते...
प्रत्येक तेरह रुपये का।
‘क्या आपको गांधी टोपी भी चाहिए?’ विक्रेता ने पूछा।
मदद करते हुए। 'यह दो रुपये का है।' डम्पी ने फैसला किया कि टोपी पूरी तरह से ठीक नहीं है।
यह उनके अंदाज के अनुरूप था। जब डम्पी ने संजय की मदद करने के लिए राजनीति में शामिल होने का फैसला किया, तो उनका
पिता ने उसे चेतावनी दी, 'अगर तुम जाओगे, तो अगले पांच साल बिताने के लिए तैयार रहना।'
जेल में।’ जून 1980 में संजय की मृत्यु तक डम्पी उनके साथ ही रहे।
और उन्हें गांधी परिवार के घर में बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने की अनुमति मिल गई।
संजय की तरह, उसके अधिकांश अन्य मित्र भी इसके विरोध में थे।

चुनाव। इनमें बंसी लाल और इंदिरा के निजी सहायक आर.के. शामिल थे।
धवन। 'लेकिन इंदिरा गांधी अपनी बात पर अड़ी रहीं।'
मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के तीन दिन बाद,
संजय ने भविष्यवाणी की कि सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। 'मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि...'
उन्होंने डम्पी से उस दिन कहा, 'जनता सरकार तीन साल तक चलेगी।'
मारुति कार्यालय से वापस आते समय। जनता नेताओं ने उन्हें साबित कर दिया।
गलत। वे महज अट्ठाईस महीनों में ही ध्वस्त हो गए।
■

राजनीतिक विश्लेषक, शिक्षाविद और मीडिया लगातार नए विचार प्रस्तुत करते रहते हैं।
इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद क्यों चुना, इसके वास्तविक कारण को लेकर कई परिकल्पनाएं हैं।
चुनाव।
उदारवादी यह मानना पसंद करते हैं कि नेहरू की बेटी ने जीत हासिल की थी।
संजय की मां के ऊपर। उन्होंने चुनाव में भाग लेने का विकल्प चुना था क्योंकि वह चाहती थीं
आपातकाल को समाप्त करने के लिए। इसने एक लोकतांत्रिक व्यक्ति के रूप में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया था, और
वह तानाशाह के रूप में देखी जाना पसंद नहीं करती थी। और वह भी, एक संतान के रूप में...
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, नेहरू की विरासत के कुछ अंश कहीं न कहीं शेष रह गए थे।
उसके मन में ये भावनाएँ बसी रहीं। पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में उसके निजी मित्र, जैसे कि
अमेरिकी फोटोग्राफर डोरोथी नॉर्मन, जिनसे वह विशेष रूप से प्रभावित थीं।
जो उसके करीब थे, वे उससे दूर हो गए थे; यह बात उसे बहुत बुरी लगी।

उसके साथ दुनिया भर की यात्रा करते समय मुझे उनमें से कई लोगों से जान-पहचान हो गई थी।
पिता जवाहरलाल नेहरू, एक कट्टर लोकतंत्रवादी थे।
ऐसा लगता है कि उसने नवंबर 1976 से कई लोगों को यह बात बताई थी।
आगे चलकर—उनमें उनकी सूचना सलाहकार एच. वाई. शारदा भी शामिल थीं।
प्रसाद और प्रधान सचिव पी. एन. धर ने यह बताया कि उनके द्वारा मना किए जाने के बावजूद, प्रसाद और प्रधान सचिव पी. एन. धर ने कहा कि ...
उसे पता था कि वह आईबी में 340 सीटें जीतेगी, लेकिन वह हार जाएगी।
फिर भी चुनाव होने वाले थे। माइकल फुट,
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता, जिनके लिए
उन्हें गहरा आदर था, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पिता (एच. वाई. शारदा) की ओर इशारा किया।
Prasad),' Ravi Visvesvarya Sharada Prasada was to reveal, that 'Indira
गांधी यह जानते हुए भी चुनाव कराने का आह्वान करती थीं कि वह हार जाएंगी।
जाहिर तौर पर, उन्होंने अपने अच्छे दोस्त अमेरिकी सीनेटर चार्ल्स पर्सी को भी यह बात बताई।
उन्हें डर था कि वह चुनाव बुरी तरह हार जाएंगी और वह चिंतित थीं।
अपने बेटे संजय गांधी के बारे में।

जनता पार्टी के नेता चंद्र शेखर अपने समर्थकों से कहा करते थे
अगर वे इंदिरा गांधी का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, तो उन्हें 'ये गोरे लोगों से' लिखवाओ (इसे विदेशी संवाददाताओं से लिखवाओ)।' एक लेख में
न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख से वह राष्ट्रीय दैनिक में छपे लेख से कहीं अधिक प्रभावित होती।
या किसी विपक्षी नेता का भाषण। और फिर भी, आलोचनात्मक राय के बावजूद।
पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में उसके दोस्तों का उस पर असर पड़ता, ऐसा नहीं है।
मानो उसे भारत के खिलाफ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा हो। कई विदेशी नेताओं ने

उन्होंने अपने आपातकालीन कदम का बचाव किया। आर्थिक स्थिति
देश की स्थिति में भी सुधार हुआ था। विश्व बैंक उससे प्रभावित था।
औद्योगिक संबंधों का प्रबंधन; छह दाता देशों ने भारत को ₹9.39 भेजे
भारत को अरबों डॉलर की विदेशी सहायता मिली, जो उसे 1967-68 के बाद से नहीं मिली थी।
विदेशी मुद्रा भंडार 1974-75 में ₹9.69 बिलियन से लगभग दोगुना हो गया।
1975-76 में यह बढ़कर ₹18.69 बिलियन हो गया।
दूसरी परिकल्पना पुपुल जयकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जयकर
उन्होंने इस बात का आध्यात्मिक स्पष्टीकरण दिया कि इंदिरा गांधी ने ऐसा करने का निर्णय क्यों लिया।
चुनाव. उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरु जिद्दू कृष्णमूर्ति,
जिनसे इंदिरा अक्सर मिलती थीं, और जिन पर जयकर को भरोसा था,
influenced her. Indira had met Krishnamurti in Jayakar's house on 28
अक्टूबर 1976। व्याकुल इंदिरा ने कृष्णमूर्ति से कहा था कि उसने ऐसा किया था।
उसे यह नहीं पता था कि जिस बाघ पर वह सवार थी, उससे कैसे उतरना है।
कृष्णमूर्ति ने उसे सलाह दी, 'सही कर्म करना आवश्यक है, यह अनिवार्य नहीं है।'
परिणाम चाहे जो भी हो।' और जब वह जाने लगी, तो उसने उससे कहा, 'करो!
आपको एहसास होता है कि यदि आप सही तरीके से काम करेंगे, तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा।
परिणाम?' जयकर ने बाद में लिखा: 'यह 28 अक्टूबर (1976) को हुआ था कि एक
इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल समाप्त करने और मांग करने के लिए एक कमजोर आंदोलन उभरा।
चुनाव चाहे जो भी परिणाम हो।
तीसरा कारण—वह बढ़ते दबाव को लेकर चिंतित थी।
विनोबा भावे जैसे उनके कट्टर समर्थकों से
और सीपीआई (एम)। अक्टूबर 1976 तक, सीपीआई ने भी अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी थीं।
संजय के परिवार नियोजन उपायों और सौंदर्यीकरण की आलोचना

अभियान चलाए गए और उन्होंने चुनावों को एकमात्र समाधान के रूप में बताया।
जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, भावे ने आपातकाल का समर्थन किया था।
अनुशासन का युग। भावे के सहयोगी गौतम बजाज के अनुसार,
भावे ने अपने आश्रम में अठ्ठावन साल बिताने के बाद आग्रह करना शुरू कर दिया था।
उन्हें सितंबर 1975 की शुरुआत में ही जेपी को रिहा करने और चुनाव कराने के लिए कहा गया था।
'क्या आप अंततः फरवरी 1977 तक चुनाव कराएंगे?' भावे
उन्होंने उससे पूछा, जब इंदिरा गांधी 24 फरवरी 1976 को उनसे मिलने गई थीं।
उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा, 'यह कहना मुश्किल है। हमने चुनाव स्थगित कर दिए हैं।'
एक साल के भीतर... लेकिन देश के सामने मौजूद खतरा अभी टला नहीं है।
आप अगले साल फरवरी में चुनाव कराने का फैसला क्यों नहीं करते?
(1977) में, भावे ने लगातार उसे एक निश्चित समय सारणी पर बांधने की कोशिश की।
वह लोगों को रिहा करके सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकती थी।
अक्टूबर (1976)...' स्वयं।
'पिछले साल 25-26 जून को आपातकाल लागू करने के बाद से, आपने
उन्होंने सुझाव दिया, 'इसे इस साल (1976) 25 जून को उठाया जा सकता है।'
उसने उसे बताया कि उसने ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचा था। लेकिन
15 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या
अगस्त 1975 ने उसे पूरी तरह से रोक दिया। उसे डर था कि कहीं वह भी उसी स्थिति में न पहुँच जाए।
हत्या कर दी गई।
'इंदिरा गांधी को विनोबाजी के प्रति आदर और स्नेह था,'
बजाज ने कहा, 'लेकिन उनके विचारों के प्रति कोई वास्तविक प्रतिबद्धता नहीं है।'
चौथा कारक—और कुछ लोगों का मानना है कि यही उसके इस कदम का असली कारण है।
—वह खुद संजय था। उसका छोटा बेटा बेकाबू होता जा रहा था।
और वह अपने आप में एक कानून था। 27 जुलाई 1976 को संजय ने कुछ ऐसा

किया जिसने सबको चौंका दिया।
उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आपातकाल के एक साल बाद, उन्होंने सीपीआई की आलोचना की, जो कि...
उनकी सरकार का समर्थन करते हुए, उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ खुलकर बात की।
उस यूनियन ने आपातकाल का समर्थन किया था। उन्होंने एक साक्षात्कार दिया।
सर्ज पत्रिका, जिसका उद्देश्य अमेरिकियों को प्रसन्न करना था। संजय
समाजवादी अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दीं, बड़े व्यवसायों की प्रशंसा की और कहा कि
सार्वजनिक क्षेत्र के पतन के लिए। प्रतिकूल प्रतिक्रिया के डर से
सीपीआई और रूसियों के बीच हुई झड़पों से इंदिरा इतनी उत्तेजित हो गईं कि उन्होंने अपना हाथ खींच लिया।
प्रधान सचिव पी. एन. धर को एक महत्वपूर्ण पारिवारिक समारोह में भाग लेने के लिए जाना पड़ा।
नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश। धर के आने का बेसब्री से इंतजार करते हुए, उसने
उसने अपने हाथ से दो पन्नों का एक नोट लिखकर उसे संक्षिप्त जानकारी दी।
उसे क्या करना चाहिए। धर ने बाद में लिखा, 'यह एक साहसिक प्रयास था (द्वारा) संजय) ने प्रधानमंत्री को दरकिनार कर दिया।' इससे पता चला कि संजय के पास 'ड्राइवर की सीट के लिए अधीर हो जाना'।
आपातकाल को 'आसानी से' लागू करने के बाद, और एक
युवा कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठन सीधे उनके अधीन होते हैं।
नियंत्रण स्थापित करने के दौरान, संजय ने मुख्यमंत्रियों से संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया था।
और अन्य देशों के साथ अपनी माँ का जिक्र किए बिना। उसने सोचा।
उनकी मां 'अस्थिर स्वभाव की' थीं और केवल तभी कार्रवाई करती थीं जब उन्हें 'किसी दबाव' का सामना करना पड़ता था।
'मजबूत दृढ़ विश्वासों वाला व्यक्ति'—वह। 'मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था...कि इंदिरा अपने बेटे से डरी हुई थी,' पी. एन. धर ने लिखा। संजय था

वह खुद ही कानून बन रहा है। लेकिन उसकी अपनी समस्याएं चाहे जो भी हों।
इंदिरा गांधी उनसे 'उनके बारे में एक भी आलोचनात्मक शब्द सुनना नहीं चाहती थीं'।
अन्य।
1976 के अंत में, संजय ने निर्णय लिया कि संविधान
इसमें बदलाव होना चाहिए और राष्ट्रपति प्रणाली होनी चाहिए।
सरकार। हालाँकि इंदिरा गांधी ने इस विचार पर विचार किया था।
संविधान पर पुनर्विचार करते हुए, सार्वजनिक रूप से वह दुविधापूर्ण रुख अपनाती रही थीं।
इसके बारे में। 1976 के मध्य में, उन्होंने कांग्रेस नेताओं डी. के. बरुआ से पूछा था,
रजनी पटेल और सिद्धार्थ शंकर राय—ये तीनों ही
उन्होंने उसे कानूनी और संवैधानिक मामलों पर सलाह दी—इस मुद्दे की जांच करने के लिए।
उन्होंने उसे एक पत्र भेजा, जिसमें एक नए संविधान के गठन की सिफारिश की गई थी।
संविधान सभा राष्ट्रपति प्रणाली की ओर अग्रसर होगी
सरकार। यह लेख वास्तव में - और गुमनाम रूप से - लिखा गया था।
ए. आर. अंतुले द्वारा। बरुआ ने अखबार लीक किया; संजय और उनकी टीम
इस मुद्दे को उठाया गया और उनमें से कुछ ने मौजूदा संसद को भंग करने की मांग की।
इसे संविधान सभा में परिवर्तित किया जाना था। प्रस्ताव यह था कि एक
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, जिनके पास अन्य निर्वाचित व्यक्तियों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति—लेकिन उन नियंत्रण और संतुलन के बिना जो पहले मौजूद थे
अमेरिकी प्रणाली।
अपनी मां पर दबाव बढ़ाने के लिए, संजय और उसके साथियों ने
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार की राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करेंगी।
संविधान सभा की स्थापना करना—जिससे इंदिरा गांधी बहुत अलग दिख रही थीं।
दुखी।

कुछ लोगों का मानना था कि संजय संविधान में बदलाव कर देते।
और अंततः गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। अन्य
मुझे संदेह था कि वह चुनाव को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। बंसी लाल,
उस समय संजय के सबसे करीबी व्यक्ति ने इंदिरा गांधी के चचेरे भाई बी.के. को यह बात बताई थी।
नेहरू ने कहा, 'इस चुनावी बकवास से छुटकारा पाओ...बस हमारी बहन (इंदिरा) को बचाओ।'
राष्ट्रपति आजीवन रहेंगे और इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है।'
संजय ने अपने गुट के साथ मिलकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी।
सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ। कई विश्लेषकों का मानना था कि
चुनाव ही एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे वह सत्ता पर अपनी पकड़ फिर से हासिल कर सकती थी।
सरकार।
इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पी. एन. धर ने हमेशा यही बात कही।
वह राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार के खिलाफ थीं।
इस मामले में, उन्होंने त्रिमूर्ति (जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था) को संविधान की पुनः जांच करने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? क्या वह इसका उपयोग करना चाहती थीं?
प्रधानमंत्री की शक्तियों को मजबूत करने और उनके पंख काटने के लिए किया गया अभ्यास
न्यायपालिका में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन संसद में बदलाव का सहारा लिए बिना।
क्या यह शासन प्रणाली के बारे में था? और क्या यह उनकी आलोचनाओं को टालने की एक चाल भी थी?
पश्चिमी राजधानियों में? क्योंकि धर ने भारत में अमेरिकी राजदूत को यही बताया था।
इंदिरा गांधी ने आपातकाल इसलिए घोषित किया था क्योंकि वह चाहती थीं कि...
वेस्टमिंस्टर प्रकार की बहुदलीय लोकतंत्र से दूर हटकर एक
अमेरिका में प्रचलित राष्ट्रपति शासन प्रणाली।
नवंबर 1976 तक, यानी उससे केवल दो महीने पहले,

चुनाव की घोषणा करते समय, उन्होंने वास्तव में चुनाव एक साल के लिए स्थगित कर दिए थे।
और उन्होंने इसे दूसरी बार दोहराया। यह 5 नवंबर 1976 को हुआ था।
उसी महीने, उन्हें संवैधानिक (42वां) संशोधन, 1976 प्राप्त हुआ।
लोकसभा में पारित हो गया। आपातकाल के प्रावधानों को रद्द करने के बजाय,
इस संशोधन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को व्यापक शक्तियां प्रदान कीं।
संवैधानिक वैधता की जांच करने की अदालतों की शक्ति को कम कर दिया।
कानूनों ने मौलिक अधिकारों को गैर-न्यायसंगत बना दिया और इसमें जोड़ा
संविधान के प्रति मौलिक कर्तव्य। इसे देखा गया
विपक्ष इसे 'छिपे हुए एकदलीय तानाशाही' की ओर एक कदम के रूप में देखता है।
संविधान का उल्लंघन करने के बजाय चुनावों की ओर कदम बढ़ाने के बजाय, संविधान को बहाल करने की दिशा में कदम बढ़ाना।
लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली।
1976 के अंत तक, और शायद इसी वजह से उसने यह कदम उठाने का फैसला किया होगा।
वह विपक्षी नेताओं को मनाने में काफी हद तक सफल हो रही थी।
उन्होंने 1976 की शुरुआत में उनमें से कई लोगों से संपर्क साधा था। धीरे-धीरे वे
अगर वह चुनाव कराती तो बात मान जाती। उसे नहीं लगता था कि ऐसा होगा।
इससे चुनाव में उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
‘तभी उन्होंने चुनावों के बारे में सोचना शुरू किया,’ इंदर मल्होत्रा ने कहा।
लिखा, ‘हालात को बेकाबू होने से रोकने का यही एकमात्र तरीका है।’ पोल्स
इससे उसे अपनी घटती हुई सत्ता को पुनः स्थापित करने में मदद मिल सकती है और समस्या को शुरू में ही खत्म किया जा सकता है।
संजय द्वारा राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बढ़ती मांग
और उसके साथियों।
■

1976 की शुरुआत में ही इंदिरा गांधी ने चरण से संपर्क साधना शुरू कर दिया था।

सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्र शेखर जो या तो
जेल में या नजरबंद। 1976 के अंत तक, उनमें से कुछ को नजरबंद कर दिया गया था।
सुलह का भाव।
सत्यपाल मलिक, जो उस समय चरण सिंह के युवा सहयोगी थे।
(बाद में अपने करियर में, वे जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल बने,)
गोवा और मेघालय में किए गए शोध से पता चला कि इंदिरा गांधी किस प्रकार एक निष्कर्ष पर पहुंची थीं।
मार्च 1976 में चरण सिंह के साथ हुई सहमति जिसके कारण किसान आंदोलन की शुरुआत हुई।
नेता की रिहाई 7 मार्च 1976 को हुई।
उसने मुश्किल स्वभाव वाले चरण को मनाने के लिए मलिक की सेवाएं लीं।
सिंह, जो उनकी सबसे बड़ी आलोचक थीं। फरवरी 1976 में, उन्होंने
मलिक को फतेहगढ़ जेल से स्थानांतरित किया गया, जहां वह कैद थे।
आपातकाल के दौरान, उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। मलिक के अनुसार, जब वह तिहाड़ पहुंचते ही उन्हें सीधे जेल अधीक्षक के कमरे में ले जाया गया।
उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि कांग्रेस नेता एच. के. एल. भगत उनका इंतजार कर रहे थे।
भगत ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, 'तुम्हें इसमें डाला जाएगा।'
cell next to Charan Singh. Aap baatcheet kar laen un se (You talk to
उसे)।'
प्रधानमंत्री चुनाव कराना चाहते हैं और विपक्ष को मुक्त करना चाहते हैं।
leaders,' Bhagat told Malik. 'Par woh bahar aakar upadrav na karaen
(लेकिन उनके बाहर निकलने के बाद उन्हें व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए।)
'उन्हें इस विचार से कोई आपत्ति नहीं थी,' मलिक ने चरण सिंह के बारे में कहा।
'लेकिन सत्यपाल,' चरण सिंह ने अपने युवा सहकर्मी को चेतावनी देते हुए कहा, 'मैं ऐसा नहीं करता।'

भगत पर भरोसा रखो... पहले इन लोगों से अपनी रिहाई करवा लो, फिर जाओ। और आप स्वयं श्रीमती गांधी से बात करें।'
मलिक को रिहा कर दिया गया। उन्होंने इंदिरा गांधी से मुलाकात की।
‘Hum toh haath barhate hain unki taraf (I offer my hand of
(उसकी दोस्ती के लिए),’ उसने मलिक से कहा, चरण सिंह का जिक्र करते हुए, ‘पर वो
haath peeche kar laete hain (but he is the one who pulls back).’
मलिक ने चरण सिंह को सूचना दी। ‘लेकिन मुझे रिहा नहीं किया जाना चाहिए’
'अकेले करो,' चरण सिंह ने मलिक से कहा। 'इसे 4-5 अन्य लोगों के साथ करना चाहिए।'
'तो, बीजू पटनायक, पीलू मोदी, राधाकृष्णन जैसे अन्य लोग
गांधी पीस फाउंडेशन की पुस्तकें भी लगभग उसी समय जारी की गईं।
चरण सिंह।
रिहाई के बाद, चरण सिंह ने अपने वादे पर कायम रहा।
मलिक के अनुसार, वह इंदिरा गांधी पर सार्वजनिक रूप से हमला नहीं करेंगे।
केवल एक बार ही वह जोश में आकर 'तीव्रा' बोल बैठा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 23 मार्च को दिया गया भाषण (जोरदार भाषण)।
1976 में, उनकी रिहाई के कुछ हफ़्ते बाद, जब उन्होंने चार लोगों के लिए बात की
आपातकाल पर घंटों चर्चा हुई और बताया गया कि इंदिरा गांधी ने किस प्रकार 100,000 लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया था।
सलाखों के पीछे।
कई महीनों बाद, 4 दिसंबर 1976 को, बिजू पटनायक ने...
भारतीय लोक दल में चरण सिंह के सहयोगी ने एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी की।
उनके आवास 3, औरंगजेब रोड पर एक विशेष और शानदार लंच का आयोजन किया गया।
चरण सिंह और वह व्यक्ति, ओम मेहता और मोहम्मद यूनुस भी थे।
प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र, सरकार की ओर से। हालांकि

ब्रह्मानंद रेड्डी गृह मंत्री थे, ओम मेहता मंत्री थे।
राज्य के होम के लिए, जो पहले फैसले लेता था, उसकी निकटता को देखते हुए संजय।
'मैं बाहर वाले कमरे में बैठा था,' मलिक ने याद करते हुए कहा। 'दस्तावेज़ थे
अंदर ही आदान-प्रदान किया गया।
बिजु पटनायक एक 'दृष्टिकोण पत्र' लेकर गए थे—ताकि जानकारी प्रदान की जा सके
इंदिरा गांधी और उनके बीच आपसी समझ का आधार
विपक्षी नेता। लेकिन जब कई विपक्षी नेता मिले तो
कुछ दिनों बाद, 16-17 दिसंबर को एच. एम. पटेल के घर पर, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा।
उनकी शर्तें। वे 'जिम्मेदारी से व्यवहार करने' के लिए सहमत हुए, लेकिन बदले में
सरकार को नागरिक अधिकारों को बहाल करना होगा, प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाना होगा।
और न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दें। 1 जनवरी 1977 को पटनायक
उन्होंने अपनी मांगें ओम मेहता तक पहुंचाईं और सुझाव दिया कि इंदिरा
संवाद को आगे बढ़ाएं।
इंदिरा गांधी जनसंघ के नेता अटल बिहारी पर भी काम कर रही थीं।
वाजपेयी। ओम मेहता ने दिसंबर 1976 में वाजपेयी से मुलाकात की; उन्होंने शिकायत की
that the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) boys had indulged
हिंसा और उखड़ी हुई रेल पटरियों के बीच। इस समय तक, वाजपेयी वहीं रह रहे थे।
फिरोजशाह रोड स्थित 1 नंबर के घर में नजरबंद। उनका तबादला कर दिया गया था।
बैंगलोर जेल से दिल्ली में एम्स में स्लिप डिस्क की सर्जरी के लिए ले जाया गया। वह ठीक हो गए।
निगरानी में कभी-कभार बाहर निकलना। सरकार के बारे में सुनकर
वाजपेयी और राम बहादुर राय, जो उस समय राष्ट्रीय सचिव थे, से किए गए संपर्क प्रयासों के संबंध में
एबीवीपी के सदस्य उनसे मिलने के लिए तुरंत पहुंचे। उन्हें अभी-अभी शिवपुर जेल से

रिहा किया गया था।
मध्य प्रदेश में। वाजपेयी ने एबीवीपी से माफी मांगने का सुझाव दिया।
counselled Rai, ‘Chunav karane ke liye agar khed prakat karne se
madad miltee hai, toh ABVP ko taiyaar rehna chahiye. (In order to hold
चुनावों के दौरान, यदि एबीवीपी के लिए खेद व्यक्त करना आवश्यक हो जाता है, तो उसने जिस हिंसा में लिप्तता दिखाई है, उसे ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
राय बेहद गुस्से में थे; उन्होंने इस बात से इनकार किया कि एबीवीपी किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल थी।
हिंसा। उन्होंने वाजपेयी से कहा, 'अफसोस जताने का तो सवाल ही नहीं उठता।'
‘हम खेद व्यक्त करने की बजाय हिंसा करना पसंद करेंगे।’
विपक्षी नेताओं के बीच अब माहौल बदल रहा था।
कई लोगों को लगा कि उन्हें किसी भी तरह इंदिरा गांधी को चुनाव घोषित करने के लिए राजी करना होगा।
आरएसएस ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया। यह बात आरएसएस की एक बैठक में स्पष्ट हो गई।
28-29 दिसंबर 1976 को दिल्ली में आरएसएस और एबीवीपी की बैठक हुई। इसमें निम्नलिखित लोग उपस्थित थे:
Ram Bahadur Rai, Bhanu Pratap Shukla, Ashok Singhal, Madhav Rao
मुले और बापू राव मोगे ने जेपी की इस बात का समर्थन किया कि एक प्रयास किया जाना चाहिए।
जल्दी चुनाव कराने और चारों विपक्षी दलों के लिए व्यवस्था की जाए।
विलय। 1975 में रिहा होने के बाद से, जेपी ने बार-बार फोन किया था।
विपक्षी नेताओं से एक एकीकृत पार्टी बनाने का आग्रह किया गया। इस समय तक, आरएसएस
सरकार के साथ सहयोग करने की पेशकश की थी—बशर्ते उसके जेल में बंद लोगों को

श्रमिकों को रिहा कर दिया गया।
चरण सिंह और वाजपेयी से संपर्क साधने के अलावा, इंदिरा गांधी ने भी उनसे संपर्क साधा।
उन्होंने चंद्र शेखर के पास भी अपने दूत भेजे। उन्हें हिरासत में लिया गया था।
दिल्ली के राउज़ एवेन्यू में नज़रबंद। एकमात्र नेता जिसने डटकर मुकाबला किया।
was Morarji Desai.
कई विपक्षी नेताओं के पीछे हटने का आभास होते देख इंदिरा गांधी
अब उन्हें पूरा भरोसा था कि वे चुनाव जीत जाएंगी। उनमें से अधिकांश लोग जो
जिन लोगों ने उसका विरोध किया था, वे अब थक चुके थे। 1976 के अंत तक, उसने
उन्हें पर्याप्त रूप से समझाने में कामयाब रहे।
शीर्ष स्तर पर लिए गए निर्णय जटिल और बहुस्तरीय कारकों से प्रभावित होते हैं।
इंदिरा गांधी ने सभी पहलुओं पर विचार किया होगा।
नकारात्मक पक्ष—संजय की बढ़ती शक्ति और अलोकप्रियता, उसका घटता प्रभाव
अधिकार, अंतरराष्ट्रीय जनमत, घरेलू दबाव, उसका अपना आंतरिक
उथल-पुथल और उसकी जीत की संभावनाओं पर मिली प्रतिक्रिया के बीच, उसने फैसला किया कि
उस विशेष समय पर चुनाव कराने का विकल्प चुनने में ही लाभ का संतुलन निहित था।
मोड़।
हो सकता है कि उसे आईबी द्वारा दी गई आसान जीत की प्रतिक्रिया पर पूरी तरह से विश्वास न हो। या
दिल्ली के एक थिंक टैंक का अनुमान था कि वह आने के लिए पूरी तरह तैयार थी
सत्ता में वापसी। हालांकि कोई भी राजनेता चुनाव जीतने को लेकर 100 प्रतिशत निश्चित नहीं होता।
चुनाव में, उन्हें अपनी जीत का काफी हद तक भरोसा था।
'यह बात स्पष्ट कर दें कि इंदिरा गांधी ने चुनाव का विकल्प चुना था,' नटवर सिंह ने कहा।
मेरे लिए, 'क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह जीत जाएगी।'
उन्होंने पी. एन. धर को फोन किया और उन्हें मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने के लिए

कहा।
आयुक्त, टी. स्वामीनाथन। 1 जनवरी 1977 को, धर ने आमंत्रित किया
स्वामीनाथन ने उन्हें चाय पर अपने घर बुलाया और चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा।
प्रसन्न स्वामिनाथन ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस अवसर पर इससे कहीं अधिक की आवश्यकता है।
जश्न मनाने के लिए बस चाय। उसी शाम उन्होंने धर को व्हिस्की की एक बोतल भेजी।
18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की।
देश को आश्चर्यचकित कर दिया। हालाँकि, चुनाव की तारीख 'द्वारा' तय की गई थी।
प्रधानमंत्री के ज्योतिषियों के।
■

इंदिरा गांधी इतनी दृढ़ निश्चयी राजनीतिज्ञ थीं कि वे
अचानक उसे अपने लोकतांत्रिक और उदारवादी विचारों के बारे में अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी
विरासत, और इसी कारण से चुनाव का विकल्प चुनना। न ही वह एक नेता थीं।
कौन यह जानते हुए भी कि वह हारने वाली है, चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएगा?
यह उनकी राजनीतिक छवि से मेल नहीं खाता था। ओम मेहता ने मुझे बताया कि
इंदिरा गांधी चुनावों के माध्यम से आपातकाल को वैधता प्रदान करना चाहती थीं।
सत्यपाल मलिक ने मुझे बताया, 'श्रीमती गांधी भी अपने अधिकार को वैध बनाना चाहती थीं।'
चुनावों के माध्यम से उत्तराधिकार योजना।
इंदिरा गांधी के इस फैसले के कई कारण बताए गए हैं।
चुनाव कराने के आह्वान के लिए, मेरे विचार से सबसे ठोस कारणों में से एक था...
संजय के लिए उत्तराधिकार योजना तैयार करना। वह शुरू से ही उसे तैयार कर रही थी।
संजय को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। व्यावहारिक रूप से देखा

जाए तो वही कंपनी चला रहे थे।
सरकार—और पार्टी—ने उन्नीस महीनों के दौरान
आपातकाल। और उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया था। वह चाहती थी कि उसका
उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी बनना चाहता था। लेकिन वह उसके साहसिक स्वभाव पर अंकुश लगाना चाहती थी, उसे अलग करना चाहती थी।
उसे उसके कुछ अप्रिय सहयोगियों से बचाया जिन्होंने एक
आपातकाल में निहित स्वार्थ था। वह यह भी चाहती थी कि वह 'सेवा करे'
इंदिरा के पदभार संभालने से पहले, उन्हें 'प्रशिक्षुता अवधि' से गुजरना होगा।
मैंने अनुमान लगाया है कि चुनाव संजय को स्थिर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात,
वे संजय की भूमिका का समर्थन करेंगे और उसे स्वीकार्य बना देंगे।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वह उन्हें 'उभरते सितारे' के रूप में प्रस्तुत करना चाहती थीं।
भारत का पुत्र।
चुनावों के माध्यम से, वह संजय की टीम को भी सत्ता में लाना चाहती थी, एक
लोगों का एक नया समूह जो उसके प्रति वफादारी रखेगा।
कांग्रेस का स्थापित नेतृत्व उनकी कार्यशैली से नाखुश था।
कामकाज चल रहा था। उन्हें रास्ता देना था, या उन्हें हटा दिया जाना था। इंदिरा गांधी के पास
युवा कांग्रेस के 200 सदस्यों को टिकट देने की योजना थी, जो
संजय के नेतृत्व में यह आकार ले रहा था, और बढ़कर छह मिलियन की कंपनी बन चुका था।
1977 की शुरुआत तक सदस्य संगठन। श्रीमती गांधी इससे प्रभावित थीं।
नवंबर 1976 में कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन में उनका उल्लेख किया गया था, और उन्होंने संतोष से कहा, 'हमारी वाहवाही छिन गई है।'
लेकिन न तो उसने और न ही आईबी ने उस गति का अनुमान लगाया था जिसके साथ विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे। वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी।
चुनाव की घोषणा के पांच दिन बाद, विपक्षी समूहों ने

वे अपनी पार्टियों को एक इकाई में मिला देंगे। चारों दलों के नेता
विपक्ष के सबसे बड़े संगठन, कांग्रेस (ओ), भारतीय लोक दल,
भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी और चंद्र के नेतृत्व वाले यंग तुर्क्स
शेखर की मुलाकात नई दिल्ली के डुप्लेक्स रोड स्थित 5 नंबर के मोरारजी देसाई के घर पर हुई।
23 जनवरी 1977 को। उनमें से कई लोग उन्नीस साल से एक साथ जेल में थे।
महीनों बाद; इसने उनके बीच एक नई सौहार्दता पैदा कर दी थी—कुछ ऐसा
उन्हें रिहा करते समय उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा था।
उनकी और संजय की उम्मीदों के विपरीत, उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया।
जनता पार्टी नामक एक नई इकाई के गठन में। यह एकमात्र घटना नहीं थी।
उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद, वह तब हैरान रह गई जब
जगजीवन राम ने अचानक कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई।
सीएफडी, जिसने बाद में जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। फिर उसने फैसला किया कि...
सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए उन्होंने स्थापित कांग्रेस नेताओं को अधिक टिकट दिए।
उन्हें बाबूजी से जुड़ने से रोकने के लिए। अंततः उसने केवल बीस ही दिए।
संजय के वफादारों के लिए टिकट।
चुनाव प्रचार शुरू होने के कुछ ही समय बाद इंदिरा गांधी को एहसास हो गया कि हालात बदल रहे हैं।
योजना के अनुसार नहीं चल रहा है। जैसा कि उन्होंने पत्रकार प्राण सभरवाल को बताया,
चुनाव की घोषणा के कुछ दिनों बाद, 'जब से चुनाव की घोषणा हुई'
hai, chaprasi theek se paani tak nahin pila rahe hain (From the
जैसे ही मैंने चुनाव की घोषणा की, चपरासी भी ठंडे पड़ गए।
मुझे कंधे पर उठाकर)।
वह संजय के भय और तिरस्कार को समझ नहीं पाई थी।
या तो उसने इसे उठाया था—या इसे अनदेखा करना चुना था। ऐसी अफवाहें थीं कि

अगर
कांग्रेस जीत गई, संजय गृह मंत्री बनेंगे। कई लोग
भयभीत। आपातकाल ने उसे ज़मीन से अलग कर दिया था; लोग
उसे वही बताया जो वह सुनना चाहती थी। 'जब आप प्रवाह को रोकते हैं'
'लोगों को जानकारी देना,' कांग्रेस के पूर्व सांसद कृष्णकांत ने कहा था।
उस युवा तुर्क ने संसद में चेतावनी दी थी, 'आप चैनल को अवरुद्ध कर रहे हैं।'
अपने लिए जानकारी।
उन्होंने जहां भी चुनाव प्रचार किया, उन्हें जनता की शत्रुता का एहसास हुआ।
फरवरी 1977 में दिल्ली के बोट क्लब में आयोजित चुनावी रैली में एकत्रित हुए लोगों में शामिल लोग भी शामिल थे।
सरकारी कर्मचारियों ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, 'कोई डीए नहीं, कोई वोट नहीं।' उनमें से कुछ
उन्होंने इंदिरा गांधी की ओर मुट्ठी लहराना शुरू कर दिया। वह वहाँ पत्थर के चेहरे के साथ बैठी रहीं। 'आपका बेटा कहाँ है? आपने उसे कहाँ छिपा रखा है? हमें दो बताएँ।' नसबंदी के मामलों पर चर्चा करें और हम आपको अपना वोट देंगे।'
इंदिरा गांधी को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा।
हालांकि कई विपक्षी नेताओं को आशंका थी कि वह
चुनाव में धांधली हो सकती है, लेकिन नतीजों से पता चला कि चुनाव स्वतंत्र थे और निष्पक्ष। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, जनता पार्टी ने 298 लोकसभा सीटें जीतीं, और
43.4 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। लेकिन अपने सहयोगियों—शिरोमणि—के साथ मिलकर उसने यह उपलब्धि हासिल की।
अकाली दल (9), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) (2), कम्युनिस्ट
पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (सीपीआई (एम)) (22), क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी (4),
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआईएफबी) (3), किसान और मजदूर पार्टी (5),
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोबरगड़े) (2)—संख्या का योग
प्रभावशाली 345। जगजीवन राम की सीएफडी, जिसने 28 सीटें हासिल कीं, के पास

जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, हालांकि इसने अपनी
चुनावों के दौरान इसकी अलग पहचान थी। औपचारिक रूप से इसका जनता पार्टी में विलय हो गया।
चुनाव के बाद ही। इंदिरा कांग्रेस ने 154 सीटें जीतीं।
जनता पार्टी की जीत पर ऐसा उत्साह देखने को मिला—और
इंदिरा गांधी की हार—जिससे उत्साहित दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल दीं
आधी रात से लेकर सुबह के तड़के तक सभी को मिठाई बांटने के लिए।
मुझे याद है 21 मार्च को मुंबई के कोलाबा में सड़क किनारे खड़े होने का दृश्य।
1977 में, बॉम्बे के नव निर्वाचित सदस्यों के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए।
संसद में राम जेठमलानी और मृणाल गोरे; जब वे उपस्थित हुए,
भीड़ खुशी से झूम उठी। एक ढोलक वादक पूरे जोश के साथ ढोल बजाने लगा।
लोग 'ज़ोर से बोलो जनता' जैसे शब्दों पर नाचने लगे, जो अनायास ही गढ़े गए थे।
Party, pyar se bolo Janata Party, upar dekho Janata Party, neeche dekho
जनता पार्टी (उत्साह से कहो, जनता पार्टी, प्रेम से कहो, जनता पार्टी)
पार्टी, ऊपर देखो तो जनता पार्टी है, नीचे देखो तो जनता पार्टी है)।
उनके लिए, और लाखों भारतीयों के लिए, तानाशाह इंदिरा गांधी
अंततः चला गया।

सातवीं

सत्ता खोने के चार महीने के भीतर ही इंदिरा गांधी के मिजाज में बदलाव आ गया।
एक बदलाव। देश का मिजाज भी बदल गया। इस बात से बेखबर कि
मोरारजी देसाई और चरण सिंह को अभूतपूर्व अवसर दिया गया है।
और जगजीवन राम अलग-अलग दिशाओं में खींचने लगे। इंदिरा अब
वापसी के तरीके तलाश रहे हैं।
दलितों के सामूहिक नरसंहार के साथ पहला अवसर आया।
पटना जिले के एक छोटे से गांव बेलची में उच्च जाति के जमींदार।
मई 1977 में बिहार में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जब यह घटना घटी, तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जुलाई में उन्होंने

फैसला किया कि...
यह मुद्दा उठाना अच्छा रहेगा। वह बेलची गई थी। भारी बारिश के साथ।
बिहार के ग्रामीण इलाकों में भीषण बारिश हो रही थी, और कीचड़ के कारण उसकी यात्रा में बाधा उत्पन्न हुई।
कीचड़ ही कीचड़ था। उसे अपनी गाड़ी बीच रास्ते में ही छोड़नी पड़ी। फिर भी, वह हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ गई।
अपनी यात्रा के अंतिम चरण में एक हाथी की पीठ पर सवार होकर वह फंसे हुए लोगों के पास पहुंची।
गांव। हाथी पर बैठी उसकी तस्वीर उस गांव का प्रतीक बनने वाली थी।
उसके जीवन में आए बदलाव के बारे में।
दलित, जिन्हें स्थानीय उच्च जाति के जमींदारों द्वारा आतंकित किया जा रहा था,
उन्होंने खुले दिल से उनका स्वागत किया। 'मैं तुम्हारे साथ हूँ',' उन्होंने कहा।
उन्होंने उन्हें इशारा किया। वह वहाँ बैठी रहीं, एक आदर्श अम्मा की तरह, सब कुछ सुन रही थीं।
उनकी परेशानियाँ। यह एक ऐसी भूमिका थी जिसे वह बखूबी निभाना जानती थी।
बेल्ची ने भेजा
इंदिरा गांधी की रगों में एक बार फिर एड्रेनालाईन का प्रवाह होने लगा। इससे एक और संदेश भी निकला।
अपने दल के सदस्यों को वह संकेत देना चाहती थी, जो उसने चाहा था—कि, इसके बावजूद
उनकी हार के बाद, कांग्रेस में उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। और लोग
उन्हें, और केवल उन्हें ही, नेता के रूप में देखा जाता था। और पार्टी की वापसी
यह सब केवल उनके नेतृत्व में ही संभव हो सकता था। इंदिरा इस बात से अवगत थीं कि
जिन समुदायों ने कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बनाई थी, वे
उसे छोड़कर चले गए। मुसलमानों में इस जबरन किए गए कृत्य से आक्रोश फैल गया था।
नसबंदी। दलितों में अधिक शक्तिशाली लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे।
जगजीवन राम की ओर, जो संरक्षण देने की स्थिति में थे।

जनता सरकार में रक्षा मंत्री। उन्हें संपर्क करना पड़ा।
दलितों का विश्वास फिर से हासिल करना और उन्हें अपने पक्ष में करना।
लेकिन इंदिरा गांधी ने बेलची को एक और कारण से भी चुना था—
जेपी। उसने फैसला किया था कि पटना जाने के बाद वह उससे मिलने जाएगी।
बेलची। उन्होंने जनता को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और
उसकी हार सुनिश्चित करना। अब अलगाव को दूर करने का समय आ गया था—यह
इससे उन्हें राजनीतिक रूप से भरपूर लाभ मिलेगा।
14 अगस्त 1977 को पटना में बादल छाए हुए थे। इंदिरा गांधी गाड़ी से पटना गईं।
कदम कुआं, शहर के मध्य में स्थित एक दो मंजिला इमारत जिसमें स्थित था
the Mahila Charkha Samiti, an organization that JP's wife, Prabhavati,
अप्रैल 1973 में उनकी मृत्यु से पहले वह इस व्यवसाय का संचालन करती थीं। जेपी
पहली मंजिल का उपयोग अपने लिए करते थे।
निवास स्थान। इस समय तक, वह नियमित डायलिसिस पर थे, उनके गुर्दे
130 दिनों तक एकांत कारावास में रहने के दौरान उसे नुकसान पहुंचा था।
आपातकाल के दौरान चंडीगढ़।
गिरफ्तारी के लगभग पांच महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।
नवंबर 1975 में, जब उनके भाई राजेश्वर प्रसाद ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था।
गांधी ने कहा कि जेपी शायद दो महीने से ज़्यादा जीवित न रह पाएं। उन्होंने लिखा,
'यह आपको तय करना है कि क्या यह हित में होगा...'
अगर जेपी की जेल में मौत हो जाती है तो सरकार को सजा मिलेगी।' तीन दिन बाद,
जेपी को रिहा कर दिया गया।
पैरोल। जब उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई, तो उनके हिरासत आदेश को रद्द कर
दिया गया।
निरस्त।
जेपी को खुद शक था कि उसे धीरे-धीरे जहर दिया जा रहा था।
नजरबंदी। 'मेरे कई दोस्तों ने संदेह व्यक्त किया है, जिसे मैं
'साझा करें,' उन्होंने फरवरी 1977 में अपने समर्थकों को लिखे एक खुले पत्र में
लिखा।

‘हो सकता है कि मेरी किडनी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया हो।’ जब
जनता सरकार सत्ता में आई, जेपी के खिलाफ जांच शुरू की गई।
हिरासत में लिया गया लेकिन विवादों में घिरे होने के कारण इसका कोई परिणाम नहीं निकला।
हालांकि, एक अंतरिम रिपोर्ट में पाया गया कि जेपी की हिरासत में देरी हुई थी।
अस्पष्ट उपेक्षा से चिह्नित—इसने हंगामा खड़ा कर दिया
संसद।
■

जेपी और इंदिरा गांधी के बीच संबंध जटिल थे। 1973-74 के दौरान, उनके बीच कई तरह के संबंध रहे।
उन्होंने ‘पूर्ण क्रांति’ के आंदोलन का नेतृत्व किया। इसकी शुरुआत नव के रूप में हुई थी।
गुजरात में छात्रों द्वारा चलाया गया निर्माण आंदोलन, जिसने
चिमनभाई पटेल की कांग्रेस सरकार। अपने समकक्षों की तरह।
गुजरात की तरह बिहार के युवाओं ने भी व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई।
भ्रष्टाचार और बढ़ती कीमतों के खिलाफ उन्होंने चुनावी सुधारों की मांग की;
जेपी को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। इसके परिणामस्वरूप, अमेरिका से बाहर निकलने की मांग उठी।
पटना में अब्दुल गफूर की कांग्रेस सरकार के दौरान यह मामला और भी गंभीर हो गया।
इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग उठाई गई।
बिहार आंदोलन का राष्ट्रगान, जिसे जेपी के एक सहयोगी ने गाया था।
Janaki—‘Jayaprakash ka bigul baja toh jaag uthi tarunai hai, tilak lagane
tumhe jawano, kranti dwar par aayi hai (Jayaprakash’s bugle has awoken
युवाओं, क्रांति अब आपके दरवाजे पर खड़ी है और आपको पुकार रही है।

जेपी (आप)' का नारा 1974-75 में बिहार के ग्रामीण इलाकों में गूंजता था।
उन्होंने राज्य के कोने-कोने का भ्रमण किया। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे
जातिविहीन समाज का निर्माण करना, सामाजिक परिवर्तन के लिए उनकी जनेऊ प्रथा को तोड़ना
होने के लिये।
उनकी एक सभा में पेड़ पर बैठे एक युवक ने पूछा, 'अब क्या?'
पूछा गया।
'हाँ।'
और उनमें से कई लोगों ने अपना लिंग उस पर फेंक दिया।
'यह संपूर्ण क्रांति की शुरुआत है,'
जेपी ने खुशी से कहा।
बिहार आंदोलन से जुड़े कई लोग आगे चलकर शासन करने लगे।
वे अपने राज्यों में या आने वाले वर्षों में एक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।
included Lalu Yadav, Nitish Kumar, Ravi Shankar Prasad, Sushil Modi,
Govindacharya, Shivanand Tiwari, and Lalmuni Chaubey.
जेपी ने इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने में मदद की।
गांधी ने जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा की थी। मतदान के दौरान
अपने अभियान के दौरान, उनकी उपस्थिति ने जहाँ भी वे गए, लोगों में जोश भर दिया।
मुझे जनवरी 1977 में मुंबई के शिवाजी नगर में उनके द्वारा संबोधित की गई एक रैली याद है?
पार्क। पार्क खचाखच भरा हुआ था। झुके हुए लोगों पर तेज रोशनी पड़ रही थी।
एक व्यक्ति मंच पर कुर्सी पर बैठा था। वह खड़ा होकर बोल नहीं सकता था।
जेल में रहने के दौरान उनके स्वास्थ्य को जो भारी नुकसान पहुंचा था, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो वह
फुसफुसाहट हो रही थी। लेकिन उस विशाल कमरे में मानो सन्नाटा पसरा हुआ था।
पार्क। वहां एक लाख से अधिक लोग जमा हुए थे और हर शब्द को ध्यान से सुनने की

कोशिश कर रहे थे।
वह बोल रहा था। उसने बहुत सरल शब्दों में उनसे तानाशाही को हराने का आग्रह किया।
इंदिरा गांधी की सरकार।
उन्होनें किया।
■

जेपी का मानना था कि इंदिरा गांधी के साथ उनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी—उनमें से कुछ
सहकर्मियों को इसे स्वीकार करना सीखना पड़ा। एक दिन, उनके सहयोगी, कुमार
प्रशांत और जानकी को सफाई करते समय कई पत्र मिले।
कदम कुआं। 'अचानक हमें यह पोटली (बंडल) मिली,' कुमार
प्रशांत ने याद करते हुए बताया, 'लगभग 20-25 पत्र एक रैपर में लिपटे हुए थे।'
कपड़े का एक टुकड़ा। हमने उन्हें जेपी को दिखाया।
'आह,' उसने संतुष्टि भरे स्वर में कहा। 'अच्छा हुआ, वे मिल गए।'
ये पत्र इंदिरा गांधी की माता कमला नेहरू ने लिखे थे।
to Prabhavati, JP's wife. Prabhavati and Kamala had become friends
इन वर्षों में—उनकी दोस्ती की शुरुआत तब हुई जब जेपी और प्रभावती
जेपी, जो उस समय एक
मार्क्सवादी, सात साल की पढ़ाई के बाद अमेरिका से लौटे थे, और
उन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन में समर्पित करने का निर्णय लिया।
कमला प्रभावती से अपने मन की बातें कहने लगी और अपने मन का बोझ हल्का करने लगी।
उसने वर्षों से उसे लिखे पत्रों में खुद का जिक्र किया था।
कुमार प्रशांत ने याद करते हुए कहा, 'हमने जेपी को 2-3 पत्र पढ़कर सुनाए।'
'I remember lines like "kuchh log apne aapko bahut superior
समझते हैं (कुछ लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं)।

यह स्पष्ट रूप से नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित की ओर इशारा था।
नेहरू परिवार के अन्य सदस्यों का भी जिक्र था।
जिनमें नेहरू भी शामिल थे, जिनसे कमला नेहरू नाखुश थीं।
ऐसा हर परिवार में होता है... उसने लिखा कि उन लोगों के लिए यह कितना मुश्किल था।
उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार में प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक कुलीन परिवार था।
जवाहरलाल उसके लिए परिवार के सामने खड़े होने में सक्षम नहीं थे।
उन्होंने प्रभावाती को यह भी बताया कि जेपी जैसे व्यक्ति का साथ पाकर वह कितनी भाग्यशाली थीं।
प्रभावती को उसका हक मिलना चाहिए। प्रशांत ने कहा कि कुछ इसी तरह के शब्द कहे गए थे।
'Tum bhagyashali ho ki tum se barabari se baat karte hain (You are
यह वाकई सौभाग्य की बात है कि जेपी आपसे बराबरी के स्तर पर बात करता है।
अगले दिन जेपी ने कुमार प्रशांत से कहा, 'मैं ये पत्र नहीं चाहता/चाहती।'
गलत हाथों में पड़ सकते हैं। इनका दुरुपयोग हो सकता है। Indu ko hee dae daen
(We can give them to Indu),' he said. 'Jo theek samjhe woh kare (She
वह जो चाहे कर सकती है।
'हम इनकी एक प्रति क्यों न बना लें?' प्रशांत ने सुझाव दिया। 'वे
तो सुरक्षित रहें।
'Woh bhi safe rakhegi (She will also keep them safe),' JP said चिड़चिड़ाकर।
Prashant pressed again. 'Kisi sanghralaya ko dae sakte hain surakshhit rakhne ke liye (We can give it to some library for safe
रखना)।
'अगर मैं इसकी कॉपी रखना चाहता,' जेपी ने पलटवार किया।

तीखे स्वर में, ‘तो देने की बात ही ना करता (मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ?)
उन्हें सौंपना)?
‘Is mahaul maen mein nahin chahta ki koi personal attacks ho (In
मौजूदा माहौल में, मैं नहीं चाहता कि चीजें व्यक्तिगत विवादों में उलझ जाएं।
हमले),' जेपी ने कहा। 'विश्वास करके चलते हैं'
उसकी)।'
उन्हें आशंका थी कि विपक्ष का कोई व्यक्ति उन पर हमला कर सकता है।
उनके हाथ पत्रों पर थे। वह नहीं चाहता था कि कोई भी 'निजी' जानकारी को ठेस पहुंचाए।
इंदिरा गांधी और नेहरू-गांधी परिवार पर हमले।
जेपी ने इंदिरा को फोन किया। उसने इंदिरा से कहा कि वह उससे मिलना चाहता है।
के.एस.
राधाकृष्ण, जो गांधी शांति फाउंडेशन के सचिव थे।
जहां जेपी दिल्ली में रहते थे, वहीं से उन्हें प्रधानमंत्री के पास ले जाया गया।
सफदरजंग रोड स्थित नंबर 1 नंबर के घर में। जेपी के अंदर जाने तक वह बाहर इंतजार करता रहा।
जेपी ने इंदिरा को पैकेट सौंप दिया। ‘ये कमला के पत्र हैं।’
उन्होंने प्रभावती को लिखा था,’ उन्होंने उससे कहा। ‘मैं नहीं चाहता था कि वे किसी मुसीबत में पड़ें।’
गलत हाथों में।
‘धन्यवाद,’ उसने कहा। उसने न तो पैकेट की तरफ देखा और न ही कुछ पूछा।
पत्रों के बारे में सवाल। वह अपनी पूरी क्षमता दिखाने की कोशिश कर रही थी।
जेपी ने बाद में प्रशांत को बताया कि उसे इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।
इस बैठक में इंदिरा गांधी ने जेपी से मदद मांगी। वह चाहती थीं कि
उसे अपनी आलोचना कम करने के लिए कहना चाहिए।
उसने उसे बताया कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है।
‘क्या आप कह रहे हैं कि मैं भ्रष्ट हूँ?’ इंदिरा ने उनसे पूछा।
आक्रोशपूर्वक।

जेपी ने समझदारी से उसे समझाया कि शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी।
वह बदलाव के लिए एक आंदोलन में काम कर रहा था। वहाँ कुछ भी नहीं था।
उसके खिलाफ व्यक्तिगत कार्रवाई की गई है।
गांधीवादियों में से कई लोग जेपी के इस फैसले से नाखुश थे।
इंदिरा गांधी को पत्र सौंप दें। उन्होंने कुमार प्रशांत की आलोचना की।
जेपी नारायण देसाई और हरिदेव शर्मा को समझाने में असफल रहने के लिए।
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के उप निदेशक ने इसे ऐसा कहा।
एक बड़ी 'गलती'। क्योंकि ये ऐसे दस्तावेज़ थे जिनमें अपार जानकारी थी।
ऐतिहासिक महत्व।
■

अब, कुछ वर्षों बाद, बदली हुई परिस्थितियों में, जेपी
वह अपने घर की पहली मंजिल के विशाल बरामदे में इंदिरा का इंतजार कर रहा था।
गांधी जी पहुंचे। वे एक आरामकुर्सी पर बैठ गए, उनके बगल में एक चांदी का डिब्बा रखा था।
इसमें लौंग थी जिसे वह समय-समय पर अपने मुंह में डाल लेता था।
अब सांसों को ताज़ा करने का समय आ गया है, जो नियमित डायलिसिस के कारण दुर्गंधयुक्त हो गई थीं।
इंदिरा, एक गंभीर, सफेद बॉर्डर वाली साड़ी पहने हुए, अपने साथ थीं।
सर्वोदयवादी नेता निर्मला देशपांडे सुबह 10 बजे समय पर पहुंचीं।
जिस समय उन्होंने मिलने का समय तय किया था।
जेपी इंदिरा को अपने छोटे, सादे ढंग से सजाए गए कमरे में ले गया। उसमें एक
एक संकरी चारपाई और दो सीधी कुर्सियाँ थीं, जिन पर वे दोनों बैठ गए।
उस दिन, भारत छोड़ो आंदोलन के साहसी और आकर्षक नायक ने
जो 1942 में ब्रिटिश जेलरों को चकमा देकर भाग गया था।
हजारीबाग जेल असामान्य रूप से जर्जर दिख रही थी।

‘Kaise aana hua (What brings you here?)’ JP asked her. ‘Koi

takleef
तो नहीं हुई (मुझे उम्मीद है कि आपको यहां आने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी)।
इंदिरा ने बेलची की अपनी यात्रा के बारे में बताया। वह पटना आई थीं।
सीधे वहां से. 'बहुत दुख था (यह बहुत दर्दनाक था)।'
जेपी ने कहा, 'जब मैं स्वस्थ था, तब मैं स्वयं इन स्थानों पर जा सकता था।'
फिर उसने पूछा, 'बच्चे कैसे हैं?' उन्होंने इस बारे में बात की कि उसकी क्या हालत है।
लड़के यही कर रहे थे।
जेपी ने पूछा, 'आनंद भवन में आपने क्या व्यवस्था की है?'
बातचीत के दौरान, इंदिरा गांधी ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने दान दिया था।
उन्होंने 1970 में यह संपत्ति सरकार को सौंप दी थी। उन्होंने वहां बिताए अपने समय को याद किया।
एक मार्क्सवादी के रूप में, उन्होंने अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1929 में भारत वापसी की।
और कैसे भाई [नेहरू] के कहने पर उन्होंने स्वयं को उसमें झोंक दिया था
उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और फिर कांग्रेस का गठन किया।
कांग्रेस के भीतर समाजवादी दल (1934 में), अन्य समाजवादियों के साथ
like Acharya Narendra Dev, Asoka Mehta, and Ram Manohar Lohia.
इंदिरा गांधी जेपी की राजनीति को हमेशा संदेह की नजर से देखती थीं।
उन्हें पूरा यकीन था कि जेपी उच्च सार्वजनिक पद चाहते हैं। 'यह कहना बकवास है।'
कि वह पद नहीं चाहता था। उसका एक हिस्सा चाहता था...' उसने लिखा।
हंगरी में जन्मी फोरी नेहरू, जिनकी शादी इंदिरा गांधी के रिश्तेदार से हुई थी,
राजनयिक बी. के. नेहरू। कहीं न कहीं उसे इस बात का दुख था कि उसके पिता
नेहरू एक समय जेपी को अपना उत्तराधिकारी मानते थे। 1953 में नेहरू ने जेपी को आमंत्रित किया था।
उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए। वह जेपी को उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। बी.के.
नेहरू, जो उस समय एक आईसीएस अधिकारी थे, ने एक सहायक को पत्र लिखा था।

नेहरू द्वारा जेपी को दिए गए निमंत्रण के बारे में संस्मरण। 'प्रधानमंत्री ने श्री नारायण को बताया...'
उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे बता सके कि वह कहाँ गलती कर रहा है...
प्रधानमंत्री ने श्री नारायण को अपने भीतर ऐसा विपक्ष गठित करने के लिए आमंत्रित किया।
उनका मंत्रिमंडल...
प्रधानमंत्री ने श्री नारायण से पूछा, उन्हें मनाया, फिर उनसे विनती की।
लेकिन श्री नारायण का जवाब दृढ़तापूर्वक "नहीं" था।
नेहरू ने जेपी से कहा कि उन्हें समाजवादियों की कांग्रेस में वापसी की जरूरत है।
अधिक रूढ़िवादी दक्षिणपंथी गुट के दबाव का सामना करने के लिए झुकना पड़ा।
पार्टी के भीतर के तत्व। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी) ने इस पर चर्चा की।
कांग्रेस-पीएसपी विलय का प्रस्ताव। अशोक मेहता जेपी के विलय के पक्ष में थे।
सरकार। राम मनोहर लोहिया और कुछ अन्य लोगों ने इसका विरोध किया।
जून 1953 में बेतुल में पीएसपी की बैठक में—जहां उन पर आरोप लगाया गया था सत्ता के लालच में आकर जेपी टूट गया। उसके बाद उसने कहीं और जाने का फैसला किया।
सत्ता की राजनीति से दूर।
जेपी शायद खुद को महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में ज्यादा देखते थे, बजाय इसके कि वे खुद को महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में देखें।
जवाहरलाल के प्रतिनिधि। गांधी ने एक बार उनसे कहा था कि वे उनके सच्चे प्रतिनिधि हैं।
वह अनुयायी था, क्योंकि वह अंग्रेजों की विरासत को नष्ट करना चाहता था, जबकि नेहरू केवल अंग्रेजों को हटाना चाहते थे। जेपी लगातार संघर्ष कर रहे थे।
'सही लक्ष्य और सही साधन' खोजने के लिए 'नैतिक संघर्ष'
उन्हें हासिल करो। लेकिन इंदिरा गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया, उन्हें उन्होंने पाया—
भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ स्वेच्छा से काम करना
भूमिहीनों को भूमि दान करना, या डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करना।

चंबल घाटी, या उग्रवाद से ग्रस्त नागालैंड में युद्धविराम कराना
—'भ्रमित'। फिर भी, वह जानती थी कि उसके पास अपार नैतिक शक्ति थी।
अधिकार। इसीलिए वह उस अगस्त के दिन पटना में थी।
इस यात्रा के दौरान इंदिरा ने जेपी से राजनीति के बारे में बात नहीं की। न ही किसी और विषय पर।
जनता सरकार के हाथों उसे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनके बारे में।
संजय की पत्नी मेनिका पहले ही जेपी से उन कठिनाइयों के बारे में बात कर चुकी थी जो उन्हें हो रही थीं।
परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उनके फोन टैप किए जा रहे थे और उनके पत्र खोले जा रहे थे।
जेपी बेहद गुस्से में था। मेनका के जाने के बाद, उसके एक साथी ने खुद को रोक नहीं पाया।
यह पूछते हुए कि, 'लेकिन इंदिरा गांधी ने भी सभी के फोन टैप किए थे'
विपक्षी नेता...?
'लेकिन अब लोकतंत्र बहाल हो चुका है,' जेपी ने पलटवार किया।
बैठक पचास मिनट तक चली। बैठक समाप्त होने पर, कमजोर दिख रहे जेपी चले गए।
इंदिरा को विदा करने के लिए सीढ़ियों के शीर्ष पर। जब प्रेसकर्मी इंतजार कर रहे थे
कदम कुआन में नीचे मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया, उसने उन्हें बताया कि यह एक
'निजी' मुलाकात। वह मुस्कुराई, हाथ हिलाया और गाड़ी चलाकर चली गई।
पत्रकार जेपी की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनके पास आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें बता दिया था।
her, 'Jitna tumhara bhootkaal ujjwal raha hai, utna hee tumhara
bhavishya bhee ujjwal ho (I told her that may she have as bright a
उसका भविष्य वैसा ही होगा जैसा उसका अतीत था।
जब इस बात का पता चला कि उसने उससे क्या कहा था, तो संपादक कुलदीप

नायर ने घर पर फोन किया। उसने पूछा, ‘जेपी उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकता है?’

कुमार प्रशांत ने गुस्से से कहा, 'उसका अतीत एक अंधकारमय अध्याय रहा है, उज्ज्वल नहीं।'

‘एक,’ उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए गुस्से में कहा। जनता पार्टी के नेताओं वे भी उतने ही क्रोधित थे। प्रशांत ने उनके संदेश जेपी को पहुंचा दिए।

‘Ghar aye ko dua dee jaati hai ya bad-dua deni chahiye (Do you

क्या आप अपने घर आए मेहमान को आशीर्वाद देते हैं या उसे श्राप देते हैं?’ जेपी उत्तर दिया।

अपनी स्वाभाविक विनम्रता के अलावा, जेपी में और भी गुण विकसित हो रहे थे।

जनता पार्टी के नेताओं से उनका मोहभंग बढ़ता जा रहा था—और शायद वे इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा जनता पार्टी के नेताओं से नाराज़ थे। उन्होंने जनता पार्टी को ये सब दिया था।

सरकार ने एक वर्ष का समय दिया था और वह अपने कार्यों से बेहद असंतुष्ट थी।

उन्होंने जो प्रगति की थी।

अक्टूबर 1978 में, जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे एक विज्ञप्ति जारी करने का आग्रह किया।

इंदिरा गांधी को वोट न देने की अपील करने वाला बयान; उन्होंने फैसला कर लिया था जॉर्ज कर्नाटक के चिकमगलूर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।

फर्नांडीस, जो अब उद्योग मंत्री हैं, ने जेपी से इस तरह का एक प्रकाशन जारी करने का आग्रह किया।

अपील की गई। जेपी ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, 'मैं अब राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं।'

फर्नांडेस ने कहा, 'वह दौर खत्म हो चुका है। आप लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई (अभी)।

उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी, उसका उद्देश्य उनके शासनकाल को समाप्त करना था।

तानाशाही शासन का अंत हो गया था। जिस दिन उसने चुना, उसी दिन उसका अंत हो

गया था।
मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया था। उन्होंने तो इसमें भाग भी नहीं लिया।
जनता पार्टी की जीत का जश्न। मधु लिमये आईं।
उन्हें व्यक्तिगत रूप से राम लीला मैदान में विजय रैली तक ले जाने के लिए।
वह अविचलित बैठा रहा। लिमाये के जाने के बाद, उसने इंदिरा के घर तक छोड़ने के लिए कहा।
घर। वह उसका स्वागत करने के लिए बरामदे में आई। 'मैंने उसे अपना
'उसके कंधे पर हाथ,' कुमार प्रशांत ने याद करते हुए बताया, जिन्होंने
accompanied him, 'I heard him say, "Khel maen haar jeet toh hoti rehti
hai. Isko khel ki tareh hee lena chahiye" (There is victory and defeat in
इस खेल को केवल एक खेल के रूप में ही लेना चाहिए।
फिर वे दोनों अंदर चले गए।
अपने तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, जेपी इंदिरा गांधी के प्रति स्नेह रखते थे।
वह उनके मित्र नेहरू की बेटी इंदु थीं, जिनसे वह शादी करना चाहते थे।
जब भी वह पत्र लिखता था तो उसे 'मेरे प्यारे भाई' कहकर संबोधित करता था।
उन्हें। 14 अगस्त 1977 को इंदिरा गांधी पटना की यात्रा पर गई थीं।
जेपी को बेअसर करना। लेकिन जेपी, जेपी होने के नाते, उसे बेअसर करने की ज़रूरत नहीं थी। वह अपने तरीके से जीता था।
उसके मूल्यों से बहुत अलग; जेल में उसने एक कविता लिखी थी
the lines, 'Safalta aur vifalta ki paribhashayen bhinn hain meri (My
सफलता और असफलता की परिभाषा अलग-अलग है।' उन्होंने एक अंतर स्पष्ट किया।
व्यक्तिगत और राजनीतिक के बीच। उसने व्यक्तिगत का उपयोग किया।
राजनीतिक। इस बैठक के बाद, दो साल बाद 8 तारीख को उनकी मृत्यु तक।
अक्टूबर 1979 में, उन्होंने इंदिरा के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया।

गांधी ने वह हासिल कर लिया था जो उन्होंने करने का लक्ष्य रखा था।

आठवीं

इंदिरा गांधी की वापसी की कहानी में अगला महत्वपूर्ण मोड़ 3 तारीख को आया।

अक्टूबर 1977। उस दिन सीबीआई उसे गिरफ्तार करने आई थी, और उसने तुरंत स्थिति को अपने फायदे में बदल दिया।

'संजय, मैं और सुरेंद्र सिंह 12 साल की उम्र में बैडमिंटन खेल रहे थे।

विलिंगडन क्रिसेंट में, जब पुलिस श्रीमती गांधी को गिरफ्तार करने आई थी,'

डम्पी अहमद ने याद करते हुए कहा, 'लेकिन उनके पास उसके लिए कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं था।'

संजय जल्दी से डम्पी को घर के अंदर ले गया और उसे सांसदों की एक सूची दे दी।

और प्रेस के लोग। संजय ने कहा, 'उनसे कहो कि वे जितनी जल्दी हो सके यहां आ जाएं।'

डम्पी को निर्देश दिया। फिर उसने युवा सदस्यों को फोन करना शुरू कर दिया।

कांग्रेस ने उनसे विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है।

इंदिरा गांधी के निजी सहायक आर. के. धवन भी इस पद पर कार्यरत थे।

टेलीफोन लाइनें। वह अखबार के दफ्तरों में फोन कर रहा था। 'अगर आप चाहते हैं तो...'

धवन ने कहा, 'बड़ी खबर है, जल्दी से 12, विलिंगडन क्रिसेंट पर आएं।'

पत्रकारों ने बताया कि इंदिरा गांधी की योजना अमल में आ चुकी थी।

उसे पहले ही सूचना मिल गई थी कि उसे गिरफ्तार किया जाने वाला है।

क्या सीबीआई और आईबी में, विशेषकर शीर्ष स्तर पर, लोग अभी भी वफादार थे?

उन्हें। टी.वी. राजेश्वर, जो खुफिया ब्यूरो के निदेशक रह चुके थे।

आपातकाल के दौरान (डीआईबी) को उनके गृह राज्य वापस भेज दिया गया था।

आंध्र प्रदेश। लेकिन इंदिरा गांधी ने चेन्ना रेड्डी को नियुक्त किया था।

वहां के कांग्रेस मुख्यमंत्री ने उन्हें निवासी आयुक्त के पद पर नियुक्त करने की बात कही है।

दिल्ली में आंध्र भवन। राजेश्वर आईबी के साथ लगातार संपर्क में रहे।

दिल्ली में रहने वाली उस महिला पर उसे सतर्क करने वालों में से एक होने का संदेह था।

उसकी आसन्न गिरफ्तारी।
जनता पार्टी के नेताओं ने चर्चा करने के लिए कई बैठकें की थीं।
क्या उन्हें इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए? चरण सिंह, जैसा कि हमने देखा है
देखा गया, 'नूरेमबर्ग-शैली के मुकदमे' की मांग की गई। जॉर्ज फर्नांडीस, जिनके दो
जानकारी निकलवाने के लिए जेल में बंद भाइयों को यातनाएं दी गई थीं।
फर्नांडेस के ठिकाने के बारे में उन्हें जानकारी देते हुए, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। ऐसा ही अन्य लोगों ने भी किया।
Jan Sangh leaders—Vajpayee, Advani, and Nanaji Deshmukh.
हालाँकि, और यह आश्चर्यजनक था, उनकी लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए।
इंदिरा गांधी के समय, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उन्हें सलाह दी थी।
चेतावनी: 'हमें केवल कानून के अनुसार ही कार्रवाई करनी चाहिए।' एक और
इस विरोध में जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्र शेखर ने भी अपनी राय व्यक्त की।
पार्टी, जिसे लगा कि जनता ने उसे हराकर पहले ही दंडित कर दिया है
वह चुनावी सभा में।
लेकिन, जैसे-जैसे दिन बीतते गए, चरण सिंह की उसे पीछे छोड़ने की इच्छा कम होती गई।
प्रतिबंध और भी सख्त हो गए। अंत में, मोरारजी देसाई ने सिंह से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि
यह ऑपरेशन त्रुटिरहित था और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई।
जब सीबीआई उसे पकड़ने आई, तो वह उनके लिए तैयार थी। उसने तो यहाँ तक तैयारी भी कर रखी थी।
उसने अपना प्रेस बयान पहले से तैयार कर लिया था। उसने चिल्लाकर कहा, 'मुझे हथकड़ी पहनाओ।'
सीबीआई टीम का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधीक्षक एन. के. सिंह पर।
जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसने कहा, 'जब तक तुम मुझे हथकड़ी नहीं लगाओगे, मैं नहीं जाऊंगी।'
उसे बताया। पुलिस के वायरलेस पर आवाज आई, 'राजा पांच से रानी चार, राजा'
पांच से रानी चार...'; गृह मंत्रालय में वापस, एक चिंतित चरण

सिंह कमरे में इधर-उधर चक्कर लगाते हुए पल-पल का जायजा ले रहे थे।
विलिंगडन क्रिसेंट के 12 नंबर पर घट रहे नाटक के बारे में। इंदिरा
फिर गांधीजी बरामदे में रखी बेंत की कुर्सी पर बैठ गईं। और वह
गिरफ्तारी वारंट की मांग की गई। सीबीआई के पास वारंट नहीं था। 'मैडम...यह है
सीबीआई के लिए गिरफ्तारी वारंट या किसी अन्य दस्तावेज की प्रति तामील करना आवश्यक नहीं है।
'एफआईआर,' एन. के. सिंह ने कहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। एन. के.
चरण सिंह ने स्वयं सिंह को नेतृत्व करने के लिए चुना था।
संचालन।
वह समय बिताने के लिए खेल रही थी। उसे पता था कि संजय अपनी सेना जुटा रहा है।
मीडिया। घर के चारों ओर भीड़ हर मिनट बढ़ती जा रही थी।
अब उनके वकीलों में से एक, ए. एन. मुल्ला, जो पूर्व न्यायाधीश थे, ने
वे आ चुके थे। साथ ही एच. के. एल. भगत और बंसी लाल जैसे कांग्रेस नेता भी आ चुके थे।
अंत में, अधिकारियों में से एक ने उसे कागज का एक टुकड़ा दिया जो था
इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के रूप में वर्णित किया गया है। उसने उससे कहा कि वह ऐसा कर सकती है।
यदि वह व्यक्तिगत जमानत प्रदान करे तो उसे उसी समय रिहा कर दिया जाएगा।
'मैं ऐसा क्यों करूँ?' उसने पलटकर जवाब दिया।
रात के 8 बजे ही वह जाने के लिए तैयार हुई। तब तक, प्रेस
विलिंगडन क्रीसेंट के 12 नंबर पते पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे।
वह बंगले से बाहर निकली तो कैमरों की फ्लैश चमकने लगी।
उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया। और,
यह उनके स्वभाव के विपरीत था, क्योंकि वह अक्सर मीडिया का सामना नहीं करती थीं।
वह और सवालों के जवाब देने के लिए इंतजार करती रही। प्रेस
उनके द्वारा तैयार किया गया बयान पत्रकारों को वितरित कर दिया गया।

फिर अचानक, उसका हट्टा-कट्टा, मूंछों वाला अंगरक्षक लेट गया।
उस जीप के सामने जो उसे ले जाने वाली थी। उसने चिल्लाकर कहा कि यह
उन्हें उसके मृत शरीर के ऊपर से गुजरना होगा। अब तक कारों, जीपों की एक कतार लग चुकी होगी,
घर के बाहर बसों की कतार लगी हुई थी। वे सभी पीछे-पीछे चलने के लिए तैयार थीं।
उसे। संजय के लड़के पूरी ताकत से इकट्ठा हो गए थे। उसने यह सुनिश्चित किया था कि
जब वह विलिंगडन क्रिसेंट से विदा होंगी, तो यह बड़े धूमधाम से होगा, और
उसके पीछे वाहनों का एक काफिला चल रहा था।
सीबीआई उसे हरियाणा के भटकल (झील) की ओर ले जा रही थी।
डम्पी अहमद ने याद करते हुए बताया। उन्हें एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकना पड़ा, जो
दुकान अभी-अभी बंद हुई थी। इंदिरा कार से बाहर निकली और पास ही एक जगह पर बैठ गई।
पुलिया, टस से मस नहीं हुई। वह किसी भी कीमत पर उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी।
उन्होंने जोर देकर कहा कि मामला दिल्ली का है। सीबीआई अधिकारी घबराए हुए थे।
उन्हें बताया गया था कि...
उसे हथकड़ी न पहनाई जाए और न ही उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया जाए। अंततः, सीबीआई को यह करना पड़ा।
उसे वापस दिल्ली ले आओ। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
उत्तरी दिल्ली में स्थित एक सड़क पर। उसने रात वहीं बिताई।
निर्मला देशपांडे, जो उनके साथ थीं।
अगले दिन उसे संसद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।
सड़क। बाहर, दंगा पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। कुछ
नारे लगाए, 'इंदिरा गांधी जिंदाबाद', अन्य ने मुर्दाबाद के नारे लगाए।
भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिनमें से कुछ को आग ने अपनी चपेट में ले लिया।
अदालत कक्ष में प्रवेश करते हुए।
अदालत के अंदर, इंदिरा गांधी कटघरे में खड़ी थीं और उन्होंने अनुरोध किया।
पानी। संजय उसके लिए गिलास लेने बाहर गया। उसने अपना गिलास उसमें डुबोया।

उसने रूमाल में रुमाल रखा और धीरे से उसकी आँखों को पोंछा ताकि उसका असर दूर हो जाए।
आंसू गैस। इंदिरा अपने समय की समझ के लिए जानी जाती थीं। लेकिन वह यह भी जानती थीं कि...
उसके पास प्रकाशिकी की अद्भुत समझ थी—और उसने इसे प्रदर्शित किया।
उस दिन उन्होंने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया—जिससे उन्हें जनता की सहानुभूति प्राप्त हुई।
मजिस्ट्रेट ने इंदिरा को बिना शर्त रिहा कर दिया।
आपातकाल की 'खलनायक' से वो रातोंरात शहीद बन गई।
प्रतिशोधी बूढ़े लोगों के हाथों। चरण सिंह की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई।
वह केवल गुस्से में शिकायत कर सकता था कि 'उन्होंने मेरे साथ साजिश की है'।
एक बार फिर। यह स्पष्ट था कि ऑपरेशन बुरी तरह विफल हो गया था।
शुरू से ही। उसकी गिरफ्तारी के दिन, जब उसे दिखाया गया था
वारंटों को लेकर सिंह बेहद गुस्से में थे। 'ये वे मामले नहीं हैं जिन पर हम काम करते हैं।'
'अभी कार्रवाई करनी चाहिए थी,' उसने अधिकारियों पर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तब तक
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीबीआई की टीम पहले ही उसके घर पहुंच चुकी थी।
इंदिरा गांधी ने न केवल चरण सिंह को हराया था, बल्कि उन्होंने
जनता सरकार की अक्षमता को उजागर करने में कामयाब रहा, और
इससे इसके नेताओं के बीच दरारें और गहरी हो जाएंगी। यहां तक कि जनता पार्टी के अध्यक्ष भी।
चंद्र शेखर ने सिंह की अक्षमता की आलोचना की।
उसे गिरफ्तार करके चरण सिंह ने सोचा कि वह हीरो बन जाएगा।
इसके विपरीत, वही कहानी की नायिका बनकर उभरी।

नौवीं

अब आप राज नारायण से मिल लो (राज से मिलने का समय आ गया है)
नारायण)' कपिल मोहन ने जुलाई 1978 में इंदिरा गांधी को संदेश भेजा।
1978 के मध्य तक, जनता सरकार के शीर्ष नेता

खुलेआम युद्ध की स्थिति थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने गृह मंत्रालय को बर्खास्त कर दिया था।
मंत्री चरण सिंह और स्वास्थ्य मंत्री राज नारायण ने 30 जून को
1978; अब वे विद्रोह पर उतर आए थे। इंदिरा गांधी के लिए अब निर्णायक क्षण आ गया था।
अंधेरे से बाहर निकलो और हमला करो।
'Main nahin miloongi, Sanjay mil laenge (I will not meet him, but
संजय उससे मिलेगा,' उसने उससे कहा।
कांग्रेस ने कहा, 'संजय कपिल मोहन के बहुत करीब हो गए थे।'
नेता कमल नाथ।
अब तक संजय अपने अनिच्छुक साथी को मनाने में कामयाब हो चुका था।
मां को पता था कि राज नारायण सत्ता को उखाड़ फेंकने की उनकी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।
जनता सरकार। वह चरण सिंह के करीबी थे—वह अक्सर उन्हें फोन करते थे।
स्वयं हनुमान, चरण सिंह के राम के समान। कम से कम 100 बार जेल जा चुके हैं।
आंदोलनों में भाग लेने के कारण, अंग्रेजों द्वारा उन्हें एक आतंकवादी के रूप में देखा जाता था।
1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। सत्ता पलटने का खेल शुरू होने के साथ ही
यह उनके लिए स्वाभाविक था—अगर वह ऐसा करते तो वह एक चैंपियन पहलवान बन सकते थे।
उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं किया था—उन्होंने सिंह को मुखिया के रूप में स्थापित करने में मदद की थी।
1967 में उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, 1968 में उन्हें सत्ता से हटाने में मदद की और फिर शामिल हो गए।
जब सिंह ने 1974 में भारतीय लोक दल की स्थापना की थी, तब वह इसी दल से जुड़े थे। अब वह चाहते थे कि...
उन्हें मोरारजी देसाई के स्थान पर प्रधानमंत्री बनाओ। उनका मंत्र था...
स्पष्ट: 'चौधरी साहब का अनुसरण करें'।

■

संजय को कपिल से विस्तृत और नियमित प्रतिक्रिया मिल रही थी।
मोहन ने जनता सरकार के भीतर बढ़ते तनाव के बारे में बताया।
मार्च 1978 में, बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जो एक शक्तिशाली नेता थे,
समाजवादी आंदोलन के नेता ने 26 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया।
राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियां, कार्यान्वयन
राज्य द्वारा नियुक्त मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशें।
इस कदम से व्यापक विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी।
जनसंघ की रीढ़ की हड्डी बनाने वाली जातियाँ अत्यधिक
उत्तेजित।
चरण सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय लोक परिषद और उनके बीच की सहमति
जून 1977 में गठित दल (बीएलडी) और जनसंघ में दरार आने लगी। इस रणनीतिक
गठबंधन (जो पूरी तरह से जनता पार्टी के भीतर था) के तहत, दोनों पार्टियां
इन लोगों ने मिलकर छह मुख्यमंत्री नियुक्त करने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके
बाद
जून 1977 में हुए राज्य चुनावों में, बीएलडी ने कर्पूरी को सत्ता में लाने में कामयाबी
हासिल की थी।
बिहार में ठाकुर मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री के रूप
में, और देवी
Lal in Haryana, while the Jan Sangh placed Bhairon Singh Shekhawat
in Rajasthan, Shanta Kumar in Himachal Pradesh, and Kailash Joshi in
मध्य प्रदेश। उच्च जाति के समर्थन खोने के डर से जन
संघ ने चरण सिंह से नाता तोड़ लिया और मोरारजी के साथ गठबंधन कर लिया।
देसाई की कांग्रेस (ओ) इसके बजाय। (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 3 देखें।)
चरण सिंह ने जनसंघ के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर दिया।

प्रधानमंत्री के बेटे कांति के कुकर्मों की निंदा करना शुरू कर दिया।
देसाई।
जून 1978 में, चरण सिंह ने मोरारजी देसाई को एक पत्र लिखा।
उस मंत्रिमंडल का वर्णन करते हुए, जिसका वह अभी भी हिस्सा थे, उन्होंने उसे 'एक संग्रह' बताया।
नपुंसक पुरुष इंदिरा गांधी को न्याय के कटघरे में लाने में सक्षम नहीं हैं।
मोरारजी देसाई ने सिंह और राज नारायण दोनों को दिखाकर जवाबी कार्रवाई की।
उनके इस्तीफे 1 जुलाई 1978 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे।
जनता सरकार के पतन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है—जो कि होने वाला है
एक साल बाद—शुरू हो गया था।
■

राम मनोहर लोहिया के माध्यम से ही मोहन मीकिन परिवार को यह विरासत मिली।
राज नारायण से पहली बार मुलाकात हुई थी। लोहिया और आरएसएस नेता नानाजी
देशमुख, कपिल मोहन के बड़े भाई वी.आर. मोहन के अच्छे दोस्त थे।
भाई। वी. आर. मोहन की पत्नी, कोमिला, खुद को राखी बहन मानती थीं।
लोहिया और देशमुख दोनों के।
कपिल मोहन राज नारायण की कारों, पैसों आदि संबंधी जरूरतों का ख्याल रखते थे।
और यात्रा। वर्षों बाद कंपनी ने उन पर एक फिल्म बनवाई।
'ग्रेट हनुमान' नामक फिल्म में उन्होंने स्वयं अभिनय किया था। 'वे ऐसे थे जैसे...'
'भाई,' कपिल मोहन की पत्नी पुष्पा मोहन ने याद करते हुए कहा। 'राज नारायण
'हम कपिलजी के पलंग पर बैठते थे और बातें करते थे।'
राज नारायण शाकाहारी थे और उन्हें दाल, सब्जी, खीर पसंद थी...और वे
पुष्पा ने कहा, 'राज नारायण हमेशा पकाए गए भोजन की प्रशंसा करते थे। राज नारायण अक्सर ऐसा करते थे।'
to often phone me and say, “Bahurani, aaj dus logon ka khana bhej
(बहू, कृपया दस लोगों के लिए खाना भेज दीजिए)” या वह

मोहन मीकिन अनिल बाली को अक्सर सुबह 5:30 बजे फोन करते और उनसे अपने से मिलने आने वाले 15-20 लोगों के लिए नाश्ता भेजने का अनुरोध करते।
कैंटीन उनके घर पर नाश्ता पहुंचाएगी।
1934 से 1974 तक समाजवादी रहे नारायण काफी धार्मिक हो गए थे।
आपातकाल के दौरान जेल में रहते हुए उन्होंने पूजा-अर्चना शुरू कर दी थी।
ज्योतिष में विश्वास करना। 1977 में चुनावों की घोषणा के बाद,
जेल से रिहा होने के बाद वह अपने परिवार से मिलने लखनऊ गया था।
ज्योतिषी, पी. डी. कपूर।
उन्होंने पूछा, 'मेरा भविष्य कैसा होगा?'
ज्योतिषी ने उससे कहा, 'तुम जीतने वाले हो।'
जनता के नेता इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए एक सशक्त नेता चाहते थे।
गांधी ने 1977 के चुनावों में भाग लिया था। उन्होंने चंद्र और चंद्र दोनों से राय ली थी।
शेखर और ए. बी. वाजपेयी। दोनों में से कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था।
राज नारायण ने चुनौती स्वीकार की और वह जीत गए।
नारायण खुद को 'दिग्गजों का नाश करने वाला' मानना पसंद करते थे। आखिरकार, उन्होंने
उन्होंने 1975 में मजिस्ट्रेट की अदालत और जनता की अदालत में इंदिरा को हराया था।
1977 में। हालाँकि उन्हें अक्सर दरबारी विदूषक के रूप में जाना जाता था और
मीडिया द्वारा विद्रोही करार दिए जाने के बावजूद, वह कमजोर नहीं थे। उन्होंने जानबूझकर संबंध बनाए।
स्वयं को 'वर्गहीन' दिखाने के लिए एक देहाती छवि अपनाना—समाजवादियों के लक्ष्यों में से एक था।
समय बिताने के लिए—और ध्यान आकर्षित करने के लिए। और उसका मसखरापन एक छिपे हुए रहस्य को छुपाता था।
फौलादी इच्छाशक्ति और किसी भी ऐसे व्यक्ति को नीचे गिराने का दृढ़ संकल्प जो उसने उसे पार कर लिया। अगर वह किसी के लिए था, तो वह पूरी तरह से उस व्यक्ति के लिए था, लेकिन

अगर वह किसी के खिलाफ होता, तो वह बिना किसी रोक-टोक के उससे भिड़ जाता। विपक्ष।
उनके पास एमए और एलएलबी की डिग्री थी, साथ ही उनका एक प्रभावशाली पारिवारिक इतिहास भी था, जिसका उन्होंने उल्लेख किया।
कभी-कभी इसका मतलब होता था जब वह उत्तेजित होता था। एक बार वह गुस्से में चिल्लाया था।
'Bol dena hum Raja Balwant Singh ke khaandan se hain, ma ka doodh
piya hai, eent se eent baja daenge (Tell them I belong to Raja Balwant
सिंह के परिवार, मैंने अपनी माँ का दूध पिया है, मैं तुमसे मुकाबला करूँगा।'
हालांकि उन्होंने इंदिरा गांधी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, फिर भी उन्हें लगा कि उन्होंने
उन्हें जनता सरकार से उनका हक नहीं मिला। और उन्होंने मोरारजी को माफ नहीं किया।
देसाई ने उसे बर्खास्त करने के लिए उसे माफ नहीं किया। न ही देसाई उसे उसके किए के लिए माफ करने को तैयार थे।
विपक्ष। एक बार जब वे अभी भी कैबिनेट मंत्री थे, तब वे गए थे
मैंने प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर स्वागत किया और उनकी जैकेट पर लगे पानी से उन्हें थपथपाया।
इत्र। देसाई ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, 'तुमने इत्र लगाया।'
लेकिन मेरे बारे में बदनामी फैलाओ।'
■

जब राज नारायण जुलाई 1978 में 46वें स्थान पर संजय गांधी से मिलने आए,
कपिल मोहन के पूसा रोड स्थित घर पर, उन्होंने माफ करने और भूल जाने का फैसला कर लिया था।
'नमक वाली पतली दाल' (बहुत अधिक नमक वाली पानीदार दाल) की यादें
उसे दिन-प्रतिदिन खाना पड़ता था, और उसे उन बदबूदार शौचालयों का सामना करना

पड़ता था।
आपातकाल के दौरान तिहाड़ जेल में इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया—
सौजन्य इंदिरा गांधी
गांधी और संजय।
अपनी पहली मुलाकात में, संजय और नारायण ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए शुरुआत की।
'गिलाए-शिकवाए' (शिकायतें और आपत्तियां)। इसके कारण कई घटनाएं हुईं।
दोनों के बीच बैठकें। या तो डम्पी अहमद या कमल नाथ
मैं संजय को कपिल मोहन के घर तक छोड़ देता था। कभी-कभी वे बैठते थे।
पूसा रोड नंबर 46 के बाहर कार में, संजय 'नेताजी' से बातचीत कर रहे थे।
कभी-कभी वे अंदर इंतजार करते थे। बाकी समय वे अध्ययन कक्ष के बाहर एक कमरे में इंतजार करते थे।
जहां आमतौर पर बैठक होती थी।
'मैं अक्सर कपिल मोहन के साथ कमरे के बाहर बैठा करता था जब
डम्पी अहमद ने याद करते हुए बताया, 'दोनों ने अंदर बात की।'
कपिलजी अपने मेहमानों से मिलते और उन्हें अपने कमरे में अकेले बातचीत करने के लिए छोड़ देते थे।
पुष्पा ने बताया, 'वह अध्ययन कक्ष था। कमरा ध्वनिरोधक था।'
कभी-कभी वे किसी सामाजिक समारोह की आड़ में मिलते थे।
एक बार हमने अन्नपराशन (बच्चे को दिया जाने वाला पहला भोजन) समारोह किया था।
हमारा भतीजा। नेताजी आए थे। संजय भी आया था।
अपनी पहली मुलाकात से ही उन्होंने तय कर लिया था कि मोरारजी देसाई
उन्हें जाना पड़ा और चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उन महीनों में
योजना धीरे-धीरे आकार लेती गई और संजय ने उसकी पटकथा लिखी।
गांधी और राज नारायण, इंदिरा गांधी की निगरानी में, और सुविधा प्रदान करने वाले
कपिल मोहन। संजय और नारायण दोनों भी इस बात से सहमत थे कि
जगजीवन राम को पहले हाशिए पर धकेलना होगा। बाबूजी उभर रहे थे।
जनता पार्टी के भीतर मोरारजीभाई के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर सकते

हैं और
उनके लिए परिस्थितियाँ और भी जटिल हो गईं; यहाँ तक कि पूर्व जनसंघ समूह को भी
बाबूजी को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जो बेहतर प्रबंधन कर सकते थे
गुटों में बंटी सरकार।
इंदिरा गांधी को जगजीवन राम पर भरोसा नहीं था, लेकिन उनके मन में कोई प्रेम भी नहीं था।
वह और चरण सिंह के बीच भी कहीं खोई हुई थी। उसने नेहरू की जमकर आलोचना की थी और
उनकी नीतियों को देखते हुए, उन्होंने सहकारी खेती को तिरस्कारपूर्वक 'एक' करार दिया।
'बोल्शेविक आंदोलन', और उनका मानना था कि महात्मा गांधी को
उन्होंने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री चुना है, नेहरू को नहीं, जिन्होंने ऐसा किया था।
भारत को नहीं समझ पाते।
इंदिरा गांधी के लंबे समय से कड़े आलोचक रहे उन्होंने उन्हें झूठा कहा था, और
ब्रिटिश लेखक डेविड सेलबोर्न के अनुसार, वह 'क्लियोपेट्रा जितनी दुष्ट' थी। लेकिन, शुरू से ही,
जैसा कि हमने देखा, वह उसके साथ सहयोग करने की अपनी इच्छा और उसके प्रति दुविधा में था।
जब मार्च 1976 में उनके साथ एक समझौता हुआ था, तो
उसे जेल में डाल दिया। सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया, 'वह उससे नफरत करता था।'
दरअसल, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह प्रधानमंत्री थीं और वह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। और क्योंकि वह
उसे जेल में डालने वाली ने उसे जेल में डालना चाहा था।' लेकिन, 1978-79 में, उसका
प्रधानमंत्री बनने की आवश्यकता उनकी इच्छा से कहीं अधिक प्रबल थी।
उसे दंडित करो।
■

कई उद्योगपतियों की तरह राजनेताओं को खुश करने के अलावा, एक नजरिया रखते हुए
दीर्घकालिक लाभों के संदर्भ में, मोहन मीकिन के शीर्ष अधिकारियों की अपनी अलग राय थी।
मोरारजी देसाई को पद से हटाने में रुचि रखने के कारण—और
इंदिरा गांधी की मदद करना। देसाई, नीति के प्रबल समर्थक थे।
शराबबंदी के चलते वे अपने शराब उत्पादन संयंत्रों को बंद करना चाहते थे।
उनकी निकटता को जानते हुए देसाई को उनके इरादों पर संदेह हुआ।
इंदिरा को।
मोहन मीकिन की उत्पत्ति कुख्यात ब्रिगेडियर से जुड़ी हुई थी।
जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जिन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया था
जलियांवाला बाग के अंदर जमा हुए निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं।
1919 में अमृतसर में सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। उनके पिता,
एडवर्ड अब्राहम डायर, 1820 के दशक में इंग्लैंड से आकर बस गए थे।
भारत की पहली शराब बनाने की फैक्ट्री। वर्षों बाद, इसे एक भारतीय ने अधिग्रहित कर लिया।
नरेंद्र नाथ मोहन, और बाद में उन्हें मोहन मीकिन के नाम से जाना जाने लगा।
ब्रूअरीज़। कपिल मोहन ने नाम से ब्रूअरीज़ हटा दिया।
इंदिरा गांधी ने कपिल मोहन के बड़े भाई वी. आर. मोहन को गोद में लिया था, जो
उनकी मृत्यु से पहले, वह कंपनी की प्रमुख थीं और उनका बहुत सम्मान था।
उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
उन्होंने उन्हें यह पुरस्कार भी दिया था। उन्होंने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया था।
1971 के आम चुनावों में लखनऊ से। जब वह हार गए, तो उन्होंने उन्हें वापस लाया।
उन्हें राज्यसभा में भेजा गया।
एक समय था, जब मेनका के संजय के जीवन में आने से पहले, इंदिरा के पास
संजय की शादी मंजुला से कराने के विचार पर विचार किया गया था, वी. आर. मोहन

की पत्नी।
बेटी। हालाँकि, मंजुला के मन में कोई और था। 'कर्नल (वी. आर.
पुष्पा मोहन ने याद करते हुए कहा, ‘कर्नल वी. आर. मोहन बहुत परेशान थे, उन्हें इस बात की चिंता थी कि वे कैसे समझौता तोड़ेंगे।’ उन्होंने आगे कहा, ‘वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि वे कैसे समझौता तोड़ेंगे।
यह बात प्रधानमंत्री को बता दें।’ वी. आर. मोहन और उनकी पत्नी इंदिरा गांधी से मिलने गए।
उन्होंने उसे अपनी बेटी के फैसले के बारे में बताया। वह हंस पड़ी। 'नहीं'
'चिंता मत करो,' उसने उन्हें आश्वस्त किया। 'मैंने भी ऐसा ही किया था।' उसने उन्हें बताया।
यह कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध फिरोज गांधी से शादी की थी।
पिता। जब मंजुला की शादी उसकी पसंद के लड़के, इंदिरा से हुई।
गांधी ने उन्हें और उनके ससुराल वालों को चाय पर आमंत्रित किया और उन्हें एक साड़ी भेंट की।
‘₹1,100’। पुष्पा मोहन ने कहा, ‘इंदिराजी हमें परिवार की तरह मानती थीं। वह हमें परिवार की तरह मानती थीं।’
मुझसे नींबू का अचार बनाने को कहा। उसे हमारे बनाए तरीके से अचार पसंद आया।
1973 में वी. आर. मोहन के निधन के बाद—वे केवल छियालीस वर्ष के थे—अधिक व्यवहारिक कपिल मोहन ने कंपनी की बागडोर संभाली। वहीं इंदिरा गांधी के पास एक वी. आर. मोहन के प्रति लगाव के कारण कपिल संजय के अधिक निकट थे।
‘सर्वशक्तिमान’
संजय ने कपिल के व्यवसाय में कई तरह से मदद की थी।
आपातकाल के वर्षों के दौरान। सुभाष ने याद करते हुए कहा, 'मैं इसे विस्तार से नहीं बताना चाहता।'
भाजपा नेता आर्य ने इस मामले पर कोई भी जानकारी देने से परहेज किया। संजय
उन्होंने अपनी मारुति उद्योग द्वारा निर्मित पहली मारुति कार कपिल को उपहार में दी थी।
मोहन। अनिल बाली ने याद करते हुए कहा, 'मैं खुद कपिल के पास कार लेकर आया

था।'

■

हालांकि इंदिरा गांधी राज नारायण के साथ सहयोग कर रही थीं, फिर भी
वह लगातार इस बात पर नजर रखता था कि वह क्या कर रहा है। 'एक सुबह मैंने
जब वे उसके घर पहुंचे तो वहां चार पानी के टैंकर खड़े थे—वे
अनिल बाली ने याद करते हुए बताया, 'वह घर के आसपास के पूरे इलाके की सफाई कर रहा था।'
मैंने पूछा कि क्या हुआ था। गार्डों को बाहर एक आदमी मिला था।
घर में जाकर वह जौ (अनाज) बिखेर रहा था और गुनगुनाते हुए एक मंत्र का जाप कर रहा था।
उसने पूछताछ करने वालों को बताया कि उसे नारायण ने वहां भेजा था। इंदिरा
संदेह था कि नारायण जादू टोना (काला जादू टोना) कर रहा होगा।
जादू) उसके घर के बाहर।
'राज नारायण से बात करो और पता करो कि वो क्या कर रहे हैं?' इंदिरा का
राजनीतिक सलाहकार एम. एल. फोतेदार ने बाली को बताया।
'Netaji yeh sab kya hai (Netaji, what is all this),' Bali asked Raj
नारायण।
'Bol dae us budhiya ko ki chinta mat kare (Tell that old hag not to
चिंता),' उन्होंने कहा। वह उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहते थे। 'श्री इंदिरा Gandhi maen mati nahin hai (Mr Indira Gandhi does not have good
(समझदारी से),' उन्होंने कहा। वह प्रभाव दिखाने के लिए उन्हें श्री कहकर पुकारते थे। वह इसका जिक्र करती थीं।
him as Banarsi babu.

■

राज नारायण के साथ अपनी कई मुलाकातों के दौरान, संजय गांधी ने लगातार
चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की अपनी रणनीति को परिष्कृत करने के लिए। 'वह
संजय ने नारायण को आश्वासन दिया, 'हमें कांग्रेस (आई) का समर्थन प्राप्त है।'
छठी लोकसभा के गणित का गहन अध्ययन किया। जनता पार्टी द्वारा
तब कांग्रेस के पास 302 सीटें थीं और सहयोगियों के साथ 345 सीटें थीं। इंदिरा
गांधी की कांग्रेस के पास थीं।
72, कांग्रेस के विभाजन के बाद वाई.बी. चव्हाण के नेतृत्व वाली कांग्रेस (एस) ने
सत्ता संभाली।
जनवरी 1978 में, जनता पार्टी में चरण सिंह की बीएलडी के पास 75 सीटें थीं।
जनता पार्टी में, चरण सिंह की बीएलडी के पास 71 सीटें थीं।
समाजवादियों और सीएफडी के पास 28-28 सीटें थीं, जनसंघ के पास 93 सीटें थीं,
मोरारजी की कांग्रेस (ओ) 51, चंद्र शेखर के यंग टर्क्स समूह 6,
और 25 अविवाहित थे।
संजय गांधी और राज नारायण दोनों जानते थे कि उन्हें ऐसा करना होगा।
चरण सिंह को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए जनता पार्टी को तोड़ना होगा। और
इसका एक तरीका यह होगा कि बीएलडी और सोशलिस्ट सांसदों को धीरे-धीरे अलग
किया जाए।
मूल निकाय। ऐसा होने के लिए, नारायण को आगे बढ़ना होगा।
उन्होंने जनसंघ और आरएसएस का विरोध किया। नारायण ने भी इस हमले में भाग
लिया।
उन्होंने जनता गुटों में मौजूद सभी पूर्व समाजवादियों को लुभाने की योजना बनाई थी;
कुल मिलाकर 60 लोग थे (इनमें सोशलिस्ट पार्टी के 28 लोग शामिल थे, जिनका
नेतृत्व
जॉर्ज फर्नांडीस, राज नारायण समूह के 26 सदस्य बीएलडी में और 2 अन्य सदस्य
चंद्र शेखर समूह के युवा तुर्कों का समूह)।
One day, to please him, Sanjay told Narain, ‘Aap bhi ban sakte ho
प्रधानमंत्री (आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं)। नारायण ने समझदारी से सिर

हिलाया। लेकिन वह बहुत ही अनुभवहीन थे।
प्रलोभन में फंसना बड़ी चतुराई थी। 'हां, मेरे बेटे, यह सच है,' उसने संजय से कहा, '...लेकिन
फिलहाल चौधरी साहब (चरण सिंह) को ही मुख्य भूमिका निभाने दीजिए।
प्रधान मंत्री।'
राज नारायण का इंदिरा गांधी के प्रति नरम रुख सार्वजनिक रूप से सामने आ गया।
1978 के अंत तक दिखाई देने लगा। उपचुनाव जीतने के मात्र छह सप्ताह बाद ही।
कर्नाटक के चिकमगलूर से लोकसभा चुनाव में
नवंबर 1978 में, संसद की विशेषाधिकार समिति ने रद्द कर दिया
उनकी लोकसभा सदस्यता। उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया गया।
संसद ने उन्हें उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया था।
मंत्री ने अधिकारियों को जानकारी एकत्र करने से रोक दिया था।
संजय गांधी की मारुति परियोजना पर संसद में पूछे गए एक सवाल का जवाब देने के लिए कहा गया। जब उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया, तो संसद ने उन्हें 20 तारीख को जेल भेज दिया।
दिसंबर 1978। वह वहाँ दस दिनों तक रहीं—जब तक कि घर खाली नहीं हो गया।
स्थगित। जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने गरजते हुए कहा...
संसद में, नारायण ने अपना बचाव करते हुए कहा, 'कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।'
उन्होंने ज़ोर-शोर से विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें जनता का जनादेश प्राप्त हुआ था। संसद
उसे इसे रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था।
■

1978 के अंत तक, राज नारायण अपने चरम पर थे, क्योंकि उनकी रणनीति ने
मोरारजी देसाई सरकार का स्वरूप उभरने लगा। एक घटना से
उस समय से पता चलता है कि संजय नारायण को रिझाने के लिए कितनी उत्सुकता से प्रयास कर रहा था।

मैं अभी-अभी अमेरिका से लौटा था और राज से मिलने गया था।
समाजशास्त्री आनंद कुमार ने याद करते हुए कहा, 'नारायण।' 'यह अवश्य ही रहा होगा।'
2 जनवरी 1979 को।
उस दिन, उन्होंने रेस कोर्स रोड स्थित 8 नंबर के होटल में रात के खाने के बाद एक साथ बैठकर खाना खाया।
राज नारायण को आवंटित किया गया मंत्रिस्तरीय बंगला
स्वास्थ्य मंत्री ने बंगले का नंबर 9 से बदलकर 9 कर दिया था।
आठ बज रहे थे, आठ उनके लिए अधिक शुभ माना जाता था। रात के 10 बज चुके थे।
नारायण कौमी एकता मंच पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने अभी-अभी पढ़ा था।
सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव रखा गया था। यह उनकी योजना का हिस्सा था।
आरएसएस और पूर्व जनसंघ की सांप्रदायिक विचारधारा के खिलाफ एक आक्रामक अभियान
एजेंडा।
उन्होंने कहा, 'अब जब तुम वापस आ गए हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपना समय दो।'
आनंद कुमार। 1952 में विधायक बनने तक, नारायण का पालन-पोषण आनंद कुमार द्वारा किया गया था।
कुमार के दादा, विश्वनाथ शर्मा। बाद में, 1960 के दशक में, उन्होंने भरोसा किया।
अपने चाचा कृष्ण नाथ पर, जो राम मनोहर लोहिया के करीबी सहयोगी थे।
आनंद कुमार नारायण को चाचा कहकर बुलाते थे।
इसी समय नारायण का पीए कमरे में दाखिल हुआ।
उन्होंने कहा, ‘साहिब, वो लोग आ गए हैं।’
अपने बॉस को।
'कौन लोग (कौन से लोग)?' राज नारायण ने पूछा।
'वाही,' पीए ने आगंतुकों के प्रति स्पष्ट श्रद्धा दिखाते हुए इस शब्द पर जोर दिया।

‘Acha, bhej do andar (OK send them in),’ Raj Narain said as he
उसे समझ आ गया कि उसका सहायक किस ओर इशारा कर रहा था।
पीए ने दो लोगों को अंदर पहुंचाया।
एक युवक था, गोरा और लंबा, और दूसरे को मैंने पहचान लिया।
आनंद कुमार ने याद करते हुए कहा, 'आर. के. धवन।'
कुमार ने यह बात गौर की और अपने मन में यह बात नोट कर ली कि राज नारायण वह अपने आगंतुकों का अभिवादन करने के लिए नहीं उठा। तब तक कुमार को यह बात समझ आ चुकी थी।
उस गोरे, नौजवान की पहचान। वह संजय गांधी थे।
‘Aaiye baithiye (Please take a seat),’ Raj Narain welcomed his visitors. ‘Aap ke liye kya mangwayain (What can I offer you)?’
फिर उन्होंने आनंद कुमार का उनसे परिचय कराते हुए कहा कि वह अभी-अभी 'लौटा' है।
कुमार अमेरिका से चार साल की पढ़ाई के बाद वापस लौटे थे।
अमेरिका में जाकर, विदेशों में आपातकाल के खिलाफ समर्थन जुटाने में मदद की।
‘हमारे लिए संजय गांधी सबसे बड़े खलनायक थे।’ उन्होंने तुरंत अपनी बात रखी।
दूर हो जाओ।
इस घटना से पता चला कि तब तक नारायण और संजय की मुलाकातें होने लगी थीं। हालांकि नारायण ने संजय के साथ अपनी मुलाकातों को गुप्त रखा था, फिर भी अक्सर ऐसा होता था।
बेहद गुप्त रहस्य, जिसे केवल कुछ ही लोग जानते हैं। साथी समाजवादी नेता
मधु लिमये—दोनों ने जनसंघ के खिलाफ मिलकर काम किया और
1978-79 में आरएसएस ने उनसे छह महीने बाद पूछा था कि क्या वे उनसे मिले थे।
संजय गांधी ने इंदिरा गांधी के साथ गुप्त रूप से सरकार बनाने की योजना बनाई।
गांधी जी की मदद। नारायण ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, 'उन्होंने मुझसे मुलाकात की थी।'
दो बार... लेकिन मैंने उनसे राजनीति पर चर्चा नहीं की।
■

अपनी वापसी की पूरी अवधि के दौरान, गांधी की सबसे बड़ी चिंता यही थी।
सवाल यह था कि संजय को सुरक्षित कैसे रखा जाए। और इसका सबसे अच्छा तरीका था उससे छुटकारा पाना।
जनता सरकार को जल्द से जल्द हटाना था; वे इस मामले में अडिग थे।
संजय को सजा दिलाने के उनके प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
कोर्ट के मुताबिक, संजय मई 1978 में किस्सा मामले में पहले ही एक महीना जेल में बिता चुका था।
कुर्सी का मामला, जो अंतिम फैसले की ओर बढ़ रहा था। केकेके एक
यह राजनीतिक व्यंग्य फिल्म तीन बार के सांसद द्वारा फिल्माई गई थी।
राजस्थान में अमृत नाहटा, एक कांग्रेसी नेता जो जनता पार्टी में शामिल हो गए थे।
1977 में पार्टी। संजय और उनकी मारुति पर आधारित पैरोडी के प्रिंट।
शबाना आज़मी और उत्पल दत्त अभिनीत इस प्रोजेक्ट में कुछ व्यंग्यात्मक पंक्तियाँ थीं, जैसे कि...
'महोदय, इस व्यक्ति को छोटी कारें बनाने का लाइसेंस दे दीजिए क्योंकि वह
उसने इसे अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था।' इन्हें सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था
आपातकाल से पहले, अप्रैल 1975 में सेंसरशिप की मंजूरी मिल गई थी। लेकिन आपातकाल के दौरान
आपातकाल के दौरान, इन प्रिंटों को नष्ट कर दिया गया था। जब जनता सरकार सत्ता में आई, तो उसने संजय और सूचना एवं प्रसारण विभाग पर आरोप लगाया।
मंत्री वी.सी. शुक्ला पर उन्हें नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप है।
केकेके के अंतिम फैसले से पहले इंदिरा गांधी बहुत तनाव में थीं।
लेकिन जब संजय और शुक्ला को दो सजाएं दी गईं तो उसे राहत मिली। लेकिन जब संजय और शुक्ला को दो सजाएं दी गईं तो उसे राहत मिली।
फरवरी 1979 में वर्षों की कैद के बाद, उन्हें जमानत मिल गई और वे
उच्च न्यायालय में अपील की गई। सर्वोच्च न्यायालय को संजय को बरी करना था और
शुक्ला ने अप्रैल 1980 में सत्ता में वापसी के बाद उन पर लगे आरोपों को खारिज कर

दिया।
31 मई 1979 को संजय पर भी दुरुपयोग के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा।
मारुति मामले में अपने व्यापारिक सौदों में इंदिरा गांधी को मिली शक्ति के बारे में उन्हें पता था।
शाह आयोग द्वारा उन पर, संजय और अन्य लोगों पर आरोप लगाए जाने के बाद
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि सरकार स्थापित करने की तैयारी कर रही थी
उस पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें गठित की जानी थीं। वह स्पष्ट थी कि उन्हें मुकदमा चलाने से पहले ही कार्रवाई करनी होगी।
संजय—और वह भी।
एक्स

1978 के उत्तरार्ध में इंदिरा गांधी का भाग्य अनुकूल रहा।
यह अप्रत्याशित लाभ सुरेश राम, जगजीवन राम के बेटे से जुड़े एक यौन घोटाले में हुआ था।
21 अगस्त 1978 को, गेट के सामने एक कार दुर्घटना हुई थी।
दिल्ली के बाहरी इलाके मोहन नगर में स्थित मोहन मीकिन संयंत्र।
मर्सिडीज कार ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार के अंदर
वे एक पुरुष और एक युवती थे। उन्हें डर था कि उन पर हमला हो सकता है।
प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा सूचना मिलने पर वे संयंत्र के द्वार की ओर दौड़े।
दुर्घटना के साक्षी चौकीदार ने कार्यालय में फोन किया।
इंटरकॉम से अनिल बाली, जो उस समय मैनेजर थे, बाहर आए। उन्होंने सुरेश को पहचान लिया।
रक्षा मंत्री जगजीवन राम के बेटे राम ने उन्हें अंदर ले जाकर पूछताछ की।
सुरेश राम ने बाली को बताया कि उसका पीछा किया जा रहा था और वह बचने की कोशिश कर रहा था।
जब वह पीछा करने वालों से बचने की कोशिश कर रहा था, तभी दुर्घटना हो गई। उसकी कार

उनके पीछे जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता, के.सी. त्यागी और ओम पाल सिंह चल रहे थे, जो
वे राज नारायण के शिष्य थे और राम को अपने संरक्षण में रखे हुए थे।
कई दिनों तक निगरानी रखी गई।
'Babuji dekh laenge garhi ko (My father will take care of the car),'
सुरेश राम ने बाली को क्षतिग्रस्त कार के बारे में बताया। बाली ने दंपति को भेज दिया।
कंपनी की एक कार में घर।
सुरेश राम ने उसी दिन कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी।
स्टेशन पर उसने जो कहानी सुनाई, वह उसके द्वारा सुनाई गई कहानी से कुछ अलग थी।
बाली के लिए। उसने आरोप लगाया कि उसे पिछली रात (20) अपहरण कर लिया गया था।
अगस्त 1978 में, एक दर्जन हट्टे-कट्टे आदमियों ने उन पर हमला किया। जाहिर तौर पर, उनकी मर्सिडीज बेंज में
नई दिल्ली में दो टैक्सियों ने उसका पीछा किया। जब वे निगमबोध घाट के पास एक सुनसान जगह पर पहुँचे, तो पीछा करने वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया।
उन्होंने गाड़ी रोकी, बाहर कूदे और अपनी रिवाल्वर निकाल लीं। उन्होंने गोलियां चलाईं।
उन्होंने कार का दरवाजा खोला और युवती को पीछे बैठा दिया।
राम को जबरन मोदीनगर ले जाने के लिए मजबूर किया गया; और उसे और उस महिला को ले जाया गया
उन्हें स्कूल के एक कमरे में ले जाया गया। उन्होंने राम से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा।
उसने मना कर दिया, उन्होंने उसे तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया।
उन्होंने बताया कि उन दोनों की आपत्तिजनक स्थिति में तस्वीरें ली गई थीं।
राज नारायण के सहयोगी ओम पाल सिंह ने कहा कि वे उनका पीछा कर रहे थे।

सुरेश राम हर तरह के ‘कुख्यात’ कामों में शामिल था।
गतिविधियों'। वे जानते थे कि वह 'पोलरॉइड' कैमरे से तस्वीरें लेता था।
'कैमरा' का इस्तेमाल वह अपनी प्रेमिका सुषमा चौधरी, जो दिल्ली में एक छात्रा है, को अपने पास रखने के लिए करता है।
कॉलेज, जो जाट समुदाय से था, जाँच में और परोक्ष रूप से प्राप्त करने के लिए
इस अभ्यास से उन्हें आनंद मिला। वे इसे छूना चाहते थे।
सुरेश ने कार के ग्लव कंपार्टमेंट में तस्वीरें ढूंढीं।
राम गाड़ी चला रहा था। नारायण के लड़कों ने जैसे ही उन पर हाथ डाला,
सुरेश राम और उसकी प्रेमिका की तस्वीरों पर, वे दौड़ पड़े।
अपने बॉस को तस्वीरें भेजें।
उस रात जगजीवन राम की मुलाकात नारायण से हुई। यह मुलाकात नारायण द्वारा आयोजित की गई थी।
कपिल मोहन अपने घर पर। हालांकि कपिल इंदिरा गांधी के करीबी थे,
राम और राजनीतिक क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ भी उनके उतने ही अच्छे संबंध थे।
स्पेक्ट्रम। सुरेश राम उनसे मिलने जाते थे, कांति देसाई और मोरारजी भी।
देसाई का बेटा।
That night, ‘Babuji Raj Narain ko manane aaye thae (Jagjivan Ram
राज नारायण को मनाने की कोशिश करने के लिए आए थे,’ बाली ने याद किया।
जगजीवन राम जाहिर तौर पर नारायण के साथ 'सौदा करना चाहता था'।
कपिल मोहन ने अपने उच्च पदस्थ अतिथि का स्वागत किया और चाय मंगाई।
और जलपान। लेकिन बाबूजी का मन नहीं था। जगजीवन राम
और नारायण लगभग बीस मिनट तक अंदर थे। जब राम
मीटिंग से बाहर निकलते ही कपिल ने उन्हें उनकी कार तक छोड़ा। यह जरूर हुआ होगा।
लगभग रात 11.45 बजे के आसपास।
जब कपिल मोहन घर में वापस आए, तो नारायण ने चुटकी ली।
खुशी से चिल्लाते हुए, 'आज ये काबू में आए (आज वो पकड़ा गया)।'
उन्होंने कहा: ‘बाबू जगजीवन राम ने मुझे वह सब कुछ देने की पेशकश की जो मैं

चाहता था—पैसा,
राज्य की मुख्यमंत्री का पद, तस्वीरों के बदले कुछ भी।
Apparently Jagjivan Ram also told him, ‘Main PM banane wala hoon,
kisi ko mantri banana ho toh batana (I am going to become PM soon,
अगर आप किसी को मंत्री बनाना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। राम द्वारा दिए गए तमाम प्रलोभनों के बावजूद, उनके और उनके बीच कोई समझौता नहीं हो सका।
नारायण।
फिर राज नारायण ने कुछ तस्वीरें कपिल को सौंप दीं।
मोहन ने कहा, 'उनमें से लगभग पंद्रह', और बाकी रख लिए। 'वहाँ अवश्य ही होंगे'।
बाली ने याद करते हुए कहा, 'उनकी संख्या चालीस से पचास के बीच थी।'
नारायण के जाते ही कपिल मोहन ने तुरंत बाली की ओर रुख किया।
‘ये तस्वीरें संजय को ले जाओ। अभी। तुरंत।’
बाली आश्चर्यचकित होकर आधी रात को इंदिरा गांधी के घर के लिए रवाना हो गया।
रात। 'मैं वहां करीब 1 बजे पहुंचा होगा। मैंने संजय से मिलने के लिए कहा।
गांधी जी ने कहा था कि यह अत्यंत आवश्यक है।
संजय की नींद खुल गई।
‘ये कोई आने का वक्त है?’ वह गुस्से से भड़क उठा।
मैंने उसे दुर्घटना के बारे में बताया और उसे तस्वीरें सौंप दीं।
He looked at them, ‘Tu kya mujhe pornography dikhane aaya hai
(क्या तुम मुझे अश्लील सामग्री दिखाने आए हो?)
‘Yeh pornography nahin hai, yeh Suresh Ram hai (This is not अश्लील सामग्री; यह सुरेश राम है)।
संजय बिना कुछ और कहे घर के अंदर चला गया।
मैडम जाग उठीं।
इंदिरा गांधी बाहर आईं। उन्होंने अपने सिर पर टोपी पहन रखी थी।
उसने पूछा, 'इसके बारे में और किसे पता है?'

बाली ने उन्हें के.सी. त्यागी और ओम पाल सिंह के बारे में बताया।
संजय ने अनिल बाली से कहा, 'तुम उन दोनों को कहीं सुरक्षित रख दो।'
(जगजीवन राम आखिरकार रक्षा मंत्री थे और उन्हें यह सुविधा मिल सकती थी)
इंदिरा गांधी के घर पर तस्वीरें जब्त करने के लिए छापा मारा गया।
इंदिरा ने बाली को निर्देश दिया, 'और तुम कपिल मोहन से कहो कि राज को संभाल कर रखे।'
नारायण नियंत्रण में है।
■

अगली सुबह (22 अगस्त को) टेलीग्राफ लेन स्थित 2 नंबर के घर पर फोन की घंटी बजी।
यह कृष्णकांत का घर था, जो उस समय जनता पार्टी के सांसद थे। यह 9
सुबह के समय परिवार के लोग खाने की मेज पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे।
कांट के बेडरूम में फोन था और वह उसका जवाब देने के लिए वहीं गए। कॉल
वह रक्षा मंत्री के आवास से था। जब वह लौटा तो...
dining room he remarked, ‘Ek aur bete nae apne baap ko duba diya

(एक और पुत्र अपने पिता के पतन का कारण बनता है)।' ये रहस्यमय शब्द थे
उस सुबह उसने अपने परिवार से केवल यही शब्द कहे थे।
दस मिनट बाद, रक्षा मंत्री के कार्यालय से एक आधिकारिक कार आई।
उसे लेने के लिए उसके घर गए। जब वह 6, कृष्णा मेनन मार्ग पर पहुंचा,
जहां जगजीवन राम रहते थे, उन्होंने वहां बैठे सभी लोगों को वहां से चले जाने के लिए कहा।
कमरे में। जब वे अकेले थे, राम खड़ा हुआ, उसने अपने गांधी वस्त्र उतार दिए।
cap and placed it at Kant’s feet. ‘Ab meri izzat apke haathon maen hai
(अब मेरा आत्मसम्मान आपके हाथों में है),’ उसने कांट से कहा। उसने कांट से कहा।
उनके बेटे सुरेश राम मुसीबत में पड़ गए थे। हालाँकि वे व्यापक रूप से

दिल्ली के सामाजिक हलकों में उसे बिगड़े हुए बच्चे के रूप में देखा जाता था और वह कई विवादों में फंस चुका था।
इस बार मामला गंभीर था। वह वेस्टर्न कोर्ट में एक कमरा इस्तेमाल कर रहा था, जो एक
संसद भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित सांसदों के लिए बनी इमारत में, उनकी मुलाकात के लिए।
प्रेमिका। दो रात पहले (20 अगस्त), वह उसे छोड़ने जा रहा था।
जब वह घर वापस आया तो राज नारायण के दो गुंडों, के.सी. ने उसका पीछा किया।
त्यागी और ओम पाल सिंह। उन्होंने कांत को बताया कि सुरेश राम ने क्या दाखिल किया था।
उनकी एफआईआर के बाद, बाबूजी ने अपने पुराने मित्र कांत से मामले को संभालने का अनुरोध किया।
वह नकारात्मक प्रचार नहीं चाहता था। क्योंकि वे साथ-साथ थे
कई वर्षों तक कांग्रेस में दोनों व्यक्ति एक-दूसरे का बहुत सम्मान करते रहे। कांट
उन्हें 1975 के मध्य में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, और राम ने इस्तीफा दे दिया था।
2 फरवरी 1977 को पार्टी।
कृष्णकांत जगजीवन राम के मुख्य समूह से बाहर एकमात्र व्यक्ति थे।
जिसे बाबूजी ने अपने जाने के इरादे के बारे में विश्वास में ले लिया था
कांग्रेस को हफ्तों पहले ही सूचना मिल जाती थी। यह बात दिसंबर 1976 की ही है।
वे कृष्णा मेनन मार्ग, नंबर 6 पर गुप्त बैठकें करते थे।
कृष्ण ने याद करते हुए कहा, 'बाबूजी को पार्टी से कब बाहर निकलना चाहिए, इस पर चर्चा हुई थी।'
कांत के पुत्र, रश्मि कांत।
दिसंबर 1976 की उन सर्दियों के हफ्तों के दौरान, कांट चुपके से बाहर निकल जाते थे।
रात 11 बजे वह घर से निकला, उसका सिर ढका हुआ था, चेहरा आधा ढका हुआ था।
गहरे रंग का कंबल।

आपातकाल लागू होने के बावजूद भी कोई
जब वह घर से बाहर निकला तो उसके आसपास पुलिसकर्मी मौजूद थे। सुरेश राम
वह उसे कोने पर अपनी कार में बिठाकर ले जाता और वे दोनों वहाँ से आगे बढ़ते।
जगजीवन राम का घर। जगजीवन राम द्वार पर तैनात पहरेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे।
कृष्णकांत के समय उनके आधिकारिक बंगले में मौजूद एक व्यक्ति ने 'चाय का ब्रेक' लिया था।
गाड़ी से अंदर आने की व्यवस्था की जा रही थी। वह यह सुनिश्चित करता था कि उसके कुछ निजी कर्मचारी अंदर आ सकें।
उस समय द्वार पर एक व्यक्ति तैनात था। बाबूजी जानते थे कि इंदिरा गांधी ने उन्हें वहां तैनात रखा था।
उन पर नजर रखी जा रही थी, उनसे मिलने आने वाले सभी लोगों की निगरानी की जा रही थी।
वे अपनी पिछली मुलाकातों में मुलाकात का समय तय करते थे।
रश्मी कांत ने बताया, 'मीटिंग के दौरान।' उन्हें पता था कि वे इसे तय नहीं कर सकते।
उन्होंने फोन को बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें संदेह था कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं।
थ्रिलर फिल्मों के लिए यही तो बढ़िया चीज़ है।
मुझे पता था कि पिता किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं।
और वे काफी नियमित रूप से मिलते थे। वह हमारे घर के पिछले दरवाजे से निकल जाता था।
घर खुला रखा था, ताकि वह सुबह-सुबह चुपके से अंदर घुस सके।
मुझे सामने के दरवाजे की घंटी बजानी पड़ी। बाद में उसने मुझे पूरी बात बताई।
कहानी।'
कभी-कभी एच. एन. बहुगुणा भी इन अंतिम बैठकों में उपस्थित होते थे।
रात की बैठकें। उनमें इस बात पर चर्चा हुई कि बाबूजी को कब और कैसे...
पार्टी छोड़ देना। यह जगजीवन राम के वास्तव में पार्टी छोड़ने से दो महीने पहले की बात है।
पार्टी 2 फरवरी 1977 को हुई थी। यह उससे एक महीने से भी अधिक पहले की बात

थी।
इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को चुनाव की घोषणा की। 'मेरे पिता ने
यह आभास कि बाबूजी को पता था कि श्रीमती गांधी जाने की योजना बना रही थीं
रश्मी कांत ने आगे कहा, 'जल्द ही चुनाव होंगे।'
जगजीवन राम चाहते थे कि यंग टर्क्स टीम उनके साथ मिलकर काम करे।
जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। 'मेरे पिता ने उनसे कहा कि उन्हें बात करनी होगी।'
चंद्र शेखर को, जो समूह का नेता था।
शेखर जेल में था। उसे 25 जून 1975 को गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन जब
अन्य युवा तुर्कों मोहन धारिया के साथ आपातकाल लागू किया गया था।
and Ram Dhan. Indira Gandhi had not arrested Krishan Kant, even
हालांकि यंग तुर्कों ने 1974 के दौरान जेपी के घर पर उनसे मुलाकात की थी।
75. जब भी वे मिलते, दो स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू)
कुछ लोग आकर किनारे पर बनी दीवार पर असुविधाजनक ढंग से बैठ जाते थे।
उन पर नज़र रखने के लिए घर के सामने एक नाली बनाई गई थी। एक बार अंदर जाने पर
वहीं, चंद्र शेखर उनके पास जाकर कहते, 'मुझे पता है'
आप अपना काम कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या चर्चा की' और वे
वह शर्मिंदा होकर दूर हट जाता।
अंततः, चंद्र शेखर ने जगजीवन के साथ जाने का विचार छोड़ दिया।
राम का सीएफडी।
कृष्णकांत ने जगजीवन राम को मीडिया से निपटने में मदद की।
राम चिंतित था क्योंकि सुरेश राम की तस्वीरों ने उनके
अखबार के दफ्तरों का रास्ता। भारतीय अखबार में पहले पन्ने पर एक खबर छपी।
एक्सप्रेस। इसे सईद नक़वी ने लिखा था—और यह एक लेख नहीं था।
सुरेश राम के प्रति सहानुभूतिहीन।
‘मुझे आरएनजी (इंडियन एक्सप्रेस के मालिक राम नाथ गोयनका) ने फोन किया था।’
नक़वी ने वर्षों बाद याद करते हुए कहा, 'और उन्होंने मुझसे अपने साथ चलने के लिए

कहा।'
हम उनकी स्टडबेकर कार में बैठे थे। जब वह महत्वपूर्ण लोगों से मिलने जाते थे।
लोग, वह अपनी स्टुडेबेकर में यात्रा करता था। रास्ते में, चार अक्षरों का उपयोग करते हुए
राज नारायण के खिलाफ शब्दों के बारे में उन्होंने कहा, "हमें बाबूजी की मदद करनी होगी।"
वे जगजीवन राम के घर पहुंचे और अंदर गए, 'राम रो रहा था।'
उन्होंने उन्हें सुरेश के साथ हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। नक़वी ने लिखा
उन्होंने स्वीकार किया, ‘यह मेरी ओर से एक निर्देशित प्रस्तुति थी।’
दुःखपूर्वक।
अन्यथा, मुख्यधारा मीडिया इस घिनौनी घटना पर चुप रहा।
मामला। हालाँकि, बाद में, इस मामले ने लुटियंस के दिल्ली को हिलाकर रख दिया—और
देश। संजय की पत्नी मेनिका द्वारा संपादित सूर्य पत्रिका ने एक लेख प्रकाशित किया।
दो पन्नों में फैली तस्वीरों में छियालीस वर्षीय सुरेश को दिखाया गया है।
राम और सुषमा चौधरी, 'यौन कलाबाजी में लिप्त'।
लेख का शीर्षक था, 'असली कहानी'। हालाँकि सबूत
इसकी ‘जांच टीम’ द्वारा उजागर की गई जानकारी अदालत में शायद ही टिक पाएगी।
कानून के क्षेत्र में, सूर्या ने ‘सुषमा अंतरराष्ट्रीय जासूसी में मोहरा’ जैसी सुर्खियां चलाईं।
‘रिंग’ और ‘रक्षा संबंधी रहस्य चीनी दूतावास को लीक हुए’।
आपातकाल के बाद पत्रिका की बिक्री में जो गिरावट आई थी, उसमें जबरदस्त उछाल आया। और
जगजीवन राम की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आई।
अंततः अदालत ने ओम पाल सिंह और त्यागी को बरी कर दिया।
असल बात तो यह थी कि तस्वीरें एक योजना का हिस्सा थीं, यह स्पष्ट था।
चरण सिंह और उसके गुर्गे (राज नारायण) द्वारा जगजीवन को फंसाने की योजना
राम के इकलौते बेटे सुरेश राम एक 'घिनौने यौन कांड' में फंस गए। मकसद यह था कि...

जगजीवन राम को नुकसान पहुँचाया। चरण सिंह और इंदिरा गांधी दोनों जानते थे कि उसने
शीर्ष पद के लिए एकमात्र अन्य गंभीर दावेदार था—और उसे आवश्यकता होगी
यदि उनकी योजना सफल हो जाती है तो उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाएगा।
जगजीवन राम के दलित होने की पृष्ठभूमि के अलावा, इंदिरा गांधी को उनके बारे में भी आशंका थी।
प्रशासनिक क्षमताएं। वह एक वर्ष से यूनियन कैबिनेट का हिस्सा रहे थे।
अंतरिम सरकार के नेतृत्व के बाद से लगातार इकत्तीस वर्षों तक
नेहरू द्वारा 1946 में नियुक्त किया गया। उन्होंने संचार जैसे कई मंत्रालयों का नेतृत्व किया था।
खाद्य, कृषि, रक्षा। शीर्ष पदों के लिए उनका नाम संक्षेप में सामने आया था।
12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा को नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर यह मामला सामने आया।
छह दिनों से उसकी स्थिति 'अस्थिर' लग रही थी। यहां तक कि सड़क पर भी
विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और जनता पार्टी के नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की।
कांग्रेस में बेचैनी बढ़ती गई। पार्टी के कई लोगों को जगजीवन से उम्मीदें थीं।
मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ मंत्री होने के नाते राम को पदभार संभालने के लिए कहा गया। आईबी ने उन्हें बताया था कि उन्हें 350 में से केवल 191 का ही समर्थन प्राप्त है।
कांग्रेस सांसदों में से एक। उन्हें नेता पद से हटाया जा सकता है। लेकिन
उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया।
वह जानती थी कि वह बाबूजी को प्रधानमंत्री बनाने का जोखिम नहीं उठा सकती, भले ही वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही क्यों न हों।
राजनीति में अंतरिम व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं थी।
दलितों को नाराज किए बिना किसी दलित को उनके पद से हटाना मुश्किल है।
कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक। इसके अलावा, रक्षा मंत्री के रूप में
1970-74 तक सशस्त्र बलों के प्रभारी रहते हुए उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की थी।
सिस्टम में प्रमुख कड़ियों पर पकड़ बनाए रखें। जबकि वह, अदालत के फैसले के

साथ
उसके विरुद्ध, अब वह कमजोर पड़ चुकी थी। लेकिन 18 जून 1975 तक, वह
उसने स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लिया, जिससे जगजीवन राम को भी मजबूर होना पड़ा।
उसका साथ दें और उसकी सहायता करें।
फिर, मार्च 1977 में, जगजीवन राम लगभग शीर्ष पर पहुँच ही गए थे जब
जनता पार्टी सत्ता में आई। तीन दावेदार थे।
throne—Morarji Desai, Charan Singh, and Jagjivan Ram. A majority of
जनता पार्टी के सांसदों ने राम के पक्ष में बात की थी। हालाँकि, अंतिम परिणाम
यह निर्णय जेपी और जे. बी. कृपलानी पर छोड़ दिया गया था, जो कांग्रेस के एक सम्मानित नेता थे।
वह नेता जो पार्टी से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा का गठन किया
पार्टी (केएमपीपी) - और आपातकाल का विरोध किया था। 'विचार यह था कि
'जनता पार्टी में फूट को रोकना,' राजमोहन गांधी ने वर्षों पहले कहा था।
बाद में, दोनों ने मोरारजी देसाई को चुना। वे सबसे वरिष्ठ थे।
प्रतिद्वंद्वी, जो खुद को गांधीवादी बताता था और पूरे समय जेल में रहा था।
आपातकाल।
दो बातें जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ गईं—वे पहले भी कई लोगों के साथ रह चुके थे।
इंदिरा गांधी ने हाल तक इस मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया था।
1975 में संसद में आपातकाल लगा था। लेकिन उन्होंने इसे उस तरह से नहीं देखा, उन्होंने बताया।
उनके समर्थकों ने कड़वे स्वर में कहा, 'एक चमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।'
इस देश में।' जेपी ने ही नाराज राम को इसमें शामिल होने के लिए राजी किया था।
सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में।
सन् 1978 में, जनता सरकार के एक साल बाद, जगजीवन राम
जैसे-जैसे मोरारजी देसाई की लोकप्रियता कम होने लगी, आशा की एक किरण दिखाई देने लगी।

और कई सांसदों ने राम को एक संभावित विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दिया। लेकिन
उनके बेटे सुरेश राम के यौन दुराचार ने उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ।
एक बार फिर महत्वाकांक्षा जागृत हो गई।
मोरारजी देसाई अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर पड़ते देखकर दुखी नहीं थे। चरण
सिंह बेहद खुश थे। इंदिरा गांधी के लिए यह एक अप्रत्याशित लाभ था। 'किसी भी keemat par Jagjivan Ram pradhan mantri nahin banane chahiye', she would tell her confidantes. 'Hatenge nahin zindagi bhar (Jagjivan Ram
उन्हें किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। वे पद नहीं छोड़ेंगे।
अपनी सारी जिंदगी)।'
जगजीवन राम के लिए, सुरेश हमेशा से ही उसकी कमजोरी रहा था।
कुछ वर्षों बाद, सुरेश की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जगजीवन Ram said brokenly to Krishan Kant, 'Maain toot gaya hoon (I am a
टूटा हुआ आदमी)।'
जबकि चरण सिंह और राज नारायण वसीयत के निष्पादक थे
'ऑपरेशन सुरेश राम', इंदिरा गांधी की सामान्य से अधिक रुचि
इस मामले ने कई लोगों को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने इसमें क्या भूमिका निभाई थी।
कपिल मोहन सुरेश राम की तस्वीरें संजय को भेजने में इतनी जल्दी क्यों करते?
आधी रात को गांधी जी? शायद यह सिर्फ एक खुशी का पल रहा हो।
यह एक संयोग था कि उसकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों में से एक उसके हाथों में आ पड़ी।
क्योंकि संयोग तब होते हैं जब देवता दयालु हो जाते हैं। और वे
वे इंदिरा के प्रति उदार होने लगे थे।

ग्यारहवीं

मुझे ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी ने इस धर्मकारम का सहारा लिया।
अनिल बाली, जो आए थे, ने कहा, '(धार्मिक अनुष्ठान) वास्तव में संजय के लिए

महत्वपूर्ण हैं।'
सत्ता से बाहर रहने के वर्षों में उनसे आसानी से संपर्क किया जा सकता था। एक ज्योतिषी
उसने उसे चेतावनी दी थी कि संजय की कुंडली में 'जीवन रेखा के अचानक समाप्त होने' का संकेत है।
इससे 1977 के बाद मंदिरों में उनकी नियमित उपस्थिति में वृद्धि हुई, जब उन्होंने
वह अत्यधिक धार्मिक हो गया था और संजय की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था।
वह हमेशा से इतनी खुलकर धार्मिक नहीं थीं। 1966 में, उन्होंने
भारत के संविधान पर प्रधानमंत्री की शपथ। 1980 में, उन्होंने यह शपथ भारत के संविधान के नाम पर ली थी।
नेहरू एक अज्ञेयवादी थे; उनकी मां कमला एक गहरी अज्ञेयवादी थीं।
वह एक धार्मिक महिला थीं। अपने जीवन के विभिन्न समयों में वह दोनों से प्रभावित हुईं।
जीवन। जब 1964 में नेहरू का निधन हुआ, तो उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया।
उन्होंने नेहरू की वसीयत में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ऐसा किया।
उन्हें धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार दिया जाए। लेकिन इंदिरा ने कुछ और ही फैसला किया। वह जानती थी
वह अपने पिता की इच्छाओं का उल्लंघन कर रही थी। लेकिन राजनेता और धार्मिक नेताओं ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत की जनता गैर-
नेहरू का धार्मिक अंतिम संस्कार हुआ। उनके भीतर की व्यावहारिकता विजयी हुई। उन्होंने यह कदम उठाया था।
आपातकाल के दौरान ज्योतिषियों से परामर्श लेने के लिए। लेकिन यह उनके दौरान हुआ था।
1977-80 के दौरान गुमनामी में बिताए वर्षों में ही उन्हें वास्तव में 'एक के रूप में देखा जाने लगा'
'पहले हिंदू और अंत में भी हिंदू'।
सत्ता खोने के बाद, वह जुनून की हद तक छोटे-बड़े मंदिरों में जाती रहीं।
अक्टूबर 1977 में, वह गुजरात के अंबाजी मंदिर गईं, जिसे इक्यावन शक्ति पीठों में

से एक माना जाता है; उन्होंने वहां प्रणाम किया।
वह वैष्णो देवी गई थीं, उन्होंने 1977 में कुंभ मेले में भाग लिया था।
उन्होंने कांची के सबसे वरिष्ठ शंकराचार्य, परमाचार्य से मुलाकात की।
नवंबर 1977 में, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच, खासकर इसलिए क्योंकि वह
तमिलनाडु में हर जगह 'इंदिरा वापस जाओ' के नारे गूंज रहे थे।
जब वह परमचार्य के आश्रम में पहुंची, तो वह अपने कमरे से बाहर आए।
इंदिरा कुएं के दूसरी तरफ खड़ी थी, जो उन दोनों के बीच में था।
आध्यात्मिक गुरु ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वहीं खड़े रहे।
वह वहीं था। फिर उसने नीचे देखा।
इंदिरा गांधी ने कहा, 'मेरा परिवार संकट में है। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है।'
परमाचार्य कुछ और मिनटों तक वहीं खड़े रहे। फिर,
बिना कुछ कहे, वह मुड़ा और वापस अपने कमरे में चला गया।
कमरा। इंदिरा बहुत परेशान थी। लेकिन वह नहीं गई। उसने पूछा
उसके साथ एक और मुलाकात। वह फिर बाहर आया। इस बार उसने कहा,
देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
जरूरत थी।' इस बार उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। बाद में, उसकी
उनके सहयोगियों ने उनकी कथित नाराजगी को समझाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने कहा, उससे बात करो, क्योंकि वह मौन धारण किए हुए था।
प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कई बार उनसे मुलाकात की थी और उनकी मदद मांगी थी।
संजय की शादी सितंबर 1974 में हुई थी और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ मिली थीं।
कांचीपुरम का मानना था कि इंदिरा ने हाथ को ही चुना था।
कांग्रेस का चिन्ह इसलिए क्योंकि परमाचार्य ने अपना दाहिना हाथ उठाया था।
आशीर्वाद में।
कुछ अन्य लोगों को लगा कि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रतीक को गाय और बछड़े से बदलकर

बाबा देवराहा के कारण हाथ में चोट आई। वे एक सिद्ध योगी थे जो वहीं रहते थे।
सरयू नदी के किनारे स्थित 12 फुट ऊँचा लकड़ी का चबूतरा
पूर्वी उत्तर प्रदेश में; वह नदी में डुबकी लगाने के लिए ही अपनी जगह से नीचे उतरता था।
जब वह 1978 में उनसे मिलने गई, तो बाबा नीचे आ गए।
विशेष रूप से उससे मिलने के लिए। उसने उसे आशीर्वाद देने के लिए अपने दोनों हाथ उठाए।
Anandamayi Ma gave her a rare ekmukhi rudraksh, a necklace of
वह अक्सर 108 भूरे रंग के मोतियों को एक ताबीज की तरह पहनती थी, जो उसकी रक्षा करता था।
गंभीर परिस्थितियों में वह उसकी मदद करती थी। एक और आध्यात्मिक व्यक्ति जिससे उसने संपर्क किया।
यह कृष्णमूर्ति और रजनीश के बीच का समय था। रजनीश का उदय उनके समय में हुआ था।
दिल्ली में छतरपुर मंदिर का निर्माण उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। धीरेंद्र
ब्रह्मचारी को उनके दरबार में संरक्षण प्राप्त हुआ और उन्होंने उन्हें योग सिखाया।
गांधी परिवार में उनकी निरंतर उपस्थिति से उनके परिवार और दोस्तों को उन पर उनके प्रभाव को लेकर चिंता होने लगी। उन्होंने श्री अरबिंदो चर्च को संरक्षण दिया।
आश्रम। उसने जिन धार्मिक संस्थानों से संपर्क किया, उनकी सूची लंबी थी।
घर में उनका एक छोटा सा पूजा कक्ष था। हर दिन, 'वहाँ एक
108 फूलों का अर्पण। जब उन्होंने जनवरी 1980 के चुनावों में जीत हासिल की,
और 1, सफदरजंग रोड स्थित अपने पुराने घर लौटकर, उन्होंने संचालन किया।
उस स्थान को शुद्ध करने के लिए विस्तृत प्रार्थनाएँ की गईं। वह हर तरह के निशान मिटाना चाहती थी।
पिछले निवासी, मोरारजी देसाई। उसी वर्ष (1980) में, 16 तारीख को
फरवरी में सूर्य ग्रहण था। इंदिरा ने गर्भवती मेनिका से पूछा कि...
वह अपने कमरे में चली गई। ग्रहण को अशुभ माना जाता था।
अजन्मे बच्चे को देखकर उसकी सहेली पुपुल जयकर परेशान हो गई।

वे और भी अधिक अंधविश्वासी होते चले गए। कई वर्षों बाद, जून 1984 के बाद
ऑपरेशन ब्लूस्टार के दौरान, उसने सेना को गोल्डन रिट्रीवर में भेजा था।
खालिस्तान की मांग करने वाले पंजाब के आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए मंदिर,
'श्रीमती'
Gandhi conducted a mahamrityunjay paath at her home for a month,'
सत्यपाल मलिक ने कहा, 'अरुण नेहरू ने मुझे व्यक्तिगत रूप से यह बताया था।' वह
उसे आशंका थी कि उसकी हत्या कर दी जाएगी।
करण सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा, 'श्रीमती गांधी बहुत धार्मिक थीं। वह पहनती थीं
धार्मिक रीति-रिवाजों के कारण अलग-अलग दिनों में अलग-अलग रंगों की साड़ियाँ
कारण)। जो बात व्यक्तिगत आस्था के विषय के रूप में शुरू हुई थी, वह भी...
1980 में सत्ता में वापसी के लिए यह एक राजनीतिक रणनीति बन गई।
■

इंदिरा गांधी के मंदिरों में बार-बार जाने का असर आरएसएस से छिपा नहीं था।
नेतृत्व। आरएसएस प्रमुख बालासाहेब देवरस ने एक बार टिप्पणी की थी।
course of a conversation, 'Indira Gandhi bahut badi Hindu hai (Indira
गांधी एक कट्टर हिंदू हैं।
बालासाहेब देवरस और उनके भाई ने इंदिरा गांधी में एक संभावित प्रतिभा देखी।
हिंदुओं के नेता,' अनिल बाली ने कहा, जो आरएसएस प्रमुख से मिलेंगे और
उनके भाई मुरलीधर देवरास (जो भाऊराव के नाम से लोकप्रिय थे) की ओर से
कपिल मोहन का।
1971 में, आरएसएस ने बांग्लादेश को अलग करने के लिए उनकी प्रशंसा की, और
weakening Pakistan. The then RSS chief Madhav Sadashiv Golwalkar,
गुरुजी के नाम से लोकप्रिय, ने उन्हें लिखा, 'सबसे बड़ा उपाय
इस उपलब्धि का श्रेय आपको जाता है।' 1974 में, उन्होंने आरएसएस का पुरस्कार

जीता।
परमाणु उपकरण विस्फोट के लिए एक बार फिर प्रशंसा व्यक्त की गई - आरएसएस ने
उन्होंने हमेशा सैन्य रूप से मजबूत भारत की वकालत की है।
इंदिरा गांधी का दक्षिणपंथी झुकाव बालासाहेब के उत्थान के साथ मेल खाता था
जून 1973 में आरएसएस की सरसंघचालक बनीं। तब तक वह वहां से जा रही थीं।
उनकी वामपंथी नीतियों के कारण। पी. एन. हक्सर बाहर हो गए। संजय अंदर आ गए।
राजनीति में निपुण बालासाहेब दोनों को मुख्यधारा में लाना चाहते थे।
वह खुलेआम यह दावा करता था कि वह आरएसएस और जनसंघ का समर्थक है।
अज्ञेयवादी; वह अक्सर खुद को 'एक कम्युनिस्ट' के रूप में संदर्भित करता था।
आरएसएस के बाद, मोहन भगवत ने भी इसी तरह का प्रदर्शन किया। उनके बाद, मोहन भगवत ने भी ऐसा ही प्रदर्शन किया।
राजनीतिक सूझबूझ। जबकि आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की
उनका मुख्य ध्यान हिंदुओं को एकजुट करने पर था, और उनके उत्तराधिकारी गोलवलकर ने भी यही लक्ष्य रखा।
बालासाहेब ने संगठन को आध्यात्मिक दिशा देने का प्रयास किया।
जनसंघ और एबीवीपी दोनों को छात्रों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
गुजरात में नव निर्माण आंदोलन और जेपी के नेतृत्व में बिहार आंदोलन
1974 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ। बढ़ते खतरे को भांपते हुए
तेल की कीमतों में अचानक उछाल और देश में व्याप्त असंतोष के कारण
पश्चिमी अमेरिका में 1973 के योम किप्पुर युद्ध के बाद उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयाँ
एशिया में, बालासाहेब ने एल. के. आडवाणी को सलाह दी थी, जो उस समय जन आंदोलन में एक उभरते हुए नेता थे।
संघ ने इंदिरा गांधी पर अपने हमलों को और तेज कर दिया। लेकिन जब
25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया, बालासाहेब प्रभावित हुए।
प्रारंभ में, जिस 'अनुशासन' को यह विकसित करना चाहता था, उसके साथ सफाई (सफाई) जिसे इसने सड़कों पर लाने की कोशिश की, और इंदिरा गांधी का आदेश

गांधी ने कहा कि वह इसे देश में लागू करना चाहती हैं।

■

आपातकाल के पांच दिन बाद इंदिरा गांधी ने बाला साहब देवरस को जेल में डाल दिया

उन्होंने 4 जुलाई को आरएसएस और पच्चीस अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया।

1975 में, आरएसएस नेतृत्व ने भूमिगत गतिविधियों को समर्थन देने का निर्णय लिया।

जेपी द्वारा स्थापित लोक संघर्ष समिति (एलएसएस) की गतिविधियों में सहायता प्रदान की गई - और इसमें मदद की गई

भूमिगत प्रेस की स्थापना करें और प्रतिरोध के लिए विदेशी समर्थन जुटाएं।

आपातकाल। लेकिन जल्द ही आरएसएस नेताओं ने फैसला किया कि, भले ही इसके यदि नेता जेल में ही रहे, तो वह 'समझौता' करने का प्रयास करेगा।

इंदिरा।

बालासाहेब देवरस ने इंदिरा गांधी को अपना पहला पत्र लिखा था।

22 अगस्त 1975 को यरवदा जेल में। उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रशंसा करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की।

'आपका संबोधन (15 अगस्त 1975 को लाल किले से दिया गया) समयोचित था और

संतुलित।' इंदिरा ने पत्र को नजरअंदाज कर दिया। बालासाहेब ने 10 तारीख को उन्हें फिर से पत्र लिखा।

नवंबर 1975। इस बार, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद से उनकी अयोग्यता को रद्द करने पर उन्हें बधाई दी, जो कि पहले जारी की गई थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को यह निर्णय दिया।

उन्होंने आरएसएस को जेपी के आंदोलन से अलग करने की भी कोशिश की, जो कि उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग की। 'संघ का इनसे कोई संबंध नहीं है।'

(बिहार और गुजरात) आंदोलन...'

एक बार फिर, इंदिरा ने कोई जवाब नहीं दिया। बालासाहेब ने अब अपील की...

विनोबा भावे, जिनके कान थे। बालासाहब को पता चल गया था कि इंदिरा थीं
24 जनवरी 1976 को भावे के पौनार आश्रम जा रहे थे। उन्होंने भावे को पत्र लिखा।
12 जनवरी: 'मैं आपसे विनती करता हूं कि आप गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास करें।'
प्रधानमंत्री ने आरएसएस के बारे में बात की ताकि आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटाया जा सके और आरएसएस
सदस्यों को जेलों से रिहा कर दिया जाता है...और...वे योगदान देने में सक्षम होते हैं।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति हो रही है।
इसी समय के आसपास, जेल में बंद कई आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बिना शर्त अपना समर्थन दिया।
जेल से बाहर निकलने के लिए दिए गए वचन, मानक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना
सरकार ने यह तैयारी कर रखी थी कि वे कुछ नहीं करेंगे।
'आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के लिए हानिकारक'। हालाँकि भावे ने ऐसा किया।
तुरंत प्रतिक्रिया न देने पर, उन्हें नरमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी।
आरएसएस के प्रति इंदिरा गांधी का रुख। भावे के अलावा, 'यह बाल भी थे।
ठाकरे ने आरएसएस को आपातकाल का समर्थन करने के लिए राजी किया था।
कमल नाथ का खुलासा हुआ। संजय गांधी ने नाथ का इस्तेमाल किया, जो उस समय उनके सबसे बड़े हथियार थे।
लेफ्टिनेंट ने बाल ठाकरे के साथ 'गुप्त बातचीत' शुरू करने का निर्देश दिया। संस्थापक शिवसेना के सदस्य और महाराष्ट्र के ताकतवर नेता के रूप में जाने जाते हैं।
ठाकरे कांग्रेस के प्रबल आलोचक थे।
1975 में आपातकाल के दौरान, संजय ने उनसे फोन पर बात की और नाथ को भेज दिया।
नाथ को उनसे मिलने के लिए मुंबई जाना था। उन्हें लगा था कि उनकी मुलाकात एक सख्त और
एक अडिग व्यक्तित्व। 'लेकिन मैंने उन्हें सौहार्दपूर्ण, स्नेही और सौम्य पाया,' उन्होंने कहा।
कहा।

ठाकरे ने आपातकाल का समर्थन करने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा, 'यह देश के लिए अच्छा है।'
देश,' उन्होंने नाथ से कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, 'एक बार कानून और व्यवस्था बहाल हो जाए तो।'
हालात सुधरने पर आपातकाल हटाया जा सकता है।' उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया।
आपातकाल का समर्थन करने के लिए आरएसएस के शीर्ष नेताओं को मनाने में कमल की भूमिका रही।
नाथ ने मुझे बताया। चौवालीस साल बाद, 2019 में, जब सोनिया गांधी थीं
शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करना है या नहीं, इस निर्णय का सामना करना पड़ रहा है।
उन्हें महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार की याद दिलाई गई।
बाल ठाकरे ने 1975 में इंदिरा गांधी को जो समर्थन दिया था।
इसके बाद के वर्षों में, आरएसएस ने यह दावा किया कि उसने विरोध किया था
आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को मिले समर्थन को कम करके आंका गया। यह विवाद समय-समय पर फिर से सामने आता रहता है।
■

बाला साहब देवरस ने इस दौरान संजय और इंदिरा से मिलने की काफी कोशिश की
आपातकाल के वर्षों में। 'लेकिन श्रीमती गांधी ने इनकार कर दिया,' टी.वी. राजेश्वर ने खुलासा किया।
खुफिया ब्यूरो के उप निदेशक के रूप में उन्हें प्रत्यक्षदर्शी का अवसर प्राप्त था।
उस काल की घटनाओं का।
संजय का अपनी माँ पर जो प्रभाव था, उसे जानते हुए, आरएसएस ने
उनके साम्यवाद-विरोधी और अमेरिका-समर्थक रुख के कारण भी लोग उनकी ओर आकर्षित हुए।
विचार। आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य ने उनकी प्रशंसा की। पुणे के एक मराठी अखबार ने भी उनकी प्रशंसा की।
आरएसएस से जुड़े दैनिक समाचार पत्र तरुण भारत ने भी एक लेख प्रकाशित किया

था।
‘संजय गांधी स्पेशल नंबर’।
बालासाहेब अंततः 'चुपचाप संबंध स्थापित करने' में कामयाब रहे।
राजेश्वर के अनुसार, 'प्रधानमंत्री आवास' में कपिल मोहन मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे।
संजय और आरएसएस। बाद में, संजय की मृत्यु के बाद, मोहन को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई।
राजीव गांधी और भाऊराव देवरास के बीच हुई बैठकें, के कहने पर
इंदिरा गांधी। (अधिक जानकारी के लिए अध्याय 2 देखें।) जब मधुमेह रोगी,
और इंसुलिन पर निर्भर बालासाहेब की सेहत बिगड़ गई,
भाऊराव उनके खास सलाहकार बने। वे अक्सर उनसे मिलने आते थे।
कपिल मोहन के घर, 46, पूसा रोड पर।
इंदिरा गांधी ने बालासाहेब के प्रस्तावों का जवाब देने का फैसला किया।
1977 के चुनावों से पहले। उसने उसे एक संदेश भेजा जिसमें अनुरोध था।
‘Chunav se Sangh alag ho jaye (The RSS should stay away from the
भाजपा नेता के. एन. गोविंदाचार्य के अनुसार, जो एक चुनाव थे, यह बात भी सामने आई है।
वह भाऊराव की शिष्या थीं और उनके साथ मिलकर काम करती थीं। उन्होंने आग्रह किया
बालासाहेब विपक्षी दलों का समर्थन नहीं करेंगे और जन आंदोलन को रोकेंगे।
संघ को जनता पार्टी के साथ जुड़ने से रोकना।
बालासाहेब ने संदेश भेजा कि अब उनके लिए पीछे हटना बहुत देर हो चुकी है।
चुनाव चल रहे थे। स्थिति में बदलाव करना संभव नहीं था।
हम उन्हें (जनता पार्टी को) बीच में नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम बाद में बात करेंगे।
उन्होंने कहा, 'चुनाव,' और भविष्य में बातचीत की संभावना को खुला रखा।
चूंकि बालासाहेब ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उन्हें जेल में रखा गया था।
21 मार्च 1977 तक, उन अन्य लोगों के विपरीत जिन्हें बाद में रिहा किया गया था।

18 जनवरी 1977 को चुनावों की घोषणा।
इंदिरा गांधी आरएसएस नेता एकनाथ रानाडे के संपर्क में थीं,
गोविंदाचार्य ने कहा, 'जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। संचार की कड़ी एकनाथ रानाडे से मोरोपंत पिंगले तक थी।'
बालासाहेब देवरास।' रानाडे से उनकी मुलाकात अपनी एक यात्रा के दौरान हुई थी।
जब उन्होंने दक्षिण में विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा किया
कन्याकुमारी जिसे उन्होंने स्थापित किया था। वह इससे बहुत प्रभावित हुईं।
उसने देखा। उसके बाद वह राणादे के संपर्क में रही, जो एक प्रचारक थे।
संघ से वह 1938 से जुड़ी हुई थीं। वह लगातार स्वतंत्र अवसरों की तलाश में थीं।
आरएसएस के बारे में, उसकी सोच और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए चैनल—
इसके द्वारा प्रस्तावित कदम। यहां तक कि जब गोलवलकर सरसंघचालक थे तब भी।
आरएसएस के रमाकांत पाटिल के साथ वह संपर्क में रहती थीं।
सर्वोदय, जिनके आरएसएस से घनिष्ठ संबंध थे, के अनुसार
Govindacharya.
रानाडे ने एबीवीपी द्वारा चलाए जा रहे राजनीतिक आंदोलनों का विरोध किया।
आपातकाल के दौरान। इसलिए, जब कांग्रेस नेता पी.सी. सेठी और वी.सी.
शुक्ला ने राणाडे को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उन पर विवेकानंद केंद्र में आरोप लगाया।
इस अभियान को आरएसएस द्वारा वित्त पोषित किया गया था, इंदिरा गांधी ने उन्हें पीछे हटने के लिए राजी कर लिया।
इसके बजाय, उन्होंने राणादे को भारतीय सांस्कृतिक परिषद का सदस्य बना दिया।
इससे आरएसएस के कुछ लोगों में संदेह पैदा हुआ; उन्हें डर था
वह आरएसएस को भी उसी तरह विभाजित कर सकती है जैसे उसने कांग्रेस को विभाजित किया था।
जिस तरह आरएसएस के शीर्ष नेताओं ने उनसे मदद मांगी थी, उसी तरह उन्होंने भी मदद का सहारा लिया।
अपने उद्देश्यों के लिए आरएसएस का उपयोग किया—लेकिन सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखी।

संगठन और खुद। आरएसएस के प्रति अपने तमाम विरोध के बावजूद, उन्होंने
आपातकाल में इसका समर्थन करने में कामयाब रहे। असंतोष को भांपते हुए
कांग्रेस के बारे में मुसलमानों के बीच जो धारणा थी, उसके अनुसार वह खुद को हिंदू धर्म में परिवर्तित करना चाहती थी।
राजनीति, इस बात से अवगत है कि आरएसएस की ओर से एक मौन संकेत या यहां तक कि एक तटस्थ रुख भी नुकसान पहुंचा सकता है।
उनके द्वारा उसकी ओर किया गया प्रयास शायद मददगार साबित हो सकता है।
■

‘आरएसएस ने 1980 में इंदिरा गांधी को सत्ता में आने में मदद की थी,’ यह बात कही गई।
अनिल बाली। बाली ने दावा किया, 'वह जानती थी कि आरएसएस ने उसका समर्थन किया था, लेकिन उसने...'
उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया। वह निजी तौर पर मानती थीं कि उन्हें यह बीमारी है।
आरएसएस के समर्थन के बिना वह 353 सीटें नहीं जीत सकती थीं।
1971 में अपने चरम पर रहते हुए उसने जितने पुरस्कार जीते थे, उससे एक अधिक।
करण सिंह ने यह भी संकेत दिया कि 'शायद वह संपर्क में थी'
आरएसएस... उसके अपने हिसाब-किताब थे।’ उन्होंने उसके बचाव में आगे कहा,
‘(हालाँकि), वह न तो हिंदू-विरोधी थीं और न ही मुस्लिम-विरोधी।’ टी.वी.
राजेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरएसएस ने 1980 के चुनावों में उनका समर्थन किया था। राजेश्वर ने कहा, ‘आरएसएस ने विशेष रूप से उनका समर्थन किया था।’
उसने आपातकाल के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को अपना समर्थन दिया।
हालांकि वे इस विचार से सहमत नहीं थे, गोविंदाचार्य ने स्वीकार किया
कई कांग्रेसी नेताओं का मानना था कि यह सच है। लेकिन असलियत क्या थी?
उन्होंने कहा कि यह सच है कि कांग्रेस ने आरएसएस की मदद मांगी थी।
कई चुनाव। '1989 के चुनावों से पहले भी... आर. के. धवन ने
उन्होंने संदेश भेजा है, जिसमें कांग्रेस को समर्थन देने के लिए हमारी (आरएसएस की)

मदद मांगी गई है।
गोविंदचार्य ने याद करते हुए कहा, ‘मैं उनसे मिलने गया था। मुझे याद है उन्होंने मुझे खाना खिलाया था।’
‘समोसे और काजू।’ ‘आखिरकार,’ धवन ने उनसे कहा, ‘आपने हमारा साथ दिया था।’
पिछले चुनावों में भी (1980 और 1984 के संदर्भ में)। 1984 से पहले
चुनावों के दौरान, आरएसएस नेता नानाजी देशमुख ने लोगों से मतदान करने का आग्रह किया था।
for the Congress: ‘Naa jaat par naa paat par, mohar lagegi haath par
(जाति या धर्म का मत करो, केवल हाथ का चिन्ह अंकित करो [के])
कांग्रेस पार्टी)।
1980 में, आरएसएस इंदिरा गांधी के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रख सकता था।
एक और कारण—जनता पार्टी का जगजीवन राम को उम्मीदवार बनाने का निर्णय—
दलितों को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखना जनता को रास नहीं आया।
आरएसएस के उच्च जाति के समर्थकों से भी नाराज था। इसके नेतृत्व को भी इससे असंतोष था।
अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से इस संगठन की आलोचना की थी
अगस्त 1979 में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हस्ताक्षरित लेख। 'ऐसा क्यों होता है (आरएसएस)?'
उन्होंने पूछा था, 'क्या यह गैर-हिंदुओं के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेगा?' उन्होंने पूछा था...
संघ नेतृत्व को यह स्पष्ट करना होगा कि 'हिंदू राष्ट्र से उनका तात्पर्य यह था कि'
भारतीय राष्ट्र जिसमें गैर-हिंदू भी समान सदस्य हैं।
1980 में वाजपेयी अपनी छवि को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इंदिरा गांधी
गांधी कांग्रेस के चेहरे को हिंदू रंग देने की कोशिश कर रहे थे।

बारहवीं

23 दिसंबर 1978 दिल्ली में एक सर्द सर्दी का दिन था। यह चौधरी का दिन था।
चरण सिंह का 77वां जन्मदिन। लगभग 8 लाख किसान थे।

दिल्ली के बोट क्लब में जश्न मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए। इतने बड़े आयोजन के लिए यह एक अभूतपूर्व अवसर था।
दिल्ली ने लंबे समय से ऐसा नजारा नहीं देखा था—वहाँ एक समुद्र सा था
जहां तक नज़र जाती थी, मानवता ही मानवता थी। सिंह एक शक्ति का निर्माण कर रहे थे।
उस दिन दिए गए बयान से यह संकेत मिला कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उनके पास था
मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद से ही वह इस दिन की तैयारी कर रहे थे।
छह महीने पहले। उनके हमवतन और बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी
ठाकुर ने मंच से गरजते हुए कहा: 'किसान अब और कुछ नहीं मांगेगा, वह
'अब लेंगे।' जब सिंह ने बात की, तो उन्होंने एक नए के जन्म की घोषणा की।
सत्ता संरचना। किसान जाग उठे थे और मध्यम वर्ग के किसान भी। वे लंबे समय से दबे हुए थे। उसने जो कुछ भी कहा।
यह हमला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के खिलाफ निर्देशित था।
लेकिन रैली में मौजूद किसानों ने इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं की कि क्या
चरण सिंह ने उस दिन कहा था। वे इंदिरा गांधी के बारे में उत्साहित थे।
सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं—और चौधरी के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है
साहब की राजनीति। किसानों को नए गठबंधनों की आहट सुनाई दी। इंदिरा
उस दिन वह जेल में था, क्योंकि उसे अवमानना का दोषी पाया गया था।
संसद। वह एक कुशल रणनीतिकार थीं, उन्होंने जेल से ही यह कर दिखाया था।
सिंह के जन्मदिन पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेजने का आदेश दिया गया।
उस दिन वह इशारा जीवंत बातचीत का विषय बन गया।
जब 26 दिसंबर को संसद का सत्र स्थगित हुआ, तो उन्हें रिहा कर दिया गया।
तिहाड़ जेल से। जब वह जेल से बाहर निकलीं, तो उनका स्वागत किया गया।
ढोल बजाना और मिठाई बांटना। इंदिरा गांधी अमर
'रहे' के नारे हवा में गूंज रहे थे। उसने बाहर जमा भीड़ की ओर देखा।
उसने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, 'मुझे अच्छा आराम मिला।' देश का माहौल बदलाव आ रहा था; उसे जेल के अंदर ही इसका एहसास हो गया था। गार्ड और

अंदर मौजूद अधिकारियों ने सम्मानपूर्वक उन्हें सलाम किया था।
27 दिसंबर 1978 चौधरी साहब के लिए एक और बड़ा दिन था।
उस दिन वह दादा बन गए थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने फैसला किया कि...
इंदिरा गांधी को चाय पर घर आमंत्रित करें। बच्चा, जयंत, का जन्म हुआ था।
अमेरिका में अपने माता-पिता, अजीत सिंह और उनकी पत्नी के साथ थे।
Gandhi chai pee laengi, toh Morarji theek ho jayenge (If Mrs Gandhi
(अगर मोरारजी देसाई मेरे साथ एक कप चाय पी लें, तो सब ठीक हो जाएगा),' चरण सिंह ने सत्यपाल मलिक से कहा। जब इंदिरा चाय पीने आईं,
चरण सिंह द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। 'गुप्प शुप्प हुई (वे)
मलिक ने कहा, 'दोनों पक्षों ने हल्की-फुल्की बातचीत की।' 'दोनों पक्ष एक-दूसरे से खुश थे।'
दिन)। जबकि धूर्त सिंह मोरारजी देसाई को संदेश भेज रहे थे।
कि जरूरत पड़ने पर वह इंदिरा गांधी के साथ हाथ मिला सकते थे, वह
देसाई के लिए उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता का संकेत देते हुए—कि वह भी मछली पकड़ने में सक्षम हो सकती हैं
इससे अशांति फैल सकती है और जनता सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
चाय पार्टी का इच्छित प्रभाव पड़ा। मोरारजी देसाई ने आगे की पढ़ाई की।
नुकसान को नियंत्रित करने के लिए—उन्होंने चरण सिंह को वापस लाने का फैसला किया।
मंत्रिमंडल में। 24 जनवरी 1979 को, उन्होंने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया, और
उन्हें वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया—इससे उन्हें रियायतों की घोषणा करने में मदद मिली
उस वर्ष के संघ बजट में किसानों को शामिल किया गया था। लेकिन, संतुलन बनाने के लिए, और
पार्टी में जनसंघ के नेताओं के दबाव में आकर देसाई ने भी
उन्होंने जगजीवन राम को द्वितीय उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। लेकिन उन्होंने राज नारायण को वापस लेने से इनकार कर दिया। नारायण का देसाई को

सत्ता से हटाने का दृढ़ संकल्प था।
कई गुना बढ़ गया। अब वह मधु के साथ मिलकर काम कर रहा था।
लिमाये को पूरा विश्वास था कि जनसंघ समूह एक 'सांप्रदायिक' समूह है।
जनता सरकार के भीतर मौजूद लोगों को हर कीमत पर हाशिए पर धकेलना था।
उन्होंने पूर्व जन परिषद की 'दोहरी सदस्यता' का मुद्दा उठाया।
संघ के सदस्य (जिनमें वे जनता के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे)
पार्टी के साथ-साथ आरएसएस से भी संपर्क साधा)—और समाजवादियों से भी संपर्क किया।
पार्टी और चरण सिंह की बीएलडी के सदस्यों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई।
उन्हें डर था कि केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनेगी।
तीन बार प्रतिबंधित आरएसएस को मुख्यधारा की ताकत बनने में मदद करना—
इसे उन्हीं ताकतों ने स्वीकार कर लिया जिन्होंने पहले इसे अस्वीकार कर दिया था।
यहाँ तक कि इससे पहले भी
आपातकाल के दौरान, आरएसएस ने जेपी के साथ संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया था, जिन्हें
बाला साहेब की तुलना गांधी और भावे और सावरकर से की गई. जेपी ने कहा था
मार्च 1975 में: 'अगर आरएसएस फासीवादी है, तो मैं भी फासीवादी हूँ'—संगठन को यह बात बताते हुए
वैधता, एक ऐसा बयान जिसने विवाद को जन्म देना जारी रखा।
कई वर्षों बाद। जन की 'दोहरी सदस्यता' का विवादास्पद मुद्दा।
संघ सदस्यों का उद्देश्य जनता संघ का विनाश करना था।
सरकार, जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर आएं, कहानी
इसमें कई नाटकीय मोड़ आए।
उप प्रधानमंत्री के रूप में चरण सिंह अपनी नई भूमिका में ढल रहे थे।
उत्तर प्रदेश में अशांति फैलने पर यूपी के मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनके चहेतों में से एक, राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया।
फरवरी 1979 में। कुछ महीनों बाद, चरण के दो अन्य शिष्यों का निधन हो गया।
सिंह, कर्पूरी ठाकुर और देवीलाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया-ठाकुर

20 अप्रैल 1979 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और देवी लाल 28 जून 1979 को मुख्यमंत्री के रूप में।
हरियाणा। जनसंघ-कांग्रेस (ओ) समर्थित भजन लाल ने स्थान लिया।
देवी लाल। जनता पार्टी के भीतर एक नया स्वरूप उभरने लगा था।
संकटग्रस्त मोरारजी देसाई और पूर्व के बीच का मिलन
जनसंघ अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहता है।
संजय गांधी के संपर्क में रहने वाले राज नारायण लगातार इस बात को हवा में लटकाए रखते थे।
चरण सिंह के समक्ष प्रधानमंत्री पद की संभावना।
उन्होंने जनसंघ से मांग करने के लिए समाजवादियों के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया।
सदस्यों ने आरएसएस से अपने संबंध तोड़ लिए। सिंह को उम्मीद थी कि वे इसे बनाए रखेंगे।
हिंदू समर्थक जनसंघ पर उनके हमले में मुसलमान भी उनके साथ हैं और
आरएसएस।
समस्याएँ पैदा करने वाले कारणों में केवल शीर्ष नेताओं का अहंकार ही नहीं था।
जनता सरकार। इसमें वे परस्पर विरोधी हित समूह भी शामिल थे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे, जो अलग-अलग दिशाओं में खींच रहे थे। जनसंघ के पास था।
एक मजबूत संगठन होने का लाभ, जो किसी अन्य संगठन के पास नहीं है।
जनता पार्टी के गुटों ने ऐसा किया। जनसंघ और मोरारजी देसाई के गुटों ने भी ऐसा किया।
कांग्रेस (ओ) को उच्च जातियों और मध्य वर्गों का समर्थन प्राप्त था।
कक्षाएं। चरण सिंह, जिनके अमृतसर से लेकर बड़े जनसमर्थक थे।
पटना, जाटों और ओबीसी का प्रतिनिधित्व करता था; शक्तिशाली मुख्यमंत्री जो थे
उनके साथ कर्पूरी ठाकुर और राम नरेश यादव दोनों ओबीसी थे।
और देवीलाल जाट थे. जयपाल रेड्डी जैसे अनुभवी जनता राजनेता
कहा जाता था, 'उत्तर भारत ने दो शक्तिशाली जन नेताओं को देखा है।'
नेहरू युग के बाद— इंदिरा गांधी और चरण सिंह।
जनता गठबंधन के भीतर विभिन्न समूह सत्ता हथियाने की होड़ में लगे हुए थे।

सत्ता में आने के बाद, जेपी ने आरएसएस को अधिक समावेशी बनने और उसे आगे बढ़ाने के लिए मनाने की कोशिश की।
जनता पार्टी में संकट को टालने के लिए गैर-हिंदुओं के लिए भी अपने दरवाजे खोलें। सरकार।
अब तक, शीर्ष पर बैठे व्यक्ति, आमतौर पर अडिग रहने वाले मोरारजी देसाई,
अपनी सरकार को रोकने के लिए वह बेताब प्रयास कर रहा था
बिखर रहा था। स्थिति को नियंत्रण में रखने के प्रयास में, उसने
जनता संसदीय बोर्ड की 9 तारीख को आपातकालीन बैठक बुलाई गई।
मई 1979 में, उन्होंने चरण सिंह को शांत करने के लिए एक योजना बनाई थी।
इंदिरा गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें। प्रधानमंत्री के लिए राहत की बात यह थी कि सिंह
उन्होंने बैठक में अपने सहयोगियों से कहा, 'मैं चाहता हूं कि यह सरकार और...'
पार्टी जारी रहेगी।' वहां मौजूद कई लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए, चरण सिंह ने लगभग
उन्होंने अपने हनुमान, राज नारायण को त्याग दिया। उन्होंने नारायण पर धक्का देने का आरोप लगाया।
पार्टी में फूट पड़ने की आशंका। और विनम्रता के अपने दुर्लभ क्षणों में से एक में,
सिंह ने देसाई की ओर मुड़कर कहा, 'शायद अगर आप उसे सलाह दें, तो वह मान जाएगा।'
अपने बयानों में नरमी लाएं।' कुछ अन्य लोगों ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री को
नारायण को मंत्रिमंडल में वापस ले आओ। 'वह केवल एक के लिए समस्याएँ पैदा करेगा।'
यदि उन्हें सरकार में पुनः शामिल किया जाता है तो वे मंत्रालय में बने रहेंगे... अन्यथा वे जारी रहेंगे
पूरी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं।
चरण सिंह के बार-बार बदलते रुख से इंदिरा गांधी चिंतित हो गईं, जब उन्हें इसकी खबर मिली।
खुफिया एजेंसी में मौजूद अपने भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था।

संजय गांधी की योजना के अनुसार, संजय ने तुरंत कमल को भेजा।
नाथ ने सिंह से कहा, ‘यह हमला करने का समय नहीं है।’ सिंह ने नाथ से कहा।
उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा, 'विशेष न्यायालयों का शीघ्र ही गठन होने वाला है।'
संतोष व्यक्त करते हुए, 'इंदिरा गांधी पर मुकदमा चलेगा।'
लड़ाई के लिए तैयार इंदिरा गांधी ने विशेष अध्यादेश के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व किया।
16 मई 1979 को अदालतों में सुनवाई हुई, जिसका समापन एक रैली के साथ हुआ। लेकिन उन्हें मिली प्रतिक्रिया ठंडी रही। अगले दिन, राष्ट्रपति संजीव रेड्डी ने अपनी सहमति दे दी।
विशेष न्यायालय विधेयक के संबंध में। यह विधेयक 17 मई 1979 को लागू हुआ।
■

अब इंदिरा गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतों के लिए रास्ता साफ हो चुका था।
गांधी—उनकी सरकार द्वारा किए गए अपराधों और अत्याचारों के लिए
आपातकाल के दौरान, जिसके लिए शाह आयोग ने आरोप लगाया था
वह, संजय और उसके कुछ सहकर्मी। कुछ विशेष न्यायालय
इन्हें मई में ही तुरंत स्थापित किया जाना था।
चिंतित संजय ने अपनी युद्ध परिषद की बैठक बुलाई।
group comprised Kamal Nath, Akbar Dumpy Ahmad, Bansi Lal, H. K.
एल. भगत और अन्य लोगों ने विशेष न्यायालयों को चुनौती देने का फैसला किया।
कमल नाथ ने सुझाव दिया कि वे इस अधिनियम को कलकत्ता में चुनौती दें, न कि दिल्ली। संजय इंदिरा गांधी को दार्जिलिंग के लिए रवाना कर दिया। पुतला।
वह अपनी सास के साथ आई थी। संजय तीन दिन बाद उनसे मिला।
विशेष न्यायालय का समन इंदिरा को 20 जून 1979 को तामील कराया गया था।
दार्जिलिंग—दिल्ली नहीं। परिणामस्वरूप, याचिका सुनवाई के लिए स्थगित कर दी गई।

कलकत्ता में।
इसी बीच कमल नाथ वकीलों से मुलाकात कर रहे थे।
कलकत्ता, जहाँ वह कई और लोगों को जानता था, क्योंकि वह वहाँ काफी समय से रह रहा था।
कई साल।
नाथ ने न्यायपालिका में लोगों से अनौपचारिक रूप से मुलाकात करके उनकी राय जानने की कोशिश की।
अधिनियम पर विचार। न्यायाधीशों में से एक ने उनसे कहा, 'इसका उपयोग किया जाना चाहिए
विशेष परिस्थितियों के खिलाफ, न कि विशेष लोगों के खिलाफ।
कमल नाथ इस 'भाग्यशाली अवसर' से बेहद खुश थे। वे संक्षिप्त जानकारी देने के लिए वापस चले गए।
संजय ने जज के साथ हुई अपनी बातचीत और उसके उद्घाटन के बारे में बताया।
उपलब्ध कराया गया। यह जून 1979 में हुआ था।
इंदिरा गांधी तुरंत कलकत्ता के लिए रवाना हुईं और उन्होंने याचिका दायर की।
उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उन्होंने स्थगन आदेश की मांग की।
उसे समन भेजा गया था। न्यायाधीश ने उसे प्रवेश दिया।
अपील की गई और समन पर रोक लगा दी गई। इंदिरा और संजय वापस लौट गए।
अगली सुबह दिल्ली में, वे स्टे ऑर्डर लेकर सुप्रीम कोर्ट गए।
हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक आदेश को पहले ही बरकरार रखा था।
विशेष न्यायालय विधेयक की वैधता सुनिश्चित करते हुए, इंदिरा गांधी ने यह सुनिश्चित किया था कि आगे कोई और उल्लंघन न हो।
स्थगन आदेश जारी रहने तक विशेष न्यायालयों में कार्यवाही हो सकती है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था। वह समय खरीदने में कामयाब रही थी।
और एक और दौर जीतें।
■

1979 के मध्य में, किसी बाहरी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होगा कि मोरारजी देसाई वह घोड़े की पीठ पर मजबूती से बैठा हुआ था। लेकिन सतही शांति ने तूफान को छिपा रखा था।

जो अंदर ही अंदर पनप रहा था। राज नारायण ने अब दबाव बढ़ा दिया।

देसाई और उनके खुद के ढुलमुल नेता चरण सिंह पर। जनता

पार्टी ने जून 1979 में नारायण को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया, और उन्होंने

उन्होंने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब, न तो नारायण और न ही तीन शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों को पद से बेदखल किया गया—देवी लाल, कर्पूरी ठाकुर और राम नरेश यादव—क्या जनता पार्टी में उनकी कोई बची-खुची हिस्सेदारी थी?

उन्होंने मोरारजी देसाई सरकार को गिराने के लिए हाथ मिलाया। 6 तारीख को

जून 1979 में, नारायण ने लोकसभा अध्यक्ष से अपने लिए एक अलग सीट आवंटित करने का अनुरोध किया।

उन्होंने अपनी सीट गंवा दी। तीन दिन बाद, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। उन्होंने इसे जनता पार्टी नाम दिया।

(धर्मनिरपेक्ष)। दस सांसद तुरंत उनके पक्ष में चले गए। अगले दिन नौ

और भी लोग उससे जुड़ गए। उनकी संख्या बढ़ती गई और लगातार बढ़ती ही रही। इसके बाद के घंटों में।

संसद के मानसून सत्र आमतौर पर छोटे हुआ करते थे।

उथल-पुथल भरा। 1979 का सत्र भी इससे अलग नहीं था। 11 जुलाई को, जब संसद का उद्घाटन हुआ, कांग्रेस (एस) नेता वाई. बी. चव्हाण ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।

मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव। केवल कुछ ही

कुछ दिन पहले ही उन्हें विपक्ष का नेता घोषित किया गया था, और उन्होंने उनकी जगह ली थी।

कांग्रेस (इंदिरा) के सी. एम. स्टीफन। विपक्ष के नेता के रूप में, चव्हाण स्वाभाविक रूप से

सरकार विरोधी छवि स्थापित करने के लिए बेताब। इंदिरा गांधी के समर्थकों में से एक।
सबसे कट्टर समर्थक, देवराज उर्स, पाइप पीने वाले बुद्धिमान प्रमुख
कर्नाटक के मंत्री ने उनसे नाता तोड़ लिया था और उनके साथ हाथ मिला लिया था।
वाई. बी. चव्हाण समूह के साथ। इससे वह बेहद परेशान हो गई। क्योंकि यह उर्स ही थी जिसने
1978 में चिकमगलूर से उनकी जीत में नारों का अहम योगदान था।
हवा गूंज उठेगी, 'एक शेरनी, सौ लंगूर, चिकमंगलूर,
चिकमगलूर (एक शेरनी बनाम सौ बंदर - यही कहानी है)
चिकमगलूर के)।' उसी शाम जब दलित कांग्रेस नेता बी.पी.
मौर्य ने उससे मुलाकात की, तो उसने पाया कि वह लगभग रो रही थी। 'उर्स... चली गई है...'
और...अक्टूबर के अंत तक मुझे दोषी ठहराया जाएगा...'
लेकिन जल्द ही, वह सांसदों की हर गतिविधि पर नजर रखने में जुट गई।
और उन्हें न केवल लोकसभा की गणितीय गणना का पूर्ण ज्ञान था, बल्कि जनता पार्टी की संरचना की भी पूरी जानकारी थी। जनता पार्टी के 302 सांसदों में से,
93 जनसंघ के थे, 71 भारतीय लोक दल के थे (इनमें से 31
26 लोग चरण सिंह समूह से संबंधित थे, 26 राज नारायण समूह से और 14 लोग बिजु पटनायक समूह को)। फिर कांग्रेस (ओ) से 51 लोग थे।
मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाला गुट और 6 यंग तुर्क थे जिनका नेतृत्व किया गया था।
चंद्र शेखर के नेतृत्व वाले समाजवादी समूह और सीएफडी दोनों।
जगजीवन राम के पास 28-28 सदस्य थे और बाकी सदस्य किसी संगठन से संबद्ध नहीं थे।
कोई भी पक्ष।
हालांकि संसद में उनके कांग्रेस गुट का समर्थन कम हो गया था,
इंदिरा गांधी और संजय ने अब सत्ता से बेदखल करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया।
मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाएं और उनकी जगह चरण सिंह को नियुक्त करें।
लेकिन,

अचानक सिंह उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गया था। वह भड़क रहा था।
कभी गर्म तो कभी ठंडा—और राजनीति 'अस्थिर गति' की स्थिति में थी।
संजय गांधी ने एक बार फिर कमल नाथ को डगमगाते हुए वापस मैदान में उतार दिया।
चरण सिंह। 'मौका खो जाएगा (यदि आप मौका खो देंगे तो)
अभी मत हिलो),' नाथ ने सिंह को समझाया।
चरण सिंह ने टालमटोल करते हुए कहा, 'मैं आपको कल बता दूंगा।'
कमल नाथ ने समझ लिया कि चरण सिंह क्यों हिचकिचा रहा है। उसने फैसला किया अपने अंतर्ज्ञान पर अमल करने के लिए।
कमल नाथ ने कहा, 'मुझे पता चल गया कि उनका ज्योतिषी कौन था। मैं उनसे मिलने गया।'
वह दरियागंज में रहता था।
'ये अच्छे दिन नहीं हैं,' ज्योतिषी ने विलाप करते हुए कहा।
'तो फिर उन्हें अच्छा बनाओ,' नाथ ने उसे निर्देश दिया। 'मैं उन्हें मनाने में कामयाब रहा।'
उसे।'
'यह उन नाजुक दिनों के दौरान हुआ था,' पुपुल जयकर ने बाद में लिखा था।
चरण सिंह के प्रिय ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तारे
देश में सर्वोच्च पद प्राप्त करने के लिए ये परिस्थितियाँ उनके लिए अनुकूल थीं।
इसी आश्वासन के साथ उन्होंने (चरण सिंह ने) अंततः इस्तीफा दे दिया।
■

हालांकि भारतीय लोक दल के 71 सांसदों में से अधिकांश का झुकाव इस ओर था
उन घंटों में, राज नारायण के समय, सभी की निगाहें 28 सदस्यीय समाजवादी गुट पर टिकी हुई थीं।
जनता पार्टी के भीतर के सांसदों के नाम इंदिरा गांधी को दिखाए गए थे।
ये वे सांसद थे जो दल-बदल करने को तैयार थे। वह अपनी सूची के साथ एक-एक करके उनके नाम बताती गई।

तर्जनी उंगली। यह केवल एक नाम पर रुकी—जॉर्ज फर्नांडीस।
मुझे विश्वास नहीं था कि वह दल बदल लेगा। लेकिन उसने ऐसा किया। गुरुवार को संसद में हुई बहस के दौरान उसने सरकार का जोरदार बचाव किया था।
12 जुलाई 1979। लेकिन शनिवार, 14 जुलाई तक उन्होंने पूरी तरह से अपना रुख बदल लिया था।
उस शाम, फर्नांडेस समेत समाजवादियों ने अलग होने का फैसला किया।
जनता पार्टी से अलग हो गए। जनता पार्टी के नेता स्तब्ध रह गए। यहां तक कि
फर्नांडीस का परिवार इस अप्रत्याशित बदलाव को समझ नहीं पा रहा था।
फर्नांडीस की समाजवादी सहयोगी मधु लिमाये, जिन्होंने राजी किया था
उसे पाला बदलने के लिए मनाना।
15 जुलाई को, लिमाये ने एक संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।
पंडारा रोड पर स्थित बंगले आम तौर पर सांसदों को आवंटित किए जाते हैं। 'यदि निर्माण
जनता पार्टी का गठन ऐतिहासिक रूप से आवश्यक था।
'आपातकाल और इंदिरा तानाशाही को पराजित करते हुए,' लिमाये ने हमें बताया।
पत्रकारों को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने कहा, 'जनता पार्टी का पूर्ण विघटन ही सबसे बड़ी उपलब्धि है।'
आज के समय में यह एक ऐतिहासिक आवश्यकता है... ऐसा न करने पर,' उन्होंने आगे कहा, 'यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
सांप्रदायिक वायरस से लड़ना या कोई विकल्प प्रदान करना संभव नहीं होगा।
सरकार।'
लिमाये शुरू में फर्नांडेस को अपने विचारों से समझाने में असफल रहे थे।
वैचारिक तर्क। फिर उन्होंने फर्नांडीस से अपील की।
भावनात्मक स्तर पर, फर्नांडेस की सहकर्मी, जया जेटली ने वर्षों पहले खुलासा किया था।
बाद में। जाहिर तौर पर, लिमाये ने कहा: 'क्या हमारी वर्षों की दोस्ती का कोई मतलब है?'
'तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता?' फर्नांडीस ने जवाब दिया, 'मधु, अगर बात सिर्फ इतनी सी है, तो मैं

मैं कल सुबह अपना इस्तीफा सौंप दूंगा।
उनके सहयोगी रवि ने कहा, 'जॉर्ज को पता था कि वह आत्महत्या कर रहा है।'
नायर ने कई साल बाद कहा, 'जब उन्होंने उस शनिवार शाम को अपना मन बदल लिया (14
जुलाई 1979) जब समाजवादियों की बैठक हुई थी।
रविवार, 15 जुलाई 1979 को, फर्नांडीस और समाजवादी सांसदों के समूह ने
पार्टी ने जनता पार्टी छोड़ दी और अलग हुए गुट के साथ हाथ मिला लिया।
राज नारायण द्वारा गठित जनता (एस) पार्टी विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी।
चरण सिंह को 16 जुलाई को इसका नेतृत्व संभालना था। एच. एन. बहुगुणा
इंदिरा गांधी द्वारा संपर्क किए जाने के बाद जगजीवन राम का साथ भी छोड़ दिया गया था।
और उसे दल बदलने के लिए मना लिया।
उस दिन तिरानवे सांसदों ने सरकार से वॉकआउट कर दिया—वे
वह बीएलडी, सोशलिस्ट और सीएफडी (जो एच.एन. के साथ अलग हो गया) से संबंधित था।
बहुगुणा); कुछ स्वतंत्र थे। मोरारजी देसाई के पास केवल यही बचा था।
उन्हें 214 सांसदों का समर्थन प्राप्त था; उनकी सरकार को सत्ता में आने के लिए कम से कम 270 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता थी।
जीवित बचना।
अपने खिलाफ मौजूद प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए, मोरारजी देसाई गाड़ी चलाकर चले गए।
15 जुलाई 1979 को राष्ट्रपति भवन में उन्होंने अगले दिन पेश होने वाले अविश्वास प्रस्ताव का सामना न करने का फैसला किया था। उन्होंने अपना पत्र सौंप दिया।
राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एक सप्ताह से भी कम समय में,
जनता सरकार का पतन इतनी तेजी से हुआ कि यह चौंका देने वाला था।
■

मोरारजी देसाई के जाने के बाद स्थिति और भी विचित्र हो गई।
लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। कुछ घंटों पहले
देसाई के इस्तीफे के बाद, जगजीवन राम ने अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की।
और उन्हें वाजपेयी के नेतृत्व वाले जनसंघ समूह के समर्थन का आश्वासन दिया गया था;
वाजपेयी को उप प्रधानमंत्री पद का वादा किया था।
यदि देसाई ने इस्तीफा दे दिया होता तो प्रधानमंत्री पद सफल हो सकता था।
जनता संसदीय पार्टी (जेपीपी) के नेता ने पद छोड़ दिया और राम के लिए रास्ता बना दिया।
देसाई ने केवल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जेपीपी के नेता पद से नहीं। लेकिन देसाई
उन्होंने इनकार कर दिया। यहां तक कि उनके इस्तीफे के एक दिन बाद, 16 जुलाई को भी, जेपी ने देसाई से विनती की:
'जनता संसदीय पार्टी के नेतृत्व से इस्तीफा दें।'
वह अपने रुख पर अड़ा रहा; वह राम के लिए रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं था।
राष्ट्रपति ने अब लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से आह्वान किया।
विधानसभा और कांग्रेस (एस) सरकार का गठन करेंगी। वाई. बी. चव्हाण
उन्होंने मना कर दिया। इसके बजाय, चव्हाण ने अपने 75 सांसदों के साथ समर्थन देने की पेशकश की।
चरण सिंह के नेतृत्व वाले समूह में। तभी इंदिरा गांधी ने उन्हें शामिल किया।
सिंह को उनके 72 सांसदों का समर्थन देना एक बड़ा कदम था। सिंह ने लिखा
उन्होंने इंदिरा गांधी को उनके 'बिना शर्त समर्थन' के लिए धन्यवाद दिया।
इसका उद्देश्य समाजवादियों को समर्थन स्वीकार करने के लिए एक बहाना प्रदान करना था।
जिस 'तानाशाह' इंदिरा गांधी का उन्होंने इतना पुरजोर विरोध किया था।
समाजवादियों की दुविधा—क्या वे उस कांग्रेस का समर्थन करें जिसके खिलाफ उन्होंने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया था?
उनका जीवन या तो भाजपा का समर्थन करना, जिसे वे सांप्रदायिक मानते थे, उनके

लिए कुत्ते की तरह व्यवहार करने जैसा था।
अगले चार दशकों के लिए उनके कदम।
चरण सिंह 269 सांसदों का समर्थन जुटाने में कामयाब रहे थे।
जनता पार्टी (एस) (93), कांग्रेस (एस) (75), कांग्रेस (आई) (72), एआईएडीएमके (18),
आरपीआई (6), पीडब्लूपी (5)। यह बहुत करीबी मुकाबला था। लेकिन मधु लिमाये को पूरा भरोसा था।
सिंह को 22 सदस्यीय सीपीआई (एम) का समर्थन प्राप्त है।
इंदिरा गांधी की तरह ही, जनता पार्टी के उन लोगों ने भी उनका पतन किया था।
सत्तावादी शासन ने युगों पुरानी विचारधारा को भी दफना दिया था और
सिद्धांतों'। अब उनका मानना था कि प्रेम में सब कुछ जायज़ है और
युद्ध। राष्ट्रपति ने अब चरण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।
और एक महीने के भीतर अपना बहुमत साबित करना होगा।
चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वाई. बी. चव्हाण ने पदभार संभाला।
राज नारायण ने उप प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। राज नारायण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था।
मोरारजी देसाई को सत्ता से हटाने और चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की उनकी प्रतिज्ञा। 'मेरा
'जीवन की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई है,' सिंह ने उत्साह से भरे स्वर में अपने समर्थकों से कहा।
शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने इंदिरा गांधी को फोन किया। उन्होंने कहा कि
वह 12, विलिंगडन क्रिसेंट स्थित उनके घर पर उनसे मिलने आता था। वह जा रहा था...
विलिंगडन अस्पताल (अब नाम बदल दिया गया है) में बीमार बिजू पटनायक से मिलने गए।
वह डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी रुकते थे। वे इंदिरा गांधी के आवास पर भी रुकते थे।
वापसी के रास्ते में। हालाँकि, जैसा कि सत्यपाल मलिक ने याद किया, उनके एक

साथी ने
रिश्तेदारों ने आखिरी क्षण में उसे मना लिया। 'तुम्हें उसके पास क्यों जाना चाहिए?'
अब आप प्रधानमंत्री हैं। उन्हें आपसे मिलने आना चाहिए।'
चरण सिंह ने यात्रा न करने का फैसला किया।
इंदिरा गांधी अपने बरामदे में प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही थीं, उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था।
उनके हाथ में फूल थे। वहां करीब 25 वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे।
मैं उसके साथ वहीं खड़ा था। 'मैं उस समय उसके घर पर ही था,' मलिक ने कहा।
इंदिरा ने कहा, 'प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रही हूं।' इंदिरा ने प्रधानमंत्री को देखा।
गाड़ियों का काफिला उसके घर के सामने से गुजर जाता है, बजाय इसके कि वे उसके गेट की ओर मुड़ें।
मलिक ने याद करते हुए कहा, 'मैंने देखा कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने गुलदस्ता फेंक दिया।' '
और घर के अंदर चला गया। तब मुझे पता चला कि चरण सिंह
मलिक ने कहा, 'सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी।'
इंदिरा गांधी को उस समय अपमान का सामना करना पड़ा जब यह बात फैल गई कि उन्होंने
फूलों की माला लेकर इंतजार किया लेकिन नए प्रधानमंत्री नहीं आए। बाद में, चरण सिंह ने सुलह करने की कोशिश की। लेकिन उसने जवाब में लिखा, 'अब नहीं।'
(अभी नहीं)।'
इसके बाद चरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही गईं। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई।
इंदिरा गांधी द्वारा सिंह को दिए गए समर्थन में यह बात निहित थी—हालांकि ऐसा माना जाता था
'बिना शर्त' होने का मतलब यह था कि नया प्रधानमंत्री इसे रद्द कर देगा।
विशेष न्यायालय जो उस पर और संजय पर मुकदमा चला रहे थे। लेकिन, सिंह
इंदिरा जी को मुकदमे में लाने की आवश्यकता पर जोर देते रहे। 'अगर इंदिरा जी चाहती हैं
उन्होंने कहा, 'मेरा समर्थन करने के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता,' और इस

तरह उन्होंने इस संभावना को खारिज कर दिया।
विशेष न्यायालयों की वापसी। उसे केवल एक ही बात की चिंता थी—कि
उन्होंने जगजीवन राम के साथ दोबारा साझेदारी नहीं की और न ही उनका समर्थन हासिल किया।
उन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी थी। अगर उस समय भी उन्हें राम का समर्थन मिल जाता, तो क्या होता?
(जनता पार्टी के पास अभी भी 211 सांसद थे), सिंह की सरकार सत्ता में आ सकती थी।
उसकी मदद के बिना भी जीवित रहे। राम के प्रति सिंह की नापसंदगी के बावजूद, दोनों
पुरुष समझौता करने में सक्षम थे। इसीलिए उन्होंने सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन देने का फैसला किया था; इसी वजह से जनता पार्टी में फूट पड़ गई थी।
पक्षकार अपरिवर्तनीय।
इंदिरा गांधी ने अब जगजीवन राम से संपर्क साधा। कमल नाथ ने पहले उनसे बात की।
सुरेश राम के साथ एक बैठक तय की गई, और इंदिरा गांधी ने इसका अनुसरण किया।
उसने अपने समस्या निवारक भीष्म नारायण सिंह को राम से मिलने के लिए भेजा।
जगजीवन राम यह भी जानना चाहते थे कि क्या वह उनके साथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
समर्थन। लेकिन उन्होंने उन्हें केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा।
राम उसकी चाल समझ गया। उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ समझौता करने के लिए। जनता पार्टी
1980 के आम चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया।
चुनाव।
1979 में, इंदिरा गांधी वास्तव में इसके जारी रहने में रुचि नहीं रखती थीं।
चरण सिंह की सरकार सत्ता में थी। अगर यह तेईस नहीं होता
अगर यह मामला छियालीस दिनों तक चलता, तो शायद छियालीस दिन तक चलता।
या ज़्यादा से ज़्यादा बानवे दिन तक।

दिनों। शुरू से ही उसकी योजना उसे बदनाम करने और हटाने की थी।
जनता त्रिमूर्ति का एक-एक करके नेतृत्व करना। और फिर मध्यावधि चुनाव कराना।
‘क्या आपको लगता है कि हम ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त कर सकते हैं जिसने इंदिराजी को झूठा कहा था?’
संजय गांधी ने अपने एक करीबी से कहा, 'हम... उसका चूर-चूर कर देंगे।'
आदमी।'
संजय गांधी का दिमाग मैकियावेली जैसा था, जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं था।
रवि नायर ने कहा, 'दोनों टीमें बराबरी कर सकती हैं।'
चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने के तेईस दिन बाद,
इंदिरा गांधी ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने 20 अगस्त को इस्तीफा दे दिया।
1979 में, उन्होंने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की।
राष्ट्रपति ने जगजीवन राम को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया।
वह शिकायत जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंत तक संजोए रखा। इसके बजाय, राष्ट्रपति रेड्डी
संसद को भंग करने की सिफारिश को स्वीकार करने का विकल्प चुना।
ऐसी सरकार जिसने अभी तक अपना बहुमत साबित नहीं किया था। सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार बनाई।
स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री जो ऐसा नहीं कर सका
संसद में अपना बहुमत साबित करने के लिए राष्ट्रपति ने उनसे कहा।
कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने के लिए—और जनवरी 1980 में चुनाव कराने का आह्वान किया।
जनता पार्टी ने जगजीवन राम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा।
वाई. बी. चव्हाण के नेतृत्व वाली कांग्रेस (एस) के नेता धीरे-धीरे इस ओर आकर्षित होने लगे।
इंदिरा गांधी फिर से लौट आईं। एच. एन. बहुगुणा कांग्रेस (आई) में वापस आ गए।
और उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया; उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी में शामिल किया।
उन्होंने 1980 में जामा मस्जिद के शाही इमाम के नेतृत्व में मुसलमानों का समर्थन

किया। उन्होंने उनका इस्तेमाल तो किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया।
1980 में सत्ता में वापसी हुई।
जनसंघ के पूर्व नेताओं, वाजपेयी और आडवाणी ने एक अभियान शुरू किया।
अप्रैल 1980 में एक नई पार्टी का गठन किया गया और इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नाम दिया गया।
जनता पार्टी (धर्मनिरपेक्ष) ने 1980 से पहले अपना नाम बदलकर लोक दल कर लिया था।
चुनाव। इसके अध्यक्ष चरण सिंह ने अपने उपाध्यक्ष को निष्कासित कर दिया और
हनुमान राज नारायण को 1 अप्रैल 1980 को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था।
नारायण को सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना था, जिन्हें उन्होंने ही प्रधानमंत्री बनाया था।
1979 में हुए चुनावों में उन्होंने 1984 के चुनावों में भाग लिया। हालाँकि वे वह चुनाव हार गए, फिर भी उनके संबंध मजबूत रहे।
सिंह के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया था; हैरानी की बात यह है कि उनके साथ उनका रिश्ता
गांधी परिवार उनके जीवन के अंत तक डटा रहा।
जब राजीव गांधी 1984 में सत्ता में आए, तो उन्होंने राज नारायण को आवंटित किया।
लक्ष्मीबाई नगर में स्थित घर, स्वतंत्रता सेनानी के कोटे के तहत।
विशेष रूप से गठित। नारायण ने उनसे कहा था, 'तुम्हारी माताजी (माता)'
वह मेरे सपनों में आई। उसने कहा कि उसे इस बात का दुख है कि मेरे पास एक भी नहीं है।
मुझे अपना खुद का घर चाहिए जिसमें मैं रह सकूं।
बिखरी हुई और पराजित गैर-कांग्रेसी सेनाओं को फिर से संगठित होना था।
फिर दस साल बाद वी. पी. सिंह के नेतृत्व में—और करारी हार
जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे, कांग्रेस ने 1989 में फिर से भाग लिया। लेकिन, अगस्त में
1979 में, जनता प्रयोग के रूप में उनका विखंडन पूर्ण हो गया था।

इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इंदिरा गांधी अपने मिशन में सफल हो गई थीं।

तेरहवें

1971 में, न्यूज़वीक के एक संवाददाता ने इंदिरा गांधी से एक सवाल पूछा था।
चुनाव प्रचार के दौरान: 'इस चुनाव में मुद्दा क्या है?' 'मैं ही मुद्दा हूँ,' उसने कहा।
उसने बड़े ही निडरता से जवाब दिया था। वह जानती थी कि 1971 की तरह ही, इस साल भी ऐसा ही होगा।
1980 के चुनाव 'वह' सर्वनाम के इर्द-गिर्द घूमते रहे। वह—इंदिरा
गांधी एक बार फिर चुनावों का मुख्य मुद्दा बन गए थे।
इंदिरा गांधी ने सितंबर 1979 में यात्रा शुरू की, जबकि स्तब्ध लोग
जनता के नेता या तो अपनी सूझबूझ जुटाने की कोशिश कर रहे थे या एक-दूसरे को दोष दे रहे थे।
दूसरे अपनी सरकार के पतन के लिए जिम्मेदार थे। वह दो लोगों के साथ अपना घर छोड़कर चली गई।
सूटकेस जिनमें आठ खूबसूरत साड़ियाँ और आठ पूरी बाजू की पोशाकें थीं
ब्लाउज़; दो फ्लास्क, एक उबले पानी के लिए, दूसरा ठंडे दूध के लिए; सूखा
फल; और एक नारंगी रंग की, जापान में बनी, पोर्टेबल ट्यूबलाइट।
पहले चरण में कार, विमान और हेलीकॉप्टर से 40,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई।
दस सप्ताह तक वह अकेले ही देश भर में यात्रा करती रही ताकि जीत हासिल कर सके।
चुनाव।
उन्होंने जनता नेताओं और श्रम संगठनों के बीच चल रही आंतरिक कलह के बारे में बात की।
unrest, and soaring prices. Slogans like 'Janata ho gayi fail, kha gaya
chini aur mithi ka tel (The Janata government has failed, it's been
मिट्टी के तेल और चीनी की कमी से त्रस्त)' की खबरें बहुतायत में थीं। मीडिया

इसे 'केरोसिन और चीनी का चुनाव' कहा गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे बरकरार रखा।

अपना पूरा ध्यान खुद पर केंद्रित करो—उस निर्णायक नेतृत्व पर जो केवल वही कर सकती थी

प्रदान करें। उन्होंने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या अन्य विषयों पर ज्यादा बात नहीं की। गरीबी दूर करना। उन्होंने लोगों से केवल एक ऐसी सरकार चुनने का आग्रह किया जो 'गरीबी को दूर करे'।

काम करता है।

नवंबर 1979 में, एस. वेंकट नारायण, जो भारत के कार्यकारी संपादक थे, ने

आज, इंदिरा गांधी के चुनाव अभियानों को किसने कवर किया था?

अतीत में, वह चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ थे। वह और एक जर्मन

फोटोग्राफर ने कुछ दिनों तक फोकर फ्रेंडशिप विमान में उसके साथ यात्रा की।

आंध्र प्रदेश के एक उद्योगपति द्वारा उपलब्ध कराए गए विमान। वे कस्बों और अन्य स्थानों की ओर उड़ान भरते थे।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के शहरों

नाडू। चेन्नई में, वह आधी रात को पहुंची और संबोधित किया।

माउंट रोड पर उत्साही समर्थकों के साथ एम. करुणानिधि भी मौजूद थे।

वह जहां भी जाती, भीड़ उसका इंतजार करती थी। वह दो जगहों से चुनाव लड़ रही थी।

उत्तर प्रदेश में रायबरेली और आंध्र प्रदेश में मेडक निर्वाचन क्षेत्र।

मेडक, उनकी पार्टी के आंध्र प्रदेश के शीर्ष नेता, पी.वी.

Narasimha Rao, Marri Chenna Reddy, and N. Janardhana Reddy,

वह उसके साथ कलेक्टर के कार्यालय गई जहाँ उसने अपना आवेदन दाखिल किया। नामांकन।

वह विमान के अगले पड़ाव पर उतरने से ठीक पहले तरोताज़ा हो जाती थी।

चुनाव प्रचार के दौरान। उनके भाषण हर जगह संक्षिप्त होते थे। वह

केवल दस से पंद्रह मिनट बोलें। उनका संदेश था, 'हाथ को वोट दें'।

अंत में एक सरल संदेश। लेकिन वह इसे कहने पर विशेष ध्यान देती थी।

स्थानीय भाषा। रात में, ग्रामीण इलाकों से गाड़ी चलाते समय, वह
वह कार में पोर्टेबल ट्यूबलाइट को इस तरह से लगाती कि उसका चेहरा
उसे देखने के लिए कतार में खड़ी भीड़ के लिए रोशनी जगमगा उठती। दर्शन ही उनके लिए सब कुछ था।
वह चाहती थी। वह यह जानती थी।
अपने देखे हुए अनुभवों के आधार पर, एस. वेंकट नारायण ने भविष्यवाणी की थी कि इंदिरा
गांधी जी भारी बहुमत से वापसी कर रहे थे। चर्चिल को...
सत्ता में वापसी के लिए छह साल इंतजार करना पड़ा, नेपोलियन को सात साल और डी गॉल को।
उन्होंने लिखा, '12 साल से। अगर श्रीमती गांधी अगले महीने सत्ता में वापस आती हैं, तो...'
यह निश्चित रूप से हाल के राजनीतिक इतिहास में सबसे तेज वापसी होगी।
अगले दिन वह पत्रिका बाजार में आ गई। उनके कार्यालय ने उन्हें फोन किया।
'Venkatji, namaskar. Main Yashpal Kapoor bol raha hoon. Aap jante
हाय होंगे (यह यशपाल कपूर बोल रहे हैं, आपने सुना ही होगा)
(मैं)।' यह इंदिरा गांधी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सहयोगी यशपाल की आवाज थी।
कपूर। 'मैडम ने मुझे आपको फोन करके धन्यवाद देने के लिए कहा था।'
'क्यों?'
आपने लिखा है कि वह जीत रही है।
कृपया उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद दें। लेकिन कृपया उन्हें यह भी बता दें कि अगर लोगों ने ऐसा किया होता तो क्या होता।
अगर उसने उस पर जूते फेंके होते, तो मैं वह भी लिख देता।
'क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे?' कपूर ने पूछा।
क्या कोई ऐसा पत्रकार है जो साक्षात्कार देने से मना कर देगा?
Indira Gandhi?'
हम दोपहर 3 बजे तकनीकी क्षेत्र से कानपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। आप

वहां आओ।'
बारह बज चुके थे। नारायण, जो सड़क पर था
कई दिनों तक, बिना दाढ़ी बनाए और बिखरे बालों के साथ, वह अपनी पत्नी से जल्दी दाढ़ी बनाने का आग्रह करता रहा।
उसने ऑफिस में एक हेयर किट और एक हेयरब्रश भेजने को कहा। उसे दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसने भेज दिया।
मुझे एक सूट दिया गया था जो मैंने लंदन में खरीदा था।
अगले दिन उन्हें फोकर विमान में इंदिरा गांधी का साक्षात्कार लेने का अवसर मिला।
मित्रता के नाम पर, कॉकपिट के पास एक छोटे से क्षेत्र को घेर लिया गया था।
उस कोने में बैठकर वह चिट्ठियाँ लिखवाती थी। उसकी स्टेनोग्राफर उन्हें टाइप करती थी।
उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के समय के रेमिंगटन टाइपराइटर पर टाइप करना था।
फिर अंतिम प्रति को हस्ताक्षर के लिए टाइप करने से पहले उनमें सुधार किया गया।
इंदिरा ने नारायण के बिना दाढ़ी वाले चेहरे को देखा और फिर उस वस्तु को देखा।
उसका हाथ। 'यह क्या है?' उसने संदेह से पूछा। यह एक टेप रिकॉर्डर था।
उन दिनों इंडिया टुडे के पास यही एकमात्र पोर्टेबल अखबार हुआ करता था।
'मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा,' उसने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा।
मैं नोट्स बना लूंगा और आपके कथन को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
साक्षात्कार शुरू हुआ।
‘अगर आप सत्ता में आते हैं, तो वी.सी. शुक्ला की क्या भूमिका होगी?’
'संजय गांधी?' नारायण ने उससे पूछा।
संजय गांधी का नाम सुनते ही उनकी भौंहें सिकुड़ गईं।
उन्होंने कहा, 'मैं ज्योतिषी नहीं हूं। अगर हम सत्ता में आते हैं, तो हम लेंगे।'
वहीं से शुरू करते हैं।'
वे रात 10 बजे दिल्ली वापस लौटे। लेकिन वहाँ किसी भी तरह के संकेत नहीं थे।
उन्हें उतरने में मदद करने के लिए सीढ़ी। पंद्रह मिनट बीत गए। वह उतर रही थी।
बेचेन होना।
‘यशपाल?’ उसने अपने सहायक को पुकारा।

'हां मैम।'
उसने पूछा, 'विमान और जमीन के बीच की ऊंचाई कितनी है?'
‘लगभग दस फीट,’ उसने जवाब दिया।
‘मैं कूदने जा रही हूँ, आप लोग सीढ़ी आने पर आना,’ उसने कहा।
उसे बताया।
वह विमान से कूदी और तेज़ी से आगे बढ़ गई।
टर्मिनल भवन। बाकी सभी लोग सीढ़ी के आने का इंतजार कर रहे थे।
उतरना।
अगली सुबह जब इंडिया टुडे का अंक बाजार में आया, तो
इसमें नारायण का इंदिरा के साथ साक्षात्कार छपा था। लेकिन कवर पेज पर इससे भी अधिक जानकारी थी।
दो चुनावी विश्लेषकों - प्रणॉय रॉय और
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अशोक लाहिड़ी—एक के आधार पर
25,000 लोगों के साथ किए गए जनमत सर्वेक्षण में, उन्होंने एकतरफा जीत की भविष्यवाणी की।
इंदिरा गांधी। यही हुआ। उन्होंने लोकसभा में 353वीं जीत हासिल की।
सीटें, जो कि 1971 में अपने चरम पर रहने के दौरान उन्हें मिली सीटों से एक अधिक है।
1980 में इंदिरा गांधी की जीत के कई कारण थे। लोग
जनता पार्टी के उन झगड़ालू और अयोग्य नेताओं से तंग आ चुका था जो यह भूल चुके थे कि ऐसा क्यों करना चाहिए।
लोगों ने उन्हें सत्ता में बिठाया था। इसके विपरीत, इंदिरा ने खुद को एक
सशक्त और निर्णायक नेता। लोग कीमतों के बोझ तले दबे हुए थे।
जो फरवरी 1979 से अंत तक 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया था।
साल भर। उन्होंने लोगों की आर्थिक कठिनाइयों का पूरा फायदा उठाया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल वही उन्हें राहत दे सकती थी।
उच्च जातियों की ओर से भी विरोध हुआ। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।
मध्य किसान जातियों के उदय द्वारा प्रदर्शित मुखरता
चरण सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के बाद, वे कांग्रेस (आई) में वापस चले गए।

कई दलित जिन्होंने बाबू जगजीवन राम को एक विकल्प के रूप में देखा था
1977 भी इंदिरा गांधी के पक्ष में लौटा। उम्मीदों के विपरीत, उन्होंने भी
संजय के जबरन किए गए कृत्यों के बावजूद, उसे कुछ मुसलमानों का समर्थन मिला।
नसबंदी अभियान ने कई लोगों को नाराज कर दिया था; इससे उन्हें आंशिक रूप से मदद मिली।
कांग्रेस के पुराने ब्राह्मण-दलित-मुस्लिम वोट बैंक को फिर से खड़ा करना। संजय
उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जानबूझकर अपनी प्रोफ़ाइल को सीमित रखा था।
इंदिरा गांधी का मंदिर जाना और 1977-80 के दौरान उनका 'हिंदू समर्थक' रुख अपनाना, इन सब बातों की भरपाई करता है।
मुस्लिम समर्थन खोने के कारण। और इसने उन्हें 'हिंदू-प्रथम' नीति अपनाने में मदद की।
भाजपा से कार्ड छीन लिया।
इंदिरा और संजय द्वारा उन्हें बदनाम करने के लिए सुनियोजित ढंग से चलाया गया अभियान
जनता सरकार ने तैंतीस महीनों में अपना वादा पूरा किया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में।
गांधी अपनी जीत का आनंद ले रही थीं, तभी उनकी एक युवा सहकर्मी को 1977 में कही गई उनकी बात याद आई। 'क्या तुम्हें नहीं पता, तुम केंद्र से भटक नहीं सकतीं?'
‘स्टेज?’ इंदिरा ने अंबिका सोनी से कहा था। ‘क्योंकि पर्दे के पीछे तो बहुत ही ठंडा।'
■

इंदिरा गांधी ने 14 तारीख को एक बार फिर भारत की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
जनवरी 1980। वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह खुश थी, पहले से कम
अपने लिए और उससे भी ज्यादा संजय के लिए। संजय ने अमेठी से शानदार जीत हासिल की।
कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन उन्होंने ही किया था। इस बार, इसके विपरीत

1977 में, जीतने वाले 353 लोगों में से 234 न केवल पहली बार भाग ले रहे थे बल्कि नए प्रतिभागी भी थे।
राजनीति में। और उनमें से 150 लोग 'संजय के कट्टर समर्थक' थे।
उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए इन्हें स्वयं चुना था।
इस जीत ने उन्हें देश के 'युवराज' के रूप में वैधता प्रदान कर दी थी।
उन्होंने जगमोहन मल्होत्रा जैसे पुराने वफादारों का पुनर्वास करने में भी तेजी दिखाई।
जनता सरकार द्वारा विवादास्पद उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया
दिल्ली विकास प्राधिकरण से उन बुलडोजरों के लिए जो उसके पास थे
तुर्कमान गेट विध्वंस में तैनात किए गए, उन्हें अब बनाया गया था
दिल्ली के उपराज्यपाल।
लोकसभा चुनाव के छह महीने बाद, इंदिरा गांधी ने नौ विधायकों को बर्खास्त कर दिया।
राज्य सरकारों ने इस आधार पर कि उन्होंने भी जनादेश खो दिया था
शासन करना—ठीक वैसे ही जैसे जनता सरकार ने 1977 के मध्य में किया था।
तमिलनाडु को छोड़कर इनमें से आठ राज्यों में कांग्रेस ने शानदार वापसी करते हुए सत्ता हासिल की।
संजय सिंह ने अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में 'अपने आदमियों' को नियुक्त किया - माधव सिंह
Solanki in Gujarat, Arjun Singh in Madhya Pradesh, Jagannath
राजस्थान में पहाड़िया और महाराष्ट्र में ए. आर. अंतुले ने कार्यभार संभाला।
जून 1980 के दूसरे सप्ताह में।
संजय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता था।
देश का सबसे बड़ा राज्य। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल की थी।
विधानसभा की 425 सीटों में से 309 सीटें। इसने 85 में से 51 सीटें हासिल की थीं।
छह महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में सीटें।
31 मई 1980 को संजय ने डम्पी अहमद को लखनऊ भेजा ताकि वह तैयारी कर सके।

मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति का आधार। तीन साल के भीतर,
डम्पी संजय के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बन गया था। उन लोगों के विपरीत जो चले गए थे
इंदिरा गांधी के सत्ता से बाहर होने पर, उन्होंने उनके पक्ष में फैसला किया था कि संजय के सत्ता से बाहर होने के ठीक बाद उनके साथ काम करना।

डम्पी अहमद का लखनऊ मिशन आम सहमति बनाना था।
संजय के नाम को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश के नेता के रूप में लेकर उनके इर्द-गिर्द चर्चाएँ चल रही हैं।
विधानसभा दल।
4 जून 1980 को उत्तर प्रदेश विधानसभा की पार्टी की बैठक लखनऊ में हुई। शिव शंकर पार्टी के पर्यवेक्षक थे। सब कुछ व्यवस्थित था। कांग्रेस
विधानसभा दल ने संजय गांधी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव पारित किया।
नेता। इसके अलावा, उन्होंने फैसला इंदिरा गांधी पर छोड़ दिया था।
सुबह 11 बजे बुलाई गई बैठक दोपहर तक समाप्त हो गई। डम्पी अहमद
रक्षा मंत्री के विमान से दिल्ली वापस लौटे। सी. पी. एन. सिंह, जिन्होंने
रक्षा राज्य मंत्री थे और गांधी परिवार के भरोसेमंद थे।
इसका इंतजाम हो गया था। दोपहर 2 बजे तक डम्पी अहमद वापस सफदरजंग रोड स्थित 1 नंबर पर आ गया था।
इंदिरा गांधी से मिलने के लिए वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी मुलाकात उनसे शाम 4 बजे ही हो सकी।
दोपहर
मैंने प्रस्ताव उसे सौंप दिया।
डम्पी अहमद ने उनसे कहा, 'विधायक संजय को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।'
इंदिरा गांधी ने उनसे साफ-साफ कहा, 'नहीं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती।'
‘उन्हें (प्रशासन का) अनुभव होना चाहिए,’ डम्पी अहमद ने कहा।
उन्होंने विरोध जताया। ‘इसे हासिल करने के लिए यूपी से बेहतर जगह और क्या हो सकती है?’
उसने चिढ़कर उससे कहा, 'मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उसे सुधारा नहीं जा सकता।'

सेमी।'
डम्पी अहमद रात के खाने तक घर पर ही रुके रहे। 'मैं पहले...'
उन दिनों वे चौबीसों घंटे सातों दिन वहीं रहते थे।' उन्होंने रात के खाने पर फिर से यह मुद्दा उठाया, इस बार
संजय के सामने।
इंदिरा गांधी ने एक बार फिर अपना कड़ा रुख अपनाया।
उन्होंने साफ-साफ कहा, 'मैंने अपना मन बना लिया है।' वे चुन सकते थे।
उन्होंने कहा कि वे जिसे चाहें उसे नियुक्त कर देंगे।
व्यक्ति।
इंदिरा, जो जीवन भर संजय को 'ना' नहीं कह सकीं, ने कहा...
अब उसे दृढ़तापूर्वक और बार-बार 'ना' कह दें।
डम्पी ने याद करते हुए कहा, 'यह वही डिनर था जो संजय ने आर. के. धवन के लिए भेजा था।'
अहमद धवन को वी.पी. सिंह को फोन करने के लिए कहा गया। शुरू में, वी.पी. सिंह मुख्यमंत्री का पदभार संभालने में वह अनिच्छुक थे—लेकिन अंततः वह सहमत हो गए।
जून 1980 में, इंदिरा गांधी स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहती थीं।
संजय को मुख्यमंत्री नियुक्त करना। वह जानती थी कि इससे लोगों में आक्रोश पैदा होगा।
विपक्ष के गुस्से का सामना करना पड़ेगा; उनकी नियुक्ति से विवाद खड़ा हो जाएगा।
उसके चारों ओर एक बार फिर। वह चाहती थी कि बदनामी की धूल जम जाए।
आपातकाल के दौरान और उसमें उनकी भूमिका के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही उन्होंने आगे की योजना बनाई। उनके मन में उनके लिए एक बड़ी भूमिका थी, अपने उत्तराधिकारी के रूप में। लेकिन उन्होंने
वह चाहती थी कि वह धीरे-धीरे इसमें ढल जाए। किसी भी हालत में, वह चाहती थी कि वह तब तक...
दिल्ली में वह उसके साथ थी। बुरे समय में वह उस पर निर्भर हो गई थी।
वर्षों तक—और उन्होंने 1980 में कांग्रेस की जीत का पूरा श्रेय उन्हें ही दिया।
इंदिरा ने यह भी कहा, 'अपने दोस्त (संजय) से कह दो कि वह मुख्यमंत्री नहीं बन

सकता।’
कांग्रेस नेता एच. आर. भारद्वाज ने कहा, 'उन्हें बता दो कि अगर वे ज़िद करते हैं, तो मैं...'
इस्तीफ़ा देना।'
संजय, जिसे आमतौर पर अपनी बात मनवाने की आदत थी, ने इस बार जिद नहीं की।
दो सप्ताह बाद, उनका देहांत हो गया।

XIV

13 दिसंबर 1980 को इंदिरा गांधी को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर उतरा।
कांगड़ा में योल कैंप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राम लाल,
वह अपने मंत्रिस्तरीय दल के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे।
इंदिरा चामुंडा देवी के मंदिर में प्रार्थना करने आई थीं।
पालमपुर को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि
इंदिरा गांधी को नौ साल पहले ही 'दुर्गा' की उपाधि से नवाजा गया था,
बांग्लादेश की मुक्ति।
सोलहवीं शताब्दी के इस मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते थे।
वर्ष। इंदिरा गांधी देवी में गहरी आस्था रखती थीं। अपनी मृत्यु तक।
1984 में, मंदिर में उनके नाम पर नियमित रूप से प्रार्थनाएँ की जाती थीं, और
प्रसाद दिल्ली में उसके पास वापस ले जाया जाता था। वह एक डिब्बे में पैसे रखती थी।
अनिल बाली ने बताया, ‘लिफाफा (लिफाफा) लो और मुझे दे दो।’ ‘हर दो
मैं महीनों तक उससे मंदिर के लिए 101 रुपये लेता था।
लेकिन इस बार वह एक गंभीर मिशन पर थी। वह यहाँ पहुँची थी...
संजय की स्मृति में प्रार्थना करें, जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
उसी वर्ष 23 जून को, वह एक छोटा विमान, पिट्स एस2-ए उड़ा रहा था, और
विमान पर नियंत्रण खो दिया। इंदिरा को यहाँ आना था।
उनकी मृत्यु से एक दिन पहले चामुंडा उनके साथ थीं।
जब उन्होंने जनवरी 1980 में जीत हासिल की, तो अनिल बाली ने उन्हें सुझाव दिया

था कि
शपथ लेने के बाद उन्हें स्वयं चामुंडा देवी से मिलने जाना चाहिए।
कार्यालय में जाकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस दिन उन्होंने 14 तारीख को शपथ ली थी।
जनवरी 1980 में, उन्होंने अपने निवास पर 12 बजे एक कीर्तन का आयोजन किया था।
विलिंगडन क्रीसेंट। वह इसमें भाग लेने के लिए जल्दी से घर लौट आई थी, जल्द ही राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद।
'मैडम, आपको चामुंडा देवी जाना होगा,' अनिल बाली ने याद दिलाया।
कीर्तन में वह।
'हां,' उसने सहमति जताते हुए कहा, 'मुझे चार से पांच महीने का समय दीजिए।'
मई 1980 के पहले सप्ताह में, बाली को आर.के. से एक पत्र प्राप्त हुआ।
धवन। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री 22 तारीख को चामुंडा जाना चाहते हैं।
जून (1980)। धवन ने लिखा कि वह शाम 4:45 बजे वहाँ पहुँचेगी। उन्होंने पूछा
बाली ने अपना कार्यक्रम आयोजित किया। बाली चामुंडा गई और कार्यक्रम का आयोजन किया।
उनके आने पर उनके द्वारा पूजा करने की व्यवस्था की गई थी। यह इसलिए किया गया था ताकि
इसके बाद स्थानीय लोगों को भोजन कराने के लिए हवन और लंगर का आयोजन किया जाएगा।
मंदिर में पूजा करने वाले लोग।
20 जून की शाम को चामुंडा में एक संदेश आया कि
प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था।
हिमाचल प्रदेश सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री राम लाल भी शामिल हैं,
वहाँ डेरा डाले हुए लोग उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब पुजारी ने सुना
अगर वह नहीं आ रही थी, तो उसने तीखी प्रतिक्रिया दी। 'तुम इंदिरा गांधी को बता दो, यह...'
चामुंडा। अगर कोई साधारण मनुष्य न आ पाए तो माँ उसे क्षमा कर देंगी।
लेकिन यदि शासक अनादर प्रदर्शित करता है तो देवी क्षमा नहीं करेंगी।

Devi ki avamanana nahin kar sakte (The ruler cannot insult the
देवी।)
'पंडितजी,' बाली ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, 'इसके पीछे कोई अच्छा कारण जरूर होगा।'
वह नहीं आ सकीं। उन्होंने कीर्तन और प्रार्थना जारी रखी।
22 तारीख को योजना के अनुसार। 23 तारीख की सुबह, समूह शहर से रवाना हो गया। 'हम
जब मैं 50 किलोमीटर आगे ज्वालामुखी मंदिर पहुंचा, तभी मेरी
बाली को याद आया, 'सेक्रेटरी दौड़कर मेरे पास आई।'
उन्होंने कहा, 'संजय गांधी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और पाकिस्तान रेडियो...'
इसका प्रसारण करना।'
तैंतीस वर्षीय संजय ने विमान पर से नियंत्रण खो दिया था।
एक हवाई करतब करते हुए। संजय अपने करतबों के लिए जाने जाते थे।
जिस छोटे विमान को वह उड़ा रहा था, उसके नियंत्रण में रहते हुए उसने खतरनाक स्टंट किए—
जीवन के प्रति उनके बेपरवाह रवैये का प्रतिबिंब। उनकी पत्नी मनेका के पास
पिछली शाम वह उसे कुछ दिखाने के लिए 'मौज-मस्ती' के लिए गाड़ी की सवारी पर गया था।
उसका नवीनतम खिलौना। 'विमान में मैं चीखती रही, मुझे लगता है दो मिनट तक।'
कुछ घंटों बाद,' उसने बाद में कहा। 'जब हम नीचे आए, तो मैं दौड़कर घर गई और अपने
सास ने कहा, "मैंने जीवन भर आपसे कभी कुछ नहीं माँगा। मुझे ज़रूरत है।"
अब आपको संजय को बताना होगा कि वह दोबारा इस विमान से उड़ान न भरे।
संजय की मौत की खबर से पूरा देश सदमे में था।
अनिल बाली और कपिल मोहन का परिवार (जो वहां मौजूद था)
चामुंडा मंदिर से बाली तुरंत दिल्ली लौट आए। बाली सीधे इंदिरा गांधी के आवास की ओर रवाना हुए। उनके पहुंचने पर सुबह के 2:30 बज रहे थे। इंदिरा गांधी बैठी थीं।

शव के साथ। उसने उसे देखा और उससे बात करने के लिए उठ खड़ी हुई।
क्या इसका मेरे चामुंडा न जाने से कोई संबंध है?
उसने बाली से पूछा।
'महोदया,' बाली ने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, 'यह (इस बारे में) बात करने का समय नहीं है।
मैं आपको बाद में बताऊंगा।
चौथे दिन के समारोह में बाली अकबर रोड स्थित 1 नंबर स्टेशन पर पहुंचीं।
इंदिरा गांधी के साथ सुनील दत्त और उनकी अभिनेत्री पत्नी नरगिस भी मौजूद थीं। लेकिन
इंदिरा ने बाली को इशारा किया और उसे एक तरफ ले जाकर कहा, 'अब मुझे बताओ क्या...'
'क्या हुआ था।' बाली ने उसे बताया कि जिस दिन उसके आने की उम्मीद थी, उस दिन क्या हुआ था।'
चामुंडा मंदिर में।
उन्होंने सोच-विचार करते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता कि मेरा कार्यक्रम किसने रद्द किया।'
उन्होंने बताया कि वे जम्मू से चामुंडा आने वाले थे। संजय के पास
वह उसके साथ गई थी और मंदिर दर्शन के लिए उसके साथ आने वाली थी।
मुझे बताया गया है कि मौसम बिगड़ गया है और बारिश हो रही है।
चामुंडा में स्थिति बहुत कठिन है। हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाएगा।
आने वाले घंटों में वे वहाँ पहुँच जाएँगे। इसलिए उन्होंने एक दिन बाद दिल्ली लौटने का फैसला किया।
इससे पहले, बाली ने हैरानी जताते हुए उससे कहा कि मौसम खराब नहीं था।
चामुंडा। बारिश भी नहीं हो रही थी। किसी ने उसे चुन लिया था।
चामुंडा से मिलने न जाने के लिए इंदिरा ने बाद में पुपुल से यह बात कही।
जयकर ने कहा कि संजय की मौत उसकी गलती थी। उसने वह काम नहीं किया था।
वह उन अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं को करना चाहती थी जो वह करना चाहती थी।
संजय की मृत्यु के कई महीनों बाद, इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार ने...
एम. एल. फोतेदार ने बाली में फोन किया।

फोतेदार ने कहा, 'प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए, अवश्य उपस्थित रहें।'
मैं वहां सुबह 7:30 बजे था।
उसने अपने सेवक नत्थू राम को बाली को अंदर आने देने का निर्देश दिया था।
निवास स्थान।
उसके सिर पर टोपी थी। बाली ने कहा, 'उसने जाहिर तौर पर अपने बालों को रंगा था।'
याद आया। वह तुरंत मुद्दे पर आ गई। 'मैं जाना चाहती हूँ'
'चामुंडा,' उसने बाली से कहा। उसने उससे आवश्यक व्यवस्था करने को कहा।
व्यवस्थाएँ।
13 दिसंबर 1980 को वह चामुंडा गई थीं।
जब वह पूजा कर रही थी, पंडित जी के हाथ कांप रहे थे।
मैं कट्टर हिंदू हूँ... और जिस तरह से वह मंत्र पढ़ती थी
पूर्णाहूति, और जब वह गर्भगृह में अपना मतथेकना (सिर झुकाना) करने गई, या (जब) वह अनुष्ठान कर रही थी
काली की पूजा के लिए मुद्राएं, उन्होंने इसे पूर्णता से किया।
और वह रोने लगी। वह बस रोती ही रही, रोती ही रही। मुझे याद आया कि
पंडित ने कहा था कि वह रोते हुए (वहाँ) आएगी।
पुजारी ने कहा, 'अब आपके पास 60 करोड़ बेटियां-बेटियां हैं।'
said as he tried to comfort her. ‘Aap inko dekhiye.’ And he added, ‘Aaj
के बाद रोना नहीं (तुम उनका ख्याल रखना। आज के बाद रोना मत)।
उसने प्रसाद ग्रहण किया, मंदिर की परिक्रमा की और
बाईं ओर। उनके साथ गृह मंत्री बूटा सिंह और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे।
प्रदेश के मुख्यमंत्री राम लाल। बाहर, उन्होंने पेड़ लगाए - उनमें से एक
आपातकाल के दौरान संजय के पांच सूत्री कार्यक्रम के प्रमुख तत्व।
वह अपने साथ जगन्नाथ शर्मा को ले गई थी, जो एक समय में
वह अपने पति फ़िरोज़ के यहाँ माली के रूप में काम करती थी। वह यह सुनिश्चित करती थी कि घाट बना रहे।
चामुंडा में संजय के नाम पर निर्मित। 'इसकी लागत 80 लाख रुपये थी।'

यह उपाधि कांग्रेस नेता सुखराम के पास थी, जो बाद में मुख्यमंत्री बने।
हिमाचल प्रदेश के मंत्री,' बाली ने कहा।
संजय की मृत्यु के बाद, कई लोगों ने सोचा था कि क्या इंदिरा गांधी
उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। लेकिन उनकी मृत्यु ने उन्हें बहुत प्रभावित किया।
1977 में संजय ने इंदिरा गांधी का पतन करवाया था। 1980 में,
संजय ने ही उनकी वापसी में मदद की थी। तीस के भीतर-
उन्हें पद से हटाए जाने के तीन महीने बाद ही उन्हें एक बार फिर सिंहासन पर बिठा दिया गया।
भारत की प्रधानमंत्री। उनके बाद लिए गए सभी निर्णयों में।
हार के बाद, उसका छोटा बेटा उसका सहारा, उसका साथी, उसका
साथी योद्धा। और अब वह चला गया था। किसी न किसी तरह, उसकी प्रार्थनाएँ
1980 के उस ठंडे दिसंबर के दिन देवी को जो भेंट चढ़ाई गई थी, उससे मदद मिली।
संजय की मृत्यु को स्वीकार करने के बाद, मंदिर से निकलने से पहले उसने इस बात को स्वीकार कर लिया।
उसने धीमी आवाज़ में कहा, 'मैंने इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी।'
जब इंदिरा गांधी चामुंडा देवी होटल से दिल्ली वापस लौटीं
मंदिर से वह सीधे उस समारोह में जाने के लिए रवाना हुई जिसमें उसे शामिल होना था।
भाषण। इस कार्यक्रम का आयोजन सहयोगी समाचार पत्र क़ौमी आवाज़ द्वारा किया गया था।
नेशनल हेराल्ड के उर्दू संस्करण में। वह अपने सामान्य अंदाज में कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुई।
तेज गति से, लेकिन उसके चेहरे पर नाजुकता झलक रही थी। इससे पहले
कार्यक्रम समाप्त होने पर उन्होंने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को मंच पर बुलाया और उन्होंने सभा में उनका परिचय कराया। उपस्थित लोगों ने उनके बारे में मन में एक बात नोट कर ली।
क्योंकि उस शाम, बिना खुलकर कहे, इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था।
उन्होंने अपने नए राजनीतिक उत्तराधिकारी को लॉन्च किया।

अध्याय दो

धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री जिसने कमजोर किया
धर्मनिरपेक्षता

शाह बानो के मामले में राजीव गांधी का ढुलमुल रुख

मैं

'राजीव, अगर तुम मुझे इस मुस्लिम महिला विधेयक के बारे में समझा नहीं सकते, तो कैसे?'
‘क्या तुम देश को मना पाओगे?’ सोनिया ने अपने पति से कहा।
राजीव।
उस समय राजीव भारत के प्रधानमंत्री थे, और वह केवल आधी ही थीं।
उसे चिढ़ाते हुए उसने कहा, 'तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करना होगा।'
उसे गंभीरता से।
‘यह सोनिया ने मेरी मौजूदगी में कहा था,’ डी. पी. त्रिपाठी ने मुझे बताया। ‘किसी ने नहीं’
अभी तक यही रिपोर्ट आई है।’ अनुभवी राजनीतिज्ञ त्रिपाठी भी वहां मौजूद थे।
एक समय वह राजीव गांधी के करीबी लोगों में से एक थे—बाद में वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक संसद सदस्य।
यह बातचीत सन् 1985 के अंत में हुई थी।
रेस कोर्स रोड स्थित प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास। वामपंथी झुकाव वाला
त्रिपाठी उन दिनों वहां अक्सर जाया करते थे और उन्हें देखा गया था
प्रधानमंत्री के सलाहकारों में से एक के रूप में।
सोनिया गांधी जिस कानून का जिक्र कर रही थीं, उसे आम तौर पर कहा जाता था...
मुस्लिम महिला विधेयक—मुस्लिम महिला विधेयक का संक्षिप्त रूप
(तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 1986। सोनिया जानती थी कि राजीव

वह विधेयक को पारित करने पर गंभीरता से विचार कर रही थी। तब उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि
इससे राजनीतिक बवाल मच जाएगा और स्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगी।
भारतीय राजनीति की रूपरेखा।
राजीव गांधी एक फैसले को पलटने के उद्देश्य से इस विधेयक पर विचार कर रहे थे।
जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल 1985 को सुनाया था।
यह मामला शाह बानो केस के नाम से मशहूर हुआ। अदालत ने पीड़ित मुस्लिम महिला शाह बानो को भरण-पोषण राशि देने का आदेश दिया था।
तलाकशुदा महिला।
इस बात से चिंतित कि विधेयक किसी गरीब, पीड़ित व्यक्ति को वंचित न कर दे,
उस दिन तलाकशुदा मुस्लिम महिला को मिलने वाले भरण-पोषण के पैसे
सोनिया गांधी अपने पति से मुस्लिम धर्म में न जाने का आग्रह कर रही थीं।
महिला विधेयक।
त्रिपाठी ने राजीव गांधी को चेतावनी देते हुए कहा, 'यह एक विनाशकारी मार्ग है। आप अपनी विश्वसनीयता खो दो।
राजनीति में निपुण त्रिपाठी परिणामों को लेकर चिंतित थे।
प्रस्तावित कानून ऐसा कर सकता था। इसके बाद के दिनों में, उसने
उन्होंने राजीव गांधी से बार-बार आग्रह किया कि वे इससे प्रभावित न हों।
मुस्लिम समुदाय में कट्टरपंथियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा।
उन्होंने राजीव को चेतावनी देते हुए कहा, 'आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों को चेतावनी दें।'
राजीव को समझाने में असफल रहने पर, उत्तेजित त्रिपाठी ने ज्योति बसु को फोन किया।
and Harkishan Singh Surjeet, asking them to intercede with Rajiv. He
मुझे लगा कि राजीव उनकी बात सुन लेंगे। दोनों ही सीपीआई के वरिष्ठ नेता थे।
(एम)। अगर राजीव आगे बढ़ गया, तो इसे रोकना 'बहुत मुश्किल' हो जाएगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि यह 'हिंदू कट्टरपंथी ताकतों' का मार्च है।
'बिल्कुल यही हुआ।' क्योंकि बिल के बाद यह आया था...

विवादित बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का फैसला भी उतना ही विनाशकारी है।
वह मस्जिद जिसे हिंदू राम जन्मभूमि होने का दावा कर रहे थे,
भगवान राम की जन्मभूमि।
1985 में, राजीव गांधी को देश के नए सितारे के रूप में देखा जा रहा था।
क्षितिज। मीडिया ने 1985 को भारत में 'आशा का वर्ष' घोषित किया था।
क्रूर घटना के बाद राजीव ने देश में शांति स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी।
अक्टूबर 1984 में उनकी माता इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद
हिंसक परिणाम। त्रिपाठी नहीं चाहते थे कि राजीव ऐसा कुछ भी करे जिससे
इससे उसे मिली पहल बेकार हो जाएगी। क्योंकि वह जानता था कि
सतही शांति के पीछे उथल-पुथल छिपी हुई थी—यह बात कुछ ही लोगों के ध्यान में आई, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इसे महसूस किया।
सत्ता के केंद्र के करीब। लेकिन यह उथल-पुथल जल्द ही फैल जाएगी।
मुस्लिम महिला विधेयक को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मची हुई है।
■

23 अप्रैल 1985 को, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया
मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में फैसला
और अन्य—कुछ ही लोग कल्पना कर सकते थे कि इससे कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। या यह कि इसका व्यापक प्रभाव आने वाले समय में देश की राजनीति को आकार देगा।
तीन दशक।
शाह बानो, एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला, का तलाक हो चुका था।
उनके पति मोहम्मद अहमद खान द्वारा पैंतालीस वर्षों के बाद
वह महिला विवाहित थी और उससे भरण-पोषण की मांग कर रही थी। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि वह महिला विवाहित है और उससे भरण-पोषण की मांग कर रही है।
अपने फैसले में, उसने उसकी याचिका स्वीकार कर ली थी।

खान मध्य प्रदेश के इंदौर में एक वकील थे। शाह बानो के पास
उन्होंने 1932 में उनसे शादी की। उनके पांच बच्चे थे। चौदह साल बाद
शादी के बाद, खान ने दूसरी महिला को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया।
1975 में, उन्होंने शाह बानो और उनके बच्चों को घर से निकाल दिया। तीन
कई वर्षों बाद, अप्रैल 1978 में, उन्होंने अदालत में एक याचिका दायर कर यह अनुरोध किया कि उनकी
पति आपराधिक अधिनियम की धारा 125 के तहत उसे भरण-पोषण का भुगतान करे प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)। धारा 125 सीआरपीसी को प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
धर्म की परवाह किए बिना किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, और यह
इसमें तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल थीं; इसने पति को अपने पति के प्रति जिम्मेदार बनाया।
विवाह के दौरान और तलाक के बाद भी, यदि पत्नी ऐसा करने में असमर्थ हो तो, पत्नी का कल्याण सुनिश्चित करना आवश्यक है।
अपना भरण-पोषण खुद करने के लिए। शाह बानो ने कहा कि उनके पति ने उन्हें एक निश्चित राशि का आश्वासन दिया था।
जब उसने उसे अपना घर छोड़ने के लिए कहा तो उसे हर महीने 200 रुपये देने पड़ते थे—लेकिन
उसने अपना वादा तोड़ दिया।
अदालत में याचिका दायर करने के छह महीने बाद, खान ने फैसला सुनाया।
उसने तीन बार तलाक दिया और उसे तलाक दे दिया। तलाक अपरिवर्तनीय था।
उसने कहा। इसलिए उसकी देखभाल करना या उसे भुगतान करना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी।
किसी भी भरण-पोषण के लिए। क्योंकि, उन्होंने तर्क दिया, भारत में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून
पति को केवल इद्दत की अवधि के लिए ही भरण-पोषण प्रदान करने की आवश्यकता थी।
तलाक के बाद की अवधि, जिसे इद्दत कहते हैं, तीन महीने की प्रथागत प्रतीक्षा अवधि

होती है।
तलाक के बाद की वह अवधि, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा निर्धारित है।
यह मामला सात साल तक चला। इंदौर की मजिस्ट्रेट अदालत में यह मामला चल रहा था।
अगस्त 1979 में फैसला सुनाया गया कि शाह बानो और उनके बच्चों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।
₹25 प्रति माह। एक उच्च न्यायालय—मध्य प्रदेश न्यायालय की जबलपुर बेंच।
प्रदेश उच्च न्यायालय ने राशि बढ़ाकर ₹179.20 प्रति माह कर दी है।
देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा।
राशि को अपरिवर्तित रखा गया। लेकिन इसने तर्क दिया—और यही कारण बना।
इस बात पर भारी विरोध हुआ कि पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना अनिवार्य है।
इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद, यदि वह अपना ख्याल रखने में असमर्थ हो।
न्यायालय
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) के तहत अपना फैसला सुनाया, जो कि नागरिक कानून है।
भूमि, जिसका व्यक्तिगत कानून से कोई लेना-देना नहीं था।
राजीव गांधी, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक क्रांतिकारी बदलाव के साथ प्रवेश किया था
आधुनिक, दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने शुरू में स्वागत किया
इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने संसद में बचाव किया।
राजीव गांधी ने अपने युवा मुस्लिम मंत्रियों में से एक, आरिफ मोहम्मद को मैदान में उतारा।
खान ने अदालत के फैसले का बचाव किया। लेकिन फिर उन पर दबाव बढ़ने लगा।
उस पर। इस फैसले से मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया।
रूढ़िवादी मुस्लिम नेताओं ने अदालत के फैसले को हस्तक्षेप के रूप में देखा।
अपने निजी कानून के साथ। वे प्रधानमंत्री से मिले और उनसे विनती की।
उन्हें नया कानून बनाकर फैसले को पलटने के लिए मजबूर किया गया। दबाव में आकर

उनसे और अपनी ही पार्टी के उन नेताओं से भी, जिन्हें हार का डर था।
मुस्लिम समर्थन मिलने पर राजीव ने अपना रुख बदल लिया। उन्होंने अपने विधिक कार्य को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
मंत्री अशोक कुमार सेन को एक विधेयक का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया है जो इस फैसले को पलट देगा।
शाह बानो का फैसला।
मुस्लिम महिला विधेयक में उचित और न्यायसंगत राशि की मांग की गई थी।
एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भुगतान किया गया, लेकिन इसका भुगतान तीनों के लिए करना पड़ा।
वे महीने जो इद्दत की अवधि का हिस्सा थे। उस अवधि के बाद, कोई भी
आगे और भुगतान करना आवश्यक था। (लेकिन इसमें एक पेंच था जिसे हम
(इस अध्याय में आगे इस पर चर्चा की जाएगी।)
प्रस्तावित विधेयक पर कई हिंदुओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इससे भी अधिक, उन्होंने राजीव गांधी के मुस्लिम दबाव के आगे झुकने पर आपत्ति जताई।
जिसे बाद में समुदाय को 'तुष्ट करने' के रूप में निंदा का सामना करना पड़ा।
हिंदू आक्रोश को शांत करने के लिए राजीव गांधी ने क्या कदम उठाया?
डी. पी. त्रिपाठी के अनुसार, यह एक विशिष्ट 'प्रबंधन समाधान' था।
इस समस्या का समाधान राजीव गांधी को उनके चचेरे भाई और सलाहकार अरुण नेहरू ने सुझाया था।
और वह उद्देश्य बाबरी मस्जिद के भीतर एक घेरा खोलना था ताकि अनुमति दी जा सके
हिंदू अपने देवता की असीमित पूजा करते हैं।
यह मस्जिद सोलहवीं शताब्दी में मुगलों द्वारा निर्मित की गई थी।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी, जो कि
संरचना को लेकर विवाद को रोकने के लिए इसे 1949 से बंद रखा गया है।
मामला बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने दावा किया कि मस्जिद का निर्माण उस स्थान पर किया गया था।
भगवान राम की जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को ध्वस्त करके उन्होंने उसे नष्ट कर दिया।
यह राम जन्मभूमि है. बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद

उन्नीसवीं शताब्दी से ही यह स्थिति समय-समय पर उफान मारती रही थी।
सदी। न तो राज के दौरान अंग्रेजों ने, न ही बाद की सरकारों ने।
स्वतंत्र भारत में, इस उलझन को सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली थी।
दिसंबर 1949 में, हिंदुओं के एक समूह ने चुपके से एक मूर्ति स्थापित की।
उन्होंने आधी रात को मस्जिद के अंदर राम लल्ला (बाल राम) की मूर्ति स्थापित की—
ताकि वे पूजा स्थल पर अपने दावे को मजबूत कर सकें।
प्रशासन ने इमारत को बंद कर दिया। लेकिन अदालत के फैसले ने इसकी अनुमति दे दी।
हिंदू एक बंद ग्रिल के पीछे से मूर्ति की पूजा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने
बाबरी मस्जिद के ताले खोलने की मांग की जा रही है ताकि हिंदू अंदर जा सकें।
अपने देवता की निर्बाध पूजा।
राजीव गांधी ने सोचा था कि मुस्लिम महिला विधेयक पारित हो जाएगा।
मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, और ग्रिल पर लगे तालों को खोलने से
हिंदुओं को प्रसन्न करो।
त्रिपाठी ने कहा, 'यही राजीव गांधी की सोच का सार था।'
लेकिन मुसलमानों और हिंदुओं को खुश करने के बजाय, राजीव का अंत इस तरह हुआ कि
दोनों समुदायों को अलग-थलग कर दिया। सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा।
ऊपर।
शाह बानो मामले पर राजीव की प्रतिक्रिया इस मामले को और बढ़ावा देना था।
राजनीति का हिंदूकरण—और इसके परिणामस्वरूप भाजपा का उदय हुआ।
तीन साल बाद, 1989 के आम चुनावों में,
कांग्रेस को दोहरी मार झेलनी पड़ी। राजीव गांधी का प्रभावशाली प्रदर्शन
संसद में बहुमत 414 से घटकर 197 हो गया। उनकी अपनी वित्तीय स्थिति
मंत्री वी. पी. सिंह, जिन्होंने राजीव गांधी से कुछ मुद्दों पर मतभेद रखा था।
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग अगली सरकार बनाएंगे और सत्ता संभालेंगे।
प्रधानमंत्री के रूप में (जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे)। कांग्रेस
उस सदमे से वह कभी उबर नहीं पाई। उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया।

उसके बाद किसी भी राष्ट्रीय चुनाव में। शाह बानो के फैसले ने स्थिति बदल दी।
भारतीय राजनीति के विशाल द्वार का छोटा केंद्र बिंदु बनने जा रहा है
इसके बाद तीन दशकों तक यह सिलसिला जारी रहा।

द्वितीय

31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी के लिए दिन की शुरुआत जल्दी हुई। यह एक ऐसा दिन था
जिससे उनका जीवन बदल जाने वाला था। वह पश्चिम में चुनाव प्रचार कर रहे थे।
बंगाल। गुटबाजी से ग्रस्त कांग्रेस ने समय से पहले ही चुनावी माहौल में प्रवेश कर लिया था।
हालांकि आम चुनाव में अभी कई सप्ताह बाकी थे। सुबह 9 बजे तक, वह
प्रणब मुखर्जी कोंटाई में अपनी दूसरी सभा को संबोधित कर रहे हैं।
वह मंच पर उनके बगल में बैठे थे; वह पश्चिम बंगाल से थे और
इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री। अचानक, बीच में
राजीव के भाषण के दौरान, मुखर्जी ने उन्हें एक पर्ची थमा दी। उस पर्ची में उनसे कुछ अंश काटने के लिए कहा गया था।
राजीव ने अपना भाषण संक्षिप्त कर दिया। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए, राजीव ने अपना भाषण समाप्त कर दिया।
जल्दी से बोलो। मुखर्जी ने उसे आया हुआ संदेश दिखाया।
दिल्ली से पुलिस वायरलेस के जरिए संदेश आया, 'इंदिरा गांधी पर हमला हुआ, वापस लौटें।'
'तुरंत दिल्ली पहुंचो।' उसके दो सुरक्षा गार्ड, दोनों सिख, ने उस सुबह 9:10 बजे उसे बेहद करीब से गोली मार दी थी। वह
वह बगल वाले अपने आवास से चलकर अपने कार्यालय तक जाती है।
दस मिनट के भीतर राजीव और मुखर्जी कोंटाई से निकल गए। राजीव ने अपना सामान शिफ्ट किया।
उनकी एम्बेसडर कार से लेकर घनी खान चौधरी की मर्सिडीज तक।
बड़ी कार से वे तेज़ी से आगे बढ़ सकते थे। राजीव गाड़ी चलाना चाहता था।
स्वयं तो गाड़ी चलाने का मन हुआ, लेकिन उन्हें गाड़ी चलाने से मना कर दिया गया।
मुखर्जी की तरह,

रेल मंत्री चौधरी भी राजीव गांधी के साथ यात्रा पर गए थे।
राजीव सबसे आगे बैठा था, और नवीनतम समाचार सुनने के लिए उसके कान से ट्रांजिस्टर चिपका हुआ था।
जानकारी। इंदिरा गांधी के शरीर में सोलह गोलियां मारी गई थीं।
बीबीसी ने पूछा, 'वीआईपी सुरक्षाकर्मियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां कितनी शक्तिशाली होती हैं?'
चिंतित राजीव ने अपने निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) से पूछा, जो वहां बैठा था।
गाड़ी की पिछली सीट पर दो मंत्री बैठे थे। वे शक्तिशाली थे, पीएसओ के सदस्य।
जवाब दिया। 'क्या वह इन सभी गोलियों की हकदार थी?' राजीव ने कहा,
यह सवाल किसी से नहीं पूछा जाना चाहिए।
यात्रा के दौरान उनमें से किसी ने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि...
यह हत्या इंदिरा गांधी के उस फैसले का बदला थी जिसमें उन्होंने अपने बेटे को भेजने का निर्णय लिया था।
1 जून 1984 को सेना ने जरनैल सिंह को समाप्त करने के लिए स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया।
भिंडरांवाले। सिख उग्रवादी ने एक पवित्र सिख मंदिर में छुपकर शरण ली थी।
यह तीर्थस्थल एक अलग सिख राष्ट्र के निर्माण का उपदेश देता है।
सड़कों की खराब हालत को देखते हुए राजीव को पहुंचने में दो घंटे लग गए।
कोलाघाट का हेलीपैड। एक हेलीकॉप्टर उन्हें आगे ले जाने के लिए इंतजार कर रहा था।
वे कलकत्ता में उतरे और उन्हें सीधे एक विशेष भारतीय अस्पताल में ले जाया गया।
एयरलाइंस की उड़ान। यह तुरंत उड़ान भर गई।
जहाज पर उन्हें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें दिल्ली से खबर मिली थी;
इनमें पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल उमा शंकर दीक्षित और उनके सहयोगी शामिल थे।
बहू शीला दीक्षित और लोकसभा अध्यक्ष बलराम
Jakhar.
टेक-ऑफ के तुरंत बाद, राजीव कॉकपिट में चले गए। कुछ मिनट बाद,

वह बाहर आया और स्पष्ट रूप से बोला, 'वह मर चुकी है।'
विमान में सन्नाटा छा गया। राजीव वहीं रुका रहा।
बाहर से शांत दिखते हुए। वह वापस कॉकपिट में चले गए और अपना अधिकांश समय वहीं बिताया।
वहां समय बिताने के लिए ताकि नवीनतम समाचार प्राप्त कर सकें।
सदमे का असर कम होने के बाद, विमान में सवार लोग धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में पहुँचने लगे।
अब जो व्यवस्थाएं करनी होंगी, उन पर चर्चा करें। मैंने उद्धृत किया
मुखर्जी ने बाद में लिखा, 'पूर्व उदाहरणों के अनुसार, जब से प्रधान मंत्री पद पर कार्यरत थे,
मंत्री नेहरू और बाद में शास्त्री जी का कार्यकाल समाप्त हो गया... दोनों ही मामलों में गुलज़ारी लाल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
वरिष्ठतम मंत्री नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया।
मुखर्जी के इन शब्दों को सत्ता हथियाने की उनकी कोशिश के रूप में देखा गया।
अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने यह भी जोड़ा था कि नेहरू और शास्त्री की मृत्यु स्वाभाविक थी, इंदिरा गांधी की मृत्यु...
हत्या ने एक 'असाधारण स्थिति' उत्पन्न कर दी थी। इसलिए उपस्थित लोगों ने
प्रणब ने फैसला किया कि राजीव को अपनी मां की विरासत संभालनी चाहिए।
मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने राजीव को विमान के पिछले हिस्से में ले जाकर उनसे आग्रह किया।
प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए।
'क्या आपको लगता है कि मैं यह कर पाऊंगा?' राजीव ने अनिश्चितता से उससे पूछा था।
'हां...हम सब आपकी मदद के लिए मौजूद हैं,' मुखर्जी ने उन्हें आश्वस्त किया।
हालांकि, राजीव गांधी की इस घटना के बारे में अलग राय थी।
उन घंटों में।
1986 में एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि उस समय क्या हुआ था।
उस दिन विमान में बैठे व्यक्ति ने—यह सवाल उठाया था कि क्या मुखर्जी ने प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश किया था।

राजीव ने जवाब दिया, 'हम इस बारे में बात नहीं कर सकते थे। मुझे नहीं पता।'
उसने दूसरों से किस बारे में बात की।
विमान दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली में उतरा। अधिकारियों के साथ-साथ विमान भी मौजूद था।
कैबिनेट सचिव कृष्णास्वामी राव साहब के नेतृत्व में, जो आए थे
राजीव का स्वागत करने के लिए, बेचैन अरुण नेहरू अपने चचेरे भाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
उसने झटपट राजीव को अपनी कार में बिठाया और ऑल इंडिया की ओर तेज़ी से निकल पड़ा।
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एआईएमएस), जहां इंदिरा गांधी की बुलेट-
शरीर पर कई घावों के निशान थे।
इंदिरा गांधी को गोली लगने के बाद, उन्हें उनके परिवार द्वारा तुरंत एम्स ले जाया गया था।
उनकी बहू सोनिया गांधी और उनके निजी साथी आर.के. धवन।
अरुण नेहरू ने उनके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी।
उन्हें सुबह ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। कांग्रेस को इस घटना से गहरा सदमा लगा।
मंत्री, मुख्यमंत्री और पार्टी नेता अस्पताल पहुंचे।
मैंने उनमें से प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप से और छोटे समूहों में बात की।
ऑपरेशन थिएटर के बाहर आठवीं मंजिल पर गलियारे में इंतजार कर रहा था।
उन्होंने राजीव का नाम अपनी मां के उत्तराधिकारी के रूप में सुझाया। राजीव को ऐसा लगा जैसे...
यह स्वाभाविक और गैर-विवादास्पद विकल्प होगा। कांग्रेस नेताओं
आसानी से सहमत हो गया। अरुण नेहरू केवल पार्टी के सांसद थे, हालांकि
राजीव का तीसरा चचेरा भाई। लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने उसे व्यायाम करते देखा था।
इंदिरा गांधी के प्रधान शासनकाल के वर्षों में अपार अधिकार
1980 के बाद मंत्री।
अपने विशिष्ट और आक्रामक अंदाज में अरुण नेहरू ने 31 तारीख को कार्यभार संभाला।

अक्टूबर 1984। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह राजीव ही हो, प्रणब नहीं।
मुखर्जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने
जानता था, उसे हटाना मुश्किल होगा, खासकर अगर वह कोई ऐसा व्यक्ति हो।
मुखर्जी जैसी सूझबूझ, और वह भी तब जब इंदिरा गांधी अब जीवित नहीं थीं।
उस पर नज़र रखने के लिए आसपास तैनात। उसे पता था कि उसका चचेरा भाई इसे ढूंढ लेगा।
नए इलाके में रास्ता खोजना मुश्किल होगा और मदद की जरूरत होगी। कोई भी नहीं।
उस दोपहर नेहरू की भूमिका पर सवाल उठाए गए।
इन बातचीत के दौरान अरुण नेहरू ने
कई कांग्रेसी नेताओं को इस बात पर यकीन हो गया कि उपराष्ट्रपति, आर.
वेंकटरमन को राजीव गांधी को तुरंत शपथ दिला देनी चाहिए थी; उन्होंने ऐसा कर दिया।
राष्ट्रपति जैल सिंह के राजधानी लौटने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
अरुण नेहरू विदेश में थे और दिल्ली वापस आने की जल्दी में थे।
इस आशंका से कि ज्ञानी ज़ैल सिंह, जिनके साथ इंदिरा गांधी के संबंध थे,
एक कठिन रिश्ते में प्रणब मुखर्जी को शपथ दिलाने पर जोर दिया जा सकता है।
प्रधानमंत्री के रूप में। आखिरकार, वे श्रीमती गांधी के मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर के अधिकारी थे। और,
जैसा कि मुखर्जी ने बताया था, इस संख्या के पहले भी उदाहरण मौजूद थे।
जवाहरलाल नेहरू और लाल नेहरू की मृत्यु के बाद दो लोगों ने शपथ ली।
बहादुर शास्त्री। सीपीपी ने राजीव को नेता चुनने के लिए बैठक नहीं की थी। न ही
इतने कम समय में बैठक करना संभव है। नेहरू को संदेह था कि
मुखर्जी के पास राजीव को मात देने की एक सुनियोजित योजना थी।
अरुण नेहरू ज्ञानी ज़ैली सिंह को अच्छी तरह जानते थे। उनके शामिल होने के कुछ ही समय बाद
1980 में राजनीति में, उन्होंने ज़ैल सिंह के साथ सहयोग किया था, जो उस समय गृह मंत्री थे।
पंजाब में राजनीतिक अशांति के शुरुआती महीनों में मंत्री। दोनों

वे पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को हटाना चाहते थे, और
पंजाब की प्रभावशाली सिख-बहुल पार्टी अकाली दल को पीछे छोड़ते हुए।
हालांकि इंदिरा गांधी ने 1982 में जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया था,
उन्होंने पी.वी. नरसिम्हा राव की तुलना में उन्हें प्राथमिकता दी, जिन पर उन्होंने विचार किया था।
राष्ट्रपति भवन के लिए, ज़ैल सिंह के साथ उनके संबंध खराब हो गए थे।
पंजाब में संकट का बढ़ना। वह छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देने लगता था, जैसे
औपचारिक 'देखभाल' के दौरान जानबूझकर उसे हवाई अड्डे पर इंतजार कराना-
'ऑफ्स'—जब प्रधानमंत्री के उपस्थित रहने की उम्मीद थी
राष्ट्रपति ने शहर छोड़ दिया था या वे किसी आधिकारिक दौरे के बाद दिल्ली लौट आए थे।
इंदिरा गांधी के चले जाने के बाद, यह कहना मुश्किल था कि आगे क्या होगा।
राष्ट्रपति ऐसा कर सकते थे। नेहरू इस स्तर पर किसी भी प्रकार की चूक का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे।
इंदिरा गांधी के शव वाले कमरे में अपने चचेरे भाई को छोड़कर,
अरुण नेहरू इंदिरा गांधी के शक्तिशाली प्रधान सचिव पी.सी. अलेक्जेंडर से गुप्त रूप से बात करने के लिए बाहर आए।
अलेक्जेंडर ने अधीर नेहरू की बात ध्यान से सुनी, जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि इसकी आवश्यकता है।
नेहरू ने कहा, 'राजीव को तुरंत प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएं। कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता।'
उसे। अगर राष्ट्रपति ने मना कर दिया तो जिम्मेदारी कौन लेगा?
"राजीव को शपथ दिलाओ," उसने अनिश्चित अलेक्जेंडर से पूछा।
एक नौकरशाह के रूप में, अलेक्जेंडर नेहरू के कार्यों के बारे में इतना आश्वस्त नहीं था।
वह शादी का प्रस्ताव रख रहा था। ऐसे में वह खुद को एक असाधारण परिस्थिति में फंसा हुआ पाया।
तकनीकी रूप से देखा जाए तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के साथ ही अलेक्जेंडर भी
वह अब प्रधान सचिव नहीं रहीं जो उनके बारे में निर्णय ले सकती थीं

उनकी ओर से। उन्हें इस कदम की वैधता को लेकर भी चिंता थी। ज़ैल सिंह
आखिरकार उन्होंने अपना अधिकार उपराष्ट्रपति को नहीं सौंपा था।
राष्ट्रपति चाहें तो इस कदम को असंवैधानिक बताकर चुनौती दे सकते हैं।
अलेक्जेंडर ने नेहरू से कहा कि वह राजीव से सलाह लेंगे।
नेहरू उस प्रतीक्षालय की ओर बढ़ने लगे, जहाँ राजीव गए थे।
सोनिया से बात करने के लिए। उसने कहा कि वह जाकर अपने चचेरे भाई से बात करेगा। लेकिन
इससे पहले कि भारी-भरकम नेहरू हिल पाते, लंबे और फुर्तीले अलेक्जेंडर ने
वह उससे पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। वह उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ राजीव खड़ा था।
सोनिया। उसने सोनिया को अपने पति से विनती करते सुना कि वह यह कदम न उठाए।
प्रधानमंत्री पद।
उसे डर था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। राजीव ने उसके माथे पर चुंबन किया और
उसने कहा कि उसके पास 'कोई विकल्प नहीं था...उसे वैसे भी मार दिया जाता'।
अलेक्जेंडर ने राजीव के कंधे पर थपथपाया। राजीव ने खुद को उससे अलग कर लिया।
सोनिया की बाहों से। वह अलेक्जेंडर के पीछे बाथरूम में गया। यह है
वहाँ प्रधान सचिव ने राजीव से दबे स्वर में बात की। राजीव
उन्होंने अलेक्जेंडर की बातों को ध्यान से सुना। वे इस बात से सहमत थे कि वे
राष्ट्रपति के लौटने का इंतजार करना चाहिए।
अब शाम के 4 बज चुके थे। देश पहले से ही नेतृत्वहीन था।
छह घंटे। इंदिरा गांधी के प्रति आक्रोश बढ़ने की खबरें थीं।
हत्या; स्थिति बेहद खतरनाक थी। जवाहरलाल के बाद
27 मई 1964 को नेहरू की मृत्यु के बाद, एक अंतरिम प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी।
दो घंटे। नेहरू का निधन दोपहर 2 बजे हुआ था और गुलज़ारी लाल नंदा अस्पताल में थे।
शाम 4 बजे तक उस स्थान पर। जब शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को

ताशकेंट में हुआ,
रात 1.32 बजे (भारतीय समयानुसार 2.02 बजे) से लेकर सुबह 3.15 बजे तक गुलजारी लाल नंदा ने अपनी जान गंवा दी थी।
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ।
कलकत्ता से विमान में सवार होते हुए, और जटिलता का एहसास करते हुए
अब उनके सामने जो स्थिति थी, प्रणब मुखर्जी ने
उन्होंने राजीव गांधी को दिल्ली को यह संदेश देने के लिए राजी किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा तब तक न की जाए जब तक कि नई सरकार सत्ता में न आ जाए।
सरकार ने कार्यभार संभाल लिया था। दिल्ली की ओर से, उपराष्ट्रपति
वेंकटरमन ने भी कांग्रेस के समक्ष यही विचार व्यक्त किया था।
अस्पताल में मौजूद नेता। वेंकटरामन और मुखर्जी दोनों।
वे अनुभवी राजनेता थे जो भविष्य का अनुमान लगा सकते थे और आने वाली समस्याओं को पहले से ही भांप सकते थे।
■

प्रणब मुखर्जी राजीव के दस मिनट बाद अस्पताल पहुंचे।
गांधी। कुछ ही मिनटों में उन्हें एहसास हुआ कि कांग्रेस के अधिकांश नेता
उनके अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के खिलाफ लोग थे। जब अलेक्जेंडर
मैंने उनसे अरुण नेहरू के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रशासन चलाने के विचार के बारे में पूछा।
राजीव को पद की शपथ दिलाने के बजाय, मुखर्जी ने सुझाव दिया कि इसके बजाय...
कांग्रेस संसदीय बोर्ड (सीपीबी) को तत्काल बुलाया जाना चाहिए।
सीपीबी, जो पार्टी की सर्वोच्च नीति-निर्माण संस्था सीडब्ल्यूसी का एक उपसमूह है,
क्योंकि सीपीपी को चुनाव के लिए बुलाने का समय नहीं था, इसलिए कोई राय नहीं बना सका।
नेता। सीपीपी बाद में सीपीबी के फैसले की पुष्टि कर सकती है।
उस दिन शाम 5 बजे सीपीबी की बैठक हुई। एम्स से मुखर्जी और

नरसिम्हा राव—जो तब तक अस्पताल पहुँच चुके थे—वहाँ से चले गए।
1, अकबर रोड, इंदिरा गांधी का कार्यालय, उनके आवास के बगल में स्थित है।
सफदरजंग रोड।
वाहनों की भीड़ में मुखर्जी अपनी कार नहीं ढूंढ पाए।
एम्स। अरुण नेहरू उन्हें 1, अकबर रोड तक ले गए और फिर जल्दी से रवाना हो गए।
राष्ट्रपति के स्वागत के लिए हवाई अड्डा।
नेहरू ने राष्ट्रपति जैल सिंह के कान में जो भी मंत्र फुसफुसाया हो।
उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम को जब वह उसे एम्स ले जा रहा था, तब उसने
यह अनुमान लगाया गया था—और ज़ैल सिंह भी इससे सहमत होते—कि यह होगा
किसी भी अन्य पदाधिकारी की तुलना में भरोसेमंद राजीव को नियंत्रित करना आसान है।
आठ सदस्यीय सीपीबी में दो पद रिक्त थे। इनमें से छह में से...
इंदिरा गांधी, समिति की पदेन सदस्य के रूप में, नेता थीं।
लोकसभा में पार्टी के सदस्य और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका निधन हो चुका था।
members, Maragatham Chandrasekar and Kamlapati Tripathi were
शहर से बाहर। यह जिम्मेदारी शेष दो सदस्यों, नरसिम्हा राव, पर छोड़ दी गई थी।
जो गृह मंत्री थे, और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी।
निर्णय लें।
उन्होंने प्रस्ताव पारित करने की औपचारिकता पूरी की—कि
राजीव गांधी को सीपीपी का नेता चुना गया। सीडब्ल्यूसी के सचिव जी. के. मूपानार ने अध्यक्ष को एक औपचारिक पत्र लिखकर बताया कि राजीव गांधी को सीपीपी का नेता चुना गया है।
गांधी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। यह निर्णय लिया गया कि सभी
वे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए।
उस दिन मुखर्जी की भूमिका एक गहन विवाद का विषय बनने वाली थी।
इसके बाद के महीनों में विवाद हुआ; इसे उनके खिलाफ तब तक इस्तेमाल किया गया जब तक कि...

अंत में, मुखर्जी ने एक बंगाली पत्रकार को गोपनीय रूप से बताया—जो
उसने मुझे बताया कि उसे शक था कि पी.वी. नरसिम्हा राव ही यह बात फैला रहे थे।
यह अफवाह है कि मुखर्जी अंतरिम प्रधानमंत्री बनना चाहते थे।
■

31 अक्टूबर 1984 को दोपहर के कुछ ही समय बाद, हमें यह स्पष्ट हो गया था कि
इंदिरा गांधी के निधन की खबर देने के लिए मीडिया घटनास्थल पर मौजूद थी। मेरी
उनसे अचानक मुलाकात हो गई थी।
मेरे परिचित एक डॉक्टर, डॉ. उर्मिल शर्मा, ने आठवीं मंजिल पर जाने की पेशकश
की।
और मेरे लिए पता लगाओ कि क्या हो रहा था। जब वह नीचे आई, तो उसने
उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। हम चुपचाप उसके पास चले गए।
कैंपस में स्थित आवास। जैसे ही हम अंदर गए, उसने कहा...
दबी हुई आवाज़ में, 'सब खत्म हो गया।' बाद में, मैंने अस्पताल में सुना कि बीबीसी ने
यह खबर प्रसारित की थी।
दोपहर 2 बजे के ठीक बाद उनकी मृत्यु की घोषणा की गई थी। सरकार ने एक
विज्ञप्ति जारी की थी।
प्रधानमंत्री पर हुए हमले पर कोई बयान नहीं।
शाम 5 बजे, एकत्रित मीडियाकर्मियों ने अरुण नेहरू को पहुंचते हुए देखा।
जैल सिंह के साथ एम्स। राष्ट्रपति की कार के गेट में प्रवेश करने से पहले,
बाहर अफरा-तफरी मची हुई थी। तब तक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे।
वहाँ। बाद में हमें पता चला कि सिंह की कार पर गुस्से में आए लोगों ने पथराव किया
था।
प्रदर्शनकारियों ने सिखों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। यह बात फैल चुकी थी
कि
इंदिरा गांधी को उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मार दी थी—यह घटना एक पूर्ववर्ती
घटना का संकेत थी।
जल्द ही शहर में हिंसक सिख विरोधी दंगे भड़क उठेंगे। सिंह का

ड्राइवर अस्पताल परिसर में तेज गति से गाड़ी चलाने में कामयाब रहा। लेकिन राष्ट्रपति का
सचिव तरलोचन सिंह, जिनकी कार राष्ट्रपति की कार के पीछे चल रही थी।
वाहन चालक इतना भाग्यशाली नहीं था; उसके वाहन का विंडशील्ड टूट गया था।
चकनाचूर हो गया। उसे अपना रास्ता बदलकर राष्ट्रपति की ओर भागना पड़ा।
भवन।
अस्पताल की आठवीं मंजिल पर राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया।
राजीव गांधी के साथ। राजीव के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने पूछा,
'Chalaen (Shall we go)?'
'कहाँ?' राजीव ने पूछा।
'शपथ ग्रहण करने के लिए,' जैल सिंह ने कहा।
'मैं घर जाकर कपड़े बदलूंगा और फिर आपके पास आऊंगा,' राजीव ने जवाब दिया।
बाद में, ज़ैल सिंह ने पंजाब के राजनेताओं के एक समूह से कहा, 'उस दिन,
जब मैंने राजीव को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, तो मैंने सभी बकाया राशि वापस कर दी।
ehsaans (favours) Indira Gandhi had done me.'
■

थके-हारे और जेट लैग से ग्रस्त राष्ट्रपति ने ही राजीव गांधी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी।
भारत के छठे प्रधानमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह 31 तारीख को शाम 6.45 बजे हुआ।
अक्टूबर 1984। समारोह में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी।
राष्ट्रपति भवन में झूमर से सुसज्जित अशोक हॉल।
एक तरफ अधिकारी खड़े थे—प्रधान सचिव पी.सी.
अलेक्जेंडर, कैबिनेट सचिव कृष्णास्वामी राव साहब, गृह
सचिव एम. एम. के. वली और राष्ट्रपति के सचिव ए. सी.
बंद्योपाध्याय—उनके सिर झुके हुए थे। दूसरी ओर चारों बैठे थे।
गंभीर दिखने वाले नेता जिन्हें राजीव गांधी के साथ शपथ लेनी थी

—Pranab Mukherjee, P. V. Narasimha Rao, Shiv Shankar, and Buta
सिंह। राजीव गांधी ने बूटा सिंह का नाम मंत्रियों की सूची में जोड़ा था।
राष्ट्रपति भवन पहुंचने के ठीक बाद, आखिरी मिनट में मुखर्जी ने कहा था कि...
उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को दलित सिख बूटा सिंह को शामिल करने की सलाह दी।
सिखों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, श्रीमती गांधी के बाद
उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या। राष्ट्रपति ने शुरुआत की
शहीद नेता की याद में दो मिनट का मौन रखा गया।
राजीव की आवाज कांप रही थी जब उसने पद और गोपनीयता की शपथ पढ़ी, 'मैं,
राजीव गांधी, कृपया पूर्णतः प्रतिज्ञा करें...
शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही मिनट बाद, राजीव गांधी के मंत्रिमंडल ने
नए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसकी पहली बैठक हुई।
राष्ट्रपति भवन में एक स्थान। शोक प्रस्ताव पारित होने के बाद, जिसमें आह्वान किया गया था कि
'शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता' के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने अंतिम रूप दिया।
इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। यह निर्णय लिया गया कि उनके शरीर को
शव को तीन दिनों तक तीन मूर्ति हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।
यह आयोजन 3 नवंबर 1984 को होगा।
इन सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही राष्ट्रपति ने
भवन भवन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें औपचारिक रूप से इंदिरा गांधी की घोषणा की गई।
मृत्यु। उपराष्ट्रपति वेंकटरमन ने सार्वजनिक दूरसंचार चैनल को बताया।
दूरदर्शन ने बताया कि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने
हावी हो गया।
राजीव अब अपनी मां का शव लेकर एम्स वापस जाने के लिए तेजी से रवाना हुआ।

परिवार द्वारा उन्हें शांतिपूर्ण विदाई देने के लिए रात भर सफदरजंग रोड पर रखा गया।
विदाई। अगली सुबह इसे तीन मूर्ति हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया जहाँ
उनके पिता भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर चुके थे और वह उनकी पूर्व प्रधानमंत्री थीं।
आधिकारिक मेजबान।
इसके बाद के घंटों में, राजीव ने टीम को बरकरार रखने का फैसला किया।
इंदिरा गांधी के मंत्रियों और अधिकारियों में प्रणब मुखर्जी भी शामिल रहे।
वित्त मंत्री और नरसिम्हा राव ने गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो अपने पास बरकरार रखा।
■

पी.वी. नरसिम्हा राव 1 तारीख से नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय के लिए रवाना हुए थे।
अकबर रोड पर, राजीव को निर्वाचित करने वाले सीपीबी प्रस्ताव को पारित करने के बाद
संसदीय दल के नेता। शाम लगभग 6 बजे उनका फोन बजा।
क्या अरुण नेहरू फोन पर थे? हमें खुफिया रिपोर्ट मिली हैं कि
अरुण नेहरू ने कहा, 'कल शहर में व्यापक हिंसा होगी।'
राव के जीवनीकार विनय सीतापति के अनुसार, राव ने उन्हें यह बात बताई थी।
उन्होंने घर को बताया, 'हमें समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करनी होगी।'
मंत्री जी ने कहा, ‘यह बेहतर होगा यदि एक ही नोडल प्राधिकरण इस मामले को संभाले।’
स्थिति।' गृह मंत्री के रूप में, दिल्ली पुलिस सीधे राव के अधीन थी।
दिल्ली में भी कानून व्यवस्था वैसी ही थी, जो एक केंद्र शासित प्रदेश था।
आगे क्या होने वाला है, यह जानते हुए राव ने नेहरू की बातें ध्यान से सुनीं।
उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा। नेहरू ने राव को बताया कि पीएमओ
अब दिल्ली की स्थिति को राव संभालेंगे—दूसरे शब्दों में कहें तो राव को
गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दें, जहां तक घटनाक्रम के बाद की स्थिति से निपटने

की बात है।
इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर चिंता थी। उन्होंने राव से आगे भेजने को कहा।
प्रधानमंत्री कार्यालय को गृह मंत्रालय में आने वाली सभी जानकारी भेजी जाती है।
शहर में शुरू हुई सिख विरोधी हिंसा। 'पीएमओ करेगा
उन्होंने राव को निर्देश दिया, 'हिंसा के खिलाफ एक समन्वित प्रतिक्रिया दें।'
संदेश स्पष्ट था—अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) यह जिम्मेदारी संभालेगा, न कि गृह मंत्रालय।
मैनेजर बनना।
जब राव बोल रहे थे तब कमरे में एक अधिकारी मौजूद था।
नेहरू। वह राव के भरोसेमंद सहयोगी थे। राव ने बाद में सहयोगी को बताया कि क्या हुआ था।
नेहरू ने उनसे फोन पर यह बात कही थी, जिसके बाद उस अधिकारी ने बताया कि यह बातचीत उनके साथ हुई थी।
सीतापति से संबंधित। मैंने एक अन्य अधिकारी से भी इसकी पुष्टि की।
'मुझे इसकी जानकारी थी और मैंने उन दिनों राव के साथ काम किया था,' उन्होंने याद किया।
मुझे यह नहीं मिलेगा।
इसके बाद के घंटों में, सिखों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी।
दिल्ली और उत्तरी भारत के बड़े हिस्से; यह स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई।
अगले तीन दिनों तक।
उन घंटों के दौरान आक्रोशित नागरिकों के समूहों ने राव से मुलाकात की—इनमें से उनमें आई. के. गुजराल भी शामिल थे, जो उस समय कांग्रेस के नेता थे और बाद में प्रधानमंत्री बने।
मंत्री, जनरल जे. एस. अरोरा, जो जनरल अधिकारी रह चुके थे
1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी कमान के कमांडिंग-इन-चीफ।
पाकिस्तान और अर्जन सिंह, जिन्होंने 1965 के युद्ध में वायु सेना का नेतृत्व किया था।
पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने गृह मंत्री से सेना तैनात करने की गुहार लगाई।
सेना को तुरंत बुलाओ।

हत्या के अगले दिन, इंदिरा गांधी की उत्तेजित समर्थक पुपुल जयकर ने कहा,
करीबी दोस्त ने राव को फोन किया। उसे बताया गया कि वह प्रधानमंत्री के साथ हैं।
मैं सीधे सफदरजंग रोड स्थित नंबर 1 पर गया और वहां राव को राजीव के साथ बैठा पाया।
उन्होंने प्रधानमंत्री को उन फोन कॉल्स के बारे में बताया जो उन्हें आ रही थीं।
सिख महिलाओं की जघन्य हत्याएं और बलात्कार हो रहे थे।
राजीव असमंजस में दिख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे।
जयकर
राजीव से आग्रह किया कि वे तुरंत सेना को बुलाकर व्यवस्था बहाल करें।
राव की ओर मुड़कर उनसे पूछा कि क्या सेना को तैनात किया जाना चाहिए। राव
वह चुप रही। फिर राजीव ने जयकर से कहा कि वह जो कुछ भी कहे उसे लिखित में दे।
उसने उसे बताया था और उसे तुरंत भेज दिया था—जो उसने किया भी। लेकिन सेना
तैनात नहीं किया गया और हत्याएं जारी रहीं।
जब अरुण नेहरू ने 31 तारीख को शाम 6 बजे नरसिम्हा राव को फोन किया था
अक्टूबर में, देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं था, जबकि हिंसा जारी थी।
राजधानी को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। भले ही नेहरू निर्देश दे रहे थे...
राजीव गांधी के कहने पर राव ने यह कदम उठाया, यह घटना राजीव गांधी के कहने
पर हुई थी, इससे पहले कि राजीव गांधी ने 45 मिनट का समय लिया।
राव ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया था। तब तक राव भारत के गृह मंत्री थे।
दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार, विशेष रूप से
प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, वे सेना को बुला सकते थे। राव
उन्होंने कोई कार्रवाई न करने का विकल्प चुना।
हालांकि राव को इस बात का अंदाजा था कि इंदिरा गांधी क्या सोचतीं।
सीतापति ने कहा कि एक स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रधानमंत्री के रूप में राजीव 'एक थे'
राव को यकीन नहीं था कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा।
क्या उन्हें पता था कि नेहरू द्वारा उन्हें दिए गए निर्देश को राजीव गांधी का समर्थन प्राप्त था या नहीं?

उन्हें इतना जरूर पता था कि नेहरू शक्तिशाली थे। उन्होंने देखा था कि
इंदिरा के जीवित रहते हुए उन्होंने जो प्रभाव डाला था। कुछ घंटे पहले ही उन्होंने
मैंने एम्स में उन्हें स्थिति को अपने नियंत्रण में लेते हुए देखा।
उनके चचेरे भाई राजीव ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
उस समय राव की चिंता यही रही होगी कि आगे क्या होगा।
'अगर वह मंत्री बन जाए तो सिखों पर हमले के बाद क्या होगा, इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि उसे मंत्री बनाया जाए।'
सीतापति ने कहा। चतुर राव को शायद इस बात से राहत मिली होगी कि नेहरू का...
उन्हें किए गए एक फोन कॉल ने उन्हें गृह मंत्री के पद से मुक्त कर दिया था।
बढ़ते संकट के बीच। जंगल के कानूनों से कठोर हो चुका।
राजनीति में काम करते हुए, राव ने जल्दी ही सीख लिया था कि जब तूफान आता है,
हिलती हुई घास की पत्ती बच गई। लेकिन एक पेड़ सीधा खड़ा रहा।
दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
सीतापति ने कहा, 'यह उसका सबसे घिनौना क्षण था।'
जैसा कि बाद में पता चला, एक के बाद एक आयोगों ने जांच की
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी नरसंहारों में दोषमुक्त
राव की हिंसा में किसी भी भूमिका की आशंका नहीं जताई गई। इसके लिए राजीव गांधी को दोषी ठहराया गया।
1984 में सिखों के क्रूर नरसंहार के लिए किसी को याद तक नहीं था।
उस समय भारत के गृह मंत्री कौन थे?
■

31 अक्टूबर की शाम को जब अरुण नेहरू की कार एम्स से निकली
1984 में, उन्होंने भीड़ में स्थानीय कांग्रेस नेता अर्जुन दास को देखा। उन्होंने
out his head and yelled at him, ‘Choorhiya pehen rakhi hain kya? Maa
को मारा है (क्या तुमने चूड़ियाँ पहनी हैं? तुम्हारी माँ की हत्या की जा रही है)।
दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य दास, उनके करीबी सहयोगी थे।

संजय गांधी के सहयोगी। बाद में एक नागरिक सुरक्षा रिपोर्ट में उनका नाम सामने आया।
नागरिक स्वतंत्रता समूह (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज) को उकसाने वाले के रूप में
सिखों के खिलाफ हिंसा के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था और 1985 में रहस्यमय तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी।
जब वह अपनी कार में था, तब स्वचालित हथियारों से लैस दो बंदूकधारियों ने उस पर हमला कर दिया।
पुर्जों की दुकान।
जैसे ही दिल्ली में रात छा गई, इंदिरा गांधी के पार्थिव शरीर को ले जाया गया।
उनके निवास स्थान पर, शहर के विभिन्न हिस्सों में बैठकें आयोजित की गईं।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने कथित तौर पर अपने समर्थकों को लामबंद किया और
उन्हें पूरे शहर में फैलने के लिए कहा गया; हत्यारी भीड़ें थीं
वे केरोसिन, चाकू और टायरों से लैस थे। उन्हें मतदाता सूचियाँ भी दी गई थीं।
सिखों के निवास स्थानों को इंगित करने के लिए। बाद में, कई प्रमुख
कांग्रेस सदस्यों पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया जाएगा—ललित माकेन, एच. के.
एल. भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमल नाथ। इनमें से अधिकांश के पास थे।
संजय गांधी के जीवित रहते हुए उनसे घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे और
संजय की मृत्यु के बाद कई लोगों ने अपनी निष्ठा अरुण नेहरू के प्रति स्थानांतरित कर दी थी।
एच. एस. फूलका, जिन्हें कई सिख परिवारों का कानूनी प्रतिनिधित्व करना था।
हिंसा से प्रभावित लोगों ने पुष्टि की कि वहाँ थे
इंदिरा गांधी के बाद राजधानी में जिन सिखों को निशाना बनाया जाना है, उनकी 'आसानी से उपलब्ध सूचियां'
गांधी की हत्या। वे कम समय में तैयार नहीं हो सकते थे।
सूचना। 'जब हम प्रस्तुत करने के लिए सामग्री संकलित कर रहे थे...'
(रंगनाथ) मिश्रा आयोग (सिख विरोधी हिंसा की जांच करने वाला)

फूलका ने कहा, 'हमें खुफिया विभाग के कुछ लोगों ने बताया था।'
वह समुदाय जो ऑपरेशन ब्लूस्टार (जून 1984 में) से कुछ समय पहले,
दिल्ली के सिखों की प्रतिक्रिया के डर से, विस्तृत जानकारी के बारे में
सरकार द्वारा समुदाय को एकत्रित किया गया था।
सरकार का अनुमान है कि दिल्ली में 2,733 सिखों की हत्या हुई।
अगले तीन दिनों में और देशभर में 3,350 मामले सामने आएंगे। लेकिन, के अनुसार
स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार, चालीस शहरों में 8,000 से 17,000 लोग मारे गए।
इंदिरा गांधी के बाद हुए व्यापक हिंसा में देश की भूमिका
हत्या।
■

स्टेट्समैन हाउस (जहां मैं काम करता था) लौटते हुए, 31 तारीख की शाम
अक्टूबर 1984 में, मुझे वह मोची मिल गया जो गेट के बाहर बैठा करता था।
वह सिसकते हुए बोली, ‘वह हमारी अम्मा थीं, वह चली गईं।’ आग की लपटें दिखाई दे रही थीं।
कनॉट प्लेस (सीपी) के कई हिस्सों से धुआं उठता हुआ,
इमारतों में आग लगा दी गई। सीपी में घूमते हुए मेरी मुलाकात एक साथी पत्रकार से हुई।
उन्होंने भावुकता से भरी आवाज में कहा, 'देखिए, हमारा दिल्ली ऊपर की ओर बढ़ रहा है।'
आग की लपटों में।' इसके बाद के दिनों में, त्रिलोकपुरी का दौरा किया गया - जो सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र था।
दिल्ली के वे विभिन्न इलाके जहाँ सिखों की आबादी बहुत अधिक है—
इससे पता चलता है कि हत्याएं कितनी भयावह थीं। मेरे अपने परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ था।
देश के विभाजन के बाद मैं पाकिस्तान से दिल्ली आ गया, और मैं
मैंने मन ही मन सोचा कि 1947 में ऐसा ही रहा होगा। सिख
महिलाएं विलाप करते हुए बता रही थीं कि उनके पुरुषों को जिंदा जला दिया गया था।

जलते हुए कार टायरों से 'हार' बना दिया गया। उन्होंने कांग्रेसियों के बारे में बात की।
उन पर हमला करने आई भीड़ का नेतृत्व करते हुए।
अन्य बस्तियों का दौरा करते समय मुझे पता चला कि कई हिंदुओं के पास
उन्होंने अपने सिख पड़ोसियों या दोस्तों को शरण दी। लेकिन उनमें से कुछ
बहुत से हिंदू शहर के अन्य हिस्सों में भाग लेने गए थे।
सिखों के खिलाफ हिंसा। इसकी पहली प्रेरणा इस आवश्यकता से उपजी थी कि

एक का उद्देश्य सामाजिक संबंध बनाए रखना था, जबकि दूसरे का उद्देश्य सांप्रदायिक भड़ास निकालना था।
नफरत। मैंने उन दिनों में सीखा कि ये दोनों चीजें साथ-साथ रह सकती हैं।
हत्याएं तीन दिनों तक चलीं। 31 अक्टूबर और 3 के बीच
नवंबर में, राजीव गांधी तीन मूर्ति में अपनी माता के पार्थिव शरीर के पास रुके थे।
हाउस के चेहरे पर गंभीरता और संयम झलक रहा था।
इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार राजीव गांधी द्वारा संपन्न किए जाने के बाद ही यह बात सामने आई।
3 नवंबर को यमुना नदी के किनारे शांति की वापसी हुई।
शहर को। उसके बाद ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आखिरकार फोन किया।
दिल्ली से सेना हटा ली गई। तीन दिन की देरी हो चुकी थी। अभी भी कोई स्पष्ट समाधान नहीं है।
इस सवाल का जवाब दें कि उन्होंने हत्याओं को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं की।
शायद राजीव गांधी स्तब्ध थे। शायद वे असमंजस में थे।
उन्हें क्या करना चाहिए, सब कुछ अरुण नेहरू और अन्य लोगों पर छोड़ते हुए।
निष्क्रियता के कारण आधुनिक इतिहास की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक घटित हुई।
भारत।

तृतीय

अरुण नेहरू का राजनीति से परिचय 1980 में शुरू हुआ। कुछ ही महीनों पहले की

बात है।
राजीव गांधी के राजनीति में कदम रखने से पहले, जब उन्होंने 'मम्मी की मदद करने' के लिए राजनीति में कदम रखा था।
उनके भाई संजय का निधन हो गया।
जनवरी 1980 में, इंदिरा गांधी ने अपनी दोनों सीटें जीत ली थीं।
उन्होंने आम चुनाव में भाग लिया। उन्होंने मेडक सीट को बरकरार रखने का फैसला किया।
आंध्र प्रदेश को छोड़ दें और उत्तर प्रदेश के रायबरेली को त्याग दें।
हम विलिंगडन क्रीसेंट के 12 नंबर वाले घर में लंच टेबल पर बैठे थे।
अकबर डम्पी अहमद ने याद करते हुए कहा, 'वहाँ संजय, मेनिका और मैं थे।'
श्रीमती गांधी भी हमारे साथ शामिल हो गईं। हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किसे उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए।
रायबरेली (वहाँ होने वाले उपचुनाव में)।
मोहम्मद यूनुस सामने आए।
यूनुस परिवार के एक वफादार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, जिन पर इंदिरा गांधी और अन्य दोनों को भरोसा था।
और संजय। वे 1974 में विदेश सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और नेतृत्व कर रहे थे।
भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, जिसने प्रदर्शनी की स्थापना की थी
दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित परिसर। संजय, के करीबी दोस्त थे।
मोहम्मद यूनुस के बेटे, आदिल शाहरयार। जब इंदिरा गांधी हार गई थीं
1977 के चुनाव के बाद, यूनुस ने विलिंगडन स्थित अपना घर खाली कर दिया था।
वह क्रेसेंट से निकलकर 12 नंबर पर सांसद के पहले तल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने चली गई।
साउथ एवेन्यू, जो हमीदा हबीबुल्लाह को आवंटित किया गया था
(वजाहत हबीबुल्लाह की माँ)। 1982 में, शाहरयार को दोषी ठहराया गया था।
अमेरिका में गंभीर अपराध, जूरी के समक्ष पूर्ण सुनवाई के बाद। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति
रोनाल्ड रीगन ने 11 जून 1985 को उनकी रिहाई के आदेश पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए थे, उसी दिन राजीव गांधी, जो तब तक प्रधानमंत्री बन चुके थे, वहाँ

पहुँचे थे।
राजकीय यात्रा पर वाशिंगटन डीसी। यह सद्भावना का प्रतीक था।
भारतीय प्रधानमंत्री को।
मोहम्मद यूनुस जीवन भर संजय के चाचा ही रहे।
और राजीव—परिवार की तरह थे। लेकिन, किसी कारणवश, इंदिरा गांधी इसके पक्ष में नहीं थीं।
रायबरेली से यूनुस को मैदान में उतारने के बारे में उनका कहना था कि यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।
वह परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है।
अचानक, मेनिका ने कहा, 'हम फैटी को टिकट क्यों नहीं दे देते?'
फैटी अरुण नेहरू थे। सबको लगा कि यह एक अच्छा विचार है।
संजय के परदादा, मोतीलाल नेहरू, और अरुण नेहरू के परदादा-
मेरे दादा, नंद लाल नेहरू, भाई थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था।
अरुण की बेदाग राजनीतिक पृष्ठभूमि पर संदेह करते हुए,
नेहरू परिवार। संजय ने तुरंत आर. के. धवन को संपर्क करने के लिए कहा।
अरुण नेहरू के साथ।
नेहरू एक दिन बाद दिल्ली पहुंचे। जब वे 12 नंबर हॉल में दाखिल हुए,
विलिंगडन क्रीसेंट, संजय बैठक कक्ष में था। 'मोटू, चुनव'
'मोटे, क्या तुम चुनाव लड़ोगे?' उसने अपने चचेरे भाई को चिढ़ाते हुए कहा।
मुझे याद है कि जब वह आया था तब उसने ग्रे रंग का फलालैन ब्लेज़र और टाई पहनी हुई थी।
'पहुंच गए,' डम्पी अहमद ने कहा। उन्होंने अरुण नेहरू को खादी जाने के लिए कहा।
कनॉट प्लेस में भंडार से कुर्ता-पायजामा खरीदें।
उनकी नई भूमिका।
दोबारा सोचने पर, बेहतर होगा कि आप सामान खरीद लें और अपना सामान प्राप्त कर लें।
उन्होंने नेहरू से कहा, 'आपके नाप के हिसाब से कुर्ते सिल दिए जाएंगे।'
नेहरू की राजनीतिक यात्रा उनके बारे में चल रही नोकझोंक के बीच शुरू हुई।
मोटापा। लेकिन भारी-भरकम नेहरू कमजोर साबित नहीं हुए। उनके पास

उन्होंने कॉर्पोरेट जगत में पहले ही अपनी पहचान बना ली थी। सैंतीस साल की उम्र तक, उन्होंने
बहुराष्ट्रीय कंपनी की भारतीय शाखा के अध्यक्ष बनें।
जेन्सन एंड निकोलसन, अपने लोकप्रिय नारे 'व्हेनएवर' के लिए याद किया जाता है।
जब आपको रंग दिखाई दे, तो हमारे बारे में सोचें।
उन्होंने अप्रैल में रायबरेली सीट जीतकर शानदार शुरुआत की।
1980 में, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में अथक परिश्रम किया और भारी बहुमत से जीत हासिल की।
शानदार अंतर से जीत। इंदिरा गांधी के समर्थन से, परिणाम यह था।
मुझे कभी कोई संदेह नहीं था।
■

संजय की मृत्यु तक राजीव और सोनिया राजनीति से दूर रहे थे।
हालांकि वे प्रधानमंत्री आवास में रहते थे, फिर भी उनका अपना एक निजी समूह था।
लुटियंस के दिल्ली के अभिजात वर्ग में मित्र। कभी-कभी, उनमें से एक या दो।
उनके करीबी दोस्त रविवार को आते थे। फिर वे चले जाते थे।
दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित उनके फार्महाउस में निशानेबाजी करने के लिए।
परिवार के साथ मिलकर आराम से समय बिताएं। शाम को वे
वे अक्सर अपने दोस्तों के घर डिनर पार्टियों में जाते हैं।
राजीव और सोनिया दोनों ही आपातकाल और इसमें शामिल भूमिका के आलोचक थे।
संजय ने इसके सबसे बुरे दौर में खेला था। जिस दिन इंदिरा गांधी थीं
1977 के चुनावों में हारने के बाद, निराश राजीव ने पुपुल जयकार से कहा था, 'मैं
मैं संजय को कभी माफ नहीं करूंगी जिसने मम्मी को इस स्थिति में पहुंचाया।
इंदिरा गांधी, जिन्हें सरकार में संजय की भूमिका को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था,
राजीव के राजनीति में प्रवेश के मामले में उन्होंने सावधानी बरतने का फैसला किया।
संजय की मृत्यु के तीन महीने बाद, उसने अचानक फैसला किया कि उसे...

उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चयन पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने अपने सहायक एम. से पूछा।
एल. फोतेदार को यह आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया था कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में किसे पदभार संभालना चाहिए।
उसने उसे दो नाम दिए—प्रणब मुखर्जी और पी.वी. नरसिम्हा।
राव. फोतेदार ने तीसरा नाम जोड़ा—आर. वेंकटरमन का। उन्होंने दिया
उसे 'अभ्यास पूरा करने' के लिए एक महीने का समय दिया गया था। वह यह पता लगाना चाहती थी कि कैसे।
पार्टी उत्तराधिकारी के प्रश्न पर प्रतिक्रिया देगी। कांग्रेसी सदस्य
नेता के मन की बात जल्दी समझ लेने वाली फोतेदार उसके पास वापस आई और बोली,
उन्हें तीनों नामों पर मिली प्रतिक्रिया 'अनुचित' लगी। इसके बजाय, उन्होंने
उन्होंने राजीव को अपना उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। 'उन महीनों में, जबकि
1, सफदरजंग रोड से पैदल चलकर बगल के बंगले 1, अकबर तक जाना।
सड़क पर, 'वह मुझसे राजीवजी के प्रवेश के फायदे और नुकसान पर चर्चा करती थी।
राजनीति।' यह बात फैल गई कि श्रीमती गांधी राजीव को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थीं।
पार्टी के नेता यह जताने के लिए एक-दूसरे से होड़ कर रहे थे कि वे क्या चाहते हैं।
राजीव गांधी को युवराज घोषित किया गया। अरुण नेहरू ने एक समूह का आयोजन किया।
लगभग पचास सांसदों ने श्रीमती गांधी से मुलाकात की; उन्होंने उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
संजय की जगह राजीव ने ली।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने 100 सैनिकों को रवाना किया।
विधायकों ने इंदिरा गांधी से राजीव गांधी को पार्टी में वापस लाने की विनती की।
एच. के. एल. भगत और बूटा सिंह भी पीछे नहीं रहने वाले थे।
इस समय तक संजय की विधवा मेनका गांधी भी धीरे-धीरे इस ओर बढ़ने लगी थीं।
राजनीति में प्रवेश करने के अपने प्रयास में उन्होंने एक स्वतंत्र रुख अपनाया।

अपनी सास की इच्छा के विरुद्ध राजनीतिक सभाएँ आयोजित करना।
जल्द ही दोनों के बीच कड़वाहट भरी दरार आ गई। 29 मार्च 1982 की आधी रात को मेनका अपने साथ प्रधानमंत्री आवास छोड़कर चली गईं।
दो वर्षीय बेटे फिरोज वरुण गांधी को मीडिया की निर्मम निगाहों के बीच देखा गया।
प्रचार। हालांकि वरुण को अपनी माँ के साथ जाते देखना बहुत दुखद था।
श्रीमती गांधी उनसे बहुत लगाव रखती थीं और वे उनके साथ सोते थे।
रात में—इंदिरा को यह सुनिश्चित करना था कि उसके बारे में कोई अस्पष्टता न रहे।
कांग्रेस में उत्तराधिकारी और दूसरे नंबर की नेता। और वह
वे पार्टी के हलकों में इस बात को जल्द से जल्द बताना चाहते थे।
■

राजीव ने कहा, 'सोनिया को मेरा राजनीति में आना बिल्कुल पसंद नहीं है।'
उन्होंने साक्षात्कारकर्ता को खुलकर बताया था।
जब जून 1980 में संजय की मृत्यु हुई, तो राजीव यह जिम्मेदारी लेने के लिए अनिच्छुक थे।
अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। उन्हें राजनीति में कभी दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल,
उन्हें राजनीति से ऊब हो गई थी। उन्होंने राजनीति अपनी मां और संजय पर छोड़ दी थी। और सोनिया पर भी।
जैसा कि उन्होंने कहा था, वे इस विचार के पूर्णतः विरोधी थे। राजीव को कई वर्षों का समय लगा।
निर्णय लेने में महीनों लग गए।
सन् 1980 के अंत में एक दोपहर, राजीव ने मुझे चुपचाप 1 के लॉन में बताया,
अकबर रोड, सक्रिय राजनीति में कदम रखने का उनका निर्णय, और इसमें शामिल होना
'अमेठी से लोकसभा', पत्रकार सुमन दुबे ने याद करते हुए कहा, जो उस समय लोकसभा में अमेठी से चुनाव लड़ने वाली थीं।
राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर वे उनके प्रेस सलाहकार बने और एक वफादार

नेहरू-गांधी परिवार के मित्र।
राजीव ने कहा था, 'मेरे हिसाब से तो मम्मी को होना ही चाहिए।'
किसी तरह मदद मिली।
अंततः, 5 मई 1981 को उन्होंने पायलट के रूप में अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया।
उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में शामिल होने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) में शामिल होने का फैसला किया।
परिवारों के गढ़ माने जाने वाले अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए
जहां संजय ने जनवरी 1980 में जीत हासिल की थी।
'राजीव ने पदार्पण किया'—12 मई 1981 को प्रमुख समाचारों के रूप में यह घोषणा की गई।
वे लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अमेठी में थे।
चुनाव के नतीजे आ गए, हफ्तों से चल रहे सस्पेंस का अंत हुआ। राजीव के साथ उनके साथी भी थे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वी. पी. सिंह, युवा सदस्यों
कांग्रेस, उनके चचेरे भाई अरुण नेहरू और सोनिया गांधी। जब सोनिया गांधी के पास
उन्होंने अपने पति के साथ सुल्तानपुर जाने की इच्छा व्यक्त की, जहाँ वे
जब उन्हें अपना नामांकन पत्र दाखिल करना था, तब इंदिरा गांधी ने उन्हें सलाह दी थी।
बहू, 'साड़ी पहनना, टीका लगाना'
बिंदी)।
राजीव गांधी के मुख्य प्रतिद्वंदी लोक दल के उम्मीदवार शरद गांधी होंगे।
यादव, जो जबलपुर में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे
1974 में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को हराया था।
अरुण की संगठनात्मक क्षमता को जानते हुए, श्रीमती गांधी ने उनसे यह अनुरोध किया था।
नेहरू ने राजीव के चुनाव अभियान का आयोजन किया। अरुण नेहरू ने कुछ भी नहीं छोड़ा।
संयोगवश। वह पूरे अभियान के दौरान वहीं डेरा डाले रहा; उसने इसकी योजना बनाई

थी।
उन्होंने उपभोक्ता उत्पाद के लॉन्च को ठीक उसी तरह से अंजाम दिया होगा जैसे वे करते।
अपने पिछले अवतार में एक कॉर्पोरेट कार्यकारी के रूप में, वह उत्पाद के बारे में जानता था।
राजीव की शानदार जीत से उन्हें काफी सराहना मिलेगी।
इंदिरा।
प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने उपचुनावों में प्रचार नहीं किया।
आम तौर पर। लेकिन वह विशेष रूप से राजीव की मदद करने के लिए अमेठी गई थी।
कपिल मोहन की मोहन मीकिन टीम पूरी ताकत के साथ वहां मौजूद थी।
हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हुए, यहाँ तक कि इंदिरा और उनके लिए भोजन भी उपलब्ध कराते हुए।
राजीव को पसंद आया। अनिल बाली ने स्वयं व्यवस्थाओं की देखरेख की। उस दिन इंदिरा आई, बाली ने याद करते हुए कहा, 'मैंने दशहरी के दोपहर के भोजन का इंतजाम किया था।'
आम, लेमन चिकन और अरहर दाल बिना किसी मसाले के, जहाँ तक मुझे पता था। श्रीमती गांधी को पसंद आया।' आखिरकार, इंदिरा गांधी को लॉन्च करने के लिए यह एक हाई-प्रोफाइल लड़ाई थी।
गांधी जी के उत्तराधिकारी।
Rajiv Ratna Birjees Gandhi, 37, defeated Sharad Yadav by a
जून 1981 में राजीव गांधी ने भारी बहुमत से 237,000 वोट हासिल किए थे। अमेठी में जीत के साथ, राजीव गांधी ने
उसने पहला कदम उठा लिया है जो उसे सत्ता के शिखर तक ले जाएगा।
जीत के बाद जब वे वापस लौटने के लिए लखनऊ हवाई अड्डे पर थे।
दिल्ली में, अनिल बाली ने राजीव की ओर मुड़कर उत्साहपूर्वक कहा, 'मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।'
भारत के भावी प्रधानमंत्री के साथ यात्रा करने का सौभाग्य।' राजीव
वह सिर्फ मुस्कुराई—लेकिन कुछ नहीं बोली।
राजीव ने 17 अगस्त 1981 को सांसद के रूप में शपथ ली और वे राजनीतिक

विवादों में घिर गए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) नामक विशाल तंत्र। उनका पहला
सांसद के रूप में शपथ लेने से पहले ही, उन्हें एक कार्य सौंपा गया था जिसमें उन्हें भाग लेना था।
प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना स्पेंसर का विवाह समारोह 27 तारीख को लंदन में हुआ।
जुलाई 1981।
इंदिरा गांधी ने यह सुनिश्चित किया कि राजीव गांधी का राजनीति में प्रवेश इस प्रकार हो कि
जितना संभव हो उतना सुचारू रूप से - उसने उसे आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी।
नौवें एशियाई खेल जिनकी मेजबानी भारत को नवंबर 1982 में करनी थी।
उन्होंने आयोजन समिति का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री से उनकी निकटता को देखते हुए।
मंत्री जी, वे खामियों को दूर कर सकते हैं और आखिरी समय में भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं।
निधि आवंटन को मंजूरी दे दी गई। संजय जगमोहन के समर्थक, जिन्होंने आपातकाल के दौरान दिल्ली में अलोकप्रिय विध्वंस किए थे।
और इंदिरा गांधी की वापसी पर उन्हें तुरंत पुनर्स्थापित कर दिया गया।
1980 में सत्ता में आने के बाद उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया था।
राजीव के साथ मिलकर उन्होंने नई सड़कें बनाईं और मौजूदा सड़कों को चौड़ा किया।
उन्होंने फ्लाईओवर और नए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया और निर्माण किया।
60,000 सीटों वाला जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। सिरी फोर्ट सभागार।
और एशियाई खेल गांव का निर्माण किया गया, जो उस भुला दिए गए स्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित था।
मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित एक पुराने किले के खंडहर
चौदहवीं शताब्दी।
19 नवंबर 1982 को उद्घाटन समारोह हुआ - संयोग से यह इंदिरा गांधी के समय हुआ था।
गांधी जी का जन्मदिन एक भव्य आयोजन था। इसमें 3,411 एथलीटों ने भाग लिया।

इस आयोजन के लिए राजीव को प्रशंसा मिली—लेकिन साथ ही साथ इसके लिए भी।
दिल्ली को एक आधुनिक शहर में रूपांतरित करना। उन्हें एक प्रगतिशील नेता के रूप में सराहा गया।
एक दूरदर्शी, तकनीकी रूप से कुशल नेता, जो पेशेवर प्रबंधन में विश्वास रखता था।
और समय सीमा का पालन कर सकता था।
एशियाई खेलों ने भारत में रंगीन टेलीविजन के युग की शुरुआत की।
यह सोने पर सुहागा था। भारतीय परिवार बड़े उत्साह से इसे देख रहे थे।
सार्वजनिक प्रसारक द्वारा प्रसारित खेलों को वे अपने टीवी सेटों पर चटख रंगों में देख सकते हैं।
दूरदर्शन। इसका श्रेय राजीव को दिया गया, और इस बात का भी कि उन्होंने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
अपनी पूर्व समाजवादी मां को रंगीन टीवी खरीदने के लिए राजी करना।
यह कदम भारत के मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए बनाया गया है, जिसका चहेता वह बनने वाला था।
■

राजीव गांधी की कार्यशैली संजय गांधी की कार्यशैली से बहुत अलग थी।
3 फरवरी 1983 को पार्टी के महासचिव बनने के बाद, उन्होंने
उन्होंने मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित 2ए स्थित अपने कार्यालय को व्यवस्थित करना शुरू किया। अन्य कार्यालयों के विपरीत,
उस समय पार्टी कार्यालयों में, राजीव के कार्यालय में एक कंप्यूटर और फाइलें थीं।
अखबारों की कतरनें, अन्य डेटा बैंक, किताबें और दस्तावेज़
विषय शीर्षक और एक ज़ेरॉक्स मशीन। और वहाँ तस्वीरें भी थीं।
कालीन—सोनिया का स्पर्श—गर्मजोशी और सुकून का माहौल बनाने के लिए।
स्वागत है। उनके कार्यालय में विन्सेंट जॉर्ज मौजूद थे, जो आगे चलकर उभरने वाले थे।
एक शक्तिशाली सहायक के रूप में, उन्हें अंत तक उनके साथ रहना था। राजीव के

बाद,
जॉर्ज—जिनकी संस्थागत स्मृति बहुत तीव्र थी—ने सोनिया के साथ काम किया।
जब वह पार्टी की अध्यक्ष बनीं तब से लेकर जब तक उन्हें पद से नहीं हटा दिया गया।
जिस प्रकार इंदिरा गांधी संजय के इर्द-गिर्द एक टीम बनाना चाहती थीं, उसी प्रकार 1977 में, और फिर 1980 में, वह एक टीम बनाना चाहती थी।
राजीव। उन्होंने अरुण नेहरू से ऐसे लोगों को भर्ती करने के लिए कहा जो उनके प्रति वफादार हों।
राजीव के साथ विश्वासघात नहीं करेगा।
संजय के विपरीत, जो नफरत का पात्र बन गया था, राजीव के पास था
नए सिरे से शुरुआत करने का फायदा। वह भूली नहीं थी।
जिन समस्याओं का सामना उन्होंने स्वयं 1966 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद किया था।
हालांकि राजीव को संजय के यूथ कांग्रेस के लड़कों का समूह विरासत में मिला था, बहुत जल्दी ही उन्होंने अपनी टीम बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने प्राथमिकता दिखाई।
'अंग्रेजी बोलने वाले, दून स्कूल से शिक्षित भारतीयों' के लिए, जिनका उन्होंने पालन-पोषण किया था।
वे ऐसे व्यावसायिक कार्यकारी वर्ग के लोग थे जो आधुनिक तकनीकों पर निर्भर थे।
प्रौद्योगिकी, डेटा और कंप्यूटरों को अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उन पर निर्भर रहने की बजाय।
चापलूस पिछलग्गू। लेकिन वे अधिकतर धनी पुरुष थे और
वे महिलाएं, जो 'ड्राइंग रूम' समूह से थीं और उनकी ही तरह, उन्हें भी बहुत कम अनुभव था।
भारत की जमीनी हकीकतों के अनुरूप। उन्होंने अपने पुराने मित्र अरुण सिंह को राजी किया।
उन्होंने कलकत्ता स्थित रेकिट एंड कोलमैन कंपनी से इस्तीफा दे दिया, जिसमें वे काम कर रहे थे।
और उनसे जुड़ गए। 1984 में, उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में लाया गया।
अरुण सिंह प्रदेश के निवासी थे और 1988 तक मध्य प्रदेश में रहे। उनकी कंपनी जूते बेचती थी।

अरुण नेहरू लोकसभा सांसद बनने से पहले पेंट बेचते थे।
राजीव अपने साथ विजय धर को भी लेकर आए, जो एक कश्मीरी पंडित हैं और जिनके पिता वामपंथी विचारधारा के हैं।
डी. पी. धर मॉस्को में भारत के राजदूत रह चुके थे और उन्होंने मदद की थी।
भारत-सोवियत मैत्री संधि का मसौदा तैयार करना, गठन से ठीक पहले।
1971 में बांग्लादेश में दूरसंचार की शुरुआत विजय धर ने ही की थी।
राजीव को गुरु सत्यन गंगाराम पित्रोदा या सैम पित्रोदा। बाद में राजीव
उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में अपने साथी पायलट सतीश शर्मा को भी शामिल किया।
एक और 'डोस्को' (दून स्कूल के पूर्व छात्र) मणि शंकर अय्यर,
पत्रकार सुमन दुबे और अभिनेता अमिताभ बच्चन—दोनों
करीबी दोस्तों को उन्होंने अपनी टीम में अलग-अलग भूमिकाओं में शामिल किया।
लेकिन 1982-84 के दौरान, ये तीन दिग्गज थे—अरुण नेहरू,
अरुण सिंह और विजय धर—जिन्होंने राजीव के साथ मिलकर काम किया था।
■

जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि हालांकि राजीव गांधी की मंशा अच्छी थी, लेकिन
वह भोला भी था। उसका भोलापन ही बार-बार उसके पतन का कारण बना।
आंध्र प्रदेश, जम्मू और
चाहे कश्मीर हो, पंजाब हो, या शाह बानो मामले को संभालने का उनका तरीका।
3 फरवरी 1982 को, सांसद बनने के छह महीने बाद, राजीव गांधी
वह हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर उतरे। वह आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे।
प्रदेश। जैसे ही वह विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरा, वह आश्चर्यचकित रह गया।
उन्हें देखने के लिए रनवे पर 200 लोग जमा हुए थे। उनका नेतृत्व करते हुए।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टी. अंजैया, जो कद-काठी में काफी मोटे थे, ने
राजीव का भव्य स्वागत करने के लिए लोग आए थे। हालाँकि राजीव तो केवल एक पार्टी के सदस्य थे।
सांसद, उन्हें अब इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। अचानक, आवाज

ढोलों की गूंज हवा में गूंज उठी और कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी धुन पर नाचने लगे।
एयरपोर्ट पर उसकी पिटाई हुई। राजीव गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके अनुसार, वह इंडियन एयरलाइंस का पूर्व कर्मचारी था।
पायलट को हवाई अड्डे की सुरक्षा का उल्लंघन हो रहा था। उसे शान-शौकत भी पसंद नहीं थी।
उनके लिए आयोजित किया गया भव्य समारोह।
बेहद क्रोधित राजीव ने सबके सामने मुख्यमंत्री अंजैया पर चिल्लाया।
वहाँ जमा हुए। 'अगर व्यवस्था नहीं बनी और पूरा मामला खत्म नहीं हुआ तो...'
पंद्रह मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा।
बेहद निराश अंजैयाह की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने माफी मांगी।
बेहद। अपने सलाहकारों द्वारा राजीव को शांत करने के बाद, वह हवाई अड्डे से चले गए।
और तिरुपति के लिए रवाना हो गए, अंजैया को हवाई अड्डे पर ही दुखी छोड़कर।
मुख्यमंत्री ने तुरंत उन समूहों को संदेश भेजा जो रास्ते में कतार में खड़े थे।
राजीव के लिए लगाए गए सैकड़ों स्वागत मेहराबों को हटा दें।
राजनीति में नए-नए आए राजीव चाटुकारिता पर अंकुश लगाना चाहते थे और एक नई व्यवस्था शुरू करना चाहते थे।
कांग्रेस में एक नई राजनीतिक संस्कृति का उदय हुआ। लेकिन उन्हें एक सामंती व्यवस्था से निपटना पड़ रहा था।
भारत और कांग्रेस में व्याप्त उन स्थापित प्रथाओं के बारे में, जिसके वे अब सदस्य थे।
उनके हठधर्मी व्यवहार ने 'विरोध की चीखें' उत्पन्न कर दीं।
मीडिया और विपक्षी नेताओं ने जमकर आलोचना की।
एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के प्रति उनका व्यवहार। अंजैया का दलित होना।
हालात और बिगड़ गए।
कुछ समय से राज्य में असंतोष पनप रहा था
दिल्ली ने मुख्यमंत्रियों के साथ जिस तरह का मनमाना व्यवहार किया था।
आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री अक्सर बदलते रहते थे।
और उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं थी। अंजैया ने एम. की जगह ली थी।

पंद्रह महीने पहले चेन्ना रेड्डी। तीन हफ्ते बाद, अंजैया
उन्हें पद से हटा दिया गया। भवनम वेंकटरामी रेड्डी ने पदभार संभाला और केवल कुछ ही समय तक टिके रहे।
सात महीने। सितंबर में उनकी जगह विजया भास्कर रेड्डी को नियुक्त किया गया।
1982.
राजीव गांधी की यह गलती बहुत महंगी साबित हुई। छह सप्ताह बाद
इस घटना में, लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता एन. टी. रामाराव, जिन्होंने 300 फिल्मों में काम किया था, की जान चली गई।
उनकी उपलब्धियों में से कई में उन्होंने एक या दूसरे देवता की भूमिका निभाई, और उन्होंने घायल गौरव और आत्मसम्मान को बहाल करने के लिए एक नए राजनीतिक संगठन की शुरुआत की।
तेलुगु लोगों का सम्मान। मात्र नौ महीनों में, तेलुगु देशम पार्टी
उनकी अगुवाई वाली टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी।
उन्होंने 201 सीटें जीतीं।
जनवरी 1983 में हुए चुनावों में 294 सीटों में से।
कांग्रेस, जिसने कभी भी इस राज्य में हार का सामना नहीं किया था, लगभग पूरी तरह से सफाया हो गई।
टीडीपी को आंध्र प्रदेश की राजनीति में उन वर्षों में बने रहना था जब
पालन किया।
■

जहां राजीव गांधी सरल स्वभाव के थे, वहीं अरुण नेहरू आसानी से लोगों के बीच घुलमिल जाते थे।
राजनीति की दुनिया। उन्होंने इंदिरा गांधी के मन की बात तुरंत समझ ली थी;
वह राजीव को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार करना चाहती थी। वह अरुण को बार-बार यही बात कहती थी।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग राजीव का फायदा न उठाएं। यह एक कारण था।

वह यही कारण चाहती थी कि परिवार का कोई सदस्य संसद में आए।
रायबरेली से। वह जानती थी कि राजीव भोला और भरोसेमंद दोनों था।
और उन्हें मदद की जरूरत होगी।
इंदिरा गांधी के समर्थन से अरुण नेहरू बहुत शक्तिशाली बन गए।
1980 के दशक की शुरुआत में, मुख्यमंत्री और पार्टी नेता भुगतान करने लगे।
काम करवाने के लिए वह उनके इशारों पर चलता था। उद्योगपति उसे 'वन विंडो' कहते थे।
उन दिनों लाइसेंस-परमिट-कोटा राज और भाई-भतीजावाद के दौर में 'मंजूरी'
पूंजीवाद। कम उम्र से ही कंपनी चलाने का अनुभव होने के कारण, उनमें यह प्रवृत्ति झलकती थी।
अधिकार का प्रयोग करता था, जल्दी फैसले लेता था और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके काम करवाता था।
उसकी तरह।
जो वरिष्ठ पत्रकार उनकी बात नहीं मानते थे, उन्हें उनके गुस्से का सामना करना पड़ता था।
उर्दू अखबार नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी को ले जाया गया था।
कांग्रेस के युवा सांसदों के एक समूह द्वारा नेहरू से मिलने का कार्यक्रम तय किया गया था। कांग्रेस ने
जून 1983 में जम्मू और कश्मीर के चुनाव हार गए; एक सरकार
फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी और उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी।
लेकिन यह एक ऐसी सरकार थी जिस पर नेहरू की नजर थी।
‘अरुण नेहरू कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठे थे,’
सिद्दीकी ने याद करते हुए बताया, ‘उनके सामने कोई कुर्सी नहीं थी। लोग खड़े थे।
वह चारों ओर घूम रहा था। सिद्दीकी ने कहा, 'उसमें घमंड झलक रहा था।'
उन्होंने सिद्दीकी को आदेश दिया, 'मैं चाहता हूं कि तुम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ लिखो।'
फारूक अब्दुल्ला ने दोपहिया वाहन चलाना शुरू कर दिया था और
बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आज़मी डल झील में बाइक पर पीछे बैठकर सैर कर रही

हैं।
इस घटना ने लोगों को चौंका दिया और उनकी प्लेबॉय वाली छवि को और मजबूत कर दिया।
Nehru turned to Siddiqui and said, ‘Aur tum jao Kashmir. Aur Farooq ki photo kheecho, Shabana ke saath (Go to Kashmir and take a
फारूक और शबाना की तस्वीर।
सिद्दीकी ने विरोध जताते हुए कहा, 'यह राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।'
‘Acha, toh tu mujhe national interest sikhayega (So, now you will
'मुझे राष्ट्रीय हित के बारे में सिखाओ?' अरुण नेहरू ने तीखे स्वर में उत्तर दिया।
इसके बाद के महीनों में, सिद्दीकी ने 'नेहरू क्या थे' के बारे में लिखा।
'तक'। बाद में, मई 1985 में, जब कठोर कानून, आतंकवादियों और
विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (TADA) को लागू किया गया था।
पंजाब में आतंकवादियों से लड़ने वाले पहले पत्रकार सिद्दीकी थे।
इसके तहत गिरफ्तार किया गया। यह एक ऐसा कानून था जिसका दुरुपयोग अधिकतर लोगों के खिलाफ किया गया।
आतंकवादियों की तुलना में राजनीतिक विरोधियों और असंतुषों के खिलाफ लड़ना अधिक प्रभावी होता है।
उन दिनों नेहरू का इतना दबदबा था कि संपादक उनसे अक्सर पूछते थे कि...
उससे ‘भयभीत’ हो जाओ।
नेहरू ने बूटा सिंह से कहा था, 'अपने दोस्त को बताओ,' उनका इशारा जी.एस. की ओर था।
इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार चावला ने कहा, 'मैं उसे तो ठीक कर'
'मैं उसे ठीक कर दूंगा।' (मैं उसे सबक सिखाऊंगा।) बूटा सिंह उस समय गृह मंत्री थे और
नेहरू 1985-86 में उनके अधीन राज्य मंत्री थे। लेकिन बूटा सिंह ने इसका इस्तेमाल किया।
नेहरू को सर कहकर संबोधित करना।

अब तक अरुण नेहरू भी अपनी एक टीम बना रहे थे जो आगे चलकर
उनके प्रति वफादार। प्रमुख सदस्यों में श्रीमती गांधी के सहयोगी एम. एल. फोतेदार शामिल थे।
कैबिनेट सचिव पी. के. कौल, कानून मंत्री शिव शंकर, गोपी अरोरा,
प्रधानमंत्री कार्यालय में तेजतर्रार नौकरशाह, वे सभी पंजाब को लेकर कट्टरपंथी हैं और
कश्मीर—नेहरू की तरह। कई युवा कांग्रेसी जो रहे थे
संजय ब्रिगेड का हिस्सा थे, और शुरुआत में नेहरू का विरोध किया था।
उसकी ओर आकर्षित होने के लिए। संजय की तरह, वह भी सख्त और निर्णायक था, और
साथ ही यह घर्षणकारी भी हो सकता है।
लेकिन इंदिरा गांधी नकारात्मक बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थीं।
उसके परिवार के बारे में, चाहे वह राजीव हो या नेहरू, वह उससे शिकायत करती थी।
उनके बारे में वह खुलकर अपनी झुंझलाहट दिखाती थी।
■

इंदिरा गांधी ने राजीव और अरुण नेहरू और उनके दोस्तों को मुफ्त में रहने की अनुमति दी।
नवंबर 1982 में, नेहरू ने राजीव गांधी के समर्थन से इंदिरा गांधी को मना लिया।
अकाली दल के साथ समझौता करने से, जो हो सकता था
उन्होंने पंजाब में स्थिति को संभाला, ऑपरेशन ब्लूस्टार को रोका और संभवतः अपनी हत्या को भी टाल दिया। यह एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।
पंजाब की कहानी।
संजय गांधी के जीवित रहते ही उन्होंने जरनैल सिंह को अपना जीवनसाथी चुना था।
भिंडरांवाले को उस व्यक्ति के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जिसे कांग्रेस को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में तैयार करना चाहिए।
पंजाब में अकाली दल। अकाली दल ने आपातकाल का विरोध किया था और
संजय उन्हें सबक सिखाना चाहता था। ज़ैल सिंह, तत्कालीन गृह मंत्री

वह संजय को रहनुमा (दयालु) कहकर संबोधित करता था।
भिंडरांवाले, एक मामूली करिश्माई उपदेशक जो
सिख धर्मग्रंथ गुरबानी के अपने गायन से वे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
शास्त्रों के बारे में। पंजाब में यह एक खुला रहस्य था कि कांग्रेस के पास
उसे सहारा दिया। ज़ैल सिंह ने प्रेस का बिल भी चुकाया था।
वह सम्मेलन जिसका आयोजन उन्होंने भिंडरांवाले के लिए किया था!
हालांकि, भिंडरांवाले जल्द ही बेकाबू हो गए—उन्हें
हिंदुओं की हत्या की, पंजाब में समानांतर सरकार चलाई और दंडात्मक कार्रवाई की।
जहां भी उसके आदेश को लागू किया जा सकता था, वहां त्वरित न्याय किया गया।
समय आने पर, उसने
सिखों के लिए एक अलग मातृभूमि के निर्माण की मांग की गई।
Khalistan.
स्थिति बिगड़ने पर इंदिरा गांधी ने संपर्क साधने का फैसला किया।
अकाली दल ने भिंडरांवाले की चुनौती का मुकाबला करने के लिए भी यही तरीका अपनाया था।
उन्होंने उग्रवादी रुख अपनाया और 1973 में कार्रवाई के लिए धर्मयुद्ध शुरू किया।
आनंदपुर साहिब में 'सत्ता के व्यापक हस्तांतरण' के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।
इंदिरा गांधी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्ण सिंह को नियुक्त किया था।
अकाली दल से बात की। वह उनके साथ एक समझौते पर पहुँचने में कामयाब रहे—
और
उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित करने पर सहमति जताई। गृह मंत्री पी.सी. सेठी ने भी अपनी बात रखी।
संसद में समझौते की शर्तों की घोषणा करने के लिए। लेकिन जब वह
जब उन्होंने भाषण दिया, तो वह तयशुदा समझौते से बिल्कुल अलग था।
अकाली दल के साथ। 3 नवंबर 1982 की रात 11 बजे, उससे एक रात पहले।
जब घोषणा होनी थी, तब इंदिरा ने सेठी के भाषण में बदलाव कर दिया था।
अंतिम क्षण में, अरुण नेहरू, राजीव गांधी और उनके मित्र
उन्होंने इंदिरा गांधी को समझौते पर आगे न बढ़ने के लिए मना लिया था।
इसे अकाली दल के सामने 'आत्मसमर्पण' के रूप में देखा जाएगा और इससे चुनाव

प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।
हरियाणा में हिंदू। राज्य में जल्द ही चुनाव होने वाले थे—और यह चुनाव हो सकता था।
कांग्रेस के लिए समस्याएं पैदा करना।
इंदिरा गांधी अकाली दल के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के फायदे को समझ सकती थीं।
इससे संभवतः उन्हें हिंदुओं का समर्थन मिल जाएगा, जो नाखुश थे।
खालिस्तान के अलग राज्य की मांग के साथ। इससे कांग्रेस को न सिर्फ हरियाणा में बल्कि एक साल बाद होने वाले आम चुनावों में भी मदद मिल सकती है।
आगे चल कर।
ज़ैल सिंह, जो अब तक अध्यक्ष बन चुके थे और मदद कर रहे थे
अरुण नेहरू ने इंदिरा गांधी से कहा था कि स्वर्ण सिंह नहीं बल्कि राजीव गांधी को विजेता घोषित किया जाना चाहिए।
किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय किसे मिलना चाहिए?
अकाली दल ने खुद को धोखा महसूस किया। उन्होंने एशियाई खेलों का बहिष्कार किया।
दो हफ्ते बाद शुरू होने वाले थे। भजन लाल, तत्कालीन मुख्यमंत्री
अरुण नेहरू और एम. एल. फोतेदार के समर्थन से हरियाणा ने तलाशी लेने का फैसला किया।
खेलों के लिए दिल्ली जाने वाले हर सिख को उनके घरों से बाहर निकाला गया।
उन्हें वाहनों में बिठाया गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिसे उन्होंने अपमानजनक पाया। इसके परिणामस्वरूप
सिखों में व्यापक आक्रोश और अलगाव की भावना फैल गई। उसके बाद,
हालात बद से बदतर होते चले गए।
भिंडरांवाले और उनके समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर में शरण ली।
1983 के अंत में, उन्होंने मंदिर की किलेबंदी शुरू कर दी।
‘मैंने मम्मी को कितनी बार बताया है,’ राजीव ने झुंझलाते हुए कहा।
पत्रकार तवलीन सिंह कहती हैं, 'हमें कुछ करना होगा। लेकिन वह सुनती हैं।'
अपने वरिष्ठ सलाहकारों से। वे उसे बताते हैं कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए

जो
इससे सिख नाराज हो जाएंगे।'
राजीव, अरुण नेहरू, अरुण सिंह, और विजय धर-'बाबा लोग' या
जिन्हें 'कंप्यूटर बॉयज़' कहा जाता था, उन्होंने एक आकस्मिक योजना तैयार कर ली थी।
सन् 1984 की शुरुआत में ही अमृतसर में सैन्य अभियान की योजना बनाई गई थी।
यह एक 'आक्रमण योजना' थी। इसका उद्देश्य भिंडरांवाले को खदेड़ना था।
स्वर्ण मंदिर से। लेकिन इंदिरा ने 'देरी की और विरोध किया'। 'वह
अरुण नेहरू ने इंदिरा गांधी से कहा, 'भगवान के घर पर हमला करने से डर लगता है।'
जीवनीकार, कैथरीन फ्रैंक। इसके बजाय, उन्होंने पूजा-अर्चना की। उन्होंने रखा
किसी चमत्कार की उम्मीद में। अंततः, स्थिति
हालात इतने बिगड़ गए कि इंदिरा गांधी को सेना भेजनी पड़ी।
गोल्डन टेंपल में सैन्य अभियान चलाया गया जिसका कोड नाम ऑपरेशन ब्लूस्टार था।
1 जून 1984 को हुई इस घटना में भिंडरांवाले की मौत हो गई और कुछ हिस्से नष्ट हो गए।
स्वर्ण मंदिर को अपमानित किया और सिख मानस को ठेस पहुँचाई। यह एक ऐसा कृत्य था जिसने
यही घटना 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या और जनसंहार का कारण बनी।
इसके परिणामस्वरूप निर्दोष सिखों की हत्याएं हुईं।
■

पंजाब में हुए घटनाक्रमों से उपजे उथल-पुथल के बावजूद
जून 1984 में, कुछ हफ्तों बाद, जुलाई और अगस्त 1984 में, कांग्रेस के बाबा लोगों ने विधिवत निर्वाचित विपक्ष को अस्थिर करने का प्रयास किया।
श्रीनगर में अब्दुल्ला की सरकार और एन. टी. रामाराव की सरकार में
हैदराबाद। कश्मीर में, उन्होंने जी के नेतृत्व वाले एक अलग गुट का समर्थन किया।
एम. शाह, जो फारूक अब्दुल्ला के बहनोई थे। आंध्र प्रदेश में

प्रदेश में, कांग्रेस ने एन. भास्कर राव का समर्थन किया, जिन्होंने पार्टी से अलग होकर पार्टी बदल ली।
एनटीआर से। दोनों ही मामलों में तकनीक एक ही थी।
दलबदल को प्रोत्साहित करना और राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करना
कांग्रेस समर्थित प्रतिद्वंद्वी सरकार स्थापित करें। दोनों ही कार्रवाईयां
इन आयोजनों को राजीव गांधी, अरुण नेहरू और उनकी टीम ने आयोजित किया था।
दो विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने के लिए
भारत के सीमावर्ती राज्य में इसके नतीजों के साथ ऑपरेशन ब्लूस्टार एक
यह एक निरर्थक कदम था। लेकिन इंदिरा गांधी एक ऐसी व्यवस्था लागू कर रही थीं जो...
जनवरी 1985 में होने वाले आम चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र—
वह पूरे देश में हिंदुओं के गुस्से को भुनाने की उम्मीद कर रही थी। उसने यह भी किया।
वे अधिक से अधिक राज्यों में सरकारी तंत्र पर नियंत्रण करना चाहते थे।
आम चुनाव में भाग लेने के समय जितना संभव हो सके। शुरुआत तक
1984 में, उन्हें यह आभास हो गया था कि अगले चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाएगा।
चुनाव में उन्हें किसी भी तरह जीतने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना पड़ा।
31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या ने सब कुछ बदल दिया।
इसके बाद दिसंबर 1984 में हुए चुनाव एक अप्रत्याशित घटना साबित हुए।
स्तब्ध राष्ट्र द्वारा शहीद नेता को दी गई श्रद्धांजलि। यह एक 'सहानुभूति वोट' था—
उन्होंने अपने बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक शानदार शुरुआत दी।

चतुर्थ

1984 में, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, मैं योजना बना रहा था...
अरुण नेहरू ने मुझसे गर्वपूर्वक कहा, ‘कांग्रेस। मेरी रणनीति यह थी कि...’
मुख्य विपक्षी नेताओं में से 8 से 10 को निशाना बनाएं। इसलिए हमने माधवराव को चुना।

Scindia vs Vajpayee, Amitabh Bachchan vs H. N. Bahuguna, C. K. Jaffer
शरीफ बनाम जॉर्ज फर्नांडीस।
उन्होंने और अरुण सिंह ने राजीव को मौके का फायदा उठाने के लिए मना लिया था।
गर्मी बहुत थी। उन्होंने गुस्से और तनाव के चलते तत्काल चुनाव कराने का फैसला किया।
लोगों के मन में दुख अभी भी ताजा था—और 1985 की शुरुआत तक इंतजार नहीं करना पड़ा।
जब मतदान होने वाला था।
राजीव गांधी ने अपने संयम और व्यवहार से देश की सहानुभूति हासिल कर ली थी।
इंदिरा गांधी के उन तीन दिनों के दौरान उन्होंने जो गंभीरता दिखाई थी
शव तीन मूर्ति हाउस में रखा हुआ था। अपने गरिमामय व्यवहार के साथ, उन्होंने
जब वह अपनी मां के पास खड़ा था, उन घंटों में ही उसने आधा चुनाव जीत लिया था।
और फिर शव का अंतिम संस्कार किया गया।
राजीव ने अथक प्रचार किया। पूरे नवंबर और
उसी साल दिसंबर में, उन्होंने देश भर में टेढ़े-मेढ़े रास्तों से यात्रा की और 19,000 किलोमीटर की दूरी तय की।
बारह दिनों में पंद्रह राज्यों में किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दस बैठकों को संबोधित किया।
एक ही दिन में। उन्होंने हर रैली में कमोबेश एक जैसा ही भाषण दिया।
मार्मिक और सुव्यवस्थित रचना में इंदिरा के जीवन का व्यक्तिगत वृत्तांत समाहित था।
इसमें गांधी जी की दुखद मृत्यु का जिक्र है। और यह सब व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
“उनकी हत्या उन लोगों ने की जो भारत को टुकड़ों में बांटने की उम्मीद रखते थे…”
आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि सभी लोग एकजुट होकर भारत की एकता की रक्षा करें।
और ईमानदारी।
लेकिन, 19 नवंबर 1984 को, जो उनकी मां का जन्मदिन था, उन्होंने
उन्होंने दांव बढ़ाने का फैसला किया। पटकथा को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था और

इसका उद्देश्य आक्रोशित हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करना था। उन्होंने वस्तुतः इसका समर्थन किया।
इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुए सिख विरोधी हत्याकांड।
राजीव ने कहा, 'जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती कांप उठती है'—यह सुझाव देते हुए कि
सिख विरोधी दंगे उस हत्या की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थे।
उसे इस सजा को भुलाने में लंबा समय लगेगा।
पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, नारे हवा में गूंजते रहे—'राजीव गांधी'
ka ailan, nahin banega Khalistan (Rajiv Gandhi has made it clear that
खालिस्तान नहीं होगा।
यह पहले राजनीतिक विज्ञापन अभियान का विषय था जिसे जारी किया गया था।
रेडिफ़्यूज़न द्वारा जारी किया गया, जो मुंबई स्थित एक विज्ञापन फर्म है जिसे इसे जारी करने के लिए नियुक्त किया गया था।
1984 में 100 मिलियन डॉलर के चुनावी अभियान के लिए एक साथ मिलकर काम किया गया। इसने मतदाताओं को चेतावनी दी कि
अगर पंजाब संकट को अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो भारत का विभाजन हो जाएगा।
'अरुण नेहरू के पुनर्वितरण में शामिल मित्रों द्वारा निर्मित...', पूर्व
पत्रकार रघुनाथ ए.एस. ने बाद में लिखा, 'अभियान में चित्रित किया गया था
सिखों को दुश्मन के रूप में देखना।
हालांकि, नेहरू ने इसे 'हमारे द्वारा लड़ा गया सबसे घटिया चुनाव' कहा।
एक लाख से अधिक (₹) प्राप्त हुए। पूरे चुनाव में इससे अधिक खर्च नहीं हुआ।
नेहरू ने मुझे बताया, '12-13 करोड़ रुपये।'
जब राजीव गांधी ने चुनाव प्रचार शुरू किया, तो लोगों ने एक विशिष्ट बदलाव देखा।
उस व्यक्ति में बदलाव आ गया था जिसने चार साल पहले तक एक शांत जीवन व्यतीत किया था।
पत्रकार सुनील सेठी ने लिखा, 'आरामदायक सुस्ती का दौर अब बीत चुका है।'
लोगों के साथ संकोचपूर्ण व्यवहार, या दोहरी ठुड्डी के शुरुआती लक्षण।
यह निश्चित रूप से दृढ़ निश्चयी, जुझारू और आत्मविश्वास से भरे राजीव गांधी थे।

साथ ही, यह राजीव उस राजीव से बिल्कुल अलग था जिसने उसके लिए प्रचार किया था।
जनवरी 1983 में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हुए राज्य चुनावों में पार्टी ने भाग लिया।
प्रदेश में—राजनीतिक स्वतंत्रता या मेहनत के महत्व जैसी अमूर्त अवधारणाओं को भ्रमित श्रोताओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा था। कांग्रेस हार चुकी थी।
दोनों राज्य।
1984 के आम चुनाव में विपक्ष के सभी दिग्गज नेता हार गए।
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 85 लोकसभा सीटों में से 84 सीटें जीतीं। पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया।
लोकसभा की 404 सीटों के अभूतपूर्व बहुमत के साथ सत्ता में आए।
514 सीटों पर चुनाव हुए। पिछले चुनावों के बाद यह संख्या बढ़कर 414 हो गई।
असम और पंजाब में मतदान में देरी हुई, जबकि 1985 में मतदान हुआ था। यहां तक कि राजीव का भी नहीं।
मेरे दादा जवाहरलाल नेहरू ने इससे भी बेहतर प्रदर्शन किया था।
■

तूफान के केंद्र में बैठा व्यक्ति 1, सफदरजंग रोड पर चुपचाप बैठा था, जब
28 दिसंबर 1984 को परिणाम घोषित हुए, जिनमें भारी बहुमत से जीत दर्ज की गई।
कांग्रेस। वह स्लैक्स पहने हुए टोस्टेड सैंडविच चबाते हुए बैठा था।
प्यूमा के स्नीकर्स और चमड़े के पैच वाला एक स्मार्ट हरा स्वेटर।
वह प्रधानमंत्री के रूप में 1, सफदरजंग रोड स्थित अपने घर में ही ठहरते रहे थे।
रेस कोर्स रोड स्थित 7 नंबर के मकान का निर्माण कार्य अभी भी जारी था। राजीव गांधी
बाहर मची हलचल का ज़रा भी असर उस पर नहीं दिखा। वह एक राजीव था जिसने
सफेद कुर्ता-पायजामा पहने इधर-उधर भागती हुई आकृति से वह बिलकुल अलग थी।
नवंबर में चुनाव प्रचार के उन कठिन हफ्तों के दौरान देश
और दिसंबर 1984।

सभी तरफ से बधाई के फोन लगातार आ रहे थे।
देश के कोने-कोने में। राजीव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी चिढ़ाया।
भजनलाल को राज्य द्वारा लोकसभा में भेजी गई 10 सीटों में से 11 सीटें न मिलने पर आपत्ति जताई गई।
सभा! जब एक आगंतुक ने राजीव को उस जीत के लिए बधाई दी जो न तो
राजीव ने टिप्पणी की कि न तो उसकी मां और न ही उसके दादाजी समय दर्ज कर पाए थे।
विनम्रता से, 'मैं क्या कह सकता हूँ?' उन पलों में, वह पड़ोस का लड़का था—
इसके बाद के दिनों में राजनीतिक रूप से सही माने जाने वाले राजीव का व्यक्तित्व सामने आने लगा।
■

31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
दूसरी बार। उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया था।
सीपीपी। इस बार अरुण नेहरू को अपने चचेरे भाई के लिए पैरवी नहीं करनी पड़ी;
यह तो तय था कि वह फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे।
यह समारोह राष्ट्रपति भवन के उसी अशोक हॉल में आयोजित किया गया था।
भवन, अपनी जगमगाती झूमरों के नीचे, जहाँ उन्होंने गंभीर भाव से कदम रखा था।
अपनी मां की हत्या के दो महीने बाद उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी।
अब राजीव पहले से कहीं अधिक उत्साहित नजर आ रहे थे।
कांग्रेस उत्साहित थी।
राजीव के शांत स्वभाव वाले, मूंछों वाले दोस्त अरुण सिंह पहली पंक्ति में बैठे थे।
गांधी परिवार के साथ। उन्हें पहले ही राज्यसभा में लाया जा चुका था।
नवंबर में सभा में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया, एक पद
अठारह वर्षों के अंतराल के बाद पुनर्जीवित, एक के बराबर शक्तियों के साथ
उप प्रधानमंत्री। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, जिन्होंने चुनाव जीता था।
इलाहाबाद से सांसद, मेहमानों के बीच बैठे अपने करीबी दोस्त को देख रहे थे।
शपथ लेना।

अरुण नेहरू, जिन्हें मंत्रालय में कनिष्ठ मंत्री बनाया गया था।
सत्ता के धनी, हालांकि उनकी शक्तियां उनके पदनाम से कहीं अधिक थीं।
वह नए मंत्रियों की पीठ थपथपाते हुए खुशी से झूम रहा था। उसने लगभग 'सत्ता से बेदखल' कर दिया था।
विदेश मंत्रालय के पूर्व सम्मानित अधिकारी नटवर सिंह को जमीन पर गिरा दिया गया; कुंवर नटवर सिंह को कनिष्ठ मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना था!
पिछले कुछ घंटों में, दोनों अरुण राजीव के साथ बैठे हुए थे और ध्यान से पढ़ रहे थे।
मंत्रिमंडल में कौन होगा और कौन नहीं, यह तय करने के लिए नामों की सूची पर विचार किया गया।
वे इससे बाहर हो जाएंगे।
आम धारणा के विपरीत, नेहरू, हालांकि तीसरे चचेरे भाई थे,
वह वास्तव में राजीव का 'दोस्त' नहीं था।
मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें प्रधानमंत्री आवास पर किसी से मिलने आते देखा हो।
राजीव और सोनिया, या तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में या राजीव के बाद 'प्रधानमंत्री बने,' राजीव के मित्र विवेक भरत राम ने याद करते हुए कहा।
मैंने अरुण सिंह को घर पर उनसे मिलने आते देखा। राजीव और सोनिया के पास प्रधानमंत्री आवास के दाहिनी ओर के कमरे।
राजीव और अरुण सिंह का रिश्ता कई सालों पुराना था। वे साथ-साथ थे।
डून स्कूल और बाद में कैम्ब्रिज में।
‘अरुण सिंह प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के प्रति सम्मानजनक थे, लेकिन अरुण
पत्रकार बी. एन. उनियाल ने याद करते हुए कहा, 'नेहरू विनम्रता से बहुत दूर थे।' एक बार
संसद में प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर राजनेताओं का एक समूह इंतजार कर रहा था।
उनियाल ने याद करते हुए बताया कि राजीव के बाहर आने पर, जब वह बाहर आया, तो सभी लोग खड़े हो गए।
केवल नेहरू ही बैठे रहे।
अरुण नेहरू ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें संबोधित करने का विशेष महत्व दिया था।
सहकर्मियों और अधिकारियों के सामने उनका पहला नाम। बाद में, जब उपराष्ट्रपति...

जब सिंह 1989 में प्रधानमंत्री बने, तो वे उन्हें इस तरह संबोधित करते थे।
विश्वनाथ। इससे जनता दल के कई नेता प्रभावित होंगे।
राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे दिग्गज बहुत असहज थे। ऐसा नहीं था।
यह उनके द्वारा लाई गई कॉर्पोरेट संस्कृति का मात्र प्रतिबिंब था। लोगों ने इसे नेहरू द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और दबदबा कायम करने के प्रयास के रूप में देखा।
नेता से उसकी निकटता का फायदा उठाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना।
एक बार जब नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीपत मिश्रा को संबोधित किया था
as Sripat, Mishra politely put him in his place. 'Arunji, kuch toh umar
ka lihaz kariye (Arunji, have some respect for age).'
राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, अरुण सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई।
प्रधानमंत्री के बंगले के बगल में, रेस कोर्स रोड नंबर 1 पर स्थित बंगला। वहाँ केवल एक ही कमरा था।
दो घरों को अलग करने वाला एक छोटा सा फाटक। दोनों दोस्तों के बीच सहज संबंध थे।
दोनों के बीच अच्छी जान-पहचान थी। उनकी पत्नियां, सोनिया और नीना सिंह, भी आपस में खूब घुलमिल गईं।
(बाद में उनके बीच अनबन हो गई।)
31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी ने अपने कार्यक्रम में बदलाव करने का निर्णय लिया था।
कैबिनेट; इसमें अनुभवी और नए चेहरों का मिश्रण था।
राजीव ने सावधानीपूर्वक सत्रह पोर्टफोलियो अपने पास रखे। सबसे बड़ा पोर्टफोलियो प्रणब मुखर्जी को पद से हटाए जाने पर सभी को आश्चर्य हुआ, जिन्हें राजीव गांधी ने अपने पास बनाए रखा था।
अपने पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में। 'मैं [उस] कॉल का इंतजार करता रहा।
'यह जानकारी प्रधानमंत्री की ओर से आई है', मुखर्जी ने बाद में कहा।
कई लोगों को आश्चर्य हुआ जब कनिष्ठ वी. पी. सिंह वित्त मंत्री बन गए।
इसके बजाय मंत्री बनें। इंदिरा गांधी के जीवित रहते हुए, वह चाहती थीं कि

उपराष्ट्रपति बनें।
उन्होंने राजीव की टीम का हिस्सा बनने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी साफ-सुथरी छवि एक संपत्ति साबित होगी। वीपी
वह श्रीमती गांधी और उनके परिवार के अटूट समर्थक थे, यहाँ तक कि
जब वे अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। यह अरुण नेहरू ही थे जिन्होंने
उन्होंने मुखर्जी को दृढ़तापूर्वक बाहर रखा—वे मुखर्जी को अपने लिए खतरा मानते थे।
राजीव। गृह मंत्री के पद के लिए एस. बी. चव्हाण का चयन भी दर्शाता है।
नेहरू की मुहर। एक सहज और लचीले व्यक्ति को मंत्रालय देना।
मंत्री का तात्पर्य प्रधानमंत्री से था—या जो भी उनकी ओर से कार्य करता था।
नेहरू की तरह—पंजाब के मामलों में उनकी सीधी भूमिका होगी और
कश्मीर। जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि नेहरू ही वह व्यक्ति होंगे जो कश्मीर का नेतृत्व करने वाले हैं।
सत्ता के पीछे की शक्ति। कुछ ही हफ्तों में, उन्हें सत्ता के पीछे के कर्ता-धर्ता के रूप में देखा जाने लगा।
तथ्य: प्रधानमंत्री।
हालांकि, उन शुरुआती दिनों में वे विद्युत राज्य मंत्री थे,
राजीव के गुट में सबसे अधिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति। और उसके पास यह शक्ति थी।
प्रधानमंत्री के कान में।
■

राजीव गांधी के नए मंत्रिमंडल ने सुर्खियां बटोरीं। विशेष रूप से वी. की नियुक्ति ने।
पी. सिंह को वित्त मंत्री बनाया जाना भी उतना ही चौंकाने वाला था। लेकिन आर. के. धवन को भी दरकिनार कर दिया गया, जो वर्षों तक इंदिरा गांधी के शक्तिशाली निजी सचिव और उनके खास आदमी रहे थे।
फ्राइडे—जिन्हें बिना किसी औपचारिकता के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अगर ऐसा होता तो
गांधी के बाद कांग्रेस हलकों में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति

परिवार में, धवन ही थे। उनके बाहर होने के बाद, राजीव अधिक आत्मविश्वासी होकर सामने आए।
सबसे पहले, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दम पर खड़ा हो सके।
1 जनवरी 1985 को, आर. के. धवन 1, सफदरजंग रोड पर गाड़ी चलाकर गए, क्योंकि वे
वह आम तौर पर हर सुबह यही करता था। अविवाहित होने के कारण, उसका दिन इसी तरह शुरू होता था।
यह कार्यक्रम जल्दी शुरू हुआ और इंदिरा गांधी के दिन का काम समाप्त करने के बाद समाप्त हुआ।
उसकी परछाईं में, वह अपार शक्ति का प्रयोग करता था, उसके प्रति पहुंच को नियंत्रित करता था।
दरबार में उपस्थित रहना और प्रधानमंत्री के आदेश पर संवेदनशील राजनीतिक कार्य करना।
उनकी ओर से। वह कुछ उद्योगपतियों के तीव्र उत्थान के लिए जिम्मेदार थे।
कटी हुई काली मूंछों, करीने से कंघी किए हुए काले बालों और चमकते हुए
काले जूते पहने, लगातार सिगरेट का कश लगाते हुए, उसने अपनी यात्रा शुरू की थी।
एक स्टेनोटाइपिस्ट के रूप में, जिसे प्रधानमंत्री के चचेरे भाई यशपाल द्वारा उनके घर में लाया गया था।
कपूर, एक गोल-मटोल दिखने वाला पंजाबी लड़का। इंदिरा ने कपूर को अपने पास रखने का फैसला किया।
धवन, और बाद में एम. एल. फोतेदार उनके निजी/राजनीतिक सहायक के रूप में नियुक्त हुए।
सिविल सेवाओं के लोगों, जैसे पी. एन. हक्सर या पी. की तुलना में उन्हें प्राथमिकता देना।
एन. धर, जिन्हें उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में चुना था।
जब प्रधानमंत्री के आवास के द्वार उनकी कार के लिए नहीं खुले,
धवन ने गार्डों पर चिल्लाते हुए पंजाबी में अपशब्दों का प्रयोग किया। लेकिन
उनके पास निर्देश थे; उन्होंने उसे अपनी कार बाहर छोड़ने के लिए कहा और
रिसेप्शन की ओर चलें। गुस्से में धवन ने अपनी कार रिसेप्शन के बाहर खड़ी कर दी।

सामने की ओर जिमखाना क्लब था और वह अंदर चला गया। जब वह
उन्होंने प्रधानमंत्री और स्वागत कक्ष के कर्मचारियों से बात करने की मांग की।
जो वर्षों से उसके आदेशों का पालन करता आ रहा था, उसने उसे कड़े शब्दों में कहा कि उसे चले जाना चाहिए।
घर वापस जाकर प्रधानमंत्री को फोन करो।
धवन को बाहर कर दिया गया। उन्हें अपने कागजात भी ले जाने की अनुमति नहीं दी गई।
या फिर उनके कार्यालय में मौजूद सामान या पैसा। बाद में उन्हें पैक कर दिया गया।
और उसे भेज दिया गया। नाथू राम जैसे अन्य कर्मचारी, जो इंदिरा थे।
गांधी जी के सेवक थे और शहर में होने वाली हर गतिविधि के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी।
प्रधानमंत्री आवास को भी उन्हें वापस भेज दिया गया। इंदिरा गांधी ने उन पर इतना भरोसा किया था कि उन्हें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी।
उसके बेडरूम की चाबियां।
'यह सोनिया गांधी ही थीं जिन्होंने फैसला किया कि वे बहुत ज्यादा शक्ति का प्रयोग कर रहे थे'
पत्रकार पंकज ने खुलासा किया, 'प्रधानमंत्री आवास में सत्ता में बैठे लोगों को जाना चाहिए।'
वोहरा, जिन्होंने उस दौर की राजनीति को कवर किया था और दोनों को जानते थे
धवन और फोतेदार का तालमेल अच्छा रहा। धवन का जाना फोतेदार के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ।
नेहरू। इससे उन्हें प्रधानमंत्री आवास पर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिली।
यह बात सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है कि आर. के. धवन, जो बने रहे थे
इंदिरा गांधी के प्रति शुरू से वफादार रहने के बावजूद, उन्होंने मुखबिर बनने पर विचार किया था।
1977 में। यह उनके सत्ता से बाहर होने के बाद हुआ था, और शाह
आयोग उनके, संजय और धवन के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रहा था।
एक सुबह कांग्रेस के दिग्गज नेता सीताराम केसरी ने जनता पार्टी को फोन किया।
पार्टी सांसद कृष्ण कांत। कांत तब तक कांग्रेस छोड़ चुके थे।

आपातकाल का विरोध किया।
‘धवन आपसे मिलना चाहता है,’ केसरी ने कांत से कहा। ‘मैं उसे भेज रहा हूँ।’
धवन चलकर 2, टेलीग्राफ लेन स्थित कांत के घर की ओर गए।
पास ही में स्थित उनके भाई के घर में, जहाँ वे उस समय रह रहे थे। धवन चाहते थे कि
कांट जनता नेतृत्व को यह संदेश देना चाहते थे कि वे बदलाव लाना चाहते हैं।
अनुमोदक।
‘ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचना भी मत,’ कांट ने उसे सलाह दी, ‘तुम पर एक कर्ज है।
उसके लिए बहुत मायने रखता है।
उन्होंने कहा, ‘जल्दबाजी मत करो, यह सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली।’
बहुत लंबा।
धवन ने इस मामले को दोबारा नहीं उठाया।
धवन का मानना था कि उनके जैसा निजी सचिव पहले कभी नहीं हुआ था।
एक बार जब पंकज वोहरा उनसे उनके 141, गोल्फ लिंक्स स्थित घर पर मिलने गए थे
घर में जाकर, उन्होंने उसे नवीनतम राजनीतिक गपशप से अवगत कराया।
कांग्रेस में अहमद पटेल की बढ़ती शक्ति के बारे में, यह था
2008 में किसी समय—धवन ने पंजाबी में गाली दी, अपना
व्हिस्की एक ही घूंट में पी ली और बड़े ही सख़्त अंदाज़ में कहा: 'ऐसा कभी नहीं हो सकता'
आर. के. धवन जितना शक्तिशाली कोई नहीं।
लेकिन 1984 के बाद, सर्वशक्तिशाली आर. के. धवन का करियर समाप्त हो गया।
1984-87 के दौरान प्रधानमंत्री आवास में राजीव गांधी का प्रभाव बढ़ा, जिसके बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए काम करना शुरू किया।
फोतेदार को इस्पात और खान मंत्रालय में भेज दिया गया ताकि उसे इस स्थिति से बाहर निकाला जा सके।
इस तरह। उनकी जगह राजीव ने विंसेंट जॉर्ज को अपना निजी सहायक नियुक्त किया।

सचिव।

■

जब राजीव गांधी ने 1985 में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, तो निराशावाद
और वह अस्थिरता जिसने इंदिरा गांधी के शासन के अंतिम वर्षों को चिह्नित किया था
ऐसा प्रतीत होता था कि यह अतीत की बात बन गई है। देश के सबसे युवा के रूप में
मात्र चालीस वर्ष की आयु में, अब तक के सबसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वादा किया
राजनीतिक स्थिरता और आशा। जब उन्होंने अतीत से नाता तोड़ने का संकेत देना शुरू किया, भले ही वे स्वयं उस अतीत का हिस्सा रहे हों, लोगों ने उन पर विश्वास किया।
थका हुआ राष्ट्र आगे बढ़ने के लिए तैयार था।
अपने कार्यकाल के शुरुआती कुछ महीनों में राजीव गांधी से कोई गलती नहीं हो सकती थी।
प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके पहले कार्यों में से एक दलबदल विरोधी कानून लागू करना था।
जनवरी 1985 में बड़े पैमाने पर दलबदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया।
एक पार्टी से दूसरी पार्टी में सांसदों का स्थानांतरण—जिसे बाद में 'आया' के नाम से जाना जाने लगा
'राम, गया राम' की अवधारणा—चाहे व्यक्तिगत लाभ के लिए हो या राजनीतिक लाभ के लिए—
भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप बन गए हैं।
1985 के दौरान, राजीव गांधी ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए—
पंजाब और असम में—और 1986 में मिजोरम में भी एक और ऐसा ही हुआ।
इनमें से तीन सीमावर्ती राज्य थे और विद्रोह से बुरी तरह प्रभावित थे।
हिंसा। पंजाब 1970 के दशक के उत्तरार्ध से ही उग्रवाद की चपेट में था।
जो आगे चलकर खालिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र के लिए आंदोलन में बदल गया।
असम में छात्रों के नेतृत्व में विदेशी विरोधी आंदोलन ने हलचल मचा दी थी।
युवाओं को बांग्लादेश से अवैध रूप से आए विदेशियों को निर्वासित करने का आदेश

दिया गया है।
मिजोरम में लंबे समय से जारी विद्रोह की समस्या बनी हुई थी।
सोलह वर्ष। राजीव गांधी का मिजोरम पर समझौता, जब विद्रोहियों ने
मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने अपनी स्वतंत्रता की मांग छोड़ दी।
यह उनकी सबसे स्थायी विरासतों में से एक साबित हुई; यह मार्ग प्रशस्त करने के लिए थी।
राज्य में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।
राजीव गांधी ने सैम के नेतृत्व में छह प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किए।
पिट्रोडा। ये पेयजल, टीकाकरण, साक्षरता आदि विषयों पर थे।
तिलहन और दुग्ध उत्पादन। यह छठा था,
दूरसंचार, जिसका सबसे व्यापक प्रभाव पड़ा।
दूरदराज के इलाकों में भी कॉल ऑफिस बूथ तेजी से बढ़ने लगे।
देश का वह हिस्सा जो भारत के गांवों को दुनिया से जोड़ता है। 1986 में, राजीव का
सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) की स्थापना की
जिससे टेलीफोन की पहुंच का विस्तार हुआ। इसके बाद, रेलवे आरक्षण।
कंप्यूटरीकृत हो गए थे। इन सबने मोबाइल टेलीफोनी की नींव रखी।
इसने आम भारतीयों के जीवन को ऐसे तरीकों से बदल दिया जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
जैसा सोचा था। शहरों में काम करने वाले लोग अब रोजाना बात कर सकते थे।
अपने प्रियजनों से गांवों में मिलने के बजाय, उनसे मिलने के लिए वे ऐसा करते हैं।
दो साल।
1988 में, राजीव गांधी ने मतदान की आयु इक्कीस से घटाकर कर दी थी।
अठारह वर्ष के युवाओं को संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से अधिकार प्रदान किया गया।
लोगों को राजनीति को आकार देने का मौका दिया। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की।
पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय सरकारों को अधिक स्वायत्तता देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देना। राजीव गांधी के शासनकाल में ये विधेयक पारित नहीं हो सके।
गांधी जी के कार्यकाल में इन्हें लागू किया गया था। ये पी.वी. नरसिम्हा राव के

शासनकाल में अधिनियमित किए गए थे।
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार प्रधानमंत्रित्व काल
और संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992—और
स्थानीय सरकारों में एक तिहाई पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।
औरत।
इन वर्षों में, इसने उन महिलाओं का एक समूह बनाने में मदद की, जिनके पास
स्थानीय सरकारों में शासन का अनुभव प्राप्त किया था—और थे
एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार। यह राजीव गांधी की एक और बड़ी उपलब्धि होने वाली थी।
अमिट विरासतें—और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
जबकि राजीव गांधी ने खुलेपन की दिशा में पहला कदम उठाया था।
अर्थव्यवस्था के मामले में, उनके कार्यकाल के दौरान हुए अत्यधिक खर्च के कारण ही संतुलन बिगड़ा।
भुगतान संकट जिससे पी.वी. नरसिम्हा राव को निपटना पड़ा था
1991 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के कुछ ही घंटों बाद, राजीव ने भी मंजूरी दे दी थी।
भारत को परमाणु परीक्षण के लिए तैयार करने के उद्देश्य से आगे की कार्रवाई की गई; अंततः इसे अंजाम दिया गया।
अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1998 में। सबसे बढ़कर, राजीव गांधी ने आगे बढ़ने की कल्पना की थी।
भारत इक्कीसवीं सदी में एक आधुनिक, वैज्ञानिक रूप से उन्मुख देश के रूप में प्रवेश कर रहा है।
प्रौद्योगिकी में निपुण और भविष्योन्मुखी राष्ट्र।
राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में दो मुद्दे दागदार साबित हुए। पहला मुद्दा यह था कि...
1985 में शाह बानो फैसले को संभालने का उनका तरीका। दूसरा था...
1987 के मध्य में बोफोर्स बंदूक सौदा, जिसमें राजीव और उनसे जुड़े अन्य लोग शामिल थे,
उन पर स्वीडिश बोफोर्स की बिक्री में रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था।

भारतीय सेना को हॉवित्जर। भारतीय राजनीति के 'मिस्टर क्लीन' के रूप में, राजीव गांधी
हथियारों के व्यापार को साफ करने और आयोगों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था।
सत्ता में आने के बाद उन्होंने हथियारों के सौदे किए। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला।
राजीव को किसी भी गलत काम में सीधे तौर पर फंसाना, उसके परिवार के संबंध
कुछ बिचौलियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है—जैसे कि इतालवी
व्यवसायी ओटावियो क्वात्रोची की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया। वी. पी. सिंह
1989 के आम चुनाव के दौरान उन्होंने बोफोर्स मामले पर उन पर लगातार हमले किए।
जिसमें राजीव हार गया।
लेकिन शाह बानो मामले की गलतियों ने ही इस पर गहरा असर डाला।
देश। उनके कार्यों के परिणाम राजीव के जीवनकाल से कहीं अधिक समय तक जीवित रहेंगे।
प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल।
वी
हर साल की तरह, 15 अगस्त 1985 का दिन भी गर्म और उमस भरा था।
दिल्ली में। लेकिन राजीव गांधी लाल किले की प्राचीरों पर चढ़े।
स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के लिए वह पूरे उत्साह से कदम बढ़ा रहा था। उसने अपनी माँ को यह सम्मान करते हुए देखा था।
वर्षों बाद। उनके लिए यह पहली बार था। जब युवा प्रधानमंत्री बोल रहे थे,
उन्होंने आशावाद का ऐसा स्वर अपनाया जो पूरे देश में गूंज उठा।
शाम को राजीव ने एक और उपलब्धि अपने नाम की—और वह थी...
अखिल असम छात्र संघ के नेताओं के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए।
केंद्र सरकार और अखिल असम गण संग्राम परिषद। पांच साल तक, उन्होंने
वह 'अवैध' अप्रवासियों के निर्वासन के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।
बांग्लादेश से आए हुए लोग जो असम आए थे और वहीं बस गए थे।

वर्षों। समझौते का उद्देश्य पहचान संबंधी मुद्दों को हल करना था।
पूर्वोत्तर राज्य में आंदोलन के कारण। एक महीने पहले, जुलाई में, उन्होंने
सिख नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
पंजाब में इस जटिल समस्या का समाधान करें।
युवा प्रधानमंत्री को गुप्त और नाटकीय घटनाओं में बहुत आनंद आता था, और
वह अक्सर रात्रिकालीन बैठकें बुलाता था जो उसके निर्णयों का हिस्सा थीं।
निर्माण प्रक्रिया।
समझौते पर हस्ताक्षर होने से एक दिन पहले, राजीव गांधी ने अरुण को फोन किया।
नेहरू ने रात के 2 बजे कहा, 'आओ मेरे साथ एक कप कॉफी पी लो। हम...'
'असम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में,' उसने अपने चचेरे भाई को उत्साह से बताया।
नेहरू उनसे मिलने गए थे।
‘राजेश पायलट ने समझौता करवा दिया है।’ राजीव बहुत खुश नजर आए।
ख़ुद के साथ।
उन्होंने खुशी से कहा, 'गृह मंत्री को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था।'
मुझे इसके बारे में बाद में पता चला।’ बाद में, 1990 के दशक में, पी. वी. नरसिम्हा ने यही कहा।
राव ने भी ऐसा ही किया—उन्होंने कश्मीर और अयोध्या में राजेश पायलट का इस्तेमाल किया, और उनकी रणनीति में बदलाव किया।
चव्हाण को हटा दिया गया, जो फिर से गृह मंत्री थे और अन्यथा काफी करीबी थे।
राव।
15 अगस्त 1985 को, उत्साहित असमिया नेता प्रधानमंत्री के यहाँ एकत्रित हुए।
इस घर में प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ-साथ अन्य लोग भी मौजूद थे; उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।
इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनें। उनके लिए परोसी गई पारंपरिक चाय के बाद।
मेहमानों के सामने, उत्साहित राजीव गांधी ने वही किया जो होना चाहिए था।
किसी भी प्रधानमंत्री के लिए यह एक सामान्य बात है कि वह किसी को निर्देश दे।
कनिष्ठ मंत्री। लेकिन उस निर्देश का उद्देश्य उन ताकतों को सक्रिय करना था जो
चार साल बाद उनकी सरकार को पराजित कर दिया।

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, एस. बी. चव्हाण और वहाँ से जाने के बजाय,
गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री भवन में वापस चले गए।
चव्हाण के डिप्टी आरिफ मोहम्मद खान भी उस समूह का हिस्सा थे।
मेहमानों को विदा करने के बाद राजीव के वापस आने का इंतजार किया।
जैसे ही सब लोग बैठ गए, राजीव ने खान से पूछा, 'आपका क्या विचार है?'
शाह बानो (फैसले) पर राय? हालाँकि शाह बानो विवाद
देश में तीन महीने से अधिक समय से अशांति फैली हुई थी, और खान एक
राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में मुस्लिम मंत्री होने के बावजूद उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं कहा था।
यह उन कई अन्य मुस्लिम मंत्रियों से अलग था जिन्होंने इस बात को कभी छिपाया नहीं था।
फैसले के प्रति उनके विरोध के कारण।
खान को आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री ने अचानक उनसे उनकी जानकारी क्यों मांगी।
राय। क्या उन्होंने चव्हाण से अपने विचारों के बारे में सुना था?
कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री ने अपने यहाँ एक बैठक बुलाई थी।
नॉर्थ ब्लॉक में स्थित कार्यालय में। वह सरकार की योजनाओं पर चर्चा करना चाहते थे।
शक्तिशाली लोगों द्वारा फैसले की आलोचना का जवाब दिया जाना चाहिए।
मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्ग।
यह मुद्दा जी.एम. बनातवाला, जो कि सांसद हैं, के साथ विवाद में फंस गया था।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग (एआईएमएल) द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक पेश करते हुए
मई की शुरुआत में लोकसभा में। एआईएमएल सत्तारूढ़ दल की सहयोगी थी।
केरल में कांग्रेस। यह एक दक्षिणपंथी पार्टी थी जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी।
मुसलमानों के हितों को बढ़ावा देना। बनातवाला भी उनमें से एक थे।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के प्रमुख सदस्य,
मुसलमानों का एक गैर-सरकारी संगठन, जिसकी स्थापना 1973 में यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि
मुस्लिम समुदाय द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन जारी रहा।

1937 में, अंग्रेजों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ नामक एक कानून लागू किया था।
(शरिया) आवेदन अधिनियम, 1937, के तहत आवेदन की व्यवस्था करने हेतु
मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून। धर्म पर आधारित, यह कानून कई मामलों से
संबंधित था।
जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और अभिरक्षा।
बच्चे। शरीयत अधिनियम के अस्तित्व में आने से पहले, भारत में मुसलमान
उन्होंने अपने आयोजन के तरीके में स्थानीय धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन किया।
निजी जीवन।
हालांकि, बनातवाला का विधेयक मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में नहीं था।
देश की दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का प्रस्ताव रखा।
धारा 125 के दायरे से मुसलमानों को बाहर करने के लिए—जिसमें प्रावधान था
बेसहारा लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, जिनमें तलाकशुदा हिंदू भी शामिल हैं।
मुस्लिम महिलाएँ, या माता-पिता या कोई भी व्यक्ति जो देखभाल करने में असमर्थ हो
स्वयं। इसी धारा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने
फैसला सुनाया गया कि शाह बानो को तलाक के बाद भरण-पोषण का भुगतान किया
जाए।
उनके पति बनतवाला ने अपने विरोध को उजागर करना चुना।
निजी सदस्य के विधेयक के माध्यम से निर्णय लेना।
संसद सदस्यों के लिए निजी सामान लाना कोई असामान्य बात नहीं थी।
एक सदस्य का विधेयक सरकार पर दबाव डालने के लिए है ताकि वह एक अधिकारी
को कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो।
इस विषय पर विधेयक। आमतौर पर शुक्रवार को इस पर चर्चा होती है।
दोपहर के समय, इन नोटों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाता था। संयोगवश,
बनातवाला का विधेयक चयनित हो गया और चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया।
इस विषय पर चर्चा कई शुक्रवार की दोपहर तक जारी रही। सभी वक्ताओं ने अपनी
राय व्यक्त की।
इस मुद्दे पर जनता पार्टी के एक सांसद को छोड़कर बाकी सभी सांसद मुस्लिम थे।
1980 के दशक में, यहां तक कि निजी सदस्यों के विधेयकों को भी महत्व दिया गया
था।

सरकार। इसीलिए गृह मंत्री ने बैठक बुलाई थी।
अपने अधिकारियों को बनातवाला के विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए कहें।
अधिकारी इस बात को लेकर आपस में बहस कर रहे थे कि गृह मंत्री को किस चरण में पदभार ग्रहण करना चाहिए।
बहस में हस्तक्षेप करना चाहिए था। अचानक, चव्हाण ने उनकी बात काट दी; वह
खान से उनकी राय पूछी गई। खान, जो तब तक चुप थे,
स्पष्टवादी होने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा, 'बनतवाला जो कह रहे हैं वह सब गलत है, और उनका रुख गलत है।'
यह कुरान के अनुसार नहीं है।
अब खान का ध्यान सब पर था। सबसे पहले, उन्होंने कहा, सीआरपीसी
धारा 125 सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित थी। 'इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है।
व्यक्तिगत कानून से संबंधित, जैसा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है
बोर्ड।' और न ही तलाक के बाद कानून अपने आप लागू हो जाता था। इसे लागू होना पड़ता था।
आर्थिक कठिनाई का सामना करने पर एक महिला द्वारा इसका सहारा लिया जाता था। 1978 में, जब
दंड प्रक्रिया में संशोधन किया गया, संकट में फंसी तलाकशुदा महिला की जिम्मेदारी तय की गई
अगर महिला देखभाल करने में असमर्थ होती तो यह संपत्ति उसके पूर्व पति को सौंप दी जाती थी।
अपने बाद। (माता-पिता के मामले में, यह उत्तराधिकार बेटों को मिलता था।)
हालाँकि, यदि एआईएमपीएलबी के तर्क को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी
भरण-पोषण राशि केवल इद्दत की तीन महीने की अवधि के लिए ही दी जानी चाहिए।
पति को किसी अन्य व्यक्ति को दान देने से रोकने वाली कोई बात नहीं थी।
एक बेसहारा अजनबी, जो आखिरकार उसकी पत्नी रह चुकी थी।
खान ने कुरान की आयतों का हवाला दिया जिनमें कहा गया है कि 'यहां तक कि

तलाक का अवसर, जो विवाह के निरस्तीकरण की घोषणा करता है
रिश्तों में, अच्छाई, विचारशीलता और सद्भावना दिखाने से पीछे न हटें।
रियायत देना एक तरह का पाप था। पैसे के बंटवारे पर आपत्ति करना ईशनिंदा माना जाता था।
किसी जरूरतमंद को दिया गया।
बैठक में उपस्थित अधिकारी प्रभावित हुए।
उन्होंने कहा, 'हमें यह बात पता नहीं थी।'
चव्हाण के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। 'बात तो सही है (आप क्या कह रहे हैं)'
बात समझ में आती है,' उन्होंने कहा।
इसलिए, जब राजीव गांधी ने 15 अगस्त 1985 को खान से उनके विचार पूछे,
खान ने वही बात दोहराई जो उन्होंने पहले चव्हाण से कही थी।
'तो फिर आप संसद में क्यों नहीं बोलते?' प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा।
'मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है,' खान ने जवाब दिया, 'क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया।'
मुझे पता है कि आप इससे कैसे निपटने की योजना बना रहे थे।
'नहीं, नहीं, हम इन लोगों की बातों से सहमत नहीं हो सकते,' राजीव ने कहा।
मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा किए गए विरोध का जिक्र करते हुए,
समुदाय के वर्ग।
बाद में, खान ने कहा, राजीव गांधी ने भी इसी तरह के कड़े शब्दों में लिखा था।
file relating to the issue. 'File pe toh Rajivji ne aur bhi sakht likha hai
(राजीव ने फाइल में जो लिखा था वह और भी कड़ा था), कि कोई समझौता नहीं होगा।
इन कट्टरपंथी तत्वों के साथ बनाया जा सकता है।' राजीव गांधी का पहला
उनकी सहज प्रवृत्ति विधेयक का विरोध करने की थी। वे उदारवादी सोच वाले एक 'आधुनिक' नेता थे।
वे परंपरावादी जो भारत को इक्कीसवीं सदी के लिए तैयार करना चाहते थे।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'चर्चा में सबसे पहले आरिफ हस्तक्षेप करेंगे।'
चव्हाण को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा, 'और आपको उनके बाद बोलना चाहिए।'

■

23 अगस्त 1985 को आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा में हस्तक्षेप किया।
बनातवाला निजी सदस्य विधेयक पर बहस के दौरान उनके शब्द थे।
मेजों को थपथपाकर उनका स्वागत किया गया, क्योंकि उनके समर्थकों ने उनकी बात का समर्थन किया।
शब्द। शाह बानो फैसले का जोरदार बचाव करते हुए, खान
एक 'प्रगतिशील' दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 'हमें बेहतर तौर-तरीके अपनाने चाहिए'
इन दिनों,' उन्होंने कहा। '...केवल दलितों के उत्थान से ही देश का उत्थान हो सकता है।
इस्लामी सिद्धांतों का पालन किया गया और न्याय हुआ, ऐसा कहा जा सकता है।
उनका भाषण समाप्त हो गया था, साथी सांसदों ने कहा कि उन्होंने एक शानदार भाषण दिया था और
उन्हें बधाई देने के लिए तुरंत दौड़ पड़े।
जब खान उस शाम घर पहुंचे, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहां एक
उनका एक पत्र इंतजार कर रहा था। यह प्रधानमंत्री की ओर से था। एक घंटे के भीतर
उनके भाषण के बारे में, यह उनके आधिकारिक आवास पर 3 बजे दिया गया था।
सुनेहरी बाग रोड। 'राजीव ने मेरी कही बातों की दिल खोलकर तारीफ की।'
लोकसभा।' अगले दिन के अखबारों में भी यही खबर छपी।
■

आरिफ मोहम्मद खान तिहरे मुद्दे को लेकर चिंतित थे।
बचपन से ही तलाक के बारे में उनकी जिज्ञासा थी। इस्लाम में तलाक के इस रूप के बारे में उनकी जिज्ञासा एक ऐसी घटना से उपजी जो दस साल की उम्र में उनके साथ घटी थी।
खान उस समय आठवीं कक्षा में पढ़ रहा था। घटना
यह घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित उनकी मां के गांव बस्सी में घटी।
मेरे परिवार में—विस्तृत परिवार में—कुछ घटित हुआ था।

आस-पास के लगभग एक दर्जन गांवों में रिश्तेदारी (रिश्तेदारी) थी—जिनमें
मुझे आश्चर्यचकित किया।'
उन दिनों गांव में, जब ताले इस्तेमाल किए जाते थे
सामने का दरवाजा सुरक्षित था, अगर ताला खुला होता तो खुले हुए ताले
दरवाजे की कुंडी से लटका हुआ छोड़ दिया गया।
एक ग्रामीण ने ताला शब्द का उच्चारण किया था, लेकिन उसके आसपास के अन्य लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
insisted that he had pronounced the word talaq. ‘Woh aadmi yeh kehta
tha ki maine toh taala kaha tha, aur doosre log yeh kehte the ki nahi
tune to talaaq kaha tha (The man said, I have uttered the word taala
लेकिन कुछ अन्य लोगों को यकीन था कि उसने तलाक कह दिया था।
वह आदमी बार-बार दोहराता रहा, 'मेरे हाथ में ताला था और मेरे पास केवल
उसने 'ताला' शब्द का उच्चारण किया। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने जोर देकर कहा कि उसने
had said talaq thrice. He remonstrated, ‘Maine teen baar kaha hai ya
chatees baar kaha hai, maine taala kaha tha (Whether I said it three
मैंने चाहे कितनी भी बार या छत्तीस बार यही शब्द बोला हो, 'लॉक'।
उस व्यक्ति के विरोध के बावजूद, उसे और उसकी पत्नी को मजबूर किया गया
अलग। वे लोग जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने तलाक शब्द सुना था
उन्होंने स्थानीय मुल्लाओं का समर्थन हासिल कर लिया। 'मुझे यह हास्यास्पद लगा,' खान ने कहा।
बाद में, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से दोबारा मिलने की कोशिश की।
तलाक के लिए मजबूर किया गया। खान ने कहा कि कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि एक

patch-up was not possible. ‘Society poora danda leke khadi ho gayi ki
nahi bhai, toone talaq kaha hai (Society stood there with a stick
इस बात पर जोर देते हुए कि उसने तलाक कहा था।
अंततः उस महिला को किसी और से शादी करनी पड़ी।
धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार, इससे पहले कि वह अपने परिवार से पुनः मिल पाती, उसे ऐसा करना पड़ा।
पहला पति।
लोगों को बहुत बुरा लगा। लेकिन किसी ने भी सबके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की।
मुल्लाओं। आरिफ ने कहा, 'मैं इस घटना को कभी नहीं भूला।' इस घटना ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया।
विवाह, तलाक और अन्य संबंधित विषयों पर कुरान में क्या कहा गया है, यह जानने के लिए कुरान का गहन अध्ययन करें।
उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून का अध्ययन किया।
इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए, इस पर लिखी गई टिप्पणियों और व्याख्याओं को पढ़ें।
खान ने पवित्र ग्रंथ का अध्ययन किया और विशेषज्ञों के साथ इसके सिद्धांतों पर चर्चा की। इसलिए जब शाह बानो का फैसला आया, तो खान ने इस पर काफी सोच-विचार कर लिया था।
विषय।
आरिफ मोहम्मद खान द्वारा 23 तारीख को संसद में हस्तक्षेप करने के बाद
अगस्त 1985 में राजीव गांधी पर दबाव बढ़ने लगा। अब
यह विचार मुस्लिम धर्मगुरुओं के शक्तिशाली वर्गों से आया था जिन्होंने इसे देखा था
यह निर्णय समुदाय के व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप है। राजीव
उन्होंने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। उन्होंने मौलाना अबुल के साथ कई बैठकें कीं।

एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष हसन अली नदवी और अन्य
संगठन के प्रतिनिधि। दिलचस्प बात यह है कि एआईएमपीएलबी
इसकी स्थापना इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से हुई थी। उन्होंने इसे एक उपाय के रूप में देखा था।
मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक निष्ठा जीतने के लिए। अली मियां,
मौलाना नदवी, जिन्हें लोग लोकप्रिय रूप से इसी नाम से पुकारते थे, ने राजीव को एक ज्ञापन सौंपा।
यह तर्क दिया गया कि यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप था।
और संविधान में उन्हें दी गई धार्मिक स्वतंत्रता।
(अनुच्छेद 25, 26 और 29)। अली मियां को 'संपूर्ण इस्लामी समाज का समर्थन प्राप्त था'।
दुनिया'।
एआईएमपीएलबी ने जोर देकर कहा कि तलाकशुदा महिला इसमें शामिल नहीं हो सकती।
तलाक के बाद भी वह अपने पूर्व पति के साथ लगातार संपर्क में रहती है।
ऐसा हो चुका था। 'इसलिए, वह उससे हर बार पैसे नहीं ले सकती थी।
महीना।'
धर्मगुरुओं और राजनीतिक नेताओं के अलावा, आम मुसलमान भी आए।
फैसले के खिलाफ मुसलमानों ने 'कड़ी मजबूती' से विरोध प्रदर्शन किया।
दिल्ली, मुंबई में लाखों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
कोलकाता, पटना, कानपुर, हैदराबाद और अन्य शहर। इसका भी प्रभाव पड़ा।
एआईएमपीएलबी पर इसका अपना दबाव।
इस फैसले के खिलाफ पहली बड़ी बैठक सिवान में आयोजित की गई थी।
बिहार। हालांकि यह एक स्थानीय पहल थी, लेकिन इसने तीन लाख लोगों को आकर्षित किया—यह
इस बैठक ने एआईएमपीएलबी को यह संकेत दिया कि मुसलमान अब
फैसले के खिलाफ आंदोलन करने को तैयार। अधिकांश भारतीयों के लिए
मुसलमानों के लिए, 'शाह बानो' का महत्व और भी अधिक बढ़ता जा रहा था।
अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद। समुदाय के कई लोगों के लिए

वे अपनी पहचान को अपने व्यक्तिगत कानूनों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ मानते थे।
1985 में हुए ये विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर वास्तविक बदलावों के पहले संकेत थे।
आजादी के बाद मुसलमानों द्वारा मुखरता दिखाई गई।
इससे पहले समुदाय द्वारा प्रदर्शन किए गए थे, बेशक। मुसलमानों की तरह।
दुनिया के अन्य हिस्सों में, उन्होंने पवित्र अल-अक्सा कुरान की कब्र खोदने पर विरोध प्रदर्शन किया था।
1969 में यरूशलम की मस्जिद पर हमला हुआ था। 1977 में अलीगढ़ दंगों के बाद, समुदाय ने अपने अधिकारों की मांग करते हुए मौन विरोध प्रदर्शन किया।
मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। कुछ अन्य अवसरों पर भी, जब समुदाय के खिलाफ दंगे या हिंसा हुई थी,
स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन इससे पहले कभी भी इसकी तुलना करने लायक कुछ नहीं हुआ था।
फैसले के बाद जो आक्रोश भड़का। शाहिद सिद्दीकी के रूप में
उन्होंने बताया कि 1985 तक, 'हम अपनी शक्ति को अधिकतर इन तरीकों से व्यक्त करते थे।'
मतदान का प्रयोग।'
कांग्रेस के कई मुस्लिम नेताओं ने आरिफ मोहम्मद की आलोचना की।
खान के रुख के लिए। समुदाय की प्रतिक्रिया को देखते हुए, मुस्लिम सांसदों ने
और कांग्रेस के मंत्री चिंतित थे। वे नहीं चाहते थे कि
एआईएमपीएलबी के सदस्यों को नाराज करना। या मुस्लिम मत के विरुद्ध जाना। सी.
राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मुस्लिम मंत्री के. जाफर शरीफ,
वह उत्तेजित थीं। कांग्रेस सांसद और उप-सांसद नजमा हेपतुल्ला भी उत्तेजित थीं।
राज्यसभा की अध्यक्ष। पूरे 1985 के दौरान, उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई।
एआईएमपीएलबी और के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने में भूमिका
सरकार। अली मियां ने उनकी भूमिका के लिए उन्हें पूरा श्रेय दिया।
हेपतुल्ला के इंडिया गेट पर आयोजित एक विरोध सभा में बेगम आबिदा ने भाग लिया।
अहमद, पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी, और
अन्य प्रमुख मुस्लिम महिलाओं ने खान के विचारों की आलोचना की।

इससे विचलित हुए बिना, खान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, 'हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है।'
उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, 'लेकिन एक बात तो मैं जानती हूँ। नजमा हेपतुल्ला ज़्यादा पैसे देती हैं।'
'शाह बानो को अदालत द्वारा आवंटित राशि से कहीं अधिक राशि वह अपने हेयरड्रेसर को दे सकती है!'
अगले दिन उनके बयान मीडिया में छा गए।
कांग्रेस पार्टी के भीतर फूट गहरी होती जा रही थी।
■

संसद में खान के हस्तक्षेप के तुरंत बाद, उत्तेजित जियाउर
Rahman Ansari met Rajiv Gandhi. ‘If Arif [Mohammad] Khan, who is
एक मंत्री निजी सदस्य के विधेयक पर बहस में बोल सकता है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता?
'बोलें?' अंसारी राजीव के मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मुस्लिम मंत्री थे।
मुस्लिम समुदाय में एक उच्च सम्मानित बुद्धिजीवी, उनका ज्ञान
अरबी भाषा पर उनका अधिकार असाधारण था। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्हें अनुमति नहीं दी गई तो वे नौकरी छोड़ देंगे।
बोलने के लिए। वह प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए पहुंचे थे।
अपने त्यागपत्र के साथ। राजीव ने त्यागपत्र लिया, फाड़ दिया
'मैंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया,' अजीज कुरैशी (जो बाद में बने) ने याद करते हुए बताया।
उत्तराखंड के राज्यपाल), जो अंसारी के साथ गए थे
बैठक।
‘तुम्हें बोलने से कौन रोक रहा है?’ राजीव ने शांत करने की कोशिश की।
अंसारी घबरा गया।
अंसारी ने संसद में तीन घंटे तक भाषण दिया, सबसे पहले 22 नवंबर को।

और फिर 3 दिसंबर 1985 को भी। उन्होंने आरिफ की तरह ही जोश से भाषण दिया।
मोहम्मद खान ने यही किया था। उन्होंने शाह बानो के फैसले की कड़ी आलोचना की थी।
उन्होंने न्यायाधीशों पर 'पक्षपाती' होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश इस मामले में सक्षम नहीं थे।
कुरान और हदीस की व्याख्या करें।
खान द्वारा फैसले का बचाव करने के बाद, अंसारी का यह बयान आया...
उनके भाषण से एक विपरीत संकेत मिला—कि राजीव ने अब अपना मन बदल लिया था।
मुस्लिम समुदाय राजीव गांधी को मनाने में कामयाब हो गया था।
और प्रधानमंत्री ने खान का मुकाबला करने के लिए अंसारी को मैदान में उतारा था।
'यह स्पष्ट है
टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक संपादकीय में लिखा, 'निस्संदेह, श्री गांधी
श्री अंसारी को हरी झंडी दे दी। सीधे शब्दों में कहें तो श्री अंसारी भी थे।
अपनी पहल पर काम नहीं कर रहा था। हालाँकि उसने खान से यह करवाया था।
शाह बानो फैसले का जोरदार बचाव करते हुए, राजीव गांधी ने महसूस किया
उन्हें उत्तेजित मुस्लिम जनमत को शांत करना था।
■

दो दिशाओं में खिंचे चले जाने के कारण, नवंबर 1985 के मध्य तक, राजीव गांधी अभी भी
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए।
16 नवंबर 1985 को खान अपने निर्वाचन क्षेत्र बहराइच में थे।
वह सिसिया नामक स्थान की यात्रा पर गया था, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है।
जिला मुख्यालय। वहीं पर स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट का पद था।
जो बेसब्री से उसकी तलाश कर रहे थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया।
उन्होंने खान को बताया, 'प्रधानमंत्री आवास से फोन आया था। संदेश यह था कि...'

आपको आज रात प्रधानमंत्री के साथ ओमान जाना है। एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है। मैं पहले ही लखनऊ से निकल चुका हूँ और आपको बहराइच से ले जाकर छोड़ दूँगा। वापस लखनऊ। इसलिए बेहतर होगा कि आप सब कुछ रद्द करके चले जाएं। तुरंत।'

खान बहराइच के लिए तेजी से रवाना हुए; वे 16 तारीख की शाम तक दिल्ली पहुँच गए।

नवंबर 1985। वह सुबह 2 बजे हवाई अड्डे पर पहुँच गया, पूरी तरह से रवाना होने के लिए तैयार था।

प्रधानमंत्री।

जैसे ही मैं विमान में सवार हुआ, एक अधिकारी ने मुझसे कहा, “सर, खुर्शीद आलम खान को साथ जाने वाले मंत्री के रूप में नामित किया गया था, उनका नाम सामने आया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि वह विदेश मामलों के राज्य मंत्री थे।

“लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना नाम हटाकर आपकी नाम जोड़ दिया,”

अधिकारी ने कहा। फिर, माहौल को गर्म करते हुए, उन्होंने और जानकारी दी, "वह (प्रधानमंत्री ने) उल्लेख किया कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसी अफवाहें फैल रही थीं कि

वह आरिफ मोहम्मद खान द्वारा लिए गए रुख को अस्वीकार करने जा रहा था।

इस समय आरिफ को अपने साथ ले जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि उन अफवाहों को खारिज किया जा सके।

एक अधिकारी ने राजीव गांधी के हवाले से यह बात कही।

प्रधानमंत्री और उनकी टीम 17 नवंबर को ओमान पहुंची।

1985 में मस्कट की राजधानी की दो दिवसीय यात्रा पर। चूंकि वह

प्रधानमंत्री के साथ आए मंत्री खान का सुइट राजीव गांधी के सुइट के बगल में था।

गांधी उस होटल में थे जहाँ वे ठहरे हुए थे। सुबह, खान

मैं प्रधानमंत्री के कमरे में दाखिल हुआ। राजीव नाश्ता कर रहे थे।

'राजीव ने वही दोहराया जो अधिकारी ने मुझे पिछली रात बताया था।'

यही कारण था कि उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था।

फिर उन्होंने खान से पूछा, 'आप इसके बारे में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं?'

आपने क्या रुख अपनाया है?
खान ने जवाब दिया, 'मैं चुनाव प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि क्या होगा।'
यही अंतिम परिणाम होने वाला है...।
उन्हें पता था कि सरकार सदस्यों से बात कर रही है।
एआईएमपीएलबी। उन्होंने राजीव गांधी को यही बात बताई। 'फिर, मैंने राजीव से कहा कि मैं
अगर कोई बीच का रास्ता निकल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।'
'मैंने अपने भाषण के अंत में ठीक यही बात कही थी।'
खान ने राजीव को याद दिलाते हुए कहा, 'संसद में कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए।' उन्होंने आगे कहा, '
इस मुद्दे पर। यह एक कानूनी और संवैधानिक मुद्दा है। और इसमें जनता की भावनाएं भी शामिल हैं।
इस पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए... ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं मिल सकता। इस गतिरोध से बाहर निकलें।'
'Nahi, koi sawaal hi nahin inke saath samjhauta karne ka (No, there
इन लोगों के साथ समझौता करने का तो सवाल ही नहीं उठता,' राजीव ने खान से कहा।
फिर उन्होंने आगे कहा, 'मैं (विंसेंट) जॉर्ज को एआईसीसी से बात करने का निर्देश दूंगा।'
लोगों से मिलें और आवश्यक व्यवस्था करें। आप एक पूर्ण पैमाने पर
इन लोगों के खिलाफ अभियान (एआईएमपीएलबी)।
'लेकिन मैंने इंतजार करने का फैसला किया,' खान ने खुलासा किया। 'क्योंकि मुझे मिल रहा था
एक अलग तरह की जानकारी—कि के साथ बातचीत
निजी विधि बोर्ड के लोग अच्छी प्रगति कर रहे थे।' और वह जानता था कि
एक निश्चित कारण से उन्हें उन वार्ताओं में शामिल नहीं किया जा रहा था—
एआईएमपीएलबी ने स्पष्ट रूप से यह शर्त रखी थी कि उन्हें वार्ता से बाहर रखा जाए।

'अगर मुझे इन वार्ताओं में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब है कि सरकार
खान ने बाद में कहा, 'आरिफ को बाहर रखने की उनकी शर्त पर सहमति जता दी है।'
खान ने एआईसीसी पदाधिकारियों की मदद नहीं मांगी, जैसा कि सुझाव दिया गया था।
प्रधानमंत्री द्वारा भी नहीं। उन्होंने विंसेंट जॉर्ज से भी संपर्क नहीं किया।
राजीव गांधी के निजी सचिव से भी उन्होंने कभी संपर्क नहीं किया।
राजीव गांधी। लेकिन इस प्रकरण से पता चला कि नवंबर 1985 के मध्य तक,
राजीव अब भी अनिश्चित था। उसके असमंजस में होने के बावजूद, स्थिति, जितनी जटिल थी, उतनी ही जटिल भी थी।
यह बात तेजी से और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो गई।
■

एम. जे. अकबर एक शिक्षित और वाक्पटु मुस्लिम थे, और एक अग्रणी व्यक्ति थे।
वह पत्रकार जिसने प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे।
उन्होंने ऐसी भाषा में बात की जिसे राजीव समझ सकें। अकबर शाह के खिलाफ थे।
बानो का फैसला, मुस्लिम समुदाय के अधिकांश लोगों की तरह था। वह चले गए।
टेलीविजन पर आरिफ मोहम्मद खान के साथ, जिन्होंने उनका विरोध किया था।
यह बहस पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई।
राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले वजाहत हबीबुल्लाह ने बताया कि...
राजीव गांधी को प्रभावित करने में अकबर की भूमिका। उस समय, हबीबुल्लाह
वे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक थे, यह पद उन्होंने इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी संभाला था।
गांधी जी के कार्यकाल में। वे राजीव गांधी के साथ दून स्कूल में थे और उनके बीच
तब से ही दोस्त रहे हैं। राजीव के प्रधानमंत्रित्व काल के कुछ महीनों बाद, वह
उन्हें संयुक्त सचिव स्तर पर पदोन्नत किया गया। हबीबुल्लाह इसके प्रभारी भी थे।
राष्ट्रीय एकीकरण परिषद (एनआईसी) और कार्यक्रमों के लिए

अल्पसंख्यकों का कल्याण। 'मैं अल्पसंख्यक मामलों की देखरेख कर रहा था। लेकिन उस समय अल्पसंख्यक मामलों जैसा कोई शब्द नहीं था,' हबीबुल्लाह ने कहा।
मुस्लिम संगठनों द्वारा सरकार को भेजी गई याचिकाओं की बाढ़
जमीयत-ए-इस्लामी और एआईएमपीएलबी जैसी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया।
सभी निर्णय हबीबुल्लाह के पास आ गए थे। उन्होंने उसे मजबूर कर दिया था कि वह...
व्यक्तिगत कानून और उसके अनुप्रयोग के संपूर्ण प्रश्न में गहराई से उतरें
भारत में। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तिगत कानूनों का सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में महत्व है।
समुदाय के भीतर संबंध। लेकिन हबीबुल्लाह को लगा कि ये कानून
अन्य देशों में प्रचलित प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी 'समीक्षा' की जानी चाहिए।
और यह कार्य 'स्वयं समुदाय द्वारा' किया जाना चाहिए।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
शाह बानो मामले में किसी भी तरह से। हालांकि कई मुस्लिम संगठन
जबकि हबीबुल्लाह का मानना था कि सर्वोच्च न्यायालय को मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित मामले पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है, वहीं उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है।
यह शासन इसलिए लागू होता था क्योंकि यह देश में सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण था।
यदि
यदि समुदाय को इस निर्णय से समस्या थी, तो इससे बदलाव हो सकता था।
सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करें। सरकार को इससे अधिक कुछ नहीं करना चाहिए।
उन्हें लगा कि 'मामले में हस्तक्षेप न करना' ही एकमात्र उपाय है। इसका कोई अंत नहीं होगा।
अगर सरकार निजी कानूनों में दखल देना शुरू कर दे तो ऐसा होगा।
इसे अदालतों पर छोड़ दिया जाए।
हबीबुल्लाह ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में अपनी सिफारिशें लिखीं।

मंत्री ने कहा, 'मैंने एक ही पत्र भेजा था...वह अभी भी वहीं होगा।' हबीबुल्लाह ने आगे कहा।
उन्होंने कहा। आम तौर पर प्रधानमंत्री इसे अपनी टिप्पणियों के साथ वापस भेज देते हैं। लेकिन इस फाइल में ऐसा नहीं हुआ।
वह उसके पास वापस नहीं आया।
फिर एक दिन राजीव गांधी ने हबीबुल्लाह को फोन किया। राजीव की शैली
उनकी कार्यप्रणाली उनकी मां से अलग थी। जब इंदिरा गांधी
अगर वह हबीबुल्लाह से मिलना चाहती, तो वह औपचारिक संदेश भेजती, लेकिन व्यंग्यात्मक लहजे में।
पुराने जमाने की शिष्टता के साथ, अपने निजी सहायक आर. के. धवन के माध्यम से।
—'Madam aapko yaad kar rahi hain (Madam is remembering you).'
राजीव अपने अधिकारियों के साथ व्यवहार में अधिक अनौपचारिक थे। उस सर्दी के मौसम में
1985 के अंत में एक दिन, राजीव ने सुरक्षित RAX नंबर पर हबीबुल्लाह को फोन किया।
रेखा।
'क्या तुम आओगे?' उसने बिना किसी भूमिका के पूछा। हबीबुल्लाह
वह साउथ ब्लॉक में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर चला गया। जब वह कमरे में दाखिल हुआ,
उन्होंने एम. जे. अकबर को वहां बैठे देखा। उस दिन हवा में हल्की ठंडक थी।
बाद में याद आया कि दिल्ली धीरे-धीरे लोकप्रिय होने लगी थी।
'अंदर आइए, अंदर आइए, वजाहत,' राजीव ने सहजता से उनका अभिवादन किया। और फिर
उन्होंने आगे कहा, 'आप हममें से ही एक हैं।'
यह क्या है? हबीबुल्लाह ने मन ही मन सोचा। बेशक मैं उनमें से एक हूँ।
'हम'। वह अवश्य ही भ्रमित प्रतीत हुआ होगा, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह था
जल्द ही पता चल जाएगा कि राजीव का क्या मतलब था।

राजीव सीधे मुद्दे पर आए। उन्होंने मुसलमानों के गुस्से का जिक्र करते हुए कहा
शाह बानो के फैसले पर प्रधानमंत्री ने कहा, 'अकबर को लगता है कि अगर
हम इस मामले पर चुप रहते हैं और कुछ नहीं कहते, मुसलमान
समुदाय को लगेगा कि...मैं उनकी अनदेखी कर रहा हूँ। उन्हें ऐसा लग सकता है कि
वे मेरे अपनों में से नहीं हैं।
इस बिंदु पर, एम. जे. अकबर ने कार्यभार संभाला और 'काफी देर तक' बात की।
इस बारे में कि फैसले को क्यों रद्द किया जाना चाहिए। राजीव को भारी रकम मिली
थी।
उन्होंने तर्क दिया कि 1984 के चुनावों में मुसलमानों का समर्थन मिला था। अकबर
उन बैठकों के बारे में बात की गई जहाँ मुस्लिम समुदाय के सदस्य कहते थे, 'राजीव
तो हमारे हैं (राजीव हम में से एक हैं)।' यह दर्शाता था
1977 से एक बदलाव आया है, जब समुदाय ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया था।
मुस्लिम पुरुषों की जबरन नसबंदी के कारण। लेकिन अगर राजीव चले गए
आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने वाले अकबर ने चेतावनी दी, वे
इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि राजीव वास्तव में उन्हें अपने परिवार का हिस्सा नहीं
मानते थे।
परिवार'।
हबीबुल्लाह को लगा कि यह एम. जे. अकबर की 'शिक्षित सलाह' थी, जिसने
इससे प्रधानमंत्री के रुख में बड़ा बदलाव आया।
‘मुझे यह स्वीकार करना होगा,’ वजाहत हबीबुल्लाह ने वर्षों बाद स्वीकार किया कि ‘मैं
और
(या यूं कहें कि) अकबर ने—दोनों ने ही निर्णय लेने में “गलती” की थी।
1985. हमने धर्मगुरुओं द्वारा दायर की गई इन तमाम याचिकाओं को...जनता की
आवाज़ के रूप में लिया।
मुस्लिम समुदाय। वह अंतर, जो "अब मेरे लिए इतना स्पष्ट है", "नहीं था"
तो फिर स्पष्ट है। और अकबर और मैं दोनों ही कुछ हद तक पश्चिमी सभ्यता से
प्रभावित हैं।
राजीव की तरह ही, वे भी इस अंतर से अनजान थे और न ही इसके प्रति संवेदनशील
थे।

आम राय और धर्मगुरुओं द्वारा व्यक्त की गई राय के बीच अंतर।
राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धार्मिक मध्यस्थों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति
भारत में यह निर्णय कोई नई बात नहीं थी। यह ब्रिटिश काल से ही चली आ रही थी।
1857 के विद्रोह के बाद से, इस्लामी धर्मगुरुओं ने यह दायित्व अपने कंधों पर ले लिया था।
ब्रिटिश सरकार के समक्ष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
बाद में कांग्रेस पार्टी के साथ जारी रहे; समय के साथ वे बन गए
मुस्लिम समुदाय की आवाज।
उस दिन हबीबुल्लाह को यह स्पष्ट हो गया कि अकबर के शब्दों का क्या अर्थ था।
राजीव की स्वीकृति। उन्हें समझ आ गया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें क्यों बुलाया था।
अपने कार्यालय में। राजीव उसे एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी करना चाहता था।
उस एक तस्वीर से जो उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे गए नोट में ली थी।
बैठक समाप्त हुई। राजीव ने हबीबुल्लाह को कोई निर्देश नहीं दिए। बाद में,
हबीबुल्लाह को पता चला कि फाइल विधि मंत्रालय को भेज दी गई है और
न्याय। तब से यह मामला विधि मंत्रालय और न्याय विभाग के बीच घूमता रहा।
प्रधानमंत्री कार्यालय। लेकिन यह मामला हबीबुल्लाह के पास कभी वापस नहीं आया।
मामला खत्म हो चुका था।
उसके हाथों से।
■

शाह बानो फैसले पर हुई बहस ने कांग्रेस पार्टी को विभाजित कर दिया।
बिल्कुल बीचोंबीच। यह सिर्फ जियाउर जैसे मुस्लिम नेताओं की बात नहीं थी।
रहमान अंसारी, सी.के. जाफर शरीफ, नजमा हेपतुल्ला और सलमान
खुर्शीद इस फैसले को पलटना चाहते थे। पी.वी. नरसिम्हा राव, अर्जुन सिंह, एन.डी.
तिवारी और एस.बी. चव्हाण जैसे वरिष्ठ पार्टी नेता भी इस फैसले के खिलाफ थे।
कानून में संशोधन के पक्ष में भी लोग थे। उनके विरोध में ये लोग खड़े थे:

अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, डी. पी. त्रिपाठी जैसे कांग्रेसी नेताओं ने...
and Sitaram Kesri.
अपने प्रधानमंत्रित्व काल के शुरुआती महीनों में, राजीव गांधी अक्सर
राजनीतिक सलाह के लिए वरिष्ठ नेताओं की ओर रुख करें। हालाँकि वह चिंतित था।
मुसलमानों के सड़कों पर उतरने के बारे में प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा था?
न केवल एम. जे. अकबर जैसे लोगों से, बल्कि इन वरिष्ठों से भी प्रभावित।
नेता—राव, अर्जुन सिंह, तिवारी और चव्हाण। इन लोगों ने
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में सरकारों का नेतृत्व किया।
प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र—जिनमें काफी बड़ी आबादी थी
उन्होंने मुस्लिम आबादी से परामर्श किया कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए।
मुस्लिम प्रतिक्रिया तेजी से बढ़ती जा रही है।
राव ने राजीव से कहा कि 'इस मामले को लंबा खींचना' केवल उल्टा ही पड़ेगा।
उत्पादक। अर्जुन सिंह को लगा कि उन्हें लोगों को अलग-थलग नहीं करना चाहिए।
मुसलमानों का नेतृत्व। तिवारी कांग्रेस की मानसिकता का प्रतीक थे—कि
पार्टी के वोट बैंक में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम शामिल थे, और
मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहिए। हैरानी की बात है कि चव्हाण भी ऐसा ही था।
वह भी इसी राय के थे, हालांकि उन्हें ताने मारकर 'संघी' कहा जाता था।
उनके कुछ पार्टी सदस्यों को लगता था कि वे आरएसएस समर्थक विचार रखते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई।
लेकिन, हैरानी की बात यह है कि आरिफ मोहम्मद को सलाह देने वाला चव्हाण ही था।
खान को 'सावधान रहने' के लिए कहा गया था, जैसा कि पहले देखा गया था।
'हालांकि राजीव ने मुझसे पूछा था कि
प्रधानमंत्री चव्हाण की उपस्थिति में संसद में भाषण देंगे, चव्हाण ने
बाद में उन्होंने मुझे चुप रहने की सलाह दी।
‘He met me separately, “Arif, mat bolo. Iss maamle mein mat pado
(आरिफ, कुछ मत बोलो, इस मामले में मत उलझो।)

खान को सावधानी बरतने की सलाह देने वाले केवल चव्हाण ही नहीं थे,
‘(एम. एल.) फोतेदार ने भी मुझसे यही बात कही थी।’
‘लेकिन,’ खान ने फोतेदार से कहा, ‘प्रधानमंत्री ने मुझे बोलने के लिए कहा है।’
‘Aap PM se baat kar leejiye. Mat boliye is maamle mein.’ (You talk to
प्रधानमंत्री से बात करें, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ न कहें।) वे ऐसा नहीं करना चाहते थे।
खान के लिए हालात कठिन होते जा रहे हैं; उन्हें एक युवा और होनहार नेता के रूप में देखा जाता था।
कांग्रेस।
‘मुझे पता था कि राजीव जी अपना मन नहीं बदलेंगे,’ खान ने बताया।
मैंने निजी विधि बोर्ड के लोगों के दबाव के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन
इन वरिष्ठ नेताओं के लिए।'
राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय इस्लामी मत का भी ध्यान रखते थे।
हालांकि यह उनके लिए प्राथमिक विचारणीय विषय नहीं था।
दिसंबर 1985 में घटनाएँ तेज़ी से आगे बढ़ने लगीं।
अब, राजीव गांधी को खुफिया रिपोर्टें मिली थीं कि भारी
मुस्लिम समुदाय में शाह बानो के खिलाफ भावनाएँ थीं।
निर्णय। असम विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के परिणाम।
सात लोकसभा और नौ विधानसभा सीटों पर मतदान 16 तारीख को हुआ था।
दिसंबर 1985—ने राजीव गांधी को चौंका दिया। असम में, कांग्रेस
राजनीतिक क्षेत्र में नवोदित असम गण परिषद (एएसपी) से बुरी तरह हार गई।
असम समझौते के ठीक सड़सठ दिन बाद। सामान्यतः,
उपचुनाव में मौजूदा सरकार को बढ़त हासिल थी। लेकिन
कांग्रेस को तीन लोकसभा और पांच विधानसभा सीटों पर अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा।
1984 में अपनी अभूतपूर्व जीत के मात्र एक वर्ष बाद ही चुनावों में। यहां तक कि इसके
दिग्गज नेता सिद्धार्थ शंकर राय सीपीआई (एम) के सोमनाथ से हार गए।

पश्चिम बंगाल के बोलपुर में चटर्जी।
उपचुनावों का संदेश स्पष्ट था। मुसलमान थे
राजीव गांधी द्वारा शाह बानो मामले के निपटारे से असंतुष्ट और
कांग्रेस से दूर होते जा रहे थे। 'हालांकि मैंने अपना अभियान जारी रखा।
जनता पार्टी के सैयद शहाबुद्दीन ने कहा, 'बहुत धर्मनिरपेक्ष नहीं।'
शाह बानो शब्द का एक बार भी जिक्र करने पर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि
केंद्र के प्रति अस्पष्ट रुख को लेकर मुसलमानों के मन में बेचैनी है।
शाह बानो केस।' उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जीत हासिल की।
किशनगंज निर्वाचन क्षेत्र।
ए. एफ. गुलाम उस्मानी, संयुक्त अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष
जिसने असम में कांग्रेस के मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई, उसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया।
कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार मंत्री ने कहा: 'यह युवा, नेक प्रधानमंत्री,
जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता है, वही अपनी पार्टी को उसके 100वें वर्ष में बर्बाद कर रहा है।
वर्ष।'
राजीव गांधी के सहयोगियों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें राजी किया जा सकता है।
जिस आखिरी व्यक्ति से उसने बात की थी, उसके विचार। यही एक कारण था।
वह काफी समय से एक दृष्टिकोण से दूसरे दृष्टिकोण की ओर झूल रहा था।
1985.
दिसंबर 1985 में, राजीव के विचारों में एक बार बदलाव आ रहा था।
फिर से। दिल्ली में कानून के एक प्रोफेसर ने उन्हें विस्तृत जानकारी दी।
विश्वविद्यालय, ताहिर महमूद, विवाह और तलाक की इस्लामी अवधारणाओं पर।
रखरखाव। उन्होंने राजीव को रखरखाव करवाने की उपयुक्तता के बारे में आश्वस्त किया।
फैसले को पलटने के लिए विधेयक।
राजीव को सोनिया की कही बातें भी परेशान कर रही थीं।

इस बार—वही उद्धरण जिससे मैंने इस अध्याय की शुरुआत की थी। वह चाहता था कि
यह सुनिश्चित करना कि एक गरीब, पीड़ित, तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उचित न्याय मिले।
जीवनयापन के लिए आवश्यक धनराशि।
■

उपचुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद, एआईएमपीएलबी के सत्रह सदस्यों ने मुलाकात की।
प्रधानमंत्री; उनके साथ ताहिर महमूद और
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। राजीव ने उनसे कहा कि वह चाहते हैं कि
यह सुनिश्चित करें कि मुस्लिम महिला विधेयक ने मुस्लिम महिला को यह अधिकार दिया है
उचित और न्यायसंगत धनराशि—जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार की है
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दिए गए फैसले में ऐसा करने में विफल रहने के बावजूद
पति को भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का आदेश देना।
क्या आप महिला की सुरक्षा के लिए उपाय तलाश रहे हैं, या आप चाहते हैं कि...
'पति को दंडित किया जाएगा?' एआईएमपीएलबी के एक आश्चर्यचकित सदस्य ने पूछा।
जब उन्हें एहसास हुआ कि राजीव वास्तव में और अधिक पैसे में दिलचस्पी रखता है
तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भुगतान किया गया, वे इस पर सहमत हो गए। राजीव ने कहा कि
वे विधेयक को तुरंत अध्यादेश के रूप में लाना चाहते थे, साथ ही
मुंबई में कांग्रेस के शताब्दी समारोह में केवल चार दिन शेष हैं।
तीन घंटे के भीतर, एआईएमपीएलबी ने उन्हें अपने मसौदे का मसौदा भेज दिया था।
मुस्लिम महिला विधेयक। इसे कानून मंत्री अशोक सेन को सौंप दिया गया।
इस पर काम करना था। लेकिन फैसला एक महीने के लिए टल गया। एक लेख में

यह बात सामने आई थी।
यह लेख पाकिस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था जिसमें भारतीय की आलोचना की गई थी।
शाह बानो फैसले को मुसलमानों द्वारा उनके विरुद्ध बताने पर जोर देने के लिए
शरीयत। राजीव ने नजमा हेपतुल्ला से इसकी जांच करने का आग्रह किया—और इसमें समय लगा।
कुछ हफ्तों का समय है।
अंततः, राजीव ने शाह बानो संधि को रद्द करने के लिए कानून बनाने का फैसला किया।
निर्णय। उन्होंने अशोक सेन को कानून बनाने और सहायता लेने का निर्देश दिया।
जियाउर रहमान और अन्य मुस्लिम नेताओं, जिनमें सदस्य भी शामिल हैं, के बारे में।
AIMPLB, इसका मसौदा तैयार करने के लिए।
मुस्लिम समुदाय का दबाव, वरिष्ठों की राय
कांग्रेस के नेताओं, पत्रकार से नेता बने लोगों जैसी सलाहों के आधार पर...
राजनीतिज्ञ एम. जे. अकबर और दिसंबर 1985 के उपचुनाव के परिणाम-
चुनावों ने राजीव गांधी के पक्ष में फैसला कर दिया।
■

सन् 1985 के अंत में इसी समय के आसपास, प्रतिवाद बढ़ने लगा।
राजीव अरुण नेहरू, जिन्होंने मुस्लिम महिला विधेयक का विरोध किया था,
राजीव को चेतावनी दी गई थी कि 'मुस्लिम कट्टरपंथियों' के सामने उनका 'आत्मसमर्पण' करना
कांग्रेस के भीतर बड़ी संख्या में सांसदों को यह बात पसंद नहीं आ रही है।
नेहरू ने कहा, 'आप रातोंरात प्रधानमंत्री नहीं बन जाते।'
उन्होंने अपने चचेरे भाई से विरोध जताया। 'यह मत भूलो, तुम प्रधानमंत्री तब बने थे जब...'
5,000 से अधिक सिखों की हत्या कर दी गई थी।' नेहरू राजीव को याद दिला रहे थे कि यह
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई सिख विरोधी हिंसा ही वह घटना थी जिसने

1984 के चुनावों में राजीव गांधी के समर्थन में हिंदू जनमत एकजुट हो गया था। अगर राजीव
नेहरू ने चेतावनी दी थी कि यदि मुस्लिम समुदाय को खुश करने का प्रयास जारी रहा, तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
इसकी वजह से उन्हें हिंदुओं के बीच अपना समर्थन आधार खोना पड़ा, जो धीरे-धीरे कम होता जा रहा था।
कांपता हुआ।
बात यहीं खत्म नहीं हुई। 'अगर आप सत्ता में वापस आना चाहते हैं तो आपको...'
नेहरू ने अपने चचेरे भाई से स्पष्ट शब्दों में कहा, ‘तीन काम करो। एक मंदिर बनवाओ।’
अयोध्या में समान नागरिक संहिता लागू करें और अनुच्छेद 370 को निरस्त करें।
Uski abhi se tayyari kar ke chalo (You had better start getting ready for
इसे अब से लागू किया जाएगा)।' उन्हें लगा कि अगर कांग्रेस ये कदम उठाती है, तो हिंदुओं का समर्थन बरकरार रखने में सक्षम होंगे।
नेहरू ने कहा, ‘हम भाजपा की हवा पूरी तरह से निकाल देंगे।’
राजीव।
इन तीनों मुद्दों को भाजपा के 'मूल आधार' के रूप में पहचाना जाने लगा था।
हालांकि पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा उठाया, फिर भी उसने 'मुद्दों' पर ध्यान केंद्रित किया।
अयोध्या में अपने राजनीतिक एजेंडे के हिस्से के रूप में, केवल 1989 में अपनी बैठक में।
Palampur.
अरुण नेहरू ने अपने चचेरे भाई को याद दिलाया कि उन्हें अब तक हासिल की गई उपलब्धियों को नष्ट नहीं करना चाहिए।
मुस्लिम महिला विधेयक लाकर यह संभव हुआ।
‘राजीव को क्या लगता है वो क्या कर रहा है?’ उसने चिढ़कर कहा था।
अधिकारियों की उपस्थिति में राजीव के प्रस्तावित कदम के बारे में एक बैठक हुई।
अरुण नेहरू विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के संपर्क में थे, जिसने भी अपनी

गतिविधियां तेज कर दी थीं।
1985 के अंत में राजीव गांधी पर दबाव बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।
धार्मिक नेताओं के सशक्त समूह ने लगभग 250 हिंदू सांसदों से पैरवी करने का काम किया।
कांग्रेस समेत सभी पार्टियां। राजीव हिंदू धर्म को कैसे भूल सकते हैं?
उन्होंने उस 'वोट बैंक' के बारे में पूछा, जिसने उन्हें चुनाव में 414 सीटें दिलाई थीं।
कुछ लोगों ने दबी आवाज़ में इस बात पर चर्चा की कि क्या मुस्लिम महिला विधेयक यदि जन आंदोलन हुआ तो संसद में इसे पराजित किया जा सकता है।
सभी दलों में इसके खिलाफ राय है।
इसी समय के आसपास राजीव को पहली बार यह सोचने का ख्याल आया कि क्या अरुण नेहरू बिल के मामले में उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें शक होने लगा था।
पार्टी में कई लोगों ने उनसे यह कहा था कि यह कदम उठाने से
मुस्लिम महिला विधेयक के खिलाफ सांसदों को लामबंद करना शायद सिर्फ एक कारगर उपाय न हो।
प्रस्तावित कानून के खिलाफ। यह उनके नेतृत्व के खिलाफ हो सकता है, और
इससे मामला इतना बढ़ सकता है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की मुहिम शुरू हो जाए।
छठी

जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा (पर्याप्त अधिकार) का अंतिम मसौदा तैयार हुआ
तलाक विधेयक, 1986, तैयार था, एम. एल. फोतेदार ने आरिफ मोहम्मद को फोन किया।
खान। उन्होंने खान को प्रधानमंत्री आवास पर आने के लिए कहा। 'मसौदे का
उन्होंने खान से कहा, 'विधेयक तैयार है, कृपया अभी जाकर कानून मंत्री से मिलें।'
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि अशोक सेन को उपस्थित होना चाहिए।
खान ने मसौदा तैयार किया। सेन एक जाने-माने वकील थे और उन्होंने कानून के क्षेत्र

में भी काम किया था।
जवाहरलाल नेहरू के अधीन मंत्री। 'सेन ने मुझे अपने अध्ययन कक्ष में आमंत्रित किया और
खान ने याद करते हुए बताया, ‘उन्होंने मुझे ड्राफ्ट सौंप दिया। मैंने उसे पढ़ा। फिर मैंने उसे दोबारा पढ़ा।’ ‘
खंड 3...तीन या चार बार।’
इस धारा में ‘उचित और न्यायसंगत प्रावधान किए जाने’ की मांग की गई थी।
और इद्दत की अवधि के भीतर भुगतान किया गया। पेशे से वकील खान थे।
प्रयुक्त शब्दावली के निहितार्थों को शीघ्रता से समझ लेना।
खान ने सेन से पूछा, 'क्या उन्होंने (एआईएमपीएलबी और इसमें शामिल अन्य लोगों ने)
क्या आप इस पर सहमत हैं?
'हां,' सेन ने उत्तर दिया।
‘वे यही तो नहीं मांग रहे थे,’ खान ने सेन की ओर देखते हुए कहा।
पूछताछ भरे लहजे में। 'वे पति की देनदारी को सीमित करना चाहते थे।'
केवल इद्दत की अवधि के लिए।' हालाँकि, विधेयक की धारा 3 की शब्दावली
इसमें यह शर्त रखी गई थी कि (तलाकशुदा महिला को दी जाने वाली) राशि
यह राशि इद्दत की अवधि के दौरान तय और भुगतान की जाती है, न कि केवल इद्दत की अवधि के लिए।
दोनों के बीच सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट अंतर था।
खान ने कहा: 'इसका मतलब है कि अब अदालत उचित सजा तय कर सकती है।'
तलाकशुदा पत्नी की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राशि।’ ‘हाँ,’
सेन ने जवाब दिया, 'लेकिन वे इसके लिए सहमत हो गए हैं।'
‘बधाई हो,’ खान ने उनसे कहा। ‘यह एक सुधार है [पिछले प्रदर्शन से]।
उनकी मांग।
जब खान जाने के लिए उठे, तो सेन ने उनकी ओर मुड़कर कहा, 'आरिफ, मैं
आपसे चुप रहने की विनती कर रहे हैं। उनमें से किसी को भी यह बात समझ नहीं आई है।
प्रावधान।’ जब वह आरिफ को विदा करने के लिए बाहर गया, तो सेन ने अपने हाथ

जोड़ लिए।
‘आरिफ, कृपया इसे किसी के साथ साझा मत करना। किसी के साथ भी नहीं।’
आरिफ ने कहा, 'उन्होंने यह नहीं कहा कि कृपया इसे मुस्लिम नेताओं के साथ साझा न करें।'
बाद में उसने सोचा। दूसरे शब्दों में, वह नहीं चाहता था कि आरिफ इस बारे में ज़िक्र भी करे।
उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा।
एआईएमपीएलबी विधेयक के मसौदा तैयार करने में शामिल था।
जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इसके सलाहकारों में कांग्रेस मंत्री सलमान खान शामिल थे।
खुर्शीद, मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ ताहिर महमूद और न्यायमूर्ति एम. ए.
अहमदी, जो बाद में भारत के छब्बीसवें मुख्य न्यायाधीश बने।
सरकार ने सांसदों, वकीलों, न्यायाधीशों, धर्मगुरुओं और अन्य लोगों से भी परामर्श किया था।
विधेयक का मसौदा तैयार करते समय विद्वानों ने इस पर विचार किया।
कुछ लोगों को बिल में छिपी 'खामी' का पता लगाना था—लेकिन केवल तभी जब वह...
बहुत देर हो चुकी थी। जब सैयद शहाबुद्दीन को पता चला, जो एक
मुसलमानों की महत्वपूर्ण आवाज, एक संशोधन पेश करना चाहती थी
लेकिन तब तक सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई भी दबाव डालेगा तो संशोधन के लिए, पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो जाएगी।
मुस्लिम महिला विधेयक को कानून मंत्री द्वारा जानबूझकर तैयार किया गया था।
अशोक सेन को इस तरह से नियुक्त किया जाए कि इससे शाह बानो के फैसले को रद्द किया जा सके।
एक आक्रोशित मुस्लिम समुदाय को संतुष्ट करना, लेकिन अदालतों के शिकंजे में न आना।
भविष्य। संबंधित अनुभाग की शब्दावली से ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिम
व्यक्तिगत कानून अप्रभावित रहा, लेकिन इसने अधिक न्यायसंगत मुआवजे की अनुमति दी।

तलाकशुदा महिला को उसके पूरे जीवन के लिए भुगतान किया जाता है, न कि केवल उस अवधि के लिए।
रूढ़िवादी मुसलमानों द्वारा जोर दिए जाने के अनुसार, इद्दत की अवधि। विधेयक
साथ ही, तलाकशुदा महिला के रिश्तेदारों को उसकी संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार भी दिया गया।
संपत्ति, और वक्फ बोर्ड, यदि उसके ऐसे रिश्तेदार नहीं हैं
उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार।
एआईएमपीएलबी को वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाने में कोई समस्या नहीं थी।
तलाकशुदा महिला के लिए समझौता। वे किस बात पर अड़े हुए थे?
क्या यह था कि भुगतान केवल इद्दत के लिए एक बार ही किया जाना चाहिए?
मासिक धर्म की अवधि (तीन मासिक चक्र) से आगे नहीं।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने वर्षों बाद कहा था कि
राजीव गांधी और उनके कानूनी सलाहकारों द्वारा तैयार किया गया 'चतुरतापूर्वक शब्दों में गढ़ा गया खंड'
सलाहकारों ने सरकार के समक्ष इस दुविधा का समाधान कर दिया था।
क्या राजीव को इस कानूनी दांव-पेच की जानकारी थी?
'अशोक सेन ने राजीव गांधी को इसके बारे में सूचित नहीं किया (यही वह पेचीदगी थी)
बिल)। मुझे इस बात का 100 प्रतिशत यकीन है,' खान ने मुझसे कहा। लेकिन सेन ऐसा क्यों कहेंगे?
यदि आप प्रधानमंत्री से जानकारी छिपाना चाहते हैं, तो
क्या उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी? सवाल अभी भी अनसुलझा है।
सैंतीस साल बाद भी इसका जवाब नहीं मिला।
■

15 जनवरी 1986 को राजीव गांधी ने घोषणा की कि वे एक कानून लागू करेंगे।
शाह बानो के फैसले को पलटने के लिए। वे एक सार्वजनिक सभा में बोल रहे थे।
दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागार में, जिसका आयोजन जियाउर द्वारा किया गया था।

अंसारी।
अपने संबोधन में उन्होंने मुस्लिम महिला विधेयक पेश करने का वादा किया।
संसद के बजट सत्र के पहले दिन, जो शुरू होने वाला था
5 फरवरी 1986 को मुस्लिम महिला विधेयक ने हलचल मचा दी।
जैसे ही इसकी घोषणा हुई, कुछ ही घंटों के भीतर सरकार ने खुद को
रक्षात्मक स्थिति में, उसे छिपने के लिए भागना पड़ा। उसे बचने के तरीके खोजने पड़े।
विधेयक से ध्यान हटाने और 'संतुलन बनाने' का प्रयास करना।
वादे के मुताबिक विधेयक को पहले दिन पेश नहीं किया जा सका।
संसद का बजट सत्र। मुस्लिम महिलाओं का संरक्षण।
तलाक के अधिकार विधेयक को अंततः 25 फरवरी 1986 को ही पेश किया गया था।
लोकसभा में कानून मंत्री द्वारा। राजीव गांधी ने जोरदार भाषण दिया।
इसका बचाव करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि शाह बानो फैसले में
इससे कुछ समुदायों के मन में अनिश्चितता पैदा हो गई।
उन्होंने अपने निजी कानूनों के अधिकार का बचाव किया; इसने इसे मजबूत किया
धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने के बजाय, उन्होंने इसे और मजबूत किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि महिलाएं
इस विधेयक के तहत सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मिलने वाली राशि से अधिक राशि प्राप्त होगी (के तहत)
जिसके तहत शाह बानो को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भरण-पोषण प्रदान किया गया था न्यायालय)। सीआरपीसी ने महिलाओं को नाममात्र का मुआवजा दिया। 'मुसलमान (आम तौर पर) करते हैं
राजीव गांधी ने कहा, 'संसद को अपने कानूनों में संशोधन करने का अधिकार स्वीकार नहीं करना चाहिए।'
इकट्ठे हुए सांसदों ने कहा, 'अब वे खुद हमसे इस विषय पर कानून बनाने को कह रहे हैं।'
यह (पहलू)।' यह भविष्य के लिए एक अच्छा विकास था।
बिल पेश होने के तीन दिन बाद, न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर, एक
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने चेतावनी दी थी—उनके शब्द ही उलटे पड़ गए।

यह भविष्यवाणी सच साबित हुई कि इससे 'सोया हुआ हिंदू महाशक्ति' जाग उठेगी।
और देश में प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना।
यह विधेयक अंततः तीन महीने बाद मई 1986 में पारित हुआ।
संसद के दोनों सदनों में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण (संरक्षण)
तलाक पर कानून, 1986। भारत के विभिन्न हिस्सों में महिला कार्यकर्ताओं ने
विरोध में काली पट्टियाँ; मुसलमानों के लिए यह एक मामूली जीत थी।
और संसद में हुई बहस ने एक नई वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया—एक सांप्रदायिक
उत्तर भारत में ऐसा विभाजन फैल गया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी।

■

आरिफ मोहम्मद खान ने मन बना लिया था कि वह इस्तीफा दे देंगे।
जिस दिन संसद में विधेयक पेश किया गया था।
उसने घर के फर्श पर अदालत के फैसले का बचाव किया, वह इसे अच्छी तरह जानता था।
अगर सरकार में बदलाव होता रहा तो उनके लिए सरकार में बने रहना असंभव हो जाएगा।
फैसले का समर्थन करें।
बिल पेश होते ही खान लोक हॉल की ओर वापस चले गए।
सभा में बैठकर उन्होंने एक बेंच पर अपना त्यागपत्र लिखा।
इसके बाद वे संसद में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर चले गए।
उसने घर जाकर पत्र वहीं छोड़ दिया। वह उस दिन घर नहीं गया। इसके बजाय,
वह डिफेंस कॉलोनी में एक दोस्त के घर गया जहाँ उसने कुछ समय बिताया।
रात। उसे आशंका थी कि उसके विरोधी उसे ढूंढ निकालेंगे।
उसके दरवाजे पर जाकर हंगामा खड़ा कर दिया। अगली सुबह वह चला गया।
वह अपने कार्यालय लौट गया। उसे मिस्रवासी से मिलने का समय मिला था।
राजदूत। उन्होंने अपने सचिव को अपनी सभी नियुक्तियाँ रद्द करने का आदेश दिया।
अपना सामान समेटा और संसद की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह

संसद भवन में प्रवेश करते ही उन्होंने अरुण सिंह को इधर-उधर टहलते हुए पाया।
बेचैनी से।
‘मैं तुम्हें ढूंढ रहा था,’ सिंह ने कहा। वह खान को अपने साथ ले गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय के बगल वाला प्रतीक्षालय।
उन्होंने कहा, ‘आपने एक सराहनीय कार्य किया है। इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता।’
आपके साथ।’ लेकिन उन्होंने उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया।
‘इससे स्थिति उत्पन्न होगी।’
राजीव के लिए समस्याएं।
मैं इसे वापस ले लूंगा। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं लगभग मृत समान हो जाऊंगा...।
मैंने पचपन मिनट तक फैसले का बचाव किया, अब मैं बचाव करूंगा।
ठीक इसके विपरीत, पचपन मिनट तक।’ यह काम नहीं करेगा, उन्होंने कहा।
सिंह।
अरुण नेहरू ने भी उनसे संपर्क किया और उन्हें पदभार ग्रहण करने के लिए मनाने की कोशिश की।
अपना इस्तीफा वापस ले लिया। खान ने याद करते हुए कहा, 'डेढ़ घंटे तक उन्होंने अपना इस्तीफा रखा।'
मुझ पर बहुत दबाव है।' हालाँकि दोनों एक साथ कदम मिलाकर चल रहे थे।
नेहरू जानते थे कि सरकार छोड़ने से खान की स्थिति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वे इस विधेयक को लेकर चिंतित थे।
पद।
‘मैं संसद में था और मैंने सदन में आरिफ को स्पष्ट रूप से परेशान देखा,’ अरुण ने कहा।
नेहरू ने मुझे बताया, 'मैंने उसे मजबूर किया कि वह मुझे बताए कि क्या हुआ था।'
इसके बाद नेहरू राजीव से मिलने के लिए रवाना हो गए।

‘आप क्या कर रहे हैं?’ उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा। ‘आरिफ को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है।’

आपकी आज्ञा पर नियुक्त मंत्री। वह आपके विश्वासपात्र थे। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
राजीव ने उसे 'लंबी व्याख्या' दी और अंत में कहा, 'तुम बोलो'
आरिफ इससे बाहर है।
खान ने अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया।
नेहरू ने फिर से राजीव से पूछा, 'आप अपना दुश्मन क्यों बना रहे हैं?'
यह आदमी?
राजीव ने उनसे खान से एक बार फिर बात करने को कहा।
खान ने फिर कहा कि वह अपना इस्तीफा वापस नहीं ले सकते। '(लेकिन) आरिफ
(तब) उन्होंने दो या तीन छोटी आवश्यकताएँ बताईं जो थीं
उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों के समायोजन जैसी महत्वहीन बातें।
कांग्रेस समिति।
नेहरू ने आगे कहा, 'मैं आरिफ को राजीव के पास ले गया और कहा कि वह नहीं जा रहा है।'
मंत्रालय में वापस आओ लेकिन उसे बताओ कि आरिफ क्या चाहता था।
'ठीक है,' राजीव ने कहा, 'मैं इसे संभाल लूंगा।' यह एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण मुलाकात थी।
दो घंटे बाद राजीव ने नेहरू को फोन किया। उन्होंने कहा, 'कुछ मत करो।'
थोड़ी देर रुकिए।
नेहरू ने विरोध करते हुए कहा: 'राजीव, तुमने आरिफ से पहले भी यही कहा था। यह उल्लंघन है।
विश्वास का।' प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से विरोधियों के दबाव में आ गए थे।
आरिफ ने कांग्रेस में लॉबिंग की ताकि खान जो चाहता था वह न किया जाए।
नेहरू ने मुझसे कहा, 'राजीव का व्यवहार अक्षम्य था।' इससे मामला और बिगड़ गया।
स्थिति और भी बदतर हो गई जब कुछ दिनों बाद, नेहरू ने आंतरिक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।
सुरक्षाकर्मियों को खुफिया एजेंसी से एक रिपोर्ट मिली है। 'आरिफ शारीरिक रूप से हिरासत में लिया जाएगा।'
'हमला किया गया', उसने चेतावनी दी।

मैंने उसके आगे और पीछे सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली थी।
नेहरू ने कहा, “निश्चित रूप से, उन पर हमला हुआ था। राजीव ने कुछ नहीं कहा।”
आप लोगों को इस तरह नहीं छोड़ सकते।'
जब खान संसद के केंद्रीय हॉल में दाखिल हुए,
जब उन्होंने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया, तो वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं।
MPs who were sitting there. ‘Mujhe jahaan tak yaad hai,’ Khan
recalled, ‘ki jab main resign karne ke baad Central Hall mein aaya
hoon, toh paanch minute tak poora central hall khada ho gaya thaa
(जहां तक मुझे याद है, जब मैं सेंट्रल हॉल गया था)
संसद से इस्तीफा देने के बाद, वहां मौजूद सभी लोग पांच मिनट तक खड़े रहे।
और तालियाँ बजाईं।
तालियों की गड़गड़ाहट महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह मूल रूप से
कांग्रेस सांसदों ने कहा, 'राजीवजी घबराए तो उसी से थे (कांग्रेस सांसदों की इस ताली बजाने से राजीव चिंतित हो गए थे)।'
एक अन्य कांग्रेस नेता ने उस दिन खान को समझाने की कोशिश की थी।
वह नरसिम्हा राव थे। राव ने उन्हें जो बताया था, उसे याद करते हुए खान ने कहा, 'मैं मैं आपको वही शब्द बता रहा हूँ जो उसने कहे थे...
Rao told him. ‘Arif, tum bahut ziddi aadmi ho (you are a very जिद्दी आदमी)। तुम यह बात अपने दिमाग में क्यों नहीं बिठा लेते कि हम
game of politics? We want votes. Hum apne vote ko kyon khrab karaen
(हमें अपने वोट क्यों खराब करने चाहिए?) आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम सामाजिक हैं?
सुधारवादी? यह हमारी भूमिका नहीं है।
अगर मुसलमान सामाजिक सुधार नहीं चाहते और वे यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं

उन्होंने कहा, 'इस अंधकार और पिछड़ेपन के साये में श्रम करने के लिए, चलो उन्हें।'
उनके अगले वाक्य ने मुझे और भी चौंका दिया। उन्होंने कहा, “अगर ये (द Muslims) gadde mein pade rehna chahte hain toh pade rehne do (If
अगर वे गटर में रहना चाहते हैं, तो उन्हें वहीं रहने दो।
फिर राव ने अपना आखिरी वार किया, ‘अब तो शाह बानो भी कह चुकी हैं कि वह अदालत द्वारा स्वीकृत भरण-पोषण राशि छोड़ देगी। तो फिर क्या है? आरिफ, तुम्हारी क्या समस्या है?
■

जबकि राजनेता, धर्मगुरु और मुस्लिम समुदाय के मुखर वर्ग
समुदाय इस विवाद पर आपस में झगड़ रहा था, महिला
इन सब के केंद्र में रहीं शाह बानो पर भारी दबाव आ गया था।
समुदाय चाहता था कि वह पारंपरिक इस्लामी कानून का पालन करे।
अंततः शाह बानो मान गईं।
‘प्रमुख मुस्लिम नेता सैयद शहाबुद्दीन ने हमारे घर का दौरा किया था।’
शाह बानो के बेटे जमील ने बाद में कहा कि वह यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके
मां ने अपना मन बदल लिया था। इंदौर के उलेमा ने भी ऐसा ही किया।
अन्य शहरों ने हमें बताया कि (सर्वोच्च न्यायालय का) फैसला हमारे खिलाफ था।
शरीयत। हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी (शरीयत के प्रावधानों के बारे में)।
रखरखाव, आदि) तो...हमारी माँ अनपढ़ थीं।’ पादरीगण
भारत और विदेश ने पैसे और यहां तक कि विदेश में नौकरी की पेशकश की (अस्वीकार करने पर)।
रखरखाव)... पत्रकार... आने लगे... दबाव
हालात ऐसे हो गए थे कि...(हमें यह भी लगा) कि अगर हम हार गए होते तो बेहतर होता।

(सुप्रीम कोर्ट में मामला),' जमील ने कहा।

देश भर में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया।
परिवार पर। 'इंदौर में भी एक लाख लोगों की रैली हुई थी जो
हमारे घर के सामने से गुजरा...अगर हर प्रदर्शनकारी एक-एक कंकड़ फेंकता, तो हमारा
कच्चा मकान ढह जाता।
तभी शाह बानो को राजीव गांधी का संदेश मिला।
वह उससे मिलना चाहता था। शाह बानो और जमील दिल्ली के लिए रवाना हुए।
दिसंबर 1985 की शुरुआत में, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई।
प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि स्थिति 'बेहद नाजुक' है।
राजीव ने कहा, 'हमें कोई न कोई रास्ता निकालना होगा।'
मैंने उसे बताया कि मैंने तब से विवाह संबंधी शरीयत के निर्देशों के बारे में पढ़ लिया है।
और रखरखाव,' जमील ने कहा, '...के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
इद्दत और मेहर के दौरान भुगतान की जाने वाली राशि को छोड़कर, भरण-पोषण के लिए आवश्यक धनराशि।
(तलाक के समय भुगतान की जाने वाली राशि)।
'राजीव ने हमसे यह घोषणा करने को कहा कि हम रखरखाव से इनकार कर रहे हैं।'
(सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया पुरस्कार),' जमील ने याद किया।
इंदौर लौटने के बाद शाह बानो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
उन्होंने घोषणा की कि वह अदालत द्वारा आदेशित भरण-पोषण राशि नहीं ले रही हैं।
क्योंकि यह शरीयत के खिलाफ था। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि प्रधान मंत्री कौन थे।
मंत्री ने उनसे कहा था। शाह बानो और उनके परिवार ने भी फैसला किया।
'मेहर' की वसूली के लिए दायर किया गया मुकदमा वापस ले लिया गया, जो कि 3,000 कलदार थे।
(चांदी के सिक्के)'।
जमील ने कहा: 'मुझे लगा था कि मेरी माँ दो, पाँच, दस साल और जिएंगी।'

वर्षों। लेकिन अगर हम (शाह बानो के फैसले को स्वीकार करने के लिए) सहमत होते हैं, तो हम होंगे।
उन्हें हमेशा के लिए उन लोगों के रूप में कलंकित किया जाएगा जिन्होंने सरकार या अदालतों को सत्ता में लाया।
शरीयत में दखल देना। ऐसे कलंक के साथ जीने का कोई मतलब नहीं है।
आप पर।'
शाह बानो की कहानी का सबसे मार्मिक पहलू वह था जो घटित हुआ।
नाटक के केंद्र में मौजूद निर्धन महिला शाह बानो को ही संबोधित करते हुए।
जिससे भारतीय राजनीति में बदलाव आना था। 1992 में मस्तिष्क आघात से उनकी मृत्यु हो गई।
रक्तस्राव के बावजूद, उसे प्रति माह 179.20 रुपये का भुगतान भी नहीं किया जा रहा था।
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उसके पति को चुकाने का आदेश दिया था।
पंद्रह साल बाद, 28 सितंबर 2001 को, पांच न्यायाधीशों की पीठ ने
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए धारा 3(1)(ए)
(तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 का संबंध इद्दत से नहीं था।
लेकिन यह अवधि तलाकशुदा पत्नी के पूरे जीवन तक विस्तारित होती है जब तक कि वह
दूसरी शादी करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा की व्याख्या की।
इसका अर्थ यह था कि उसे इद्दत की अवधि के लिए नहीं बल्कि इद्दत की अवधि के दौरान एक उचित और तर्कसंगत राशि का भुगतान किया जाना था। यह राशि उसकी देखभाल के लिए थी।
अपने शेष जीवन के लिए।
1985 में इस कानून का मसौदा तैयार करने वाले कानून मंत्री अशोक सेन ने
सफल रहे। लेकिन कई मुसलमानों को ठगा हुआ महसूस हुआ। उनसे किया गया वादा, कि
कानून उस फैसले को रद्द कर देगा जिसे वे हस्तक्षेप मानते थे।
मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं किया गया था। लेकिन कानून के लागू होने के तुरंत बाद

इसे पेश किया गया था, और उन्होंने 1986 के मध्य में कानून में मौजूद 'खामी' को पकड़ लिया था।
अली मियां ने अपने समर्थकों से कहा कि वे इसे मुद्दा न बनाएं। लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसा किया।
विधेयक का मसौदा तैयार करते समय सभी से परामर्श किया गया था। इससे केवल यह पता चलेगा कि...
उन्हें गलत रोशनी में दिखाया गया। बाद में, अदालत ने माना कि मुस्लिम महिलाओं के यह अधिनियम 'असंवैधानिक नहीं था'। न ही इसने अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन किया।
संविधान।
शाह बानो के फैसले ने भारत को इस तरह विभाजित कर दिया जैसा कि कुछ ही कानूनी लड़ाइयों ने किया है।
और इस मामले की केंद्र में मौजूद महिला को कोई मदद नहीं मिली। मामला और भी उलझता चला गया।
वैधता या महिलाओं के अधिकारों के बारे में, और राजनीति के बारे में अधिक।
हिंदू-मुस्लिम आधार पर श्रेष्ठता की होड़।

सातवीं

'Taala khulwa do,' Arun Nehru advised the prime minister (Get the
ताले खुल गए)। यह जनवरी 1986 के तीसरे सप्ताह की बात है। एक चिंतित
राजीव ने अपने चचेरे भाई को सलाह लेने के लिए बुलाया था। 18 जनवरी 1986 को,
आर एंड एडब्ल्यूए और आईबी प्रमुखों ने राजीव गांधी को रिपोर्ट दी थी कि
सरकार के रुख को लेकर हिंदुओं में असंतोष बढ़ता जा रहा था।
शाह बानो फैसले को पलटने का निर्णय।
नेहरू ने सुझाव दिया कि गेट 'ओ' पर दो ताले लगे हुए थे।
और 'पी'—बाबरी मस्जिद के परिसर में खोला जाए। जैसा कि उल्लेख किया गया है, एक
राम की मूर्ति को गुप्त रूप से गर्भगृह में स्थापित किया गया था।

दिसंबर 1949 में उग्रवादी हिंदुओं द्वारा मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया। यह मस्जिद, जो बाद में एक
विवादित ढांचे को बंद कर दिया गया था, और न तो मुसलमानों को और न ही
हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।
बंद ग्रिल के बाहर। श्री राम मुक्ति यज्ञ समिति, एक मुखौटा संगठन।
विश्व हिंदू परिषद ने रथ यात्रा का आयोजन किया था।
सीतामढ़ी (जहां सीता का प्रकट होना कहा जाता है) से अयोध्या तक 25 तारीख को
सितंबर 1985 में, राम जन्मभूमि की मुक्ति की मांग की गई।
अगर राजीव ताले खुलवाकर वहां मंदिर बनवा लेता, तो 'हिंदुओं
khush ho jayengae (The Hindus will be happy),' Nehru told Rajiv.
उन्होंने अपने चचेरे भाई को बताया कि कई हिंदू राजीव के रवैये से नाराज थे।
मुसलमानों को 'तुष्ट करना'।
अरुण नेहरू ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा
कि वह अपनी पकड़ खो रहा था। यह सिर्फ रूढ़िवादी और
कट्टरपंथी हिंदू जो उनसे नाराज थे, यहां तक कि उदारवादी मत भी।
अब हालात उनके खिलाफ हो रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक, गिरिलाल
जैन ने राजीव गांधी के खिलाफ एक तीखा लेख लिखा था, जो
मध्यम वर्ग को प्रभावित करना। अब तक वे राजीव को अपना नया नेता मानते थे।
मसीहा। एक अन्य प्रख्यात संपादक, अरुण शौरी ने दो पुस्तकें लिखी थीं।
उसी अखबार में समान रूप से आलोचनात्मक लेख—प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना करते हुए
अपने रुख में बदलाव लाने और आरिफ मोहम्मद खान को धोखा देने के लिए; वह भी
राजीव की आलोचना करते हुए कहा गया कि उन्होंने अपने ही विभागों की सलाह को नजरअंदाज किया।
विधि और गृह मंत्रालय—शाह बानो के फैसले को पलटने के लिए नहीं।
राजीव गांधी ने अरुण शौरी को अपने यहाँ बुलाया। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई।

संसद भवन में। नरसिम्हा राव और एच. आर. भारद्वाज भी उपस्थित थे।
उपस्थित। 'मैंने राजीव को मुस्लिम पर्सनल लॉ से पूरी तरह निर्दोष पाया,
भारत में प्रचलित कानूनी मामलों और यहां तक कि (जिस विधेयक को वह पारित करने की योजना बना रहे थे) के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है,' शौरी ने कहा।
याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि यह विधेयक प्रतिक्रिया को भड़काएगा।'
लोगों को पहले से ही यह महसूस होने लगा था कि राज्य झुक रहा है।
चरमपंथियों से पहले। यह घटना पंजाब में घटी थी (और इसने जानमाल का नुकसान किया था)।
उनकी माता, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित।
‘तिहत्तर वर्षीय व्यक्ति को प्रति माह 179.20 रुपये का भुगतान करना कैसे उचित हो सकता है?’
'क्या बेसहारा महिलाएं इस्लाम को खतरे में डाल सकती हैं?' शौरी ने प्रधानमंत्री से पूछा। महिलाओं
समूह भी हिंसक होने की राह पर थे।
‘Taala khul sakta hai kya (Can the locks be opened)?’ Rajiv asked
आरिफ मोहम्मद खान के अनुसार, जिन्होंने मुझे यह बताया, अरुण नेहरू थे।
कहानी।
‘इसकी जांच करो, क्या यह संभव है?’ राजीव ने अपने चचेरे भाई से कहा।
नेहरू ने कहा, 'मैं पता लगाऊंगा कि क्या किया जा सकता है।'
नेहरू ने (जैसा कि उन्होंने खान को बताया था) फिर वीर बहादुर से बात की।
सिंह, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यमंत्री, जहां विवादित बाबरी जलसंधि स्थित है।
मस्जिद स्थित थी।
राजीव को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वीर बहादुर सिंह पहले से ही इस काम में लगा हुआ था।
एक महीने पहले, 19 दिसंबर 1985 को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
अयोध्या में मंदिर में आयोजित रामायण मेले में भाग लेने के लिए गए थे।
शहर में रहते हुए, सिंह ने अधिकारियों से पूरी फाइल दिखाने को कहा। वहां पहुंचकर,

सिंह ने अधिकारियों से इस मामले पर पूरी फाइल दिखाने को कहा।
अयोध्या विवाद। अधिकारियों से मिली जानकारी और अध्ययन के बाद, उन्होंने
पता चला कि ताले किसी 'प्रशासनिक' अधिकारी द्वारा लगाए गए थे।
और 1949 में 'यह न्यायिक आदेश नहीं था'। उन्होंने कथित तौर पर इसके बंद होने के संबंध में कोई विशिष्ट अदालती आदेश नहीं पाया। यात्रा के दौरान, उन्होंने मुलाकात की।
इस मुद्दे पर उनकी राय जानने के लिए वीएचपी के सदस्यों से बात की गई।
चूंकि वीर बहादुर सिंह अरुण नेहरू के शिष्य थे, इसलिए यह बात समझ से परे नहीं है।
यह अकल्पनीय है कि नेहरू ने उन्हें बुलाए जाने से पहले ही इस काम पर लगा दिया था।
उन्होंने राजीव से बात की और ताले खोलने का सुझाव दिया। सिंह ने राजीव का आभार व्यक्त किया।
नेहरू ने उन्हें सितंबर 1985 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, जिसके बाद
राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। 18 सितंबर 1985 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. डी.
तिवारी ने अचानक राजीव गांधी को पत्र लिखकर अपनी इच्छा व्यक्त की थी।
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। सभी ने केवल एक ही नाम का जिक्र किया।
उनके उत्तराधिकारी के रूप में विधायक वीर बहादुर सिंह। छोटे कद के और देहाती वीर बहादुर सिंह।
उत्तर प्रदेश से अच्छी तरह वाकिफ बहादुर सिंह ने पदभार संभाला।
24 सितंबर 1985 को राज्य के नए मुख्यमंत्री। अगला
सुबह तिवारी दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली।
राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में उद्योग को विशेष स्थान दिया गया। 1985 में उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान भी उद्योग जगत को प्राथमिकता दी गई।
विधानसभा में, विजयी हुए 269 कांग्रेस विधायकों में से, बहुमत (लगभग 150) प्राप्त हुआ।
अरुण नेहरू-वीर बहादुर सिंह के अनुयायी थे। जब इंदिरा गांधी

अगर वह जीवित होतीं, तो उन्होंने सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के नेहरू के विचार को खारिज कर दिया होता।
मंत्री। लेकिन सितंबर 1985 में, नेहरू ने अपनी बात मनवा ली और स्थिति को और मजबूत कर दिया।
उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़।
आरिफ मोहम्मद खान के अनुसार, नेहरू राजीव को रिपोर्ट करते थे।
ताले खुलने पर।
'Tell Vir Bahadur, khulwaye (Tell Vir Bahadur Singh to get it
खोला गया),' प्रधानमंत्री ने नेहरू को निर्देश दिया।
नेहरू ने प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री को फोन किया।
'डीएम से कहो कि ताला खोलो (डीएम से कहो कि ताले खुलवाएं),'
नेहरू ने राजीव की उपस्थिति में सिंह से कहा, 'कितने दिनों में यह संभव हो सकता है?'
ताले खोले जा सकते हैं?
Then, suddenly he handed the phone to Rajiv. 'Lo PM se baat karo
नेहरू ने कहा, '(यहां प्रधानमंत्री से बात करें)।'
नेहरू ने बाद में आरिफ खान से कहा, 'मैं नहीं चाहता था कि बाद में ऐसा कहा जाए कि...'
अरुण नेहरू ने वीर बहादुर सिंह (अपने स्वयं के) को निर्देश दिए थे
समझौता)।
नेहरू ने बताया, 'वीर बहादुर को निर्देश राजीव गांधी ने ही दिए थे।'
खान।
मुझे नहीं पता कि अरुण नेहरू ने मुझे जो बताया वह सही था या नहीं।
'गलत है,' खान ने मुझे वर्षों बाद बताया, 'लेकिन उसने मुझे यही बताया था।'
उस समय स्थिति ऐसी थी कि यदि नेहरू निर्देश देते,
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये संदेश सीधे प्रधानमंत्री की ओर से आ रहे हैं। 'मैं बस इतना ही कह सकता हूँ।'
कहा जाता है कि अरुण नेहरू (दिल्ली से) पूरे मामले का प्रबंधन कर रहे थे।

वीर बहादुर सिंह ने अपने दोस्तों से कहा, जब वे केंद्रीय मंत्री बने थे...
Rajiv Gandhi's cabinet in 1988.
दिल्ली से मिले स्पष्ट निर्देशों के साथ, यूपी के मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की।
संदेशवाहक से उन्होंने सबसे पहले महंत अवैद्यनाथ से मुलाकात की, जो प्रमुख थे।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली गोरखपुर पीठ; अवैद्यनाथ वहां थे।
18 तारीख को राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।
जुलाई 1985। उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। अवैद्यनाथ की तरह, वीर
बहादुर सिंह भी गोरखपुर के ही रहने वाले थे। उन्हीं के माध्यम से—और
स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से—सिंह ने वीएचपी को संदेश भेजा,
यह सुझाव दिया गया कि वीएचपी ताले खुलवाने के लिए अदालत का रुख करे।
जब उन्हें वह जवाब मिल जाएगा जिसकी वे तलाश कर रहे थे।
अधिकारियों (यथासः जिला मजिस्ट्रेट और
पुलिस अधीक्षक ने अनौपचारिक रूप से वीएचपी से एक याचिका दायर करने का अनुरोध किया।
के. आर. मलकानि ने बाद में लिखा, 'ताली खोलने के लिए आवेदन।'
परिसर में, सकारात्मक प्रतिक्रिया के आश्वासन के साथ, मलकानी थे।
मदरलैंड के संपादक, जो आरएसएस-वीएचपी के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक समाचार पत्र है।
लेकिन वीएचपी ने इस झांसे में न आने का फैसला किया। वीएचपी को इसमें दिलचस्पी थी।
मालकानी ने खुलासा किया, 'खुला ताला खोलने में तो मदद मिली, लेकिन अदालत जाने में नहीं।'
ताले खुलवाने के लिए वर्षों से आंदोलन करते रहे, वे इसे लेना चाहते थे।
इसका श्रेय उसे दिया जाना चाहिए, और दूसरों को इस मुद्दे को अपने हाथ में लेने नहीं देना चाहिए।
अरुण नेहरू, जो हिंदू भावनाओं को एकजुट करना चाहते थे
कांग्रेस के पीछे रहकर, उन्होंने अपनी सीधी संपर्क रेखा स्थापित कर ली थी।
वीएचपी के साथ संचार—वीएचपी से उनके संबंधों में से एक बी.पी. थे।
सिंघल, वीएचपी नेता अशोक सिंघल के छोटे भाई। 1986 में, बी.पी.

सिंघल गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे।
अरुण नेहरू के राज्य मंत्री रहते हुए उनके सीधे अधीन काम करना।
गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा का प्रभारी।
अशोक सिंघल ने एक साक्षात्कार के दौरान मुझसे कहा था
अप्रैल 1986 में ताले खोलने का निर्णय 'ठीक उसी समय' लिया गया था।
शीर्ष पर। 'अरुण नेहरू ने इस तख्तापलट की योजना बनाई थी,' सिंघल ने कहा था।
हम
उनकी मुलाकात विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के उस समय के कार्यालय में हुई थी,
जो नई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में स्थित था।
अशोक सिंघल ने उस दिन मुझे जो बताया, उसके अनुसार अरुण नेहरू ने
उन्होंने यह विचार गढ़ा, राजीव गांधी को बेचा और फिर इसे अंजाम दिया। विश्व हिंदू
परिषद को पहले ही यह 'आश्वासन' दिया गया था कि ताले लगे रहेंगे।
राम जन्मभूमि के द्वार खोले जाएंगे।
राजीव गांधी ने स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया था कि द्वार
राम जन्मभूमि शिवरात्रि (8 तारीख) से पहले भक्तों के लिए खुल जानी चाहिए।
सिंघल ने कहा, 'मार्च 1986।'

सातवीं

राजीव गांधी और अरुण नेहरू का राजनीतिक दीक्षा समारोह
यह घटना इंदिरा गांधी के सबसे हिंदूवादी दौर में घटी।
नेहरू भी इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है।
इसके पीछे हिंदू हैं। वह खुद को 'बाज' होने पर गर्व करता था।
दूसरी ओर, सहज स्वभाव वाले राजीव ने परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए, और
जो उसकी माँ चाहती थी।
जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, इंदिरा गांधी ने अपना रुख बदल लिया था।
1977 में अपनी हार के बाद से वह तेजी से धार्मिक हो गईं।
मीनाक्षीपुरम में जो कुछ हुआ, उससे वह चिंतित थी। 18 अप्रैल 1981 को,
दलित पल्ला जाति के 800 हिंदुओं का धर्मांतरण कर दिया गया था।
तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम मंदिर नगर में इस्लाम।

आरएसएस ने इसके खिलाफ जमकर विरोध जताया। जब वह सत्ता में वापस आईं तो...
1980 में, वह बदलते हुए माहौल के प्रति और भी अधिक सचेत हो गई थी।
हिंदू—और उनसे संपर्क साधने की आवश्यकता।
आरएसएस ने ही उसे यह सूचना भेजी थी कि करण सिंह ही वह व्यक्ति है।
कांग्रेस को जिस सर्वश्रेष्ठ हिंदू चेहरे को आगे बढ़ाना चाहिए, वह यही है। उनकी हिंदू साख।
वे बेदाग थे, वे वैष्णो देवी ट्रस्ट के प्रमुख थे। लेकिन वह थीं
शाह आयोग में उसके खिलाफ गवाही देने के कारण वह उससे बहुत नाराज थी।
आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था।
1980 के चुनावों में स्वतंत्र उम्मीदवार। हालाँकि, वहाँ शायद ही कोई था।
1975-80 के बीच इंदिरा गांधी और करण सिंह के बीच संपर्क हुआ था।
1980 के बाद उनसे सुलह करने का फैसला किया।
1981 में, करण सिंह ने विराट हिंदू समाज की स्थापना की; उन्होंने यह कार्य किया।
विश्व हिंदू परिषद के साथ सहयोग। अशोक सिंघल इसके संस्थापक थे।
विश्व हिंदू परिषद के महासचिव; आरएसएस ने इस प्रयास का समर्थन किया। और इसमें इंदिरा गांधी भी शामिल थीं।
गांधी जी की मौन स्वीकृति।
कर्ण सिंह ने विराट हिंदू सम्मेलन (मेगा हिंदू) का आयोजन किया
हिंदू एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने देशभर में सम्मेलन आयोजित किए। हालाँकि उन्होंने
इंदिरा गांधी की इसमें भूमिका होने से इनकार करते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि 'होने के नाते
एक चतुर राजनीतिज्ञ होने के नाते, उन्होंने इन सम्मेलनों का लाभ उठाया। वे इस धारणा को फैलने देने में संतुष्ट थीं।
कि 1981 की पहल को उनका आशीर्वाद प्राप्त था।
राजीव गांधी और अरुण नेहरू ने भी इंदिरा गांधी को मौन रूप से देखा था।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा 1983 में शुरू की गई एकात्मा यात्रा का समर्थन

करें।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने पचासी प्रमुख हिंदू संप्रदायों के समर्थन से यात्राएं कीं।
हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से 3 लाख गांवों तक पहुंच बनाना। बानवे धार्मिक
देश के विभिन्न हिस्सों से होकर कारवां गुजरे। ट्रक
गंगा नदी के पानी से भरा एक 8 फुट का बर्तन और एक तस्वीर ले जा रहा था।
शेर पर सवार देवी भारत माता की छवि। इसी के साथ, भारत माता।
हिंदू धर्म के 33,000 देवी-देवताओं के समूह में शामिल हो गया।
धर्म।
एकात्मा की यात्रा देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। वे 50 सीसी की बंदूकें खरीदते थे।
वक्ताओं ने गंगा जल (पवित्र गंगा जल) की बोतलों के बारे में चेतावनी दी।
'हिंदू धर्म खतरे में है' और 'वोट बैंक के रूप में मुसलमानों को लाड़-प्यार करना'।
यह एल. के. आडवाणी की सात साल बाद शुरू होने वाली राम रथ यात्रा का एक प्रारंभिक कार्यक्रम था।
बाद में 1990 में, सोमनाथ से अयोध्या तक।
इंदिरा गांधी लगभग यात्रा की एक सभा में शामिल होने ही वाली थीं। लेकिन उन्होंने अंतिम क्षण में इसके विरुद्ध निर्णय लिया गया। '1983 में एकात्मा की यात्रा'
अनिल बाली ने खुलासा किया, 'विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) को इंदिरा गांधी द्वारा वित्त पोषित किया जाता था।'
अरुण नेहरू एक तेज सीखने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने देखा था कि इंदिरा गांधी किस प्रकार प्रयोग करती थीं।
उसने बिना खुलकर बताए यात्रा का लाभ उठाया। उसे वरिष्ठता मिल गई।
पार्टी के नेताओं ने इसकी निंदा की। लेकिन उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा।
वह दोनों तरफ से खेल खेलना जानती थी। वह चुपचाप भी थी।
अचानक पनपे नए हिंदू संगठनों को प्रोत्साहित करना
-हिन्दू मंच, हिन्दू सुरक्षा समिति, उत्तर भारत का हिन्दू शिव
सेना (महाराष्ट्र की शिव सेना से भिन्न)।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) को अपना पहला धर्म प्रदर्शन आयोजित करने में सक्षम बनाया।

7-8 अप्रैल 1984 को संसद (हिंदू प्रचारकों का धार्मिक सम्मेलन) में
सरकार का प्रतिष्ठित सम्मेलन केंद्र, विज्ञान भवन में
दिल्ली। यह बैठक, जिसकी अनुमति के बिना आयोजित नहीं की जा सकती थी।
शीर्ष नेतृत्व ने हिंदुओं को तीन मंदिर वापस करने की मांग की—
Ram Janmabhoomi in Ayodhya, the Kashi Vishwanath Temple in
Varanasi, and the Shri Krishna Janmasthan in Mathura.
अप्रैल 1986 में एक साक्षात्कार के दौरान, विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक ने कहा:
सिंघल ने मुझे बताया था कि इंदिरा गांधी ने इसका उपयोग करने पर विचार किया था।
'अयोध्या को एक चुनावी मुद्दा बनाना' 'उचित समय पर'।
स्पष्टतः, वह लोगों की भावनाओं के प्रति अधिक सचेत हो गई थी।
हिंदुओं को मुसलमानों या सिखों की भावनाओं की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। सीपीआई
(एम) नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की थी कि
अब इंदिरा गांधी के लिए हरियाणा के हिंदुओं के हित अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे।
गांधी जी ने पंजाब समस्या के समाधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तीन गुना अधिक
पंजाब और के बीच विवाद पर समझौता हो गया था
उन्होंने कहा कि हर बार वह चंडीगढ़ के बजाय हरियाणा से पीछे हट गईं।
इंदिरा गांधी तेजी से एक हिंदू समर्थक नेता की छवि हासिल कर रही थीं।
और यही तो वह चाहती थी।
■

जब से राजीव गांधी सांसद बने, तब से उन्हें पता था कि उनकी मां
आरएसएस से संपर्क साध रहा था। आपातकाल के वर्षों के दौरान, आरएसएस ने
उन्होंने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उनके प्रति उदासीन थी। 1977 में
जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, चुनावों के दौरान उन्होंने उनसे मदद मांगी थी।
लेकिन तब तक वे जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके थे।

लेकिन इंदिरा गांधी ने आरएसएस के किसी भी नेता से मिलने से इनकार कर दिया था।
व्यक्तिगत रूप से—जैसा कि संजय गांधी ने किया था।
लेकिन 1982 में, अपने कार्यकाल के लगभग आधे समय में, उन्होंने राजीव से मिलने का अनुरोध किया।
आरएसएस नेता भाऊराव देवरास से बातचीत शुरू करें।
कपिल मोहन द्वारा तय की गई बैठकें सार्वजनिक जानकारी में नहीं थीं।
अरुण नेहरू को इनके बारे में जानकारी नहीं थी। आरएसएस प्रमुख के भाई भाऊराव।
बालासाहेब देवरास संगठन के राजनीतिक विंग की देखरेख करते थे।
और उसे राजीव से दोस्ती करने का काम सौंपा गया था।
राजीव गांधी ने 1982-84 के बीच भाऊराव से तीन बार मुलाकात की, जब इंदिरा गांधी सत्ता में थीं।
वह तब भी प्रधानमंत्री थे, और एक बार 1991 की शुरुआत में, जब वह सत्ता से बाहर थे।
पहली बैठक सितंबर 1982 में 46, पूसा रोड पर आयोजित की गई थी।
कपिल मोहन का निवास स्थान। मोहन और भाऊराव की दोस्ती काफी पुरानी थी।
कई वर्षों तक। दूसरी बैठक भी पूसा रोड पर हुई थी।
तीसरा कार्यक्रम फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित अनिल बाली के आवास पर आयोजित किया गया था।
चौथी बैठक 10, जनपथ में आयोजित की गई।
अनिल बाली इन बैठकों में राजीव गांधी के साथ जाया करते थे। सुभाष
भाऊराव के बेहद करीबी भाजपा नेता आर्य उनके साथ जाया करते थे।
उससे पहली मुलाकात एक अनौपचारिक परिचय के तौर पर हुई थी। भाऊराव और राजीव
उनकी आपस में अच्छी बनती थी और उन्होंने कई विषयों पर बात की, जिनमें शामिल थे...
उस समय राजीव गांधी द्वारा आयोजित एशियाई खेलों, कम्युनिस्टों के उदय और आरक्षण नीति की सीमाओं के कारण उत्पन्न आर्थिक संकटों के बीच हुए व्यवधानों, और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण हुए नुकसानों ...

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। दोनों ही मिलनसार थे।
व्यक्तित्व; अनिल के अनुसार, उनके बीच 'शुरू से अंत तक सौहार्दपूर्ण संबंध' बने रहने थे।
बाली ने कहा, ‘भौराव को लगता था कि हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा।’
राजीव।
मैं राजीव गांधी को चरण स्पर्श करते हुए देखने वाला प्रत्यक्षदर्शी हूँ।
‘पैर) भाऊराव को,’ बनवारीलाल पुरोहित ने वर्षों बाद खुलासा किया। पुरोहित
वह 1984 और 1989 में कांग्रेस के सांसद थे, फिर भाजपा में शामिल हो गए और बाद में
वे तमिलनाडु और पंजाब के राज्यपाल बने।
भाऊराव के मार्गदर्शन में पले-बढ़े के. एन. गोविंदाचार्य ने याद करते हुए कहा कि...
जिस दिन वह राजीव से पहली बार मिलने के बाद लौटा था। 'मैं
मैं संयोगवश झंडेवालन में था (जहाँ दिल्ली में आरएसएस का मुख्यालय है)।
जब भौराव वापस आए तो उन्होंने कहा कि यह उनके जैसा ही था।
जेपी से मुलाकात तब हुई जब वह भूमिगत था (जिसके बारे में उसे पता था)।
बहुत खुश हूं),’ गोविंदचार्य ने मुझे बताया।
भाऊराव मधुमेह रोगी थे। 'हम ताज़ा भोजन लाने पर विशेष ध्यान देते थे।
पुष्पा ने कहा, 'जब भी वह पूसा रोड आता था, मैं उसके लिए जामुन का रस बनाती थी।'
मोहन या अनिल बाली जामुन का रस झंडेवालन ले जाते थे।
‘जब भी मैं उससे मिलने वहां जाता था’—कपिल मुझसे बाली के बारे में यही पूछता था
मोहन आरएसएस नेताओं को अपना संदेश पहुंचाएगा।
बाली इंदिरा गांधी को हर घटनाक्रम की जानकारी देता रहता था।
झंडेवालन से संबंधित। उन्होंने तय किया था कि वह उसे रिपोर्ट करेगा।
हर शनिवार सुबह। वह सुबह 7.45 बजे उसके घर पहुँच जाता था।
और उन्हें 8.15 बजे तक घर से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि उनके दूसरे सहायक आर. के. धवन भी निकल जाएं।
वे इसलिए आए थे ताकि धवन को कुछ पता न चले।

इन बैठकों को सुगम बनाने वाले प्रमुख व्यक्ति के अनुसार,
अनिल बाली, इंदिरा गांधी के राजनीतिक सचिव एम. एल. फोतेदार थे। 'अगर वहाँ
वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजीव गांधी पर हिंदूकरण का प्रभाव डाला था।
1985-87 के बीच (इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे),
वो फोतेदारजी थे।
'इंदिराजी ने एक बार मुझसे कहा था,' फोतेदार ने एक बातचीत के दौरान खुलासा किया था।
बातचीत के दौरान, "राजीव से कहो कि वह इस बारे में (आरएसएस के साथ अपनी बातचीत के बारे में) बात न करे।"
खाने की मेज पर। वह जानती थी कि सोनिया आरएसएस की सख्त खिलाफ थी।
राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भाऊराव को एक कॉन्टेसा कार उपहार में दी थी।
पंकज ने बताया कि वे उसके लिए आवागमन को आसान बनाना चाहते थे।
वोहरा ने कहा, 'मुझे तो कार का रंग भी याद है—वह चॉकलेट रंग की थी।'
'रंग,' वोहरा ने याद किया।
प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने भाऊराव से मुलाकात नहीं की।
वे संपर्क में रहे। अपने कार्यकाल के मध्य में, आरएसएस ने एक
राजीव से अनुरोध है कि वे रामायण धारावाहिक के प्रसारण में सुविधा प्रदान करें।
दूरदर्शन पर रामानंद सागर का प्रसारण—इसमें कई बाधाएं आ गई थीं। कांग्रेस
नेता एच. के. एल. भगत, जो बाद में सूचना मंत्री बने और
प्रसारण जगत उस समय चिंतित हो गया जब राजीव ने आरएसएस के अनुरोध का जिक्र किया।
उसने राजीव को चेतावनी दी कि इससे एक मुसीबतों का पिटारा खुल जाएगा—और
भाजपा-विश्व हिंदू परिषद-आरएसएस के नेतृत्व वाले राम के पक्ष में माहौल उत्पन्न करें
जन्मभूमि आंदोलन।
जब भौराव को पता चला कि भीतर से ही प्रतिरोध हो रहा है...
उन्होंने राजीव को पत्र लिखकर कांग्रेस को इस विचार के लिए राजी किया। 'चिरंजीवी

राजीव, रामायण’
agar Bharat men nahin dekhi jayegi to kya New York maen dikhayi
जाएगी (प्रिय राजीव, अगर रामायण नहीं दिखाई जाएगी तो आप दीर्घायु हों)
भारत में इसे कहाँ दिखाया जाएगा—न्यूयॉर्क में?’
राजीव ने भगत की आशंकाओं पर ध्यान नहीं दिया।
रामायण धारावाहिक 25 जनवरी 1987 को शुरू हुआ और 31 जुलाई तक चला।
1988—जिसे 650 मिलियन लोगों ने देखा। एक बार, गृह मंत्री बूटा
सिंह ने रामायण के कारण मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित करवा दी थी।
उस समय इसका प्रसारण होगा!
रविवार की सुबह भारतीय शहरों की सड़कें सुनसान होती थीं।
कई परिवार रामायण देखने के लिए अपने टीवी सेट से चिपके हुए थे, जिनमें से कई अपने टीवी सेटों को नमन करते हुए। जैसा कि एच. के. एल. भगत ने भविष्यवाणी की थी,
टीवी सीरियल ने हिंदुओं के बीच धार्मिक उत्साह पैदा कर दिया।
अभूतपूर्व प्रकार का।
1989 की शुरुआत में, चिंतित भाऊराव को एक संकटग्रस्त व्यक्ति को सलाह देनी थी।
राजीव ने साल के अंत में होने वाले आम चुनाव को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
उस समय वह भ्रष्टाचार का सामना करते हुए, पूरी तरह से हताश होकर संघर्ष कर रहा था।
स्वीडन से बोफोर्स तोपों की खरीद के सौदे में लगे आरोप।
‘भौराव ने जनवरी 1989 में मेरे माध्यम से राजीव को संदेश भेजा था,’
अनिल बाली ने खुलासा किया कि विपक्षी दल अभी तक एकजुट नहीं हो पाए थे।
शुरुआती प्रहार से राजीव को विपक्ष पर बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी।
आपत्तिजनक। भाऊराव की राजीव को सलाह आई, और यह अजीब बात थी, जब भाजपा ने उनके प्रतिद्वंदी वी. पी. सिंह का समर्थन करने का फैसला किया था। लेकिन राजीव ने ऐसा नहीं किया।
इस पर ध्यान दें। आईबी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि पार्टी 300 सीटें जीतेगी।

सीटें।
उसी साल नवंबर में, बनवारीलाल पुरोहित ने कई साल बाद इस बात का खुलासा किया।
राम मंदिर की नींव रखने के लिए शिलान्यास करने के संबंध में आरएसएस और राजीव गांधी के बीच एक 'गुप्त समझौता' हुआ था।
विश्व हिंदू परिषद द्वारा। 'उस समय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, मैंने एक
तत्कालीन आरएसएस प्रमुख बालासाहेब देवरस और राजीव गांधी के विशेष प्रतिनिधि के बीच हुई बैठक।
दूत भानु प्रकाश सिंह। यह एक गुप्त व्यक्तिगत मुलाकात थी जो काफी समय तक चली।
एक घंटा...' पुरोहित ने कहा। 'उसके तुरंत बाद, देवरास की एक बैठक थी।'
तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह के साथ नई दिल्ली में, जहां
पुरोहित ने दावा किया, 'इस सौदे को मंजूरी दे दी गई थी।'
लेकिन बूटा सिंह ने पुरोहित के दावे का उपहास किया। हालाँकि, यह व्यापक रूप से
उस समय यह ज्ञात था कि बूटा सिंह ने समझौता कर लिया था।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी)। 'मुझे याद है कि सिंह अक्सर झंडेवालन आते थे।'
उन दिनों की बात याद करते हुए सुभाष आर्य ने कहा, 'उन दिनों की बात याद आई।'
राजीव ने शिलान्यास नहीं रोका। इससे काफी हंगामा मच गया।
मुस्लिम समुदाय। 1989 के चुनावों में कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का नुकसान उठाना पड़ा।
और उन्होंने वी. पी. सिंह को सत्ता में आने में मदद की।
कुछ महीनों बाद, राजीव गांधी ने सैयद शहाबुद्दीन को बताया कि बूटा
सिंह और एन. डी. तिवारी ने 1989 में उन्हें 'गुमराह' किया था।
मैं आपको वही बताऊंगा जो आरजी ने मुझे मार्च 1991 में, दो महीने पहले बताया था।
he died,' Shahabuddin told me.
'शाहबुद्दीन साहब, आप सही हैं,' उन्होंने कहा था। और उन्होंने उसे खींच लिया था।
बाबरी मस्जिद की फाइल निकालकर उसे दिखाओ। 'दो लोगों ने मुझे धोखा दिया है'
—एन. डी. तिवारी और बूटा सिंह (जिन्होंने समझौते पर बातचीत की थी)

वीएचपी और आरएसएस के साथ)। उन दोनों ने मुझे बताया कि शिलान्यास साइट
'विवादित क्षेत्र से बाहर था।' लेकिन, वास्तव में, उस स्थल को रखा गया था।
न्यायालय के यथास्थिति आदेश के तहत, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।
‘उस दिन राजीव ने स्वीकार किया कि शिलान्यास किया गया था।
शाहबुद्दीन ने कहा, ‘अदालत के आदेश का उल्लंघन, ठीक उसी तरह जैसे...’
1949 में (बाबरी मस्जिद में) मूर्ति की स्थापना करना कानून के विरुद्ध था।
कानून।'
हालांकि, राजीव और भाऊराव के बीच यह चौथी मुलाकात थी।
इससे उनके बीच वर्षों से विकसित सौहार्दपूर्ण संबंध का पता चलता है।
राजीव की पहल पर आयोजित बैठक 1991 में जनपथ स्थित 10 नंबर पर हुई थी।
राजीव की मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले। चंद्र शेखर सरकार सत्ता में थी।
उस समय सत्ता में रही शरद पवार को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था।
राजीव को बताया कि चंद्र शेखर एक बड़ी सफलता के कगार पर थे।
अयोध्या वार्ता जो प्रतिनिधियों के बीच चल रही थी
हिंदू और मुसलमान। अगर चंद्र शेखर सफल हो जाते, तो राजीव के
उनके सहयोगियों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे रातोंरात राष्ट्रीय नायक बन जाएंगे।
इससे शक्तियों का पुनर्गठन हो सकता है और आंतरिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
चंद्र के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को देखते हुए कांग्रेस की राजनीति
शेखर के कांग्रेस के भीतर के नेताओं से अच्छे संबंध थे।
राजीव ने भाऊराव से चंद्र द्वारा विकसित फार्मूले को अस्वीकार करने का अनुरोध किया।
शेखर भाऊराव ने राजीव की बात ध्यान से सुनी, जो अभी-अभी लौटा था।
वह यात्रा से लौटा था। वह थका हुआ और भूखा था। जब वे चाय का इंतजार कर रहे थे,
राजीव ने मेज पर रखे फलों के कटोरे में रखे सेबों को काटना शुरू कर दिया।
अनिल बाली ने याद करते हुए कहा, 'वह अनाड़ीपन से फल काट रहा था। लेकिन वह
वह अड़ा रहा। उसने उन सभी को अपने द्वारा काटे गए सेब का एक-एक टुकड़ा दिया।
भाऊराव ने बैठक में बहुत कम बोला। जब वह 10 से बाहर आया,

Janpath, he remarked to Bali, ‘Bahut shaleen ladka hai (He is a very
विनम्र लड़का)।
Bali drove Bhaurao back to Jhandewalan. As he bade him goodbye
आरएसएस मुख्यालय में, भाऊराव ने बाली की ओर मुड़कर धीरे से कहा,
‘Rajiv ko bol dena ki theek hai (Tell Rajiv, we will go along with what
उन्होंने पूछा है)। ऑल इंडिया के बारे में हमारे फैसले की जानकारी उन्हें कल मिलेगी। रेडियो।
उत्साहित बाली वापस 10 जनपथ की ओर भागे। उन्होंने राजीव भाऊराव को दिया संदेश। राजीव बाली को घर से बाहर ले गया। 'तुम्हें नहीं पता क्या है'
'जासूसी की जा रही है और क्या नहीं,' उन्होंने कहा। वे 10 के ड्राइववे में चले गए, Janpath.
‘हमने दबी आवाज़ में बात की… मैंने उसे बताया कि भाऊराव ने क्या कहा था। तीन बाली ने याद करते हुए कहा, ‘कई बार वह मेरे पीठ पर हाथ रखता था। इससे पता चलता था कि वह...
प्रशंसा।'
चंद्र द्वारा लगभग तैयार किया गया समाधान
शेखर अचानक मुश्किल में पड़ गया। यह अनुमान का विषय है कि क्या
भाऊराव-राजीव वार्ता वास्तव में आरएसएस के इस निर्णय के लिए जिम्मेदार थी।
वार्ता रद्द कर दें। ऐसे निर्णय शायद ही उचित होंगे।
यह एक ही अनुरोध पर निर्भर था, भले ही वह अनुरोध पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा किया गया हो।
हालांकि चंद्र शेखर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और आरएसएस समेत कई समुदाय उनसे सावधान थे।
राजीव, उन्हें शायद यह आशंका रही होगी कि चंद्र शेखर सारा अधिकार हथिया लेगा।
मंदिर के निर्माण का सारा श्रेय, जिसे वे अपना हक समझते थे, उन्हें ही दिया गया।
आरएसएस और राजीव गांधी दोनों जानते थे कि चंद्र शेखर स्वयं

वह हिंदू कार्ड का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने में सक्षम है। (अध्याय 4 भी देखें)
पी.वी. नरसिम्हा राव पर।)
राजीव गांधी ने चंद्र शेखर से अपना समर्थन वापस ले लिया।
इसके तुरंत बाद सरकार ने भी इस्तीफा दे दिया। ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस प्रमुख बालासाहेब देवरस ने किया था।
उन्होंने 1980 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, क्योंकि वे
उन्हें एक ऐसी 'हिंदू' नेता के रूप में देखा गया जो हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती थीं।
समुदाय के साथ-साथ वे राजीव गांधी का भी समर्थन कर रहे थे। देवरा समुदाय
भाई बालासाहेब और भाऊराव ने राजीव को 'निर्दोष' पाया, जबकि वह वास्तव में
'ढाला हुआ'। न तो वह वैचारिक बोझ ढोता था और न ही उसके पास कोई पूर्वाग्रह था।
वैचारिक आधार। उन्होंने राजनीतिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व किया जिसे आरएसएस आकर्षक पाया गया।
■

इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के साथ होने वाली मुलाकातों को गुप्त रखने के लिए हर संभव प्रयास किया।
भाऊराव को गुप्त रखा गया। उन्होंने अरुण नेहरू को भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी।
हालांकि इंदिरा नेहरू पर निर्भर थीं, लेकिन उन्हें उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था—और
वह इतनी समझदार थी कि उसकी महत्वाकांक्षाओं को भांप गई थी।
जब राजीव गांधी पहली बार सितंबर 1982 में भाऊराव से मिले, तब इंदिरा गांधी
वह आधिकारिक दौरे पर मॉस्को गई थीं। उनकी वापसी पर अनिल बाली वहां मौजूद थे।
वह उसे लेने के लिए हवाई अड्डे पर आया था। उसने उसे देखा और हाथ हिलाकर

अभिवादन किया।
जैसे ही उसने उसे देखा, उसने पूछा, 'क्या सब ठीक रहा?' वह
राजीव-भौराव की मुलाकात का जिक्र करते हुए।
‘हां,’ बाली ने कहा।
‘बैठक साढ़े चार घंटे तक चली,’ बाली ने प्रसन्न होकर उसे बताया।
‘इस बारे में किसी से बात मत करना,’ उसने बाली को निर्देश दिया, उसकी आवाज़ में था।
पर्दा नीचे करना।
'कोई नहीं,' उसने उसे घूरते हुए कहा।
उन्होंने आगे कहा, ‘कपिल मोहन से भी कह दो कि वो कुछ न कहें।’ ‘वो एक
बड़बोला।
‘क्या इसमें अरुण नेहरू भी शामिल हैं?’ बाली ने पूछा।
उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'आपका क्या मतलब है, क्या इसमें अरुण नेहरू भी शामिल हैं?'
तीखे स्वर में। उन्होंने यह सवाल आवेग में आकर पूछा था। नेहरू
अब इंदिरा गांधी के साथ कांग्रेस में सत्ता की बागडोर संभालती नजर आ रही थी।
गांधी जी का आशीर्वाद।
'वह आखिरी व्यक्ति होगा जिससे मैं बात करना चाहूंगी,' उसने आश्चर्यचकित बाली से कहा।
उन्होंने दृढ़ता से कहा, 'अरुण नेहरू से एक शब्द भी नहीं कहूंगी।'
■

आरएसएस, और विशेष रूप से भाऊराव ने, राजीव के इस निर्णय को प्रभावित किया।
1 फरवरी 1986 को राम जन्मभूमि के ताले खोले गए।
भाजपा नेताओं गोविंदचार्य और सुभाष आर्य ने मुझे इसकी पुष्टि की है।
भौराव के बहुत करीबी लोगों के साथ-साथ अनिल बाली भी, जिनकी उन तक पहुंच थी, के माध्यम से भी यह बात सामने आई।
गांधी परिवार।

'भौराव को लगा कि ताला खोलने से राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनेगी।'
गोविंदचार्य ने मुझे बताया, 'देश के सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर।'
'राम जन्मभूमि का ताला खोलो,' भाऊराव ने राजीव को संदेश भेजा था,
'हिंदुओं के नेता बनो (ताले खोलो और नेता बनो)
हिंदू)।
बाली के अनुसार, ताले खुलने के बाद, भाऊराव ने लिखा...
Rajiv, 'You have taken a historical step. Hindu Hridaya samrat bano aur
राज्य करो (हिंदुओं के दिलों के राजा बनो और राज करो)।
1984 के चुनावों में, नानाजी देशमुख, जो वर्षों से जुड़े हुए थे
आरएसएस ने खुलेआम लोगों से राजीव गांधी को वोट देने का आग्रह किया था: 'ना जात पर'
naa paat par, mohar lagegi haath par (Vote not on the basis of caste, but
हाथ के प्रतीक के लिए)।
राजीव गांधी ने स्वयं कभी भी खुले तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने आरएसएस के संपर्क में था।
आठवीं

1 फरवरी 1986 को फैजाबाद में कड़ाके की ठंड थी।
छोटे शहर के जिला न्यायालयों पर आमतौर पर छाए रहने वाला माहौल
उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पास स्थित वह व्यक्ति उस दिन लापता था। इसके बजाय, अदालत में हलचल मची हुई थी।
उम्मीद के साथ। मामले को खोलने के लिए सुनवाई होने वाली थी।
बाबरी मस्जिद में लगे ताले, जहां बालक राम की मूर्ति की पूजा की जाती थी।
ताले लगे जालीदार दरवाजों के पार से। अदालत कक्ष में 'हलचल' मची हुई थी।
यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, आस-पास के न्यायालय कक्षों से उत्सुक दर्शक अंदर आ गए।
ऐसा होगा।

देश के अधिकांश जिला न्यायालय कक्षों की तरह, इस कक्ष का संचालन किया जाता था।
नीचे। पेंट उखड़ रहा था, पानी के रिसाव के निशान थे।
पिछले साल मानसून ने दीवारों पर निशान छोड़ दिए थे। लेकिन दो स्टेनोग्राफर बैठे थे।
न्यायाधीश कृष्ण मोहन के आने की प्रतीक्षा में, न्यायाधीश की मेज की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हुए।
पांडे के आने का इंतज़ार था। वे वहाँ अपनी रेमिंगटन के पीछे तत्पर बैठे रहे।
न्यायाधीश के आदेश को टाइप करने के लिए टाइपराइटर का इस्तेमाल किया गया।
हैरानी की बात यह है कि न्यायाधीश के पास
याचिका स्वीकार कर ली गई।
न्यायाधीश ने अपना फैसला पिछले दिन यानी 31 जनवरी 1986 को सुरक्षित रख लिया था।
और इसे 1 फरवरी को सौंपना था।
एक तरफ उत्सुकता से खड़े जिला अधिकारी थे। दूसरी तरफ
उमेश चंद्र पांडे उपस्थित थे; वे याचिकाकर्ता और कांग्रेसी थे।
चूंकि विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने अदालत जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अदालत का रुख किया।
उन्होंने स्थानीय कनिष्ठ अधिवक्ता उमेश चंद्र पांडे को याचिका दायर करने के लिए कहा था।
आवेदन। यह सर्वविदित था कि वह एक पूर्व व्यक्ति का पुत्र था।
फैजाबाद के कांग्रेस अध्यक्ष।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के जिज्ञासु सदस्य भी अदालत में यह देखने के लिए मौजूद थे कि क्या होता है।
जज ऐसा कहेंगे। अब तक वीएचपी कार्यकर्ताओं तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि शीर्ष
कांग्रेस नेतृत्व ने इसे खोलने में सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया था।
ताले।
याचिकाकर्ता पांडे ने 21 जनवरी 1986 को याचिका दायर की थी।
बाबरी मस्जिद के ताले खोलने के लिए हरि शंकर दुबे की अदालत में मामला दर्ज

किया गया था।
मस्जिद। दुबे फैजाबाद में मुंसिफ सदर (सबसे निचली अदालत) थे।
पांडे ने अपील की कि श्रद्धालुओं को सीधे भगवान से प्रार्थना करने की अनुमति दी जाए।
राम प्रतिमा। 28 जनवरी को मुंसिफ ने फैसला देने से इनकार कर दिया। तब से
उच्च न्यायालय के समक्ष स्वामित्व संबंधी मुकदमे से जुड़े मामले में उसे ऐसा करना होगा।
उन्हें उच्च न्यायालय के पास मौजूद फाइलों की जांच करनी थी, इससे पहले कि वे ऐसा कर सकें।
अपना विचार व्यक्त करें।
यह जानते हुए कि लगभग हर साल एक याचिका दायर की जाती थी, और निवेदन हमेशा अस्वीकार किया जाता था, मुंसिफ ने सोचा होगा कि खेलना बेहतर होगा।
सुरक्षित। यह मामला बेहद संवेदनशील था और एक से अधिक समय से लंबित था।
तीन दशक।
मुंसिफ की अदालत के फैसले के बिना, उमेश चंद्र पांडे
इसके तुरंत बाद 31 तारीख को फैजाबाद जिला न्यायालय में अपील दायर की गई।
जनवरी। जिला न्यायाधीश ने—और यह भी आश्चर्यजनक था—निर्णय लिया कि मामले की सुनवाई उसी दिन होगी।
केंद्र सरकार की संलिप्तता का संदेह होने पर
ताले खुल गए, मोहम्मद हाशिम ने मामले में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया।
वह विवादित संपत्ति के स्वामित्व के मुकदमे में वादियों में से एक थे।
वह ढांचा, जिसकी सुनवाई होनी बाकी थी। हाशिम की तरह, वहाँ और भी लोग थे।
कई अन्य लोगों का मानना था कि न्यायाधीश को निर्देश दिए गए थे।
दिल्ली द्वारा ताले खोलने के लिए।
ऐसी अफवाह थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने
न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडे से पक्ष में फैसला देने के लिए बात की गई।
ताले खोलना।
हैरानी की बात यह है कि जज पांडे ने हाशिम की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया।
लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता पांडे की दलील तुरंत स्वीकार कर ली, जिनका पहले वाले

मामले से कोई लेना-देना नहीं था। उमेश पांडे ने दलील दी कि
ताले तुरंत खोले जाएं। उन्होंने तर्क दिया कि संरचना
1949 में अदालत द्वारा प्रशासनिक रूप से बंद किया गया, न कि न्यायिक रूप से।
आदेश देना।
हर साल, जब ताले खोलने की गुहार लगाई जाती थी, तब
जिला अधिकारी याचिका का विरोध करने के लिए एक जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे।
उनका तर्क था कि शांति बनाए रखने के लिए ताले लगाना आवश्यक था।
क्षेत्र। तब अदालत याचिका खारिज कर देगी।
उस दिन अधिकारी जिला न्यायालय में उपस्थित थे।
मजिस्ट्रेट इंदु कुमार पांडे (याचिकाकर्ता या उससे संबंधित नहीं)
पीठासीन न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों ही वहां मौजूद थे।
Karamveer Singh.
'डीएम और एसएसपी स्वयं अदालत में आए थे,' न्यायाधीश कृष्णा ने कहा।
मोहन पांडे को बाद में इसका विवरण देना था। उन्होंने तर्क दिया कि ताला लगाने से
यह मंदिर अयोध्या के मुख्य स्वामित्व मुकदमे का हिस्सा नहीं था। इसे अलग रखा गया था।
वहाँ, तत्कालीन जिला प्रशासन के निर्देश पर, कार्रवाई के रूप में
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत।
जज पांडे ने कहा, 'मैंने उनसे (डीएम और एसएसपी से) खुली अदालत में सवाल किया।'
क्या आपने राज्य सरकार से परामर्श किया है?
अधिकारियों ने जवाब दिया, 'यह अदालत का मामला नहीं है। हम ही हैं...'
सरकार मौके पर मौजूद है और हम कानून व्यवस्था संभालेंगे।
(परिस्थिति)।'
न्यायाधीश ने अधिकारियों से पूछा, 'यदि कानून-व्यवस्था की समस्या है तो क्या होगा?'
फिर से, 'क्या आप इसे संभाल पाएंगे?'
हमने जिला न्यायाधीश को बताया कि हम स्थिति को संभालने में सक्षम होंगे।

डीएम इंदु कुमार पांडे ने मुझे इसकी पुष्टि की।
लेकिन न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडे ने अपना फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय लिया।
(31 जनवरी 1986 को)। 'मैंने सोचा कि अगर सरकार को पता नहीं है, और
यह एक संवेदनशील मुद्दा था, तो कम से कम उन्हें सतर्क तो कर दिया जाएगा।'
न्यायाधीश ने कहा, 'जब मैं अपने कक्ष में पहुँचा, तो मेरे पेशीकर (क्लर्क)'
उन्होंने हैरानी से कहा, "साहब, बाहर दूरदर्शन की टीम है।" उन दिनों
वहां कोई निजी टीवी चैनल नहीं थे, केवल सार्वजनिक प्रसारणकर्ता ही था।
दूरदर्शन।
जज पांडे ने कहा, 'मैंने मन ही मन सोचा, कौन भेजेगा?'
'दूरदर्शन की टीम यहाँ है?' यहाँ दूरदर्शन का कोई कार्यालय नहीं था।
फैजाबाद। टीम लखनऊ से आई होगी, जो फैजाबाद से तीन घंटे की दूरी पर है।
दूर चले जाना।
1 फरवरी को जिला न्यायाधीश पूरी तैयारी के साथ अदालत कक्ष में दाखिल हुए।
अपना फैसला सुनाने के लिए। 'अदालत कक्ष में जाने से पहले,' जज पांडे ने कहा।
मुझे याद आया, 'मेरे पेशीकर ने मुझसे कहा, "आजकल 8-9 दूरदर्शन चैनल हैं।"
बाहर लोग थे और दो कैमरा टीमें मौजूद थीं... तब मुझे तसल्ली मिली।
सरकार चाहती थी कि ऐसा हो (ताले खोले जाएं)।
अदालत कक्ष में प्रवेश करते ही न्यायाधीश पांडे को पता चल गया था कि उन्हें क्या करना है।
उन्होंने विवादित ढांचे पर लगे ताले खोलने का आदेश दिया।
तुरंत। 1,000 शब्दों के फैसले में, न्यायाधीश पांडे ने इस पर भरोसा किया।
जिला अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन की अनुमति देने के लिए दिए गए आश्वासनों के संबंध में
'राम लल्ला'। उन्होंने उसे बताया था कि नमाज़ नहीं अदा की गई थी।
यह मस्जिद छत्तीस वर्षों से थी, और ताले वहाँ इसलिए लगाए गए थे क्योंकि...
मूर्ति की सुरक्षा।
"ओ" द्वारों पर ताले खोलने से आसमान नहीं गिर जाएगा और
"पी", न्यायाधीश ने खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में घोषणा की।
फैसला शाम 4.40 बजे सुनाया गया। उसके बाद, डीएम और

एसएसपी ने जिला न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से उनके घर तक पहुँचाने का विशेष ध्यान रखा।
निवास स्थान।
फैजाबाद के स्थानीय प्रशासन ने बड़ी संख्या में
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अदालत परिसर में पुलिसकर्मी तैनात थे। लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं थी।
मुश्किल।
शाम 5.19 बजे जंग लगे तालों को तोड़कर खोला गया। दूरदर्शन की एक टीम ने यह कार्रवाई की।
उस स्थान पर, भविष्य के लिए यादगार बनाने के लिए, उमड़ती हुई भीड़ को कैद किया गया, जो अंदर प्रवेश कर रही थी।
ताले खुलने के बाद की संरचना।
जैसे ही जिला न्यायाधीश ने अपना आदेश पढ़ा, अरुण नेहरू वहीं बैठे रहे।
लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर के साथ निकट मुलाकात हुई।
मैं फैजाबाद में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रख रहा हूं। 'मुझे यह बात कांग्रेस के एक सदस्य ने बताई।'
'यूपी के एक नेता प्रतीक्षालय में बैठे थे,' वजाहत हबीबुल्लाह ने मुझे बताया।
चौबीस साल बाद, 30 सितंबर 2010 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने
अदालत को जिला न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडे के आदेश पर विचार करना था।
अवैध। न्यायाधीश पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया।
उन्होंने कहा कि उनके आदेश के कारण ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था।
6 दिसंबर 1992 को। उनकी अदालत के समक्ष अपील निराधार थी।
क्योंकि मुंसिफ अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया था; उसने केवल राशि तय की थी।
अगली सुनवाई की तारीख। चूंकि मामले की फाइलें उच्च न्यायालय के पास थीं।
अदालत ने दावा किया कि न तो मुंसिफ और न ही जिला न्यायाधीश को यह अधिकार था।
इस मामले में कोई राय बनाने के लिए। लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका

था; ताले खोलने के फैसले को पलटना बहुत देर हो चुकी थी।
विवादित ढांचे पर।
वीएचपी ने ताला खोलने का श्रेय लिया। उन्होंने ही ताला खोला था।
इसके लिए जनजागरण (सामूहिक जागरूकता) का आयोजन रथ यात्राओं के माध्यम से किया जा रहा है।
देश।
■

ताले खुलने के पांच दिन बाद, 6 फरवरी 1986 को, आरिफ
मोहम्मद खान ने राजीव गांधी से मिलने का फैसला किया। ‘शाह बानो अब’
उन्होंने प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा, 'अयोध्या को पीछे हटने दो। इसके बजाय, अयोध्या को पीछे हटना होगा।'
यह विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) का नारा बन गया है।
राजीव ने खान से आत्मविश्वास से कहा, 'मुझे ऐसा कोई डर नहीं है।'
मंत्री को पूरा भरोसा था कि अगर कोई तूफान आया भी तो वह उससे पार पा लेंगे।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने खान से कहा, स्वयं पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, 'मैं'
दूसरी तरफ के संबंधित पक्षों (मुस्लिम) को सतर्क कर दिया था
मैंने संगठनों को बताया कि मैं क्या करने की योजना बना रहा था (ताले खोलने की)।
उन्होंने कहा कि उन्होंने एआईएमपीएलबी को विश्वास में लिया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से
मैंने प्रस्तावित ताला खोलने से पहले अली मियां से इस बारे में बात की थी।
घटित।
खान के राजीव से मिलने से कुछ दिन पहले अली मियां ने एक बयान दिया था।
ताले खोलने को हल्के में लेते हुए। यह 3 फरवरी को प्रसारित हुआ था।
1986 में नेशनल हेराल्ड के उर्दू अखबार कौमी आवाज में, जो
यह कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। ताले को कम करके आंकना-
opening, he said, ‘Aur bhi bahut si masjidon par gairon ka kabza hai

(इसके अलावा कई अन्य मस्जिदें भी हैं जो नियंत्रण में हैं)
अन्य)।' अपने इस बयान से वह महत्व को कम करके आंक रहे थे।
क्या हुआ था?
लेकिन मुस्लिम समुदाय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। 'सब कुछ पहले से तय था-
'योजनाबद्ध,' वकील अब्दुल मन्नान ने गुस्से से कहा। '...राज्य पुलिस
और प्रांतीय सशस्त्र पुलिस बल (पीएसी) को तैनात कर दिया गया था।
जिला न्यायाधीश द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने से काफी पहले ही।
आम मुसलमान तेजी से उत्तेजित होने लगे। 5 फरवरी को
1986 में, समुदाय के कई नेताओं और सुन्नी वक्फ के वकीलों ने
बोर्ड की बैठक लखनऊ में हुई। इसमें तेईस मुस्लिम विधायक भी उपस्थित थे।
उन्होंने बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति बनाने का फैसला किया।
यह समिति बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए मुस्लिम समुदाय की ओर से लड़ाई लड़ने वाली सर्वोच्च समिति बन जाएगी। सैयद
शहाबुद्दीन ने मंदिर के उद्घाटन को 'एकतरफा कब्ज़ा' करार दिया।
बाबरी मस्जिद—जिसने धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास को 'कमजोर' कर दिया। वह एक
जनता पार्टी के सांसद और एक अन्य प्रभावशाली संगठन के प्रमुख को
मुस्लिम हितों की रक्षा करना—ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-
विचार-विमर्श।
ताले खुलने के तुरंत बाद, मैंने कई हिस्सों की यात्रा की।
उत्तर प्रदेश का दौरा किया और पाया कि राज्य में अत्यधिक तनाव है। सांप्रदायिक विभाजन
यह बीमारी गांवों तक फैल चुकी थी। फरवरी और मार्च में,
ताला खुलने के बाद सांप्रदायिक झड़पें हुईं।
मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। की इकाइयाँ
मुरादाबाद जिले के गांवों में पीएसी तैनात किए गए थे। दोनों समुदायों
ताले खोलने के फैसले को 'राजनीतिक'—एक 'लड्डू' की तरह देखा गया।
हिंदुओं ने मुसलमानों को दी गई रियायत की भरपाई करने के लिए
मुस्लिम महिला विधेयक शाह बानो फैसले को रद्द करने के लिए लाया गया है। और

फिर भी
दोनों में से कोई भी समुदाय खुश नहीं था।
शफीकुर रहमान बर्क, बाबरी मस्जिद एक्शन के संयोजक
उत्तर प्रदेश की समिति ने धमकी दी है, 'अगर बाबरी मस्जिद को बहाल नहीं किया गया तो...'
मुसलमान कांग्रेस से नफरत करने लगेंगे (मैं)। कांग्रेसी
मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट मांगने के लिए भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ।
मैं इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ।
■

'राजीव ने (अरुण) नेहरू और अन्य लोगों के साथ इस विषय पर चर्चा की होगी।
ताले खोलने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी,' ऐसा दावा किया गया।
वजाहत हबीबुल्लाह. 'उन्हें एक सच्ची उपलब्धि प्रदान की गई।'
हबीबुल्लाह ने बताया कि यह बात राजीव ने उन्हें बताई थी। सितंबर में
1986 में, जब राजीव गुजरात दौरे पर थे, तब हबीबुल्लाह उनके साथ थे।
वह प्रधानमंत्री के विमान में आगे की सीट पर बैठा था। वहाँ कोई नहीं था।
उस समय वहां कोई और बैठा था। राजीव अपने केबिन से बाहर आया, उसने देखा
हबीबुल्लाह उनके पास आकर बैठ गया और बातचीत शुरू कर दी।
बातचीत का रुख बदलते हुए पिछले कुछ महीनों की घटनाओं की ओर मुड़ गया।
हालांकि वह अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में थे, हबीबुल्लाह इसमें शामिल नहीं थे।
ताले खोलने का निर्णय। 'शायद आपने अनुमान लगाया होगा कि
इस विषय पर बात करते हुए हबीबुल्लाह ने कहा, 'इस पर कोई (प्रतिकूल) प्रतिक्रिया नहीं हुई है।'
राजीव।
'देखो,' राजीव ने उसकी बात काटते हुए कहा, 'पूजा स्थलों में दखल देना
कोई भी धर्म गलत है और उसका पालन कभी नहीं करना चाहिए।

हबीबुल्लाह अचंभित रह गया।
लेकिन,' वह कहने से खुद को रोक नहीं पाए, 'आप प्रधानमंत्री थे। यह आपके नेतृत्व में हुआ था।
सरकार को सूचित किया गया कि ये ताले खोले गए थे।
'हां, लेकिन मुझे अभी तक यह नहीं पता कि इसका ऑर्डर किसने दिया था,' राजीव ने कहा। 'मुझे नहीं पता था।'
ताले खुलने तक इसके बारे में कुछ भी नहीं।
हबीबुल्लाह ने अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा।
प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, 'मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।' 'मैं
'मुझे अरुण पर शक है,' उन्होंने आगे कहा। 'अरुण नेहरू और फोतेदार पर। लेकिन मुझे अब भी शक नहीं है।
मुझे पक्का पता है... और जब मुझे पता चलेगा तो मुझे डर है कि मुझे लेना पड़ेगा कार्रवाई।'
जी हां, राजीव गांधी ने भी मुझे बताया था कि उन्होंने यह आदेश नहीं दिया था।
'ताले खोलो,' शाहिद सिद्दीकी ने बाद में इस बात से सहमति जताई।
उस समय सूचना एवं संचार ब्यूरो (आईबी) के निदेशक रहे एम. के. नारायणन को भी इस पद से हटा दिया गया था।
वर्षों बाद कहते हैं, 'मुझे नहीं लगता कि राजीव गांधी को इसके खुलने की जानकारी थी।'
ताले, हालांकि मुझे सौ प्रतिशत यकीन नहीं है। (लेकिन फिर) कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है
सर्वशक्तिमान।
फिर भी, यह अकल्पनीय प्रतीत होता था कि भारत के प्रधानमंत्री
इतनी बड़ी घटना के बारे में उन्हें अंधेरे में रखा जा सकता था।
एक ज्वलंत मुद्दे से संबंधित, जिसमें कई खुफिया एजेंसियां शामिल हैं।
उन्हें प्रतिदिन जानकारी दी जाती है। विभिन्न पक्षों के कई बयान हैं।
इस अध्याय में मैंने जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया है, वे इस बात का संकेत देते हैं कि राजीव

जानकारी में था। और अगर किसी अप्रत्याशित स्थिति में भी उसे जानकारी न होती, तो भी।
जो निर्णय लिया गया था, उसे न ढूंढ पाना अविश्वसनीय लगता है।
आठ महीने बीत जाने के बाद भी यह पता नहीं चल पाया है कि ताले खोलने के पीछे कौन था।
यह घटना घटी (और इसी दौरान हबीबुल्लाह के साथ बातचीत हुई)।
उसके पास भारतीय राज्य की सभी शक्तियां थीं।
यह दावा करके कि उसे ताला खुलने के बारे में पहले से पता नहीं था
जो हुआ, उससे वह एक नौसिखिया के रूप में भी सामने आ गया। क्या राजीव गांधी
क्या वह उस बात के लिए बहाना पेश कर रहा था जिसे उसने बाद में निर्णय की गलती माना?
क्या वह अपने चचेरे भाई को बर्खास्त करने की तैयारी कर रहा था, जो उसने किया भी था?
हबीबुल्लाह के साथ उनकी बातचीत के कुछ हफ्तों बाद—एक और
शाह बानो की कहानी में एक दिलचस्प मोड़?
यह संभव नहीं है कि राजीव गांधी को इसके बारे में जानकारी न हो।
ताले खोलने के बारे में,' एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, जो पहले भी इस मामले में शामिल रहे थे।
अरुण नेहरू और राजीव दोनों के करीबी। हालाँकि, यह संभव है कि उन्हें पूरी बात नहीं बताई गई हो, और उन्हें इसके परिणामों के बारे में ठीक से नहीं समझाया गया हो।
फ़ैसला।'

नौवीं

'राजीव और अरुण नेहरू के बीच मतभेद बोफोर्स कांड को लेकर शुरू हुए थे।'
राजीव गांधी के एक ऐसे मित्र ने टिप्पणी की जो राजनीति में नहीं हैं।
दोनों चचेरे भाइयों के बीच मतभेद सामने आने लगे थे।
राजीव गांधी के सत्ता में आने के पहले कुछ महीने।
अरुण नेहरू स्वीडिश सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे।
बोफोर्स कंपनी से 155 मिमी हॉवित्जर तोपों की खरीद में

स्वीडन। फिर अचानक राजीव ने उन्हें बातचीत से बाहर निकाल लिया। 'जुलाई 1985 में,
राजीव गांधी ने मुझसे कहा कि मैं स्वीडन के बारे में और अधिक चिंता न करूं और यह कि
वह स्वयं श्री पाल्मे (ओलोफ पाल्मे, तत्कालीन प्रधान मंत्री) से निपटेंगे।
जब मामला सामने आया तो नेहरू ने सीबीआई के सामने गवाही देते हुए कहा, 'स्वीडन के मंत्री)।'
कई वर्षों बाद भी इसकी जांच की जा रही है।
राजीव गांधी ने स्वयं स्वीडनवासियों से निपटने का जिम्मा संभाला और
मार्च 1986 में समझौते को अंतिम रूप दिया गया।
सितंबर 1985 में, राजीव गांधी ने अरुण नेहरू को सत्ता से हटा दिया।
गृह मंत्रालय के अधीन, आंतरिक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में
सुरक्षा। नेहरू का स्वीडिश सरकार के साथ विवाद हो गया था।
भारत में एक विद्युत संयंत्र की स्थापना को लेकर।
उनके बीच बढ़ते मतभेदों के बावजूद, राजीव उन मामलों में सावधानी से आगे बढ़ा।
प्रधानमंत्री के रूप में शुरुआती महीने। राजीव, अपनी भोली सोच के बावजूद, जानते थे कि वह
वह अपने चचेरे भाई को बिना किसी महत्वहीन मंत्रालय में भेजे नहीं जा सकता था।
इससे उनकी दुश्मनी मोल हो गई। अरुण नेहरू बहुत शक्तिशाली हो गए थे।
राजीव गांधी ने अरुण नेहरू से कहा कि वह विशेष रूप से यह व्यवस्था कर रहे हैं।
उनके लिए आंतरिक सुरक्षा विभाग। नेहरू ने कहा, 'मैं इसे कभी नहीं चाहता था।'
मुझे याद आया। 'मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था।'
अरुण नेहरू और राजीव गांधी के बीच मतभेद उनके बाद ही शुरू हो गए थे।
उन्होंने सत्ता संभाली। नेहरू ने कहा, 'हमने पहले दिन से ही तोड़-फोड़ शुरू कर दी थी।'
उन्होंने कहा कि राजीव दिल्ली पुलिस के बारे में ‘अपमानजनक राय’ रखता था... ‘मैंने कहा था’
उन्हें बता दें कि वे मुझे रिपोर्ट करेंगे। मुझे उनका बचाव करना होगा। यह मेरी टीम है। अब।'

नेहरू ने गर्व से दावा किया कि सभी खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी
जब उन्होंने आंतरिक सुरक्षा मंत्री का पदभार संभाला, तब मैंने उनसे कहा, 'जब मैं'
आंतरिक सुरक्षा मंत्री बने...आर एंड एडब्ल्यूए, आईबी, सीबीआई के प्रमुख
वह मुझसे मिलते थे और मुझे रिपोर्ट भेजते थे।
उन्होंने कहा, 'राजीव गांधी के पास उनसे मिलने का समय नहीं था, इसलिए वे मुझसे मिले।'
सीबीआई को बताया।
खुफिया प्रमुखों के लिए रिपोर्ट न करना अकल्पनीय था।
प्रधानमंत्री,' एम. के. नारायणन ने कहा।
आईबी के निदेशक और आर एंड एडब्ल्यूए के प्रमुख का पैदल चलना प्रथागत था।
हर सुबह प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाकर उन्हें जानकारी दें।
जवाहरलाल नेहरू के समय से यही परंपरा चली आ रही थी।
डीआईबी गृह मंत्री को अलग से जानकारी देगा; उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी।
गृह राज्य मंत्री को संक्षेप में जानकारी दें—जब तक कि कोई स्पष्ट निर्देश न हो।
प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ऐसा करना पड़ा। खुफिया जानकारी के अनुसार
उस समय की एजेंसियां 'अपने तौर-तरीकों पर अड़ी रहीं, भले ही उनके कार्यों का सार बदल गया हो'
भूमिका कमजोर कर दी गई थी।
'कोई भी नौकरशाह प्रधानमंत्री के निर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकता,'
वरिष्ठ पत्रकार बी. एन. उनियाल ने यह खुलासा किया।
हालांकि, नारायणन के अनुसार, अरुण नेहरू अपनी सीमाओं से परे जाने को तैयार रहते थे।
सरकार में चल रही गतिविधियों से खुद को अवगत रखने का एक तरीका।
कभी-कभी वह मुझे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करते और बातचीत करते।
वह खाना ऑर्डर करते।
पास के ताज होटल से दोपहर का भोजन।
'लेकिन,' नारायणन ने कहा, 'वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा था, और
यही मुख्य समस्या थी।'

जब खुफिया प्रमुखों ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी, तो किसी अन्य ने
मंत्री को उपस्थित होना था। 'लेकिन कभी-कभी अरुण नेहरू
मैं सुबह राजीव से मिलने आती और वहीं बैठी रहती।
उनियाल ने खुलासा किया, 'जब खुफिया प्रमुख आए तो वे वहीं मौजूद थे।'
खुफिया प्रमुख प्रधानमंत्री को 'राजनीतिक खुफिया जानकारी' भी देते हैं;
हर प्रधानमंत्री ने इस जानकारी को किसी न किसी फाइल में छिपाकर रखा था।
उनके कार्यालय को उचित समय पर निकालकर उपयोग में लाया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय के पास विरोधियों से संबंधित फाइलें थीं। 'यह विरोधियों को सामने लाने का एक तरीका था।'
उनियाल ने कहा, 'पार्टी के अंदर और बाहर, सब एक ही लाइन में हैं।'
लेकिन बहुत जल्द ही, 'राजीव गांधी इस (स्थिति) से परेशान हो गए।'
अरुण नेहरू ने बाद में यह बात कही थी।
'राजीव ने (खुफिया) निदेशकों को निर्देश दिया कि वे मुझे रिपोर्ट न भेजें।'
इसलिए, वे मुझे मौखिक रिपोर्ट देते थे।'
नेहरू ने समझाया, 'असल में यह सब सतही तौर पर था। राजीव के पास एक
लगातार डर, दूसरों द्वारा बढ़ाया गया, और वे उसे यह कहते थे कि मैं शायद
मैं उससे बेहतर साबित हुआ। मेरी कार्यशैली बहुत आक्रामक थी।'
राजीव का संदेह बढ़ता गया।
अरुण नेहरू ने कहा, 'लोग कह रहे थे कि वह (अरुण) बहुत अहंकारी है।'
समस्या यह थी कि राजीव किसी से मिलता नहीं था। वह सिर्फ एक व्यक्ति से मिलता था।
एक सप्ताह का समय देने के लिए...वे मेरे पास आते... एक बार राजीव और मेरे बीच एक
बहस। वह मेरे स्टडी रूम में बैठकर मजाक करता था, "मैं तुम्हारे स्टडी रूम में हूँ।"
किताबों से घिरा हुआ।" मैंने कहा, "राजीव, जब मैं तुम्हारे अध्ययन कक्ष में बैठता हूँ तो मैं किताबों से घिरा हुआ होता हूँ।"
स्क्रूड्राइवरों से घिरा हुआ।" वह मुझसे पूछा करता था कि तुम्हारा क्या फायदा है
इतिहास की समझ। मुझे जो भी जानकारी चाहिए, मैं दस विशेषज्ञों से पूछ सकता हूँ।
मुझे। वे मुझे किसी भी चीज़ पर रिपोर्ट दे देंगे।'

अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि मैं तीन साल की उम्र से राजनीति में आया था-
हजार लोगों की कंपनी। मुझे लोगों को संभालने की आदत थी। राजीव के पास...
उन्होंने जीवन भर कभी लोगों का प्रबंधन नहीं किया। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तब उन्होंने ऐसा किया।
जिम्मेदारी उसकी थी। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे (राजीव की) सबसे बड़ी गलती यही लगती है।
उसका मानना था कि मम्मी ने जो कुछ भी किया हो, वह उससे बेहतर कर सकता है।
उसने अपने सारे किए हुए काम उलट दिए।
दोनों चचेरे भाइयों के बीच मतभेद भी सामने आ गए थे।
पंजाब समझौता। जब राजीव ने संत हरचंद के साथ बातचीत शुरू की।
जुलाई 1985 में सिंह लोंगोवाल के समय, नेहरू, जो खुद पर गर्व करते थे
इंदिरा गांधी के समय से ही कट्टरपंथी होने के नाते, मैं इसके खिलाफ था। 'मैंने इसका विरोध किया।'
नेहरू ने खुलासा किया, 'उन्हें लगा कि राजीव अपना तुरुप का पत्ता गंवा रहे हैं।' उन्हें लगा कि राजीव अपना तुरुप का पत्ता खो रहे हैं।
(सिख विरोधी हिंदू संघ), जिसने उन्हें सत्ता में लाया था।
राजीव गांधी ने 24 जुलाई 1985 को लोंगोवाल के साथ पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए।
असम और
मिजोरम समझौते। प्रधानमंत्री के रूप में, राजीव गांधी का मानना था कि भारी जनादेश के साथ
उसे जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसे उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए जो उत्पन्न हो चुकी थीं।
अड़ियल। अरुण नेहरू का मानना था कि राजीव गांधी का यह मानना भोलापन था कि वह
वह वह कर सकता था जो उसकी माँ नहीं कर पाई थी। (समस्या)
राजीव ने नेहरू से कहा, 'आप टकराव चाहते हैं, मैं सुलह चाहता हूं।'
■

अरुण नेहरू ने अपने पति से संबंध टूटने के लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया। राजीव। 'सोनिया उसके (राजीव के) पीछे थी... लोग भूल जाते हैं कि पहले सोनिया गांधी परिवार की बहू थीं, जो इंदिरा गांधी के दौरों के लिए सिर्फ उनके कपड़े पैक करती थीं।

यही उनकी अधिकतम भागीदारी थी। उसके बाद वे महारानी बन गईं।

और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी...

'प्रधानमंत्री बनने से पहले भी सोनिया राजीव को जानकारी देती रहती थीं और कहती थीं कि

(अरुण नेहरू) चतुर हैं, वे नेहरू हैं, और पार्टी में अधिक लोकप्रिय हैं... मेरा रिश्ता इंदिरा गांधी से था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

घर के लॉबी या किचन कैबिनेट के लिए।

सोनिया को शक था कि अरुण नेहरू राजीव पर नजर रख रहे थे।

और परिवार। नेहरू उनके निजी पत्रों को खुलवाते थे।

उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। 'सोनिया गांधी ने राजीव को बताया था कि मैं उन्हें अपने पास रखे हुए था।

निगरानी के तहत।'

'अरे भाई,' उसने हाथ लहराते हुए लापरवाही से कहा, 'सुरक्षा की

प्रधानमंत्री आवास अब मेरा काम था।

शुरुआत से ही सोनिया अरुण नेहरू के अहंकारी स्वभाव से नाराज थीं।

उनके तौर-तरीके, खासकर जिस तरह से वह राजीव से बात करते थे। वह उद्दंड थे।

वे राजीव को नजरअंदाज कर सकते हैं और यहां तक कि सार्वजनिक रूप से उस पर गुस्सा भी निकाल सकते हैं।

'Mitra bhi agar Raja ho jaye toh aap usko "hey rajan" bulate hain

(भले ही कोई मित्र शासक बन जाए, फिर भी आप उससे उचित आदरपूर्वक बात करें)

बी. एन. उनियाल, जिन्होंने उस समय की राजनीतिक घटनाओं को कवर किया था, ने

टिप्पणी की, 'उनके लिए)।'
अवधि को बारीकी से देखें।
‘अरुण नेहरू को कभी भी क्वात्रोची परिवार से निकटता पसंद नहीं थी, और
दिनेश त्रिवेदी ने खुलासा किया, 'वे दोनों साथ में छुट्टियां मनाने गए थे।'
राजीव को चेतावनी देते हुए कहा जाता, “आप प्रधानमंत्री हैं और वह आपकी पत्नी हैं…”
(और आपको सावधान रहना होगा)।" ओटावियो क्वात्रोची - एक इतालवी
भारत में रहने वाले एक व्यवसायी, जिन पर 1999 में आरोप लगाए गए थे।
बोफोर्स मामले में रिश्वत लेने वाले व्यक्ति को अपने करीबी लोगों के लिए जाना जाता था।
सोनिया और प्रधानमंत्री से। क्वात्रोची अक्सर मिलते थे।
प्रधानमंत्री आवास पर आने वाले आगंतुक।
■

फरवरी 1986 में पोप जॉन पॉल द्वितीय की भारत यात्रा ने
राजीव-सोनिया और अरुण नेहरू के बीच मतभेद चरम पर थे। 'अरुण
नेहरू नहीं चाहते थे कि सोनिया पोप का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे जाएं (जब
जब वह भारत पहुंचे), नेहरू के दो करीबी सहयोगी, जो उच्च पदों पर पहुंचे
उच्च पदों पर बैठे लोगों ने मुझे बताया, ‘उन्होंने कहा कि तुम्हें पोप के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘तुम्हारे सामने पोप के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे।’
'जैसा कि उनकी प्रथा है, मैंने उनकी अंगूठी चूमी,' उनके एक सहयोगी ने कहा। 'यह
यहां के लोगों को यह स्वीकार्य नहीं होगा कि प्रधानमंत्री की पत्नी
ऐसा किया।’ हालाँकि पोप की अंगूठी पोप की शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है।
नेहरू के अनुसार, सत्ता को चूमना आज्ञाकारिता और सम्मान का प्रतीक है।
वह अपने चचेरे भाई की हिंदू छवि की रक्षा करना चाहता था।
‘सोनिया पोप का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे नहीं गईं।’ केवल राष्ट्रपति
ज़ैल सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पोप का स्वागत किया।
1 फरवरी 1986 को जब वह भारत पहुंचे तो हवाई अड्डे पर सोनिया उनसे मिलीं।

पोप शाम को राष्ट्रपति भवन में होंगे।
नेहरू के एक सहयोगी ने कहा, 'हो सकता है सोनिया इसे भूली न हों।'
लेकिन यूपीए-द्वितीय शासनकाल में हालात बदल गए, और परिवार ऐसा प्रतीत होने लगा कि...
सुलह हो गई है।
■

‘शाह बानो’ सिर्फ शाह बानो के बारे में नहीं थी; यह शाही परिवार के बारे में भी थी।
'दिल्ली में गद्दी (शाही सिंहासन),' शाहिद सिद्दीकी ने चुटकी लेते हुए कहा।
‘अरुण नेहरू को लगता था कि वही असली कुलीन नेहरू हैं,’ एक व्यक्ति ने कहा।
नेहरू और राजीव गांधी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेसी नेता। 'उन्होंने सोचा कि वह
वह प्रधानमंत्री बन सकता था। और, वह अपना खेल खेल रहा था।
सुनियोजित, योजनाबद्ध फैशन।
In the early days, ‘Rajiv Arun Nehru se bahut ghabrate thae (Rajiv
‘अरुण से सावधान रहने की आदत थी’,’ पत्रकार जी.एस. चावला ने खुलासा किया, जो एक उत्साही पत्रकार हैं।
उस समय के राजनीतिक परिदृश्य का पर्यवेक्षक।
जैसे-जैसे राजीव गांधी सत्ता के साधनों का प्रयोग करने में सहज होते गए
सत्ता मिलने पर, उसे अपने चचेरे भाई के दबंग रवैये से चिढ़ होने लगी।
दोनों के बीच मतभेद 1985 के मध्य में ही सामने आने लगे थे, लेकिन
बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। जबकि राजीव अरुण नेहरू को अनुमति देने के लिए तैयार थे।
वह उसे 'सत्ता का केंद्र' बनने देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसे खुद सत्ता का केंद्र बनने देने के लिए तैयार था।
नेहरू को 'वैकल्पिक शक्ति केंद्र' के रूप में देखा जाने लगा था।
तथ्य: प्रधानमंत्री।
राजीव गांधी अरुण नेहरू की संभावित क्षमता को लेकर चिंतित हो गए थे।

यदि हिंदू सांसदों की असंतुष्टि का फायदा उठाकर पार्टी में विद्रोह भड़काया जाए तो उनके खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा था—यही एक और कारण था कि वह ऐसा क्यों करते।
उन्होंने ताला खोलने का विकल्प चुना। नेहरू आखिरकार एक 'अंदरूनी व्यक्ति' थे, और एक
वो भी 'नेहरू'। इंदिरा गांधी के ज़माने से ही उन्होंने एक खास मुकाम हासिल कर लिया था।
पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़।
नेहरू ने कई वर्षों बाद यह स्वीकार करते हुए स्पष्टवादिता दिखाई कि 'वे'
(कांग्रेस नेतृत्व) को डर था कि मैं खुद को (इस स्थिति में) स्थापित कर रहा था
(राजीव की जगह)
मंत्री पद)।' फिर उन्होंने काफी आक्रामक लहजे में पूछा, 'इसमें क्या गलत है?'
पदस्थापन? अगर कोई अच्छा है, तो क्यों नहीं? कौन खुद को स्थापित नहीं करता?'
उन्होंने स्वीकार किया कि 1980 के दशक में 'यह सत्ता का खेल था'। और उन्होंने
उन्होंने यह भी स्वीकार किया, और वह भी काफी स्पष्ट रूप से, कि 'मैं राजीव का 50 प्रतिशत था।'
समस्याएं।
■

मई 1986 की शुरुआत में राजीव गांधी का अरुण नेहरू से टकराव हुआ था। उन्होंने अठारह महीनों तक उनके कठोर व्यवहार को सहन किया। उनके बीच एक नाराज़गी थी।
अदला-बदली।
नेहरू व्याकुल होकर अपने परिवार के साथ कश्मीर के लिए रवाना हो गए। वे वहीं रुक गए।
वहाँ सुरम्य क्षेत्र में स्थित एक राज्य सरकार के पर्यटक रिसॉर्ट में।
दाचीगाम के आसपास के इलाकों में। वह लंबी सैर पर जाया करते थे—जैसा कि वे करते थे।

उन्हें वजन कम करने के लिए कहा गया था। 31 मई 1986 को सुबह 3 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा।
आक्रमण करना।
Earlier in the day, he had met Governor Jagmohan. Jagmohan
तुरंत दाचीगाम के लिए रवाना हुए और अरुण नेहरू को वहां ले गए।
शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, 16 किलोमीटर दूर।
राज्यपाल ने यह सुनिश्चित किया कि हृदय रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध रहें।
जब नेहरू सुबह 6 बजे अस्पताल पहुंचे, तो जगमोहन की निकटता
नेहरू काफी प्रसिद्ध थे। जगमोहन ने ही उन्हें बर्खास्त किया था।
जुलाई 1984 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार में, जी.एम. शाह को पदस्थापित किया गया।
अरुण नेहरू के कहने पर, उनकी जगह पर। 1990 में, जब वी. पी. सिंह
अगर अरुण नेहरू सत्ता में आते हैं, तो वे उन्हें राज्यपाल बनाकर भेजेंगे।
अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान नेहरू से मिलने वालों का तांता लगा रहा।
चिदंबरम दिल्ली से आए थे। वे राज्य मंत्री थे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग द्वारा भेजा गया था और स्पष्ट रूप से इसके द्वारा भेजा गया था।
राजीव गांधी; बाद में उन्होंने नेहरू के स्थान पर आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री का पद संभाला।
राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह भी आए। वे बाथरूम के रास्ते आए।
पत्रकार जी.एस. चावला ने याद करते हुए कहा, 'सामने के प्रवेश द्वार से नहीं, बल्कि दरवाजे से।'
ज़ैल सिंह से उनकी नज़दीकी के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुनिश्चित किया कि डॉ. एस. पी.
बॉम्बे के न्यूरोसर्जन मनचंदा और प्रोफेसर खलीउल्लाह,
दिल्ली के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ श्रीनगर में नेहरू के लिए उपलब्ध रहेंगे।
डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम दो महीने तक पूर्ण विश्राम करने का आदेश दिया।
दिल्ली में अब यह अफवाह फैल रही थी कि अब इस सफर का अंत हो चुका है।

नेहरू। कई लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री श्रीनगर आएंगे। लेकिन
राजीव अपने बीमार चचेरे भाई से मिलने नहीं गया। यह इस बात का पहला स्पष्ट संकेत था कि...
दोनों के बीच दरार पैदा हो गई। कई महीनों तक निष्क्रिय रहने के कारण नेहरू का प्रभाव कम होने लगा। राजीव गांधी अब विचार कर रहे थे...
उन्होंने अपने चचेरे भाई को मंत्रालय से हटा दिया। उन्होंने नटवर से भी यही बात कही थी।
सिंह से जुलाई 1986 में और वजाहत हबीबुल्लाह से दो महीने बाद शादी कर ली।
■

मंत्रिमंडल में फेरबदल की तारीख 22 अक्टूबर 1986 तय की गई थी।
विधानसभा फेरबदल से पहले, राजीव गांधी ने अरुण नेहरू को आकर देखने के लिए कहा।
उसने अपने चचेरे भाई को बताया कि वह अपने जीवन में बदलाव करने जा रहा है।
अलमारी।
'उन्होंने मुझे ब्रिटेन में उच्चायुक्त के रूप में भेजने का प्रस्ताव दिया,' अरुण नेहरू मुझे बताया।
'इससे आपको आवश्यक इलाज मिल जाएगा,' राजीव ने अरुण से कहा। 'आप
छह महीने बाद कभी भी वापस आ सकते हैं।
नेहरू ने पलटवार करते हुए कहा, 'मैं बेवकूफ नहीं हूं। आप मुझे बाहर निकालना चाहते हैं।'
'मैं तुम्हें छोड़ दूंगा,' राजीव ने धमकी दी।
'आप यह कर सकते हैं।'
नेहरू ने याद करते हुए कहा, 'हमारी मुलाकात बहुत खराब रही। उस दिन मैंने उनसे कहा,
अब मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूँ।'
बैठक का समापन राजीव गांधी द्वारा अरुण नेहरू से पूछे गए एक प्रश्न के साथ हुआ।
इस्तीफा दे दिया। जिन अन्य मंत्रियों को पद से हटाया गया, उन्होंने भी अपना

इस्तीफा पत्र लिखकर भेजा।
उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि वे राजीव के अधीन किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार रहेंगे।
उन्हें जितनी क्षमता चाहिए थी, नेहरू ने उतनी क्षमता देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसा कोई वादा करने से मना कर दिया।
उन्होंने अपने इस्तीफे पत्र में लिखा, 'मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।'
आपने मुझे आपके साथ काम करने का अवसर दिया है।
राजीव गांधी ने पत्र पर अपनी बड़ी, मोटी लिखावट में लिखा,
उन्होंने जिस मोटे निब वाले मोंटब्लैंक पेन का इस्तेमाल किया था, उसी से लिखा था —'स्वीकृत'।
फिर वे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के लिए रवाना हो गए। राजीव गांधी के रूप में
बाहर निकलते हुए, उन्होंने जल्दबाजी में अपने राजनीतिक सहयोगी एम. एल. फोतेदार को इशारा किया।
उसके साथ कार में आओ।
'क्या हुआ?' फोतेदार ने रास्ते में उससे पूछा।
Rajiv told him.
'अब क्या होगा?' राजीव ने फोतेदार से पूछा। 'हम'
नेहरू को अच्छी तरह जानने वाले फोतेदार ने कहा, 'हमें इसके परिणामों का इंतजार करना चाहिए।'
कार राष्ट्रपति भवन की ओर मुड़ गई।
प्रधानमंत्री के चेहरे पर चिंता के भाव थे।

शपथ ग्रहण के बाद, बेचैन राजीव ने फिर से फोतेदार से पूछा कि
उसके साथ रेस कोर्स रोड तक वापस चलो।
बाद में फोतेदार ने कहा, 'राजीवजी तनाव में थे।'
जैसे ही कार रेस कोर्स रोड पर पहुंची, उन्होंने सोनिया गांधी को देखा और
गांधी परिवार के वफादार कैप्टन सतीश शर्मा बरामदे में इंतजार कर रहे हैं।
सोनिया के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी।

‘तभी मुझे समझ आया कि अरुण नेहरू को टीम से क्यों बाहर किया गया था,’ फोतेदार ने कहा।
बाद में कहा।
22 अक्टूबर 1986 को अरुण नेहरू को पद से हटाए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर, वी.
पी. सिंह नेहरू से मिलने गए। उन्होंने कुछ घंटे साथ बिताए।
नेहरू ने कहा, ‘तब से वीपी को एहसास हो गया कि अब उनके लिए भी हालात बेहतर हो गए हैं।’
मुझे बताया।
सार्वजनिक रूप से अरुण नेहरू पूरी तरह से बेपरवाह दिखाई दिए। उन्होंने मुलाकात की।
लोगों ने मीडिया से ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने
ऐसी धारणा थी कि उन्हें जल्द ही सरकार में वापस ले लिया जाएगा। लेकिन
वह सही समय का इंतजार कर रहा था। उसने तभी वार किया जब वह तैयार था—और वह
एक साल बाद 1987 में (अध्याय 3 देखें) स्वीडिश रेडियो ने एक कार्यक्रम किया।
कार्यक्रम ‘डेगेंस एको’ जो एक व्यक्ति की गवाही पर आधारित था
बोफोर्स के पूर्व कर्मचारी ने दावा किया था कि बोफोर्स ने भारतीयों को रिश्वत दी थी।
राजनेता।
‘अरुण नेहरू ने ही बोफोर्स कांड की कहानी स्वीडन को लीक की थी।’
एच. आर. भारद्वाज ने मुझसे कहा, 'रेडियो। हमें पता था।'
बोफोर्स घोटाले ने राजीव गांधी के सत्ता में बचे हुए वर्षों को धूमिल कर दिया।
इससे 1989 में उनके दोबारा चुनाव जीतने की संभावना खत्म हो गई और वी. पी. सिंह सत्ता में आए।
सत्ता में।

एक्स

21 मई 1991 को अपनी मृत्यु से तीन दिन पहले, राजीव गांधी ने एक कार्यक्रम की मेजबानी की थी।
जनपथ स्थित 10 नंबर के होटल में इफ्तार पार्टी। वह डेढ़ साल से सत्ता से बाहर थे।

और उन्हें पूरा भरोसा था कि वे सत्ता में वापस आ रहे हैं।
अधिकांश मेहमानों के चले जाने के बाद, वह कुछ लोगों के छोटे समूह के साथ बैठ गया।
लोगों को कांग्रेस नेता ने विशेष रूप से रुकने के लिए कहा था।
सलमान खुर्शीद। वे अधिकतर अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल के प्रोफेसर थे।
विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से। खुर्शीद
मैं चाहता था कि मुस्लिम बुद्धिजीवी राजीव को उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें।
मध्य 1991 में होने वाले आम चुनावों में संभावनाएं।
राजीव ने सभी के विचार जानने के लिए कमरे में घूमकर पूछा। अधिकांश लोगों की राय अलग थी।
उत्साह का माहौल था—उन्होंने कहा कि राजीव के पास यूपी में अच्छा मौका है। फिर बारी पत्रकार कुर्बान अली की आई।
'वे तुम्हें जो कुछ भी बता रहे हैं, वह सब गलत है,' कुर्बान ने कहा। उसके पास राजीव का सामान था।
ध्यान।
आपने मुसलमानों पर बहुत बड़ा उपकार किया है (मुस्लिमों को लाकर)
उन्होंने कहा, 'महिलाओं के अधिकारों से संबंधित विधेयक शाह बानो के फैसले को पलटने के लिए है।'
लेकिन आपने मंदिर के ताले खोलकर इसकी भरपाई कर दी...
और इसके चलते बाराबंकी, मलियाना,
उन्होंने कहा, 'हाशिमपुरा, भागलपुर।' ये स्थान इन चीजों के पर्याय थे।
मुसलमानों की भयानक हत्याएं।
इस पर राजीव ने बीच में ही टोकते हुए कहा, 'लेकिन, आप जानते हैं कि किसे मिला?'
बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का काम पूरा हो गया है।
'हां, और चूंकि आप उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, इसलिए मैं नाम बता दूंगा।'
कुर्बान अली ने कहा। 'यह अरुण नेहरू थे।'
'हां,' राजीव ने कहा।
लेकिन आप प्रधानमंत्री थे।

राजीव चुप था।
अली ने आगे कहा, 'शिलान्यास के समय भी, वहाँ था
कांग्रेस और वीएचपी के बीच एक औपचारिक समझौता (जिसके आधार पर)
अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला का पत्थर बीचोंबीच रखा गया था।
1989 के चुनाव अभियान में)।
राजीव फिर चुप रहा। उसने असहजता से इनकार नहीं किया।
अवलोकन। इस समय तक, खुर्शीद स्पष्ट रूप से अलग दिखने लगा था।
असंतुष्ट। बैठक अचानक समाप्त हो गई।
कई कांग्रेसी नेता कहते थे कि राजीव गांधी बहुत ही
अपने दूसरे कार्यकाल में वह अलग थे। 'राजीव अब उतने भोले नहीं रहे थे जितना लोग उन्हें समझते थे।
'सोचा था,' चतुर एच. आर. भारद्वाज ने राजीव के बारे में तब कहा था जब वह
सत्ता से बाहर। सत्ता से बाहर होने के बाद, उन्हें इस बात की बेहतर समझ प्राप्त हुई थी।
भारतीय समाज, भारतीय जनता और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन नियति ने ऐसा नहीं चाहा था।
उसे दूसरा मौका देने के लिए।
■

शाह बानो संधि के दुष्परिणामों को नियंत्रित करने के लिए राजीव गांधी के निर्णय
निर्णय कई अंतर्धाराओं से प्रभावित थे। पहली धारा यह थी कि
मुस्लिम विरोध प्रदर्शन। शीर्ष पद पर नए होने के कारण, वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से घबरा गए थे।
जिन मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, उनकी संख्या
इसे उन्होंने अपने निजी कानूनों में हस्तक्षेप के रूप में देखा। देश के भीतर के दबावों के अलावा, उन्हें इस बात का भी एहसास था कि उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
अंतर्राष्ट्रीय दबाव। इसी दबाव ने उन्हें मुस्लिम मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया।

महिलाओं से संबंधित विधेयक का उद्देश्य आक्रोशित समुदाय को शांत करना है।
साथ ही, उन्हें हिंदुओं के बीच किसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी।
एक बार फिर, राजीव दबाव के आगे झुक गए, इस बार हिंदू समूहों के दबाव के आगे।
विश्व हिंदू परिषद जैसे कट्टरपंथी संगठनों से लेकर उदारवादी विचारधाराओं तक।
हिंदू।
अपने आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ, वे भारत को तैयार करने की उम्मीद रखते हैं।
राजीव गांधी इक्कीसवीं सदी को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे।
भारतीय समाज के विशाल वर्गों पर जाति या समुदाय का प्रभाव। वह ऐसा कर सकता था।
समझ में नहीं आता कि हिंदुओं को इस बात पर इतना गुस्सा क्यों आना चाहिए
मुस्लिम महिला विधेयक, जिसका उनसे कोई लेना-देना नहीं था। और न ही इसका कारण पता चला।
बाबरी मस्जिद के ताले खोलने से इतनी उथल-पुथल मच जानी चाहिए थी।
मुसलमानों के बीच। उनकी पश्चिमी विचारधारा ने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया।
उनके करियर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक। परिणामस्वरूप, उन्होंने दोनों को नाराज़ कर दिया।
मुसलमानों और हिंदुओं—और चुनावों में दोनों का समर्थन खो दिया।
इसके बाद 1989 में जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें उनकी बहुमत वाली सीटें 414 से घटकर 197 रह गईं।
उसके बाद कांग्रेस कभी उबर नहीं पाई। न ही उसे बहुमत मिला।
संसद में अपने दम पर। ऐसे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा होना।
अभूतपूर्व बहुमत को उसी तरह से इधर-उधर धकेला जा सकता था जिस तरह से वह था।
इससे राजीव गांधी की छवि को नुकसान पहुंचा। देश एक मजबूत नेता चाहता था।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के नेता—और उन्हें जनादेश दिया गया,
जिसे अभी तक बेहतर नहीं बनाया जा सका है।
पार्टी की चुनावी संभावनाओं को झटका देने के अलावा, राजीव ने

मुस्लिम महिला विधेयक पर गांधीजी की कार्रवाइयों के अन्य प्रभाव भी थे।
परिणाम। कि 'अदालतों का कोई महत्व नहीं था, राजनीतिक आंदोलनों का महत्व था।'
चुनावी वोट बैंकों का भी यही हाल था। इससे हिंदू अखबार को और भी अधिक बढ़ावा मिला।
दक्षिणपंथी एजेंडा, विशेष रूप से उत्तर भारत में—किसी भी अन्य एकल एजेंडा की तुलना में कहीं अधिक
तब तक जो निर्णय लिया गया था, वही लागू था। अप्रैल 1986 में उत्तर प्रदेश में घूमना-फिरना।
(राज्य में 'सांप्रदायिक विभाजन' पर तीन भागों में लेख लिखने के लिए)
(द स्टेट्समैन)
विभाजन इतना गहरा हो गया था कि हिंदुत्व की राजनीति के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हो गई थी।
भाजपा द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद, वे भागने के लिए तैयार थे।
इसी समय 'मुस्लिम तुष्टीकरण' की नीति भी सामने आई—जिसका उद्देश्य मुस्लिम तुष्टीकरण को खत्म करना था।
शाह बानो का फैसला कट्टरपंथियों के दबाव में आया।
मुस्लिम समुदाय—राजनीतिक शब्दावली और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश कर गया
प्रवचन।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और हिंदू कट्टरपंथियों को इसके खुलने से करारा झटका लगा।
बाबरी मस्जिद के ताले। यह उन्हें मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था।
6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पर उस समय हमला हुआ जब शक्तिशाली भारतीय सेनाएँ वहाँ मौजूद थीं।
राज्य असहाय होकर देखता रहा, विध्वंस को रोकने में असमर्थ था—और
इसके लिए किसी को भी दंडित नहीं किया गया।
तीन दशक बाद, नरेंद्र मोदी को उसी का फल मिलेगा।
इसकी नींव राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान रखी गई थी।

अध्याय 3

भारत को नया रूप देने वाला धूर्त प्रधानमंत्री
राजनीति

वी. पी. सिंह की मंडल चाल

मैं

रिपोर्टर संसद के केंद्रीय हॉल से चिल्लाते हुए बाहर भागा, 'यह है
'देवी लाल प्रधानमंत्री बनें।' वह अपनी प्रति दाखिल करने के लिए जल्दी में थे। उन्होंने काम किया।
यह खबर यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) की समाचार सेवा से संबंधित थी और प्रेस में प्रकाशित होने वाली थी।
पहली मंजिल पर स्थित कमरा। आस-पास मौजूद हर कोई दंग रह गया। वे
विश्वनाथ प्रताप सिंह को नया प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद थी।
उनके नेतृत्व में ही वी.पी. द्वारा गठित गठबंधन राष्ट्रीय मोर्चा अस्तित्व में आया।
सिंह ने हाल ही में हुए आम चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती थीं।
देखते ही देखते समाचार चैनलों पर यह खबर फैल गई: 'देवी लाल नए प्रधानमंत्री हैं'
भारत के मंत्री। विद्रोही जाट नेता देवी लाल प्रमुख थे।
हरियाणा राज्य के मंत्री। मेरे बगल में खड़े कुछ लोग।
निराशा से आह भरी। 1 दिसंबर 1989 को शाम के 4:10 बज रहे थे।
घटनाक्रम के इस मोड़ से मैं दंग रह गया। मैं अभी-अभी यहाँ आया था।
parliament after meeting Om Prakash Chautala, Devi Lal's eldest son.
वह अपने पिता को प्रधानमंत्री बनाने के अभियान का नेतृत्व कर रहे थे।
मेरे पत्रकार साथी हरीश गुप्ता, जिनसे मेरी अचानक मुलाकात हुई थी, उनके साथ थे।

हम चौटाला को दोपहर का भोजन करते हुए पाए। उसने अपनी आँखों से नज़र नहीं हटाई।
हमारा स्वागत करने के लिए उसने थाली दी। वह उदास लग रहा था, और उसके जवाब संक्षिप्त थे।
लगभग यह स्वीकार करते हुए कि उनके पिता के लिए खेल खत्म हो चुका था—और यह कि वी.पी.
सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे।
दिन भर देश में राजनीतिक हलचल मची रही।
राजधानी। 28 नंबर लोदी एस्टेट में, वी. पी. सिंह के आवास पर, सैकड़ों लोग जमा हुए।
कुछ लोग उम्मीद से इधर-उधर मंडरा रहे थे, कुछ घर के अंदर घुस गए थे, अन्य
लॉन में बाहर खड़े होकर, कुछ लोग दीवारों से सटकर खड़े थे।
वे रसोई में थे। वे इस खबर का इंतजार कर रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्हें पता था कि वरिष्ठ नेता अलग-अलग जगहों पर समूहों में इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे हैं।
शहर के कुछ हिस्सों में बातचीत चल रही है।
देवी लाल ने पूरे समय वी.पी. सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया था।
1989 के चुनाव अभियान में उन्होंने भाग लिया। लेकिन, चुनाव के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया।
स्वयं शीर्ष पद के लिए। उपराष्ट्रपति के निजी सचिव एस. एन. सिंह उत्तेजित अवस्था में थे।
जो इलाहाबाद में उनके शुरुआती दिनों से उनके साथ थे, उन्होंने टिप्पणी की,
लगभग रोते हुए, 'राजीव गांधी ने भी राजा साहब (वी. पी.) को अपमानित नहीं किया था।'
सिंह) को इस तरह। जनता दल के कुछ नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं।
उसे...' उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। वे इनकार करने पर तुले हुए थे।
उपराष्ट्रपति को वह सम्मान मिला जो देश भर में कई लोगों का मानना था कि उनका हक था—भारत के सर्वोच्च नेता का पद।
मंत्री पद।

राजधानी के अन्य हिस्सों में, हरियाणा भवन भी चहल-पहल से भरा हुआ था।
गतिविधि। देवी लाल के लिए दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हुई थी। वह
कुछ दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए। देवी लाल ने देखा था
उन्होंने खुद को राजनीतिक दलों के ढीले-ढाले समूह में किंगमेकर के रूप में स्थापित किया।
जिसने एक साझा मंच पर चुनाव लड़ा था—जब तक कि उसने ऐसा करना शुरू नहीं कर दिया।
स्वयं प्रधानमंत्री बनने की संभावना की झलक। राजनेता,
पत्रकार, शिक्षाविद और राजनीतिक कार्यकर्ता जिन्होंने इसके लिए काम किया था
राजीव गांधी की हार, हरियाणा भवन में आना-जाना।
सुबह, देवी लाल से परामर्श करने की उम्मीद में।
अकबर रोड स्थित 14 नंबर के आवास पर भी काफी चहल-पहल थी।
अरुण नेहरू के बारे में, जो कभी राजीव गांधी के शासनकाल में सबसे शक्तिशाली मंत्री थे।
राजीव गांधी द्वारा बर्खास्त किए जाने तक वह सरकार में थे और उसके बाद उन्होंने वी.के. के साथ गठबंधन कर लिया।
पी. सिंह। कांग्रेस से अलग होने के बाद वे वीपी के साथ ही रहे थे।
1987 में उन्होंने जनता दल के गठन में मदद की और 1988 में भी उन्होंने इसी दौरान चुनाव जीता था।
उत्तर प्रदेश के बिल्हौर से लोकसभा के लिए चुने गए थे और उपराष्ट्रपति के दाहिने हाथ के उम्मीदवार के रूप में उभरे थे।
उन दिनों मेरा खास आदमी। मैंने उपराष्ट्रपति को चुनाव से दो दिन पहले बताया था...
नेहरू ने मुझसे कहा, 'यह मामला मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम इससे दूर रहो।'
उस दिन की गतिविधियों का चौथा केंद्र उड़ीसा भवन था। यहाँ भी,
किसी और की निगरानी में गहन बातचीत चल रही थी।
शक्तिशाली राजनीतिज्ञ, बिजू पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री।
एक जगह से दूसरी जगह भागते-भागते मुझे कुछ मिनट की देरी हो गई।
संसद में आगमन। जनता दल संसदीय समिति की बैठक।
जेडीपीपी पार्टी की अभी शुरुआत ही हुई थी। यह पार्टी के नेता का चुनाव करेगी जो...

फिर वे देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे।
राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन जनता दल का इंतजार कर रहे थे और
वह अपने सहयोगियों को अपना नेता चुनने का अधिकार देगा, जिसे वह बाद में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है।
गुंबददार सेंट्रल हॉल के दरवाजे अब बंद थे। दर्जनों
पत्रकार बाहर खड़े होकर बेसब्री से यह जानने का इंतजार कर रहे थे कि कौन है।
वह भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे।
अभी हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में, देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसने 217 सीटें गंवा दी थीं।
1984 के आम चुनाव में इसने रिकॉर्ड बहुमत से 414 सीटें जीती थीं।
फिर भी, इसने 197 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की, जो किसी भी अन्य पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की सबसे बड़ी संख्या है।
चुनाव लड़ रही पार्टियां। पार्टी के नेता राजीव गांधी—
और निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था।
राष्ट्रपति वेंकटरमन ने 29 नवंबर को अपना समर्थन न देने का फैसला किया था।
सबसे बड़ी सरकार का नेतृत्व करने के बावजूद नई सरकार बनाने का उनका दावा
लोकसभा में पार्टी। इससे राष्ट्रपति की दुविधा समाप्त हो गई थी।
मैं इस बात पर कानूनी मिसालों का गहन अध्ययन कर रहा हूं कि क्या सबसे बड़े एकल निगम को कहा जाए या नहीं।
बहुमत खोने के बावजूद पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना। या आमंत्रित करना
दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसने सत्ताधारी को हराया था। राजीव गांधी
यह स्पष्ट था कि उनमें गठबंधन सरकार चलाने की क्षमता नहीं थी।
कांग्रेस में एक व्यक्ति राजीव के फैसले से असहमत था। लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं था।
जीतने वाली टीम जनता दल थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास बहुमत है, लेकिन इस बात को लेकर झगड़े हो रहे थे कि नेता कौन बनेगा।
वी.पी. सिंह ने 1988 में जिस जनता दल का गठन किया था, वह

143 लोकसभा सीटों पर विजयी। यह सरकार बना सकती है।
सरकार और उसके सहयोगियों को मिलाकर सत्ताधारी गठबंधन को कम से कम 263 सीटों की आवश्यकता होगी।
लोकसभा में साधारण बहुमत के लिए सीटें। चुनाव से पहले, उपराष्ट्रपति
उन्होंने जनता दल के साथ गठबंधन करके नेशनल फ्रंट का गठन किया था।
केंद्र, जिसे आंध्र प्रदेश की टीडीपी सहित क्षेत्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त है,
तमिलनाडु की डीएमके, असम की एजीपी और एक अलग हुए गुट ने
कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस (समाजवादी)। उपराष्ट्रपति की खुशी के लिए, जनता कांग्रेस।
दल ने चुनावों में 60 प्रतिशत की स्ट्राइक रेट हासिल की थी।
उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था।
पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 85 में से 54 सीटें जीती थीं और बिहार की 54 में से 32 सीटें हासिल की थीं।
हालांकि, उनके दक्षिणी सहयोगियों ने उन्हें निराश किया। टीडीपी को केवल 2 सीटें ही मिलीं।
सीटों पर चुनाव हुए और डीएमके को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस (एस) को 1 सीट मिली। और
एजीपी को कुछ नहीं मिला।
जैसा कि 1977 में हुआ था, जब उत्तरी राज्यों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था,
1989 में भी दक्षिण भारत कांग्रेस के साथ ही रहा था। भाजपा
और वामपंथी दलों ने सत्तारूढ़ गठबंधन को 'बाहर से' समर्थन देने का फैसला किया—
और सरकार में शामिल नहीं हुए। इन दोनों समूहों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी।
देश में चल रही ‘उपराष्ट्रपति पद की लहर’ के चलते भाजपा की सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 2 हो गई थी।
1984 से 1989 तक लोकसभा की सीटें; वामपंथी दलों ने मिलकर
उन्होंने मिलकर 52 सीटें जीतीं, जिनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल से थीं।
भाजपा और वामपंथी दलों के समर्थन से, नेशनल फ्रंट की संख्या में वृद्धि हुई है।
लोकसभा में कुल 283 मत हुए, जो 525 सदस्यीय सदन में आरामदायक बहुमत है।

सांसदों ने। (बाद में, और भी पार्टियों ने नई सरकार को अपना समर्थन दिया।)
राष्ट्रपति जनता दल से जवाब का इंतजार कर रहे थे, तभी पार्टी ने
सरकार बनाने का दावा पेश करने की कोई कोशिश नहीं की गई। समस्या इसमें नहीं थी।
गणित के साथ-साथ नेताओं के बीच की आपसी केमिस्ट्री भी मायने रखती है। 28 से नवंबर से 1 दिसंबर 1989 तक, इस बात पर संघर्ष तेज हो गया था कि कौन
प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति वी. पी. सिंह स्वाभाविक पसंद थे; यह पहले से ही तय था।
उनके नाम पर यह घोषणा की गई कि चुनाव जीत लिए गए हैं। लेकिन देवी लाल की निगाहें इस ओर थीं।
शीर्ष स्थान पर। अनुभवी दिग्गज चंद्र शेखर भी शीर्ष स्थान पर थे।
उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित। 'विश्वनाथ अगर'
‘आप चुनाव लड़ें, मैं भी चुनाव लड़ूंगा,’ उन्होंने उपराष्ट्रपति से सीधे-सीधे कहा। वे तैयार नहीं थे।
एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करना जिसे वह अपने से काफी कनिष्ठ मानता था।
वीपी गांधी परिवार के दरबारी थे, जब उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली थी।
कांग्रेस में प्रशंसित 'यंग तुर्क' के रूप में धनी और शक्तिशाली, और बाद में
उन्होंने 1975-77 के आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ी थी। हालाँकि,
जब यह स्पष्ट हो गया कि उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिलेगा
पार्टी के समर्थन में, उन्होंने देवी लाल का साथ देने का फैसला किया। देवी लाल ने ही अधिकांश फंडिंग की थी।
उम्मीदवारों के प्रति उनका पूरा भरोसा था कि उन्हें उनका समर्थन मिलेगा।
सरकार गठन में देरी बढ़ने के साथ-साथ आलोचना भी बढ़ती गई।
जनता दल के नेतृत्व के खिलाफ नेता चुनने में असमर्थता को लेकर विरोध प्रदर्शन।
अंततः, 1 दिसंबर को जेडीपीपी की बैठक बुलाई गई।
सेंट्रल हॉल के अंदर, तनावपूर्ण बैठक शाम 4 बजे शुरू हुई थी।
मंच पर अनुभवी समाजवादी मधु दंडवते विराजमान थीं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधि को

नियुक्त किया था।
अधिकारी होने के नाते, उन्हें सुचारू और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना था। उनके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा, "..."
तीन संभावित दावेदार थे—वी. पी. सिंह, चंद्र शेखर और
Devi Lal.
दंडवते ने बैठक शुरू करने की घोषणा की और नामांकन आमंत्रित किए।
जेडीपीपी के नेता वी. पी. सिंह ने तुरंत कहा, 'मैं देवी लाल का प्रस्ताव रखता हूं।'
नाम,' उन्होंने कहा। मुस्कुराते हुए चंद्र ने तुरंत इसका समर्थन किया।
शेखर। कमरे में सन्नाटा छा गया। चूंकि वहां कोई नहीं था
दूसरे नामांकन के बाद, दंडवते ने देवी लाल को निर्वाचित घोषित कर दिया। और प्रतिद्वंद्वी एजेंसियों के खबर फैलाने से पहले ही यूएनआई के पत्रकार ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर लेकर हड़बड़ी में रिपोर्टर को बुला लिया।
उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया।
तभी लंबे और देहाती दिखने वाले देवी लाल धीरे-धीरे पूरी तरह से उठ खड़े हुए।
ऊंचाई। उन्होंने सफेद कुर्ता और धोती तथा भूरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी।
कार्डिगन। उन्होंने कहा, 'यह चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा गया है।'
धीरे-धीरे, '...और इस लड़ाई का नेतृत्व वी. पी. सिंह ने किया है।' उन्होंने आगे कहा:
'Aur phir Haryana maen jahan mujhe log tau keh kar pukarte hain, main
wahan tau hi ban kar rehna chahta hoon (In Haryana people know me as
उन्होंने कहा, 'मेरे चाचा, और मैं हरियाणा में चाचा के रूप में ही रहना चाहता हूं।'
फले-फूले। 'मैं संसदीय नेता के रूप में वी. पी. सिंह का नाम प्रस्तावित करता हूं।'
दल।'
फिर उन्होंने विजयी भाव से घोषणा की, 'वीपी हो गया (वीपी विजेता है)।'
इकट्ठे हुए सांसदों ने जोरदार तालियां बजाईं।
इतनी हलचल और उत्तेजना थी कि कुछ सेकंड के लिए किसी को भी पता ही नहीं चला।
देवी लाल के प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर, अजीत सिंह, जो प्रमुख थे, ने भी

समर्थन किया।
राष्ट्रीय लोक दल और पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र चरण सिंह।
वह खड़ा हो गया। शोरगुल के बीच उसने चिल्लाकर कहा, 'मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।'
मधु दंडवते ने पूछा कि क्या कोई और नामांकन हैं?
सन्नाटा छा गया। उन्होंने घोषणा की कि वी. पी. सिंह को नेता चुना गया है।
जेडीपीपी.
'पहले वाली खबर को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो,' तार फिर से गूंज उठे।
भगवा वस्त्र पहने टीडीपी के एन. टी. रामाराव ने अब मोर्चा संभाला।
उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए वी. पी. सिंह को नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी की।
नेशनल फ्रंट संसदीय पार्टी के सदस्य होना एक औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि केवल तीन ही सदस्य थे।
जनता दल के अलावा अन्य पार्टियों के सांसदों ने सीटें जीती थीं।
अब वी. पी. सिंह नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे।
सेंट्रल हॉल में उत्साहपूर्ण बातचीत चल रही थी, जहाँ एक और कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था।
राजनीतिक मील का पत्थर। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक 'मिलन' किया था।
14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को नियति के भाषण के साथ, यह घोषणा करते हुए कि...
भारत की स्वतंत्रता। इसी सेंट्रल हॉल में इस प्रस्ताव को अपनाया गया था।
तिरंगा, राष्ट्रगान और गणतंत्र का संविधान
इसका भव्य गुंबदनुमा हॉल।
चंद्र शेखर अब मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक कोने में बैठ गया।
सेंट्रल हॉल। उसकी नाक के नथुने फूल गए, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके पास था
उन्हें धोखा दिया गया है और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह समझ है।
मैंने उनसे जो बात की, उससे उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि देवी लाल प्रधानमंत्री

बनेंगे।
That is what he had been told by both Biju Patnaik and Devi Lal at Orissa Bhavan only two hours earlier. ‘Iska anjam acha nahin hoga (This
यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है,’ उन्होंने चेतावनी दी।
'बिजु ने मुझे उड़ीसा भवन बुलाया था और बताया था कि उपराष्ट्रपति आएंगे।'
चंद्र शेखर ने कहा, 'देवी लाल का नाम प्रस्तावित करें और मैं उनका समर्थन करूंगा।'
उन्होंने कहा। इसके बाद वे संसद से बाहर निकल गए और अपने आश्रम की ओर चल दिए।
गुड़गांव में भोंडसी। बिजू पटनायक उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे दौड़े।
‘बीजू मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे उप प्रधानमंत्री पद की पेशकश की,’ चंद्र ने कहा।
शेखर ने खुलासा किया, ‘(बाद में) देवी लाल ने मुझे फोन किया और मुझे कोई भी प्रस्ताव दिया।
मैंने पोर्टफोलियो लेने से इनकार कर दिया।' जब चंद्र शेखर प्रधानमंत्री बने
ग्यारह महीने बाद, वी. पी. सिंह सरकार के पतन के बाद,
पटनायक ने उससे कहा, ‘अरे बल्लिया, अगर मुझे पता होता कि तुम भाग जाओगे तो...’
अगर सरकार ऐसी होती, तो मैं वो नहीं करता जो मैंने किया। उनका यही मतलब था।
'मुझे धोखा देने के लिए,' चंद्र शेखर ने आगे कहा।
वी. पी. सिंह को सत्ता में स्थापित करने का वह दिखावा, या जिसे 'फॉर्मूला' कहा जाता था
प्रधानमंत्री द्वारा ओडिशा भवन में कुछ ही घंटों पहले तैयार की गई योजना पर चर्चा हुई थी।
जेडीपीपी की बैठक से पहले। यह तय किया गया था कि वीपी पहले
देवी लाल का नाम प्रस्तावित करें और वे बदले में उपराष्ट्रपति का ताज पहनाएंगे। बस यही तरीका है।
उपराष्ट्रपति भारत के सातवें प्रधानमंत्री बने।
उस शाम 7 बजे, वी. पी. सिंह ने राष्ट्रपति आर. से मुलाकात की।

वेंकटारमन के साथ मधु दंडवते और एक दंपति भी थे।
दूसरों के बारे में। उन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेज सौंपा जिसमें लिखा था कि उपराष्ट्रपति ने
उन्हें नेशनल फ्रंट संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया है।
भाजपा और वामपंथी दलों के समर्थन पत्र भी मौजूद थे।
राष्ट्रपति ने वी. पी. सिंह को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।
उन्होंने कहा कि वे अगले दिन उन्हें शपथ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि यह गार्डों का परिवर्तन होगा।
यह बिना किसी देरी के होना चाहिए। अन्य मंत्री हो सकते हैं।
बाद में शपथ ग्रहण किया गया। वेंकटरमन ने उपराष्ट्रपति को अपना बहुमत साबित करने के लिए तीस दिन का समय दिया।
सदन के फर्श पर। शपथ ग्रहण समारोह 12 तारीख को निर्धारित किया गया था।
2 दिसंबर 1989 को दोपहर।
■

जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक हर प्रधानमंत्री इस मुकाम तक पहुंच चुका था।
अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में शिखर तक पहुँचना। लेकिन वी. पी. सिंह ने अंततः कैसे सफलता प्राप्त की?
शिखर तक पहुंचना कुछ हद तक परी कथा जैसा था—और इससे एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई।
दिल्ली दरबार का कामकाज। ठीक उसी तरह जैसे इसने नाटकीय रूप से निर्णय लिया था

अतीत में मुगल और शाही दरबारों में उत्तराधिकारों के दौरान, यह सिलसिला जारी रहा।
ऐसा 1989 के लोकतांत्रिक भारत में किया गया।
जैसा कि हमने देखा है, प्रधानमंत्री बनने की होड़ में
1 दिसंबर 1989 की सुबह स्थिति चरम पर पहुंच गई। देवी लाल के पास
उन्होंने सुबह होते ही फोन पर काम करना शुरू कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री एक

जल्दी उठने वाला। वह सुबह की सैर के लिए परिसर में निकला।
हरियाणा भवन में सुबह 5:30 बजे, उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था—
उभरती हुई स्थिति के फायदे और नुकसान का आकलन करना।
पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देवी लाल ने वी.पी. सिंह को ही आगे रखा था।
प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन 28 तारीख को चुनाव परिणाम घोषित होने के कुछ ही घंटों के भीतर
नवंबर 1989 में उन्होंने अपना मन बदल लिया था। चंद्र शेखर ने
इससे उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करने की प्रेरणा मिली। वह आगे बढ़ रहे थे।
ओम प्रकाश चौटाला के माध्यम से। देवी लाल ने आगंतुकों से कहना शुरू किया, 'क्या है
मेरे बिना जनता दल? ...मैंने जनता दल बनाया है। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने
उसने चुनाव पर पैसा खर्च कर दिया है।'
इसके बाद उन्होंने भाजपा नेताओं को संदेश भेजकर उनका समर्थन मांगा।
पार्टी पहले से ही हरियाणा में उनकी सरकार का समर्थन कर रही थी। उन्होंने प्रतिनिधि नियुक्त किए।
'धर्मगुरु' चंद्रस्वामी और उनके सहयोगी कैलाश नाथ अग्रवाल, जिन्हें
अधिकांश लोग इन्हें मामाजी के नाम से जानते हैं, दोनों अपनी राजनीतिक दांव-पेच की क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, और उनकी मुलाकात तय हुई।
बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेई. मामाजी ने वाजपेयी से देवी बनाने का आग्रह किया
देवी लाल प्रधानमंत्री बनेंगे और सरकार में शामिल होंगे।
भाजपा की हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन करने को तैयार। लेकिन वाजपेयी
और एल. के. आडवाणी इस विचार के प्रति उदासीन थे। उन्होंने वी. पी. सिंह का समर्थन किया।
उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया, क्योंकि उन्हें जनता का जनादेश प्राप्त था।
जब देवी लाल हरियाणा भवन के लॉन में टहल रहे थे, तो उनके मन में कई विचार चल रहे थे।
उसने पिछली शाम को हुई अपनी तीखी बहस का जिक्र किया।

जनता दल के नेता सोम पाल। पाल, जो उनके रिश्तेदार थे और उन्हें बुलाते थे।
मामाजी (चाचा) ने उपराष्ट्रपति के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी और एक
उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए ज़ोरदार पैरवी। 'मामाजी, पूरे चुनाव अभियान के दौरान, आपने
पाल ने बार-बार कहा था कि वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे।
देवी लाल ने याद दिलाया, 'अब, तुमने जो वादा किया था, उस पर कायम रहो।'
चंद्र शेखर जेडीपीपी के नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं।
देवी लाल ने इसका जवाब दिया था।
'चंद्र शेखर के खिलाफ आंकड़े बहुत प्रतिकूल हैं,' सोम पाल ने कहा।
उसने पलटकर जवाब दिया, 'हमने हिसाब-किताब कर लिया है।' फिर उसने नामों की झड़ी लगा दी।
उन सांसदों में से जो चंद्र शेखर और उनके साथ जाने की उम्मीद कर सकते हैं
देवी लाल—वे अल्पसंख्यक थे।
'लेकिन चंद्र शेखर सहमत नहीं हो रहे हैं,' देवी लाल ने जोर देकर कहा। 'और
आपका आदमी (उपराष्ट्रपति) चुनाव नहीं चाहता।
वी. पी. सिंह सर्वसम्मति से निर्वाचित होना चाहते थे। यदि चुनाव होता तो
उन्होंने कहा कि इससे पार्टी में शुरू में ही फूट पड़ जाएगी। वे नहीं चाहते थे कि सरकार ऐसा करे।
शुरुआत ही बेमेल तरीके से हुई। उपराष्ट्रपति आसानी से जीत जाते। लेकिन वह...
अन्य कारकों के बारे में आशंका थी। उद्योगपतियों ने अपने
परिणाम घोषित होने के कुछ ही घंटों के भीतर, बड़े-बड़े हथियारों से लैस प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे।
पैसा। वे नव निर्वाचित सांसदों को पांच सितारा होटलों में ठहरा रहे थे।
उन पर प्रभाव डालने के लिए। ये शक्तिशाली व्यवसायी थे जिनके विरुद्ध वीपी ने कार्रवाई की।
जब उन्होंने कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के लिए छापे मारे थे, तब उन्होंने
वह राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्हें संदेह था कि
अब वे चंद्र शेखर और देवी लाल के साथ मिलकर इनकार करने की साजिश रच रहे थे।

उन्हें पार्टी नेतृत्व सौंपना। हालांकि जनता दल के कई सांसद चाहते थे
अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो मतदान होने पर उनकी निष्ठाएँ विभाजित हो सकती हैं।
देवी लाल ने कई लोगों के चुनाव अभियान को आर्थिक सहायता दी थी।
जैसे-जैसे वह पिछले कुछ घंटों की घटनाओं पर विचार कर रहा था, यह स्पष्ट होता जा रहा था।
देवी लाल को बताया गया कि अब बहुमत वीपी के पक्ष में है।
जैसे ही उनके दिमाग में योजना आकार लेने लगी, उन्होंने कुछ लोगों से बात करने की इच्छा जताई।
उनके प्रति वफादार नेताओं में से। अगर उन्हें शीर्ष पद नहीं मिलने वाला था, तो उनके पास
एक कठिन सौदेबाजी करने के लिए। सबसे पहले, उसने सोम पाल को फोन किया और उससे पूछा कि
तुरंत इधर आओ। एक जाट, जो अपनी बात कहने में संकोच नहीं करता था, पाल आया।
सीधी बात पर आते हैं। 'मामाजी, केंद्र सरकार चलाना ऐसा नहीं है जैसे
हरियाणा मंत्रालय चलाना... हरियाणा में आपको कुछ समय लगा।
‘सालों तक इसकी रफ्तार धीमी रहेगी,’ उन्होंने देवी लाल से साफ-साफ कहा। ‘दिल्ली में तो यह और भी कम हो जाएगा।
इसमें आपको दो महीने लगेंगे।
फिर उन्होंने देवी लाल को एक प्रलोभन दिया, 'अगर आप उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन देते हैं...तो आप'
वह उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हम इस बारे में बात कर सकते हैं।'
लेकिन धूर्त देवी लाल को यह पहले से ही पता था। उन्होंने सुना था कि वी. पी.
सिंह उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार थे। सोम पाल इसके लिए तैयार नहीं थे।
केवल वही एक व्यक्ति था जिसने उसे यह बात बताई थी। एक समय पर, वीपी ने इस बारे में सोचा था।
दो उप प्रधानमंत्रियों के होने का विचार—उत्तर से देवी लाल
और दक्षिण से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव।

‘(हालाँकि) मुझे टीडीपी के पी. उपेंद्र ने सलाह दी थी कि मैं आमंत्रित करूँगा
'मुसीबत आ गई है,' वीपी ने मुझसे कहा।
देवी लाल की निगाहें अब सिर्फ उप प्रधानमंत्री पर ही नहीं टिकी थीं।
वह मंत्री पद भी चाहते थे। वह गृह मंत्री भी बनना चाहते थे। अचानक, मानो उन्हें
जैसे ही उन्होंने अपना मन बना लिया, उन्होंने सोम पाल की ओर मुड़कर कहा, 'अरुण नेहरू को मेरे पास भेजो।' अब तक उन्होंने नेहरू से बात करने से इनकार कर दिया था, जो उनकी ओर से कार्य कर रहे थे।
उपराष्ट्रपति सोम पाल नेहरू को ढूंढने के लिए हरियाणा भवन से बाहर भागे।
■

‘क्या हमने राजीव गांधी से इसलिए लड़ाई लड़ी थी ताकि ऐसी गड़बड़ी पैदा हो?’ संपादक ने अफसोस जताते हुए कहा।
कुलदीप नैयर, जो उस सुबह बाद में देवी लाल के साथ बैठे थे। उनके साथ जे. भी थे।
डी. सेठी, एक जाने-माने शिक्षाविद थे, जो नायर के साथ गए थे।
कई पेशेवर लोग चाहते थे कि उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनें और
भारत के मध्यमवर्गीय वर्ग का एक बड़ा हिस्सा। वे देवी लाल को मनाने के लिए उनसे मिलने आए थे।
उन्हें उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने के लिए राजी करना।
नायर गर्व से दावा करता था कि उसने इसके निर्माण में भूमिका निभाई थी।
भारत के तीन प्रधानमंत्रियों—लाल बहादुर शास्त्री, वी. पी. सिंह,
और आई. के. गुजराल। नायर शास्त्री के प्रेस सचिव बने, और भारत के
उपराष्ट्रपति के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान 1990 में लंदन में उच्चायुक्त, और
Gujral sent him to the Rajya Sabha in 1997.
चौटाला, जिसे चंद्र शेखर ने अपने पिता को ऐसा न करने देने के लिए कहा था।
नज़र से ओझल होकर, वह अपने पिता से बड़बड़ा रहा था, 'बाबूजी, बरहागरक करने वाले।'
hain Kuldip Nayar aur Sethi (Kuldip Nayar and Sethi are going to spoil

चीजें)।' सुबह 8 बजे, अखबार के संपादक अश्विनी कुमार चोपड़ा
वह कमरे में दाखिल हुआ। देवी लाल ने उसे एक घंटे पहले फोन किया था और
उसे आने के लिए कहा। उसे देखकर चौटाला और भी ज्यादा उत्साहित हो गया।
derisive, 'Lo teesra bewakoof aa gaya (Look, a third fool has come).'
'आप क्या सुझाव देते हैं (मुझे क्या करना चाहिए)?' देवी लाल ने चोपड़ा से पूछा, उनकी बात अनसुनी करते हुए।
उनके बेटे के ताने।
"तुम्हारा ऐसा पूछने का क्या मतलब है? एक गठन प्रक्रिया शुरू करो।"
सरकार,' चोपड़ा ने जवाब दिया। 'आप उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बना दें और आप गृह मंत्री बनें।
'गृह मंत्री बन जाऊं (क्या मैं गृह मंत्री बनूं)?' देवी
लाल ने ऐसे कहा मानो यह विचार पहली बार उसके मन में आया हो।
'Usme kya hoga mere paas (What will I get under it)?'
चोपड़ा ने उन फायदों की सूची गिनानी शुरू कर दी जो उनके विचार से देवी लाल को मिल सकते थे।
आकर्षक लगता है। 'खुफिया ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और एक विमान'
बीएसएफ का, जिसका इस्तेमाल सिर्फ गृह मंत्री ही कर सकते हैं... फिर आता है...
आईटीबीपी [भारत-तिब्बत सीमा पुलिस]। इसके पास भी एक हेलीकॉप्टर है।' वह होगा
पुलिस से नियुक्ति कराने और खुफिया एजेंसी से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम। 'राजा
कि जान तोते में होती है (एक शासक की धड़कन उसके तोते में होती है)। रखें
'टोटा आपके साथ है,' उन्होंने सलाह दी।
'तुम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते,' अश्विनी कुमार चोपड़ा ने देवी लाल से कहा।
दृढ़ता से।
'हम उसे यही तो बता रहे हैं,' नायर ने कहा।
नायर, सेठी और चोपड़ा एक साथ हरियाणा भवन से बाहर निकले।
और उन्होंने अरुण नेहरू के घर जाने का फैसला किया। नेहरू ने

वह उपराष्ट्रपति की ओर से मुख्य वार्ताकार के रूप में उभरे और उन्हें एक कुशल वार्ताकार के रूप में जाना जाता था।
एक सख्त सौदागर। उन्होंने जनता दल के नेताओं को यह बता दिया था कि वीपी इसका चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए। अन्यथा, उन्होंने चेतावनी दी, 'हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे।'
एक प्रतियोगिता। उनके और देवी लाल के बीच मानसिक संघर्ष चल रहा था। नेहरू देवी लाल के पहले पलक झपकाने का इंतजार कर रहा था।
नेहरू ने बाद में कहा, 'मैं इसे देवी लाल को वापस दे देता था। आप थोड़ा दौड़ते हैं।'
हरियाणा जैसे राज्य में, और आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं... अंततः, वह
पीछे हट जाएगा।
'बिजु (पटनायक) ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो
नेहरू ने कहा था, 'अगर आप उसे धमकाएंगे और उस पर चिल्लाएंगे, तो वह छिप जाएगा।'
टिप्पणी की।
नेहरू ने नायर, सेठी और चोपड़ा से कहा, 'हमें देवी लाल की परवाह नहीं है।'
जब वे उनके आवास पर उनसे मिले तो उन्होंने हमेशा की तरह आक्रामक रवैया अपनाया। लेकिन
उन्हें पता था कि समय तेजी से बीत रहा है। उन्होंने देवी लाल से बात करने के लिए सहमति जताई।
बशर्ते कोई बदतमीज़ी (दुर्व्यवहार) न हो। 'तुम देवी लाल को बुलाओ'
मुझे फोन करना।' उत्साहित तीनों दौड़कर हरियाणा भवन वापस चले गए।
■

इस बीच, सोम पाल उपराष्ट्रपति के आवास पर चले गए, बजाय खुद जाने के।
सीधे अरुण नेहरू को। उन्होंने सोचा कि पहले उन्हें इस बात से अवगत करा देना चाहिए।

नवीनतम घटनाक्रमों के बाद, उन्होंने मिलकर नेहरू के घर जाने का फैसला किया।
वहाँ उनके साथ पत्रकार संतोष भारतीय, संपादक भी शामिल हुए।
चौथी दुनिया, जो उपराष्ट्रपति के भी करीबी थे। बहुत जल्दी, सोम पाल
उन्होंने नेहरू को उस सुबह देवी लाल के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया—कि
अब देवी लाल को मनाने के लिए तैयार हो गए। प्रसन्न नेहरू रवाना हो गए।
हरियाणा भवन। दोपहर में नेहरू ने उपराष्ट्रपति को फोन किया और उन्हें पहुंचने के लिए कहा।
मुझे तुरंत ओडिशा भवन जाना होगा। वह भी जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे।
ओडिशा भवन में, उपराष्ट्रपति सोम पाल और संतोष भारतीय के बीच बैठक हुई।
लिफ्ट से बीजू पटनायक अंदर आए। जब भारतीय ने उनका अभिवादन करते हुए पूछा, 'दादा, आप कैसे हैं?' तो चिड़चिड़े पटनायक ने पलटकर जवाब दिया, 'क्या आप डॉक्टर हैं या...?'
क्या?' उनकी चिड़चिड़ाहट ने उन्हें दिखा दिया कि तब तक कोई समझौता नहीं हुआ था।
मामला सुलझ गया था। पटनायक और नेहरू उन दिनों साथ मिलकर काम कर रहे थे।
समाधान खोजने में घंटों लग गए।
ऊपर, बिजू पटनायक उपराष्ट्रपति और नेहरू को कमरा नंबर 301 में ले गए, जिसमें यह उनके उपयोग के लिए आवंटित किया गया था। यहीं पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बैठक की थी।
वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी सभी 'विशेष बैठकें'। कम महत्वपूर्ण लोग बैठे रहते थे।
कमरा नंबर 302 से सटा हुआ कमरा, जो श्रीकांत जेना को आवंटित किया गया था, जो बाद में
1996-97 में संयुक्त मोर्चा सरकार में मंत्री बने। लेकिन
उन घंटों में, वह लगातार पटनायक के साथ ही रहता था। अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी,
पटनायक और नेहरू एक ही राह पर चल रहे थे।
पटनायक सर्वसम्मति से चुने जाने की संभावना को लेकर संशय में थे।
उपराष्ट्रपति के पक्ष में चुनाव। उन्होंने नेहरू से साफ-साफ कहा था, 'ऐसा नहीं हो

सकता।'
‘चंद्र शेखर चुनाव लड़ेंगे।’ पटनायक देवी लाल पर काम कर रहे थे।
उन्हें उपराष्ट्रपति पद स्वीकार करने के लिए राजी करना। 'केवल बीजू ही ऐसा कर सकते थे...'
चंद्र शेखर ने देवी लाल को (प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए) राजी किया।
बाद में उन्होंने कहा, 'अरुण नेहरू देवी लाल को मना नहीं सकते थे।'
बिजु पटनायक ने अब देवी लाल को उड़ीसा भवन में बुला लिया।
माहौल में तनाव चरम पर था। अभी तक कोई फैसला नजर नहीं आ रहा था।
शरद यादव ने अरुण नेहरू को एक तरफ ले जाकर उनसे विनती की, 'किसी तरह'
कोई रास्ता निकालो। देवी लाल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनना चाहते हैं।
मंत्री।'
‘कभी नहीं,’ अरुण नेहरू ने उत्तर दिया।
‘फिर क्या होगा?’ जनता दल के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने चिंता से पूछा।
देवी लाल समूह में शामिल एक नेता।
नेहरू ने कहा, ‘हम उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाएंगे और उन्हें कृषि विभाग सौंपेंगे।’
उसने अविचलित होकर उत्तर दिया, "आखिरकार, वह किसानों का नेता है।"
एक बार उपराष्ट्रपति ने नेहरू से कहा, ‘उसे दे दो। अरुण, मत दे दो।’ ‘अरुण, मत दे दो।’
'इतना दबाव डालो कि पार्टी ही टूट जाए'
लेकिन नेहरू अंत तक दृढ़ रहना चाहते थे। 'देवी लाल आक्रामक थे।'
नेहरू ने याद करते हुए कहा, 'और यह अनुचित था। हम सभी इससे बाहर आ चुके थे।'
कांग्रेस की संस्कृति। हम उनके तौर-तरीकों के आदी नहीं थे। मैंने उपराष्ट्रपति से कहा, "क्यों?"
क्या मैं इस आदमी के आगे झुक जाऊं? बात यहीं खत्म नहीं होगी।
‘Main samjhata hoon (I’ll try and convince him),’ Yadav offered.
उड़ीसा भवन में अंतिम समाधान पर सहमति बनी।
जेडीपीपी की बैठक होने से एक घंटा पहले, वीपी ने मुझे बताया कि यह 'फॉर्मूला' देवी

लाल का विचार था। 'मुझे लगता है कि यह देवी लाल का ही विचार था।'
यह विचार कि उनका नाम पहले प्रस्तावित किया जाए।
‘Hamari izzat, hamari pagari bacha lijiye (Please save my honour),’
उसने वीपी को बताया, जिसे वह कमरा नंबर 301 में ले गया था।
‘Hum aapke liye kuch bhi kar sakte hain (I can do anything for you),’
उपराष्ट्रपति ने उन्हें आश्वासन दिया।
Devi Lal then said, ‘Hamara naam propose ho jaye, phir hum
एक बार मेरा नाम प्रस्तावित हो जाने के बाद, मैं अपना नाम वापस ले लूंगा (withdraw karlenge)
दौड़ से)।
‘Aap withdraw kyon kar lenge, aap hi ban jaeeye (Why should you
अगर आप पीछे हट जाते हैं, तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं?’ उपराष्ट्रपति ने अपने अनोखे, विनम्र लहजे में उनसे कहा।
ढंग।
‘जनता हमें पीटेगी,’ देवी लाल ने जवाब दिया।
लेकिन उपराष्ट्रपति से बात करने से पहले, देवी लाल ने बिजू पटनायक से बात की थी और
नेहरू ने कमरा नंबर 301 में अपनी दुविधा व्यक्त की। ‘हम (चंद्र शेखर)’
se vaada kiya hai ki main banoonga, chahe ek minute ke liye hi kyon
नहीं हो (मैंने चंद्र शेखर से वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा)
भले ही यह एक मिनट के लिए ही क्यों न हो)।’ फिर उन्होंने आगे कहा, ‘Usee (VP) ko banayenge.
Soch raha tha kaise karaenge (However, we will make VP PM, I have
मैं इसे करने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था।’ देवी लाल ने बाद में कुलदीप

को बताया था।
नायर को उड़ीसा भवन में हुई घटना के बारे में बताया।
यह 'फॉर्मूला' वास्तव में अरुण नेहरू का विचार था।
अरुण नेहरू ने मुझे बताया, 'यह फॉर्मूला देवी लाल के उद्धार के लिए विकसित किया गया था।'
गर्व... मेरे पास सभी (अन्य लोगों) का पावर ऑफ अटॉर्नी था... यह घटना घटी।
ओडिशा भवन में हुई एक बातचीत के दौरान। यह (पहले) नहीं था।
सावधानीपूर्वक विचार किया।'
'यह अरुण नेहरू का विचार था,' एस. पी. शुक्ला ने पुष्टि की, जो उस समय मौजूद थे।
नेहरू के कार्यकाल के दौरान वाणिज्य मंत्रालय के सचिव
1990. 'उन्होंने बिना मांगे यह बात मुझसे साझा की जब...हम एक दौरे पर गए थे।
मेक्सिको। वह मेरे साथ काफी खुले दिल से पेश आते थे। नेहरू के लिए यह सब एक सवाल था।
लोगों को कैसे प्रबंधित करें।
अरुण नेहरू ने अंततः बिजू पटनायक को यह विश्वास दिला दिया कि यही एकमात्र रास्ता था।
गतिरोध से बाहर निकलने के लिए। लेकिन, सहमत होने से पहले, पटनायक ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया।
चंद्र शेखर को उपराष्ट्रपति पद के लिए राजी करने का प्रयास छोड़ दें। उन्होंने पूछा
Chandra Shekhar over to Orissa Bhavan. Srikant Jena escorted him upto
पटनायक के कमरे में। चंद्र शेखर अडिग रहे। उन्होंने उड़ीसा छोड़ दिया।
भवन में दस मिनट में। यह दोपहर 3 बजे से ठीक पहले की बात है। पटनायक ने चंद्र शेखर को सौदे का केवल एक हिस्सा बताया था—कि देवी लाल का नाम
इसका प्रस्ताव वी. पी. सिंह रखेंगे और चंद्र शेखर इसका समर्थन करेंगे।
चंद्र शेखर प्रसन्न होकर तुरंत सहमत हो गए।
पटनायक ने निष्कर्ष निकाला कि अब 'फॉर्मूला' अपरिहार्य हो गया है।
हमने देवी लाल से कहा कि वह चंद्र शेखर को बताए कि क्या हुआ है।

samjhauta (deal) was,' Arun Nehru said later.
'मैं उसे सूचित कर दूंगा,' देवी लाल ने उसे आश्वासन दिया।
नेहरू ने कहा, 'लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो क्या होता।' उन्होंने आगे कहा, '(कि) अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो क्या होता?'
चंद्र शेखर से कहा गया था कि वह सहमत नहीं होते।
चंद्र शेखर के उड़ीसा भवन से निकलते ही पटनायक तुरंत वहां पहुंचे।
जेना से संसद भवन। 'तुरंत सेंट्रल हॉल जाओ, मधु को बताओ'
दंडवते... पहले उपाध्यक्ष देवी लाल का नाम प्रस्तावित करेंगे और फिर देवी
लाल औपचारिक रूप से अपना नाम वापस लेंगे और वी. पी. सिंह का नाम प्रस्तावित करेंगे।
'आप चुपके से कुछ सांसदों को भी इसके बारे में बता दीजिए,' पटनायक ने जेना से कहा, 'ताकि
ताकि उन्हें झटका न लगे।'
'क्या होगा अगर देवी लाल उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव स्वीकार कर लें और राष्ट्रपति के पास दौड़ पड़ें?'
'क्या भवन प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश करेगा?' जेना ने मन ही मन चिंता से सोचा।
यह एक ऐसा जोखिम था जो उन्हें उठाना ही था।
'वीपी को प्रधानमंत्री बनाना है, यही सर्वसम्मत है'
Patnaik told Jena.
2 दिसंबर 1989 को दोपहर 12 बजे, राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन ने
उन्होंने वी. पी. सिंह को प्रधान मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
मंत्री ने देवी लाल को भी शपथ दिलाई। देवी लाल को शपथ ग्रहण करना था।
मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्हें उप प्रधानमंत्री नामित किया जाएगा।
इसके बाद। सरदार पटेल के सत्ता में आने पर इसी परंपरा का पालन किया गया था।
1947 में उप प्रधानमंत्री के रूप में, और फिर जब मोरारजी देसाई ने पदभार संभाला, तब भी वे उप प्रधानमंत्री रहे।
1967 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। और तब भी जब चरण

सिंह और जगजीवन राम ने उप प्रधानमंत्रियों के रूप में शपथ ली।
1978 में मोरारजी देसाई ने शपथ ली थी। लेकिन शपथ लेते समय देवी लाल ने उस बात को दोहराया नहीं।
राष्ट्रपति के बाद मंत्री शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके बजाय, वह बार-बार ऊप कहता रहा।
प्रधानमंत्री (उप प्रधानमंत्री) के रूप में अपना वर्णन करते हुए।
राष्ट्रपति वेंकटारमन ने उन्हें विनम्रता से सुधारा। लेकिन देवी लाल अपनी बात पर अड़े रहे।
अगर उसने नहीं सुना होता। तब राष्ट्रपति ने हार मान ली।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद, उत्साहित देवी लाल गाड़ी में बैठ गए।
उनके लिए निर्धारित आधिकारिक कार, जिसे 'चमरा खोलो' कहकर मंगवाया गया था, का संदर्भ देते हुए
सरकारी गाड़ी के बोनट पर झंडे को ढकने वाला चमड़ा, जो
लाल बत्ती थी; उसकी आवाज अधिकारपूर्ण ढंग से गूंज उठी।
फिर उन्होंने अश्विनी कुमार चोपड़ा से पूछा, जो उनके साथ आए थे।
राष्ट्रपति भवन, ‘मेरा कार्यालय कहाँ है?’
उनकी तमाम चालाकियों के बावजूद, हरियाणा में एक देहाती सादगी थी।
तगड़ा आदमी।
उनके सहायक दीपक ने उन्हें बताया, 'साउथ ब्लॉक।'
चलिए दफ्तर चलते हैं।
चोपड़ा ने तब उन्हें सुधारते हुए कहा, 'साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री का कार्यालय है।'
आपको अभी तक कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है, आप उप प्रधानमंत्री बन गए हैं।
बिना पोर्टफोलियो के।’ आगे क्या करना है, इस बारे में अनिश्चित होकर, उन्होंने जाने का फैसला किया।
इसके बजाय राजघाट जाएं और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। फिर वे हरियाणा भवन में वापसी हुई, जो एक निराशाजनक अंत था।
ऐतिहासिक सुबह। देवी लाल को कृषि विभाग मिला, गृह विभाग नहीं। यह उसका हिस्सा था।

उड़ीसा भवन में हुए समझौते के बावजूद,
देवी लाल को इसकी जानकारी थी।
लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। उस शाम कुलदीप नैयर ने फोन किया...
देवी लाल सरकार में नए नंबर दो से बातचीत करने जा रहे हैं। जब नायर
हरियाणा भवन पहुंचने पर, देवी लाल का परिवार इस बात का विश्लेषण कर रहा था कि क्या हुआ था।
प्रधान मंत्री पद में निहित शक्तियों और अन्य लाभों के संदर्भ में कई बातें शामिल होती हैं।
Suddenly Devi Lal interrupted them, 'Woh oop bhi uttar jayega (That
उप-प्रतिनिधि भी जल्द ही गायब हो जाएगा)। वी. पी. सिंह के राज्याभिषेक के कुछ ही घंटों के भीतर,
देवी लाल पहले से ही सिंहासन पर कब्जा करने की लालसा रखते थे। वे हर किसी को यही बात बताते थे।
उसके बाद के दिनों में उस पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा कि उसे उपराष्ट्रपति पद पर ताज पहनाया गया था—और यह कि उसने
वह उनका ऋणी था। 'मेरी वजह से ही वह प्रधानमंत्री हैं।'
आज।'
उन्होंने तीसरे उपराष्ट्रपति से कहा, 'आपको राजनीतिक नैतिकता के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।'
कुछ महीनों बाद जब देवी लाल के बेटे ओ. पी. चौटाला की करतूतों का खुलासा हुआ, जनता दल में हलचल मचने वाली थी। 'आप प्रधानमंत्री बन गए।'
क्योंकि मैंने झूठ बोला था।' इसके बाद के महीनों में, वही किंगमेकर बन गया,
देवी लाल, जिसका उद्देश्य उपराष्ट्रपति सरकार को अस्थिर करना था।
वी. पी. सिंह की समस्याओं की शुरुआत, जो समय के साथ-साथ सामने आती रहीं,
अगले ग्यारह महीनों का सवाल इस बात पर टिका है कि वे 1 दिसंबर को कैसे चुने गए।
1989. चंद्र शेखर इसे कभी नहीं भूले, न ही उन्होंने इसके लिए उन्हें माफ किया। उन्होंने इसे और हवा दी।

उपराष्ट्रपति के खिलाफ असंतोष का फायदा उठाया और देवी लाल के माध्यम से काम किया। राजीव ने भी ऐसा ही किया।
गांधी, जिन्हें वीपी ने सत्ता से बेदखल कर दिया था, जो जैसे ही मौका मिलता, हमला करने के लिए तैयार थे।
एक अवसर सामने आया। इन वरिष्ठों की साजिशें
राजनीतिज्ञों, जनता दल शासन में निहित अस्थिरता, जिसे उन्होंने बढ़ावा दिया, और भाजपा की अपनी पहुंच बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने वी.पी.
सिंह ने मंडल को चुना। लेकिन इससे उनके शासन का पतन और भी तेज हो गया।
द्वितीय

8 दिसंबर 1989 को शाम 5:30 बजे, कार्यालय में फोन की घंटी ज़ोर से बजी।
श्रीनगर का एक अखबार, कश्मीर टाइम्स। हिजबुल मुजाहिदीन ने
नव नियुक्त गृहस्थी की बेटी रुबैया सईद का अपहरण कर लिया गया।
भारत के मंत्री, मुफ्ती मोहम्मद सईद, दूसरी तरफ से आवाज दे रहे थे।
फोन उठाने वाले कर्मचारी को फोन की लाइन के बारे में बताया गया। मुखबिर ने कहा वह जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चा (जेकेएलएफ) से संबंधित थे और मांग कर रहे थे जम्मू और कश्मीर के लिए 'आज़ादी'। रुबैया को तब तक बंधक बनाकर रखा जाएगा जब तक...
सरकार ने अपनी हिरासत में मौजूद पांच आतंकवादियों को रिहा कर दिया। वे थे...
जेकेएलएफ के 'क्षेत्रीय कमांडर' शेख अब्दुल हमीद, गुलाम नबी भट,
फांसी पर लटकाए गए आतंकवादी मकबूल भट का छोटा भाई और तीन अन्य लोग।
इस खबर से सरकार स्तब्ध रह गई। उसने आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला किया।
गृह मंत्री की बेटी की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन झुक जाना
दबाव से इसकी छवि में कोई सुधार नहीं हुआ।
वीपी की मुश्किलें उनके पदभार संभालने के एक सप्ताह के भीतर ही शुरू हो गई थीं।
यहां तक कि इससे पहले भी
वह प्रधानमंत्री के रूप में स्थिर हो सकते थे, कश्मीर में अशांति फैली हुई थी और
भारतीय शांति सेना के बल, जिन्हें सजा मिली थी, एक अभियान से लौट रहे थे।

श्रीलंका में अभियान असंतोषजनक रहा। पाकिस्तान के साथ स्थिति भी ठीक नहीं थी।
तनावपूर्ण स्थिति थी। उपराष्ट्रपति ने मुझसे कहा, 'मैंने इस बारे में न तो प्रेस से बात की और न ही कैबिनेट से।'
लेकिन मैंने सशस्त्र बलों के साथ ऑपरेशन थिएटर में समय बिताया था।
मुझे क्या करना चाहिए, इस बारे में अधिकारियों से बात करो।
लेकिन खतरा कश्मीर, श्रीलंका या पाकिस्तान से नहीं था।
उनके मंत्रालय में। उनकी सरकार उन प्रतिद्वंद्विताओं से ग्रस्त थी जो
उन्होंने जनता दल का जो स्वरूप बनाया था, उसमें अशांति का भी वर्णन था। अशांति की शुरुआत हुई।
उत्तर प्रदेश, जो उपराष्ट्रपति की 'कर्मभूमि' थी, उनके जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी।
राजनीति। उपराष्ट्रपति पद की लहर के कारण ही जनता दल को जीत मिली थी।
नवंबर 1989 में उत्तर प्रदेश में हुए राज्य चुनावों में पार्टी को आमंत्रित किया गया था।
लखनऊ में सरकार बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अपनी उम्मीदवारी दांव पर लगा दी।
मुख्यमंत्री होने का दावा करने वाले वरिष्ठ जनता दल नेता अजीत सिंह
उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे।
‘Aap UP ke pachrhe maen mat parho (Don’t get entangled in the UP
उपराष्ट्रपति ने अजीत सिंह को सलाह दी, 'गड़बड़ है।'
उन्होंने तर्क दिया, ‘अगर मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, तो...’
पार्टी का विघटन कल से ही शुरू हो जाएगा।’ और मुलायम सिंह
यादव कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने अजीत सिंह को आश्वासन दिया कि उनके समर्थकों को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। 'मैं देखता हूं
'केंद्र में आपका उज्ज्वल भविष्य है,' उपराष्ट्रपति ने अजीत को लुभाने के लिए यह प्रस्ताव रखा।
सिंह। लेकिन अजीत सिंह ने मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गए। दोनों
मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह ने चुनाव के लिए वी.पी. सिंह को दोषी ठहराया।

'मुलायम सिंह आज भी मानते हैं कि अजीत के पीछे वीपी सिंह का हाथ था।'
सोम पाल ने कहा, 'अजीत सिंह कहा करते थे कि यह वीपी ही थे जिन्होंने सबसे पहले यह किया था।'
उन्हें मुलायम सिंह यादव से मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित किया और बाद में उन्हें (अजीत) पराजित हुए—जब यह स्पष्ट हो गया कि यादव समस्याएँ खड़ी कर सकते हैं।
उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए इस चुनाव ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में मौजूद मतभेदों को और गहरा कर दिया।
जनता दल ने बिल्कुल शुरुआत में ही ऐसा किया।
■

असल में, तीन 'एम'—मेहम, मंडल और मंदिर—ने इस बात को परिभाषित किया कि...
वी. पी. सिंह सरकार का ग्यारह महीने का शासन। 'मेहम में तबाही'
हरियाणा के मेहम में उपचुनाव के बाद मीडिया की सुर्खियों में यही खबर छाई रही।
27 फरवरी 1990 को जब देवी लाल हरियाणा से दिल्ली आए थे।
उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश को उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था।
चौटाला ने राज्य के मुख्यमंत्री बनने से पहले उपराष्ट्रपति से सलाह नहीं ली थी।
चौटाला को अब राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना था।
छह महीने के भीतर। उन्होंने फरवरी 1990 में मेहम से चुनाव लड़ने का फैसला किया।
यह वही निर्वाचन क्षेत्र है जहां से देवी लाल ने 1987 में जीत हासिल की थी।
चुनाव के साथ ही सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया। इसके परिणामस्वरूप ऐसी घटनाएं हुईं जो...
'एक हॉरर फिल्म और बरलेस्क थिएटर का मिश्रण'। मुख्यमंत्री
चौटाला पर आरोप है कि उसने खुलेआम धमकी और बूथ पर कब्जा करने का इस्तेमाल करके यह हासिल किया।
अपने प्रतिद्वंदी आनंद सिंह डांगी से बेहतर। डांगी जनता दल के बागी नेता थे।

नेता। मेहम में चुनाव के बाद हुई हिंसा में आठ लोग घायल हुए।
मारे गए लोगों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार, आमिर सिंह भी शामिल थे। चौटाला
आरोप है कि उसने मेहम के गांवों में बदमाशों के समूहों का नेतृत्व किया, जबकि
उनके पिता देवी लाल की कुख्यात 'ग्रीन ब्रिगेड' ने मतपेटियों में हेराफेरी की।
और बूथों पर कब्जा कर लिया। चौटाला के रास्ते में खड़े होने वाले, जिनमें शामिल थे
चुनाव कवर कर रहे पत्रकारों की जमकर पिटाई की गई। चौटाला ने इस बात से
इनकार किया।
उनके खिलाफ लगे आरोप।
8 मार्च 1990 को, चुनाव आयोग ने आदेश रद्द कर दिया।
चुनाव। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया, 'पूरी चुनाव प्रक्रिया दूषित थी।'
चौटाला पर गंभीर आरोप लगे। जनता ने इसका कड़ा विरोध किया और मांगें उठाईं।
चौटाला के इस्तीफे के लिए। प्रतिदिन, जंतर मंतर रोड स्थित 7 नंबर के जनता दल
मुख्यालय में आयोजित होने वाली दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में, मीडिया से तीखे सवाल पूछे
जाते थे।
जनता दल के प्रवक्ता जयपाल रेड्डी। सवाल बना रहा।
स्थिति अपरिवर्तित रही—चौटाला कब इस्तीफा देंगे? यही सिलसिला हफ्तों तक
चलता रहा।
लेकिन चौटाला ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया।
अंततः, 16 मार्च 1990 को, उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दल की एक बैठक बुलाई।
जनता दल की कार्य समिति ने तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने के लिए यह कदम
उठाया।
हालात बेकाबू होते जा रहे थे। जनता दल के कई नेता—अजीत सिंह,
George Fernandes, Madhu Dandavate, and Nathuram Mirdha
—
देवी लाल ने चौटाला से तत्काल पद छोड़ने की मांग की। देवी लाल बेहद क्रोधित हुए।
उन्होंने कहा कि वह इन 'बदमाशों' की बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सिद्धांतों', यह जानते हुए कि आक्रमण ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। 'कौन
“क्या तुमने अजीत सिंह को मेहम जाने के लिए कहा था?” बैठक समाप्त होते ही वह
गरज उठा।

शुरू हो गया। अजीत सिंह, जो अब देवी लाल का कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन चुका था, मेहम से मिलने आया था।
और वहां फैली व्यापक हिंसा की रिपोर्ट दी। 'मैं जानता हूँ कि मेरा
उन्होंने आक्रामक लहजे में आगे कहा, 'उप प्रधानमंत्री कई लोगों के लिए कांटा हैं।' 'मैं
मैं तुरंत इस्तीफा दे रहा हूँ।' ये शब्द कहकर वह बैठक से बाहर निकल गया।
एक गहरी सांस। जनता दल के नेता एक-दूसरे को अचंभित होकर देखने लगे।
मुझे लगा कि देवी लाल फिर से नखरे दिखा रही है। लेकिन एक घंटे बाद
बाद में उन्होंने उप प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया।
जनता दल के वरिष्ठ नेता विलिंगडन स्थित उनके आवास (29) पर पहुंचे।
उसे शांत करने के लिए, उसने क्रिसेंट का सहारा लिया। उसके बाद के घंटों में, उसे एहसास हुआ कि
उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया ठंडी रही थी। देवी लाल ने अनुमति दी।
उन्होंने खुद को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए 'राज़ी' कर लिया। लेकिन नुकसान जो कुछ भी हो चुका था—उसके कारनामों ने पार्टी की छवि को और भी धूमिल कर दिया था।
हालांकि देवी लाल मंत्रिमंडल की बैठकों में उतने आक्रामक नहीं थे जितने कि वे थे।
पार्टी के मंचों पर तो वे मौजूद रहते थे—कैबिनेट में वे ज्यादातर चुप ही रहते थे—वहाँ भी।
उन्होंने एक बार कैबिनेट सचिव विनोद पांडे को बिना किसी औपचारिकता के फटकार लगाई थी।
‘Ae Pande tujhe kya pata hai iske bare maen (Oh Pande, what do you
(क्या आपको लगता है कि आप इसके बारे में जानते हैं?)' उन्होंने वी. पी. सिंह को भी नहीं बख्शा। एक
एक अवसर पर, सरकार बनने से पहले, उन्होंने एक व्यक्ति पर चिल्लाया था।
उत्तेजित उपाध्यक्ष, जो बैठक से बाहर चले गए, बोले, 'जाता है तो जा (अगर बाहर जा रहे हो तो)।'
(आप ऐसा चाहते हैं)। शरद यादव ही थे जो उपराष्ट्रपति को लाने के लिए दौड़े थे।
पीछे।

बाद में वीपी ने याद करते हुए कहा, 'जब देवी लाल ने पहली बार अपना इस्तीफा दिया था।'
'मेरी पहली इच्छा इसे स्वीकार करने की थी।' फिर उन्होंने कुछ खेद भरे लहजे में कहा,
'आपकी पहली सहज प्रवृत्ति अक्सर सही होती है। मैंने इंदिरा गांधी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद मुझे (दूसरी) ट्रेनिंग मिली—पंचायत करो (आओ)। किसी तरह का समझौता—दृढ़ रुख अपनाने के बजाय।'
मेहम के बाद उनकी सरकार की छवि को जो नुकसान पहुंचा था, उसे देखते हुए,
उपराष्ट्रपति मध्यावधि चुनाव कराने पर विचार कर रहे थे। 'अप्रैल में (मेहम के बाद), मैंने
संसदीय चुनावों के साथ-साथ चुनाव भी कराना चाहते थे।
वीपी ने कहा, 'बिहार और बंगाल की विधानसभाओं में। मैं जाना चाहता था।'
लोगों ने इस आधार पर विरोध किया कि मेरे पास बहुमत नहीं था। (मैं) बहुत स्पष्ट था।
कि (इस बार) मुझे दक्षिण में भी लाभ होगा।' उपराष्ट्रपति ने अरुण से सलाह ली।
नेहरू ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। उन्होंने मुझसे कहा, 'जिस क्षण यह आएगा'
मंत्रिमंडल में और मेरे (वी. पी. सिंह) राष्ट्रपति भवन जाने से पहले,
भाजपा तुरंत अपना समर्थन वापस ले लेगी।' ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति
चुनाव का आदेश शायद न दिया जाए। क्योंकि चुनाव तो कुछ ही समय पहले हुए थे।
कुछ महीने पहले। 'संभवतः वह कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देंगे।'
नेहरू ने कहा, 'सरकार। यह उल्टा असर डालेगी।' इसलिए उपराष्ट्रपति ने कहा।
देवी लाल की हरकतों को वह लगातार सहन करता रहा।
■

राजीव गांधी के सहयोगी एम. एल. फोतेदार ने कहा, 'देवी लाल हमारे लिए ईश्वर का दिया हुआ वरदान थे।'
मुझे। 'हमने उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दिन ही तय कर लिया था कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए।'

नवंबर 1990… यहां तक कि आर.वी. (राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन) भी निजी तौर पर उस समय के उपराष्ट्रपति के खिलाफ।
महम की खबर राजीव गांधी के लिए सबसे अच्छी खबर थी जिसकी वे उम्मीद कर सकते थे।
इससे उन्हें सत्ता पलटने के अपने फैसले को तेजी से आगे बढ़ाने का अवसर मिला।
नेशनल फ्रंट सरकार।
फरवरी-मार्च 1990 के आसपास, असंतोष उभरने लगा था।
कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई। कई असंतुष्ट लोग
अब कांग्रेसी जनता दल और अपने पूर्व समर्थकों की ओर देख रहे थे।
अपने सहयोगी, जो अब प्रधानमंत्री थे—दिलचस्पी के साथ। चिंतित राजीव
जिन्हें एन. के. शर्मा कहा जाता था—एक तांत्रिक जो पंडितजी के नाम से व्यापक रूप से जाने जाते थे—जिन्हें राजीव ने
समय-समय पर परामर्श लेंगे और समस्या निवारण के लिए इसका उपयोग करेंगे।
कार्य। शर्मा राजीव के प्रति आकर्षित हो गए थे—और बाद में…
पी.वी. नरसिम्हा राव के दरबार में घुसपैठ करना। 'उपराष्ट्रपति को पदच्युत करो'
सरकार,' शर्मा ने राजीव को सलाह दी। उपराष्ट्रपति की बढ़ती लोकप्रियता
उन्होंने तर्क दिया कि अगर वह अस्थिर दिखने लगे तो कांग्रेसियों का साथ खत्म हो जाएगा। 'हम
सरकार को बदनाम करना होगा।'

मार्च 1990 में, राजीव गांधी ने देवी लाल के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया।
वे उस समूह का हिस्सा थे जो 8 तारीख को जम्मू और कश्मीर गया था।
मार्च 1990 में अशांत घाटी की स्थिति का अध्ययन करने के लिए राजीव के दरबारी भेजे गए।
अब तक यह बात समझ में आ चुकी थी कि देवी लाल जनता पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी थे।
दल सरकार। 'देवी लाल ने मुझे पहले ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री नहीं थे।'
एन. के. ने याद करते हुए कहा, 'मैं किसानों से संबंधित मुद्दों पर उनकी बातें सुनता था।'

शर्मा, जो देवी लाल को अच्छी तरह जानते थे।
20 मई 1990 को राजीव गांधी ने शर्मा को एक आपातकालीन संदेश भेजा।
लगभग आधी रात के आसपास। जब शर्मा जनपथ स्थित 10 नंबर की गली में पहुँचे, तब तक 1:30 बज चुके थे।
राजीव को ये रात्रिकालीन गुप्त रणनीति नियोजन सत्र बहुत पसंद थे।
उन्हें उस रात खबर मिली थी कि जेडीपीपी की बैठक अगली सुबह होनी है।
और देवी लाल को घेरने और 'अपमानित' करने की एक योजना बनाई जा रही थी।
राजीव गांधी ने सुना था कि जन मोर्चा के पूर्व नेता—अरुण
नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान और अन्य जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी
उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर बैठक में हंगामा खड़ा कर देंगे और मांग करेंगे
चौटाला का इस्तीफा। उन्हें कुछ अधिकारियों ने सूचना दे दी थी।
मैं राजीव के साथ संपर्क में रहा और समय-समय पर उसे प्रतिक्रिया देता रहा।
समय। राजीव को लगा कि देवी लाल अपने विरोधियों पर पलटवार कर सकते हैं, 'अगर
वह चौटाला का इस्तीफा अपने साथ बैठक में ले जाता है।
हमें अभी चौधरी साहब (देवी लाल) से बात करनी होगी, और
राजीव ने कहा, 'हमने जो रणनीति बनाई थी (उसे अपने पक्ष में करने के लिए) उसे जारी रखें।'
Gandhi told Sharma.
‘रात के इस समय?’ शर्मा को विश्वास नहीं हुआ।
'कल मेरे पास तीन लोग होंगे जो उनसे बात कर सकेंगे।'
राजीव ने कहा, 'अब सिर्फ तुम ही हो जो यह कर सकते हो।'
तब तक रात के 2 बज चुके थे। शर्मा गाड़ी चलाकर देवी लाल के आवास पर गए, जो 29 नंबर पर स्थित था।
विलिंगडन क्रीसेंट। देवी लाल को नींद से जगाए जाने पर बहुत गुस्सा आया।
अंततः, वह सुझाए गए प्रस्ताव से सहमत हो गया। शर्मा
वह जनपथ स्थित 10 नंबर पर वापस गया। राजीव उसका इंतजार कर रहा था। शर्मा ने उसे बताया।
क्या हुआ था?

देवी लाल ने शर्मा को सुबह वापस आने के लिए कहा था।
जब शर्मा सुबह 5:30 बजे अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने पूछा, 'पंडितजी, क्या आप...?'
'क्या तुम वही दोहराओगे जो तुमने मुझे कल रात बताया था?' जब शर्मा ने ऐसा किया, तो देवी लाल
उन्होंने अपने कर्मचारियों को ओम (ओम प्रकाश चौटाला) को फोन करने के लिए कहा और उन्हें तुरंत आने को कहा।
चौटाला ने तुरंत दिल्ली जाने का फैसला किया। हालांकि, चौटाला ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और राजीव गांधी ने भी इस्तीफा दे दिया।
गांधी की योजना को अमल में नहीं लाया जा सका। लेकिन इस घटना ने
Devi Lal closer to Rajiv.
अब भाजपा भी उन लोगों की कतार में शामिल हो गई है जो मांग कर रहे थे
चौटाला का इस्तीफा। अंततः, चारों ओर से बढ़ते दबाव के साथ,
Chautala quit on 22 May 1990.
इस पूरी अवधि के दौरान, देवी लाल और वी.पी. के बीच की दूरी...
सिंह का कद बढ़ गया था। जून 1990 तक, उनके बीच बातचीत का कोई खास संबंध नहीं रह गया था।
रूठकर, देवी लाल जिंदल नेचुरिक्योर इंस्टीट्यूट (जेएनआई) के लिए रवाना हो गईं, जो एक अग्रणी संस्थान है।
इलाज के लिए बैंगलोर के बाहर एक प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल। राजीव गांधी अब उसके पास एक और योजना थी। उसने देवी लाल से फोन पर बात की।
जब उन्होंने रिसीवर नीचे रखा, तो उन्होंने वहां मौजूद शर्मा से कहा, 'मैं'
मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही। तुम वहां जाओ, उससे बात करो और मुझे फोन करो।
वापस।' राजीव ने शर्मा से देवी लाल को एक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करने को कहा, जिसमें हमला किया गया था।
अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान; इससे मतभेद और बढ़ जाएगा।
जनता दल के भीतर।
'मैं अपने साथ एक पत्र का मसौदा ले गया था। यह अरुण नेहरू के खिलाफ था और आरिफ ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की... यह पत्र टी. एन. द्वारा तैयार किया

गया था।
Seshan (who had been cabinet secretary to Rajiv Gandhi when he was
एन. के. शर्मा ने खुलासा किया, 'प्रधानमंत्री)।'
जिंदल केंद्र पहुंचने पर शर्मा ने देवी को वह पत्र दिखाया।
लाल। 'देवी लाल ने इसे उप प्रधानमंत्री के लेटरहेड पर हूबहू कॉपी कर दिया, और उस पर हस्ताक्षर किए। फिर उन्होंने पत्र प्रधानमंत्री को संबोधित किया। पत्र को भेजा जा रहा था।
दिल्ली में इसकी बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही थी—ताकि इसे प्रेस को जारी किया जा सके। लेकिन
शर्मा की बैंगलोर-दिल्ली की फ्लाइट छूट गई। इसके बजाय, उन्हें एक अन्य फ्लाइट लेनी पड़ी।
मुंबई के लिए फ्लाइट। मुझे बताया गया था कि कोई मुझसे मिलने आएगा।
मुंबई हवाई अड्डे पर कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए मेरे बोर्डिंग कार्ड के साथ।
दिल्ली... जैसे ही मैं विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरा, वहाँ एक व्यक्ति था।
मैं वहां अपने बोर्डिंग कार्ड के साथ इंतजार कर रहा था... वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण था।
उद्योगपति... वह स्वयं मेरे द्वारा लाया गया पत्र देखना चाहता था।
देवी लाल।' रनवे पर उद्योगपति की उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि
उपराष्ट्रपति विरोधी अभियान को अब शक्तिशाली संस्थाओं का समर्थन प्राप्त था।
कॉर्पोरेट जगत के लोग जो उन्हें पद से हटाने के लिए काम कर रहे थे। शर्मा को पद से हटा दिया गया।
मैं देर रात दिल्ली पहुँचा और सीधे जनपथ स्थित 10 नंबर मकान पर चला गया।
देवी लाल का पत्र कुछ कारणों से तुरंत प्रेस को जारी नहीं किया गया था।
देवी लाल और वीपी के बीच सुलह के प्रयास शुरू हो गए। देवी लाल के साथ
गुस्से में आकर सोम पाल ने बैंगलोर जाने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि क्या वह ऐसा कर सकता है।
अपने आक्रामक रवैये को थोड़ा नरम करें। उनके साथ रणजीत सिंह और देवी लाल भी थे।

छोटा बेटा, जिसका अपने बड़े भाई ओम प्रकाश से मतभेद था।
चौटाला उपराष्ट्रपति का समर्थन कर रहे थे। दोनों 26 जून 1990 को जिंदल सेंटर पहुंचे। उन्होंने शाम 4:30 बजे देवी लाल को उनकी दोपहर की नींद से जगाया।
Ranjit told his father, 'Babuji aapke dushman aapki halat Charan Singh
से भी बदतर कर देंगे (आपके दुश्मन आपको बदतर हालत में पहुंचा देंगे)
चरण सिंह की तुलना में)।
'वीपी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं,' देवी लाल ने शिकायतों की एक लंबी सूची गिना दी। 'वह
यूपीएससी सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मुझसे परामर्श नहीं किया जाता है।
राजदूत, राज्यपाल।'
'ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं,' सोम पाल ने उसे शांत करने की कोशिश की। 'इनसे निपटा जा सकता है।'
इसका समाधान आप और प्रधानमंत्री के बीच हो जाएगा।'
अरुण नेहरू जैसे लोग मुझे और उपराष्ट्रपति को दरकिनार करने पर तुले हुए हैं।
'मैं उनके जाल में फंस गया,' उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उन्होंने उसे आश्वासन दिया था कि प्रधानमंत्री
उनकी शिकायतों का समाधान किया जाए। देवी लाल को 7 जुलाई को दिल्ली वापस लौटना था।
उन्होंने फैसला किया कि वापस आने के तुरंत बाद वह उपराष्ट्रपति से मिलेंगे।
दिल्ली लौटने पर सोम पाल और रणजीत सिंह ने प्रधानमंत्री को स्थिति की जानकारी दी।
देवी लाल की शिकायतों के बारे में। वीपी ने कहा कि वह उनका समाधान करेंगे।
देवी लाल के दिल्ली लौटने पर, उपराष्ट्रपति ने तुरंत उन्हें रात्रि भोज में आमंत्रित किया।
8 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास पर सोम पाल ने देवी लाल को रेसकोर्स पर छोड़ा।
सड़क।
अगली सुबह सोम पाल के घर पर फोन की घंटी बजी।
देवी लाल। उपराष्ट्रपति के साथ रात्रिभोज में जो कुछ हुआ उससे वे बेहद खुश थे।

कुछ लोगों ने जानबूझकर ये गलतफहमियां पैदा की हैं।
‘हमारे बीच,’ उसने सोम पाल से कहा। ‘आओ और मेरे साथ सुबह 9 बजे नाश्ता करो।’
और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा,’ उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा।
वीपी ने सुबह 8 बजे सोम पाल को भी फोन किया। वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हुआ।
देवी लाल ने रात के खाने के बारे में सोचा था। 'देवी लाल ने आज सुबह फोन किया था और
सोम पाल ने प्रसन्नतापूर्वक उपाध्यक्ष को बताया, 'उन्होंने कहा कि वह रात्रिभोज से बहुत खुश थे।'
फिर, अपनी जिज्ञासा पर काबू न पा पाने के कारण, सोम पाल ने वीपी से पूछा, “क्या देवी
लाल ने चौटाला को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का मुद्दा क्यों उठाया?
'हां,' उपराष्ट्रपति ने उत्तर दिया।
सोम पाल ने वीपी को चेतावनी दी थी कि जब देवी लाल शिकायत कर रहे थे
उपेक्षा करते हुए, 'उनका अंतिम लक्ष्य चौटाला को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से सत्ता में लाना है।'
सोम पाल, जो ‘मामाजी’ को अच्छी तरह से जानता था, ने देवी लाल के तीखे प्रहार को देखा।
अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान पर हमले को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया।
वी. पी. सिंह के साथ।
‘तुमने क्या किया है?’ अब उत्तेजित सोम पाल ने पूछा।
सचमुच चिंतित। 'इससे दिक्कतें पैदा होंगी।' लेकिन वीपी को भरोसा था।
संकट से उबरना।
एक घंटे बाद नाश्ते के दौरान सोम पाल की आशंकाएं और भी बढ़ गईं।
देवी लाल। उप प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा में संदिग्ध रूप से अतिशयोक्ति की।
his boss: ‘V. P. Singh is a fantastic person. Bahut zordar admi hai (He is

एक शानदार इंसान। वह बहुत अच्छे थे। जब मैंने चौटाला का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने
said, “Chaudhury sahib Haryana to aapka hai. Janata Dal banane se
pehle apne jeeta thaa. Aap aur Haryana ke MLAs jaisa chahen vaisa
करेन (चौधरी साहब, हरियाणा आपका है। आपने तो राज्य भी जीता था)
जनता दल के गठन से पहले। आप और हरियाणा के विधायक ऐसा करते हैं।
जो आपको सबसे अच्छा लगे)”।
सोम पाल अब समझ गया था कि मामला टकराव की ओर बढ़ रहा है।
देवी लाल से विनती की कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक महीने तक इंतजार करें।
चौटाला को फिर से नियुक्त करो। उन्होंने कहा, 'पहले धूल को बैठने दो।' 'लेकिन उन्होंने शुरुआत कर दी।'
मुझ पर चिल्ला रहे थे।'
सोम पाल ने भी ऊंची आवाज में कहा, 'अगर सरकार गिर गई, तो...'
इसका दोष आपका होगा, मामाजी।
देवी लाल की अपने बेटे को फिर से पद पर बहाल करने की मांग को मानकर
हरियाणा के मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति को उम्मीद थी कि इससे शांति और समय मिल जाएगा।
देवी लाल ने चौटाला को फिर से मुखिया पद पर स्थापित करने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया।
मंत्री। 11 जुलाई 1990 को उन्होंने सोम पाल को कृषि स्थित अपने कार्यालय में बुलाया।
भवन में शाम 4 बजे। 'जब मैं पहुंचा, तो उसने मुझे दो पन्नों का बयान सौंपा।'
बनारसी दास गुप्ता (जिन्होंने चौटाला के स्थान पर मुख्यमंत्री का पद संभाला था) द्वारा।
जब उन्होंने कहा कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो देवी लाल चाहते थे कि सोम पाल...
इसे वी. पी. सिंह के पास ले जाओ।

प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं पदभार ग्रहण कर लूँ।
गुप्ता ने बयान में दावा किया, 'केंद्र।' देवी लाल ने राज्य को तलब किया।
12 जुलाई 1990 को, ओम प्रकाश विधायकों को दिल्ली स्थित हरियाणा भवन ले गए।
चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए।
■

उस दिन, चिंतित आरिफ मोहम्मद खान ने विदेश में फोन किया।
लंदन में मौजूद अरुण नेहरू को बताया कि चौटाला को बहाल कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पुनः नियुक्ति की व्यापक आलोचना हुई थी;
जनता दल और नेशनल फ्रंट में आक्रोश फैल गया। अरुण नेहरू वापस लौट आए।
अगले दिन यानी 13 जुलाई को वे दिल्ली के लिए रवाना हुए। वे तुरंत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे।
नेहरू ने उपराष्ट्रपति को गुस्से में बताया कि चौटाला की मुख्यमंत्री के रूप में वापसी विनाशकारी थी—और उन्होंने
बिना देरी किए जाना होगा। प्रधानमंत्री आवास से नेहरू अपने सहयोगियों से मिलने के लिए 14, अकबर रोड गए। अरुण, आरिफ और सत्यपाल मलिक ने फैसला किया कि...
सरकार से इस्तीफा दें; पत्र एक प्राचीन कागज पर टाइप किया गया था।
एक स्टेनोग्राफर द्वारा जल्दबाजी में प्राप्त किए गए रेमिंगटन टाइपराइटर का उपयोग किया गया।
उन्होंने याद करते हुए कहा, ‘हम शाम को अरुण नेहरू के घर पर इकट्ठा हुए थे।’
सत्यपाल मलिक। 'मैं वहां रात करीब 8:30 बजे गया था और अरुण ने मुझे बताया कि हम
उन्हें इस्तीफा देना पड़ा... अजीत सिंह भी वहां मौजूद थे। उन्हें भी इस्तीफा देना था।
हमें।’ लेकिन बाद में अजीत सिंह ने अपना मन बदल लिया।
कुछ ही घंटों में उनका पत्र प्रेस में लीक हो गया। उपराष्ट्रपति ने अरुण को फोन किया।

नेहरू रात 10 बजे—वे टोस्ट, पनीर और कॉफी खा रहे थे जब
फोन आया। प्रधानमंत्री ने उन्हें आने के लिए कहा।
हम रात करीब 11 बजे उपराष्ट्रपति के घर गए और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया।
सत्यपाल मलिक ने कहा, 'सरकार से इस्तीफा देने की इच्छा है।'
‘Agar aap yeh kar rahen hain, toh main bhi yahi karoonga (If you are
उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया, 'अगर मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो मैं भी अपना इस्तीफा दे दूंगा।'
लेकिन उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि...
जनता दल के अध्यक्ष एस. आर. बोम्मई ने कहा कि सरकार अब डगमगा रही थी।
कगार पर। बोम्मई सलाह लेने के लिए एक नेता से दूसरे नेता के पास दौड़ रहा था।
इस नए संकट से निपटने के तरीके पर, छह राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों ने चर्चा की।
कुछ ही घंटों के भीतर मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। अचानक, न तो उपराष्ट्रपति और न ही नेहरू बचे थे।
अब यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया। देवी लाल ही केंद्र में आ गए।
नाटक के अगले चरण में भी यही हुआ। जैसा कि वीपी ने उम्मीद की थी,
क्षेत्रीय प्रांतपतियों और अन्य सभी पक्षों से दबाव बढ़ने लगा।
भाजपा और वामपंथी नेताओं ने उपराष्ट्रपति पद संभालने की अपनी मांग को मुखर रूप से उठाया।
उनके इस्तीफे का समर्थन किया जाए और चौटाला को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
देवी लाल ने पलटवार किया। उन्होंने पहले लिखा हुआ पत्र जारी कर दिया—यह
यह पत्र 15 जुलाई 1990 का था, जिसमें प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे।
अरुण नेहरू और आरिफ खान के खिलाफ—जिसे एन. के. शर्मा ने शुरू किया था
दिल्ली, और जो संभवतः उस पैच के कारण पीछे रह गया था-
चल रहे प्रयासों को तेज करने के लिए। इस पत्र ने हंगामा खड़ा कर दिया। देवी लाल

‘कांग्रेस’ के बारे में रोजाना बयान देकर उन्होंने इस उथल-पुथल को और बढ़ा दिया।
'संस्कृति' जिसने जनता दल के भीतर के वातावरण को दूषित कर दिया था।
मध्यस्थ एक बार फिर सक्रिय हो गए। लेकिन इस बार उनके प्रयास व्यर्थ गए।
लाभ लेना।
■

राजनीतिक रूप से चतुर वी. पी. सिंह ने अपने इस्तीफे का दांव खेलकर स्थिति को पलट दिया था।
अपने जन मोर्चा सहयोगियों पर आरोप लगाते हुए, देवी से खुद को अलग करने की कोशिश की।
लाल को अपने पक्ष में करने और गठबंधन में अपनी प्रमुख स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए।
वह जानता था कि वह दोतरफा हमले की चपेट में आ गया है।
क्योंकि जुलाई 1990 तक अरुण नेहरू का मोहभंग हो चुका था।
सरकार के प्रति अपनी असंतुष्टि को खुलकर व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा: 'अब यह स्थिति बन गई है।'
इस सरकार में बने रहना या इसे चलाना बहुत मुश्किल है।
लंदन में रहते हुए नेहरू ने अपने मन की बात बता दी थी।
ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कुलदीप नैयर: 'उपराष्ट्रपति स्वयंभू हैं'
हमने उसे अपना लक्ष्य बना लिया। हम जानते थे कि वह उसे नष्ट कर देगा।
पहले राजीव गांधी को प्राथमिकता दी जाएगी और इस प्रक्रिया में वे स्वयं को ही नष्ट कर लेंगे।
‘Kuldip Nayar told me this afterwards,’ the senior Janata Dal
राजनीतिज्ञ सुरेंद्र मोहन ने मुझसे कहा, ‘दूसरे शब्दों में, जिस तरह से होगा
नेहरू को शीर्ष पद के लिए मंजूरी मिल जानी चाहिए।
जन मोर्चा समूह द्वारा कांग्रेस में वापस जाने का कदम
अन्य लोगों ने भी इसकी पुष्टि की। ‘अरुण नेहरू ने राजीव से संपर्क किया था’।
फोतेदार ने पुष्टि करते हुए कहा, 'मई-जून 1990 के आसपास।' 'वह (अरुण नेहरू)

थे।'
राजीव को लगातार (वहां क्या हो रहा था उसके बारे में) जानकारी देते रहना।
जनता दल के उपाध्यक्ष को पता था कि उनके पूर्व सहयोगियों ने इस बारे में खुलकर बात की थी।
राजीव गांधी के साथ संचार के माध्यमों के माध्यम से—और इसकी पुष्टि की।
बाद में।
मैंने उपाध्यक्ष से पूछा था कि जनता दल इतनी जल्दी क्यों ध्वस्त हो गई।
पूर्व कांग्रेस नेता दिनेश त्रिवेदी ने मुझे बताया। वह उनके करीबी थे।
अरुण नेहरू ने कांग्रेस छोड़कर जनता दल में शामिल हो गए थे। 'पूछो'
आपके दोस्त (उनका इशारा जन मोर्चा के नेताओं की ओर था),' वीपी ने जवाब दिया।
उन्होंने रहस्यमय ढंग से कहा, 'अरुण नेहरू और वे सभी जाना चाहते थे।' फिर उन्होंने आगे कहा, 'अरुण नेहरू और वे सभी जाना चाहते थे।'
कांग्रेस में वापसी।
त्रिवेदी ने मुझे बताया, 'यह मंडलों के बनने से पहले का समय था।' अरुण नेहरू
और उनका समूह एम. एल. फोतेदार और कप्तान सतीश के बीच से गुजरा था।
शर्मा। 'जब राजीव को एहसास हुआ कि सरकार गिर सकती है, तो उन्होंने
प्रक्रिया को तेज कर दिया।
एच. आर. भारद्वाज ने यह भी खुलासा किया कि राजीव गांधी ने उनसे ऐसा करने को कहा था।
जून 1990 में लंदन से वापस भागते हुए उन्होंने कहा, 'वीपी सरकार'
जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि राजीव गांधी इस्तीफे के पीछे थे।
जुलाई 1990 में उपराष्ट्रपति सरकार से अरुण नेहरू और आरिफ खान को हटाने के संबंध में।
भारद्वाज ने मुझसे कहा कि इससे जनता दल के भीतर संकट उत्पन्न हो जाएगा।
'वीपी अरुण नेहरू (और उनके संभावित कार्यों) को लेकर सतर्क रहते थे,' के. एन.
गोविंदाचार्य ने टिप्पणी की, 'उन्हें राजीव की बातों की इतनी चिंता नहीं थी।'
गांधी जी ऐसा कर सकते थे।
■

जनता दल में चल रहे संघर्षों के अलावा, उपराष्ट्रपति को और भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
एक और तूफान जोर पकड़ रहा था—भाजपा अब तैयार हो रही थी।
जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ देने के लिए। वरिष्ठ सदस्यों की एक गुप्त बैठक।
भाजपा का मतदान दिल्ली में 1 जुलाई 1990 को हुआ था।
‘यह एक गुप्त बैठक थी जहाँ उन्होंने रथ जुलूस निकालने का फैसला किया।
'देश में यात्रा,' प्रेम शंकर झा ने मुझे बताया। झा मीडिया सलाहकार थे।
तत्कालीन प्रधानमंत्री को। ‘पीएमओ को यह जानकारी मिली थी—
हो सकता है कि रथ के अंत में वे (भाजपा) सरकार गिरा दें।
30 अक्टूबर 1990 को यात्रा के दौरान, जब कार सेवा की जानी थी
अयोध्या।’ पार्टी अपने मूल मुद्दों में से एक पर वापस लौटना चाहती थी।
देश में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना—राम मंदिर का निर्माण
Ayodhya.
जून 1990 में हरिद्वार में हुई अपनी बैठक में, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने पहले ही अपने आह्वान को बढ़ा दिया था।
उन्होंने तनाव का माहौल बनाया और 30 अक्टूबर से अयोध्या में कार सेवा आयोजित करने का आह्वान किया।
राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 2 नवंबर तक का समय दिया गया था।
जब उपराष्ट्रपति ने इस संबंध में कोई फैसला लिया, तो उपराष्ट्रपति ने इसकी पुष्टि की।
दिसंबर 1989 में सरकार ने सत्ता संभाली, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने इसे छह कार्यकाल दिए थे।
इस समस्या को हल करने के लिए महीनों का समय दिया गया था। इसकी समय सीमा जून 1990 में समाप्त हो गई थी।
जब मैंने पदभार संभाला था, तब मैंने सोचा था कि भाजपा को दो साल लगेंगे।
इससे पहले कि वह प्लग निकाल दे,’ वीपी ने मुझे बताया। अब सब कुछ तेजी से हो रहा था।
अग्रेषित।

अब वीपी को पता चल गया था कि उसे एक साथ तीन ताकतों से निपटना होगा।
जो उसे घेरना चाहते थे—महत्वाकांक्षी देवी लाल, जिन्हें समर्थन प्राप्त था
चंद्र शेखर; राजीव गांधी उन्हें सत्ता से हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।
अरुण नेहरू और उनके सहयोगियों के साथ सुलह की संभावना पर भी विचार करना;
और भाजपा द्वारा एक ऐसे मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया गया, जिसके होने की संभावना थी।
भावुक।
■

1 अगस्त 1990 को वी. पी. सिंह ने देवी लाल को उनके मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया। 'मैं था
उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहने के पक्ष में,' उपराष्ट्रपति ने कई साल बाद कहा। 'लेकिन
बिजु पटनायक और अरुण नेहरू ने मुझसे कहा... तुम्हें सख्त होना पड़ेगा। उसे बर्खास्त कर दो। वे जानते थे कि बर्खास्तगी से रिश्ता टूटना नामुमकिन हो जाएगा।' एक उत्तेजित
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उपराष्ट्रपति से भिड़ते हुए कहा, 'आप ऐसा कर सकते थे।'
उन्होंने आलोचना भरे स्वर में कहा, 'अगर उन्होंने इसे अलग तरीके से संभाला होता।'
उपराष्ट्रपति यादव से पूछा, 'देवी लाल आपके मंत्रिमंडल में थे, और उन्होंने ये बातें कही थीं।'
वह कह रहा था, 'तुम क्या करते?' यादव ने जवाब दिया
अनिच्छा से उसने कहा, 'मैं उसे गिरा देता।'
देवी लाल को सरकार से हटाए जाने से एक रात पहले, सोम
पाल वी. पी. सिंह के आवास पर उनके साथ थे। उन्होंने देर रात तक बातचीत की।
'आपको कल ही इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर मध्यावधि चुनाव की मांग करनी चाहिए,' सोम ने कहा।
पाल ने वीपी से कहा, 'मंडल के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है।' सोम पाल वीपी

को जानते थे।
सुरेंद्र मोहन रिपोर्ट को लागू करने पर विचार कर रहे थे।
उन्होंने उपराष्ट्रपति को मध्यावधि चुनाव कराने की सलाह दी। ‘आप एक नेता रहे हैं’ आम सहमति बन गई है, और वह छवि बनी रहेगी। और आप एक और लड़ाई लड़ने के लिए जीवित रहेंगे।
दिन।'
सोम पाल ने उपराष्ट्रपति को चेतावनी दी: 'अगर आप मंडल के पीछे पड़े तो दूसरों को ही निशाना बनाया जाएगा, किसी और को नहीं।'
'तुम्हें इससे लाभ होगा।' सोम ने मुझे उस बातचीत के बारे में बताते हुए कहा।
पाल ने कहा, 'वीपी को यह गलतफहमी थी कि मंडल हर चीज को बांट देगा।'
कांग्रेस सहित पार्टी, ठीक बीचोंबीच अन्य के साथ
पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और गैर-ओबीसी दोनों वर्गों के लिए यह मददगार होगा।
राजनीतिक रूप से।
इतिहास ने सोम पाल को सही साबित किया। लेकिन, जुलाई 1990 में, उपराष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया।
वे अपनी सरकार का पतन नहीं चाहते थे। न ही वे समय से पहले चुनाव चाहते थे।
■

विरोधाभासी रूप से, वी. पी. सिंह हमेशा से मंडल के पक्ष में नहीं थे। 'मैं (एक बार) दिनेश त्रिवेदी ने याद करते हुए बताया, 'मैंने उनसे आरक्षण पर उनके विचार पूछे थे।'
यहां तक कि 1987-88 में भी, वीपी का दृष्टिकोण अलग था। "भले ही आपके पास हो
“100 प्रतिशत आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,” उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया था।
“कैसे?”
क्या बहुत से लोगों को नौकरियां मिलेंगी? नौकरियां कहां हैं?” उन दिनों, वह ऐसा करता था।
वह आरक्षण के बारे में बात नहीं करेंगे। वह रोजगार बढ़ाने के बारे में बात करेंगे।
बाज़ार।'

जनता दल के 1989 के चुनाव घोषणापत्र में मंडल का नाम भी शामिल था।
इसके वादे। पार्टी के ओबीसी सांसद, विशेषकर उत्तर प्रदेश और
बिहार के सांसद, जिनमें जनता दल के सांसदों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसके पक्ष में थे।
मंडल। बस यह देखना था कि इसे कब लागू किया जाएगा।

सत्ताधारी जनता दल में चल रहा आंतरिक संघर्ष अब सबके सामने आ चुका था, और वीपी को यह बात पता थी।
कि अगर उसे अपनी सरकार को बचाना है, तो उसे पलटवार करना होगा।
कुछ बड़ा होने वाला था। देवी लाल के जाने के साथ ही मंडल के लिए मंच तैयार हो गया था।
मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन
रिपोर्ट में सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की वकालत की गई थी।
केंद्र सरकार की नौकरियों में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की भागीदारी।
उपराष्ट्रपति का कहना था, 'मंडल जनता दल की राजनीतिक अभिव्यक्ति थी।'
उन्होंने वर्षों बाद अपने इस निर्णय के बारे में कहा।

तृतीय

शरद यादव के बेडरूम में लगा सुरक्षित आरएएक्स फोन देर रात बजा।
वस्त्र एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने अपनी कलाई घड़ी देखी।
रात के 10 बज चुके थे—और तारीख थी 1 अगस्त 1990। वह
यादव को वह समय और तारीख बहुत बाद तक याद रही।
रिसीवर पर प्रधानमंत्री थे। वी. पी. सिंह आए।
the point quickly, ‘Sharad bhai, ab toh Devi Lalji ke saath kaam karna
मुश्किल हो गया है (भाई शरद, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है)
देवी लाल के साथ काम करो।’ घबराकर और खतरे को भांपते हुए यादव ने पलटवार किया।
तुरंत, ‘निकलना मत (उसे बाहर मत निकालो)। मैं जाकर उससे मिलूंगा’

मैं कल आकर देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। उसके बाद मैं आकर आपसे बात करूंगा।'
VP replied sagely, 'Hum tho, Sharad bhai, nikaal chuke hain (Brother
शरद, मैंने उसे पहले ही बर्खास्त कर दिया है।' आमतौर पर शांत रहने वाले शरद
यादव अचंभित रह गए। यादव को प्रबंधन में अपनी दक्षता पर गर्व हुआ करता था।
contradictions others could not handle. 'Yeh aapne kya kiya (What have
आपने कर लिया?' जबकि वीपी यह समझा रहे थे कि यह क्यों असहनीय हो गया था
देवी लाल के बोलने के बाद, यादव का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा।
उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि जनता दल में उनकी अपनी स्थिति खतरे में पड़ सकती है।
देवी लाल के बिना पार्टी कमजोर पड़ गई थी। पार्टी के भीतर का संघर्ष जारी था।
अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, सत्यपाल मलिक के बीच बढ़ी नोकझोंक
और अन्य लोग जो वी.पी. सिंह के साथ कांग्रेस और देवी से आए थे
लाल और अन्य लोग जो लोहिया विचारधारा के समाजवादी और समर्थक थे, उनका प्रतिनिधित्व करते थे।
जनता दल के किसान सांसदों में यादव दूसरे समूह से थे।
यह संघर्ष केवल भिन्न विचारधाराओं के बीच ही नहीं था और
दो अलग-अलग व्यक्तित्वों के बीच सत्ता के लिए होड़ मची हुई थी। यह दो अलग-अलग व्यक्तित्वों के बीच भी था।
कार्यशैली। पूर्व के कांग्रेसी सदस्य काम करने के आदी थे।
एक ही नेता के अधीन रहकर और आदेश जारी होने के बाद नियमों का पालन करते हुए समस्याओं का समाधान करना।
एक संघर्ष। समाजवादी अपने संचालन के तरीके में अधिक अराजकतावादी थे।
हर कोई खुद को नेता समझता था। उनके अहम के टकराव ने 1979 में केंद्र में बनी पहली गैर-कांग्रेसी सरकार को आधे रास्ते में ही गिरा दिया था।
अपने कार्यकाल के दौरान। इससे पहले, उनके व्यक्तिगत एजेंडे ने भारी तबाही मचाई थी।

1967 में सत्ता में आई गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ
उत्तर भारतीय राज्यों में।
उस रात, फोन पर, वीपी ने शरद यादव को एक प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव था...
couched in courteous words, 'Jo Devi Lalji ki sthiti thee woh ab aapki
रहेगी (अब आपको वही दर्जा प्राप्त होगा जो देवी लाल को प्राप्त था)।
शरद यादव इतने समझदार थे कि उन्हें यह एहसास हो गया था कि प्रधानमंत्री ने उनकी चाल भांप ली है।
आशंकाएं। सरकार बनने के बाद से, वीपी ने यादव को अपना समर्थन नहीं दिया था।
हालांकि यादव खुद को वरिष्ठ नेताओं में से एक मानते थे।
जनता दल के उपाध्यक्ष ने उन्हें शक्तिशाली राजनीतिक मामलों से दूर रखा था।
समिति। न ही उन्हें कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा गया था; इसके बजाय, उन्हें
उन्हें कम महत्वपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया।
लेकिन उदास शरद यादव ने चुप्पी साध रखी थी—सही समय का इंतजार कर रहे थे।
वह क्षण आने का इंतजार कर रहा है जब वह पलटवार कर सके।
उस रात, उन्होंने प्रधानमंत्री से यह नहीं पूछा कि उनके कहने का क्या मतलब था।
'Devi Lalji ki sthiti (standing)'. He would find out soon enough though,
इसके बाद के हफ्तों में—वीपी को यादव की स्थिति को मजबूत करना था।
सरकार से अनुरोध है कि उन्हें राजनीतिक मामलों की समिति का हिस्सा बनाया जाए।
स्पष्टतः, प्रधानमंत्री स्वयं के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में थे। वे चाहते थे
शरद यादव का समर्थन। अचानक, उपराष्ट्रपति ने बातचीत समाप्त कर दी। 'यह है...'
शरद भाई, काफी देर हो गई है, मैं आपको सुबह फोन करूंगा।
जब वह प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, शरद ऋतु में एक योजना आकार ले रही थी।
यादव के मन में यही विचार था। यह एक ऐसा अवसर था जिसे वह हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। उन्होंने इसे अपने हाथ में ले लिया।
फोन नीचे रखा हुआ था, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसका हाथ पास रखी घंटी की ओर बढ़ा।
एक तरफ झुककर उसने अपने लिए एक नया पान लाने को कहा। लेटे हुए

अपने बैठक कक्ष में सोफे पर रखे लंबे, गोल कुशनों के सहारे, वह
योजना को अमल में लाना शुरू किया गया। यह मंडल के इर्द-गिर्द घूमती थी।
आयोग की रिपोर्ट; जनता दल के घोषणापत्र में वादा किया गया था कि
इसे लागू किया जाएगा। समय-समय पर मांगें उठती रहेंगी।
इसके कार्यान्वयन के लिए पार्टी की बैठकें हुईं। जैसे-जैसे कार्यवाही का समय बीतता गया,
उस रात, शरद यादव ने फैसला किया कि अगर प्रधानमंत्री मंडल व्यवस्था लागू करते हैं तो
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वह उसके साथ रहेगा। तब वह ऐसा कर पाएगा।
ओबीसी के नेता के रूप में उभरें और उनके अधिकारों की पैरवी करें। यदि नहीं, तो वह देवी लाल के साथ ही रहेगा। यह निर्णय लेने के बाद, उसने शुरुआत की।
उन्होंने कई प्रमुख ओबीसी नेताओं को फोन किया, जिनमें से कई उनके करीबी थे—नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव—और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या किया था।
फैसला किया।
अगली सुबह, RAX का फोन जल्दी बज उठा। फिर से प्रधानमंत्री का फोन था।
‘क्या आप सात बजे नाश्ते पर आ सकते हैं?’ शरद यादव मान गए।
तुरंत। अब तक, वह जान चुका था कि उसे क्या करना है। जैसे ही वह बैठा
शरद यादव ने रेस कोर्स रोड पर प्रधानमंत्री के साथ नाश्ते के दौरान कोई कसर नहीं छोड़ी।
उपराष्ट्रपति को यह समझाने में समय व्यतीत किया जा रहा है कि उन्हें 'मंडल' के लिए क्यों जाना चाहिए।
तुरंत। उनकी मुलाकात 'दो घंटे' तक चली।
पिछली रात मैंने मंडल शब्द का जिक्र नहीं किया था, यह सोचकर कि
यादव ने बाद में बताया, 'हो सकता है प्रधानमंत्री को यह विचार पसंद न आए।' इसके तुरंत बाद
जब नेशनल फ्रंट की सरकार सत्ता में आई, तो प्रधानमंत्री ने
मामले की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में देवी लाल को नियुक्त किया गया।

मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन। 'यह था
मेरे लिए यह संकेत काफी था कि प्रधानमंत्री मंडल को लाने में कोई जल्दी नहीं कर रहे थे।
शरद यादव ने खुलासा किया, ‘मुझे पता था कि देवी लाल इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जाट
उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया था। और मैं देवी लाल से अक्सर झगड़े करता था।
(मंडल का कार्यान्वयन)
मंडल के बारे में देवी लाल के विचार किसी से छिपे नहीं थे। राष्ट्रीय स्तर पर इसके तुरंत बाद
जब फ्रंट सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने एक बयान दिया था, मध्य में-
दिसंबर 1989 में, यह तय किया गया कि आरक्षण 'आर्थिक' आधार पर होना चाहिए।
और ‘शैक्षिक’ मानदंडों का उपयोग करें, न कि सामाजिक (दूसरे शब्दों में, जाति) मानदंडों का।
मापदंड।
उन्होंने आरक्षण बढ़ाने के संदर्भ में ये टिप्पणियां की थीं।
अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को जो
नवीनीकरण के लिए आ रहा है। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में आक्रोश फैल गया।
इससे पार्टी के मंडल सदस्यों में भी आक्रोश पैदा हो गया। उन्होंने देवी लाल पर आरोप लगाया कि
संविधान के विपरीत रुख अपनाना। अनुच्छेद 15(4) के लिए
आरक्षण का प्रावधान केवल ‘सामाजिक और शैक्षिक’ आधार पर किया गया है।
और आर्थिक पिछड़ापन नहीं। देवी लाल की टिप्पणियों से नाराज होकर,
उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख कुर्मी नेता राम पूजन पटेल, जो बाद में शामिल हो गए
उपराष्ट्रपति के मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर देवी लाल पर आरोप लगाया।
संविधान, मंडल आयोग और के विरुद्ध होने के कारण
जनता दल का घोषणापत्र। देवी लाल से कुछ भी करने की उम्मीद करना मुश्किल है।

उन्होंने क्रोधित होकर लिखा, 'पिछड़े वर्गों के लिए, जब वह खुलेआम बात कर रहा है।'
दलितों के लिए आर्थिक मानदंडों के बारे में।' फिर भी, प्रधानमंत्री—
जो सभी विकल्प खुले रखना चाहते थे—उन्होंने देवी लाल को पद पर बनाए रखा।
समिति के अध्यक्ष।
लेकिन अब जब देवी लाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था, शरद
यादव ने मंडल को लागू करने के लिए वीपी पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया।
आयोग की रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करें।
सुबह 9:30 बजे, उपराष्ट्रपति नाश्ते की मेज से उठे। प्रधानमंत्री भी वहीं थे।
जाते हुए यादव ने अपनी आखिरी बात कही। 'आपको इसकी घोषणा करनी चाहिए'
मंडल आयोग की रिपोर्ट को 9 अगस्त से पहले लागू करने का निर्णय।
उस दिन देवी लाल ने नाव पर एक विशाल रैली आयोजित करने की योजना बनाई थी।
क्लब। यादव को डर था—और प्रधानमंत्री को यह बात पता थी—कि देवी लाल
सार्वजनिक बैठक में मंडल रिपोर्ट के कार्यान्वयन की मांग करें
इससे उपराष्ट्रपति के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इससे वह ओबीसी के लिए एक मोहरा बन सकते हैं।
जनता दल के सांसदों को प्रभावित करते हुए, वे पूरे देश में पिछड़े वर्गों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं।
उत्तर भारत। इससे जनता दल दो हिस्सों में बंट जाएगी।
और इससे उपराष्ट्रपति सरकार के पतन की घोषणा हो जाएगी।
वीपी ने यादव की बात सुनी। लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। क्योंकि उन्होंने पहले ही योजना बना ली थी।
मंडल रिपोर्ट को लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने एक बैठक बुलाई थी।
उसी दिन नेशनल फ्रंट संसदीय पार्टी की बैठक थी;
संसद के केंद्रीय हॉल में आयोजित किया जाएगा। इसका स्पष्ट कारण यह है कि
देवी लाल की बर्खास्तगी पर चर्चा होनी थी। लेकिन उन्हें पता था कि मंडल का मुद्दा जरूर उठेगा।
जैसा कि अधिकांश पार्टी बैठकों में होता था, चर्चा के लिए। उन्होंने पहले ही सतर्क

कर दिया था।
कुछ सांसद। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि यह मुद्दा उठाया जाए। एक बार जब यह मुद्दा उठ खड़ा हो।
अगर यह मुद्दा उठता, तो यह अपने आप गति पकड़ लेता।
इंदिरा गांधी की तरह, उपराष्ट्रपति भी अपनी शतरंज की बिसात बिछाने में विश्वास रखते थे।
फिर वह अपने प्रतिद्वंदी के पहले कदम उठाने का इंतजार करता—इससे पहले कि...
उसने जवाबी चाल चली और फिर लगातार हमला करके विरोधी को मात दे दी।
विरोधी। अब, वह मंडल के लिए सावधानीपूर्वक मंच तैयार कर रहा था।
■

जुलाई 1990 तक जब उनके खिलाफ ताकतें एकजुट होने लगीं, तो वीपी को पता चल गया था कि वह
उन्हें तुरंत पलटवार करना होगा। उनके सामने मौजूद विरोधाभासों को देखते हुए।
गठबंधन के मामले में, अगर अचानक चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उन्हें तैयार रहना होगा।
वह। वह अपने कारण मध्यम वर्ग का चहेता था।
भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और स्वच्छ सरकार का उनका वादा। लेकिन
जनता पार्टी में चल रही खुली खींचतान से वे निराश होते जा रहे थे।
दाल। उन्होंने वर्षों पहले इंदिरा गांधी से सीखा था कि यह महत्वपूर्ण है।
मध्य वर्ग का नहीं, बल्कि गरीब वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, ताकि
चुनाव जीतना। उपराष्ट्रपति कहते थे, 'दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, स्थिरता गरीबों से ही मिलती है।' अब उन्हें एक
जन आधार, न कि केवल मध्यम वर्ग और गरीबों के बीच अनुयायी
बुद्धिजीवी वर्ग, अगर उन्हें कांग्रेस और भाजपा दोनों का सामना करना पड़े तो
अगला दौर।
जैसा कि उम्मीद थी—और पहले से तय था—सांसदों ने मंडल की मांग उठाई।
2 अगस्त 1990 को नेशनल फ्रंट संसदीय दल की बैठक में।

वीपी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने उन्हें बताया कि वह पहले ही चौदह लगा चुका है।
केंद्रीय मंत्रालयों के संयुक्त सचिव अपने कार्य में लगे हुए थे। वे पहचान करेंगे
मंडल द्वारा वर्गीकृत पिछड़े वर्ग की सूचियों और उन सूचियों में विसंगतियां
राज्यों के साथ। उस समय, पच्चीस में से बारह राज्यों में पहले से ही था।
ओबीसी के लिए कोटा। उपराष्ट्रपति ने विस्तार से बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
इस अभ्यास को अंजाम दिया गया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक मल्लाह था।
एक पिछड़ी जाति, लेकिन दिल्ली में मल्लाह एक अनुसूचित जाति था। एक बनिया
(व्यापारी) बिहार में पिछड़ा हुआ था, लेकिन उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं था।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में कुर्मी समुदाय को 'पिछड़ा' माना जाता था।
महाराष्ट्र में भी ऐसा ही था, जहाँ कुर्मी समुदाय को कुनबी के नाम से जाना जाता था।
लेकिन यह
गुजरात में ऐसा नहीं था। वहां सामाजिक और शैक्षिक कारक थे, न कि
उन्होंने कहा कि पिछड़ेपन का निर्धारण केवल जाति से होता है। उन्होंने बताया, 'यह विचार...'
एकत्रित समूह का उद्देश्य 'इन विसंगतियों को दूर करना' है।
लेकिन सांसद आंकड़ों या स्पष्टीकरणों को सुनने के मूड में नहीं थे। 'हमें चाहिए
घोषणा में देरी न करें। विसंगतियों को दूर किया जा सकता है।
बाद में,' कई लोगों ने कहा। बैठक में लगभग दो दर्जन सांसदों ने भाषण दिया। अधिकांश
मंडल रिपोर्ट को तुरंत लागू करने की मांग की गई।
शरद यादव के विचारों के मद्देनजर, कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि अगर मंडल नहीं बनाया गया तो
यदि इसे तुरंत लागू किया गया, तो देवी लाल 9 अगस्त को अपने मत से इस मुद्दे को अपने पक्ष में कर लेंगे।
रैली करके सरकार को घेर लिया। सांसदों को चिंता थी कि एक
देवी लाल के साथ टकराव से समय से पहले चुनाव हो सकते हैं।

उन्होंने यह भी तुरंत बताया कि मंडल रिपोर्ट
एक साधारण राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाएगा। 'कोई कानून नहीं है'
राज्यसभा सदस्य सत्य प्रकाश ने बताया, 'ऐसा करना आवश्यक है।'
Malaviya.
फिर, ओबीसी सांसद हुकुम नारायण यादव आए, जो कि
चंद्र शेखर के खेमे में बैठे लोग उठ खड़े हुए। प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करते हुए।
मंत्री जी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने उपराष्ट्रपति से कहा, 'जब तक सवर्ण (उच्च जाति) प्रधान मंत्री हैं, तब तक...'
मंत्री जी, मंडल रिपोर्ट कभी लागू नहीं होगी।'
नाराज उपाध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'ठीक है, आइए अभी तारीख तय कर लेते हैं।'
हमें इसे कब लाना चाहिए?
हमें इसकी घोषणा संसद सत्र के पहले दिन करनी चाहिए।
कुछ सुझाव दिए गए। संसद का सत्र 7 अगस्त 1990 को शुरू होना था। उपराष्ट्रपति सहमत हो गए।
तुरन्त।
वीपी ने दस साल से भुला दी गई मंडल रिपोर्ट को पहले ही निकाल लिया था।
भारत सरकार की एक धूल भरी अलमारी में—और उसने मन बना लिया कि
इसे अपना लें। उन्हें बस सांसदों का समर्थन चाहिए था। उन्हें मिल गया।
2 अगस्त 1990 को उनसे औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई।

चतुर्थ

दस साल पहले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने यह अनुरोध किया था।
ज्ञानी ज़ैल सिंह से तुरंत मुलाकात करें। तत्कालीन गृह मंत्री ज़ैल सिंह थे।
मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसने अनुमान लगाया कि मंडल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता था।
ओबीसी के लिए आरक्षण पर। ज़ैल सिंह के लिए, यह एक और रिपोर्ट थी।
जिस पर धूल जमती रहती। लेकिन उन्होंने अपने सचिव को यह सुनिश्चित करने के

लिए कहा कि
‘पिछड़ेपन के मुद्दे’ से संबंधित ‘अधिकारी’ बैठक में उपस्थित थे।
बी. जी. देशमुख वह अधिकारी थे जिन्होंने इससे संबंधित सभी मामलों की देखरेख की थी।
मंडल आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1979 को हुई थी।
जब बी. पी. मंडल नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे, जहां होम स्थित था।
मंत्रालय में बहुत कम लोग मौजूद थे। चूंकि यह आखिरी दिन था।
1980 में, नॉर्थ ब्लॉक का अधिकांश हिस्सा सुनसान था, और वहां की सामान्य चहल-पहल गायब थी।
सरकारी कार्यालय अनुपस्थित थे।
मंडल के साथ उनके कुछ सहकर्मी भी थे, जिनमें शामिल हैं:
आयोग के सदस्य सचिव, एस. एस. गिल। वह एक बर्फीली सर्दी का मौसम था।
दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल का दिन। प्रतिनिधिमंडल को गृह मंत्री के कार्यालय में ले जाया गया।
विशाल कार्यालय। ज़ैल सिंह उठे और उन्होंने सभी से हाथ मिलाया।
उन्होंने बी. पी. मंडल को अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया।
मंडल ने औपचारिक शिष्टाचार में समय बर्बाद नहीं किया। बिना किसी
प्रस्तावना के बाद, उन्होंने रिपोर्ट ज़ैल सिंह को सौंप दी। गृह मंत्री
उन्होंने न तो रिपोर्ट देखी और न ही उसके बारे में कोई सवाल पूछा। जल्द ही,
नॉर्थ ब्लॉक में स्मार्ट कपड़े पहने वेटर चाय और बिस्कुट लेकर आए।
मेहमानों को चाय परोसी गई। चाय सफेद बोन चाइना के कपों में परोसी गई थी, जिन्हें एक
स्टार्चयुक्त सफेद ट्रे का कपड़ा, ब्रिटिश काल की एक औपचारिक निशानी।
चाय खत्म हो गई थी, और यह आभास हो रहा था कि मंत्री से मुलाकात का समय नजदीक आ रहा है।
अंत में, मंडल उठा और उसने ज़ैल सिंह से दोबारा हाथ मिलाया।
समूह के अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। वे सभी घर से बाहर निकल गए।
मंत्री के कार्यालय में लगभग दो वर्षों के निराशाजनक अंत के बाद
वर्षों का काम।

जैसे ही वे नॉर्थ ब्लॉक की चौड़ी लाल बलुआ पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे, बी.पी. मंडल ने गिल की ओर मुड़कर संदेह भरे स्वर में कहा, 'साहब,
aap ne report par bahut mehnat ki hai. Par aaj hum iskaa visarjan kar
आए हैं (आपने रिपोर्ट पर बहुत मेहनत की है लेकिन आज हमारे पास)
इसका अंतिम विसर्जन समारोह संपन्न हुआ)। जब उसने इसे सौंप दिया था
गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपते हुए बी.पी. मंडल को पूरा भरोसा था कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
उसकी सिफारिशों पर अमल किया। वह सही साबित हुआ; दस साल तक
इसे लागू करने की कोई पहल नहीं हुई। मंडल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा।
वह घर-घर में जाना-पहचाना नाम बन जाएगा—और एनिमेटेड फिल्मों का विषय भी।
पूरे भारत में चर्चा का विषय। और उनकी रिपोर्ट, सबसे विवादास्पद रिपोर्टों में से एक।
स्वतंत्र भारत के दस्तावेज़ दशकों तक भारतीय राजनीति को परेशान करते रहेंगे।
उसके बाद।
■

इंदिरा गांधी की रिपोर्ट आते ही बी.पी. मंडल ने रिपोर्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पूरी रफ्तार पकड़ ली थी।
गांधी जनवरी 1980 में सत्ता में वापस आए। 'सरकार ने
उन्होंने अपने सहयोगियों को चेतावनी देते हुए कहा, 'बदल गया है। इस सरकार में बदलाव नहीं होगा।' 'इस सरकार में वह बदलाव नहीं होगा जो...'
ओबीसी के लिए आरक्षण के विचार के प्रति वही प्रतिबद्धता। तब तक,
उन्होंने इस पर अपना समय लिया था। जब मोरारजी देसाई ने
जब मंडल को रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था, तब उन्हें कोई जल्दी नहीं थी।
इसे पूरा करो। चौधरी चरण सिंह के आने पर वह शांत रहा।
मोरारजी देसाई के बाद पांच महीने के लिए प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। यह केवल

1980 में ही हुआ था।
उन्होंने जल्दी से रिपोर्ट पूरी की और बिना समय गंवाए उसे जमा कर दिया।
सरकार।
यह रिपोर्ट मूल रूप से सदस्य सचिव एस.एस. गिल द्वारा लिखी गई थी।
गिल ने कहा, 'रिपोर्ट का हर एक शब्द मैंने लिखा है। बी. पी. मंडल'
वह एक अच्छे इंसान थे...(लेकिन) उनकी मुख्य रुचि मास्टर ऑफ सर्विस (MoS) प्राप्त करने में थी।
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद। बी.पी.
मंडल को केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था।
सरकार।
गिल, जो एक शहरी पंजाबी था और जिसे जाति व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी थी, के लिए
भारत में, सामाजिक संरचना के बारे में सीखना एक 'शिक्षा' के समान था।
देश का हृदयस्थल। 'तभी समाजशास्त्र में मेरी रुचि शुरू हुई और
मैंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। मंडल रिपोर्ट शायद एकमात्र ऐसी रिपोर्ट है।
सरकारी रिपोर्ट जो उपराष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा के बाद बेस्टसेलर बन गई
गोद लेना। गिल ने कहा कि इसमें इतनी अधिक रुचि थी कि एक अन्यथा नीरस दस्तावेज़ का पुनर्मुद्रण करवाना पड़ा। फिर भी, इसके अनुसार
अज्ञात सह-लेखक, 'जिन्होंने इसे लागू किया था उन्होंने इसे पढ़ा नहीं था'
रिपोर्ट। गिल ने कहा, 'लेकिन अगर आप जाति को नहीं समझते हैं तो आप वास्तव में इसके परिणामों को समझें।
मंडल रिपोर्ट ने जाति को निर्धारण के मापदंड के रूप में इस्तेमाल किया।
पिछड़ापन, हालांकि यह एकमात्र मानदंड नहीं था जिसका इसने उपयोग किया। इसने अन्य मानदंडों का भी उपयोग किया।
शिक्षा की कमी और आर्थिक अभाव को मापदंड के रूप में लिया गया है। लेकिन,
अंततः, यह 'सामाजिक पिछड़ेपन' पर अधिक निर्भर था (दूसरे शब्दों में
जाति के आधार पर भेदभाव) का उपयोग पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
गिल एक बार में एक अध्याय लिखते और उसका मसौदा सदस्यों को भेजते थे।

आयोग ने अपनी टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं। सदस्य मुख्य रूप से
यह सुनिश्चित करने में रुचि रखते थे कि अधिकतम संभव आरक्षण दिया जाए
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति को पहले से ही नौकरियों में 22.5 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है।
और संविधान द्वारा निर्धारित विधानमंडलों में—यह इसी प्रकार था
उनकी जनसंख्या के अनुपात में अभाव के स्तर के कारण।
गिल ने आयोग के सदस्यों से कहा कि वे यह उम्मीद नहीं कर सकते।
ओबीसी के लिए '27 प्रतिशत से अधिक आरक्षण'। उन्होंने यह आंकड़ा निकाला।
देश में कुल ओबीसी आबादी के प्रतिशत को आधा करके,
जो 1931 की जनगणना के आधार पर 52 प्रतिशत होने का अनुमान था।
इसका मतलब 26 प्रतिशत था।' लेकिन आयोग के सदस्य लगातार मांग करते रहे।
'अधिकतम संभव आरक्षण'। गिल ने कहा, 'यह आंकड़ा अंततः तय किया गया था।'
इसे 27 प्रतिशत पर तय किया गया था। इसका उद्देश्य इसे एक तर्कसंगत आधार देना था।
गिल 1963 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बंधे हुए थे—और
रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने एम. आर. बालाजी मामले में फैसला सुनाया था।
मैसूर राज्य बनाम मामले में यह तय किया गया था कि आरक्षण को 'प्रति वर्ग 50' तक सीमित किया जाना चाहिए।
प्रतिशत'। चूंकि अनुसूचित जातियों को 15 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।
और अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा के लिहाज से 7 प्रतिशत, ओबीसी कोटा आवंटित किया गया।
इसे 27 प्रतिशत पर निर्धारित करना पड़ा।
■

आइए अब भारत में आरक्षण की कहानी पर एक संक्षिप्त नज़र डालें—इसे समझने के लिए
वी. पी. सिंह उस विचार के मसीहा क्यों बन गए जो पहले से ही प्रचलित था?

स्वतंत्रता के बाद से—और जिसके परिणामस्वरूप मंडल आयोग की रिपोर्ट आई (जो समय के साथ यह संक्षिप्त होकर 'मंडल' बन गया, जो देश का हिस्सा बन गया। राजनीतिक शब्दावली)।
भारत को आजादी मिलने के बाद, संविधान ने प्रतिबंध लगा दिया।
अस्पृश्यता और जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव
जाति या जन्म स्थान (अनुच्छेद 15) के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। इसमें समूह अधिकारों का भी प्रावधान किया गया।
सकारात्मक कार्रवाई का तरीका (अनुच्छेद 15(4)), जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि विशेष
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए प्रावधान (आरक्षण) किए जा सकते हैं।
पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के नागरिकों के लिए। या अनुसूचित जातियों के लिए।
अनुसूचित जनजाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी)। (आधिकारिक तौर पर नामित एससी और
अनुसूचित जनजातियाँ दलित और स्वदेशी आदिवासी हैं, और सबसे अधिक आबादी वाले समुदायों में से हैं।
भारत में वंचित समूह।) इसके अतिरिक्त, संविधान सभा
आयोग की स्थापना के लिए विशेष रूप से प्रावधान करने हेतु अनुच्छेद 340 जोड़ा गया।
पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार लाने के लिए।
संदर्भ प्रदान करने के लिए, भले ही इससे एक जटिल विषय को सरलीकृत करने का जोखिम हो,
इस विषय में, हिंदुओं में निहित जाति व्यवस्था को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
सदियों से अस्तित्व में आई और संरचित हुई पदानुक्रमिक व्यवस्था
हिंदू समाज को चार समूहों या वर्णों में विभाजित किया गया है—ब्राह्मण जो
पुरोहित, बुद्धिजीवी और अधिकारी; क्षत्रिय, योद्धा और शासक;
वैश्य जो व्यापारी थे; और शूद्र जो बड़ी संख्या में शामिल थे
निम्न जातियों के अधिकांश लोग श्रमिक और सेवा प्रदाता थे। पाँचवाँ हिस्सा

लोगों के एक समूह को जाति व्यवस्था से बाहर रखा गया था; उन्हें माना जाता था
सदियों से तिरस्कृत और निम्न स्तर के काम करने के लिए विवश 'अछूत'
तथाकथित उच्च जातियों द्वारा। स्वतंत्रता के बाद, अस्पृश्यता समाप्त हो गई।
प्रतिबंधित कर दिया गया और इस समूह से संबंधित लोगों को इस नाम से जाना जाने लगा।
दलित।
आधुनिक युग में, सामाजिक सुधार, शिक्षा, शहरीकरण, वृद्धि
समृद्धि, प्रवासन और अंतरजातीय विवाह, विशेषकर शहरी भारत में।
जाति व्यवस्था की अटूट पकड़ को झटका लगा। लेकिन, एक अन्य स्तर पर,
लोकतंत्र की शुरुआत के साथ ही, राजनीतिक दलों ने जाति को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया।
विभिन्न समूहों को उनके समर्थन में संगठित करने से, उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई।
अडिग। पहले के वर्षों में, निचली जातियाँ अपनी जाति को छिपाती थीं।
उच्च जाति के परिवारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपनामों को अपनाना। अब यह
निम्न जाति की पहचान का प्रदर्शन करना—या यहाँ तक कि
निम्न जातियों से संबंध होने का दिखावा करना—आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए
हाशिए पर रहने वाले इन लोगों के लिए आरक्षण की नीति से मिलने वाले लाभ
समुदायों। स्वीकृति के बाद इस प्रवृत्ति को गति मिलने लगी।
मंडल। मंडल ने समाज को विभाजित तो किया, लेकिन साथ ही साथ समानता का सूत्र भी बन गया।
■

आजादी के बाद, सत्ताधारी कांग्रेस ने अपने समर्थकों के समर्थन पर भरोसा किया।
उच्च जातियाँ, जो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख रही थीं। हालाँकि
संख्या में कम होने के बावजूद, वे सत्ता में आने में सक्षम हुए क्योंकि अन्य
समूह खंडित थे। वास्तव में, भारतीय गणराज्य के प्रारंभिक वर्षों में,
अधिकांश राज्य सरकारों का नेतृत्व ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों द्वारा किया जाता था।

यह स्थिति 1960 के दशक के मध्य में किसान वर्ग के उदय के साथ बदलने लगी।
और मध्यम जातियाँ। 1951 में जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, भूमि
दो दशकों (1950-72) की अवधि में हुए सुधारों और ग्रीन पार्टी के लिए किए गए सुधारों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई।
1960 के दशक में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए हुई क्रांति ने स्थिति में सुधार किया था।
कुछ प्रमुख पिछड़े वर्गों की वित्तीय स्थिति, जैसे कि
यादव, कुर्मी और कोइरी। जैसे-जैसे वे समृद्ध होते गए, वे एक
सत्ता संरचना में अधिक हिस्सेदारी। 1967 के राज्य चुनावों में,
उत्तर भारत के नौ राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जिन सरकारों ने
जिन मुख्यमंत्रियों ने कार्यभार संभाला, उनका नेतृत्व गैर-ब्राह्मण प्रधानमंत्रियों ने किया —यह एक संकेत था
सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हो रहा था। ये सरकारें थीं
अन्य पिछड़ा वर्ग और मध्यवर्ती जातियों (जैसे जाट) द्वारा समर्थित।
जिसने भारतीय लोक दल जैसी गैर-कांग्रेसी पार्टियों का समर्थन किया।
किसान नेता चरण सिंह।
हालांकि जाति हमेशा से मतदाताओं के चुनाव में एक कारक रही है, लेकिन इस पर कभी बात नहीं की गई।
स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में इतनी खुले तौर पर। भारत के पहले प्रधान मंत्री
मंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो स्वयं एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, ने इसका विरोध किया।
राजनीति में धर्म और जाति का इस्तेमाल करने के बारे में। 'मुझे नहीं लगता कि नेहरू वास्तव में
एस.एस. गिल ने कहा, 'जाति को समझा।'
एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत साकार होने के साथ ही निचली जातियों के बीच भेदभाव शुरू हो गया।
अपनी संख्या के महत्व को समझने और इसमें अधिक भागीदारी की मांग करने के लिए।
निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ।

1950 के दशक की शुरुआत में, पिछड़े वर्ग के नेताओं ने प्रधानमंत्री से संपर्क किया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मंत्री नेहरू ने पहला कदम उठाया। उन्होंने प्रथम सरकारी मंत्रालय की स्थापना की।

पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को इस मामले की जांच के लिए किया गया था।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति

(एसईबीसी)। इसका नेतृत्व दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर ने किया था, जो एक स्वतंत्रतावादी थे।

योद्धा और समाज सुधारक, जो काका साहब कालेलकर के नाम से लोकप्रिय हैं।

उन्होंने 1955 की शुरुआत में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

2,399 जातियों को पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जो सहायता के पात्र हैं, और यह सिफारिश की गई कि

मध्य क्षेत्र में उनके लिए 25-40 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की जानी चाहिए।

शासकीय सेवाएं।

जब कालेलकर रिपोर्ट सामने आई, तो पुंजला शिव शंकर और दो अन्य लोगों ने

आंध्र प्रदेश के अन्य ओबीसी नेता नेहरू से मिलने गए। नेहरू

उन्हें आम तौर पर पंडितजी कहा जाता था—यह उपाधि उनकी जाति को दर्शाती थी —भले ही वे

वह जातिवाद को तुच्छ समझते थे। उन्होंने तीन मूर्ति हाउस में उनसे मुलाकात की और अपनी बात मनवाने की कोशिश की।

रिपोर्ट का कार्यान्वयन। 'हमें ऐसा लगा कि वह चाहता था

उन्होंने (कालेलकर रिपोर्ट को) लागू करने की बात कही, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा।

चार वर्षों से अधिक समय तक आरक्षण के प्रबल समर्थक रहे शिव शंकर ने याद किया।

दशकों तक। नेहरू ने उनकी बात सुनी। अंत में, उन्होंने उनसे कहा, 'आप घर'

'आप जाकर गृह मंत्री से मिल लीजिए।'

गोविंद बल्लभ पंत गृह मंत्री थे। 'हम पंतजी से मिलने गए थे।'

उनके कार्यालय में। हम तीन लोग थे—मैं, बुज्जन नरसिमलू, जो एक

हैदराबाद से कांग्रेस पार्षद और विधायक गौथु लचन्ना
जो 1953 में आंध्र प्रदेश में मंत्री थे... (लेकिन) हम आए
इस भावना को दूर भगाएं कि पंतजी को कुछ आपत्तियां थीं और वे रिपोर्ट चाहते थे
इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा... लेकिन, फिर से (नेहरू की तरह), उन्होंने सीधे
तौर पर ऐसा नहीं कहा।
पंत का मानना था कि कालेलकर रिपोर्ट के कार्यान्वयन से विभाजन पैदा होगा।
भारतीय समाज। जैसा कि बाद में पता चला, रिपोर्ट न तो पेश की गई और न ही
संसद में इस पर चर्चा भी नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट के लेखक ने,
कालेलकर दलितों के प्रति सहानुभूति रखते थे, उन्होंने विरोध किया था
पिछड़ेपन को निर्धारित करने के मानदंड के रूप में जाति का उपयोग। चूंकि ऐसा कोई
मानदंड नहीं था
रिपोर्ट पर सर्वसम्मति न होने के कारण, सरकार को इसे नजरअंदाज करना आसान
लगा।
हालाँकि, 1961 में, इसने निर्णय लिया कि वह इसे राज्य सरकारों पर छोड़ देगा।
यह तय किया गया कि आरक्षण के लिए कौन पात्र होगा। लेकिन इसने आरक्षण को
खारिज कर दिया।
केंद्र सरकार में ओबीसी के लिए।
राज्य सरकारों ने अपने-अपने आयोग गठित किए। इन वर्षों में
इसके बाद, ऐसे पंद्रह आयोगों का गठन किया गया। दक्षिणी राज्यों
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक ने इस मामले में अग्रणी भूमिका निभाई।
राज्यों ने अपने-अपने कोटे तय किए। कर्नाटक ने 50 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया।
आरक्षण के मामले में पंजाब ने 5 प्रतिशत का विकल्प चुना।
जब 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ, तो उसने लागू करने का वादा किया था।
अपने घोषणापत्र में कालेलकर आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया। लेकिन एक बार
पार्टी ने
जब सत्ता में आई, तो जैसा कि अक्सर होता है, उसने कोई कार्रवाई नहीं की।
हालाँकि,
बिहार के जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई।
समाजवादी कर्पूरी ठाकुर ने मार्च 1978 में राजनीति में उतरने का फैसला किया।

ओबीसी के लिए आरक्षण। उन्होंने इसे लागू करने का निर्णय लिया।
बिहार में आरक्षण के लिए मुंगेरी लाल आयोग की सिफ़ारिशें
ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत सरकारी नौकरियां आरक्षित। 1959 में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले 60 प्रतिशत आरक्षण का विचार रखा था।
ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा हुई।
सोशलिस्ट पार्टी। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने नारा दिया, 'सासोपा ने
bandhi gaanth, pichde paanve sau maen saath (The SSP has made a
यह संकल्प लिया जाए कि पिछड़े वर्गों को 100 में से 60 का प्रतिनिधित्व मिलेगा।
जिसका प्रभाव हिंदी भाषी क्षेत्रों में वर्षों तक गूंजता रहा।
कर्पूरी ठाकुर को उम्मीद थी कि उनके आरक्षण के कदम से मदद मिलेगी
उन्हें जनता पार्टी की अस्थिर सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी।
इसके बजाय, उनकी समस्याएं और बढ़ गईं। इस फैसले ने व्यापक विरोध को जन्म दिया।
राज्य में हिंसा भड़क उठी। उच्च जातियों ने विरोध में जवाबी कार्रवाई की। राष्ट्रीय स्तर पर
नेतृत्व ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, समितियाँ एक
तनाव कम करने का आजमाया हुआ और कारगर तरीका। अंततः, एक समझौता हुआ।
विकसित हुआ। कर्पूरी ठाकुर अपनी नीति में बदलाव करने के लिए सहमत हो गए।
उन्होंने फैसला किया कि
सभी जातियों की महिलाओं को 3 प्रतिशत आरक्षण दें और अन्य 3 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दें।
सभी जातियों के गरीबों को प्रतिशत राशि दी गई। इससे प्रभावी रूप से राशि में कमी आई।
ओबीसी आरक्षण को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने उच्च वर्ग के लोगों को भी अपने पास रखने का निर्णय लिया।
ओबीसी वर्ग में वे लोग शामिल हैं जिनकी आय ₹1,000 से अधिक थी।
हर महीने—निर्णय के दायरे से बाहर। इसका असर समर्थक पर पड़ा-

आरक्षण समर्थक उग्र हो गए और उन्होंने जनता पार्टी को पूरी तरह से विभाजित कर दिया।
मध्य में। जनता पार्टी में पूर्व कांग्रेस (ओ) और जनसंघ गुट।
उच्च जातियों में लोकप्रिय इस पार्टी ने विरोध किया।
ठाकुर का कदम। चरण सिंह के नेतृत्व वाली बीएलडी और समाजवादी, जिन्होंने
ओबीसी समुदाय से समर्थन प्राप्त करने वाले लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया।
दिलचस्प बात यह है कि जयप्रकाश नारायण आरक्षण चाहते थे
केवल आर्थिक मानदंडों पर आधारित, सामाजिक मानदंडों पर नहीं।
आरक्षण इतना ज्वलंत मुद्दा बन गया कि प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई ने मामले की जांच के लिए एक नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया।
मामला। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जैसा कि इसे कहा जाता था,
1 जनवरी 1979 को स्थापित और 1 फरवरी 1979 को अधिसूचित। देसाई
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को नियुक्त किया गया।
इसका नेतृत्व करने के लिए; जल्द ही, इसे मंडल के नाम से जाना जाने लगा।
आयोग। देसाई ओबीसी सांसदों का समर्थन बनाए रखना चाहते थे, जो
वे तेजी से बेचैन होते जा रहे थे, अपने संकटग्रस्त लोगों के लिए समय खरीदने के लिए।
सरकार को नियंत्रित रखना और अपने प्रतिद्वंद्वी चरण सिंह पर लगाम लगाना। जैसा कि हमने देखा
अध्याय 1 में, एक दृढ़ निश्चयी चरण सिंह ने एक दुर्जेय आक्रमण खड़ा किया था।
1978 के उत्तरार्ध में देसाई के नेतृत्व के लिए चुनौती।
■

मंडल रिपोर्ट इंदिरा गांधी की सरकार को सौंपे जाने के बाद

31 दिसंबर 1980 को विपक्ष ने मांग की कि इसे सदन में पेश किया जाए।
संसद। जनता पार्टी अब विपक्ष में थी। चरण सिंह
सरकार पर हमले का नेतृत्व उन्होंने ही किया था। उनके सामने कानून मंत्री शिव थे।

शंकर स्वयं एक ओबीसी (कापू) थे, जो चरण सिंह की तरह ही एक
ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रबल समर्थक। 'मैं एक बार चरण गया था।'
शिव शंकर ने बताया, 'सिंह ने गृह मंत्री रहते हुए कुछ काम किया था।'
me. ‘He immediately told his officials, “Kaam kar doh, hai toh backward
(वह जो चाहता है वही करो, आखिर वह तो पिछड़ा हुआ है!) (जब बी.पी.
मंडल अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहे थे, तभी शिव शंकर ने चुपचाप
आयोग को आर्थिक मानदंडों को आधार के रूप में न अपनाने की सलाह दी गई।
आरक्षण।)
जैसे-जैसे रिपोर्ट के पक्ष में विपक्ष की आवाजें तेज होती गईं
कार्यान्वयन के संबंध में, इंदिरा गांधी ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया।
मामलों की समिति इस पर विचार करेगी। बैठक में पी.वी. उपस्थित थे।
Narasimha Rao, Kamalapati Tripathi, R. Venkataraman, Pranab
मुखर्जी और ज़ैल सिंह। ज़ैल सिंह को छोड़कर (जिनके पास रिपोर्ट थी)
बी.पी. मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को छोड़कर बाकी सभी ने इसका विरोध किया।
उन्होंने इसके कार्यान्वयन के लिए जाति को आधार बनाने की आलोचना की।
पिछड़ेपन की पहचान करना।
इंदिरा गांधी असमंजस में लग रही थीं। हालाँकि वह वापस आ चुकी थीं।
हिंदू, उच्च जाति के लोगों के समर्थन से मिली एकजुटता के कारण सत्ता हासिल हुई —
यह पिछड़े वर्ग की राजनीति के खिलाफ एक प्रतिक्रिया भी थी।
जनता पार्टी—वह यह भी जानती थी कि वह पिछड़े वर्गों को नाराज नहीं कर सकती।
She called Shiv Shankar to her office. ‘Shiv Shankarji, kya karaen
“हम क्या करें?” उसने उससे पूछा। शिव शंकर कुछ देर चुप रहा।
कुछ पल। वह उसकी दुविधा से अवगत था। उसने खुलकर बोलने का फैसला किया।
'तुम'

उन्होंने कहा, 'इसे इतनी आसानी से ठुकराया नहीं जा सकता। यह 52 प्रतिशत लोगों से जुड़ा मामला है।'
जनसंख्या का प्रतिशत। आपको इसे घर के सामने रखना होगा। लेकिन
इसे पेश करने से पहले भी, आपको यह स्पष्ट करना होगा कि एटीआर (एक्शन) क्या है।
रिपोर्ट में कहा जाना चाहिए।' इंदिरा गांधी सोच में पड़ गईं। फिर,
एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह, वह सोच-समझकर अपने शब्दों का चयन करती थी।
said, 'Aisa ATR likhiye ki saamp bhi mar jaye aur laathi bhi naa toote
(कृपया एटीआर को इस तरह से तैयार करें कि यह सांप को मार डाले लेकिन उसे नुकसान न पहुंचाए)
जिस छड़ी से इसे मारा गया है उसे तोड़ दो।' शिव शंकर ने एटीआर का मसौदा तैयार किया। वह उसे इंदिरा के पास ले गया। इंदिरा ने उस पर एक नज़र डाली।
वह खुश दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मसौदे में कहा गया था कि जबकि
सरकार ने मंडल की सिफारिशों को 'सैद्धांतिक रूप से' स्वीकार कर लिया।
आयोग की रिपोर्ट में, एक 'मंत्रिस्तरीय समिति' की नियुक्ति की बात कही गई थी।
इसके सभी निहितार्थों पर विचार किया गया। इसने अधिकारियों की एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया।
एक समिति को इसके निष्कर्षों की जांच करने के लिए कहा गया है।
फिर इंदिरा गांधी ने शिव शंकर की ओर देखते हुए पूछा, 'कौन नेतृत्व करेगा?'
'मंत्रियों की समिति?' उसके जवाब का इंतजार किए बिना, उसने उससे पूछा।
अगर वह इसकी अध्यक्षता करने को तैयार हो तो। वह मान गया। लेकिन उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा।
राजनीतिक मामलों की समिति के भीतर से प्रतिरोध आया। यह प्रतिरोध 'से' आया।
शिव शंकर ने याद करते हुए कहा, 'चार ब्राह्मण सदस्य थे। वे पी.वी. थे।'
Narasimha Rao, Pranab Mukherjee, R. Venkataraman, and Kamalapati
त्रिपाठी।' उसने फैसला टालने का निर्णय लिया। कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ।

कुछ महीने। फिर, एक दिन, उन्होंने राव को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।
समिति ने सबसे आसान रास्ता अपनाया।
राव अनिर्णय के उस्ताद थे। अगर वे किसी बात का विरोध करते थे, तो वे उसे नकार देते थे।
उन्होंने टालमटोल किया और निर्णय को स्थगित कर दिया। समिति, जिसमें शिव भी शामिल थे।
शंकर भी सदस्य थे और साल में दो बार नियमित रूप से मिलते थे। लेकिन
इन बैठकों से कुछ भी नतीजा नहीं निकला।
'शिव शंकर जी, समिति में क्या चल रहा है?' इंदिरा पूछती थीं।
समय-समय पर उनसे विनम्रतापूर्वक पूछें। उनके पास बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा।
शिव शंकर ने याद करते हुए कहा, 'जब मैं समिति में किसी मुद्दे पर जोर देता था,'
'नरसिम्हा राव उपस्थित अधिकारियों की ओर मुड़ते और उन्हें निर्देश देते,
"Acha, iski implications study kariye (Please study the implications of
जो सुझाव दिया गया है)"। अधिकारी अगले एक साल बिताएंगे।
इसके निहितार्थों का 'अध्ययन' किया जा रहा था। और यह सिलसिला चलता रहा।
व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने ओबीसी आरक्षण को लागू किया था।
मामला ठंडे बस्ते में चला गया। समिति उनके बाद भी अस्तित्व में रही।
1989 तक, उसकी हत्या के पाँच साल बाद तक। लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
रिपोर्ट। इंदिरा ने मंडल की सिफारिशों को सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक माना था।
उसके तरकश में ऐसे तीर थे जिनका इस्तेमाल वह शायद भविष्य में करे। वह जानती थी, इससे कहीं अधिक।
देश में उभरती 'पिछड़ी' राजनीति का महत्व सबसे अधिक है।
उनके मामले में, इसने कांग्रेस को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा लिया था।
1977 में दक्षिणी राज्यों में। इसके अलावा, जब वह वापसी की राह पर थी।

1977-80 के दौरान, उन्होंने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को नाराज न करने का पूरा ध्यान रखा था।
दक्षिण। इससे उसे अच्छा खासा लाभ मिला था।
पिछड़े वर्गों का आंदोलन तो दक्षिण में इससे पहले ही शुरू हो चुका था।
स्वतंत्रता—और वह इस इतिहास से परिचित थी। दक्षिण में
उत्तरी राज्यों द्वारा ऐसा करने से बहुत पहले ही आरक्षण प्रणाली अपना ली गई थी—
उदाहरण के लिए, मैसूर में महाराजा ने आरक्षण को इस हद तक अपनाया था।
1921 से ही। 1977 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज उर्स, एक
असारू समुदाय से संबंध रखने वाले पिछड़े वर्ग के नेता ने
ओबीसी-एससी-एसटी धुरी को सफलतापूर्वक तैयार किया गया, जिसने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।
1977 के चुनावों में कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आई और उसने 26 सीटें जीतीं।
28 लोकसभा सीटों में से, जबकि पार्टी को पूरे देश में करारी हार का सामना करना पड़ा, पार्टी ने जीत हासिल की।
उत्तर भारत। उर्स ने ही इंदिरा गांधी को यह सुझाव दिया था कि वे
हरे-भरे, कॉफी के बागानों से सजे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।
1978 के उपचुनाव में चिकमगलूर से उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की।
उसके बाद उसे रोकना असंभव हो गया—और वह फिर से सत्ता में लौट आई।
1980.
■

इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी राजीव गांधी इसके पक्ष में नहीं थे।
कुछ शंकाएँ थीं। क्योंकि वह एक शहरी, पश्चिमीकृत, समृद्ध परिवार से आया था।
पृष्ठभूमि के आधार पर, वह मंडल के विरोधी थे। उनके अनुसार, इससे इस बात पर जोर दिया गया कि
भारतीय समाज में सामंती और जातिगत विभाजन। राजीव को लगा कि 'अन्य कदम' उठाने चाहिए।

पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। 'मंडल'
उन्होंने अपने सहयोगियों से उपेक्षापूर्वक कहा, 'आयोग की रिपोर्ट एक रहस्य का पिटारा है।'
'और मैं इसे खोलने वाला नहीं हूँ।' उन्होंने जाने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था।
पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण के पक्ष में, भले ही वह
उन्हें बताया गया था कि इससे पार्टी को चुनावी लाभ होगा।
हालांकि ओबीसी के लिए आरक्षण से कांग्रेस को फायदा हुआ था
दक्षिणी राज्यों के बारे में राजीव अब भी आलोचनात्मक लहजे में बोलते थे। वी.पी. के एक महीने बाद...
मंडल पर सिंह के फैसले की राजीव ने कड़ी निंदा की।
अनिश्चित शर्तों पर। वे 6 सितंबर 1990 को संसद में बोल रहे थे।
विपक्ष के नेता। उन्होंने ढाई घंटे तक भाषण दिया—
लोकसभा में दिया गया अब तक का सबसे लंबा भाषण। 'मंत्री उकसा रहे हैं।'
'जातिगत युद्ध,' राजीव गांधी ने जोश से कहा।
वी

प्रधानमंत्री के प्रवेश करते ही विशाल लकड़ी का दरवाजा जोर से चरमरा उठा।
कैबिनेट बैठक के लिए कमरे में प्रवेश करते हुए। उनके सहयोगी, जो प्रतीक्षा कर रहे थे।
वह बेचैनी से आशा भरी निगाहों से ऊपर देखने लगा। मंत्रिमंडल की बैठक मंडल के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन उनमें से कई लोग इस बात से अनभिज्ञ थे। शाम के 6 बज रहे थे।
अगस्त 1990, दिल्ली का एक गर्म और उमस भरा दिन, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा—
और बाद में उद्धृत किया गया।
वी. पी. सिंह ने एकदम कड़क इस्त्री किया हुआ सफेद कुर्ता पहना हुआ था।
पायजामा। उनका पहनावा आमतौर पर उस भूमिका को दर्शाता था जो वे उस समय अपने लिए देखते थे।
वह खास पल। जब उन्होंने अपनी शेरवानी और सर्दियों की टोपी पहनी, तब...

सरकार के मुखिया, मुख्य प्रशासक, को प्रदर्शित किया जा रहा था।
पार्टी नेता मजाक में कहते थे कि इससे एक 'धर्मनिरपेक्ष' उपराष्ट्रपति का भी संकेत मिलता है। जब उन्होंने कपड़े पहने
सफेद कुर्ता-पायजामा पहने हुए, उनके अंदर का राजनेता सामने आ गया।
मंत्रीगण दोपहर में बैठक के लिए धीरे-धीरे पहुंचने लगे थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) स्थित साउथ ब्लॉक के बाहर अपनी कारों से उतरते हुए,
वे अंदर गए और लिफ्ट से पहली मंजिल पर स्थित उस कमरे में गए जहाँ
मंत्रिमंडल की बैठकें सामान्यतः आयोजित की जाती थीं। अधिकारियों ने पहले ही भाग ले लिया था।
मंत्रियों के आने तक वे अपनी-अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। बी. जी. देशमुख,
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव विनोद पांडे के बगल में बैठे थे।
कैबिनेट सचिव। इलाहाबाद के रहने वाले अविवाहित पांडे एक उपन्यासकार भी थे।
और वह वीपी के पिता और बड़े भाई की ज्योतिष में रुचि साझा करता था।
उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उपराष्ट्रपति एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। यह
जब उपराष्ट्रपति वित्त मंत्री थे और पांडे राजस्व सचिव थे, तब उनके अधीन थे।
उन्हें (1985-87 से)। उपराष्ट्रपति उन पर भरोसा करते थे और उन्हें नेतृत्व के लिए लाए थे।
सिविल सेवा। जब उन्हें 'कैब सचिव' के रूप में नियुक्त किया गया, तब कई लोग
हालांकि पांडे एक ईमानदार अधिकारी थे, लेकिन वे क्या कर सकते थे, इस बात को लेकर आशंका थी।
उनकी विद्रोही छवि को देखते हुए। लेकिन वे जानते थे कि वह उपराष्ट्रपति के खास आदमी थे।
और उनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।
बी. जी. देशमुख राजीव गांधी के प्रधान सचिव थे जब
वह प्रधानमंत्री थे। सामान्यतः, जब सत्ता परिवर्तन होता था
दिल्ली सरकार में शीर्ष अधिकारियों में भी बदलाव हुआ।
प्रधानमंत्री अपनी खुद की टीम बनाना चाहते थे, हालांकि भारत में नौकरशाही काफी जटिल है।

उन्हें राजनीति से दूर रहने वाला माना जाता है। उपराष्ट्रपति पद के तुरंत बाद देशमुख ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी।
उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली। लेकिन नए प्रधानमंत्री ने उनसे पद पर बने रहने को कहा।
प्रशासन की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ उपराष्ट्रपति को पद पर बनाए रखना,
वाणिज्य, वित्त और रक्षा मंत्रालयों में मंत्री रह चुके हैं।
इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कांग्रेस सरकारों में विभाग
गांधी, नौकरशाही को यह संदेश देना चाहते थे कि वे
प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होंगे।
उपराष्ट्रपति की कैबिनेट बैठकें आमतौर पर अनौपचारिक होती थीं। मंत्री और अधिकारी
उन्हें खुलकर बोलने की आजादी थी। जैसा कि उन्होंने खुद एक बार कहा था, एक अप्रत्याशित स्पष्टवादिता के क्षण में, 'मुझे अपने मंत्रिमंडल में कभी कोई समस्या नहीं हुई। यह समस्या तब पैदा हुई जब...'
वह पार्टी जो मेरी बर्बादी का कारण बनी।'
उस दिन प्रधानमंत्री ने सीधे मुद्दे पर बात की। उन्होंने अपना
बैठते ही उन्होंने औपचारिकताओं में समय बर्बाद किए बिना बात शुरू की, 'हम पहले चर्चा करेंगे'
मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन।'
देशमुख के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। यह उसके लिए बिल्कुल नया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
यह एजेंडा का हिस्सा रहा है। और नौकरशाहों को गुमराह होना पसंद नहीं है।
आश्चर्य की बात है। प्रधानमंत्री कार्यालय को स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी नहीं थी और उसे कोई चेतावनी भी नहीं दी गई थी।
हालांकि उपराष्ट्रपति का प्रधानमंत्री कार्यालय राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय जितना शक्तिशाली नहीं था।
इंदिरा गांधी के शासनकाल में, प्रधानमंत्री कार्यालय को आमतौर पर नजरअंदाज नहीं किया जाता था और निर्णय लिए जाते थे।
सामान्यतः इसके माध्यम से रूट किया जाता है।
देशमुख ने विनोद पांडे की ओर जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। पांडे ने स्पष्ट रूप से

देखा।
वह नाखुश था। उसने नीचे देखा लेकिन उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह
देशमुख को कुछ-कुछ अंदाजा था कि क्या चल रहा है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस बारे में अपनी राय रखेंगे।
उन्होंने अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर मुड़कर स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं थी।
प्रधानमंत्री यही विषय चर्चा के लिए चाहते थे। उन्हें इसके लिए समय चाहिए था।
उन्होंने कहा, 'सामग्री एकत्र करें और एक नोट तैयार करें।' प्रधानमंत्री ने संकेत दिए।
अपने प्रधान सचिव के प्रति अधीरता का। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक नोट, जिसमें
देशमुख जो तैयारी करना चाहते थे, वह स्पष्ट रूप से खरीद-फरोख्त की एक नौकरशाही चाल थी।
समय। देशमुख उस समय अचंभित रह गए जब सामान्यतः विनम्र रहने वाले वी.पी. सिंह ने उनके अनुरोध को काफी रूखेपन से खारिज कर दिया।
उपराष्ट्रपति ने राम विलास पासवान की ओर रुख किया। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा
समाज कल्याण विभाग ने उन्हें अपना प्रस्तुतीकरण देने के लिए आगे बढ़ने को कहा।
वे एक समाजवादी हैं।
शुरुआती वर्षों में पासवान मंडल के कट्टर समर्थक थे। वीपी के पास
उन्होंने अपने सबसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से काम न करने का फैसला किया। वे ऐसा नहीं चाहते थे।
अंतिम समय में होने वाली नौकरशाही देरी का जोखिम उठाने के बजाय, उन्होंने मंजूरी दे दी थी।
पासवान को कैबिनेट बैठक के लिए कागजी कार्रवाई तैयार करने के लिए भेजा गया है।
यह कार्य मुख्य रूप से समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था, और इसके
सचिव, पी. एस. कृष्णा।
मैंने राम विलास पासवान को फोन किया था और उनसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए

(दलीय) समिति (जो मंडल पर राय लेने के लिए गठित की गई थी), आप
'इसकी विभागीय प्रक्रिया पूरी करें और इसे मंत्रिमंडल के समक्ष लाएं,' उपराष्ट्रपति ने मुझसे कहा।
पासवान कागजों का एक बंडल लेकर कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही वह
जोश में आकर पासवान ने मंडल व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए।
आयोग की रिपोर्ट। यह जनता दल के कार्यकाल में किया गया एक वादा था।
घोषणापत्र। उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा निभाने का समय आ गया है। उन्होंने बात की
लगभग दस मिनट तक। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया, तो उपराष्ट्रपति शरद यादव
की ओर मुड़े और उनसे कुछ शब्द कहने को कहा। यादव ने भी पक्ष में बात की।
प्रस्ताव। यादव के बोलने के बाद, उपराष्ट्रपति ने चारों ओर देखा।
उन्होंने कमरे में जाकर पूछा कि क्या उनके अन्य सहयोगियों में से कोई अपनी राय व्यक्त करना चाहता है।
उद्योग मंत्री अजीत सिंह आगे बढ़ने के पक्ष में थे, बशर्ते जाटों को
मंडल सूची में शामिल थे। भारत के पहले मंडल सूची में मुफ्ती मोहम्मद सईद को शामिल किया गया था।
जम्मू और कश्मीर के मुस्लिम गृह मंत्री ने और अधिक की गुहार लगाई।
इस फैसले से कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।
देश के कुछ हिस्सों में। वह अर्धसैनिक बलों को सतर्क करने के लिए समय चाहता था।
यदि उनकी आवश्यकता पड़े तो।
दो लोगों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ स्पष्ट विरोध व्यक्त किया था।
वे वाणिज्य मंत्री अरुण नेहरू और चिमनभाई मेहता थे।
शिक्षा राज्य मंत्री, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार था, जो कि से थे
Gujarat. ‘Is sae duvidha hogi (This will create a dilemma),’ Chimanbhai
मेहता ने प्रधानमंत्री को आगाह किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति को व्यापक स्तर पर हो रहे नुकसान की याद दिलाई।
1985 में गुजरात में हुए दंगे, आगजनी और हत्याएं।
आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा पदवृद्धि के विरोध में अशांति भड़क उठी थी।

तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में ओबीसी कोटा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करना।
मेडिकल कॉलेज। इसने माधवसिंह की सरकार गिरा दी थी।
1985 में सोलंकी के साथ। मेहता ने संयमित लहजे में विनती की, 'सर, ऐसा मत कीजिए।'
हमने गुजरात में ऐसा किया था। इससे कई समस्याएं पैदा होंगी।
अरुण नेहरू मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उन्होंने बैठक में भाग लिया था।
एक दिन पहले राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति। 'विश्वनाथ,
उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था, 'राजनीति गणित नहीं है। हमें...'
इसे करने से पहले बहुत गंभीरता से सोचें।' कैबिनेट में नेहरू की अनुपस्थिति
बैठक से पता चला कि यद्यपि वह इस कदम के विरोध में थे, फिर भी वह इसे नहीं चाहते थे।
प्रधानमंत्री का खुलेआम विरोध करते हुए दिखना।
फिर कैबिनेट सचिव विनोद पांडे ने अपनी बात रखी। उन्होंने अपना पक्ष रखा।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया जाए।
उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया उसी तर्ज पर होनी चाहिए जिस तर्ज पर कर्पूरी ने की थी।
1978 में बिहार में ठाकुर के बारे में भी पांडे ने बैठक को याद दिलाया।
आरक्षणों के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। पांडे
प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं। लेकिन, इस बार उपराष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया।
वह उसकी बात नहीं सुन रहा था। हताशा में, दुखी पांडे ने उसकी ओर देखा।
Finance Minister Madhu Dandavate for help. Pande and Deepak Nayyar,
उपराष्ट्रपति सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने चर्चा की थी।
एक दिन पहले उन्होंने दंडवते से इस मामले पर बात की थी। उन्होंने उनसे समझाने-बुझाने को कहा था।
प्रधानमंत्री को यह कदम उठाने से रोकने के लिए। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मना लिया है। लेकिन दांडवते, जो एक समाजवादी थे, लंबे समय से
मंडल का समर्थक। हालाँकि उसने पांडे से कुछ नहीं कहा था और

नैयर ने बाद में मुझसे कहा, 'मैंने (उपराष्ट्रपति पद के) इस कदम का शत प्रतिशत समर्थन किया था।'
कुछ दिन पहले विनोद पांडे, वित्त सचिव बिमल जालान
(जो आगे चलकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने)
(दो कार्यकालों के लिए) और दीपक नायर ने मंडल का गहन अध्ययन किया था।
आयोग की रिपोर्ट और उसके अनुलग्नक। 'मेरी उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा हुई थी।'
नैयर ने कहा, 'इसमें उपराष्ट्रपति भी शामिल हैं, ताकि उन्हें समझाया जा सके।'
'दीपक, राजनीति का काम मुझ पर छोड़ दो,' आमतौर पर विनम्र रहने वाले उपराष्ट्रपति ने कहा।
कुछ ही देर में नय्यर से, 'और मैं अर्थशास्त्र का काम आप पर छोड़ देता हूँ।'
कैबिनेट बैठक में, पांडे के बाद उपराष्ट्रपति ने एक बार फिर पासवान की ओर रुख किया।
यह संकेत देने के लिए बोला गया कि उसे जारी रखना चाहिए। अंतर्निहित भावनाओं को भांपते हुए
पासवान ने कमरे में कहा कि वह मंडल रिपोर्ट को लागू करने जा रहे हैं।
सिफारिशें केवल 'आंशिक रूप से' ही लागू होती हैं। 'मैंने पूरी तरह से प्रयास नहीं किया है,' उन्होंने कहा।
उन्होंने सुलह भरे लहजे में कहा। बात को नरम करने की कोशिश करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि
ओबीसी की पूरी सूची स्वीकार करने से समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। वह ऐसा करेगा।
उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं जातियों को शामिल किया जाए जो केंद्रीय सूची में समान हों।
और राज्य सूचियों को ध्यान में रखते हुए। इसलिए अंतिम सूची काफी 'छोटी' होने वाली थी।
पहले की परिकल्पना से कहीं अधिक। वह आरक्षण की व्यवस्था नहीं करने जा रहा था।
प्रचार। इसके बाद उन्होंने उन क्षेत्रों की सूची दी जहां आरक्षण की आवश्यकता होगी।
लागू नहीं होता—शिक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा विभाग,

अस्पताल, सेना और न्यायपालिका। और मंडल, उन्होंने अपने
सहकर्मियों के अनुसार, केवल केंद्र सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक नौकरियों के लिए ही आवेदन करना था।
सेक्टर इकाइयाँ।
वीपी ने अपने सहयोगियों की बात सुनी। लेकिन उन्होंने खुद शायद ही कुछ कहा।
मंत्रियों द्वारा पूछे गए किसी भी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं किया गया।
मुद्दा उठाया गया। 'कैबिनेट में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। शायद कुछ लोगों ने किया हो।'
वीपी ने कई साल बाद कहा, 'यह एक तरह की चेतावनी भरी टिप्पणी थी। लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया।'
सीधे तौर पर। किसी ने नहीं कहा, "यह गलत है"। कोई भी "नहीं" कह देता तो बात बन जाती।
मेरे मन में। देवी लाल ने कभी कुछ नहीं कहा... क्योंकि तब तक वह हो चुका था।
कैबिनेट से निकाल दिया गया।
वहाँ मौजूद सभी लोगों को यह स्पष्ट था कि वी. पी. सिंह दृढ़ निश्चयी थे।
उस दिन ही निर्णय पर अमल करो। वह बस औपचारिक समझौता चाहता था।
मंत्रिमंडल की मंजूरी। बैठक ज्यादा देर तक नहीं चली, जयपाल रेड्डी।
याद दिलाया गया। एजेंडा में कुछ और आइटम भी थे। लेकिन वे
कुछ ही मिनटों में सब कुछ ठिकाने लगा दिया गया। बाद में किसी को याद नहीं रहा कि क्या हुआ था।
वे थे। जब अंततः सब कुछ समाप्त हो गया, तो वी. पी. सिंह ने घोषणा की, 'तो, यही सर्वसम्मति है।' उन्होंने अपने सहयोगियों की ओर देखा और कहा, 'यही सर्वसम्मति है।'
मंत्रिमंडल ने मंडल आयोग के निर्देशों को लागू करने के निर्णय को मंजूरी दे दी है।
पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण की सिफारिश।
फिर वीपी ने बी.जी. देशमुख की ओर रुख किया। 'क्या आप मेरे लिए एक नोट तैयार कर सकते हैं?'
ताकि मैं कल संसद में फैसले की घोषणा कर सकूं?' उन्होंने पूछा।
उनके उदास दिखने वाले प्रधान सचिव।

तब प्रधानमंत्री ने देशमुख से कहा, 'कृपया शिव से बात करें।'
बयान का मसौदा तैयार करने से पहले शंकरजी से इस बारे में बात की थी। जैसा कि उल्लेख किया गया है, शिव शंकर
वह मंडल का भक्त था, लेकिन वह मंडल को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया था।
कांग्रेस सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली।
देशमुख, वीपी की बातों से हैरान रह गया। उसने बस सिर हिलाया।
नाखुशी से। उसने अपने सचिव की ओर मुड़कर निर्देश दिए। लेकिन
प्रधानमंत्री के अनुरोध ने प्रधान सचिव को उत्सुक कर दिया।
दिल्ली के राजनीतिक और नौकरशाही हलकों में यह कोई रहस्य नहीं था कि
वी. पी. सिंह और शिव शंकर के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं थे। 1986 में, स्थिति यह थी कि
शिव शंकर ने उपराष्ट्रपति को वित्त मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए पैरवी की थी।
1987 में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपने निष्कासन के लिए दबाव बनाया था। शिव शंकर को उम्मीद थी कि उन्हें 1984 में वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो मिलेगा, जब राजीव गांधी ने
गांधी ने उपराष्ट्रपति को वित्त मंत्री बनाया था। लेकिन, 1986 के अंत तक, शिव शंकर का भाग्य अब ढलान पर आने लगा था। वह अपने भीतरी भाग से विमुख हो गया था।
राजीव गांधी के करीबी लोगों के समूह में। वीपी के विपरीत, जिन्होंने 1987 में कांग्रेस छोड़ दी थी, शिव गांधी...
शंकर पार्टी में बने रहे। लेकिन वे राजीव से निराश हो गए थे।
कांग्रेस छोड़ने के बाद भी वह उपराष्ट्रपति के संपर्क में थे।
अधिकांश लोगों को यह पता नहीं था कि वी. पी. सिंह को चुनाव लड़ने के लिए प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन था।
मंडल शिव शंकर थे। शिव शंकर ने वीपी को आगे बढ़ने की सलाह दी।
मंडल...और एक और अंबेडकर बनो,' एच. आर. भारद्वाज ने मुझसे कहा।
जब देशमुख शिव शंकर से मिलने गए, तो उनके पास एक मसौदा था...
सरकारी आदेश को शिव शंकर ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "यह ऐसा था कि..."

एक नीरस प्रकार का लेखन जो सामाजिक परिभाषा में फिट नहीं बैठता था।
'न्याय,' शिव शंकर ने तिरस्कारपूर्वक याद करते हुए कहा। 'मैंने सरकारी आदेश को फिर से तैयार किया।'
मैं स्वयं सामाजिक न्याय की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने में लगा हुआ हूँ। मुझे कहना होगा कि प्रत्येक
मेरे कहे को सरकारी आदेश में बरकरार रखा गया।
कैबिनेट बैठक के बाद, उपराष्ट्रपति ने राम विलास पासवान और सामाजिक कार्यकर्ता को फोन किया।
कल्याण सचिव पी.एस. कृष्णन अपने आवास पर। कृष्णन उन लोगों में से एक थे जिन्होंने
मंडल परियोजना को लागू करने की आवश्यकता के प्रति आश्वस्त दो वरिष्ठ नौकरशाहों ने
दूसरे व्यक्ति वाणिज्य सचिव एस. पी. शुक्ला थे। उन्हें इस कदम की सभी बारीकियों को लागू करने का कार्य सौंपा गया था।
मैंने उनसे उन मुद्दों पर चर्चा की जो वे अगले दिन संसद में उठाएंगे।
निर्णय लेने के बाद, वीपी ने अब आगे की चुनौतियों से निपटने की ओर रुख किया।
जिन पार्टियों ने उनकी सरकार को बाहरी समर्थन दिया—भाजपा और
वामपंथी समूहों के साथ काम करना—एक ऐसा कार्य जिसे उन्होंने जानबूझकर अंतिम क्षण तक टाल दिया था।
उन्हें पता था कि वे इस फैसले का स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें यह भी पता था।
कि वे उसे पद से नहीं हटाएंगे। न तो पार्टी, न ही उपराष्ट्रपति ने ऐसा किया।
सोच-समझकर चुनाव कराए गए थे। वे कांग्रेस को खतरे में नहीं डालना चाहते थे।
सत्ता में वापसी।
उपराष्ट्रपति ने स्वीकार किया, 'यह एकमात्र ऐसा समय था जब मैंने उनसे सलाह नहीं ली।' 'मैंने बस इतना ही किया।'
उन्हें सूचित किया।
उन्होंने सबसे पहले भाजपा नेता एल.के. आडवाणी से और फिर हरकिशन से बात की।
सीपीआई (एम) के महासचिव सिंह सुरजीत आडवाणी ने वीपी से बात करने की

कोशिश की।
वे इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। वे मंगलवार की साप्ताहिक बैठक में इस पर चर्चा करेंगे।
जो कि केवल दो दिन दूर था', आडवाणी ने सुझाव दिया। उनके बनने के बाद
प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हर मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे।
उन्हें सरकार में हो रही घटनाओं से अवगत कराएं और उनकी सहायता लें।
सुझावों पर विचार किया जाएगा। वह वामपंथी नेताओं के साथ भी ऐसा ही करेंगे।
'नहीं, मैं
'मैं इंतजार नहीं कर सकता,' आमतौर पर मिलनसार रहने वाले उपराष्ट्रपति ने आडवाणी से कहा। 'मुझे करना ही होगा।'
इसकी घोषणा कल करें।
बाद में, उपराष्ट्रपति ने सोम पाल को आडवाणी से मिलने और उन्हें समझाने के लिए भेजा।
उन्हें स्थिति के बारे में विस्तार से बताएं। 'अगर जनता दल इस तरह की चाल चलने पर तुला हुआ है तो...'
सोम पाल से आडवाणी ने साफ-साफ कहा, 'मंडल कार्ड के जरिए भाजपा को मजबूर होना पड़ेगा।'
'मंदिर कार्ड खेलना'—राम मंदिर के निर्माण का संक्षिप्त रूप।
Ayodhya.
वी. पी. सिंह ने 7 तारीख को संसद के दोनों सदनों में इस फैसले की घोषणा की।
अगस्त 1990—दिल्ली के बोट क्लब में देवी लाल की रैली से दो दिन पहले।
मंत्रिमंडल का निर्णय कार्मिक विभाग को भेजा गया था।
प्रशिक्षण। इसने 13 अगस्त को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें सूचीबद्ध किया गया था
मंडल आयोग और राज्य के लिए 1,200 ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समान हैं।
सरकार ने नीति के संभावित लाभार्थियों की सूची जारी की है।
अब इस फैसले से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है।
मंडल, निस्संदेह वी. पी. का सबसे दूरगामी निर्णय है।

सिंह के करियर ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी।
उनके राजनीतिक करियर के तीसरे चरण के दौरान। अब मैं पहले चरण पर नज़र डालूंगा।
दो चरण—सामंती और वफादार चरण, एक कांग्रेसी के रूप में
इंदिरा गांधी का शासनकाल और वह विद्रोही दौर जब उनका राजीव गांधी से मतभेद हो गया। ये उप-उपराष्ट्रपति के व्यक्तित्व, मानसिक संरचना और उनके विचारों की झलक देते हैं।
जिन तरीकों से उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, उन सभी का उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा।
अंततः मंडल के लिए आगे बढ़ने का निर्णय।
छठी

दिसंबर 1981 में, एक दो मंजिला इमारत में दोपहर के भोजन की पार्टी चल रही थी। शाहजहाँ रोड, 82 नंबर पर स्थित बंगला। ढलान वाली छतों वाले मकान जो
लुटियंस के दिल्ली में वृक्षों से घिरी सड़क के एक किनारे पर स्थित पेड़-पौधों से सजी सड़क कुछ इस प्रकार दिखती थी:
स्विस शैले में वरिष्ठ संसद सदस्य रहते थे।
दोपहर के भोजन के दौरान हंसी-मजाक और नोकझोंक—और राजनीतिक चर्चाएँ जो देश की राजधानी में ऐसे अवसरों की यही विशेषता है। बोले गए शब्द
ये बातें शिष्टता और विनम्रता से कही गई थीं, जो सामंती परिवारों की एक विशिष्ट विशेषता थी।
संत बक्स सिंह मेजबान थे। वे सत्तारूढ़ दल के उत्तर प्रदेश सांसद हैं।
कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्होंने अपने दो भाइयों, चंद्र शेखर को आमंत्रित किया था।
प्रसाद सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उनके एक मित्र, देवेंद्र नाथ
द्विवेदी, इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित थे। उस समय सी.एस.पी. सिंह न्यायाधीश थे।
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वी.पी. सिंह उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री।
उस सर्दी की दोपहर में, जब भाई आपस में मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे मानो...

उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, कुछ बनावटीपन सा लग रहा था।
वहाँ जो सौहार्द व्याप्त था। अचानक, अपने दोनों भाइयों की ओर इशारा करते हुए, सी.
एस. पी. सिंह ने द्विवेदी की ओर मुड़कर मज़ाक में पूछा, 'देवेंद्र, कौन सा वाला?'
उनमें से कौन चालाक है?' द्विवेदी के जवाब देने से पहले ही, वीपी
मैंने विरोध किया। 'दादा भाई, आप मुझे सच में 'चैन' तो नहीं समझते?' वह हँस पड़ा।
अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने कहा, 'मैं एक साधारण व्यक्ति हूं।' और
उन्होंने आगे कहा, 'आप अपना प्रश्न दोबारा क्यों नहीं पूछते? आप यह क्यों नहीं पूछते कि कौन'
हम दोनों में से बड़ी चेन किसकी है?
सी.एस.पी. सिंह हँसे। 'नहीं, नहीं, हम जानते हैं कि बड़ी चेन कौन है'।
और वो हैं राजा बहादुर। (राजा बहादुर एक सम्मानजनक उपाधि थी जो अक्सर दी जाती थी)
वीपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मांडा की संपत्ति के मालिक के रूप में, जो एक पूर्व रियासत थी।
राज्य।)
सी.एस.पी. सिंह उपराष्ट्रपति को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे उपराष्ट्रपति के बहुत बड़े प्रशंसक थे।
वह अपने छोटे भाई के प्रति शिष्टाचार दिखाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था।
सौतेला भाई, संत बक्स, जैसा कि अक्सर पारंपरिक परिवारों में होता है। यह एक
उपराष्ट्रपति के प्रति उनके स्पष्ट स्नेह को संतुलित करने का प्रयास करना—और ऐसा करके,
सैंट बक्स को अच्छा लग रहा था। हालाँकि वह अपने भाई सी.एस.पी. को आधा चिढ़ा रहा था।
उस दिन सिंह एक वास्तविकता को स्वीकार कर रहे थे—वी. पी. सिंह ने दिखाया था
अपने बड़े भाई संत बक्स सिंह, जो पहले राजनीति में आए थे, की तुलना में उनमें कहीं अधिक राजनीतिक सूझबूझ और चालाकी थी। इससे उनके बीच तनाव पैदा हो गया था।
दो।

तीनों सिंह बंधुओं का संबंध राजपूत वंश से था और वे दहिया समुदाय से थे।
उत्तर प्रदेश में एक वंश। वे भगवती प्रसाद सिंह के पुत्र थे।
दहिया रियासत के राजा, जिन्होंने तीन रानियों से विवाह किया था। सबसे बड़ी रानी संतान को जन्म दिए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। संत बक्स सिंह उन पांच लोगों में से एक थीं।
दूसरी रानी से जन्मे बच्चे सी.एस.पी. सिंह और वी.पी. सिंह थे।
तीसरी रानी साहिबा के तीन बच्चों में से एक। ये बच्चे बड़े हुए।
उन्हें बड़ी माँ और छोटी माँ कहकर पुकारते हुए।
माँ)।
वी. पी. सिंह का जन्म 25 जून 1931 को हुआ था। युवा विश्वनाथ थे
पांच साल की उम्र में उसे उसके जैविक परिवार से अलग कर दिया गया और उसे सौंप दिया गया
मांडा के निःसंतान राजा राम गोपाल सिंह द्वारा गोद लिया गया। मांडा एक
दहिया से भी बड़ी पड़ोसी जागीर में 500 गाँव शामिल थे।
अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद राजा शराबी बन गया था और वह चाहता था कि...
एक बच्चे को गोद लेना। तभी हेरफेर और जोड़-तोड़ शुरू होती है।
इसकी शुरुआत दहिया में हुई। बड़ी रानी चाहती थीं कि सी.एस.पी. सिंह को गोद लिया जाए।
इससे उनके बेटे संत बक्स सिंह के लिए रास्ता खुल जाता।
दहिया का राजा बनना। हालाँकि, यह वीपी की कुंडली थी कि
मांडा के राजा की आवश्यकताओं को 'पूरा' किया।
भगवती प्रसाद सिंह ने पांच वर्षीय वीपी को इस उम्मीद में दान करने पर सहमति जताई कि
भविष्य में दोनों पड़ोसी संपत्तियों को समेकित करने के लिए। वीपी के पास सभी अधिकार थे।
अपने दत्तक घर में भौतिक सुख-सुविधाएं और नौकरों का एक दल साथ लेकर चलता था।
लेकिन उनके साथ बहुत कम ही लोग रहते थे। उनके शुरुआती साल अकेलेपन से भरे रहे।

उन्हें अपने मायके वालों से कोई संपर्क रखने की अनुमति नहीं थी—यह उन कारणों में से एक था जिनकी वजह से उन्हें अपने मायके वालों से संपर्क करने की इजाजत नहीं थी।

उसके दत्तक पिता द्वारा निर्धारित शर्तें। उसका जीवन कष्टों से भरा था, यहाँ तक कि दर्दनाक बचपन। शुरुआत में, उनके दत्तक पिता ने उनकी संपत्ति पर दावा किया। प्रबंधक, कैप्टन कुक नामक एक स्कॉटिश व्यक्ति, और उनकी पत्नी को देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया था।

श्रीमती कुक एक सख्त अनुशासक थीं, लेकिन विशेष रूप से

उपराष्ट्रपति बनने में रुचि रखते थे। जब उनके दत्तक पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, तब...

तपेदिक से पीड़ित वीपी को देहरादून के एक स्कूल में भेजा गया। कुछ वर्षों बाद वहाँ, कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल में, और जैसे ही वह व्यवस्थित हो रहा था

नीचे गिरने के बाद, उसे वापस घर लाया गया। इस बार, उसके दत्तक पिता,

हालांकि वे अभी भी बहुत बीमार थे, उन्हें इलाहाबाद में ही रखा गया। वीपी एक विशाल घर में रहते थे।

ऐश महल नामक दो मंजिला हवेली जो मांडा का हिस्सा थी

उन्होंने शहर के बॉयज़ हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की। इलाहाबाद में ही उन्होंने अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते को फिर से संजोया।

फिर से भाई।

एक दिन स्कूल में एक बड़ा लड़का उसके पास आया। वह नीचे झुका और

उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, 'मैं तुम्हारा भाई हूँ।' उसने चारों ओर देखा कि क्या

उन्होंने कहा, "कोई भी उन्हें सुन सकता है, किसी से एक शब्द भी मत कहना वरना वे हमें मिलने नहीं देंगे।' तब सी.एस.पी. सिंह ने अपने छोटे भाई-बहन के लिए एक नया वाहन खरीदा।

आइसक्रीम। वीपी ने वर्षों बाद याद किया कि उन्हें अभी भी वह आइसक्रीम याद है। स्वाद। 'यह मैग्नोलिया था।' अगले हफ्तों में, वीपी बहुत बढ़ गया।

सी.एस.पी. सिंह के करीबी। पढ़ाई से नफरत होने के कारण सी.एस.पी. सिंह अक्सर उसका होमवर्क चुपके से कर लो और अगले दिन वापस ले आओ।

संत बक्स सिंह अपने छोटे सौतेले भाई के साथ अलग तरह से व्यवहार करते थे। शुरुआत में,
उन्हें मांडा एस्टेट के बारे में अधिक जिज्ञासा थी, जिसके बारे में सभी को पता था कि उपराष्ट्रपति
उन्हें विरासत मिलेगी। वह और उनके दूसरे भाई हर बक्स सिंह कभी-कभी
मांडा एस्टेट की 'बग्गी' में चुपके से उसके साथ जाकर उसे देखने के लिए
वह विशाल ऐश महल जहां वह रहते थे।
वीपी के इलाहाबाद जाने के एक साल बाद उनके दत्तक पिता का निधन हो गया।
वीपी और संपत्ति की देखभाल की जिम्मेदारी हस्तांतरित कर दी गई थी।
सरकार ने अमर सिंह माथुर को, जो एक सिविल सेवक थे, यह पद सौंपा। माथुर और उनके
परिवार ऐश महल में वीपी के साथ रहने लगा। युवा वीपी को वह जगह बहुत पसंद आने लगी।
उन लोगों और श्रीमती माथुर ने उन्हें वह स्नेह दिया जिसकी उन्हें लंबे समय से चाह थी। लेकिन
जब वीपी दस साल के थे, तब उनके जैविक पिता उन्हें वापस ले आए।
बच्चे के विरोध के बावजूद कि वह जाना नहीं चाहता था, दहिया ने फिर से दहिया को वहाँ जाने के लिए कहा।
माथुर परिवार। उनके पिता को अपनी जान का खतरा था—और उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का भी।
उसे उसके दत्तक पिता ने गोद लिया था। लोगों ने अदालत में उसके गोद लेने को चुनौती दी थी।
और रामगोपाल सिंह की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर दावा किया। वीपी
उसे अपने भाइयों के साथ उसी स्कूल में दाखिला दिलाया गया, लेकिन बहुत जल्द उसके पिता ने उसे दूसरे स्कूल में भेज दिया।
उसे एक बार फिर रवाना कर दिया गया, इस बार वाराणसी में प्रसिद्ध उदय विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए।
प्रताप कॉलेज, जहां कई राजपूत बच्चे पढ़ते थे।
अपने प्रारंभिक वर्षों में अपने अस्थिर जीवन के बारे में बात करते हुए, वीपी

उन्होंने कहा, 'मैं असुरक्षित था, बहुत असुरक्षित।' उनका अकेलापन भरा बचपन भी इसी का हिस्सा था।
उन्हें राजनीति में एक अकेला व्यक्ति बना दें।
■

वीपी जब कॉलेज में थे तभी से उन्होंने सैंट बक्स को अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया था।
सिंह। अपने बड़े भाई के प्रभाव में, जो 'विद्वान और' थे
अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने के बाद, उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने की वकालत शुरू की। उन्होंने इस विषय पर बहसों में भाग लिया। गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी।
उन शुरुआती वर्षों में, वे समाजवादियों के प्रभाव में भी आए और
अपने कॉलेज के दिनों में कम्युनिस्टों के समर्थक रहे। उपराष्ट्रपति ने अपनी 200 बीघा जमीन दान कर दी।
विनोबा भावे के नेतृत्व वाले भूदान आंदोलन के लिए।
उपराष्ट्रपति को चुनाव जीतने के शुरुआती सबक तब मिले जब वे काम करते थे।
1967 के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर से अपने भाई के चुनाव अभियान के लिए।
चुनाव। उन्होंने उत्तर प्रदेश के उस कस्बे में एक महीने तक डेरा डाला जो चुनाव से 135 किलोमीटर दूर है।
इलाहाबाद। यहीं पर उन्होंने व्यापार की उन बारीकियों को सीखा जो उनके लिए महत्वपूर्ण थीं।
आने वाले वर्षों में यह बात उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। उन्होंने देखा कि उनके भाई के चुनाव परिणाम कैसे आए।
टीम ने मतदाता सूचियों का विश्लेषण किया और मतदान के आधार पर नामों को वर्गीकृत किया।
बूथों का दौरा किया, यह तय किया कि किन क्षेत्रों का दौरा करना है और किन क्षेत्रों को छोड़ना है। सैंट बक्स
सिंह ने कई लोगों को संदेश और अपनी तस्वीर वाला पोस्टकार्ड भेजा।

अपने निर्वाचन क्षेत्र में; फिर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की। बचाने के लिए
पैसे की कमी के कारण, टीम ने दोस्तों से वाहन उधार लिए। परिवार के सदस्यों
वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए वे खुद वाहन चलाएंगे।
वीपी और उनके तीन भाई इस दौरान छल-कपट का सहारा लेते थे।
प्रचार के लिए। वे रात में गांवों में जाते थे, हर एक
वे उम्मीदवार होने का नाटक करते थे। वे ग्रामीणों से बात करते थे।
समूहों में, और चूंकि वे जिन स्थानों पर बोलते थे वे अंधेरे और कम रोशनी वाले थे,
गांव वाले उस उम्मीदवार का चेहरा नहीं पहचान पाए जो यह काम कर रहा था।
बातचीत शुरू हुई। जल्द ही, उनके विरोधियों को आश्चर्य होने लगा कि एक अकेला व्यक्ति कैसे...
उम्मीदवार संत बक्स सिंह व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे क्षेत्रों को कवर कर सकते थे!
हालांकि यह राजपूत बहुल निर्वाचन क्षेत्र था, और संत बक्स सिंह
अगर वह राजपूत होता, तो जीत निश्चित नहीं होती। राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस, जिसका नेतृत्व कर रही थी,
इंदिरा गांधी 1967 के चुनाव में बड़ी मुश्किल से जीत पाईं। लेकिन
संत बक्स सिंह ने शानदार जीत हासिल की। बाद में, वह लोगों को बताते थे कि यह जीत कितनी कठिन थी।
उपराष्ट्रपति ने उन्हें चुनाव जितवाने के लिए काम किया था।
उपराष्ट्रपति ने राजनीति में दिखावे के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था।
दिसंबर 1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री मांडा आए, तब वीपी ने एक
शास्त्री के माथे पर तिलक लगाया। उन्होंने ब्लेड से अपने अंगूठे पर कट लगाया और फिर
उसने पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार आगंतुक नेता के माथे पर अपना खून मल दिया।
राजपूतों द्वारा लौटते हुए नायक का स्वागत करने की विधि। शास्त्री ने अभी-अभी
सितंबर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध जीता। वह इससे इतना प्रभावित हुआ था।
उन्होंने यह घोषणा की कि उपराष्ट्रपति उनके पांचवें पुत्र होंगे। दो दशक बाद,
शास्त्री की पत्नी ललिता ने 1988 के चुनाव में अपने बेटे सुनील के लिए प्रचार करने

से इनकार कर दिया था।
इलाहाबाद में उपचुनाव में उनका मुकाबला उपराष्ट्रपति से था, जिन्होंने तब तक कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि वह किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना चाहतीं।
दो बेटों के बीच।
कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के कुछ ही समय बाद, वीपी ने आगे की पढ़ाई करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया।
राजनीति। यह करना स्वाभाविक प्रतीत होता था; मांडा के राजा होने के नाते वह
लोगों की समस्याओं को हल करने की उम्मीद थी। बाद में उपराष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि लोगों की समस्याओं को हल करने की इच्छा थी।
सार्वजनिक मामलों में पहचान बनाने और अपनी छाप छोड़ने का भी अपना महत्व था।
इसका संबंध उनके राजनीति में प्रवेश से है। 1969 में, संत बक्स सिंह के प्रोत्साहन से,
वीपी ने सोरांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो कि
उत्तर प्रदेश के फूलपुर में पांच विधानसभा क्षेत्र। यह सोरांव में था।
उस उपराष्ट्रपति ने अपने चेन वाले स्वभाव को पूरी तरह से प्रदर्शित किया, जिससे इंदिरा को मजबूर होना पड़ा।
गांधी जी ने उनसे सीट मौजूदा पदाधिकारी को नहीं बल्कि उन्हें आवंटित करने का आग्रह किया। उन्होंने ऐसा करने में कामयाबी हासिल कर ली।
दलित उम्मीदवार को अपने पक्ष में नाम वापस लेने के लिए राजी करना। उच्च जाति के वोट
सोरांव में तो 5 प्रतिशत भी नहीं थे। यह मूलतः एक निर्वाचन क्षेत्र था।
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व था; और कांग्रेस की स्थापना की।
नेताओं ने उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था।
उनकी टीम के एक सदस्य ने कहा, 'नेताओं को भूल जाओ, जनता के पास जाओ।'
उसके बाद, उपराष्ट्रपति घर-घर जाने लगे। वे रात में दलितों के घरों में जाया करते थे।
और अपने परिवारों के साथ आग के चारों ओर बैठें। तब तक कांग्रेस नेता
दलित केवल अपने गांवों की सीमाओं तक ही आए थे। दलित बहुत ही स्पष्ट रूप से

दिखाई दे रहे थे।
यह उनके चुनाव प्रचार का हिस्सा था। उन्होंने कहा, 'मेरी जीप में ज्यादातर दलित ही सवार होते थे।'
उसने मुझसे कहा। सोराओन में अपने अभियान के दौरान ही उसने यह बात शुरू की थी।
ओबीसी और दलितों की आकांक्षाओं और पीड़ा को समझें।
अपने चुनाव ने मुझे अंदर सुलग रही आग की एक झलक दी,' उपराष्ट्रपति को यह कहना था।
कई साल बाद, उपराष्ट्रपति ने सोराओन से जीत हासिल की।
जब भाइयों ने दिसंबर 1981 में दिल्ली में आयोजित दोपहर के भोजन के दौरान पुरानी यादों को ताजा किया,
देवेंद्र द्विवेदी ने उन्हें कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन किया। सबसे लोकप्रिय कहानी यह थी:
इस बारे में कि कैसे वीपी ने अपने पहले संसदीय चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट हासिल किया।
1971 में हुए चुनाव में, उन्होंने प्रतिष्ठित फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था।
वह निर्वाचन क्षेत्र जहां से जवाहरलाल नेहरू ने कभी जीत हासिल की थी। कांग्रेस
दिग्गज एच. एन. बहुगुणा ने द्विवेदी से उपराष्ट्रपति को समझाने के लिए कहा था।
फूलपुर से खड़े हों। वह ब्राह्मणों और
ठाकुर मतदान कराने के लिए उपस्थित होंगे। (बहुगुणा ब्राह्मण थे और उप-वकील एक अन्य व्यक्ति थे)
ठाकुर।) बहुगुणा ने अनुमान लगाया कि इससे उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में मदद मिलेगी।
इलाहाबाद, जो फूलपुर के निकट था। द्विवेदी उपराष्ट्रपति को उनसे मिलने ले गए।
बहुगुणा, जो एआईसीसी के महासचिव के रूप में इसके लिए जिम्मेदार थे
टिकट वितरण।
वे वीपी की फिएट कार में बैठकर बहुगुणा के घर गए। वहाँ एक
बहुगुणा को देखने के लिए बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। 'जैसे ही मैं अंदर गया...'

Bahuguna told me, “Inko andar lekar jao (Please take him inside)”.’
‘हम अंदर एक कमरे में गए।’ अंत में बहुगुणा कमरे में आ गई।
जहां वे बैठे थे. 'इनको तैयार करना है
(चुनाव लड़ने के लिए),’ उन्होंने द्विवेदी से बिना किसी भूमिका के कहा।
At this point VP spoke up, ‘Bahugunaji, humko rehne deejiye
(बहुगुणा जी, कृपया मुझे इसमें शामिल न करें)।’ बहुगुणा ने उनकी ओर देखा।
अचंभित। बाहर 1,000 लोग थे, सभी नामांकन की मांग कर रहे थे।
और यह आदमी पार्टी का टिकट लेने से इनकार कर रहा था।
‘Bahugunaji, humare paas paisa nahin hai,’ VP said. ‘Humare bahut
mukadme chal rahen hain (I have little money. I have many legal cases
मेरे खिलाफ जा रहे हैं)।
‘आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है,’ बहुगुणा ने उन्हें आश्वस्त किया। ‘हम हम प्रत्येक उम्मीदवार को 1 लाख रुपये देने जा रहे हैं।
बहुगुणा ने अनिच्छुक उपराष्ट्रपति को फूलपुर से चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया। उस समय उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली रहे बहुगुणा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी प्रस्तुत की।
इंदिरा गांधी एक अपरिहार्य स्थिति के रूप में थीं। हालाँकि उन्हें यह तथ्य पसंद नहीं था कि
यह निर्णय उनकी सहमति के बिना लिया गया था, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।
योजना।
इंदिरा गांधी को वी. पी. सिंह शुरू से ही पसंद थे।
वह उनके प्रति समर्पित थे और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जब
1975-77 के आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच शुरू हुई, और दर्जनों कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन उपराष्ट्रपति उनके साथ खड़ी रहीं। जब इंदिरा गांधी

दिसंबर 1978 में गिरफ्तार किए गए, वह उन लोगों में से एक थे जिन्हें जेल भेजा गया था।

विरोध।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उपराष्ट्रपति का पदोन्नति होना एक विचित्र घटना थी।

उनकी वफादार छवि की बदौलत उन्हें कई बार सौभाग्य का साथ मिला।

इंदिरा ने संजय को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने देने से इनकार कर दिया।

जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा, जून 1980 में प्रदेश में संजय ने उपराष्ट्रपति को नेतृत्व के लिए चुना।

देश का सबसे बड़ा राज्य। शुरुआत में, उपराष्ट्रपति मुखिया का पदभार संभालने के लिए अनिच्छुक थे।

लेकिन उन्होंने संजय की बातों में आकर मंत्री पद स्वीकार कर लिया। लेकिन वे संजय के बहकावे में आ गए और मंत्री बन गए।

9 जून 1980 को उन पर आरोप लगाया गया था—संजय की मृत्यु से ठीक दो सप्ताह पहले।

विमान दुर्घटना। एक अनिच्छुक राजनीतिज्ञ होने के नाते, उस राजनीतिज्ञ के विपरीत जिसे देखा जाता था

सत्ता हथियाने की प्रवृत्ति एक ऐसी रणनीति थी जिसका उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बड़े प्रभावी ढंग से उपयोग किया।

राजनीतिक करियर।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने किसी विशेष पक्ष के प्रति कोई विशेष झुकाव नहीं दिखाया।

किसी विचारधारा पर उनका कोई दृढ़ मत नहीं था। न ही किसी राजनीतिक विषय पर उनके कोई प्रबल विचार थे।

वह व्यावहारिक, विवेकशील और शांत कार्यकुशलता के लिए जाने जाते थे—और,

बेशक, नेहरू परिवार के प्रति वफादारी। लेकिन उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी खुद को साबित किया।

प्रशासक, हालांकि वह अक्सर काम करवाने के लिए अपरंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करता था।

हो गया।
एक बार जब राज्य में बिजली की कमी थी और
बिजली बोर्ड के अध्यक्ष लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि लोगों को बिजली मिल रही है।
आठ घंटे बिजली आपूर्ति के बाद, उपराष्ट्रपति ने उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाया।
सुबह। उन्होंने आश्चर्यचकित अधिकारी से कहा, 'हम लखनऊ से जा रहे हैं।'
बुलंदशहर तक... मैंने उसे हेलीकॉप्टर में बैठने को कहा (जो कि था)
उड़ान भरने के लिए तैयार)। वीपी ने पहले ही 'छापेमारी' कर ली थी और पाया था कि राज्य के कई हिस्सों में बिजली की कमी के अलावा, बिजली
कुछ औद्योगिक घरानों को धन भेजा जा रहा था।
राज्य भर में उड़ान भरते समय, उपराष्ट्रपति पायलट से बेतरतीब ढंग से कुछ भी करने के लिए कहते थे।
कुछ जगहों पर उतरना। ग्रामीण हेलीकॉप्टर के चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, और वीपी मैंने उनसे उनके यहाँ उपलब्ध बिजली के बारे में पूछा। उन्होंने पुष्टि की।
उन्हें तीन घंटे से अधिक समय तक बिजली नहीं मिली। बुलंदशहर में, एक
सार्वजनिक सभा में, उपाध्यक्ष ने सभा में उपस्थित लोगों से अध्यक्ष का परिचय कराते हुए कहा, 'आपके पास है
'मैंने लोगों की बात सुनी,' उपराष्ट्रपति ने भीड़ के सामने उनसे कहा। 'अगर
आप स्थिति को सुधार सकते हैं, लखनऊ वापस आ जाइए, अगर नहीं तो घर चले जाइए।
वीपी उसे वहीं छोड़कर लखनऊ वापस चले गए। बिजली की स्थिति
उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है।
उस दिसंबर के दिन सिंह बंधुओं ने जिस बारे में बात नहीं की, वह यह थी:
कुछ ऐसा जो संत बक्स सिंह को वर्षों से खटकता रहा था—और जो पुराना हो चुका था
बात 1974 की है। उस साल, वीपी ने अपने बड़े भाई को मात दे दी थी और
इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। उन्होंने उन्हें नियुक्त किया था।
डी.पी. के अधीन 10 अक्टूबर 1974 को वाणिज्य उप मंत्री।

चट्टोपाध्याय। उस समय, वीपी संसद में केवल एक बैकबेंचर थे।
और घर में शायद ही कभी बोलते थे। दूसरी ओर, संत बक्स सिंह थे
ऑक्सफोर्ड में शिक्षित, एक वाक्पटु वक्ता, एक सक्षम सांसद, और एक
विदेश नीति विशेषज्ञ। उनका नाम ही चर्चा में था।
कांग्रेस के हलकों में उन्हें मंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन
उपराष्ट्रपति अप्रत्याशित उम्मीदवार के रूप में उभरे। 1974 में इंदिरा गांधी की स्थिति अच्छी नहीं थी।
संत बक्स जैसे स्वतंत्र विचारों वाले मंत्री के लिए। वह तलाश कर रही थीं
वीपी जिस 'वफादारी' के लिए जाने जाते थे, भले ही वे 'नौसिखिए' थे।
अपने भाई की तुलना में। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच संबंध अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए। उपराष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी में ऊंचे पद पर पहुंचे।
संत बक्स सिंह से भी तेज।
■

संत बक्स सिंह के घर पर दोपहर के भोजन के तीन महीने बाद, एक दुखद घटना घटित हुई।
सिंह परिवार। 20 मार्च 1982 को, सी.एस.पी. सिंह और उनके पंद्रह वर्षीय बेटे...
बड़े बेटे अजीत की आधी रात को डाकुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी।
इलाहाबाद के पास, जो उनके भाई की हत्या के बदले की कार्रवाई प्रतीत होती है।
उत्तर प्रदेश को डाकुओं से मुक्त कराने का अभियान। वे लोग 'वीकेंड शूटिंग' के लिए गए थे।
यह सी.एस.पी. सिंह ही थे जिन्होंने भाईचारे का स्नेह और आत्मीयता लाई थी।
वीपी के बचपन के अकेलेपन भरे जीवन की याद दिलाता है। घंटों तक, वीपी लगातार दुखी होकर बगल में बैठा रहा।
शरीर। उसके भाई ने अपने पद की कीमत चुकाई थी, वह बार-बार यही दोहराता रहा।
और बार-बार।
जब वीपी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, तब राज्य में अराजकता फैल गई थी।

डाकुओं द्वारा। खूंखार गिरोहों ने कस्बों और गांवों में लोगों को आतंकित कर रखा था।
फूलन देवी के नेतृत्व वाले इस गिरोह में ओबीसी समुदाय की महिला डकैत शामिल थी।
और बाद में संसद के लिए निर्वाचित हुए, उन्होंने बीस से अधिक ठाकुरों की हत्या की थी।
बेहमई की घटना के परिणामस्वरूप राजपूतों ने जवाबी कार्रवाई की। 23 नवंबर 1981 को,
उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश को डाकुओं के आतंक से मुक्त कराने का संकल्प लिया।
अगर वह सफल नहीं हुए, तो...
उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद के इकतालीस दिनों में, 299
मुठभेड़ों में 'डाकुओं' का सफाया कर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने पुलिस को आदेश दिए थे।
सबसे कुख्यात लोगों से निपटने के लिए ब्लैंच को नियुक्त किया गया था। लेकिन जल्द ही वे नियंत्रण से बाहर हो गए।
उन्होंने खुद को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस कदम के खिलाफ भारी विरोध हुआ।
'मुठभेड़'। नागरिक अधिकार समूह और मीडिया, मुठभेड़ की पड़ताल कर रहे हैं।
मौतों के मामले में, उपराष्ट्रपति की सरकार पर आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया गया और गिरफ्तार किया गया।
छोटे-मोटे अपराधी और निर्दोष लोग।
इन्हीं महीनों के दौरान वीपी का पहली बार सामना हुआ।
मुलायम सिंह यादव, जो उस समय उत्तर प्रदेश में विपक्षी लोक दल के नेता थे।
यादव इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित थे क्योंकि उनमें से बड़ी संख्या में लोग
मारे गए लोगों में ओबीसी और दलित शामिल थे।
28 जून 1982 को—सी.एस.पी. सिंह की हत्या के तीन महीने बाद—
एक और भयावह घटना में दस यादवों और छह दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
एपिसोड। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस

बुलाई और
उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की। घोषणा करने के बाद ही उन्होंने
उन्होंने राज्यपाल सी. पी. एन. सिंह को अपना त्यागपत्र भेजा। उन्होंने ऐसा नहीं किया।
वे इसे वापस लेने के लिए दबाव में आना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी के उच्च कमान से सलाह लिए बिना यह कदम उठाया, जबकि उन्हें पता था कि वे इंदिरा गांधी को आमंत्रित कर सकते हैं।
गांधी जी का क्रोध।
हालांकि उन्होंने अपने इस वादे का पालन किया था कि अगर वे स्थिति से निपट नहीं पाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे।
डाकुओं के खतरे को देखते हुए, वह इतना समझदार था कि स्थिति को समझ सके।
उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उन्हें बदलना तो तय ही था।
राजनीतिक समय की सहज समझ, जो उन्होंने इंदिरा गांधी से सीखी थी, और
परिणामों की जानकारी न होते हुए भी जोखिम उठाने की क्षमता।
यह उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, खासकर बाद के समय में।
वर्षों तक। उन्हीं दिनों में उन्होंने 'त्याग' का महत्व भी सीखा।
अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण। वह पहले ही इसका महत्व समझ चुका था।
सत्ता को राजनीतिक हथियार के रूप में हथियाने के प्रति 'अनिच्छा'।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे ने कुछ हद तक आक्रोश को शांत किया।
जो उसके खिलाफ पनप रहा था। जैसे-जैसे वह राज्य भर में घूमता रहा, उसने
उन्होंने पाया कि इस कदम से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। उच्च पद ग्रहण करने से
अब, कमान संभालने के बाद, उन्हें अपने आप में एक नेता के रूप में देखा जाने लगा था।
उनके इस्तीफे से इंदिरा गांधी नाराज हो गईं, लेकिन पहले की तरह ही,
उसने जल्द ही उसे माफ कर दिया और उसे व्यापार के केंद्र में वापस ले आई।
उन्होंने 29 जनवरी 1983 को मंत्री पद संभाला और उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया।

उनकी मृत्यु से दो महीने पहले, आम चुनाव की तैयारियों के दौरान
जो 1985 की शुरुआत में होने वाले थे, उन्होंने उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी। उपराष्ट्रपति का सितारा एक बार फिर चमक रहा था। लेकिन
अपने राजनीतिक करियर के अगले चरण में, कांग्रेस के वफादार उपराष्ट्रपति पद से उन्हें एक नई दिशा मिलेगी।
कांग्रेस के बागी नेता को उपाध्यक्ष बनने का रास्ता।

सातवीं

स्वतंत्र भारत का राजनीतिक इतिहास शायद अलग होता अगर
1987 में राजीव गांधी और वी.पी. सिंह के बीच कोई अनबन नहीं हुई थी। वीपी ने शायद ऐसा नहीं किया होता।
प्रधानमंत्री बनना और ओबीसी के लिए सकारात्मक कार्रवाई की कहानी
उनके रिश्ते की दिशा अलग हो सकती थी।
घनिष्ठ सौहार्द के दौर के साथ-साथ गहरे अविश्वास और कटुता के दौर भी आए।
जब राजीव गांधी ने 1981 के मध्य में लोकसभा चुनाव लड़ा था।
उत्तर प्रदेश के अमेठी से उपराष्ट्रपति उनके लिए प्रचार करने वहां गए थे। वे मुख्य
उस समय के राज्य मंत्री। 'मैंने उन्हें उसी पर लेटते हुए देखा है।
कांग्रेस नेता एच. आर. भारद्वाज ने याद करते हुए कहा, 'अमेठी के दौरे पर चारपाई पर सवार होकर घूमने का अनुभव।'
राजनीतिज्ञ। 'मुझे यह बात अच्छी तरह याद है। हम अमेठी में चुनाव प्रचार कर रहे थे,
और राजीव को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही थी। हम पास ही एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे।
नहर, जहाँ हम जलपान के लिए रुके थे। समय बहुत कम था।
आधे घंटे के आराम के लिए राजीव और वीपी नहर में डुबकी लगाने गए। लेकिन वहाँ आराम करने के लिए केवल एक ही चारपाई थी। दोनों उस पर लेट गए।
'कच्चा-बनियान नहाकर।'
1970 के दशक में और 1980 के दशक के मध्य तक, वीपी की गांधी-
नेहरू परिवार ने पहले संजय गांधी को, फिर इंदिरा गांधी को और अंत में राजीव गांधी को यह अधिकार दिए।

इस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया था। अपनी हत्या से पहले, इंदिरा ने यह बात कही थी।
उन्हें उम्मीद थी कि वीपी राजीव की मुख्य टीम का हिस्सा बनेंगी। उन्होंने उनकी साफ-सुथरी छवि देखी थी।
नेहरू-गांधी परिवार के प्रति छवि और वफादारी को एक संपत्ति के रूप में देखा जाता है।
उपराष्ट्रपति पहली बार दिसंबर 1984 में राजीव गांधी से नाराज हुए थे।
उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता के खिलाफ अमिताभ बच्चन को मैदान में उतारने का उनका फैसला,
Hemvati Nandan Bahuguna, from the Allahabad parliamentary
निर्वाचन क्षेत्र। धूर्त बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ दी थी।
फरवरी 1977 में जगजीवन राम के साथ जनता पार्टी में शामिल हो गए।
जिसे उन्होंने 1979 में इंदिरा गांधी के साथ फिर से जुड़ने के लिए छोड़ दिया था, जब सरकार का पतन हो गया था।
जनता सरकार के प्रयोग से अलग होकर, उन्होंने 1980 में अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए उससे नाता तोड़ लिया।
पार्टी। उन्हें प्रसिद्ध गढ़वाल उपचुनाव में कांग्रेस ने हराया था।
1981 में, कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली के आरोपों के बीच, सभी के अधीन उपराष्ट्रपति का नेतृत्व।
राजीव के फैसले पर वीपी की नाराजगी तो बस शुरुआत थी।
दोनों के बीच उतार-चढ़ाव भरा रिश्ता। 'एक दिन आधी रात को—यह
यह 1984 के चुनावों से ठीक पहले की बात है—राजीवजी ने मुझे 1, अकबर रोड पर बुलाया था।
एच. आर. भारद्वाज ने बताया कि जैसे ही वह घर में दाखिल हुए, उन्होंने वीपी को बैठे हुए देखा।
वहाँ। उस समय, वीपी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख थे, और उनका काफी प्रभाव था।
राज्य में पार्टी टिकट किसे मिलेगा, इस पर राजीव गांधी की राय को नजरअंदाज करते हुए, उन्होंने उपराष्ट्रपति की बात को भी खारिज कर दिया।

भारद्वाज को अंदर ले गया। अमिताभ बच्चन वहां बैठे थे। 'क्या आप'
'क्या आप उसे जानते हैं?' राजीव ने भारद्वाज से पूछा। 'वह एक अभिनेता है,' भारद्वाज ने जवाब दिया।
लेकिन मैं उसके पिता को जानता था।
Harivansh Rai Bachchan, Amitabh's father, was an eminent Hindi
कवि। नेहरू-गांधी परिवार उनके लंबे समय से मित्र थे।
Bachchans. Sarojini Naidu had first introduced Harivansh Rai and his
1940 के दशक की शुरुआत में आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से उनकी पत्नी तेजी का विवाह हुआ था।
उन्हें 'कवि और कविता' कहा गया था। तेजी बच्चन ने आगे बढ़कर प्रहार किया।
इंदिरा गांधी के साथ उनकी दोस्ती दशकों तक कायम रही। सोनिया
जब गांधी इटली से राजीव से शादी करने आई थीं, तब वे उनके घर पर ही रुकी थीं।
1968 में, बाद में जब राजीव कैम्ब्रिज में थे, तो वे इनके साथ समय बिताने लगे थे।
अमिताभ जब छुट्टियों में घर आए थे। उस समय,
बच्चन परिवार दिल्ली के 13, विलिंगडन क्रिसेंट स्थित मकान में हरिवंश के नाम से रह रहा था।
इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद, 1966 में राय को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। गांधी परिवार 1, सफदरजंग रोड में रहता था।
दोनों घर इतने पास थे कि वे अक्सर मिलते रहते थे।
बच्चन और गांधी परिवार के बेटे एक साथ स्विमिंग पूल में तैरा करते थे।
Rashtrapati Bhavan.
■

राजीव गांधी ने भारद्वाज को अमिताभ बच्चन को लखनऊ ले जाने के लिए कहा था।
लेकिन आपको इसे चुपचाप करना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बहुगुणा के खिलाफ

larhana hain inhe. Par Bahuguna ko pata nahin lagana chahiye.' (We
उन्हें बहुगुणा के खिलाफ खड़ा करना होगा, लेकिन बहुगुणा को जरा भी मौका नहीं मिलना चाहिए।
इस का।)
अमिताभ बच्चन ने चुनाव लड़ने के लिए इसलिए सहमति दी थी ताकि वे 'समर्थन के लिए खड़े रहें'।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव ने भी ऐसा ही किया, हालांकि जैसा कि उन्होंने राजीव को बताया था,
मुझे राजनीति का "p" भी नहीं पता।
भारद्वाज को निर्देश देने के बाद राजीव गांधी पैदल चल पड़े।
उन्हें अपने साथ आगंतुकों के कमरे में ले गए जहाँ वी. पी. सिंह उनका इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने 1 सितंबर 1984 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला था।
उन्नीस महीने तक वाणिज्य मंत्री रहने के दौरान, मुझे इस बात की चिंता थी कि...
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की संभावनाओं को देखते हुए, इंदिरा गांधी ने उन्हें यूपी भेजा था।
वहां पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए। राजीव बच्चन की स्थिति मजबूत करना चाहते थे।
इलाहाबाद से तुरंत उम्मीदवारी पेश की गई। लेकिन कांग्रेस का टिकट पहले ही दिया जा चुका था।
यह पहले ही के.पी. तिवारी को दिया जा चुका था, जो वी.पी. सिंह के अनुयायी थे।
किसी भी राजनेता के लिए अपनी हार से ज्यादा अप्रिय कुछ नहीं होता।
अपने निर्वाचन क्षेत्र पर पकड़ बनाए रखने के मामले में, इंदिरा गांधी ने वीपी को 1980 में उपराष्ट्रपति पद की उपाधि दी थी।
उन्होंने इलाहाबाद से कांग्रेस का टिकट लिया था। उन्होंने एच.एन. की तुलना में उन्हें प्राथमिकता दी थी।
बहुगुणा। उसके बाद, वीपी ने इलाहाबाद को अपना गढ़ मान लिया था। मांडा, का
जिस राज्य का वह राजा था, वह इलाहाबाद से मात्र 70 किलोमीटर दूर था। वीपी के

पास
यह ज्ञात था कि इस बार इलाहाबाद में बहुगुणा एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित होगा।
लेकिन उन्हें तिवारी पर भरोसा था; उन्होंने इलाहाबाद से जीत हासिल की थी जब वीपी
जून में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र खाली कर दिया था।
1980.
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, उपराष्ट्रपति का हर निर्णय निर्णायक होता था।
अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में उनकी बात नहीं मानी गई।
इलाहाबाद—जहां इसकी सबसे ज्यादा अहमियत थी।
उस रात, उपराष्ट्रपति ने ज्यादा कुछ नहीं कहा।

उन्होंने राजीव गांधी से विनम्रतापूर्वक कहा, 'कोई समस्या नहीं है। हम बदलाव कर लेंगे।'
उसे (तिवारी को)।' लेकिन इस फैसले ने उन्हें परेशान कर दिया। तिवारी को मुआवजा देने के लिए,
उन्हें उत्तर प्रदेश मंत्रालय में शामिल करने का निर्णय 'उसी रात' लिया गया था। के.पी.
तिवारी ने अगले दिन शपथ ली। बाद में, उन्हें सदस्य बनाया गया।
अमिताभ के लिए रास्ता बनाने के लिए पुरस्कृत विधानसभा परिषद (एमएलसी)।
बच्चन।
अगली सुबह, अरुण नेहरू, जो 1984 के चुनाव की देखरेख कर रहे थे,
रणनीति के तहत, उन्होंने अमिताभ और जया बच्चन को लखनऊ तक पहुंचाया।
भारद्वाज
वे उनके साथ गए। वे हवाई अड्डे से सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय तक गए।
लखनऊ में निवास।
यह तय किया गया कि बच्चन परिवार इसके बाद इलाहाबाद जाएगा।
गुप्त रूप से।' मकसद एच. एन. बहुगुणा को अचानक पकड़ना था। इसीलिए
अमिताभ बच्चन ने अपना नामांकन पत्र अंतिम क्षण में ही दाखिल किया।

दोपहर 3:30 बजे। नामांकन शाम 4 बजे बंद हो गए। इससे बहुगुणा को कोई समय नहीं मिला।
दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले जाना। वह फंस गया था।
जब अमिताभ बच्चन चुनाव प्रचार के लिए इलाहाबाद पहुंचे,
उत्साह से भरी महिलाओं ने अपनी चुन्नियाँ उस पर फेंक दीं। 'वहाँ 1,785 चुन्नियाँ थीं।'
'फेंक दिए गए,' डी. पी. त्रिपाठी ने मुझे बताया। 'मुझे पता है क्योंकि मैंने उनकी गिनती करवाई थी।'
बच्चन की फिल्मी सितारे वाली शान-शौकत उनकी सभाओं में भारी भीड़ खींच लाती थी। वे
वे राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे। इसी वजह से स्थापित
उत्तर प्रदेश के राजनेता ईर्ष्यालु और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति अकेले नहीं थे।
बच्चन से खतरा महसूस करते हुए, उन्होंने उनके साथ रैलियों को संबोधित करने से परहेज किया;
वह केवल तभी उपस्थित रहने के लिए सहमत हुए जब राजीव चुनाव प्रचार के लिए इलाहाबाद आए।
18 दिसंबर 1984 को बच्चन के लिए। अमिताभ बच्चन ने आगे चलकर...
बहुगुणा को हराकर, उन्होंने डाले गए वोटों का 68 प्रतिशत प्राप्त किया।
इसके बाद, वीपी को लगा कि उन्हें 'इलाहाबाद से निर्वासित' कर दिया गया है।
उसने जिस शब्द का प्रयोग किया वह था 'बेदखल'। धीरे-धीरे उसके पास बहुत कम ही बचा था।
इलाहाबाद के मामलों में उनकी कोई राय नहीं थी। वे यह भी तय नहीं कर पाते थे कि कौन क्या होगा।
टेलीफोन सलाहकार समिति या किसी अन्य सरकारी निकाय में।
'तुम मेरे लिए भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर रहे हो,' उसने अरुण से शिकायत की।
नेहरू। 'भूल जाओ', नेहरू ने उपराष्ट्रपति की चिंताओं को हमेशा की तरह हाथ हिलाकर खारिज कर दिया।
उसके हाथ से। 'हमें पहले इन (विपक्षी) लोगों को हराना होगा।'

अरुण नेहरू की रणनीति—अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को मैदान में उतारना।
against H. N. Bahuguna and Madhavrao Scindia against Atal Bihari
ग्वालियर में वाजपेयी का शासन कारगर रहा। विपक्ष के बड़े नेता भी सफल रहे।
1984 के चुनाव में पराजित हुए। (वैसे, बच्चन का कार्यकाल
राजनीति में उनका करियर अल्पकालिक रहा; एक उत्साहपूर्ण शुरुआत के बाद, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा करना शुरू कर दिया और उनके मतदाता जल्द ही उनसे निराश हो गए।
कुछ वर्षों बाद, 1987 के मध्य में, आरोपों के बाद उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया।
उसके भाई अजीतभ के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था। और मांडा के राजा को
(इलाहाबाद में अपनी अहमियत फिर से हासिल करना।)
दिसंबर 1984 में, राजीव गांधी ने वी. पी. सिंह को सबसे बड़ा काम सौंपा।
उनका राजनीतिक करियर, जो आगे चलकर उनके लिए एक लॉन्चपैड बनने वाला था।
बड़ी बातें। राजीव गांधी ने अपने नए कार्यकाल में उपराष्ट्रपति को वित्त मंत्री नियुक्त किया।
प्रणब मुखर्जी जैसे अनुभवी व्यक्ति की जगह मंत्रिमंडल में नए सदस्य आए। राजीव गांधी को उन पर भरोसा नहीं था।
मुखर्जी की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, जिनका मैंने विस्तार से वर्णन किया है,
पिछले अध्याय में। नए प्रधानमंत्री एक ऐसा चेहरा भी चाहते थे जो
अतीत से एक विराम। उन्होंने पत्रकार एम. जे. अकबर से कहा: 'वित्त
मंत्री को बहुत सख्त होना पड़ता है... मुझे नहीं लगता कि वह (मुखर्जी) सख्त थे।
बस बहुत हो गया।' वीपी राजीव की उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त निकला।
वी. पी. सिंह द्वारा वित्त मंत्री के रूप में 1985 में पेश किया गया पहला बजट का स्वागत किया गया।
उद्योग और व्यापार जगत के लिए यह एक बड़ी राहत की बात थी। इंदिरा गांधी के बाद यह उनके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया।
गांधी की समाजवादी नीतियों के कारण, वे उपराष्ट्रपति को दिलचस्पी से देखने लगे।

नए वित्त मंत्री ने आयकर और संपत्ति कर की दरों में कमी की थी।
संपत्ति कर समाप्त कर दिया, आयकर छूट सीमा बढ़ा दी और इस पर विचार किया।
कई अन्य बाजार-अनुकूल उपाय। कुछ कॉर्पोरेट नेताओं ने इनकी सराहना की।
इसे 'स्वतंत्र भारत में अब तक का सर्वश्रेष्ठ' बताया गया। हालाँकि, उनकी शुरुआती
उनके प्रति उत्साह कम होने लगा, जब नए वित्त मंत्री ने पदभार संभाला।
आर्थिक अपराधियों और शीर्ष उद्योगपतियों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी।
कथित तौर पर अनुचित व्यापारिक प्रथाओं में शामिल होने का आरोप है।
जब उपराष्ट्रपति ने बड़े व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो उन्होंने अपने भरोसेमंद लोगों को यह बात बताई।
राजस्व खुफिया विभाग और आपातकालीन विभाग में कोई भी नहीं था
पवित्र। उन्होंने विनोद पांडे को राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया था और
भूरे लाल को ईडी का प्रमुख नियुक्त किया गया।
वीपी को लाल के बारे में तब पता चला था जब उसने उसकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे, क्योंकि
इलाहाबाद के कलेक्टर। इंदिरा गांधी को 1978 में जेल भेजा गया था और उपराष्ट्रपति
कई अन्य लोगों के साथ उन्होंने भी अपनी एकजुटता दिखाने के लिए गिरफ्तारी स्वीकार की थी।
उसे। पांडे और लाल दोनों ईमानदार थे—और उपराष्ट्रपति के प्रति वफादार थे। वह जानता था कि
उन पर भरोसा किया जा सकता था। बुलडॉग जैसे स्वभाव वाले भूरे लाल ने बड़े व्यवसायों को निशाना बनाया।
बिना किसी डर के। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि उन्हें एक ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए।
सरकार और राजा (उपराष्ट्रपति) ने इसे गंभीरता से लिया,' लाल ने कहा। 'अगर आप
आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए गंभीरता से कदम उठाए जाने के बाद, सूचनाओं का प्रवाह शुरू हो गया।
अपने आप ही। यहां तक कि परिवार के सदस्यों ने भी हमें (के खिलाफ) जानकारी दी।

गलत रास्ते पर चलने वाले व्यापारियों)।
वीपी बार-बार पांडे से 'बड़ी मछली पकड़ने' का आग्रह करते थे। पांडे
वह अपने कार्यालय में मछली की तस्वीर टांगा करता था। हर बार ऐसा होने पर
बातचीत के बाद, वह अपने कार्यालय में वापस आता और एक बड़ी मछली का चित्र बनाता।
उसके द्वारा पहले बनाए गए चित्र के आसपास।
सबसे पहले, वीपी ने उद्योगवार छापेमारी की - जिसकी शुरुआत रियल एस्टेट से हुई।
पहले विकासकर्ता आए। फिर आभूषण और हीरा व्यापारी आए। इसके बाद,
बॉलीवुड निर्माताओं में एन. एन. सिप्पी और सुभाष जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
घई समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। और यह सिलसिला चलता रहा। कई बड़े व्यवसायी पकड़े गए।
अखबारों के पहले पन्नों पर उनके नाम गलत कारणों से छपते हैं।
वित्त मंत्री के संदिग्ध व्यापारिक सौदों के खिलाफ अभियान के चलते और
कर चोरी में तेजी आई।
यह सिलसिला पूरे 1985 तक चलता रहा। जब इसके बारे में पूछा गया, तो उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया।
रहस्यमय ढंग से, 'मैंने तो बस इग्निशन चालू किया है।'
6 दिसंबर 1985 को, सुबह तड़के, भूरे लाल
और उनकी टीम ने बयासी वर्षीय उद्योगपति के घर पर छापा मारा।
एस. एल. किर्लोस्कर। वे उसे पुलिस स्टेशन ले गए। उससे पूछताछ की गई।
यह सिलसिला अठारह घंटे तक चला। इस गिरफ्तारी से पूरे देश में सदमे की लहर फैल गई।
वित्तीय जगत। एक अन्य प्रमुख व्यापारिक दिग्गज, ललित थापर,
थापर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को कथित विदेशी मुद्रा के आरोप में रात 1 बजे गिरफ्तार किया गया।
उनकी कंपनियों द्वारा विनिमय नियमों का उल्लंघन। दिल्ली में बेहतर संपर्कों के कारण, उनके
गिरफ्तारी से संसद में हलचल मच गई। इस बार तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी एक
वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, थापर

उन्होंने माफी मांगी और अपने ऊपर लगे अधिकांश आरोपों को स्वीकार किया।
वापसी पर, ईडी ने उनके खिलाफ आपराधिक आरोप वापस लेने पर सहमति जताई।
अन्य
जिन प्रमुख औद्योगिक घरानों पर कार्रवाई की गई उनमें बजाज ऑटो भी शामिल था।
वोल्टास और बाटा। कटघरे में खड़े कई लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।
इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन, आदि शामिल थे।
बिलिंग और ओवर-इनवॉइसिंग, बेनामी शेयरों का अधिग्रहण, इनसाइडर ट्रेडिंग,
और कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर जनता को धोखा देना।
वीपी अब और भी बड़े शिकार को निशाना बना रहा था। और फिर वह उनके पीछे पड़ गया।
उनमें से सबसे बड़ी कंपनियों में से एक - रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी शुरुआत धीरूभाई ने की थी।
अंबानी ने 1967 में फंड जुटाने के लिए दोनों तरह के शेयर जारी किए थे।
खुदरा निवेशकों के लिए परिवर्तनीय और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (पर)
अलग-अलग ब्याज दरें)। बाद में, इसे वित्त मंत्रालय से विशेष अनुमति मिल गई।
मंत्रालय को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर को भी शेयरों में परिवर्तित करना होगा। 10 तारीख को
जून 1986 में, उपराष्ट्रपति ने 'गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों के सभी रूपांतरणों' पर प्रतिबंध लगा दिया।
शेयरों'। रिलायंस ने हाल ही में इस तरह के डिबेंचर की दो नई श्रृंखलाएं ('ई' और 'एफ' श्रृंखला) जारी की थीं, जिनके बारे में बाजार को उम्मीद थी कि वे
पहले की तरह परिवर्तित होने पर, इसके शेयर की कीमत में गिरावट आई। वीपी
साथ ही रिलायंस की मदद करने में बैंकों की भूमिका की जांच का भी आदेश दिया गया।
उनके कुछ मंत्रिमंडल सहयोगी उनसे बेहद नाराज थे। एन. डी. तिवारी
had once remarked in disgust, ‘Aisa shaneechar bitha diya hai sir par
(उन्होंने हम पर किस तरह का राक्षस थोप दिया है?)’ वीपी, उन्होंने आरोप लगाया,
जिससे देश के औद्योगीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है।

आरंभ में, राजीव गांधी ने वी. पी. सिंह को कार्रवाई करने की पूरी छूट दी थी।
रिलायंस, हालांकि उनकी मां के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान धीरूभाई
अंबानी को हमेशा से पसंद किया जाता रहा था। एक कहानी जो अक्सर देखने को मिलती थी।
1980 के दशक के उत्तरार्ध में कई दौर चले और ये देश की राजनीति का हिस्सा बन गए।
लोककथाओं के अनुसार, यह एक ऐसी मुलाकात थी जो कथित तौर पर धीरूभाई अंबानी ने की थी।
राजीव अंबानी ने प्रधानमंत्री को बताया कि उनके पास भारी मात्रा में धनराशि है।
राजीव की दिवंगत मां की ओर से, मैं यह जानना चाहता था कि इसका क्या किया जाए।
धन'।
Eventually, V. P. Singh did not raid Dhirubhai Ambani. He had
बयासी वर्षीय व्यक्ति की हिरासत को लेकर पहले ही काफी आलोचनाओं का सामना कर चुके हैं।
किर्लोस्कर—और प्रधानमंत्री का समर्थन खोने लगे थे।
परिणामस्वरूप, उन्होंने भूरे लाल को अंबानी को गिरफ्तार न करने के लिए कहा।
निर्णायक मोड़ तब आया जब लाल ने एक विदेशी जासूस एजेंसी को काम पर रखा।
फेयरफैक्स रिलायंस के विदेशी लेन-देन की जांच करेगा। अमिताभ बच्चन
राजीव गांधी से शिकायत की गई कि फेयरफैक्स की ओर से एजेंट गए थे।
स्विट्जरलैंड में उसके भाई अजीतभ से पूछताछ करें, जहां उसने एक
घर। वीपी ने कहा कि ये फर्जी एजेंट थे जो राजीव की नजरों में उन्हें बदनाम करने के लिए भेजे गए थे।
प्रधानमंत्री के दोस्तों ने उन्हें बताया कि उपराष्ट्रपति फेयरफैक्स एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे।
राजीव पर नजर रखने के लिए।
फेयरफैक्स की नियुक्ति से संसद में हंगामा मच गया।
वी. पी. सिंह और कांग्रेसियों ने सवाल उठाया कि वित्त मंत्रालय ऐसा कैसे कर सकता

है।
उन्होंने एक विदेशी जासूस एजेंसी को काम पर रखा। उन्होंने पूछा कि इसका खर्च कौन उठा रहा है?
एजेंसी? उन्होंने उपराष्ट्रपति को गद्दार और सीआईए एजेंट कहा।
बाद में, 1989 में, कांग्रेस पार्टी ने वी. पी. सिंह पर आरोप लगाया।
अपने बेटे अजय प्रताप के नाम पर विदेश में एक अवैध खाता रखना
सेंट किट्स में सिंह। दस्तावेज़ जाली निकला।
उन हफ्तों में सरकार का भ्रष्ट चाल विभाग काफी सक्रिय था।
'फेयरफैक्स' और 'सेंट किट्स' इस घटनाक्रम के प्रतीक बन गए।
राजीव गांधी और वी. पी. सिंह के बीच।
इसी दौरान वीपी के प्रति राजीव के रवैये में बदलाव आया।
बदलाव। सितंबर 1986 तक, वीपी को छापों के लिए राजीव का समर्थन प्राप्त था।
हालांकि, प्रधानमंत्री अब उतने उत्साहित नहीं थे
जैसा कि वह कभी बड़े व्यवसायों के पीछे जाने के बारे में था, उसने अपने
वित्त मंत्री को 'सख्त' रुख अपनाना होगा, राजीव गांधी को उन्हें यह बताने में कठिनाई हो रही थी।
call it off. At one point, Rajiv told VP, 'Jitna soft kar sakte ho karo
(जितना हो सके, प्रभाव को कम करने की कोशिश करें।)
VP replied, 'Yeh jail maen nahin hain, kya itna kam soft hai (That
ये लोग जेल में नहीं हैं, क्या यह काफी नरम रुख नहीं है?
17 सितंबर 1986 को राजीव गांधी ने एफआईसीसी की एक बैठक को संबोधित किया।
कलकत्ता। आक्रोशित उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री का सामना किया और शिकायत दर्ज कराई।
उन्हें उनके वित्त मंत्री द्वारा अपमानित किया जा रहा था। एफआईसीआई अध्यक्ष
प्रधानमंत्री के साथ मंच पर बैठे रामा प्रसाद गोयनका ने कहा कि...
देश में 'छापेमारी का राज' शुरू हो चुका था। राजीव ने गोयनका का खंडन नहीं किया।

इसके बजाय, बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एल. एम. की गिरफ्तारी...
थापर ने 'मेरे दिशानिर्देशों के अनुसार' काम नहीं किया था। उनकी अप्रत्यक्ष निंदा...
वित्त मंत्रालय की खबर मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित हुई।
उस समय वी. पी. सिंह देश में नहीं थे। वे उरुग्वे में थे।
एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में वैश्विक व्यापार बैठक में भाग लेना
प्रतिनिधिमंडल। अखबारों ने जनरल में उनकी भूमिका की प्रशंसा की थी।
पुंटा डेल एस्टे में टैरिफ और व्यापार समझौते (जीएटीटी) पर वार्ता -
वैश्विक दक्षिण के लिए जीत हासिल करने के बाद, 'बिना किसी को पराजित किए'
उत्तर की ओर। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को कलकत्ता में घटी घटनाओं की जानकारी मिली,
वह तुरंत भारत लौट आए। वे तुरंत राजीव गांधी से मिलने गए—और
उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की। राजीव ने उन्हें शांत किया। उनके पास कुछ भी नहीं था।
उन्होंने कहा, "जब मैंने यह टिप्पणी की थी, तब मुझे याद आया।"
हालांकि, व्यापारिक समूहों ने राजीव पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने बताया
प्रधानमंत्री और उनके वित्त मंत्री नियंत्रण से बाहर हो रहे थे।
आठवीं

1985 में ही वी. पी. सिंह को यह संभावना नजर आने लगी थी कि वे
सोम पाल ने टिप्पणी की, 'प्रधान मंत्री।'
मुझे लगता है कि जब वह प्रमुख थे तब भी उनके मन में यह संभावना आई थी।
उत्तर प्रदेश के मंत्री,' देवेंद्र द्विवेदी ने मुझे बताया। छापों और उनके
भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के दौरान, कई लोगों को संदेह था कि उपराष्ट्रपति ने शुरुआत कर दी थी...
उन्होंने 1985 के अंत तक शीर्ष पद के लिए खुद को तैयार किया।
सितंबर 1985 में, इम्प्रिंट पत्रिका ने वी पर एक लेख प्रकाशित करने का निर्णय लिया।

पी. सिंह। संपादक आर.वी. पंडित ने अमृता शाह को उन पर एक लेख लिखने के लिए नियुक्त किया था। पत्रिका के मुखपृष्ठ पर उनकी एक आकर्षक तस्वीर छपी थी। जिसमें वे महात्मा गांधी से मिलते-जुलते दिखते थे। 'उनका संयम,
सोम पाल के अनुसार, रचना और अभिव्यक्ति बिल्कुल सही थी। (वीपी)
यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किए गए कि अमृता शाह को सभी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके।
उसे जो जानकारी चाहिए थी, वह उसने सोम पाल से पश्चिमी द्वीप समूह तक उसके साथ चलने को कहा।
उत्तर प्रदेश में, जहाँ उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, ताकि वह वहाँ के लोगों से मिल सके।
गांवों। उनकी प्रोफाइल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल और उनके द्वारा
वित्त मंत्री ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में वर्णित किया जिन पर भरोसा किया जा सकता है।
भारत की जनता। इस लेख का व्यापक प्रभाव पड़ा। कई अन्य लेखों का भी प्रभाव पड़ा।
मीडिया में उनके बारे में खबरें आने लगीं।
‘यह उपराष्ट्रपति का जनसंपर्क का पहला प्रयास था। इसके बाद जो हुआ वह कोई नई बात नहीं थी।’
दुर्घटना।'
■

1985 और 1986 के बाकी बचे समय में छापों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ वीपी की संख्या भी बढ़ती गई।
लोकप्रियता। लोग अब उन्हें एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे जो चुनौतियों का सामना कर रहा था।
भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों के बीच एक ऐसा नेता जो साहसिक निर्णय लेने में सक्षम हो।
प्रधानमंत्री ही अपनी पकड़ खो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे

बेईमानों को संरक्षण देना। वी. पी. सिंह अब राजीव गांधी की जगह ले रहे थे।
भारतीय राजनीति के मिस्टर क्लीन। अगस्त 1986 में, इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
सर्वेक्षण से पता चला कि वी. पी. सिंह अब राजीव से बस थोड़ा ही पीछे हैं।
लोकप्रियता चार्ट में गांधीजी। वित्त मंत्री के रूप में उनके दो वर्षों के दौरान,
वीपी ने 6,000 छापे मारे थे, 100,000 परिसरों की तलाशी ली थी, और
लगभग पांच लाख लोगों से पूछताछ की गई। इस अवधि के दौरान, प्रकृति में बदलाव आया।
वित्त मंत्रालय में भी बदलाव आया था—यह विशुद्ध रूप से एक मंत्रालय होने से बदल गया था।
नीति-निर्माण निकाय के रूप में विकसित होकर यह एक ऐसी संस्था बन गई थी जो यह चाहती थी कि...
आर्थिक अपराधियों को दंडित करें।
■

क्वात्रोची ही मेरे मतभेदों के कारणों में से एक था।
वीपी ने खुलासा किया, 'राजीव।' उनका इशारा इटली के ओटावियो क्वात्रोची की ओर था।
दिल्ली में रहने वाला वह व्यवसायी जो बाद में बोफोर्स कांड में फंसा।
घोटाले। गांधी परिवार के मित्र होने के नाते, क्वात्रोची घोटाले करने के लिए प्रवृत्त थे।
सरकारी हलकों में उनका काफी दबदबा था। 'वह मुझसे एक मांग रहे थे।'
'नियुक्ति,' वीपी ने कहा। 'मैं इसे नहीं दे रहा था। मैंने सोचा था कि अगर कोई नियुक्ति होती है तो...'
निविदा, मैं लोगों को कॉल कर सकता हूँ... फिर राजीव ने मुझे मिलने के लिए कहा।
मैंने हाँ कह दी। उसने मुझे एक ज्ञापन दिया। मैंने उसे प्रोसेस करवा लिया... बनता नहीं था (लेकिन मैं)
उसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया जा सका। (मैंने कुछ नहीं किया।)
राजीव ने मुझे (फिर से) बुलवाया और कहा, “अब यह (परियोजना) तुम्हारे पास है।”

इन दृष्टिकोणों से जांच की गई।" उन्होंने पांच से छह बिंदु बताए...।
ये सभी बिंदु वे थे जिनका उपयोग क्वात्रोची ने अपने लेखन में किया था।
प्रतिनिधित्व।
मैंने इसे दोबारा प्रोसेस करवाया। फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ।
वित्त विभाग की सिफारिश पर... मैंने फाइल भेज दी।
प्रधानमंत्री। इसे किसी और को दिया गया, मंजूरी मिली और भेज दिया गया।
वापस।' क्वात्रोची ने परियोजना का अनुबंध हासिल कर लिया, जिससे अन्य लोगों को दरकिनार कर दिया गया।
वित्त मंत्रालय।
'या तो आप मुझ पर भरोसा करें कि मैं इन परियोजनाओं को संभाल सकता हूँ,'
असंतुष्ट उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से शिकायत की, 'वरना मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है।'
पर।'
इस समय, उपराष्ट्रपति के कुछ शुभचिंतकों ने उन्हें आगाह किया कि प्रधानमंत्री का...
उनके प्रति रवैया बदल रहा था। सितंबर 1986 में ही सोम पाल
उन्होंने उपराष्ट्रपति को चेतावनी दी थी कि उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाया जा सकता है।
सोम पाल ने याद करते हुए कहा, 'मैं उनसे मिलने गया था। मैंने उन्हें एक बात बताई।'
मैंने बॉम्बे में जो बातचीत सुनी थी, उससे पता चला कि वह बाहर होगा।
एक हफ्ते के अंदर।
लेकिन वीपी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने पाल को आश्वस्त करते हुए कहा, 'नहीं, इसमें कुछ भी चिंता की बात नहीं है।'
चिंता... मुझे राजीव गांधी पर पूरा भरोसा है, उन्हें सब कुछ पता है।
इसके बारे में (मैं क्या कर रहा हूँ)।
दिसंबर 1986 की शुरुआत में, सोम पाल ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति को चेतावनी दी। 'मैंने सुना था
पाल ने कहा, 'राजनीतिक हलकों में यह चर्चा थी कि उन्हें एक सप्ताह के भीतर पद से हटा दिया जाएगा।'
इस बार उनके चेहरे पर चिंता के लक्षण दिखाई दे रहे थे।
उपराष्ट्रपति ने बचाव करते हुए जवाब दिया, 'मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं।'

‘मुझे जो भी दिया जाएगा, मैं वही करूंगा।’
21 जनवरी 1987 को वी. पी. सिंह को वित्त विभाग से हटा दिया गया।
‘मुझे रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत है,’ राजीव ने कहा।
गांधी ने वी. पी. सिंह को समझाया। हालाँकि उनके अधीन रक्षाकर्मी थे, फिर भी
उन्होंने कहा कि उन्हें ‘एक पूर्णकालिक मंत्री’ चाहिए और वे रक्षा का जिम्मा ‘किसी और पर’ नहीं छोड़ सकते।
जूनियर्स’। उनका इशारा अरुण सिंह की ओर था, जो उनके पुराने दोस्त थे।
जो रक्षा राज्य मंत्री थे। इस समय राजीव भी नाखुश थे।
सेना प्रमुख जनरल के. सुंदरजी द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ,
अरुण सिंह एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान, ऑपरेशन ब्रासस्टैक्स को विस्तार देने में लगे हुए हैं।
18 नवंबर 1986 को राजस्थान में शुरू हुए अभ्यास के कारण सीमा पर पाकिस्तान के साथ गतिरोध उत्पन्न हो गया था और दोनों पक्ष लगभग आमने-सामने आ गए थे।
देशों को युद्ध की ओर धकेलना।
राजीव गांधी ने सोचा था कि वी. पी. सिंह का तबादला करके वे
एक साथ दो समस्याओं का समाधान करना—वीपी को वित्त विभाग से बाहर निकालना जहाँ वह पहले थे
उन्होंने कई प्रभावशाली व्यापारियों को नाराज कर दिया—जिनमें से कुछ उनके करीबी थे।
दोस्तों—और उसे रक्षा का प्रभार सौंपना जहाँ वह निगरानी कर सके
अरुण सिंह और जनरल सुंदरजी की कार्रवाइयां। हालांकि प्रधानमंत्री ने कोशिश की।
इस तबादले को सकारात्मक रूप देने के लिए, वित्त मंत्रालय से उनका बाहर निकलना मांडा के राजा को डंक मारा।
■

24 जनवरी 1987 को दिल्ली में एक उज्ज्वल, धूप वाला सर्दियों का दिन था, लेकिन वी.पी.

सिंह अपने घर में बिल्कुल अकेले बैठे थे। बाहर उमड़ने वाली भीड़ का उन्हें कोई आभास नहीं था।
बगीचे में टहलें, या बरामदे में बैठकर किसी से बात करने का इंतज़ार करें।
वह लापता था। सांसदों को तुरंत आभास हो गया कि वह पार्टी से बाहर हो गया है।
कृपा। उन्हें तीन दिन पहले ही वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया था।
जब सोम पाल उस सुबह उनसे मिलने गए तो वीपी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, 'अये!'
सोमपालजी, आप जो कह रहे थे, उसका एक अंश सच हो गया है।
Som Pal told him, 'Khapaenge aap yehan bhi nahin (You won't fit
रक्षा में भी)। पाल और वीपी दोनों जानते थे कि रक्षा
यह संस्था भी भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी, शुरुआत से ही।
सैनिकों की भर्ती से लेकर जनरलों की पदोन्नति तक, खरीद से लेकर...
खर्च। दोनों जानते थे कि उपराष्ट्रपति अपना 'अभियान' बंद नहीं करने वाले थे।
भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन उस दिन, वीपी सतर्क थे, 'देखेंगे। अभी तो'
हम मशीन को स्टडी कर रहे हैं (हम देखेंगे। फिलहाल मैं हूं
इस मशीन का अध्ययन करना)। बिना अध्ययन किए, अगर कील पेच हाथ को लग
गया तो गढ़बर हो जाएगी (इसके मूल सिद्धांतों का अध्ययन किए बिना, अगर मैं)
गलती से भी गलत जगह छू लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा...।
मैं जो भी करूंगा, वह अध्ययन करने के बाद ही करूंगा और उसे अपने तरीके से करूंगा।
Chahe kuch bhi ho, hum to apne tareeke se kaam karenge (No matter
कोई कुछ भी कहे, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है।
वी. पी. सिंह को जल्द ही हमला करने का मौका मिल गया। यह मौका तब आया जब...
नौसेना द्वारा जर्मनी से एचडीडब्ल्यू पनडुब्बियों की खरीद। उपराष्ट्रपति ने आदेश दिया।
सौदे की जांच। उन्हें भारतीय पक्ष से एक टेलीग्राम मिला था।
जर्मनी में राजदूत ने कहा कि एचडीडब्ल्यू पनडुब्बियों की कीमत संभव नहीं हो सकती।

इसे कम किया जा सकता है। राजदूत ने कहा—और उन्होंने एक जर्मन अधिकारी का हवाला दिया—कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि 7 प्रतिशत का भारी कमीशन है।

एक भारतीय एजेंट को भुगतान किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति ने रक्षा सचिव एस. के. से इस बारे में सवाल किया।

भटनागर ने इसके बारे में बताया। भटनागर ने उसे बताया कि एक बड़ा व्यापारिक परिवार था।

इस सौदे के पीछे। वीपी ने सारी जानकारी फाइल में दर्ज कर ली और एक आदेश जारी किया।

विभागीय जांच। उन्होंने इस बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की कि उनके पास क्या था।

हो गया। फिर से संसद में हंगामा मच गया। उपराष्ट्रपति भी उपस्थित थे।

जब उत्तेजित सांसदों ने अधिक जानकारी की मांग की तो उन्होंने सदन में इसकी पुष्टि की।

उन्हें बताया गया कि उनके मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी किया है।

कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति को अपने कार्यालय में बुलाया—यह

यह घटना 9 अप्रैल 1987 को हुई थी। राजीव गांधी बेहद क्रोधित थे। 'उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था।'

वीपी ने याद करते हुए पूछा, 'आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो टेलीग्राम मिला है वह सही है?'

'सही है?' राजीव ने पूछा।

‘आपको कैसे पता कि यह गलत है?’ वीपी ने जवाब दिया। ‘यह एक के माध्यम से आया है’

यह एक गुप्त प्रक्रिया थी, जिसका डिकोडिंग कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और रक्षा मंत्रालय में किया गया था।

मंत्रालय। यह एक गुप्त चैनल के माध्यम से आया है, संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

वीपी ने आगे कहा, 'यह अस्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर यह सही नहीं भी है, तो भी एक जांच होनी चाहिए।'

वह (सच) उजागर करेगा, और राजदूत इसका खंडन करेगा। यदि ऐसा है तो
यह गलत है, यह एक गंभीर मामला भी है और इसकी जांच होनी चाहिए।'
'जांच का नतीजा क्या होगा?' राजीव ने चिढ़कर वीपी से पूछा।
'बिचौलियों को शामिल न करना आपकी नीति है,' वीपी ने शांत भाव से जवाब दिया।
अक्टूबर 1985 में, राजीव गांधी ने उत्साहपूर्वक शहर को स्वच्छ बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर यह कार्य शुरू किया।
अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद, सिस्टम ने रक्षा एजेंटों पर प्रतिबंध की घोषणा की थी।
रक्षा सौदों की बातचीत में। तब तक वैश्विक रक्षा कंपनियां
वे भारतीय एजेंटों के माध्यम से काम करते थे, जिन्हें बदले में बड़ा कमीशन मिलता था।
और इससे यह प्रभावित होता कि ठेके किसे मिलेंगे। राजीव ने आदेश दिया कि तब से सरकार सीधे तौर पर हथियारों के सौदों पर बातचीत करेगी।
राजीव गांधी और वी. पी. सिंह के बीच मतभेद तब शुरू हुआ जब...
11 अप्रैल 1987। दिल्ली में शाम ढल चुकी थी। दिन भर उपराष्ट्रपति संदेश छोड़ते रहे थे।
प्रधानमंत्री आवास पर राजीव गांधी से मिलने का समय मांगा। लेकिन उन्हें
कोई जवाब नहीं मिला। किसी वरिष्ठ मंत्री के लिए अनुरोध करना असामान्य बात थी।
प्रधानमंत्री से आपातकालीन बैठक हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
मौन अपने आप में एक संदेश था। फिर उपराष्ट्रपति बैठ गए और एक पत्र लिखने लगे।
रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शाम ढलती चली गई लेकिन अभी भी कोई नतीजा नहीं निकला।
रेस कोर्स रोड से खबर मिली है।
अंत में, उपराष्ट्रपति ने अपने बेटे अभय को उन्हें प्रधानमंत्री आवास तक ले जाने के लिए कहा।
अभय, जो एक चिकित्सक हैं, उन्हें अपनी मारुति 800 ओमनी में वहां ले गए।
अपनी छवि को लेकर सचेत उपराष्ट्रपति अपने आधिकारिक वाहन से इस्तीफा सौंपने नहीं जाना चाहते थे, जबकि राजीव का घर उनसे सिर्फ तीन मिनट की दूरी पर था।

वह रेस कोर्स रोड पर 7 बजे घर से बाहर थे। वह घर पर नहीं थे। वीपी ने अपना घर छोड़ दिया था।
एम. एल. फोतेदार के साथ त्यागपत्र लेकर वापस कार की ओर चल दिए। वीपी और उसका बेटा चुपचाप गाड़ी चलाकर घर लौट आया। बाद में उसी शाम उसने सुना कि प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था।
■

दिल्ली से सत्तर किलोमीटर दूर, एक पारिवारिक बहस चल रही थी।
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित छोटे से कस्बे बरौत में प्रगति हुई। यह घटना अगले दिन की थी।
उपराष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया—और अखबारों में उनके इस्तीफे की खबर छाई हुई थी।
जब हमें पता चला कि वी. पी. सिंह ने
सोम पाल ने याद करते हुए कहा, 'मैंने इस्तीफा दे दिया। हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा
मां ने मुझसे कहा, “तुम्हें वी. पी. सिंह के साथ रहना चाहिए।” परिवार
परिषद ने फैसला किया कि सोम पाल को उसी दिन दिल्ली जाना चाहिए और
उपराष्ट्रपति से मिलें। अगली सुबह जब वह 1, राजाजी मार्ग पहुंचे, तो वहां
घर में करीब 100 लोग मौजूद थे। लेकिन माहौल कुछ ऐसा था...
शोक का माहौल। कई लोगों ने पूछा, 'राजीव ने (उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार करके) क्या कर दिया है?'
अफसोस जताते हुए अन्य लोगों ने वीपी से कहा, 'आप इतना अच्छा काम कर रहे थे,' और
इसका श्रेय कांग्रेस को मिल रहा था। उपराष्ट्रपति अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं दिखे।
उन्होंने अपने उत्तेजित समर्थकों को शांत करने की कोशिश की। ‘चिंता मत करो। सब ठीक हो जाएगा।’
सब ठीक हो जाएगा। राजीव के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हम केवल उनकी देखरेख में

काम करेंगे।
उनके नेतृत्व में।' स्पष्ट रूप से, वीपी को उम्मीद थी कि राजीव के साथ उनके मतभेद दूर हो जाएंगे।
मामला सुलझ जाएगा।
सोम पाल, जो उपराष्ट्रपति को बधाई देने के लिए उनके लिए फूलों की माला लेकर आए थे।
उनके इस्तीफे के फैसले से निराशा हुई। 'अगर आप मेरे अधीन काम करना चाहते थे' उन्होंने उपराष्ट्रपति से पूछा, 'राजीव के नेतृत्व में आपने इस्तीफा क्यों दिया?' उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया, 'मैं चाहता था कि...'
'इस बंधन को तोड़ने के लिए आपको बधाई।' फिर उन्होंने आगे कहा, 'मैं हूँ।'
तुम्हारे साथ।'
वीपी ने कुछ नहीं कहा। 'लेकिन मुझे लगा कि मैंने उनकी आंखों में स्वीकृति देखी।' पाल ने कहा। जब वह बाहर जा रहा था, तभी उपराष्ट्रपति के एक परिचारक, गुलाब ने उसे देखा।
तिवारी दौड़कर उसके पास गया। उसने कहा, 'साहिब आपसे मिलना चाहते हैं।' पाल वापस चला गया।
घर में। वीपी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, 'एक-दो दिन में,
मैं आपसे राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं लखनऊ जा रहा हूँ।
कल, 17 तारीख को मुझसे मिलने आना।
'लखनऊ कौन तुम्हारे साथ जा रहा है?' सोम पाल ने पूछा।
'अगर आ सकते हो तो आओ,' उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया।
जैसा कि बाद में पता चला, वे उसी शाम 6:30 बजे की फ्लाइट से लखनऊ के लिए रवाना हो गए।
शाम की उड़ान। हवाई अड्डे जाते समय, पाल ने वीपी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपने दम पर आगे बढ़ते हुए कहा, 'आप कांग्रेस के भीतर तालमेल नहीं बिठा पाएंगे।'
अभी। आप जितनी जल्दी कांग्रेस से बाहर आ जाएं, उतना ही अच्छा है... ऐसा हो चुका है।
चाहे आप बाहर आएं या वे आपको बाहर निकाल दें, यह बात महत्वहीन हो जाती है।

उपराष्ट्रपति के साथ आए कांग्रेस नेता वी.एन. दीक्षित भी थे।
वह अचंभित हो गया। ‘सोम पालजी, आप राजा साहब को क्या सलाह दे रहे हैं?’
उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा, 'उन्हें कांग्रेस नहीं छोड़नी चाहिए।'
सोम पालजी, आप मुझसे उस संगठन को छोड़ने के लिए कह रहे हैं जिसमें मैं कार्यरत हूँ।
मैंने बीस साल बिताए हैं। मैं इसे इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता हूँ?’ जब वीपी बोल रहे थे,
उसकी आँखें नम हो गईं। दीक्षित ने पाल के हाथ को छूकर उसे रुकने का इशारा किया।
तब तक, उपराष्ट्रपति ने अपने समर्थकों को इस्तीफे का कोई संकेत नहीं दिया था।
कांग्रेस का ख्याल उनके मन में दूर-दूर तक भी नहीं आया था। लेकिन तभी मांडा के राजा ने...
वह अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ की बात बताने का आदी नहीं था।
कर रहा है।
दिल्ली हवाई अड्डे पर उन्होंने कांग्रेस के चार मंत्रियों को देखा।
उत्तर प्रदेश सरकार में किसी ने भी वी.पी. सिंह की ओर देखा तक नहीं।
राज्य परिवहन मंत्री संजय सिंह, जिनकी शादी वीपी की पत्नी से हुई थी।
भतीजी गरिमा ने दूर से ही औपचारिक नमस्कार किया। एक घंटे से भी कम समय में
सप्ताह के दौरान, हवा का रुख भांपने वाले कांग्रेसी सदस्य,
उपराष्ट्रपति को कम महत्व देना।
विमान में वी. पी. सिंह, वी. एन. दीक्षित और संजय सिंह बैठे थे।
पहली पंक्ति में सोम पाल बैठे थे। सोम पाल तीसरी पंक्ति में बैठे थे। उड़ान भरने के बाद वीपी उठ गए।
वह अपनी सीट से उठकर वापस पाल के पास गया और खाली सीट पर बैठ गया।
उसके बगल में। ‘अब क्या किया जाए?’ उसने सोम पाल से पूछा। क्या उपराष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया था?
अगर वह कांग्रेस छोड़ने के बारे में सोच रहे होते, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया होता।
उस दिन सोम पाल से संपर्क किया गया। जल्द ही, पाल पूरी तरह से अपने वाक्पटुता में आ गए। 'तरीका'

आप (कांग्रेस से) कैसे इस्तीफा देते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है... आपको खुद फैसला करना होगा।

चाहे आप 1990 में कांग्रेस को हटाना चाहें या 1995 में। लेकिन अगर आप

अगर आप इसे 1990 में करना चाहते हैं, तो आपको सभी गैर-कांग्रेसी पार्टियों को साथ लाना होगा।

एक ही मंच पर एक साथ।

वी. पी. सिंह को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी।

या फिर उसके प्रति सद्भावना जल्द ही खत्म हो जाएगी। कुछ कहा नहीं जा सकता था।

1995 तक जो घटनाएँ उन्हें प्रभावित कर सकती हैं, उनके बारे में सोम पाल ने बात की।

इस समय भाजपा और वामपंथी दलों द्वारा उपराष्ट्रपति को समर्थन देने की संभावना है।

वीपी ने पाल को दिलचस्पी से देखा। पाल ने ज़ोर देकर कहा कि यह दोनों के लिए संभव था।

उन्हें समर्थन देने के लिए पार्टियों की आवश्यकता थी। हालाँकि उनकी विचारधाराएँ भिन्न थीं, लेकिन उनके प्रभाव क्षेत्र अलग-अलग थे। और, दोनों पार्टियाँ यह समझती हैं कि वे किसी समझौते पर नहीं पहुँच सकतीं।

केंद्र में सत्ता अपने दम पर हासिल की जाए।

हालांकि उन्होंने सोम पाल की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कुछ ही समय में...

सुदूर भविष्य में, उपराष्ट्रपति को ठीक यही करना था—पूरे विपक्ष को एकजुट करना था।

एक साझा मंच पर एक साथ।

■

14 अप्रैल 1987 को, वी. पी. सिंह के रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के तीन दिन बाद,

मंत्री ने बोफोर्स घोटाले का खुलासा किया—यह उपराष्ट्रपति के लिए एक पासपोर्ट बन जाएगा
प्रधान मंत्री पद। जैसा कि पिछले अध्याय में उल्लेख किया गया है, कांग्रेस नेता
एच. आर. भारद्वाज ने मुझे बताया कि उन्हें शक था कि अरुण नेहरू ने जानकारी लीक की थी।
स्वीडिश रेडियो को बोफोर्स की कहानी सुनाई गई।
स्वीडिश प्रसारक ने घोषणा की कि स्वीडिश हथियार
कंपनी ने बिचौलियों को कमीशन का भुगतान किया था, जिनमें भारतीय भी शामिल थे।
155 मिमी पिस्तौल की खरीद के लिए राजनेताओं, अधिकारियों और हथियार डीलरों से बातचीत की गई।
प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बावजूद भारतीय सेना द्वारा हॉवित्जर तोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
आयोगों की प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। उन दिनों और महीनों में
इसके बाद, 'बोफोर्स' वह हथियार बन गया जिसकी जरूरत उपराष्ट्रपति को राजीव गांधी को हराने के लिए थी।
सीधे-सीधे। वह जहाँ भी जाता, बोफोर्स और विदेशी मुद्रा के बारे में बात करता।
राजीव के बयानों के अनुसार, हालांकि वह किसी भी आरोप को साबित नहीं कर सका,
उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा के रूप में वीपी की प्रतिष्ठा बढ़ती गई।
‘इसमें कितना बोफोर्स है (How much Bofors is there in this)?’
जब भी रिश्वत का जरा सा भी संकेत मिलता, लोग उपहासपूर्वक पूछते थे।
हालांकि राजीव गांधी या उनके सदस्यों को जोड़ने वाला कोई सबूत कभी नहीं मिला।
बोफोर्स सौदे में रिश्वतखोरी के कारण उनके तत्काल परिवार को नुकसान पहुंचा।
राजीव की छवि को अपूरणीय क्षति पहुंची है। राजीव ने चाहे कितनी भी ज़ोरदार तरीके से विरोध किया हो, उनकी छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
निर्दोषता का दाग नहीं मिट सका। उपराष्ट्रपति के बाद के महीनों में...
यदि इस्तीफे होते तो काफी उथल-पुथल मच जाती।

■

25 जून 1987 को, आरिफ मोहम्मद खान, जो तब तक इस्तीफा दे चुके थे, ने...
सरकार ने उनके आवास पर एक पार्टी का आयोजन किया। यह वी. पी. सिंह का जन्मदिन था।
और पार्टी उनके सम्मान में आयोजित की गई थी। कई असंतुष्ट कांग्रेस सांसद थे।
उपस्थित थे। वहां कभी शक्तिशाली रहे अरुण नेहरू भी थे, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।
राजीव गांधी द्वारा अक्टूबर में आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
1986 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे वी.सी. शुक्ला भी इस पद पर थे। शुक्ला
राष्ट्रपति ज़ैल सिंह से संपर्क स्थापित करने की अफवाह थी, जिनके बारे में यह अफवाह थी कि वे बर्खास्त कर सकते हैं।
भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रधानमंत्री को पद से हटाने और उनकी जगह किसी और को शपथ दिलाने के लिए
प्रधानमंत्री के प्रति असंतोष देश के भीतर और बाहर दोनों जगह बढ़ रहा था।
पार्टी में और देश में। सरकार से उनके इस्तीफे के बाद,
कई असंतुष्ट कांग्रेसी नेता उपराष्ट्रपति के घटनाक्रम को दिलचस्पी से देखने लगे थे।
अगली चालें।
पार्टी में कई मीडियाकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया था। हममें से कई लोग
खान के आवास पर, जो 3, सुनेहरी बाग रोड पर स्थित है, यह उम्मीद करते हुए पहुंचे कि उन्हें वहां कुछ मिलेगा।
इतने सारे असंतुष्ट कांग्रेसी सदस्यों की उपस्थिति में यह एक अच्छी कहानी है।
शाम के बाद जो संकेत मिला वह यह था कि वी. पी. सिंह ने
राजीव गांधी के खिलाफ अरुण नेहरू के साथ हाथ मिला लिया। अगले दिन
अखबारों में भी यही कहा गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन 'कौन' की राय जानने के लिए किया गया था।

kitne paani maen hai (To test the waters)'.
मुझे बताया गया था, आपको चाय पार्टी में आना ही होगा। हमें राजा को धक्का देना होगा।
सत्यपाल मलिक ने याद करते हुए कहा, 'एक स्टैंड लेने के लिए।' मलिक, जो कांग्रेस सांसद हैं,
समय आने पर, वे उपराष्ट्रपति अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद के साथ हाथ मिलाएंगे।
खान।
आरिफ मोहम्मद खान और अरुण नेहरू एक साथ मिलकर काम कर रहे थे।
और चाहते थे कि उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अंतिम रूप से संबंध तोड़ लें। हालाँकि
उन्होंने सरकार छोड़ दी थी, उपराष्ट्रपति अभी भी अगले उम्मीदवार को लेकर दुविधा में थे।
उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। राजीव गांधी उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए थे।
अपने युवा मंत्री राजेश पायलट जैसे दूतों के माध्यम से। उससे पहले
राजीव ने सुलह कराने के लिए उपराष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से दो बार मुलाकात भी की।
जब उसने मुझे पहली बार फोन किया, तो मैं यह सोचकर गई कि शायद वह कुछ चाहता हो।
मामलों को सुलझाने के लिए,' वीपी ने याद करते हुए कहा। 'मैंने राजीव से कहा, अब हम नहीं हैं
हम प्रधानमंत्री और उनके मंत्री के रूप में बात कर रहे हैं। हम राजीव और विश्वनाथ के रूप में बात कर रहे हैं।
मैंने उनसे पूछा, यह क्या है, हर दिन कल्पनाथ राय और के.के. तिवारी
यह बयान देना कि मैं सीआईए एजेंट हूं।
Rajiv said, 'Nahin nahin, gussa hai party maen (No, no, there is anger
पार्टी में)। यह उसी की अभिव्यक्ति है।'
'मैंने तुम्हारी माँ के साथ यह मशीन चलाई है,' वीपी ने साफ-साफ कहा। 'मुझे पता है जहां हर नट, बोल्ट और तार जुड़ा हुआ है। के. के. तिवारी और कल्पनाथ

ये लाउडस्पीकर हैं। माइक्रोफोन इसी कार्यालय में लगे हुए हैं।'
'नहीं, नहीं,' राजीव ने कहा। 'मैं उनसे कहूंगा कि कम करो।'
'तुम्हारा मतलब "कुम करो" से क्या है?' वीपी ने गुस्से से कहा। 'अगर मुझे लगता है कि तुम
मेरे साथ खेल खेल रहे हैं... इस तरह से हमारी कोई सच्ची बातचीत नहीं हो सकती... आप मुझे अक्षम मंत्री या निकम्मा पार्टी कार्यकर्ता कह सकते हैं।
वीपी ने आगे कहा, 'लेकिन अगर तुम देश के प्रति मेरे प्रेम को चुनौती देते हो, तो राजीव,
I will dig in and fight. Itihas maen is issue par logon ne sar kata diye. Is
par hum khatam ho jayenge (History has shown that people have given
अगर उनकी देशभक्ति को चुनौती दी जाती है, तो वे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मैं भी ऐसा ही करूंगा।
वही। इसके बाद जो भी होता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वीपी ने आगे कहा, 'अगले दिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि...
मैंने ही राजीव से (समझौता करने के लिए) मिलने का समय मांगा था।
ये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा खेले जा रहे छोटे-मोटे खेल थे।
कुछ दिनों बाद, राजीव ने वीपी को फिर से अपने घर बुलाया। 'ऐसा होना ही चाहिए।'
उपराष्ट्रपति ने याद करते हुए बताया, 'यह रात करीब 11 बजे का समय था।' इस बार प्रधानमंत्री आगे बढ़े।
हमला करते हुए, 'जब इंदिरा गांधी (1977 के चुनाव में) हार गईं, तो आपने उन्हें छोड़ दिया।'
ओर।'
VP replied: 'Jo aap keh rahe hain, dharti phat jaani chahiye (What
आप जो कह रहे हैं वह इतना असत्य है कि धरती फट जानी चाहिए।
हम इंदिराजी से मिलने उनके विलिंगडन क्रिसेंट स्थित घर जाया करते थे।
वीपी को ठेस पहुँचने पर उसने राजीव से कहा, 'संजय तो आसपास था, लेकिन... तुम

नहीं थे।'
आप वहां थे और अब आप मुझे बता रहे हैं कि मैं वहां उसके साथ नहीं था।
राजीव चुप रहा।
उपराष्ट्रपति ने कहा, 'अगर आप (सचमुच) यही सोचते हैं, तो आप इसे इसी रूप में ले सकते हैं।'
विश्वनाथ मर गया है।' वह जाने के लिए खड़ा हो गया।
'नहीं, नहीं, विश्वनाथ,' उसने कहा, 'बैठ जाओ।'
राजीव ने उपराष्ट्रपति से कहा कि कांग्रेस के बिना उनका अस्तित्व भी संभव नहीं है।
तीन महीने के लिए।
'Rajivji, if I can stand firm for three months toh main kharha reh
jaunga. Meri toh problem hi pehle teen maheenae ki hai (Rajivji, if I can
तीन महीने तक दृढ़ रहो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा।
समस्या पहले तीन महीनों की है।' वीपी को पता था कि अगर वह रुका रहा तो
पहले कुछ हफ्तों के दौरान, वह इतनी गति उत्पन्न कर लेगा कि वह
बंद हो गया—और ठीक यही हुआ।
■

15 जुलाई 1987 को बरसात का दिन था जब असंतुष्टों के एक समूह ने
कांग्रेसी नेता एक राजनीतिक सभा को संबोधित करने के लिए हरिद्वार गए।
वे 'स्थिति का जायजा लेना' चाहते थे और देखना चाहते थे कि जनता की प्रतिक्रिया कैसी रहती है।
उन्हें मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति उनके साथ थे। बड़ी संख्या में लोग धैर्यपूर्वक छतरियों के नीचे उनका इंतजार कर रहे थे। आरिफ मोहम्मद खान
उन्होंने राजीव गांधी पर तीखा हमला किया। उपराष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए, इस लड़ाई को 'आर पार की लड़ाई'

का नाम दिया गया है।
(अंत तक लड़ो)'। उस रात आरिफ मोहम्मद खान, अरुण नेहरू और
वी.सी. शुक्ला, ये सभी राजीव गांधी सरकार में पूर्व मंत्री थे।
उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन उपराष्ट्रपति का नाम निष्कासित लोगों की सूची में नहीं था।
जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उन्होंने इसके खिलाफ कड़ा बयान जारी किया।
कांग्रेस उच्च कमान ने बिना सुने ही कार्रवाई कर दी
नेताओं को अपने बचाव में कुछ कहना पड़ा।
राजीव ने उपराष्ट्रपति को निष्कासित न करके रणनीतिक चाल चली थी।
अन्य लोगों से उसका संबंध तोड़ना था। राजीव को उम्मीद थी कि इससे उसे उनसे अलग किया जा सकेगा।
अन्य लोगों को रास्ते से हटा दें तो, कांग्रेस के भीतर उपराष्ट्रपति की स्थिति मजबूत हो जाएगी।
कमजोर हो गया। अगर उसने निष्कासित नेताओं का समर्थन किया, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
उनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाया जा सकता था। राजीव ऐसा नहीं चाहते थे।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए उपराष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो
इससे वह हीरो बन जाएगा। वीपी राजीव की चाल समझ गया था।
उन्होंने उसी रात अरुण नेहरू को फोन किया। उन्होंने कहा, 'मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा।'
'मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैंने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं।' उपराष्ट्रपति ने यह घोषणा की।
अगले दिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सबसे पहले यह घोषणा की।
हरिद्वार में प्रेस को घोषणा करने के बाद ही उन्होंने यह घोषणा की।
उन्होंने अपना त्यागपत्र राजीव को भेजा। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया—
तुरंत।

राजीव गांधी ने उपराष्ट्रपति को आखिरी बार 19 जुलाई 1987 को बुलाया था।
जिस दिन इंडियन एक्सप्रेस ने अजीतभ बच्चन के खिलाफ एक खुलासा प्रकाशित किया,
अमिताभ बच्चन के भाई अजीतभ पर 45 लाख रुपये का घर खरीदने का आरोप लगाया गया है।
अप्रैल 1986 में स्विट्जरलैंड के मोंट्रेक्स में एक फ्लैट में, जब वह अभी भी रह रहा था
दिल्ली। इस खबर ने अधिग्रहण की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए।
उपराष्ट्रपति ने तुरंत प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राजीव गांधी से 'वापसी' करने का आग्रह किया।
इस पत्थर के नीचे क्या छिपा है, यह जानने के लिए। उपराष्ट्रपति ने मांग की कि या तो
यदि इंडियन एक्सप्रेस का आरोप गलत साबित होता है, तो उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, या
अजीतभ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वीपी लगातार इस मामले को आगे बढ़ा रहा था।
प्रधानमंत्री पर दबाव।
इस बार प्रधानमंत्री ने मीडिया मालिक नरेंद्र मोहन को भेजा।
मोहन उपराष्ट्रपति के दूत के रूप में नियुक्त हुए थे। वे व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले हिंदी अखबार के अध्यक्ष थे।
paper Dainik Jagran. Mohan urged VP to meet Rajiv again.
'आइए पहले एक एजेंडा तय करें और फिर उस पर चर्चा करें,' उपराष्ट्रपति ने कहा।
उन्होंने कहा, 'या...मैंने (पहले ही) राजीव को पत्र लिख दिए हैं (और जो कहना था कह दिया है)।'
'Ab chaliye bhi (Now, come with me),' Narendra Mohan cajoled
उसे, 'ये लड़ाई ठीक नहीं है (यह लड़ाई किसी के लिए अच्छी नहीं है)।'
वह चाहता है कि आप सरकार में वापस आ जाएं। आप कोई भी मंत्रालय ले सकते हैं।

चाहत, जिसमें वित्त भी शामिल है...
वीपी ने कहा, 'जब इंदिराजी ने मेरा मंत्रालय छीन लिया और मुझे पीसीसी बना दिया।'
मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने इसे इस तरह से किया कि मुझे सम्मानित महसूस हुआ।
आज, मुझे यह महसूस हो रहा है कि
अपमानजनक। यही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बीच का अंतर है।
गांधी...' फिर उन्होंने निर्णायक स्वर में कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है।'
उनसे मिलने के बारे में।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजीव गांधी से भिड़ने और अपने 'अपने
नावों' के बारे में, वह जानता था कि अगर वह वापस लौटता है तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा।
कांग्रेस ने एक मंत्रालय के लिए चुनाव लड़ा।
उस दोपहर, 19 जुलाई 1987 को, वी. पी. सिंह को निष्कासित कर दिया गया।
कांग्रेस पार्टी। 'जब यह खबर आई तब मैं (रामकृष्ण) हेगड़े के घर पर था।'
आया। हेगड़े ने मेरी ओर मुड़कर कहा, "बधाई हो, तुम अब स्वतंत्र हो।"
अब आप कांग्रेस से निष्कासित हो चुके हैं।

नौवीं

'Chalaen (Shall we go)?'
उस एक शब्द के साथ, मीडियाकर्मियों के एक समूह को संबोधित करते हुए, जो वहां इकट्ठा हुए थे।
विश्वनाथ प्रताप सिंह के घर के बाहर, 1, तीन मूर्ति मार्ग पर।
एक ऐसी यात्रा शुरू की जो आगे चलकर एक आंदोलन में तब्दील हो गई।
भ्रष्टाचार और उन्हें देश का सातवां प्रधानमंत्री बनाना—यह सब
अट्ठाईस महीने।
26 जुलाई 1987 को सुबह 5:50 बजे, अपने customary सफेद कुर्ते में –
पायजामा पहने हुए, वह अपने आवास से बाहर निकले और समर्थकों का अभिवादन किया जो वहां मौजूद थे।
मैं उनके साथ जा रहा था। वह अपनी पहली सार्वजनिक रैली में भाग लेने जा रहे थे।
भारत के गन्ना उत्पादक क्षेत्र में स्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर शहर,

कांग्रेस पार्टी से निष्कासन के एक सप्ताह बाद। यह एक परीक्षा होगी
भारत के भीतरी इलाकों में उनके निष्कासन को किस नज़रिए से देखा गया। बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी।
मुजफ्फरनगर तक उनका पीछा करने वाली कारों का काफिला। लगभग
120 किलोमीटर के इस मार्ग पर पचास वाहनों को कई बार रोका गया।
दिल्ली से मुजफ्फरनगर तक। सड़क किनारे खड़े लोगों के समूह।
would raise full-throated slogans, 'V. P. Singh sangharsh karo, hum
tumhare saath hain (V. P. Singh fight on, we are with you)'. 'Gali gali
maen shor hai, Rajiv Gandhi chor hai (Every alley is resounding with the
राजीव गांधी एक चोर हैं।
मुजफ्फरनगर का विशाल अंतर-विद्यालय मैदान खचाखच भरा हुआ था।
भीड़ चार घंटे से उसका इंतजार कर रही थी। इधर-उधर घूमते हुए, मैं
मुझे एहसास हुआ कि यह कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था—जैसा कि आमतौर पर राजनीतिक सभाओं में होता है।
ऐसा होना चाहिए, जिसमें संबंधित पार्टी द्वारा प्रायोजित भुगतान किए गए समर्थकों की भरमार हो।
सैकड़ों लोगों ने अपने दम पर कार्यक्रम स्थल तक का सफर तय किया था।
मैदान के चारों ओर खड़े ट्रैक्टर। या वे आ गए थे
पैदल या खुद किराए पर ली गई बसों में। वहां जमा हुए लोग
जो लोग एक ऐसे व्यक्ति का स्वयं मूल्यांकन करने आए थे जिसे वे एक विकल्प के रूप में देखते थे।
सत्ताधारी सरकार के लिए। वातावरण उम्मीदों से भरा हुआ था।
Slogans rent the air here too, 'Raja nahin, faqir hai, desh ki taqdeer hai
(वह राजा नहीं बल्कि भिक्षु है, वह देश का भाग्य है।)
वीपी ने अपने सहयोगियों के साथ भीड़ को संबोधित किया।

कांग्रेस से निष्कासित या निलंबित - अरुण नेहरू, आरिफ
Mohammed Khan, Satyapal Malik, and Ram Dhan, who was a senior
दलित नेता।
वी. पी. सिंह, जो कोई महान वक्ता नहीं थे, ने पहले स्थानीय मुद्दों पर बात की। फिर उन्होंने
उन्होंने राजीव गांधी और बच्चन परिवार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, 'मेरी एकमात्र गलती यही थी।'
'वह भ्रष्टाचार के बारे में यह जानकारी लोगों के साथ साझा कर रहा था।' और
crowd shouted, 'V. P. Singh aur bhanda phorho, aur bhanda phorho (V. P.
सिंह उन्हें और भी उजागर करो, उन्हें और भी उजागर करो)। अंत तक,
उत्साही युवा मंच पर चढ़ गए थे, वे देखना चाहते थे कि...
नेताओं के करीब जाकर उन्हें छूना। उन्होंने उन पर फूलों की पंखुड़ियां फेंकीं।
उन्हें। मंच लगभग ढह गया और राजनेताओं को अपने खिलाफ लड़ना पड़ा।
बड़ी मुश्किल से भीड़ से बाहर निकलने का रास्ता। मुजफ्फरनगर ने दिखाया
भारत के मध्य भाग में लोगों का मिजाज बदल रहा था। लोग निराश हो रहे थे।
राजीव के साथ उनके संबंध थे और वे उन्हें भ्रष्टों का रक्षक मानते थे।
उपराष्ट्रपति को अपना उद्धारकर्ता मानने लगे हैं। नारा है 'तख्त बदल दो, ताज'।
badal do, beimaano ka raaj badal do (Change the throne, change the
'राजमुकुट, भ्रष्टों के शासन को बदलो' (यह मांग) उस समय के प्रचलित भाव को दर्शाती थी।
■

मुजफ्फरनगर बैठक की सफलता ने गहन चर्चाओं को जन्म दिया।
वीपी समूह के भीतर। वे हर शाम उनके घर पर मिलते थे।
रणनीति बनाने के लिए उन्होंने 200 कांग्रेस सांसदों और विधायकों की एक सूची

तैयार की।
वे राजीव गांधी से निराश थे—और वे उनके साथ जुड़ सकते थे।
उन्होंने फैसला किया कि वे एक राजनीतिक दल के बजाय एक नया गैर-राजनीतिक संगठन—जन मोर्चा—शुरू करेंगे। इससे असंतुष्टों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
सांसदों और महिला सांसदों को उनके साथ बिना किसी कारण के संबंध रखने की अनुमति नहीं है।
अनुशासनात्मक कार्रवाई को आकर्षित करना, जो किसी राजनीतिक दल में शामिल होने से संभव होता।
हो गया।
सार्वजनिक रूप से समूह ने भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने की बात की। निजी तौर पर,
वे जानते थे कि अधिक कांग्रेसी सदस्य उनके दल में तभी शामिल होंगे जब...
अगले चुनावों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। उपराष्ट्रपति का विचार था कि...
यह समय राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक वैकल्पिक कांग्रेस बनाने का था।
जन मोर्चा गांधी का समर्थन करता था, न कि कांग्रेस विरोधी राजनीतिक मोर्चे का।
2 अक्टूबर 1987 को शुरू किया गया—और इसका नेतृत्व दलित नेता राम ने किया था।
सभी।
■

संतोष भारतीय ने कहा, 'राजा साहब चाहते हैं कि आप अभी जाकर देवी लाल से मिलें।'
सोम पाल को बताया। पाल और भारतीय वी के प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरे थे।
पी. सिंह। उस दिन दोनों को पता था कि पाल को क्या करना है।
वीपी हरियाणा में चुनावों पर करीब से नजर रख रहे थे। परिणाम
परिणाम 16 जून 1987 को घोषित किए गए। देवी लाल ने बड़ी जीत हासिल की थी।
चरण सिंह के नेतृत्व वाली लोक दल पार्टी ने 60 सीटें जीती थीं।

उसने अकेले दम पर 16 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगी भाजपा को कुल 90 सीटों में से 16 सीटें मिलीं।
राजीव गांधी की कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसे केवल 5 सीटें ही मिलीं।
संदेश स्पष्ट था। लोकसभा में भारी बहुमत होने के बावजूद, राजीव गांधी
अपने कार्यकाल के आधे समय में ही वह अपनी पकड़ खोने लगे थे।
Som Pal met Devi Lal in Chandigarh. He urged 'Mamaji' to play 'a
राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने के लिए', और 'उपराष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति का समर्थन करने' के लिए।
विपक्ष के उम्मीदवार'। देवी लाल ने इस विचार का उपहास उड़ाया। 'हरियाणा में
उन्होंने पाल से कहा, 'देश को रास्ता दिखाया है। अगले चुनाव तक, एक गैर-
केंद्र में कांग्रेस विपक्ष सरकार बनाएगा... सरकार
tho humari hee banegi (देखो, हम अगली सरकार बनाएंगे)
समय),' उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। 'कांग्रेस से बाहर आने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता।
'नेता बनो,' उसने तिरस्कारपूर्वक कहा। 'लेकिन,' उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा।
एक रियायत देते हुए उन्होंने कहा, 'वी. पी. सिंह का मेरी पार्टी में स्वागत है।' फिर उन्होंने आगे कहा,
बाद में याद आया, 'मैंने सुना है कि वह एक अच्छा और सक्षम व्यक्ति है।'
"वज़ीर-फ़ज़ीर" बना देंगे (हम उन्हें तब मंत्री बना सकते हैं जब हम एक पार्टी का गठन करेंगे)
केंद्र में सरकार)।
लेकिन कुछ दिनों बाद, देवी लाल ने सोम पाल को फोन किया। 'मैं आ रहा हूँ'
'मैं 27 जुलाई को दिल्ली में आपसे मिलना चाहता हूं।' हैरान पाल उनसे मिलने चला गया।
हरियाणा भवन में। मुख्यमंत्री के कमरे में प्रवेश करते ही देवी लाल ने कहा
अचानक, 'मैं वी. पी. सिंह से मिलना चाहता हूँ।' हृदय परिवर्तन से उत्सुक होकर,
ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना देवी लाल में घटी थी, पाल ने उनसे पूछा, 'मामाजी,

आपने इतने कम समय में अपना मन क्यों बदल लिया?' देवी लाल
उन्होंने जवाब दिया, 'मैंने दिल्ली में त्वरित सर्वेक्षण करने के लिए एक दर्जन सीआईडी कर्मियों को भेजा था और...'
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों से रिपोर्ट लेकर वे वापस आए।
वह उपराष्ट्रपति पहले ही जनता के चहेते बन चुके हैं।' देवी लाल
उन्होंने अगले दिन सुबह नाश्ते पर उपराष्ट्रपति से मिलने का प्रस्ताव रखा। 'हम मिल सकते हैं।'
या तो हरियाणा भवन में या उपराष्ट्रपति के तीन मूर्ति मार्ग स्थित आवास पर,
जो भी उसके लिए अधिक सुविधाजनक हो।
वीपी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि चूंकि देवी लाल वरिष्ठ थे, और साथ ही
सोम पाल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हरियाणा भवन जाया करते थे।
मैं वीपी को वहां ले गया। पाल ने याद करते हुए कहा, 'जब उनका काम खत्म हो गया, तो मुझे अंदर बुलाया गया।'
मुझे बताया गया था कि उत्तर प्रदेश या किसी अन्य स्थान पर बैठक आयोजित की जानी चाहिए।
राजस्थान, जिसे दोनों नेता संबोधित करेंगे (अपने दौरे की शुरुआत के लिए)।
संयुक्त अभियान)।
वीपी और देवी लाल ने 9 अगस्त को अपनी पहली संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया।
1987, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ। उन्होंने चुना
Sangariya in Ganganagar district in Rajasthan as the venue. It was a
एक छोटा सा कस्बा, जिसकी आबादी मात्र 30,000 लोग थी। लेकिन यह पास ही था।
सीमा के पास स्थित है, और देवी लाल के अपने गांव चौटाला से केवल 3 किलोमीटर दूर है।
उन्होंने रणनीतिक रूप से स्थान का चयन किया था। इसका उद्देश्य लोगों को सक्षम बनाना था।
हरियाणा के गांवों से बड़ी संख्या में लोग आएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि

प्रभावशाली उपस्थिति।
बैठक बेहद सफल रही। देवी लाल अब आश्वस्त हो गए थे कि
उपराष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाना राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगा। उन्होंने संपर्क किया।
अन्य विपक्षी नेता भी उनके साथ जुड़ेंगे।
हालांकि कुछ अड़चनें भी आईं, जैसे कि देवी लाल की शुरुआती हिचकिचाहट।
साथी जाट और प्रतिद्वंद्वी अजीत सिंह (जो लोकसभा अध्यक्ष थे) के विरोध का
दल (अजीत)), पूर्व लोक दल की एक और छोटी पार्टी, उनके पिता
चरण सिंह के नेतृत्व में, विभिन्न समूह अंततः एकजुट होने लगे।
वी. पी. सिंह.
■

जब मुझे इतनी सशक्त और व्यापक प्रतिक्रिया मिलने लगी, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ।
कि...कांग्रेस का एक वास्तविक विकल्प संभव हो सकता है...(और) होगा
'देश के लोकतंत्र में योगदान दें,' वी. पी. सिंह ने मुझसे कहा।
उसने सोचा कि उसके सामने तीन विकल्प हैं। पहला, चयन करना।
देश भर के प्रतिष्ठित लोगों को चुनकर एक नई पार्टी का गठन करें। दूसरा,
मौजूदा राजनीतिक दलों को एकजुट करके एक नई पार्टी का गठन करना। और
तीसरा, एक मोर्चे के रूप में काम करना जारी रखना और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आंदोलन खड़ा करना।
'व्यक्तिगत रूप से, मैं एक मोर्चे के रूप में काम जारी रखने और एक नई व्यवस्था बनाने का विकल्प चुनता।'
लोगों के आंदोलन के बारे में। राम धन ने उन्हें पार्टी बनाने के खिलाफ चेतावनी दी।
Sarvodaya leader Acharya Ramamurti felt that this ‘urja’ (energy) VP
‘राजनेताओं द्वारा उपभोग नहीं किया जाना चाहिए’ को उजागर किया था, लेकिन इसका उपयोग किया जाना चाहिए

बदलाव लाना। हालाँकि, यह वास्तव में अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण नहीं था।
राजनीतिक नेता जो उपराष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करना चाहते थे—ओडिशा के बिजू पटनायक,
कर्नाटक के आर. के. हेगड़े, हरियाणा के देवी लाल। साथ ही, उनके अधिकांश
जन मोर्चा के सहयोगी चुनाव लड़ने के पक्ष में थे, और सिर्फ इतना ही नहीं।
सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन का हिस्सा बनना। अंततः बनी आम सहमति
उन सभी लोगों में से जो उसके साथ जुड़ने पर विचार कर रहे थे
वह एक राजनीतिक दल शुरू करने के पक्ष में थे।
अब सवाल यह उठा कि क्या यह काम 'अच्छे लोगों का चयन' करके किया जाए।
देश भर से और मौजूदा पार्टियों के भीतर से या उन्हें लाकर
मौजूदा राजनीतिक संस्थाओं को एक साथ लाना। उनमें से 'अच्छे लोगों' को चुनकर उनका चयन करना।
विभिन्न पक्षों द्वारा एक नई इकाई का गठन करने से स्थिति और अधिक खंडित हो जाती।
विपक्ष। उपराष्ट्रपति ने कहा, 'विपक्ष की हर पार्टी में फूट पड़ जाती।'
उन्होंने कहा, 'कर्नाटक में...सरकार गिर जाती।' यहां तक कि भाजपा भी।
शायद विभाजन हो गया हो।
'उस समय अटल बिहारी वाजपेई, जसवन्त सिंह और भैरों
वीपी ने दावा किया कि सिंह शेखावत एक नई पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार थे।
(वाजपेयी ने बाद में इस बात से इनकार किया।) दूसरी ओर, भाजपा नेता जसवंत
सिंह ने उपराष्ट्रपति को मौजूदा पार्टियों को एकजुट न करने की चेतावनी दी।
अंत में, उपराष्ट्रपति ने निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस से निपटने का एकमात्र तरीका यही है।
इसका उद्देश्य मौजूदा विपक्षी दलों को एकजुट करना था। कोई भी समूह मजबूत नहीं था।
यह अकेले ही राजीव गांधी को उनकी 414 सीटों के साथ चुनौती देने के लिए काफी था।
लोकसभा सीटें। एक बिल्कुल नई पार्टी किसी मौजूदा पार्टी को हराने में सक्षम नहीं होगी।

कांग्रेस जैसे स्थापित संगठन। उपराष्ट्रपति जानते थे कि उन्हें ऐसा करना होगा।
कांग्रेस विरोधी ताकतों के पूरे समूह को एक साथ लाने के लिए
साझा मंच। उन्होंने उम्मीद जताई कि जन मोर्चा 'सीमेंट' का काम करेगा।
विपक्ष में मौजूद बड़े-बड़े पत्थरों के बीच। लेकिन अधिक यथार्थवादी एच. एन. बहुगुणा ने उन्हें बताया, और उनकी चेतावनी भविष्यवाणीय सिद्ध हुई।
विश्वनाथ, सीमेंट एक पत्थर को दूसरे से जोड़ सकता है, लेकिन (यह)
एक पत्थर को लकड़ी के टुकड़े से जोड़ें।
वी. पी. सिंह यह भी जानते थे कि उन्हें बड़े-बड़े अहंकारी लोगों से निपटना होगा।
विभिन्न विपक्षी नेताओं में से, सभी अपनी मनमानी करने के आदी हैं।
जीवन भर सांसद रहे, अब उपराष्ट्रपति को एक ऐसे जोखिम भरे क्षेत्र से गुजरना पड़ा जिसे वे कहते हैं...
विपक्षी राजनीति—यह उस व्यवस्था से बिल्कुल अलग है जिसमें वह खुद थे।
पहले कहा करता था। 'विरोधाभासों का प्रबंधन एक कला है,' उपाध्यक्ष कहा करते थे।
आशावादी रूप से, 'जिसमें सामान्य हित की पहचान करना शामिल है...
मतभेदों की बात नहीं कर रहा था... मैं साझा हित की पहचान कर सका—जो कि था कांग्रेस को हराने के लिए... मेरा उद्देश्य था कि किसी की भी आवाज न उठे।
विपक्ष को इस गठन से बाहर रखा गया। मैं इन सभी ताकतों को संगठित कर सकता था।
कांग्रेस को हराने के एक साझा लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता मिली, और यह कारगर साबित हुआ।'
■

जून 1988 में हुए इलाहाबाद उपचुनाव ने विपक्ष को मजबूती प्रदान की।
उपराष्ट्रपति अब जिस एकता की तलाश कर रहे थे, वही एकता थी। अमिताभ बच्चन की भी चर्चा चल रही थी।
कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में दोबारा खड़े होने पर, उपराष्ट्रपति को यह खबर सुनते ही बच्चन चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे चुनाव लड़ेंगे—उनसे

मुकाबला करने के लिए।
संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति के लिए, यह एक
सम्मान की रक्षा। आखिरी क्षण में, बच्चन ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया।
कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र सुनील शास्त्री को उम्मीदवार बनाया, जिनके परिवार के प्रति उपराष्ट्रपति का बहुत सम्मान था। मकसद उपराष्ट्रपति के लिए मुश्किलें पैदा करना था।
शास्त्री से लड़ने के लिए, उपराष्ट्रपति ने व्यापक प्रचार किया, दो-पहिया वाहन पर पीछे बैठकर चुनाव प्रचार किया।
जून की भीषण गर्मी में, उसने अपने सिर को तौलिए से लपेटे हुए, एक पहिएदार स्कूटर पर सवार होकर यह सब किया।
यह शैली कांग्रेस की शैली से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने इस पर जोर दिया।
उन्होंने मितव्ययिता की बात की, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। कांग्रेस ने इस पर ध्यान केंद्रित किया।
विभिन्न जातियों को लुभाने के लिए देवी लाल ने स्वयंसेवकों की अपनी 'ग्रीन ब्रिगेड' भेजी।
उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रचार करते समय, उन्होंने पहचान के लिए हरे रंग की पट्टियाँ पहनी थीं।
उन्होंने खुद को अन्य प्रचारकों से अलग कर लिया। उपराष्ट्रपति ने ताकतवर लोगों को भी मात दी।
उन्होंने कांग्रेस में भाग लिया और शानदार जीत हासिल की। और उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे
कांग्रेस की चुनावी मशीनरी के बिना भी जीत हासिल कर सकते हैं। कार्टूनिस्ट
आर. के. लक्ष्मण को इलाहाबाद के सार को चित्रित करना था: उनके कार्टून में यही बात झलकती है।
डू ने सड़क किनारे पड़े एक विशाल टैंक के मलबे को दिखाया जबकि वी.
पी. सिंह मोटरसाइकिल पर सवार होकर चले गए; बुर्ज में सुनील शास्त्री बैठे थे।
वॉकी-टॉकी पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहते हुए, 'राजीव, उसने अपनी गाड़ी में टक्कर मार दी।'
मेरी साइकिल में टक्कर मारी और गाड़ी चलाकर भाग गया।

इलाहाबाद की घटना का विपक्षी दलों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा।
उन्होंने देखा कि अगर वे कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए हाथ मिला लें तो क्या संभव हो सकता है।
■

27 जुलाई 1988 को वी. पी. सिंह ने सात सदस्यीय दल के गठन की घोषणा की।
जनता पार्टी, लोक दल (बी) और कांग्रेस (एस) से मिलकर बना राष्ट्रीय मोर्चा।
टीडीपी, डीएमके और एजीपी। जन मोर्चा जो कि एक गैर-दलीय संगठन था।
यह मंच भी गठबंधन में शामिल हो गया। आधिकारिक तौर पर, नेशनल फ्रंट था।
दो महीने बाद मरीना बीच पर बड़े धूमधाम से इसका शुभारंभ किया गया।
मद्रास (चेन्नई)। 'राष्ट्रीय मोर्चा भगवान आदित्य (सूर्य) का रथ है।'
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव ने गरजते हुए कहा, 'यह रथ
हमारे प्रयास उस अंधकार और अंधेरे को दूर करेंगे जो चारों ओर गहराता जा रहा है।
राष्ट्रीय इतिहास के पिछले कुछ दशकों के बीतने के साथ ही रामाराव बने।
मोर्चे के अध्यक्ष और इसके संयोजक वी. पी. सिंह। इस आयोजन ने संगठन को बढ़ावा दिया।
उपराष्ट्रपति का प्रोफाइल; अचानक देश के दक्षिणी हिस्से में भी हलचल शुरू हो गई।
उन्हें विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है।
11 अक्टूबर 1988 को, जो जयप्रकाश का जन्मदिन था।
उप प्रधानमंत्री नारायण ने जनता दल नामक एक नई पार्टी के गठन की घोषणा की;
संयुक्त विपक्ष का केंद्रबिंदु यही होगा। लंबे समय के बाद और
जटिल वार्ताओं के बाद, वह मध्यमार्गी पार्टियों को अपने पक्ष में करने में सफल रहे थे।
विपक्ष—जनता पार्टी (जिसमें अब लोक दल (ए) भी शामिल था)
लोक दल (बी), कांग्रेस (एस), जो कि एक छोटा अलग हुआ समूह था
कांग्रेस और उनकी अपनी जन मोर्चा को भंग करने के लिए।
अपनी पहचान को बदलकर नई पार्टी में विलय कर लें। जनता दल की शुरुआत हुई थी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बैंगलोर में आयोजित एक सम्मेलन
रामकृष्ण हेगड़े। यह विलय बिना किसी बाधा के नहीं हुआ।
चंद्र शेखर और हेगड़े के बीच खुलकर विवाद हुआ, दोनों ही
जनता पार्टी और एच.एन. के बीच शब्दों का उतना ही भयंकर युद्ध।
बहुगुणा, जो उनके नाम पर बनी लोक दल (बी) के प्रमुख थे, और देवी लाल।
'हीरो नहीं, जीरो', देवी लाल ने बहिष्कार करने के लिए बहुगुणा पर जमकर हमला बोला।
बैंगलोर में होने वाली बैठक।
बहुगुणा के विपरीत, चतुर चंद्र शेखर लॉन्च में आए थे।
जनता दल के बारे में उनका मानना था कि अगर वहाँ कोई समस्या हो तो बाहर रहने की बजाय अंदर रहना बेहतर होगा।
नए गुट के सत्ता में आने की संभावना थी। चंद्र शेखर और बहुगुणा दोनों ही वीपी के नेतृत्व के विरोधी थे। हेगड़े
और देवी लाल वीपी के साथ खड़े रहे।
■

कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए साधन तैयार करने के बाद, उपराष्ट्रपति ने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया।
राजीव गांधी को सत्ता से हटाने की लड़ाई में। अब तक, इस लड़ाई में गति आ चुकी है।
राजीव के खिलाफ बोफोर्स मामला धीरे-धीरे खत्म होने लगा था। यह सब इसके बावजूद था।
द हिंदू और द स्टेट्समैन द्वारा प्रकाशित अतिरिक्त जानकारी।
और इंडियन एक्सप्रेस, समय-समय पर भारतीय फ्रंट कंपनियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं।
इस सौदे के लिए भुगतान पाने वाले एजेंट। विपक्ष के दबाव में,
राजीव गांधी ने 6 अगस्त को एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया था।

1987 में ₹64 करोड़ के कमीशन के प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने के लिए भुगतान किया गया था
बोफोर्स ने समझौता कर लिया। अप्रैल 1988 में जेपीसी ने बोफोर्स को दोषमुक्त कर दिया।
सरकार पर किसी भी प्रकार के गलत काम का आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सरकार की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुईं।
अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। 18 जुलाई 1989 को, सीएजी की आधिकारिक रिपोर्ट जारी की गई।
सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट संसद में पेश की गई। इसमें सरकार पर आरोप लगाए गए।
बोफोर्स पर।
सीएजी की रिपोर्ट राजीव गांधी के लिए वही थी जो इलाहाबाद का फैसला था।
यह चुनाव 1975 में उनकी मां इंदिरा गांधी के लिए हुआ था, जिसके कारण वे अयोग्य घोषित हो गए थे।
उन्हें संसद से बाहर कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने संसद में बहस की मांग की।
लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने इनकार कर दिया। तीन दिनों तक सांसदों ने...
उन्होंने संसद का गतिरोध कायम कर दिया और राजीव गांधी से इस्तीफा देने तथा नए चुनाव कराने की मांग की।
'सीएजी की रिपोर्ट ने राजीव गांधी को 1984 में मिले जनादेश को समाप्त कर दिया है,' वी. पी. सिंह
गरज उठा।
24 जुलाई 1989 को, दिल्ली में एक बादल भरे सोमवार के दिन, तिहत्तर सांसदों ने...
बारह दलों के प्रतिनिधि संसद में गए और अपना मत प्रस्तुत किया।
लोकसभा से इस्तीफे। इस कदम से कांग्रेस को झटका लगा।
अचानक। अगर राजीव गांधी ने बोफोर्स कांड पर इस्तीफा नहीं दिया होता, तो बेहतर होता कि
सांसदों ने कहा कि उन्होंने ऐसा किया। ये इस्तीफे एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए।
कांग्रेस को सत्ता से हटाने की लड़ाई। उपराष्ट्रपति ने विपक्ष को मना लिया था।

सामूहिक इस्तीफों के प्रभाव के बारे में दिग्गज विचारक। सांसदों
उसने उसकी योजना से सहमत होकर उसका साथ दिया, भले ही इसका मतलब वेतन का नुकसान था।
भत्ते, रेल और हवाई यात्रा व्यय—ये अभी भी तीन थे।
चुनाव होने में अभी कई महीने बाकी थे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि...
उन्हें आजीवन मिलने वाली मासिक पेंशन छोड़नी पड़ेगी जो उन्हें मिलती।
यदि वे अपना पूरा कार्यकाल पूरा करते तो उन्हें यह राशि प्राप्त होती।
इस कदम से वी. पी. सिंह कांग्रेस को अस्थिर करने में कामयाब हो गए थे।
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्तीफों के कारण भाजपा और वामपंथी दलों को झटका लगा।
आपस में तमाम असंतोष के बावजूद, वे उपराष्ट्रपति वाजपेयी के पीछे खड़े रहे।
उन्होंने घोषणा की, 'वामपंथी से लेकर दक्षिणपंथी तक, हम सभी अब एक साथ मिलकर एक को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं।'
'साझा दुश्मन।' एन. टी. रामाराव ने वामपंथियों से संपर्क साधा था।
नेता ज्योति बसु और ई. एम. एस. नंबूदिरिपाद और भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और एल. के. आडवाणी को साथ लाने के लिए भाजपा ने प्रयास किए थे।
केवल दो लोकसभा सांसद थे, जबकि वामपंथी दलों के बावन सांसद थे। एक रात्रिभोज में
एन. टी. रामाराव द्वारा विपक्षी नेताओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में मधु दंडवते ने भाग लिया।
उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था, 'अब हमें कॉमरेड वाजपेयी और पंडित की जरूरत है।'
नंबूदिरिपाद राजीव को सत्ता से हटाने के लिए मिलकर काम करेंगे!
अचानक, बोफोर्स एक चुनावी मुद्दे के रूप में फिर से केंद्र में आ गया था।
17 अक्टूबर 1989 को चुनाव की घोषणा हुई, और चारों ओर यही नारा गूंज उठा।
over North India, ‘Gali gali maen shor hai, Rajiv Gandhi chor hai’. Rajiv
गांधी की विश्वसनीयता को झटका लगा था। कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया।

चुनाव में पार्टी रक्षात्मक मुद्रा में थी। पार्टी के प्रबंधकों को पता था कि यह सुखद स्थिति नहीं है।
जिस स्थिति में होना चाहिए।
वी. पी. सिंह ने राजीव गांधी पर अपने हमले जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
एक बार, 1989 में उपराष्ट्रपति के साथ उत्तर प्रदेश की यात्रा के दौरान, मैंने पूछा था क्या उन्हें इस बात की चिंता थी कि देवी लाल और चंद्र शेखर
शायद उन्हें प्रधानमंत्री बनने की अनुमति न मिले। 'मुझे परवाह नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बनता है।'
मंत्री जी,' उन्होंने इतने जोश से कहा कि मैं चौंक गया। 'लेकिन यह आदमी
(राजीव) को जाना होगा।' उस दिन मैं सोच रहा था कि क्या उसे कोई तकलीफ हुई है।
राजीव के हाथों हुए अज्ञात अपमानों ने उनके संघर्ष को अतिरिक्त मजबूती प्रदान की।
किनारा।
वी. पी. सिंह एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार साबित हुए—मिलनसार और
सहयोगियों के प्रति नरम रुख अपनाना, अक्सर उन्हें श्रेय लेने देना।
फिर भी उन्होंने पहल को अपने हाथों से निकलने नहीं दिया। जारी रखते हुए
राजीव गांधी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और बिहार में, उन्होंने अपने सहयोगियों को अन्य राज्यों की देखरेख के लिए नियुक्त किया। उनकी कार
वे एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक पहुँचने के लिए रात में ग्रामीण इलाकों से होकर तेज़ी से गुज़रते थे।
एक सभा से दूसरी सभा तक जाते हुए, यह गरीब ग्रामीणों के छोटे-छोटे समूहों के पास से गुजरती थी।
सड़क किनारे खड़े होकर मिट्टी के तेल के लैंप जलाकर रोशनी पाने की कोशिश कर रहे हैं
'राजा से फकीर बने' की एक झलक। हर बार जब वह इनमें से किसी एक को देखता था
जब वह समूहों के सामने गाड़ी रोकता और उनसे कुछ शब्द बोलता, तो वह गाड़ी रोककर उनके साथ बातचीत करता।

आगे बढ़ने से पहले ग्रामीणों को सूचित किया जाता है।
■

वी. पी. सिंह की चुनावी रणनीति सरल थी: राजीव गांधी पर प्रहार करना और
कांग्रेस का सफाया कर दो। जैसा कि उसने जुलाई 1987 में मुजफ्फरनगर में किया था।
अक्टूबर 1989 के चुनाव अभियान के दौरान भी उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर बात की थी।
राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए। और, हर रैली में, वह पूछते थे,
'Bofors ka dalaal kaun hai (Who is the middleman/broker for Bofors)?'
दर्शक जोश से चिल्लाते, 'राजीव गांधी।' उपराष्ट्रपति का संदेश
यह खबर गांवों तक पहुंच चुकी थी।
दूसरी ओर, राजीव गांधी ने एक एजेंसी को उच्च स्तरीय चुनाव प्रचार करने के लिए नियुक्त किया।
कांग्रेस के चुनाव अभियान में भारी तनाव था। इसमें विपक्ष को 'बिच्छू' बताया गया था।
और मुर्गों की लड़ाई। यह बात आम लोगों को समझ नहीं आई।
उन्होंने अन्य गलतियाँ भी कीं। उन्होंने अपना चुनाव अभियान शुरू किया था।
3 नवंबर 1989 को अयोध्या में उन्होंने राम लाने की घोषणा की।
देश में राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से। अब वह भाजपा के गढ़ में चुनाव लड़ रहे थे और उसी का इस्तेमाल कर रहे थे।
शब्दावली। फिर उन्होंने वीएचपी को आधारशिला रखने की अनुमति दी।
9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर। 'वह दिन था...
वी. पी. सिंह ने बताया, 'पहली बार...जब मुझे लगा कि हमारे पास जीतने का मौका है।'
मुझे।
मुसलमानों के एक वर्ग ने अब उपराष्ट्रपति का समर्थन करना शुरू कर दिया, इसके

बावजूद
भाजपा के साथ उनका गठबंधन। वामपंथी दलों के साथ उनकी साझेदारी ने भी उन्हें लाभ पहुंचाया।
गठबंधन को सीटों का भारी लाभ मिला।
जनता दल ने दूसरी सबसे अधिक सीटें जीतीं।
चुनाव। जब राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, तब
संसद में 197 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के नेता, लेकिन फिर भी बहुमत से पीछे
बहुमत प्राप्त होने पर वी.पी. सिंह ने भारत के सातवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
2 दिसंबर 1989 को। उन्होंने संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
भारत के इतिहास में विरोधाभासों से भरी सरकार, भले ही वह प्रतिनिधित्व करती हो
वामपंथी से लेकर दक्षिणपंथी तक, विचारों के व्यापकतम संभव अंतर। अस्थिर
पहले दिन से ही, कुछ ही लोगों को लगा था कि यह अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएगा। यह उस समय की बात है जब...
अपने सबसे गहरे संकट के चरम पर ही वीपी ने मंडल की चाल चली।
इससे ऐसी प्रतिक्रिया हुई जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
एक्स

मंडल फैसले के बाद के घटनाक्रम उतने ही नाटकीय थे जितना कि यह फैसला।
मंडल की कहानी इसके परिणामों पर एक नजर डाले बिना अधूरी है।
जिसने तीन दशकों से अधिक समय तक देश का राजनीतिक एजेंडा निर्धारित किया।
मंडल ने ऐसी ताकतों को उजागर किया जिनकी वीपी ने कल्पना भी नहीं की थी।
हालाँकि वह 'विरोधाभासों को संभालने' की अपनी क्षमता पर गर्व करता था—ये
अंततः यही उनकी सरकार को भी निगल जाएगा।
19 सितंबर 1990 को, बीस वर्षीय छात्र राजीव गोस्वामी की मृत्यु हो गई।
दिल्ली के देशबंधु कॉलेज के एक प्रोफेसर ने अपने परिसर के पास आत्मदाह कर लिया।
मंडल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जैसे ही आग की लपटें उसके धड़ को घेरने लगीं और
दर्द से चीखते हुए लड़का अपना सिर पकड़कर आग बुझाने की कोशिश करने लगा।

हरे कुर्ते पहने उसकी बाहें; उसके स्तब्ध मित्र चारों ओर खड़े होकर देख रहे थे।
बेबसी से।
मंडल के फैसले से नाराज होकर, नौ दिन पहले, एक समूह ने
छात्र अपने कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था।
उन्हें मीडिया का उतना ही ध्यान मिला जितनी उन्हें उम्मीद थी। तभी उन्हें
उन्होंने कुछ अधिक नाटकीय करने का फैसला किया—आत्मदाह। उनमें से दो
राजीव के दोस्त भी उसके साथ आत्मदाह करने वाले थे। लेकिन वे
आखिरी क्षण में पीछे हट गया। दर्शक राजीव को चीखते हुए देख रहे थे।
दर्द और छटपटाहट। लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया।
अंततः आग बुझाने वाले पुलिसकर्मी।
राजीव गोस्वामी की चीखें इस विरोधी आंदोलन का निर्णायक क्षण बन गईं।
मंडल आंदोलन। आग बुझने से पहले, उन्होंने
उसके पूरे शरीर पर 50 प्रतिशत जलने के निशान थे। उस समय कहा गया था कि
उसने केवल अपने टखनों और पैरों पर केरोसिन डालने और फिर तैयार होने की
योजना बनाई थी।
उन्हें उतारो। उसके दोस्तों को उसे बचाना था। चाहे वह खुद
अंतिम क्षण में उसने अपने या दूसरों के शरीर पर केरोसिन डालने का फैसला किया।
यह रहस्य बना हुआ है कि राजीव ने ऐसा क्यों किया।
mother the night before, 'Hum sirf tamasha karne jaa rahe hain.' (We are
(केवल कुछ नाटकीयता दिखाने जा रहा हूँ।) कहीं न कहीं, मंचन की योजना है
एक नाटक बुरी तरह बिगड़ गया। गंभीर रूप से घायल राजीव को अस्पताल ले जाया गया।
सफदरजंग अस्पताल के लिए। दो दिन बाद, सफदरजंग के पास का चौराहा।
छात्रों ने अस्पताल का नाम बदलकर कुर्बानी चौक रख दिया।
कुछ दिनों बाद दिल्ली में दूसरी आत्मदाह की घटना घटी। एक युवक
एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से एम्स चौराहे तक गया और शांति से उसे पार्क कर दिया।
सड़क के एक किनारे पर, उसने अपने बैग से केरोसिन की एक बोतल निकाली।

उसने उसे अपने ऊपर उड़ेल लिया और खुद को आग लगा ली। छात्रों की भीड़ जो वे सभी बर्न यूनिट के अंदर राजीव के बारे में खबर मिलने का इंतजार कर रहे थे।
मैं जलते हुए आदमी को बचाने की कोशिश में उसकी ओर दौड़ा। 'जैसे ही मैं मौके पर पहुंचा, मैंने कहा...
जहां वह था... मैंने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा,' पराग वोहरा ने लिखा।
घटना के प्रत्यक्षदर्शी छात्र ने बताया, 'वहाँ पिघले हुए नाइकी के जूते ही बचे थे।'
'एक व्यक्ति का बस इतना ही अंश बचा था।' उस आदमी की मृत्यु हो गई। उसके बाद लोगों को उसका नाम तक याद नहीं रहा। राजीव गोस्वामी बच गया, लेकिन चौदह वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई।
कई वर्षों बाद, 24 फरवरी 2004 को, तैंतीस वर्ष की आयु में पीलिया से उनका निधन हो गया।
जटिलताओं के कारण। उनके शरीर को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंची थी।
स्वयं को अग्नि में समर्पित करने का प्रयास।
■

'मुझे मंडल के विरोध की उम्मीद थी,' वी. पी. सिंह ने मुझे कई साल बाद बताया।
और मैं इसके लिए तैयार था। लेकिन मुझे आत्मदाह की उम्मीद नहीं थी।
छात्रों।
प्रधानमंत्री को उम्मीद थी कि मध्यम वर्ग और उच्च जाति के लोग ऐसा नहीं करेंगे।
मंडल का समर्थन करें। यह उनके हितों के खिलाफ था। 'आप किसी तर्क से इसका खंडन नहीं कर सकते।'
'ब्याज,' वीपी ने दार्शनिक अंदाज में कंधे उचकाते हुए कहा। 'आप केवल ब्याज के साथ ही समझौता कर सकते हैं।'
एक रुचि... मैंने तो यह भी सोचा था कि (विपक्ष) इसमें हो सकता है
उत्तर प्रदेश और बिहार के गाँव... लेकिन,' उन्होंने बार-बार कहा, 'नहीं...
आत्मदाह।'
शुरुआत में, मंडल विरोधी प्रदर्शन मोमबत्ती जलाकर किए जाने तक ही सीमित थे।

दिल्ली विश्वविद्यालय में कैंडल मार्च और मौन प्रदर्शन हुए। कुछ घटनाएं भी हुईं।
छात्रों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की खिड़कियों के शीशे तोड़ने की घटना।
(डीटीसी) बसें। राजनीतिक रूप से संबद्ध छात्र संघ, कांग्रेस-
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) और भाजपा समर्थक अखिल बीजेपी ने गठबंधन किया।
Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) were initially cool to the protests.
उन्होंने तभी कदम उठाया जब उन्हें राजनीतिक मंजूरी मिल गई।
वे जिन दलों से जुड़े हुए थे।
लेकिन राजीव के आत्मदाह ने पूरे भारत के युवाओं को प्रेरित किया।
आत्मदाह की संख्या बढ़ने के साथ ही स्थिति हिंसक हो गई।
सरकार को चंडीगढ़ में सेना बुलानी पड़ी; अन्य स्थानों पर,
पुलिस ने गोलीबारी की। आत्मदाह करने से 63 युवकों की मौत हो गई।
खुद। अंततः, यह आंकड़ा बढ़कर 200 हो गया।
आधिकारिक तौर पर, भाजपा और कांग्रेस ने मंडल विरोधी रुख नहीं अपनाया।
उनकी स्थिति। वे केवल इस बात से नाखुश थे कि उनसे परामर्श नहीं किया गया था —और
उन्होंने इसके कार्यान्वयन के तरीके की निंदा की।
मंत्रिमंडल के फैसले के एक दिन बाद, यानी 8 अगस्त 1990 को, जब
Rajya Sabha debated Mandal, BJP leader Pramod Mahajan had
निर्णय में केवल आर्थिक मानदंडों को शामिल करने का सुझाव दिया गया।
हालांकि, राजीव गोस्वामी के आत्मदाह के प्रयास के बाद—ऐसा हुआ
सितंबर में आडवाणी की रथ यात्रा शुरू होने से एक सप्ताह पहले ही भाजपा में अफरा-तफरी मच गई। उत्तर भारत भर के छात्र विरोध प्रदर्शन करने लगे।
मंडल—शहर दर शहर। जब आडवाणी और मदन लाल खुराना गए
राजीव के माता-पिता के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए वे सफदरजंग अस्पताल गए थे।
प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन पर हूटिंग की। खुराना के साथ मारपीट की गई।

आडवाणी और खुराना को मंडल की सार्वजनिक रूप से निंदा करने के लिए कहा गया था।
आयोग की रिपोर्ट। या उन्हें सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए।
छात्रों। चूंकि आडवाणी मंडल को अस्वीकार नहीं कर सकते थे—यह इसका हिस्सा था।
भाजपा के घोषणापत्र में उन्होंने केवल पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों की निंदा की थी।
छात्र।
जैसे-जैसे छात्र विरोध प्रदर्शन फैलते गए, आडवाणी को भाजपा के लिए समर्थन मिलता नजर आने लगा।
विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे कम हो रहा था। छात्र भाजपा के दिल्ली कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए।
आडवाणी जानते थे कि जब तक पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी, मध्यम वर्ग और
उच्च जातियाँ, जो मंडल से सबसे अधिक उत्तेजित थीं, और जो थीं
भाजपा की रीढ़ की हड्डी, उन्हें ही छोड़ देगी।
भाजपा की चिंता का एक और कारण था। भाजपा नेताओं को संदेह था कि
कि वी. पी. सिंह ने मंडल कार्ड का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा था।
समय से पहले चुनाव कराने के लिए तैयार।
जब उपराष्ट्रपति ने वाजपेयी से पूछा कि अचानक भाजपा उनके खिलाफ क्यों हो गई है
जैसा कि वीपी ने मुझसे कहा, सरकार ने भाजपा के दिग्गज नेता के जवाब में कहा था कि...
स्पष्टवादिता, 'आपका 15 अगस्त (1990) का भाषण... यह पहली बार था
पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन पर छुट्टी घोषित की गई थी।
उपराष्ट्रपति ने विरोध जताया कि जब राजीव गांधी को पद से हटाया गया था तब भाजपा ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी।
वह अपनी कलम की एक ही चोट से छुट्टियों की संख्या लगातार बढ़ाता रहता था।
वाजपेयी: '(लेकिन) हमें लगा कि यह एक घोषणापत्र की तरह है...और आप इसमें

जा सकते हैं
चुनाव के लिए।' उन्होंने आगे कहा, 'इससे पहले कि आप ऐसा करते, हमें कार्रवाई करनी पड़ी।'
VP: 'Mandal toh aapke manifesto maen bhi thaa, usi se prerna lee hai
(मंडल का जिक्र आपके घोषणापत्र में था, मैंने उससे प्रेरणा ली है।)
'प्रेरणा लेते रहते (आप प्रेरणा लेते रह सकते थे)
from it),' Vajpayee was quick with his riposte, 'par prakriya kyon kar
डी (आपको इसे लागू क्यों करना पड़ा?)
■

वी. पी. सिंह ने मुझसे कहा, 'मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि मेरी सरकार लंबे समय तक चलेगी।'
दो साल से ज्यादा नहीं।' यह बात उन्हें उस दिन स्पष्ट हो गई थी जिस दिन उन्होंने यह कदम उठाया था।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा ही वह पार्टी होगी जो प्रधानमंत्री पद से हट जाएगी।
सरकार को गिरा देंगे।
'मैं स्पष्ट था क्योंकि भाजपा भी उसी पद के लिए दावेदार थी...' लेकिन
उनके नेतृत्व वाले गठबंधन के भीतर और विशेष रूप से देवी लाल के भीतर मौजूद विरोधाभास
—वे पतन को और तेज कर देंगे।
के. एन. गोविंदाचार्य का यह भी स्पष्ट मत था कि भाजपा का असली प्रतिद्वंदी कौन है?
भविष्य वी. पी. सिंह का होगा। 'हमारी लड़ाई अंततः इसी के इर्द-गिर्द घूमती रहेगी।'
गोविंदचार्य ने भविष्यवाणी की, 'वी. पी. सिंह के विरुद्ध।' 'यह वैचारिक रूप से अपरिहार्य।' भाजपा के एक उच्च पदस्थ महासचिव ने मुझसे यह बात कही।

जिस दिन उपराष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली—और यह बात मुझे आश्चर्यजनक लगी—वह दिन मेरे लिए आश्चर्यजनक था।
भाजपा के समर्थन से मंत्री बने। मैं भाजपा कार्यालय गया था।
2 दिसंबर 1989 को दिल्ली के अशोका रोड पर, मैं बातचीत कर रहा था।
गोविंदाचार्य ने दिन की घटनाओं के बारे में बताया। जब हम वहाँ बाहर खड़े थे...
मीडिया रूम में, उन्होंने याद किया कि 1989 की शुरुआत में, इससे पहले उपराष्ट्रपति ने उनसे क्या कहा था।
नेशनल फ्रंट सत्ता में आया। 'गोविंदजी, पहले यह सरकार (राजीव की)'
गांधी जी को जाना होगा। तभी या तो आप या मैं आगे बढ़ सकते हैं।'
उस दिन उपराष्ट्रपति ने वोट बैंकों के महत्व के बारे में विस्तार से बात की थी।
आप अपनी इच्छानुसार संगठन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अनदेखी करते हैं
'वोट बैंक, आप जीत नहीं पाएंगे।' इसके बाद उपराष्ट्रपति ने गोविंदाचार्य से कहा।
उन्होंने राजीव गांधी को हराने के लिए जिस वोट बैंक को बनाने की उम्मीद की थी, उसके बारे में बात की।
कांग्रेस। 'मैं आधी अगड़ी जातियों (जो कांग्रेस के साथ हैं) को तोड़ सकता हूँ।'
कांग्रेस)। आपके कुछ समर्थक (जो उच्च जाति के भी हैं) भी आ सकते हैं।
हमारे साथ। (लेकिन) हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम पिछड़ों को नाराज न करें।
वर्ग। वे स्वभावतः विपक्ष के साथ हैं। दलित ऐसा नहीं करेंगे।
वे कांग्रेस के प्रति ऋणी महसूस करते हैं, इसलिए वे जल्दी से हमारे साथ आ रहे हैं, है ना?
महात्मा गांधी के समय से... (हालांकि) मुसलमानों के बिना
कांग्रेस से अलग होने पर कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा।
“...अगर मुझे तुम्हारे साथ अंधाधुंध देखा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर हम विपक्ष में बैठे रहना जारी रखें... हम मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे।
आप राम जन्मभूमि के माध्यम से हिंदू वोटों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं।
(हलचल)। आप मुझे गाली दे सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैं नहीं कर सकता।
आपके साथ एक ही मंच साझा करने के लिए, कृपया बुरा महसूस न करें... कृपया।

अपने लोगों को यह बात समझाएं।
गोविंदाचार्य और वी.पी. सिंह के बीच बातचीत इसके तुरंत बाद हुई।
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी शहर मथुरा में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। जब उपराष्ट्रपति ने...
वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मंच पर जनता पार्टी के झंडे के साथ-साथ भाजपा के झंडे भी लहरा रहे थे।
दल के झंडे। उन्होंने हंगामा किया। 'जब तक भाजपा ऐसा नहीं करेगी, मैं मंच पर नहीं जाऊंगा।'
झंडे हटा दिए गए हैं।
वी. पी. सिंह ने मथुरा से गोविंदाचार्य को फोन किया। ‘कृपया, बात कीजिए’
उन्होंने कहा, 'अपने लोगों को बुलाओ और भाजपा के झंडे उतरवाओ।' झंडे
इसे जनता के सामने गिरा दिया गया। तभी उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया।
रैली। इस कार्रवाई से उन्होंने मुसलमानों को स्पष्ट संदेश दिया कि वह
उन्होंने भाजपा से खुद को अलग कर लिया। ‘मैं ऐसा कर सकता हूँ (झंडे उतार सकता हूँ),’
गोविंदाचार्य ने कहा, 'क्योंकि उस समय मुझे संगठन का समर्थन प्राप्त था।'
उस दिन वीपी ने गोविंदाचार्य से कहा, 'राजीव के जाने के बाद हम लड़ सकते हैं।'
हम एक दूसरे से लड़ेंगे। बाद में पता चलेगा कि कौन किस पर हावी होता है।
■

सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।
गोविंदाचार्य ने मुझे बताया, '29 जून 1990 को ही।' (अनौपचारिक रूप से)
जून 1990 के दौरान भाजपा के भीतर लगातार विचार-विमर्श चलता रहा।
जैसा कि पहले बताया गया है, 1 जुलाई 1990 को दिल्ली में एक गुप्त बैठक में यह बात सामने आई थी कि
निर्णय को अंतिम रूप दे दिया गया था। यह उपराष्ट्रपति के निर्णय लेने से पांच सप्ताह पहले की बात है।
अगस्त में मंडल यात्रा को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। यात्रा की तैयारियां

पूरी हो चुकी थीं।
यह कार्य जुलाई 1990 में ही शुरू हो गया था।
‘रथ यात्रा का विचार मेरा था,’ आमतौर पर विनम्र रहने वाले व्यक्ति ने कहा।
गोविंदाचार्य ने खुलासा किया। उन्होंने इस बारे में भाऊराव देवरस से चर्चा की थी, जिन्होंने
वे आरएसएस के राजनीतिक विंग के प्रभारी थे। 'भौराव'
गोविंदाचार्य ने कहा, 'नए विचारों को प्रोत्साहित करें।'
भाऊराव ने गोविंदाचार्य को आगे बढ़ने के लिए अपना समर्थन दिया।
योजना। हालांकि गोविंदचार्य ने ऐसा नहीं कहा, आरएसएस के तौर-तरीकों को देखते हुए।
यदि यह कार्यप्रणाली कारगर होती, तो उनके प्रस्ताव पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई होती।
संघ के निर्णय लेने वाले पदानुक्रम से परामर्श लेने के बाद ही इसे मंजूरी दी गई।
तब तक भाजपा ने मंदिर (मंदिर निर्माण का प्रस्ताव) को अपना लिया था।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण (अपनी कार्ययोजना के तहत) किया गया था। यह कार्य मध्यकाल में किया गया था।
1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में आयोजित अपनी राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में।
तब तक, केवल विजया राजे सिंधिया और जैसे व्यक्तिगत भाजपा सदस्यों को ही यह अवसर मिला था।
Vinay Katiyar, had supported the VHP’s temple plan.
शुरू में, कई वरिष्ठ भाजपा नेता मंदिर को शामिल करने के लिए अनिच्छुक थे।
पालमपुर प्रस्ताव में उन्हें केवल हल्की प्रतिक्रिया मिली थी।
इस विचार पर प्रतिक्रिया देते हुए, 'मुझे याद है सुषमा स्वराज ने हिमाचल प्रदेश में भाषण दिया था।'
गोविंदचार्य ने याद करते हुए कहा, ‘प्रथम प्रदेश। जब उन्होंने राम का जिक्र किया।’
जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भीड़ शांत थी। जब उसने शुरुआत की
किसानों की जरूरतों के बारे में बोलते हुए, उनके शब्दों का जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। लेकिन आरएसएस और वीएचपी ने भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया।

मंदिर के निर्माण के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करना।
भाऊराव देवरास ही थे जिन्होंने आडवाणी को मनाने में कामयाबी हासिल की।
वाजपेयी ने भी इस योजना का समर्थन करने का फैसला किया। लेकिन, राष्ट्रीय फ्रंट के सत्ता में आने पर वाजपेयी की उदारवादी विचारधारा फिर से मजबूत हो जाएगी।
स्वयं। जब भी भाजपा की आंतरिक बैठकों में मंदिर का मुद्दा उठता था,
वाजपेयी कहते, 'जल्दी क्या है? यह कुछ समय के लिए इंतजार कर सकता है...।'
अगर हम इन "कट्टर" धर्मनिरपेक्ष लोगों के साथ सख्ती से पेश आते हैं, तो गठबंधन टूट सकता है।
वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाए।
सत्ता। भाजपा नेता यह नहीं भूल सके कि उपराष्ट्रपति के साथ उनके गठबंधन ने इससे पार्टी को 85 सीटें मिलीं, जो कि अकेले चुनाव लड़ने पर मिली मात्र 2 सीटों से कहीं अधिक थीं।
1984 में, वे चुनावी कारणों से मंदिर के मुद्दे को दरकिनार करने को तैयार थे।
लाभ।
लेकिन जनता दल में महम के बाद हुए हंगामे ने यह बात आश्वस्त कर दी थी।
भाजपा-आरएसएस-वीएचपी परिवार के कई सदस्यों का मानना था कि उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।
उपराष्ट्रपति सरकार। जैसा कि देखा गया है, वीएचपी ने पहले ही एक और घोषणा कर दी थी।
अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा के माध्यम से निर्माण कार्य शुरू किया गया।
मंदिर।
जून 1990 में इसी समय गोविंदाचार्य ने बात की थी।
आडवाणी ने रथ यात्रा करने के बारे में बात की।
'हालांकि मैं छोटा था, आडवाणी जी मेरी बातें सुनते थे और उन्हें महत्व देते थे।'
गोविंदाचार्य ने कहा, 'मैंने जो कहा, उस पर प्रतिक्रिया हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि...'
संघ (आरएसएस)। एक तरह से, वह मुझे भाऊराव के प्रतिनिधि के रूप में मानते थे

(में)।
भाजपा)। गोविंदाचार्य ने आडवाणी को अभूतपूर्व सफलता की याद दिलाई।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की 1983 में हुई एकात्मा यात्रा के बारे में। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा, यह यात्रा
यह घटना हिंदू धार्मिक उत्साह की लहर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार थी।
आज भाजपा की भूमिका कुछ इसी तरह का माहौल बनाने की हो सकती है...
'देश,' गोविंदचार्य ने आडवाणी से प्रभावी ढंग से कहा।
आडवाणी ने जवाब दिया, 'बात तो सही है (यह अच्छा लगता है)।' 'एक काम कर,'
उन्होंने गोविंदचार्य से कहा, 'आप बाकी लोगों से भी बात कीजिए—अटलजी से, सिकंदर से।'
Bakhtji, Rajmataji....'
गोविंदाचार्य ने विभिन्न भागों से चार यात्राओं का प्रस्ताव रखा।
देश के लोग 30 अक्टूबर के अवसर पर अयोध्या में एकत्रित होंगे।
कर सेवा। 'विचार यह था कि आडवाणी कन्याकुमारी से प्रस्थान करें या
Kalady,' Govindacharya recalled. 'Sikander Bakht would start his yatra
मुंबई से, वाजपेयी जम्मू से और राजमाता (विजया राजे सिंधिया) कामाख्या (असम) से। और उनकी मुलाकात अयोध्या में होगी
30 अक्टूबर (1990) को वहां कार सेवा में भाग लेने के लिए...
'(हालांकि), जब मैंने बाकी तीनों से बात की, तो उन्होंने मना कर दिया...।
Rajmataji said she could not do it for reasons of health. Sikander Bakht
उसने कहा कि कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन "मैं कभी-कभार इसमें शामिल हो जाऊंगा"।
अटलजी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा, "मैं इस नौटंकी में विश्वास नहीं करता।"
(नाटकीयता)...।"
गोविंदचार्य ने आडवाणी को रिपोर्ट दी। तब यह निर्णय लिया गया कि
इस यात्रा का नेतृत्व केवल आडवाणी ही करेंगे। आडवाणी ने कहा, 'हम एक ही काम करेंगे।'

उन्होंने कहा, 'अगर मैं कलाडी से शुरू करूं तो यह बहुत ज्यादा धार्मिक मुद्दा बन जाएगा...'

मैं सोच रहा था कि शायद मुझे सोमनाथ से शुरुआत करनी चाहिए। समस्या यह है कि इसे राजनीतिक ही रहना चाहिए। क्योंकि, आखिरकार, हम यह काम भाजपा के लिए कर रहे हैं (जैसा कि

एक राजनीतिक दल)।

भाजपा नेता प्रमोद महाजन को, उनके जुझारू स्वभाव के कारण, इस काम में शामिल किया गया।

उन्हें रसद व्यवस्था संभालने और रथ लाने का काम सौंपा गया था।

(रथ) का निर्माण हो गया। 'यह सब मुझ पर छोड़ दो,' महाजन ने कहा।

आश्वस्त करने वाली बात यह थी कि वह अपने संपर्कों के कारण बड़े आयोजनों के आयोजन के लिए जाने जाते थे।

उन्होंने मुंबई के कॉर्पोरेट जगत के साथ संबंध स्थापित किए और रथ यात्रा के लिए उनका लाभ उठाया।

अरुण जेटली को दिल्ली में प्रेस और प्रचार संबंधी मामलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया था।

और गोविंदचार्य को यात्रा की दैनिक योजना बनाने का कार्य सौंपा गया था।

‘रथ यात्रा का निर्णय (मंडल के निर्णय से) बहुत पहले ही हो गया था।’

गोविंदाचार्य ने मुझे जोर देकर बताया, ‘जुलाई (1990) में भी यही निर्णय लिया गया था।’

हमने खुद ही यह घोषणा की थी कि हम इसे सार्वजनिक रूप से केवल 15 या 16 सितंबर को ही घोषित करेंगे।

तब तक इसे गुप्त रखा जाना था... यात्रा 25 तारीख से शुरू होनी थी।

सितम्बर।'

योजना के अनुसार, यात्रा की घोषणा 16 सितंबर 1990 को की गई थी। लेकिन

क्योंकि तब तक वी. पी. सिंह मंडल को गोद ले चुके थे, इसलिए भाजपा ने रथ को ही मुख्य मुद्दा बना दिया।

यात्रा उनके निर्णय की प्रतिक्रिया थी।

■

मंडल मंदिर की प्रतिक्रिया थी—न कि इसके विपरीत—जैसा कि
यह व्यापक रूप से माना जाता है। यहां तक कि रथ यात्रा भी मंडल आंदोलन की प्रतिक्रिया नहीं थी।
जैसा कि अभी देखा गया, इसे आयोजित करने का निर्णय एक महीने पहले, 29 तारीख को लिया गया था।
जून 1990—वी. पी. सिंह द्वारा मंडल की घोषणा किए जाने से चालीस दिन पहले
7 अगस्त 1990।
भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद की लहर का फायदा उठाते हुए अपनी सीटों की संख्या में 2 से 2 की वृद्धि दर्ज की।
1989 में सीटों की संख्या बढ़ाकर 85 कर दी गई। इसके लिए बहुत मेहनत से प्रारंभिक कार्य किया गया था—जो कि
उत्तर प्रदेश में आमने-सामने की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ेगा।
कांग्रेस में फूट को रोकने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का रुख
विपक्ष के वोटों ने मदद की। लोकसभा की अधिकांश सीटों पर ऐसा ही हुआ।
राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विपक्षी एकता का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन
महम के बाद, भाजपा को लगा कि सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। उसने फैसला किया
मंदिर वापस जाकर धार्मिक आधार पर लोगों को संगठित करना—और प्राप्त करना
शीघ्र चुनाव के लिए तैयार।
जैसा कि हम देख चुके हैं, वीपी ने देवी लाल को मात देने के लिए मंडल कार्ड का इस्तेमाल किया।
लेकिन, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह एक वैकल्पिक समर्थन व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहा था।
सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आधारित—जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से मिलकर बना है,

मुसलमान और उच्च जातियों का एक वर्ग, जिनमें उनकी अपनी जाति भी शामिल है —यह जानते हुए कि
भाजपा के पास जो योजनाएँ थीं, वे योजनाएँ थीं। लेकिन चीजें ठीक से नहीं हो पाईं।
जैसा कि उपराष्ट्रपति ने योजना बनाई थी।
मंडल ने रथ यात्रा के लिए, जिसकी योजना पहले से ही बनाई जा चुकी थी, एक सहायता प्रदान की।
यह बेहद जरूरी था। भाजपा जाति के आधार पर अपने मतदाता आधार के विखंडन का जोखिम नहीं उठा सकती थी।
उसे डर था कि अगर वह मंडल के प्रति नाराज़ अपने समर्थकों को खो देगा तो वह उन्हें खो देगा।
वी. पी. सिंह सरकार को लगातार समर्थन देते रहे।
अगस्त और सितंबर में आत्मदाह करने वाले युवक
1990 में मंडल के सिकुड़ते स्वरूप के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया।
अवसरों; इसने उनमें पीड़ित होने की भावना पैदा कर दी। अचानक,
उच्च जातियाँ एक 'मजबूत आधार' बन गईं। मंडल ने विभिन्न वर्गों को एकजुट किया।
लोग—गांधीवादी, मार्क्सवादी, धार्मिक कट्टरपंथी और धर्मनिरपेक्षवादी
—क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। कई लोगों ने भाजपा की ओर रुख किया।
सुरक्षा और समर्थन।
उच्च जातियों के कड़े विरोध ने एक प्रतिवाद को जन्म दिया।
ओबीसी समुदायों में अपनी पहचान को लेकर राजनीतिक चेतना—जो
अन्यथा शायद इतनी जल्दी ऐसा नहीं होता।
■

इसी दौरान एक दिन भूरे लाल के घर एक बिना हस्ताक्षर वाला पत्र पहुंचा।
यह राष्ट्रपति भवन से लाया गया था और यह उपराष्ट्रपति के निवास के लिए था।
सिंह की आँखों में। राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन से, यह संकेत मिलता है कि प्रधान
मंत्री ने अनुच्छेद के तहत मंडल को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया।

संविधान का अनुच्छेद 143। इससे उस स्थिति को शांत किया जा सकता था जो बिगड़ती जा रही थी।
तेजी से ज्वलनशील होता जा रहा है।
भूरे लाल वह पत्र वी.पी. सिंह के पास ले गए। वी.पी. सिंह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे।
सुझाव दिया। लेकिन पार्टी में मंडलवादियों ने उन्हें ऐसा न करने के लिए मना लिया। इसलिए।
वीपी को पता था कि वह मंडल के बारे में लिए गए अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता—भले ही वह
वे ऐसा करना चाहते थे। किसी भी तरह के पीछे हटने से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) विरोध प्रदर्शन के लिए बाहर आ जाते।
सड़कों पर हिंसा भड़क उठी, जिससे और अधिक झड़पें और हिंसा हुई। अब उसके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
आगे बढ़ो। उपराष्ट्रपति दृढ़ रहे।
'मंडल के पीछे बहुत सारी राजनीति थी,' वीपी ने वर्षों पहले कहा था।
बाद में। 'पहली प्रतिक्रिया (मंडल के प्रति छात्रों का विरोध) वास्तविक थी।'
बाद में, राजनेताओं ने अपने स्वार्थों के लिए इसे हवा दी।
हालांकि, उपराष्ट्रपति ने अपनी सरकार को बचाने के लिए अंतिम प्रयास किया।
रथ यात्रा के दौरान ही 19 अक्टूबर 1990 को एक अध्यादेश जारी किया गया था।
यह अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विचार यह था कि...
सरकार को विवादित भूमि (27 हेक्टेयर) का अधिग्रहण करना होगा।
विवादित ढांचे को खाली कराकर वहां वीएचपी को कार सेवा शुरू करने की अनुमति दी जाए।
विवादित बाबरी ढांचा सरकार के पास तब तक रहेगा जब तक...
सुप्रीम कोर्ट ने इस पेचीदा सवाल का फैसला किया कि क्या कोई मंदिर मौजूद था।
अतीत में वहां। वीएचपी और भाजपा इस योजना पर सहमत हुए। 'अगर आप जीतते हैं तो
उपराष्ट्रपति ने भाजपा नेताओं से आशावादी लहजे में कहा, 'अदालत में सुनवाई का समय बढ़ाया जा सकता है।' उन्होंने आगे कहा, 'आप इसे बढ़ा सकते हैं।'

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके बगल में ही एक मंदिर है।'
‘(तब) मैं भी आपके साथ कार सेवा करने चलूंगा,’ उन्होंने कहा।
भाजपा नेता प्रसन्नतापूर्वक। इस पर भैरों सिंह शेखावत ने चुटकी लेते हुए कहा,
व्यंग्यात्मक लहजे में, 'अगर आप कार सेवा करेंगे, तो हमारे लिए क्या बचेगा?'
करना!'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ही गोली चलाई थी।
प्रस्ताव पर उन्होंने कहा, 'अयोध्या में एक चिड़िया भी प्रवेश नहीं करेगी।'
जिसे आने वाले वर्षों तक उद्धृत किया जाना था। उन्होंने कार की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
सेवकों को अयोध्या में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। दो दिनों के भीतर, उपराष्ट्रपति को अपना आदेश वापस लेना पड़ा।
अध्यादेश। ‘उसी दिन मैंने रात 9 बजे लालू (यादव) को फोन किया और उन्हें बताया आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए। हमने रेड अलर्ट जारी किया। लेकिन मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए थी।
प्रशासनिक तंत्र को और मजबूत करने के लिए कुछ समय की मोहलत... मैंने कहा।
लालू ने (अडवानी को) रात 2 बजे के बाद गिरफ्तार किया ताकि प्रेस में कुछ भी न आए।
अगली सुबह, (भाजपा) समर्थकों ने कोई उग्र रुख नहीं अपनाया।’ वीपी ने
मैंने यह तरकीब इंदिरा गांधी से सीखी थी। वह किसी विवादास्पद फैसले की घोषणा देर रात करती थीं ताकि प्रेस अपनी तय समय सीमा चूक जाए। एक दिन की देरी
शीर्षक का प्रभाव उतना नहीं पड़ा।
आडवाणी को लालू यादव ने 23 अक्टूबर 1990 को सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया था।
बिहार के समस्तीपुर जिले में भाजपा ने उपराष्ट्रपति से अपना समर्थन वापस ले लिया।
सरकार। भाजपा का वापसी पत्र पहले ही वाजपेयी के पास था।
वह राष्ट्रपति के पास गए और उसे सौंप दिया। बाद में वाजपेयी ने उपराष्ट्रपति को बताया,
‘Aapne Mandal kiya, toh humne Kamandal kar diya (You went

in for
मंडल इसलिए हमने कमंडल का विकल्प चुना। कमंडल एक अवशेष पात्र है जो
हिंदू तपस्वी इसे धारण करते हैं।
■

एच.आर. ने खुलासा किया, 'राजीव ने रथ यात्रा को सफल बनाने में मदद की।'
भारद्वाज ने रहस्यमय ढंग से कहा, 'ताकि उपराष्ट्रपति आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हो जाएं।'
और भाजपा उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी।' हालांकि
भारद्वाज ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस ने मदद दी थी।
रथ यात्रा के लिए लोगों को बिना आगे आए ही जुटाएं। फिर
भारद्वाज ने बाद में कहा, 'राजीव उतना भोला नहीं था जितना लोग समझते हैं।'
माना जाता है।'
जब यह स्पष्ट हो गया कि उपराष्ट्रपति सरकार अपने अंतिम चरण में है,
अरुण नेहरू ने राजीव गांधी को एक संदेश भेजा। जनता दल के कई सदस्यों ने उनसे असहमति जताई।
उन्होंने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करते हैं तो वे उनका समर्थन करने को तैयार होंगे।
यह मंत्री पद उन लोगों के लिए घर वापसी होगी जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी।
1987 में। कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा था कि राजीव गांधी सत्ता संभाल लेंगे।
फिर से प्रधानमंत्री के रूप में। 'मुझे यह पता है। यहां तक कि पड़ोसी देश भी...'
दिनेश त्रिवेदी ने कहा, 'हमें सतर्क कर दिया गया था...।'
हम कांग्रेस में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार थे। यहां तक कि (हमारे) शामिल होने का दिन और समय भी तय हो चुका था।
त्रिवेदी ने कहा, 'जॉइनिंग तय हो चुकी थी। मुझे लगता है कि यह (ठीक) पहले ही हुई थी।'
नवंबर (1990) के पहले सप्ताह में विश्वास प्रस्ताव। निर्णय
कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा सुबह 9 बजे की गई थी। इसकी घोषणा शाम 6

बजे होनी थी।
उसी दिन दोपहर को... खुशी का माहौल था, मानो आखिरकार सब कुछ ठीक हो रहा हो।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। और राजीव प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगे। और वही पुरानी बातें।
टीम वापस आ जाएगी। अरुण नेहरू का पुनर्वास किया जाना था। उनके पास था।
परिपक्व हो गया था। वह अक्सर कहते थे, "हमें कांग्रेसी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, हम अभ्यस्त हैं..."
मध्य मार्ग का अनुसरण करना।
कांग्रेस के दिग्गज नेता एच. के. एल. भगत अरुण नेहरू का समर्थन कर रहे थे।
पार्टी में वापसी। देखने में तो एम. एल. फोतेदार और सतीश शर्मा भी वापसी कर रहे थे। लेकिन (वास्तव में) फोतेदार, सतीश शर्मा और आर. के. धवन
त्रिवेदी ने खुलासा किया, 'उन्होंने इसमें तोड़फोड़ की।' हालांकि शुरुआत में फोतेदार और सतीश ने
शर्मा ने अरुण नेहरू को राजीव गांधी से दोबारा संपर्क स्थापित करने में मदद की थी।
'उन्हें नेहरू की कांग्रेस में वापसी का वाकई डर था।'
राजीव को डर था कि दोनों चचेरे भाई, राजीव और अरुण,
साथ मिलकर वे कांग्रेस पर फिर से हावी होने लगते हैं—और वे ऐसा कर भी सकते हैं।
हाशिये पर धकेल दिया गया।
पूर्व जन मोर्चा समूह को सोनिया गांधी पर भी संदेह था।
अरुण नेहरू को कांग्रेस में दोबारा प्रवेश करने से रोकने में उनका हाथ था।
■

राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन ने ही इस प्रस्ताव को खारिज किया था।
जब उपराष्ट्रपति सरकार गिरी तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एम. को बताया...
एल. फोतेदार ने कहा कि वे कांग्रेस सरकार को शपथ दिलाने के लिए तैयार हैं।

तुरंत। लेकिन यह इस शर्त पर होगा कि राजीव गांधी सहमत हों।
प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
राजीव गांधी की उसी दिन बाद में वेंकटरमन से मुलाकात होनी थी।
फोतेदार सुबह राष्ट्रपति से बात करने गए थे।
'आरवी (वेंकटरमन) व्यक्तिगत रूप से राजीव के खिलाफ थे,' एच. आर. भारद्वाज ने कहा।
उन्होंने मुझे बताया था। उनका मानना था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक
पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रति उनकी प्राथमिकता, जिन्हें उन्होंने अपने साथ बनाए रखा था
मंत्रालय ने वेंकटारमन को सरकार से बाहर करते हुए उन्हें दूसरे मंत्रालय में भेज दिया।
अगस्त 1984 में उपराष्ट्रपति का औपचारिक पद।
हैरान फोतेदार ने राजीव गांधी को बताया कि राष्ट्रपति ने क्या किया।
वेंकटारमन ने उनसे कहा था, 'राजीव काफी देर तक सोच में डूबा रहा।'
फोतेदार ने याद करते हुए कहा, 'लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।' तभी उन्हें यह एहसास हुआ।
अंततः, उन्होंने चंद्र शेखर को प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन देने का निर्णय लिया।
■

जब उपराष्ट्रपति सरकार डगमगा रही थी, तब उनके एक सहयोगी ने फोन किया था।
मुंबई के एक शीर्ष उद्योगपति से कहा गया, 'हम लगातार सुन रहे हैं कि आप नाखुश हैं।'
सरकार... ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता,' उन्होंने कहा।
चापलूसी भरे लहजे में। उद्योगपति ने उसे बीच में ही रोक दिया। 'क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ?'
(एक कमीना)?', उसने बेरहमी से कहा। 'इस आदमी (वी. पी. सिंह) ने खत्म करने की कोशिश की है।
हमें। क्या आपको लगता है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे और उसे नष्ट नहीं करेंगे?

अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में, वी. पी. सिंह को राजीव गांधी से लगातार प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी।
गांधी उसे गिराने की कोशिश कर रहा था, क्रोधित चंद्र शेखर परेशानी को और बढ़ा रहा था, एक
विद्रोही देवी लाल की मांगें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं, और अंत में
एक दौर में, आक्रामक भाजपा ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। फिर
उद्योगपतियों का एक समूह था जो उससे बदला लेना चाहता था।
वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने उनमें से कई लोगों के खिलाफ छापे मारे थे।
मंत्री। इन सभी ताकतों और अन्य कई कारकों के संयोजन ने यह सुनिश्चित किया कि उनका
सरकार केवल ग्यारह महीने तक चली।
■

7 नवंबर 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विश्वास खो दिया।
संसद में प्रस्ताव। उनकी ग्यारह महीने पुरानी सरकार पारित हो गई।
इतिहास। उनके कट्टर विरोधी चंद्र शेखर प्रधानमंत्री बने।
जनता दल के साठ बागी सांसदों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए, जिन्हें समर्थन प्राप्त था।
राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस द्वारा 'बाहर' कर दिया गया। चंद्र शेखर का
सरकार केवल सात महीने तक चली, जिनमें से तीन महीने उसने...
कार्यवाहक सरकार के प्रमुख। लेकिन यह एक अलग प्रधानमंत्री पद का मामला है।
कहानी।
ग्यारहवीं

‘Jab tak samaj maen vishamta hai, tab tak samajik nyay ki avashyakata
है (जब तक समाज में असमानताएं रहेंगी, तब तक इसकी आवश्यकता रहेगी)
सामाजिक न्याय)।’ ‘ये शब्द वी.पी. सिंह ने नहीं कहे थे,’ वीपी ने कहा।

1999 में, अत्यधिक संतुष्टि व्यक्त करते हुए। 'ये बातें अटल द्वारा कही गई थीं।
बिहारी वाजपेयी (ओबीसी के लिए आरक्षण की आवश्यकता के बारे में)। वाजपेयी का
उनके शब्दों से पता चलता है कि मंडल ने किस प्रकार देश के राजनीतिक एजेंडे को
बदल दिया था।
लगातार सरकारों को नौकरी की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना
ओबीसी के लिए आरक्षण 'अपरिवर्तनीय' है। कोई भी प्रधानमंत्री इसे रद्द नहीं कर
सकता।
प्रक्रिया।
अगर कुछ हुआ भी तो, उपराष्ट्रपति के बाद के प्रधानमंत्रियों ने नौकरी आरक्षण के
दायरे को बढ़ाया।
ओबीसी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जाटों को आरक्षण दिया था।
राजस्थान में उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल करना, जहां उनकी संख्या अधिक है
हरियाणा या उत्तर प्रदेश के जाटों से भी पिछड़ा हुआ।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में एक कदम और आगे बढ़ाया और
केंद्रों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
उच्च शिक्षा संस्थानों सहित, जिनमें विशिष्ट संस्थान भी शामिल हैं।
■

मंडल फैसले के बाद के दिनों में, कई लोगों ने सरकार को चुनौती दी।

अदालत में फैसला। 1 अक्टूबर 1990 को, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया।
निर्णय स्थगित। अदालत द्वारा लगाया गया यह स्थगन कानून के लिए राहत की बात
साबित हुआ।
संकटग्रस्त उपराष्ट्रपति सरकार, जिस पर चारों ओर से हमले हो रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ मिलाकर सुनवाई की।
इसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के नाम से जाना जाएगा। दो साल बाद,
1992 में, देश की सर्वोच्च अदालत ने इसकी वैधता को बरकरार रखा।
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर 27 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का निर्णय
ओबीसी के लिए सरकार। इसमें जाति को एक स्वीकार्य निर्धारक भी पाया गया।

पिछड़ेपन का। फैसले में यह भी कहा गया कि आरक्षित सीटों की संख्या
कुल उपलब्ध सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते थे। हालाँकि,
अदालत ने सरकार से संपन्न वर्गों को सूची से बाहर रखने को कहा।
लाभार्थियों के बारे में—जो उसने एक अन्य ज्ञापन जारी करके किया।
8 सितंबर 1993 को।
अब तक नरसिम्हा राव सत्ता में आ चुके थे। उन्हें ही कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया था।
मंडल आयोग की रिपोर्ट—वही नरसिम्हा राव, जैसा कि हमने देखा
अध्याय में पहले बताया गया है कि उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा नियुक्त समिति की अध्यक्षता की थी।
मंडल आयोग की रिपोर्ट पर गठित मंत्रिस्तरीय समिति में वे सदस्य के रूप में बैठे रहे।
नौ साल तक इस प्रयास से कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
राव सरकार ने 1 लाख रुपये की वार्षिक आय को एक प्रमुख सीमा के रूप में निर्धारित किया था।
पात्रता के लिए मानदंड। बाद में इसे बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया। इसके बाद,
मंडल भारतीय सरकार की आधिकारिक नीति बन गई।
आरक्षण रद्द करने की कोशिश की तो जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ा। आरएसएस ने 2015 के बिहार चुनावों के दौरान आरक्षण पर सवाल उठाने का प्रयास किया गया था। लेकिन
बहुत जल्दी ही उसे पीछे हटना पड़ा। आरक्षण रद्द होने के डर से उसने ऐसा किया।
ओबीसी समूह एकजुट हुए; यही एक कारण था कि भाजपा उस चुनाव में हार गई।
चुनाव हुए और लालू यादव-नीतीश कुमार की जोड़ी जीत गई।
अक्टूबर 2017 में, जी. रोहिणी आयोग का गठन वर्गीकरण के लिए किया गया था।
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उपसमूहों में विभाजित करना और उनकी जनसंख्या के बारे में डेटा एकत्र करना।
आरक्षण के लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए
बड़ी संख्या। 2018 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, केवल दस
समुदायों ने आरक्षित नौकरियों में से 97 प्रतिशत पर कब्जा कर लिया था।
ओबीसी समुदाय। और 2,600 ओबीसी समुदायों में से 983 को कोई सहायता नहीं

मिली।
नौकरियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व। आयोग, जिसका उद्देश्य मदद करना था
आरक्षण नीति को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार को तीन महीने के भीतर यानी जनवरी 2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इसके बजाय, अब तक
सितंबर 2022 तक, इसे दस बार एक्सटेंशन मिल चुका था।
वी. पी. सिंह के बाद किसी भी सरकार ने आरक्षण की नीति को रद्द करने का प्रयास नहीं किया।
ओबीसी के लिए। उन्होंने तो केवल और अधिक समुदायों को इसके दायरे में लाने की कोशिश की थी।
दायरा।
■

उपराष्ट्रपति ने अपने इस फैसले के बारे में कहा, 'मंडल ने राजनीति के व्याकरण को ही बदल दिया।'
मंडल के साथ, जाति महज एक राजनीतिक श्रेणी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई।
केवल रीति-रिवाजों, व्यवसाय और पूर्वाग्रहों पर आधारित पदानुक्रमित सामाजिक संरचना
इसे परिभाषित करना। जैसा कि हमने देखा है, जाति का राजनीतिकरण तो शुरू ही हो चुका था।
स्वतंत्रता से पहले, जब अंग्रेजों ने इसे एक श्रेणी के रूप में स्वीकार किया था
1931 की जनगणना। इन समूहों ने निम्नलिखित आधारों पर संरक्षण की मांग शुरू कर दी:
उनकी संख्या। लेकिन उपराष्ट्रपति के फैसले ने इस प्रक्रिया को अभूतपूर्व गति प्रदान की।
पहले।
मंडल ने क्षेत्रीय दलों और पहचान की राजनीति को भी बढ़ावा दिया।
और इस प्रकार गठबंधन शासन की ओर अग्रसर हुए। जाति आधारित क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ।

उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश की आरजेडी, समाजवादी पार्टी और जनता दल (यू) जैसी पार्टियां हैं।
और बिहार। जाति आधारित छोटे-छोटे समूह तेजी से उभरने लगे—उदाहरण के लिए, राजभर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी, कुर्मी-बहुल समुदाय
अपना दल, निषादों की एक और पार्टी, ये तीनों अकेले उत्तर प्रदेश में—और ये
मुख्यधारा की पार्टियों ने उन्हें लुभाने की कोशिश की। उनकी संख्या बढ़ने लगी थी।
मामला।
उनकी बढ़ती ताकत ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में ओबीसी को सक्षम बनाया—
अनुसूचित जातियों को भी उच्च जातियों के साथ रणनीतिक गठबंधन करने के लिए ऐसा करना चाहिए।
चुनाव के समय मजबूत स्थिति से। जब दलित नेता मायावती
2007 में ब्राह्मणों के साथ गठबंधन करते हुए, उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल किया।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने एक लंबा सफर तय किया था।
war cry given by her mentor Kanshi Ram, 'Tilak, Tarazu, aur Talwar,
इनको मारो जूते चार'. (नारे में दलितों को लात मारने का जिक्र था
उच्च जातियों में, तिलक ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करता है, तराजू या तराजू का।
बनिया समुदाय का प्रतिनिधित्व तलवार करती है, और तलवार राजपूतों का।
हालांकि दलितों और सबसे पिछड़ी जातियों के खिलाफ अत्याचार होते रहे हैं
अब भी जारी है, वो दिन चले गए जब उच्च जाति के गुंडे दबदबा कायम रख सकते थे
दलितों या सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों की ओर से मतपत्रों पर मुहर लगाएं।
कक्षाएँ (एमबीसी), चुनाव का अपहरण।
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में अधिक प्रभावशाली, जैसे यादव और कुर्मी।
—या ओबीसी के बीच 'मलाईदार परत'—को अधिक लाभ हुआ। लेकिन समय के साथ,
सत्ता धीरे-धीरे गैर-यादव/कुर्मी ओबीसी, या एमबीसी को हस्तांतरित होने लगी—
दलितों में सबसे वंचित महादलित—और 'पसमांदा'
मुसलमानों में सबसे पिछड़े वर्ग के लोग।
मंडल ने देश में जातिगत चेतना को भी बढ़ावा दिया।

उच्च जाति के लोग इस बात पर अफसोस जताते थे कि इसने समाज को विभाजित कर दिया है। लेकिन मंडल के लिए
लाभार्थियों के लिए, जाति एक सम्मान का प्रतीक बन गई - जिससे इसका महत्व कम हो गया।
उनके रुतबे के इर्द-गिर्द फैली नफरत। उनके साथ भेदभाव किया गया।
सदियों से, सकारात्मक कार्रवाई उनके सशक्तिकरण का एक साधन रही है—एक हालचाल जानने का अवसर।
व्यवहार में, जातिवाद और
सामाजिक न्याय। एक बार जब एक समाजवादी कार्यकर्ता ने शरद से कहा था
यादव ने कहा कि उनकी लड़ाई मूल रूप से 'सामाजिक न्याय' के बारे में थी।
उसने पलटवार करते हुए कहा, 'अपना मन बना लो, क्या तुम सामाजिक न्याय चाहते हो या फिर...'
'क्या आप यादव राज चाहते हैं?' उनके जवाब से पता चलता है कि नए विचारों का समूह कितनी जल्दी बदल जाता है।
ब्राह्मणों का उदय हो सकता है।
■

ओबीसी निर्वाचन क्षेत्र के जिस नए उपाध्यक्ष ने उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी, उन्होंने उन्हें अपना नेता नहीं माना।
नेता। वे अपने ही जाति के नेताओं की ओर अधिक मुड़ गए। लेकिन उनका निर्णय
इसके परिणामस्वरूप एक नए ओबीसी नेतृत्व का उदय हुआ जिसने दो दशकों तक भारत पर शासन किया।
that followed. Mulayam Singh Yadav, Lalu Prasad Yadav, Nitish Kumar,
Akhilesh Yadav, Uma Bharati, Kalyan Singh, Shivraj Chouhan, Ashok
गहलोत और अन्य लोगों ने अपने-अपने राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश - पर शासन किया।

Pradesh, and Rajasthan.
2014 में, जब 'चायवाले' नरेंद्र मोदी ने सत्ता की बागडोर संभाली,
देश में, वह पहले एमबीसी बने—वह घांची या
तेल निकालने वाले मजदूर की जाति से भारत का प्रधानमंत्री बनना।
वीपी बार-बार कहते थे कि मंडल का मतलब 'सत्ता में शिरकत' होता है।
(सत्ता में भागीदारी)। यह ‘शिरकत’ होनी चाहिए थी, न कि ‘सहुलियत’ (सत्ता का प्रयोग)।
सत्ता, संरक्षण का वितरण नहीं। उन्होंने मंडल को केवल एक
केंद्र सरकार की सेवाओं में ओबीसी के लिए 44,000 पद आरक्षित किए गए हैं।
ओबीसी द्वारा राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण का प्रयोग करने के बारे में—जो कि
उन्हें सामाजिक उन्नति और आर्थिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मंडल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण जारी है।
ओबीसी और एससी समुदायों के छोटे समूह—जो
वे दुनिया में अपना स्थान चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोट की ताकत का एहसास हो गया है।
लोकतंत्र में। जानबूझकर या अनजाने में, वी. पी. सिंह ने इसका फायदा उठाया।
ओबीसी के बीच हो रही महत्वाकांक्षी क्रांति—और
इससे उसे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित होने में मदद मिली।
बारहवीं
लालटेन से रोशन नावें
समुद्र में बिखरा हुआ
मुझे कौन लेगा?

2003 में अपने जीवन के अंतिम समय में, अपोलो अस्पताल के बिस्तर पर बंधे हुए, उनका निधन हो गया।
नई दिल्ली के एक अस्पताल में, वी. पी. सिंह ने मुझे अपनी कुछ कविताएँ पढ़कर सुनाईं।
उन्होंने लिखा था, ‘एक सुबह मैं बहुत जल्दी उठा और बाहर देखा…’

वी. पी. सिंह ने मन ही मन सोचा, ‘खिड़की से मैंने लालटेन से रोशन नावों को अपनी ओर आते देखा।’
उस समय वह मुंबई के समुद्रतटीय राजभवन में ठहरे हुए थे।
‘ये समुद्र में छोटी नावें थीं जिन पर रोशनी लगी हुई थी... हमारी
धर्म और पौराणिक कथाओं के अनुसार, आप अपनी अंतिम यात्रा करते हैं।
नाव।'
मुंबई में धरने के दौरान 1994 में वीपी के गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए थे।
फ्लोरा फाउंटेन। अब वह हर सेकंड डायलिसिस मशीन से बंधा रहता था।
फिर उन्हें मायलोमा हो गया, जो एक प्रकार का रक्त कैंसर है, जिससे उनके 50 दांत क्षतिग्रस्त हो गए।
उनके अस्थि मज्जा का प्रतिशत हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। डॉक्टरों ने कीमोथेरेपी की सलाह दी, लेकिन उन्होंने
इससे बचने में कामयाब रहा।
उस दिन वह चिंतनशील मनोदशा में थे। अचानक उन्होंने कहा, 'पूरी जिंदगी
मैंने कुछ-कुछ लिख दिया।
उन्होंने आगे कहा, 'अब मुझे एक इरेज़र चाहिए।'
एक समय ऐसा आता है जब आप पूछते हैं—इन सब का अर्थ क्या है?
यह?'
1990 में सत्ता से बाहर होने के बाद, वह वापस चित्रकला की ओर लौट गए थे और कविता लेखन, जो उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में शुरू किया था—सबसे पहले
डायलिसिस के अंतरालों के बीच, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। मंडल
मसीहा अपने जीवन के सफर पर पीछे मुड़कर देख रहा था। कुछ तस्वीरें जो उसने देखीं।
अब उनकी कविताओं में 'देख' का वास दिखाई देता था।
मैं बचपन में कागज की नावों से खेला करता था... जब आप
अपनी यात्रा समाप्त करते ही आपको अपनी... कागज़ की नावों की याद आ जाती है।

अचानक मुझे तैरता हुआ पाया गया

मेरे बचपन की कागज़ की नाव
इसने संकेत दिया
‘चलो, अब जाने का समय हो गया है।’
■

विश्वनाथ प्रताप सिंह यकीनन सबसे विवादास्पद प्रधानमंत्रियों में से एक थे।
भारत में मंत्री रह चुके हैं।
निःसंदेह, वह चालाक या राजनीतिक रूप से धूर्त था—और वह हो भी सकता था।
कठिन। लेकिन उनका एक भावनात्मक पक्ष भी था, जो उनकी कविता में झलकता है।
यह प्रतिबिंबित हुआ—और इसने इस जटिल व्यक्तित्व को परिभाषित किया। वीपी एक थे।
कई मायनों में विरोधाभास—सामंती होते हुए भी सामंती नहीं, एक वफादार और
एक ही समय में विद्रोही, चरित्रवान व्यक्ति और राजनीतिक पाखंडी।
उन्हें अच्छी तरह जानने वाले कई लोगों का कहना था कि उनके 'वास्तविक' व्यक्तित्व को जानना असंभव था।
उपराष्ट्रपति या उनकी निष्ठाएँ किसके प्रति थीं। हालाँकि वे एक सर्वोत्कृष्ट वफादार थे।
अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर के बारे में वे अक्सर बाद के वर्षों में कहते थे।
कि ‘राजनीति में वफादारी जैसी कोई चीज नहीं होती’, यह सब कुछ इसके बारे में है हितों का अभिसरण।
वी. पी. सिंह ने जो किया, वैसा कांग्रेस छोड़ने वाले किसी और ने नहीं किया।
वर्षों से ऐसा नहीं हो पाया था। न तो चंद्र शेखर, न ही शरद पवार,
nor Ramkrishna Hegde, nor Mamata Banerjee, nor Jagan Mohan Reddy.
उन्होंने भी उपराष्ट्रपति की तरह कांग्रेस नेतृत्व से संबंध तोड़ लिए थे।
पिछली शताब्दी के 1970, 1980 और 1990 के दशक में, और साथ ही बीसवीं शताब्दी में भी...
पहली शताब्दी। हेगड़े, पवार, बनर्जी, रेड्डी ने बाद में उनकी जगह ली।

विडंबना यह है कि कांग्रेस ने अपने राज्यों में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने।
कभी-कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया था।
चंद्र शेखर
वह एक ऐसे गुट के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री बने थे जिसे कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त था।
एक बड़ी, दबंग कांग्रेस। लेकिन कोई भी ऐसा निर्माण करने में सफल नहीं हुआ था।
कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में—जैसा कि उपराष्ट्रपति ने किया था, हालांकि यह कुछ ही समय तक चला।
एक साल से कम समय में।
उन्होंने दक्षिणपंथी विचारधारा की लगभग सभी कांग्रेस विरोधी ताकतों को एकजुट किया।
पहली बार सचमुच में एक मंच पर वामपंथी, मध्यमार्गी और क्षेत्रीय दल एक साथ आ रहे हैं।
राष्ट्रीय गठबंधन। यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, जो अपने आप में एक दुर्लभ उपलब्धि थी।
विपक्षी एकता का प्रदर्शन। उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को इसमें हिस्सेदारी दी।
केंद्र में राष्ट्रीय शासन। 'यहां तक कि जब डीएमके के पास भी कोई सत्ता नहीं थी तब भी।
'एकमात्र सांसद होने के नाते, मैं इसे मंत्रिमंडल में लेकर आया,' वे कहते थे। 'विचार यह था कि
एक बार जब वे देश के प्रबंधन में भाग लेना शुरू कर देंगे, तो विखंडन की कोई प्रवृत्ति नहीं रहेगी।' उन्होंने इसे अपने प्रमुख लक्ष्यों में से एक माना।
उपलब्धियां।
मंडल ने कांग्रेस पार्टी के पतन को गति दी, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी का पतन हुआ।
जाति और समुदाय के दोहरे ध्रुवों के बीच, जिसे आम तौर पर कहा जाता है
the ‘Mandal versus Kamandal’ face-off.
कांग्रेस पार्टी के ‘वर्चस्व’ को तोड़ते हुए, उपराष्ट्रपति ने ऐसा प्रहार किया
भारत की इस महान पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है—जिसने

उपराष्ट्रपति के सत्ता संभालने तक उन्होंने चार दशकों तक देश पर शासन किया (छोड़कर)
जनता पार्टी के शासनकाल का संक्रमणकालीन दौर (1977-79) - कभी उबर नहीं पाया
उसके बाद। न ही इसे अपने दम पर बहुमत मिला। पी.वी. नरसिम्हा राव आए।
मनमोहन सिंह 1991 में अल्पमत सरकार के मुखिया के रूप में सत्ता में आए और
सिंह ने 2004 से 2014 तक दस वर्षों तक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया।
वीपी का राजीव गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में उभरना उस दौर के अंत का प्रतीक था।
नेहरू-गांधी परिवार का शासन। भारत के प्रथम परिवार का कोई भी सदस्य,
तब से लेकर इस लेख को लिखे जाने तक, उन्होंने एक सरकार का नेतृत्व किया।
वी. पी. सिंह का नाम आज भी लोगों की भावनाओं को भड़का देता है—कुछ लोग उनकी निंदा करते हैं,
कुछ लोग उन्हें आदरणीय मानते हैं। कुछ लोग उन्हें एक धूर्त राजनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं जो एक
सत्ता बरकरार रखने के हताश प्रयास ने एक ऐसे जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया जिसने
इसे वापस नहीं लाया जा सका। कुछ लोग उन्हें सामाजिक न्याय का मसीहा कहते हैं, और
वह खुद को इसी रूप में देखना पसंद करता था।
‘कुछ लोग सरकारें चलाते हैं,’ उन्होंने मुझसे कहा, प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हुए।
उसने तबाही मचा दी थी। 'मैंने इतिहास रचा है। यह सरकारों को परिभाषित करेगा और'
आने वाले समय में गठबंधन बनेंगे।'

अध्याय 4

वह प्रधानमंत्री जिसने फैसला लेने से इनकार कर दिया

पी.वी. नरसिम्हा राव और बाबरी मस्जिद का विध्वंस

मैं

मैंने सुना है कि आप 6 दिसंबर को रात बारह बजे के बाद पूजा कर रहे थे।
वामपंथी पत्रकार निखिल चक्रवर्ती ने प्रधानमंत्री पी. से कहा।
वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री से मिलने रेस कोर्स रोड स्थित 7 नंबर के कार्यालय में आए थे।
6 दिसंबर 1992 के कुछ दिनों बाद, जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। यह वास्तव में कोई बयान नहीं था, बल्कि एक सवाल था, आंशिक रूप से-
गंभीर और कुछ हद तक व्यंग्यात्मक। लेकिन चक्रवर्ती उत्सुक थे।
यह जानना जरूरी है कि मस्जिद के समय प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे।
उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसे ध्वस्त किया जा रहा था।
6 दिसंबर को दोपहर के समय, एक उन्मादी भीड़ ने धावा बोल दिया था।
बाबरी मस्जिद परिसर में, वे तीनों गुंबदों पर चढ़ गए।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित सोलहवीं शताब्दी की मस्जिद।
प्रदेश में, उन्होंने इमारत को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना शुरू कर दिया।
रस्सियाँ, फावड़े और कुल्हाड़ी। शाम 4:55 बजे तक, वह ढाँचा, जिसे हिंदू
और मुसलमान तैंतालीस साल से भी अधिक समय से इस पर झगड़ते रहे थे,
पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। न तो मस्जिद के आसपास तैनात पुलिस, न ही
अर्धसैनिक बलों को, जिन्हें एक महीने पहले वहां भेजा गया था
केंद्र सरकार को ठीक इसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।
भीड़ को इमारत गिराने से रोका।
मंत्री, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
प्रदेश, और सरकार की कई एजेंसियां जो ऐसा कर सकती थीं
मस्जिद को बचाया, बेबस होकर देखता रहा।

राव ने गुस्से में आकर चक्रवर्ती को जवाब दिया, 'दादा, आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता?'
मुझे राजनीति की अच्छी समझ है। मेरा जन्म राजनीति में हुआ है और मैं हमेशा से राजनीति ही करता आया हूँ।
आज तक की राजनीति। जो हुआ वो ठीक हुआ... (जो हुआ सो हुआ)
for good.) Maine is liye hone diya…ki Bharatiya Janata Party ki mandir ki rajniti hamesha ke liye khatam ho jaye (I allowed it to happen
क्योंकि मैं भाजपा की मंदिर संबंधी राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था।
चक्रवर्ती प्रधानमंत्री से खुलकर बात कर सके क्योंकि
पत्रकार होने के अलावा, वह वर्षों से राव के मित्र भी थे।
उनके साथ तीन अन्य पत्रकार भी थे—प्रभाष जोशी
जनसत्ता, ब्लिट्ज के आर. के. मिश्रा और राम बहादुर राय, जिन्होंने काम किया था
जनसत्ता में जोशी के साथ घनिष्ठ रूप से काम किया।
राय ने याद करते हुए कहा, 'वे राव से अक्सर मिलते थे। उस दिन मैं
मैं संयोगवश उनके साथ था।
बाबरी मस्जिद के पतन से पांच महीने पहले, चक्रवर्ती,
जोशी और मिश्रा प्रधानमंत्री को रास्ता खोजने में मदद कर रहे थे।
अयोध्या में गतिरोध से बाहर निकलने के लिए। हिंदू संगठनों ने जोर दिया कि
मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाया जाए—जो कि वे
दावा किया गया था कि यह भगवान राम का जन्मस्थान है—और मुस्लिम समूह
वे उस इमारत को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे जिसे वे मस्जिद मानते थे। तीनों ने
उन्होंने विवाद के दोनों पक्षों के साथ पर्दे के पीछे कई वार्ताएं कीं।
6 दिसंबर को पूरे दिन दिल्ली अफवाहों की चपेट में रही।
कि प्रधानमंत्री मस्जिद और उसके आसपास के इलाके में सो रहे थे।
गुंबदों को गिरा दिया गया। दूसरों ने कहा कि वह पूजा कर रहा था।
पहला गुंबद ढह गया, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने गोली चलाई
भीड़ को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को लिखे गए कड़े शब्दों वाले पत्र में कहा गया है

कि...
मस्जिद को गिराना।
प्रधानमंत्री ने उस दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई।
निर्णय लेने के लिए—लेकिन यह निर्णय शाम 6 बजे ही लिया गया। तब तक बाबरी मस्जिद में आग लग चुकी थी।
मस्जिद मलबे में तब्दील हो चुकी थी। केंद्र सरकार के लिए
हस्तक्षेप करने और राज्य सरकार का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में लेने की स्थिति में, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कर सकते थे।
यह केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही संभव है। प्रधानमंत्री
मंत्री ने सारी कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही बैठक बुलाई।
■

चक्रवर्ती और उनके सहयोगियों के जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर, राव
एक अन्य आगंतुक, युवा रश्मी कांत के सामने भी उन्होंने इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं।
दिल्ली के एक जाने-माने राजनीतिक परिवार से आने वाले फिल्म निर्माता। चारों
पत्रकार बाहर निकल रहे थे, और वह मुख्य कार्यक्रम देखने के लिए अंदर आ रहा था।

मंत्री। उन्हें जाते हुए देखकर, वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि क्या हुआ होगा।
वे उससे मिलने आए थे।
आम तौर पर वे गृह मंत्री एस.बी. चव्हाण के साथ आते थे और
यूनुस सलीम, जो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। सलीम ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उसने सबसे पहले कश्मीरी आतंकवादियों को अपने पक्ष में लाने के लिए उसकी मदद मांगी थी—ताकि
उनका पुनर्वास किया जा सकता था। राव आमतौर पर उनसे पूछते थे कि...
वे रात में आते, जब उनका दिन का काम खत्म हो जाता। उन्हें प्रधानमंत्री मिल जाते।
सफेद बनियान, लुंगी और सफेद चप्पल पहने, ढेर के बगल में बैठी हुई।

उसके दाहिनी ओर सोफे पर फाइलें पड़ी हुई थीं। सोफे का कुशन हल्के बेज रंग का था।
सोफे का चयन स्पष्ट रूप से सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था।
दिव्यांगजन विभाग (पीडब्ल्यूडी)। फिल्म निर्माता इस बात से बेहद प्रभावित थे कि कैसे एक
अवचेतन की एक आदत प्रकट हो जाती थी—और राव अपना हाथ रगड़ने लगते थे।
जब वह अपने आगंतुकों की बातें ध्यान से सुन रहा था, तो उसका पेट गोलाकार गति में हिल रहा था।
दिसंबर 1992 में, रश्मि कांत राव से अकेले मिलने आई थीं।
उन्हें इतनी जल्दी नियुक्ति मिलने पर आश्चर्य हुआ।
विध्वंस।
कांत ने मुझे बताया, 'मैंने उनसे अयोध्या के बारे में पूछकर शुरुआत की।'
‘ये तो होना ही था (यह होना ही था, यह अपरिहार्य था),’ राव
उसने अपने युवा आगंतुक को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। दूसरे शब्दों में, उसने कहा था
मुझे 6 दिसंबर को जो हुआ उसकी उम्मीद थी।
प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे।
‘आप दबाव में दिख रहे हैं,’ उसने सहानुभूति जताने की कोशिश की।
‘आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं?’ राव ने चिड़चिड़ाते हुए पलटवार किया।
‘ये लोग जो अभी गए हैं (ये लोग जो अभी-अभी गए हैं),’ उसने कहा
उन्होंने आगे कहा। उनका इशारा निखिल चक्रवर्ती और पत्रकारों की ओर था।
जिसने अभी-अभी उसे देखा था।
‘Yeh bhi keh rahen hai ki daer ho rahi hai, jaldi karo. They were also
सलाह देते हुए, 'देर हो रही है, आपको जल्दी करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए', प्रधानमंत्री ने कहा।
यह कहते हुए राव ने अपने हाथ में पकड़े दस्तावेज़ को लहराया।
हाथ। प्रधानमंत्री जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वह एक ऐसा सुझाव था जिसे कई लोग

अभी-अभी निकले पत्रकारों के अलावा, सभी ने यह मांग उठाई थी कि वह प्रतिबंध लगाए।
आरएसएस, वीएचपी और जैसे प्रमुख हिंदू दक्षिणपंथी संगठन
बजरंग दल—जिसके लिए उन्होंने 10 दिसंबर 1992 को मतदान किया।
विध्वंस के बाद के दिनों में, राव को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।
उनकी पार्टी के भीतर से, विपक्ष से, मीडिया से आलोचना हुई।
बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की अनुमति देने के लिए जनता की भी आलोचना की जा रही थी। अब उन पर धर्मनिरपेक्षता को पुनः स्थापित करने का दबाव बढ़ता जा रहा था।
उनकी सरकार की साख।
'Kya karoon, saari umar clerk hee tho raha hoon (What can I do, all
(मैंने अपना पूरा जीवन क्लर्क के रूप में बिताया है),' राव ने कहा, उनके शब्दों में एक तरह का भाव झलक रहा था।
अप्रत्याशित कड़वाहट। वह व्यंग्यात्मक रूप से इस बात का जिक्र कर रहा था।
उन्हें एक साहसी नेता के बजाय एक अनिर्णायक के रूप में चित्रित किया गया, लेकिन पार्टी के लिए उनका उपयोग किया गया।
मसौदाकार, इसके कई प्रस्तावों और घोषणापत्रों को लिखते हुए, पीड़ा से जूझते हुए
कौन सा वाक्य शेष रहेगा और कौन सा अल्पविराम और पूर्णविराम हटाना होगा
इसे हटा दिया जाए। राव एक सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति थे, और उन्होंने इसके फायदे और नुकसान का तौल-तौल किया।
एक बेहद गलत निर्णय—और इसमें उनके द्वारा स्थिति को संभालने का तरीका भी शामिल था।
अयोध्या का विवाद, जिसके कारण उसका विनाश हुआ।
मुझे नहीं पता कि वह उस दिन खुश था या दुखी, लेकिन मुझे समझ आ गया
उन्हें ऐसा लग रहा था कि (विध्वंस) उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी,' उन्होंने याद किया।
Rashmi Kant.
■

विध्वंस के वर्षों बाद, भाजपा और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया
उन्होंने नरसिम्हा राव को चेतावनी दी थी कि बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा।
इसे 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने राव को सतर्क कर दिया था, इसलिए
कि वह प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकता है।
विध्वंस के बाद का दृश्य।
‘Kushabhau Thakre (President of the BJP) told me this,’ Som Pal,
जनता दल के नेता से भाजपा सांसद बने व्यक्ति ने खुलासा किया, ‘उन्होंने कहा, ‘उनसे बात हो’
gayee thee ki 6 December ko aisa karenge (We had told Rao we will do
यह 6 दिसंबर को हुआ था।
ठाकरे ने कहा, 'आप खुद तय करें कि आप स्थिति को कैसे संभालेंगे।'
राव को बताया था।
सोम पाल ने कहा, 'आरएसएस प्रमुख के. सुदर्शन ने भी मुझे इसकी पुष्टि की है।'
‘Sudarshan told me, “Humari understanding ho gayi thee (We had
पीवी के साथ समझौता कर लें।
ठाकरे और सुदर्शन ने यह जानकारी तब सामने लाई जब सोम
पाल ने उन्हें राव के साथ हुई अपनी एक मुलाकात के बारे में बताया। यह मुलाकात इस प्रकार थी:
मस्जिद के विध्वंस के ठीक एक साल बाद, 5 दिसंबर 1993 को,
राव ने सोम पाल से मिलने की इच्छा जताई थी। बाबरी मस्जिद के तूफान से बच निकलने के बाद, वह
विभिन्न राजनीतिक समूहों के नेताओं से इस बारे में परामर्श कर रहा था कि कैसे कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करें।

मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था, और शायद मैं शरारत कर रहा था।
सोम पाल ने याद करते हुए कहा, 'जब मैंने पीवी से कहा, शायद इतिहास तुम्हारा मूल्यांकन करेगा।'
भविष्य में अलग तरह से... बाबरी मस्जिद एक नासूर की तरह रिसता हुआ घाव थी और मुझे लगता है
कुछ सर्जरी करनी पड़ी।
पीवी मुस्कुराए। सोम पाल ने आगे कहा, 'यह पहचान की मुस्कान थी और वहाँ
उसकी आँखों में एक चमक थी। उसकी मुस्कान देखकर मुझे लगा कि वह
मेरी बातों से वह प्रसन्न प्रतीत हुआ। और उसने मेरी बातों को स्वीकार किया।
हुई थी।'
■

बाबरी मस्जिद का विध्वंस केवल विनाश के बारे में नहीं था,
मुसलमानों द्वारा एक परित्यक्त इमारत पर उन्मादी भीड़ द्वारा हमला किया गया था।
प्रार्थना करना बंद कर दिया—और जिसे कई हिंदू एक
भगवान राम का जन्मस्थान।
बाद में पीवी ने इसका कारण विश्वास के टूटने को बताया।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के कामकाज के लिए आवश्यक हैं।
संघीय शासन प्रणाली का। राव के अनुसार, विध्वंस तक, विरोध जारी रहेगा।
केंद्र और राज्यों में राजनीतिक दलों के सदस्यों का चुनाव होता था।
उनके अलग-अलग विचारों के बावजूद, उनसे 'सामंजस्य' में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी।
‘राष्ट्रीय हित’। लेकिन विध्वंस के बाद, यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया।
अयोध्या में राव ने स्वयं कहा था कि यह कठिन है, और यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे उन्होंने लिखा था।
उनकी मृत्यु के बाद 2004 में इसका प्रकाशन हुआ था। 6 तारीख को जिस चीज़ की पिटाई हुई थी
दिसंबर 1992 का महीना 'संघीय ढांचे में सद्भावना' का प्रतीक था।

केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को प्रभावित करने के अलावा,
मंदिर आंदोलन ने देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया था।
धार्मिक दायरे में। स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्षता को इस रूप में देखा गया था
'सर्वधर्म संभाव' या सभी धर्मों के प्रति सम्मान—इसके विपरीत
राज्य के मामलों में धर्म का अभाव, जैसा कि कुछ पश्चिमी देशों में था
लोकतंत्र। लेकिन मंदिर आंदोलन ने सब कुछ बदल दिया; इसने तो यहाँ तक कि मजबूर भी कर दिया।
धर्मनिरपेक्ष दलों को भाजपा के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, 'केवल इसका मुकाबला करने के लिए'।
इससे उत्पन्न चुनौती। इसने सांप्रदायिक कार्ड को सम्मान प्रदान किया।
अल्पकालिक चुनावी लाभ।
राव की 23 दिसंबर 2004 को हुई मृत्यु के दशकों बाद भी, यह सवाल बना हुआ है कि
जो बात मिटती नहीं: क्या पामुलापार्टी वेंकट नरसिम्हा
क्या राव ने बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए और अधिक प्रयास किए होंगे? वे कितने दोषी होंगे?
इतिहास उन्हें 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में घटी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराता है, एक ऐसी घटना जिसने देश की राजनीति और सामाजिक परिदृश्य को आकार दिया।
इसके बाद के दशकों में भी इसके संबंध प्रभावित होते रहे और यह प्रभाव आज भी इसके संबंधों को खराब कर रहा है।
पथ?
हालांकि 6 दिसंबर की घटना के लिए कई लोग जिम्मेदार थे।
इस त्रासदी के बाद, मस्जिद को बचाने की अंतिम जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर थी।
यह कहानी है कि कैसे और क्यों नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने।
बाबरी मस्जिद की रक्षा करने में विफल रहने के बावजूद, यह एक तरह से 'अत्यंत बड़ी विफलता' थी।
भारत के नौवें प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया 'निर्णय'।
द्वितीय

पी.वी. नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद नहीं थी।
भारत। मई 1991 में राजीव गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया गया।
विधानसभा चुनावों के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया था। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं।
1991 के चुनावों से पहले के हफ्तों में यह बात व्यापक रूप से फैली हुई थी कि राजीव को उस पर शक था।
शीर्ष पद पाने की चाहत रखने के कारण ही उन्हें दरकिनार कर दिया गया था।
राव ने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें श्री का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था।
Siddheswari Peetham, a matha in Tamil Nadu with which he had been
वर्षों से जुड़े रहे। वह सभी सांसारिक संबंधों का त्याग कर देगा।
जब उन्होंने पद स्वीकार किया।
फिर भी, चूंकि चुनाव का समय था, और वह अध्यक्ष थे
वह चुनाव के लिए कांग्रेस समन्वय समिति के सदस्य थे।
पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन उनका मन चुनाव प्रचार में नहीं लग रहा था।
हैदराबाद लौटने के लिए उसने पहले ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था।
अपने गृहनगर। उसने अपनी आधी किताबें और कागज़ बक्सों में भरकर भेज दिए थे।
उन्हें वापस घर ले आओ। लेकिन हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह
एक मठ में शामिल होने के बाद, वह एक कट्टर राजनीतिज्ञ बन गए—और अभी भी एक अवसर की तलाश में थे।
यह एक ऐसा अवसर है जो उन्हें सक्रिय राजनीतिक जीवन में बने रहने में सक्षम बना सकता है।
भूमिका। उन्होंने चुपचाप मुख्यमंत्री एन. जनार्दन रेड्डी से कहा था।
Andhra Pradesh, with whom he enjoyed a rapport: ‘Khayal rakhna.
अगर मौका मिले तो मेरे लिए राज्यसभा सीट का विकल्प ध्यान में रखें।

■

20 मई 1991 को नरसिम्हा राव रामटेक में थे, जो कि एक निर्वाचन क्षेत्र है।
उन्होंने पहले महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। यह उन 204 लोक परिषदों में से एक थी।
जिन विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान हो रहा था
जगह।
उस दिन, राजीव गांधी, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे,
उन्होंने प्रणब मुखर्जी और एम. एल. फोतेदार को संदेश भेजा। उन्होंने उनसे पूछा
पालम हवाई अड्डे पर उनसे मिलने के लिए। वह दिल्ली में केवल एक दिन के लिए रुकने वाले थे।
कुछ ही घंटों में उनसे बात करनी थी।
पालम में उतरते ही राजीव थका हुआ और अस्त-व्यस्त लग रहा था।
कांग्रेस नेताओं ने उन्हें घर जाकर तरोताजा होने का सुझाव दिया।
एक व्यस्त दौरे पर दोबारा रवाना होते हुए। घर पर, वह
मैंने मुखर्जी और फोतेदार से अलग-अलग बात की। बातचीत खत्म होने के बाद
Mukherjee, he turned to Fotedar. ‘Kitnee seataen (How many seats)?’
फोतेदार के जवाब देने से पहले ही, राजीव ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, 'हम करेंगे'
सरकार का गठन करें।' फिर, कुछ मिनटों तक, उन्होंने इस बात पर विचार किया कि कौन
उन्हें उनके द्वारा गठित की जाने वाली नई सरकार का हिस्सा होना चाहिए। उन्हें पूरा यकीन था।
वह सत्ता में वापस आ रहा था। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। जब वह जा रहा था,
he looked back and said, ‘Achcha Fotedarji, ta-ta.’
फोतेदार ने बाद में कहा, 'उन्होंने पहले कभी उस शब्द का प्रयोग नहीं किया था।'
यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी।

उसी रात राजीव गांधी उड़ीसा के लिए रवाना हुए और वहां एक सभा को संबोधित किया।
और अगली दोपहर तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए। यह उन अनुभवों में से एक था।
यह एक अजीब संयोग था कि इंदिरा गांधी भी एक दिन पहले ओडिशा में थीं।
उनकी हत्या से पहले जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे।
उनकी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले ओडिशा में उनका निधन हुआ था।
अगली रात, 21 मई 1991 को, रात 10 बजे, राजीव एक बम धमाके में टुकड़े-टुकड़े हो गया।
श्रीपेरुम्बुदुर में एक चुनावी रैली। एलटीटीई के एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर दिया था।
उसके सीने पर एक बम बंधा हुआ था जब वह उसके पैर छूने के लिए झुकी। कुछ ही सेकंड में
अपनी हत्या से पहले, जयंती नटराजन बगल में खड़ी थीं।
राजीव के लिए। वह उनके लिए तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद कर रही थी।
राजीव ने उसकी ओर मुड़कर कुछ कहा। लेकिन उसके शब्द स्पष्ट नहीं थे।
फिर उसने उसे साफ-साफ कहते सुना, 'मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ।' उसने सोचा कि वह
वह चाहती थी कि उसे विदेश से आए दो पत्रकारों के बारे में पता चले।
उन अखबारों के पत्रकारों ने भी उनके साथ श्रीपेरुम्बुदुर की यात्रा की थी।
नटराजन के जाने के तुरंत बाद एक धीमी सी धमाके की आवाज आई। वह गिर पड़ी।
धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। जब नटराजन अचेत अवस्था में उठीं, तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा।
उसके सामने एक दृश्य फैल गया—नरसंहार के बीच, सफेद लोट्टो
राजीव ने जो जूते पहने थे, उन पर उसकी नजर पड़ी।
‘कई लोगों ने उसे लपेट लिया, और (जी. के.) मूपानार और मैं और
कुछ अन्य लोग उसे सामान्य अस्पताल ले गए जो एक से अधिक था।
एक घंटे की दूरी पर, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने... जब हम वहाँ पहुँचे तो रात के लगभग 11 बज रहे होंगे... मुझे शव की पहचान के लिए हस्ताक्षर करने पड़े...
डॉक्टर बहुत गुस्से में था। "तुम्हें मेरे पास यह सब लाने में ज़रा भी शर्म नहीं आती?"

वह इतना सुंदर आदमी था और तुम मुझे यह बंडल लाकर उसे बुला रही हो।
Rajiv Gandhi….”’
अस्पताल में राजीव गांधी को मृत घोषित कर दिया गया। बाद में, लगभग 3 बजे
सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया।
इमारत के बाहर भीड़ जमा होने लगी थी।
तमिलनाडु के राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह लगभग 4 बजे पहुंचे।
सुबह उसने पूछा, 'किसकी मृत्यु हुई?'
‘Rajivji,’ Natarajan replied.
उन्होंने कहा, 'मुझे पता है।'
राज्यपाल ने पूछा, ‘वे कौन-कौन से महत्वपूर्ण लोग थे जिनकी मृत्यु हुई?’
दोबारा।
नटराजन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, 'हर कोई महत्वपूर्ण है,' उनका इशारा इस ओर था।
जिन सोलह लोगों की मौत हुई थी, उनमें राजीव गांधी और उनके हत्यारे भी शामिल थे।
राज्यपाल ने उनकी टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया।
इसके तुरंत बाद नटराजन और मूपनार ताबूत के साथ चले।
चेन्नई के मीनांबक्कम हवाई अड्डे के लिए। सुबह 6 बजे विमान में सवार लोग सवार हुए।
सोनिया गांधी और प्रियंका लैंड कर गईं। (राहुल उस दिन दिल्ली में नहीं थे।)
नटराजन ने याद करते हुए कहा, ‘प्रियंका ताबूत पर गिर पड़ी और रोने लगी। सोनिया...’
बहुत संयमित। उसने काले रंग के चश्मे पहने हुए थे। वह बोलती नहीं थी।
कोई भी।'
विमान शव को वापस दिल्ली ले गया।
■

नरसिम्हा राव 22 मई 1991 की सुबह दिल्ली पहुंचे, और
वह जनपथ स्थित 10 नंबर के राजीव गांधी के आवास पर पहुंचे। उनका निजी

जैसे ही खबर मिली, सचिव रामू दामोदरन ने उन्हें फोन किया था।
राजीव की हत्या के बाद जो घटनाक्रम सामने आया, उससे कांग्रेसी स्तब्ध रह गए और
खबर मिलते ही कांग्रेस की महिला सदस्य जनपथ स्थित 10 नंबर गली में इकट्ठा होने लगी थीं।
अपने नेता की मृत्यु की खबर फैला दी। कई वरिष्ठ
प्रणब मुखर्जी और राजीव गांधी के सहयोगी आर. के. धवन जैसे कांग्रेसी नेता
और एम. एल. फोतेदार ने जनपथ स्थित 10 नंबर के घर के लॉन में रात बिताई थी।
शव के आने का इंतजार किया जा रहा था। व्यवस्थाएं चल रही थीं।
अंतिम संस्कार।
'अब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा?' यही सवाल उठ रहा था।
वहाँ मौजूद लोग दबी आवाज़ में इस पर चर्चा कर रहे थे। राव के बगल में खड़े होकर,
Pranab Mukherjee said to him, 'Aap ban jao (You take over).'
'Abhi to arthi nahin uthi hai (The body has not yet been cremated),'
राव ने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह वही रूखापन लिए हुए जवाब दिया। 'लोग कहेंगे, तुम हो...'
playing politics. Jis ko sab mil kar karenge woh banega (Whoever
हर कोई चाहता है कि वही पार्टी का नेता बने।
'लेकिन आपके नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है,' मुखर्जी ने जोर देकर कहा।
निजी तौर पर राव को ऐसी ही उम्मीद थी। लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
उन्हें मुखर्जी पर पूरा भरोसा नहीं था। उन्हें यकीन नहीं था कि मुखर्जी
उसे दौड़ से बाहर करने के लिए यह सुझाव दिया जा रहा था।
समय से पहले ही उत्सुक हो जाना। या फिर वह दूसरों की कही बातों को ही दोहरा रहा था।
उसी दिन बाद में, राजीव गांधी के पार्थिव शरीर को तीन मूर्ति ले जाया गया।

भवन, भारत के पहले प्रधानमंत्री का निवास स्थान और राजीव गांधी का निवास स्थान।
दादा, जवाहरलाल नेहरू। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर।
मंत्री के पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों के दर्शन हेतु रखा गया था।
श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इमारत में भारी भीड़ उमड़ी, कुछ लोगों को याद आया कि यह
जहां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के पार्थिव शरीर भी रखे गए थे
राज्य में। कई कांग्रेसी सदस्यों को पता ही नहीं था कि उन पर क्या आफत आई है। मणि
शंकर अय्यर एक कोने में दीवार की चौखट पर अकेले बैठे थे, उन्होंने अपना सिर हाथों में थाम रखा था।
वह चुपचाप अपने दोस्त और बॉस के लिए शोक मना रहा था।
उस दोपहर, भुवनेश चतुर्वेदी, जो कांग्रेस के एक नेता थे,
राजस्थान से राव से मिलने के लिए मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित 9 नंबर के आवास पर गए।
‘आपको (कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए) उम्मीदवार बनना चाहिए।’
चतुर्वेदी ने राव को बताया।
राव ने जवाब दिया, 'यह सर्वसम्मति से होना चाहिए।'
‘यह मेरे लिए पर्याप्त संकेत था कि वह तैयार था।’
चतुर्वेदी ने बाद में कहा।
■

'जॉर्ज, अर्जुन सिंह और मैंने फैसला किया था कि हमें सोनिया को बनाना चाहिए।'
फोतेदार ने दावा किया, 'गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे।' विंसेंट जॉर्ज
राजीव गांधी के निजी सहायक थे और अर्जुन सिंह एक वरिष्ठ नेता थे।
कांग्रेस में।
राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सदस्य नहीं थीं।

लेकिन उन्हें सदस्य के रूप में नामांकित कराना और फिर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कराना काफी आसान होता।
कांग्रेस कार्यकारी समिति, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था
पार्टी के सदस्यों की उस शाम 5 बजे बैठक होनी थी, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन
राजीव गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्हें संभालना चाहिए था। यह एक
'विस्तारित' कार्यकारी समिति की बैठक। सीडब्ल्यूसी के अतिरिक्त
सदस्यों, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और विशेष आमंत्रितों को भी उपस्थित होना था।
उसमें उपस्थित रहें।
'अर्जुन सिंह, जी.के. मूपनार, सीताराम केसरी और मैं पीवी से मिलने गए
सीडब्ल्यूसी (बैठक) से ठीक पहले,' फोतेदार ने बताया। 'राव साहब, हमारे पास है
सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद संभालने के लिए राजी करने का निर्णय लिया गया।
'कांग्रेस,' फोतेदार ने उनसे कहा।
'अर्जुन सिंह जी, आपकी क्या राय है?' राव ने उनसे पूछा।
'सर, मैं उनका नाम प्रस्तावित करूंगा,' अर्जुन सिंह ने उत्तर दिया। राव चुप रहे।
फिर बिना कुछ और कहे, उन्होंने उनके साथ सीडब्ल्यूसी जाने का फैसला किया।
बैठक।
केसरी ने राव से बैठक की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई।
एआईसीसी मुख्यालय में एक बड़ा कमरा था जिसका इस्तेमाल मीडिया के लिए किया जाता था।
बैठक के बीच में ही अचानक एन. जनार्दन रेड्डी ने संक्षिप्त जानकारी दी। बैठक के दौरान अचानक एन. जनार्दन रेड्डी ने अपनी बात रखी।
वह फोतेदार के पास गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फोतेदार
रेड्डी के साथ बैठक से बाहर निकल गया। 'फोतेदारजी, माहौल कुछ ऐसा है...'
रेड्डी ने बताया, 'सोनिया गांधी के लिए अनुकूल। लेकिन आपको यह करना होगा।'
शरद पवार और करुणाकरण से बात करें।
'बाकी के बारे में क्या?' फोतेदार ने उससे पूछा।
'बाकी सब ठीक हैं।'

फोतेदार ने पवार को बैठक से बाहर बुला लिया।
उन्होंने पवार से कहा, ‘मेरी आपसे एक निवेदन है। अगर आप इसका समर्थन नहीं करते हैं, तो...’
कृपया इसका विरोध न करें। हम प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं।
सर्वसम्मति से... हम सोनिया गांधी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं।’ पवार
प्रस्ताव का समर्थन करने पर सहमति जताई। पवार के लिए भी स्थिति बदल गई थी।
इस हत्या के बाद स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया। राजीव गांधी
मराठा नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाने का प्रयास किया गया
महाराष्ट्र में 1990 में, उन पर पूर्व अधिकारियों के साथ मेलजोल रखने का संदेह करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
प्रधानमंत्री चंद्र शेखर। लेकिन पवार ने राजीव गांधी को पीछे छोड़ दिया—और
विधानसभा दल ने उनके पक्ष में भारी बहुमत से मतदान किया। फोतेदार उनमें से एक थे।
वे लोग जिन्होंने राजीव गांधी से चुनाव तक मामले को जल्दबाजी में आगे न बढ़ाने का आग्रह किया था
वे सब खत्म हो चुके थे। पवार यह बात जानता था।
अर्जुन सिंह ने राष्ट्रपति पद के लिए सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित किया।
कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। केसरी ने इसका समर्थन किया। पूरे सदन ने इसका समर्थन किया।
करुणाकरण ने केवल एक ‘असंतुलित’ स्वर उठाया: ‘आइए सोनियाजी से पूछें कि क्या
वह तैयार है।’ करुणाकरण राव के करीबी थे और उन्हें बल्लेबाजी करते देखा गया।
उसके लिए। 'क्या उससे पूछने का यही सही समय है?' फोतेदार ने अपने हाथ से बात को टाल दिया।
सुझाव। ‘पहले प्रस्ताव पारित कर लेते हैं।’ प्रस्ताव पारित हो गया।
सर्वसम्मति से। इसने सोनिया गांधी से भारतीय नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया।
राष्ट्रीय कांग्रेस। राव ने इस विचार का कोई विरोध नहीं किया। न ही उन्होंने
खुद को एक वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में पेश करना।
'सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद, मैंने कुछ नेताओं को एक-दूसरे को गले लगाते देखा।'

'एक अन्य व्यक्ति एआईसीसी मुख्यालय के एक कमरे में है,' भुवनेश
चतुर्वेदी ने याद करते हुए कहा, 'उन्हें लगा था कि वे सोनिया को नियंत्रित कर पाएंगे।'
ठीक वैसे ही जैसे (वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के सिंडिकेट ने) सोचा था कि वे
इंदिरा गांधी को नियंत्रित कर सकते थे और उन्होंने 1966 में मोरारजी (देसाई) के खिलाफ मतदान किया था।
शाम 6:30 बजे, वरिष्ठ कांग्रेसी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल सीमा पार गया।
सोनिया गांधी से जनपथ स्थित 10 नंबर की इमारत में मुलाकात करें, जो एआईसीसी के बगल में थी।
सीडब्ल्यूसी की बैठक 24, अकबर रोड स्थित मुख्यालय में हुई थी।
उन्होंने सोनिया गांधी से पार्टी की कमान संभालने का अनुरोध किया। सोनिया
उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनकी बात सुनी। लेकिन उन्होंने उनका अनुरोध ठुकरा दिया।
रात 8 बजे, फोतेदार जनपथ स्थित 10 नंबर के मकान में वापस गया। उसने जॉर्ज से अनुरोध किया कि...
सोनिया गांधी को एक पत्र भेजें। उनका अंतिम निर्णय जो भी हो, उन्होंने लिखा।
पर्ची पर लिखे अनुसार, उसे इसे सार्वजनिक करने से पहले एक दिन इंतजार करना चाहिए।
मान गया।
अगली सुबह के अखबारों में सुर्खियां थीं कि कांग्रेस ने
उन्होंने सोनिया गांधी से भारत की सबसे पुरानी पार्टी की कमान संभालने का अनुरोध किया।
फोतेदार ने सोनिया से अपने फैसले को एक दिन के लिए सार्वजनिक करने में देरी करने का अनुरोध किया था।
क्योंकि उनका मानना था कि सीडब्ल्यूसी के फैसले पर पहले व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए।
प्रचार। उनका 'ना' बाद में आना चाहिए। अगर दोनों की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती है तो...
अगर वह मीडिया के साथ-साथ ऐसा करती है, तो उसके फैसले का महत्व खो जाएगा। अगर वह
यदि वह इसे अस्वीकार कर देती है, तो इस निर्णय को उसकी ओर से एक 'बलिदान'

के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
फोतेदार ने कहा, 'भविष्य में उनकी जरूरत पड़ेगी। वह एक नेता होंगी।'
रिजर्व में।
सोनिया गांधी को एक नेता के रूप में देखने वाले फोतेदार अकेले नहीं थे।
भविष्य। 1997 में सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश करने से बहुत पहले, या एक बनने से पहले।
कांग्रेस पार्टी की सदस्य होने के नाते, उन्हें एक शक्तिशाली नेता के रूप में देखा जाने लगा था।
पार्टी के भीतर केंद्र। राव को अपने कार्यकाल के दौरान इसी चुनौती का सामना करना पड़ा था।
प्रीमियरशिप।
■

‘चूंकि आपको प्रधानमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है,’ नटवर ने कहा।
राजीव की मृत्यु के कुछ दिनों बाद सिंह ने सोनिया गांधी से कहा, 'आपको अवश्य ही...'
यह तय करें कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए।’ अब तक दुनिया
राजीव गांधी के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए नेता जा चुके थे।
कठिन निर्णय लेने का समय आ गया था।
उन्होंने सुझाव दिया, ‘आप पी. एन. हक्सर से सलाह क्यों नहीं लेते?’ हक्सर के पास एक समय वह सोनिया की सास इंदिरा गांधी के भरोसेमंद सलाहकार रह चुके थे।
और परिवार में अब भी उनका बहुत सम्मान था।
‘मैं आपको बता दूंगी,’ सतर्क सोनिया ने कोई निश्चित जवाब नहीं दिया।
मैंने एक दिन बाद उसे वापस फोन किया और उससे हक्सर को 10 बजे आमंत्रित करने के लिए कहा।
जनपथ। हक्सर ने एक सुझाव दिया। 'आपको अरुणा आसिफ अली को भेजना चाहिए।'
और नटवर से शंकर दयाल शर्मा को,’ उसने सोनिया से कहा, ‘और उसे बता देना कि सोनियाजी ने उनसे कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनने का अनुरोध किया है।

मंत्री (यदि कांग्रेस जीतती और सत्ता में वापस आती)। शर्मा थे
उस समय भारत के उपराष्ट्रपति का नाम हक्सर ने तय कर लिया था।
क्योंकि वह एक अनुभवी प्रशासक थे, इसलिए वे हिंदी भाषी थे।
वह एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण एक प्रमुख स्तंभ रहे थे।
उत्तर भारत में कांग्रेस का निर्वाचन क्षेत्र था, लेकिन अब लोग इसे छोड़ने लगे थे।
भाजपा के बढ़ते प्रभाव के लिए, हक्सर को लगा कि वह स्थिति को संभाल लेंगे।
राजीव गांधी की हत्या से उत्पन्न अनिश्चितताएं।
अरुणा आसफ अली और नटवर सिंह छठे नंबर पर गए, मौलाना आजाद
सड़क। शर्मा ने उनकी बात गंभीरता से सुनी। फिर उन्होंने अपना भाषण दिया।
उन्होंने चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, 'सोनियाजी का यह प्रस्ताव देना बहुत ही उदारतापूर्ण है।'
‘Mera swasthya saath nahin dega, haath jorh ke shama kar deejiye (My
स्वास्थ्य इसकी अनुमति नहीं देता, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं।
आश्चर्यचकित दूत सोनिया को रिपोर्ट देने के लिए वापस भागे—और साथ ही साथ
हकसर। ‘अब पी.वी. नरसिम्हा राव को बुलाओ,’ एक अविचलित व्यक्ति ने सलाह दी।
हकसर। कांग्रेस में तीन अन्य नामों पर भी चर्चा हुई थी।
पार्टी अध्यक्ष पद के लिए संभावित दावेदारों में अर्जुन सिंह, शरद पवार और एन. शामिल हैं।
डी. तिवारी। कई लोगों के लिए, राव स्वाभाविक पसंद थे। वे अनुभवी थे,
शांत और विनम्र स्वभाव के। बूढ़े और कमजोर होने के कारण, उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जो
वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेंगे। उनकी हाल ही में हृदय की सर्जरी हुई थी।
उनके पास जनसमर्थन नहीं था, उन्हें किसी के लिए खतरा नहीं माना जाता था।
पार्टी में अधिक महत्वाकांक्षी राजनेता।
हालांकि राव के लिए सोनिया गांधी की सहमति निर्णायक साबित हुई।
उन्होंने इस बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। आर. डी. जैसे लोग थे।
प्रधान, पूर्व गृह सचिव और सोनिया गांधी के एक समय के सलाहकार।
गांधी ने उन्हें इस फैसले से दूर रखने की कोशिश की और इस बात से इनकार किया

कि
राव के चयन में सोनिया की भूमिका थी।
29 मई 1991 को पी. वी. नरसिम्हा राव अध्यक्ष चुने गए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
■

कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते ही राव ने शुरू कर दिया...
उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करना। वह हिंदी भाषी क्षेत्रों में पार्टी की लोकप्रियता का जायजा लेना चाहते थे।
मुख्य क्षेत्र। सलमान खुर्शीद उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में ले गए।
फर्रुखाबाद। जैसे ही वह पहली बैठक में पहुंचा, और बहुत कुछ
राव की नाराजगी पर नारे लगाए गए। ये नारे किसी और बात के बारे में नहीं थे।
उनके खिलाफ वोट पड़े, लेकिन यूपी कांग्रेस प्रमुख एन. डी. तिवारी के पक्ष में वोट जुटाए गए।
‘Desh ka neta kaisa ho, Narayan Dutt Tiwari jaisa ho (What should the
देश का नेता कैसा होना चाहिए? उसे नारायण दत्त तिवारी जैसा होना चाहिए।
भुवनेश चतुर्वेदी ने याद करते हुए कहा, 'पीवी को बहुत बुरा लगा। नारे
यह विवाद तब भड़का जब नारायण दत्त तिवारी पीवी को यूपी से परिचित करा रहे थे।
राव के अनुसार,
फर्रुखाबाद में हुआ स्वागत इस बात की पुष्टि थी कि वह या तो
या तो उसके पीछे कतार में खड़े होना होगा, या बिना उसके शासन करना होगा।
राज्य पर निर्भर।
■

‘Maa bete ka balidan, yaad karega Hindustan (The sacrifice of mother
इंदिरा गांधी और उनके पुत्र को भारत हमेशा याद रखेगा। इंदिरा गांधी के बारे में यह

नारा था।
गांधी और राजीव गांधी की शहादत की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी।
कांग्रेस ने 1991 के आम चुनाव के अंतिम दो चरणों के लिए प्रचार अभियान चलाया।
इन चरणों के दौरान मतदान मुख्य रूप से 12 और 15 जून 1991 को हुआ था।
दक्षिणी राज्यों में, हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी चुनाव होने बाकी थे।
उत्तर में।
राजीव के लिए सहानुभूति वोट—हालांकि यह पहले जैसा कुछ भी नहीं था
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से जो देखा गया है—उसने इसे और बढ़ा दिया है
कांग्रेस की गिनती। राव के अपने राज्य आंध्र प्रदेश में, एक
कांग्रेस के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पहले चरण में 15 सीटों में से केवल 5 सीटें जीतने के मुकाबले दूसरे चरण में उसने 27 में से 20 सीटें जीतीं।
चरण।
उत्तर में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के साथ, राजनीतिक सत्ता
दक्षिण की ओर खिसकते हुए। चार दक्षिणी राज्य—आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से लोकसभा के लिए 88 सांसद चुने गए।
दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में भी यही स्थिति है।
दूसरी ओर, केवल 33 सीटें भेजी गईं। यह 171 सीटों से काफी कम थी।
कांग्रेस ने 1984 के आम चुनावों में इन राज्यों से जीत हासिल की थी।
अंतिम परिणाम आने पर, कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिलीं।
हालांकि संसद में पूर्ण बहुमत से कम सीटें थीं—232 सीटें।
अब, राव ने बहुत जल्दी और चुपचाप अपने भरोसेमंद लोगों को काम पर लगा दिया।
प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी हेतु समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने इसका उपयोग किया।
‘धर्मगुरु’ चंद्रस्वामी, तांत्रिक एन. के. शर्मा और कप्तान की सेवाएं
सतीश शर्मा, जो राजीव गांधी के मित्र थे और जिनकी उन तक पहुंच थी,
सोनिया गांधी।
दक्षिण के अधिकांश शक्तिशाली कांग्रेसी नेता, जी. के.

मूपनार, के. करुणाकरन, एन. जनार्दन रेड्डी- शिव को छोड़कर सभी
शंकर ने उनके लिए समर्थन जुटाया। अनुभवी लोगों ने भी ऐसा ही किया।
पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता सिद्धार्थ शंकर राय, जिन्होंने
उन्होंने सांसदों को भी राव को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने के लिए राजी किया।
चुनाव के बाद, अर्जुन सिंह का नाम संक्षेप में एक संभावित उम्मीदवार के रूप में सामने आया था।
शीर्ष पद के दावेदारों में से। लेकिन यह बहुत जल्दी ही समाप्त हो गया;
कांग्रेस ने उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था।
महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार ही उभरकर सामने आए।
राव के लिए एक गंभीर चुनौती। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने
उन्होंने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतीं। उन्होंने आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी।
देश भर में कई कांग्रेस उम्मीदवार, विशेष रूप से वे जो
चुनाव के दूसरे चरण में भी उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे उन्हें दो से चार लाख सीटें मिल सकती हैं।
प्रत्येक रुपये। 1989 में, राव स्वयं शरद पवार पर निर्भर थे।
उन्होंने रामटेक से अपनी लोकसभा सीट जीत ली। पवार को विश्वास था कि इसके अलावा
महाराष्ट्र से जीतने वाले, दक्षिणी राज्यों के कई सांसद
जिन्होंने मदद की थी वे उसका समर्थन करेंगे।
शुरुआत में कई लोग पवार के समर्थक थे। उनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी।
पवार अभियान एन. के. पी. साल्वे के घर से चलाया जा रहा था।
औरंगजेब रोड। साल्वे, नजमा हेपतुल्ला और सुरेश कलमदी थे।
अपने नेता के लिए समर्थन जुटाना।
पवार ने गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कराने पर जोर दिया। अपने लिए आयोजित रात्रिभोज में उन्होंने कहा कि पवार ने अपने परिवार के लिए गुप्त मतदान का आयोजन किया था।
नव निर्वाचित सांसदों ने 'अंतरात्मा की आवाज पर मतदान' करने का प्रस्ताव पारित

किया।
नेता का चयन करें।
लेकिन जोखिम से बचने वाले राव कोई मुकाबला नहीं चाहते थे। दक्षिणी क्षेत्र में खेलना
उन्होंने खुद को तेलुगु बिद्दा (तेलुगु मूल का पुत्र) के रूप में प्रस्तुत किया।
यदि उनका चयन होता है, तो वे दक्षिण से पहले प्रधानमंत्री होंगे।
पवार पर पीछे हटने का दबाव भी तेज कर दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी,
उस समय राव के लिए बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की।
और यह बात सबको पता चल जाए कि वह पवार की भूमि संबंधी संलिप्तता का पर्दाफाश करेगा।
घोटाला।
19 जून 1991 को तनाव बढ़ गया। तीक्ष्ण वार्ता शुरू हो गई।
एक समझौता समाधान खोजें। अंततः, पवार को एहसास हुआ कि संख्याएँ शायद
उन्हें पसंद नहीं किया। बाद में उन्होंने दावा किया कि वे राव से हार गए थे।
क्योंकि 'सोनिया गांधी एक स्वतंत्र सरकार को बर्दाश्त नहीं करतीं-
सोच-समझकर प्रधानमंत्री की तलाश।
पवार ने राव को संदेश भेजा कि वह इस पर समझौता करने को तैयार हैं।
उप प्रधानमंत्री पद। लेकिन वह चाहते थे कि राव उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित करें।
राव ने एन. के. शर्मा से कहा, 'पंडितजी, मैं उन्हें फोन नहीं करूंगा।' युद्ध में
अगर घबराहट हो रही हो, तो इसे कमजोरी की निशानी माना जाएगा। शर्मा,
राव जिसे मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, उसने एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन करने का फैसला किया।
वह कांग्रेस नेता को जानता था। 'कृपया साल्वे के घर जाओ और शरद को ले आओ।'
पवार को पीवी के आवास पर ले जाओ, जो 9, मोती लाल नेहरू मार्ग पर स्थित है,' उन्होंने कहा, और फिर
कोई सवाल पूछे जाने से पहले ही फोन कट गया। बीस मिनट में,
कांग्रेस नेता पवार के साथ राव के आवास पर पहुंचे। उनके पास बस इतना ही था।
पवार को बताया गया था कि 'उनके लिए 9, मोती लाल की ओर से निमंत्रण आया

था'
नेहरू मार्ग'। उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि फोन कॉल शर्मा का था।
राव और पवार ने पैंतालीस मिनट तक बात की। 'आप यहाँ आते हैं (तो
दिल्ली) में मंत्री के रूप में, और आप जो भी पोर्टफोलियो चाहें ले सकते हैं। आपके
किसी करीबी को मंत्री बनाया जा सकता है।
'चुने गए व्यक्ति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे,' राव ने कहा।
पवार को प्रस्ताव दिया। फिर, उन्होंने भावनात्मक स्तर पर अपील की: 'मैं
एक बूढ़ा आदमी... तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे सामने पड़ा है।
'तुम्हारा भी मौका आएगा।' 20 जून 1991 को पवार ने अपना नाम वापस ले लिया।
उसी दिन, राव को सर्वसम्मति से सीपीपी का नेता चुना गया।
संसद में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में, अब उन पर पूरी जिम्मेदारी थी।
राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने की संभावना है—और
भारत के अगले प्रधानमंत्री बनें।
सीपीपी नेता के रूप में राव का पहला कदम था लोगों से मिलना।
सोनिया गांधी। जनपथ पर 10 बजे, जब राव सोनिया के साथ अंदर थे, 'एक
हममें से कुछ लोग जॉर्ज के कमरे में (बाहर) बैठे थे,' एन. के. शर्मा
याद आया। 'जॉर्ज की आँखों में आँसू थे'। केसरी भी बन गया।
भावुक। मैंने उनसे पूछा कि वे क्यों रो रहे थे... "अगर राजीव ने
जॉर्ज ने कहा, "अगर वह जीवित होते, तो उन्हें नेता चुना जाता।"
आज सीपीपी।
21 जून 1991 को पी. वी. नरसिम्हा राव ने नौवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
भारत के प्रधानमंत्री। उन्होंने पवार को अपने कार्यकाल में रक्षा मंत्री बनाया।
मंत्रिमंडल। यह वह पोर्टफोलियो था जिसे मराठा नेता ने चाहा था। उनके गुरु,
वाई. बी. चव्हाण भी रक्षा मंत्री रह चुके थे। लेकिन राव ने उन्हें यह पद नहीं दिया।
पवार को उप प्रधानमंत्री पद की वो चाहत थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके।
वी. पी. सिंह ने प्रधानमंत्री बनने पर जो गलती की थी, वह थी अभिषेक करना।
समझौते के तहत देवी लाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया।
प्रतिद्वंद्वी सत्ता केंद्र बनाकर उसने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली।
सरकार।

प्रधानमंत्री बनने की पूरी लड़ाई के दौरान, राव ने एक
कुशल राजनीतिक सूझबूझ। इसके बाद, उनके दल के सदस्य केवल अनुमान ही लगा सकते थे कि क्या हुआ होगा।
पवार पर विजय प्राप्त करने में उनके पक्ष में जो बात काम आई थी, वह थी एक प्रस्ताव।
उसके लिए उसकी स्थिति, या वह छड़ी जिसका उसने दूसरों के माध्यम से इस्तेमाल किया था, जैसे
सुब्रमण्यम स्वामी, या राव के लिए सोनिया गांधी द्वारा दी गई सहमति, या
पूरी संभावना है कि ये सभी कारक मिलकर इसका कारण बने। राव
न तो वे प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत उत्सुक दिखे, और न ही उन्होंने ऐसा किया।
किसी भी स्थिति में, वह खुद को दौड़ से बाहर कर सकता है।
राजीव गांधी का शव लाए जाने के एक महीने के भीतर
जनपथ में 10 तक, राव ने असंभव को संभव कर दिखाया था। एक ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा टिकट से वंचित होने के बाद, उन्होंने संन्यासी बनने का निश्चय कर लिया।
दक्षिण भारत के एक धार्मिक मठ के प्रमुख पी.वी. नरसिम्हा राव अब पदभार संभालने के लिए तैयार थे।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करें।

तृतीय

एक बार आईबी अधिकारी ने नरसिम्हा राव को उन लोगों के बारे में आगाह किया था जो ऐसा कर सकते थे।
भविष्य में उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। राव ने अविचलित होकर बुद्धिमानी से उत्तर दिया, 'मैं
मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे पता है कि इन लोगों (विरोधियों) से कैसे निपटना है।'
अपने ब्राह्मणवादी पूर्वजों को पर्याप्त प्रमाण मानते हुए
अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करना।
28 जून 1921 को जन्मे राव एक तेलुगु ब्राह्मण और नियोगी थे।
वह भी ब्राह्मणों की उपजाति, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, विद्वत्ता और प्रशासनिक कौशल के लिए जानी जाती है। तेलुगु ब्राह्मण दो भागों में विभाजित थे।

प्रमुख समूह—वैदिक ब्राह्मण जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और
पुरोहिती को अपना पेशा चुना और नियोगी ब्राह्मणों ने, जिन्होंने
वे प्रशासक, जमींदार, सैन्य अधिकारी, विद्वान और शासक बने।
राव की तरह उनमें से कई सफल राजनीतिज्ञ बन गए थे।
इनमें स्वतंत्रता सेनानी बी. पट्टाभि सीतारामय्या भी शामिल थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष (1947-48), एस. राधाकृष्णन,
टी. प्रकाशम, जो 1962-67 तक भारत के राष्ट्रपति रहे,
आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और बुरगुला रामकृष्ण राव,
हैदराबाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री, जिनके साथ नरसिम्हा राव
उन्होंने मिलकर काम किया था।
राव के नियोगी जीन ने उन्हें खेती छोड़ने के लिए प्रेरित किया—उनके पिता के पास 200 एकड़ जमीन थी।
वर्तमान समय में वारंगल जिले के वांगारा में एकड़ शुष्क भूमि
तेलंगाना में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नागपुर, पुणे और अन्य स्थानों पर जाएँ।
हैदराबाद।
अपने नियोगी ब्राह्मण पूर्वजों के अलावा, वांगारा गांव में जहां
उनके परिवार का निवास और खेती-बाड़ी का काम भी उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को प्रभावित करता था।
वांगारा कई भाषाई प्रभावों के संगम पर स्थित था—और
उन्होंने ही उन्हें वह बनाया जो वे थे। राव ने तत्कालीन रियासत में वांगारा का वर्णन किया था।
हैदराबाद राज्य को 'भौगोलिक रूप से उत्तर और के बीच एक पुल' के रूप में वर्णित किया गया है।
दक्षिण।
इस छोटी बस्ती के निवासी तेलुगु और हिंदी बोलते थे।
राव को मराठी, कन्नड़ और थोड़ी-बहुत ओडिया भाषा का भी ज्ञान था।
वह अपनी मातृभाषा तेलुगु सहित दस भाषाओं में निपुण हैं।
तेलुगु के अलावा, उन्होंने स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी बोलना भी सीखा।
वह अपने अनपढ़ माता-पिता से सीखी हुई संस्कृत की धर्मग्रंथों का पाठ कर सकता

था।
पिता; वह उर्दू में पारंगत हो गए थे, जो निजाम के शासनकाल में बोली जाती थी।
और फारसी भाषा में निपुण, जो दरबार की भाषा थी।
उन्होंने पढ़ाई के लिए कई साल नागपुर में बिताए, वे मराठी धाराप्रवाह बोलते थे—
और
उन्होंने 1968 में चेन्नई जाने के दौरान तमिल सीखने का फैसला किया था।
लेखन से विराम। अपने राजनीतिक पतन के वर्षों के दौरान, उन्होंने कक्षाओं में भाग लिया।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्पेनिश सीखने के लिए। एक बार पूछा गया कि क्या
उन्होंने गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ की रचना 'लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा' पढ़ी थी।
उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि उन्होंने इसे मूल स्पेनिश भाषा में पढ़ा था!
उसके पिता ने चार वर्षीय नरसिम्हा को गोद देने के लिए एक अन्य संस्था को सौंप दिया।
वांगारा में पड़ोस में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके पास कुछ भी नहीं था।
वे नहीं चाहते थे कि निज़ाम एक निःसंतान दंपत्ति की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर ले। वी. पी. सिंह की तरह, जिन्हें उनके पिता ने गोद दे दिया था।
दोनों परिवारों की भू-जोतों को समेकित करने के लिए पिता को दूसरे राजा के अधीन कर दिया गया।
राव को भी उनके मायके से अलग कर दिया गया था। वीपी की तरह, उनका भी एक परिवार था।
अकेलापन भरा बचपन बिताने के कारण वे एकांतप्रिय बन गए। उनकी शादी कम उम्र में ही हो गई थी।
दस में से एक, और उनकी पत्नी सत्यम्मा को उनकी जमीनों की देखभाल करनी थी।
अपने जीवन के अंत तक गांव और उनके आठ बच्चों के साथ रहीं। दूसरी ओर राव ने अपने परिवार का भरण-पोषण किया।
उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक करियर की शुरुआत की।
तेज रोशनी के बीच।
जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर, राव सबसे विद्वान प्रधानमंत्री थे।

भारत में ऐसा हुआ है। लेकिन नेहरू से कहीं अधिक, उन्होंने जटिलताओं को समझा।
भारतीय समाज और उस पर जाति और धर्म के प्रभाव का विश्लेषण।
भारतीय मानसिकता। प्रधानमंत्री बनने तक, उनके पास यह अनुभव भी था।
दो दशकों का प्रशासनिक अनुभव। वे मुख्यमंत्री रह चुके थे।
आंध्र प्रदेश के। राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विदेश मामले, गृह, रक्षा और मानव संसाधन जैसे विभाग
इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में विकास।
■

अपने युवा दिनों में राव हथियारों की तस्करी करता था। एक साल तक वह यह काम करता रहा।
वे महाराष्ट्र के चंदा में एक शिविर में तैनात थे और हथियारों की तस्करी करते थे।
हैदराबाद के निज़ाम को सत्ता से हटाने के लिए काम कर रहे समूह। एक प्रमुख
राव की राजनीतिक सोच को आकार देने वाला एक कारक उनकी भागीदारी थी।
निज़ाम विरोधी आंदोलन, रियासत के मुस्लिम शासक के खिलाफ
हैदराबाद। 1938 में, हैदराबाद में कांग्रेस ने एक अभियान शुरू किया था।
निज़ाम के खिलाफ सत्याग्रह में सत्रह वर्षीय राव ने गीत गाया।
प्रतिबंधित राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का गायन अन्य हिंदू छात्रों के साथ किया गया।
वारंगल स्थित उनके कॉलेज में प्रधानाचार्य ने 300 छात्रों को निष्कासित कर दिया, जिनमें शामिल हैं:
राव। नागपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रवादी कुलाधिपति ने इसके बारे में सुना।
कई छात्रों को निष्कासित किया गया और उन्हें प्रवेश की पेशकश की गई, जिनमें शामिल हैं:
राव ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के लिए नागपुर में दाखिला लिया; बाद में उन्होंने
उन्हें कानून की डिग्री हासिल करने के लिए शहर लौटना था।
■

नरसिम्हा राव के गुरु और मार्गदर्शक भगवा वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति थे।
स्वामी रामानंद तीर्थ, जो एक साधु, राजनीतिज्ञ और समाजवादी थे।
और आंशिक रूप से अध्यात्मवादी थे। वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गांधीवादी अहिंसा के साथ-साथ हिंसा को भी उचित ठहरा सकते थे—और वे इसके अध्यक्ष थे।
हैदराबाद राज्य कांग्रेस। राव ने उनके अधीन काम किया जब तीर्थ ने नेतृत्व किया।
अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के बीच निज़ाम विरोधी आंदोलन।
तीर्थ ने एस. बी. चव्हाण और वीरेंद्र पाटिल को भी प्रभावित किया।
महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के लिए।
अन्य रियासतों के विपरीत, जो भारत में विलय हो गई थीं
स्वतंत्रता के बाद, निज़ाम ने हैदराबाद के एकीकरण का विरोध किया।
भारत। सितंबर 1948 में, गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल
हैदराबाद में पुलिस भेजी और राज्य को अपने राज्य में मिला लिया।
हैदराबाद का अंततः भारतीय संघ में विलय हो गया, लेकिन इससे एक दशक से भी अधिक समय बीत चुका था।
निज़ामों का दो शताब्दियों का शासन। लेकिन यह हिंसा से भरा हुआ था, और
लगभग 40,000 मुसलमानों की हत्या कर दी गई।
हैदराबाद की मुक्ति के बाद, उनमें से कई जिन्होंने नेतृत्व किया था
राव और तीर्थ जैसे निज़ाम विरोधी संघर्ष के अनुयायियों ने राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। राव
वे कांग्रेस के करीमनगर जिले के अध्यक्ष बने।
उन्होंने हैदराबाद के हुज़ूरबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा।
1952 में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बाद में, वे मुंथानी से विधायक बने।
1957 में, उन्होंने बीस वर्षों तक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1962 से
इसके बाद, नौ वर्षों तक वे राज्य सरकार में मंत्री रहे।
शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों का प्रबंधन करना।
निज़ाम विरोधी आंदोलन ने तीन अलग-अलग समूहों को एक साथ ला दिया था।
धार्मिक-राजनीतिक धाराएँ—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने चाहा
भारत का एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में एकीकरण; हिंदू

महासभा और आर्य समाज आंदोलन, जो इसके विरोधी थे
निज़ाम ने इस्लामी शासक के रूप में हिंदू विचार पर जोर दिया और
दर्शनशास्त्र; और वे कम्युनिस्ट जिन्होंने निज़ाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी,
तेलंगाना में किसानों की यह मांग है कि जमीन किसान को ही दी जाए।
इन तीनों धाराओं का राव के चिंतन पर प्रभाव पड़ा।
■

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल ही वह था जिसने उन्हें प्रभावित किया।
राव एक राजनीतिज्ञ के रूप में बेहद प्रभावशाली थे। उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया था।
1971 में इंदिरा गांधी आंध्र प्रदेश सरकार की प्रमुख बनीं।
क्योंकि वह तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्र से आया था (संयुक्त राज्य अमेरिका में)।
आंध्र प्रदेश), और वह एक ब्राह्मण थे। तब तक शक्तिशाली जमींदार
रेड्डी समुदाय का आंध्र प्रदेश की राजनीति पर दबदबा था। तीर्थ के अलावा, राव नेहरू से भी प्रभावित थे।
वामपंथी विचारधारा; उनका मानना था कि राज्य को ही मुख्य मध्यस्थ होना चाहिए।
विकास। समाजवादी राव को भूमि विकास से संबंधित दूरगामी कानून बनाने थे।
मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कई सुधार किए और भूमि सीमा को सख्ती से लागू किया।
उस समय वामपंथी विचारधारा में रहीं इंदिरा गांधी ने उनका समर्थन किया।
भूमि सुधार। लेकिन उन्होंने जमींदारों के गुस्से को आमंत्रित किया और वे
1972 में मौका मिलते ही उन्होंने पलटवार किया। पीछे हटने के बजाय,
उन्होंने उनका डटकर सामना किया और अपने मंत्रालय को और अधिक लोगों से भरने का फैसला किया।
ओबीसी और दलित। लेकिन भूमि सुधारों को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ गए।
दबाव के चलते इंदिरा गांधी ने उन्हें बर्खास्त करने का फैसला किया। उन्होंने राष्ट्रपति का आदेश लागू किया।
आंध्र प्रदेश में शासन किया और राव को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल नहीं किया।

आंध्र प्रदेश के अनुभव ने राव को कई सबक सिखाए। उनमें से एक यह था कि...
उसने अपनी क्षमता से अधिक काम अपने हाथ में ले लिया। उसने यह भी सीखा कि
कठिन परिस्थितियों से निपटने के तरीके के रूप में 'असमंजस्य'। जब
रामानन्द तीर्थ का मुकाबला बुरगुला रामकृष्ण राव से था।
दोनों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद पाने की कोशिश की थी।
राव का समर्थन। वे पार्टी के भीतर दो गुटों के प्रमुख थे। इससे स्थिति उत्पन्न हुई।
राव के लिए यह एक बहुत बड़ी दुविधा थी। क्योंकि वह उन दोनों के बहुत करीब थे।
नागपुर से कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने रामकृष्ण राव के अधीन काम किया।
तीर्थ उनके आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे। राव ने किसी तरह यह सब संभाल लिया।
उन्होंने किसी का पक्ष लेने से परहेज किया और ऐसा करते हुए किसी को भी नाराज नहीं किया। इस प्रक्रिया में,
उसने 'मध्य मार्ग' पर चलने का अर्थ सीखा।
राव ने उन दिनों सही राह पर बने रहने का महत्व भी सीखा।
उच्च कमान के पक्ष में—इंडियन नेशनल जैसी पार्टी में
कांग्रेस।

चतुर्थ

नरसिम्हा राव को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता था।
लोकप्रिय रूप से जाने जाने वाले—पहले दक्षिण भारतीय थे जो प्रधान मंत्री बने।
मंत्री। तब तक, गुजरात के रहने वाले मोरारजी देसाई को छोड़कर,
भारत के सभी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही रहे हैं।
हालांकि राव राज्यकला और वास्तविक राजनीति के माहिर थे, लेकिन वे जनवादी नहीं थे।
नेता। वे निस्संदेह भारत के सबसे कम करिश्माई प्रधानमंत्री थे।
कांग्रेसी नेता जयराम के शब्दों में, वह 'मरी हुई मछली' की तरह करिश्माई हैं।
रमेश। उनके सहकर्मी उन्हें निर्मम, निरक्षर और हिसाब-किताब करने वाला मानते थे।
वह आमतौर पर केवल अपने सहयोगियों को ही जानकारी प्रदान करता था—और
अधिकारियों को—आवश्यकतानुसार जानकारी दी जाती थी। और उन्होंने उनकी सेवाओं का उपयोग किया।

आवश्यक था—और वे उन प्रधानमंत्रियों में से एक थे जिनके पास कोई गुट नहीं था।
शायद ही किसी को पूरी जानकारी दी गई थी—इसी वजह से वे नियंत्रण कर पाए।
वह किसी कुशल कठपुतली नचाने वाले की तरह स्थिति को नियंत्रित करता है।
जनता से जुड़ने में उनकी असमर्थता ही उनके पतन का कारण बनी।
जब वे 1996 में दोबारा चुनाव के लिए खड़े हुए थे। और फिर भी, हमलों के बावजूद
उनकी पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के पास कहने को न के बराबर जनसमर्थन है।
अल्पमत सरकार के नेतृत्व में शासन की चुनौतियाँ,
एक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को विरासत में पाकर, उग्रवाद का सामना करना पड़ रहा है।
कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती राज्य, और एक आक्रामक हिंदू
राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव के बीच, नरसिम्हा राव ने अपना कार्यकाल पूरा किया।
वह पहले ऐसे कांग्रेसी थे जो पार्टी के प्रथम सदन से संबंधित नहीं थे।
नेहरू-गांधी परिवार को ऐसा करने के लिए कहा गया।
राव के कार्यकाल (1991-96) के दौरान ही राजनीतिक केंद्र में बदलाव आया।
गुरुत्वाकर्षण देश के दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गया। संयोगवश, या जानबूझकर,
यह घटना उसी समय घटी जब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा।
राज्य को फिर कभी पटरी पर लाने के लिए। राव पर अक्सर जानबूझकर किए गए कार्यों का आरोप लगाया जाता था।
उत्तर प्रदेश को कांग्रेस के हाथों से फिसलने देना। उत्तर प्रदेश का नुकसान, नेहरू-गांधी परिवार का गृह राज्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनका राजनीतिक आधार कमजोर हो गया।

■

नरसिम्हा राव नेहरू-गांधी परिवार के बारे में ज्यादा अच्छी राय नहीं रखते थे।
उनकी क्षमताओं के बारे में। इंदिरा गांधी के साथ उनके जटिल संबंध थे।
राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ।
हालाँकि उनकी तरक्की में इंदिरा गांधी का योगदान था, और उन्हें एक
इंदिरा गांधी के वफादार राव को तब गहरा दुख हुआ जब 1973 में इंदिरा गांधी ने उन्हें

पद से हटा दिया।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। हालांकि वे कुछ समय के लिए रूठ गए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया।
उसे न छोड़ने के लिए—और अपनी वफादारी के लिए पुरस्कृत होने के लिए। 1980 में, इंदिरा
गांधी ने उन्हें पहले विदेश मंत्री और फिर गृह मंत्री बनाया।
1984 में जब उनकी हत्या हुई थी, तब वे इसी पद पर थे। एक समय वे
उन्होंने 1982 में उन्हें राष्ट्रपति भवन भेजने पर भी विचार किया था।
हालांकि अंततः उन्होंने ज़ैल सिंह को राष्ट्रपति के रूप में चुना।
निजी तौर पर वह आपातकाल लागू करने के उसके फैसले से असहमत थे।
और वे छद्म नाम से मेनस्ट्रीम पत्रिका के लिए लिखते थे।
इसका संपादन उनके मित्र निखिल चक्रवर्ती ने किया था। उन्होंने इसकी आलोचना की।
विपक्षी नेताओं को जेल में डालना और प्रेस पर प्रतिबंध लगाना
सेंसरशिप। लेकिन पार्टी के महासचिव नियुक्त होने के बाद।

1976 में आंध्र प्रदेश से दिल्ली आने के बाद, इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने यहाँ बसाया था।
उन्होंने खुले तौर पर उनका विरोध नहीं किया।
उन्होंने अपने द्वारा लिखे एक उपन्यास में इंदिरा गांधी के प्रति तीखी आलोचना व्यक्त की थी।
इसका मूल शीर्षक 'द अदर हाफ' था, और बाद में इसे 'द इनसाइडर' के रूप में प्रकाशित किया गया।
लेखक का मुख्य पात्र (एक राजनेता जो उसका दूसरा रूप था) था
राव इंदिरा गांधी के बारे में कहते हैं: 'इंदिरा गांधी कभी भी, दोहराता हूँ, कभी भी, इस सदमे से उबर नहीं पाएंगी।'
उसकी... बेहद जटिल... हीनता की भावना... और एक स्वीकारोक्ति
आंतरिक अपर्याप्तता, और इन सबसे ऊपर एक प्रबल जुनून
अपने महान पिता को भी पीछे छोड़ते हुए अमर प्रसिद्धि प्राप्त करना।

वे राजीव गांधी की क्षमताओं की और भी अधिक आलोचना करते थे—और
वह अपनी पीड़ा निखिल्दा से अकेले में व्यक्त करता था। हालाँकि वह वरिष्ठ था।
राजीव अक्सर राव को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में इंतजार करवाते थे।
उस अवसर पर, राजीव के जाने के बाद राव दो घंटे तक आगंतुक कक्ष में इंतजार करते रहे।
उन्हें तत्काल परामर्श के लिए 7, रेस कोर्स रोड पर बुलाया गया।
अंदर राजीव अपने दोस्तों रोमी चोपड़ा और राजीव के साथ गपशप कर रहे थे।
सेठी।
चक्रवर्ती ने उत्तेजित होकर पूछा, 'तुम यह सब क्यों सहते हो?'
राव। 'आप कोई स्टैंड क्यों नहीं लेते?'
'क्या रुख अपनाऊं?' पीवी ने जवाब दिया। 'वह कहेगा,
"Jao phir chutti karo (Go, pack your bags)".'
1991 में, राजीव गांधी ने ठीक यही किया—उन्होंने राव को भेजा
पैकिंग। हालाँकि राजीव ने अपने फैसले को यह कहकर सही ठहराया कि वह चाहता था
उन्होंने एक युवा टीम को लाने के संबंध में एक लेख पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
जो मेनस्ट्रीम में प्रकाशित हुआ था, जिसके बारे में राव पर संदेह था कि उसने इसे प्रकाशित किया था।
इसे लिखा गया था। यह वी. पी. सिंह द्वारा राजीव गांधी को हराने के कुछ ही समय बाद प्रकाशित हुआ था।
गांधी जी ने 1989 के आम चुनावों में भाग लिया था। इसका शीर्षक था 'महान आत्महत्या', और
'कांग्रेसी' नामक छद्म नाम से लिखे गए इस लेख में तीखा हमला किया गया था।
राजीव पर टिप्पणी करते हुए, उसे 'तारीफ का आदी' बताया गया, जिसने अपना सारा समय बर्बाद कर दिया था।
उनकी अपरिपक्वता के कारण उन्हें 1984 में भारी जनादेश दिया गया था और अहंकार।
राव और सोनिया गांधी के बीच संबंध भी उतने ही जटिल थे।
शुरू में, उसने उसकी बात मान ली और इस बारे में उसके सुझावों को स्वीकार कर

लिया कि किसे होना चाहिए।
प्रधानमंत्री पदभार संभालने के बाद मंत्रिमंडल में रहें।
“कैबिनेट कैसी लगी?” उसने भुवनेश से पूछा था।
21 जून 1991 को शपथ ग्रहण समारोह के बाद चतुर्वेदी।
‘आप मेरी राय क्यों पूछ रहे हैं?’ चतुर्वेदी ने अपने जवाब में कहा था।
स्पष्ट शब्दों में। 'यह आपकी कैबिनेट नहीं है, और आप यह जानते हैं।' जाहिर तौर पर, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन को भेजा था।
मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की तीन अलग-अलग सूचियाँ—प्रत्येक
पिछले वाले को संशोधित करते हुए पुनरावृति की गई और राष्ट्रपति ने एक
चतुर्वेदी के प्रति इस बारे में उपहासपूर्ण टिप्पणी।
‘मैं क्या कर सकता हूँ?’ राव ने बेबसी जताते हुए कहा। ‘(विंसेंट)’
जॉर्ज का कहना है कि यह सोनिया गांधी की पसंद है और वह इसमें और नाम जोड़ते हैं।
अपने प्रधानमंत्रित्व काल के पहले वर्ष के दौरान, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि सोनिया गांधी अच्छे मूड में थीं। हालांकि वे प्रधानमंत्री थे,
और वह एक आम नागरिक थी, इसलिए वह नियमित रूप से उससे मिलने जाता था।
उसे यहाँ बुलाने के बजाय, उसके निवास स्थान 10, जनपथ पर चले जाओ।
रेस कोर्स रोड स्थित 7 नंबर पर स्थित प्रधानमंत्री आवास के बारे में उन्हें जानकारी देते रहें।
सरकार क्या कर रही थी, इस बारे में भी उन्होंने सुनिश्चित किया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वह जो कुछ भी करे,
जनपथ स्थित 10 नंबर भवन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं कर ली गईं।
प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के एक साल बाद उन्हें यह संदेह होने लगा कि
उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। यही उसके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित होने वाला था।
उनके रिश्ते।
‘क्या आपको लगता है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए?’ सोनिया ने राव से

पूछा था।
यह बात उन्होंने मुझे 1992 में एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान बताई थी।
अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप मुझे क्या सलाह देते?
'चूंकि आप मुझसे इस तरह सलाह मांग रही हैं जैसे आप मेरी बेटी हों,'
राव ने जवाब दिया, 'मैं कहूंगा, "नहीं"।'
उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन अगर आपके बच्चे रुचि रखते हैं, तो मैं उन्हें तैयार करूँगा।'
मैं उन्हें अपने कुछ दौरों पर अपने साथ ले जाऊंगा।'
तभी से राव को सोनिया की संभावित हरकतों को लेकर चिंता सताने लगी।
उसी वर्ष के अंत में, उनके रिश्ते में और अधिक तनाव आ गया।
बाबरी मस्जिद का विध्वंस। इससे सोनिया बहुत दुखी थीं—और
उसे शक था कि उसने जानबूझकर उस ढांचे को लाने की अनुमति दी थी।
नीचे।
1993 से ही राव पर चापलूसी करने के लिए आलोचनाएं होती आ रही थीं।
उसके। जनपथ स्थित 10 नंबर की जगह पर उसका आना-जाना धीरे-धीरे कम होता गया और फिर बंद हो गया।
उनके बीच दूरियां बढ़ती गईं। पार्टी के भीतर उनके प्रतिद्वंद्वियों का प्रभाव बढ़ता गया।
सोनिया उनके खिलाफ हो गईं और 1995 में उन्होंने पहली बार खुले तौर पर उनकी आलोचना की।
समय बीतने के साथ ही उन्होंने ऐसा अमेठी में किया, जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है।
राजीव गांधी के मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए।
हत्या। यह राव के लिए एक स्पष्ट संकेत था कि वह अब हत्या की योजना बना रही थी।
सक्रिय राजनीति में आना।
राव ने उनके आरोप पर अपनी अनूठी शैली में प्रतिक्रिया दी।
उनकी कार्यशैली का उदाहरण देते हुए। उन्हें भ्रम में ही आनंद आता था, जो
कभी-कभी वह स्वयं एक साथ कई सिग्नल भेजने के लिए व्यवस्था करता था।
इसी समय के आसपास, अचानक गृह मंत्रालय ने एक नोट भेजा।

कैबिनेट ने कहा कि राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहे जैन आयोग
इसे भंग कर देना चाहिए। राव ने इस प्रस्ताव को दृढ़ता से खारिज कर दिया। यह था
हालांकि यह बात विचित्र है कि गृह मंत्री एस. बी. चव्हाण, जो राव के विश्वासपात्र थे,
प्रधानमंत्री की मंजूरी के बिना इतना व्यापक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।
राव जाहिर तौर पर सोनिया गांधी को यह दिखाना चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में वे
भी उतने ही सक्षम हैं।
वह राजीव गांधी के हत्यारों को ढूंढने के लिए काफी चिंतित थीं।
फिर दोषियों को सजा दिलाने के अपने संकल्प पर और जोर देने के लिए,
राव ने जांच की प्रगति की निगरानी का जिम्मा एक मंत्री को सौंपा।
जांच में तेजी लाएं।
मंत्री ने सहायता के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध किया।
आयोग। मंजूरी के लिए राव से अनुरोध किया गया था। लेकिन
प्रधानमंत्री आवास से फाइल वापस नहीं आई। सामान्यतः, एक फाइल जो
उसे शाम को भेजा गया था, और अगली सुबह वापस कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने के बाद, 'उन फाइलों को छोड़कर जिन्हें
वह नहीं चाहते थे'
स्पष्ट'।
मंत्री जी, जो आसानी से प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं थे, प्रधानमंत्री से मिलने
वापस आए। ऐसा क्यों हुआ?
उन्होंने पूछा कि नौकरशाह की नियुक्ति में इतना समय क्यों लग रहा है? राव ने फोन
किया।
अपने सहायकों के बीच। उन्होंने मंत्री के सामने उन्हें फटकारा। 'क्या हुआ है?'
फाइल का क्या हुआ? मुझे क्यों नहीं भेजी गई?' उन्होंने याद दिलाया।
उसे पहले ही मंजूरी के लिए मामला भेजा जा चुका था।
उन्होंने कहा, 'महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भूरे रंग के कवर में रखना चाहिए।'
चिड़चिड़ाते हुए, 'तो मुझे पता है कि महत्वपूर्ण कौन से हैं। कृपया शुरू करें।'
ऐसा करने से।
उन्होंने फाइल को भूरे रंग के कवर में लपेटकर भेजा। वह अभी तक वापस नहीं आई
है।

उनके हस्ताक्षर के साथ। ज्यादातर लोग इस स्तर पर हार मान लेते। आप
किसी मुद्दे पर बार-बार प्रधानमंत्री से मत मिलिए।
अधिकारी की नियुक्ति। लेकिन इस मंत्री के साथ ऐसा नहीं था, उन्होंने एक बैठक की मांग की।
एक बार फिर प्रधानमंत्री के साथ।
राव ने अपने कर्मचारियों को एक बार फिर बुलाया। इस बार उन्होंने उन्हें फटकार लगाई।
और भी कड़े शब्दों में।
'क्या आप लोग एक साधारण मामला भी नहीं संभाल सकते?'
उन्होंने जोर देकर कहा कि फाइल उन्हें भूरे रंग के कवर में भेजी गई थी। 'यह
राव ने चिढ़कर कहा, 'इससे पता चलता है कि आप मुझे बहुत सारी ब्राउन फाइलें भेज रहे हैं।' इसके बाद उन्होंने मंत्री को आश्वासन दिया कि वे इस मामले को तुरंत देखेंगे।
कुछ नहीं हुआ। इस बार तो महत्वाकांक्षी मंत्री भी पीछे हट गए।
उन्हें पता था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कार्यालय में जाना ठीक नहीं होगा।
नरसिम्हा राव को यह अच्छी तरह पता था कि जब वह नहीं चाहते थे तब भी लोगों को कैसे थकाना है।
निर्णय लेने।
■

राव अक्सर कहते थे, 'कोई निर्णय न लेना भी एक निर्णय है', और इस तरह वे एक
कुछ लोगों को लगा कि यह केवल निर्णयों पर टालमटोल थी, लेकिन इसे दार्शनिक मोड़ दे दिया गया।
'पीवी ठंडा करके खाते हैं (पीवी पहले भोजन को ठंडा करने में विश्वास रखता है और फिर उसे खाकर),' भुवनेश चतुर्वेदी अपने बॉस के बारे में वफादारी से कहते थे।
पाउट—यह उपनाम राव को मीडिया ने दिया था, क्योंकि उनके चेहरे पर हमेशा भौंहें चढ़ी रहती थीं।
वह हमेशा उसके चेहरे पर बैठा रहता था—इसके फायदे और नुकसान का आकलन करता था।

निर्णय लेने में वह इतना व्यस्त रहता था कि अक्सर वह निर्णय लेने का समय ही नहीं निकाल पाता था।
लेकिन जो लोग उन्हें बेहतर जानते थे, वे कहते थे कि राव इसका इस्तेमाल करते थे।
...
केवल राजनीतिक हथियार के रूप में टालमटोल करना। 'ऐसा तभी होता था जब वह नहीं चाहता था।'
उनके एक सचिव ने कहा, 'उन्होंने इसे स्थगित करने का फैसला लिया है।'
जिसने उसे करीब से देखा था। 'लेकिन वह ठीक-ठीक जानता था कि उसे क्या चाहिए।'
जब वह चाहता था, तब वह निर्णायक हो सकता था। उसे बस कुछ ही पल लगे।
आर्थिक सुधारों को लागू करने का दूरगामी निर्णय लेने के लिए घंटों का समय था।
जून-जुलाई 1991। भारत के पास भुगतान करने के लिए मुश्किल से तीन सप्ताह की विदेशी मुद्रा थी।
आयात के मामले में कंपनी की स्थिति खराब थी और वह अपने वित्तीय ऋणों पर चूक करने के कगार पर थी।
दायित्वों के संबंध में, राव ने संकट से उबरने के लिए तेजी से कदम उठाते हुए एक सुरक्षा उपाय सुरक्षित किया।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज (गिरवी रखकर)
सरकार के स्वर्ण भंडार)। अपने वित्त मंत्री के साथ,
मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उन्होंने व्यापक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की।
अगले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और राव की खूब सराहना हुई।
आर्थिक सुधारों के जनक।
बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले राव की अनिर्णय की स्थिति में,
जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, त्रासदी घटित होने के बाद उन्होंने दृढ़ता से कार्रवाई की।
‘मौन’, ‘असमंजस’, ‘टालमटोल’ और ‘नाटकीयता’—ये सब थे
उसने अपने इच्छित कार्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से हथियारों का इस्तेमाल किया। और उसने
उन्होंने अफरा-तफरी के बीच फल-फूलकर छल और छल का इस्तेमाल किया।
अपने विरोधियों को असमंजस में रखने के लिए छलावा करना।

■

अपने कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान, राव द्वारा अपने प्रबंधन के तरीके के कई उदाहरण सामने आए।
अल्पमत सरकारों की संख्या बहुत अधिक थी। वह काफी हद तक समर्थन पर निर्भर थे।
विपक्षी नेताओं को खुश रखा और उनका मनोबल बनाए रखा।
प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मिलने आए विपक्षी नेता वहीं रुके रहे।
'अनाम'; उन्हें रजिस्टर में केवल 'आरक्षित' के रूप में दर्शाया गया था।
नियुक्ति थी, इसलिए उनके उससे मिलने का कोई रिकॉर्ड नहीं था।
प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देश दिए गए थे कि यदि वे किसी भी 'कार्य' के लिए अनुरोध करते हैं तो
चाहे ठेके देना हो या अधिकारियों का तबादला, यह होना चाहिए।
काम तुरंत निपटा दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने अपनी सीमाओं से परे जाकर काम किया।
लालू यादव और मुलायम यादव जैसे अन्य दलों के नेताओं को अपने पक्ष में करने का तरीका
सिंह यादव, ज्योति बसु, एच. डी. देवेगौड़ा। चूंकि उन्हें चुनाव लड़ना था
शुरुआत में गठबंधन सरकार के बारे में, वह जानता था कि उसे राजनेताओं को अपने साथ रखना होगा।
of other parties happy: 'Na jaane kis bhesh main Narayan mil jaye (We
मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि भगवान किस वेश में प्रकट हो सकते हैं।
कभी-कभी उनकी रणनीति कारगर साबित होती थी। एन. टी. रामाराव, जिन्होंने नेतृत्व किया था
तेलुगु देशम—राव के शासनकाल में कांग्रेस का विरोध करने वाला एक क्षेत्रीय संगठन।
अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश ने अपने खिलाफ उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया है।

राव ने नवंबर 1991 में उपचुनाव में संसद में प्रवेश किया। राव ने जीत हासिल की।
नंदीयाल से रिकॉर्ड 5.8 लाख वोटों के साथ। उनमें से 90 प्रतिशत लोगों ने
उन्होंने अपना वोट डालकर उन्हें चुना।
राव जानते थे कि वे इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की तरह शासन नहीं कर सकते।
उनके पास भारी बहुमत था, जो उनके पास नहीं था।
आम सहमति से शासन करना। और विरोधी दलों को ऐसा न करने के लिए राजी करना।
उनकी सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न करना।
■

‘PV bahut zaalim hain (PV is very ruthless),’ Bhuvnesh Chaturvedi
एक बार उन्होंने अपने बॉस के बारे में चुटकी ली थी। विपक्षी नेताओं के प्रति सुलह का रवैया रखते थे।
वह अपने पार्टी सहयोगियों के साथ सख्त रवैया अपना सकते थे, खासकर उनके साथ जो...
वे संभावित प्रतिद्वंद्वी थे।
उन्होंने प्रणब मुखर्जी को अपने साथ रखा, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे।
1991 में कांग्रेस को अपने मंत्रिमंडल से बाहर करने की उम्मीद में मुखर्जी को यह पद मिला।
वित्त मंत्रालय। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए राव की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। 'प्रणब
भुवनेश ने कहा, 'उन्होंने मुझसे पीवी से बात करने के लिए कहा था ताकि वह उसे आर्थिक सहायता दे सकें।'
चतुर्वेदी ने मुझे बताया। राव ने चतुर्वेदी से कहा, 'यह समस्याग्रस्त होगा'—और

मुखर्जी की एक बड़े औद्योगिक समूह से कथित निकटता का हवाला दिया गया।
अनुरोध न मानने के कारण।
जब मंत्रियों की सूची सामने आई, तो मुखर्जी आशा से भरे हुए थे।

अपना नाम न देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया।
समारोह। राव ने उसी रात उसे फोन किया और उसे कम पेशकश की।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण होता है।
मुखर्जी ने कहा कि वह इस पर विचार करेंगे। राव ने जवाब दिया, 'आप सोच सकते हैं।'
जब तक आप चाहें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सोमवार को शामिल होंगे।
अधिसूचना जारी होने वाली है।' मुखर्जी ने अपने संस्मरणों में लिखा, 'मैं
आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।' कुछ दिनों बाद राव ने बताया
मैंने उससे कहा, 'प्रणब, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि मैंने तुम्हें मंत्रिमंडल में क्यों नहीं लिया।'
शायद एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपसे इस बारे में बात कर सकूंगा।' उस दिन
कभी नहीं आए। और मुखर्जी उपाध्यक्ष बने रहे।
योजना आयोग।
फिर अर्जुन सिंह थे: वे राव के लिए हमेशा एक कांटा बने रहे।
अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने और फोतेदार ने राव का समर्थन किया था।
प्रधानमंत्री पद के लिए राव की उम्मीदवारी इस शर्त पर कि राव अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।
तीन महीने के भीतर कांग्रेस के अध्यक्ष। 'तीन महीने क्यों?'
राव ने अर्जुन सिंह और फोतेदार को आश्वासन दिया, 'मैं पैंतालीस वर्षों में पद छोड़ दूंगा।'
दिन।' वे पैंतालीस दिन कभी नहीं आए। 'जैसे ही आम सहमति बन जाएगी
'किसी नाम पर, मैं पद छोड़ दूंगा,' राव हर बार उनसे यही कहते थे।
इस विषय को उठाया। राव ने अनुमान लगाया कि इस बात पर आम सहमति बन जाएगी कि कौन यह कर सकता है।
पार्टी अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाना लगभग असंभव था—अर्जुन सिंह
शरद पवार को वह स्वीकार नहीं करेगा और शरद पवार को भी वह स्वीकार नहीं करेगा। और वह ऐसा करने वाला भी नहीं था।

एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी को खड़ा करना जो उसे अस्थिर कर सके। उसने शुरू में ऐसा किया था
अर्जुन सिंह को लोकसभा में पार्टी के नेता के पद पर बनाए रखने के लिए।
अच्छे हास्य के साथ—और अपनी सरकार को सुचारू शुरुआत दें। राव ऐसा नहीं कर सके।
उन्हें सदन में नेता बनना पड़ा क्योंकि वे सांसद नहीं थे। उन्हें चुनाव जीतना पड़ा।
संसद को विधिवत रूप से निर्धारित छह महीने के भीतर।
महीनों तक, अर्जुन सिंह सुलह के सारे बहाने बनाता रहा। 'उनकी
meherbaani hai ki mujhe leader banaya, rakhenge tho bhi theek,
nahin tho bhi theek hai (It's his goodness that he has made me a leader.
अगर वो मेरे साथ बना रहता है तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी ठीक है।' लेकिन
जब राव सांसद बने और अर्जुन सिंह की जगह नेता बने
लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी से सिंह नाराज थे। वे एक नेता के रूप में उभरे।
इसके बाद के महीनों में राव के कट्टर विरोधी। जब वह और
अप्रैल 1992 में तिरुपति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव में शरद पवार ने शानदार जीत हासिल की, जिसके बाद राव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनकी राजनीतिक गतिविधियों को सीमित कर दिया।
उनके पंख। उन्होंने नव निर्वाचित उम्मीदवारों में से कुछ को इस्तीफा देने के लिए राजी कर लिया।
इस आधार पर कि महिलाओं और दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था
शरीर और सीडब्ल्यूसी को पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप, सभी सिंह और पवार समेत नए सीडब्ल्यूसी सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा।
इससे राव को पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय का पुनर्गठन करने में मदद मिली।
और पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करें।

अंततः, 1995 में अर्जुन सिंह ने कांग्रेस को विभाजित कर दिया।
नारायण दत्त तिवारी और एम.एल. तिवारी के साथ मिलकर कांग्रेस (तिवारी) का गठन करना।
फोतेदार, शीला दीक्षित और अन्य। हालांकि अर्जुन सिंह ने कोशिश की थी
सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में, उन्होंने खुलकर विरोध नहीं किया।
मूल पार्टी से अलग होने के बाद कांग्रेस (तिवारी) के साथ उनका क्या संबंध था?
पार्टी। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, राव ने पार्टी का पूरा नियंत्रण रखा।
पार्टी के भीतर उनके विरोधियों के बारे में।
■

राव का भाजपा के साथ जटिल संबंध था। उन्होंने भाजपा को संभाला।
उन्होंने पार्टी से निपटने का तरीका अपने पूर्ववर्तियों से बिल्कुल अलग रखा।
जैसा कि हमने देखा है, राव ने हिंदू विचार में रुचि दिखाई थी और
उन्हें बचपन से ही दर्शनशास्त्र सिखाया गया, न केवल इसलिए कि वे ब्राह्मण थे।
न केवल उनके पूर्ववृत्तों के कारण बल्कि निज़ाम विरोधी आंदोलन के कारण भी।
में भाग लिया।
राव ने सबसे पहले आरएसएस नेताओं बालासाहेब देवरस और उनके भाई से मुलाकात की।
नागपुर में भाऊराव देवरास के साथ उनकी दोस्ती हो गई।
यह बालासाहेब के आरएसएस प्रमुख बनने से पहले की बात है। उन दिनों राव रहते थे।
‘सोना गली में एक कमरे के छोटे से मकान’ में रहकर उन्होंने लॉ कॉलेज में पढ़ाई की।
नागपुर।
राव एक नए शहर में थे, अपने परिचित परिवेश से दूर। 'संघ'
लोगों से दोस्ती करने और चाय की चुस्की लेते हुए उनसे मिलने की उनमें यह खासियत है।

चाय, भले ही वे तुरंत उपयोगी न हों,' यह बात सामने आई।
गोविंदचार्य, जिन्हें स्वयं भाऊराव ने ही मार्गदर्शन दिया था। 'राव और
भाऊराव का एक दूसरे से मिलना जारी रहा और वे एक दूसरे को जानने लगे।
राव वर्षों तक देवरास बंधुओं के संपर्क में रहे। लेकिन उन्होंने
भाऊराव के साथ उनका विशेष संबंध था, जिन्होंने, जैसा कि उल्लेख किया गया है, देखभाल की।
संघ की 'राजनीतिक शाखा' के रूप में, और जब यह शक्तिशाली हो गई थी
बालासाहेब 1980 के दशक और 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में बीमार थे।
इस दौरान संघ (आरएसएस) को आर. के. खांडेकर के बारे में भी पता चला था।
उस समय। 'मैं छह साल की उम्र से स्वयंसेवक थी और स्कूल जाया करती थी।'
खंडेकर ने मुझे बताया, 'आरएसएस की शाखाओं में। उस समय, हर सेकंड
नागपुर के एक घर में एक स्वयंसेवक रहता था। शाखाओं में बच्चे...
उन्हें हिंदू एकता के बारे में पढ़ाया गया था।
राव साहब को इस बात का (मेरे स्वयंसेवक होने के बारे में) पता था जब उन्होंने
उन्होंने मुझे काम पर रख लिया।' खांडेकर वाई. बी. चव्हाण के साथ काम करने के लिए दिल्ली आए थे;
इसके बाद उन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेता वसंत साठे ने नौकरी पर रख लिया।
राव की टीम में शामिल होने से पहले। वह राव का एक भरोसेमंद सहयोगी बनने वाला था।
जब वह प्रधानमंत्री बने। 'अंत तक, उन्हें मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि
मैंने जो भी कहा, वो हो गया। खांडेकर ने पैसों का भी ख्याल रखा।
राव की राजनीतिक गतिविधियों के लिए लोग रेस कोर्स रोड आए थे। खांडेकर
राव के साथ यात्रा की, उनकी नियुक्तियों को संभाला, संवेदनशील कार्यों को अंजाम दिया।
उन्हें राजनीतिक कार्य सौंपे गए थे, जिनमें नेताओं तक गोपनीय संदेश पहुंचाना शामिल था।
प्रधानमंत्री की ओर से।
वह अपने कपड़ों पर भी नजर रखता था। एक बार राव को रानी से मिलने जाना था।
एलिजाबेथ द्वितीय जब इंग्लैंड की यात्रा पर थीं। वह तैयार हो चुकी थीं, और

जब वह जाने ही वाले थे तभी उनके निजी सचिव रामू दामोदरन ने उन्हें देख लिया।
उसके मोजे। उनका रंग उसकी कमीज से बिलकुल अलग था।
उसने जो पहना था, उसे देखो। दामोदरन ने हैरानी से कहा, 'उसने कैसे मोज़े पहने हैं!'
हताशा में। दामोदरन, जो भारतीय विदेश मंत्रालय का हिस्सा थे,
राव के साथ जुड़ने से पहले सेवा में रहते हुए, उन्हें पहनावे के महत्व का ज्ञान था।
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। उन्होंने खांडेकर से कहा कि वे प्रधानमंत्री से बदलाव करने के लिए कहें।
उसके मोजे, 'लेकिन कृपया इसे सावधानी से करें और उसे मराठी में बताएं।'
खांडेकर ने राव के कान में मराठी में कुछ शब्द कहे, और फिर
वह अपने लिए मोजों की एक नई जोड़ी लेने के लिए अपने कमरे में भागा। वह ऐसा करता था।
राव के लिए कपड़ों का एक अतिरिक्त सेट ले जाएं, 'यहां तक कि एक जोड़ी चश्मा भी'।
कभी-कभी नरसिम्हा राव के 'आर. के. धवन' कहे जाने वाले खांडेकर थे
राव ने उस मध्यस्थ का इस्तेमाल किया जब प्रधानमंत्री को भाजपा को संदेश भेजने होते थे।
आरएसएस नेताओं के लिए। या उन आगंतुकों का स्वागत करने के लिए जिनका नाम सूची में नहीं था।
प्रधानमंत्री का औपचारिक घोषणापत्र।
संयोगवश या अनजाने में, अयोध्या को लेकर राव की परेशानियाँ यहीं से शुरू होने वाली थीं।
मई 1992 में भाऊराव की मृत्यु के तुरंत बाद—छह महीने पहले
बाबरी मस्जिद का विध्वंस। इसके तुरंत बाद, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने
मंदिर निर्माण को लेकर राव ने फिर से जोर लगा दिया। अब राव के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।
आरएसएस के भीतर एक विश्वसनीय संपर्क सूत्र। भाऊराव उनसे संपर्क में थे।
राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके साथ उनका संबंध बना रहा। राव ने एक बार भाऊराव से कहा था—यह बात 1992 की शुरुआत में कही गई थी—‘अगर ऐसा हुआ तो मुझे पहले से बता देना।’

अगर आप कभी बाबरी मस्जिद को गिराने का फैसला करते हैं तो?
अगर कुशभाऊ की बात पर विश्वास किया जाए तो भाजपा ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा किया था।
ठाकरे और के. सुदर्शन, जिनकी टिप्पणियाँ इस लेख में पहले प्रकाशित हो चुकी हैं।
अध्याय।
■

‘अगर पीवी सत्ता में बने रहते तो वे वास्तव में भाजपा का सफाया कर देते।’
भुवनेश चतुर्वेदी ने एक बार मुझसे कहा था, 'थोड़ा और समय लगेगा।' उनकी रणनीति
इसका उद्देश्य भाजपा को कमजोर करना था—लेकिन सीधे टकराव के माध्यम से नहीं।
भाजपा ने राम मंदिर और एक अन्य भवन के निर्माण की वकालत की।
देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। यह इसके विपरीत कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध था।
जम्मू और कश्मीर को उसके विलय के समय दिया गया विशेष दर्जा
भारत में आकर उन्होंने राष्ट्रीय एकता लाने के लिए हिंदुत्व का समर्थन किया। राव
वह जानता था कि वह भाजपा की चुनौती का सामना न तो किसी भी रूप में कर सकता है और न ही किसी भी रूप में।
हिंदू विरोधी या राम विरोधी—या फिर उसकी राष्ट्रवादी बयानबाजी का मुकाबला करके।
कांग्रेस को एक हिंदू समर्थक पार्टी के रूप में स्थापित करना चाहते थे (बिना
अल्पसंख्यक-विरोधी रुख अपनाना), और भाजपा से उसका हिंदू मुद्दा छीन लेना।
आरएसएस में भाऊराव के अलावा, राव का अन्य लोगों के साथ भी एक दुर्लभ सौहार्दपूर्ण संबंध था।
अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों ने कई मौकों पर एक-दूसरे की मदद की।
अपने करियर में। वाजपेयी की कविताओं की एक पुस्तक का विमोचन करते हुए, 13 तारीख को
अक्टूबर 1995 में, राव ने उन्हें अपना 'गुरु' बताया था। वाजपेयी ने तुरंत ही

राव को ‘गुरुघंटाल’ कहकर पलटवार किया। (इस विशेषण का अर्थ या तो यह हो सकता है)
(एक बहुत ही चालाक व्यक्ति या एक महान शिक्षक।)
योजना के अनुसार, और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, राव ने हमेशा से ही इस बात को बढ़ावा दिया था कि
भाजपा के ‘उदारवादी’ तत्व— वाजपेयी, जसवंत सिंह और भैरों
सिंह शेखावत उनके मित्र थे। लगातार अपने संबंधों को मजबूत करते हुए
इस पद के जरिए उन्होंने एल.के. आडवाणी जैसे कट्टरपंथियों को कमजोर करने की उम्मीद की थी, और
भाजपा में फूट और गहरी हो गई है। शुरुआत में, यहाँ तक कि अधिक कट्टरपंथी भी।
आडवाणी राव को न केवल 'सबसे विद्वान प्रधानमंत्री' के रूप में देखते थे।
नेहरू के बाद, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जो 'कठिनाइयों और कठिनाइयों' को समझता था।
हिंदुओं के, जिन्होंने कट्टरपंथी निज़ाम के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी
हैदराबाद।
भाजपा को लुभाने की अपनी रणनीति के तहत, प्रधानमंत्री बनने के बाद राव ने दिया
लोकसभा में उपसभापति का पद पार्टी के दिग्गज नेता एस. को दिया गया।
मल्लिकार्जुनैया। इससे भाजपा खुश हुई लेकिन वामपंथी दल, जिनकी मदद की उन्हें भी जरूरत थी, नाराज हो गए। इसलिए जब उन्होंने दूरगामी कदम उठाए-
संबंधित कानून—पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991,
जिसके कारण धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त को जैसी थी वैसी ही बनी रही।
1947, विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के अलावा
कानूनी जांच के दायरे में आई संरचना—उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि यह जानबूझकर किया गया था।
कृपया कम्युनिस्ट पार्टियों को खुश करें। वह जानता था कि वे इस बात को लेकर चिंतित थे।
भाजपा की मंदिर संबंधी राजनीति।
दिसंबर 1991 में उन्होंने भाजपा की एकता यात्रा को जिस तरह से संभाला,
कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का सफर, राव की कुशल निर्देशन शैली का एक और

उदाहरण था।
तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने इस यात्रा की घोषणा की थी।
कांग्रेस की 'समस्या से निपटने में असमर्थता' की ओर ध्यान आकर्षित करना।
कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद। यह चौदह महीने का मामला था।
एल. के. आडवाणी द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा करने के बाद।
एकता यात्रा के माध्यम से जोशी को उम्मीद थी कि वे मंदिर से ध्यान हटा सकेंगे।
'मुद्दा', जो आडवाणी से जुड़ गया था।
डीसीएम टोयोटा वैन में भारत के चौदह राज्यों की यात्रा करते हुए,
15,000 किलोमीटर की यह यात्रा ध्वजारोहण समारोह के साथ समाप्त होनी थी।
1992 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्रीनगर में आयोजित समारोह में जोशी उपस्थित होते।
उसने अनुमान लगाया कि राव यात्रा से पहले उसे गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हो जाएगा।
श्रीनगर में प्रवेश किया। इससे वह हीरो बन जाएगा—और एक प्रतीक भी।
राष्ट्रीय एकता।
कश्मीर मुद्दे के इर्द-गिर्द मौजूद राष्ट्रवादी संवेदनशीलता को जानते हुए,
राव ने जोशी की पहल की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की। उन्होंने स्थिति को इस तरह संभाला कि...
स्थिति को इस तरह से प्रस्तुत करना जिससे 'उसके इरादों पर संदेह पैदा हो'।
प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जम्मू और कश्मीर मुक्ति
जेकेएलएफ फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन ने धमकी दी थी कि वे
श्रीनगर में भाजपा को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं दी गई। जैसा कि बाद में पता चला,
23 जनवरी 1992 को, जोशी के श्रीनगर पहुंचने से तीन दिन पहले, छह
राज्य में उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी करने पर भाजपा समर्थकों को मार गिराया गया।
पार्टी सदस्यों को श्रीनगर ले जा रही बसों पर आगजनी की गई। भाजपा ने फैसला किया।
श्रीनगर की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए
ध्वजारोहण।

इसी समय राव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने जोशी को हवाई जहाज से लाने की पेशकश की।
जम्मू से श्रीनगर तक सैन्य विमान से। जोशी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था।
स्वीकार करने के लिए। उन्होंने 26 जनवरी को लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
1992—योजना के अनुसार। लेकिन इसे गोलियों की आवाज के बीच फहराया गया।
कर्फ्यू के बावजूद शहर में ग्रेनेड फट रहे थे और सड़कों पर शायद ही कोई दिखाई दे रहा था। (जम्मू और कश्मीर उस समय शासन के अधीन था)
राष्ट्रपति शासन के दौरान, और राव की केंद्रीय सरकार के अधीन।
एक ऐसा आयोजन जिसे हजारों लोगों द्वारा देखा जाना था, उसमें केवल कुछ ही लोग उपस्थित हो पाए।
67 भाजपा सदस्य और सुरक्षाकर्मी दर्शक के रूप में मौजूद थे।
श्रीनगर से राष्ट्रीय एकता के लिए गरजने वाला नेता नहीं, बल्कि एक ऐसा नेता जो
उसे सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों द्वारा अपनी सुरक्षा करनी पड़ी।
जिसे ऐतिहासिक घटना के रूप में प्रचारित किया गया था, वह एक निराशाजनक घटना साबित हुई। मुरली
मनोहर जोशी को भाजपा अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल नहीं मिला।
राव ने कहा, 'अगर राजीव जीवित होते तो वे एकता यात्रा को रोक देते।'
उन्होंने अपने कुछ सहकर्मियों से कहा, 'और संदेश चला गया होता।'
(यह बात सामने आई) कि भाजपा श्रीनगर में तिरंगा फहराना चाहती थी लेकिन
केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया था।
राव की रणनीति शुरू से ही भाजपा को 'एक और' पार्टी के रूप में पेश करने की रही है।
कांग्रेस'—न कि 'एक अलग तरह की पार्टी'। अपने कार्यकाल के अंत में
सितंबर 1995 के मार्च महीने में गुजरात में 'महान सितंबर विद्रोह' हुआ था।
और शंकरसिंह वाघेला के नेतृत्व में भाजपा के सैंतालीस विधायकों ने विद्रोह कर दिया।
बागी विधायक खजुराहो के एक होटल में छिपे हुए थे और धमकी दे रहे थे कि वे...
मुख्यमंत्री केशूभाई पटेल की नवगठित सरकार को गिरा दें।
हालांकि वाजपेयी ने एक समझौता किया, और वाघेला के एक वफादार ने,

सुरेश मेहता ने केशूभाई की जगह ली, पार्टी में चल रहे आंतरिक कलह ने स्थिति को और बिगाड़ दिया।
दुखी वाजपेयी अपने सहयोगियों के सामने रो पड़े। उन्होंने कॉलर ऊपर खींच लिया।
अपने कुर्ते के बारे में अफ़सोस जताते हुए आडवाणी ने भी कहा, 'हम इसे हमेशा ऊँचा उठा सकते थे।'
अब और नहीं कर सकते।' अचानक, भाजपा की चमक फीकी पड़ गई थी—और
यह 'गुटबाजी से ग्रस्त, सत्ता के भूखे' कांग्रेस (I) से मिलता-जुलता दिखने लगा है।
इस पूरे घटनाक्रम के पीछे 'मास्टर कठपुतली निर्देशक' कोई और नहीं बल्कि पी.वी. थे।
Narasimha Rao. Shankarsinh Vaghela was in touch with Gujarat
भुवनेश ने खुलासा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष प्रबोध रावल 'हमारे आदमी' थे।
चतुर्वेदी। 'हमने रावल को बताया था कि हमने एक और पीसीसी अध्यक्ष को भेजा है।'
चतुर्वेदी ने खुलासा किया, 'गुजरात।'
'कौन?' रावल ने पूछा था।
चतुर्वेदी ने कहा, 'नरेश चंद्र।'
गुजरात के राज्यपाल नरेश चंद्र का कभी भी संपर्क नहीं था।
प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर, उन्होंने सरकार के एक वरिष्ठ सचिव के माध्यम से यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
भारत।
ऑपरेशन खजुराहो भारतीय राजनीति में एक नया चलन स्थापित करने वाला था।
पार्टियां अपने विधायकों को पांच सितारा होटलों में हवाई यात्रा करा रही हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके।
विपक्ष के शोषणकारी तौर-तरीके।
इस घटना के बाद, 'भाजपा का कांग्रेसीकरण' वाक्यांश प्रचलित हो गया।
मुद्रा।
चतुर्वेदी ने टिप्पणी की, 'यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह जानबूझकर किया गया था।'
पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा योजनाबद्ध तरीके से। वे इसे प्रदर्शित करना चाहते थे।
कांग्रेस, चाहे अच्छी हो या बुरी, एकमात्र ऐसी सत्ताधारी पार्टी है जो अकेले ही शासन

कर सकती है।
शासन करना जानता था।
वी

राव के प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद, 1992 के मध्य में, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने
मंदिर पर दबाव फिर से बढ़ा दिया गया।
तब तक, भाजपा को राव द्वारा कठिन परिस्थितियों को संभालने का तरीका पसंद आया था।
उन्हें विरासत में मिली स्थिति के बारे में। आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य ने लिखा कि राव का समर्थन। आरएसएस प्रमुख बालासाहेब देवरस ने राव के बारे में अच्छी बातें कही थीं।
उसे।
राव के कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान, भाजपा-विश्व हिंदू परिषद गठबंधन निष्क्रिय रहा था।
1991 के चुनावों में भाजपा द्वारा जीती गई 120 सीटों से संतुष्ट थे। लेकिन
1992 के मध्य में, वे काफी चिंतित थे। क्योंकि राव तेजी से अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे।
उनकी स्थिति। उन्होंने गंभीर आर्थिक संकट से सफलतापूर्वक निपटा था।
जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब देश को जिस संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने तुरंत ही
सोवियत संघ के विघटन के बाद एकध्रुवीय दुनिया के लिए भारत की स्थिति
दिसंबर 1991 में यूनियन में शामिल हुए। उन्होंने रणनीतिक रूप से स्थित यूनियन से संपर्क किया।
और खनिज संपदा से भरपूर मध्य एशियाई गणराज्य, उनके बनने के बाद
सोवियत संघ के पतन के बाद स्वतंत्र हुआ। (राव को यात्रा करनी थी)
1993 और 1995 के बीच पांच में से चार गणराज्य—कजाकिस्तान,
उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज़ गणराज्य।) उन्होंने एक व्यवस्था लागू की।
दक्षिणपूर्व के साथ अधिक सहयोग के लिए 1991 में 'लुक ईस्ट पॉलिसी' लागू की

गई।
एशियाई राष्ट्र। इसके तुरंत बाद, 29 जनवरी 1992 को, राव ने दूरगामी कदम उठाया।
इजराइल को मान्यता देने के चरण तक पहुँचने के बारे में पीएलए नेता यासर ने जानकारी दी।
अराफात, जो उस समय भारत में थे, ने इसकी घोषणा करने से पहले ही यह बात कही थी।
7 अगस्त 1991 को भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी, का परीक्षण किया गया था।
लॉन्च किया गया। उसी वर्ष 3 नवंबर को, त्रिशूल, अल्प दूरी की सतह-
वायु मारक क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिससे देश में गर्व की भावना का संचार हुआ।
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राव जाति बनाम संघर्ष को कम करने में सफल रहे थे।
वी.पी. के बाद धर्म संबंधी टकराव जिसने भारतीय राजनीति को ध्रुवीकृत कर दिया था।
सिंह का मंडल आयोग को लागू करने का विवादास्पद निर्णय
रिपोर्ट, और एल. के. आडवाणी की राम प्रतिमा के निर्माण के लिए रथ यात्रा
अयोध्या में मंदिर। उन्होंने वहां उत्पन्न तनाव को कम किया।
पंजाब और जम्मू-कश्मीर में, दोनों राज्यों में अलगाव की मांग जोर पकड़ रही थी—
और फिर भी चुनाव कराने में कामयाबी हासिल की गई।
फरवरी 1992 में पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बनाई।
वहाँ।
चिंतित भाजपा ने फैसला किया कि उसे राजनीतिक पहल वापस हासिल करनी होगी।
और इसने संतों को मंदिर के मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया।
साधुओं और
संत मई 1992 में उज्जैन में मिले और उन्होंने घोषणा की कि वे फिर से शुरुआत करेंगे।
उनकी कार सर्वर ने 9 जुलाई को सेवा शुरू की।

अब चिंतित राव ने अपने राजनीतिक सचिव को भेजा।
जितेंद्र प्रसाद उनसे मिलने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए जाएंगे।
उनकी योजना के साथ। प्रसादा ने प्रधान मंत्री के साथ उनकी एक बैठक तय की।
मंत्री राव ने प्रधानमंत्री आवास पर उनका स्वागत किया। जो लोग आए थे वे थे:
गोरखपुर के महंत अवैद्यनाथ, स्वामी जैसे प्रसिद्ध नाम
वामदेव, स्वामी चिन्मयानंद, और उडिपी से पेजेवार स्वामी
कर्नाटक में मठ। संतों ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे व्यक्तिगत रूप से आए थे।
उन्हें 9 जुलाई 1992 को प्रस्तावित कार सेवा के बारे में सूचित नहीं किया गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था।
मैं चाहता हूं कि वह आश्चर्यचकित हो जाए।
राव ने संतों की बातें सुनीं—लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। मौन ही उनका एकमात्र सहारा था।
राव ने जिस हथियार को निखारा था। एक बार, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह कैसे किया,
अपने ऊपर हुए इतने सारे हमलों को नाकाम करने के बाद, राव ने टिप्पणी की, 'मूनह जो बंद रखा है (क्योंकि मैंने अपना मुंह बंद रखा है)।' जब वह
वह चुप रहा, कुछ लोग उसकी चुप्पी को हां मानेंगे। अन्य
इसे ना समझो। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वह क्या चाहता था।
जैसे ही धार्मिक नेता जाने वाले थे, राव ने अपना हाथ रोक लिया।
सन्नाटा। उसके पास अपने व्यंग्यात्मक वाक्य तैयार थे। 'मैं भी निर्माण चाहता हूँ'
उन्होंने उनसे कहा, ‘मंदिर। और मैं चाहता हूं कि इस मामले का समाधान हो जाए।’ ‘मैं चाहता हूं कि यह मामला सुलझ जाए।’
जल्दी से...।'
वे आश्चर्यचकित दिखे। दुर्भाग्यवश, मामला बिगड़ चुका था।
राव ने कहा कि इसका राजनीतिकरण हो गया है। जरूरत इस बात की है कि इसमें राजनीति को शामिल न किया जाए। संतों
प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे चंद्र द्वारा छोड़ी गई बातों को आगे बढ़ाएं।
शेखर ने तब बोलना बंद कर दिया था, जब लगभग एक बड़ी सफलता मिल ही गई थी।

दोनों पक्षों के बीच अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया था।
संबंधित दावे। वीएचपी ने दिखाया था कि मस्जिद में कोई समस्या नहीं थी।
1936 से उपयोग में। अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद कार्रवाई समिति
(एआईबीएमसी) ने यह तर्क दिया था कि रामायण की कहानी
पौराणिक, ऐतिहासिक नहीं। राव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इसे ले लेंगे।
जहां चंद्र शेखर ने बात खत्म की थी, वहीं से संवाद फिर से शुरू करें।
वीएचपी और एआईबीएमसी के बीच।
राव ने संतों को इस धारणा के साथ जाने दिया कि वह सहमत हो गया था।
उनके सुझाव पर बातचीत फिर से शुरू करें। प्रधानमंत्री बस यही चाहते थे।
उस समय उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उनकी कार सेवा केवल प्रतीकात्मक ही बनी रहे।
■

टेलीफोन की घंटी इतनी तेज बजी कि हवा की हल्की-हल्की आवाज़ भी दब गई।
कंडीशनर। देवेंद्र द्विवेदी, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल।
वह घर पर अपने अध्ययन कक्ष में कुछ केस पेपरों का अध्ययन कर रहा था। काफी रात हो चुकी थी।
जून 1992 के अंत की शाम, राव के संतों से मिलने के कुछ दिनों बाद।
द्विवेदी ने अनमने ढंग से रिसीवर उठा लिया।
‘Kaho, Devendra, kaise ho (Tell me, Devendra, how are you)?’ said
the prime minister amiably. ‘Bahut din se dikhe nahin. Kya ho raha hai
(मैंने आपको कई दिनों से नहीं देखा। क्या हो रहा है?) प्रधानमंत्री
ऐसा लग रहा था मानो द्विवेदी से बात करने के लिए उनके पास दुनिया का सारा समय हो।
जो एक संवैधानिक विशेषज्ञ थे और पुराने स्कूल से संबंधित थे।

राव जैसे 'बुद्धिमान' कांग्रेसी राजनेता। एक राजनेता
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, वे कुछ समय से राज्यसभा सांसद थे।
एक दशक पहले—और राव के करीबी सलाहकार के रूप में उभरे थे।
द्विवेदी को पता था कि पीवी उसे तभी फोन करता था जब उसे किसी चीज की जरूरत होती थी।
उस दिन उसे इस बात का आभास हो गया था कि किस वजह से वह कॉल आया होगा।
उस दिन प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की थी—और वे दबाव में आ गए।
आग। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा 9 जुलाई 1992 से अपनी कार सेवा की घोषणा के साथ, राव के प्रतिद्वंद्वी
कांग्रेस में अपने हथियार निकालने शुरू हो गए थे। राव के मंत्री पद के कार्यकाल में
उनके सहयोगी अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री को साफ-साफ बता दिया था कि वह ऐसा नहीं कर रहे हैं।
अयोध्या समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त। राव ने उस वर्ष के दौरान
सत्ता में आने के बाद, अर्जुन सिंह ने उन्हें पत्र लिखना शुरू कर दिया था।
नीति के किसी न किसी पहलू में खामी, जिसकी जानकारी वह लीक कर देता था।
प्रेस। उन्होंने अपने एक तीखे पत्र की 3,000 फोटोकॉपी करवाई थीं।
और उन्होंने पार्टी नेताओं को उनकी टिप्पणी लेने के लिए भेजा। वह कोशिश कर रहा था कि
राव की नाराजगी के बावजूद, उन्होंने स्वयं को पार्टी प्रमुख की भूमिका सौंप दी।
झुंझलाहट।
मंत्रिमंडल की बैठक के एक घंटे के भीतर, उपस्थित मंत्रियों में से एक ने कहा...
उन्होंने द्विवेदी को फोन करके सारी बात बता दी थी। और इसलिए, जब
प्रधानमंत्री ने फोन किया, द्विवेदी ने उन्हें सावधान रहने को कहा।
हनीमून पीरियड खत्म हो रहा था। विश्व हिंदू परिषद की कार सेवा, राव
वह जानता था कि इससे उसकी अपनी पार्टी के भीतर ही उसके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी।
'Toh kya karna hai (So what is to be done)?' Rao asked Devendra

द्विवेदी।
द्विवेदी ने जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि आपको भाजपा से बात करनी चाहिए।'
‘Maain tumhe kal bulata hoon (I will call you tomorrow),’ Rao said,
द्विवेदी के सुझाव से प्रसन्नता जताते हुए उन्होंने कहा, 'मेरा दिन काफी व्यस्त रहने वाला है।'
लेकिन कल...आप खुद को खाली रखें।' अगले दिन, द्विवेदी ने इंतजार किया।
पूरा दिन बीत गया। लेकिन कोई कॉल नहीं आया। आखिरकार राव ने रात 8 बजे उसे फोन किया।
मैं आपके सुझाव के बारे में सोच रहा था... मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें।
राव ने कहा, 'कुछ तो बात है। भाजपा से बात करने के लिए आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं।'
प्रधानमंत्री ने कहा, 'उनके साथ अच्छे संबंध रखें।' द्विवेदी
वह भाजपा के आलोचक थे लेकिन उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे।
पार्टी के वरिष्ठ नेता।
‘ठीक है,’ द्विवेदी ने सहमति जताई।
राव ने उनसे कहा, 'आप तुरंत भाजपा नेताओं से बात करें।'
‘क्या? अभी?’ द्विवेदी ने आश्चर्य व्यक्त किया।
‘जी हां, अभी,’ प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया।
नरसिम्हा राव और एल.के. आडवाणी के बीच संबंध सहज नहीं थे।
समय। और आडवाणी, हालांकि पार्टी प्रमुख नहीं थे, सबसे शक्तिशाली थे।
भाजपा में एक प्रमुख हस्ती।
द्विवेदी ने रिसीवर नीचे रखा और आडवाणी का नंबर डायल किया।
घर पर नहीं थे। द्विवेदी ने आडवाणी की पत्नी से बात करने को कहा। कुछ देर इंतजार के बाद।
पांच मिनट बाद कमला आडवाणी लाइन पर आईं। द्विवेदी ने परिचय कराया।
उसने खुद से कहा कि वह ‘अडवानी जी से तुरंत बात करना चाहता है’।
उसने उससे अपना नंबर छोड़ने को कहा और बताया कि वह उसे सूचित कर देगी।
पति। दस मिनट बाद आडवाणी ने वापस फोन किया। वह अपने घर पर थे।

मुरली मनोहर जोशी। जोशी, जो उस समय भाजपा अध्यक्ष थे, ने भाजपा के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया था।
उस शाम सांसदों को रात्रिभोज के लिए बुलाया गया था। लेकिन 'यह 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा'।
आडवाणी ने द्विवेदी से कहा। उन्होंने कहा कि वह घर जा रहे हैं और पूछा।
द्विवेदी रात 10 बजे आएंगे।
'मुझे याद है कि मैं वहां 10.07 बजे पहुंचा था।' आडवाणी पहले से ही वहां मौजूद थे।
उसका इंतज़ार कर रहे थे। 'हमने रात 12:30 बजे तक बात की।' आडवाणी ने सुझाव दिया कि
द्विवेदी को मुरली मनोहर जोशी से भी बात करनी चाहिए। जोशी संवेदनशील थे।
पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्हें उचित सम्मान न मिलने के बारे में। द्विवेदी उनसे मिलने गए।
अगली सुबह जोशी से मुलाकात हुई। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से भी बात की।
अगले दिन द्विवेदी ने राव को फोन किया और उन्हें सारी घटना बताई।
भाजपा नेताओं के साथ उनकी बैठकों में ये बातें सामने आईं। नरसिम्हा राव
वे प्रसन्न लग रहे थे। द्विवेदी द्वारा ज़मीन तैयार किए जाने के बाद, प्रधानमंत्री ने आडवाणी और जोशी दोनों को आरसीआर में आमंत्रित किया। उन्होंने वाजपेयी से भी बात की।
तीनों ने राव को समाधान खोजने के लिए समय देने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने दोनों से बात की।
वाजपेयी और मुझे मंदिर आंदोलन के नेताओं को मनाने के लिए भेजा गया था।
आडवाणी ने पुष्टि की, 'उन्हें कुछ समय देने के लिए।' वे इस बात पर सहमत हुए कि कार
अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद द्वारा घोषित सेवा मात्र प्रतीकात्मक होनी चाहिए।
राव की यही इच्छा थी। और इसके बाद बातचीत होनी चाहिए।
योजना के अनुसार, कार सेवा 9 जुलाई को शुरू हुई, हालांकि अदालत ने
उन्होंने ऐसा ही किया। पूरी कार सेवा के दौरान, राव सभी के सम्राट बने रहे।
व्याप्त भ्रम की स्थिति में, विरोधाभासों से कुशलतापूर्वक निपटते हुए।

आधिकारिक तौर पर, केंद्र सरकार की स्थिति को इस प्रकार व्यक्त किया गया था:
गृह मंत्रालय ने कहा कि 9 जुलाई को आयोजित कार सेवा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन थी।
आदेशों का पालन किया गया। उसी समय, गृह मंत्री एस. बी. चव्हाण ने पूजा-अर्चना की।
जब वह गया तो विवादित ढांचे के अंदर बना अस्थायी मंदिर दिखाई दिया।
अयोध्या में जमीनी हालात का जायजा लिया जाएगा!
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि न तो सरकार और न ही
अदालतें मंदिर के निर्माण को रोक सकती हैं। जमीन के लिए
यह राम लल्ला की संपत्ति थी। अदालत के निषेधाज्ञा के बावजूद, कार
सेवकों ने एक स्थान पर चबूतरा (प्लेटफॉर्म) का निर्माण किया, जिसका नामकरण किया गया।
सिंहद्वार (मंदिर का द्वार) उस स्थान से कुछ ही दूरी पर है जहाँ
शिलान्यास (मंदिर की नींव रखने का समारोह) 9 तारीख को हुआ था।
नवंबर 1989, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान।
राव अदालत के स्टे ऑर्डर से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने कार को अनुमति दे दी।
सेवा बिना किसी रोक-टोक के जारी रहे। वह विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) को नाराज नहीं करना चाहता था।
और वह समय खरीदना चाहता था। वह पहले ही आडवाणी को अपने पक्ष में कर चुका था।
जोशी और वाजपेयी। अब उन्होंने वीएचपी नेता अशोक सिंघल से संपर्क साधा।
उन्होंने समाधान निकालने के लिए चार महीने का समय मांगा। अंततः, वीएचपी सहमत हो गई।
26 जुलाई को कार सेवा रोक दी गई और राव को तीन महीने का समय देने का फैसला किया गया।
समाधान खोजने के लिए। (हालांकि राव एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, लेकिन अब वे
उन्हें सावधानीपूर्वक उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकल जाए। उन्होंने आशा

जताई कि दोनों
दोनों पक्ष कम से कम अदालत के फैसले का पालन करने पर तो सहमत होंगे।
कार सेवा समाप्त होते ही द्विवेदी राव से मिलने गए। 'वह एक
वह ठंडा स्वभाव का आदमी था, लेकिन वह उठा और उसने मुझे दोनों कंधों से पकड़ लिया।
"देवेंद्र, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।" प्रधानमंत्री ने फिर पूछा, "क्या है?"
अगला कदम क्या होगा?" राव ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिया। "आप
भाजपा से बातचीत जारी रखनी चाहिए।
द्विवेदी ने पलटवार करते हुए कहा, 'मेरे पास ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए।'
विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की गई। द्विवेदी ने सुझाव दिया कि एक तरीका यह हो सकता है कि वे प्रस्तावित अयोध्या प्रकोष्ठ का नेतृत्व करें।
'हो गया,' राव ने उत्तर दिया।
फिर उन्होंने अयोध्या सेल के गठन और उसमें शामिल होने वाले लोगों के बारे में चर्चा की।
इसमें मैं, (गृह मंत्री) चव्हाण शामिल हो सकते हैं।
और नरेश चंद्र,' द्विवेदी ने सुझाव दिया, और उन्हें यह विचार पसंद आने लगा।
प्रधानमंत्री सहमत हो गए। 'मैं परसों बलिया जा रहा हूँ। मैं तब जाऊँगा जब
मैं लौट आया'।
इसके बाद के दिनों में द्विवेदी को राव से कोई जवाब नहीं मिला।
बाद में पता चलेगा कि (द्विवेदी द्वारा अयोध्या सेल का नेतृत्व करने का) विचार
प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे खारिज कर दिया था। अतिरिक्त वकील ऐसा कैसे कर सकता था?
अधिकारियों ने तर्क दिया कि भारत के जनरल, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक ऐसे सेल के प्रमुख होते हैं, जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय आता है।
क्या मंत्री सिर्फ एक सदस्य थे? कांग्रेस के भीतर ब्राह्मणों की लॉबी
जितेंद्र प्रसाद, राव के राजनीतिक सचिव सहित, के पास भी कोई जानकारी नहीं थी।
मैं द्विवेदी, जो खुद एक ब्राह्मण हैं, को शक्तिशाली बनते देखना चाहता हूँ। 'इसके बाद, द्विवेदी ने याद करते हुए बताया, 'पीवी मुझसे बचने लगा था।'

2 अगस्त 1992 को राव ने नरेश चंद्र को प्रमुख नियुक्त किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय में अयोध्या प्रकोष्ठ।
छठी
राव अक्सर अफसोस जताते हुए कहते थे, ‘मुझे अयोध्या विवाद विरासत में मिला है। यह कोई आम बात नहीं है।’
'यह मेरी ही गलती है।' लेकिन वह सारी बारीकियों से वाकिफ था।
यह लंबे समय से चला आ रहा विवाद था। राजीव गांधी ने उन्हें एक समिति का प्रमुख बनाया था।
उन्होंने अयोध्या पर सलाह देने के लिए 1987 में गठित मंत्रियों की समिति का गठन किया था।
इस नाटक में कई उतार-चढ़ाव आए—जिसमें घटी हुई गड़बड़ी भी शामिल है।
1986 में जब राजीव ने मस्जिद का ताला खुलवाया था, और उनसे हुई बड़ी गलती।
1989 में जब उन्होंने वीएचपी को 'शिलान्यास' करने और ज़मीन बिछाने की अनुमति दी थी।
अयोध्या में मंदिर की नींव का पत्थर।
राव ने अयोध्या प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने के लिए स्थापित करने का निर्णय लिया।
गृह मंत्रालय के अधीन रहकर मंदिर के मुद्दे पर सीधा नियंत्रण बनाए रखें।
इस समिति में गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।
मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था।
उनके बीच समन्वय स्थापित करना। इसमें इन तीनों से संयुक्त सचिव थे।
विभागों—गृह विभाग से विनोद ढाल, विधि विभाग से एस.सी. जैन, और
प्रधानमंत्री कार्यालय से निशिकांत सिन्हा।
नरेश चंद्र को प्रधानमंत्री का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया था।
मंत्री। 'मैं आधिकारिक तौर पर सरकार का सचिव नहीं था।'
न तो भारत, न ही अयोध्या प्रकोष्ठ का सचिव, न ही प्रधानमंत्री कार्यालय का सचिव
चंद्र ने राव की चतुराई को याद करते हुए हँसी से चेहरा बिगाड़ते हुए मुझसे कहा, 'मंत्री।' उन्हें मंत्री के समकक्ष पद दिया गया था।

मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार में सबसे वरिष्ठ अधिकारी।
ताकि उनकी बात को नजरअंदाज न किया जा सके। 'जिस तरह से उन्होंने पोस्ट को डिजाइन किया,
और यह राव के काम करने के तरीके का एक विशिष्ट उदाहरण था, मैं उस सेल का प्रमुख था लेकिन
चंद्र ने कहा, 'उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जा सका।' इसीलिए
राव द्वारा 16 दिसंबर 1992 को स्थापित लिबरहान आयोग का उद्देश्य समस्याओं को ठीक करना था।
विध्वंस की जिम्मेदारी के लिए 'मुझे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता था'।
अगर कोई ऐसा अधिकारी था जो राव का करीबी माना जाता था और उनकी बातों से वाकिफ था
मुझे लगा कि यह नरेश चंद्र है। चंद्र ने सभी महत्वपूर्ण पदों को संभाला था।
भारत सरकार में पद— मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव
रक्षा सचिव। लंबा, गठीला और हंसमुख, उनका
मिलनसार बाहरी व्यक्तित्व के पीछे छिपी कठोरता थी। जरूरत पड़ने पर वह सचमुच बहुत सख्त हो सकता था।
उसने ऐसे निर्णय लेने शुरू कर दिए जिन्हें वह 'व्यापक हित' में मानता था।
'राष्ट्रीय हित'। क्रमिक प्रधानमंत्रियों ने उनकी सेवाओं का उपयोग किया था।
असाधारण परिस्थितियों में भी वे अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। वे राजनीतिक रूप से भी काफी तेज थे।
और विवेकपूर्ण।
राव ने चंद्र को विवाद से संबंधित सभी कागजात इकट्ठा करने को कहा और
पूर्व द्वारा आयोजित वार्ताओं से संबंधित अभिलेखों को प्रमाणित करें
सरकारें। चंद्रा पर राव को न केवल भरोसा था, बल्कि वह एक जीवित
अयोध्या पर विश्वकोश, उपराष्ट्रपति के समय गृह सचिव के पद पर रहते हुए।
सिंह प्रधानमंत्री थे और एल.के. आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा निकाली थी।
और जब दो राज्यपालों द्वारा गंभीर प्रयास किए गए, कृष्णकांत
और यूनुस सलीम ने अयोध्या गतिरोध को तोड़ने के लिए चंद्र का साथ दिया। चंद्र थे
चंद्र शेखर के प्रधानमंत्री रहते हुए कैबिनेट सचिव और बस कुछ ही पलों का अंतर था।

एक बड़ी सफलता से।
अजीब बात यह है कि राव ने न तो कृष्णकांत से पूछा और न ही चंद्र से।
शेखर—जिनके दोनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे—ने इस बारे में पूछा कि उनके प्रयासों से कोई परिणाम नहीं निकला था। 'मेरे उत्तराधिकारियों में से किसी ने भी बात नहीं की थी।'
'मुझे अयोध्या में मैंने जो किया था, उसके बारे में पांच मिनट के लिए भी मत बताना,' दुखी चंद्र शेखर ने एक बार मुझसे कहा था।
राव के साथ अपने अच्छे संबंधों को देखते हुए, कृष्णकांत ने सोचा कि राव
वे अयोध्या मामले में उनकी मदद मांग सकते हैं। विशेषकर राव और कांत के संदर्भ में —वे
राव के प्रधानमंत्री रहते हुए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पर भी यही स्थिति थी।
शिवानंद मूर्ति, जो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और गुरु बन चुके हैं, ने भी गुरु की भूमिका निभाई है।
पच्चीस वर्ष की आयु में अध्यात्मवाद। मूर्ति ने भविष्यवाणी की थी कि राव
प्रधानमंत्री बनेंगे—और भविष्यवाणी की थी कि कांट
घटना घटने से एक साल पहले ही वह उपराष्ट्रपति बन गए थे।
राव ने एक बार पूछा था, 'गुरुजी, बाबरी मस्जिद का क्या होगा?'
शिवानंद मूर्ति। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वे खुलेआम संबोधित करते थे।
मूर्ति को 'गुरुजी' कहकर पुकारें, साल में दो बार उनके आश्रम में उनसे मिलने जाएं।
विशाखापत्तनम में उनके साथ हिंदू धर्म के बारे में घंटों बातें करना।
विचार और दर्शन।
बाबरी मस्जिद के भविष्य के बारे में राव का सवाल सुनकर, मूर्ति
उसने कुछ मिनटों के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं। फिर उसने जवाब दिया, 'मुझे वह वहाँ नहीं दिख रहा है।'
इससे राव बहुत प्रभावित हुए—और इससे उनके अंधविश्वास का पहलू भी उजागर हुआ।
उनके व्यक्तित्व के बारे में। 'तब से, मुझे लगता है कि उनके अंदर कहीं न कहीं, वह
एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया, 'हमने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाएगा।'

एक सरकारी अधिकारी जिसने आंध्र प्रदेश में कई साल बिताए, और
मैं शिवानंद मूर्ति को अच्छी तरह जानता था।
■

जब राव ने अगस्त 1992 में अयोध्या सेल का गठन किया, तो वे 'वहां गए और'
नरेश चंद्र के साथ 'फिर से' लंबी यात्रा में प्रमुख मील के पत्थर हैं।
संघर्ष का इतिहास।
बाबरी मस्जिद के बारे में बुनियादी तथ्य और विवाद
इसके आसपास की बातें सर्वविदित हैं। मैं संक्षेप में ही उनका उल्लेख करूंगा।
इस मस्जिद का निर्माण मुगल सेनापति मीर बाकी ने 1528 में करवाया था।
सम्राट बाबर के आदेशों पर। इसी पर मुसलमानों का दावा आधारित था।
संरचना। हिंदुओं के लिए, अयोध्या पवित्र थी क्योंकि उनका मानना था कि यह
भगवान राम की जन्मभूमि। उनमें से कई लोगों का मानना था कि मस्जिद
उस स्थान पर निर्माण किया गया जहाँ पहले एक मंदिर स्थित था। इसके कारण एक दीर्घकालिक विवाद उत्पन्न हुआ।
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संरचना को लेकर विवाद।
उन्नीसवीं शताब्दी में दोनों समुदायों के बीच कुछ झड़पें हुईं।
सदी। 1885 तक, संरचना के बाहरी हिस्से को परिवर्तित कर दिया गया था।
हिंदू पूजा स्थलों में। इसमें एक 'राम चबूतरा' भी शामिल था जहाँ एक
भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई; संरचना का भीतरी भाग अपरिवर्तित रहा।
यह मस्जिद वह स्थान है जहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं। 1934 में, हिंदू दंगाइयों ने
मस्जिद के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था; अंग्रेजों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया।
1934 में, हिंदू प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि मुसलमान अब पूजा-अर्चना नहीं करते हैं।
मस्जिद होने का दावा—जिसका मुसलमानों ने तुरंत खंडन किया।
दिसंबर 1949 में मस्जिद को 'विवादित' घोषित किया गया था।

फैजाबाद की अदालत ने राम लल्ला की मूर्ति को 'संरचना' घोषित कर दिया था।
इसे गुप्त रूप से मंदिर के गर्भगृह में ले जाया गया था। यह अयोध्या की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की है।
क्योंकि दशकों से सभी जलधाराएँ गंगोत्री से ही प्रवाहित होती आ रही थीं।
इसके बाद जो कुछ हुआ। राव ने इस घटना का बारीकी से अध्ययन किया था, विशेष रूप से
1949 की स्थिति और उनके सामने आने वाली स्थिति के बीच समानताएं
1992.
इसके पीछे की राजनीति ने उन्हें और भी अधिक आकर्षित किया—यह खींचतान
कांग्रेस में प्रतिनिधित्व करने वाले परंपरावादी हिंदू मत के बीच
by Govind Ballabh Pant and Sardar Vallabhbhai Patel on the one side
और धर्मनिरपेक्षता को लेकर नेहरू पार्टी को जो प्रोत्साहन देना चाहते थे,
दूसरी ओर।
1949 की घटना 22 दिसंबर की आधी रात को घटी थी।
आधी रात होने ही वाली थी, और मस्जिद के आसपास घना अंधेरा था।
आश्चर्यजनक रूप से, वह क्षेत्र सुनसान था और तीनों गुंबदों की रूपरेखा दिखाई दे रही थी।
मुश्किल से दिखाई दे रहा था। सरयू नदी की धीमी कलकल ध्वनि सुनाई दे रही थी।
रात के सन्नाटे में एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे लोगों का एक समूह चुपके से आगे बढ़ रहा हो।
वे इमारत की ओर जा रहे थे। वे पहले ही गार्ड को अपने साथ ले आए थे।
ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उनका कोई विरोध नहीं किया। उन्हें मस्जिद में प्रवेश करना पड़ा।
आधी रात से पहले जब पहरेदारों की अदला-बदली हुई। घुसपैठिए
उसने दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया। बाहरी परिसर में कई
कुछ छोटे मंदिरों सहित संरचनाएं। भीतरी परिसर
मस्जिद वहीं स्थित थी। अंदर पहुँचने पर उन्होंने राम लल्ला की मूर्ति ले ली।
वे इसे अपने साथ ले गए थे और इसे केंद्रीय गुंबद के नीचे रख दिया था।

मस्जिद। और वे भोर होने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने पहली मस्जिद देखी।
प्रकाश की एक झलक देखकर, उन्होंने मूर्ति के सामने एक दीपक जलाया और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया।
वे जो घंटियाँ, झांझ और शंख लाए थे, उनकी झंकार के लिए प्रार्थनाएँ।
उनके साथ।
बहुत जल्द ही यह खबर फैल गई कि राम लल्ला चमत्कारिक रूप से जीवित हो गए हैं।
manifested himself within the mosque—'Bhaya prakat kripala Deen
दयाला (भगवान ने स्वयं को प्रकट किया है)। भक्त इकट्ठा होने लगे।
वहां प्रार्थना करने के लिए।
इस 'चमत्कार' की कहानी को बनने में कुछ महीने लगे थे।
हिंदू धर्म द्वारा गठित अखिल भारतीय रामायण महासभा
महासभा, जो भारतीय जनसंघ की पूर्ववर्ती संस्था थी और
भारतीय जनता पार्टी ने राम लल्ला की एक मूर्ति स्थापित की थी।
मस्जिद के बाहर बने चबूतरे पर मूर्ति को स्थानांतरित करने के लिए प्रार्थनाएं आयोजित की गईं।
मस्जिद के अंदर, जिसे वे चमत्कार मान रहे थे। लेकिन तीन हफ्तों तक कोई चमत्कार नहीं हुआ—जब तक कि 22 दिसंबर की रात नहीं आ गई।
1949.
यह बात इतनी प्रसिद्ध नहीं है कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता नानाजी देशमुख और
1977 तक भारतीय जनसंघ के शीर्ष तीन संगठनों में गिने जाने वाले संगठन।
वाजपेयी और आडवाणी के साथ, वह उस समूह का हिस्सा थे जो
22 दिसंबर को राम लल्ला की मूर्ति को बाबरी मस्जिद में तस्करी करके लाया गया।
1949. कई वर्षों तक, आरएसएस अपने इस खुलासे को लेकर संशय में रहा था।
1949 की घटना में संलिप्तता।
एक दिन मैं दीन दयाल चर्च में नानाजी देशमुख से मिलने गया था।
Shodh Sansthan where he used to sit as its adhyaksh (president),' Ram

वरिष्ठ पत्रकार बहादुर राय ने मुझे बताया, “उस दिन, उन्होंने बात करना शुरू किया।”
अयोध्या में घटी घटनाओं के बारे में।
नानाजी का मूड काफी खुशनुमा था। उन्होंने बताया कि वे
वह समूह जो उस रात मूर्ति स्थापित करने के लिए मस्जिद गया था।
Besides himself, the group, according to Nanaji, included ‘Abhiram
Das, Bhaiji Hanuman Prasad Poddar, Mahant Ramchandra Paramhans, and Shakuntala Nair’.
‘मैं इस योजना का हिस्सा था,’ नानाजी ने राय से कहा। ‘और यह सब हनुमान जी की वजह से हुआ।’
प्रसाद पोद्दार की योजना।’ प्रचलित धारणाओं का खंडन करते हुए
चालीस वर्षों से चली आ रही निराशा के बाद, नानाजी को लगा कि उस दिन कोई चमत्कार हुआ था।
Deshmukh told Rai, ‘Sach yeh hai ki murtiyo ko Sarayu mein vidhivar
snaan karaya gaya. Unki puja archana hui, aur raat ko Abhiram Das
murtiyon ko sar par rakh kar le gaye …Shakuntala Nair ne unse apne
सिर पर लेकर रखा (सच तो यह है कि मूर्ति को सरयू नदी में ले जाया गया था)
नदी में स्नान किया, प्रार्थनाओं का जाप करते हुए तैयारी की, और फिर
रात में अभिराम दास ने उसे अपने सिर पर रखा और ले लिया…फिर
शकुंतला नायर (जिला मजिस्ट्रेट के.के.के. नायर की पत्नी) ने
उसने मूर्ति को अपने सिर पर रख लिया...
‘(Unhone) Vistar se varnan kiya,’ Ram Bahadur Rai said. ‘Yeh log
aaye, murtiyan stapith ki. Raat me gayae (He told me in great detail,
वे वहाँ कैसे गए थे और मूर्ति कैसे स्थापित की थी)। और यह 5 पर पाया गया।

पूर्वाह्न।'
■

यह खबर दिल्ली में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। उन्होंने आदेश दिया।
कि मूर्तियों को तुरंत हटा दिया जाए और मस्जिद को उसके पुराने स्वरूप में बहाल किया जाए। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने यह बात कही।
नेहरू के दबाव में आकर तुरंत कार्रवाई की गई। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ।
होना।
स्थानीय अदालत में, के. के. के. नायर, जो जिला मजिस्ट्रेट थे
फैजाबाद और जिले के शीर्ष नौकरशाह, इस मामले में सहानुभूति रखते थे।
हिंदू महासभा। उन्होंने स्थिति को इस तरह से संभाला कि
नेहरू के निर्देशों की अवहेलना की गई।
नायर ने लखनऊ में अपने वरिष्ठों को बताया कि यह मुद्दा भावनात्मक था।
एक ऐसा मामला जिसमें हजारों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ऐसा होना ही था।
इसे सावधानीपूर्वक निपटाया जाना चाहिए। अन्यथा इसके कानून-व्यवस्था पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
23 दिसंबर 1949 को, इस मामले की जांच के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई।
इस मामले में अभिराम दास और लगभग साठ अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया था।
मस्जिद में अवैध प्रवेश के कारण। हिंदू मस्जिद की स्थापना के साथ
मूर्ति के कारण, मस्जिद एक 'विवादित संरचना' बन गई थी। शहर
नायर के अधीन कार्यरत मजिस्ट्रेट गुरु दत्त सिंह ने 'अटैच' कर दिया।
संरचना तैयार की और एक रिसीवर नियुक्त किया।
फैजाबाद अदालत ने 16 जनवरी 1950 को आदेश दिया कि हिंदू ऐसा कर सकते हैं
बंद दरवाजों के पीछे से राम लल्ला की पूजा करना संभव नहीं था।
किसी के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति होने के कारण,

मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो,
वह ढांचा अब मस्जिद नहीं रहा।
हिंदू महासभा द्वारा आधी रात को नियोजित प्रवेश एक घटना के बाद हुआ।
यह प्रस्ताव चार महीने पहले पारित किया गया था। 14 अगस्त 1949 को, इसने
उन्होंने उन सभी मंदिरों को मुक्त कराने की कसम खाई जहां मुसलमानों ने मस्जिदें
बना रखी थीं।
—including the Ram Janmabhoomi in Ayodhya, the Vishwanath
Temple in Kashi, and the Krishna Janmasthan in Mathura.
■

हिंदू महासभा को इस तनावपूर्ण स्थिति से और भी अधिक हौसला मिला था।
देश के विभाजन के बाद व्याप्त सांप्रदायिक माहौल में
1947. 1948 में अयोध्या में हुए उपचुनाव के परिणाम ने भी यही संकेत दिया था।
महासभा का नया हृदय। प्रजा समाजवादी पार्टी, जो पहले
1934 में अपनी स्थापना के बाद से कांग्रेस का हिस्सा रहे, उन्होंने 1948 में इसे छोड़
दिया था।
नेता आचार्य नरेंद्र देव ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण उपचुनाव की
आवश्यकता पड़ी।
चुनाव। हालाँकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, नेहरू चाहते थे कि वे चुनाव लड़ें।
प्रधानमंत्री की सहमति से उनके वामपंथी, प्रगतिशील विचारों को देखते हुए, कांग्रेस ने
पहले एक ऐसे उम्मीदवार का चयन किया था जो केवल मामूली चुनावी चंदा ही दे
सकता था।
नरेंद्र देव के खिलाफ नाममात्र की लड़ाई। लेकिन उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रांत)
समय) सीएम गोविंद बल्लभ पंत हिंदू भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं।
chose Baba Raghav Das to contest against Narendra Dev. Das, a
पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक घोषित गांधीवादी और साधु ने एक 'सांप्रदायिक' आंदोलन का

नेतृत्व किया।
देव के खिलाफ तीखा हमला—और विशेष रूप से रूढ़िवादी लोगों को आकर्षित किया
उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान हिंदुओं को तुलसी के पत्ते भी बांटे।
लोगों को आकर्षित किया—और इसे जी. बी. पंत का पूरा समर्थन प्राप्त था। पंत के लिए, यह था
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का एक अवसर—और
नरेंद्र देव को हाशिये पर धकेलना, जो उत्तर प्रदेश में उनके प्रतिद्वंदी थे और जिन्हें
नेहरू का विश्वास।
हिंदू महासभा और महंत दिग्विजय जैसे उसके नेताओं के लिए
गोरखपुर के गोरखपुरपीठ के प्रमुख रहे नाथ ने रस्साकशी में भाग लिया।
कांग्रेस के भीतर उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर था।
एजेंडा। संदिग्ध संलिप्तता के बाद वे कुछ समय से छिपे हुए थे।
जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या। उन्होंने फैसला किया कि
हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए बाबरी मस्जिद में राम लल्ला की प्रतिमा स्थापित करना।
उनका पक्ष लेने के लिए—और इसे चुपके से करो ताकि वे न आ सकें
सीधे सरकार के निशाने पर।
राघव दास ने आचार्य नरेंद्र देव को हराया और एक महान व्यक्तित्व बन गए।
killer. Mahant Digvijay Nath exulted afterwards that ‘the Congress
नेताओं को मतदाताओं की हिंदू भावनाओं को अपील करना था।
नेहरू के शासनकाल में गृह मंत्री सरदार पटेल की मजबूत उपस्थिति थी।
government, backed Govind Ballabh Pant. Pant regarded Sardar Patel
अपने नेता के रूप में। हालाँकि दुखी नेहरू ने पंत को लिखा था।
बार-बार अनुरोध करने के बावजूद और यहां तक कि स्वयं अयोध्या जाने की पेशकश करने के बावजूद, अंततः उनका आदेश स्वीकार कर लिया गया।
चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस में रूढ़िवादी हिंदू मत के कारण
विजयी हुआ।

दिसंबर 1949 में जो कुछ हुआ, वह हिंदू बनाम
कांग्रेस के भीतर धर्मनिरपेक्षता की दुविधा जो सामने आने वाली थी
इसके बाद के वर्षों में समय-समय पर, नेहरू ने इस पर जोर न देने का विकल्प चुना।
1949 में अपनी बात मनवाने के लिए उसने एक हद पार कर दी। वह सत्ता पर मज़बूत पकड़ बनाने में कामयाब रहा।
पार्टी का गठन सरदार पटेल की मृत्यु के बाद दिसंबर 1950 में ही हुआ था।
■

1948-49 और 1991-92 के बीच कई समानताएं थीं, जो
राव को इनमें दिलचस्पी थी—और उन्होंने नरेश चंद्र के साथ इन पर चर्चा की।
दोनों ही मौकों पर, कांग्रेस के भीतर की खींचतान ने ही प्रभाव डाला।
मंदिर मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख। 1949 में, यह स्थिति थी।
हिंदू हितों के प्रति सहानुभूति रखने वाली पंत-पटेल की जोड़ी, जो हिंदू हितों के खिलाफ खड़ी थी,
'धर्मनिरपेक्ष' नेहरू। 1992 में राव और अर्जुन के बीच गतिरोध उत्पन्न हुआ था।
सिंह, धर्मनिरपेक्षता को हथियार बनाकर दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं।
राव ने उन पर नरम हिंदुत्व का रुख अपनाने का आरोप लगाया। यह एक मामला है।
यह बात दिलचस्प है कि दोनों मौकों पर 'धर्मनिरपेक्षवादियों' को हार का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद कि
स्वतंत्रता के बाद नेहरू का प्रभाव। दूसरी ओर, राव का प्रभाव...
1992 में वह एक अस्थिर अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व कर रहे थे।
1949 की तरह ही 1992 में भी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने
दंगाइयों को मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ करते देख मैं असहाय होकर देखता रहा।
कानून। दोनों ही मौकों पर कांग्रेस सरकारें सत्ता में थीं और
निर्णायक कार्रवाई करने में स्पष्ट अनिच्छा दिखाई दी। दोनों ही मामलों में, भीड़ ने अधिकारियों पर भारी पड़ गया। और, दोनों ही मामलों में, जिम्मेदारी
क्योंकि इस अराजकता का दोष किसी पर भी नहीं लगाया जा सकता था—न ही किसी दोषी पर।

दंडित किया गया। दोनों ही बार भारतीय राज्य की सत्ता चकनाचूर हो गई।
1949 और 1992 दोनों ही पूर्व नियोजित थे। 1949 में छल-कपट का प्रयोग किया गया था।
इसके अलावा 1992 में—1949 में, राम की एक मूर्ति को चुपके से बाबरी किले में तस्करी करके लाया गया था।
मस्जिद; 1992 में, इस आश्वासन के बावजूद कि मस्जिद नहीं होगी
नुकसान होने के बावजूद, कल्याण सिंह ने विध्वंस की अनुमति दे दी।
सातवीं

अयोध्या विवाद जितना देश को ध्रुवीकृत करने वाला विवाद पहले कभी नहीं हुआ था।
अयोध्या को लेकर अदालती मुकदमे सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण थे।
स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबी कानूनी लड़ाई—वह भी सिर्फ एक मामूली बात पर।
1,500 वर्ग गज की भूमि। इसने तीन वर्षों तक भारत की राजनीति को आकार दिया।
दशकों बीत चुके हैं, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हालाँकि एक राम मंदिर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उस जगह पर एक नई इमारत बनेगी जहाँ कभी मस्जिद हुआ करती थी।
2019 के फैसले के बाद, इन स्थलों को 'मुक्त' करने की मांगें फिर से उठाई जा रही हैं।
मथुरा और वाराणसी, जहाँ मंदिर मस्जिदों के बगल में स्थित हैं। इससे पहले मैं
दिसंबर 1992 की घटनाओं और उससे पहले की परिस्थितियों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें।
यह जानना उपयोगी होगा कि अदालतों ने इस मुद्दे से कैसे निपटा। और
यह देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि मध्यस्थता के प्रयास क्यों विफल रहे।
संकट विफल रहा। उन्होंने वह पृष्ठभूमि तैयार की जिसके आधार पर नरसिम्हा राव ने अपनी कला का परिचय दिया।
उसे अपने फैसले लेने थे।
बाबरी मस्जिद को लेकर पहला कानूनी मुकदमा महंत ने दायर किया था।
1885 में रघुबीर दास ने अदालत से अपील की कि उन्हें अनुमति दी जाए।

राम चबूतरे पर, बाहरी परिसर में एक राम मंदिर का निर्माण करें।
मस्जिद। अदालत ने इस आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी कि यह
मंदिर का इतने करीब होना कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर देगा।
मस्जिद। राम लल्ला की मूर्ति को गुपचुप तरीके से मस्जिद के अंदर स्थापित करने के बाद...
22 दिसंबर 1949 की रात को मस्जिद पर ताले लगा दिए गए थे।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा संरचना। संक्षेप में
इसके बाद, जनवरी 1950 में, अदालत ने आदेश दिया कि मूर्ति को नहीं रखा जा सकता।
इसे हटा दिया गया और पूजा द्वार के बाहर से करने की अनुमति दी जा सकती थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1955 में इस आदेश की पुष्टि की। 1959 में,
निर्मोही अखाड़ा ने विवादित संपत्ति के स्वामित्व के लिए 'स्वामित्व का मुकदमा' दायर किया।
भूमि। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी 1961 में ऐसा ही किया, और भूमि को हटाने की मांग की।
मूर्ति। तब तक मुस्लिम समुदाय ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था।
जो कुछ घट रहा था उसमें रुचि।
1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने आदेश पारित किया।
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के ताले खोलने के लिए (जैसा कि
हमने अध्याय 2 में देखा था)। हिंदू अब विवादित स्थल पर पूजा कर सकते थे।
इस संरचना ने मुसलमानों की ओर से प्रतिक्रिया उत्पन्न की; उन्होंने एक
1987 में प्रतिष्ठित मुसलमानों की अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद कार्रवाई समिति का गठन किया गया था।
मस्जिद की सुरक्षा के लिए—और पूरे उत्तरी आयरलैंड में विरोध रैलियां आयोजित कीं।
भारत। इसने हिंदुओं के बीच एक प्रतिप्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिससे तनाव और गहरा गया।
सांप्रदायिक विभाजन। 1989 में, पांच मूल स्वामित्व मुकदमे, जो थे

तब तक साइट के स्वामित्व को चुनौती देने वाले सभी मामले समेकित कर दिए गए थे।
और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि उन पर विचार किया जा सके।
एक साथ ले जाया गया।
स्वामित्व तय करने के लिए चल रहे मुकदमे के अलावा
अयोध्या में विवादित भूमि के मामले में, अदालतें एक बार फिर से सक्रिय हो गईं।
कल्याण सिंह ने जून 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला और यह प्रतिज्ञा की कि वे
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना। उन्होंने 2.77 एकड़ जमीन अधिग्रहित की।
मस्जिद के आसपास की विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया और इमारतों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया।
उस पर मंदिर के निर्माण की तैयारी में लोग खड़े थे। जबकि
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल्याण सिंह सरकार को अनुमति दी।
मस्जिद के आसपास की जमीन का अधिग्रहण करें और उस पर बनी इमारतों को ध्वस्त कर दें,
इस पर स्थायी संरचनाओं के निर्माण पर रोक लगा दी गई।
तब तक राव प्रधानमंत्री बन चुके थे।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और विभिन्न संतों ने घोषणा की कि कार सेवा का आयोजन किया जाएगा।
9 जुलाई 1992 को उस स्थान पर यह घटना घटी। सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया।
23 जुलाई 1992 को उनके कार्यों को चुनौती देते हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके फैसले को बरकरार रखा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला—कि किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि नहीं की जा सकती
किसी भी प्रकार का आयोजन उस भूमि पर नहीं होना चाहिए जिसे अधिग्रहित किया गया था
कल्याण सिंह। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इस मामले पर फैसला करना होगा।

उत्तर प्रदेश द्वारा अधिग्रहित 2.77 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की वैधता
सरकार। (हालांकि 2.77 एकड़ का आंकड़ा अक्सर उल्लेख किया जाता है)
विवादित स्थल का जिक्र करते हुए, वास्तविक क्षेत्रफल केवल 1,500 वर्ग मीटर था।
गज या 0.309 एकड़ (जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजित किया गया है)।
1992 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम निर्णायक बिंदु था।
कानूनी तौर पर—जब राव को बढ़ते संकट से निपटना पड़ा। (इसके बाद)
मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, अदालतों में लड़ाई 2019 तक जारी रही।
जब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इसके लिए अपनी मंजूरी देने का फैसला किया
(वह मंदिर जहाँ कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी।)
■

अयोध्या विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का पहला गंभीर प्रयास था
दो राज्यपालों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया - कृष्णकांत (आंध्र प्रदेश के राज्यपाल)
प्रदेश) और यूनुस सलीम (बिहार के), एक हिंदू और दूसरा भारतीय
मुस्लिम। यह घटना वी. पी. सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 1989-90 में हुई थी।
कांत और सलीम ने उपराष्ट्रपति के सत्ता में आने से पहले ही पहल कर दी थी।
उन्होंने अपने कार्यों के बारे में उपराष्ट्रपति को सूचित किया और उन्होंने इसका समर्थन किया।
उनके प्रयासों के बारे में। सलीम ने मुझे बताया कि वह कृष्णकांत से मिलने गया था।
लखनऊ में भड़की भीषण सांप्रदायिक हिंसा के बाद,
मेरठ, मलियाना और हाशिमपुरा—के खुलने के बाद
फरवरी में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे पर लगे ताले
1986.
मैं टेलीग्राफ लेन स्थित कृष्णकांत के घर उनसे मिलने गया था।
सलीम ने बताया। वे दोस्त थे और एक ही पार्टी के सदस्य थे।
जनता दल। 'हालात बिगड़ रहे हैं, क्या आप कुछ कर सकते हैं?'

दुखी सलीम ने कांट से पूछा। कुछ दिनों बाद कांट ने सलीम को फोन किया।
'मैंने कांची (कांची कामकोटि) के शंकराचार्य से संपर्क किया है
पीठम, कांचीपुरम, तमिलनाडु), जयेंद्र सरस्वती। वह है
बात करने को तैयार है। लेकिन उसने एक शर्त रखी है—कि दो लोग आपस में बात नहीं करेंगे।
(इस प्रयास में) (सैयद) शहाबुद्दीन और इमाम बुखारी को शामिल किया जाए। मैंने वार्ता के लिए आपका और अली मियां का नाम सुझाया है।' जैसा कि हम
मैंने देखा है कि अली मियां, एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान, एआईएमपीएलबी के प्रमुख थे।
शुरू में तो वह अनिच्छुक था, लेकिन अंततः वह इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो गया।
और उन्होंने अपने शिष्य अब्दुल करीम पारिख को भी इस प्रयास में शामिल किया। धूर्त
पारिख एक व्यवसायी, व्यावहारिक व्यक्ति और नागपुर निवासी थे, जिनके अच्छे संबंध थे।
वहां आरएसएस के नेतृत्व के साथ। 'आप उनसे एक बैठक तय करें।'
'हम शंकरचार्य के पास साथ जाएंगे,' अली मियां ने कांत से कहा।
और सलीम।
इस समय तक कृष्णकांत और यूनुस सलीम नियुक्त हो चुके थे।
क्रमशः आंध्र प्रदेश और बिहार के राज्यपाल। राज्यपाल के रूप में,
उनकी आवाजाही प्रतिबंधित थी। वे बिना अनुमति के यात्रा नहीं कर सकते थे।
राष्ट्रपति की अनुमति। 'अगर हम मद्रास में मिलने जाते तो...'
राष्ट्रपति को यह जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि कांची के शंकराचार्य क्या सोच रहे थे।
हम यही कर रहे थे।' कांट ने अध्यक्ष आर. वेंकटरमन को साथ लेने का फैसला किया।
विश्वास में लाना। कांट ने कहा, 'मैंने उसे सब कुछ बता दिया।' 'यदि आप सफल होते हैं तो...'
राष्ट्रपति ने उनसे कहा, ‘यह समझौता करवा सकता है, यह करवाएगा।’
यह इस सदी की सबसे बड़ी घटना होगी, यहाँ तक कि स्वतंत्रता से भी बड़ी।
भारत।'

कृष्णकांत ने कांची के शंकराचार्य को 'कम से कम एक दर्जन बार' देखा था।
इसके बाद के हफ्तों में टाइम्स में। 19 मार्च 1990 को, कांत, सलीम,
उनके एडीसी, और अली मियां, अब्दुल करीम पारिख, और अली मियां के
निजी सेवक अब्दुल रजाक चेन्नई गए। वहाँ, वे
दो शंकराचार्यों, जयेंद्र सरस्वती और विजयेंद्र से मुलाकात की
सरस्वती। दूसरे अवसर पर, उनके बेटे जुनैद और रश्मी भी।
उनके साथ गए।
अली मियां ने अपनी सात खंडों वाली रचना में इन प्रयासों का उल्लेख किया है।
संस्मरण, कारवां-ए-ज़िंदगी, जिसका यूनुस सलीम ने अनुवाद किया
निम्नलिखित अंश: 'जब मोहम्मद यूनुस सलीम और कृष्ण
कांत ने मुझसे मुलाकात की और मुझे बताया कि शंकराचार्यों, वरिष्ठों
और कनिष्ठ सदस्य मदद करने और किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार हैं।
ऐसा उपाय जिससे स्थिति को संभाला जा सके और मस्जिद को बचाया जा सके
और मंदिर का निर्माण दूर किया जा सकता है... मैं सहमत हो गया।
चर्चा में भाग लें।
अली मियां ने तीन शर्तें रखीं—कि वार्ता नहीं होगी
इसे औपचारिक माना जाता था; वह स्वयं किसी भी समाधान पर हस्ताक्षर नहीं करता
था;
और वह अपने सहयोगी अब्दुल के साथ शंकराचार्य से मिलने आता था।
Karim Parikh.
दो शंकराचार्यों के अलावा, समूह ने वरिष्ठ अधिकारी से भी मुलाकात की।
कांची मठ के प्रमुख, परमचार्य। 'मुझे याद है कि वह झूठ बोल रहे थे।'
कांट ने याद करते हुए कहा, 'वह सीमेंट के चबूतरे पर सिकुड़कर बैठा था। उसने कुछ
नहीं कहा।'
सलीम ने कहा, 'उन्होंने सिर्फ सहमति में सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं किया।'
'मुझे वह याद है।'
सिर हिलाते हुए।
शंकराचार्य और अली मियां ने इसका विस्तार करने का निर्णय लिया।
इस चर्चा में दोनों समुदायों के अधिक से अधिक धार्मिक प्रमुखों को शामिल किया

जाए।
उन्होंने 'मुस्लिम धर्मगुरुओं' और 'हिंदू संतों' को बुलाया
बातचीत की मेज। अली मियां की सलाह पर, चालीस मुस्लिम विद्वानों ने
भारत के सभी हिस्सों से लोग बिहार भवन आए। इसी प्रकार, हिंदू संत भी आए।
आंध्र भवन में दोनों राज्यपाल एकत्रित हुए थे। दोनों राज्यपालों ने उत्साह व्यक्त किया कि
वे प्रगति कर रहे थे।
सम्मेलन में दोनों पक्षों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
दिल्ली स्थित आंध्र भवन के कमरे में। उन्होंने तय किया कि इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए।
शांतिपूर्वक निर्णय लिया जाए; कि मस्जिद में कोई व्यवधान न हो और न ही
क्या मंदिर निर्माण के प्रयासों को रोका जाएगा; कि एक कार सेवा, जो
यह आयोजन 30 अक्टूबर को होने वाला था और 2 नवंबर 1990 को होगा।
योजना के अनुसार शांतिपूर्वक आयोजित किया गया; कि एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा
अली मियां के नामित व्यक्ति और शंकराचार्यों में से एक, और एक
भारत सरकार के प्रतिनिधि। और यह कि
शंकराचार्य और अली मियां संयुक्त रूप से समाधान की घोषणा करेंगे।
लेकिन अचानक ही हालात बिगड़ने लगे।
सफलता के कगार पर पहुँचते ही वार्ता में बाधा उत्पन्न कर दी गई।
गृह मंत्रालय से जानकारी लीक हुई थी। शंकराचार्य ने यह सूचना दी।
कृष्णकांत ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल उनसे मिलने आए थे।
सिंघल ने उन्हें बताया था कि सुबोध कांत सहाय—जो उस समय राज्य मंत्री थे—
(गृह) जो अयोध्या पर प्रयासों का समन्वय कर रहे थे, और उनके करीबी थे
चंद्र शेखर ने उनसे आग्रह किया था कि वे शंकराचार्य को बुला लें।
इस प्रयास से अलग हो जाओ। वीपी सिंह सरकार अपने रास्ते पर थी।
सहाय ने कहा, "बाहर हो जाओ, और चंद्र शेखर अगली टीम बनाएंगे।"
सरकार। मध्यस्थता के सभी प्रयासों को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शंकराचार्य पर दूरी बनाने के लिए दबाव बढ़ा दिया।
उन्होंने स्वयं को उस प्रयास से मुक्त कर लिया—जो उन्होंने किया भी।
कृष्णकांत और यूनुस सलीम ने एक ऐसे संगठन के निर्माण की परिकल्पना की थी।
अयोध्या में एक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करते हुए, मंदिर का निर्माण और उसे बरकरार रखते हुए
भारत की समन्वित संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मौजूदा मस्जिद। अली मियां
उन्होंने अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद कार्रवाई समिति को मनाने का वादा किया था।
शंकराचार्य कहते थे, 'विश्व हिंदू परिषद को मेरे भरोसे छोड़ दो।'
कृष्णकांत ने बार-बार ऐसा कहा।
कांत ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी अपने साथ रखने पर विशेष जोर दिया था।
लूप, और जसवंत सिंह भी इन बैठकों में से एक में उपस्थित थे।
मुझे पता था कि जो भी समाधान निकाला जाएगा, उसे भाजपा को ही मंजूरी देनी होगी।
अंततः, एक ईमानदार और नेक इरादे से किया गया प्रयास सफल नहीं हुआ।
राजनीतिक वर्चस्व और श्रेय पाने की लालसा के कारण
शीर्ष पर बैठे कुछ लोग यही चाहते थे।
■

‘आप कहां हैं?’ चंद्र शेखर ने वीएचपी नेता अशोक सिंघल से पूछा।
यह 10 नवंबर 1990 का दिन था—जिस दिन चंद्र शेखर ने पदभार संभाला था।
प्रधानमंत्री। सिंघल ने जवाब दिया कि वे विजयराज में एक बैठक में थे।
सिंधिया का घर।
चंद्र शेखर ने उनसे कहा, 'प्रधानमंत्री आवास पर आकर मुझसे मिलिए।'
इन शब्दों के साथ, चंद्र शेखर ने दूसरी गंभीर कार्रवाई शुरू की।
अयोध्या विवाद को सुलझाने का प्रयास। कांत और सलीम के विपरीत, जिन्होंने
चंद्र शेखर ने दोनों पक्षों के धार्मिक व्यक्तित्वों के माध्यम से बात की।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के साथ सीधे बातचीत करने का फैसला किया। चंद्र शेखर चाहते थे कि

समय बर्बाद न करने के लिए; वह जानता था कि उसकी सरकार शायद ज्यादा समय तक न टिके।
उनकी तिरसठ सदस्यीय जनता दल (एस) को राजीव गांधी का समर्थन प्राप्त था।
गांधी की कांग्रेस पार्टी को 'बाहर से' देखा जाए तो वह स्थिर नहीं थी।
व्यवस्था।
जब सिंघल और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रधानमंत्री आवास पहुंचे,
चंद्र शेखर सीधे मुद्दे पर आए और बोले, 'हम इस समस्या का समाधान कैसे करें?'
अयोध्या समस्या?' उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि मंदिर अवश्य बनाया जाना चाहिए
बाबरी मस्जिद की जगह पर नई मस्जिद बनाई जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो
'खून की'
उनमें से एक ने कहा, 'नदिया बह जाएंगे (खून की नदियाँ बहेंगी)'
विवादास्पद रूप से।
चंद्र शेखर ने पलटवार करते हुए कहा, 'मैं एक भी ईंट गिरने नहीं दूंगा।'
अंत में सिंघल ने प्रधानमंत्री से पूछा, 'क्या आगे बढ़ने का कोई रास्ता है?'
बैठक का,
'बातचीत करो (संवाद शुरू करें),' चंद्र शेखर ने सुझाव दिया।
उन्होंने पूछा, 'कैसे?' 'बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नहीं होगी'
तैयार।'

चंद्र शेखर ने उनसे कहा, 'तुम अपने बारे में बात करते हो। क्या तुम...?'
तैयार?'
वीएचपी ने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई।
चंद्र शेखर ने बाबरी मस्जिद एक्शन मुस्लिम संगठन से बात की। इसके बाद उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन ग्रुप के सदस्यों से भी बात की।
समिति से आग्रह किया गया कि वे विस्फोटक स्थिति को शांत करें, जो उत्पन्न कर सकती है।
भारत के उन छह लाख गांवों को छोड़कर जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे अगल बगल।
दस दिन बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई। चंद्र

शेखर ने भैरों सिंह सहित एक समिति नियुक्त की।
Shekhawat, Sharad Pawar, and, later, Mulayam Singh Yadav to find ‘a
बाहर निकलने का रास्ता। वह इससे अधिक व्यावहारिक राजनेताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था।
भारत को एक ऐसे मुद्दे से जूझना पड़ा जो असाध्य हो चुका था।
1 और 4 दिसंबर 1990 को वीएचपी के बीच बैठकें आयोजित की गईं।
और मुस्लिम नेताओं ने यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या वहां कोई मंदिर था।
बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्तित्व था। दोनों पक्ष सहमत हो गए।
उन्होंने जो सबूत जुटाए हैं, उन्हें गृह मंत्रालय को सौंप दें, और फिर
जनवरी में फिर मिलेंगे।
भैरों सिंह भाजपा और विश्व हिंदू परिषद से निपट रहे थे। पवार ने कमान संभाली।
'नागपुर छोर' (आरएसएस) में काम किया और आरएसएस नेता मोरोपंत के माध्यम से कार्य किया।
पिंगले, जिन्हें वे अच्छी तरह जानते थे और जो संघ परिवार के प्रमुख व्यक्ति थे।
अयोध्या पर एक व्यक्ति। 'तांत्रिक-धर्मगुरु' चंद्रस्वामी ने भी मदद की।
‘साधुओं को एक साथ लाओ।’ उन्होंने ‘200 साधुओं से संपर्क किया,’ जिनमें शामिल थे
अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर के प्रमुख नृत्य गोपाल दास और राम
चंद्र परमहंस, जो राम जन्मभूमि न्यास नामक संस्था के प्रमुख थे
जिसे मंदिर के निर्माण का कार्य सौंपा गया था।
एक बार उनसे पूछा गया कि उन्होंने 'धर्मगुरु' की सेवाएं क्यों लीं।
चंद्रस्वामी, जिन्होंने एक निश्चित बदनामी हासिल कर ली थी, चंद्र
Shekhar replied cryptically ‘Kaun mahatma hai aur kaun duratma hai,
काम जरूरी है (कौन कह सकता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा)
भावना, महत्वपूर्ण बात यह है कि काम पूरा हो जाए)। बाद में, चंद्रस्वामी
नरसिम्हा राव के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू की जानी थी।

Chandra Shekhar told Om Prakash Chautala to keep the sadhus
उन्हें ‘खुश’ रखें और उन्हें वाहन, मुश्तंडा (सुरक्षा गार्ड) और
वे जो कुछ भी चाहते थे।
मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व के साथ उनके अच्छे संबंधों को देखते हुए, मुलायम
सिंह यादव ने दारुल उलूम नदवतुल के प्रमुखों से बात की।
लखनऊ में स्थित उलेमा नामक इस्लामी संस्था ने दुनिया भर के मुस्लिम विद्वानों को आकर्षित किया। उनकी मुलाकात अली मियां से भी हुई। 'वहाँ एक
चंद्र शेखर ने मुझे बताया, 'दोनों पक्षों में समाधान खोजने की तत्परता है।'
एआईबीएमसी और राम के बीच कई बैठकें हुईं।
जन्मभूमि न्यास। यह निर्णय लिया गया कि इस स्थल की खुदाई की जाएगी।
और यदि यह पाया जाए कि मस्जिद का निर्माण बाद में किया गया था
अगर वहाँ किसी मंदिर को तोड़ दिया जाए, तो मुसलमान अपना दावा छोड़ देंगे। लेकिन, 'अगर
चंद्र शेखर ने विश्व हिंदू परिषद से कहा, 'कोई ढांचा नहीं था, तब हम ऐसा कर सकते थे।'
भागीरथी और सरयू नदियों के किनारे एक भव्य मंदिर का निर्माण करो।’
यह उस फार्मूले का आधार था जिस पर चंद्र शेखर काम कर रहे थे।
वीएचपी नेताओं से मिलने के तुरंत बाद, चंद्र शेखर ने फोन किया
सैयद शहाबुद्दीन से परामर्श के लिए। शहाबुद्दीन उनके बहुत करीबी थे।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय का नेतृत्व किया।
5 फरवरी 1986 को गठित समिति (बीएमएमसीसी) के बाद
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए
राजीव गांधी द्वारा निर्मित संरचना।
‘Bhai, woh (VHP) log aaye thae, unke paas saboot tha ki wahan
मंदिर था (भाई, वीएचपी के लोग आए थे, वे कहते हैं कि उनके पास
(इस बात का सबूत कि यहाँ एक मंदिर था),’ चंद्र शेखर ने लिया
शहाबुद्दीन को विश्वास में ले लिया। शहाबुद्दीन यह देखकर चकित रह गया कि

चंद्र शेखर विश्व हिंदू परिषद के बयान पर विश्वास करने के लिए इच्छुक प्रतीत होते थे।
‘आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं,’ शहाबुद्दीन ने तीखे शब्दों में कहा।
वापस। 'आप दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं। आप बताते हैं...'
वीएचपी, अगर उनके पास सबूत हैं, तो उन्हें अदालत के सामने पेश करना चाहिए। मैं आपको देता हूँ
मैं अपने वचन का वचन देता हूँ कि मैं अदालत के फैसले को स्वीकार करूँगा। लेकिन मैं नहीं करूँगा।
आपको न्यायाधीश और मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करें।
चंद्र शेखर से इस तरह बात करना आसान नहीं था।
शहाबुद्दीन। क्योंकि चंद्र शेखर ने ही उनके निर्माण में मदद की थी।
राजनीतिक जीवन। एक समय ऐसा भी था जब शहाबुद्दीन एक कुर्सी पर बैठा करते थे।
जंतर मंतर रोड स्थित 7 नंबर के जनता पार्टी कार्यालय में एक जर्जर कुर्सी और
वहाँ आने वाले उर्दू पत्रों का उत्तर देना। बाद में, 1979 में, चंद्र
शेखर ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उसके बाद उसके लिए।
शहाबुद्दीन ने बाद में मुझसे कहा, 'मैंने एक ऐसे आदमी से इस तरह बात की थी जिसका
मैं धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता। लेकिन (मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि) मुझे संदेह था।
चंद्र शेखर के इरादे... मैं यह बात पहली बार कह रहा हूँ।
किसी को भी। वह इस कार्रवाई पर अपना राजनीतिक भविष्य बनाना चाहता था। वह मुसलमानों को मनाने का श्रेय लेना चाहता था, इसलिए उसने
कह सकते हैं, “मैंने मुसलमानों को तैयार किया”।
चंद्र शेखर ने एआईबीएमएसी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी संपर्क किया।
जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी (जो ऑल इंडिया मजलिस-ए- के साथ थे)
इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एक सांसद, और असदुद्दीन ओवैसी के पिता)

और वरिष्ठ अधिवक्ता ज़फ़रयाब गिलानी। वीएचपी के विशेषज्ञ एक निष्कर्ष पर पहुंचे।
मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक। मुसलमानों ने अपने विशेषज्ञों को बुलाया।
इनमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय के चार इतिहासकार भी शामिल थे, जिन्होंने उनका समर्थन किया।
मुसलमानों का तर्क था कि मस्जिद की रक्षा करना आवश्यक है।
कानून के शासन को कायम रखना। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के लिए यह 'आस्था का विषय' था।
चंद्र शेखर को उम्मीद थी कि विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) 'छोड़ने के लिए सहमत हो जाएगी'।
(इसके अलावा) काशी और मथुरा पर उनका दावा—यदि कोई समझौता हुआ हो
अयोध्या को लेकर। यह मुसलमानों की मुख्य चिंताओं में से एक थी।
उस समय समुदाय में। वीएचपी न केवल एक की मांग कर रही थी।
अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिर, लेकिन साथ ही वापसी भी।
उनका दावा था कि जिन 3,000 मंदिरों की जगह मस्जिदें बनाई गई थीं, वे अब मौजूद हैं।
'विष्णु हरि डालमिया...ने मुझे बताया कि चंद्र शेखर ने गुहार लगाई थी
उन्होंने वाराणसी और मथुरा छोड़ने के लिए उनसे कहा था और उन्होंने यह बात भी कही थी।
रोमेश भंडारी, जो उस समय राज्यपाल थे, ने स्पष्ट रूप से कहा, 'बिल्कुल नहीं।'
उत्तर प्रदेश। हालांकि, दोनों पक्ष अदालत के फैसले का पालन करने पर सहमत हुए, और यह कि
यह एक कदम आगे था।
चंद्र शेखर ने मुख्य अधिकारी सी. रंगनाथ मिश्रा से बात की।
भारत का न्याय। उन्होंने न्यायमूर्ति मिश्रा से यह निर्धारित करने को कहा कि क्या राम अयोध्या में स्थित मंदिर को दरअसल वहां मस्जिद बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया था।
मैंने उनसे कहा, 'आप एक महीने में अपना फैसला सुना दीजिए।'
चंद्र शेखर के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए सहमति दे दी है।

उनका फैसला: 'मिश्रा ने कहा कि वह तीन दिनों में फैसला सुना देंगे।'
महीने।'
“लेकिन,” मिश्रा ने आगे कहा, “यह अनिवार्य होना चाहिए, न कि
सिफारिशी।
चंद्र शेखर सहमत हो गए। 'ठीक है। यह अनिवार्य होगा।' प्रधानमंत्री
मंत्री ने मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ वीएचपी और
एआईबीएमसी—कि सरकार आदेश का पालन करेगी
सुप्रीम कोर्ट।
सरकार के वार्ताकारों ने प्रभावशाली हस्तियों से संपर्क साधा था।
अरब जगत में मुस्लिम पक्ष को अपने पक्ष में करने के लिए। उन्होंने संपर्क किया।
सऊदी अरब। ‘क्राउन प्रिंस इसमें शामिल थे, उनकी मदद ली गई थी, और उनके माध्यम से धार्मिक प्रमुखों से बात की गई थी...। हम आगे बढ़े।
धार्मिक और राजनयिक नेता।
सऊदी अरब ने मक्का के प्रमुख धार्मिक नेताओं से भी संपर्क किया।
They said that ‘Jhagrhe ki jageh naek Musalmaan nahin jaata (A
एक धर्मनिष्ठ मुसलमान विवादित स्थल पर प्रार्थना नहीं करता है।
काबा तो इसे लिखित में देने के मूड में भी थे—उन्होंने पूछा कि
मुसलमानों को इसमें (मस्जिद में) नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह विवादित थी।’ ‘हम
भारत के शीर्ष मुस्लिम नेताओं द्वारा उन्हें सूचित किया गया था कि यह एक
वार्ताकारों में से एक ने कहा, 'बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, और लड़ाई खत्म हो जाएगी।'
स्थिति समझौते की ओर बढ़ रही थी। तीन सदस्यीय
समिति ने प्रधानमंत्री से अंतिम मंजूरी लेने के लिए दोबारा मुलाकात की। 'जाओ'
चंद्र शेखर ने उनसे कहा, 'आगे बढ़ो।' विश्व हिंदू परिषद ने तो यहाँ तक तय कर लिया था कि वह आगे बढ़ेगी।
एआईबीएमसी के नेताओं को इस सफलता का जश्न मनाने के लिए रात्रिभोज पर आमंत्रित किया गया था।
इसी समय शरद पवार ने राजीव गांधी को रिपोर्ट दी।

'विस्तार से'—कि समझौता लगभग पूरा हो चुका था। उन्होंने इसे 'अच्छे तरीके से' किया।
उन्होंने बाद में कहा, 'विश्वास'।
राजीव ने बस इतना कहा, ‘तुम यहाँ (दिल्ली में) इतना समय बिता रहे हो।’
पवार की बात सुनने के बाद गांधी ने उनसे कहा, ‘इनकी देखभाल कौन करेगा?’
राज्य?'
कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र में पवार के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा।
केंद्रीय नेताओं विलासराव देशमुख, सुशील कुमार ने इसे और बढ़ावा दिया।
शिंदे, एस. बी. चव्हाण और वी. एन. गाडगिल। उन्होंने पवार की मांग की।
पवार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन पवार अपने समर्थकों को एकजुट रखने में कामयाब रहे।
एक साथ—और अंत में विद्रोहियों को केवल 11 लोगों का समर्थन प्राप्त रह गया।
210 विधायकों में से।
लेकिन दिल्ली के सत्ता हलकों में यह कानाफूसी बढ़ने लगी कि चंद्र शेखर
‘अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था’। राजीव गांधी के करीबी लोग अचानक सतर्क हो गए।
सलाहकारों ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि चंद्र शेखर किसी तरह से प्रभाव डालने में कामयाब हो गए तो
अयोध्या मुद्दे पर निर्णायक सफलता मिलने पर, वह लोकप्रिय हो जाएंगे
राष्ट्रीय स्तर पर नेता। उन्हें कांग्रेस के भीतर भी समर्थन मिल सकता है, और
समय आने पर या तो पार्टी पर कब्जा कर लो या कांग्रेस को विभाजित कर दो।
आखिरकार, उसके पास यही था।
मैं एक समय कांग्रेसी रह चुका था और पार्टी के नेताओं से मेरे पुराने संबंध थे।
और कांग्रेस के मुख्यमंत्री। गुट को डर था कि शरद पवार
चंद्र शेखर के साथ हाथ मिला सकते हैं।
अपने प्रधानमंत्रित्व काल के अंत में, नरसिम्हा राव उस मुकाम पर पहुँच चुके थे।
चंद्र शेखर को कांग्रेस में शामिल करने के उद्देश्य से उनसे संपर्क किया गया ताकि पार्टी में सोनिया गांधी के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके।
लेकिन आखिरी क्षण में वह घबरा गया।

फरवरी 1991 में राजीव गांधी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया।
चंद्र शेखर सरकार। राजीव गांधी का चंद्र शेखर के साथ संबंध।
इस समय तक शेखर की हालत वैसे भी काफी खराब थी। इसका कारण यह बताया गया कि
कि 'हरियाणा के दो सब-इंस्पेक्टर' आसपास ताक-झांक करते पाए गए
Gandhi residence at 10, Janpath, a bungalow Rajiv Gandhi had shifted
प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद।
प्रधानमंत्री चंद्र शेखर ने 5 मार्च 1991 को इस्तीफा दे दिया, और
उनके साथ अयोध्या विवाद के समाधान का एक और मौका भी चला गया।
शांतिपूर्वक।
बाद में जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा, तो चंद्र शेखर ने कंधे उचका दिए।
दार्शनिक रूप से, 'मैं यह नहीं कह सकता कि क्या (समस्या का समाधान) हो पाता।'
happened…. I think thora khoon kharaba hota, par implement ho jata
(थोड़ा बहुत खून-खराबा हो सकता था, लेकिन बात यहीं खत्म हो जाती)
लागू किया गया)। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक पानी ठंडा करने में सफल रहा।
एक संकटपूर्ण स्थिति पर।
■

नरेश चंद्र के अनुसार, राव ने जिस प्रकरण का सबसे सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, वह यही था।
मुलायम सिंह यादव ने इसी तरह सफलतापूर्वक इसे रोकने में कामयाबी हासिल की थी।
30 तारीख को कुल्हाड़ियों से लैस कार सेवकों ने मस्जिद पर धावा बोल दिया।
अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को। 'इस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की।'
'मेरे साथ,' चंद्र ने खुलासा किया।

चंद्र ने उन्हें बताया था कि कैसे हजारों कार सेवक इकट्ठा हुए थे।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के आह्वान पर 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या में उनकी संख्या इतनी होगी।
एहतियाती उपायों के कारण ऐसा नहीं हो सका, अन्यथा ये नुकसान कहीं अधिक बड़ा होता।
मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने ये व्यवस्थाएं लागू की थीं।
उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक कार सेवकों को गिरफ्तार किया गया। इस समय, केंद्र सरकार ने
वी. पी. सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पतन के कगार पर थी। जैसा कि देखा गया है
पिछले अध्याय में, लालू के बाद भाजपा ने इससे अपना समर्थन वापस ले लिया था।
Yadav arrested L. K. Advani in Samastipur in Bihar, cutting short his
23 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा।
उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। राज भार्गव
नरेश चंद्र उस समय मुख्य सचिव और नरेश चंद्र गृह सचिव थे।
केंद्र में मौजूद दोनों अधिकारी मस्जिद की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों की निगरानी कर रहे थे। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे।
राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी
संरचना में प्रवेश करें। लेकिन 30 अक्टूबर को, यूपी पीएसी के कर्मियों ने
इमारत की सुरक्षा में लापरवाही के कारण सुरक्षा में सेंध लग गई।
कार सेवकों को बाहर रखने के लिए लगाई गई बाधा को हटा दिया गया।
ऐसी भी खबरें थीं कि एक साधु ने पीएसी वैन को शहर के भीतर से चलाया था।
अवरोध। लगभग चालीस उत्साहित युवक संरचना में प्रवेश कर गए, एक रिपोर्ट के अनुसार।
चंद्र ने कुल्हाड़ी से दीवारें तोड़ना शुरू कर दिया।
आईबीआई द्वारा फिल्मांकन किया गया और फिल्म को दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय को भेजा गया।
जहां अधिकारियों ने वीएचपी के बारे में विस्तार से जांच की ताकि पता चल सके कि

वीएचपी ने क्या किया था।
करने का इरादा था।
भीड़ से निपटने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की, हालांकि
कोई हताहत नहीं हुआ। और स्थिति नियंत्रण में आ गई। लेकिन
कार सेवकों ने जिस आसानी से बाबरी मस्जिद में प्रवेश किया था,
उन्हें प्रोत्साहित किया।
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों—सीमा सुरक्षा बलों—को भेजने का फैसला किया।
सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)—को
नरेश ने याद करते हुए कहा, 'मैं हर घंटे स्थिति पर नजर रख रहा था।'
चंद्र।
भारत सरकार के निर्देश स्पष्ट थे। केंद्रीय
सेनाएं गोलीबारी नहीं करेंगी। यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो ही गोलीबारी की जाएगी।
यह कार्रवाई यूपी पुलिस ने की।
मैंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि यूपी
पीएसी को (यदि आवश्यक हो) कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्हें।'
हमने उनसे कहा, “यदि आप कार सेवकों को (संरचना में) प्रवेश करने की अनुमति देते हैं,
बीएसएफ-सीआरपीएफ के जवान तुमसे निपटेंगे...वे तुम पर हमला भी कर सकते हैं।
हमने पंजाब में यह कोशिश की थी जब हमने सभी को पीछे कर दिया था।
पंजाब पुलिस के अधीन।
2 नवंबर 1990 को कार सेवक बाबरी मस्जिद में एकत्रित हुए।
और भी अधिक संख्या में। वे संरचना में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े।
उन्होंने दो दिन पहले ऐसा किया था। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी।
उन्हें। 'मृतकों की आधिकारिक संख्या बारह थी, लेकिन वास्तव में अठारह थीं।
बाद में मुलायम सिंह यादव ने खुलासा किया कि अट्ठाईस लोगों की हत्या कर दी गई

थी।
उस दिन गोलीबारी में लोग मारे गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने
मृतक की आयु छप्पन वर्ष थी।
1990 में मुलायम सिंह यादव ने पूरी छूट दे दी थी।
इस उभरते संकट से निपटने के लिए नौकरशाही का सहारा लेना होगा।
नरेश ने याद करते हुए कहा, 'मैंने छावनियों में 90,000 लोगों को कैद कर रखा था।'
चंद्र। 'इन लोगों को बस मार्गों से लाने वाले दर्जनों पुलिया थे।
उत्तर प्रदेश में धमाका हुआ। ट्रेनों को मनमाने ढंग से रद्द किया गया।
चंद्र ने गृह सचिव की शक्तियां राज को सौंप दी थीं।
भार्गव को महत्वपूर्ण पद पर बिठाया गया था ताकि वे निर्णय ले सकें।
मौके पर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को बताया गया था कि यदि मुख्य
सचिव का कहना है कि इस ट्रेन को रद्द करो, आप इसे रद्द कर दें। इसे बिहार, मध्य प्रदेश में ही रहने दें।
—यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए वहां इसकी संख्या कम करने के लिए यह सब करना पड़ा।
(अयोध्या में)। एक बार जब भीड़ जमा हो जाती है (और बेकाबू हो जाती है), तो आप गोली चलानी होगी।
राज भार्गव ने मुलायम सिंह यादव को हर चरण की जानकारी दी।
हालांकि प्रधानमंत्री वी.पी. के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण थे।
मुलायम सिंह ने केंद्र के साथ सहयोग किया और ऐसा नहीं किया।
गृह मंत्रालय द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधों में हस्तक्षेप करना।
योजना पूरी तरह से लागू हो गई। यह योजना मुलायम सिंह को बेहद पसंद आई।
यह घोषणा की गई कि एक भी परिंदा (पक्षी) संरचना में प्रवेश नहीं कर पाएगा।
उस दिन। 2 नवंबर को स्थिति को संभालने का उनका सख्त तरीका।
मस्जिद की रक्षा करने के कारण वह अल्पसंख्यकों का चहेता बन गया—और
इसी वजह से उन्हें 'मुल्ला मुलायम' की उपाधि मिली। लोगों का विश्वास इतना प्रबल था।
मुसलमानों ने उसमें यह बात कही थी कि 6 तारीख को विध्वंस के बाद वे ऐसा कहते थे।

दिसंबर 1992, ‘यदि नेताजी (मुलायम सिंह) उत्तर प्रदेश के प्रभारी होते,’
वह ऐसा होने ही नहीं देता।
हालांकि उन्होंने मुलायम सिंह की रक्षा रणनीति की बारीकी से जांच की थी
1992 में राव को इस बात का यकीन नहीं था कि मस्जिद सफल होगी।
उन्होंने चंद्र को बताया कि 1990 और 1992 के बीच मूलभूत अंतर क्या था। 1990 में,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खुद को बाबरी मस्जिद का रक्षक मानते थे।
मस्जिद। 1992 में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने खुद को मस्जिद का निर्माता बताया था।
राम मंदिर।
‘इस बार आप कार सेवकों को अंदर आने से नहीं रोक पाएंगे’
राव ने चंद्र से कहा, 'अयोध्या को सीमा पर उसी तरह स्थापित किया जाए जैसा 1990 में हुआ था।'
उत्तर प्रदेश के अलावा, भाजपा पड़ोसी राज्यों में भी सत्ता में है।
मध्य प्रदेश और राजस्थान।’ और इतनी बड़ी सेना तैनात करना।
राज्यों के बीच की सीमाओं को सील करना असंभव है।
इसके अलावा, मुलायम सिंह के विपरीत, जो गोली चलाने से नहीं हिचकिचाते थे,
कार सेवकों को मस्जिद को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए, राव उन पर गोली चलाने के खिलाफ थे। लेकिन उस समय, मुलायम सिंह मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे।
राव हिंदू मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि बाद में पता चला, एक समर्थक-
कल्याण सिंह ने कार सेवकों पर गोली न चलाने के भी आदेश दिए।
6 दिसंबर 1992 को। बहुत बाद में, 2007 में, राहुल गांधी ने दावा किया कि
अगर नेहरू परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती।
गांधी परिवार सत्ता के शीर्ष पर था। चंद्र शेखर एक समय सत्ता में थे।
remarked to me, ‘Agar main hota, toh 2,000 log bhi mar jaate na, I

अगर मैं वहां होता तो (बाबरी मस्जिद) की संरचना की रक्षा कर लेता।
मैं उस ढांचे की रक्षा करता, भले ही 2000 लोग मर जाते।'
कैबिनेट सचिव नरेश चंद्र ने इस बात से सहमति जताई कि वह यह जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं।
यह एक साहसिक निर्णय था। लेकिन पी.वी. नरसिम्हा राव चंद्र शेखर नहीं थे।

आठवीं

'कोई पत्रकार दोस्त नहीं हो सकता, हालांकि एक दोस्त पत्रकार हो सकता है।'
नरसिम्हा राव ने एक बार अपने एक सहकर्मी से कहा था। हालाँकि उन्होंने
आम तौर पर पत्रकारों पर अविश्वास होने के कारण, उन्होंने वरिष्ठ पत्रकारों की एक टीम नियुक्त की थी।
जिन संपादकों के साथ वह सहज महसूस करते थे, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था।
chapter—Nikhil Chakravartty, Prabhash Joshi, and R. K. Mishra—to
अयोध्या वार्ता में सहायता करना।
उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण के तीनों सदस्यों को नियुक्त किया था।
परिषद, प्रतिष्ठित राजनीतिक और नागरिक समाज के नेताओं का एक निकाय है जिसकी स्थापना की गई थी
1961 में देश को विभाजित करने वाली समस्याओं को हल करने के लिए।
संकट के बेकाबू होने से पांच महीने पहले, 27 जुलाई को
1992 में, प्रधानमंत्री राव ने संसद को बताया कि वे 'संकट को कम करना' चाहते हैं।
'स्थिति', 'टकराव से बचना', 'समझौता कराना', और
बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ना।
कांग्रेस पार्टी ने अपने 1991 के घोषणापत्र में जो प्रतिबद्धता जताई थी, उसे याद किया गया।
विवाद का बातचीत के जरिए समाधान ढूंढना, सम्मान करते हुए
हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं।
संसद में बोलते समय राव काफी उत्साहित लग रहे थे; वीएचपी के पास

उन्होंने कार सेवा समाप्त कर दी और उन्हें समाधान खोजने के लिए तीन महीने का समय दिया।
सामान्यतः संशयवादी रहने वाले राव अब सावधानीपूर्वक आशावादी हो गए थे।
कि इस उलझन से निकलने का कोई रास्ता संभव हो सकता है। अगर नहीं, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि...
उनसे पहले चंद्र शेखर ने जो किया था, उससे कम से कम दोनों पक्षों को
अदालत के फैसले का पालन करने के लिए सहमत हों।
इसके बाद अत्यावश्यक गतिविधियाँ शुरू हो गईं। अगस्त से अक्टूबर 1992 तक, राव ने दबाव बनाया।
संचार के खुले चैनल बनाने के लिए कई वार्ताकारों को सेवा में लगाया गया।
विवाद के दोनों पक्षों से। औपचारिक स्तर पर, उन्होंने अपने एक कनिष्ठ मंत्री, पी. आर. कुमारमंगलम को, विवाद के नेताओं से बात करने के लिए नियुक्त किया।
विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच; ऐसा करने से नियंत्रण उनके पास ही रहेगा।
उसे।
चंद्र शेखर की तरह, उन्होंने भी विवादास्पद बाबा का सहारा लिया।
चंद्रस्वामी साधुओं और संतों को संगठित करने में मदद कर रहे हैं। साथ ही सहायता भी कर रहे हैं।
धार्मिक क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति तांत्रिक पंडित एन. के. शर्मा थे। फिर से, जैसे
चंद्र शेखर और राव ने राजनीतिक वार्ताकार शरद पवार को शामिल किया।
Bhairon Singh Shekhawat, and also roped in Digvijay Singh and
कमल नाथ। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अलावा, नरेश चंद्र
आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल को लाया गया, जो सीआईएसएफ में डीआईजी थे, और
वीएचपी के करीबी, उनके साथ काम करने के लिए।
वीएचपी और एआईबीएमएसी के बीच बातचीत 3 तारीख को फिर से शुरू हुई।
अक्टूबर 1992 में, उन्होंने वहीं से काम शुरू किया जहाँ उन्होंने फरवरी 1991 में छोड़ा था।
जब चंद्र शेखर प्रधानमंत्री थे। दूसरी बैठक

दोनों समूहों के बीच बैठक 16 अक्टूबर 1992 को हुई; उन्होंने आदान-प्रदान किया
दस्तावेज़ और एक-दूसरे के पत्रों और तर्कों पर उनकी प्रतिक्रियाएँ।
राव की आलोचना इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को मैदान में उतारा था। कभी-कभी वे
वे एक-दूसरे के विपरीत काम कर रहे थे, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे।
इससे व्याप्त भ्रम और भी बढ़ गया। यह विचित्र था कि राव
उन्होंने संरचित संवाद का विकल्प नहीं चुना। न ही उन्होंने औपचारिक रूप से ऐसा किया।
किसी व्यक्ति या समूह को दोनों पक्षों से बात करने के लिए अधिकृत करना। वरिष्ठ
कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी ने बाद में कहा कि राव को 'ऐसा करना चाहिए'
कठिन बातचीत का कार्य एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दिया है और
उत्तर प्रदेश की राजनीति से परिचित अनुभवी राजनेता—जैसे एन. डी. तिवारी।
मुखर्जी का मानना था कि गृह मंत्री एस.बी. चव्हाण इस बात को समझ नहीं पाए।
समस्या के भावनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, कुमारमंगलम बहुत 'युवा' थे।
और 'अनुभवहीन'।
जब उनके वार्ताकार संबंधित पक्षों के साथ बैठकें कर रहे थे
इस विवाद के दौरान राव स्वयं कई साधुओं के सीधे संपर्क में थे।
और मुस्लिम धर्मगुरुओं से। वह संतों से संस्कृत में बात करते थे।
कभी-कभी वह उनके साथ अपने कार्यालय के फर्श पर बैठ जाता है और पाठ करता है।
उपनिषदों के बारे में सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो जाते। और वह मुसलमानों से बात करता।
फ़ारसी में नेता। वे भी प्रभावित होंगे। वह इससे परिचित था।
मुस्लिम और हिंदू दोनों संस्कृतियों में। और इस तरह, वह बने रहे।
एक कुशल कठपुतली कलाकार जिसके नियंत्रण में सभी डोरियाँ मजबूती से टिकी हुई हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा की गई इसी लामबंदी ने दहशत पैदा कर दी।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) में साधुओं के साथ राव के बढ़ते संबंधों को देखते हुए, वीएचपी को संदेह होने लगा कि राव स्वयं एक राम मंदिर बनाना चाहते हैं।

अयोध्या में मंदिर—और इससे उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। हालाँकि राव को उन्होंने मंदिर निर्माण की अपनी योजनाओं का खुलासा अपने विश्वसनीय सहयोगी पी.वी.आर.के. के सामने किया।

विध्वंस होने के बाद ही प्रसाद ने शायद इस बारे में सोचना शुरू किया होगा।

इस विचार के साथ। आखिरकार, कांग्रेस पार्टी ने अपने 1991 के घोषणापत्र में यह बात कही थी,

उसने अयोध्या में मंदिर निर्माण करने का संकल्प लिया।

पीवी की हिंदू संतों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातचीत का उद्देश्य इस मुद्दे को समाप्त करना था।

चतुर्वेदी ने स्वीकार किया, ‘भाजपा की उन पर पकड़ मजबूत हो गई। एक बार विश्वास पैदा हो जाने के बाद।’ ‘

(समुदायों के बीच) और मंदिर का निर्माण हुआ, हिंदुओं ने

वे पीवी को अपना नेता मानते होंगे।'

इससे मतदाताओं के बीच, विशेष रूप से, उन्हें जबरदस्त प्रभाव प्राप्त होता।

उत्तर प्रदेश में, जहां उनका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं था।

पी.वी. ने एक बार के.के. बिरला से (उनके द्वारा) ₹2 दान करने के बारे में बात की थी।

भुवनेश चतुर्वेदी ने खुलासा किया, 'मंदिर के निर्माण के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए।'

मैंने अली मियां से भी इस बारे में बात की थी।' कुछ लोगों को डर था कि राव ऐसा करना चाहता था।

‘हिंदू चर्चों का एक संघ’ बना सकता है जो

वीएचपी के विकल्प के रूप में उभर सकता है। यदि ऐसा कोई समूह होता तो

अयोध्या में मंदिर के निर्माण की योजना पर अमल हुआ और उसे पूरा किया गया।

(मस्जिद को नष्ट किए बिना), यह एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकता था

मंदिर के अलावा अन्य मुद्दों पर भी अधिकार।

जब राव को सफलता मिलती दिख रही थी, तभी अचानक वीएचपी को एक बड़ा झटका लगा।

पुनर्विचार। यह अक्टूबर 1992 के अंत की बात है। धर्म

संसद ने 30-31 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि
अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कार सर्वर को फिर से शुरू करने की घोषणा।
यह अयोध्या की कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
■

जिस दिन कार सेवा की घोषणा हुई, राव साहब को यह आभास हो गया कि "दल
'मैं कुछ काला है (कहीं न कहीं कुछ बहुत गलत है)', आर. के.
खांडेकर, जिन्होंने अपनी युवावस्था में आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण लिया था, ने यह बात याद करते हुए बताई।
तब तक हिंदू संतों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठकें होती रही थीं...
सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि कोई न कोई रास्ता निकल ही जाएगा।
मिला...।
बातचीत के बीच में कार सेवा की घोषणा करना दर्शाता है
वे (विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के अन्य सदस्य) ऐसा नहीं चाहते थे।
खंडेकर ने कहा, 'समझौते के बाद, राव साहब को इसका एहसास होने लगा।' 'तभी राव साहब को इसका एहसास होने लगा।'
बाबरी मस्जिद को बचाना शायद संभव न हो।
राव ने अब अपनी रणनीति बदल दी। इसके बाद के हफ्तों में, उन्होंने यह किया:
समय खरीदने के लिए हर संभव प्रयास किया, अच्छे की उम्मीद की और तैयारी की।
सबसे बुरा। आखिरकार, मस्जिद को गिराने का प्रयास किया गया था।
दो साल पहले अक्टूबर-नवंबर 1990 में जब मुलायम सिंह
यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
राव ने शायद यह अनुमान लगाया होगा कि अगर मस्जिद को गिरा दिया गया तो,
इससे एक ऐसी जटिल समस्या का समाधान हो जाएगा जिसने भाजपा को सत्ता में आने के लिए प्रेरित किया था।
इसका उदय हुआ है; और इसके गायब होने से भाजपा की रफ्तार धीमी पड़ सकती

है।
और इससे तेजी से असुरक्षित होते जा रहे मुसलमानों को वापस धकेला जा सकता है।
कांग्रेस के हथियार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
■

वीएचपी द्वारा अपनी चौंकाने वाली घोषणा करने के तुरंत बाद राव की
पार्टी के विरोधियों ने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। 6 नवंबर को
1992 में अर्जुन सिंह की मुलाकात एम. एल. फोतेदार से हुई।
'अर्जुन सिंह मुझसे मिलने कुशक रोड स्थित 6 नंबर पर आया था। वह अपने साथ था।
फोतेदार ने याद करते हुए कहा, 'मैंने उससे दो घंटे तक बात की। मैंने उसे बताया कि मेरी जानकारी यह थी...'
कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री
जल्दी कार्रवाई न करें। मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं चाहूंगा कि वह (अर्जुन सिंह) यह जिम्मेदारी लें।
अगर ऐसा हुआ तो पहल करके इस्तीफा दे दें।
'मैं तुम्हें अकेले कूदने के लिए नहीं कह रहा हूं,' फोतेदार ने अर्जुन सिंह से कहा।
दिन में, 'मैं भी यह कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप नेतृत्व करें तो यह अधिक प्रभावी होगा।'
क्योंकि आपके साथ एक राज्य है... मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। आप कर सकते हैं।
आप चाहें तो मेरा इस्तीफा अभी ले लें और बाद में भेज सकते हैं।'
हालांकि अर्जुन सिंह और फोतेदार दोनों में से किसी ने भी युद्ध के दिन इस्तीफा नहीं दिया था,
उन्होंने राव पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया।
उत्तर प्रदेश। वे कैबिनेट समिति के माध्यम से आगे बढ़े।
राजनीतिक मामलों की बैठक 20 नवंबर से नियमित रूप से होने लगी।
से आगे।
■

पुलिस अधिकारी किशोर कुणाल ने नरेश से कहा, 'बातचीत का समय समाप्त हो गया है।'
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा घोषणा किए जाने के तुरंत बाद चंद्र ने यह कदम उठाया।
अब तो युद्ध होने वाला है (अब यह पूरी तरह से युद्ध होने वाला है)
उन्होंने कहा, 'युद्ध के दौरान'। उन्होंने सीआईएसएफ में अपनी नौकरी पर लौटने का फैसला किया।
कुछ दिनों बाद, नरेश चंद्र ने कुणाल को फोन किया और उससे पूछा
तुरंत दिल्ली लौटने के लिए, कुणाल ने दिल्ली के लिए अगली फ्लाइट पकड़ी।
मैं हवाई अड्डे से सीधे चंद्र से मिलने गया। 'इस बार मैं नहीं हूँ।'
चंद्र ने उससे कहा, 'आपको किसने बुलाया है? शरद पवार जी ने बुलाया है।'
मैं तुम्हें ढूंढ रहा था।' चंद्र ने पवार से फोन पर बात की। पवार ने पूछा
उस दिन कुणाल को शाम 4 बजे आना था। उनकी मुलाकात के अनुसार,
Kunal, Pawar said: 'Kunalji, ab toh ghoshna inhone kar di hai. Aap
sadhu samaaj ko thoda sa phod dijiye, todh dijiye (Now these people
कार सेवा आयोजित करने की घोषणा कर दी गई है। आप तोड़ दें
साधुओं के बीच मतभेद पैदा करना और उनमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना)...' पवार
then elaborated, 'Jo VHP ke saath log jude hue hain, unko kuch udhar
se tod karke idhar mila dijiye (You bring over some of the people who
(इस तरफ वीएचपी के साथ हैं)।
'Toh maine kaha, sir, yeh mera swabhaav nahi hai (I said this is not
in my temperament),' Kunal told Pawar. 'Yeh kaam maine zindagi bhar

मैंने ऐसा कभी नहीं किया है (मैंने यह काम अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया है)।
कुणाल ने पवार से कहा कि स्थिति को अभी भी सुधारा जा सकता है, भले ही
हालांकि समाधान मुश्किल लग रहा था।
'कैसे?' पवार ने पूछा।
कुणाल ने मराठा नेता के साथ 'संभावनाओं' पर चर्चा की। पवार
उसे जो सुना वो पसंद आया।
पवार ने तुरंत आरएएक्स लाइन पर प्रधानमंत्री को फोन किया। राव ने उनसे पूछा
कुणाल को तुरंत लेकर आ जाओ। पता: 7, रेस कोर्स रोड, पवार
पहले वे अकेले राव से मिलने गए। फिर कुणाल को भी उनके साथ बुलाया गया।
कमरे में प्रवेश करते ही राव ने सबसे पहले कहा, 'मैं नहीं हूँ'
उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने जा रहे हैं। कल्याण सिंह की सरकार विधिवत निर्वाचित है।
सरकार।' चूंकि कुणाल वीएचपी के करीबी माने जाते थे, राव
जाहिर तौर पर वे चाहते थे कि यह संदेश उन तक पहुंचाया जाए। 'आप क्या चाहते हैं?'
'क्या आपके पास कोई सुझाव है?' राव ने फिर कुणाल से पूछा। 'एक समाधान है,' कुणाल ने कहा।
उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, 'आप अयोध्या, फैजाबाद और
नंदीग्राम को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करना। (किशोर कुणाल का विचार नंदीग्राम को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने का था।)
अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों को एक ऐसे प्रादेशिक इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है जो
(केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासित।)
उन्होंने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कर लिया था। 'अगर मुलायम सिंह या...'
कुणाल ने आगे कहा, 'वामपंथी (पार्टियां) आपके फैसले पर सवाल उठाती हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि चूंकि हमें यकीन नहीं था कि कल्याण सिंह... रक्षा करेंगे...
मस्जिद के मामले में, हमने इस तरह से इलाके का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया... और अगर भाजपा
और अगर वीएचपी आपके इस कदम पर सवाल उठाती है, तो आप उन्हें बता सकते हैं

कि आप दे रहे हैं।
अयोध्या को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करके उसे वेटिकन के समान दर्जा दिया जा सकता है।
इससे उन्हें खुशी होनी चाहिए।'
उन्होंने सुझाव दिया कि यह प्रस्ताव एक समग्र योजना का हिस्सा हो सकता है, जो अयोध्या से संबंधित सभी मुकदमों को दस साल के लिए रोक दिया जाएगा, और सक्षम बनाया जाएगा
मंदिर का निर्माण, संरचना में कोई बदलाव किए बिना किया जा सकता है।
कुणाल ने कहा कि अध्यादेश द्वारा तत्काल। लाल नारायण सिन्हा, जो
इंदिरा गांधी की सरकार में एक शीर्ष कानूनी पदाधिकारी रह चुके थे।
उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि वे इस पर काम कर रहे हैं।
राव ने कहा, 'यह एक अच्छा सुझाव है।' वे इस बारे में 'उत्साहित' प्रतीत हुए।
विचार।
फिर राव ने उनसे पूछा, 'अध्यादेश कहां है?'
‘सर, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और मुझे पता नहीं है कि कैसे बनाना है।’
अध्यादेश।'
‘मुझे यह कब मिलेगा?’ राव ने पूछा।
आपको यह कल सुबह तक मिल जाएगा।
मीटिंग के बाद कुणाल ने लाल नारायण सिन्हा को फोन किया और उनसे पूछा
अध्यादेश तैयार करने के लिए। उन्होंने अपने एक पायलट मित्र को पटना से इसे उड़ाने के लिए कहा।
दिल्ली—और इसे शरद पवार के पास ले गया। ‘मैंने अध्यादेश दोनों को सौंप दिया।
और मैंने उन्हें वह फॉर्मूला बताया... मैंने उनसे कहा, महोदय, कृपया इसे प्रसारित करवा दीजिए, यह
स्वीकार किया जाएगा... मैंने अहमद बुखारी (दिल्ली के राजनीतिक रूप से
प्रभावशाली मस्जिद (जामा मस्जिद) के बारे में उन्हें भी यह बात पता चली और उन्हें भी यह पसंद आया।
सूत्र।
हालांकि, कुणाल की योजना सफल नहीं हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने

सरकार—और दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे पत्रकारों का समूह
सूत्र—उन्हें यह 'व्यवहार्य' नहीं लगा। तीनों संपादकों, आर. के.
Mishra, Prabhash Joshi, and Nikhil Chakravartty had also worked out a
तीन सूत्रीय सूत्र. उन्होंने इसे रज्जू भैया (प्रोफेसर) को दिखाया था
राजेंद्र सिंह, जो सरकार्यवाह या महासचिव थे
RSS) on 1 December at Keshav Kunj, Jhandewalan, the RSS's
दिल्ली में मुख्यालय। उनकी योजना में 2.77 किलोमीटर पर कार सेवा की सिफारिश की गई थी।
विवादित क्षेत्र के आसपास एकड़-प्लॉट; द्वारा शीघ्र निर्णय।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2.77 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की वैधता पर फैसला करेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकड़ भूमि दी गई; और संघ परिवार ने संरचना की रक्षा करने का आश्वासन दिया। हालांकि, इनमें से किसी का भी कोई परिणाम नहीं निकला।
योजना।
उन दिनों इससे बचने के लिए कई नुस्खे प्रचलित थे।
impending crisis. Ved Pratap Vaidik, the editor of Bhasha and a friend
राव के एक रिश्तेदार ने 20 नवंबर 1992 को प्रधानमंत्री को फोन किया था और सुझाव दिया था कि वे
यदि आवश्यक हो तो अयोध्या में उपयोग के लिए रबर की गोलियां प्राप्त करें। वह और
रक्षा विश्लेषक के. सुब्रह्मण्यम उन तरीकों पर चर्चा कर रहे थे जिनसे
6 दिसंबर को कार सेवकों को बिना किसी को चोट पहुंचाए नियंत्रित किया जा सका।
उन्हें। प्रधानमंत्री हंसने लगे। अरे भाई, विश्व हिंदू परिषद ने वादा किया है कि
कार सेवा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की जाएगी। आरएसएस ने मुझे यह अधिकार दिया है।
वादा करो। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो?' राव ने कहा।

■

नवंबर और दिसंबर 1992 के पहले पांच दिनों के दौरान, राव ने कोशिश की
आरएसएस-वीएचपी-बीजेपी को कार सेवा स्थगित करने के लिए राजी करें जिससे उसे लाभ होगा
अधिक समय; उसने अपने विरोधियों को विभाजित और कमजोर करने के लिए चालें चलीं, जैसा कि हम
मैंने अभी-अभी देखा है। और उसने अपने लिए ऐसे झूठे बहाने बनाए जो उसे बचा सकते थे।
दोषारोपण से परे, अकल्पनीय घटना घटित हो सकती थी।
उन्होंने अदालतों, राष्ट्रीय एकता परिषद और यूपी से इस मामले में मदद की उम्मीद जताई।
राज्यपाल उसे किसी भी प्रतिकूल परिणाम से बचाने के लिए ढाल के रूप में कार्य करेगा।
यदि स्थिति और बिगड़ती है।
राव ने 23 नवंबर 1992 को एनआईसी की बैठक बुलाई। इसमें अधिकृत किया गया
प्रधानमंत्री को संरचना की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हों, वे उठाने होंगे।
हालाँकि यह केवल आधी अनुमति थी क्योंकि बैठक
भाजपा नेताओं द्वारा बहिष्कार किया गया। लेकिन एनआईसी बैठक के एक दिन बाद, 'प्रधानमंत्री ने
अंततः उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बलों को भेजने की अनुमति दे दी गई।
सचिव ने अयोध्या में 20,000 केंद्रीय बलों की तैनाती की, जो 'एकल सबसे बड़ी' तैनाती है।
स्वतंत्रता के बाद से ऐसे अभियान के लिए लामबंदी...। 26 तक
नवंबर में, वे अयोध्या में अपनी स्थिति संभाले हुए थे, अपनी कार्रवाई के लिए तैयार थे।
आदेशों का पालन न करने पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अप्रत्याशित रूप से कड़ा

विरोध जताया।
■

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहे थे।
मामला। राव को उम्मीद थी कि अगर वे स्पष्ट फैसले सुनाते हैं, तो इससे उन्हें बरी कर दिया जाएगा।
उन्हें किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
लगभग प्रतिदिन। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई जनहित याचिकाएँ थीं। इनमें से कई याचिकाएँ अवमानना की कार्यवाही थीं।
कल्याण सिंह सरकार पर उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है।
जुलाई 1992 में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि पर रोक लगा दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से स्पष्ट आश्वासन मांगा।
सरकार ने संरचना की रक्षा करने का वादा किया था। सरकार इससे असंतुष्ट थी।
कल्याण सिंह की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के साथ; इसने नियुक्ति की धमकी दी
कल्याण सिंह की संपूर्ण संपत्ति के 'प्राप्तकर्ता' के रूप में केंद्र सरकार।
आश्वासन संतोषजनक नहीं था। अंततः, कल्याण सिंह ने अदालत को यह बात बताई।
27 और 28 नवंबर 1992 को सुरक्षा के लिए स्पष्ट आश्वासन दिए गए।
संरचना का निर्माण करें, और 6 तारीख को कार सेवा के दौरान कोई भी निर्माण कार्य न करें।
दिसंबर।
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर विश्वास करना चुना।
■

राव द्वारा अगस्त 1992 में दोनों पक्षों के साथ बातचीत शुरू करने के बाद,
आरएसएस और भाजपा के नेताओं ने उनसे बार-बार आग्रह किया था कि वे
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में तेजी लाई गई। एल.के. आडवाणी ने कमल को बताया।

राव के वार्ताकारों में से एक नाथ ने कहा, 'फैसला चाहे जो भी हो, उससे मदद मिलेगी।'
राजेंद्र सिंह ने राव से उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निर्णय देने का भी अनुरोध किया।
न्यायालय। मूलतः, न्यायालय को यूपी की वैधता पर फैसला सुनाना था।
सरकार द्वारा 1991 में विवादित भूमि के 2.77 एकड़ का अधिग्रहण। यदि
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण को वैध माना और निर्माण कार्य को भी वैध ठहराया।
मंदिर का निर्माण कार्य वहीं से शुरू हो सकता था। यदि यह अवैध पाया जाता, तो भूमि
मूल मालिकों को वापस मिल जाएगा—2.09 एकड़ जमीन राम को मिलेगी।
जन्मभूमि न्यास, जिसने इसे और बाकी सब कुछ सुन्नियों को खरीदकर दिया था
इसके बाद वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली भूमि पर कार सेवा शुरू की जा सकती है।
न्यास। कल्याण सिंह ने न्यास को 42 एकड़ का एक बड़ा भूभाग हासिल करने में मदद की थी।
मार्च 1992 में संरचना के आसपास एकड़ भूमि।
शुरू में कमल नाथ ने आडवाणी के सुझाव को ठुकरा दिया था। यह बात स्पष्ट नहीं थी कि...
उन्होंने कहा कि अदालत से फैसला जल्द सुनाने का अनुरोध करना संभव है। लेकिन वह आए
अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में भाजपा नेता के पास वापस जाएं और उन्हें यह जानकारी दें।
एक और प्रस्ताव पेश करें। सरकार 2.77 सौंप देगी।
राम जन्मभूमि न्यास को एकड़ भूमि इस समझ के साथ दी जाएगी कि
कि न्यायिक फैसला आने तक जमीन को छुआ नहीं जाएगा। और
न्यास बदले में अदालत के दृष्टिकोण का पालन करने के लिए सहमत होंगे। जैसा कि उल्लेख किया गया है,

राम जन्मभूमि न्यास विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के सदस्यों द्वारा गठित एक ट्रस्ट था।
अयोध्या में एक मंदिर के निर्माण की देखरेख करना।

‘क्या यह भाजपा को स्वीकार्य होगा?’ नाथ ने आडवाणी से पूछा। ‘मैंने नहीं किया’ प्रस्ताव के बारे में कहने में एक मिनट भी संकोच न करें
'स्वीकार्य,' आडवाणी ने जवाब दिया।
कुछ दिनों बाद, राव ने अब सेवानिवृत्त हो चुके भाजपा-आरएसएस नेता को आमंत्रित किया।
Nanaji Deshmukh to meet him. During the conversation, Deshmukh
कमल नाथ के प्रस्ताव का जिक्र किया गया। देशमुख के आश्चर्य के लिए, राव ने
उन्होंने इस बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, 'ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।'
यह सर्वविदित था कि कमल नाथ रिपोर्ट करेंगे
आडवाणी के साथ हुई उनकी मुलाकातों की कार्यवाही प्रधानमंत्री को सौंपी गई। बाद में,
जब आडवाणी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो राव ने उनके मंत्रियों को तिरस्कारपूर्ण ढंग से संबोधित किया।
‘हर-फैन-मौला’ (हरफनमौला)।
कमल नाथ ने मुझे कई साल बाद बताया कि राव अपने वादे से मुकर गए थे।
पहले ही इस पर सहमति बन चुकी थी। कमल ने जोर देकर कहा, 'अडवानी ने जो कहा वह सही था।'
नाथ। हालाँकि राव ने शुरू में इस प्रस्ताव पर विचार किया था, लेकिन अंत तक
अक्टूबर 1992 में उन्होंने अपना मन बदल लिया था।
प्रधानमंत्री द्वारा अदालत से फैसले में तेजी लाने का अनुरोध करने से इनकार करना यह वार्ता के टूटने के कारणों में से एक था,’ किशोर कुणाल ने कहा।
बाद में कहना था। यह उन अनसुलझे रहस्यों में से एक बना रहा।
बाबरी मस्जिद कांड।
राव ने बाद में लिबरहान आयोग को बताया, जिसका गठन उन्होंने जांच के लिए किया था।
विध्वंस के संबंध में, 'केंद्र सरकार ऐसा कैसे कर सकती है?'
यदि वह कार्यवाही में पक्षकार न भी हो, तो भी अनुरोध कर सकता है, भले ही वह

ऐसा करना चाहता हो।
क्या राव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष यह बात बताई थी? क्या राव ने यह जानकारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय को दी थी?
मंदिर आंदोलन के प्रतिनिधियों ने अचंभित आडवाणी को देखा।
उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, 'हम कोई और रास्ता अपनाते।'
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख भी उतना ही विचित्र था।
इसने 4 नवंबर 1992 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
उस दिन अशोक सिंघल इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे थे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी ऐसा ही सोचते थे। सिंघल और न्यायाधीश ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत को अपना समय और विवेकाधिकार देना चाहिए।
फैसला जल्दी आएगा। मुख्य न्यायाधीश ने उनसे कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि फैसला आ जाएगा।
नवंबर के अंत से पहले। इससे पहले इस बात का ‘निजी तौर पर संकेत’ दिया गया था।
(सिंघल को) प्रधानमंत्री द्वारा।
भाजपा ने निष्कर्ष निकाला कि अयोध्या स्थित पीएमओ में 'प्रधानमंत्री के सलाहकार' सेल या खुफिया ब्यूरो ने उन्हें सलाह दी थी कि टकराव (अब) अपरिहार्य है और इसे बाद में होने के बजाय अभी करना बेहतर है।
चुनावों के लिए।'
यह फैसला 11 दिसंबर 1992 को आया था—मस्जिद के बाद
पूरी तरह से नष्ट हो गया है।
■

जुलाई 1992 से ही पी.वी. नरसिम्हा राव पर दबाव बढ़ता जा रहा था।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके बाद केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है।
राज्य पर सीधे शासन करें और मस्जिद की रक्षा करें। राव के आलोचकों का कहना है

कि...
कांग्रेस इसकी मांग कर रही थी। विपक्षी सांसद भी यही मांग कर रहे थे।
गृह सचिव माधव गोडबोले इस मुद्दे को उठाएंगे।
प्रधानमंत्री बार-बार मेरी बात सुनते थे। गोडबोले ने मुझे बताया, 'प्रधानमंत्री मेरी बात ध्यान से सुनते थे।'
दुःख भरे स्वर में, 'लेकिन वह ज्यादातर चुप ही रहता था... अंत में वह कहता था, "मुझे इस पर थोड़ा सोचने दीजिए।" और बात यहीं खत्म हो जाती।
यह कुछ ऐसा था जैसे एक पत्नी अपने पति से कहती है, "देखते हैं"—वास्तव में वह क्या करती है
इसका मतलब है "नहीं"। गोडबोले ने दावा किया कि उनकी योजना को उनके बॉस का समर्थन प्राप्त था।
गृह मंत्री चव्हाण।
उन्होंने सबसे पहले जुलाई 1992 में एक आकस्मिक योजना तैयार की थी, जब
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने अपनी कार सेवा का आयोजन किया था। इसे नवंबर 1992 में पुनः शुरू किया गया।
दरअसल, गोडबोले ने प्रस्ताव दिया था कि पहले कार्रवाई शीघ्रता से की जाए।
अनुच्छेद 355 के अनुसार, 22 नवंबर 1992 की मध्यरात्रि को यह कार्य संपन्न किया जाए। अनुच्छेद 355
इसने केंद्र सरकार को बाहरी खतरों से राज्यों की रक्षा करने का अधिकार दिया।
आक्रामकता और आंतरिक अशांति। इससे सुरक्षा बलों को मदद मिलेगी।
परिसर का तुरंत अधिग्रहण करने के लिए पर्याप्त 'पूर्व समय'—
आधी रात को। इसके बाद निम्नलिखित सूचना प्राप्त होगी:
अगले दिन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, जिससे
इसमें थोड़ा अधिक समय लग गया। गोडबोले ने तारीखों का चुनाव बहुत सावधानी से किया था—ऐसा करने से
सरकार को उद्घाटन दिवस पर अपनी कार्रवाई की घोषणा करने में सक्षम बनाना
संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर 1992 को हुआ था। वह जानता था कि
विपक्ष अयोध्या के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करेगा।
लेकिन राव को यह योजना कुछ खास पसंद नहीं आई। शरद पवार, जो

रक्षा मंत्री को भी राव से वही प्रतिक्रिया मिली जब उन्होंने
केंद्रीय शासन की वकालत की।
उत्तर प्रदेश में केंद्रीय शासन लागू करने के लिए उन पर बढ़ते दबाव को देखते हुए,
राव ने अपने बचाव के लिए यूपी के राज्यपाल को तीसरे बहाने के रूप में चुना।
उन्होंने कहा कि जब तक यूपी के राज्यपाल इसकी सिफारिश नहीं करते, वे केंद्र शासित प्रदेश शासन लागू नहीं कर सकते। गोडबोले इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि...'
राज्यपाल की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया जा सकता है... क्योंकि सरकार
उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा था,' गोडबोले ने कहा।
उन्होंने मुझसे कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री चंद्र द्वारा लिए गए एक उदाहरण का हवाला दिया।
शेखर ने 30 जनवरी को तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किया था।
1991 में उन्होंने गवर्नर एस. एस. बरनाला की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया था।
चंद्र शेखर ने मुझे बताया था कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है।
सत्ताधारी डीएमके के बारे में खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद
एलटीटीई की आतंकवादी गतिविधियों से सख्ती से निपटने की अनिच्छा।
उन्होंने राज्यपाल से एक रिपोर्ट मांगी थी, बरनाला ने उन्हें एक रिपोर्ट भेजी थी।
चंद्र शेखर ने अनौपचारिक रूप से यह सूचना दी कि वह इसे देने में असमर्थ हैं।
नरेश चंद्र से पत्र को सुरक्षित रखने के लिए कहा। 'मेरे पास अभी भी है'
'वह पत्र मेरी अलमारी में कहीं है,' चंद्र ने मुझे पुष्टि करते हुए कहा।
लेकिन राव ने जोर देकर कहा कि वह तभी कार्रवाई कर सकते हैं जब राज्यपाल इस संबंध में कोई मामला पेश करें।
राज्य में संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए राव ने केंद्रीय शासन की वकालत की।
बाद में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता।
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को 26 तारीख को दिल्ली बुलाया।
नवंबर। राज्यपाल बी. सत्य नारायण रेड्डी को नियुक्त किया गया था।
जब वी. पी. सिंह प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने रेड्डी को राज्यपाल नियुक्त किया था। रेड्डी आंध्र प्रदेश से थे।
प्रदेश, राव का गृह राज्य था। वे एक पुराने समाजवादी थे जो शामिल हो गए थे।

टीडीपी। लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि वे 'सरकार की अनुमति के बिना कुछ नहीं करेंगे।'
पीवी से आगे।
राज्यपाल रेड्डी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की।
दिल्ली। गृह मंत्री के साथ अपनी चर्चा के दौरान, उन्होंने इस बात पर सहमति जताई थी।
उन्होंने उसी शाम अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करने के लिए अपनी रिपोर्ट भेजी।
'संविधान,' गोडबोले ने याद किया। लेकिन फिर, राज्यपाल ने अचानक एक कदम उठाया।
उन्होंने गृह मंत्री से कहा कि यह उचित नहीं होगा।
मेरे लिए अनुच्छेद 356 के तहत कोई कार्रवाई करना। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए
सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में उन्होंने एक हलफनामा दायर किया था।
27 और 28 नवंबर 1992 को—और अदालत को आश्वासन दिया कि वह रक्षा करेगा
विवादित ढांचा। 1 दिसंबर 1992 को राज्यपाल रेड्डी ने एक संदेश भेजा।
प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र। उन्होंने इसके लिए ठोस तर्क दिए—लेकिन यह
राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध। वह इस हद तक चला गया कि...
यह कहते हुए कि राष्ट्रपति शासन विवादित ढांचे को खतरे में डाल देगा।
कई लोगों को संदेह था कि राज्यपाल रेड्डी राष्ट्रपति शासन के खिलाफ तर्क दे रहे हैं।
राव के कहने पर—प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार के दबाव से बचाने में मदद करने के लिए
नियम।
‘सत्य नारायण रेड्डी ने एक अक्षर भी नहीं लिखा होता,
राव से पूछे बिना अल्पविराम और पूर्ण विराम लगा दिया,’ एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, जिसे इस बात की जानकारी थी।
रेड्डी भी ठीक था। जब 6 दिसंबर 1992 को विध्वंस कार्य चल रहा था,
राज्यपाल रेड्डी राव से संपर्क करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे।
दोपहर में फोन पर बात हुई। वह कल्याण को स्वीकार नहीं करना चाहता था।

सिंह ने प्रधानमंत्री की सहमति के बिना ही इस्तीफा दे दिया।
यहां तक कि राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भी इस बारे में काफी चिंतित थे।
फोतेदार के अनुसार, राज्यपाल ने जो भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति
फोतेदार ने 6 दिसंबर 1992 को जब उनसे मुलाकात की थी, तब उन्होंने उन्हें यह बात बताई थी।
राज्यपाल के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र ने राव को बरी कर दिया और उन्हें एक तरह से छूट भी दे दी।
पूर्व-निवारण लेने में अपनी विफलता के लिए उन पर हुए हमले के समय यह एक उत्तम बहाना साबित हुआ।
बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए किए गए निर्णायक कदम। राव ने इसका हवाला दिया था।
बहुत समय बाद, यही कारण था कि उसके हाथ बंधे हुए थे।
ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्रियों ने किसी राज्यपाल से पूछने से परहेज किया हो।
किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई। कुछ ही महीने पहले, राव ने
उन्होंने खुद आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कृष्णकांत से इस पद को बदलने में मदद मांगी।
तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी, एक समय उनके
विजय भास्कर रेड्डी के साथ शिष्य। कांत ने उनसे कहा कि स्थिति ऐसी नहीं थी।
राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता नहीं है। और राव को राजनीतिक रूप से कार्य करना चाहिए (और नहीं)
राज्यपाल के माध्यम से)—यदि वह राज्य में सत्ता परिवर्तन चाहता था।
राव ने राजनीतिक सूझबूझ से काम लिया और अक्टूबर 1992 में जनार्दन रेड्डी की जगह ले ली।
■

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से एक दिन पहले की बात है।
राव वास्तव में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करने के सबसे करीब पहुंच गए थे।

30 नवंबर 1992 को उन्होंने सीसीपीए की बैठक बुलाई थी। सभी
समिति के सदस्य उपस्थित थे—राव के अलावा, वहाँ थे
गृह मंत्री एस.बी. चव्हाण, रक्षा मंत्री शरद पवार और
वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। एक अंतिम प्रयास में संकट को टालने के लिए।
भाजपा के साथ टकराव के मद्देनजर, सीसीपीए इस बात पर फैसला करने के लिए बैठक कर रही थी कि क्या
अयोध्या मामलों को अनुच्छेद 138(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाए।
संविधान के अनुसार यह निर्धारित किया जाएगा कि मंदिर अस्तित्व में था या नहीं।
मस्जिद। धारा 138(2) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण यह होगा कि
सभी पक्षों पर बाध्यकारी। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को खरीदना आवश्यक था।
योजना में।
राव ने कल्याण सिंह को दिल्ली बुलाया। सीसीपीए की कार्यवाही के दौरान
सत्र के दौरान, बेचैन कल्याण सिंह 5 बजे आगंतुक कक्ष में बैठे थे।
कोर्स रोड। एक ऐसे भावनात्मक युद्ध में (जिसमें राजनेता माहिर होते हैं),
प्रधानमंत्री ने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ देर इंतजार कराया।
फिर उन्होंने शरद पवार को उनसे बात करने के लिए भेजा। कुछ मिनट बाद, उन्होंने
वे उनके साथ शामिल हो गए। लेकिन बहुत जल्द, राव और पवार बैठक में लौट आए।
‘कल्याण सिंह ने अनुच्छेद 138(2) के तहत कार्रवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया है,’
असंतुष्ट राव ने अपने प्रतीक्षारत सहयोगियों से कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
केवल गैर-बाध्यकारी सलाहकारी संदर्भ स्वीकार करने के लिए तैयार
अनुच्छेद 143.
राव ने संक्षेप में कहा, 'राष्ट्रपति शासन अब अपरिहार्य हो गया है।'
उनके सहकर्मियों के आश्चर्य के बीच, उनके चेहरे पर उदासी और भी गहरी हो गई।
उन्होंने निर्णायक लहजे में कहा, 'गॉडबोले को कैबिनेट नोट तैयार करने दीजिए।' सीसीपीए
मान गया।
गोडबोले तेजी से नॉर्थ ब्लॉक की ओर वापस भागा। उसने ऊपर लिखे नोट को तैयार

किया।
गति। उसने इसकी पैंतालीस प्रतियाँ बनाईं। ये प्रतियाँ दी जानी थीं।
अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने भाग लिया, जो कि होनी थी...
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर औपचारिक निर्णय।
लेकिन अगला दिन एक अलग ही दिन था। मंत्रिमंडल की बैठक कभी नहीं हुई।
घटना घटित हुई। राव पीछे हट गए—और ऐसा करने के लिए उन्होंने 'प्रक्रिया' का सहारा लिया।
सामान्यतया, गृह मंत्रालय कैबिनेट सचिव को एक नोट भेजता था।
यह मामला कैबिनेट से मंजूरी चाहता था। इसके बाद कैबिनेट सचिव को...
इसे लगाने से पहले प्रधानमंत्री की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करें।
मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया। प्रधानमंत्री की मंजूरी कभी नहीं मिली।
■

राव उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना चाहते थे, इसके कई कारण थे।
कारण। वह बार-बार कहते थे कि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता।
'संवैधानिक व्यवस्था' के टूटने की आशंका में इसे लागू किया गया।
तंत्र व्यवस्था; केंद्रीय शासन लागू होने से पहले यह गड़बड़ी होनी ही थी।
लागू किया जाए।
कानूनी पहलुओं को छोड़ दें तो, राव इससे इसलिए कतराते क्योंकि उन्होंने देखा कि इसे राजनीतिक आत्मघाती कदम बताया गया। उनके विधि सचिव पी.सी. राव ने उन्हें समझाया कि
इससे सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कड़ी आलोचना हो सकती है। कानूनी आलोचना।
उन्होंने कांग्रेस में अपने सहयोगियों जैसे एन. डी. तिवारी को भी मौका दिया होगा।
प्रणब मुखर्जी और अर्जुन सिंह को वह मौका मिल गया जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे—उन पर हमला करने का। अन्य लोग भी ऐसा ही करते।
उन्होंने सत्ता के मनमाने इस्तेमाल के लिए उनकी निंदा की। भाजपा ने शायद ऐसा किया होगा।
उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिससे उन्हें डर था कि

भावनाओं में बह जाना।
राव यह कभी नहीं भूले कि वे अपनी पार्टी की 'समझौते वाली' पसंद थे।
वह अपने दम पर निर्वाचित नेता नहीं थे। दिसंबर 1992 में भी, वह अभी भी
उन्होंने अल्पमत सरकार का नेतृत्व किया। अगर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया तो...
वह यहीं नहीं रुकेगा—उसे अपनी रक्षा के लिए बल का प्रयोग करना पड़ सकता है।
मस्जिद, यदि मस्जिद की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाती है
केंद्र सरकार।
जब पी.वी. अयोध्या में होने वाली घटनाओं की कल्पना कर रहे थे... तब
नरेश चंद्र ने कहा, 'हवा में नहीं।' 'वह यह बात जानता था, यहाँ तक कि इसके बाद भी।'
राष्ट्रपति शासन के तहत उसे "बहुत से लोगों को गोली मारनी पड़ सकती है"। लोग सोचते हैं
अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा...(अगर ऐसा हो जाए तो)
(यदि ऐसा होता) तो कश्मीर की समस्या हल हो जाती, पंजाब की समस्या हल हो जाती
गलतियों को सुधारा गया है। रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार, कम से कम 50 से
अगर अयोध्या में राष्ट्रपति शासन लागू होता तो 100 लोग मारे जाते।
थोपा गया। और यह रिपोर्ट और मौखिक प्रस्तुति थी जो दी गई थी।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, कोई कम नहीं।
यह एक ऐसा जोखिम था जिसे राव उठाने के लिए तैयार नहीं थे। यह एक अलग बात है कि
मस्जिद की सुरक्षा में हुई विफलता के कारण लगभग 1,000 लोग मारे गए।
देश में फैले सांप्रदायिक दंगों में मारे गए लोग
विध्वंस।
राव ऐसे हालात पैदा कर सकते थे जिससे सजा थोपने को जायज ठहराया जा सके।
केंद्रीय शासन—एक ऐसा मार्ग जिसे अपनाने में कई नेताओं को कोई आपत्ति नहीं है।
'मान लीजिए पी.

वी. नरसिम्हा राव ने मुझ जैसे मुंशी (प्रबंधकों) को पूरी छूट दे रखी थी।
Naresh Chandra told me, ‘ki yaar dekho isko kisi tarah se President’s
नियम बनाना है (देखो, मेरे दोस्त, हमें किसी तरह लागू करना होगा)
राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, आप प्रशासनिक रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जिससे
इसे सही ठहराएं।'
चंद्र सरकार की गंदी चालों का इस्तेमाल करने का संकेत दे रहे थे।
विभाग (डीटीडी)। डीटीडी अवैध और
सरकार के इशारे पर उठाए गए निम्न स्तर के कदम—नीचे गिराने के लिए
इसके विरोधियों। प्रधानमंत्री कार्यालय, विभिन्न प्रधानमंत्रियों के अधीन।
मंत्रियों पर अक्सर गंदी चालें चलने के आरोप लगते रहे थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्रियों पर भी यही आरोप लगे थे।
राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी ने एक बार सीबीआई को 'गंदी चालों का विभाग' कहा था, क्योंकि यह कुख्यात रूप से कई गुप्त और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाइयां करती थी।
सरकार।
चंद्र ने फिर अनकहा सवाल उठाया: 'आप कितनी दूर हैं?'
क्या आप देश के लिए उस रणनीतिक लाभ को हासिल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसकी अनुमति देते हैं?
राज्य द्वारा व्यापक हित में कुछ बुरे कार्य किए जाने चाहिए।
राज्य? मुझे लगता है कि भारत में हमने इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।
क्योंकि यह एक खतरनाक स्थिति है।'
चंद्र के अनुसार, राव की सरकार में शीर्ष नौकरशाह थे
वे उससे ऐसा सवाल पूछने में भी हिचकिचा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था।
इसे कैसे स्वीकार किया जाएगा।
‘(हालांकि) ये अपरंपरागत विकल्प...परिणाम दे सकते थे’,
उन पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया था। अगर राव ने इन विकल्पों के बारे में सोचा होता,
उन्होंने यह बात किसी के साथ साझा नहीं की, यहां तक कि मेरे साथ भी नहीं।

■

2 दिसंबर 1992 को—उनके असफल मिलन के तीन दिन बाद—
कल्याण सिंह राव ने मणि शंकर अय्यर को फोन किया। सुबह के 5 बज रहे थे।
दिल्ली की अंधेरी, ठंडी सुबह। आँसुओं से भरी आवाज़ में उसने अपनी बात कही।
अयोध्या में बढ़ते तनाव के प्रति अपनी बेबसी को देखते हुए, उन्होंने अय्यर की मदद मांगी।
सलाह। भोर होते ही, चिंतित अय्यर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दौड़ पड़े।
राव ने सुझाव दिया कि वे अयोध्या में सांसदों की एक सर्वदलीय टीम भेजें—
इससे स्थिति को शांत करने में मदद मिल सकती है। राव ने अय्यर से सहमति जताई।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
कुछ नहीं। संभव है कि उसने अय्यर से संपर्क करके कुछ संदेश भेजा हो।
उत्तेजित सोनिया गांधी और चिंतित धर्मनिरपेक्षवादियों को संदेश देते हुए कि वह
वह इस मुद्दे को लेकर चिंतित थे और अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे थे।
अय्यर, अपने
गांधी परिवार से निकटता और उनकी स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष साख,
उस संदेश को संप्रेषित करने का यही सबसे अच्छा साधन था।
3 दिसंबर को स्थिति और भी गंभीर हो गई, जब भाजपा ने
नेता एल. के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने अपनी यात्राएं शुरू कीं।
वाराणसी और मथुरा से लोगों को 6 तारीख को कार सेवा के लिए जुटाने हेतु अभियान चलाया जाएगा।
दिसंबर।
5 दिसंबर 1992 की सुबह, एक अंतिम प्रयास किया गया था।
नरेश चंद्र और बी. पी. सिंघल, एक नौकरशाह जो शामिल हुए थे
भाजपा—और जैसा कि हम देख चुके हैं, वीएचपी नेता अशोक सिंघल कौन थे?
भाई। उन्होंने फैसला किया कि यूपी सरकार याचिका दायर करेगी।
उसी दोपहर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया कि कम से कम निर्णय का मुख्य भाग तुरंत सुनाया जाए—और उसकी याचिका

केंद्र सरकार का समर्थन प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार
केंद्र ने अपनी दलील पेश की। लेकिन केंद्र के वकील अदालत में पेश नहीं हुए।
एक दिन पहले, 4 दिसंबर को, राव ने प्रतिद्वंद्वी-सह-मंत्रिस्तरीय-
अयोध्या विवाद पर उनके सबसे कड़े आलोचक रहे सहयोगी अर्जुन सिंह उत्तर प्रदेश चले गए।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में पर्याप्त व्यवस्था की गई है
मस्जिद की रक्षा करना। इसका उद्देश्य सिंह को हमला करने से रोकना था।
बाद में प्रधानमंत्री को सूचित किया गया—अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। सिंह वापस आए और सूचना दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिति 'नियंत्रण में' है।
लेकिन अपनी आत्मकथा में अर्जुन सिंह ने लिखा है कि वे लखनऊ गए थे।
उन्होंने अपनी मर्जी से कल्याण सिंह के साथ नाश्ते पर मुलाकात की।
उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार अयोध्या नहीं गए, क्योंकि कल्याण सिंह ने उन्हें बताया था।
इससे वहां जमा हुए कार सेवकों में आक्रोश फैल जाएगा।
दिल्ली लौटने पर अर्जुन सिंह ने गृह सचिव को फोन किया।
गोडबोले ने पूछा, 'तो अब सब कुछ सुरक्षित है, गृह सचिव साहब?'
गोडबोले। 'क्या मैं अपने समारोह में जा सकता हूँ?' उन्होंने कहा कि उन्हें एक कार्यक्रम में शामिल होना था।
6 दिसंबर को दिल्ली के बाहर आयोजित कार्यक्रम। गोडबोले, एक सीधे-सादे नागरिक हैं।
नौकर को 'समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था।' नरेश चंद्र ने मुझे बताया।
सिंह राजधानी छोड़ने की योजना बना रहे थे ताकि अगर हालात बिगड़ें तो वे वहां से जा सकें।
6 दिसंबर को स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी, वह कह सकता था कि उसे आश्वासन दिया गया था।
शीर्ष अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सब कुछ नियंत्रण में है। मौके पर मौजूद न होने के कारण।
इससे उसे बदलती हुई स्थिति में अधिक विकल्प भी मिलेंगे।

स्पष्टवादी गोडबोले ने अर्जुन सिंह को सारी जानकारी दे दी।
उसने फैजाबाद में जो कंपनियां, वाहन और सशस्त्र बटालियनें भेजी थीं।
Arjun Singh then rang Naresh Chandra. 'Toh bhai Naresh
चंद्राजी, अब सब कुछ आपके नियंत्रण में है। बस इतना ही।
समारोह, मैंने जाने का वादा किया है, तो मैं चला जाता हूं।'
अर्जुन सिंह की मंशा समझकर चंद्र ने जवाब दिया, 'सर, हम लोग'
kya control karenge, humaare control mein hi nahi hai (Officers in
दिल्ली के पास कोई अधिकार नहीं हैं, न ही वे किसी चीज की गारंटी दे सकते हैं।
सिंह ने कहा, 'लेकिन गोडबोले यह कह रहे थे...'
चंद्र: 'उन्होंने वहां सेना भेज दी है... गृह मंत्रालय ने
प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में बैठे सेवानिवृत्त अधिकारियों की तुलना में अधिक नियंत्रण। और
आप जानते हैं, महोदय, सलाहकारों को कोई कार्रवाई करने की अनुमति नहीं होती। उन्हें केवल बात करनी होती है।'
सिंह ने कहना शुरू किया, 'नहीं, नहीं, तो क्या आपको लगता है कि...'
चंद्र ने बीच में ही टोकते हुए कहा, 'देखिए साहब, मेरा ज्ञान इतना अच्छा नहीं है।'
और आपकी तरह ही नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लखनऊ में थे। और आपने (यूपी के) मुख्यमंत्री से बातचीत की है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमें कुछ जानकारी देंगे।
मार्गदर्शन का।
अर्जुन सिंह बचाव की मुद्रा में आ गए और बोले, 'यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि'
सब कुछ नियंत्रण में है...' और फिर उसने अचानक फोन काट दिया।
■

किशोर कुणाल ने कहा, '4 दिसंबर को मैंने नरेश चंद्र से पूछा था।'
बाद में बताते हुए उन्होंने कहा, 'सर, 250 कंपनियां अयोध्या गई हैं, डेढ़
कल लाख कार सेवक वहां पहुंच गए, परसों क्या होगा?

कल?'
'मैंने अभी-अभी नरसिम्हा रावजी से यही सवाल पूछा था,' चंद्र ने जवाब दिया।
वह अभी-अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से लौटे थे।
'The PM told me, "Maain Supreme Court ke dwaar par Hanumanji
मैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पर बैठा हूँ (मैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पर बैठा हूँ)
हनुमान जी ने भगवान राम के द्वार पर जिस प्रकार निर्देश दिए थे, उसी प्रकार निर्देश प्राप्त करने के लिए।
'Jaisa Supreme Court ka direction hoga, waisa hi karna hai (I will do
जो अदालत निर्देश देती है,' राव ने चंद्र से कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना किया कि उसने एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की।
मेरठ को अयोध्या में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अनुरोध किया गया ताकि वह उसकी आंख और कान का काम कर सके।
उसे मंदिर नगर में चल रही घटनाओं की जानकारी हर दिन अदालत को देने के लिए कहा गया था।
आधा घंटा। उसे संवाद करने के लिए एक वायरलेस सेट भी दिया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय!
'राज्य ने अपनी सत्ता का त्याग कर दिया है,' कुणाल ने उत्तेजित होकर टिप्पणी की।
उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर 'वास्तव में बहुत चिंता' थी।
6 दिसंबर को दोपहर के समय कुणाल को लेफ्टिनेंट का फोन आया।
जनरल एस. के. सिन्हा, जो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। 'बाबरी मस्जिद'
गिर गया है।
'यह कैसे हो सकता है?' कुणाल चौंक गया। 'इतनी बड़ी ताकत कैसे हो सकती है?'
वहाँ तैनात।
सिन्हा ने जवाब दिया, 'बीबीसी यही कह रहा है।'
उन्होंने तुरंत राम चंद्र परमहंस को फोन किया जो नेतृत्व कर रहे थे।
राम जन्मभूमि न्यास कुणाल उन्हें वर्षों से जानते थे।
परमहंस ने किशोर को अपनी योजना के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था।

Kunal, ‘Hum log usko gira karke, leepa-pothi karke, sab baraabar kar
हम इसे गिरा देंगे, जमीन को समतल कर देंगे,
और चीजों को फिर से व्यवस्थित करें)।’ बिल्कुल यही हुआ।
नौवीं

6 दिसंबर 1992—जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी—वह रविवार का दिन था।
बाद में इसे 'ब्लैक संडे' के नाम से याद किया जाएगा। उस दिन की घटनाएँ
उस दिन ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, और उस दिन का अंतिम शब्द यही था।
कहानी अभी तक लिखी नहीं गई है।
हालांकि सप्ताहांत था, फिर भी सुबह 9:30 बजे तक वेद प्रताप वैदिक
संसद स्ट्रीट स्थित प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भवन में उनका कार्यालय।
मध्य दिल्ली।
वैदिक नरसिम्हा राव के मित्र भी थे। ‘नरसिम्हा राव मेरे मित्र हैं’
वह दावा करता था, 'सबसे करीबी दोस्त।' हालाँकि कुछ ऐसे भी थे जो...
मुझे लगा कि वह बस कुछ नामों का जिक्र कर रहा था, जो पत्रकारिता में असामान्य नहीं है।
प्रधानमंत्री के करीबी सूत्रों और उनके चबूतरे के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके समर्थन की पुष्टि की।
राव के निकट। उस सुबह, कार्यालय जाने से पहले, वैदिक ने
राव ने फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा, 'आप कैसे हैं?'
‘Haath par haath dhare baithe hain,’ Rao replied non-commitally.
‘Dekhein aapke mitra log kya karte hain (I am sitting here twiddling
मेरे अंगूठे। देखते हैं तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं।' वहाँ एक था
प्रधानमंत्री के शब्दों में अंतर्निहित व्यंग्य था। वे वैदिक के संदर्भ में बात कर रहे थे।
आरएसएस और भाजपा में उनके 'मित्र'—जिनमें से कई उनके भी मित्र थे।

वैदिक आरएसएस के कई प्रमुख व्यक्तियों के करीबी थे, विशेष रूप से
इसके वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह थे। वैदिक कई वरिष्ठ नेताओं से मिल चुके थे।
आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ उनके पिता, जो आरएसएस के एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं।
इंदौर में आर्य समाज आंदोलन, जिसे आरएसएस ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी—
और बाद में वैदिक को पत्रकार के रूप में उनसे परिचय हुआ।
अपनी तमाम हंसी-मजाक के बावजूद, राव और वैदिक चिंतित व्यक्ति थे।
सुबह, आने वाले घंटों में क्या होगा, इस बात को लेकर चिंतित। वैदिक
उन्होंने योगेश माथुर नाम के एक प्रतिभाशाली पत्रकार को अयोध्या भेजा था और उनसे कहा था कि
भाषा को ही सबसे पहले इस घटना की खबर देनी पड़ी।
अयोध्या में उस दिन। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनका संगठन पहला था।
मीडिया संस्था ने यह खबर प्रकाशित की। 'पीटीआई ने इसे हमसे लिया।'
उन दिनों मोबाइल फोन नहीं होते थे। वैदिक को पता था कि सार्वजनिक टेलीफोन जानकारी अविश्वसनीय हो सकती है। जब कोई गड़बड़ी हो रही हो तो वह जोखिम नहीं उठा सकता था।
अयोध्या जैसी बड़ी खबर सुर्खियों में आने ही वाली थी। उसने एक पुराने व्यक्ति को फोन किया।
मेरी दोस्त शीतला सिंह, जो जन मोर्चा नामक एक संगठन चलाती थीं,
फैजाबाद। उन्होंने सिंह से कहा, 'मुझे टेलीफोन की सुविधा चाहिए। मेरा फोन
'आपका,' सिंह ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया।
■

राव का दिन सुबह 7 बजे शुरू हो गया था—वैदिक के फोन आने से काफी पहले।
उन्होंने सबसे पहले मंदिर के प्रमुख नेता और भाजपा नेता विनय कटियार को फोन किया था।
वह अयोध्या की स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी चाहते थे।
राव ने कुछ महीने पहले कटियार की खेती शुरू की थी।

भाजपा के कारण एल.के. आडवाणी के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे।
नेता ने हर्षद मेहता स्टॉक घोटाले में राव की भूमिका की आलोचना की थी।
अप्रैल 1992 में, उन्हें सूचना प्राप्त करने के लिए भाजपा में वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता थी।
'चिंता मत करो,' कटियार ने राव को आश्वस्त करते हुए कहा। 'कार सेवा तो बस कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी।'
'यह प्रतीकात्मक है, जैसा कि हमने तय किया था।'
कटियार को फोन करने के बाद ही प्रधानमंत्री ने सूचना सूचना विभाग के प्रमुख वी. से बात की।
जी वैद्य. वैद्य ने बताया, 'कारसेवा की तैयारी चल रही है।'
प्रधानमंत्री ने फिर अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या का पालन किया।
ट्रेडमिल पर व्यायाम, नाश्ता और एक शारीरिक परीक्षण
उनके चिकित्सक, डॉ. श्रीनाथ रेड्डी भी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे।
वे अंग्रेजी और तेलुगु के बीच-बीच में बातचीत करते हुए उस विशाल क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे।
अयोध्या में बड़ी संख्या में कार सेवक एकत्रित हुए, जो अखबारों के पहले पन्ने की खबर थी।
उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी।
फिर एक और कॉल आया। राव ने उसे उठाने का फैसला किया। यह कॉल उस तरफ से था।
तांत्रिक एन. के. शर्मा, जो आलोचकों से निपटने में उनकी मदद कर रहे थे
जैसा कि पहले देखा गया है, शर्मा ने पार्टी में 'राजनीतिक मध्यस्थ' की भूमिका भी निभाई थी।
राजीव गांधी के दरबार में। 'अर्जुन सिंह गुस्से में हैं,' शर्मा ने उन्हें चेतावनी दी।
'आपके वफादार उस पर हमला कर रहे हैं।' जैसा कि उल्लेख किया गया है, अर्जुन सिंह ने
अयोध्या के मुद्दे पर पर्याप्त कदम न उठाने के लिए राव पर हमले का नेतृत्व कर रहे हैं।
सिंह इस बात से नाराज थे कि राव के समर्थकों ने जवाबी हमला कर दिया था।

उसके खिलाफ।
फोन कॉल खत्म होने के बाद, राव अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गए।
वह इस पर घंटों काम कर सकता था, यह उसका पसंदीदा शौक था।
यह तनाव दूर करने का भी एक अच्छा तरीका था। हालांकि राव एक पुराने जमाने के राजनेता थे,
अपने कबीले के उन कुछ लोगों में से एक जो नई तकनीक से सहज हैं।
उन्होंने 1985 में कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जो उनके कई साथियों से बहुत पहले की बात है।
उसके सहकर्मी भी जानते थे कि वह कैसा दिखता है। उसने अपने छोटे सहकर्मी से पूछा था।
राजीव की एक उपहासपूर्ण टिप्पणी के बाद, बेटे प्रभाकर ने उसके लिए एक लाने का फैसला किया।
तत्कालीन प्रधानमंत्री गांधी ने कहा था कि 'मेरी पार्टी के पुराने नेता ऐसा नहीं करेंगे'
कंप्यूटर आयात करने की उनकी इच्छा को समझना।
रविवार होने के कारण प्रधानमंत्री का कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था।
उनके डॉक्टर के अलावा, उस सुबह उनसे मिलने कोई और नहीं आया था। आर. के. खांडेकर,
प्रधानमंत्री के विशेष कर्तव्य पर तैनात अधिकारी (ओएसडी) ने याद किया कि स्थिति कितनी 'भयानक' थी।
राव ने देखा। ‘उस दिन उसके मन में बस एक ही बात थी और वो ये थी कि...’
बाबरी मस्जिद।
सुबह करीब 10:30 बजे, बेचैन प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया।
सचिव, एस. राजगोपाल। 'क्या हो रहा है?'
‘मैं दफ्तर के लिए निकल रहा हूँ, महोदय, मैं आपको सूचित करूँगा,’ राजगोपाल ने कहा।
जवाब दिया। रविवार को राजगोपाल आमतौर पर अपने बुजुर्ग से मिलने जाया करते थे।
मां। 'मैं जाने ही वाली थी कि उनसे मिलने जाऊं, लेकिन फिर मैंने जाने का फैसला किया।'

'इसके बजाय ऑफिस जाओ।' वह अपने बॉस की तरह ही इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या होगा।

उस दिन ऐसा हुआ। उन्होंने कैबिनेट सचिव का पदभार केवल चार दिन पहले ही संभाला था।

कुछ महीने पहले। राव ने वास्तव में अयोध्या के मुद्दे पर उन्हें शामिल नहीं किया था—सिवाय इसके।

कैबिनेट समिति की बैठकों में जो भी मुद्दे उठे, उनके लिए

राजनीतिक मामले।

अयोध्या मुद्दे की दिन-प्रतिदिन की जिम्मेदारी इनमें निहित है।

गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में अयोध्या प्रकोष्ठ के साथ मिलकर,

नरेश चंद्र के नेतृत्व में अयोध्या प्रकोष्ठ से 'मार्गदर्शन' की अपेक्षा की गई थी।

प्रधानमंत्री को गृह सचिव पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने गृह सचिव को नियुक्त करने का फैसला किया।

मंत्रालय अपनी इच्छानुसार स्थिति से निपट सकता था। राव यह जानते थे कि

गृह सचिव माधव गोडबोले एक ईमानदार अधिकारी थे और सर्वश्रेष्ठ थे।

आप उसे पा सकते थे, लेकिन आपने उसे 'अपनी राय पर अड़े रहने वाला और हठी' पाया।

राव से बात करने के कुछ घंटों बाद वैदिक के फोन की घंटी बजी।

क्या योगेश माथुर लाइन पर थे? रिपोर्टर की उत्साहित आवाज लड़खड़ा गई।

on the line. ‘Pehla dome gir gaya hai (The first dome has fallen),’ he

उसने अपने बॉस को बताया। वैदिक हैरान रह गया। उसने रिसीवर नीचे रख दिया, और

उसने प्रधानमंत्री का नंबर डायल किया। बिना किसी भूमिका के, उसने प्रधानमंत्री को बताया

जो उसने सुना था। राव को पहले ही खबर मिल चुकी थी। 'हां, वैद्य ने मुझे फोन किया था।'

राव ने कहा, 'आरएएक्स पर। उसने मुझे बताया।'

■

6 दिसंबर की सुबह अयोध्या में बादल छाए हुए थे। लाखों करदाता
सेवक बाबरी मस्जिद के पास इकट्ठा होने लगे थे।
The kar sevaks had washed the Ram Chabutra that morning.
लगभग 500 साधुओं ने प्रतीकात्मक पूजा करने के लिए उस पर बैठकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कहा कि...
नेता एल. के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचे। उनके साथ संस्थापक-अध्यक्ष विनय कटियार भी थे।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की युवा शाखा बजरंग दल और अशोक सिंघल।
विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष। मंदिर को स्थापित करने में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
मुद्दा केंद्र बिंदु बन गया। उन्हें देखकर भीड़ उत्साहित हो गई। कटियार और
सिंघल उस मंच की ओर बढ़े जहाँ उन्हें संबोधित करना था।
सभा।
दोपहर से ठीक पहले, लगभग 150 लोग अचानक किले की दीवार तोड़कर अंदर घुस गए।
सुरक्षा घेरा टूट गया। उन्होंने वहां खड़े पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।
वहाँ। कुछ ही मिनटों में, लगभग एक हजार लोग ऊपर चढ़ गए थे।
मस्जिद के चारों ओर खड़ी की गई बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुस गए।
इमारत। इमारत की रखवाली कर रहे पुलिस बलों ने कमजोर सुरक्षा व्यवस्था अपनाई।
प्रतिरोध किया—लेकिन वे बह गए। दोपहर 12.20 बजे तक, लगभग अस्सी
भीड़ के सदस्य गुंबदों के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए थे, और
वहाँ भगवा झंडे फहराए गए। फिर एक उन्मादी विध्वंस शुरू हुआ।
फावड़े, लोहे की छड़ें और कुल्हाड़ी। कुछ ही मिनटों में, भीड़ के भीतर
बैरिकेड्स की संख्या बढ़कर 25,000 हो गई थी। 'जैसे-जैसे कार सेवक बैरिकेड्स को हटाते गए...'
वहाँ मौजूद भाजपा-विश्व हिमाचल प्रदेश-आरएसएस के कुछ नेताओं ने संरचना के संबंध में दलीलें दीं।

'उन्हें रोकने के लिए,' नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक में लिखा था।
घटना घटी। लेकिन किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। बाबरी मस्जिद
महज चार घंटे से कुछ अधिक समय में इसे ध्वस्त कर दिया गया। शाम 4:55 बजे तक सारा काम खत्म हो चुका था।
चारों ओर अविश्वास का माहौल था। कई लोगों ने सोचा था कि जब तक
भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी थे।
वे किसी न किसी तरह मस्जिद को रोकने का रास्ता निकाल लेंगे।
नुकसान होने से। वह विश्वास महज भोलापन साबित हुआ।
■

फोटोग्राफर प्रवीण जैन दो दिन पहले अयोध्या पहुंचे थे।
कार सेवा को कवर करने के लिए। वह द पायनियर के साथ काम कर रहे थे और रहे थे।
उन्हें यह कार्य उनके संपादक विनोद मेहता द्वारा सौंपा गया था। 4 दिसंबर 1992 को, जैन की मुलाकात भाजपा सांसद बी. एल. शर्मा उर्फ प्रेम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी।
सम्मेलन। यह ब्रीफिंग विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा मीडियाकर्मियों के लिए आयोजित की गई थी।
अयोध्या में उपस्थित थे। अशोक सिंघल प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थे।
पत्रकारों को 6 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहचान पत्र दिए गए थे।
1992.
जैन प्रेम को वर्षों से जानते थे। 'मैं उन्हें तब से जानता था जब वह...'
वह दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस में प्रेस विज्ञप्तियां लेकर आते थे। तब से वह मेरे दोस्त थे। बाद में, वह सांसद बन गए... मैंने उनसे पूछा था कि क्या
जैन ने कहा, 'यह 6 दिसंबर को होगा।'
जवाब में, प्रेम ने जैन के साथ घटनास्थल पर जाने की पेशकश की।
मुझे वीएचपी का एक (पहचान) कार्ड और एक पीला कार सेवक स्कार्फ दिया गया।

इससे मुझे वीएचपी फोटोग्राफर के रूप में (उस क्षेत्र में) प्रवेश करने की अनुमति मिली... “अगर कोई भी
आप कुछ भी पूछें, आप कह देते हैं कि आप वीएचपी से हैं।
5 दिसंबर को जैन घटनास्थल पर पहुंचे। वहां कोई और मौजूद नहीं था।
वहां मीडियाकर्मी मौजूद थे। 'मैंने बिना किसी समस्या के तस्वीरें खींचीं।'
वहाँ कुछ नकाबपोश (मास्क पहने हुए) लोग थे जिनके चेहरे
वे मस्जिद को गिराने का प्रशिक्षण दे रहे थे।
जैन ने कहा, ‘उनके पास छड़ें और हथौड़े थे। सब कुछ पहले से तय था।’
मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले दिन भी इसी विधि का प्रयोग किया गया था।
मस्जिद तोड़ दो। उनके पास रस्सियाँ भी थीं। वहाँ एक छोटा सा टीला था, एक
वहाँ ज़मीन का एक उठा हुआ टुकड़ा था। लोग... इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, इसका इस्तेमाल करते हुए।
रस्सियों के मामले में...(वे) पूरी तरह से पेशेवर लोग थे।
जैन को याद आया, 'वे इसे कैसे तोड़ेंगे?' उसी शाम उन्होंने ये भेजे।
उन्होंने दिल्ली स्थित अपने संपादक को तस्वीरें भेजीं। लेकिन कार्यालय ने 'इंतजार करने' और 'होने' का फैसला किया।
'ज़रूर।' 'उस समय, किसी को भी वास्तव में विश्वास नहीं था कि बाबरी मस्जिद को नष्ट किया जा सकता है।' '
अगले दिन नष्ट हो गया।
■

5 दिसंबर की रात को एक गुप्त बैठक आयोजित की गई थी।
अयोध्या। आरएसएस और वीएचपी के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे; वे गए।
अगले दिन की योजना पर चर्चा हुई। यह तय किया गया कि जब संत और
साधु योजना के अनुसार चबूतरे पर कार सेवा करेंगे,
यह हमला दक्षिण और पूर्व दिशा से होगा।
वीएचपी की गुप्त योजना को तड़के तक अंतिम रूप दिया जा रहा था।

सुबह। कार सेवकों को अयोध्या को 'सील' करने का आदेश दिया गया था।
लोहे की छड़ों और बैरिकेड्स जैसी कई बाधाएँ क्यों पाई गईं?
फैजाबाद-अयोध्या रोड पर स्थित इस इमारत को ध्वस्त करने का कार्य जारी है।
उन्हें पाँच समूहों में बाँटा गया था। इनमें से एक समूह को यह निर्देश दिया गया था कि वह
मीडिया को चुप करा दिया जाए, बलपूर्वक भी, यदि आवश्यक हो। विध्वंस के दिन,
जैन और अन्य मीडियाकर्मी तीन मंजिला इमारत की छत पर थे।
मस्जिद से कुछ ही दूरी पर स्थित इमारत ताकि पूरे दृश्य का अच्छा नजारा मिल सके।
क्षेत्र। उन्होंने उन्मादी कार सेवकों को बाबरी मस्जिद में प्रवेश करते और शुरू करते देखा।
कुल्हाड़ी से उसे नष्ट करने के लिए। जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई, लोगों का एक समूह उस इमारत में आ गया जहाँ पत्रकार तैनात थे।
उन्होंने खुद ही उन्हें पीटना शुरू कर दिया, और पहचान पत्र के आधार पर उनकी पहचान की।
उनके गले में कार्ड लटके हुए थे। उन्होंने फोटोग्राफरों पर हमला किया, तोड़फोड़ की।
अपने कैमरों के साथ, उन्होंने विशेष रूप से विदेशी पत्रकारों को निशाना बनाया। कई लोग भाग गए।
अपनी जान बचाने के चक्कर में, अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए।
मैं सबसे पहले उस मंच की ओर दौड़ा जहां से भाजपा नेता आए थे।
जैन ने याद करते हुए कहा, 'मैंने भीड़ को संबोधित किया। मैंने आडवाणी से विनती की, जो जानते थे कि...'
दिल्ली से मीडियाकर्मियों ने व्यक्तिगत रूप से मदद करने के लिए कहा। लेकिन वे ऐसे दिख रहे थे...
दूसरी तरफ। फिर जैन दौड़ते हुए अपने होटल, शान-ए-अवध पहुंचे।
जिस तरह से, 'मैंने मुस्लिम घरों को आग लगाते हुए भयावह रूप से देखा।' दंगे
तब तक विद्रोह छिड़ चुका था। वर्षों बाद, प्रवीण जैन उस घटना को फिर से याद करेंगे।
उस काले रविवार का आघात जब उन्हें एक मामले में गवाही देनी पड़ी थी
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामलों में और लखनऊ अदालत के समक्ष गवाही दी गई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ।
■

त्रासदी वाली सुबह दिल्ली में सर्दियों की सुहावनी धूप खिली हुई थी।
धूप खिली हुई थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुबह करीब 10 बजे एकत्रित हुए थे।
पार्टी कार्यालय 11, अशोका रोड पर स्थित है। वे बाहर लॉन में एक साथ बैठे थे।
वह विशाल बंगला। उन दिनों दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था।
बाद के वर्षों में यह धुंध की एक प्रदूषित परत से ढक जाएगा। 'सूर्य ऐसा था जैसे
'हवा में हल्की ठंडक के साथ मीठी गर्माहट ताजगी का एहसास करा रही थी,' के.
आर. मलकानि
बाद में उन्हें याद किया गया। वे भाजपा के उपाध्यक्ष थे और
आरएसएस के मुखपत्र 'ऑर्गेनाइजर' के संपादक।
देश भर के कई लोगों की तरह, वे भी अयोध्या से खबर आने का इंतजार कर रहे थे।
भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुंदर सिंह भंडारी अभी-अभी लौटे थे।
अयोध्या से। वह अपने देखे हुए के बारे में विस्तार से बता रहा था—दो लाख
कार सेवा अर्पित करने के लिए उत्साही लोग मंदिर नगर में एकत्रित हुए।
उस सुबह एक लाख और लोगों के उनके साथ जुड़ने की उम्मीद थी।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, मार्ग दर्शक मंडल,
उन्होंने घोषणा की थी कि कार सेवा केवल 'नाममात्र' होगी। कार सेवकों ने
यह केवल पहले से खोदे गए एक गड्ढे में मिट्टी ले जाएगा जो ठीक दक्षिण में स्थित है।
राम जन्मस्थान (वह स्थान जहाँ भगवान राम का जन्म माना जाता है)
वे (जन्म के समय) उसे भरते थे। फिर वे पास की नदी से पानी लाते थे।
सरयू, और उस प्लेटफॉर्म को धोना जो उन्होंने जुलाई में पहले बनाए थे।
kar seva.
मलकानि पहले से ही उस प्रेस नोट का मसौदा तैयार कर रहे थे जिसे उन्हें जारी करना
था।
शाम को मीडिया को जारी किया गया। अचानक, मलकानि ने भाजपा राज्य देखा।
विधानसभा सांसद अश्विनी कुमार कार्यालय से जल्दी से बाहर निकले।

उसने मलकानि के कान में फुसफुसाते हुए कहा, 'हमें अब प्रेस नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी।'
मलकानि दौड़कर अंदर गया। उसे बताया गया कि सुंदरलाल पटवा ने फोन किया था।
अयोध्या से खबर आई थी कि मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। पटवा प्रमुख था।
मध्य प्रदेश के मंत्री कार सेवा के लिए अयोध्या गए थे।
उसी शाम बाद में, मलकानि ने दिन की घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया:
'दुर्भाग्यपूर्ण'। वे विवादित ढांचे को हटाना चाहते थे, 'लेकिन...हम'
पार्टी चाहती थी कि यह विधिवत कानूनी प्रक्रिया से गुजरे। पार्टी ने 'नैतिक' रुख अपनाया।
जो कुछ हुआ उसके लिए 'जिम्मेदारी'।
एक्स

दोपहर होने से कुछ मिनट पहले ही फोन की घंटी बजी (सुबह 5 बजे, रेस)।
कोर्स रोड। प्रधानमंत्री अपने डेस्क पर थे—और उन्होंने उठाया...
सुरक्षित RAX लाइन पर रिसीवर। यह IB प्रमुख वी. जी. वैद्य थे। उन्मादी
कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद में घुसपैठ की और ऊपर चढ़ गए।
गुंबदों को तोड़ दिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें तोड़ने में असमर्थ रही थी।
उन्हें रोकने के लिए। वैद्य ने यह जानकारी राव को मराठी में दी।
वह एक महाराष्ट्रीयन थीं, और चूंकि राव मराठी में निपुण थीं, इसलिए उन्होंने
वह मुख्यतः उसी भाषा में बातचीत करता था।
राव अपने एक दोस्त के साथ बैठे थे जो अभी-अभी आया था, तभी फोन की घंटी बजी।
रंग 5, आरसीआर, अपनी लकड़ी की पैनलिंग और चित्रों के साथ, सबसे अधिक
रेस कोर्स के चारों घर—3, 5, 7, 9—बहुत ही सुंदर ढंग से सजाए गए हैं।
भारत के प्रधानमंत्री के लिए आवंटित सड़क। राजीव गांधी
राव ने नंबर 5 को अपने विशेष मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया था।
गुप्त राजनीतिक बैठकें आयोजित करने के लिए जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।

प्रधानमंत्री लगभग दस मिनट तक अपनी कुर्सी पर बैठे रहे।
'वह एकदम स्थिर था, मानो सदमे की स्थिति में हो', उसके साथ मौजूद दोस्त ने याद करते हुए बताया।
उसे। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। 'मैंने उसे इतना स्तब्ध कभी नहीं देखा था।'
उन्हें पता था कि उनका राजनीतिक भविष्य अब दांव पर लगा है।
उन क्षणों में, राव ने रूपरेखाओं का अवलोकन किया होगा।
उसे नुकसान को कम करने के लिए एक रणनीति लागू करनी होगी।
ऐसा किया जा चुका था। सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की संभावना थी।
अयोध्या। कानून व्यवस्था की स्थिति बेकाबू हो सकती है।
अयोध्या में मौजूद दंगाइयों और कार सेवकों के समूह भाग रहे थे।
चारों ओर, मस्जिद के चल रहे विध्वंस का जश्न मनाया जा रहा है।
अगर कार सेवकों पर नियंत्रण नहीं होता, तो बाबरी मस्जिद के पूरी तरह से नष्ट होने की पूरी संभावना थी। राव ने अवश्य ही विचार किया होगा कि क्या वे ऐसा कर सकते थे—
या फिर—इतने अंतिम चरण में भी विध्वंस को रोक देना चाहिए। फिर यह था
उत्तर प्रदेश सरकार को कब बर्खास्त किया जाए, यह एक समस्या है, जिसका समाधान उन्हें करना होगा।
क्या करना है। और यह सवाल कि अपने मंत्रिमंडल की बैठक कब बुलानी है।
उन्हें पता था कि उनके इस्तीफे की मांग उठेगी।
पहले दस मिनट के बाद प्रधानमंत्री ने काम करना शुरू कर दिया।
वह अगले दो घंटों तक फोन पर लगा रहा। लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
उनके राजनीतिक सहयोगियों के फोन आ रहे थे, जो उनसे संपर्क करने की बेताब कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने सिर्फ गृह मंत्री एस.बी. चव्हाण से बात की। अर्जुन जैसे अन्य लोगों ने उनसे बात नहीं की।
Singh, P. R. Kumaramangalam, M. L. Fotedar, even Madhu Limaye said
बाद में राव के सहायकों ने उन्हें जो बताया था—कि उन्हें निर्देश मिले थे कि
प्रधानमंत्री को 'परेशान नहीं किया जाना था'। शिखर पर राव से संपर्क करने में

असमर्थता।
इस संकट के कारण यह अफवाह फैल गई कि प्रधानमंत्री या तो
बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के दौरान सोना या पूजा करना
मैदान।
हर प्रमुख पार्टी के नेता एक-दूसरे से बात कर रहे थे।
वे बेचैनी से यह पता लगाना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है।
सभी लोग असमंजस में थे। यहां तक कि वे लोग भी जिनसे कुछ उम्मीद की जा रही थी।
प्रधानमंत्री से निकटता को देखते हुए, समाचार एजेंसियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
'Apne buddhe premi se baat hui kya (Have you managed to talk to
हमारा पुराना प्रेमी (राव के लिए एक व्यंग्यात्मक संदर्भ)?' जितेंद्र प्रसाद,
प्रधानमंत्री के राजनीतिक सचिव ने फोन पर वैदिक से पूछा।
'Kya chal raha hai (What's going on)?' an anxious Atal Bihari
वाजपेयी ने वैदिक से पूछा। लेकिन वैदिक के पास उन्हें बताने के लिए बहुत कम था —सिवाय उनके अपने
राव को सुबह का फोन आया।
अंततः, प्रधानमंत्री ने अपने मुखर आलोचक की बात मानने का फैसला किया।
फोतेदार ने कहा, 'मैंने दोपहर 1:40 बजे नरसिम्हा राव से बात की।' उनके बाद से
इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में अपने शुरुआती दिनों में, फोतेदार के पास यह अवसर था।
उनकी बैठकों का सटीक समय नोट करने की आदत और
राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत।
मैंने राव से दो काम करने को कहा। टेलीविजन और रेडियो पर आना और
शोक संतप्त राष्ट्र को सांत्वना देना। और 100 से 200 हेलीकॉप्टरों को ले जाने का आदेश देना।
क्षेत्र का चक्कर लगाएं और यदि आवश्यक हो तो हवा से आंसू गैस छोड़ना शुरू कर दें।

भीड़ तितर-बितर हो गई... अगर हम कम से कम एक स्तंभ को बचा सकें तो...
इस संरचना के माध्यम से, हम देश को बता सकते हैं कि सरकार ने इसे बचाने की कोशिश की थी।
अन्यथा,' फोतेदार ने मौन बैठे राव को चेतावनी दी, 'कांग्रेस...
खत्म।'
राव ने दोनों में से कोई भी सुझाव नहीं माना। लेकिन दोपहर 1:40 बजे तक, जब उन्होंने फैसला किया कि...
फोतेदार का फोन आने पर, उसने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है।
करो। क्योंकि, आधे घंटे बाद, उसने फोतेदार को वापस फोन किया और पूछा, 'क्या...'
'क्या हम कैबिनेट की बैठक बुलाएँ?' फोतेदार ने जवाब दिया, 'आपको कार्रवाई करनी चाहिए।'
पहले और फिर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करें।' बिना यह महसूस किए कि उस समय ऐसा हो रहा था।
उस समय, फोतेदार मंत्रिमंडल की बैठक को स्थगित करने के पक्ष में तर्क दे रहे थे।
राव यही चाहते थे।
■

ठीक उसी समय जब प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या की स्थिति पर नजर रख रहे थे।
उस सुबह के घटनाक्रमों के साथ-साथ उनके शीर्ष अधिकारी भी सतर्क थे।
कर्तव्यनिष्ठ गृह सचिव माधव गोडबोले और उनकी पत्नी सुजाता
उन्हें एक शादी के रिसेप्शन में जाना था। इसलिए गोडबोले ने जाने की योजना बनाई थी।
दोपहर के आसपास ऑफिस पहुंचे। लेकिन, अपने अन्य सहकर्मियों की तरह, उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ।
वह बेचैन था और इसके बजाय नॉर्थ ब्लॉक की ओर चल पड़ा। वह वहां सुबह 9 बजे पहुंचा।
पूर्वाह्न।

मुझे लग रहा था कि सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था।
'एक मौका लो,' गोडबोले ने कहा। 'हम स्थिति पर नजर रख रहे थे।
'नॉर्थ ब्लॉक में मेरा ऑफिस है।' ऑफिस पहुँचकर गोडबोले ने आईबी को फोन किया।
मुख्य वैद्य से नवीनतम प्रतिक्रिया जानने के लिए। फिर उन्होंने आर. के. वढेरा से बात की।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक (डीजी),
1962 में स्थापित अर्धसैनिक बल। वढेरा वहां तैनात थे।
अयोध्या से महज 7 किलोमीटर दूर फैजाबाद में, अपनी बटालियनों के साथ
तत्परता। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, केंद्र सरकार ने भेजा था
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के लगभग 20,000 जवानों को
अयोध्या। वे पास के फैजाबाद में तैनात थे, सहायता के लिए तैयार।
संकट की स्थिति में राज्य सरकार।
इनमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान शामिल थे।
(आरएएफ) के कुछ सदस्य, और यहां तक कि विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के भी कुछ सदस्य शामिल हैं।
वे 'स्टन' जैसे कई 'सॉफ्ट' हथियारों से लैस थे।
'ग्रेनेड', 'रबर की गोलियां' और 'रबर की बुलेट'।
'कृपया मेरी अनुमति का इंतजार न करें,' गोडबोले ने वढेरा को निर्देश दिया।
अगर राज्य सरकार की ओर से मदद का अनुरोध आता है। सामान्य तौर पर
इन परिस्थितियों में, वढेरा को कार्य करने के लिए अधिकृत होने की आवश्यकता होगी।
गोडबोले। 'समय बर्बाद मत करो,' उन्होंने वढेरा से बार-बार कहा। 11 तक
सुबह 'सब कुछ ठीक लग रहा था'।
दोपहर से ठीक पहले, गोडबोले के घर में फोन की तेज घंटी बजी।
कार्यालय। फिर से आईबी प्रमुख का फोन आया। 'कार सेवकों का एक समूह अंदर घुस गया है।'
वैद्य ने गोडबोले को बताया, 'मैं मस्जिद में गया और गुंबद के ऊपर चढ़ गया।'
आईबी प्रमुख ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पहले ही सूचित कर दिया था।

वैद्य कहते थे, 'पता नहीं मैंने प्रधानमंत्री को यह बात सबसे पहले बताई थी या नहीं।'
बाद में। 'बेशक, प्रधानमंत्री को सूचित करना डीआईबी का कर्तव्य है।'
तुरंत, जो मैंने किया... लेकिन एक ऑक्टोपस को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है,
इसके दो पैर भी हैं (सिर्फ दो पेट ही नहीं, बल्कि दस पैर भी हैं)।
उन्होंने बोलचाल की भाषा का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया कि राव के पास बहुत कुछ था।
सूचना के स्वतंत्र चैनल। 'प्रधानमंत्री के पास इतने सारे राजनीतिक अवसर थे।
सूत्रों के अनुसार, अगर कोई हमला होता तो उसे तुरंत पता चल जाता।
बाबरी मस्जिद पर।'
वैद्य ने गृह मंत्री एस. बी. चव्हाण को भी इस बारे में सूचित किया था, जिन्होंने
टर्न ने प्रधानमंत्री से बात की। गोडबोले ने भी फोन किया और उन्हें सूचित किया।
उन्होंने तुरंत गृह मंत्री को फोन किया। फिर उन्होंने कैबिनेट सचिव को बुलाया।
Rajgopal, and Naresh Chandra.
'हे भगवान!' राजगोपाल ने हैरानी से कहा। 'ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो
nahin ho sakta (This is not possible),' Chandra was incredulous.
गोडबोले खुद हैरान थे। उन्होंने कहा, 'मैंने सोचा भी नहीं था कि वे वहाँ जाएँगे।'
मस्जिद के शिखर तक जाने की हद तक।
विध्वंस से पहले के तनावपूर्ण हफ्तों में, शीर्ष अधिकारियों ने
प्रधानमंत्री की टीम एहतियाती कदम उठाने को लेकर विभाजित थी।
ढांचे को बचाओ। हफ्तों से, गोडबोले यह तर्क दे रहे थे कि कल्याण सिंह,
उत्तर प्रदेश के भाजपा मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा शासन लागू किया जाना चाहिए।
राज्य में लागू किया गया। हालाँकि, चंद्र और राजगोपाल दोनों के पास
उन्होंने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुच्छेद 356 का उपयोग करने के विचार का विरोध किया।
चंद्र एल. के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को अच्छी तरह से जानते थे—और
उन्होंने इस बात पर भरोसा किया कि मस्जिद को छुआ नहीं जाएगा।
उनका यह भी मानना था कि आरएसएस और वीएचपी इसे नष्ट नहीं करेंगे।

यह संरचना इसलिए प्रतिबंधित है क्योंकि 1949 से इसका उपयोग एक मंदिर के रूप में किया जा रहा था जिसमें एक मूर्ति स्थापित थी।
वहां भगवान राम की पूजा की जाती थी। प्रधानमंत्री के अमर नाथ वर्मा के अनुसार, प्रधान सचिव ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया; उन्होंने अपने बॉस से ही निर्देश लिए।
केंद्रीय कार्रवाई का विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि कल्याण सिंह ने आखिरकार सिर्फ दस दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट को एक गंभीर वादा दिया गया था।
कि उनका प्रशासन मस्जिद की रक्षा करेगा।
फिर गोडबोले ने लखनऊ फोन किया। मुख्य सचिव
उपलब्ध नहीं था। आखिरकार उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से संपर्क किया और उन्हें तत्काल 'केंद्रीय बलों को भेजने' का आदेश दिया।
फैजाबाद से अयोध्या तक। 'हमें मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी।'
डीजीपी ने पलटवार करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी। 'हम केवल यही कह सकते हैं कि...'
अगर वह सहमत हो जाता है तो केंद्रीय ताकतें।
दोपहर करीब 1 बजे तक, भारतीय सरकार के पांच शीर्ष अधिकारी
वे नॉर्थ ब्लॉक में थे, जहां एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। इसके अलावा
गोडबोले, एस. राजगोपाल, वी. जी. वैद्य और नरेश चंद्र, विधि विशेषज्ञ
सचिव पी. सी. राव भी आ चुके थे। वे चिंतित व्यक्ति थे—और
उन्हें पता था कि पहल उनके हाथ से निकल चुकी है। 'हमें लगा कि हमारे विकल्प
बंद हो चुका था। अब यह राज्य सरकार पर निर्भर था कि वह तय करे कि
केंद्रीय बलों को बुलाना है या नहीं। हालाँकि, भले ही केंद्रीय बल
यदि उन्हें बुलाया गया, तो वे राज्य सरकार के अधीन होंगे।
■

'Aap Shankar Raoji (S. B. Chavan) se baat kar lo (You talk to S. B.
राव ने वैदिक को बताया, 'चव्हाण)' जब उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन करके इस बारे में बताया था।

विध्वंस। यह एक असामान्य अनुरोध था। क्योंकि प्रधानमंत्री जानते थे कि
तब तक अधिकारी गृह मंत्री को नवीनतम जानकारी दे चुके होंगे।
घटनाक्रम। इसके अलावा, चव्हाण ने खुद राव से बात की थी।
राजनीतिक रूप से कुशल राव को यह जरूर लगा होगा कि कोई न कोई तो ऐसा करेगा ही।
विध्वंस की जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे-जैसे समय बीतता गया,
सत्ता के गलियारों में बैठे कई लोगों को यह बात समझ आने लगी थी। चव्हाण की
उसका नाम बलि का बकरा बनने की आशंका के साथ सामने आने लगा था। कुछ ही घंटों में
इसके बाद, राव ने गुलाम नबी आजाद से भी पूछा था,
संसदीय मामलों के मंत्री, चव्हाण से बात करने के लिए। चव्हाण को इसका आभास हो गया था।
बढ़ते तनाव के चलते गृह मंत्री ने खुद को सबसे अलग कर लिया।
विवादास्पद धर्मगुरु और राजनीतिक मध्यस्थ के आश्रम के लिए रवाना हो गया।
चंद्रस्वामी उनसे सलाह लेंगे।
'चव्हाण वास्तव में एक नाममात्र के गृह मंत्री थे,' राव के सहयोगी आर. के.
खांडेकर कहते थे। उनकी निकटता के बावजूद, राव 'वास्तव में उन पर भरोसा नहीं करते थे'।
एस. बी. चव्हाण पर राव ने अपने 'पुराने और भरोसेमंद दोस्त' को शामिल करने का फैसला किया था।
चव्हाण को मंत्रालय में शामिल करना इसलिए उचित होगा क्योंकि इससे प्रधानमंत्री के लिए काम आसान हो जाएगा।
उन्हें अपना गृह मंत्री खुद बनाना था। राव ने चव्हाण को दरकिनार कर दिया था।
अयोध्या वार्ता के दौरान वे केवल औपचारिक बैठकों में ही उपस्थित रहते थे।
राव ने हिंदू संतों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ जो वार्ता की थी, उसमें ऐसा नहीं था।
प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार वैदिक ने गृह मंत्री को फोन किया।
wife picked up the phone. 'Abhi toh woh so rahein hain (He is sleeping

इस समय (फिलहाल),' उसने आश्चर्यचकित वैदिक से कहा।
'क्या सब ठीक है?' उसने पूछा।
उन्होंने आज सुबह लंबी सैर की और उसके बाद सो गए।
नाश्ता,' उसने बताया। वैदिक ने उसके लिए एक संदेश छोड़ा। 'कृपया बताएँ'
him bahut bada sankat paida ho gaya hai. Masjid ka dome gir gaya hai
(कृपया उसे बता दें कि एक बड़ी समस्या है, मस्जिद का गुंबद टूट गया है)
(जिसे गिरा दिया गया था)। चव्हाण का 'सोना' स्पष्ट रूप से एक बहाना था।
गृह मंत्री जिन लोगों से बचना चाहते थे, उनसे बचने के लिए। क्योंकि वह पहले से ही
प्रमुख अधिकारियों और प्रधानमंत्री से संपर्क।
चव्हाण ने दोपहर 12.25 बजे कल्याण सिंह से भी बात की और उनसे आग्रह किया
कि वे इसका उपयोग करें।
घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए फैजाबाद में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था।
विवादित ढांचे को लेकर उन्होंने राज्यपाल रेड्डी को भी फोन किया और उनसे अपनी
सहमति मांगी।
संरचना को बचाने के लिए हस्तक्षेप।
■

दोपहर के तनावपूर्ण घंटों के दौरान, राज्यपाल रेड्डी ने लगातार प्रयास किया।
वे प्रधानमंत्री से संपर्क करने के लिए बेताब थे। वे जानना चाहते थे कि क्या करना है।
ऐसी स्थिति में जो पल-पल बदल रही थी। प्रधानमंत्री के साथ
रेड्डी ने फोन उठाने के बजाय वैदिक से संपर्क किया। वैदिक उन्हें जानता था।
दोनों को 1965 में भारत बंद में भाग लेने के लिए जेल भेजा गया था।
समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा बुलाया गया। हालाँकि वैदिक
इंदौर में रहने वाले रेड्डी और हैदराबाद में रहने वाले रेड्डी एक-दूसरे के संपर्क में थे।
साल।
'Doctor saab, Kalyan Singh meri jaan kha raha hai (Kalyan Singh is

मेरे जीवन के बाद),' उस दोपहर व्याकुल रेड्डी ने वैदिक से कहा। 'राज्यपाल
हाउस के नहीं (वह गवर्नर हाउस के बाहर हैं, मैंने जवाब नहीं दिया है।)
क्या मुझे उससे मिलने के लिए सहमत होना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए?
'What can I say?' Vaidik replied. 'Rao saab se poochhiye (You ask
राव)।
रेड्डी ने जवाब दिया, "राव साहब को चार बार फोन कर चुका हूं।"
'Mera phone hi nahi le rahein. Aap unse baat keejiye. Main kya karoon
(मैंने राव साहब को चार बार फोन किया है। वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। आप उनसे बात करें)
उससे पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए?
जब वैदिक ने दोपहर में प्रधानमंत्री से बात की, तो उन्होंने यह जानकारी दी।
राज्यपाल के संदेश को नजरअंदाज करते हुए, राव ने राज्यपाल के प्रश्न को अनदेखा कर दिया।
Instead, he vented his spleen on the VHP–BJP. 'Unhone aashvaasan
diya thaa…. Ab itna galat kaam kar diya (They had assured me…What
उन्होंने अब जो किया है वह बहुत गलत है।
मदद करने की कोशिश करते हुए, वैदिक ने सुझाव दिया, 'आप जाफर शरीफ (
तत्कालीन रेल मंत्री ने दस से बीस ट्रेनें भेजने और खाली करने का आदेश दिया।
फैजाबाद।' लेकिन राव ने विश्वासघात के बारे में बोलना जारी रखा। 'मेरे साथ
bahut bada dhokha hua hai (They have betrayed me).'
'Rao saab, Raja ko kabhi nahin kehna chahiye ke mere saath
dhokha hua hai,' Vaidik found himself telling the PM, as if from a 'guru
एक चेले को। (श्री राव, यह स्वीकार करना किसी शासक के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि उसने

(धोखा दिया गया है।) वैदिक ने कहा कि वह कौटिल्य के कथन को प्रधान मंत्री के समक्ष अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे थे।
मंत्री। नरसिम्हा राव चुप हो गए।
■

दोपहर करीब 3 बजे प्रधानमंत्री ने गृह सचिव गोडबोले से मुलाकात की।
उसके बाद राव ने नरेश चंद्र से अलग से मुलाकात की।
गोडबोले ने प्रधानमंत्री को बताया कि कल्याण सिंह ने आखिरकार उनसे यह अनुरोध किया था।
केंद्रीय बलों को अयोध्या की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था।
कि उन्हें कार सेवकों पर गोली नहीं चलानी थी—भले ही भीड़
वे सेनाओं की आवाजाही में बाधा डाल रहे थे, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे।
मस्जिद तक पहुँचते हुए। आधे रास्ते में, उनकी धीमी प्रगति को देखते हुए,
उनके साथ आए मजिस्ट्रेट ने उन्हें फैजाबाद लौटने के लिए कहा।
मैंने कल्याण सिंह से जिले के लिए लिखित आदेश देने को कहा था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख्य आवास पर मजिस्ट्रेट को जरूरत पड़ने पर गोली चलाने का अधिकार है।
उस समय के सचिव प्रभात कुमार ने बाद में कहा, 'इसके बजाय, कल्याण'
सिंह ने लिखित में यह दर्ज कराया कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी।
kar sevaks.'
राव ने गोडबोले की बात ध्यान से सुनी, उनके चेहरे पर शिकन और गहरी होती चली गई।
उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। गोडबोले को यह आभास हुआ कि प्रधानमंत्री सुन रहे थे।
लेकिन उसे जो कुछ भी बताया जा रहा था, उसके बारे में उसे पूरी जानकारी थी।
जब गोडबोले प्रधानमंत्री के साथ थे, तभी राज्यपाल का फोन आया।
इस बार प्रधानमंत्री ने फोन उठाया। रेड्डी ने उन्हें बताया कि कल्याण सिंह ने

इस्तीफा दे दिया।
राव ने रिसीवर नीचे रखा और गोडबोले की ओर मुड़कर पूछा, 'क्या होने वाला है?'
अब हो गया?
‘कल्याण सिंह को सम्मानपूर्वक विदा नहीं किया जाना चाहिए,’ घर ने कहा।
सचिव ने कहा, ‘हमें पहले राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए।’
उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए।’ प्रधानमंत्री ने फोन उठाया और पूछा
राज्यपाल से दोबारा संपर्क स्थापित किया गया। जब रेड्डी ने फोन उठाया,
राव ने उनसे कहा कि वे कल्याण सिंह का इस्तीफा स्वीकार न करें। उन्हें इसे अपने पास रखना चाहिए।
यह मामला लंबित है और दिल्ली से सूचना का इंतजार है। मंत्रिमंडल की बैठक शाम 6 बजे होगी।
शाम को बैठक करें और सरकार की बर्खास्तगी पर अपना विचार व्यक्त करें।
प्रधानमंत्री शायद गृह सचिव को शांत करना चाहते थे।
उन्होंने राज्य को केंद्रीय शासन के अधीन रखने की उनकी पिछली सलाह को अस्वीकार कर दिया था।
वह जानता था कि अब उससे इस बारे में कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया।
जब उनके पास समय था, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया।
ऐसा करने के लिए।
■

कैबिनेट सचिव राजगोपाल के कार्यालय को प्रधानमंत्री कार्यालय से एक फोन आया।
दोपहर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के लिए फोन किया गया। फोन कॉल
राजगोपाल के उस सहयोगी के लिए अभिप्रेत था जो सामान्यतः मंत्रिमंडल का आयोजन करता था।
राजगोपाल ने कहा कि उनकी बैठकों में मंत्रियों के फोन नंबर थे।
लेकिन वह सहकर्मी अपने घर पर नहीं था। रविवार होने के कारण वह नहीं आ सका।
पता लगाया जा सके।’ प्रधानमंत्री कार्यालय ने कैबिनेट सचिवालय को इसे ठीक करने

का निर्देश दिया।
मंत्रिमंडल की बैठक, लेकिन ऐसा तभी किया जाए जब यह 'सुनिश्चित' कर लिया जाए कि कुछ
वरिष्ठ मंत्री, विशेषकर अर्जुन सिंह, जो विदेश यात्रा पर गए थे
उस दिन दिल्ली में मौजूद लोग थे। फोतेदार को मंत्रिमंडल के बारे में खबर मिली।
बैठक शाम करीब 5 बजे होगी।
'हमने शाम छह बजे तक इंतजार किया, क्योंकि अर्जुन सिंह दिल्ली में नहीं थे।'
नरेश चंद्र ने बाद में स्पष्टीकरण दिया। 'उसे वापस लाने में हमें समय लगा।'
यहां... नरसिम्हा राव अपनी बैठक शुरू नहीं करना चाहते थे।
अनुपस्थिति। उनके आते ही (कैबिनेट) की बैठक शुरू हो गई। वह (था)
देरी का कारण...
मंत्रिमंडल बुलाने में देरी का मतलब यह था कि राव ने किसी भी संभावना को खारिज कर दिया था।
चल रहे विध्वंस को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप। तब तक
विध्वंस शुरू होने के छह घंटे बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई।
ढांचे को गिरा दिया गया था।
■

नरेश चंद्र शाम करीब 4:30 बजे रेस कोर्स रोड स्थित 7 नंबर स्टेशन पर पहुंचे।
मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने से पहले। 'शांत' व्यवहार के विपरीत
प्रधानमंत्री ने गोडबोले को जो प्रस्तुत किया था, चंद्र ने प्रधानमंत्री को पाया
'बहुत उत्तेजित'। राव चंद्र के साथ अपने से कहीं अधिक अनौपचारिक थे।
वह अपने गृह सचिव के साथ थे। पीवी ने इस पर जरा भी समय बर्बाद नहीं किया।
प्रारंभिक चरण।
'यह सब कैसे हुआ?' उसने चंद्र से पूछा।
'हमें आईबी से सभी तथ्य प्राप्त करने होंगे,' चंद्र ने कहना शुरू किया।
'But I got a mouthful from him. Uspe woh humaare upar hi bigad
गे।' (वह मुझसे गुस्सा होने लगा।)

प्रधानमंत्री को शांत करने की कोशिश करते हुए, चंद्र ने फिर से कहा, 'हम इसे रोकेंगे।'
आईबी को कड़ी चुनौती दो और उन्हें मजबूर करो...'
चंद्रा अपना वाक्य पूरा कर पाता, उससे पहले ही राव ने उसे बीच में ही रोक दिया।
उनकी तीक्ष्णता उनके स्वभाव के विपरीत थी: 'आईबी!! आईबी की बात मत करो।'
'वह बहुत गुस्से में थे, मुझे थोड़ा झटका लगा।'
कुछ ही मिनट पहले, राव घर के प्रति नरम रुख अपना रहे थे।
सचिव, जो शुरू से ही इस संभावित घटना की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन
चंद्र ने आईबी की जमकर आलोचना की और सारा दोष उसी पर मढ़ दिया।
आने वाले हफ्तों और महीनों में वह खुफिया विफलता की बात पर अड़ा रहा।
इसके बाद जो हुआ, उसके लिए उन्होंने कल्याण सिंह को दोषी ठहराया। और उन्होंने अपने वादे को पूरा न करने के लिए कल्याण सिंह को जिम्मेदार ठहराया।
उसने जो आश्वासन दिए थे। उन घंटों में, उसने उन दोनों की पहचान कर ली थी।
वह बलि का बकरा बनना पसंद करता था।
‘अयोध्या में जो कुछ हो रहा था, वह सबके सामने था...
'पूरी दुनिया को देखने के लिए,' वैद्य ने बाद में खुफिया विभाग के बचाव में कहा।
ब्यूरो। एक वरिष्ठ नौकरशाह के रूप में, यह उनके लिए यथासंभव खुला रहने का एकमात्र तरीका था।
यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने प्रधानमंत्री को उस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी जो
अयोध्या में हो रहा है। जैसा कि पहले देखा गया, यह एक दैनिक परंपरा थी।
आईबीआई और आर एंड एडब्ल्यूए के प्रमुख प्रधानमंत्री को संवेदनशील जानकारी से अवगत कराएंगे।
यह बात प्रधानमंत्री को केवल मौखिक रूप से ही बताई जा सकती थी। वैद्य ने आगे कहा, 'हर कोई...'
(और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे) उन्हें पता था कि स्थिति बिगड़ सकती है।
नियंत्रण से बाहर।'
जब वे प्रधानमंत्री से मिलने आए, तो नरेश चंद्र और
माधव गोडबोले ने पहले से ही वे कागजात तैयार कर लिए थे जो प्रस्तुत किए जाने थे।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक था। चंद्र ने कहा, 'हम तैयार थे।'
उन्होंने कहा, ‘कैबिनेट द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी मिलते ही हम तुरंत कार्रवाई करेंगे।’
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए कागजात भेज दिए जाएं।
इस प्रक्रिया के लिए पैंतालीस सेट कागजात तैयार किए गए थे।
कल्याण सिंह को बर्खास्त करना, यूपी विधानसभा को भंग करना और अध्यादेश जारी करना
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन।
■

मैं कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चाय और पकौड़े खा रहा था, तभी मुझे यह बात पता चली।
मुझे खबर मिली कि कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद में घुसपैठ की है,’ उसने कहा।
इस पूरे विवाद के केंद्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हैं।
कालिदास मार्ग पर स्थित उनके आधिकारिक आवास की छत पर बैठे थे।
लखनऊ भी सर्दियों की धूप का आनंद ले रहा है।
मुझे अयोध्या पुलिस नियंत्रण कक्ष से एक फोन आया था।
कल्याण सिंह ने मुझे बताया, ‘उन्होंने कहा कि ढांचा (ढांचा) का एक हिस्सा...’
'इसे ध्वस्त किया जा रहा था।' उन्होंने आगे कहा: 'यह दोपहर लगभग 12-12.15 बजे का समय था।'
मुझे शाम करीब 4:30 बजे ही पता चला कि पूरी संरचना
उसे गिरा दिया गया था।
कल्याण सिंह ने कहा, 'मैंने तुरंत राज्य पुलिस को उन्हें रोकने का आदेश दिया।'
उन्होंने कहा। उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस को हर संभव प्रयास करना चाहिए।
मस्जिद खाली कराओ। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि '
पुलिस को भीड़ पर गोली नहीं चलानी चाहिए। पुलिस की गोलीबारी और भगदड़।
इसके बाद जो होता, उससे कई लोग मारे जाते। कल्याण सिंह ने अनुमान लगाया।
उस दिन अयोध्या में 300,000 लोग जमा हुए थे। 'यह पूछकर कि...'

पुलिस द्वारा गोली न चलाने के कारण, मैंने हजारों राम भक्तों की जान बचाई, हालांकि मैं
उन्होंने कहा, 'ढांचा को बचाने में असमर्थ रहा।'
जैसे-जैसे दोपहर बीतती गई, स्थिति को संभालने का प्रयास विफल होता चला गया।
यह प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच वाकयुद्ध में बदल गया।
मुझे पता था कि कल्याण सिंह का जाना अपरिहार्य था। सवाल यह था कि कैसे।
यह हो जाएगा—और कौन इससे राजनीतिक लाभ उठा पाएगा?
नरसिम्हा राव की तरह कल्याण सिंह ने भी कहा कि उन्हें 'निराशा' हुई है।
मुख्यमंत्री इस बात से नाराज थे कि उन्हें अप्रत्याशित रूप से घेर लिया गया था और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) को
उन्हें अंधेरे में रखा गया। अगर उनका इरादा ऐसा था तो उन्हें उसे चेतावनी देनी चाहिए थी।
एक नाराज मुख्यमंत्री ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा, "इस ढांचे को ध्वस्त कर दो।"
हालांकि वे मुख्यमंत्री थे, लेकिन यह विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और विनय कटियार ही थे जिनकी बदौलत
फैजाबाद में स्थानीय प्रशासन पर शब्दों का अधिक प्रभाव था और
Ayodhya.
कल्याण सिंह ने जून 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था।
लगभग उसी समय राव प्रधानमंत्री बने थे। एल. के. आडवाणी के शिष्य सिंह ने मंदिर मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया था।
सत्ता में आते ही उन्होंने भाजपा के मूल समर्थकों को स्वीकार्य होने की कोशिश की।
वह निर्वाचन क्षेत्र जिसके लिए यह आस्था का विषय था। एक पिछड़े वर्ग के रूप में
नेता—वह लोध समुदाय से संबंध रखते थे। वह उन कुछ लोगों में से एक थे।
मंडल घटनाक्रम और दोनों से लाभान्वित होने वाले राजनेता
1990 के दशक में मंदिर आंदोलन।
विध्वंस से एक दिन पहले, 5 दिसंबर की शाम को,
कल्याण सिंह बेचैन होने लगा था। उसे खबर मिली थी कि एक

कार सेवकों के बीच एक आक्रामक समूह चाहता था कि कार सेवा
यह महज प्रतीकात्मक नहीं था। उन्होंने एल. के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से पूछा।
अयोध्या के लिए तुरंत रवाना होना था। उन्हें मंदिर पहुंचना था।
6 दिसंबर की सुबह शहर जाने का इरादा था—लेकिन वहाँ पहुँचने का फैसला किया 5 दिसंबर की रात।
6 दिसंबर को, राव की तरह, कल्याण सिंह ने भी अपने दिन की शुरुआत की।
phoning Vinay Katiyar. Advani and Joshi were at Katiyar's house in
अयोध्या में नाश्ता करते हुए। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल भी साथ थे।
उन्हें। मुख्यमंत्री ने आडवाणी से अपील की: 'कृपया सुनिश्चित करें कि
आज कार सेवा का सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है।
हालांकि, चीजें उस तरह से नहीं हुईं। जैसे ही
घुसपैठिए गुंबदों पर चढ़ गए, कल्याण सिंह समझ गया कि अब अंत आ गया है।
मुख्यमंत्री के रूप में उनके लिए रास्ता बंद हो गया था। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया,
उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। आखिरकार, उन्होंने एक वचन दिया था।
सुप्रीम कोर्ट—और उन्होंने राव को बार-बार आश्वासन दिया था—कि वह ऐसा करेंगे मस्जिद की रक्षा करें। बेहतर होगा कि वे अपना इस्तीफा सौंप दें।
केंद्र सरकार द्वारा उन्हें बर्खास्त किए जाने से पहले ही उन्होंने राज्यपाल पद संभालने का फैसला कर लिया।
कल्याण सिंह ने राज्यपाल से तुरंत मिलने का अनुरोध किया। इससे पहले
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने शाम 5 बजे अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया था।'
और मैंने उन्हें अपने इस्तीफे के इरादे के बारे में सूचित कर दिया।' कल्याण सिंह ने कहा।
उन्होंने मुझे अपनी सहमति दे दी। मैंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
शाम करीब 5.15 बजे। लेकिन मेरी सरकार को केंद्र सरकार ने उखाड़ फेंका।
रात करीब 9 से 9.15 बजे के बीच। इतिहास में यह पहली बार था कि ऐसा हुआ।

उन्होंने कहा, 'ऐसी सरकार को उखाड़ फेंका गया जो असल में अस्तित्व में ही नहीं थी।'
व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की।
■

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की तैयारी कर रहे थे।
राव अब नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गए थे। उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि...
अर्जुन सिंह को काबू में करने के लिए। शाम 6 बजे से कुछ मिनट पहले, मंत्रियों ने शुरू किया...
7, रेस कोर्स रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास में सामूहिक प्रवेश करें।
बैठक कक्ष का माहौल 'निराशाजनक' था। मंत्रियों
दबी आवाज़ में बातचीत हुई। एम. एल. फोतेदार पंद्रह मिनट बाद पहुंचे।
देर हो गई थी। जब वह कमरे में दाखिल हुआ, तो उसके सभी सहकर्मी बैठे हुए थे। वह भी वहीं था।
प्रधानमंत्री से पूछा, 'यह मंत्रिमंडल की बैठक किसलिए है?' फोतेदार ने पूछा।
उसका लहजा स्पष्ट रूप से व्यंग्यात्मक था।
नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया और वी.सी. शुक्ला
संसदीय मामलों के मंत्री ने आश्चर्य से ऊपर देखा और कहा, 'क्या आप नहीं?'
जानना?'
'नहीं,' फोतेदार ने सीधे चेहरे से जवाब दिया।
उन्होंने कहा, 'बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है।'
फोतेदार: 'क्या ऐसा है?'
हम यहां उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने और भंग करने आए हैं।
'सभा,' किसी ने बीच में टोकते हुए कहा।
फोतेदार: 'आप किस विधानसभा को भंग करने जा रहे हैं?' (कल्याण)
सिंह ने (पहले ही) इस्तीफा दे दिया है।
फोतेदार के अनुसार, सभी लोग आश्चर्यचकित दिख रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव को पता लगाने के लिए कहा। वह वापस आ गए।
मैंने पांच मिनट में कहा, "जी सर, दूरदर्शन यही कह रहा है।"
फोतेदार राष्ट्रपति कार्यालय से सीधे रेस कोर्स रोड आए थे।
भवन। उन्होंने शाम 5.30 बजे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से मुलाकात की थी।
जब फोतेदार राष्ट्रपति के साथ थे (शाम 5.30 बजे से 6 बजे के बीच),
शर्मा को एक संदेश मिला था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फोतेदार ने राष्ट्रपति को बेहद उत्तेजित पाया था।
फोतेदार ने कहा, 'शंकर दयाल शर्मा सचमुच रो रहे थे।'
इससे पहले दिन में, जब शाहिद सिद्दीकी और मुसलमानों के एक समूह ने
नेता दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति से मिलने गए, 'उन्होंने हमें एक पत्र दिखाया जो उन्होंने लिखा था।'
उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। वह पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है।
एक बहुत ही कड़ा पत्र (जिसमें) उन्होंने प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया।
विध्वंस के लिए। यह पहले गुंबद के गिरने के बाद लिखा गया था और इसमें आग्रह किया गया था।
प्रधानमंत्री को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।' फोतेदार के बोलने के तरीके से ऐसा लगता है कि
राष्ट्रपति ने जाहिर तौर पर उन्हें प्रधानमंत्री को लिखे उनके पत्र के बारे में भी बताया था। 'मैं
फोतेदार ने कहा, 'मैंने राष्ट्रपति से कहा कि वे रेडियो पर आकर राष्ट्र को संबोधित करें। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी अनुमति नहीं दी। केवल उनके (राष्ट्रपति के)
बयान का प्रसारण किया गया।
कैबिनेट बैठक में, फोतेदार ने राव की ओर मुड़कर कहा, 'श्रीमान प्रधानमंत्री जी,
इस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और इस नाजायज बच्चे को (
हजरत महल पार्क में सरकार द्वारा स्थापित व्यवस्था। आपको इसे स्वीकार करना होगा।
'संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं और इस नाजायज बच्चे को अपनाएं।' उन्होंने कहा
प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। अन्य

मुझे याद है जब फोतेदार प्रधानमंत्री पर चिल्ला रहे थे। एक समय पर, फोतेदार ने 'चिल्लाना शुरू कर दिया था'।
रोना'। व्यथित सी. के. जाफर शरीफ ने चेतावनी दी कि देश को
जो कुछ हुआ था, उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अधिकांश मंत्रियों ने कुछ नहीं कहा।
कुछ भी। कमरे का माहौल तनावपूर्ण था।
■

बैठक शुरू होने के एक घंटे बाद, राव एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए बाहर निकले।
उनसे मिलने आए थे। इनमें उत्तेजित मुस्लिम नेता शामिल थे जो
मैं दिन भर उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा। समूह का नेतृत्व सैयद कर रहा था।
Shahabuddin, Shahid Siddiqui, Maulana Parikh (an associate of Ali
देवबंद के मियां, सुलेमान सैत और कई अन्य लोग। वे मिले थे
विध्वंस की खबर मिलने के बाद उस दोपहर सुलेमान सैत का घर।
संपर्क टूट गया। दिन के दौरान उन्होंने राव और चव्हाण से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन
उन्हें बताया गया कि वे 'आराम कर रहे हैं'। आखिरकार, शाम 5 बजे, उन्हें सूचना मिली।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें रेस कोर्स रोड पर आने के लिए कहा है।
शाम 7 बजे।
'Bahut bura ho gaya, bahut bura ho gaya (It's terrible what's
जो हुआ है, वह बहुत भयानक है,' राव ने अंदर आते हुए विलाप किया।
कमरा।
'Rao sahib, gumbad gir gaya (Rao sahib, the domes have fallen),'

उनमें से कई लोग एक साथ बोलते हुए उससे बोले।
‘Usse bhi zyada,’ Rao said. ‘Sab kuch gir gaya, sab kuch gir gaya.
Leken mein banaoonga doobara. Sab kuch banaoonga (Not just the
गुंबद, सब कुछ ढह गया है। लेकिन मैं इसे फिर से बनाऊंगा।
इस मौके पर शहाबुद्दीन टूट गया। ‘वह भावुक था।’
‘यार,’ सिद्दीकी ने मुझसे कहा। सालों से, शहाबुद्दीन ने वकालत की थी
अयोध्या पर मुस्लिम नजरिया. 'आप बनवा दीजिए
उन्होंने राव से विनती की, 'पुनर्निर्मित किया जाए।'

इस मौके पर सिद्दीकी अचानक अपना आपा खो बैठे। ‘शाहबुद्दीन साहब,
yeh aadmi!’ he said angrily, ‘hum inse kehte rahe din raat aur inhone
bachaya nahi. Ye jab bacha nahi sakae, to yeh kya banwayaengae. Inki
himmat nahi. Isko bachane ke liye humne saari power di thee inhe
(हम इस आदमी से मस्जिद को बचाने की लगातार विनती करते रहे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया)
ऐसा करो। अगर वह इसे बचा नहीं सका, तो अब वह क्या पुनर्निर्माण करेगा?
उसमें साहस नहीं है। हमने उसे सारी शक्तियाँ सौंप दी थीं।
हमारे पास जो भी आवश्यक था, वह करने के लिए साधन उपलब्ध थे (मस्जिद को बचाने के लिए)।
सिद्दीकी 23 नवंबर 1992 को हुई एनआईसी की बैठक का जिक्र कर रहे थे।
जिसने प्रधानमंत्री को जो भी आवश्यक हो, वह करने का अधिकार दिया था।
इमारत को बचाने के लिए। सिद्दीकी और भी ज्यादा उत्तेजित थे क्योंकि उनके पास
विध्वंस से एक रात पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। और राव ने
उन्होंने एक बार फिर उन्हें आश्वस्त किया कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया

जाएगा।
अचानक, सिद्दीकी को याद आया कि राव ने उससे पहले क्या कहा था।
1991 के चुनाव। वह राजीव गांधी के कहने पर उनसे मिलने गए थे।
मुसलमानों के कल्याण के लिए सुझावों से लैस, जिन्हें इसमें शामिल किया जाना है कांग्रेस का घोषणापत्र। घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने का जिम्मा राव के पास था।
समिति और सिद्दीकी ने उन्हें अपने विचारों के बारे में बताया।
'Haan. Musalman ka vote chahiye. Hindu ka toh vote hee nahi chahiye,' Rao had remarked sarcastically. 'Hindu ki toh koi aukaat hi
nahi hai iss desh mein, aapki party mein (Yes, you need the votes of
मुसलमानो, तुम्हें हिंदुओं के वोटों की जरूरत नहीं है, उनकी क्या अहमियत है?
इस देश में हिंदुओं की संख्या तो है ही, और आपकी पार्टी में भी है।
Siddiqui was taken aback: 'Sir, aapki party hai. Meri toh koi aukaat
nahi hai. Mujhe toh kaha thaa ki minority ke baare mein kuch deejiye,
तो मैं ये दे रहा हूँ (सर, ये आपकी पार्टी है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है)
मुझे अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ देने के लिए कहा गया था, इसलिए मैं वह दे रहा हूँ।
लेकिन सिद्दीकी ने 6 दिसंबर को जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया।
शाम को, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, 'राव साहब, कृपया एक काम कीजिए।'
अधिक शांति से। '(आज) वहाँ न तो मस्जिद है और न ही मंदिर।'
कृपया इस यथास्थिति को न बदलें। इसे किसी और चीज़ में नहीं बदलना चाहिए...
मंदिर। फिर हम इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर सकते हैं। ज़मीन का बंटवारा कर दो।
एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद का निर्माण किया जाए।
'नहीं, नहीं, मैं मस्जिद का पुनर्निर्माण करने जा रहा हूं,' राव ने प्रतिनिधिमंडल से कहा।
मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है और मैं फैसला लेने जा रहा हूं।

प्रधानमंत्री ने मस्जिद के पुनर्निर्माण के अपने निर्णय की घोषणा की।
अगले ही दिन, 7 दिसंबर को, संसद में दिए गए अपने भाषण के दौरान राव ने कहा, 'मस्जिद का विध्वंस एक अत्यंत बर्बर कृत्य था।'
उन्होंने घोषणा की कि ‘सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इसका पुनर्निर्माण हो।’
■

मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के चले जाने के बाद, प्रधानमंत्री वापस चले गए।
मंत्रिमंडल की बैठक। किसी ने भी राव से इस्तीफा देने को नहीं कहा। फोतेदार थे।
राव की आलोचना में सबसे तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार विफल रही है
केंद्र द्वारा पास में तैनात सभी बलों से मस्जिद की रक्षा करें।
अयोध्या। फोतेदार ने प्रधानमंत्री से बार-बार गुहार लगाई थी।
उनके अनुसार, 18 नवंबर और 22 नवंबर को कई कैबिनेट बैठकें हुईं।
और फिर 4 दिसंबर को—उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को बर्खास्त करने के लिए।
सभा स्थगित करें। यदि मस्जिद 6 तारीख को सुरक्षित रही।
उन्होंने तर्क दिया कि दिसंबर में वे हमेशा 'विधानसभा को बहाल' कर सकते हैं।
इसके बाद भी। जुलाई 1992 में भी, जब कार सेवा का आयोजन किया गया था।
मस्जिद के संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी थी कि इसकी अनुमति न दी जाए। हर बार
प्रधानमंत्री भी यही वादा करेंगे—कि वे ‘बचाएंगे’
किसी भी कीमत पर मस्जिद बनवानी है।
6 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में अर्जुन सिंह ने भाग नहीं लिया।
राव के इस्तीफे की मांग करें। उन्होंने केवल गृह मंत्रालय को ही फटकार लगाई।
पर्याप्त तैयारी न होने के कारण। अगर अर्जुन सिंह ने उस दिन इस्तीफा दे दिया होता,
राव का जाना अपरिहार्य हो जाता। आक्रोशित कांग्रेसी
वह अर्जुन सिंह की ओर आकर्षित होकर उसके पीछे खड़ा हो जाता।
सिंह राव की जगह प्रधानमंत्री बन सकते थे।
प्रधानमंत्री से अपनी निराशा के बावजूद, फोतेदार भी

किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। यहां तक कि कैबिनेट बैठक में भी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया।
शाम होने से संकटग्रस्त राव की स्थिति और भी गंभीर हो जाती।
अर्जुन सिंह ने बाद में बताया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, 'मुझे नहीं लगा कि वहाँ उनके (प्रधानमंत्री) साथ खुले टकराव में उतरना उचित नहीं है और
उन्होंने सुलह का रुख अपनाने का फैसला किया।
■

उस रात करीब 9:30 बजे, अर्जुन सिंह गाड़ी चलाकर फोतेदार के घर 6 बजे पहुंचा।
कुशक रोड पर अनिल बाली भी उनके साथ शामिल हो गया। बाली, फोतेदार के काफी करीब हो गया था।
राजीव गांधी की मृत्यु के बाद। 'मैं उनसे लगातार इस्तीफा देने की गुहार लगाता रहा,' बाली ने कहा।
याद आया। 'दोनों यही कहते रहे कि अगर वे इस्तीफा दे देंगे, तो "देश टूट जाएगा (द देश टूट जाएगा)। मुझे ऐसा लगा कि शंकर दयाल शर्मा उस शाम फोतेदार से मिलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो गए थे (
अर्जुन सिंह को इस्तीफा देने से रोकना। राजनीति को देखते हुए...
मध्य प्रदेश, जिससे अर्जुन सिंह और डॉ. शर्मा दोनों संबंधित थे,
बाली को लगा कि 'राष्ट्रपति नहीं चाहते थे कि अर्जुन सिंह प्रधानमंत्री बनें'
राष्ट्रपति ने तर्क दिया होगा कि अर्जुन सिंह मंत्री नहीं थे।
अन्य कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिलने की संभावना है। और यह संभव है कि ऐसा हो।
सिंह और फोतेदार के लिए सरकार में बने रहना और विरोध करना बेहतर होगा।
राव को अंदर से बाहर ठंड में रहने से बेहतर है। हालाँकि कोई भी खुलकर ऐसा नहीं कहता।
जब उनके इस्तीफे की मांग उठी, तो कुछ ही मिनटों में राव के खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं।
मंत्रिमंडल की बैठक के समापन के बारे में। वैदिक की निकटता को जानते हुए।

to Rao, Arjun Singh called him at 10.30 that night. ‘Dekhiye, Narasimha
रावजी ने (मस्जिद) गिरवाया है (मुझे पता है नरसिम्हा राव ने मस्जिद बनवाई है)
mosque destroyed). Aapne milke saazish ki hai (You people have
उन्होंने ऐसा करने की साजिश रची थी),’ वह भड़क उठा। जाहिर तौर पर वह वैदिक से यही चाहता था।
राव को यह बता दें कि वह सुलह का रुख नहीं अपनाने वाले हैं।
Narasimha Raoji ko dekh lenge,’ the normally restrained Arjun Singh
said. ‘Hum aapko bhi dekh lenge (I will deal with Narasimha Rao, and I
मुझे यह भी पता है कि आपसे कैसे निपटना है।
An angry Vaidik shot back, ‘Aap Narasimha Raoji ko dekh lena. Aap
mujhe dekhne ki baat mat karna. Agar main raajneeti karne laga hota,
toh main aapko Delhi nahi aane deta (You deal with Narasimha Rao,
लेकिन मुझसे निपटने की बात मत करो। अगर मैंने राजनीति की होती, तो मैं...
मैंने तुम्हें दिल्ली में राजनीति करने के लिए प्रवेश नहीं करने दिया होता,’ उन्होंने सिंह से कहा।
■

उस शाम 7 बजे के ठीक बाद, यूनियन कैबिनेट ने सिफारिश की थी कि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना, विधानसभा भंग करना
राज्य विधानसभा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना।
शाम करीब 7.30 बजे गृह मंत्री चव्हाण राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचे।

भवन, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आवश्यक कागजात लेकर। राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री ने रात 9.10 बजे केंद्रीय शासन की घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
मंत्री ने रात 9.30 बजे राष्ट्र को संबोधित किया।
कैबिनेट बैठक में अर्जुन सिंह ने सुझाव दिया था कि प्रधानमंत्री
उस रात राष्ट्र को संबोधित करने के लिए। उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया।
'सुझाव,' सिंह ने कहा। राव ने अर्जुन सिंह, फोतेदार और
माधवराव सिंधिया को अपने भाषण का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया।
उस रात अपने भाषण के बाद, राव ने कई जगहों पर लगी आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया।
जो जल रहा था। रात 10 बजे, वह राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए।
राष्ट्रपति को दिन भर की घटनाओं से अवगत कराना—और उन्हें शांत करना।
आगे कई कठिन निर्णय लेने थे और राव जानते थे कि एक गैर-
सहयोगात्मक राष्ट्राध्यक्ष समस्याग्रस्त हो सकता है। आखिरकार, राष्ट्रपति
उनके पास किसी को भी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने और उन्हें पद देने का अधिकार था।
अब उन्हें अपना बहुमत साबित करने का समय आ गया है।
विध्वंस से पहले हफ्तों की अनिश्चितता के बाद, चीजें
अचानक ही गाड़ी बेहद तेज गति से चलने लगी। बत्तियाँ देर रात तक जलती रहीं।
नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के दफ्तरों में रात भर।
मंत्री के अधिकारियों को दिए गए निर्देश अब स्पष्ट थे—और
स्पष्ट। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ, सलाहकारों ने
राज्यपाल की नियुक्ति तत्काल करनी थी। केंद्र सरकार
लखनऊ में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना पड़ा।
गोडबोले ने सलाहकारों की एक छोटी सूची पहले ही तैयार कर ली थी। यह इसका हिस्सा था।
उन्होंने नवंबर 1992 में जो आकस्मिक योजना तैयार की थी। लेकिन प्रधानमंत्री
उसके अपने विचार थे। उसने गोडबोले द्वारा पहचाने गए सभी नामों को हटा दिया।
संकट के बीच भी, उन्होंने निर्देश दिए कि अब से,
कैबिनेट सचिव, न कि गृह सचिव, नियुक्ति करेंगे।

सलाहकारों से बात करने के बाद, राजगोपाल ने प्रधानमंत्री से बात करके अशोक चंद्र को चुना।
बी. के. गोस्वामी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। यहां तक कि गृह मंत्री से भी परामर्श नहीं लिया गया।
प्रधानमंत्री कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उनके पास अच्छे विचार रखने वाले सलाहकार थे।
उनकी अपनी समस्याएं समस्याग्रस्त साबित हो सकती हैं। रात 1:30 बजे, मंत्रिमंडल सचिव और गृह सचिव ने नए सलाहकारों को जानकारी दी। फिर उन्होंने
वे लखनऊ के लिए बीएसएफ के विमान में सवार हुए। यह एक अलग बात थी कि वे
उस रात खराब मौसम के कारण वापस लौटना पड़ा और अगले दिन जाना पड़ा।
अचानक, प्रधानमंत्री ने अनिर्णय या निष्क्रियता के कोई लक्षण नहीं दिखाए;
वह दृढ़ता और अधिकार के साथ आगे बढ़ रहा था। दिन के अंत तक, राव
उसने पहला दौर जीत लिया था—वह अंदर से हुए हमले में बच गया था।
मंत्रिमंडल में शामिल थे और अभी भी प्रधानमंत्री थे।
रात 11 बजे वैदिक ने राव को फोन करके अर्जुन सिंह के बारे में बताया।
धमकी भरा संदेश। 'राव साहब को तेज बुखार है,' एक अविचलित व्यक्ति ने कहा।
खांडेकर ने उन्हें बताया, 'वह सो रहा है।'

ग्यारहवीं

विध्वंस की कहानी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम यह न देख लें कि पी.वी.
नरसिम्हा राव ने इसके बाद की स्थिति से निपटा—और तब उन्हें समझ आया कि भारत के नौवें प्रधानमंत्री ने हुए नुकसान को किस प्रकार नियंत्रित किया।
उनके प्रधानमंत्रित्व काल को बर्बाद कर दिया गया।
विध्वंस के बाद, उस स्थान पर एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया।
जहां कुछ घंटे पहले मस्जिद खड़ी थी। इसे स्थापित किया गया था।
6 और 7 दिसंबर की रातों में, राव ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, हालांकि
अब राज्य में केंद्र सरकार का नियंत्रण था।
आंतरिक सुरक्षा मंत्री राजेश पायलट और राव के चहेते
उस लड़के ने अपने बॉस को एक शानदार सुझाव दिया। उसने प्रधानमंत्री को बताया।
कि गोंडा में एक जर्जर मस्जिद से एक गुंबद को बचाया जा सकता है

पूर्वी उत्तर प्रदेश से लाया गया और अयोध्या में एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया गया।
destroyed mosque. ‘Uska gumbad toota pada hai. Hum yahan deewar
bana ke us gumbad ko rakh denge (Its dome is lying there broken. We
(गुंबद को यहाँ लाकर उसके चारों ओर दीवार बनाई जा सकती है)। इससे नुकसान कम हो सकता है।
पायलट को लगा कि विध्वंस से कुछ नुकसान हुआ है।
राव ने पायलट को अपनी 'गुंबद' योजना पर आगे बढ़ने के लिए कहा।
शाहिद सिद्दीकी ने कहा, 'राजेश पायलट और मैंने इस पर जमकर काम किया।'
अब देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। 'हम
गुंबद को उठाने के लिए एक सेना के हेलीकॉप्टर की आवश्यकता थी। और इसके लिए, हमने
गृह और रक्षा सचिवों की अनुमति आवश्यक थी। लेकिन राव
मैंने उन्हें “ना” कह दिया।
‘यह आदेश (ऐसा न करने का) ऊपर से आया है,’ एक निराश व्यक्ति ने कहा।
पायलट ने सिद्दीकी को बताया। यह योजना, कई अन्य योजनाओं की तरह, शुरू होने से पहले ही विफल हो गई।
8 दिसंबर 1992 को एल. के. आडवाणी को मुरली के साथ गिरफ्तार किया गया था।
Manohar Joshi, Ashok Singhal, Vishnu Hari Dalmia, Vinay Katiyar,
और उमा भारती। उन पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था।
उकसावे के कारण मस्जिद का विध्वंस हुआ। आडवाणी, जिन्होंने
उन्होंने पहले 6 दिसंबर को 'मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन' कहा था, लेकिन बाद में इसे ‘हिंदू जागरण का दिन’ करार दिया गया था, और इसे अदालत के आदेश से जारी किया गया था।
10 जनवरी 1992 को।

10 दिसंबर को सरकार ने आरएसएस, वीएचपी और बजरंग पर प्रतिबंध लगा दिया।
Dal, Jamiat-e-Islami Hind, and Islamic Sevak Sangh. Six months later,
4 जून 1993 को, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. के. बाहरी की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया।
अदालत के न्यायाधीश को आरएसएस और बजरंग पर लगे प्रतिबंध को रद्द करना था।
दाल। लेकिन उन्होंने वीएचपी के लिए ऐसा करने से परहेज किया, क्योंकि वीएचपी की भूमिका के कारण।
अयोध्या विध्वंस। न्यायाधिकरण ने महसूस किया कि सरकार ने
तीनों हिंदुत्ववादियों के खिलाफ व्यापक मामला तैयार करने में विफल रहा।
संगठनों।
13 दिसंबर 1992 को राव ने सीबीआई को कानून और व्यवस्था की जांच करने का आदेश दिया।
विध्वंस से संबंधित उल्लंघन। 15 दिसंबर 1992 को, केंद्रीय
सरकार ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया।
राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को, इस बीमारी को नियंत्रित करने में उनकी विफलता के लिए
सांप्रदायिक दंगे। उत्तर प्रदेश की तरह, केंद्र ने इन दंगों पर सीधा नियंत्रण कर लिया।
राज्यों। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने एक आयोग का गठन किया।
दोष सिद्ध करने के लिए जांच समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने की थी।
लिबरहान, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश हैं।
सत्रह वर्षों की जांच और अड़तालीस बार समय विस्तार के बाद,
आयोग ने पाया कि विध्वंस 'पूर्व नियोजित' था और उसे अंजाम दिया गया था।
'साहसपूर्वक तैयारी' के साथ—और इसका 'उद्देश्य यह नहीं था कि'
यह योजना दिखावटी थी। ऐसी योजना को गुप्त रखना संभव नहीं था।
आयोग ने फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या आरएसएस का प्रमुख ही दोषी हो सकता है।
हालांकि इसने विनाश के कृत्य के लिए अड़सठ नेताओं पर आरोप लगाया, लेकिन

किसी ने भी
उसे दंडित किया गया।
राव ने अंदर बढ़ते विरोध का मुकाबला करने के लिए ये कदम उठाए।
कांग्रेस ने 'कार्रवाई' की मांग की। उन्हें इसके लिए भी भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था।
विध्वंस के कारण हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे, जिनमें 1,200 लोग घायल हो गए थे।
मृतकों की संख्या 4,000 और घायलों की संख्या में वृद्धि हुई। स्वाभाविक रूप से, भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई।
16 दिसंबर को संसद में राव सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया।
1992—जिसमें वह बच गए।
विध्वंस के तीन सप्ताह बाद, राव सरकार ने फैसला किया कि
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल पर 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया।
जन शांति और सद्भाव के हित में। इसने एक अध्यादेश के माध्यम से ऐसा किया।
7 जनवरी 1993 को अयोध्या में एक निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण का अधिनियम पारित हुआ।
जो बाद में कानून बन गया। केंद्र सरकार ने भी इसका जिक्र किया।
मूल प्रश्न यह है कि क्या मस्जिद से पहले कोई मंदिर मौजूद था।
विवादित स्थल को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने का मामला राव ने उठाया। इस बार राव ने मामला सर्वोच्च न्यायालय में भेजा।
संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत नहीं, बल्कि कल्याण से यह पूछने पर कि क्या उन्होंने ऐसा किया था।
सिंह को इसे स्वीकार करना पड़ा, जो सरकार पर बाध्यकारी होता। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।
संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, जो केवल एक
यह सिफारिश—जिससे कल्याण सिंह सहमत होने को तैयार थे।
जैसा कि बाद में पता चला, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने 'विनम्रतापूर्वक' जाने से इनकार कर दिया।
इस मुद्दे में।

अचानक, झिझकते हुए प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्प दिखाने लगे—और
जिन चीजों पर वह पहले हिचकिचा रहा था, उन्हें करने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया।
खुद को और अपनी सरकार को बचाना।
■

विध्वंस के बाद, अयोध्या में दायर किए गए कानूनी मुकदमों की भरमार हो गई।
मामला दो धाराओं में विभाजित हो गया—दीवानी और आपराधिक। इसके अलावा
विध्वंस के लिए उत्तरदायित्व तय करने हेतु चल रहे दीवानी और आपराधिक मामले
कार सेवकों और भाजपा एवं विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। यह केवल
2002 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी सुनवाई शुरू की।
स्वामित्व तय करने के लिए दायर किए गए दीवानी मुकदमों के तेरह साल बाद
विवादित भूमि को एक साथ मिलाकर इलाहाबाद को हस्तांतरित कर दिया गया।
उच्च न्यायालय।
जुलाई 2003 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खुदाई का आदेश दिया।
विवादित स्थल पर पुरातत्व विभाग द्वारा यह कार्य किया गया।
सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की रिपोर्ट में कहा गया था कि वहां एक संरचना थी।
विवादित संरचना के नीचे, जिसमें मंदिर की दीवारें और
स्तंभ। यह अदालती कार्यवाही में दर्ज किया गया था। लेकिन मुस्लिम समूहों
एएसआई के निष्कर्षों पर विवाद किया गया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया।
अंततः न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। इसने विवादित भूमि को विभाजित कर दिया।
three parts, and gave it to Ram Lalla Virajman, Nirmohi Akhara, and
सुन्नी वक्फ बोर्ड। तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।
अगस्त 2011।

9 नवंबर 2019 को, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाया।
अयोध्या मामले में दीवानी मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए पांच न्यायाधीशों की एक बेंच ने फैसला सुनाया।
संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से लंबे समय से लंबित भूमि विवाद का निपटारा किया।
विवाद। इसने हिंदुओं को उस स्थान पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दी, जबकि
मुसलमानों को कहीं और मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करना।
मंदिर नगर। न्यायालय ने निर्देश दिया कि विवादित 2.77 एकड़ स्थल को
केंद्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा।
नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्माण कार्य सौंपने का विकल्प नहीं चुना।
राम जन्मभूमि न्यास का मंदिर, जिसके कारण
राम मंदिर के लिए आंदोलन। बल्कि, इसने एक नए ट्रस्ट का गठन किया—श्री
Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra—to raise the temple. On 5 August
2020 में राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यह फैसला शायद कारगर न हो।
इससे पीड़ित पक्षों को न्याय मिला, लेकिन इसने एक मामले को समाप्त कर दिया।
यह एक ऐसा मुद्दा था जिसने सत्तर वर्षों से अधिक समय तक भारत को बुरी तरह से विभाजित कर रखा था।
दो आपराधिक मामलों में विनाश के लिए उत्तरदायित्व तय किया जाना है।
बाबरी मस्जिद मामले में कई उतार-चढ़ाव आए। सबसे पहले, निचली अदालत ने अपना फैसला वापस ले लिया।
तकनीकी आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरोप खारिज किए गए। सीबीआई ने
उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। फिर, 2017 में, आरोप लगाए गए।
जिन भाजपा नेताओं पर पहले आरोप लगाए गए थे, उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और
दोनों अलग-अलग मामलों को मिला दिया गया। अंततः, एक विशेष अदालत ने
लखनऊ अदालत ने एल.के. आडवाणी समेत सभी बत्तीस आरोपियों को बरी कर दिया।
Murli Manohar Joshi, Kalyan Singh, Uma Bharati, and Vinay

Katiyar
आपराधिक साजिश के आरोप में (30 सितंबर 2020 को), बीस-
बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के आठ साल बाद। एक फैसले में जो
आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद, अदालत ने अपने 2,000 पृष्ठों के फैसले में कहा कि
विध्वंस की कोई पूर्व योजना नहीं थी, बल्कि यह अचानक ही हुआ।
पल।
■

मस्जिद को गिराए जाने के तुरंत बाद देश में दंगे भड़क उठे।
मुंबई का वित्तीय केंद्र। विध्वंस के विरोध में पहला मुस्लिम प्रदर्शन।
हिंसा भड़क उठी। इसके तुरंत बाद, शिव सेना द्वारा संगठित हिंदुओं ने हिंसा का सहारा लिया।
सेना ने पलटवार किया। राव, जो एक कुशल खिलाड़ी थे, ने इसका फायदा उठाया।
अनिच्छुक रक्षा मंत्री शरद पवार को वापस भेजने का अवसर
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
पवार ने वर्षों बाद याद करते हुए कहा, 'मुझे प्रधानमंत्री के आवास पर बुलाया गया था।'
मैं जाने को तैयार नहीं था। बैठक छह घंटे तक चली। अंततः
पवार मान गए। लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी 'घर वापसी' (घर वापसी)
उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उस भूमिका को सीमित कर दिया जो अन्यथा वे निभा सकते थे।
क्रीड़ा करना।
एक सप्ताह से भी कम समय बाद, 12 मार्च को, बारह बम धमाकों की एक श्रृंखला हुई।
इसने विभिन्न हिस्सों में होटलों, बैंकों और बाजारों को तहस-नहस कर दिया।
मुंबई में एक ही दिन में 257 लोगों की मौत हो गई और 1,400 लोग घायल हो गए।
20 मार्च 1993 को राव ने अपने रक्षा सचिव एन. एन. वोहरा को फोन किया।

शाम को। 'मैं चाहता हूं कि आप सुबह 8 बजे से गृह सचिव का पदभार संभाल लें।'
उन्होंने कहा, 'कल।' वोहरा चौंक गए, क्योंकि अगला दिन एक
रविवार। ‘कल सुबह 6:30 बजे मेरे घर आना और हम
बात करेंगे।
अगली सुबह जब वोहरा प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, तो राव वहां मौजूद थे।
वोहरा अपने बरामदे में स्टेशनरी बाइक पर व्यायाम कर रहे थे, उन्होंने घुटनों तक आने वाले ढीले शॉर्ट्स पहने हुए थे। वोहरा प्रधानमंत्री के व्यायाम समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे।
सुबह के अखबारों को देख रहा था। थोड़ी देर में एक कप कॉफी आ गई।
जब प्रधानमंत्री ने व्यायाम समाप्त कर लिया, तो उन्होंने वोहरा से कहा, 'मैं चाहता हूं कि तुम...'
इस बात की जांच करें कि साढ़े तीन टन विस्फोटक सामग्री कैसे आई।
देश का महानगर।
मैंने रिपोर्ट पूरी करने के लिए खुद को नब्बे दिन का समय दिया था। लेकिन मैं
वोहरा ने कहा, 'इसे पचासी दिनों में पूरा किया।' उन्होंने दस पन्नों का नोट बनाया।
जिसमें किए गए आकलन का सारांश दिया गया और आगे का रास्ता सुझाया गया।
आगे बढ़ें। चूंकि समिति के कुछ सदस्य बोलने में हिचकिचा रहे थे।
वोहरा की अध्यक्षता में हुई बैठकों में वे खुलकर उपस्थित होते थे और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते थे।
और ‘उनकी राय लिखित में प्राप्त की’। वोहरा ने रिपोर्ट की तीन प्रतियां बनाईं।
एक प्रति गृह मंत्री एस. बी. चव्हाण को दी गई, दूसरी राजेश को।
पायलट, आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री, और तीसरे को रखा गया था
गृह सचिव के गोपनीय रिकॉर्ड में। सभी 'सहायक'
वोहरा ने कहा, ‘सामग्री को डीआईबी के टीएस [अति गोपनीय] वॉल्ट में रखा गया था।’
दस पन्नों की रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम और अन्य लोगों का जिक्र किया गया था।
मेमन बंधुओं का इसमें हाथ था। वोहरा ने एक संस्था स्थापित करने का सुझाव दिया।
उनकी अध्यक्षता में गठित समिति जांच को आगे बढ़ाएगी।
फिर एक दिन वोहरा को गृह मंत्री का संदेश मिला।

चव्हाण ने उनसे 'रिपोर्ट वापस लेने' को कहा। एक अनुभवी होने के नाते
उस नौकरशाह ने कुछ नहीं किया। कुछ हफ़्ते बाद, उसे एक और आदेश मिला।
इस बार संदेश में ‘एक पैराग्राफ हटाने’ के लिए कहा गया था—इस पैराग्राफ में यह लिखा था कि
देश के कई हिस्सों में माफिया ने स्थापित सत्ता को विस्थापित कर दिया था।
देश'।
इसके बाद वोहरा ने अपने निष्कर्षों के संबंध में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वोहरा ने कहा, 'मैंने उन्हें इस बारे में जानकारी दी।'
उन्होंने कहा, 'राजनीतिक और अन्य व्यक्तियों के बहुत व्यापक दायरे में से जो
वे विभिन्न नेटवर्कों में शामिल थे।' उनकी जांच में यह बात सामने आई थी।
यह संबंध कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा हुआ है—जिनमें से कई
उन शीर्ष नामों ने रियल एस्टेट, तंबाकू आदि के कारोबार में माफिया के साथ गठबंधन कर रखा था।
शराब, राजमार्ग और अन्य क्षेत्र। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।
कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता था कि वोहरा किसका जिक्र कर रहा था।
मुझे बताया। अनुलग्नक लगभग 1,000 पृष्ठों के थे। वोहरा के पास
अपराधियों, पुलिस और के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित किया गया।
राजनेता। 'इसकी जड़ें गहरी जम गई हैं। यह इतनी गहरी जड़ें जमा चुका था कि यह
यह आसानी से हार नहीं मानने वाला।
इसके बाद के महीनों में सरकार ने आश्वासन दिए।
1993 और 1994 में संसद में तेरह बार यह उल्लेख किया गया कि वोहरा रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इन सबके बावजूद
‘आश्वासन’ तो दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेवानिवृत्त होने से पहले, अपने आखिरी दिन...
31 मई 1994 को कार्यालय में, वोहरा ने आगे की कार्रवाई के लिए मामला उठाया।
रिपोर्ट। उन्होंने कहा, 'मैंने एक हस्तलिखित नोट छोड़ा था...कि तेरहों को देखते हुए
संसद को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि रिपोर्ट समिति को भेजी जानी चाहिए।
संसद के आश्वासनों पर। (राज्य में गठित यह समिति)
1972 में सभा ने संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की गहन जांच की।

यह देखने के लिए कि क्या उन्हें लागू किया गया था।)
राव ने वोहरा रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं किया। न ही उनके उत्तराधिकारियों ने।
और न ही इन परिशिष्टों को कभी सार्वजनिक किया गया। लेकिन इनका अस्तित्व ही
राव के लिए समस्याएँ पैदा करने वालों को चुप कराने के लिए यह काफी था।
प्रधानमंत्री के लिए यह काफी प्रतीत हुआ।
■

‘Aisi baat hai,’ police officer Kishore Kunal told me, ‘Narasimha Raoji
jahaan Ram Lallaji virajman hai, waheen mandir banaana chahte thae
(वास्तव में, नरसिम्हा राव स्वयं इस मंदिर का निर्माण करवाना चाहते थे)
जहां मूर्तियां रखी जाती थीं।
राव ने अपने मीडिया सलाहकार पी.वी.आर.के. प्रसाद को एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया।
जिससे उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया जा सके जहां कभी मस्जिद हुआ करती थी।
विध्वंस के बाद वाले रविवार (13 दिसंबर 1992) को प्रसाद ने
राव से मिलने गया था। उसने प्रधानमंत्री को अकेले और चिंतनशील मुद्रा में पाया।
उन्होंने प्रसाद से पूछा, ‘हम भाजपा से तो लड़ सकते हैं, लेकिन भगवान राम से कैसे लड़ेंगे?’
चिंतनशील भाव से। 'जब हम कहते हैं कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है।'
उन्होंने आगे कहा, ‘मतलब हम नास्तिक हैं। भाजपा (बीजेपी) इस मामले में कितनी हद तक न्यायसंगत है?’ ‘
भगवान राम को एकाधिकार का दर्जा देकर लोगों को धोखा देना
अयोध्या में मंदिर का निर्माण?
इसके बाद उन्होंने 1991 में कांग्रेस की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया।

अयोध्या में मंदिर निर्माण के घोषणापत्र में कहा गया है, 'हमारा उद्देश्य होना चाहिए
मंदिर और मस्जिद दोनों को अदालतों के माध्यम से नहीं, बल्कि अदालतों के माध्यम
से प्राप्त करना होगा।
राजनेताओं के माध्यम से।'
उन्होंने आश्चर्यचकित प्रसाद को 'एक प्रतिनिधि' बनाने का काम सौंपा और
सभी हिंदू मठों के प्रमुखों से मिलकर बनी एक गैर-राजनीतिक समिति और
'पीठम हिंदू धर्म के संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।' वह स्तब्ध रह गया।
उन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं जो सदस्य होने चाहिए— प्रमुखों
अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत पीठ, श्रृंगेरी, कांची, द्वारका, बद्री और पुरी के शंकराचार्य।
फिर उसने दूसरों को जोड़ा
like 'Tamil Nadu Jiyars', and 'Andhra Jiyyangars', heads of Vaishnav
उत्तर में रामानुजा परंपरा से संबंधित गणितज्ञ और उनके प्रमुख
द्वैत परंपरा से संबंधित उडुपी और उत्तरादि मठ।
नामों की झड़ी लगाते हुए, उन्होंने अंत में 'महंतों' का नाम गिनाया।
अयोध्या'। जाहिर है, उन्होंने इस परियोजना पर काफी सोच-विचार किया था।
प्रसाद ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसने किशोर के साथ काम करना शुरू
कर दिया।
कुणाल और नरेश चंद्र। राव ने तत्कालीन प्रमुख दिग्विजय सिंह से भी पूछा।
मध्य प्रदेश के मंत्री की मदद के लिए दिग्विजय सिंह प्रसाद को अपने साथ ले गए।
राव ने कुछ धार्मिक नेताओं से मिलने के लिए विमान का इस्तेमाल किया। उन्होंने
उनमें से कुछ से मुलाकात की।
स्वयं। कई प्रमुख हिंदू संप्रदायों के प्रमुख, जो लगभग सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
हिंदू धार्मिक मतों का संपूर्ण समूह, इसका हिस्सा बनने के लिए सहमत हुआ।
विश्वास। उन्हें सब कुछ गुप्त रखने के लिए कहा गया था। अंततः विश्वास टूट गया।
1995 में पंजीकृत।
राव ने प्रसाद से बैठक बुलाने को कहा। और फिर, अचानक, उसने
ऐसा लग रहा था कि उसकी दिलचस्पी कम हो गई है। उसने एक व्यक्ति से कहा,
'चुनाव खत्म होने तक इंतजार करो।'

प्रसाद हैरान रह गया। और प्रसाद के अनुसार, 'यही कहानी का अंत था'।
यदि राव हर हाल में मंदिर बनवाने के लिए प्रतिबद्ध होते, तो वे
इसका निर्माण कार्य 1995 में ही शुरू हो गया था। लेकिन राव की रुचि इसमें थी।
मंदिर की राजनीति। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा था कि अयोध्या एक ऐसा क्षेत्र था।
जहां हम भाजपा का सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर सकते।
1995 के अंत तक, बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद, मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो चुका था।
यह अब वह भावनात्मक आधार नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था जब ऐसा था
मस्जिद को लेकर विवाद। राव अब अन्य मुद्दों पर ध्यान दे रहे थे।
इससे उन्हें 1996 के आम चुनावों में वोट मिल सकते थे जो कि
बिल्कुल पास ही। उन्होंने परमाणु परीक्षण करने पर विचार किया, लेकिन फिर मना कर दिया।
जब इसकी जानकारी अमेरिकियों तक लीक हुई तो उसने इसका खुलासा कर दिया।
अंततः, उसने
उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रचार करने का विकल्प चुना। उन्होंने इस दिशा में कार्रवाई शुरू की।
हवाला घोटाले में, जिसमें उनकी अपनी पार्टी के कई सहयोगी भी शामिल थे,
इसमें शामिल थे। लेकिन इससे मतदाताओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा। यहां तक कि इस दौरान भी
चुनाव प्रचार के दौरान यह स्पष्ट था कि हवा किस दिशा में बह रही है; लोग
जब राव बोलना शुरू करते थे तो मैं उनकी सभाओं से बाहर निकल जाता था। कांग्रेस
भाजपा बहुमत हासिल करने में विफल रही। भाजपा, जिसके पास सबसे अधिक सीटें थीं,
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सीटों को राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया गया था।
सरकार का गठन करें।

बारहवीं

विध्वंस के तीस साल बाद भी, कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या

नरसिम्हा राव को पता था कि बाबरी मस्जिद को 6 तारीख को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
दिसंबर 1992? क्या उसने हिंदू कट्टरपंथियों के साथ मिलकर साजिश रची थी?
क्या इसे गिराने का कोई प्रयास किया गया था? क्या वह मस्जिद को बचाने के लिए और कुछ कर सकता था?
जैसा कि पूरे अध्याय में देखा गया है, यह मानना मुश्किल है कि राव ने ऐसा किया।
मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वीएचपी-बजरंग के भीतर लोगों का एक समूह
दल-आरएसएस इस ढांचे को ध्वस्त कर सकता है। उसकी खुफिया एजेंसियां
इससे उसे सतर्क हो जाना चाहिए था। यह भी संभव है कि उसके संपर्कों के बीच
BJP–RSS family—like Kushabhau Thakre and K. Sudarshan as
जैसा कि पहले बताया गया था—उन्होंने उसे अपने आगामी स्थानांतरण के बारे में सूचित कर दिया था।
और अयोध्या में सबके सामने इस बात की रिहर्सल चल रही थी कि कैसे
घटना घटने से कुछ घंटे पहले ही ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया था।
भारत के मंत्री को इस बात की जानकारी अवश्य ही रही होगी, क्योंकि कई कारण मौजूद हैं।
जिन एजेंसियों ने उन्हें प्रतिक्रिया प्रदान की।
इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि राव ने साजिश रची थी।
भाजपा और आरएसएस इस ढांचे को गिराने के लिए। लेकिन वह ऐसा कर सकता था।
यह जानते हुए भी कि मस्जिद खतरे में है, उन्होंने कोई कठिन कदम न उठाने का फैसला किया।
इसकी रक्षा के लिए राजनीतिक निर्णय आवश्यक हैं। हो सकता है उसने सुलह कर ली हो।
उसने मस्जिद के गिरने की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि ऐसा होगा
उस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दो जो एक नासूर बन चुकी थी।
हिंदुओं को बढ़ावा देकर भाजपा की राजनीति को हवा दी जा रही है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, वह ऐसा करना चाहता था।

उन्होंने स्वयं उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी।
जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वे हिंदुओं के उद्धारकर्ता बन सकेंगे।
लेकिन 1995 में परियोजना में उनकी रुचि कम हो गई। क्योंकि उनके कार्यकाल के अंत तक
प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंदिर को लेकर हिंदुओं का आंदोलन समाप्त हो गया था।
क्या राव मस्जिद को बचाने के लिए और कुछ कर सकते थे? उनके द्वारा चुने गए विकल्प
जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा वे आसान नहीं थीं। लेकिन वह इलाहाबाद को मना सकता था।
राष्ट्रीय अदालत में उच्च न्यायालय को 6 दिसंबर 1992 से पहले अपना फैसला सुनाना होगा।
भाजपा-आरएसएस-वीएचपी गठबंधन द्वारा मांगी जा रही ब्याज दर के अनुसार।
इससे बिगड़ती स्थिति को शांत किया जा सकता था और उसे सांस लेने में मदद मिल सकती थी।
कमरा। लेकिन, समझ से परे, राव ने ऐसा नहीं किया। हो सकता है उन्होंने कोई विचार किया हो।
उसके लिए लाभ का संतुलन मस्जिद को छोड़ देने में निहित था, यदि ऐसा संभव हो तो
अगर बात यहाँ तक आ गई, तो भाजपा को नई जान देने से बेहतर यही होगा। अदालत का फैसला
इससे भाजपा को या तो मंदिर का निर्माण शुरू करने में मदद मिल सकती थी।
नए जोश के साथ या मंदिर के लिए अपने आंदोलन को तेज करना।
और, अगर भाजपा के साथ टकराव होना ही था, जिसे वह अब देख रहे थे
चूंकि यह अपरिहार्य था, इसलिए वह चाहता था कि यह 1992 में ही समाप्त हो जाए और इसे 1996 के चुनावों के करीब न ले जाया जाए।
शायद इसीलिए राव ने कुछ दिनों तक सेना को न बुलाने का फैसला किया।
6 दिसंबर से पहले, कार सेवकों के वहां इकट्ठा होने से पहले। वी. पी. सिंह
यह सुझाव उन्हें नवंबर 1992 के अंत में दिया गया था, जब
राव ने उनसे सलाह मांगी थी। लेकिन राव ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने जो कुछ

किया वह यह था कि...
सेना को 'सतर्क' करना—न कि उन्हें बैरिकेड्स पर तैनात करना! न ही उन्होंने अभ्यास किया।
अन्य विकल्प।
हालांकि उन्होंने अनुच्छेद 356 का सहारा न लेने के लिए कानूनी कारणों का हवाला दिया—कि
उत्तर प्रदेश में आर्थिक संकट के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
संविधान, और किसी टूटने की आशंका में नहीं—यह है
राव को ऐसे कदम के राजनीतिक नतीजों की चिंता थी। वह जानते थे कि
राम मंदिर की मांग करने पर कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करना
इससे पूरे उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में हिंदू भावनाओं को भड़काया जा सकता है।
देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली राज्य के मौजूदा माहौल को देखते हुए।
इससे केवल भाजपा को ही बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा।
ऐसा किया जा सकता था। जैसा कि उन्होंने बाद में तर्क दिया, इससे आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता था।
सुप्रीम कोर्ट से, अपनी ही पार्टी के भीतर अपने विरोधियों को मौका देते हुए
वे उसे सत्ता से हटाने के लिए इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि उसने अपने भाषण में कहा था।
पुस्तक, अयोध्या, 'बाबरी मस्जिद के साथ-साथ, मैं भी वही था जिसे उन्होंने'
जिसे वे ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे।
मंदिर के विध्वंस के साथ ही मंदिर का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया।
अस्थायी रूप से। विध्वंस के बाद के महीनों में, भाजपा ने
हिंदुओं में पीड़ित होने की भावना पैदा करना मुश्किल था; यह विफल हो गया।
उत्तर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में
एक साल से भी कम समय में, और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली एक गैर-भाजपा पार्टी।

मध्य 1993 में उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन किया, साथ ही साथ
Bahujan Samaj Party.
इसके बाद मंदिर भाजपा के लिए वोट बटोरने का हथकंडा नहीं रह गया।
दिसंबर 1992, हालांकि पार्टी ने इसे लेकर चिंता जताना जारी रखा। यह होगा
इसे मुख्य रूप से अपने प्रमुख मतदाताओं को खुश रखने के लिए अपने घोषणापत्र में शामिल किया गया है।
भाजपा के शीर्ष नेताओं को यह आभास हो गया था कि उन्होंने मंदिर का चुनावी रूप से भरपूर फायदा उठा लिया है।
जितना वे कर सकते थे। 1996 के आम चुनावों में, भाजपा का मुख्य चुनावी अभियान
समस्या मंदिर नहीं, बल्कि राव परिवार के भीतर फैला भ्रष्टाचार था।
सरकार। 'अबकी बारी अटल बिहारी' के नारे के साथ पार्टी ने बिगुल फूंका
इसके करिश्माई नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। 1998 में
और 1999 में, इसने अयोध्या को—और अपनी अन्य दो प्रमुख प्रतिबद्धताओं को—अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और एक समान नागरिक संहिता लागू करना—अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाने और एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
सरकार। भाजपा ने अपने मंदिर संबंधी एजेंडे में अन्य मुद्दे भी जोड़ दिए थे, क्योंकि
देश के माहौल में बदलाव महसूस हुआ।
पी.वी. नरसिम्हा राव ने संभवतः अल्पकालिक लाभ प्राप्त किया होगा
राव ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में अयोध्या संकट को सुलझाने का प्रयास नहीं किया।
नुकसान का आकलन करें—या उसने इसे अनदेखा करना चुना—विध्वंस से
मुस्लिम मानसिकता के कारण। कांग्रेस ने मुस्लिम समर्थन खो दिया। लेकिन, फिर भी
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने समुदाय के विश्वास को ठेस पहुँचाई।
भारतीय संविधान और भारतीय राज्य की रक्षा करने की क्षमता
उनके जीवन और उनके अधिकारों का हनन हुआ। इससे उन्हें असहाय, असुरक्षित और असहाय महसूस हुआ।
अपने ही देश में 'द्वितीय श्रेणी के नागरिक'। इसके अलावा, राव ने इस बात पर भी

ध्यान नहीं दिया।
विध्वंस से भारत की बहुलता पर दीर्घकालिक क्षति होगी
सामाजिक व्यवस्था और उसकी बहुसांस्कृतिक विरासत।
इस विध्वंस ने आक्रामक हिंदू की धारणा को और मजबूत कर दिया।
स्वतंत्र भारत के इतिहास में राष्ट्रवाद जैसा कुछ और नहीं था
हो गया—जिसके साथ ही एक छाया हिंदू राज की शुरुआत हुई। यह था
जिसके परिणामस्वरूप भाजपा का निरंतर उत्थान हुआ।
■

राव की सरकार गिरने के बाद उनका राजनीतिक करियर बुरी तरह से लड़खड़ा गया।
1996 में सत्ता से बेदखल कर दिए गए। उनकी अपनी पार्टी ने ही उन्हें दरकिनार कर दिया। बहुत कम लोगों ने उनका साथ दिया।
कुछ अपवादों को छोड़कर, वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में बने रहे।
मनमोहन सिंह। उन्हें सीपीपी नेता के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था।
और पार्टी अध्यक्ष के रूप में, सीताराम केसरी के लिए रास्ता बनाना पड़ा। मामले भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई। इससे उन्हें दुख और परेशानी हुई।
उन्हें—और अपने जीवन के अंत तक, बाबरी मस्जिद के विध्वंस को—समर्थन दिया।
यह बात नरसिम्हा राव के मन में लगातार बनी रही।
नवंबर 2004 में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान, उन्होंने एक दिन खाना खाने से इनकार कर दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि...
उसे जीने का कोई अर्थ नहीं दिखता था। एक दिन वह बगल में रखी कुर्सी पर बैठा रहा।
दिल्ली के एम्स अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए भी उन्होंने इस बात पर अड़े रहे कि वे कोई भी दवा नहीं लेंगे।
भोजन या पानी। उनकी हताश बेटी वाणी देवी ने संदेश भेजा।
कांग्रेस नेतृत्व उनसे मदद मांग रहा है। कांग्रेस नेता शिवराज

पाटिल ने 24 नवंबर 2004 को उन्हें फोन किया और कहा सोनिया गांधी, अहमद पटेल और राव से मिलने जाएंगे। वे रात 10:30 बजे अस्पताल पहुंचे।
अहमद पटेल ने बीमार नेता को उनकी हठधर्मिता छोड़ने के लिए मनाते हुए, उन्हें चुना। उन्होंने पानी का एक गिलास उठाया और उन्हें पीने के लिए कहा। इस पर, राव, जो अपना आपा खोने के लिए नहीं जाने जाते थे, अचानक उत्तेजित होकर बोले, 'आप लोग आरोप लगाते हैं...'
मुझे मस्जिद तोड़ने के लिए दोषी ठहराया गया है। अब मुझे पानी दो।' राव के जीवनीकार
विनय सीतापति को यह पत्र लिखना था।
राव ने आगे कहा, 'गलती किसने नहीं की? (लेकिन) मुझे क्यों करनी चाहिए?'
मुझे किसी ऐसी चीज के लिए दोषी ठहराया जा रहा है जो मैंने नहीं की?
सोनिया गांधी वहां बैठी सुन रही थीं। लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा।
आगंतुक अंततः सुबह 2:30 बजे चले गए। अगली सुबह, वह बिल्कुल सामान्य थे।
खुद से बात की और खाना शुरू कर दिया। फिर उसने बच्चों से पूछा, 'क्या मैंने ज़्यादा बात की?'
जितना मुझे करना चाहिए था उससे अधिक?
नरसिम्हा राव का निधन एक महीने बाद यानी 23 दिसंबर 2004 को हो गया।
राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस में लाया गया।
मुख्यालय की ओर जाते समय, इसे बंद द्वारों पर ही रोक दिया गया था।
फूलों से सजे जुलूस को अकबर रोड स्थित 24 नंबर की इमारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।
ताकि उनके पार्टी सहयोगी उस व्यक्ति को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें, जिसने
उन्होंने आधी सदी तक कांग्रेस की सेवा की।
जिस प्रकार विध्वंस की घटना ने राव को जीवन भर परेशान किया, उसी प्रकार विध्वंस में उनकी भूमिका ने भी उन्हें प्रभावित किया।
इससे कांग्रेस नेतृत्व परेशान हो गया और उन्होंने उसे तब तक माफ नहीं किया जब तक कि...
समाप्त।

अध्याय 5

शांतिप्रिय प्रधानमंत्री जो दहाड़ते थे

ए. बी. वाजपेयी ने परमाणु उपकरणों के परीक्षण को अधिकृत किया

मैं

अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की आपातकालीन बैठक में पहुंचने में देर हो रही है।
मंत्री मोरारजी देसाई ने साउथ ब्लॉक में जल्दी से प्रवेश करते हुए फोन किया था।
बैठक को एक 'गुप्त' मामला माना जा रहा था। दिल्ली, उसने सोचा था,
अप्रैल 1979 का महीना होने के बावजूद भी पहले से ही बहुत गर्मी थी।
लेकिन जिस लाल बलुआ पत्थर की इमारत में उसने कदम रखा, उसके अंदर काफी ठंडक थी।
जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय स्थित था।
देसाई ने अपने शीर्ष चार मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाया था।
अत्यावश्यक रूप से। रक्षा मंत्री, मोटे-ताज़े बाबू जगजीवन राम,
सबसे पहले अंदर आने वाले व्यक्ति। अपनी खास खादी की गांधी टोपी पहने हुए, वह एक
रायसीना हिल पर एक जाना-पहचाना चेहरा, जो अपने समय से ही मंत्री रहे हैं।
जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद चरण सिंह आए, जो अब वित्त मंत्री हैं।
मंत्री, लेकिन किसान नेता के रूप में अधिक जाने जाते थे। केवल तीन महीने पहले,
देसाई ने जगजीवन राम और चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया था।
यह उनके द्वारा अपनी कलहग्रस्त सरकार में किए गए एक युद्धविराम का हिस्सा था।
गंजे सिर वाले गृह मंत्री एच.एम. पटेल ठीक उनके पीछे आए—और
पटेल के बाद वाजपेयी विदेश मंत्री बने।
भारत।

मोरारजी देसाई अपने कार्यालय में बेचैनी से बैठे थे और बेसब्री से अपनी प्रतीक्षा कर रहे थे।
सहकर्मियों के आने का इंतज़ार कर रहा था। सामान्य से अधिक गंभीर दिखते हुए, वह चाहता था कि...
इस बैठक को समाप्त करो। अगर उसे खुद पर छोड़ दिया जाता, तो वह इसे बुलाता ही नहीं।
चारों मंत्री अपनी-अपनी सीटों पर बैठ गए और उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे।
प्रधानमंत्री को उन्हें यह बताना था कि उन्होंने उन्हें अचानक क्यों बुलाया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने
उन्होंने उन्हें यह नहीं बताया कि प्रधानमंत्री उनसे क्यों मिलना चाहते थे।
अत्यावश्यक रूप से। सामान्यतः, वे अपने साथ होते।
विभाग के सचिव। लेकिन, इस बार उन्हें अकेले आने के लिए कहा गया था। मंत्री जनता सरकार की सर्वोच्च निर्णय समिति के सदस्य थे।
गठन निकाय—राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति।
मोरारजी देसाई ने तुरंत मुद्दे पर आते हुए कहा। उन्होंने उन्हें फोन किया था।
सरकार को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए।
वाजपेयी, राम और पटेल अब सचमुच उत्सुक थे। वे जानते थे कि
देसाई भारत द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने के खिलाफ थे। अब तक वे
वे इस विषय पर चर्चा करने से भी कतरा रहे थे। देसाई ने उन्हें बताया कि
अब निर्णय को और टाला नहीं जा सकता था। क्योंकि पाकिस्तान कगार पर था।
परमाणु हथियार हासिल करने के बारे में।
उन्हें इस 'गुप्त' बैठक को बुलाने के लिए प्रेरित करने वाली बात एक रिपोर्ट थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा था।
यह बात संयुक्त समिति के अध्यक्ष के. सुब्रह्मण्यम ने कही थी।
सरकार की खुफिया समिति। सुब्रह्मण्यम ने यह बात कही थी।
कि पाकिस्तान 'बम बनाने से बस एक पेचकस की दूरी पर था'।
1979 में, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति विकसित करने की ओर अग्रसर है।

'हथियार,' लंबे और गंभीर स्वभाव वाले सुब्रमण्यम ने मुझे अपने फ्लैट में बताया।
नई दिल्ली में वसंत कुंज।
रिपोर्ट पूरी होते ही सुब्रह्मण्यम ने उसे सौंप दिया था।
अब कैबिनेट सचिव निर्मल मुखर्जी को। उस पर सरसरी नजर डालते हुए, एक
चिंतित मुखर्जी ने सुब्रह्मण्यम को चेतावनी दी, 'मोरारजी बहुत होने वाले हैं
इस रिपोर्ट से असंतुष्ट।
'यह रिपोर्ट तैयार करना मेरा कर्तव्य है,' सुब्रह्मण्यम ने उत्तर दिया।
वह अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते थे, और 'आप भी इसे उतनी ही गंभीरता से लें।'
भारत का परमाणु शक्ति बनना एक ऐसा मुद्दा था जो सुब्रह्मण्यम के दिल के बेहद करीब था।
सुब्रह्मण्यम ने याद करते हुए कहा, 'आम तौर पर इन बैठकों में, मैं अपने पास रखता था।'
'मिनटों की गिनती करो।' लेकिन उस दिन मुखर्जी ने उनसे 'बाहर रहने' को कहा।
'सुब्बू, तुम...मीटिंग में मत आना,' उन्होंने निर्देश दिया।
सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'किसी भी अन्य सचिव को अंदर आने की अनुमति न दें।'
कैबिनेट सचिव ने आगे कहा, 'दोनों में से कोई भी नहीं।'
हमने विदेश सचिव को छोड़कर किसी भी सचिव को सूचित नहीं किया था।
(जगत मेहता)। मंत्रियों के अलावा, केवल दो अधिकारी थे।
उस दिन सीसीपीए की बैठक में वे सभी उपस्थित थे। उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।
परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी सेठना और निर्मल
Mukherji.
जैसे ही बैठक शुरू हुई, प्रधानमंत्री ने अपनी बात छुपाने की कोशिश नहीं की।
रिपोर्ट से उनकी असंतुष्टि थी। वे इससे 'बेहद आश्चर्यचकित' थे।
उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि सुब्रह्मण्यम के निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट में सिफारिशें की गई हैं।
भारत को तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता थी—और इसका मतलब प्रधानमंत्री के परमाणु-विरोधी रुख और उनकी संपर्क नीति के विरुद्ध जाना होता।

इस्लामाबाद। लेकिन रिपोर्ट के निष्कर्षों की गंभीरता को देखते हुए, देसाई ऐसा नहीं कर सके।
बैठक स्थगित कर दी गई। क्योंकि इसमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या भारत
परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए। बैठक डेढ़ घंटे तक चली।
घंटे।
बैठक समाप्त होने के बाद, कैबिनेट सचिव तुरंत संक्षिप्त जानकारी देने के लिए बाहर आए।
सुब्रह्मण्यम। उन्हें कार्यवाही का विवरण तैयार करना था—और उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि...
प्रतीक्षाकक्ष में प्रतीक्षा करें।
'कैसा रहा?' सुब्रह्मण्यम ने उत्सुकता से उससे पूछा।
मुखर्जी ने बेपरवाही से जवाब दिया, 'निर्णय यह था कि हमें...'
हम अपने प्रयासों को जारी रखेंगे।
मुखर्जी की बातों का महत्व समझते हुए, सुब्रह्मण्यम ने
पूछा गया, 'क्या यह सर्वसम्मति से है?'
मुखर्जी हँसे। उन्होंने कहा, 'नहीं, फैसला विभाजित था। यह 3:2 था।'
'मोरारजी ने इसका विरोध किया होगा,' सुब्रह्मण्यम ने उत्सुकता से पूछा।
'जी हां,' मुखर्जी ने उत्तर दिया।
मुखर्जी ने पूछा, 'अनुमान लगाओ दूसरा व्यक्ति कौन था?'
सुब्रह्मण्यम।
'Was it Charan Singh?' he asked Mukherji.
Subrahmanyam knew that H. M. Patel and Jagjivan Ram had
भारत द्वारा बम परीक्षण को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे। 'मैंने पहले ही बात कर ली थी।'
एच. एम. पटेल और जगजीवन राम को। और मुझे पता था कि वे इसके पक्ष में थे।'
और, उन्होंने
यह भी पता था कि वाजपेयी की मूल पार्टी, भारतीय जनसंघ (
भाजपा के पूर्ववर्ती संगठन ने दिसंबर 1962 से खुले तौर पर यह वकालत की थी कि भारत परमाणु हथियार संपन्न देश (एनडब्ल्यूएस) बन गया। वाजपेयी ने स्वयं ऐसा

होने से रोका था।
1964 में संसद में बम के पक्ष में भाषण दिया गया था।
‘No, it was Vajpayee,’ Mukherji said, to Subrahmanyam’s surprise.
सुब्रह्मण्यम ने बाद में मुझसे पुष्टि की कि 'मोरारजी और वाजपेयी थे।'
आगे बढ़ने का विरोध किया। एच. एम. पटेल, जगजीवन राम और चरण सिंह
वे इसके पक्ष में थे।
■

सुब्रह्मण्यम की रिपोर्ट ने भारत के राजनेताओं और वैज्ञानिकों को चौंका दिया।
उठो। ‘उनके (पाकिस्तान) पास नई सेंट्रीफ्यूज तकनीक थी। ऐसा हो सकता है
सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को समृद्ध करने में किया जाता है।'

वैज्ञानिक विशेष रूप से चिंतित थे क्योंकि '1979 में हमने (भी)
उन्हें ए. क्यू. खान के बारे में नए सबूत मिले थे। उन्हें खबर मिली थी कि परमाणु
वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान—जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु विज्ञान का जनक माना जाता है—
बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था।
पाकिस्तान। अपनी रिपोर्ट में सुब्रह्मण्यम ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था
‘पाकिस्तान अब इस नई तकनीक का उपयोग करके परमाणु ऊर्जा विकसित कर रहा था’।
खान 1952 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद से वहीं रह रहे थे।
यूरोप में काम कर रही थी। यह सितंबर 1974 की बात है, इंदिरा गांधी के चार महीने बाद।
गांधी ने 18 मई को भारत के 'शांतिपूर्ण परमाणु उपकरण' का परीक्षण किया था,
भोपाल में जन्मे खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जेड. ए. भुट्टो को पत्र लिखा और प्रस्ताव रखा

उन्होंने अपनी विशेषज्ञता पाकिस्तान को सौंपी। अब उन्होंने पाकिस्तान के साथ काम करना शुरू कर दिया।
परमाणु ऊर्जा आयोग। भुट्टो ने उसे इस पर स्वायत्त नियंत्रण दिया।
पाकिस्तान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम जिसका उपयोग बनाने के लिए किया जाएगा
खान ने पाकिस्तान के स्वदेशी परमाणु बम के विकास पर ध्यान केंद्रित किया।
कहूटा में यूरेनियम संवर्धन क्षमता। बहुत बाद में खान
वह बागी हो गया था और उस पर उत्तर कोरिया को परमाणु रहस्य बेचने का आरोप लगाया गया था।
कोरिया, लीबिया, ईरान और अन्य देश।
पाकिस्तान की गतिविधियों को सबसे पहले समझने वाला व्यक्ति वास्तव में
परमाणु वैज्ञानिक के. संथनम—जिन्हें उनके सहकर्मी सैंटी के नाम से जानते थे।
उन्होंने आर एंड एडब्ल्यूएस में रणनीतिक विश्लेषक के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में, 1986 में, वे इसमें शामिल हो गए।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ),
देश का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्थापित करना।
‘मैंने पाकिस्तान के कार्यक्रम का पर्दाफाश किया था (1976 में),’ संथानम ने कहा।
खुलासा हुआ। (लेकिन, उस समय,) किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि
ट्रॉम्बे में होमी सेथना जैसे बड़े लोग थे। होमी सेथना ही वह व्यक्ति थे।
इंदिरा गांधी के समय परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) की अध्यक्ष
वह प्रधानमंत्री थे। सुब्रह्मण्यम द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही यह घटना घटी।
वैज्ञानिक जगत ने इस बात पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया कि
संथानम यही कह रहा था।
भारत के बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी।
1971 में बांग्लादेश के निर्माण के साथ देश का विभाजन हुआ,

पूर्व पूर्वी पाकिस्तान ने जनवरी 1972 में परमाणु शक्ति बनने का निर्णय लिया।
क्योंकि उसे लगा कि उसे वह सारी मदद नहीं मिली जो वह चाहती थी—भले ही वह चीन से सहायता प्राप्त करना। चीन ने पाकिस्तान के साथ अपनी सहायता साझा की थी।
16 अक्टूबर 1964 को किए गए लोप नोर परीक्षणों से परमाणु बम के डिजाइन।
इन वर्षों में इसने पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को 'महत्वपूर्ण सहायता' प्रदान की। पाकिस्तान का शस्त्रागार मूलतः चीनी निर्मित था।
डिज़ाइन।
‘(जेड. ए.) भुट्टो ने परमाणु वैज्ञानिकों की एक बैठक बुलाई थी...
पाकिस्तानी लोगों को लगता था कि अमेरिकियों और यहां तक कि चीनियों ने भी उनकी मदद नहीं की।
जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी,’ रणनीतिक विश्लेषक सी. राजा मोहन ने कहा। बाद में चीन
पाकिस्तानी लोगों के प्रति 'असाधारण रूप से' उदार हो गया क्योंकि पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों ने इसके साथ उच्च गति के बारे में रहस्य साझा किए थे।
हथियार बनाने योग्य यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए सेंट्रीफ्यूज तकनीक का उपयोग।
■

सीसीपीए की बैठक के एक दिन बाद, सुब्रह्मण्यम ने वाजपेयी का सामना किया।
उन्होंने वाजपेयी से पूछा, ‘आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? आप तो इसके पक्ष में रहे हैं।’
सभी के साथ।'
नहीं, नहीं, अब सबसे महत्वपूर्ण बात पाकिस्तान को रोकना है।
'बम बनाना,' वाजपेयी ने बचाव करते हुए जवाब दिया। 'और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।'
उन्हें उकसाओ।'
मोरारजी देसाई का रुख सर्वविदित था, लेकिन वाजपेयी का रुख

सीसीपीए की बैठक सुब्रह्मण्यम के लिए एक झटके के रूप में आई थी। क्योंकि, जब तक
तब वाजपेयी को परमाणु समर्थक के रूप में देखा जाता था। सुब्रह्मण्यम
मुझे याद है कि चीन के कुछ दिनों बाद वाजपेयी संसद में गरजते हुए बोले थे।
अपने पहले परमाणु परीक्षण में 16 किलोटन का बम विस्फोट किया, जिससे यह पांचवां परमाणु परीक्षण करने वाला देश बन गया।
परमाणु हथियारों के विशिष्ट क्लब में शामिल होने वाला राष्ट्र: 'परमाणु का एकमात्र समाधान'
'बम एक परमाणु बम है, और कुछ नहीं,' उसने गरजते हुए कहा था।
चीन के इस परीक्षण ने भारत में चिंता पैदा कर दी थी, क्योंकि यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ था जब चीन ने अपने देश में ही परीक्षण किया था।
1962 में भारत-चीन युद्ध के दो साल बाद। इससे उत्पन्न खतरे को लेकर चिंतित।
भारत की सुरक्षा के लिए एक मुखर जनसंघ और विपक्ष खतरा बन सकते हैं।
वाजपेयी जिस पार्टी से संबंधित थे, उसने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया।
27 नवंबर 1964 को जारी एक पत्र में भारत से परमाणु हथियार बनाने का आह्वान किया गया था।
हथियार। जनसंघ ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की।
और ऐसा उन्होंने आने वाले महीनों में बार-बार किया—क्योंकि उन्होंने अनदेखी की थी
चीन ने भारत के लिए जो खतरा पैदा किया, खासकर परमाणु समझौते में उसके प्रवेश के बाद।
क्लब।
■

वाजपेयी के बदले हुए रुख ने उनके मंत्री सहयोगियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया था।
बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा दिए गए आश्वासनों को दोहराया था। अपने कार्यकाल के दौरान

13-14 जून 1978 को वाशिंगटन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान, देसाई ने यह प्रतिज्ञा की थी कि
भारत परमाणु हथियार न तो बनाएगा और न ही हासिल करेगा, भले ही बाकी देश ऐसा करें।
दुनिया ने ऐसा किया' और यह कि इसने 'परमाणु विस्फोटों का भी त्याग कर दिया'
शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। या यह कि मोरारजी की तरह वाजपेयी भी चाहते थे कि...
पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारना। कश्मीर मुद्दे का समाधान खोजना।
यह समस्या वाजपेयी के बचपन से संजोए सपनों में से एक थी।
जनसंघ में बिताए वो दिन जब उन्होंने इसके संस्थापक श्यामा के साथ काम किया था
प्रसाद मुखर्जी। लेकिन, 1979 में विदेश मंत्री के रूप में वाजपेयी
सही पक्ष में बने रहने की आवश्यकता से प्रेरित हो सकता है
प्रधानमंत्री। और अपने लिए एक अलग मुकाम हासिल करना, जो कि था
यह उनकी पार्टी की स्थिति से बिल्कुल अलग था। इससे उन्हें अपने विचारों को आकार देने में मदद मिली।
एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि जो उदारवादी थे, कट्टरपंथी नहीं।
■

यह पहली बार नहीं था जब वाजपेयी ने इस मुद्दे पर अपना रुख बदला हो।
परमाणु मुद्दा। 1950 के दशक में, वे शांतिवादी थे। 1960 के दशक में, वे एक
अपनी पार्टी की इस स्थिति के अनुरूप कि भारत को अधिग्रहण करने की आवश्यकता है, वह कट्टरपंथी रुख अपनाते हैं।
परमाणु हथियार। 1970 के दशक में, वह फिर से शांतिवादी बन गए थे।
1950 के दशक में उन्होंने एक व्यथित कविता भी लिखी थी, ‘हिरोशिमा की’
'पीड़ा' (हिरोशिमा की पीड़ा)। यह कविता हिरोशिमा में हुई तबाही के बारे में थी।
हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों के कारण
6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर में, उन्होंने लगभग लोगों को मार डाला था।
210,000 लोग। कविता में, उन्होंने भावुकतापूर्वक प्रश्न पूछे।

बम का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों ने क्या कभी एक पल के लिए भी ऐसा महसूस किया?
वाजपेयी ने भावुक होकर पूछा, क्या उन्हें अपने किए पर पछतावा था?
जब उन्हें अपने इलाके में हुई तबाही के बारे में पता चला तो वे रात को चैन से सो पाए।
इस आविष्कार का क्या कारण था?
उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न उनके अपने आंतरिक उथल-पुथल को दर्शाते प्रतीत होते थे।
परमाणु हथियारों से मानवता को होने वाले खतरे।

कभी-कभी रात में,
अचानक, नींद मेरा साथ छोड़ देती है।
मेरी आंखें खुल गईं,
मैं सोचने लगता हूँ—वे वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु हथियारों का आविष्कार किया,
उस भयावह मानव विनाश के बारे में सुनकर,
हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में,
वे रात को कैसे सो पाते होंगे?
■

अप्रैल 1979 में हुई CCPA की बैठक में एक ऐसा मोड़ आया—जो अंततः सफल नहीं हुआ।
प्रकाश। हालाँकि सुब्रह्मण्यम को कैबिनेट सचिव ने बताया था।
सीसीपीए ने सामरिक परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने के लिए 3:2 के बहुमत से निर्णय लिया था।
दरअसल, अगले कदम उठाने के बारे में मतदान हुआ था।
हथियार बनाना। दूसरे शब्दों में, क्या भारत को परमाणु बम विकसित करने चाहिए?
और वितरण प्रणालियाँ। इस बार, 3:2 के मत से, CCPA ने निर्णय लिया
भारत द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने के विरोध में मतदान हुआ। इस मतदान का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया।
बैठक के बाद, सुब्रह्मण्यम ने कृष्णकांत को बताया, जिनके पास सब कुछ था।

मोरारजी देसाई उनके साथ बम के लिए युद्ध में उनके साथी रहे थे।
उन्होंने अपने निर्णायक वोट का प्रयोग किया।
प्रधानमंत्री अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल टाई होने की स्थिति में करते हैं।
उनके अन्य मंत्रिस्तरीय सहयोगियों के मत 2:2 के अनुपात में बराबर विभाजित थे।
अपनी ज्ञात स्थिति को देखते हुए, मोरारजी का वोट स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ ही होता।
परमाणु हथियार हासिल करने की ओर अग्रसर। लेकिन हो सकता है कि वह ऐसा चाहता हो।
सरकार के रुख के बारे में अस्पष्टता बनाए रखें ताकि ऐसा न हो कि
इससे भारत अपने विरोधियों की नजरों में कमजोर हो जाएगा, खासकर
पाकिस्तान।
आधिकारिक रिकॉर्ड की बात करें तो, कार्यवाही विवरण में बस इतना ही लिखा था कि देश अपना रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा।
स्वतंत्रता के बाद से हर सरकार द्वारा अपनाए गए रुख के अनुरूप।
जनता पार्टी के सत्ता में आने के संक्षिप्त अंतराल को छोड़कर।
1977 में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दिया गया।
सरकार'।
सुब्रह्मण्यम ने मुझे बताया कि उन्होंने कार्यवाही का विवरण 'अपने हाथ से' लिखा था।
और उन्हें मोरारजी देसाई को भेज दिया। प्रधानमंत्री ने कार्यवाही के विवरण पर हस्ताक्षर किए।
तुरंत। उस समय मोरारजी देसाई परमाणु मंत्री भी थे।
ऊर्जा।
सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'मैंने कार्यवाही की ज़ेरॉक्स कॉपी ली और उड़ान भरी।'
इसे बॉम्बे ले जाकर सेठना को सौंप दिया।
एईसी के अध्यक्ष होमी सेथना ने कुछ ही समय बाद मोरारजी देसाई से मुलाकात की।
सीसीपीए की बैठक में। उन्होंने प्रधानमंत्री से सीधे-सीधे पूछा, 'क्या आप
क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे (परीक्षण के लिए) करूं?
जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं कभी भी किसी प्रयोग की अनुमति नहीं दूंगा।
देसाई ने सेठना को बताया। लेकिन देसाई ने उन्हें डिजाइन को 'सुधारने' की अनुमति दे

दी।
विस्फोटक उपकरण का। वैज्ञानिक इसे 'छोटा' करने की कोशिश कर रहे थे।
सब कुछ' और उपकरण का वजन और व्यास कम करें। हालाँकि,
यह स्पष्ट था कि यह बम से बहुत दूर होगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
वैज्ञानिकों को जो करने की अनुमति दी गई थी, वह केवल भारत के चल रहे परमाणु कार्यक्रम को जारी रखना था।
कार्यक्रम, अनुसंधान का विस्तार, परमाणु प्रौद्योगिकी का उन्नयन, और
बुनियादी ढांचे और डिजाइन को परिष्कृत करना—लेकिन हथियारों के निर्माण तक नहीं पहुंचना।
■

एक घोषित गांधीवादी के रूप में, मोरारजी देसाई को भारत में उत्पादन के प्रति घृणा थी
परमाणु हथियार कोई रहस्य नहीं था। मार्च में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद।
1977 में, भारत में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट आर. गोहीन ने उनसे मुलाकात की थी।
उन्होंने नए प्रधानमंत्री के समक्ष भारत की परमाणु नीति का मुद्दा उठाया और कहा
वह देसाई से 'अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की ओर से' बात कर रहे थे।
प्रधानमंत्री से पूछा गया कि क्या वे परमाणु उपकरण को मंजूरी देने की योजना बना रहे हैं।
राजदूत ने देसाई से आश्वासन मांगा, उन्होंने एक अप्रत्यक्ष संकेत भी दिया।
खतरा: तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए अमेरिका द्वारा आपूर्ति किया गया कोई भी ईंधन।
इसका उपयोग केवल बिजली उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में नहीं।
उपकरण। इस पर देसाई सचमुच क्रोधित हो गए। इसमें कोई सवाल ही नहीं था।
देसाई ने जवाब दिया कि भारत अपने सहमत प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा,

जो अपनी आत्म-धार्मिकता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने यह बात 'जोरदार' ढंग से कही और
‘भावनात्मक रूप से’।
अप्रैल 1979 में सीसीपीए द्वारा 'आगे बढ़ने' के निर्णय के बावजूद
परमाणु कार्यक्रम के दौरान शेष महीनों में कुछ खास प्रगति नहीं हुई।
जनता सरकार। तीन महीने बाद मोरारजी सरकार गिर गई।
हालांकि, राजनीति में हमेशा मौजूद रहने वाली उन दुर्लभ विडंबनाओं में से एक यह है कि,
वाजपेयी, जो 1950 के दशक में शांतिवादी थे, 1964 तक कट्टरपंथी बन गए और फिर से परमाणु युद्ध के पक्षधर हो गए।
1979 में, दो दशक बाद इतिहास रचने वाला था। 1998 में, प्रधान मंत्री के रूप में
मंत्री के रूप में, उन्होंने भारत को परमाणु हथियार क्लब में शामिल किया। वह
इसका औचित्य यह कहकर सिद्ध करें कि परमाणु हथियारों ने युद्ध को रोका। और यदि भारत
अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना आवश्यक था, इसके लिए एक व्यवस्था का होना जरूरी था।
विश्वसनीय परमाणु निवारक।

द्वितीय

वाजपेयी ने एक बार चुटकी लेते हुए कहा था, 'मैं सबसे लंबे समय से प्रधानमंत्री बनने की प्रतीक्षा कर रहा व्यक्ति हूं।'
1988 में, उन्होंने अपने मित्र, जनता पार्टी के नेता कृष्णकांत से यह बात कही थी। यह टिप्पणी उन्होंने आधी मज़ाक में की थी, लेकिन इसमें उनकी अंतर्निहित निराशा झलकती थी। नौकरी
बहुत लंबे समय से अपेक्षित था। यहां तक कि उनके पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी।
1996 में एक बार उन्हें दो संक्षिप्त कार्यकाल झेलने पड़े थे, इससे पहले कि वे
अंततः उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। यह कार्यकाल भी कुछ महीनों पहले ही समाप्त हो गया।

क्योंकि उन्होंने 2004 में समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया था।
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले यह बात कही थी।
1950 के दशक में वाजपेयी की प्रतिभा को पहचाना गया। वाजपेयी पहली बार नेहरू के पास आए थे।
1958 में नोटिस जारी किया गया। उन्होंने विदेश नीति पर एक बहस के दौरान भाषण दिया था।
लोकसभा। नेहरू उनकी वाक्पटुता और भाषा की समझ से प्रभावित थे।
विदेश मामलों पर चर्चा के दौरान जब नेहरू ने जवाब दिया, तो उन्होंने—प्रधानमंत्री ने भी—
विदेश मामलों का प्रभार संभाला—अचानक अंग्रेजी से भाषा बदल दी
उन्होंने अपने भाषण के बीच में ही हिंदी का प्रयोग किया। उन्होंने ऐसा जानबूझकर वाजपेयी को सक्षम बनाने के लिए किया।
जो हिंदी में अधिक सहज था, वह सभी बारीकियों को समझ सकता था।
प्रधानमंत्री की उनके भाषण पर प्रतिक्रिया।
1960 में, तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने
भारत आए। यह एक हाई-प्रोफाइल यात्रा थी। सरकार ने एक योजना बनाई।
उनके लिए भोज का आयोजन किया गया। वाजपेयी, जो पहले से ही सांसद थे, को इसमें आमंत्रित किया गया था।
सोवियत नेता के बगल में, प्रधानमंत्री नेहरू परिचय करा रहे थे।
उनके यहाँ आने वाले भारतीय अतिथियों के बारे में नेहरू ने वाजपेयी के बारे में कहा था,
‘यही हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं।’ नेहरू ने वाजपेयी को प्रोत्साहित करते हुए कहा।
अपने शुरुआती वर्षों में—उन्होंने एक बार अमेरिका में तैनात एक भारतीय राजदूत को प्रशिक्षण दिया था।
वाजपेयी को उन लोगों से 'परिचय' कराना 'जो मायने रखते थे' क्योंकि 'उनके पास' संभावना...।'
हालांकि वाजपेयी प्रधानमंत्री की आलोचना करते थे, नेहरू
युवा सांसद का समर्थन जारी रखा। जब वाजपेयी गए थे
1962 के दौरान नेहरू के निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाया गया

था।
आम चुनाव—नेहरू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई थी जो
वाजपेयी पर निशाना साधते हुए कहा, 'आने दो ना।' वो...अच्छा बोलता है. बोलने दो ना
(उसे आने दो, यह नौजवान अच्छी तरह बोलता है, उसे बोलने दो)।' फिर उसने
added, 'Jisko vote dena hai toh doh, nahin dena toh mat doh (If voters
अगर वे मुझे वोट देना चाहते हैं, तो ठीक है, अगर वे किसी और को वोट देना चाहते हैं, तो भी ठीक है।
ठीक है)।' वाजपेयी ने बाद में इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए कहा था
शिवराज पाटिल—वे लोकसभा अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बनने वाले थे।
गृह मंत्री—जब वह उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने गए
1996 में लातूर निर्वाचन क्षेत्र में वाजपेयी को उनके बारे में अच्छी बातें कहते हुए सुनकर।
बाद में उनके पति शिवराज पाटिल की पत्नी विजया ने उन्हें चिढ़ाया था।
'क्या आपने उन्हें रैली में बोलने के लिए आमंत्रित किया था या उनकी पार्टी ने?'
लेकिन नेहरू की तरह वाजपेयी भी मानते थे कि चुनावी लड़ाइयाँ
लोकतंत्र में राजनीतिक विरोधियों के बीच संबंधों का अपना स्थान था, लेकिन उनके बीच संबंध नहीं थे।
हमेशा टकराव की स्थिति होना जरूरी नहीं है।
■

वाजपेयी के व्यक्तित्व और राजनीतिज्ञ के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए अब एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने वह निर्णय क्यों और कैसे लिया जिसने भारत को इसका हिस्सा बनाया।
परमाणु संघ। उनकी अपरंपरागत जीवनशैली इसके विपरीत थी।
अपनी पार्टी की कट्टरपंथी विशेषताओं के बावजूद, वह अपनी स्थिति बनाए रखने में

कामयाब रहे।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए हमेशा से ही यह बात दिलचस्प रही है कि वह इस पद तक कैसे पहुंचे।
एक कट्टरपंथी हिंदू पार्टी में उदारवादी बनें।
मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि नेहरू के बाद के प्रधानमंत्रियों ने किस प्रकार इस स्थिति से निपटा।
परमाणु प्रश्न को हल किया और कार्यक्रम को जारी रखा—जो कि देता है
वाजपेयी ने परमाणु विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय क्यों लिया, इस बारे में अंतर्दृष्टि।
1998.
वाजपेयी परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश से था। वे
आगरा जिले का मंदिरों से घिरा हुआ बटेश्वर गांव—अपनी किंवदंती के लिए प्रसिद्ध
जब भगवान शिव पहाड़ों में नहीं होते थे, तो वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे।
यहां ध्यान लगाने के लिए पेड़ है। वाजपेयी के दादा, श्याम लाल वाजपेयी, थे।
एक कन्याकुब्ज ब्राह्मण थे और ग्वालियर जिले के मोरेना में आकर बस गए थे।
मध्य प्रदेश. तब वाजपेई के पिता कृष्णबिहारी वाजपेई थे
ग्वालियर चले गए और वहाँ एक स्कूल शिक्षक बन गए। अटल बिहारी
उनका और उनकी पत्नी कृष्णा देवी का जन्म 1924 में क्रिसमस के दिन हुआ था—और
मैं एक संकरी गली में स्थित दो मंजिला घर में पला-बढ़ा।
ग्वालियर। लड़के को कविता का शौक बचपन से ही स्वाभाविक रूप से था। उसने इसे सीख लिया था।
उन्हें यह विरासत अपने पिता से मिली, जो अपनी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे।
छोटा अटल बिहारी स्कूल जाते समय कविताएँ सुनाता था, अपने हाथ में पकड़े हुए।
उसके पिता की उंगली, और कृष्णा बिहारी उसकी भाषा को सुधारते थे और
उच्चारण।
हालांकि साहित्यिक जगत में कुछ लोग उनकी कविता को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, फिर भी
उन्हें बाद के वर्षों में इसलिए प्रसिद्धि मिली क्योंकि वे जैसे थे वैसे ही थे। उनके भीतर

छिपे कवि ने ही उन्हें प्रसिद्धि दिलाई।
आम लोगों के बीच जटिल राजनीतिक संदेशों का संचार कर सकता था।
जिससे लोग जुड़ाव महसूस कर सकें।
उन्हें न केवल उनकी काव्य प्रतिभा के कारण बल्कि एक कुशल सार्वजनिक वक्ता के रूप में भी पहचान मिली।
न केवल उनकी भाषा शैली के लिए, बल्कि उनके भाषणों में आने वाले प्रसिद्ध विरामों के लिए भी, जो
इसी ने उन्हें वह वक्ता बनाया जो वे थे। कई लोग केवल उन्हें सुनने के आनंद के लिए उनकी रैलियों में जाते थे। वे बिना तैयारी के भी बोलने के लिए जाने जाते थे।
1934 में, जब वे उज्जैन में स्कूल में ही पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक ऐसा सबक सीखा जो
इसका उद्देश्य उनकी वाक्पटुता को प्रभावित करना था और वह कभी भी रटने पर आधारित अध्ययन करना नहीं था।
स्कूल में दिए जाने वाले भाषण को उसने पूरी तरह से याद कर लिया था।
भारतीय रेलवे में, वह अचानक अपनी लाइनें भूल गए और उनकी जुबान लड़खड़ा गई।
उस दिन के बाद से, वह अपने भाषणों पर बहुत मेहनत करने लगा।
सूचनाओं, कहानियों, किस्सों और मानसिक अनुभवों का एक संग्रह बनाना
रूपकों का इस्तेमाल वह तब करता था जब उसे अपनी बात समझाने की जरूरत होती थी।
उसके पास सूचनाओं का भंडार था जिसका वह उपयोग कर सकता था और वह हमेशा यही पसंद करता था।
बिना तैयारी के बोलना। वाजपेयी को जब अपना भाषण पढ़ना पड़ता था, तब वे अपने असली रूप में नहीं होते थे।
भाषण दें या नोट्स का अनुसरण करें।
वह कभी-कभी उदास होकर कहते थे कि राजनीति ने उनके जीवन में दखल दिया था।
एक कवि के रूप में उनकी यात्रा। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक उनकी घुड़सवारी प्रतियोगिता के बारे में थी।
मृत्यु के साथ—जब वह 1988 में न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में भर्ती थे।

उन्होंने कविता को प्रकाशन के लिए हिंदी पत्रिका धर्मयुग को भेजा।
उन्होंने संपादक को लिखा, 'ये पंक्तियाँ कविता की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं।'
'kintu yeh meri zindagi ka dastavez hai (…but these words capture the
कथा मेरे जीवन की)।'
कविता प्रकाशित हुई। इसे वाजपेयी की शैली का एक उदाहरण मानते हुए सराहा गया।
विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार न मानने वाला जज्बा।

Toote hue sapno ki, kaun sune siski,
Antar ki cheer vyatha, palkon par thithki,
Haar nahin manoonga, raar nahin thanoonga,
Kaal ke kapal par, likhta hoon mithata hoon,
Geet naya gaata hoon.

(टूटे सपनों की सिसकियों को कौन सुनेगा, अंदर का दर्द क्या है?)
यह ढक्कनों तक तो पहुँच जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता, मैं हार स्वीकार नहीं करूँगा, मैं
मैं नए सिरे से संघर्ष शुरू करूँगा, मैं अपने लिखे को फिर से लिखूँगा और मिटाऊँगा।
नियति, और मैं एक नया गीत गाऊंगा।)

उनकी एक और प्रसिद्ध कविता बीमारी के खिलाफ उनके संघर्ष के बारे में थी।
कैंसर।
'Kal agar kaal aakar mere dwar par dastak de, toh main usi shaan se
uske saath chal kharha hoonga (Tomorrow if death knocks on my door, I
वाजपेयी ने लिखा, 'बिना किसी आपत्ति के इसके साथ चलेंगे।' '…Kintu yadi maut

mere sath khel karegi…toh us sae main larhoonga. Akhri dam tak doh doh haath karoonga (But if it plays games with me, then I will fight it.
और मैं अपनी आखिरी सांस तक इसके खिलाफ लड़ूंगा।
इन शब्दों से वाजपेयी उस अनुभूति का वर्णन कर रहे थे जो उन्होंने तब महसूस की थी जब...
उन्हें 1988 की सर्दियों में पता चला कि उन्हें कैंसर है। उनका कैंसर उन कैंसरों में से एक था।
वाजपेयी के बारे में गुप्त रखे गए रहस्य। उनकी बीमारी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे।
'मुझे नहीं पता था कि उन्हें कैंसर है,' यशवंत सिन्हा ने हैरानी से मुझसे कहा।
2021 में; सिन्हा उनके अधीन वित्त मंत्री थे। उपचार के बाद
जिस उपचार से वह गुजरा, उसमें बीमारी दोबारा नहीं उभरी।
शक्ति सिन्हा ने खुलासा किया, 'उन्हें अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में कैंसर हो गया था।' 'दोनों,
किडनी और कैंसर आपस में जुड़े हुए थे...यह बात पुष्ट हो चुकी थी। मुझे इसके बारे में पता था।'
Shakti Sinha told me.
वाजपेयी का न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज हुआ था। जब लोग
जब उनकी कविता में परिलक्षित उनके उदास मन के बारे में टिप्पणी की गई, तो उन्होंने पलटवार किया।
'Meri kavita jang ka elan hai, parajaya ki prastavana nahin (My poem is
यह युद्ध का आह्वान नहीं है, हार का प्रस्ताव नहीं है। मैं कविता इसलिए लिखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि क्या है।
वह अक्सर कहते थे, ताकत।
1991 में राजीव गांधी के निधन के बाद ही वाजपेयी ने खुलासा किया कि कैसे
राजीव ने उनकी जान बचाई थी। 'जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने
मुझे किसी तरह पता चला कि मुझे किडनी की समस्या है और इलाज की जरूरत है।

वाजपेयी ने बताया, ‘विदेश में। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और कहा कि वह
मुझे संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने की योजना थी और उम्मीद थी कि मैं
मैं इस अवसर का उपयोग अपने आवश्यक उपचार को प्राप्त करने के लिए करूंगा।
मैं न्यूयॉर्क गया था और यही एक कारण है कि मैं आज जीवित हूं।
राजीव गांधी ने निर्देश दिया कि वाजपेयी को भारत लौटना चाहिए।
न्यूयॉर्क में उनका इलाज पूरा होने के बाद ही। राजीव ने भी ऐसा ही किया।
उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की कि उन्होंने वाजपेयी को भारतीय प्रतिनिधिमंडल में क्यों शामिल किया, और न ही
क्या वाजपेयी ने राजीव की मृत्यु के बाद तक कभी इसका जिक्र किया था?
राजीव गांधी के बाद के प्रधानमंत्रियों में भी शामिल थे
वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए।
हर साल संयुक्त राष्ट्र विधानसभा में भाग लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सत्र में भाग लेने के अलावा, उनका वार्षिक कार्यक्रम
न्यूयॉर्क की यात्रा से उन्हें अपनी वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराने में मदद मिलेगी।
किसी भी प्रधानमंत्री ने वाजपेयी के कैंसर के बारे में जानकारी लीक नहीं की।
यह उनके विरोधियों के मन में उनके प्रति सम्मान का संकेत था। उनकी कैंसर की कहानी
इससे सभी विचारधाराओं के राजनेताओं के साथ उनके व्यापक संबंधों का पता चलता है।
■

मिलनसार और 'जिंदादिल' स्वभाव के वाजपेयी को जीवन की अच्छी चीजों का भरपूर आनंद लेने की चाह थी।
वह बड़े चाव से समोसे, जलेबी और कबाब खाता था।
उन्हें रात में शराब पीना बहुत पसंद था। उन्होंने एक बार ब्रजेश मिश्रा को निर्देश दिया था कि...

पत्रकार राजदीप सरदेसाई को बताइए कि उन्हें सबसे बढ़िया स्टेक कहाँ मिल सकता है।

न्यूयॉर्क! अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान, उन्होंने दुनिया के विभिन्न पहलुओं का अन्वेषण किया।

न्यूयॉर्क शहर में मिलने वाले विभिन्न व्यंजनों में से उन्हें मैक्सिकन व्यंजन विशेष रूप से पसंद थे।

उनके मित्र मुकुंद मोदी, जो एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, के अनुसार, भोजन

वह ईस्ट ब्रुकलिन में प्रैक्टिस करते थे और वाजपेयी को 1970 के दशक से जानते थे।

वाजपेयी को भारत से दूर रहना बहुत अच्छा लगता था। इससे उन्हें यह सुविधा मिलती थी कि वे

भीड़ में घुलमिल जाना, विदेश में बने दोस्तों से मिलना, यात्रा करना

सुपरमार्केट जाना, सफारी सूट पहनना और मनपसंद खाना खाना। न्यूयॉर्क

यह एक ऐसा शहर था जिसका वह विशेष रूप से आनंद लेता था—उसे यहाँ की 'उच्च स्तरीय राजनीति' पसंद थी।

संयुक्त राष्ट्र और 'दुनिया भर के नेताओं का आना-जाना।'

यदि कविता और जीवन की उत्तम चीजों की सराहना ने आकार दिया

वाजपेयी और राजकुमारी कौल दोनों का व्यक्तित्व एक जैसा था। दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी।

उनकी मुलाकात 1941 में ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हुई थी और वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे।

वाजपेयी की जीवनीकार सागरिका ने लिखा है कि वाजपेयी को ‘एक दिन उनसे शादी करने की उम्मीद थी’।

घोष ने शादी कर ली, लेकिन उसके परिवार को यह मंजूर नहीं था—और फिर उनका संपर्क टूट गया।

सोलह साल बाद पुनः संपर्क स्थापित हुआ। वाजपेयी पहली बार सांसद बने थे और

दिल्ली के रामजस कॉलेज में भाषण देने गए हैं। बी. एन. कौल, जो कि एक प्रोफेसर हैं,

कॉलेज के छात्र अपनी युवा पत्नी के साथ वाजपेयी को सुनने आए थे।

राजकुमारी। इस मुलाकात ने वाजपेयी और उनके बीच संबंधों की चिंगारी को फिर से जगा दिया।
राजकुमारी। इसके बाद, राजकुमारी और उसका परिवार राजकुमारी के साथ रहने चले गए।
वाजपेयी सरकार में श्रीमती कौल की एक मजबूत हस्ती के रूप में पहचान बनी।
जब वह प्रधानमंत्री बने तो उनके घरवाले उन्हें 'कौल आंटी' कहते थे।
दुनिया। करण सिंह, जो वाजपेयी के घर पर उनसे कभी नहीं मिले थे, केवल
एक साझा मित्र के घर पर आयोजित पार्टियों में, उन्हें एक
'असाधारण महिला'।
वाजपेयी का राजकुमारी के साथ संबंध उन अनिश्चित संबंधों में से एक था।
ऐसे संबंध जिनसे संघ नेतृत्व बेहद नाखुश था—और
आरएसएस और भाजपा के हलकों में इस पर कटाक्ष किए जाएंगे।
आरएसएस वाजपेयी के 'रोमांस करने, व्हिस्की पीने और मांस खाने' के रवैये को नापसंद करता था।
खाने-पीने के तरीकों के मामले में, वे 'उनकी राजनीतिक प्रसिद्धि के आगे बेबस' थे।
लेकिन, कई राजनेताओं के विपरीत जिनके संबंध थे
अटकलों के बावजूद, वाजपेयी ने अपनी मृत्यु तक अपने रिश्ते को स्वीकार किया।
श्रीमती कौल ने सार्वजनिक रूप से ऐसा किया। और कोई उनसे इस बारे में सवाल नहीं कर सका। वाजपेयी
उन्होंने श्रीमती कौल के बच्चों को गोद ले लिया था। वे विशेष रूप से उनकी बेटी नमिता, जिसे लोग गुन्नू के नाम से जानते थे, और नमिता के बच्चों के प्रति समर्पित थे।
बेटी निहारिका। गुन्नू को उनकी 'पालक पुत्री' के रूप में जाना जाने लगा।
और उनके पति रंजन भट्टाचार्य को उनके 'दत्तक दामाद' के रूप में।
'राजकुमारी और वाजपेयी के बीच संबंधों का मूल आधार,'
राजनीति वैज्ञानिक विनय सीतापति ने अपनी पुस्तक जुगलबंदी में लिखा था,
वह 'बुद्धिमान' थीं। वह एक कश्मीरी पंडित परिवार से थीं और थीं।
दिल्ली के शक्तिशाली 'कश्मीरी माफिया' से जुड़ा हुआ, जिसमें पी.एन. शामिल हैं।
Haksar, R. N. Kao, P. N. Dhar, D. P. Dhar, T. N. Kaul, the 'panj

pyaras’
इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दिल्ली दरबार में कार्यरत। सुशिक्षित और अंग्रेजी में धाराप्रवाह।
श्रीमती कौल ने प्रांतीय राजनेता वाजपेयी के सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया पेश की।
भारत के बारे में उनका दृष्टिकोण। दोस्तों ने याद किया कि 'राजकुमारी वाजपेयी से इस बारे में बहस कर रही थीं।
राजकुमारी कौल राजनीति में अपने प्रभाव का एक प्रमुख कारण बनने वाली थीं।
वाजपेयी का जीवन ही उन्हें 'उदारवादी' बनाने वाला था।
■

वाजपेयी का आरएसएस से सामना काफी जल्दी हो गया था और इसने उनके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनमें राजनेता बनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। स्कूल के दिनों से ही वे आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे थे।
और 1946 में वे विस्तारक (पूर्णकालिक कार्यकर्ता) बन गए। तब तक आरएसएस ने एक लाख स्वयंसेवकों की एक सुप्रशिक्षित सेना के रूप में विकसित हो चुकी थी। वाजपेयी
हिंदू राष्ट्रवाद के विचार से आकर्षित होकर और सादगी से प्रभावित होकर
आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारकों का जीवनयापन। आरएसएस के प्रचारकों की ओर से...
उनकी वाक्पटुता से लोग उत्साहित थे और उन्होंने विशेष रूप से उन पर ध्यान केंद्रित किया।
1940 के दशक के आरंभ में, वाजपेयी निम्नलिखित विचारों से आकर्षित हुए थे:
उन्होंने समाजवाद का समर्थन किया था और 1944 में साम्यवाद में भी हाथ आजमाया था, और उसमें शामिल हो गए थे।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ)। लेकिन, जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली।

1947 में, जब देश खूनी विभाजन और हिंदू-मुस्लिम संघर्ष से बुरी तरह प्रभावित था, तब
हिंसा—तब तक वह एमए कर चुका था और कानून की डिग्री के लिए दाखिला ले चुका था—
तेईस वर्षीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्ण-सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया।
आरएसएस के समय प्रचारक।
आरएसएस ने उनसे अपने नवगठित प्रकाशन के संयुक्त संपादक बनने का अनुरोध किया।
1948 में उन्होंने राष्ट्रधर्म पत्रिका के संपादक के रूप में काम किया और उसके नए संस्करण के संपादक बने।
लखनऊ में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पंचजन्य में उन्होंने कई लेखकों के साथ मिलकर काम किया। यहीं पर उन्होंने कई लेखकों के साथ घनिष्ठ रूप से काम किया।
आरएसएस के दिग्गज आयोजक—आरएसएस के यूपी सचिव—दीन
दयाल उपाध्याय ने उनके उदय में सहयोग दिया था। वाजपेयी दिल्ली चले गए थे।
in 1950. When Syama Prasad Mookerjee launched the Bharatiya Jan
21 अक्टूबर 1951 को आरएसएस की मदद से संघ का गठन होना स्वाभाविक ही था।
राजनीतिक रूप से झुकाव रखने वाले वाजपेयी के उनके साथ जुड़ने के लिए।
महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंधित होने के बाद, आरएसएस अब
उन्होंने भारतीय जनसंघ नामक एक राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास किया।
उसके बाद वाजपेयी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
■

वाजपेयी की पहली मुलाकात लाल कृष्ण आडवाणी से कोटा में हुई थी। यह 1952 की बात है।
आडवाणी आरएसएस के प्रचारक भी थे, जो राजस्थान में आकर बस गए थे।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कुछ वर्षों बाद, 1957 में, दीन दयाल उपाध्याय

अंग्रेजी में निपुण आडवाणी से वाजपेयी की सहायता करने के लिए कहा गया।
संसदीय कार्य। वाजपेयी अभी-अभी सांसद बने थे। इस प्रकार एक नई शुरुआत हुई।
यह साझेदारी आधी सदी तक चली। आडवाणी ने बाद में इस बारे में बात की।
‘दिल्ली के बंगाली बाजार में जाकर खाई जाने वाली चाट’ के बारे में, या
'चुनावी हार के गम को भुलाने के लिए साथ में फिल्म देखना।'
जब कांग्रेस 1977 के चुनाव हार गई, और जनता पार्टी
सरकार का गठन किया—भारतीय जनसंघ ने अपने दलों का विलय कर लिया था।
जनता पार्टी में अपनी पहचान बनाने के बाद वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री बने।
पार्टी के समाजवादियों ने मांग की कि पूर्व जनसंघ
अब जब सदस्यों को आरएसएस से अपने संबंध तोड़ लेने चाहिए, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए।
एक नई पार्टी के सदस्य। आश्चर्यजनक रूप से, वाजपेयी ने इस विचार का समर्थन किया।
उन्हें लगता था कि उन्हें केवल जनता पार्टी के प्रति ही वफादार रहना चाहिए, जिसके प्रति वे अब वफादार हैं।
संबंधित होना—और उस प्रथा को समाप्त करना जिसे उनकी 'दोहरी सदस्यता' कहा जाने लगा था।
(आरएसएस और जनता पार्टी के)। उन्होंने आरएसएस से अपने दरवाजे खोलने का भी आग्रह किया।
मुसलमानों के लिए द्वार। इंडियन एक्सप्रेस में एक हस्ताक्षरित लेख में उन्होंने लिखा।
आरएसएस को ‘राजनीतिक भूमिका नहीं निभानी चाहिए’ और केवल एक ‘हिंदू’ के रूप में काम करना चाहिए।
धार्मिक सह सामाजिक सांस्कृतिक संगठन'—और यह स्पष्ट करें कि
‘हिंदू राष्ट्र’ से तात्पर्य उस भारतीय राष्ट्र से है जिसमें गैर-हिंदू भी शामिल हैं।
सदस्यों के। उनके विचारों ने उन्हें आरएसएस नेतृत्व के बीच लोकप्रिय नहीं बनाया।
यह वह दौर था जब वाजपेयी अपनी छवि को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इंदिरा गांधी
गांधी एक 'हिंदू' छवि प्रस्तुत कर रहे थे।
‘दोहरी सदस्यता’ के मुद्दे ने जनता पार्टी को तबाह कर दिया।

सरकार, और पार्टी 1980 में इंदिरा गांधी, वाजपेयी और
आडवाणी ने एक नई पार्टी - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - लॉन्च करने का फैसला किया।
अप्रैल 1980 में। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अब तक के इस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित न करने का विकल्प चुना।
भंग हो चुकी भारतीय जनसंघ के बाद, वाजपेयी ने नवगठित भाजपा के लिए 'गांधीवादी समाजवाद' को अपना मूलमंत्र चुना।
नई पार्टी की पहचान न तो दक्षिणपंथी और न ही वामपंथी विचारधारा से करने का प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन गांधी जी के साथ। वाजपेयी ने 'एकीकृत शासन' के सिद्धांत को नहीं अपनाया।
आरएसएस के विचारक दीन दयाल उपाध्याय द्वारा विकसित 'मानववाद', जो
1965 में जनसंघ की आधिकारिक नीति यही थी—इसने पूंजीवाद को भी अस्वीकार कर दिया था।
और समाजवाद, तथा 'मूल्यों' पर आधारित एक स्वदेशी मॉडल की मांग की।
सनातन धर्म का।
लेकिन वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा को सफलता नहीं मिली।
1981 में हुए चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा। वह अपने पहले चुनाव में कांग्रेस से हार गई।
जम्मू और कश्मीर में 1983 में हुए चुनावों में जम्मू एक मजबूत गढ़ था।
जनवरी में दिल्ली में हुए नगर निगम चुनावों में इसे करारी हार का सामना करना पड़ा।
year. ‘Atal Bihari atak gaya, kamal ka phool latak gaya (Atal Bihari has
(अटक गया और परिणामस्वरूप कमल मुरझा गया)’, विजयी कांग्रेस
नेताओं ने जोरदार नारे लगाए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में...
वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा को चुनाव में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन करते हुए
मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्थानीय स्तर पर विचार किया
यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण था कि इसके बारे में लिखा जा सके।
1984 के आम चुनावों में, भाजपा मात्र 2 लोकसभा सीटों तक सिमट गई थी।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद विधानसभा सीटों की संख्या में गिरावट आई।

जनसंघ ने लोकसभा में अपनी पिछली संस्था द्वारा जीती गई 4 सीटों की तुलना में कहीं अधिक सीटें जीती हैं।
1957 के आम चुनावों में, वाजपेयी उन चार उम्मीदवारों में से एक थे।
1980 के दशक का उत्तरार्ध विशेष रूप से आर्थिक रूप से निम्न दौर था।
वाजपेयी। आरएसएस के समर्थन से, आडवाणी ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनकी जगह ली।
1986. प्रसिद्धि पाने के बाद पहली बार वाजपेयी
किनारे कर दिया गया।
अब आडवाणी केंद्र में आ गए। 1980 के दशक के अंत तक, उन्होंने यही देखा था।
खुद को वाजपेयी का नंबर दो बताते हुए। 'अडवानी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।'
जब तक अटलजी हैं,' गोविंदचार्य ने कहा, जो अक्सर आडवाणी के विचारों को प्रतिबिंबित करते थे।
मुझे 1989 में थिंकिंग ने बताया था, 'उनका रिश्ता ऐसा ही है।'
आडवाणी के नेतृत्व के बाद इस रिश्ते में एक सूक्ष्म बदलाव आना तय था।
सितंबर 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा। आडवाणी की
लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। ग्रामीण रथ के पास आकर उसे छूने लगे।
श्रद्धापूर्वक। महिलाएं रथ की आरती करती थीं।
मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि धार्मिकता लोगों के जीवन में इतनी गहराई से समाई हुई है।
आडवाणी ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'भारतीय लोगों ने मुझे यह एहसास दिलाया कि अगर मुझे
धार्मिक मुहावरे के माध्यम से राष्ट्रवाद का संदेश संप्रेषित करना, मैं
इससे इसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रसारित किया जा सकेगा।'
तब तक वाजपेयी ही थे जिन्होंने अपने भाषणों से जनता को जागरूक किया था।
भाषण कला। अब, पहली बार, आडवाणी को एक नेता के रूप में देखा जाने लगा।
जिसे जनता ने सराहा—और सिर्फ एक कुशल गुप्त टीम ने नहीं।
आयोजक। यात्रा के दौरान लोगों से जुड़ने में सक्षम होने के कारण, उन्होंने शुरुआत की...
उन्हें लगता था कि वे प्रधानमंत्री बन सकते हैं—यह एक ऐसा सपना था जो अधूरा ही

रह गया।
अपूर्ण। वाजपेयी ही आगे चलकर प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने वाले बने।
मंत्री।
आधी सदी से भी अधिक समय तक फैले उनके बराबरी के रिश्ते—यहाँ तक कि
प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरने से वाजपेयी और आडवाणी सबसे अधिक
जवाहरलाल नेहरू के बाद भारतीय राजनीति की विशिष्ट राजनीतिक जोड़ी—
सरदार पटेल। वाजपेयी के न होने पर उनके रिश्ते में अचानक दरार आ गई।
आडवाणी को अपने निर्णय के बारे में अंतिम क्षण तक विश्वास में रखना।
जैसा कि हम इस अध्याय में आगे देखेंगे, परमाणु परीक्षण को हरी झंडी देना।
वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी प्रतिद्वंद्विता और भी तीव्र हो गई।
उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को टूटने की कगार पर नहीं आने दिया। साथ मिलकर उन्होंने
उनकी पार्टी को सत्ता में लाने का लक्ष्य था, पहले 1996 में, फिर 1998 में और फिर से
1999.
■

वाजपेयी के राजनीतिक व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू उनका वह तरीका था जिससे वे अपने राजनीतिक व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते थे।
उन्होंने जानबूझकर आरएसएस में अपने लिए एक मध्यमपंथी स्थान बनाया।
दक्षिणपंथी भारतीय जनसंघ द्वारा समर्थित और फिर उसके बाद के दौर में
भाजपा का अवतार। यह एक ऐसी छवि थी जिसे भाजपा का कोई अन्य नेता हासिल नहीं कर सका।
और इसी वजह से वह सबसे अलग दिखे।
1950 के दशक की शुरुआत में ही, वाजपेयी ने, हालांकि बहुत ही कम समय में, लाभ उठाने में कामयाबी हासिल कर ली थी।
नेहरू की उनमें एक युवा सांसद के रूप में बढ़ती रुचि को सूक्ष्म रूप से दर्शाया गया था—ताकि वे एक

उनकी छवि उनकी पार्टी की छवि से अलग थी। हालाँकि वे आलोचक थे।
1950 के दशक के उत्तरार्ध में नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति के चलते, वे और अधिक मुखर हो गए।
1977-79 के दौरान जब वे विदेश मंत्री थे, तब उनका दृष्टिकोण नेहरूवादी था।
—कई कांग्रेसी सदस्यों से भी कहीं अधिक। उन्होंने तो खुद को एक
संसद में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने खुद को 'गुटनिरपेक्षता का समर्थक' बताया था।
इस प्रक्रिया में, उन्हें अधिक 'उदारवादी' के रूप में देखा जाने लगा—कभी-कभी
यहां तक कि वह अपनी पार्टी की तुलना में वामपंथी भी था, जो दक्षिणपंथी और बाजार समर्थक थी।
और अमेरिका समर्थक। जैसा कि हमने देखा है, राजकुमारी कौल एक महत्वपूर्ण
वाजपेयी के जीवन में उदारवादी प्रभाव ने उन्हें समावेशी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर किया।
विचार।
1980 के दशक की शुरुआत में, वाजपेयी ने भाजपा के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता को महसूस किया था।
उनका मानना था कि इसका आधार बनिया-ब्राह्मण जाति से परे होना चाहिए।
नींव। अप्रैल 1980 में भाजपा के गठन के महीनों बाद, चौधरी
राधाकृष्णन, पंजाब में भाजपा के पहले अध्यक्ष और एक सम्मानित व्यक्ति थे।
गांधीवादी विचारधारा के अनुयायी वाजपेयी को पंजाब में सभाओं को संबोधित करने के लिए ले जा रहे थे।
रास्ते में, उन्होंने एक दीवार पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ देखा, जिसमें लोगों से आग्रह किया गया था कि वे
join the BJP, ‘Bhajpa ke sadasya baniye (Become a member of the
भाजपा)’। इसे धीरे-धीरे जोर से पढ़ते हुए, वाजपेयी ने ‘बनिये’ शब्द पर व्यंग्य किया।
and quipped, ‘Yahi to dikkat hai, baniye hi baniye hain. Aur koi nahi
(यही असली समस्या है, इससे केवल व्यापारिक समुदाय में ही समस्या बढ़ती है)

बनिया, और कोई नहीं)।
उनके रहस्यमय शब्दों ने पार्टी के चरित्र का वर्णन किया था—एक पोशाक
उच्च जातियों के। वाजपेयी जानते थे कि उन्हें अपना दायरा और व्यापक करना होगा और
अन्य समुदायों तक पहुंचें। कुछ साल बाद, गोविंदाचार्य ने फोन किया।
ओबीसी को पार्टी में शामिल करने के लिए 'सामाजिक इंजीनियरिंग' का इस्तेमाल किया गया। बाद में,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग को संगठित करने का जिम्मा लेना था।
उच्च स्तर पर, संख्यात्मक रूप से बड़े वर्ग तक पहुँचते हुए
पार्टी को मुख्यधारा में लाने के लिए एमबीसी समुदाय के साथ-साथ दलित समुदाय को भी शामिल किया जा रहा है।
लेकिन अपने मिलनसार और सहज स्वभाव के बावजूद, वाजपेयी
उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प दिखाया, जो तब सामने आया जब उन्हें चुनौती दी गई।
यह सुनिश्चित किया गया कि के. एन. गोविंदाचार्य कभी मुख्यधारा में वापस न आ सकें।
भाजपा ने उन्हें इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने वाजपेयी को पार्टी का 'मुखौटा' कहा था।
(गोविन्दाचार्य ने इस बात से इनकार किया और कहा कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था)
(संदर्भ।) वाजपेयी ने सुनिश्चित किया कि गोविंदाचार्य का राजनीतिक करियर
घटना के बाद जब सब कुछ शांत हो गया था, तब भी बात खत्म हो गई थी।
दो अन्य कारकों ने वाजपेयी को एक उदारवादी के रूप में प्रस्तुत करने में मदद की।
अपने पार्टी सहयोगियों के लिए—संसद सदस्य के रूप में उनका लंबा कार्यकाल और
भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बेहतर बनाने की इच्छा। हालाँकि उन्हें एक
आरएसएस में प्रचारक के रूप में, यह संसदीय राजनीति थी जिसमें टकराव शामिल था।
विचार, संवाद पर जोर—और इसमें निहित आदान-प्रदान—
जिससे उनमें राजनीतिक मतभेदों वाले लोगों के प्रति अधिक सहिष्णुता विकसित हुई।
वाजपेयी, जिन्होंने 1951 में राजनीति में प्रवेश किया, मूल रूप से उसी सांचे में ढले

थे।
एक सांसद के रूप में—वे पचास वर्षों से अधिक समय तक सांसद रहे, निर्वाचित हुए। लोकसभा में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से दस बार और राज्यसभा के लिए भी उपस्थित रहे।
वे दो बार लोकसभा चुनाव हार चुके थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव भी पांच बार हारे थे। उन्होंने पहली बार 1957 में बलरामपुर से लोकसभा चुनाव जीता था, 1962 में वहां से हार गए थे, लेकिन 1967 में दृढ़ संकल्प के साथ सीट वापस हासिल कर ली थी। बाद में, उन्होंने
उन्हें ग्वालियर, नई दिल्ली, गांधीनगर और लखनऊ का प्रतिनिधित्व करना था।
जब वे 1957-77 तक संसद में अपनी पार्टी के प्रमुख थे, तब अन्य
BJP MPs like Balraj Madhok and Sundar Singh Bhandari would
उनकी शिकायत है कि वाजपेयी के सारे ध्यान अपनी ओर खींचने के कारण उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिल पा रही थी।
संसद में बोलने का मौका दिया गया।
वाजपेयी को संसद में रहना बहुत पसंद था, और वहीं उन्होंने अपना पहला प्रहार किया।
कई ऐसे घनिष्ठ संबंध थे जो अंत तक कायम रहे; वह
विशेष रूप से पी.वी. नरसिम्हा राव के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था, जैसा कि
हम देखेंगे कि क्या मई में परमाणु परीक्षण करने के उनके निर्णय पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है।
1998.
वाजपेयी की शुरुआत से ही भारत के संबंधों को सुधारने की इच्छा थी।
पाकिस्तान, जिसके बिना जम्मू और कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो सकता था
सुलझ जाना, एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि को भी मजबूत करता है जो इन बाधाओं से ऊपर उठ सकता है।
उनकी पार्टी।
जैसा कि हम देख चुके हैं, उन्होंने जन के नेतृत्व में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की

थी।
संघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो संघ के सदस्य थे...
नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन नेहरू से मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी ने नेहरू मंत्रिमंडल में काम किया था।
विरोध में भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मुखर्जी के साथ कश्मीर गए।
जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे के विरुद्ध। 'दोह विधान,
doh pradhan, doh nishan nahin chalega (Two constitutions, two prime
'मंत्री, दो झंडे, यह ठीक नहीं है'—यह मुखर्जी का युद्धघोष था।
राज्य का अलग संविधान, प्रधानमंत्री और ध्वज।
मुखर्जी को शेख अब्दुल्ला ने गिरफ्तार किया था। जेल में उनकी मृत्यु हो गई।
23 जून 1953 को कश्मीर में हुई घटना ने वाजपेयी को बहुत प्रभावित किया।
जब वे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में विदेश मंत्री बने, तब वाजपेयी ने
उन्होंने फरवरी 1978 में पाकिस्तान की यात्रा की, जिसे उन्होंने 'ऐतिहासिक' यात्रा बताया—और यह
उदारीकृत वीजा सुविधाएं। वे चीन का दौरा करने वाले पहले मंत्री थे।
और पाकिस्तान, दोनों देशों द्वारा 1962 में भारत के साथ युद्ध लड़ने के बाद।
और 1965 में। प्रधानमंत्री के रूप में, उन्हें संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास करने थे।
पाकिस्तान—उन्होंने फरवरी 1999 में लाहौर की बस यात्रा की, और
पाकिस्तान द्वारा कारगिल में भारत पर हमले के साथ जवाबी कार्रवाई करने के बावजूद, उन्होंने
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ को शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया।
जुलाई 2001 में आगरा में वार्ता का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच लंबित मुद्दों को हल करना था।
दो देशों में। हालाँकि उनकी पहल सफल नहीं हुई, लेकिन इसने उन्हें यहाँ आने के लिए प्रेरित किया।
एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो खुले विचारों वाले थे और सुधार करना चाहते थे।
भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध।

■

हालांकि वाजपेयी ने बड़ी चतुराई से खुद को एक उदारवादी नेता के रूप में स्थापित किया।
कट्टरपंथी हिंदू पार्टी में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में, वह अपने बदलते रुख के लिए जाने जाते थे।
उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में जो रुख अपनाए। और क्या था?
आश्चर्यजनक रूप से, वह बच निकलने में कामयाब रहा। सागरिका के अनुसार
घोष ने कहा, 'वाजपेयी एक चतुर करियरवादी थे।' उन्होंने 'रणनीतिक' रणनीति को अच्छी तरह समझ लिया था।
उसके लिए 'जीवित रहना' ही सब कुछ था; वह हवा का रुख भांप सकता था।
और उन्होंने तदनुसार अपना रुख बदल लिया। लेकिन वे कभी भी इससे बहुत दूर नहीं भटके।
मुख्यधारा की पार्टी का रुख।
अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनका लगातार बदलता रुख,
उदाहरण के लिए, यह समझा सकता है कि परमाणु हथियारों पर उनके विचार और कार्य क्यों महत्वपूर्ण थे।
वे इतने परिवर्तनशील थे।
1989 में भाजपा के पालमपुर सम्मेलन के बाद से, स्वीकार करना
वाजपेयी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को अपने एजेंडे में शामिल किया है।
उन्होंने दोहरी बातें कहीं। अप्रैल 1991 में उन्होंने कहा कि एक मंदिर आवश्यक है 'ताकि...'
राष्ट्रीय सम्मान बहाल करना। लेकिन, दिसंबर 1992 में, उन्होंने कहा कि
बाबरी मस्जिद का विध्वंस मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था। मई में
1996 में, उन्होंने विध्वंस को लगभग उचित ठहराते हुए कहा कि यदि धर्म से संबंधित अगर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो इससे एक और अयोध्या जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन
दिसंबर 1997 में, उन्होंने अपने रुख से पीछे हटते हुए घोषणा की कि अयोध्या 'नहीं होगी'

भाजपा के लिए प्रमुख मुद्दा। फरवरी 1998 में, वाजपेयी ने इसमें शामिल किया:
भाजपा के घोषणापत्र में 'अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण' शामिल है। लेकिन,
जून 1998 में, उन्होंने आश्वासन दिया कि न्यायपालिका 'स्वतंत्र होगी'
अयोध्या मामले में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए। 6 दिसंबर 2000 को उन्होंने
अयोध्या एजेंडा अभी अधूरा है, यह कहकर कई लोगों को चौंका दिया गया।
राम जन्मभूमि आंदोलन को 'राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति' कहना
'भावना' - अभी पूरी होनी बाकी है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मंदिर बन सकता है।
विवादित स्थल पर निर्माण किया जाए और मस्जिद अयोध्या में किसी अन्य स्थान पर बनाई जाए।
लेकिन, चार दिन बाद, 10 दिसंबर 2000 को, वह एक बार फिर पीछे हट गया।
और एनडीए से अयोध्या में यथास्थिति बनाए रखने का प्रस्ताव पारित करवाया।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने तक इसे बरकरार रखा जाएगा।
1 अगस्त 2003 को, उन्होंने एक बार फिर उल्टी दिशा में कदम बढ़ाया; उन्होंने वादा किया कि
मंदिर निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें, विरोधियों से आग्रह करें कि वे 'आएं'
उन्हें होश में लाने के लिए।
भारत में शायद ही कोई अन्य प्रसिद्ध नेता ऐसा होता जो ऐसा कर पाता।
वाजपेयी की तरह बार-बार कुछ कहना और फिर उससे मुकर जाना— इसके बावजूद,
उन्होंने जनसमर्थन नहीं खोया। उन्होंने बड़ी कुशलता से एक ऐसी स्थिति बनाई थी
यह धारणा बनी कि दबाव से बचने के लिए उसे दोहरी भाषा का सहारा लेना पड़ा।
'आरएसएस परिवार' के भीतर के कट्टरपंथियों से। और दिल से, वह वही था।
वास्तव में एक उदारवादी। उनके बारे में यही आम धारणा बनी रही। इसने उन्हें
उनकी लोकप्रियता भाजपा के समर्थन आधार से कहीं अधिक व्यापक है।
इनमें से कई उलटफेर राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित थे—
घिर जाने से बचें। वाजपेयी के विचार एक जटिल मानसिकता से प्रभावित थे।
विभिन्न प्रभावों का मिश्रण। उनकी राजनीति हिंदू विचारधारा से प्रभावित थी और
दर्शनशास्त्र, सांस्कृतिक झुकाव, भारत की विविधता के प्रति सम्मान और

लोकतंत्र, विभिन्न दलों के बीच बनी दोस्ती का अनुभव—और
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका के बारे में स्पष्टता। इसके अलावा एक और बात भी थी।
कवि होने से उत्पन्न मानवतावाद।
सोम पाल, जो वी.पी. सिंह के शिष्य थे और भाजपा में शामिल हो गए थे, ने एक घटना को याद किया।
उस अवसर पर जब वह बागपत से अजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वे 16 सितंबर 1999 को एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। एल.के.
आडवाणी उनके लिए प्रचार करने आए थे। सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए,
सोम पाल ने गरजते हुए कहा, "जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।"
‘Yeh apni party ka prashasan bhi gori chamrhi ke bina nahin chala sakte
(ये लोग किसी श्वेत व्यक्ति के बिना अपनी पार्टी भी नहीं चला सकते)
(हेल्म)। बैठक के बाद, आडवाणी ने उनके 'जुमले' की प्रशंसा की।
(वाक्य); यह इतना समझदारी भरा था कि इसे उनके अभियान में अन्यत्र भी इस्तेमाल किया जा सके।
नौ दिन बाद, 25 सितंबर को, वाजपेयी ने एक सभा को संबोधित किया।
उसी निर्वाचन क्षेत्र में बरौत और सोम पाल ने जुमला दोहराया।
वाजपेयी ने सोम पाल के भाषण की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही उन्हें फटकार भी लगाई, 'कभी नहीं'
अगर आपने दोबारा किसी के बारे में इस तरह से बात की तो... आपका करियर अभी लंबा चल रहा है।
आपके सामने राजनीति है।
वाजपेयी ने पार्टी की सहयोगी सुषमा स्वराज से भी इसी तरह की बात कही थी।
जब उसने अपने बाल मुंडवाने, भुने हुए चने खाकर जीने की धमकी दी थी, और
सोनिया गांधी को पद से हटाने के कदम के विरोध में लोग ज़मीन पर सो गए।
मई 2004 में प्रधानमंत्री ने कहा, 'वह जो कह रही हैं वह सही नहीं है।'
उसने सोम पाल से, जो उससे मिलने गया था, असंतुष्ट होकर कहा, 'हम कौन हैं?'

किसी अन्य पार्टी का नेता कौन होना चाहिए, यह तय करने के लिए?
वाजपेयी की सिखों के खिलाफ हिंसा पर सहज प्रतिक्रिया
31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली की स्थिति ने एक संकेत दिया कि...
एक ऐसे नेता जो मानते थे कि भारत सभी भारतीयों का है। अपने पद पर खड़े होकर लुंगी पहने हुए, बरामदे से बाहर निकलकर, वह अपने घर के बाहर सिख टैक्सी चालकों को बचाने के लिए दौड़ा, क्योंकि उसने उनके घर के बाहर से धुआँ उठता देखा था।
टैक्सी स्टैंड।
‘Maaro mujhe maaro (Kill me, kill me),’ he shouted. His colleague
जसवंत सिंह को उसे छह बजे जबरदस्ती घसीटकर घर के अंदर लाना पड़ा।
Raisina Road. He kept saying agitatedly, ‘Yeh toh nahi chalega, yeh toh
यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता (यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता)।
तृतीय
'आपको क्या लगता है, आप जिस खेल में शामिल हो रहे हैं वह एक सभ्य खेल है?'
डेनियल पैट्रिक मोयनिहान ने अपने सामने बैठे युवकों से पूछा।
उस समय भारत में अमेरिकी राजदूत विदेश सेवा से बात कर रहे थे।
न्यूजीलैंड में विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रशिक्षु।
दिल्ली। यह भारत द्वारा अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण करने से एक साल पहले की बात है।
1974.
उन्होंने उन्हें बेरहमी से चेतावनी देते हुए कहा, 'आप एक खूनी खेल में फंसने जा रहे हैं।'
उस दोपहर मोयनिहान को सुनने वाले केवल वे पुरुष ही नहीं थे,
आने वाले वर्षों में ही उन्हें पता चलेगा कि 'खूनी खेल' वास्तव में क्या था।
इसके बाद इंदिरा गांधी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी का दौर आया।

जिन्हें यह एहसास होना था कि कठोर प्रतिबंधों का सामना करने का क्या मतलब होता है।
वैश्विक समुदाय ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे।
क्रमशः। यहां तक कि अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी, जिन्होंने परीक्षण नहीं कराया, लेकिन जो
जिसने भारत के परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा, उसे इस बात का कुछ अंदाजा हो गया था कि क्या होने वाला है।
यह खूनी खेल इसी बारे में था।
■

भारत के प्रधानमंत्री ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शुरुआत करने का अधिकार प्राप्त है।
परमाणु युद्ध। या किसी अन्य देश द्वारा किए गए परमाणु हमले का जवाब देना।
प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, उनका 'परमाणु ब्रीफकेस' उनके साथ जाता है; उनके पास एकमात्र अधिकार होता है।
इसकी सुरक्षा में। यह एक विशेष रूप से सुसज्जित ब्रीफकेस है, ताकि प्रधानमंत्री इसे अपने कब्जे में रख सकें।
परमाणु मिसाइल दागने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से
अनुमति मिलने पर लॉन्च स्वतः शुरू नहीं होता। पूरी प्रक्रिया
इस प्रक्रिया को कई तरह की जाँच और संतुलन के अधीन किया जाता है—जैसा कि इस मामले में है
अमेरिका जैसे परमाणु हथियार रखने वाले पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में—इससे पहले हथियार अपने साइलो से निकलते हैं। भारत में, कई प्रोटोकॉल लागू हैं।
परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण को नियंत्रित करने वाले कानून गोपनीय हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
सार्वजनिक जांच।
‘इन कागजों को कोई नहीं देखता, कर्मचारियों को भी इसके बारे में पता नहीं है,’ इंदर

ने कहा।
भारत के बारहवें प्रधानमंत्री कुमार गुजराल ने मुझे बताया, 'मैंने उन्हें रखा था।'
मेरे घर में ताला लगा हुआ था और चाबी कभी मुझसे दूर नहीं गई।
मैंने एक सुरक्षित कमरा बनवाया था।
एक अलिखित परंपरा है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री
आने वाले व्यक्ति को देश की परमाणु तैयारियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता है —और
'परमाणु ब्रीफकेस' सौंप देता है।
यह सर्वविदित है कि नरसिम्हा राव ने परंपरा का पालन किया और
मैंने 1996 में वाजपेयी को इस बारे में जानकारी दी और उनसे तुरंत परीक्षण करने का आग्रह किया। लेकिन
परंपरा का हमेशा पालन नहीं किया गया। वी. पी. सिंह ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी गई थी।
राजीव गांधी द्वारा। चंद्र शेखर ने शिकायत की कि उन्हें वी. द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी।
पी. सिंह. नरसिम्हा राव ने नरेश चंद्र और ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को भेजा।
एच. डी. देवेगौड़ा को जानकारी देने के लिए। देवेगौड़ा ने कहा कि उन्होंने गुजराल को जानकारी नहीं दी थी।
वैसे भी, वह उनके अधीन विदेश मंत्री रह चुके थे, इसलिए उन्हें 'सब कुछ पता था'।
गुजराल ने 1998 में वाजपेयी को संक्षिप्त जानकारी दी थी, लेकिन वैसे भी उनकी परवरिश इस तरह हुई थी कि
नरसिम्हा राव द्वारा 1996 में स्थापित। यह ज्ञात नहीं है कि वाजपेयी ने इसे स्थापित किया था या नहीं।
मनमोहन सिंह को सरकार की परमाणु तैयारियों के बारे में जानकारी दी। या
अगर मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी को आधुनिक युग के अनुसार ढाल देते तो क्या होता?
हमने देखा है कि जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई किस प्रकार थे।
वाजपेयी दार्शनिक रूप से इस विचार के विरोधी थे। उन्होंने कई मौकों पर अपने रुख में बदलाव किया।
उनके राजनीतिक करियर के विभिन्न चरण। लेकिन, उनके विरोध के बावजूद, न तो

नेहरू
न तो देसाई और न ही किसी अन्य प्रधानमंत्री ने भारत को बंद किया।
रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम। यहां तक कि देसाई, जो सबसे कम उत्साही थे
शस्त्रीकरण के संबंध में, अनुसंधान एवं विकास तथा छोटे स्तर के प्रयोगों को जारी रखा गया।
जा रहे हैं। जैसा कि गुजराल ने बताया, 'राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, कोई भी
प्रधानमंत्री ने जिस तरह से व्यवहार किया वह गैर-जिम्मेदाराना था।
■

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बम के खिलाफ थे।
वह खुद को शांति, गुटनिरपेक्षता और परमाणु शक्ति का दूत मानता था।
विश्व में निरस्त्रीकरण। लेकिन अपने सबसे आदर्शवादी रूप में भी, नेहरू इसके पक्षधर नहीं थे।
भारत द्वारा परमाणु अभ्यास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के मैं पूरी तरह खिलाफ हूं।
विकल्प—यदि आवश्यकता हो। लेकिन वह सावधानी से आगे बढ़ना चाहता था। 'यह है
'आम तौर पर ज्ञात नहीं,' इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल ने कहा, जो
नेहरू के जीवनीकार (और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पुत्र),
नेहरू परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ थे।
उनकी नीति बम का इस्तेमाल न करने की थी, बल्कि उसे अपने पास रखने की थी, 'क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते'।
इसका पूर्णतः त्याग कर दो।' होमी जहांगीर भाभा, जो बाद में प्रसिद्ध हुए,
भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति ने इस पर प्रतिबंध लगाना चाहा था।
नेहरू के सार्वजनिक भाषणों को गंभीरता से लेते हुए, उन्होंने बम गिराया। भाभा थे
परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान (एईईटी) के संस्थापक निदेशक
ट्रॉम्बे—बाद में इसका नाम उनके नाम पर भाभा परमाणु विमान रखा गया।

वह नेहरू से संशोधन करने की भी मांग कर रहे थे।
संविधान में बम को गैरकानूनी घोषित करने वाला एक खंड जोड़ें। 'नहीं, नहीं,'
नेहरू ने उनसे कहा, 'इतनी दूर मत जाओ। यह एक राजनीतिक निर्णय है कि ऐसा नहीं करना है।'
'परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा लिया गया,' नेहरू ने संबंधित फाइल पर लिखा।
उस समय ऐसी खबरें आई थीं, जिनकी पुष्टि नहीं हुई थी, कि
नेहरू मिस्र के राष्ट्रपति गमाल नासिर के साथ सहयोग करने वाले थे।
और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिफ टिटो, दो अन्य महत्वपूर्ण सदस्य
गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बम बनाने की विशेषज्ञता हासिल करने के लिए ऐसा किया।
कि 'वे एक शक्तिशाली तीसरी शक्ति का निर्माण कर सकते थे'। यूगोस्लाविया ऐसा करने में सक्षम था।
भारी जल बनाने के लिए और यह विचार था कि मिस्र प्लूटोनियम बनाएगा।
सोवियत संघ और नॉर्वे की मदद से।
इसलिए, नेहरू ने इस बारे में भाषण दिए कि भारत को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए।
परमाणु हथियारों के मामले में, वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत किसी भी खतरे में न हो।
नुकसान या उसकी सुरक्षा से समझौता। उन्होंने योजनाओं को मंजूरी दी।
भाभा को परमाणु हथियार बनाने में सक्षम बुनियादी ढांचा स्थापित करने का काम सौंपा गया है।
■

नेहरू के उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री भी परमाणु ऊर्जा के समर्थक थे।
शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। उनके दृष्टिकोण में बदलाव आना शुरू हुआ।
भारत का 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध।
उन्हें यह महसूस होने लगा था कि भारत को परमाणु शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
जरूरत पड़ने पर परमाणु निवारक विकल्प उपलब्ध हो सकता है। परमाणु प्रतिरोधक

क्षमता के साथ, भारत अपनी सुरक्षा को बेहतर बना सकता है।
सीमाओं के अनुरूप, 1965 में एक प्लूटोनियम पुनर्संसाधन संयंत्र शुरू किया गया था।
ट्रॉम्बे में। 5 अप्रैल 1965 को, उन्होंने एक परमाणु संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी।
डिजाइन समूह, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोटों का अध्ययन
(SNEPP) यह प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे का अधिग्रहण और विकास कर सकता है।
परमाणु उपकरण में विस्फोट करने के लिए आवश्यक। इस समूह का नेतृत्व परमाणु विशेषज्ञ कर रहे थे।
भौतिक विज्ञानी राजा रामन्ना। एसएनईपीपी इस यात्रा का पहला कदम था।
बम बनाओ।
अपनी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले, शास्त्री ने होमी भाभा को योजनाओं में तेजी लाने के लिए कहा था।
एक 'शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट' (पीएनई) के लिए, जो गैर-
सैन्य उद्देश्यों के लिए। लेकिन शास्त्री जी का निधन इसके कुछ ही समय बाद 11 जनवरी 1966 को हो गया।
उनके बाद सत्ता संभालने वाली इंदिरा गांधी को ही पीएनई की आठ सदस्यीय पार्टी शुरू करने का जिम्मा सौंपा गया था।
कई वर्षों बाद।
■

सितंबर 1972 के एक गर्म और उमस भरे दिन, इंदिरा गांधी ने पहली बार राष्ट्रपति पद ग्रहण किया।
भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम था। वह पहली ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया।
आईआईटी बॉम्बे के वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में।
प्रतिष्ठित पवई परिसर। उन्होंने राजा रामन्ना को मिलने के लिए संदेश भेजा था।

वह वहां मौजूद थीं। वह बीएआरसी के निदेशक थे। होमी सेथना, अध्यक्ष थे।
परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य भी उपस्थित थे। सेथना इसके अध्यक्ष भी थे।
आईआईटी, बॉम्बे के।
दीक्षांत समारोह के बाद, सेथना ने प्रधानमंत्री और राजा को साथ ले गए।
रमन्ना को उनके कार्यालय में बुलाया गया। उनके कमरे का उपयोग करने का विचार
प्रधानमंत्री का ही था।
बैठक के लिए—वह परमाणु वैज्ञानिकों से ऐसी जगह पर मिलना चाहती थी जहाँ
ध्यान आकर्षित नहीं होता। अगर उसने उन्हें प्रधान केंद्र में बुलाया होता तो
मंत्री कार्यालय में, इससे सवाल उठ सकते थे। उस दिन, उसने दिया
उन दोनों को परमाणु उपकरण बनाने और उसे प्राप्त करने की अनुमति मिल गई।
इसका परीक्षण करने के लिए तैयार। रामन्ना को बम परियोजना की देखरेख करने के
लिए कहा गया था—
उनके मार्गदर्शन में उपकरण का डिजाइन पूरा किया जाएगा।
लेकिन उन्हें बताया गया कि वे उससे सूचना मिलने का इंतजार करें कि इसे कब
बनाना है।
परिचालन में। वह जानती थी कि इसमें लगभग अठारह महीने लगेंगे।
परीक्षा के लिए सब कुछ तैयार कर लो। रमन्ना ने मुझे खुद यही बताया था।
(बाद में) 1978 में,' के. सुब्रमण्यम ने खुलासा किया।
अप्रैल 1974 में, इंदिरा गांधी ने अपनी मुख्य टीम की बैठक बुलाई।
नौकरशाह और वैज्ञानिक जो परमाणु परियोजना में उनकी मदद कर रहे थे
कार्यक्रम। इनमें उनके प्रधान सचिव, पी. एन. धर; विश्वसनीय लोग शामिल थे।
सलाहकार, पी. एन. हक्सर (जिन्होंने 1971 में प्रधान सचिव पद से इस्तीफा दे दिया
था, लेकिन
(उन्हें सलाह देना जारी रखा था), एईसी अध्यक्ष होमी सेथना, बीएआरसी
निदेशक राजा रमन्ना, सेना प्रमुख जनरल गोपाल गुरुनाथ बेवूर,
और बसंती दुलाल नागचौधरी, जो डीआरडीओ प्रमुख और वरिष्ठ थीं
रक्षा मंत्री की सलाहकार। उन्होंने उनके साथ इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा की।
परमाणु शक्ति अपनाने के नुकसान। दिलचस्प बात यह है कि इंदिरा गांधी ने अपनी
राजनीतिक स्थिति को संयमित रखा।

जानकारी लीक होने से रोकने के लिए सहकर्मियों को अलग रखा गया था—वाजपेयी ने भी चौबीस साल बाद ऐसा ही किया, जब उन्होंने फैसला किया
मई 1998 में परीक्षण के लिए। इंदिरा गांधी ने रक्षा मंत्री से भी बात नहीं की।
उन्होंने जगजीवन राम को इस बात का भरोसा नहीं दिलाया। न ही उन्होंने विदेश मंत्रालय को इसकी सूचना दी।
मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह। उन्हें केवल अड़तालीस घंटे का समय दिया गया था।
परीक्षा होने से पहले वाजपेयी को अपने बचाव पक्ष को भी सूचित करना था।
मंत्री और विदेश मंत्री को केवल दो दिन पहले सूचना दी गई।
अर्थशास्त्री पी. एन. धर इस परीक्षण के खिलाफ थे—वे
अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को लेकर आशंकाएं थीं।
उन्होंने इंदिरा गांधी को चेतावनी दी थी कि भारत के साथ मैत्री संधि के बाद यह अपरिहार्य था।
सोवियत संघ के साथ 1971 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय, दोनों महाशक्तियाँ
हम अभी भी शीत युद्ध में उलझे हुए थे। हालाँकि, वैज्ञानिक उत्सुक थे।
परीक्षण। एक राजनीतिक रणनीतिकार होने के नाते, हक्सर चाहते थे कि परीक्षण हो।
1976 में होने वाले चुनावों के करीब; उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी शायद ऐसा कर सकेंगी
इसे चुनावी रूप से हासिल किया जाता है।
कोर ग्रुप की बैठक में इंदिरा गांधी ने सिर्फ सुना और साथ ही कुछ चित्र भी बनाती रहीं।
उसके सामने रखे पैड पर। उसने अपनी टीम के किसी भी सदस्य का खंडन नहीं किया। इसके बाद
सभी अपनी बात कह चुके थे, उसने बस एक संक्षिप्त घोषणा की—कि वह
परीक्षण आगे बढ़ाया जाएगा।
18 मई 1974 को सुबह 8.05 बजे, भारत ने एक 'शांतिपूर्ण' बैठक की।
'इम्प्लोजन', भूमिगत रूप से किया गया एक परमाणु परीक्षण। परीक्षण का कोड-
इसका नाम 'स्माइलिंग बुद्धा' था; यह बुद्ध पूर्णिमा के दिन आयोजित किया गया था।
इसकी घोषणा बहुत ही सामान्य और औपचारिक तरीके से की गई थी। ऑल इंडिया

रेडियो ने इसे प्रसारित किया।
अपने एक समाचार बुलेटिन में। जब इस बारे में पूछा गया, तो प्रधानमंत्री ने
सरकार ने इसके महत्व को कम करके आंका। सरकार ने इस उपकरण को एक
'शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटक'।
लेकिन इंदिरा गांधी ने परीक्षण के समय का चुनाव बहुत सावधानीपूर्वक किया था।
1974 में, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रावधान का लाभ उठाने की उम्मीद की
थी।
अप्रसार संधि (एनपीटी), जिसने देशों को संचालन करने की अनुमति दी
शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु परीक्षण।
इसी वजह से इस परीक्षण को 'शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण' कहा गया।
'विस्फोट'। उसे उम्मीद थी कि इससे दुनिया की ओर से इसकी निंदा कुछ हद तक कम
हो जाएगी।
—जो होना ही था। लेकिन न तो अमेरिकियों ने और न ही
रूसियों ने भारत के इस स्पष्टीकरण को मान लिया कि विस्फोट जानबूझकर किया
गया था।
शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। न ही पाकिस्तानियों ने ऐसा किया।
इंदिरा गांधी ने बम का परीक्षण करने का निर्णय 1972 में ही ले लिया था।
1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध जीतने और नए राष्ट्र की स्थापना के बाद
बांग्लादेश में उन्हें 'दुर्गा' के रूप में सम्मानित किया गया था। लेकिन 1973-74 तक
बांग्लादेश को लेकर उत्साह कम होने लगा। अर्थव्यवस्था की हालत खराब थी।
युद्ध की लागत और शरणार्थियों के भारी प्रवाह से बोझिल, संकट में डूबा हुआ।
नया राष्ट्र बना। फिर सूखा पड़ा। तेल की कीमतें भी बढ़ रही थीं। 1974 तक,
घरेलू स्थिति तेजी से बिगड़ गई। आंदोलन का नेतृत्व
भ्रष्टाचार और कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने सभा का
आयोजन किया।
गति; उग्र समाजवादी नेता के नेतृत्व में रेलकर्मियों की हड़ताल
जॉर्ज फर्नांडीस ने लगभग पूरे देश को ठप्प कर दिया था। रणनीतिक
इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए, इंदिरा गांधी को सत्ता हथियाने के लिए कुछ
साहसिक कदम उठाना ही था।

फिर से राजनीतिक पहल। उसने अनुमान लगाया होगा कि अगर वह परीक्षण करती है, तो वह
उन्हें एक बार फिर एक सशक्त नेता के रूप में सराहा जाएगा—हालांकि वह जानती थीं कि
इसके बाद प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
इंदिरा गांधी ने तुरंत ही धमाका कर दिया।
ये प्रतिबंध अमेरिका के नेतृत्व में औद्योगिक जगत द्वारा लगाए गए थे।
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी), जिसका गठन इसके तुरंत बाद हुआ था
भारत के परीक्षण ने उसे प्रमुख प्रौद्योगिकी और सामग्रियों के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया और
अन्य देशों जिन्होंने राष्ट्रीय नीति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, उन पर भी प्रतिबंध लगाए गए। ये प्रतिबंध एक तरह से लागू किए गए थे।
भारत के परमाणु कार्यक्रम को भारी झटका लगा है, खासकर 'निर्माण' के लिए।
'ऊर्जा रिएक्टरों' पर उनके इतने सख्त नियम थे कि 1980 के दशक के मध्य में, अमेरिका ने
यहां तक कि उन्होंने भारत को मौसम की निगरानी के लिए एक सुपर कंप्यूटर बेचने से भी इनकार कर दिया।
उद्देश्यों के लिए! इसे दोहरे उपयोग वाली तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो हो सकती है
इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया गया। भारत को एक दुष्ट राष्ट्र की तरह माना जाता था।
हालांकि उसने जो किया उसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं था। उसने बस इतना ही किया था।
उसने राष्ट्रीय नीति समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करके एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग किया।
जो कि मूलतः हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच एक निजी संधि थी।
इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समझौते (एनपीटी) के तहत भी पीएनई की अनुमति थी।
1974 के परीक्षण के अन्य परिणाम भी थे। चीन ने कदम बढ़ाया।

उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता कम कर दी। वे नहीं चाहते थे कि भारत का प्रभाव बढ़े।
इस क्षेत्र में—और पाकिस्तान के समर्थन में सामने आए। जुल्फिकार अली के बाद 1979 में भुट्टो की मृत्यु के बाद, पाकिस्तानी सेना ने परमाणु हथियारों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
कार्यक्रम। एक दशक से भी कम समय बाद, यह अफवाह फैल गई कि पाकिस्तान ने बम। अमेरिका ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत थी। अफगानिस्तान में उसकी नाकाम कोशिशों के कारण। पाकिस्तान के प्रभाव के चलते, यहां तक कि परमाणु हथियारों के घोर विरोधी मोरारजी देसाई भी ऐसा नहीं कर पाए थे।
1979 में परमाणु कार्यक्रम को बंद करने का साहस किया (जैसा कि हमने देखा था) अध्याय की शुरुआत)।
1980 में, विजयी इंदिरा गांधी सत्ता में वापस लौटीं, और उन्होंने
उन्होंने एक और परीक्षण करने का फैसला किया। वैज्ञानिकों को पता था कि 1974 के प्रारंभिक पीएनई में सुधार करना होगा। वह राजा को लेकर आई।
मोरारजी देसाई द्वारा स्थानांतरित किए गए रमन्ना को वापस
जनवरी 1981 में BARC के निदेशक के रूप में उन्होंने तुरंत सुझाव दिया कि भारत उन दो हथियार डिजाइनों का परीक्षण करें जिन्हें उन वर्षों में विकसित किया गया था कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। 1982 के मध्य तक, जिन शाफ्टों में...
पोखरण में विस्फोट होने की आशंका के चलते खुदाई करके तैयारी कर ली गई थी। राजस्थान। लेकिन, आखिरी क्षण में इंदिरा घबरा गईं। आर. के अनुसार...
उस समय रक्षा मंत्री रहीं वेंकटारमन ने अपना रुख बदल दिया।
एक दिन से दूसरे दिन तक मन बदलता रहता है। अमेरिकी उपग्रहों ने इसका पता लगा लिया था।
आसन्न परमाणु परीक्षण के संदिग्ध संकेत। ये तस्वीरें
अमेरिकी विदेश उप सचिव (राजनीतिक मामलों के लिए) लॉरेंस द्वारा दिखाया गया। ईगलबर्गर ने भारत के विदेश सचिव एम. के. रसगोत्रा को पत्र लिखा। रसगोत्रा ने इंदिरा गांधी के आगमन से ठीक पहले, मई 1982 में, मैं उनसे मिलने वाशिंगटन डीसी गई थी।

गांधी जी की अमेरिका यात्रा।
इंदिरा गांधी ने अपना प्रस्ताव इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि वह जानती थीं कि अमेरिकी प्रतिक्रिया क्या होगी।
यह परीक्षा दंडात्मक होगी—और वह यह भी जानती थी कि उसे एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
देश में कठिन आर्थिक स्थिति है। वह अब वह नहीं रही।
1974 में अपने छोटे बेटे को खोने के बाद भी वह एक आत्मविश्वासी नेता थीं।
संजय की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह यह भी नहीं भूल पाई थी कि दो साल बाद भी...
1974 के परीक्षण में, शक्तिशाली अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने
उसने अपने एक सहयोगी को चेतावनी देते हुए कहा, 'ऐसा दोबारा मत करना। इस बार हम इसे पूरी तरह नष्ट कर देंगे।'
'तुम्हें।' मंजूरी देने के कुछ ही घंटों के भीतर, उसने 'आरवी' को वी को फोन करने के लिए कहा।
एस. अरुणाचलम, जिन्होंने डीआरडीओ के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला था, और
रमन्ना—और उनसे कहो कि वे इसे रद्द कर दें।
'क्यों?' निराश रामन्ना ने उससे पूछा।
उसने उससे कहा, 'हम नहीं चाहते कि हमारी खोपड़ी टूट जाए।'
■

राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विशेष रूप से इसे अधिकृत किया था।
1989 में परमाणु हथियारों का संयोजन।
के. संथनम ने राजीव द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों के बीच अंतर समझाया।
गांधी के मन में वही विचार और वही युक्ति थी जो उनकी माता इंदिरा गांधी के मन में थी।
परीक्षण किया गया। '1974 में पीएनई केवल एक उपकरण था। दूसरी ओर एक हथियार।

हाथ को वेक्टर डिलीवरी के लिए अनुकूलित किया गया है... एक ऐसा उपकरण जो परमाणु हथियार बन सकता है।
डिलीवरी के लिए बम को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें बहुत कुछ शामिल होता है।
जटिल इंजीनियरिंग। इसे उड़ान के लिए योग्य होना चाहिए और तापमान, वातावरण और कम दबाव में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने में सक्षम होना चाहिए।
जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहां 40-50 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग निर्वात होता है।
संथनम के अनुसार, राजीव गांधी के निर्देश थे कि 'रखते रहें'
काम जारी है', लेकिन 'हर पड़ाव को मेरी मंजूरी से ही पूरा किया जाना चाहिए'। उन्होंने चेतावनी दी कि
अगर जानकारी लीक हो गई तो गंभीर समस्याएं पैदा हो जाएंगी। 'राजीव था
इस बात के सबूतों से आश्वस्त होकर कि पाकिस्तान कुछ गलत काम कर रहा था, उसने
1989 में मंजूरी दे दी।
राजीव गांधी ने परमाणु निरस्त्रीकरण के समर्थक के रूप में अपना करियर शुरू किया था।
मई 1984 में, भारत ने स्वीडन सहित पांच अन्य देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया था।
अर्जेंटीना, तंजानिया, मैक्सिको और ग्रीस—छह राष्ट्रों, पांच-
निरस्त्रीकरण पर महाद्वीपीय वैश्विक पहल। उनके पदभार संभालने के कुछ दिनों बाद।
प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जनवरी 1985 में दिल्ली में पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। 1988 तक, उन्होंने
उन्होंने निरस्त्रीकरण को एक लक्ष्य के रूप में आगे बढ़ाना जारी रखा।
लेकिन उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे। अपने पूर्ववर्तियों की तरह, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया।
देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम को बंद करो। यह मुद्दा उठेगा।
1985 में उन्होंने विशेष रूप से स्थापित किए गए एक छोटे समूह में चर्चा के लिए यह विचार रखा था।

इसका उद्देश्य देश के सामने मौजूद सभी रणनीतिक मुद्दों की समीक्षा करना था, जिनमें परमाणु मुद्दा भी शामिल था।
मुद्दा एक ही था। इसे अंतर्विषयक समूह कहा जाता था, जिसमें राजीव शामिल थे।
गांधी, अरुण सिंह, रक्षा राज्य मंत्री, जो राजीव गांधी के मित्र भी थे, दो
कांग्रेस के मुख्यमंत्री, केरल के के करुणाकरण और हितेश्वर
असम के सैकिया, परमाणु ऊर्जा प्रमुख, राजा रामन्ना और मुख्य
आर्थिक सलाहकार बिमल जालान। कैबिनेट सचिव, अध्यक्ष
चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, दोनों खुफिया प्रमुख और प्रमुख
संयुक्त खुफिया समिति के सदस्य भी इसके सदस्य थे।
समिति में के. सुब्रह्मण्यम एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो समिति के बाहर से थे।
सरकार।
समूह की मासिक बैठकों में से एक में, सुब्रमण्यम थे
भारत को परमाणु शक्ति क्यों हासिल करनी चाहिए, इस विषय पर विस्तार से बताते हुए, राजीव ने कहा। जब उन्होंने अपनी बात समाप्त की, तो
गांधी ने उनकी ओर मुड़कर पूछा, 'आपने इनमें से किसी से भी निपटा नहीं है।'
हमें एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करने चाहिए, इसके कारण।
'इसके लिए आपको मुझे एक और सत्र देना होगा,' सुब्रह्मण्यम ने कहा।
उन्होंने जवाब दिया। अगले सत्र में उन्होंने बताया कि भारत को इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करने चाहिए।
एनपीटी। एक अन्य बैठक में, राजीव गांधी ने रामन्ना से कहा, 'क्यों नहीं?'
क्या आप कोई ऐसा वैकल्पिक एनपीटी (गैर-भेदभावपूर्ण नीति) तैयार कर सकते हैं?
फिर भी, हालांकि राजीव निरस्त्रीकरण को एक लक्ष्य के रूप में अपना रहे थे, उन्होंने अनुमति दी
टीम को शोध जारी रखने के लिए। सुब्रह्मण्यम के अनुसार, 'उन्होंने ऐसा किया।'
पैसे बचाने की कोशिश न करें।
अगस्त 1985 में किसी समय, रमन्ना और सुब्रमण्यम ने प्रस्ताव रखा
राजीव गांधी से यह अनुरोध किया गया कि भारत पाकिस्तान को 'पहले हमला न करने' की गारंटी दे।
उपयोग। और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

दूसरे की परमाणु सुविधाओं के बारे में। राजीव ने उनसे कहा कि वे 'मेरे साथियों' से बात करें—कैबिनेट
सचिव पी. के. कौल और गोपी अरोरा, दोनों ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा, 'हम ऐसा नहीं कर सकते।'
'क्यों नहीं?' सुब्रह्मण्यम ने पूछा।
हम यह स्वीकार कर रहे होंगे कि या तो हमारे पास परमाणु हथियार हैं या
हम इन्हें बनाने पर काम कर रहे हैं... हम प्रधानमंत्री को इसकी सिफारिश नहीं कर सकते।'
राजीव गांधी ने उनसे नरसिम्हा राव से परामर्श करने को भी कहा था।
तत्कालीन रक्षा मंत्री राव ने रामन्ना और सुब्रह्मण्यम को बताया,
आपके द्वारा प्रस्तुत दो प्रस्तावों में से, आक्रमण न करने वाला प्रस्ताव ठीक है।
लेकिन मैं पहले इस्तेमाल न करने के सिद्धांत से सहमत नहीं हूं।'
उन्होंने उससे पूछा, 'क्यों?'
आप जानते हैं कि हमारे युवा प्रधानमंत्री देशभर में घूम-घूमकर भाषण दे रहे हैं।
राव ने उनसे कहा, 'पाकिस्तानी बम के बारे में। अगर अब आप पहले नहीं का विकल्प चुनते हैं तो...'
अगर इसका इस्तेमाल किया गया, तो पाकिस्तानी कहेंगे, "भारत डर गया है और इसलिए ऐसा कर रहा है।"
डर का।
प्रधानमंत्री के साथ उनकी एक बैठक के दौरान—यह बैठक हुई थी
अक्टूबर 1985- सुब्रह्मण्यम ने राजीव गांधी से कहा, 'आप आगे नहीं बढ़ सकते
इस पर निर्णय को टालना (परमाणु युद्ध छेड़ना)। यदि आप देरी करते रहे, तो
रक्षा खर्च आसमान छू जाएगा। आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
लोग आपको बता रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है।
आपके पास हथियार कार्यक्रम शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
राजीव ने कमरे में घूमकर सभी से पूछने का फैसला किया।
राय। अधिकतर लोग तटस्थ रहे। बिमल जालान ने स्पष्ट रूप से 'नहीं' कहा।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, 'हम इसे वहन नहीं कर सकते, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो

जाएगी।'
ऐसा हुआ कि सेना प्रमुख जनरल अरुण श्रीधर वैद्य उपस्थित नहीं थे।
उस दिन वहां उनका प्रतिनिधित्व नौसेना प्रमुख आर. एच. ताहिलियानी ने किया।
ताहिलियानी ने सावधानी बरतते हुए कहा, 'हम इसका अध्ययन करेंगे और अगली बैठक में आपको बताएंगे।'
बैठक।' उसी रात, रमन्ना और सुब्रह्मण्यम देखने गए।
ताहिलियानी नई दिल्ली के नेवी हाउस में। ताहिलियानी ने उनसे कहा, 'मैं
इसकी लागत की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी।
'वैद्य के वापस आने से पहले, आपको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में,
उन्होंने सुझाव दिया, 'समिति नियुक्त करें, क्योंकि हमें समिति चाहिए।'
इसका नेतृत्व सुंदरजी करेंगे।
उस समय जनरल के. सुंदरजी सशस्त्र बलों के उप प्रमुख थे।
उन्होंने कहा, 'वही एकमात्र व्यक्ति है जिसे इस विषय की जानकारी है।' ताहिलियानी जनरल सुंदरजी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:
नौसेना से एडमिरल के. के. नायर, एयर मार्शल जॉनी ग्रीन
वायु सेना और परमाणु वैज्ञानिक ए. पी. जे. अब्दुल कलाम और
राजगोपाला चिदंबरम। उन्होंने दस दिनों के भीतर एक रिपोर्ट तैयार की।
अनुमान है कि सात वर्षों में भारत न्यूनतम परमाणु क्षमता हासिल कर सकता है।
7,000 रुपये की लागत से सौ मिसाइलों और युद्धक हथियारों को रोकने की क्षमता।
करोड़ों। 'परमाणु निवारक' की अवधारणा सबसे पहले इसी रिपोर्ट में सामने आई थी।
बीस पन्नों की रिपोर्ट अरुण सिंह, रमन्ना और वी.एस. को दिखाई गई।
अरुणाचलम, जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे, और
सुब्रमण्यम को. जनरल सुन्दरजी ने इसे व्यक्तिगत रूप से टाइप किया था। उसने कहा वह
उन्होंने अपने पास मौजूद एकमात्र प्रति राजीव गांधी को दे दी।
इसी चरण में शस्त्रीकरण के विचार को एक नई दिशा मिली।
अप्रत्याशित घटना। अक्टूबर 1985 के अंतिम सप्ताह में, राजीव गांधी ने मुलाकात की।

अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन अमेरिका में थे। यह बैठक यहाँ हुई।
न्यूयॉर्क में वाल्डोर्फ एस्टोरिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा भी वहीं थी।
सत्र। राजीव और रीगन के बीच तब अच्छे संबंध स्थापित हुए जब भारतीय प्रधानमंत्री
उस वर्ष जून में मंत्री ने राजकीय यात्रा पर अमेरिका का दौरा किया था।
आशा है कि भारत, अपने युवा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अधिक
संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के साथ संबंधों में संतुलित रुख अपनाना
संघ।
जब वे अक्टूबर 1985 में मिले, तो रीगन ने राजीव गांधी से कहा,
'पाकिस्तान पहले ही बम बना चुका है।' जब राजीव ने इस बारे में बात करना शुरू
किया
निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा,
'सिद्धांतों की बात मत करो, सोचो...'
अपनी सुरक्षा स्वयं करो।' यह बात मुझे राजनयिक एस. के. सिंह ने बताई थी। उनके
पास
वियना में भारतीय राजदूत (1979-82) के रूप में कार्य करने के कारण उन्हें सभी
विवरणों की जानकारी थी।
देश के रणनीतिक हथियार कार्यक्रम के। वह इसमें भी शामिल थे।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु नियामक प्राधिकरण के शासी मंडल,
वियना में मुख्यालय वाली आईएईए अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों पर बारीकी से नजर
रखती थी।
परमाणु हथियारों के विकास पर सिंह की राय। सिंह भी इस चर्चा में शामिल थे।
पाकिस्तान के मामले में वह दुविधा में पड़ गए थे। 1985 में उन्हें वियना से वापस
बुला लिया गया और
पाकिस्तान में उच्चायुक्त के रूप में तैनात।
एस. के. सिंह ने मुझे बताया कि इसी समय राजीव गांधी ने यह दिया था।
हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश। 'मुझे इसकी जानकारी थी।'
राजीव ने जो निर्देश दिए थे, कि कुछ भी लिखित में नहीं होगा और
हम हथियारों की खरीद पर पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे।'
अब तक, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के बारे में काफी जानकारी सामने आई है।

कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन राजीव से रीगन के शब्दों के बाद—कि
पाकिस्तान के पास पहले से ही बम था—चिंतित प्रधानमंत्री ने एस. के. सिंह से अनुरोध किया कि...
उन्होंने पाकिस्तान की समृद्ध यूरेनियम सुविधा के बारे में जितनी भी जानकारी हो सके, उसकी पुष्टि की।
कहूटा, इस्लामाबाद से 22 किलोमीटर दूर स्थित है।
'राजीव ने मुझे खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए थे।'
मेरे निजी घर की छत पर एक उपकरण लगा हुआ है। पाकिस्तान के दो
मुझसे सीधे तौर पर संपर्क करने वाले केंद्र जुड़े हुए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि मुझे यह मिला।
उत्तर पश्चिम सीमांत में स्थित चौकियों से सीधे प्राप्त जानकारी और
दक्षिण पूर्व सीमांत।' उन्होंने आगे कहा, 'हमें ब्रिटेन को सबूत देना था और
अमेरिका (पाकिस्तान की गतिविधियों के बारे में)।
उन्हें जो काम करने को कहा गया था, उनमें से एक यह था कि वे पुख्ता जानकारी जुटाएं कि
जरूरत इस बात की थी कि कहूटा के पास सड़क किनारे एक नाई की दुकान खोली जाए।
इसका उद्देश्य कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के बाल एकत्र करना था। 'बाल एक संवेदनशील क्षेत्र होते हैं।'
मानव शरीर रचना विज्ञान का, जो माइक्रोन को कैप्चर और संप्रेषित करता है और
परमाणु।' सिंह ने मुझसे कहा, 'चपरासी के काटे गए बालों के माध्यम से,
आदि, जिन्होंने काहुता में काम किया, हम यह पता लगा सकते थे कि समृद्ध यूरेनियम वहां इसका इस्तेमाल हो रहा था... इससे रीगन ने राजीव को जो बताया था, उसकी पुष्टि हो गई।
भारत को 1987 तक यह स्पष्ट हो चुका था कि पाकिस्तान के पास 'बम' मौजूद था।
सी. राजा मोहन ने कहा, 'उस समय भारत के सामने सवाल यह था कि आप क्या करते हैं?'
भारत द्वारा परमाणु हथियार कार्यक्रम को गति देने का संकल्प सामने आया।

सन् 1987 की शुरुआत में, ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी दी थी।
ब्रासस्टैक्स, एक बड़े पैमाने का भारतीय सैन्य युद्ध अभ्यास था जो
पाकिस्तान की सीमा के पास का स्थान। ब्रासस्टैक्स से डरा हुआ, जूनियर
पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय में मंत्री ज़ैन नूरानी (उस समय)
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक रक्षा मंत्री भी थे।
उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त एस. के. सिंह को अपने कार्यालय में तलब किया।
सिंह को रात 10 बजे बुलाया गया। उन्हें दो घंटे तक इंतजार कराया गया।
नूरानी ने उसे अंदर बुलाया। उसने सिंह को बताया कि वह सीधे आ रहा है।
राष्ट्रपति जिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति एक संदेश देना चाहते थे।
भारत सरकार: यदि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया
और क्षेत्रीय अखंडता के मामले में, पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने की स्थिति में था।
भारत को 'असहनीय क्षति'। (यही शब्द प्रयोग में लाए गए थे)
एस. के. सिंह ने मुझे बताया कि पाकिस्तान ने परमाणु बल के प्रयोग के लिए बाद में दावा किया।
कि उसके परमाणु खतरे ने ही भारत को उस पर आक्रमण करने से रोका था।
इस बात के 'अकाट्य सबूत' पेश किए गए कि पाकिस्तान के पास
फरवरी 1987 में परमाणु बम के हमले के बाद, राजीव गांधी ने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम को गति देने का फैसला किया। वैसे भी वे अपने देश से निराश थे।
निरस्त्रीकरण पर पहल, जो एक असफल प्रयास साबित हुई थी
जुलाई 1988 में संयुक्त राष्ट्र।
शनिवार, 18 मार्च 1989 को, राजीव ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी।
पर्याप्त संख्या में हथियार बनाना और उनकी आपूर्ति को परिपूर्ण बनाना
प्रणालियों के संबंध में। उन्होंने अपने रक्षा सचिव नरेश चंद्र को आदेश दिए।
उस सुबह वह तिलपत पर्वतमाला में एक हवाई शो में भाग ले रहा था, और देख रहा था
नरेश चंद्र ने अपनी पत्नी सोनिया के साथ एक प्रभावशाली फ्लाईपास्ट किया।
वह भी कार्यक्रम में उनके ठीक पीछे बैठी थीं।
शो खत्म होने पर राजीव ने अपने बचाव पक्ष के प्रतिनिधियों से बात करने की इच्छा

जताई।
सचिव। नरेश चंद्र ने वर्षों बाद मुझे बताया, 'राजीव ने मुझसे कहा था,'
'Yeh aapko karna hai (You have to do this).' The prime minister
चंद्र को परमाणु और डीआरडीओ कार्यक्रमों की देखरेख करने के लिए अधिकृत किया गया, और
मिसाइलों को तैयार करना—और प्रधानमंत्री का प्रमुख बनना
परमाणु मुद्दे से जुड़े हर मामले में समस्या निवारक।
लगभग 1988-89 के आसपास राजीव ने एक योजना बनाने के बारे में सोचना शुरू किया।
कमान एवं नियंत्रण प्रणाली लागू है। टी. एन. सेशान, मंत्रिमंडल
सचिव को 'एक बाहरी स्थान खोजने का जिम्मा सौंपा गया था...जहां से
एस. के. ने कहा, 'परमाणु हमले की स्थिति में भी पूरी सरकार काम कर सकती है।'
सिंह ने कहा, 'बेशक, सरकार विस्तार से नहीं बताएगी, लेकिन फिर भी
रक्षा, वित्त, विदेश मामलों, गृह मामलों आदि की देखरेख के लिए एक टीम होगी।
और प्रधानमंत्री का कामकाज... इसे गुप्त रूप से ही करना पड़ा...
रेडियो और टीवी तथा नई तकनीक और संचार से जुड़ा हुआ
और जहां खुफिया जानकारी दी जा सके और जहां यह सुनिश्चित किया जा सके
जनता का मनोबल ऊंचा बना रहे... गोपी अरोरा, शेषन और मैं थे।
हमें कमान और नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने का कार्य सौंपा गया था... हम थे
वैकल्पिक सरकार के लिए तीन स्थानों पर विचार किया जा रहा था, लेकिन वे स्थान स्वीकृत नहीं हुए।
अंतिम रूप दे दिया गया। वे दिल्ली के पास नहीं थे और वास्तुशिल्प योजनाएँ
भूमिगत स्थल बनाए गए थे।
राजीव गांधी ने परमाणु मुद्दे पर अपने हर कदम को बेहद गोपनीय रखा।
यह एक गुप्त रहस्य था। इसमें केवल कुछ ही लोग सीधे तौर पर शामिल थे।
रणनीतिक गुरु के. सुब्रह्मण्यम, जो इसमें गहराई से जुड़े हुए थे
मुझे सिस्टम की जरा भी आहट नहीं मिली।
मुझे भारत के बम के बारे में औपचारिक और आधिकारिक तौर पर जुलाई में ही

बताया गया था।
1990,' Subrahmanyam said.
तब तक वी. पी. सिंह प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल चुके थे।
■

जुलाई 1990 में, प्रधानमंत्री पद संभालने के सात महीने बाद, वी. पी. सिंह

सभी संबंधित मामलों की देखरेख के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया।
अब जब हमें परमाणु बम मिल गया था, तो हमने इस पर विचार किया।
इसमें अरुण सिंह और जनरल सुंदरजी शामिल थे, जो अब तक सेवानिवृत्त हो चुके थे।
सेना प्रमुख के रूप में, लेकिन परमाणु हथियारों पर किसकी विशेषज्ञता थी?
ज्ञात, और के. सुब्रमण्यम और के. संथानम।
के. सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'यह एक गुप्त समिति थी।' इसकी बैठकें आधे समय होती थीं।
कई बार। राजीव गांधी के समय में, उन्होंने 'इस तरह की चीजों' पर चर्चा की थी।
मान लीजिए कि राजधानी पर हमला हुआ और राजनीतिक नेतृत्व का सफाया हो गया।
बाहर कौन जाएगा, फिर कौन बटन दबाएगा, इन सब बातों का हिसाब-किताब पहले से ही तय था।
समिति के सचिव संथानम ने कहा: 'विचार यह था कि इसे मूर्त रूप दिया जाए।'
परमाणु सिद्धांत को बाहर निकालें, जिसे परिचालन में लाया जा सकता है
'विवरण।' उन्होंने कहा, 'ब्लू बुक की तरह, जो मानक निर्धारित करती है।'
प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर परिचालन प्रक्रिया, समिति
उन्होंने एक लाल किताब पर काम करना शुरू किया जिसमें यह बताया जाएगा कि आगे क्या होगा।
परमाणु युद्ध की स्थिति में क्या किया जाएगा। समूह ने विभिन्न स्थितियों की कल्पना करने का प्रयास किया।
परमाणु हमले से देश के तबाह हो जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले परिदृश्य।

नेतृत्व—और कमान की तीन श्रृंखलाओं पर चर्चा की—राजनीतिक,
तकनीकी और प्रशासनिक—जो कि ऐसी स्थिति में लागू होने होंगे।
यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए।
जब प्रशासनिक कमान श्रृंखला पर चर्चा हो रही थी, तब
इस बैठक में कैबिनेट सचिव और अन्य सचिव भी उपस्थित थे।
रक्षा, गृह और विदेश मामलों के लिए।
'सज्जनों, हम यहां इस बात पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि हमारे बाद कौन बचेगा,' बचाव पक्ष ने कहा।
सचिव एन. एन. वोहरा ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में कहा, 'यह बहुत मजेदार था।'
संथनम ने बाद में याद किया। वोहरा के बयान में निहित बात यह थी कि
यह धारणा कि यदि आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) का अस्तित्व नहीं रहा,
कुछ भी नहीं बचता।
वी. पी. सिंह ने रणनीतिक आवश्यकता को शीघ्र ही समझ लिया था।
हथियार कार्यक्रम को और भी तेज़ गति दी जाएगी। वह रक्षा मंत्रालय में थे।
ऑपरेशन ब्रासस्टैक्स के दौरान मंत्री, जब पाकिस्तान ने धमकी दी थी
भारत ने 1987 में परमाणु हमला किया था। वह जानता था कि पाकिस्तान और दोनों
भारत के कम मित्र पड़ोसी देश चीन के पास परमाणु हथियार थे।
भारत को इस मामले में लापरवाह नहीं रहना चाहिए था।
हालांकि, उनके और उनके पूर्ववर्ती के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए,
राजीव गांधी ने वी.पी. सिंह और कुछ संबंधित लोगों को अद्यतन जानकारी नहीं दी थी।
परमाणु वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन को इस बात के लिए राजी करने का फैसला किया कि वे राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन को इस विषय पर चर्चा के लिए राजी करें।
प्रधानमंत्री को नवीनतम जानकारी थी। इसके बाद ही वी. पी. सिंह को पता चला।
देश का परमाणु कार्यक्रम वास्तव में कितना उन्नत था। डॉ. वी. एस.
रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार अरुणाचलम ने प्रधानमंत्री को बताया था:
'जरूरत पड़ने पर हम एक हफ्ते से दस दिनों के भीतर (बम) पहुंचा सकते हैं...'

वी. पी. सिंह ने बाद में कहा, 'हमने इसे हासिल कर लिया था।'
नैनोसेकंड... हमें खबरें मिली थीं कि पाकिस्तान सेना को इकट्ठा करने के बहुत करीब था।
एक...(और यह कि) इसमें ऐसा करने की क्षमता थी... मेरी चिंता यह थी कि हम पीछे नहीं रहना चाहिए। इससे पाकिस्तान और अधिक साहसी बनेगा।
Kashmir….'
'आम तौर पर मैं उन्हें रक्षा मंत्री के रूप में (1987 में) जानता था,' वी. पी. सिंह उन्होंने आगे कहा, 'हमारी क्षमता और भंडार मौजूद थे। और हमारे परमाणु विस्फोट की क्षमता मौजूद थी... जब मैं प्रधानमंत्री बना, तो यह सब करना पड़ा। तेजी से। प्रधानमंत्री के रूप में, एक परिचालन प्रणाली रखने पर जोर दिया गया था। बम।
लेकिन अंत में वी. पी. सिंह ने परीक्षण न कराने का फैसला किया। सीमा पाकिस्तान की स्थिति 'नाजुक' थी; पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्चाबंदी कर ली थी। 'हमारे सीमावर्ती इलाकों में उनके द्वारा किए गए अभ्यासों के बाद।' बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत के साथ 1,000 साल के युद्ध की बात कही थी। इसके अलावा, वी. पी. सिंह ने समझाया, 'विस्फोट से नाराज़गी हुई होगी।' 'अमेरिका और चीन, जब हमें दोनों की जरूरत थी।' फिर उन्होंने उदास स्वर में कहा, 'निर्णय शून्य में नहीं लिए जाते।'
■

जब चंद्र शेखर ने वी.पी. सिंह से प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, तब उन्होंने
उन्होंने एस. के. सिंह को फोन किया, जिनसे वे अच्छी तरह परिचित थे, और उन्हें आने के लिए कहा।
सिंह ने उपराष्ट्रपति के पदभार संभालने के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया था।
चंद्र शेखर ने 'एसके' से आदेश समझाने को कहा और
नियंत्रण संरचना।
'आप प्रधानमंत्री हैं। क्या आपको किसी ने जानकारी नहीं दी?' एक अचंभित व्यक्ति ने पूछा।

सिंह ने नए प्रधानमंत्री से पूछा।
‘नहीं, मुझे किसी ने जानकारी नहीं दी,’ चंद्र शेखर ने चिढ़ते हुए कहा।
अपने पूर्ववर्ती वी. पी. सिंह द्वारा की गई इस चूक का जिक्र करते हुए।
दोनों के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था।
यदि संसद भवन, दक्षिण और उत्तरी ब्लॉक नष्ट हो जाते हैं, तो फिर कहाँ बचेगा?
सरकार कहाँ से शुरू होती है? और किस चरण में विभिन्न अंग कार्य करना शुरू करेंगे?
क्या सरकार और उनके प्रमुख कर्मियों को वहां ले जाना होगा?’ एस.
के. सिंह ने प्रधानमंत्री से पूछा।
‘मुझे नहीं पता,’ चंद्र शेखर ने कहा।
तब सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 'तो फिर तुम और मैं एक ही श्रेणी में हैं।'
'नाव।' चंद्र शेखर हँस पड़े।
हालांकि चंद्र बम के शुरू से ही विरोधी थे,
शेखर ने कार्यक्रम नहीं रोका; उन्होंने रिहाई के लिए बिलों पर हस्ताक्षर किए।
चल रहे परमाणु कार्यक्रम के लिए धन।
चंद्र शेखर के उत्तराधिकारी पी.वी. नरसिम्हा राव के आने के बाद ही यह संभव हो पाया।
राव ने आरोप लगाया कि भारत परमाणु हथियार परीक्षण के सबसे करीब पहुंच गया था। लेकिन राव ने
आखिरी क्षण में पीछे हट गया। हालाँकि, वही वह व्यक्ति था जिसने प्रभाव डाला।
अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में परीक्षण करने का प्रस्ताव रखा था। और उन्होंने भारत को परीक्षण के लिए तैयार किया था।
स्थिति को टी-3 चरण (विस्फोट से तीन दिन पहले) तक ले जाना।
अब जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि वाजपेयी ने परमाणु शक्ति का प्रयोग कैसे और क्यों किया,
इस विकल्प के तहत, राव की भूमिका का विश्लेषण किए बिना कहानी अधूरी है।
राव द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का अधिक व्यापक रूप से विश्लेषण किया जाएगा।
नीचे दिए गए अनुभाग में वाजपेयी के निर्णय लेने की प्रक्रिया का वर्णन है। लेकिन

उससे पहले, एक
एच. डी. देवेगौड़ा और आई. के. गुजराल, जिन्होंने उनका अनुसरण किया, उनके द्वारा किए गए कार्यों की संक्षिप्त समीक्षा।
नरसिम्हा राव, जो वाजपेयी से पहले प्रधानमंत्री थे, ने निम्नलिखित मुद्दों को संभाला: 1996-97 में अपने संक्षिप्त प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान उन्होंने परमाणु मुद्दे पर चर्चा की।
■

देवे गौड़ा के शासनकाल के दौरान ही देश में एक बड़ा बदलाव आया।
नीति लागू हुई। फरवरी 1996 में, देवे गौड़ा से तीन महीने पहले।
सत्ता संभालने के बाद, नरसिम्हा राव सरकार ने अचानक घोषणा कर दी थी कि भारत की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार आवश्यक नहीं थे। यह बात जल्द ही गलत साबित हो गई।
राव द्वारा परीक्षण न करने का निर्णय लेने के बाद। लेकिन देवेगौड़ा के नेतृत्व में, भारत पहली बार यह घोषणा की गई कि वह परमाणु हथियारों को 'सुरक्षा खतरा' मानती है। 'यह एक मुद्दा है'—और यह कि परमाणु विकल्प केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं था।
जिनेवा में 20 जून को निरस्त्रीकरण पर एक सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी। 1996.
यह देवेगौड़ा के अधीन विदेश मंत्री रहे आई. के. गुजराल थे, जिन्होंने
नीतिगत बदलाव के पीछे का कारण। 'यह गुजराल का काम था,' के. सुब्रह्मण्यम खुलासा हुआ, ‘और नीति में यह बदलाव उनके कार्यकाल में हुआ।’
वैज्ञानिकों को देवे गौड़ा के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आई—यह मुलाकात तारीफ करने लायक कुछ नहीं। 'जब हम देवे गौड़ा से मिलने गए, तो उनके बाद जब कलाम, चिदंबरम और मैं प्रधानमंत्री बने, तब से वे लगातार असफल होते रहे। संथनम ने बताया, ‘सोने के लिए। उसका सिर नीचे गिर जाता था।’ इस बैठक में, गौड़ा ने परीक्षण कराने का निर्णय टाल दिया। तीन सप्ताह बाद, उन्होंने एक और परीक्षण कराया।

वैज्ञानिकों के साथ बैठक। इस बैठक में उन्होंने उनसे स्पष्ट रूप से कहा,
‘नहीं, नहीं। अभी नहीं।’ लेकिन देवे गौड़ा ने टेस्ट करवाने के बारे में सोचा ज़रूर था।
अपने प्रधानमंत्रित्व काल के अंतिम समय में घरेलू समस्याओं से निपटने की एक चाल के रूप में।
और कांग्रेस की ओर से उन पर पड़ रहे राजनीतिक दबाव को टालना।
जिसने उनकी सरकार का समर्थन किया था। अंततः, उन्होंने इसके खिलाफ फैसला लिया।
आई. के. गुजराल एक कट्टर शांतिवादी थे। उन्होंने सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।
भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, जिसे बाद में गुजराल के नाम से जाना गया।
सिद्धांत। जो बात ज्ञात नहीं है वह यह है कि उन्होंने भी गंभीरता से इस पर विचार किया था।
अपने प्रधानमंत्रित्व काल के अंतिम महीनों में परमाणु परीक्षण—के बाद
कांग्रेस ने 1997 में उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।
जब वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पांच महीने तक सत्ता में रहे।
मंत्री को बताया गया कि गुजराल ने इस संभावना पर विचार किया था।
‘उसी समय गुजराल ने अचानक गंभीरता से विचार करना शुरू किया कि क्या
'उसे जांच करानी चाहिए,' उनके प्रधानाचार्य एन. एन. वोहरा ने याद करते हुए कहा।
सचिव।
‘सबसे पहले, आपको यह जानना होगा कि हम किस चरण में हैं,’ वोहरा ने अपने साथियों को सलाह दी।
उस समय, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी बॉस के रूप में कार्य करते थे।
सुरक्षा सलाहकार वोहरा ने कहा कि उन्होंने गुजराल की मुलाकात का इंतजाम किया था।
वैज्ञानिक।
ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, तत्कालीन सचिव, डीआरडीओ और मुख्य वैज्ञानिक
रक्षा मंत्री के सलाहकार उस समय हैदराबाद में थे। 2 तारीख को और
3 जनवरी 1998 को गुजराल को राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करना था।
वे हैदराबाद में थे और राज्यपाल कृष्णकांत के साथ ठहरे थे।
मैंने उनके कार्यक्रम में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच एक निजी लंच दिखाया।

और दोपहर 2 से 5 बजे के बीच आराम का समय,' वोहरा ने कहा। स्थानीय
राजनेताओं को बताया गया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्तियाँ 5 तारीख के बाद ही शुरू होंगी।
दोपहर
'दोपहर 1:45 बजे हम गुजराल को एकीकृत मिसाइल विकास केंद्र ले गए।'
डीआरडीओ का केंद्र। इस बारे में केवल दो ही लोगों को पता था।
डॉ. कलाम और के. संथानम।' यह बैठक तीन घंटे तक चली।
जनवरी के मध्य में, 'गुजराल साहब ने एक परीक्षण कराने का फैसला किया।'
वोहरा ने कहा, 'मैंने उनसे कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी... (लेकिन) उनकी कही हर बात से मुझे पता चल गया था कि उन्होंने कुछ गलत किया है।
वह अपने मन में विचार रखता था। वह इस तरह की टिप्पणियाँ करता था कि किसे इसमें शामिल होने की आवश्यकता है।
तस्वीर, किसे पता चलेगा, आदि।' वैज्ञानिक भी उनसे मिल रहे थे।
सीधे तौर पर, विशेष रूप से भौतिक विज्ञानी आर. चिदंबरम, जो अध्यक्ष थे।
परमाणु ऊर्जा आयोग, और 'इस बात की पुष्टि करवाने के लिए उत्सुक' था।
उनके लड़कों द्वारा किए गए शोध।
परीक्षणों के समय को लेकर चिंतित वोहरा ने सुझाव दिया कि
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से बात की। राष्ट्रपति के. आर. नारायणन थे।
जिसने अंततः गुजराल को आगे बढ़ने से रोक दिया। यह उनकी मुलाकात के बाद हुआ था।
नारायणन के साथ, उन्होंने परीक्षण के संबंध में 'उन संदर्भों का प्रयोग करना बंद कर दिया'
परमाणु उपकरण।
■

यह दिलचस्प बात है कि सभी प्रधानमंत्रियों ने इसे दरकिनार कर दिया।
परमाणु मुद्दे पर निर्णय लेते समय कमान की एक स्थापित श्रृंखला तैयार की गई;

उन्होंने रक्षा मंत्री की बात अनसुनी कर दी और सीधे उनसे बातचीत की।
वैज्ञानिक। इंदिरा गांधी ने अपने रक्षा मंत्री जगजीवन राम को इससे दूर रखा था।
लूप के लिए, पी.वी. नरसिम्हा राव ने नरेश चंद्र को पुल के रूप में चुना।
वैज्ञानिकों के साथ अपने संबंधों के बारे में ए. बी. वाजपेयी ने ब्रजेश से खुलकर बात की।
मिश्रा। इसमें शामिल वैज्ञानिकों ने भी नौकरशाही का पालन नहीं किया।
पदानुक्रम।
जैसा कि नरेश चंद्र ने बाद के वर्षों में समझाया: 'एकमात्र तरीका जिससे हम कर सकते थे
यह सब इसलिए किया गया ताकि हम सिस्टम का हिस्सा न बन सकें।
ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें इस तरह के किसी भी व्यक्ति के होने की जानकारी हो।
नरेश चंद्र ने कहा, 'कोई जरूरी लक्ष्य या वार्षिक कार्यक्रम नहीं थे।' 'कोई तत्काल लक्ष्य या वार्षिक कार्यक्रम नहीं थे।'
रिपोर्ट या लक्ष्यों को पूरा करना या समयबद्ध परिणाम दिखाना। विचार यह था कि
अच्छी तरह से तैयार रहना और धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहना।' फिर उन्होंने
उन्होंने आगे कहा, 'वैज्ञानिक समुदाय अत्यंत विश्वसनीय है, और प्रतिबद्ध है।'
लोग...और इससे मदद मिली।'
तब चंद्रा हँसते हुए बोले, 'मेरे भाई गैरी (गिरीश सक्सेना) ने भी ऐसा ही किया था।'
पता नहीं नरेश क्या कर रहा था।

चतुर्थ

आगे बढ़ने से पहले, हम यह देखेंगे कि धूर्त नरसिम्हा राव और उनके बार-बार बदलते रुख वाले व्यक्ति ने कैसे...
वाजपेयी ने परमाणु मुद्दे पर चर्चा की, एक संक्षिप्त अवलोकन
प्रधानमंत्रियों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु नियामक व्यवस्था का पालन करना पड़ता था।
और 1974 के बाद भारत को जिन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।
कहानी की शुरुआत हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी से हुई।
अगस्त 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की ओर, अमेरिका ने परमाणु हथियार

हासिल कर लिए।
द्वितीय विश्व युद्ध। परमाणु नरसंहार के भयावह परिणाम, जिसने जान ले ली।
210,000 लोगों की जान गई और इससे अकल्पनीय तबाही और पीड़ा हुई।
अमेरिका किसी भी अन्य राष्ट्र को परमाणु ऊर्जा विकसित करने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
हथियार। क्योंकि इससे अमेरिका की सुरक्षा और उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।
अमेरिका ने नवगठित संयुक्त राष्ट्र महासभा को विकसित करने के लिए प्रेरित किया परमाणु खतरे से निपटने के उपाय। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया।
इस संबंध में 24 जनवरी 1946 को लंदन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप यह हुआ कि...
संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, जिसका उद्देश्य था
परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को विनियमित करना—और
परमाणु हथियारों का खात्मा, जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर विनाश के लिए किया जा सकता है
विनाश।
हालांकि, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बावजूद, वे सफल नहीं हो सके।
अन्य देशों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। सोवियत संघ
1949 में परमाणु हथियार का परीक्षण किया, ब्रिटेन ने 1950 में, फ्रांस ने 1958 में, और
1964 में चीन। (आज नौ परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। इसके अलावा)
जिन देशों ने 1968 से पहले परीक्षण किया था, उनमें से अन्य चार देश भारत, पाकिस्तान और इज़राइल हैं।
और उत्तर कोरिया।)
1968 में, परमाणु प्रसार को रोकने के अमेरिकी प्रयासों को आखिरकार कुछ सफलता मिली।
गति। दुनिया के पहले परमाणु हथियार संपन्न देश—अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संधि (एनपीटी) का निर्माण किया।

हथियारों को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और सामान्य तौर पर
परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ना। परमाणु शक्ति वाले पांच राष्ट्र
हथियारों ने आपस में तय कर लिया था कि 1 जनवरी 1968
किसी भी अन्य देश के लिए परमाणु शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने की अंतिम तिथि।
ऐसा करने के लिए हथियार। वे लोग जिनके पास इससे पहले परमाणु हथियार थे
उस तारीख को एनडब्ल्यूएस कहा जाएगा और जिनके पास ऐसे हथियार नहीं थे
परमाणु-हथियार रहित राज्य (NNWS) होंगे। NNWS जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं
एनपीटी के तहत परमाणु ऊर्जा के विकास या अधिग्रहण से बचना होगा।
भविष्य में उन्हें अपने सभी नागरिक परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखना होगा।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा के अंतर्गत सुविधाएं
संयुक्त राष्ट्र की संस्था, भारतीय मनोरंजन प्राधिकरण (आईएईए), की स्थापना जुलाई 1957 में हुई थी।
एक कारगर परमाणु हथियार विकसित करने में वर्षों, बल्कि दशकों लग गए।
पांच परमाणु-समृद्ध देशों के अलावा, कार्यक्रम को पारदर्शी तरीकों से चलाया जाएगा।
परमाणु विकल्प वास्तव में अन्य सभी देशों के लिए अनुपलब्ध होगा।
विश्व। एनपीटी ने विश्व को परमाणु शक्ति संपन्न (एनडब्ल्यूएस) और परमाणु शक्ति से वंचित (एनएनडब्ल्यूएस) देशों में 'कानूनी तौर पर' (अर्थात, स्वैच्छिक रूप से अनुबंधित संधि के माध्यम से) विभाजित किया।
दायित्वों।) इसे विश्व के देशों के हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।
1968 में प्रस्तावित और 1970 में लागू हुआ। '[एक] अंतर्राष्ट्रीय उपकरण,
यह स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण ढंग से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य निहत्थे लोगों को निहत्था करना है।
वरिष्ठ राजनयिक सौरभ कुमार ने भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रीय संधि (एनपीटी) के शब्दों का हवाला देते हुए यह बात कही।
वार्ताकार विष्णु त्रिवेदी। (कुमार आईएईए में भारत के राजदूत थे)
(2008 में वियना में हुई एनएसजी बैठक के नाटकीय घटनाक्रम के समय।) भारत ने पाया

एनपीटी को 'भेदभावपूर्ण' बताते हुए, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत के साथ-साथ,
पाकिस्तान और इजराइल ने भी एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
भारत के लिए, एनपीटी पर हस्ताक्षर करने का मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान होता।
चीन के साथ कठोर, रणनीतिक दृष्टि से। चूंकि चीन ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे।
1964 में इस हथियार को परमाणु हथियार संकट (एनडब्ल्यूएस) घोषित किया गया था। अगर भारत ने राष्ट्रीय नीति वार्ता (एनपीटी) पर हस्ताक्षर किए होते,
इसे एक गैर-राष्ट्रीय जलसंधि (एनडब्ल्यूएस) के रूप में ऐसा करना पड़ता। इसका मतलब यह होता कि देना पड़ता।
चाहे कुछ भी हो जाए, वह भविष्य में परमाणु हथियारों का उपयोग करने का विकल्प चुन सकता है।
भविष्य में क्या आएगा।
वाजपेयी की पार्टी, भारतीय जनसंघ द्वारा जोरदार समर्थन मिलने के बाद
1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद भारत के परमाणु ऊर्जा अपनाने के फैसले पर सरकार ने प्रतिक्रिया दी।
दोतरफा रणनीति अपनाने का निर्णय लिया गया। पहला था कूटनीतिक प्रयासों को तेज करना।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे बढ़ने के लिए राजी करने के प्रयास
सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण, जिसका समर्थन जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी दोनों ने किया था
कोशिश की गई, लेकिन लगभग कोई सफलता नहीं मिली। दूसरा प्रयास परमाणु ऊर्जा हासिल करने का था।
हथियारों की क्षमता। भारत द्वारा सार्वभौमिक हथियारों को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ।
निरस्त्रीकरण से कोई प्रगति नहीं हो रही थी, परमाणु उपकरण का विस्फोट ही एकमात्र उपाय बचा था।
देश के परमाणु हथियारों से लैस और आक्रामक रवैये को देखते हुए, उसके पास उपलब्ध प्रतिक्रिया विकल्पों की तुलना की जा सकती है।
पड़ोसी देश चीन। 1974 में किया गया परीक्षण, कुछ मायनों में, एक विलंबित

परीक्षण था।
1964 में चीन के परमाणु शक्ति बनने के जवाब में।
भारत ने परमाणु विस्फोट की तैयारी शुरू कर दी और आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित कीं।
एक ऐसी नीति जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति के प्रावधानों का उल्लंघन न करने के लिए सावधानी बरतती थी।
ताकि यह वैश्विक स्तर पर नैतिक श्रेष्ठता हासिल कर सके और साथ ही खुद को तैयार भी कर सके।
अपने परमाणु विकल्प का प्रयोग करने के लिए, जो उसने 1974 में किया था।
इसके वैज्ञानिक और परमाणु प्रतिष्ठान ने परमाणु ईंधन पर महारत हासिल कर ली थी।
इस चक्र में नागरिक उपयोग से निकले ईंधन के पुनर्संसाधन को शामिल किया गया था।
इन रिएक्टरों से प्लूटोनियम प्राप्त होता था, जो एक कच्चा माल है जिसका उपयोग बनाने के लिए किया जाता है
परमाणु हथियार समृद्ध यूरेनियम की तुलना में अधिक कुशल और कॉम्पैक्ट होते हैं।
प्लूटोनियम के इस दोहरे उपयोग ने भारत को आलोचनाओं के घेरे में ला दिया।
जिससे यह संकेत मिलता है कि वह गुप्त रूप से परमाणु क्षमता विकसित कर रहा था —जो
इस पर छूट दी गई। भारत ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन तथा परमाणु विस्फोट करने की क्षमता भी विकसित की।
जिन्हें राष्ट्रीय नीति समझौते (एनपीटी) द्वारा अनुमति दी गई थी (हालांकि भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे)।
बशर्ते कि वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हों।
■

अब हम सीधे 1990 के दशक में चलते हैं। परमाणु ऊर्जा को विनियमित करने के लिए एक नई संधि की स्थापना हुई।
हथियारों के अस्तित्व में आने का खतरा मंडरा रहा था। राष्ट्रीय नीति संधि (एनपीटी)

का विस्तार किया जा चुका था।
समय-समय पर, हर बार जब इसकी अवधि समाप्त होने वाली होती थी। अंततः, यह 1995 में इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया था।
इसके तुरंत बाद, 1996 में, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर किए गए।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 सितंबर को अपनाया गया—
अधिक को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक संरचना का एक अन्य भाग
परमाणु हथियार हासिल करने से देशों को रोकना। सीटीबीटी ने एक कदम और आगे बढ़ाया।
1963 की आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी) की तुलना में, इसने परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
शांतिपूर्ण और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए, सभी प्रकार की परिस्थितियों में।
सीटीबीटी की आसन्न समय सीमा ही तात्कालिक कारण थी।
भारत 1994-95 में परीक्षण पर विचार करेगा। जब भारत इस पर विचार कर रहा था...
पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान परीक्षण के लिए, या जब राव ने आग्रह किया था
वाजपेयी ने मई 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में अपने तेरह दिनों के कार्यकाल के दौरान ऐसा किया था।
या जब वाजपेयी ने आखिरकार मई 1998 में परीक्षा दी, तो यह निर्णय शासित था।
सीटीबीटी के लागू होने के कारण भारत को चिंता थी।
इसका कारण यह था कि यदि वह सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करता है, तो वह अपने परमाणु विकल्प को समाप्त कर देगा।
हमेशा के लिए। अगर उसने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो वह वैश्विक स्तर पर बहिष्कृत हो जाएगा।
समुदाय—हालांकि, संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत अरुंधति घोष ने कहा कि
जिनेवा ने 1996 में स्पष्ट रूप से कहा था, 'भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।'
'असमान संधि, न अभी, न बाद में।' लेकिन तब, भारत ऐसा नहीं चाहता था।
घिर गए। उस समय यह ज्ञात नहीं था कि अमेरिकी सीनेट ऐसा नहीं करेगी।

1999 में सीटीबीटी की पुष्टि की गई। परिणामस्वरूप, संधि को पीछे छोड़ दिया गया।
बर्नर। सीटीबीटी तब तक लागू नहीं हो सकता था जब तक कि इसकी पुष्टि न हो जाए।
उन चौवालीस विशिष्ट देशों के पास परमाणु शक्ति और अनुसंधान क्षमता थी।
रिएक्टर (और इसकी पुष्टि आईएईए द्वारा की जानी थी)। इनमें से आठ
कई देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया। इनमें से तीन देश - भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया - शामिल हैं।
कोरिया ने तो इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए थे। और जिन पांच देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, वे भी इससे असंबद्ध थे।
जिन देशों ने इसकी पुष्टि नहीं की, वे थे मिस्र, चीन, ईरान, इज़राइल और अमेरिका।
यह वहीं पर बना रहता है, हालांकि यह समय-समय पर सामने आता रहता है।
अंतर्राष्ट्रीय मंच।
वी

'यह 1994 की बात है जब पीवी ने पहली बार मेरे सामने (परीक्षण के बारे में) यह मामला उठाया था।'
नरेश चंद्र ने खुलासा किया, जो उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ सलाहकार थे।
समय बीतने के साथ-साथ चंद्र राव के परमाणु मामलों के मुख्य सलाहकार बन गए।
सवाल। राव को पता था कि चंद्र इस मामले में कितनी गहराई से शामिल था।
राजीव गांधी के कार्यकाल के अंत में परमाणु मुद्दा।
चंद्र ने बताया कि राव 1993 से ही इस विचार पर विचार कर रहे थे।
चंद्र और वैज्ञानिक प्रधानमंत्री कार्यालय में एकत्रित होंगे।
आरसीआर राव सबकी बात सुनते थे। फिर वे अपना फैसला टाल देते थे।
यह कहकर, 'बात करिन्गे फुर्सत से (हम फुर्सत में इस बारे में बात करेंगे)।'
उन्होंने परमाणु युद्ध के परिणामों के बारे में विस्तृत अध्ययन करवाया था।
परीक्षण—विशेष रूप से इसके आर्थिक और सुरक्षा संबंधी परिणाम। उन्हें बहुत कुछ मिला।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तत्वावधान में जारी की गई शब्दावली।

राजीव गांधी के विपरीत, जिनका अंदाज़ सीधा था, राव अधिक मुखर थे।
उनका दृष्टिकोण वृत्ताकार था। वे पूछते थे, 'क्या करना है (क्या करना है)'
किया गया)?' या, 'क्या तैयारी है (तैयारी क्या है)?'
अधिकारियों को उसके बारे में छिपी हुई बातों को समझने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
दिमाग।
एक दिन राव ने चंद्र से पूछा: 'क्या आप जानते हैं कि वे (पाकिस्तान) ऐसा कर सकते हैं?'
'आठ घंटे में पलटवार करोगे?' उनका मतलब उस समय से था जब पाकिस्तान
भारत द्वारा परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं? उन्होंने चंद्र से पूछा।
यह आकलन करने के लिए कि यदि पाकिस्तान पहले हमला करता है तो हमें (जवाब देने में) कितना समय लगेगा।
'मैंने पूरी प्रक्रिया से गुज़रा,' चंद्र ने याद करते हुए कहा। जैसे कि, कौन
परमाणु ऊर्जा आयोग के पास चाबी थी, इसमें कितना समय लगेगा
सरकारी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना, जिन्होंने यह आयोजन किया था
विखंडनीय पदार्थ, और डीआरडीओ जिसके पास वह उपकरण था। फिर वहाँ
सवाल था वारहेड को चार्ज करने का, उसे डिलीवरी सिस्टम से जोड़ने का।
सिस्टम को लोड करना और उसे चालू करना।
चंद्र राव के पास प्रतिक्रिया की जानकारी लेकर लौटा।
समय संभवतः लगभग छत्तीस घंटे था।
राव के प्रश्न से चंद्र को पता चला कि प्रधानमंत्री अब गंभीर स्थिति में हैं।
परीक्षण की संभावना पर विचार करते हुए। एईसी और डीआरडीओ, जो
प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करने वालों को तैयारी के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई थी।
राव
उन्होंने चंद्र को धनराशि का प्रबंधन करने के लिए कहा था।
परमाणु कार्यक्रम के लिए मुझे दो बार...बड़ी रकम मिली, जो
इसे खातों में नहीं दिखाया जा सका। राव ने उसे अपने वित्त विभाग के पास जाने को कहा था।

मंत्री मनमोहन सिंह। चंद्र के अनुसार, मनमोहन सिंह हर साल इस कार्यक्रम के लिए धन जारी करते थे, हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।
इसका कुछ हिस्सा रखा गया था।
सन् 1994 के मध्य में चंद्र ने राव को सुझाव दिया कि वायु सेना
उन्हें इस मामले में शामिल किया जाए और रक्षा सचिव को इसकी जानकारी दी जाए।
अत्यधिक सावधानी बरतते हुए राव ने चंद्र को मिलने की अनुमति दे दी।
रक्षा सचिव के. ए. नाम्बियार—लेकिन भारत में नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि वे
पेरिस में मुलाकात। नाम्बियार वैसे भी एक बैठक में शामिल होने के लिए पेरिस जा रहा था।
रक्षा मंत्रालय की एक टीम भी फ्रांस में जाने वाली थी।
राजधानी में एक हवाई शो में भाग लेने के लिए। नरेश-नांबियार की मुलाकात होगी।
राव का मानना था कि वे शायद ही किसी का ध्यान आकर्षित करेंगे। चंद्र, जिसे भी जाना था
अमेरिका के जो लोग वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में होने वाली बैठकों में भाग लेंगे, वे वहां से उड़ान भर सकते हैं।
वहां से पेरिस तक।
चंद्र ने याद करते हुए कहा, 'मैंने न्यूयॉर्क से पेरिस जाने के लिए कॉनकॉर्ड विमान लिया था।'
चंद्र और नाम्बियार ने आर्ट गैलरी में मिलने का फैसला किया।
लूव्र। जब नाम्बियार दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय में पहुंचे, तो उन्होंने
चंद्रा बेचैनी से इधर-उधर टहल रही थी। 'मैं लूव्र संग्रहालय में थी,'
इधर-उधर घूम रहा था, जाहिर तौर पर यह पता लगाने के लिए कि कौन सी पेंटिंग खरीदनी है।
'भारत सरकार, जिसे हम खरीद नहीं सकते थे,' चंद्र ने टिप्पणी की।
हंसते-हंसते चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं।
कोई केवल उन दो आदमियों की कल्पना कर सकता था, गंभीर, भावहीन चेहरे वाला, नीचा
प्रोफ़ाइल, दक्षिण भारतीय नाम्बियार, और लंबा और मोटा चंद्र खड़ा है
मोना लिसा के चित्र के सामने, उसकी रहस्यमयी मुस्कान की प्रशंसा करते हुए,

चंद्र ने रक्षा सचिव को नवीनतम घटनाक्रमों की जानकारी दी।
भारत के परमाणु कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की निगरानी की कल्पना करना असंभव था।
एजेंसी ने उनके होंठों की हरकत को जरूर पकड़ लिया होगा!
नरसिम्हा राव, जो मई 1994 में राष्ट्रपति से मिलने के लिए अमेरिका में थे।
बिल क्लिंटन ने जोर देकर कहा कि चंद्रा वापस न्यूयॉर्क लौटकर रिपोर्ट करे।
उसे तुरंत। अमेरिकियों ने बाद में कहा कि राव ने वादा किया था
क्लिंटन ने कहा था कि वह परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। लेकिन चतुर राव ने ऐसा नहीं किया।
अपने विकल्पों को खुला रखते हुए।
राव ने परीक्षण को लेकर गंभीरता से गंभीरता 1995 के मध्य में ही दिखाई।
एनपीटी के अनिश्चितकालीन विस्तार ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए राजी कर लिया।
एनपीटी को 11 मई 1995 को अनंत काल के लिए वैध घोषित कर दिया गया था।
भारत इस बात से भी नाराज था कि अमेरिका ने हैंक ब्राउन को पेश किया था।
संशोधन, जिसने अमेरिका को सैन्य बलों के एक बार के हस्तांतरण की अनुमति दी थी
पाकिस्तान को 368 मिलियन डॉलर मूल्य का हार्डवेयर दिया गया। इससे प्रेसलर कानून निरस्त हो गया।
जिसके तहत अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी थी और 1.4 अरब डॉलर के उन हथियारों को रोक दिया था जिनका भुगतान हो चुका था।
भारत ने इसका विरोध किया। लेकिन संदेश
अमेरिका से आ रही सूचना स्पष्ट थी कि समय तेजी से बीत रहा था।
भारत।
हालांकि अधिकारी बैठकें कर रहे थे, चाहे इसमें भागीदारी हो या न हो।
नरेश चंद्र के अनुसार, राव तब तक प्रधानमंत्री थे, और उनके पास 'बस
मैं टालमटोल कर रहा हूँ।
राव की चंद्रा और उनके साथ हुई पहली गंभीर बैठक में
वैज्ञानिक 1994 के अंत में हैदराबाद में थे। यह वही दिन था जब राव का भव्य समारोह हुआ था।

बेटी की शादी हो गई।
यह एक गुप्त बैठक थी, जो डीआरडीओ कार्यालय के एक सीलबंद कमरे में आयोजित की गई थी।
हैदराबाद के ठीक बाहर। यह घटना शादी समारोह के बाद घटी।
समाप्त हो गए थे। राव ने चंद्र को शादी में आमंत्रित किया था। वैज्ञानिक—ए.
पी. जे. अब्दुल कलाम और आर. चिदंबरम हैदराबाद गए थे।
जाहिर तौर पर 'काम' के लिए।
बैठक में उन्होंने तैयारियों की स्थिति पर चर्चा की।
परमाणु प्रतिष्ठान, और एक दुर्घटना के बाद परीक्षण करने में कितने दिन लगेंगे
निर्णय ले लिया गया। वैज्ञानिक चाहते थे कि समय-सारणी को आगे बढ़ाया जाए।
हमने पीवी को पिच और संभावित परिणामों के बारे में पूरी जानकारी दी थी।
चंद्र ने बताया।
राव ध्यान से सुन रहे थे। बीच-बीच में वे 'अच्छा' कहते थे।
अगर राव किसी बात पर सहमत भी हो जाते, तो भी सतर्क राव यही कहते, 'ठीक है, हम'
इस पर फैसला लेना होगा।' हालांकि यह एक घनिष्ठ समूह था, और
विचार-विमर्श गोपनीय था, 'वह बातों को इस तरह से रखता था कि कोई भी उसे समझ न पाए।'
बाद में यह आरोप लगाया जा सकता है कि वह विस्फोट को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा था।
कार्यक्रम।
चंद्र ने कहा, 'मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर से हैदराबाद वापस आया।'
और हमने और बातें कीं।
जब चंद्र ने उनसे अंतिम आदेश के समय के बारे में सवाल किया,
Rao said, ‘Haan vaapis chal kar baat karenge (We will talk when we
दिल्ली वापस लौटना)।' लेकिन उस दिन राव ने टीम को अनुमति दे दी थी।
‘तैयार हो जाओ’—हालांकि अभी भी परीक्षण का अंतिम आदेश नहीं आया है। राव ने पूछा।

चंद्र ने इस विषय पर एक शोधपत्र तैयार किया। चंद्र ने कहा, 'मैंने यह शोधपत्र लिखा है।'
फिर भी, चंद्र और वैज्ञानिकों ने इस बैठक को एक प्रगति के रूप में देखा।
फिलहाल उन्हें केवल अंतिम मंजूरी का इंतजार करना था।
1995 के उत्तरार्ध में, तीन वैज्ञानिकों में से एक - कलाम,
चिदंबरम और संथानम अहमदाबाद चले गए। तब तक चंद्र
उन्हें 1 जुलाई, 1995 को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 'हम राजभवन में नहीं बल्कि अहमदाबाद के पास स्थित प्लाज्मा सेंटर में मिले थे, ताकि...'
किसी भी तरह के संदेह को आमंत्रित करने के लिए।
लगभग इसी समय राव ने एक लिखित आदेश पारित किया—और यह
'यह वह क्षण था जब वह अपनी सावधानी छोड़ने के सबसे करीब आया था'—एक समूह स्थापित करने के लिए
नरेश चंद्र को अध्यक्ष बनाकर परमाणु ऊर्जा पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया है।
कार्यक्रम।
मुझे याद है कि उसमें "रणनीतिक हथियार" जैसे शब्द शामिल थे।
नरेश चंद्र ने याद करते हुए कहा, 'आदेश में इरादा स्पष्ट था।'
'उसकी केवल एक ही प्रति थी और वह कलाम के पास थी। उन्होंने उसे दिखाया।
मैंने उसे यह मुझे दे दिया। मैंने उससे कहा कि इसे तिजोरी में रख दे। यह आदेश हमारी सुरक्षा के लिए था।'
■

दिसंबर 1995 में, पी.वी. नरसिम्हा राव ने ए.पी.जे. अब्दुल को अधिकृत किया।
कलाम ने आगे बढ़ने की अनुमति दी और समयसीमा को टी-3 तक कम करने की अनुमति दी।
इसका मतलब था कि वह तीन दिनों में परीक्षा दे सकता था।
दिसंबर 1995 तक, उन्होंने (राव ने) ऑक्सीजन लगाने का मन बना लिया था।
के. संथनम ने कहा, 'विकल्प में। टी-3 दिसंबर में था, लेकिन...'

(अंतिम) समय निर्धारण का अधिकार सरकार के पास था...।
‘कलाम ने ही मुझे अहमदाबाद में फोन करके बताया था कि पीवी ने
नरेश चंद्र ने खुलासा किया, 'टी-3 का ऑर्डर मिलने पर, जब आप टी-3 पर पहुंचते हैं,'
‘तुम भी ऐसा कर लो,’ चंद्र ने कहा। ‘मैंने कलाम, संथानम से कहा था,
और चिदंबरम, आप टी-3 को छिपा नहीं सकते। इसे गुप्त नहीं रखा जा सकता।
उसके बहुत समय बाद।
'राव परीक्षण के सबसे करीब तभी पहुंचे थे।'
लेकिन, दिसंबर 1995 के मध्य में अमेरिकी उपग्रहों ने यह पता लगाया कि...
पोखरण (राजस्थान) में परमाणु परीक्षण स्थल पर गतिविधि।
भारत में अमेरिकी राजदूत फ्रैंक विस्नर अभी-अभी दिल्ली लौटे थे।
वॉशिंगटन डीसी में अपने घर लौटने के बाद—और वह पूरी तैयारी के साथ आया था
पोखरण में चल रही तैयारियों की तस्वीरें। केबल बिछाने का काम चल रहा था।
तलवारबाजी की आड़ में यह सब चल रहा था। भारत का मानना था कि जो कुछ भी हो रहा था वह तलवारबाजी के नाम पर हो रहा था।
चल रहा कार्य नियमित रखरखाव का कार्य था।
चंद्र ने याद करते हुए कहा, 'विस्नर सबसे पहले मेरे पास आए थे।' उन्होंने चंद्र को दिखाया कि...
पोखरण में संदिग्ध गतिविधियों को दर्शाने वाली तस्वीरें। 'मैंने
bhaga diya (I shooed him off),’ he said airily.
लेकिन, परमाणु प्रतिष्ठान के करीबी सूत्रों के अनुसार,
चंद्र, जिन्हें राजस्थान में अपने एसडीएम (उप-विभागीय मजिस्ट्रेट) के दिनों से ही दस्तावेजों को पढ़ने और उन्हें याद करने का प्रशिक्षण दिया गया था,
विस्नर द्वारा ली गई तस्वीरों के विवरण को पहचानने के लिए वह काफी तेज था।
उसे दिखाया।
तस्वीरों के किनारों पर घटना की तारीख और समय अंकित था।
पोखरण के ऊपर से गुजरते समय उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरें। उपग्रह से ली गई तस्वीरों के दो सेट।
यह अमेरिकी उपग्रह द्वारा पोखरण लौटने में लगे समय को दर्शाता है।

यह जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाई गई। वैज्ञानिकों ने अपना काम किया।
गणनाएँ। यह पृथ्वी की गति और हलचल पर आधारित थी।
उपग्रह का। उन्होंने उपग्रह को आवश्यक समय का पता लगाया।
अगले दौर के लिए वापस आने के लिए। उन्होंने यह पता लगाया कि यही वह दौर होगा।
उन्हें ज़मीनी स्तर पर काम पूरा करने के लिए समय चाहिए होगा।
‘नरेश चंद्र ने मेरे पिता (जसवंत सिंह) को कहानियां सुनाई थीं...
'उन्होंने अमेरिकियों को कैसे हराया था,' मानवेंद्र सिंह ने याद करते हुए कहा।
लेकिन उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से उनके बारे में बात नहीं की।
चंद्र से मिलने के बाद, विस्नर प्रणब मुखर्जी से मिलने गए, जो
उस समय विदेश मंत्री थे। मुखर्जी को यह बात पता नहीं थी।
(कुछ भी)। इसके तुरंत बाद, जब पत्रकारों ने मुखर्जी से इस बारे में सवाल किया
उन्होंने उनसे कहा, 'हमारे पास (परीक्षण करने की) ऐसी कोई योजना नहीं है।'
इसके बाद विस्नर राव के प्रधान सचिव ए. एन. वर्मा के पास गए।
जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो वे भड़क उठे। नरेश चंद्र के अनुसार,
वर्मा को इस मामले की जानकारी नहीं थी।
जब विस्नर को कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने क्लिंटन से राव को फोन करने की व्यवस्था की।
सरकार के इस आश्वासन को 'पक्का' बना दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा
परीक्षण।
मुझे अहमदाबाद से अचानक (दिल्ली) बुलाया गया था।
चंद्र ने याद करते हुए कहा, 'मैं तुरंत आया और सीधे दक्षिण की ओर चला गया।'
अवरोध पैदा करना।'
प्रधानमंत्री कार्यालय में दीपक भोजवानी के अलावा कोई मौजूद नहीं था।
मंत्री के निजी सचिव, जिन्हें मामले की पूरी जानकारी थी।
चंद्र ने भोजवानी से पूछा, 'संक्षिप्त जानकारी क्या है?'
‘आपको ही निर्देश दिया गया है,’ उसने जवाब दिया।
उन्होंने चंद्र से राव के भाषण की तैयारी करने को कहा। ‘प्रधानमंत्री को एक भाषण दीजिए।

यह बयान और इसके बाद आने वाले प्रश्न और उत्तर (अमेरिका से)
अध्यक्ष)।'
'हमने उच्च सुरक्षा मंजूरी प्राप्त एक सहायक कर्मचारी को नियुक्त किया और प्रयास किया...'
राव को क्लिंटन से क्या कहना चाहिए, इस पर एक रूपरेखा तैयार की गई है।
दूसरी ओर, बिल क्लिंटन, जो गैर-राजनीतिक व्यवस्था में दृढ़ विश्वास रखते थे,
प्रसार पर भी उनका संक्षिप्त व्याख्यान था। उन्होंने भी तैयार पाठ पढ़ा।
अमेरिकी प्रणाली इसी तरह काम करती थी।
क्लिंटन ने 'श्रीमान प्रधानमंत्री...' से शुरुआत की और पढ़ना शुरू किया, 'हम हैं'
आपके विदेश मंत्री के इस बयान के लिए आभारी हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
परीक्षण।
राव ने क्लिंटन से कहा, 'मैंने इस संबंध में प्रेस रिपोर्ट भी देखी हैं।'
मुझे इसके बारे में जल्द ही स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी।
जबकि राव मुखर्जी के इस बयान से सहमत थे कि कोई परीक्षण नहीं किया जाएगा
निहाई के बारे में वह यह भी कह रहा था कि कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता है—
और इस प्रकार अपने विकल्पों को खुला रखता है।
इसके बाद क्लिंटन ने राव से सीधे तौर पर पूछा कि क्या भारत परीक्षण करने जा रहा है।
राव ने कहा, 'नहीं, नहीं। बातों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी।'
मौजूदा सुविधाओं का रखरखाव। मैं जल्द ही एक बयान जारी करूंगा।' उन्होंने यह भी कहा।
उन्होंने 'जिम्मेदारी से' काम करने की बात की, जिसका यहाँ कोई महत्व नहीं था।
क्लिंटन भारत के रुख की लगातार प्रशंसा करते रहे और कहते रहे कि...
भारत की परमाणु अप्रसार और संचार नियंत्रण नीति (सीटीबीटी) को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझा।
राव बातचीत से बहुत खुश थे।
'Galti ho gayi, Gujarat bhej diya (I made a mistake, I sent you to

Gujarat),' he said to Chandra, 'Washington jana thaa. Jayenge na (I
तुम्हें वाशिंगटन भेज देना चाहिए था। तुम जाओगे ना?
नरेश चंद्र ने कई साल बाद कहा, 'मैं अक्सर यह सोचता था।'
'क्या मुझे गुजरात के राज्यपाल के रूप में एक आवरण के तौर पर भेजा गया था', ताकि
परीक्षण की संभावना से ध्यान हटाने के लिए।
राव ने नरेश चंद्र को वाशिंगटन डीसी में भारत के राजदूत के रूप में भेजा।
1996 में। यह घोषणा उसी वर्ष जनवरी में की गई थी। चंद्र
जब राव से दूसरी बातचीत हुई, तब मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था।
मार्च 1996 में क्लिंटन के साथ हुई मुलाकात।
राव की क्लिंटन के साथ पहली बातचीत से पता चला था कि उनका परमाणु
विकल्प खुले थे। दूसरी कॉल इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि उसने हार मान ली थी।
इस पर।
चंद्र ने कहा, 'दूसरी बातचीत बेतरतीब थी, वह सार्थक नहीं थी।'
अच्छा... प्रधानमंत्री का संतुलन बिगड़ गया था।
क्लिंटन ने सीटीबीटी के बारे में बात की। उन्होंने परमाणु अप्रसार के बारे में बात की।
शासन व्यवस्था का काम न करना, शासन व्यवस्था पर दबाव, और इसके परिणाम।
चीन द्वारा परीक्षण...
'हमने एक अलग ब्रीफ तैयार किया था। बातचीत इस तरह आगे बढ़ी।
उत्तरोत्तर कठिन।
अंत में पी.वी. कह रहे थे, "नहीं, सर। मैं समझ गया, सर।"
चंद्र ने कहा, 'या तो गुस्से में 'सर' कहो, या फिर किसी वरिष्ठ व्यक्ति को।'
या फिर आप इसे व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहते हैं।
■

पी.वी. नरसिम्हा राव क्यों पीछे हट गए? यह सवाल कई लोगों को परेशान कर रहा है।
वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और रणनीतिक समुदाय के लिए एक चौथाई से अधिक

समय से।
शतक।
जैसा कि हमने पुस्तक में पहले देखा, राव को बहस करने की आदत थी।
वह मन ही मन किसी मुद्दे पर बहस करता और दोनों पक्षों के विचार देखता।
देखने का दायरा इतना कम हो गया कि कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई। फिर वह इस मुद्दे पर और विचार करने का निर्णय लिया गया—और एक बार फिर निर्णय को टाल दिया गया।
हालांकि, जब राव कोई काम करवाना चाहते थे, तो वे बहुत सख्त हो सकते थे।
निर्णयक।
स्पष्ट रूप से, दिसंबर 1995 में, राव ने यह निष्कर्ष निकाला कि संतुलन
परीक्षणों को स्थगित करने में ही लाभ था। एक बार जब उन्होंने यह निर्णय ले लिया, तो
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अमेरिकियों द्वारा पकड़ा गया था या नहीं।
उसने खुद को पकड़े जाने दिया।
कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय राजनीति के चाणक्य ने एक
जानबूझकर पकड़े जाने का निर्णय। वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम था।
यह अमेरिकियों के लिए उसे फंसाने का मंच होगा। फिर उसे न होने का बहाना मिल जाएगा।
परीक्षण करना और वैज्ञानिकों और उनके लिए एक वैध स्पष्टीकरण होना चाहिए।
रणनीतिक समुदाय—वह पूरी तरह से उत्साहित था और आगे बढ़ने के लिए बेताब था।
दिलचस्प बात यह है कि इन परीक्षणों की योजना दिसंबर महीने में बनाई जा रही थी।
जब राजस्थान के रेगिस्तान में मौसम बहुत साफ होता है, तो वृद्धि होती है
पकड़े जाने की संभावना। राव, जिसने कभी भी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले।
अपने सहायकों या करीबी सहयोगियों के साथ और जरूरत पड़ने पर जानकारी साझा की।
जानकारी के आधार पर, आश्चर्यजनक रूप से इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे।
परीक्षण करने का निर्णय। सामान्यतः अत्यधिक सतर्क रहने वाले राव ने भी आदेश दिया था।

कई अध्ययन किए जाने बाकी हैं, जिससे जानकारी लीक होने की संभावना बढ़ जाती है।
और ऐसा ही हुआ। टी-3 चरण में, वैसे भी स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल था।
गुप्त रूप से। जैसा कि हम आगे देखेंगे, जब वाजपेयी को 1998 में परीक्षण करना था, तब ऐसा हुआ था।
वास्तव में केवल ब्रजेश मिश्रा और वैज्ञानिक ही तारीख जानते थे।
समय। अन्य लोग डी-डे और एच-ऑवर से कुछ ही घंटे पहले जहाज पर सवार हुए।
1995 में, राव अंतरराष्ट्रीय मोर्चे के साथ-साथ अन्य मोर्चों पर भी कमजोर स्थिति में थे।
अपनी ही पार्टी के भीतर। वह जानता था कि अमेरिका कानूनी रूप से अनिवार्य प्रतिबंध लगाएगा।
भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूरोपीय राजधानियां भी ऐसा ही करेंगी।
आर्थिक रूप से,
भारत एक संकट से उबर रहा था, लेकिन स्थिति अभी भी 'नाजुक' थी।
वित्त सचिव मोंटेक सिंह अहलूवालिया को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था।
आर्थिक प्रभावों पर वित्तीय दस्तावेज। अहलूवालिया ने चेतावनी दी कि
अर्थव्यवस्था अभी तक संकट से उबर नहीं पाई थी और इसका प्रभाव पड़ सकता था।
काफी महत्वपूर्ण। वह परीक्षण को लेकर 'निराशावादी' थे।
अर्थव्यवस्था में सुधार होने के बावजूद, राव को इस बात की चिंता थी कि आगे क्या होगा।
यदि अमेरिका भारत पर तेल प्रतिबंध लगाता है तो क्या होगा?
खाड़ी के तेल उत्पादक देशों पर भी ऐसा ही करने का दबाव पड़ेगा। इससे
खाद्य पदार्थों, उर्वरकों, दवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, बस
अप्रैल-मई 1996 में होने वाले चुनावों से महीनों पहले। वह ऐसा कर सकता था।
साथ ही इस बात को लेकर भी चिंता थी कि भारत द्वारा किए गए परीक्षण पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया होगी।
हालाँकि पंजाब में स्थिति में सुधार हुआ था, कश्मीर में अभी भी हालात वैसे ही थे।
अस्थिर। और चीन एक अनिश्चित कारक बना रहा। राव शायद ऐसा कर सकते थे।

उसने अनुमान लगाया कि उसे अठारह से चौबीस घंटे का अग्रिम समय चाहिए होगा।
चुनाव से महीनों पहले इसके नतीजों को नियंत्रित करने के लिए। दिसंबर 1995 में, उन्होंने
केवल पांच महीने।
इसके अलावा, राव को वास्तव में इस बात का यकीन नहीं था कि उनकी अपनी पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी।
जवाब दें। सोनिया गांधी उनके खिलाफ हो रही थीं; उन्होंने पहली बार ऐसा किया था।
उन्होंने राजीव गांधी की हत्या को हल्के में लेने के लिए सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की।
जांच शुरू हो गई है। अर्जुन सिंह जैसे कांग्रेस के बागी नेताओं ने पहले ही एक अलग दल बना लिया था।
पार्टी, कांग्रेस (तिवारी), जो हमलावर मुद्रा में थी। अगर स्थिति ऐसी होती
प्रतिबंधों के बाद स्थिति कठिन हो सकती है, जो कि उनकी पार्टी के लिए संभव है।
हमेशा उसे हटाकर किसी और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को चुन लें। वैसे भी, वह
वह न तो करिश्माई व्यक्तित्व थे और न ही जन नेता।
उन्हें पता था कि भाजपा परीक्षण का समर्थन करेगी। लेकिन वह भी नहीं चाहेगी कि परीक्षण हो।
उसे उस मुद्दे पर श्रेय लेने देना जिसे वह अपना मानती थी।
राव द्वारा प्रतिबंधों और आर्थिक व्यवस्था को संभालने के तरीके की आलोचना की गई होती।
इससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा।
अंत में, राव इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हुए कि परीक्षण
इससे वह भारत की वांछित सशक्त नेता बन जाएगा। या फिर यह एक
उनकी परेशानियों का रामबाण इलाज। इंदिरा गांधी ने 1974 में इसका परीक्षण किया था जब उन्होंने भी ऐसा ही किया था।
संकट में घिर गया था। कुछ ही हफ्तों में, हासिल की गई उपलब्धियां खत्म हो गईं। परमाणु
उसे संदेह था कि विस्फोट से उसे कुछ अस्थायी लाभ मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।

इससे राष्ट्रीय उत्साह पैदा होने और उन्हें चुनाव जीतने में मदद मिलने की संभावना नहीं थी।
चंद्र ने कहा, '(ए. एन.) वर्मा ने पी.वी. के डर का फायदा उठाया, वह एक
चतुर राजनीतिज्ञ थे और लगातार उस हार की बात करते रहे जिसका सामना राव को करना पड़ सकता था।
1996 में होने वाले आगामी चुनाव)।
जाहिर तौर पर, वर्मा ने राव से कहा कि अगर वह टेस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो 'तो America peeche parh jayega (America will get after you)'. And that 'the
तब अमेरिकी लोग भाजपा का समर्थन करेंगे।
जैसे ही वर्ष 1995 समाप्त हो रहा था, राव के सामने दो विकल्प थे: एक
परमाणु विस्फोट और हवाला प्रणाली अपनाने से यह मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है।
1996 के मध्य में भ्रष्टाचार उनका मुख्य चुनावी मुद्दा था।
वर्मा ने राव को हवाला घोटाले की ओर इशारा किया।
इस कथित मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं समेत कई राजनेता शामिल थे।
चार हवाला दलालों के माध्यम से काले धन का भुगतान। 1991 में, एक कश्मीरी
उग्रवादी की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी की गई और विदेशी मुद्रा बरामद हुई।
और डायरियों में प्रमुख व्यक्तियों को किए गए भुगतानों का विवरण था।
जिन राजनेताओं की पहचान उनके नाम के शुरुआती अक्षरों से की गई थी। अदालत ने
हवाला जांच की निगरानी करना।
वर्मा ने तर्क दिया कि राव की छवि में सुधार होगा—और उन्होंने
उन्हें भारतीय राजनीति को साफ करने वाले नेता के रूप में देखा जाएगा।
उनकी टीम, सीबीआई प्रमुख विजय रामाराव ने 'हवाला नीति' को आगे बढ़ाया; उन्होंने
नरेश चंद्र के अनुसार, वह ए. एन. वर्मा का विश्वासपात्र व्यक्ति था।
उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी ने इसके बजाय परमाणु परीक्षण का समर्थन किया।
नरेश चंद्र ने भी ऐसा ही किया।
हवाला का रास्ता चुनकर राव ने एक बड़ी गलती की।

उनके प्रधानमंत्रित्व काल में हुए घोटालों की तरह— हर्षद मेहता
स्टॉक घोटाला, चीनी घोटाला, उर्वरक और पर्यावरण घोटाले—उनके
मंच बिल्कुल भी साफ-सुथरा नहीं था। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की संभावना बहुत कम थी।
लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना।
नरेश चंद्र ने कहा, 'हवाला उनके जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता थी।'
मैं उसे ज्यादातर लोगों से ज्यादा जानता था।
■

नरेश ने कहा, 'परीक्षण के लिए सबसे अच्छा समय 1994-95 था।'
Chandra concluded. 'Par mauke par kuchh nahin kiya (He lost a golden
अवसर)।'
1994 और 1995 की शुरुआत में, अमेरिका, चीन और फ्रांस ने भी ऐसा किया था। परीक्षण किए गए। संथनम ने कहा, '(क्योंकि) यह एक तरह का सामान्य चलन बन रहा था।...अगर हर कोई पटाखे फोड़ रहा होता, तो यह स्थिति और बिगड़ जाती।
पृष्ठ सात पर मत जाओ, पृष्ठ एक पर ज्यादा देर तक मत रहो। इसके अलावा,
अगर हमने परीक्षण किया होता तो हम किसी संधि का उल्लंघन नहीं करते। हमने परीक्षण नहीं किया था।
हमने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, हम सीटीबीटी (जो कि विचाराधीन था) के विरोधी थे।
और जमीनी स्तर पर परीक्षण करना अनुमेय था।'
कई वर्षों बाद जब नरेश चंद्र भारत के प्रतिनिधि के रूप में वाशिंगटन में थे
राजदूत होने के नाते, अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान के लोग उनसे पूछते थे, 'क्यों?'
क्या आपने ऐसा तब नहीं किया था जब फ्रांस और चीन ने 1994 में ऐसा किया था?
तब हम अपेक्षाकृत सुरक्षित बच जाते।
राव को उम्मीद थी कि वह सत्ता में वापस आएंगे और सक्षम होंगे।
परीक्षण करने के लिए। उन्हें उम्मीद थी कि 1996 में उन्हें पर्याप्त सीटें मिल जाएंगी

जिससे वे किसी तरह एक टीम बना सकें।
गठबंधन सरकार। वह सदन में पूर्ण बहुमत नहीं चाहते थे।
जिसे वह अपने लिए एक जोखिम भरा प्रस्ताव मानता था। क्योंकि तब, वह
सोनिया गांधी को पार्टी प्रमुख के रूप में स्थापित करने के दबाव का सामना करने में सक्षम नहीं होना
नेता। 1995 में, वह सक्रिय भूमिका के लिए तैयार होने के संकेत दे रही थीं।
राजनीतिक भूमिका। राव के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की संभावना कहीं अधिक थी।
ऐसा तभी संभव है जब कांग्रेस अल्पमत में हो और गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर सके।
सरकार।
विदेश मंत्री रह चुके होने के नाते, वे भारत की स्थिति से भली-भांति परिचित थे।
परीक्षण करने की बाध्यता। यह सीटीबीटी को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकता था और
वैश्विक समुदाय में बहिष्कृत हो जाना। वह राजनीतिक दांव-पेच जानता था।
परमाणु प्रतिरोधक क्षमता रखने का महत्व।
दिलचस्प बात यह है कि हालांकि राव ने दिसंबर 1995 में पद छोड़ने से इनकार कर दिया था, फिर भी
वह लगातार यही आभास देता रहा कि उसने अपने विकल्प खुले रखे हैं।
हालांकि पता चलने के तुरंत बाद ही जांच कराने के लिए जाना पड़ा।
अमेरिकियों के लिए, और इस कारण से निर्णय को स्थगित करना, गलत होता।
कठिन था। लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय को यह संकेत देना जारी रखा कि उनके पास यह था।
1996 के पहले चार महीनों के दौरान इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया था।
उन्होंने उनसे सब कुछ तैयार रखने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि
कलाम को चुनाव परिणामों से दो दिन पहले तैयारी करनी थी। एक बार जब वह
जब उन्हें एहसास हुआ कि वे चुनाव हार गए हैं, तो उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया।
नरेश चंद्र ने वर्षों पहले कहा था, 'पीवी अपनी नियति से मिलने से चूक गए।'

बाद में, राव की हार अटल बिहारी वाजपेयी के लिए लाभ साबित हुई।
छठी

हम अगला चुनाव अटल बिहारी के नेतृत्व में लड़ेंगे...
'वाजपेयी,' एल. के. आडवाणी गरजते हुए बोले। उन्होंने ये शब्द बीच में ही कहे।
नवंबर 1995 में मुंबई में दिए गए एक भाषण से—1996 के आम चुनाव से छह महीने पहले। 'और वे हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे।'
श्रोतागण सन्नाटे में छा गए। क्योंकि यह आडवाणी ही थे जो...
भाजपा के उभरते सितारे के रूप में देखे जाने वाले और पार्टी के उम्मीदवार बनने की उम्मीद रखने वाले इस नेता को पार्टी का उम्मीदवार माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री पद।
आडवाणी ने अपने बोलने से पहले किसी तरह की चेतावनी नहीं दी थी।
वे 'महादिवेषण' (बड़े आयोजन) के दूसरे दिन बोल रहे थे।
मुंबई में 11 से 13 नवंबर 1995 तक आयोजित बैठक में एक सौ लोगों ने भाग लिया।
इस सभा में एक हजार प्रतिनिधि उपस्थित थे।
वाजपेयी के 12 मई 1995 को भाषण समाप्त करने के बाद ही यह घटना घटी।
भाजपा अध्यक्ष के रूप में आडवाणी ने दिन का अंतिम भाषण देने के लिए पदभार संभाला।
कई वर्षों से, न केवल हमारे पार्टी कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी
'अगली बारी अटल बिहारी' का नारा लगा रहे हैं।' यहां हैं आडवाणी
वह रुके। उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा अगली सरकार बनाएगी।'
अटलजी के प्रधानमंत्रित्व काल में सरकार। एक क्षणिक
सन्नाटा छा गया। और फिर दर्शक जोरदार तालियों से गूंज उठे।
मुस्कुराते हुए आडवाणी अपनी कुर्सी पर वापस जाने के लिए मुड़े। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते,
वाजपेयी अपनी सीट पर बैठ गए, उठे और माइक ले लिया। उन्होंने कहा, 'भाजपा चुनाव जीतेगी।'
उन्होंने घोषणा की, 'चुनाव होगा, और हम सरकार बनाएंगे, और आडवाणी जी'

प्रधानमंत्री बनेंगे।
‘Ghoshna ho chuki hai (I have already made the announcement),’
Advani interjected going back to the mike. ‘Toh main bhi ghoshna karta
'मैं भी घोषणा कर रहा हूँ', वाजपेयी ने कहा, 'कि
प्रधान मंत्री (कि प्रधानमंत्री...)
आडवाणी माइक पर वापस आ गए और उन्होंने उनके लिए वाक्य पूरा किया।
‘Atalji hi banaenge (Atalji will be prime minister).’
और तालियाँ बजने लगीं।
वाजपेयी ने आडवाणी की ओर मुड़कर पूछा, 'आपने क्या घोषणा की? कुम से कुम।'
मुझे से तो बात करते (You should have at least talked to me).’
Advani retorted, ‘Kya aap maante agar humne aap se poocha hota
(अगर मैंने आपसे पूछा होता तो क्या आप सहमत होते?)’ सौहार्दपूर्ण द्वंद्वयुद्ध
उन्होंने कुछ ऐसा छिपा रखा था जो कहीं अधिक तीखा था। आडवाणी और वाजपेयी के पास
पार्टी के नेतृत्व के लिए एक अप्रत्यक्ष संघर्ष चल रहा है।
उस शाम, अचंभित गोविंदाचार्य आडवाणी के घर की ओर दौड़े।
होटल के कमरे में। 'तुमने ऐसी घोषणा कैसे कर दी?' उसने अपने
गुरु ने उत्तेजित होकर कहा।
‘Maine kiya jo mujhe theek laga,’ Advani replied matter-of-factly. (I
मैंने वही किया जो मुझे सही लगा।
‘अगर मैंने (दूसरों से) सलाह ली होती, तो ऐसा नहीं होता,’ एल. के.
जब मैंने आडवाणी से उनकी इस अप्रत्याशित घोषणा के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझसे यह कहा।
यह उस नेता के स्वभाव के विपरीत था जिसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जो

एक संगठित संगठन और व्यापक विचार-विमर्श के बाद निर्णय लेने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति।
पार्टी के सहयोगियों के साथ परामर्श।
आडवाणी की घोषणा का समय विचित्र था। क्योंकि यह उनकी पहली घोषणा थी।
राजनीतिक सितारा, और वाजपेयी का नहीं, जो कि उसके बाद से बढ़ रहा था।
उन्होंने 1990 में रथ यात्रा का नेतृत्व किया था। आडवाणी के नेतृत्व में ही यह संभव हो पाया था।
इससे पार्टी को 1991 में लोकसभा की अप्रत्याशित रूप से 120 सीटें मिलीं।
चुनाव। इसने उनके और 'अटलजी' के बीच सत्ता के संतुलन को बदल दिया था।
तब तक वाजपेयी को भाजपा के शीर्ष नेता के रूप में देखा जाता था, और आडवाणी को...
नंबर दो।
कई लोगों को संदेह था कि 1995 में आडवाणी ने एक गुण को ही अपना गुण बना लिया था।
आवश्यकता। उन्होंने वाजपेयी को पार्टी का प्रमुख नेता घोषित किया होगा।
मंत्री पद के उम्मीदवार को यह खबर मिलने पर कि पी.वी. नरसिम्हा राव
हवाला मामले में आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने जा रहे हैं
राजनेताओं, जिनमें वह स्वयं भी शामिल थे—जिसके कारण उन्हें बाहर निकाला जा सकता था।
प्रधानमंत्री पद की दौड़।
जनवरी 1996 में, उनकी उस महत्वपूर्ण घोषणा के दो महीने बाद,
मुंबई में, आडवाणी के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया।
एक सांसद—और उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें बरी नहीं किया जाता तब तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगे।
उन्होंने 1996 के चुनाव नहीं लड़े और 1998 में ही संसद में वापसी की।
उनका नाम साफ हो गया—सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
आडवाणी और अन्य वरिष्ठ राजनेताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए थे।
आडवाणी का मानना था कि तेज गति से गाड़ी चलाने में नरसिम्हा राव की भूमिका

थी।
वाजपेयी की मदद करने के लिए उनके और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र को बढ़ा दिया गया।
वाजपेयी के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुल गया था।
1996 के आम चुनाव में उम्मीदवार।
'पिव ने हवाला मामले को आगे बढ़ाकर वाजपेयी की मदद की,' भुवनेश
चतुर्वेदी ने मुझसे यह बात स्वीकार की।
यह मामला सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में चलाया जा रहा था।
अदालत में गए, लेकिन पीवी जानते थे कि इससे (वाजपेयी को) मदद मिलेगी।'
चतुर्वेदी ने आगे कहा:
'Advani asked me at a function, "Aapne mujhe kisi ke kehne par
क्या आपने किसी के कहने पर मुझ पर मुकदमा चलाया था? (क्या आपने किसी के कहने पर मुझ पर मुकदमा चलाया था?)
"अन्य)?" उनका इशारा वाजपेयी की ओर था, हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया।
'Kisi ke kehne par nahin (No, we did not act at the instance of
किसी और के निर्देश पर (हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत काम कर रहे थे)।'
चतुर्वेदी ने आडवाणी से कहा, 'वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था।'
आडवाणी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने राव से भी यही सवाल पूछा, जब वे
एक अन्य समारोह में उनसे मुलाकात हुई। 'पीवी ने इससे साफ इनकार कर दिया।'
यह इतिहास की उन अटकलों में से एक है कि अगर हवाला जांच हुई होती तो क्या होता।
अगर 1995 के अंत तक प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई गई होती, तो क्या आडवाणी ने ऐसा किया होता?
क्या वाजपेयी ने 1996 के चुनाव के लिए भाजपा के चेहरे के रूप में घोषणा की थी?
■

1996 में, यह 'अबकी बारी अटल बिहारी' था और उनका करिश्मा लोगों के दिलों में गूंज उठा।
मतदाताओं को। भाजपा के शीर्ष दो नेताओं के भाग्य में आए अप्रत्याशित बदलाव ने सुनिश्चित किया।
वाजपेयी ने 1996 के चुनाव में पार्टी के अभियान का नेतृत्व किया था। अन्य लोगों के विपरीत
एक ही दिन में एक दर्जन से अधिक रैलियों में भाग लेने वाले राजनेता-
वाजपेयी चार से पांच से अधिक सभाओं को संबोधित नहीं करते थे।
दिन की शुरुआत आराम से होगी और चुनाव प्रचार जल्द ही समाप्त हो जाएगा।
सूर्यास्त के बाद। उन्हें शाम को ड्रिंक के साथ आराम करना पसंद था। वह और
आडवाणी इस बात से सहमत थे कि हिंदुत्व चुनाव के मुद्दों में से केवल एक मुद्दा होगा।
16 मई 1996 को, इकहत्तर वर्षीय वाजपेयी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
भारत के दसवें प्रधानमंत्री। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।
लोकसभा में पार्टी ने 161 सीटें जीतकर 41 सीटें और हासिल कीं।
1991 की तुलना में। इसके तीन सहयोगी दल, शिवसेना, हरियाणा विकास पार्टी और
समता पार्टी को कुल 26 सीटें मिलीं, जिससे गठबंधन की कुल सीटों की संख्या बढ़ गई।
187 तक। हालांकि, यह अभी भी 273 सीटों की आवश्यकता से काफी कम था।
लोकसभा में बहुमत होना आवश्यक था।
यह स्पष्ट नहीं था कि सरकार बनाने के लिए पार्टी का समर्थन कौन करेगा।
और न ही वाजपेयी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था।
लेकिन एक ऐसे कदम में जिसने कई लोगों को चौंका दिया, राष्ट्रपति शंकर दयाल
शर्मा ने उन्हें नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वे देश के नेता थे।
सबसे बड़ी पार्टी—लेकिन यह बताए बिना कि वह अपनी बात कैसे साबित करेगा
सदन में बहुमत।
'वाजपेयी खुद इस बात से हैरान थे कि उन्हें बुलाया गया था,' यह खुलासा हुआ।
भुवनेश चतुर्वेदी, जो वाजपेयी के मित्र थे और जिनसे उन्होंने बात की थी

उन्हें। कुछ लोगों को संदेह था कि वाजपेयी को संसद सदस्य बनाने के लिए दिया गया निमंत्रण उनके लिए था।
सरकार राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई खिचड़ी थी।
पीएम राव के साथ।
कुछ घंटों तक, अनिश्चित वाजपेयी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए या नहीं।
चतुर्वेदी ने कहा कि राष्ट्रपति का निमंत्रण उनके लिए स्वीकार्य नहीं था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उन्हें अन्य पार्टियों या सरकार का समर्थन मिल पाएगा।
स्वतंत्र उम्मीदवार।
उनके पास सतर्क रहने का कारण था; बाबरी मस्जिद का विध्वंस...
1992 के घटनाक्रम ने कई पार्टियों को भाजपा से सावधान कर दिया था—वे इसे एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते थे।
राजनीतिक रूप से अछूत। राष्ट्रपति ने वाजपेयी को दो सप्ताह का समय दिया था।
अपना बहुमत साबित करें। तुरंत ही, उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, भैरों को आगे किया।
सिंह शेखावत, प्रमोद महाजन और जसवन्त सिंह, काम करने के लिए। वे
क्षेत्रीय संगठनों से संपर्क किया गया।
■

वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के दो दिन बाद, नरसिम्हा राव
उन्होंने उन्हें फोन किया। वे नए प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे। परंपरा के अनुसार, निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने उत्तराधिकारी से मुलाकात की। लेकिन वाजपेयी ने उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे राव से मिलने जाएंगे। यह एक सम्मान के तौर पर था।
दशकों पुरानी दोस्ती। वाजपेयी आरसीआर गए। राव
प्रधानमंत्री आवास से अभी तक बाहर नहीं निकले थे। बैठक 18 तारीख को हुई थी।
मई 1996—और इसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। राव ने संक्षिप्त जानकारी दी।

देश की परमाणु तैयारियों पर उनके उत्तराधिकारी को, तत्काल आवश्यकता पर
हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, परीक्षण करने में असमर्थ होने के कारण, और विशेष रूप से
वाजपेयी को किन-किन मुश्किलों से बचना चाहिए? इसी बैठक के बाद वाजपेयी ने यह निर्णय लिया।
उन्होंने परमाणु युद्ध छेड़ने का फैसला किया।
राव ने वाजपेयी को परमाणु परीक्षण के लिए राजी करने की कोशिश की।
तुरंत—बहुमत परीक्षण करने से पहले ही। उन्होंने तर्क दिया कि यदि
वाजपेयी की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चली, और अगले उत्तराधिकारी ने सरकार बनाने का फैसला किया।
सरकार संयुक्त मोर्चा (यूएफ) की सरकार होगी; आई. के. गुजराल
अगर यूएफ सत्ता में आता तो उन्हें विदेश मंत्री बनाए जाने की उम्मीद थी और
परीक्षण का विरोध करना सुनिश्चित करें।
के. सुब्रह्मण्यम, जिन्हें राव ने स्वयं बैठक के बारे में बताया था,
राव ने मुझे बैठक के बारे में जो बताया था, उसकी पुष्टि की।
1999 में सुब्रह्मण्यम कारगिल समीक्षा समिति के प्रमुख थे।
वाजपेयी सरकार द्वारा (29 जुलाई 1999 को) स्थापित - तीन दिन बाद
कारगिल युद्ध की समाप्ति। खुफिया विफलताओं की जांच करने का कार्य सौंपा गया और
सुब्रह्मण्यम ने भविष्य के लिए सुझाव देने का अनुरोध किया।
नरसिम्हा राव, अन्य समिति सदस्यों के साथ।
‘तुम पहले खुद आकर मुझसे मिल लो,’ एक सतर्क राव ने उसे भेजा।
सुब्रमण्यम उनसे अकेले मिलने गए। सुब्रमण्यम ने राव से कहा, 'हम आपसे आपकी कश्मीर नीति के बारे में बात करना चाहते हैं। और आपकी...'
परमाणु नीति।'
राव ने कहा, ‘मैं कश्मीर पर आपसे बात करूंगा, लेकिन आपसे बात नहीं करूंगा।’
परमाणु नीति पर।'
'क्यों?'
राव: 'नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि देश को गुमराह किया गया था'

लोग। और मुझे सब कुछ ठीक करना था। हमारे लोगों को बताया गया था कि हम परमाणु कार्यक्रम के मामले में वे पाकिस्तान से आगे थे...

सुब्रह्मण्यम: 'क्या जनता के प्रति आपका यह कर्तव्य नहीं है कि आप रिकॉर्ड स्थापित करें?'

सीधा?'

'नहीं,' राव ने कहा। 'मैं किसी का ऋणी नहीं हूँ, सिवाय एक के।'

व्यक्ति। और वह कर्तव्य मैं पहले ही निभा चुका हूँ।'

'वह व्यक्ति कौन था?' सुब्रह्मण्यम हैरान रह गया।

राव ने जवाब दिया, 'अटलजी, जिन्होंने मुझसे पदभार संभाला। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया।'

बाद में, वाजपेयी ने इस उपलब्धि का पूरा श्रेय नरसिम्हा राव को दिया।

परीक्षण के लिए सब कुछ तैयार था। राव ने मुझे बताया कि बम तैयार है। मैंने बस इतना ही कहा था।

'उसने इसे उड़ा दिया,' राव की मृत्यु के तुरंत बाद भावुक वाजपेयी ने कहा।

दिसंबर 2004।

बातचीत के दौरान राव ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि उन्होंने सलाह दी थी।

वाजपेयी ने अपने तेरह दिवसीय पहले कार्यकाल के दौरान परीक्षा लेने का प्रयास किया, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

संसद में बहुमत हासिल करने के लिए, 'मैंने वाजपेयी को ऐसा करने के लिए कहा था,' राव ने नरेश से कहा।

Chandra. 'Humne toh Atalji ko kaha thaa kar jaate, jo ayenge woh

देखेंगे (मैंने अटलजी को यह करने को कहा था, तुम्हारे बाद जो भी आएगा वह इसे संभालेगा)

इसके परिणाम (परिणामस्वरूप),' राव ने चंद्र से कहा।

18 मई 1996 को वाजपेयी के साथ अपनी मुलाकात में राव ने अपील की कि...

नए प्रधानमंत्री को दो स्तरों पर परीक्षा देनी थी। पहला स्तर 'भावनात्मक' था। यह एक परीक्षा थी।

ऐसा माना जाता था कि इससे राष्ट्रीय गौरव उत्पन्न होगा। दूसरा कारण इससे

संबंधित था।
सुरक्षा संबंधी—यदि भारत ने कड़े उपायों से पहले तुरंत परीक्षण नहीं किया,
सीटीबीटी के प्रावधान लागू होने पर, ऐसा करना संभव नहीं होगा।
भविष्य। यह एक अलग बात है कि सीटीबीटी पास नहीं हो पाया। लेकिन
राव को 1996 में वाजपेयी को जानकारी देते समय इस बात की जानकारी नहीं थी।
राव ने वाजपेयी को यह चेतावनी भी दी कि वे वही गलती न दोहराएं जो उन्होंने की थी।
दिसंबर 1995 में जब अमेरिकी उपग्रहों ने इस गतिविधि को पकड़ा था।
पोखरण में युद्ध जारी है। के. संथानम ने बताया था कि अमेरिकी किस प्रकार से...
उन्हें चल रही घटनाओं की भनक लग गई थी: 'शाफ़्ट को सील कर दिया गया था'
1983 से आगे। जब शाफ्टों का नवीनीकरण शुरू हुआ और पानी बाहर निकाला गया, तो पानी रेत पर जमा हो गया और अमेरिकी उपग्रह ने उसे पकड़ लिया।
इसे साफ करो... यह (दूषित पानी) पहले सांभर की तरह लाल हुआ करता था।'
वाजपेयी ने उस दिन राव द्वारा कही गई हर बात को ध्यानपूर्वक सुना।
■

स्वतंत्र भारत में वाजपेयी-राव का रिश्ता अद्वितीय था।
इतिहास। हालाँकि वे विरोधी दलों से संबंधित थे, और उन्होंने सदस्यता ले रखी थी।
अलग-अलग विचारधाराओं के बावजूद, उनमें एक-दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास था।
अपने पार्टी के साथियों के साथ आनंद लें।
उनका रिश्ता बहुत पुराना था—और वे एक-दूसरे की मदद के लिए आए थे।
उनके करियर के महत्वपूर्ण क्षण। जैसा कि अध्याय 4 में उल्लेख किया गया है, कई लोग भी
दोनों के बीच 'ब्राह्मणीय संबंध' देखा गया—दोनों ब्राह्मण थे—और
वे एक दूसरे की बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे।
राव और वाजपेयी की पहली मुलाकात 1977 में हुई थी जब
वाजपेयी जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री थे। राव

तब वह आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा से पहली बार सांसद बने थे।
राव 1980 में विदेश मंत्री बने, वे अक्सर वाजपेयी से सलाह लेते थे।
उन्होंने वाजपेयी के अधिकांश कर्मचारियों को बरकरार रखा था।
बाद में, हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य में उनकी साझा रुचि ने उन्हें इस साहित्य के प्रति आकर्षित किया।
भाषा ने उन्हें करीब ला दिया। वाजपेयी द्वारा अपनी कविताओं में उर्दू का प्रयोग
वे उन्हें और भी अधिक भावपूर्ण बनाते हैं। हैदराबाद के निवासी राव ने इसकी सराहना की।
वाजपेयी को ग़ज़लें बहुत पसंद थीं और उनकी पसंदीदा ग़ज़लों में से एक उर्दू थी।
करण सिंह, और एक गाना जो उन्हें कभी-कभी गाना पसंद था: 'रंजीशे ही सही'
dil dukhane ke liye aa, Aa phir se mujhe chorhne ke liye aa.’
Karan
सिंह ने लखनऊ से वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं जीता था।
चुनाव प्रचार के दौरान एक ने दूसरे पर हमला किया।
नवंबर 1995 में, राव ने वाजपेयी की कविताओं की पुस्तक, 'मेरी' का विमोचन किया।
इक्यावन कवितयेन। मीडिया जगत से हममें से कई लोगों ने समारोह में भाग लिया।
दिल्ली में फिक्की सभागार में उस अद्भुत जादू के लिए, जो केवल वाजपेयी ही कर सकते थे।
शब्दों से बुनना। वह शाम सिर्फ दो शब्दों के लिए यादगार थी।
दो मुख्यधारा की पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो राजनीतिक दिग्गजों द्वारा कहा गया
भारत—ये दो शब्द थे ‘गुरु’ और ‘गुरुघंटाल’।
While launching Vajpayee’s book, Rao remarked, ‘Atalji mere haal
kaal ke guru rahe hain (Atalji has been my teacher in my bad times).’
अपने जवाब में वाजपेयी ने प्रधानमंत्री को 'गुरुघंटाल' बताया।

(गुरुओं के गुरु)। दरअसल, वे अक्सर एक-दूसरे को गुरुजी कहकर संबोधित करते थे। स्वाभाविक रूप से, उनकी कही बातें अगली सुबह सुर्खियों में छा गईं।
1994 में, वाजपेयी ने जिनेवा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने पर सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के उदाहरण पर। पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव प्रायोजित किया था।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) में निंदा करते हुए
जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों के मामले में भारत का रिकॉर्ड असामान्य था।
विपक्षी नेता को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने देने का प्रस्ताव
और विदेश मामलों के राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद को उनके अधीन कर दिया। लेकिन भारत के पड़ोसियों को यह संकेत दिया कि सरकार और विपक्ष ने
कश्मीर मुद्दे पर देश एकमत होकर आगे बढ़ रहा था। इसके लिए देश के प्रयासों का धन्यवाद।
प्रतिनिधिमंडल के समक्ष प्रस्ताव खारिज कर दिया गया।
राव ने वाजपेयी की कई बार मदद की। अक्टूबर 1995 में, उन्होंने
वे संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क में एक साथ थे।
महासभा। 'वाजपेयी मेरे और पीवी के बीच बैठे थे,' याद करते हुए बताया।
भुवनेश चतुर्वेदी। 'वह मेरी ओर मुड़ा और फुसफुसाते हुए बोला, "मैं बात करना चाहता हूँ
पीवी को।" चतुर्वेदी ने उनसे कहा, "शाम को होटल आ जाना।"
वाजपेयी: 'शाम को बात करने का समय नहीं होता।'
तो फिर अभी उससे बात करो।
Vajpayee leaned across and said to Rao, 'Kalyan Singh humare bahut
virodh maen hai, unko nahi banna chahiye (Kalyan Singh has been
मेरा विरोध करने वाले व्यक्ति को (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में) पदभार नहीं संभालना चाहिए।'

‘हम्म, हम्म’, राव ने पहले तो अस्पष्ट आवाजें निकालीं। फिर उन्होंने आगे कहा,
‘Dekhte hain, governor se baat karenge (Let’s see, we will talk to the
राज्यपाल)।
जब वे शाम को होटल लौटे, तो चतुर्वेदी ने पूछा
Rao, ‘Karna hai unka kya (Do we help him with it)?’
‘Haan keh do Voraji ko (Yes, tell Voraji to do what’s necessary),’ Rao
उत्तर दिया।
मोतीलाल वोरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे और एक आदर्श व्यक्तित्व थे।
‘वफादार’। चतुर्वेदी ने न्यूयॉर्क से वोरा को फोन किया, ‘प्रधानमंत्री कह रहे हैं’
कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए।
‘लेकिन,’ वोरा ने कहा, ‘वह यहाँ बाहर वाले कमरे में बैठा है और अपनी योजना पर दांव लगा रहा है।’
सरकार बनाने का दावा करते हैं।
चतुर्वेदी का रुख स्पष्ट था, 'उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए।'
वोरा: 'ठीक है।'
अक्टूबर 1995 में, लखनऊ में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई थी।
17 अक्टूबर को भाजपा ने गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया था।
बहुजन समाज पार्टी की मायावती के नेतृत्व वाली सरकार। उन्हें उसी वर्ष 3 जून को भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनाया गया था।
समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन के बाद
बिखर गया। कल्याण सिंह, जो एल. के. आडवाणी के शिष्य थे, उनके पास सब कुछ था।
वह शुरू से ही मायावती का समर्थन करने के खिलाफ थे। आखिरकार, उनकी बात मान ली गई और
भाजपा ने उनसे समर्थन वापस ले लिया। ऐसा लग रहा था कि वह शायद ऐसा कर पाएंगे।
सरकार बनाने के लिए जुगाड़ करना। उन्होंने बहुमत के समर्थन का दावा किया।

मायावती के उनसठ विधायक। वाजपेयी को वहां की गतिविधियों की जानकारी मिल गई थी।

लखनऊ। लखनऊ में कल्याण सिंह का मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापन समारोह।

इसका मतलब होगा कि सत्ता आडवाणी के हाथों में चली जाएगी। इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

वाजपेयी के लिए समस्याएं खड़ी हो गईं, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ मानते थे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि वे

अगर वे भाजपा में राज्य के निर्विवाद नेता के रूप में देखे जाते, तो

प्रधानमंत्री बनने के लिए। देश के अधिकांश प्रधानमंत्रियों

जिनकी जड़ें उत्तर प्रदेश में थीं—जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, Charan Singh, Rajiv Gandhi, V. P. Singh, Chandra Shekhar. Rao

उन्होंने वाजपेयी के लिए उत्तर प्रदेश के महत्व को समझा और उनकी मदद करने का फैसला किया।

दोस्त।

जब राव 26 अक्टूबर 1995 को न्यूयॉर्क से लौटे, तो मोतीलाल

वोरा पालम हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में उसका इंतजार कर रही थी।

किसी राज्यपाल के लिए प्रधानमंत्री का स्वागत करना असामान्य बात है—और वह भी उनके अपने दिन पर।

विदेश यात्रा से वापसी। अगली रात, 27 अक्टूबर 1995 को, यूपी

विधानसभा भंग कर दी गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। वोरा कल्याण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।

उनके राज्यपाल पद छोड़ने के काफी समय बाद, मैंने वोरा से इसके बारे में पूछा था।

एपिसोड। वह बस समझदारी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया।

■

राव ने हवाला मामले को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाकर वाजपेयी की मदद की,

जब राव मुश्किल में थे, तब वाजपेयी भी उनकी मदद के लिए आगे आए थे।

उन्होंने नरसिम्हा राव को (जेएमएम मामले में) बरी कराने में मदद की।
Bhuvnesh Chaturvedi told me.
सितंबर 2000 में, निचली अदालत ने राव और बूटा को सजा सुनाई थी।
सिंह को झारखंड मुक्ति मोर्चा में तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई।
मामले की सुनवाई 29 सितंबर 2000 को विशेष न्यायाधीश अजीत भरिहोके ने की थी।
दो लोग जेएमएम सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने के लिए रिश्वत देने के दोषी पाए गए।
राव की अल्पमत सरकार के खिलाफ (28 जुलाई, 1993 को)।
राव ने मामले को बंद करने के लिए वाजपेयी की मदद मांगी। चतुर्वेदी ने मुझे बताया कि
वह मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था।
'मैं अटलजी से मिलने गया था,' चतुर्वेदी ने याद करते हुए बताया। 'उन्होंने ब्रजेश को बुलाया।
room. He told him, "Isko khatam keejiye".'
16 मार्च 2002 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने राव और बूटा को बरी कर दिया था।
जेएमएम रिश्वत कांड में सिंह, जिसमें दोनों को सजा सुनाई गई थी
तीन साल की कैद। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर.एस. सोढ़ी।
यह देखा गया कि एकमात्र गवाह, जेएमएम सांसद शैलेंद्र महतो (उन्होंने
(जो बाद में गवाह बन गया), एक 'स्वयं कबूल किया झूठा' था—और उसने 2000 के मुकदमे को रद्द कर दिया।
राव और बूटा सिंह के खिलाफ अदालत का फैसला। राव के वकील आर. के. आनंद
उन्होंने तर्क दिया था कि पूरा अभियोजन मामला केवल एक गवाह पर आधारित था।
जिसने कई बार खुद का खंडन किया था। चार जेएमएम सांसदों ने
कथित तौर पर रिश्वत ली गई है।
ये राजनीतिक निर्णय हैं, बाकी (कानूनी पहलू) महज़ औपचारिकताएं हैं।
'इसका हल निकाल लिया गया है,' चतुर्वेदी ने आगे कहा।
आई. के. गुजराल, जो उस समय स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, ने भी यह बात कही थी।

वाजपेयी ने कहा था कि 'प्रधानमंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों का होना अच्छा नहीं है' जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई।' तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत ने भी इस बारे में बात की थी।
वाजपेयी को राव की मदद करने के लिए।
यह महत्वपूर्ण था कि वाजपेयी सरकार ने अपील न करने का निर्णय लिया।
उच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत, सीबीआई ने मामला वापस लेने का फैसला किया।
एल. के. आडवाणी के नेतृत्व में कुछ भाजपा नेताओं ने विरोध की आवाज उठाई। लेकिन
वाजपेयी अपने रुख पर अडिग रहे; उन्होंने अपील न करने का फैसला किया। वाजपेयी मैंने पीवी को नुकसान न पहुंचाने की कोशिश की—और इसके विपरीत भी।
राव का वाजपेयी को जानकारी देने में सहज महसूस करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।
परमाणु विकल्प के सभी पहलुओं पर।
■

18 मई 1996 को राव से मुलाकात के तुरंत बाद, उत्साहित वाजपेयी ने
जल्दी से घर वापस भागा। उसने अपने नवयुवक को निर्देश दिया, 'कृपया कलाम को बुलाओ।'
नियुक्त निजी सचिव, शक्ति सिन्हा। सिन्हा को इसमें घंटों लग गए।
ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का पता लगाएँ। वे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे।
1992 से प्रधानमंत्री और साथ ही डीआरडीओ के सचिव। अधिक जानकारी के लिए
महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कई वर्षों से भारत द्वारा अधिग्रहण के समर्थक रहे थे।
एक परमाणु निवारक। अंततः, सिन्हा ने उसे कोलकाता में खोज निकाला। तब तक 9 बज चुके थे।

रात में। सिन्हा ने उन्हें बताया, 'प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं।' उन्होंने आग्रह किया।
कलाम सुबह की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

‘Patakha chorhna hai (We have to let off the cracker),’ Vajpayee told
कलाम ने अगली सुबह उसे देखते ही प्रतिक्रिया दी। कलाम
के. संथानम के साथ, कलाम ने प्रधानमंत्री से कहा कि उन्हें आवश्यकता है।
कुछ समय। लेकिन वाजपेयी ने उन्हें तैयार होने की अनुमति दे दी। 'हम कर सकते थे।'
उन्होंने यह काम उन तेरह दिनों में किया होगा जब वाजपेयी ने अपना
संथनम ने कहा, 'ध्यान रखो। लेकिन उसे एक उच्च स्तर की सलाह भी दी गई थी।'
कि उन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। और अधिकार क्या होगा?
ऐसे प्रधानमंत्री को...एक ऐसे आयोजन का संचालन करना जिसका व्यापक राष्ट्रीय और
अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ।
कैबिनेट सचिव सुरिंदर सिंह इस फैसले के खिलाफ थे। वाजपेयी
उन्होंने तर्क दिया कि इतना व्यापक कदम नहीं उठाना चाहिए। यह उचित नहीं होगा।
ताकि बाद में किसी और सरकार को सारी समस्याओं को समेटने का काम सौंपा जा सके।
कैबिनेट सचिव को इस बात की चिंता रही होगी कि अगला प्रधानमंत्री क्या करेगा।
अगर उसे बच्चे की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता तो वाजपेयी उससे क्या कहते—यानी अगर वाजपेयी
सरकार गिर गई, जिसकी संभावना पहले से ही लग रही थी।
वाजपेयी के लिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था। अगर वह अंदर चले जाते तो क्या होता?
एक परीक्षा के लिए, हो सकता है कि वह संसद में विश्वास मत जीत जाते।
कुछ लोगों को लगा कि इससे उस तरह का उत्साह पैदा हो सकता था जो हो सकता था
इससे कुछ राजनीतिक दलों को अपना रुख बदलने और उनका समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
दूसरी ओर, उन्हें अपनी सरकार की क्षमता के बारे में भी सोचना था—और यह
सरकार कमजोर थी—और उसे अमेरिका की दंडात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा।

जो होना ही था। 1974 में जो हुआ था, उसे जानते हुए जब
इंदिरा गांधी ने एक परीक्षा दी, उन्हें इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि कैसे
अमेरिकी लोग प्रतिक्रिया देंगे।
फिर भी, वह इस विचार की ओर झुक रहा था कि समय आ गया है।
परीक्षण करने के लिए; विस्तृत जानकारी के बाद वह इस बात से और भी आश्वस्त हो गया था।
राव के साथ बैठक।
वाजपेयी ने अन्य पार्टियों से संपर्क साधने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया।
किसी तरह बहुमत जुटाया। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीस को भेजा।
भुवनेश चतुर्वेदी से मदद के लिए मिलने के लिए। फर्नांडिस ने चतुर्वेदी से आग्रह किया कि
चंद्र शेखर को आठ सदस्यीय समता को अनुमति देने के लिए 'कृपया मनाएं'
फर्नांडीस के नेतृत्व वाली पार्टी वाजपेयी सरकार में शामिल हो गई। हालांकि
चंद्र शेखर पार्टी के सदस्य नहीं थे—वे पार्टी से अलग हो गए थे।
1994 में जनता दल से अलग होने के बाद, उन्होंने दल के कुछ सदस्यों पर अपना प्रभाव जमाया, जो उनके संरक्षण में थे। चतुर्वेदी चंद्र से बात करने के लिए सहमत हुए।
शेखर सहमत नहीं हुआ। लेकिन वह सहमत नहीं हुआ।
वाजपेयी ने दलित समुदाय के प्रमुख कांशी राम से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की।
उनका समर्थन मांगने के लिए बहुजन समाज पार्टी पर हावी हो गए। कांशीराम के बाद से
अगर वह खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता, तो वह किसी का समर्थन नहीं करने वाला था।
वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने भी इनकार कर दिया।
इसके बाद वाजपेयी ने अपना आखिरी हताशा भरा कदम उठाया। उन्होंने जॉर्ज से पूछा
फर्नांडीस नरसिम्हा राव से मिलने जा रहे हैं—ताकि प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर सकें।
अपनी सरकार को संकट से बचाने के लिए। 'मैंने खुद जॉर्ज के लिए एक अपॉइंटमेंट तय किया था।'
'पीवी को देखें,' भुवनेश चतुर्वेदी ने खुलासा किया।

‘ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है।’
फर्नांडीस ने राव से बहस की, जो अब प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन राव
अस्वीकार करना।
राव चाहते थे कि वाजपेयी इसका परीक्षण करें। लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा संभव नहीं था।
कांग्रेस आत्मघाती कदम उठाए बिना भाजपा का समर्थन कर सकती है। भले ही वह
अगर अगर वह वाजपेयी को संकट से बाहर निकालना चाहते, तो वह इस स्थिति को संभाल नहीं पाते।
उनकी पार्टी उनके साथ थी। कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं।
1996 के चुनाव हारने के बाद।
वाजपेयी को उम्मीद थी कि अगर वह किसी एक अन्य पार्टी को भी राजी कर सकें तो भाजपा का समर्थन करें और इस तरह उस पर लगे 'अस्पृश्यता' के कलंक को तोड़ें।
अन्य समूह उनका समर्थन करने का निर्णय ले सकते थे। ऐसा नहीं हुआ। और सभी
वाजपेयी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचे थे।
■

वाजपेयी की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले सिर्फ सुरिंदर सिंह ही नहीं थे।
परीक्षण करने की योजना है। निर्णायक जीत अमेरिकियों की ओर से आई, जिन्होंने
वाजपेयी के टेस्ट करवाने की आशंका बढ़ने लगी थी। अमेरिका की सतर्कता
उनकी छवि अमेरिका द्वारा वाशिंगटन को भेजे गए कुछ ईमेल में भी झलकती थी।
दिल्ली स्थित दूतावास के वे दस्तावेज, जिन्हें बाद में 2011 में सार्वजनिक किया गया था।
भारतीय राजदूत के रूप में वाशिंगटन जाने से ठीक पहले, नरेश
चंद्र ने अप्रैल 1996 में दिल्ली में वाजपेयी से मुलाकात की थी। राव तब भी राष्ट्रपति थे।
उस समय के प्रधानमंत्री। किसी नामित राजदूत के लिए किसी से मुलाकात करना असामान्य बात थी।
राजनयिक कार्य पर जाने से पहले विपक्षी नेता, आईबी प्रमुख वी.

जी. वैद्य ने मुझे बताया।
कहा जाता है कि चंद्र ने नरसिम्हा के कहने पर वाजपेयी से मुलाकात की थी।
राव शायद अपने उत्तराधिकारी को आगाह करना चाहते थे। राव को आभास था कि अमेरिका वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से वंचित करने के लिए पैरवी करेगा।
अशोक टंडन ने लिखा, '1996 में त्रिशंकु लोकसभा की घटना'।
उन्हें प्रधानमंत्री वाजपेयी का मीडिया सलाहकार बनना था।
जब वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तब अमेरिकी वे स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए थे—और वाजपेयी यह बात जानते थे। एक दिन, अपने शासन के उन तेरह दिनों के दौरान, वाजपेयी ने नरेश को फोन किया।
वाशिंगटन में चंद्र।
‘Wisner aa rahe hain (Wisner is coming to see me),’ he said cryptically. ‘Kya kehne aa rahe hai (What does he intend to say)?’
हम दोनों जानते थे कि यह एक खुली लाइन थी। हम दोनों जानते थे कि वह क्या था।
'मैं यही कहने आया था,' चंद्र ने बाद में कहा।
यह स्पष्ट था कि फ्रैंक विस्नर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भाजपा सरकार परीक्षण शुरू करने की योजना बना रही थी। कहीं न कहीं अमेरिकियों को वाजपेयी के झुकाव के बारे में जानकारी मिल गई थी।
चंद्र ने वाजपेयी से सावधानीपूर्वक कहा, 'यह एक शिष्टाचार भेंट होगी।'
‘Inki sun leejiye. Keh deejiye…that we attach importance to Indo–
चंद्र ने प्रधानमंत्री से कहा, 'अमेरिका के साथ संबंध (उनकी बात सुनिए और अपनी राय रखिए)।'
वाजपेयी ने अपनी बात कह दी।
बाद में अमेरिकियों ने गोपनीय दस्तावेजों के माध्यम से खुलासा किया कि वाजपेयी परीक्षा देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। विस्नर, जो वाजपेयी से मिल चुके थे, उनकी शारीरिक भाषा से यह स्पष्ट था कि वे परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध थे।
दिसंबर 1996 के अंत में, अमेरिकी विदेश मंत्री वारेन क्रिस्टोफर ने एक बयान जारी किया।

भारत सरकार को चेतावनी दी गई थी—और इसे दिल्ली को सौंप दिया गया था।
नरेश चंद्र के माध्यम से। तब तक एच. डी. देवेगौड़ा ने कार्यभार संभाल लिया था।
प्रधानमंत्री। चंद्र ने याद करते हुए कहा, 'मुझे उसमें से एक वाक्य याद है, कि एक परीक्षण
इससे भारत-अमेरिका संबंधों के लिए "विनाशकारी परिणाम" होंगे।
अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए वाजपेयी ने आगे न बढ़ने का फैसला किया।
उन्होंने अपनी परीक्षण योजना के बारे में वैज्ञानिकों को बताया।
वाजपेयी की सरकार केवल तेरह दिनों तक चली, जो कि सबसे कम अवधि है।
स्वतंत्र भारत में किसी भी सरकार में। उन्होंने 28 मई 1996 को इस्तीफा दे दिया, लेकिन
कुछ और दिनों तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। एच. डी. देवे
गौड़ा ने 1 जून 1996 को अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
वाजपेयी ने 1996 में परीक्षण करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
आगे बढ़ो। लेकिन, अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान, उन्हें यकीन था कि अगर उन्हें मौका मिल गया तो...
अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वह ऐसा जरूर करेगा।

सातवीं

उपराष्ट्रपति कृष्णकांत ने परेशान छात्र से पूछा, 'कैसा चल रहा है?'
वाजपेयी के राष्ट्रपति बनने के कुछ हफ़्ते बाद उनकी मुलाकात हुई थी।
19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया।
कांट के अनुसार
मुझे पता था कि वाजपेयी को अपना मंत्रालय बनने से पहले ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।
गठित किया गया।
वाजपेयी कांत के विचारों से सहज थे और उनके बारे में खुलकर बात कर सकते थे।
भाजपा के सहयोगियों के साथ उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था —'ममता, समता,
'जयललिता'—मीडिया ने उनके लिए मुसीबत खड़ी करने वाली इस महिला को यही

नाम दिया था।
यह संदर्भ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जॉर्ज के बारे में था।
फर्नांडीस की समता पार्टी और जे. जयललिता की एआईएडीएमके, ये तीनों सहयोगी दल हैं।
भाजपा के वे लोग, जो प्रधानमंत्री को परेशान कर रहे थे।
वाजपेयी दो साल पूरे होने से ठीक पहले दोबारा प्रधानमंत्री बन गए थे।
1996 में पद छोड़ने के बाद। इस बार वह शीर्ष पद पर थे।
भाजपा के नेतृत्व वाले एक अन्य गठबंधन को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन कहा जाता है।
(एनडीए)। 1996 में उनकी जगह लेने वाली संयुक्त मोर्चा सरकार।
दो बार देखने के बाद, यह अपने विरोधाभासों के भार तले ढह गया था।
प्रधानमंत्री के रूप में एच. डी. देवेगौड़ा और फिर आई. के. गुजराल ने सत्ता संभाली।
इसके बाद 1998 में हुए मध्यावधि चुनावों में भाजपा ने 182 सीटें जीतीं।
यह 1996 में जीती गई 161 जीतों से अधिक है, लेकिन फिर भी 273 जीतों के आसपास भी नहीं है।
लोकसभा में बहुमत के लिए आवश्यक है। हालाँकि, इस बार,
चुनाव के बाद भाजपा को पंद्रह पार्टियों का समर्थन प्राप्त करने में सफलता मिली;
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का गठन किया और एक साझा मंच तैयार किया।
इस कार्यक्रम को इसने राष्ट्रीय शासन एजेंडा (एनएजी) नाम दिया।
वाजपेयी अपने भोजन की मेज पर बैठे और उन्होंने अपने एक सहकर्मी को एनएजी का मसौदा लिखवाया।
सचिव शक्ति सिन्हा। जब वाजपेयी राष्ट्रपति के. आर. नारायणन से मिले।
सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए उन्हें 267 का समर्थन प्राप्त था।
लोकसभा में सांसद। लेकिन फिर राष्ट्रपति ने गुगली गेंद फेंकी।
वाजपेयी-नारायणन ने उनसे समर्थन पत्र उपलब्ध कराने को कहा।
भाजपा का समर्थन करने वाली पार्टियां। इनमें चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात दोनों पार्टियां शामिल थीं।
भाजपा के सहयोगी दल। अवसर को भांपते हुए, अब सहयोगी दलों ने भी इस अवसर का लाभ उठाया है।

उन्होंने अपने समर्थन के बदले अपनी मांगों को बढ़ाना शुरू कर दिया।
इसकी शुरुआत जे. जयललिता के नखरों से हुई, जो एक कठोर नेता थीं।
एआईएडीएमके। जयललिता भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर चिंतित थीं।
उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वह चाहती थी कि अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी को दोषी ठहराया जाए।
वित्त मंत्री। आमतौर पर उदार रहने वाले वाजपेयी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया।
नीचे। दोनों पुरुषों के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था। जब स्वामी
जनसंघ में कुछ साल पहले उन्होंने वाजपेयी पर तीखा हमला किया था। वाजपेयी किसी भी हालत में स्वामी को अपना सहयोगी नहीं मानते।
वित्त मंत्री।
12 मार्च 1998 तक, सभी समर्थक दलों ने वाजपेयी को समर्थन दे दिया था।
उनके समर्थन में लिखे गए पत्रों में से जयललिता को छोड़कर सभी सांसदों के समर्थन पत्र थे। जयललिता को तीस सांसदों का समर्थन प्राप्त था।
सरकार के लिए एआईएडीएमके और उसके सहयोगी संगठनों का समर्थन महत्वपूर्ण था।
गठन। लेकिन वह अड़ी रही। राष्ट्रपति ने वाजपेयी को
आवश्यक संख्या जुटाने के लिए 14 मार्च तक, यानी दो और दिन बाकी हैं।
चिंतित वाजपेयी अपने वरिष्ठ पार्टी सहयोगी, 'मेजर' के पास दौड़े।
जसवंत सिंह को उनके सैन्य पृष्ठभूमि के कारण 'साहिब' कहा जाता था।
जयललिता को मनाने के लिए। घंटों की कड़ी सौदेबाजी के बाद, जयललिता
अंततः वह मान गईं। उन्होंने वाजपेयी को अपना समर्थन पत्र भेजने पर सहमति जताई।
14 मार्च। लेकिन राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने अपना पत्र नहीं भेजा।
वाजपेयी को तुरंत निमंत्रण भेजा गया। उन्होंने अपना परामर्श जारी रखा।
अन्य दल। यह तभी हुआ जब सोनिया गांधी ने अपना दावा पेश करने से इनकार कर दिया।
राष्ट्रपति ने वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था।
सरकार।
लेकिन वाजपेयी की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं।

बहस जारी रही, इस बार इस बात पर कि नया वित्त मंत्री कौन होगा।
प्रधानमंत्री पद के लिए नामित व्यक्ति ने जसवंत सिंह को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था।
उन्हें अपना वित्त मंत्री बनाने के लिए। 18 मार्च 1998 को रात 8 बजे, उन्होंने संदेश भेजा था।
राष्ट्रपति के मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्तियों के नामों की सूची।
जसवंत सिंह का नाम सूची में था। शपथ ग्रहण समारोह होना था।
अगली सुबह 9:30 बजे, मैंने खुद सूची टाइप की थी,' उन्होंने याद करते हुए कहा।
शक्ति सिन्हा। सूची भेजे जाने के बाद, वाजपेयी और उनका परिवार बैठ गया।
रात के खाने के लिए नीचे।
उस रात वाजपेयी के यहाँ एक उच्चस्तरीय अतिथि उपस्थित थे—आरएसएस के संयुक्त जनरल।
सचिव, के. एस. सुदर्शन। सुदर्शन ने शाम को पहले फोन किया था।
वाजपेयी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। वाजपेयी ने उन्हें रात के खाने पर रुकने का निमंत्रण दिया। रंजन
वाजपेयी के दत्तक दामाद भट्टाचार्य, जो होटल में मौजूद थे,
उद्योग ने यह सुनिश्चित किया कि भोजन में टमाटर न हों—सुदर्शन
उन्हें इनसे एलर्जी होने की जानकारी थी।
रात के खाने के बाद, वाजपेयी अपने मेहमान को दूसरे कमरे में ले गए ताकि वे
निजी बातचीत। अन्य आरएसएस नेताओं के विपरीत, सुदर्शन अपने निजी जीवन के लिए जाने जाते थे।
स्पष्टवादी अंदाज में। बिना लाग-लपेट के, उन्होंने वाजपेयी को साफ-साफ कह दिया कि वे ऐसा न करें।
जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन को मंत्रिमंडल में शामिल करें। उनके बाद
लोकसभा चुनाव में वे सभी हार गए। इससे वाजपेयी के सामने एक दुविधा खड़ी हो गई—क्योंकि वे दो ऐसे लोग थे जिन पर वे भरोसा करते थे और जिनके साथ उन्हें सहजता महसूस होती थी।
स्तर के साथ।
जसवंत सिंह अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पक्षधर थे।

जिसकी शुरुआत नरसिम्हा राव ने की थी। आरएसएस को यह बात पता थी।
वाजपेयी भी उसी रास्ते पर चलना चाहते थे। वे नया
सरकार को स्वदेशी (आत्मनिर्भरता) के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने पाया
जसवंत सिंह के आर्थिक विचार समस्याग्रस्त हैं। सेना छोड़ने के बाद,
और भाजपा में शामिल होने से पहले, जसवंत सिंह एक सांसद थे।
दक्षिणपंथी स्वतंत्र पार्टी, जिसकी शुरुआत भारत के पहले गवर्नर जनरल सी. ने की थी।
राजगोपालाचारी (राजाजी) - जो मुक्त उद्यम और एक
बाजार अर्थव्यवस्था।
दबाव बनाए रखते हुए, सुदर्शन ने वाजपेयी से कहा कि वह यहाँ आया है।
उन्हें आरएसएस प्रमुख राज्जू भैया के आशीर्वाद से देखें। आरएसएस
इस अनुरोध से वाजपेयी बेहद नाराज हो गए। विधिवत निर्वाचित प्रधानमंत्री होने के नाते, उन्होंने
एक अरब भारतीयों के मंत्री पद के लिए नामित व्यक्ति से अपना बयान वापस लेने को कहा जा रहा था।
जसवंत सिंह को यह बात बताई गई। उन्हें एहसास हुआ कि 'वे' उनके पंख काट रहे हैं।
उसके उड़ान भरने से पहले ही। लेकिन वह अपने प्रीमियरशिप की शुरुआत इस तरह नहीं करना चाहता था।
एक विवादास्पद प्रस्ताव के बावजूद, उन्होंने उसके अनुरोध को मान लिया।
शक्ति सिन्हा ने रात करीब 2 बजे एक और नोट टाइप किया, जो कि
इसमें जसवंत सिंह का नाम है। इसे तुरंत राष्ट्रपति भवन ले जाया गया।
19 मार्च 1998 की सुबह-सुबह।
अगली सुबह, 19 मार्च को, शपथ ग्रहण समारोह था। लेकिन
रायसीना रोड स्थित 6 नंबर के वाजपेयी के आवास पर शांति थी। वाजपेयी बैठ गए।
सुबह 7:30 बजे नाश्ते के लिए। उन्होंने आराम से पपीता और टोस्ट खाया। लेकिन वह
वह उदास दिख रहा था—उसे उत्साहित नहीं होना चाहिए था। शपथ ग्रहण समारोह
यह कार्यक्रम सुबह 9.30 बजे निर्धारित था।

राष्ट्रपति भवन जाते समय, चिंतनशील वाजपेयी ने सिन्हा से पूछा,
जो व्यक्ति उसके साथ कार में था, उसने पूछा, 'फाइनेंस का क्या होगा?'
फिर उन्होंने पूछा, 'अगर मैं वित्त मंत्रालय अपने पास रखता हूं तो क्या होगा?'
शक्ति सिन्हा ने जवाब दिया, 'कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दो-तीन ले सकते हैं।'
वित्त मंत्रालय में अच्छे राज्य मंत्री।
वाजपेयी ने बाकी यात्रा में और कुछ नहीं कहा। एक वाक्पटु वक्ता
वक्ता के अनुसार, वे व्यक्तिगत रूप से बहुत बातूनी व्यक्ति नहीं थे। राष्ट्रपति भवन में भवन में उन्होंने वीआईपी मेहमानों, पूर्व प्रधानमंत्रियों की लंबी कतार का अभिवादन किया।
और विपक्ष के नेता जो समारोह के लिए वहां एकत्रित हुए थे।
वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब कार्यवाही का अधिक औपचारिक हिस्सा शुरू हुआ—जब नए मंत्रियों ने शपथ ली—तब तक स्थिति बदल चुकी थी।
कार्यालय और गोपनीयता—वह गंभीर और परेशान दिख रहे थे।
शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के बाद, पत्रकार नए भवन के चारों ओर जमा हो गए।
प्रधानमंत्री। ‘जसवंत सिंह का नाम सूची से क्यों हटा दिया गया?’
वे जानना चाहते थे, 'मंत्री कौन हैं?'
वाजपेयी ने सहज भाव से जवाब दिया, 'वित्त व्यवस्था मैं खुद संभाल लूंगा।' टीवी कैमरों ने उनके शब्दों को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद पत्रकार तुरंत उस स्थान की ओर दौड़े।
आडवाणी खड़े हो गए। उन्होंने आडवाणी से भी वही सवाल पूछा। वाजपेयी को चाहिए था कि...
आडवाणी ने जवाब दिया कि वह स्वयं वित्त मंत्री पद पर नहीं रहेंगे।
चार घंटे के भीतर ही वाजपेयी को एक बार फिर अपनी बात से पलटना पड़ा।
यह एक अपमानजनक कदम था, जिसके चलते उन्हें यशवंत सिन्हा को नियुक्त करना पड़ा।
दिन ढलने से पहले ही यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री के रूप में उभर आए थे।
अंतिम समय में किए गए समझौते के तहत। वे वित्त मंत्री रह चुके थे।
उन्होंने 1991 की शुरुआत में चंद्र शेखर की सरकार में काम किया था और 1994 में

भाजपा में शामिल हो गए थे।
शक्ति सिन्हा ने खुलासा किया, 'वाजपेयी यशवंत सिन्हा को लेकर उत्सुक नहीं थे।'
उस समय यशवंत सिन्हा को 'स्वदेशी' के करीबी माना जाता था।
आरएसएस में एक लॉबी थी जिसने आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए जोर दिया। हालाँकि,
बाद में सिन्हा ने अपना रुख बदल लिया और उदारीकरण समर्थक रुख को आगे बढ़ाया।
वाजपेयी सरकार का आर्थिक एजेंडा। प्रधानमंत्री ने
उन्होंने उद्योगपतियों को पहले ही संकेत दे दिया था कि वे उन्हें महत्व नहीं देते।
अविश्वास के साथ।
शुरुआती दिक्कतों के बाद, नए एनडीए के पहले पचास दिनों में
सरकार के दौरान वाजपेयी के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। झुककर
आरएसएस और भाजपा के दबाव के चलते नए प्रधानमंत्री को
इससे संकेत मिला कि उसे आसानी से दबाया जा सकता है। उसके सहयोगियों ने तुरंत इसका फायदा उठाया।
यह ऊंचा।
जयललिता, सुब्रमण्यम स्वामी, राम जेठमलानी, रामकृष्ण
हेगड़े, बूटा सिंह, ममता बनर्जी—इन सभी ने अपनी-अपनी मांगें रखीं।
और नए प्रधानमंत्री को रक्षात्मक स्थिति में डाल दिया। हालाँकि उन्होंने अपना समर्थन दिया।
वाजपेयी को समर्थन देने वाली जयललिता के साथ काम करना आसान नहीं था।
उनकी पार्टी एआईएडीएमके, जो अब एनडीए में सहयोगी है, ने पंद्रह सीटों पर कब्जा कर लिया था।
राजस्व, बैंकिंग, कानून जैसे प्रतिष्ठित मंत्री पदों सहित अन्य मंत्री पद।
और सतही परिवहन। उन्होंने वाजपेयी को यह भी बताया कि उन्हें अपनी टीम में किसे रखना चाहिए।
अलमारी!
वाजपेयी पहले दिन से ही इस बात को लेकर चिंतित थे कि जयललिता क्या करेंगी।
शायद ठीक रहेगा। जब 9 तारीख को उसका उससे पहली बार मिलने का कार्यक्रम

था।
मार्च 1998 में, उसने उसे जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उसने यह भी पता लगा लिया था कि जब वह उससे मिलने आएगी तो उसे क्या परोसा जाना चाहिए। क्या उसने
चाय पसंद है? 'नहीं, कृपया उन्हें नारियल पानी दीजिए,' उनके एआईएडीएमके के प्रतिनिधि ने कहा।
दिल्ली में आर. के. कुमार ने प्रधानमंत्री के सहयोगियों को बताया।
उसके व्यवहार को देखकर पार्टी के अन्य नेता भी अपनी ताकत दिखाने लगे।
मांसपेशियों पर। जब उसने आर. के. हेगड़े पर हमला किया, जो अब एक मंत्री हैं।
वाजपेयी सरकार ने उनके इस सुझाव का विरोध किया था कि तमिल भाषा को
जब जयललिता को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, तो हेगड़े ने इसका जवाब देते हुए उन्हें राष्ट्रीय भाषा कहा।
और सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें 'कीड़े' कहा। स्वामी ने राम जेठमलानी को 'कीड़े' कहा।
सरकार में एक और मंत्री, 'झूठमलानी'।
एक महीने से भी कम समय में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई।
भाजपा में यह सुझाव देना शुरू हो गया कि वाजपेयी के लिए 'जाना' बेहतर होगा।
ब्लैकमेल के आगे झुकने के बजाय 'जनता के पास वापस लौटना' बेहतर है। अप्रैल की शुरुआत तक, लोग
मुझे यह सोचने लगा कि सरकार कितने समय तक टिकेगी।
वाजपेयी को चारों ओर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा—उनकी अपनी पार्टी से भी,
आरएसएस, कांग्रेस और वामपंथी। हरकिशन जैसे वरिष्ठ वामपंथी नेता।
सिंह सुरजीत और ज्योति बसु ने तो उनकी सरकार को 'विरोधी' करार दिया।
राष्ट्रीय'।
वाजपेयी के लिए आलोचना कोई नई बात नहीं थी। न ही उनकी भावनाएं नई थीं।
निराशा—इस बार उनके बहुप्रतीक्षित प्रधानमंत्री पद के अवसर के तरीके को लेकर।
उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। 1984 में भी उन्हें निराशा हुई थी जब भाजपा के नेतृत्व में सत्ता हाथ से निकल गई थी।
उनके कार्यकाल में उन्हें केवल 2 लोकसभा सीटें मिलीं। उनका राजनीतिक करियर

बुरी तरह से प्रभावित हुआ।
1980 के दशक में ऐसे चरण आए जब उन्हें दरकिनार कर दिया गया और आडवाणी को पदोन्नत किया गया।
पार्टी और आरएसएस। लेकिन उस समय उन्हें जो निराशा महसूस हुई थी, वह आज के समय की निराशा से बिलकुल अलग थी।
1998 में जब उनकी सरकार एक संकट से दूसरे संकट की ओर बढ़ रही थी, तब उन्हें जो निराशा हुई, उससे वे उबर नहीं पाए।
संकट।
‘अटल बिहारी वाजपेयी की वो दिव्य मुस्कान कहाँ चली गई?’ मणि
कांग्रेस के शंकर अय्यर ने व्यंग्यपूर्वक पूछा। महज एक महीने में, चले गए
वह थे ‘उत्साही और हंसमुख’ वाजपेयी। उनकी जगह एक अन्य नेता ने ले ली थी।
अपरिचित आकृति—‘कमजोर, थकी हुई, हतोत्साहित’।
एक समय हालात इतने खराब हो गए थे कि उसने खुद को
'असंपर्कहीन,' शक्ति सिन्हा ने बाद में बताया। संघर्ष में
कुछ परिस्थितियों में, वाजपेयी आत्मसंतुष्ट हो जाते थे। वे कभी-कभी आक्रामक भी हो सकते थे।
राजनीतिक स्तर पर तो उन्होंने संघर्ष से परहेज किया, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में संघर्ष से दूर रहे।
कुछ हफ्तों में, उनके प्रति लोगों की अपार सद्भावना धीरे-धीरे कम होने लगी।
सवाल उठने लगे: क्या वाजपेयी में देश पर शासन करने की क्षमता है?
यह अविश्वसनीय लग रहा था कि ऐसा किसी नेता के साथ हो रहा है।
पचास वर्षों का राजनीतिक अनुभव रखने वाले, जिन पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा था, और विपक्ष द्वारा 'दक्षिणपंथी' कहे जाने तक उनका सम्मान करने वाले व्यक्ति
वह व्यक्ति जो गलत पार्टी में था, अल्पसंख्यकों को स्वीकार्य था, इसके बावजूद
भाजपा में होने के नाते, जिसका काव्यात्मक हृदय, सुलहकारी छवि और सम्मोहक
उनकी वाक्पटुता ने उन्हें लाखों लोगों का प्रिय बना दिया था।
टिप्पणीकारों ने उनसे कुछ 'साहसिक' करने का आग्रह किया। एक लोकपाल को लाने को कहा।
जैसा उन्होंने वादा किया था, संसद में विधेयक पेश करें। या आरक्षण हेतु कानून बनाने

की पहल करें।
संसद और विधान सभाओं में एक तिहाई सीटें
महिलाओं के लिए। यह कुछ गंभीर और क्रांतिकारी होना चाहिए था। जैसे-जैसे शोरगुल बढ़ता गया,
जब बड़े और निर्णायक कदम उठाए गए, तो वाजपेयी जान गए कि उन्हें क्या करना है।
उन्होंने 1996 में अपने तेरह दिवसीय शासनकाल के दौरान लगभग ऐसा कर ही दिया था।
वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण करने की अनुमति दे दी थी—लेकिन
आखिरी क्षण में पीछे हट जाना। घरेलू समस्याओं के अलावा, पाकिस्तान को और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था।
इसके अलावा इसने भारत को परमाणु परीक्षण के लिए तत्काल उकसावा भी प्रदान किया।
6 अप्रैल 1998 को गौरी मिसाइल का परीक्षण किया गया।
सैद्धांतिक रूप से तो उसने परीक्षण करने का मन बना ही लिया था। यह केवल एक
यह तो बस समय की बात थी। उन्होंने अपने कदम का समय बहुत सावधानी से चुना। और एक
उनके इस निर्णय के समय को लेकर एक कारण एनडीए के भीतर उनकी 'अस्थिर' स्थिति थी।
और अपनी ही पार्टी के भीतर। 'वह ताकत हासिल करना चाहते थे,' उन्होंने कहा।
भुवनेश चतुर्वेदी, जो वाजपेयी को अच्छी तरह जानते थे। 'दूसरा,
वैज्ञानिक समुदाय तैयार था।' संसद के प्रमुख के रूप में
विदेश मामलों की स्थायी समिति, 1996-98 के बीच, वाजपेयी
सीटीबीटी पर वैश्विक वार्ताओं का बारीकी से अनुसरण किया था और बन गया था
भारत को जल्द से जल्द परीक्षण करने की आवश्यकता के बारे में और भी अधिक आश्वस्त।
और इसलिए, मई 1998 में परीक्षणों का समय सब कुछ निर्धारित करता था।
भारत की सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं से संबंधित होने के साथ-साथ, इसे इस प्रकार भी डिजाइन किया गया था कि यह

अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगियों और उनकी अपनी पार्टी द्वारा उनके खिलाफ आवाजें उठाई गईं।
और इसके वैचारिक मार्गदर्शक, आरएसएस।
वाजपेयी ने 11 मई 1998 को 'बिग बैंग' तकनीक अपनाने का निर्णय लिया।
■

बृजेश मिश्रा, वाजपेयी के सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार,
इस बात पर सहमति बनी कि अटलजी के भी राजनीतिक कारण थे, जिसके चलते उन्होंने यह विकल्प चुना।
उस विशेष मोड़ पर परीक्षण करें।'
वाजपेयी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत तक मिश्रा एक प्रमुख नेता के रूप में उभर चुके थे।
उनका सबसे भरोसेमंद राजदार और समस्या निवारक। उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब
वाजपेयी 1977 में विदेश मंत्री बने और मिश्रा एक आईएफएस अधिकारी थे। मिश्रा 1970 में एक घटना के कारण सुर्खियों में आए थे।
यह घटना तब घटी जब वे बीजिंग में भारत के चार्ज डी'अफेयर्स के पद पर तैनात थे।
मई दिवस समारोह में माओत्से तुंग ने मिश्रा से हाथ मिलाया और एक संदेश भेजा।
भारतीय प्रधानमंत्री को संदेश भेजा गया, जिसमें कहा गया, 'हम इस तरह से झगड़ा जारी नहीं रख सकते।'
हमें फिर से दोस्त बनना होगा।
1970 के दशक में वाजपेयी-मिश्रा का रिश्ता 'औपचारिक' था, लेकिन
‘सौहार्दपूर्ण’—वह प्रकार का संबंध जो आमतौर पर एक नौकरशाह और एक कर्मचारी के बीच होता है
हालांकि, मिश्रा, जो 1991 में भाजपा में शामिल हुए थे, मंत्री के करीबी बन गए।
वाजपेयी ने अगले सात वर्षों के दौरान, जब वे कार्यभार संभाल रहे थे,
1998 तक भाजपा के विदेश मामलों के प्रकोष्ठ में—और अक्सर एक बैठक होती थी।

मैं शाम को वाजपेयी के साथ शराब पीता था। हमारी कई चर्चाएँ हुईं।
मिश्रा ने कहा, 'इससे हम एक-दूसरे के और करीब आ गए।'
वाजपेयी मिश्रा के पिता द्वारका प्रसाद मिश्रा को जानते थे।
वास्तविक राजनीति के दिग्गज अभ्यासी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश में 1960 के दशक के मध्य में। इंदिरा गांधी अक्सर यह मांग करती थीं कि...
प्रधानमंत्री बनने के बाद वरिष्ठ मिश्रा की सलाह।
मार्च 1998 की शुरुआत में, वाजपेयी ने मिश्रा को अपने यहाँ बुलाया। चुनाव
अभी नतीजे घोषित नहीं हुए थे, लेकिन जनमत सर्वेक्षणों में उनकी जीत की भविष्यवाणी की जा रही थी।
वाजपेयी ने मिश्रा से कहा, 'मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रधान सचिव बनें।'
मिश्रा ने उनसे कहा, 'देखिए, मैं 1987 में नौकरशाही से सेवानिवृत्त हुआ था।'
ग्यारह साल बाद आप मुझसे फिर से नौकरशाह बनने के लिए कह रहे हैं।'
वाजपेयी: 'मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं।'
मिश्रा ने वाजपेयी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया: 'आप प्रधानमंत्री को मना नहीं कर सकते,' उन्होंने कहा।
हँसे। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद जिस पहले आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, वह यही था।
मंत्री मिश्रा को अपना प्रधान सचिव नियुक्त करने वाले थे। वह भी
उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। लेकिन वे इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गए।
बहुत जल्दी ही, वह यह समझने लगा कि उसका बॉस क्या करवाना चाहता है और क्या नहीं।
हो गया। वाजपेयी तकनीकी मामलों में माहिर नहीं थे, वे आरामपसंद थे; उन्होंने
उन्होंने सहज, व्यापक दृष्टिकोण वाले निर्णय लिए और छोटी-मोटी बातों को दूसरों पर छोड़ दिया।
मिश्रा ने कहा, 'उनकी सूझबूझ अद्भुत थी। वे छोटी-छोटी बातों को भी बखूबी समझते थे।
यह मेरा काम था। मुझे हमेशा उन्हें (प्रधानमंत्री को) जानकारी देने की आदत थी।

हर सुबह और हर शाम विस्तार से चर्चा करें। यहां तक कि सबसे छोटी से छोटी बात पर भी।

इसलिए, प्रधानमंत्री कार्यालय या राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के कार्यों से उन्हें कभी आश्चर्य नहीं हुआ।

'कर रहे हैं,' मिश्रा ने कहा।

वाजपेयी ने मिश्रा को अपने पास आने की पूरी छूट दे दी थी। वह उनके घर में बिना किसी रोक-टोक के जा सकते थे।

किसी भी समय कमरे में आएं और अधिकारियों के बीच तत्काल निर्णयों को मंजूरी प्राप्त करें।

व्यस्तताओं के मामले में उन्होंने वाजपेयी पर से शासन के बारीक पहलुओं का बोझ कम कर दिया। 'उन्होंने मेरे काम की सराहना की क्योंकि यह एक

राष्ट्रीय हित और उसके (स्वयं के) हित का संयोजन। जब भी कोई

यदि किसी आगंतुक ने वाजपेयी के समक्ष कोई मुद्दा उठाया हो, या कुछ करवाना चाहा हो, तो

PM would tell them, ‘Aap Brajesh se baat kar lo (Please talk to बृजेश)।' जब वाजपेयी मिश्रा के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हुए, तो उन्होंने

वे अस्पष्टता का सहारा लेंगे, 'हम इस बारे में बाद में बात करेंगे।' हालाँकि, अधिक

अक्सर वह काम मिश्रा पर छोड़ देता था। बहुत जल्द, सदस्यों

पार्टी, मंत्री और यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी इसका जिक्र करने लगे।

बृजेश मिश्रा को 'वास्तविक प्रधानमंत्री' के रूप में देखा गया। असल में, वे ही प्रधानमंत्री बने।

सरकार में अनौपचारिक रूप से दूसरे नंबर पर, हालांकि औपचारिक रूप से एल.के. आडवाणी के नाम से जाने जाते हैं।

उन्हें वाजपेयी का उप-प्रधान सचिव माना जाता था। किसी अन्य प्रधान सचिव को यह पद प्राप्त नहीं था।

निर्णय लेने की इतनी खुली छूट कभी किसी को नहीं दी गई—यहां तक कि पी. एन. हक्सर को भी नहीं।

इंदिरा गांधी के शासनकाल में। हालांकि वे मूल रूप से एक नौकरशाह थे, फिर भी उनका

उनका कार्यक्षेत्र व्यापक था। वाजपेयी राजनीतिक मामलों की देखभाल के लिए भी उन पर भरोसा करते थे।
सोनिया गांधी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने जैसे मामलों में वाजपेयी ने ऐसा किया। जब वह सत्ता में थे तब उन्होंने सोनिया गांधी को न तो उकसाया और न ही सोनिया गांधी ने उन्हें, जब वह सत्ता में थे
कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में आई। सोनिया गांधी ने एक बार मुझसे कहा था, 'मैं
वाजपेयी की तरह। मुझे आडवाणी पर भरोसा नहीं है।'
मिश्रा ने स्वयं प्रधानमंत्री के साथ अपने संबंधों का वर्णन इस प्रकार किया:
'सहजीवी'। 'यह अब प्रधानमंत्री और प्रधान सचिव का मामला नहीं रह गया था।
यह पूरी तरह भरोसे का मामला था। उन्हें पूरा यकीन था कि मैं उनके लिए कुछ भी कर दूंगा।
उसे।'
मिश्रा ने एक बार कहा था, 'मैंने एक बार अटलजी से कहा था कि यही मेरा एकमात्र एजेंडा है।'
उन्होंने टिप्पणी की, 'कि इस मामले से किसी भी प्रकार के घोटाले की कोई अफवाह भी नहीं निकलनी चाहिए।'
प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास।' लेकिन उनकी भूमिका इससे कहीं अधिक व्यापक थी।
जैसा कि हम आगे देखेंगे, 'संभावित' घोटालों का प्रबंधन।

आठवीं

6 अप्रैल 1998 को सुबह 7.25 बजे, पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया।
झेलम छावनी में मालूट से दागी गई मिसाइल। हाटफ-V गौरी-I
इस मिसाइल की मारक क्षमता 1,500 किलोमीटर तक थी और यह 700 मिसाइलें ले जाने में सक्षम थी।
इसमें किलोग्राम का वारहेड लगा हुआ था, और इसे पाकिस्तान के मुख्य परमाणु संयंत्र में डिजाइन किया गया था।

ए. क्यू. खान द्वारा स्थापित हथियार प्रयोगशाला।
उस दिन परीक्षण की गई मिसाइल ने 1,100 किलोमीटर की दूरी तय की थी।
गौरी मिसाइल की मारक क्षमता इसे सुदूर शहरों पर हमला करने में सक्षम बनाएगी।
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे भारतीय क्षेत्र।
उस सोमवार की सुबह हुए लॉन्च ने भारत को चौंका दिया। दिल्ली में,
बृजेश मिश्रा को यह खबर टीवी स्क्रीन पर और फिर खुफिया एजेंसियों से मिली। वह आत्मविश्वास से प्रधानमंत्री के कमरे की ओर बढ़े।
वाजपेयी ने संक्षेप में कहा कि भारत को बिना लाग-लपेट के जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को बिना घुमा-फिराए जवाब देना होगा।
झाड़ियों में। या इससे देश का मनोबल गिर सकता है। गौरी के लॉन्च से
वाजपेयी को परीक्षण आगे बढ़ाने का एक कारण मिल गया। वाजपेयी सहमत हो गए।
तुरंत। उन्होंने मिश्रा को वैज्ञानिकों की एक आपातकालीन बैठक बुलाने के लिए कहा।
एनडीए सरकार ने मिसाइल के नाम को एक अतिरिक्त हथियार के रूप में देखा।
पाकिस्तान द्वारा उकसावे के तौर पर इसका नाम मुहम्मद घोरी के नाम पर रखा गया था।
वह फारस के घुरिद साम्राज्य से संबंधित एक मुस्लिम शासक था जो
बारहवीं शताब्दी में हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान पर युद्ध में विजय प्राप्त की।
शताब्दी में। घोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में चौहान को हराया था।
1192.
महज दो हफ्ते पहले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने
वाजपेयी को पत्र लिखकर, उन्होंने सृजन की दिशा में 'अतिरिक्त प्रयास' करने का वादा किया।
‘अच्छे पड़ोसी संबंध’, ‘पुरानी मानसिकता’ से दूर
टकराव। लेकिन 6 अप्रैल को, शरीफ ने सफल घोषणा की।
गौरी के लॉन्च के दौरान उन्होंने कहा, 'भाजपा के सार्वजनिक बयान कि भारत
परमाणु हथियार अपनाने वाले लोग हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हैं।
इंडिया टुडे ने एक पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से कहा कि 'मुख्य उद्देश्य'
गौरी का परीक्षण दिल्ली को यह संकेत देने के लिए किया गया था कि पाकिस्तान उनका मुकाबला कर सकता है।

भारत की परमाणु शक्ति बनने की किसी भी योजना के बारे में। कुछ लोग गौरी को पाकिस्तान का
भारत द्वारा पृथ्वी मिसाइल का उत्पादन शुरू करने पर दिया गया जवाब, जिसकी मारक क्षमता
250 किलोमीटर की दूरी तय करके, इसे 1997 में पाकिस्तानी सीमा के करीब स्टोर कर दिया गया था।
रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस ने इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
गौरी के बारे में। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत इससे कहीं अधिक सक्षम है।
स्वयं की देखभाल करना। '...हमारी समझ यह है कि चीन जननी है
गौरी,' उन्होंने कहा। फर्नांडेस ने आगे कहा, 'सब जानते हैं कि चीन के पास
पाकिस्तान को मिसाइल प्रौद्योगिकी की आपूर्ति की जा रही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर है।
राज्यों को इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाना चाहिए।' पाकिस्तान ने दावा किया कि गौरी
स्वदेशी रूप से उत्पादित। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि
मिसाइल का विकास चीनी तकनीक से किया गया था। भारत में इसकी मांग बढ़ रही थी।
चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु और मिसाइल निर्माण में मदद करने के सबूत
इस कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को पचास से अधिक एम-11 मिसाइलों की आपूर्ति की गई थी।
1992 और 1994 में, और काहुता में यूरेनियम संवर्धन के लिए रिंग मैग्नेट का उपयोग किया गया था। भारत के पास
उन्होंने विशेष रूप से चीनी संलिप्तता का मुद्दा उठाया क्योंकि वे इससे नाराज थे।
गौरी के प्रक्षेपण पर अमेरिका की उदासीन प्रतिक्रिया से नई दिल्ली नाराज थी।
अमेरिका और के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को चिंता के साथ देखा।
चीन में 1997 में चीनी राष्ट्रपति जियांग ज़ेमिन की वाशिंगटन यात्रा के बाद से ही भारत को यह एहसास हो गया था कि वाशिंगटन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कारण गौरी के साथ चीनी संबंध।
उसी वर्ष जून में बीजिंग की आगामी यात्रा।
हालांकि प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपने रुख में अधिक संयम बरता।
गौरी को उनके रक्षा मंत्री से अधिक प्रतिक्रिया मिली। 'परमाणु परमाणु होड़ नहीं होगी'
उन्होंने कहा, 'यह घटना गौरी की बर्खास्तगी के कारण शुरू हुई।'
हालांकि, पर्दे के पीछे, पाकिस्तानी मिसाइल प्रक्षेपण ने हलचल मचा दी।
भारतीय सरकार हरकत में आ गई। गौरी के प्रक्षेपण के कुछ घंटों बाद, एक
चिंतित ब्रजेश मिश्रा ने सुरक्षा रणनीतिकार के. सुब्रमण्यम को बुलाया
परामर्श के लिए।
‘What can we do, Subbu?’ Mishra asked Subrahmanyam.
'हमारी प्रतिक्रिया भी मिसाइल परीक्षण होनी चाहिए,' सुब्रह्मण्यम ने जवाब दिया।
लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं।
सामरिक परमाणु कार्यक्रम की धीमी गति का जिक्र करते हुए
1996-98 तक संयुक्त मोर्चे का दो साल का शासन। 'यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई,'
सुब्रह्मण्यम ने बाद में कहा, 'वे परीक्षा देने जाएंगे।'
गौरी के विमोचन के दो दिन बाद वाजपेयी ने यह बात कही थी।
वैज्ञानिकों ने हरी झंडी दे दी। 'हमने 8 अप्रैल (1998) को आगे बढ़ने का फैसला किया।
बृजेश मिश्रा ने मुझे बताया, ‘परीक्षण किया और वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी।’
(उस दिन)।
■

अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि वाजपेयी ने पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
गौरी के भागने से पहले परमाणु विकल्प का प्रयोग करना। कुछ ही घंटों के भीतर।
पदभार ग्रहण करने के बाद, प्रधानमंत्री ने ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और आर. को

बुलाया था।
चिदंबरम अपने रेस कोर्स रोड स्थित कार्यालय में गए। उनका वहाँ एक आरामदायक माहौल था।
कलाम के साथ संबंध; कलाम उनसे संपर्क बनाए रखने को 'अत्यंत महत्वपूर्ण' मानते थे।
राजनीतिज्ञों। वाजपेयी ने वैज्ञानिकों को पोखरण में परीक्षण स्थल तैयार करने का निर्देश दिया।
थार रेगिस्तान में परीक्षण की तैयारी के लिए। ब्रजेश मिश्रा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे।
बैठक में उपस्थित अन्य व्यक्ति।
वैज्ञानिकों को इस बुलावे की कुछ हद तक उम्मीद थी। भाजपा सहमत हो गई थी।
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण जैसी अपनी मूल प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए,
संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और एक समान नागरिक कानून लागू करना।
कोड को फिलहाल रोक दिया गया है, ताकि अन्य देशों के साथ गठबंधन बनाया जा सके।
उन दलों को भी आपत्ति थी जिन्हें इसके हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे पर आपत्ति थी। लेकिन अपने साझेदारों को परमाणु विकल्प के प्रयोग पर सहमत कराने में कामयाब रहा था।
यह एनडीए के राष्ट्रीय एजेंडा का हिस्सा था।
वाजपेयी द्वारा जारी की गई शासन व्यवस्था की पुस्तक में उन्होंने अपनी सरकार को प्रतिबद्ध किया था।
भारत की परमाणु नीति पर पुनर्विचार करें।
हालांकि प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को औपचारिक मंजूरी नहीं दी थी
इस बैठक के बाद, 'हमें मार्च 1998 के अंत तक सक्रिय कर दिया गया था,' संथानम ने कहा।
खुलासा हुआ। ‘परीक्षा का वास्तविक दिन... प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है... यह ऐसा है जैसे
घर बनाना लेकिन गृह प्रवेश का दिन तय करना
(गृहप्रवेश) के बाद। हम लगभग टी-3 के आसपास थे, यानी तीन

'अप्रैल 1998 के अंत तक, कुछ दिनों का नोटिस।'

■

पोखरण में पहले से ही काफी जमीनी काम हो चुका था—जैसे कि नींव रखना
नियंत्रण कक्ष से शाफ्ट के मुहाने तक जाने वाले केबल 2 किलोमीटर लंबे हैं।
पहले दूर और फिर अंदर। 'हमें (यह करना शुरू करने की) जरूरत नहीं थी।
संथनम ने कहा, 'क्योंकि केबल रेत के नीचे दबे हुए थे, इसलिए खरोंच आ गई थी।'
और (परीक्षण के लिए पिछली तैयारियों से) बरकरार थे। हमें ऐसा करना पड़ा।
बेशक, सभी उपकरणों की जाँच कर लें... केबल बहुत ही अव्यवस्थित स्थिति में थे।
उचित स्थिति।
संथनम ने विस्तार से बताया कि इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने किस प्रकार
1995 में, जब नरसिम्हा राव ने कई सौ किलोमीटर केबल बिछाई थी, तब इस दौरान
यह कार्य किया गया था।
परीक्षण के करीब पहुँच गए थे। 'हमने रात में मोमबत्ती की रोशनी में केबल बिछाई
थी।
1995 में। इसलिए आप इसे कैंडललाइट केबल बिछाने का काम कह सकते हैं, न
कि कैंडललाइट
'रात का खाना,' संथनम हँसते हुए बोला।
उपग्रह मोमबत्ती की रोशनी को तब तक नहीं पकड़ सकते थे जब तक कि मोमबत्तियाँ
जलती हुई न हों।
एक क्रम में जुलूस में देखा गया। शाफ्ट बहुत गहरे थे, उससे भी अधिक।
100 मीटर। 'व्यास 2 मीटर था और हम तीनों नीचे जा सकते थे।
संथनम ने याद करते हुए कहा, 'बाल्टी में शाफ्ट।' जब वे पहुँचे...
नीचे, बाल्टी का दरवाजा खुला और वे शाफ्ट में बाहर निकल सके।
जो एल-आकार का था। 'अंदर बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी आवाज आ रही
थी।'
पानी गिर रहा था। हम हेलमेट और टॉर्च लिए हुए थे,' संथनम ने बताया।
नीचे बेहद उमस थी। थोड़ी सी भी मेहनत करते तो पसीना आ जाता था।

एक सुअर की तरह। वहां तीन क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए थे और
तस्वीरें 2 किलोमीटर दूर स्थित नियंत्रण कक्ष को भेजी गईं।
कभी-कभी, वैज्ञानिकों की निराशा के लिए, रेगिस्तानी चूहे
केबलों को कुतर रहे थे। वैज्ञानिकों को वहां सांप भी मिले, हालांकि
गड्ढे उनकी सुविधा के लिए बहुत गीले थे।
राव के समय में वैज्ञानिकों ने जो सबक सीखे थे, उनमें से एक यह था कि
कक्षा में मौजूद उपग्रहों की जासूसी भरी निगाहों से कैसे बचा जाए। उपग्रहों
रेगिस्तान में कोई भी बदलाव नहीं देखा। 'आप पहले दिन एक तस्वीर लेते हैं और
फिर दसवें दिन, तस्वीरों को एक दूसरे के ऊपर रखें और रद्द कर दें।
'सामान्य बातों को उजागर करो।' अंततः जो नया था, वह यह था कि
तस्वीरें देखी जा सकती थीं। कंप्यूटरों ने इसे 'डिजिटल' विधि से किया।
इमेज प्रोसेसिंग'। 'जब आप टी-3 चरण में हों,' संथानम
उन्होंने समझाया, 'शाफ्टों को भरने का काम एक ही बार में पूरा हो जाना चाहिए।'
अन्यथा रात में ही परिवर्तन का पता चल जाएगा।
'भरने के लिए हमने रेत को इधर-उधर किया और ऐसा दिखाया जैसे वहाँ कुछ खाली
जगह हो।'
रेगिस्तान में रेत के टीले। लेकिन हवा द्वारा निर्मित प्राकृतिक रेत के टीले थे
किसी एक दिशा में झुकने का एक तरीका।
'1998 में हमारे रेत के टीले विपरीत दिशा में थे,' संथानम ने कहा।
व्यंग्यपूर्वक कहा, 'लेकिन जब तक अमेरिकियों को पता चला, तब तक घटना
ऊपर।'
■

मार्च के दूसरे आधे भाग और अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान, जबकि
पोखरण में वैज्ञानिक और इंजीनियर तैयारियां कर रहे थे।
प्रधानमंत्री ने ब्रजेश मिश्रा के साथ विस्तृत चर्चा की।
उन्होंने अपने प्रधान सचिव को बताया कि कैसे वे उनके कार्यकाल के दौरान लगभग
'वह काम' कर ही चुके थे।

1996 में तेरह दिनों की सरकार, और उन्हें पद क्यों छोड़ना पड़ा। इसके विपरीत
1979 तक, वाजपेयी को पूरा विश्वास हो गया था कि एक विश्वसनीय परमाणु निवारक क्षमता मौजूद है।
देश के शत्रु पड़ोसी देशों के साथ युद्धों को रोकने के लिए यह आवश्यक है। और,
बेशक, तुरंत कुछ बड़ा करने की सख्त जरूरत थी।
उनकी सरकार को विश्वसनीयता प्रदान करें।
हालांकि, वाजपेयी इन परीक्षणों के नतीजों को लेकर चिंतित थे।
वैश्विक, भूराजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों पर। मिश्रा ने आश्वासन दिया कि
प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था, जो अब तक की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी,
नरसिम्हा राव वर्षों तक प्रतिबंधों के झटके को सहन कर सकते थे। देश
कंपनी के पास 35 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जिससे उसे आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलती।
व्यापार पर कोई भी अस्थायी प्रतिबंध, जब तक कि अमेरिका इस हद तक न चला जाए
तेल प्रतिबंध लागू होने की आशंका, जिससे परिवहन, ऊर्जा आदि प्रभावित हो सकते हैं।
उर्वरकों का प्रयोग करने से स्थिति असहनीय हो जाती है। लेकिन मिश्रा को लगा कि यह
'बहुत संभावना नहीं'।

मिश्रा ने कहा, ‘मैं चीजों को लेकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाता था।’ वाजपेयी
उन्हें तात्कालिक राजनीतिक नतीजों की ज्यादा चिंता थी।
'हमें यह (परीक्षण) तुरंत करना चाहिए,' मिश्रा ने अपने बॉस से कहा। अगर ऐसा होता तो
उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि अगर देरी हुई तो अमेरिकी दबाव बढ़ाना शुरू कर देंगे।
उन्हें ऐसा कदम उठाने से रोकने के लिए। 'हमें उन्हें एक संकेत देना होगा।'
उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, 'अमेरिकियों को हमें गंभीरता से लेना होगा।' वाजपेयी ने

कहा।
मैं उससे सहमत था।
जानकार लोगों के अनुसार, ज्यादातर लोगों के लिए वह ब्रजेश मिश्रा ही थे जिन्होंने
इस फैसले ने भारत की विदेश नीति में मौलिक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका
निभाई।
नीति। वह न केवल परमाणु निवारक के प्रति प्रतिबद्ध थे, बल्कि 'वह' थे।
के. के अनुसार, परमाणु परीक्षणों के मामले में 'वास्तविक निर्णय लेने वाला' वही था।
सुब्रह्मण्यम। 'यह ब्रजेश मिश्रा ही थे जिन्होंने (इसकी) सफलता में अहम भूमिका
निभाई।
वैज्ञानिक आर. चिदंबरम ने वर्षों बाद खुलासा किया, ‘परीक्षणों के माध्यम से।’
‘इसका श्रेय’
उन्हें यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उन्होंने वाजपेयी की प्रशंसा की।
नरेश चंद्र ने भी सहमति जताते हुए कहा, 'मई 1998 में ब्रजेश ने अहम भूमिका
निभाई थी।'
1998 में, ब्रजेश मिश्रा वाजपेयी के उस निर्णय के प्रमुख समर्थक थे।
परीक्षण। विडंबना यह है कि यह एक अन्य नौकरशाह, उनके विदेश सचिव जगत थे।
सिंह मेहता, जिन्होंने परमाणु परीक्षण का विरोध करने के उनके निर्णय को प्रभावित
किया था।
1979 में मेहता देश की पूर्ण निर्भरता से मुक्ति चाहते थे।
इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान सोवियत संघ के साथ एक नए संबंध की ओर
अमेरिका के साथ—और परिणामस्वरूप चीन और पाकिस्तान के साथ। यह स्थिति थी
मोरारजी देसाई की सोच के साथ-साथ वाजपेयी की सोच से भी मेल खाता है।
उस समय मेहता को लगता था कि उपमहाद्वीप का भविष्य भारत में ही निहित है।
अपने पड़ोसियों के साथ शांति स्थापित करना। उन्होंने वाजपेयी को इस मामले में
'बहुत ग्रहणशील' पाया।
मेहता परमाणु बम के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि अगर भारत
इसका परीक्षण करने से उपमहाद्वीप में हथियारों की होड़ को ही बढ़ावा मिलेगा। यह
एक
इंदिरा गांधी का 1974 में परमाणु परीक्षण करना एक गलती थी।

ऐसा महसूस हुआ, और भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करना भी एक कारण था।
दिलचस्प बात यह है कि जगत मेहता और ब्रजेश मिश्रा दोनों ही एक ही परिवार से थे। विदेश सेवा में, दोनों ने अपनी शुरुआती पोस्टिंग में चीन में सेवा की थी, दोनों
वे अमेरिका के साथ एक नया संबंध स्थापित करना चाहते थे—हालाँकि उनके विचार परीक्षण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। 1998 में, मिश्रा को यह समझ में आया कि
भारत की सुरक्षा स्थिति में बदलाव आ चुका था। यह 'वर्तमान' की बात थी।
या फिर 'कभी नहीं'। एनपीटी को 1995 में अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया था। सीटीबीटी
जिसमें सभी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाया गया था।
सितंबर 1996 में राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव को पारित किया और इसकी पुष्टि की प्रतीक्षा की। भारत ने इसका विरोध किया था।
दोनों समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले, भारत अपने परमाणु विकल्प को खत्म नहीं करना चाहता था। लेकिन भारत के पास अवसर की खिड़की बहुत छोटी थी। अंततः उसे परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे।
यदि सीटीबीटी को अनुमोदित कर दिया गया और शेष विश्व ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो हमें भी इस पर हस्ताक्षर करने होंगे।
योजना यह थी कि भारत इसका परीक्षण करे ताकि वह इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके और फिर समझौते पर हस्ताक्षर कर सके।
सीटीबीटी।
(जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, सीटीबीटी को कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया था, लेकिन मार्च 1998 में)
न तो वाजपेयी और न ही मिश्रा को यह बात पता होगी।
■

वाजपेयी द्वारा परीक्षण का निर्णय लेने के एक सप्ताह बाद, अमेरिकी राजदूत

संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष बिल रिचर्डसन एक दल के नेतृत्व में नई दिल्ली पहुंचे।
प्रतिनिधिमंडल। वह अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दूत के रूप में आए थे। क्लिंटन
मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि वाजपेयी की नई सरकार किस दिशा में जा रही है।
परमाणु मोर्चे पर क्या करने की योजना बना रहे हैं। रिचर्ड फ्रैंक सेलेस्टे, अमेरिका
दिल्ली में राजदूत ने रिचर्डसन को प्रधानमंत्री से मिलवाया। उन्होंने अन्य लोगों से भी मुलाकात की।
ब्रजेश मिश्र व अन्य एनडीए नेता.
जब रिचर्डसन ने जॉर्ज फर्नांडीस को बुलाया, तो उन्होंने बचाव पक्ष से सवाल किया।
मंत्री ने अपने स्पष्टवादिता में कहा, 'जॉर्ज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।'
क्या परीक्षण के दौरान कोई अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे?
'बिल्कुल नहीं,' फर्नांडेस ने भावहीन चेहरे से जवाब दिया। हालाँकि
फर्नांडीस को ठीक से पता नहीं था कि क्या योजना बनाई जा रही है, उन्हें बस एक आभास था।
वाजपेयी इस बात की जांच जल्द ही करेंगे।
वाजपेयी चुनाव से पहले अमेरिकियों को नरम करने की कोशिश कर रहे थे।
परीक्षण इसलिए किए गए ताकि उस प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके जिसके बारे में वह जानता था कि वह बाद में होगी।
चुपचाप, उसने उनके साथ संवाद का एक और माध्यम खोल दिया।
उन्होंने अमेरिकी राजदूत को संदेश भेजा और उनसे जसवंत सिंह से मिलने का अनुरोध किया।
"ऑफ़लाइन"—अर्थात, निजी तौर पर। जसवंत सिंह रूजवेल्ट हाउस गए।
उन्होंने बताया कि यह दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित अमेरिकी राजदूत का आवास है।
सेलेस्टे प्रधानमंत्री का संदेश लेकर आई थी। जसवंत इस मामले में कार्रवाई करेगा।
'वाशिंगटन के लिए एक विवेकपूर्ण—और यदि आवश्यक हो, तो गुप्त—चैनल' के रूप में।
अमेरिकी नेतृत्व संवेदनशील प्रकृति का कोई भी संदेश भेज सकता था।
उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को संदेश भेजा जाएगा। उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया मिलेगी।

उन्होंने वादा किया। उन्होंने यह भी कहा कि इससे किसी भी तरह की 'लीक' होने से भी रोका जा सकेगा।
अमेरिकियों, पाकिस्तानियों और अन्य लोगों के संदेह के बावजूद
अपने राजनीतिक सहयोगियों की जिज्ञासा के बावजूद, प्रधानमंत्री परीक्षणों को गुप्त रखने में कामयाब रहे।
गुप्त रूप से। वाजपेयी और मिश्रा ने इसके प्रसार को रोकने में कामयाबी हासिल की।
जानकारी साझा करने में अत्यधिक कंजूसी बरतकर। और जिन लोगों को उनके पदों के कारण सूचित करना अनिवार्य था, उन्हें बताया गया।
केवल अंतिम क्षण में।
■

जनरल वी. पी. मलिक ने याद करते हुए कहा, 'बृजेश मिश्रा ने मुझे 8 मई को फोन किया था।'
1998 में सेना प्रमुख थे। 'प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं,' मिश्रा ने कहा।
उन्होंने कहा। उस सुबह मिश्रा ने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया था कि समय बीत चुका है।
तीनों प्रमुखों को बुलाकर उन्हें अभी जानकारी देने के लिए आओ। अन्य दो प्रमुख
उन्हें भी इसी तरह के कॉल आए। उन्हें 5, रेस कोर्स पर आने के लिए कहा गया।
अगली सुबह, 9 मई को सड़क पर।
प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री को दी गई अपनी ब्रीफिंग को उस ब्रीफिंग से अलग कर दिया जो उन्होंने स्वयं दी थी।
सेवा प्रमुखों को दिया गया। सेवा प्रमुखों का मानना था कि उनके बॉस,
जॉर्ज फर्नांडीस को परीक्षणों के बारे में उसी दिन बताया गया था।
जब हम (तीनों प्रमुख) पहुंचे, तो ब्रजेश मिश्रा और अब्दुल
जनरल मलिक ने याद करते हुए कहा, ‘कलाम पहले से ही वहां बैठे थे।’ ‘यह था
उन्होंने कहा, 'सुबह करीब 9:30 या 10 बजे।' बिना समय बर्बाद किए,
प्रधानमंत्री ने उन्हें आगामी परीक्षाओं के बारे में सूचना दी। 'आप क्या सोचते हैं?'
उन्होंने प्रमुखों से पूछा, 'हम प्रतिक्रिया के रूप में क्या उम्मीद करते हैं? हमें क्या करना

चाहिए?'
इसके लिए तैयार रहें?
जनरल मलिक एक पृष्ठ का दस्तावेज़ लेकर तैयार आए थे, जिसमें
इसमें इस बात की योजना शामिल थी कि 'हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए...'
जब ब्रजेश मिश्रा ने फोन किया था, तब मुझे पहले से ही अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ है।
इस तरह की बात पर चर्चा की जाएगी।' जनरल मलिक को संदेह था कि...
बहुत जल्द एक परीक्षा होने वाली है। जिन गड्ढों में परीक्षा होगी—
जहां काम चल रहा था, वह सेना की देखरेख में था।
'तब तक मुझे ज़मीनी स्तर से जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी,' जनरल ने कहा।
मलिक ने कहा, 'पोखरान इलाके में जो कुछ भी हो रहा था, सेना की टुकड़ियाँ
हमें उच्च स्तर पर सूचना मिल रही थी। इसलिए मुझे तैयारियों के बारे में पता था।
चल रहा था... आम तौर पर ऐसे मामलों में ज़मीन पर मौजूद कोई व्यक्ति
सेना में भरोसे की बात मानी जाती है...और इस मामले में यह स्थानीय व्यक्ति था।
गठन कमांडर। सैन्य अभियानों के महानिदेशक
(डीजीएमओ) लेफ्टिनेंट जनरल इंदर वर्मा थे और उन्हें यह पद मिल रहा था।
मुझे जमीनी स्तर से जानकारी मिलती थी और कलाम फोन करते थे और
ऐसा कहो कि ऐसा हो जाए।
प्रमुखों से तैयारियों के बारे में पूछने के अलावा, प्रधानमंत्री ने
'ज्यादा कुछ नहीं बोला'। कलाम ने ही ज्यादातर बातें कीं। उन्होंने सरदारों को योजना के बारे में समझाया। 'बृजेश ने भी बात की...।'
ऐसा लग रहा था कि यह अगले दो-तीन दिनों में हो जाएगा...
उस दिन भी हमें सटीक दिन या समय नहीं बताया गया था।
प्रधानमंत्री आवास से निकलने से पहले, डॉ. कलाम ने मुझसे कहा था
कि परीक्षण से चौबीस घंटे पहले, यह आवश्यक होगा कि
खेतोलाई गांव (जनसंख्या: 1,200) के ग्रामीणों को स्थानांतरित करें, जो 5 किलोमीटर दूर स्थित है।
परीक्षण स्थल से किसी वैकल्पिक स्थान पर।' इस कदम के बारे में जनरल मलिक ने कहा।

उन्होंने कहा कि इसे रात में ही बनाना होगा, 'जिसके लिए स्थानीय इंजीनियर रेजिमेंट को
मुझे जानकारी दे दी गई है।
घर लौटने के बाद, जनरल मलिक ने ऑपरेशनल स्टाफ को निर्देश दिए।
पोखरण में किसी भी कार्य के लिए पर्याप्त परिवहन सुनिश्चित करना।
कम समय की सूचना। 'खेतोलाई गांव के निवासियों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता'
यह उम्मीद से पहले, 10 मई को आ गया।
उस दिन जनरल मलिक ने कहा, 'हमने प्रधानमंत्री से इस बारे में बात नहीं की थी।'
पाकिस्तान द्वारा परीक्षण किए जाने की संभावना। मेरे नोट में, या उस दिन हुई चर्चा में,
हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलेगा, हालांकि हमारे पास पहले की खुफिया रिपोर्टों में इस क्षेत्र में पाकिस्तान की क्षमता के बारे में बताया गया था। यह केवल
हमारे विस्फोट के बाद हमने सोचना शुरू किया कि पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है।
परीक्षण आयोजित करें।
जब वाजपेयी ने सेना प्रमुखों को जानकारी दी, तो वे इस बारे में चिंतित नहीं थे।
वह जो कदम उठाने वाला था, उसके दीर्घकालिक परिणाम। उसने केवल
हम उनसे यह जानना चाहते थे कि उन्हें तुरंत क्या करना चाहिए।
■

रक्षा प्रमुखों से बात करने के बाद वाजपेयी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन किया।
राजनीतिक सहयोगी।
प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने राजनीतिक सहयोगियों को दो दिन पहले ही यह बात बता दी थी।
'परीक्षा से पहले, यानी 9 मई को,' ब्रजेश मिश्रा ने मुझे बताया।
जिन लोगों को ‘सूचित’ किया गया था उनमें गृह मंत्री एल.के. आडवाणी, जसवंत

शामिल थे।
सिंह, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और
परीक्षणों के संबंध में प्रधानमंत्री के मुख्य व्यक्ति के रूप में उभरे, रक्षा मंत्रालय
मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा।
मुझे यकीन नहीं है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें परीक्षणों की सही तारीख बताई थी या नहीं।
मिश्रा ने टालमटोल भरे लहजे में कहा। उनका इशारा था कि 9 मई को भी वे ऐसा नहीं कर रहे थे।
उन्होंने परीक्षणों की सटीक तिथि या समय बताया।

शक्ति ने पुष्टि की, '9 मई को दोपहर में एक बैठक हुई थी।'
सिन्हा। 'इसमें प्रधानमंत्री आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीस और अन्य लोग शामिल हुए थे।
जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को छोड़कर बाकी दो सदस्य थे।
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के समक्ष वाजपेयी ने कोई जानकारी न देने का विकल्प चुना।
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक समूह के रूप में—ताकि वह जसवंत को शामिल कर सके
सिंह उनके कार्यक्रम के संचालक होंगे।
वाजपेयी को पता था कि फर्नांडीस बम के खिलाफ थे, और आडवाणी
वह इसके पक्ष में था। उसने शायद यह अनुमान लगाया होगा कि फर्नांडिस अधिक उपयुक्त होगा।
आडवाणी के सामने अपने विचारों को लेकर फर्नांडिस सतर्क थे। लेकिन फर्नांडिस को कुछ आभास हो गया था।
हवा की दिशा। छह दिन पहले उन्होंने एक बयान जारी किया था।
पहले परमाणु हथियारों की संभावना से इनकार नहीं किया जाता था, अब उन्हें स्वीकार कर लिया गया है।
चीन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे 'बिल्कुल हास्यास्पद' बताया।
यशवंत सिन्हा को अलग से सूचित किया गया था—और उन्हें यह बात याद थी।
दिन अच्छा बीता। प्रधानमंत्री के बुलावे पर वे वाजपेयी के घर पहुंचे।
केवल यह कहने के लिए: 'उनके बेडरूम में जा कर मिलिये (उनके बेडरूम में जाओ)'

उससे मिलो)।'
यशवंत सिन्हा ने कहा, 'आप मेरी भावनाओं की कल्पना कर सकते हैं। बेडरूम में...'
jaa ke milne ka kya matlab? Naukri janewali hai zaroor? Ki kuch baat ho
गई है... (बेडरूम में जा रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं
मेरी नौकरी जाने वाली है। कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। ये सब इन्हीं की वजह से हुआ।
मुझे लगा कि मैं उसके बेडरूम में गई थी... बाद में पता चला कि
शयनकक्ष घर का सबसे सुरक्षित कमरा था। वाजपेयी बैठे हुए थे।
वहाँ उसका इंतज़ार हो रहा था। प्रारंभिक शिष्टाचार के बाद, उसने कहा, 'हमलोग येह'
हम लगभग 10 या 11 तारीख को करने जा रहे हैं।
(10 या 11 तारीख को—परमाणु परीक्षण का संकेत देते हुए।) 'मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ।'
क्योंकि अब हमें आर्थिक प्रतिक्रिया के संदर्भ में सोचना होगा।
सामने... आपको इस बात की पूरी तरह से तैयार योजना बनानी होगी कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे।
इसके नतीजों से निपटने जा रहे हैं।'
सिन्हा दंग रह गए। प्रधानमंत्री ने उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई। 'मैं बहुत हैरान था।'
और इस खबर से इतना घबरा गया था,' उन्होंने कहा, 'कि मैंने उनसे यह भी नहीं पूछा, "कौन
क्या आपने मुझे विश्वास में लिया है, अगर मुझे बात करने की जरूरत हो तो मैं किससे बात कर सकता हूँ?
मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा।' सिन्हा ने आगे कहा, 'मुझे इस मामले की गंभीरता का एहसास था।
जो जानकारी उन्होंने मेरे साथ साझा की थी। मुझे यह भी पता था कि
अमेरिकी दबाव के कारण नरसिम्हा राव को परीक्षण करने से रोक दिया गया था।
क्योंकि खबर लीक हो चुकी थी... इसलिए इसे साझा करने का कोई सवाल ही नहीं था।
मैं यह जानकारी किसी के साथ साझा नहीं कर सकता था। मैं मंत्रालय में किसी से

बात नहीं कर सकता था।
मैं वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करके यह नहीं कह सका, “ऐसा होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए?” इसलिए, मैंने इसे अपने तक ही सीमित रखा... मैंने इसे अपने तक ही रखा।
आर्थिक परिणामों के बारे में सोचते हुए, और हम संभवतः क्या कर सकते हैं करना।'
■

ऐसे संकेत मिले थे कि वाजपेयी ने आरएसएस प्रमुख राज्जू को भी अपने साथ लिया था।
भैया को भरोसे में लेकर। जैसा कि हमने देखा है, वह मुसीबत में पड़ गया था।
जसवंत सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त करने की उनकी योजना को लेकर आरएसएस ने उनकी आलोचना की।
अब वह उन्हें अपनी दाहिनी ओर रखना चाहता था। इसलिए उसने उन्हें दे दिया।
आवश्यक न्यूनतम जानकारी। उस सप्ताह, 11 मई 1998 को,
आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र ने बताया कि यह परीक्षा का दिन है।
इसके मुखपृष्ठ पर एक आकर्षक शीर्षक था, 'परमाणु भारत'। इस अंक में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं था।
उनका कहना था कि परीक्षण हो चुके थे। परीक्षण से कुछ घंटे पहले ही यह बाजार में आ गया था।
मुखपृष्ठ पर छपी पट्टी चिल्ला रही थी, 'परीक्षा का समय आ गया है'।
भारत को परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना। हालाँकि, और यह
कहानी का उल्लेखनीय हिस्सा यही था, संस्करण छपकर तैयार हो चुका था।
11 मई को वितरण के लिए, जिसका मतलब था कि आरएसएस के शीर्ष नेताओं को पहले से ही इसकी जानकारी थी।
कि ये परीक्षण बहुत जल्द होने वाले थे।
एक और संकेत जिससे पता चलता है कि आरएसएस के शीर्ष अधिकारियों को इस

बात का अंदाजा था कि इसमें क्या है।
राज्जू भैया का बॉम्बे स्थित बीएआरसी का दौरा कुछ ही दिनों में होने वाला था।
परीक्षा से पहले। आयोजक पत्रिका ने इस यात्रा की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी—वह लेख
उन्होंने 'आरएसएस के सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह' का वर्णन इस प्रकार किया:
एक ‘परमाणु भौतिक विज्ञानी’ जिसने कहा कि भारत को परमाणु शक्ति प्राप्त करनी चाहिए
निवारक। आरएसएस प्रमुख ने कहा, 'हम अपने परमाणु विकल्प को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते।'
BARC में रहते हुए उन्होंने कहा, 'जब चारों ओर हर कोई पूरी तरह से हथियार जमा कर रहा है...'

नौवीं

11 मई 1998 को यशवंत सिन्हा को उनके RAX फोन पर एक कॉल आया।
Singh was on the line. ‘Bhaiya, aap zara paanch number aa jaiye
(भाई, कृपया रेस कोर्स रोड नंबर 5 पर आ जाइए),’ जसवंत ने कहा।
सिन्हा। बंगला नंबर 5 प्रधानमंत्री आवास का हिस्सा था।
‘Kyun (Why)? Ghatna ghat gayi hai kya (Has the event taken
'जगह)?’ सिन्हा ने उससे पूछा। जसवंत सिंह ने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा
सिन्हा ने जॉर्ज फर्नांडीस को भी फोन किया था। वाजपेयी ने व्यक्तिगत रूप से
मैंने आडवाणी को फोन किया और उन्हें आने के लिए कहा।
यशवंत सिन्हा ने बताया, ‘जब मैं वहां गया, तो मैंने पाया कि इसके अलावा
जसवंत सिंह और ब्रजेश मिश्रा की ओर से... आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडीस को भी बुलाया गया था। इसलिए, पूरी कैबिनेट कमेटी को बुलाया गया था।
वहां सुरक्षा व्यवस्था थी।
उनकी मुलाकात पहले सुबह होनी थी। लेकिन बैठक स्थगित कर दी गई।
पोखरण में तेज़ हवाओं के कारण परीक्षणों में देरी हुई थी, इसलिए इन्हें स्थगित कर दिया गया।

हवा गलत दिशा में बह रही थी, और उसे अपने साथ ले जाती।
रेडियोधर्मी विकिरण गांवों की ओर फैल रहा था। यह बुद्ध पूर्णिमा का दिन था।
1974 में जब इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, तब की बात है।
इसका कोडनेम 'स्माइलिंग बुद्धा' रखा गया था।
वाजपेयी उसी सुबह रेस कोर्स रोड स्थित 3 नंबर के घर में रहने चले गए थे;
गृह प्रवेश शुभ समाचार लेकर आता है।
तनावग्रस्त प्रधानमंत्री 900 किलोमीटर दूर रेगिस्तान से खबर का इंतजार कर रहे थे।
दूर।
■

पोखरण में वैज्ञानिकों के लिए दिन की शुरुआत जल्दी हो गई थी।
मई के पहले सप्ताह में बताया गया कि 11 मई को युद्ध-दिवस होगा। के.
मिशन निदेशक संथानम ने याद करते हुए कहा, 'हमें इसे 8 बजे से पहले करना था।'
सुबह लेकिन ट्रॉम्बे के लोग (भाभा से जुड़े वैज्ञानिक)
परमाणु अनुसंधान केंद्र ने पाया कि हवा अनुकूल नहीं थी...
वैज्ञानिक टीम बेसब्री से इंतजार करती रही, जब तक कि उन्हें आखिरकार अनुमति नहीं मिल गई।
आगे। एक बुलंद आवाज के साथ यह बात सामने आई, "अब अनुकूल समय है,"
सार"। संथानम ने आगे जो हुआ उसका वर्णन किया। विस्फोट से पहले
यदि यह प्रक्रिया हो सकती है, तो 'इलेक्ट्रो-रिले' में एक कुंजी डालने की आवश्यकता होगी।
संचालित स्विच। 'यह ऐसा है जैसे आपकी कार की चाबी स्विच में जाती है।'
संथानम ने समझाया। मिशन निदेशक के रूप में, संथानम ने सौंपा
चाबी 'रेंज सेफ्टी ऑफिसर' को दी गई, जिसने फिर यह देखने के लिए चारों ओर चक्कर लगाया कि क्या
परीक्षण के लिए रेंज साफ़ थी। 'मैंने चाबी वासुदेव को सौंप दी, जो कि
रेंज सुरक्षा अधिकारी... उसने इसे डीआरडीओ के एक व्यक्ति को दे दिया जिसने इसे बदल दिया

कुंजी...' संथानम ने आगे कहा, 'ये वस्तुतः चाबियाँ थीं
'परमाणु साम्राज्य।' उस समय वे इस बात पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि वे क्या कर रहे थे।
ऐसा करने से, किसी भी तरह की उत्तेजना महसूस करने का तो सवाल ही नहीं था।
जब विस्फोट हुआ, तो पूरी जमीन ऊपर उठ गई और फिर...
'गिरने से एक गड्ढा बन गया'। जहाँ से वैज्ञानिक कांच के पीछे बैठे थे और
विकिरण रोधक, ऐसा लगा जैसे 'एक हल्की सी गुदगुदी' हो रही हो।
लेकिन जब हमने गड्ढा देखा तब...उत्साह का अनुभव हुआ।
वैज्ञानिकों ने सुरक्षित लाइन से प्रधानमंत्री के नंबर पर डायल किया।
■

रेस कोर्स रोड स्थित 5 नंबर होटल में प्रधानमंत्री सोफे पर बैठे हुए सूचना का इंतजार कर रहे थे।

पोखरण; आडवाणी, फर्नांडीस, सिन्हा और जसवंत सिंह चारों ओर बैठे थे।
खाने की मेज। हंसी-मजाक धीरे-धीरे शांत हो गया था। कोई नहीं बोला। कोई नहीं।
फिर वो कॉल आई जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। एक तनावपूर्ण
पहली घंटी बजते ही ब्रजेश मिश्रा ने फोन उठाया। 'सबसे पहले,
कलाम ने (दिल्ली से) अंग्रेजी में बात की, फिर चिदंबरम ने बात की।
संथनम ने बताया।
'सर, हमने यह कर दिखाया है,' कलाम ने मिश्रा से कहा।
'भगवान आपका भला करे,' एनएसए ने उससे कहा और फोन रख दिया।
इसके बाद के कुछ मिनटों में उस कमरे में बहुत सारे आंसू बहे।
ये राहत के आंसू थे, गर्व की भावना के आंसू थे, और इस बात के आंसू थे कि आखिरकार हमने यह काम कर लिया।
यह। वाजपेयी का चेहरा, जो तब तक गंभीर था, अचानक एक चौड़ी मुस्कान में खिल उठा।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सूचित किया कि भारत
11 मई 1998 को दोपहर 3.45 बजे तीन परमाणु उपकरणों का विस्फोट किया था।

राष्ट्रपति के. आर. नारायणन लैटिन अमेरिका में थे और वापस लौट आए थे।
नारायणन एक दिन पहले ही दिल्ली गए थे। उनके लौटने के तुरंत बाद...
राजधानी में, वाजपेयी राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति भवन गए थे।
अगले दिन वे क्या करने वाले थे, इस बारे में। उन्होंने (परीक्षणों का) समय निर्धारित किया।
इस तरह से कि (राष्ट्रपति) जो लैटिन अमेरिका में थे,
सुब्रह्मण्यम ने बाद में खुलासा किया, 'मुझे दिल्ली वापस जाना होगा, ताकि मैं बच सकूँ।'
विदेश में रहते हुए असहज सवालों का सामना करना पड़ा।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने जसवंत सिंह को के. को फोन करने के लिए कहा।
सुब्रह्मण्यम को बताएँ कि परीक्षण हो चुके हैं। वह
सरकार के बाहर सबसे पहले सूचित किया जाने वाला व्यक्ति। लेकिन तब तक
जसवंत सिंह ने फोन किया, सुब्रह्मण्यम पहले ही सुन चुका था। 'पहला
'मुझे इसके बारे में कृष्णकांत ने बताया था,'
सुब्रह्मण्यम।
एक सप्ताह पहले, वाजपेयी स्वयं कांत को जानकारी देने गए थे।
उपराष्ट्रपति आधिकारिक दौरे पर काहिरा के लिए रवाना हो गए—उन्हें तारीख बताए बिना।
और विस्फोटों का समय।
'Aap jo chahte rahen hain, woh hum karne jaa rahe hain (We are
तुम वही करने जा रहे हो जो तुम लंबे समय से चाहते थे,' वाजपेयी ने कहा।
कांट ने अपने घुमावदार तरीके से।
कृष्णकांत, जिन्होंने खुले तौर पर 'भारत के आगे बढ़ने' के मुद्दे का समर्थन किया था।
'परमाणु' के बारे में प्रधानमंत्री का मतलब समझ गए थे। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। वाजपेयी ने इस पर विस्तार से कुछ नहीं कहा।
'क्या तुमने इसके बारे में सुना है?' कांट ने सुब्रह्मण्यम से पूछा।
'किस बारे मेँ?'
कांट ने कहा, 'परमाणु विस्फोट के बारे में।'

नहीं, मैंने नहीं किया है।
कांट: 'अभी-अभी प्रधानमंत्री ने मुझसे बात की... मैंने यह बात किसी को नहीं बताई है'
अभी तक तो यही है। आप पहले व्यक्ति हैं (जिन्हें मैं बता रहा हूँ)।
'Jo humari baat hui thee kuch din pehle...woh humne kar diya hai
प्रधानमंत्री ने कहा, "(हमने वही किया है जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात की थी)।"
कांट को बताया था।
तब कांट ने सुब्रह्मण्यम से पूछा, 'मैं इसके बारे में क्या कहूँ?'
'अपना मुंह मत खोलो,' सुब्रह्मण्यम ने उपाध्यक्ष को सलाह दी।
जब तक सरकार आपको आधिकारिक बयान नहीं देती, तब तक आपको एक
प्रधानमंत्री से संक्षिप्त जानकारी (कि क्या बोलना है)।
मैंने फोन रख दिया और पांच मिनट बाद फोन फिर बज उठा।
सुब्रह्मण्यम ने आगे कहा, 'वह जसवंत सिंह था।'
उन्होंने कहा, 'मुझे आपको बताना होगा कि हमने एक परमाणु परीक्षण किया है।
मुझे लगा कि इसके बारे में सबसे पहले आपको ही पता चलना चाहिए।
सरकार। परमाणु परीक्षण में थर्मो-न्यूक्लियर परीक्षण (जिसे भी कहा जाता है) शामिल था।
उदजन बम)।'
शुरुआती फोन कॉल की झड़ी के बाद, समूह 5, रेस कोर्स पर इकट्ठा हुआ।
रोड को आगे के कदम तय करने थे। 'हमें यह करना था...'
परिणामों से निपटने और इसकी घोषणा करने के बारे में चर्चा करें...
यशवंत सिन्हा ने याद करते हुए कहा, 'दुनिया।' उन्होंने फैसला किया कि वाजपेयी को वह स्वयं मीडिया को संबोधित करेंगे। वह घोषणा एक अलग स्थान से करेंगे।
रेस कोर्स रोड स्थित 7 नंबर के विशाल लॉन में बने पोडियम पर प्रमोद खड़े थे।
प्रधानमंत्री के राजनीतिक सचिव महाजन—जो तब तक आरसीआर पहुंच चुके थे—
वाजपेयी के पीछे राष्ट्रीय ध्वज लगाने का विचार भी किसने दिया था? यह भी एक गलत विचार था।

अंतिम क्षण में लिया गया निर्णय। यह तय किया गया कि घोषणा इस प्रकार की जाएगी।

वाजपेयी का कार्यकाल संक्षिप्त होगा। ब्रजेश मिश्रा और जसवंत सिंह

उन्होंने इसे शक्ति सिन्हा को लिखवाया, जिन्होंने इसे प्रधानमंत्री के पास पहुंचाया।

वाजपेयी ने इसमें केवल एक शब्द बदला। उन्होंने जानबूझकर उसमें से एक शब्द हटा दिया।

उन्होंने जिस बयान को पढ़ने वाले थे, उसका वर्णन करने के लिए 'संक्षिप्त' शब्द का प्रयोग किया। बयान था...

‘संक्षिप्त’, लेकिन शब्दों के उस्ताद होने के नाते, वे ‘संक्षिप्त’ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते थे।

इसके महत्व को कम करने के लिए। यह भी तय किया गया कि प्रधानमंत्री कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

सवाल। उनके कार्यालय में लगातार फोन बजते रहे। प्रतिनिधियों ने

मीडिया को तुरंत आरसीआर आने के लिए कहा गया।

इसके कुछ ही समय बाद, वाजपेयी अपने आवास से बाहर निकले और चलने लगे।

धीरे-धीरे। वह सीधे पोडियम की ओर बढ़ा जो वीरान खड़ा था।

रेस कोर्स रोड स्थित 7 नंबर के सुव्यवस्थित लॉन, भारतीय तिरंगे के सामने।

जो पृष्ठभूमि का निर्माण कर रहा था। प्रमोद महाजन और शक्ति सिन्हा खड़े थे।

उसके पीछे।

प्रधानमंत्री ने अपना बयान पढ़ना शुरू किया। उनका लहजा गंभीर था।

उनके शब्दों में विजय का कोई भाव नहीं था। उन्होंने मुश्किल से ही ऊपर देखा।

उन्होंने पढ़ा। यह वाजपेयी के स्वभाव के विपरीत था, जिन्हें पढ़ने की आदत थी।

उन्होंने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी। और यह जीवन में एक बार होने वाला अवसर था।

वह जो घोषणा करने जा रहे थे, उसके बाद वाजपेयी ने अपनी बात समाप्त की।

मुड़कर वापस घर में चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।

देखते ही देखते सब खत्म हो गया। प्रधानमंत्री ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनका छह वाक्यों का भाषण...

11 मई 1998 को पत्रकारों को दिया गया बयान संक्षिप्त और सीधा-सादा था।

तथ्य।
आज दोपहर 3:45 बजे भारत ने पोखरण पर्वतमाला में तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। आज किए गए परीक्षणों में एक विखंडन उपकरण, एक कम क्षमता वाला उपकरण और एक ऊष्मापरमाण्विक उपकरण (हाइड्रोजन बम) शामिल थे। मापी गई क्षमताएं अपेक्षित मानों के अनुरूप हैं।
मापों से पुष्टि हुई है कि रेडियोधर्मिता का कोई रिसाव नहीं हुआ।
वातावरण। ये नियंत्रित विस्फोट थे, जैसे मई 1974 में किए गए प्रयोग में। मैं इन सफल परीक्षणों को अंजाम देने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हार्दिक बधाई देता हूं।

जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में उल्लेख किया था, हाइड्रोजन के अलावा
भारत ने परमाणु बम और कम क्षमता वाले विखंडन हथियार का परीक्षण किया।
'सब-किलोटन यील्ड' (1,000 टन टीएनटी के समतुल्य से कम)।
बाद में पश्चिमी वैज्ञानिकों के एक समूह ने भारत के 5-
परमाणु परीक्षणों के लिए किलोटन उत्पादन का अनुमान अधिक लगाया गया था।
दो दिन बाद, 13 मई को, भारत को परीक्षणों का दूसरा दौर आयोजित करना था।
दो सब-किलोटन परीक्षणों में से। इन पांचों परीक्षणों को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था।
प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा, 'भारत अब परमाणु हथियार संपन्न देश है।'
परीक्षणों के तुरंत बाद घोषणा कर दी गई।
इंदिरा गांधी ने 1974 में जैसा किया था, वाजपेयी ने भी उसी तरह की भूमिका निभाने का विकल्प चुना।
इस आयोजन में गिरावट आई। हालाँकि, इसमें महत्वपूर्ण अंतर था।
1974 और 1998। इंदिरा गांधी ने 1974 के विस्फोट को एक
'अंतर्विस्फोट' का उद्देश्य 'शांतिपूर्ण' था। वाजपेयी ने ऐसा न करने का विकल्प चुना।
1998 के परीक्षण को शांतिपूर्ण बताया गया है। न तो उनके 11 मई के बयान में और न ही
उस दिन बाद में जारी किए गए लंबे आधिकारिक पाठ में विस्फोटों को इस प्रकार बताया गया था:

‘शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण’—भले ही भारत की मंशा शांतिपूर्ण हो। दूसरे शब्दों में, भारत शस्त्रीकरण की ओर अग्रसर होगा। वाजपेयी ने भी यही बात कही थी।
सीटीबीटी या एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने के कारण
भेदभावपूर्ण। लेकिन इंदिरा गांधी की तरह वाजपेयी भी इस बात से भलीभांति अवगत थे।
कि आगे अगली और अधिक कठिन चुनौती थी—प्रबंधन की।
विवाद।
■

जैसे-जैसे राजनेता दिल्ली में अपनी चालें चल रहे थे, पोखरण में वैज्ञानिक
उन्होंने चिंतापूर्वक विकिरण स्तरों को मापा। उन्होंने इसके प्रभाव का आकलन किया।
आस-पास के गांवों में विस्फोट हुए। तीन समूह तीन जीपों में सवार हुए।
और वे अलग-अलग दिशाओं में चले गए। वे यह भी देखना चाहते थे कि क्या वहाँ कुछ था।
क्या आस-पास की बस्तियों में बने घरों में कोई दरारें आई हैं?
गांव वाले इतने समझदार थे कि वे समझ गए थे कि कोई बड़ी घटना घटित हुई है।
अभी-अभी एक घटना घटी थी; और यह कुछ पैसे कमाने का मौका था। इसलिए कुछ
उसने कहा, ‘यह गाय और यह ऊंट चल नहीं पा रहे हैं।’ पुलिसवाले ने कहा, ‘…’
फिर समूह उन्हें कुछ धनराशि का भुगतान करता था। 'हमने उन्हें नकद दे दिया।'
और वे खुश थे,’ संथानम ने कहा। दूसरे कहते: ‘अभी कमाल है!’
हुआ है (हमारे घरों में अभी दरारें पड़ गई हैं)। उन्हें भी यह संदेश मिला।
तत्काल मुआवजा।
लेकिन विस्फोटों के तात्कालिक प्रभावों से ही नहीं, बल्कि और भी कई चीज़ों से इसका प्रभाव पड़ा।
निगरानी की आवश्यकता थी। पर्यावरणविद चिंतित थे—
इन परीक्षणों का क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
छह महीने बाद, नवंबर 1998 में, जब पत्रकार कल्पना शर्मा
परीक्षण स्थल से 5 किलोमीटर दूर खेतोलाई गांव का दौरा किया, असंतुष्ट

ग्रामीणों ने उनसे कहा कि वे एक स्वास्थ्य निगरानी केंद्र स्थापित करवाना चाहते हैं।
वहाँ। 1974 के विस्फोट के बाद किए गए एक अध्ययन में वृद्धि देखी गई थी।
पश्चिमी राजस्थान में कैंसर के मामलों में। ग्रामीणों को क्या पता नहीं था
शर्मा ने जोधपुर के विश्वसनीय सूत्रों का हवाला देते हुए लिखा कि उन्हें बस इतना पता था कि वे
चिंता का कारण था—सरकार एक 'गुप्त अध्ययन' की योजना बना रही थी।
परीक्षणों के प्रभाव पर, क्योंकि उसे 'हालिया उछाल से चिंतित होने' की आशंका थी।
बारिश के कारण भूमिगत जलभंडारों में कुछ प्रदूषण हो सकता है।
परमाणु परीक्षण स्थल के आसपास।
मई 1998 के विस्फोटों के पंद्रह साल बाद, घटनास्थल के आसपास के ग्रामीणों ने
पोखरन में कैंसर से होने वाली लगातार मौतों की शिकायत जारी रही। लेकिन अधिकारियों ने
उनकी शिकायतों को 'वैज्ञानिक आधारहीन' बताकर खारिज कर दिया गया।
■

उन्हें मिले फोन कॉल के बाद, सुब्रह्मण्यम ने टाइम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स को फोन किया।
भारत—और उन्हें यह खबर दी। वह संपादकीय मंडल में थे।
वह अखबार के लिए नियमित रूप से लिखता रहता था। वह अभी-अभी घर पहुँचा था।
टाइम्स के कार्यालय से—लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि वह एक लेख लिखने के लिए जल्दी वापस जा रहे हैं।
लेख। एच. के. दुआ अखबार के कार्यकारी संपादक थे। उन्होंने बताया
सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'अगर वे आपको संपादन पृष्ठ पर जगह नहीं देते हैं, तो मैं...'
आपको पहले पृष्ठ पर जगह देंगे।' सुब्रमण्यम का लेख प्रकाशित हुआ।
12 मई 1998 को टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पृष्ठ पर प्रकाशित 'समाचार विश्लेषण'।
शीर्षक ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया: 'भारत अब परमाणु हथियार रखने वाले पांच देशों के क्लब में शामिल हो गया है'
राज्यों के बारे में लिखे उनके लेख को देश भर में और अन्य जगहों पर भी काफी रुचि के साथ पढ़ा गया।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। क्योंकि, समर्थक के सर्वमान्य नेता के रूप में-
भारत के रणनीतिक समुदाय में बम लॉबी, सुब्रह्मण्यम के विचार
रणनीतिक विश्लेषकों और परमाणु अप्रसार संगठनों द्वारा इन पर बारीकी से नज़र रखी गई थी।
पश्चिमी राजधानियों में लॉबियां।
सुब्रह्मण्यम ने अपने लेख में तीन महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। भारत के पास
कंपनी ने घोषणा की कि वह सीटीबीटी में शामिल होगी, और इस प्रकार सभी संभावनाओं को समाप्त कर देगी।
परीक्षण करने के लिए अतिरिक्त विकल्प। (यह उन वर्षों में भारत द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव था।)
परीक्षण के बाद तड़के के घंटों में प्रतिबंधों को कम करने के लिए यह पता चला कि अमेरिका और
पश्चिमी दुनिया इसका कड़ा विरोध करेगी।) दूसरे, उन्होंने दावा किया, भारत
यह एक 'अनिच्छुक परमाणु-हथियार संपन्न देश' था। इसे इसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था।
परमाणु क्लब क्योंकि निरस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ने की उसकी सभी योजनाएँ विफल हो चुकी थीं
परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया था। उन्हें अपने परमाणु हथियार मिल चुके थे।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वैध ठहराया गया, और इसे इसके माध्यम से किया गया
परमाणु अप्रसार नीति का 'बिना शर्त' और 'अनिश्चित' विस्तार
संधि (1995 में)। पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए भारत के पास बहुत कम विकल्प बचे थे।
हाल ही में गौरी मिसाइल का परीक्षण और चल रहे परमाणु और मिसाइल परीक्षण
पाकिस्तान और चीन के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग। तीसरा, उन्होंने कहा
उन्होंने भारत से 'तत्काल' 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' घोषित करने का आग्रह किया। और उन्होंने भारत से यह भी आग्रह किया कि वह भारत को 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' प्रदान करे।
सरकार चीन, रूस और पाकिस्तान को एक संयुक्त अभियान में शामिल होने के लिए

आमंत्रित करेगी।
'प्रथम उपयोग घोषणा नहीं'। वाजपेयी ने आगे के उपयोग पर रोक लगा दी।
एक के बाद एक परीक्षण। लेकिन उन्हें यह घोषणा करने में चार महीने लग गए कि भारत
इसका इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे।
■

जब वाजपेयी अपने भाषण के बाद प्रधानमंत्री आवास में वापस लौटे
रेस कोर्स रोड पर पत्रकारों के सामने घोषणा के बाद, उनके सहयोगी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें इस बारे में चर्चा करनी होगी।
उन्हें आगे क्या कदम उठाने होंगे।
यह तय किया गया था कि वाजपेयी को (अमेरिका को) पत्र लिखना चाहिए।
यशवंत सिन्हा ने खुलासा किया, 'राष्ट्रपति क्लिंटन को बताएं कि यह
हमने परमाणु परीक्षण के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को ध्यान में रखा था।
वाजपेयी ने अगले दिन क्लिंटन को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने चीन का जिक्र किया था।
भारत के परीक्षणों का कारण बताते हुए उन्होंने लिखा, 'हमारे पास एक खुला परमाणु हथियार है।'
हमारी सीमाओं पर स्थित एक राज्य, एक ऐसा राज्य जिसने हमारे विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण किया।
1962 में भारत। हालांकि उस देश के साथ हमारे संबंध सुधर गए हैं।
पिछले एक दशक से, मुख्य रूप से इसके कारण अविश्वास का माहौल बना हुआ है।
सीमा का अनसुलझा मुद्दा।
वाजपेयी ने लिखा कि चीन ने पाकिस्तान को एक 'गुप्त' देश बनने में मदद की थी।
'परमाणु-हथियार संपन्न राज्य', और 'इस कट्टर पड़ोसी' ने 'तीन अपराध' किए थे।
पिछले 50 वर्षों में हुए आक्रमणों के बारे में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने ये आक्रमण किए हैं।
भारत के विभिन्न हिस्सों में 'लगातार आतंकवाद और उग्रवाद' जारी है।
यह आशा व्यक्त करते हुए कि इन परीक्षणों से भारत के संबंधों को कोई नुकसान

नहीं होगा
उन्होंने अमेरिका से कहा, 'हम आपके साथ अपनी मित्रता और सहयोग को महत्व देते हैं।'
हम आशा करते हैं कि आप भारत के प्रति हमारी चिंता को समझेंगे।
सुरक्षा।'
वाजपेयी का क्लिंटन को लिखा पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुआ था।
यह खबर जाहिर तौर पर व्हाइट हाउस पहुंचने के तुरंत बाद लीक हो गई। लीक तब हुई जब...
वाजपेयी सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने
चीन को परीक्षण करने के अपने निर्णय के लिए सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया।
अमेरिका ने भारत के परीक्षण के तर्क की आलोचना की। बाद में ही यह बात सामने आई।
कई वर्षों बाद, हेनरी किसिंजर सहित अमेरिकियों ने यह स्वीकार कर लिया कि
भारत के पास चीन के खिलाफ निवारक उपाय करने का ठोस आधार था। क्लिंटन ने इन परीक्षणों को इस तरह से लिया।
यह एक व्यक्तिगत अपमान था। जब उसने इसके बारे में सुना तो वह 'ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा'।
विदेश नीति सलाहकार और लंबे समय से मित्र रहे स्ट्रोब के अनुसार,
टैलबॉट। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना एक
क्लिंटन प्रशासन की घोषित प्राथमिकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने
दोनों देशों के परमाणु कार्यक्रमों को वापस लेने के लिए 'व्यक्तिगत पहल' की है।
भारत और पाकिस्तान। एक कड़े शब्दों वाले संदेश में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने
उन्होंने भारत से अपने परमाणु कार्यक्रम को 'सीमित करने, वापस लेने और समाप्त करने' का आह्वान किया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया।
13 मई को जब भारत ने दो और परीक्षण किए, तब क्लिंटन
भारत के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। उस समय वह जर्मनी में थे।
अमेरिका ने मानवीय सहायता को छोड़कर भारत को दी जाने वाली सभी सहायता

रोक दी, जिसमें रक्षा संबंधी प्रतिबद्धताएं भी शामिल थीं। अमेरिकी सरकार ने स्पष्ट किया कि वह
विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का भी विरोध किया।
जापान ने भारत को दिए जाने वाले सभी ऋण रोक दिए। जापान ने भी 1 अरब डॉलर से अधिक की सभी सहायता रोक दी।
डॉलर के बदले, जर्मनी ने अपनी सहायता पर रोक लगाने की घोषणा की, जो कि 300 डॉलर थी।
मिलियन, अमेरिका से अधिक था। हालाँकि, फ्रांस ने कहा कि
प्रतिबंधों का कोई मतलब नहीं था। ब्रिटेन और रूस ने भी इसी तरह का कदम उठाया।
हालांकि रूसी प्रधानमंत्री बोरिस येल्तसिन ने अपनी स्थिति व्यक्त की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
भारत से निराशा। चीन की प्रतिक्रिया, जो शुरू में संयमित थी, बाद में तीव्र हो गई।
वाजपेयी द्वारा चीन को परीक्षणों का मूल कारण बताए जाने के बाद।
शुरुआत में, वाजपेयी वैश्विक स्थिति से बहुत निराश थे।
समुदाय की प्रतिक्रियाओं को लेकर उनकी अपेक्षाएँ अलग थीं—हालाँकि उन्हें इसकी उम्मीद थी।
सरकार के प्रमुख सचिवों की तत्काल बैठक बुलाई गई।
भारत से इस स्थिति से निपटने के तरीकों पर उनके विचार जानने के लिए। मोंटेक सिंह
बैठक में मौजूद अहलूवालिया ने कहा कि अगर भारत ने जारी रखा तो
उदारीकरण और अमेरिका के साथ आर्थिक जुड़ाव के साथ,
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को स्वीकार कर लेगा।
वाजपेयी ने ब्रजेश मिश्रा को विश्व की राजधानियों में भेजा ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।
नुकसान। सरकार के सामने तत्काल कार्य था इसे समाप्त करना।
कूटनीतिक अलगाव से बाहर निकलकर, विशेष रूप से अमेरिका के साथ अपने संबंधों को फिर से स्थापित करना।
वाशिंगटन में, अमेरिका में भारत के राजदूत नरेश चंद्र ने भाग लिया।
कुशल कूटनीति; उन्होंने अमेरिकी विचारकों के बीच भारत का दृष्टिकोण प्रसारित

किया।
टैंकों और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने—और इस मांग का खंडन किया कि
भारत ने अब सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए हैं।
■

परीक्षणों के एक दिन बाद, वाजपेयी ने सोनिया गांधी को आमंत्रित किया। उन्होंने उनसे कहा
ये परीक्षण उसकी सास द्वारा अपनाई गई नीतियों की निरंतरता थे।
उन्होंने अपनी पत्नी इंदिरा गांधी और उनके पति राजीव गांधी के बारे में बताया। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि उनकी पत्नी का नाम इंदिरा गांधी और उनके पति राजीव गांधी था।
सहकर्मियों को पता चला कि उसने उस दिन उससे क्या कहा था—कि '1988 का निर्णय'
राजीव गांधी द्वारा (पर्याप्त संख्या में हथियार बनाने के लिए)
इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया था। लेकिन उसे पता था कि राजीव ने अपनी सहमति दे दी थी।
आगे चलकर इसे हथियार बनाने की दिशा में।
शुरुआत में विपक्षी दल असमंजस में थे—अनिश्चित थे।
उन्हें इस बारे में क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस बारे में शुरू में कांग्रेस पार्टी को पता नहीं था।
क्या इन परीक्षणों को उस प्रक्रिया की निरंतरता के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिसकी शुरुआत की गई थी?

इंदिरा गांधी और राजीव वाजपेयी द्वारा आगे बढ़ाए गए विचारों की आलोचना करने के लिए या तो उनकी आलोचना करने के लिए।
सरकार ने परीक्षणों के समय की आलोचना की।
सोनिया गांधी के अलावा, प्रधानमंत्री ने अधिकांश लोगों को जानकारी देने का निर्णय लिया।
विपक्षी नेता व्यक्तिगत रूप से। इसके बाद के महीनों में, जब

जब वाजपेयी पर सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने का दबाव बढ़ता गया, तो उन्होंने फैसला किया
दबाव से बचने में मदद के लिए उन्होंने सीपीआई (एम) नेताओं से बात की। उन्होंने एच. को आमंत्रित किया।
के.एस. सुरजीत और ज्योति बसु, जिन्होंने परीक्षणों की आलोचना की थी, चाय पर आमंत्रित किए गए।
'परमाणु परीक्षणों के बारे में लोग क्या कह रहे हैं?' उन्होंने सुरजीत से पूछा।
बातचीत के दौरान सुरजीत ने जवाब दिया, 'लोग इसका विरोध कर रहे हैं।'
वाजपेयी: 'लेकिन कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है।'
सुरजीत को तुरंत समझ आ गया कि वाजपेयी उनसे एक नई शुरुआत करने के लिए कह रहे थे।
भारत को सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए आंदोलन।
अपने से पहले के अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह, वाजपेयी ने भी इसका इस्तेमाल किया।
विपक्षी नेता सरकार पर बाहरी दबावों को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं।
यह बात उन्होंने इंदिरा गांधी से सीखी थी। बांग्लादेश युद्ध के दौरान, उन्होंने
taunted him. 'Toh, aap log nahi chahete ke Bangladesh azaad ho (So,
आप लोग बांग्लादेश को मुक्त नहीं देखना चाहते।
'Nahi, hum poori tarah se aap ke saath hai (No, we are fully with
वाजपेयी ने बचाव करते हुए जवाब दिया था, 'आप)।'
इंदिरा गांधी ने व्यंग्य करते हुए कहा था, 'मुझे इसके कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।' 'आप नहीं हैं।'
किसी भी प्रकार का आंदोलन खड़ा करना।
बाद में उन्होंने अपने सहायक आर. के. धवन को वाजपेयी के पास भेजा और उनसे अनुरोध किया कि वे
ऐसा माहौल बनाएं जिससे लगे कि इस मुद्दे पर पूरा देश एकमत है।
इसी तरह वाजपेयी ने वामपंथी नेताओं से कहा, 'कुछ जनता

ओपिनियन बनाएं (सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ जनमत बनाएं)।
एक्स

28 मई 1998 को पाकिस्तान ने खूबसूरत वातावरण में पांच परमाणु परीक्षण किए।
पूर्वी बलूचिस्तान में रास कोह पर्वतमाला की ग्रेनाइट पहाड़ियाँ। धूल उड़ने से पहले।
चागाई परीक्षण स्थल पर सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद, 30 मई को इसका छठा विस्फोट किया गया।
अब पाकिस्तान यह दावा कर सकता है कि उसने पांच विस्फोटों से एक अधिक विस्फोट किया था।
ये परीक्षण भारत द्वारा किए गए थे। इन परीक्षणों की घोषणा करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि...
नवाज़ शरीफ़ ने घोषणा की: 'अगर भारत ने बम विस्फोट नहीं किया होता, तो पाकिस्तान
ऐसा नहीं किया होता। एक बार जब नई दिल्ली ने ऐसा कर दिया, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा।
जनता के दबाव के कारण।' इन परीक्षणों ने तनाव को और बढ़ा दिया।
दोनों पड़ोसी देशों पर भी भारत की तरह ही दुनिया ने प्रतिबंध लगा दिए।
पाकिस्तान। जैसे-जैसे सप्ताह बीतते गए, उस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया।
दो नए परमाणु शक्ति संपन्न देशों, भारत और पाकिस्तान से आग्रह किया गया है कि वे तनाव कम करें, संयम बरतें और बातचीत फिर से शुरू करें। चार महीने बाद ऐसा करने का अवसर मिला है।
यह अवसर सामने आया—और वाजपेयी और नवाज शरीफ दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया।
सितंबर 1998 में वाजपेयी और शरीफ एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे।
न्यूयॉर्क शहर में, अपने आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ। दोनों प्रधान मंत्री
संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में भाग लेने के लिए मंत्री शहर में आए थे।
General Assembly. Jaswant Singh, Brajesh Mishra, Shakti Sinha, and
कुछ अन्य लोग भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। पाकिस्तानियों में

वह पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज थे। इसके बिल्कुल विपरीत...
कुछ महीने पहले के तनाव और युद्ध के खतरों के बीच, हंसी-मजाक भी चल रहा था और
उस दोपहर भारतीयों और पाकिस्तानियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध देखने को मिले।
दोनों पक्षों ने अपने देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की।
दोपहर के भोजन की व्यवस्था एक महीने पहले ही कर ली गई थी, जब वाजपेयी और शरीफ
29 जुलाई 1998 को सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी।
कोलंबो। 'हमारी नवाज़ शरीफ़ के साथ एक व्यक्तिगत बैठक हुई थी।'
ब्रजेश मिश्रा ने पुष्टि की, 'कोलंबो में मुलाकात होगी।' दोनों नेता बैठक के लिए सहमत हुए थे।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की चर्चाओं के दौरान न्यूयॉर्क में फिर से। एक समय ऐसा भी आया जब...
दोपहर के भोजन के दौरान, दोनों पक्ष भूमि खोलने पर चर्चा कर रहे थे।
मार्गों के बारे में सोचते हुए, जसवंत सिंह ने अचानक सुझाव दिया, 'बस क्यों नहीं होनी चाहिए?'
दिल्ली से लाहौर?' दोनों प्रधानमंत्रियों ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
बस यात्रा का विचार।
निर्णय यह लिया गया कि अटलजी को पहले बस से लाहौर जाना चाहिए...
वाजपेयी ने तुरंत ही इसकी अहमियत समझ ली... यह सिर्फ इतना ही नहीं था
प्रतीकात्मक... इसका उद्देश्य पाकिस्तान और बस के साथ संबंधों को सुधारना था।
जसवंत सिंह ने कहा, 'यह इसे करने का साधन बन गया, एक जुड़ाव और एक प्रतीक के रूप में।'
उन्होंने कहा, 'नवाज़ शरीफ़ भी सहमत थे क्योंकि यह पंजाब से संबंधित था।'
जहां से वह आया था... इसका मकसद लोगों की कल्पना को आकर्षित करना था।'
वाजपेयी की फरवरी 1999 में हुई ऐतिहासिक लाहौर यात्रा, एक ऐसी घटना थी जो
परमाणु परीक्षणों के परिणामस्वरूप, इसने दो उद्देश्यों की पूर्ति की। यह
पाकिस्तान को सहज महसूस कराने और एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए सोची-समझी रणनीति अपनाई गई।

इसके साथ। इस यात्रा का उद्देश्य वैश्विक समुदाय को यह संकेत देना भी था कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु सुरक्षा उपायों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त परिपक्व थे।
उनकी चिंताओं को दूर करने और उनके मुद्दों को 'द्विपक्षीय' रूप से हल करने के लिए।
लाहौर में वाजपेयी ने मीनार-ए-पाकिस्तान पर, जो पाकिस्तान का प्रतीक है, घोषणा की।
पाकिस्तान की राष्ट्रवाद की भावना, और यह कि एक मजबूत पाकिस्तान भारत के हित में था।
प्रधानमंत्री के मुंह से निकले ये शब्द महत्वपूर्ण थे।
भाजपा से संबंधित, एक ऐसी पार्टी जो लगातार इस विचार को दोहराती रही है कि एक अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश एकीकृत भारत का हिस्सा बन जाएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री विशेष विमान से लाहौर के लिए रवाना हुए।
Vajpayee touch. He said in one of his speeches: 'Yeh loha aur ispaat ki
bus nahi hai. Yeh hamare dono mulko ke awam ke jasbaaton ke baat hai
(यह लोहे और धातुओं से बनी बस नहीं है, यह भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है) हमारे दोनों देशों के लोग।
दुर्भाग्यवश, लाहौर बस यात्रा से उत्पन्न सद्भावना का कोई लाभ नहीं हुआ।
लंबे समय तक चलने वाला। पाकिस्तान ने मई 1999 में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर युद्ध शुरू किया।
हिमालय में। हालांकि पाकिस्तानी पक्ष के बारे में अलग-अलग मत हैं।
शत्रुता शुरू करने के लिए जिम्मेदार था (नवाज शरीफ ने कहा कि वह था)
(हालाँकि इस पर विवाद हुआ है, फिर भी कार्रवाई से अनभिज्ञ) कारगिल युद्ध
ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की थी।
पाकिस्तानी जनरल जिसने सैन्य तख्तापलट में नवाज़ शरीफ को सत्ता से हटा दिया था 1999.
कारगिल के बाद इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण हुआ।
दिसंबर 1999 में कंधार में हुआ हमला और भारतीय सेना पर हुआ आतंकवादी हमला

13 दिसंबर 2001 को संसद में हुई बैठक के जवाब में, भारत ने अपनी सशस्त्र सेना को जुटा लिया। इसके जवाब में, भारत ने अपनी सशस्त्र सेना को सक्रिय कर लिया। ऑपरेशन पराक्रम के तहत नौ महीने तक सीमा पर तैनात बलों ने...
हालांकि वाजपेयी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ को आमंत्रित किया था।
जुलाई 2001 में आगरा में हुई वार्ता में नए आयाम स्थापित करने की उम्मीद थी, लेकिन शिखर सम्मेलन सफल नहीं हुआ।
कोई प्रगति करना।
वाजपेयी को खुद अप्रैल 1999 में जयललिता ने सत्ता से बेदखल कर दिया था।
पार्टी, एआईएडीएमके, वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए का एक प्रमुख घटक थी, लेकिन
उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ हाथ मिलाया और सत्ता से बेदखल कर दिया।
वाजपेयी सरकार ने विश्वास मत के दौरान एक मत से जीत हासिल की।
मध्यावधि चुनाव होने तक अक्टूबर में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे।
उन्हें 1999 में फिर से सत्ता में लाया गया और वे 2004 तक पद पर बने रहे।
विरोधाभासी रूप से, परमाणु परीक्षणों का उद्देश्य संबंधों को बदलना था।
भारत और अमेरिका के बीच—जैसा कि ब्रजेश मिश्रा ने अप्रैल में भविष्यवाणी की थी 1998 में उन्होंने वाजपेयी से कहा था कि परीक्षण करने से अमेरिकियों को मजबूर होना पड़ेगा।
भारत को और अधिक गंभीरता से लें—ठीक यही हुआ।
पिछले कुछ वर्षों में भारत के संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
अमेरिका के साथ।
परीक्षणों के बाद अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, अमेरिकियों ने
उन्होंने सुरक्षा मुद्दों पर भारत से गंभीरतापूर्वक बातचीत करने की इच्छा दिखाई।
अमेरिकियों के लिए, भारतीय परीक्षण 'एक बहुत ही गंभीर खुफिया जानकारी' के रूप में सामने आए थे।
'विफलता', विशेष रूप से इसलिए क्योंकि 'सीआईए के कामों में से एक यह है कि उसे मूर्ख न बनाया जाए'। लेकिन कुछ भारतीय ऐसे भी थे जिन्हें संदेह था कि अमेरिकी विफलता

‘मनगढ़ंत’—ताकि भारत को ‘अपना काम आगे बढ़ाने’ की अनुमति दी जा सके और फिर सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए जा सकें।
वाजपेयी के लिए अमेरिका के साथ संबंध सुधारना उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर था।
जसवंत सिंह को प्रतिनियुक्त किया गया—तब तक उन्हें विदेश मंत्री नियुक्त किया जा चुका था।
अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने के लिए। जसवंत सिंह और
अमेरिकी उप विदेश सचिव स्ट्रोब टैलबॉट उन लोगों में से एक बनने वाले थे।
भारत-अमेरिका की दूसरी कूटनीति के प्रमुख उदाहरण। जुलाई 1998 से आगे,
भारत और अमेरिका ने संकट से निकलने का रास्ता खोजने के लिए अठारह दौर की बातचीत की।
गतिरोध। दोनों व्यक्ति, जो कभी मित्र थे, उनके बीच गहरी दुश्मनी विकसित हो गई।
दोनों पक्षों के बीच अच्छे संबंध थे। भारत के समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद बातचीत समाप्त हो गई।
सीटीबीटी। लेकिन भारत और अमेरिका को एक रणनीतिक समझौते की ओर बढ़ना था।
इसके बाद के महीनों और वर्षों में साझेदारी जारी रही।
■

वर्ष 2000 में, दिल्ली ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल का भव्य स्वागत किया।
क्लिंटन के लिए—जैसा कि लंबे समय से किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति के लिए नहीं किया गया था।
अब क्लिंटन, जो भारत के परमाणु परीक्षणों को लेकर बेहद नाराज थीं,
एक अलग भाषा बोलना। एक अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे।
बाईस साल का अंतराल था, और यह दौरा इस बात का प्रतिबिंब था कि वाजपेयी ने और ब्रजेश मिश्रा ने 1998 के परीक्षणों के बाद उत्पन्न स्थिति को संभाला था।
वाजपेयी के यह स्पष्ट कर देने के बावजूद कि वहाँ
भारत के परमाणु कार्यक्रम को वापस लेने का तो सवाल ही नहीं था।

23 मार्च 2000 को, क्लिंटन की इस महत्वपूर्ण यात्रा के तीसरे दिन, क्लिंटन
उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित किया।
मान्यता प्राप्त संसदीय संवाददाताओं को कवरेज करने की अनुमति दी गई थी।
क्लिंटन को पता था कि सही तरीके से लोगों के दिलों को कैसे छूना है।
श्रोताओं से बात करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया और भारत के 'नेतृत्व' की प्रशंसा की।
उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के हवाले से कहा, 'इस क्षेत्र में।'
उन्होंने सिलिकॉन वैली की उपलब्धियों का उल्लेख किया और उनकी जमकर प्रशंसा की।
भारत की पंचायती राज संस्थाएं और इसकी विकेंद्रीकृत लोकतंत्र प्रणाली।
क्लिंटन के शब्दों से पता चलता है कि उन्हें कितनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें बताया गया था
भारत को कोई भी संदेश पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है: उसे दो हिस्सों में लपेटना।
दो परतें हैं, एक जो उसके अहंकार को संतुष्ट करती है और दूसरी उसके स्वार्थ को।
क्लिंटन के भाषण समाप्त करने और गलियारे से नीचे आने के बाद, हम
पत्रकारों ने निर्वाचित सदस्यों के अभूतपूर्व तमाशे को देखा।
संसद में अचानक बॉलीवुड फिल्मों के प्रशंसकों जैसा व्यवहार शुरू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के गुजरते ही सांसद उनसे हाथ मिलाने के लिए एक-दूसरे पर टूट पड़े।
यह कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कम से कम 300 सांसदों ने ऐसा किया होगा।
उस दिन क्लिंटन से हाथ मिलाया था। 'कई सांसद हाथ नहीं धोते।'
'क्लिंटन की शैली को बरकरार रखने के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा,' एक व्यक्ति ने चुटकी लेते हुए कहा।
इसके बाद युवा सांसद ने अनादरपूर्वक टिप्पणी की।
भारत की विदेश नीति का आधार रही अमेरिका-विरोधी भावना
शीत युद्ध के वर्षों के दौरान उत्पन्न हुई स्थिति 1998 के बाद समाप्त होने लगी थी।
2000 में जब क्लिंटन सत्ता में आईं, तो भारतीय सांसद एक स्पष्ट संकेत थे।

देश में जो बदलाव हो रहा था।
क्लिंटन की यात्रा ने भारत-अमेरिका संबंधों के लिए एक नया ढांचा प्रदान किया।
साझेदारी; यह इस बात की स्वीकृति थी कि भारत को अब देखा जा रहा है।
एक अलग दृष्टिकोण से—एक उभरती हुई शक्ति जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।
ब्रह्मा चेलानी के अनुसार, परमाणु परीक्षण पर 'भारत का दांव' सफल साबित हुआ।
रणनीतिक मामलों के स्तंभकार को यह बात इंगित करनी थी।
यह दौरा भारत-अमेरिका संबंधों में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।
यह उस नीतिगत बदलाव का अग्रदूत था जो आगे चलकर होने वाला था।
जॉर्ज डब्ल्यू बुश का संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यकाल (2001-09)।
उनके कार्यकाल के अंत में, जब वाजपेयी जनवरी में वाशिंगटन डीसी गए थे।
2004 में, अमेरिकी स्तर पर पहले से ही पुनर्विचार हो रहा था। भारत और
अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी में अगले कदम (एनएसएसपी) की घोषणा की,
अंतरिक्ष, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी और नागरिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग—
हालांकि उस समय यह केवल 'नियामक और सुरक्षा मुद्दों' तक ही सीमित था।
2005 में, मनमोहन सिंह ने एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जिसके परिणामस्वरूप दो
भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश—जिसके कारण
रिश्ते को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले गया। इसके परिणामस्वरूप अरबों डॉलर का लाभ हुआ।
व्यापार, और बढ़ती रक्षा साझेदारी, अन्य बातों के अलावा—और था,
सी. राजा मोहन के अनुसार, इसका 'सबसे बड़ा परिणाम' यह है कि...
1998 के परीक्षण। 'केवल हमारे परमाणु शक्ति बनने से ही अमेरिकी हार मान गए।'
'अगर भारत हमारे साथ चलने को तैयार होता तो ऐसा नहीं होता।' ऐसा तब नहीं होता, अगर भारत ने ऐसा किया होता।
'परदे से बाहर नहीं आया' और उसने घोषणा की कि उसके पास हथियार हैं।

ग्यारहवीं

11 मई 1998 को परीक्षणों पर प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मुझे
मैं रेस कोर्स रोड से नॉर्थ ब्लॉक की ओर जा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं पकड़

लूंगा।
आडवाणी से परीक्षणों पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए। वे मुझसे मिलने के लिए सहमत हो गए—और हम
उन्होंने अनौपचारिक बातचीत की। मुझे लगा था कि वह बेहद उत्साहित लोगों से घिरे होंगे।
पार्टी के सदस्य इस अवसर का जश्न मना रहे थे। लेकिन वह उस विशाल कमरे में बिलकुल अकेले बैठे थे, जिसका इस्तेमाल कभी भारत के लौह पुरुष वल्लभभाई पटेल किया करते थे।
वह उनका अनुकरण करना चाहता था, और उनकी तस्वीर उनके पीछे की दीवार पर लगी हुई थी।
आडवाणी प्रसन्न नहीं बल्कि गंभीर दिख रहे थे। जैसे-जैसे वे बात करते गए, उनका चेहरा गंभीर होता गया।
भावुक। मुझे यह बात अजीब लगी कि वह परमाणु के बारे में कम बात क्यों करता है। हालांकि उन्होंने पार्टी की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को याद किया कि वह परीक्षण करेगी।
एक बम—और पार्टी को सफल बनाने के लिए वर्षों से उनके संघर्षों के बारे में और भी बहुत कुछ।
मुख्यधारा की ताकत। उन्होंने शुरुआती वर्षों को भावुकता से याद किया जब वह और वाजपेयी ने भाजपा की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने ऊपर हुए तीन जानलेवा हमलों के बारे में बताया था।
कुछ महीने पहले, 14 तारीख को कोयंबटूर में उन पर हुए हमले के बारे में बात करते हुए
फरवरी 1998 में हुई एक घटना में वे बाल-बाल बचे थे। आडवाणी एक भावुक व्यक्ति हैं।
और जैसे-जैसे वह उस दिन की घटनाओं के बारे में सोचने लगा, उसकी आंखों में आंसू भर आए।
उस शाम मुझे यह एहसास हुआ कि आडवाणी आहत थे—कि वाजपेयी
परमाणु विकल्प का प्रयोग करने जैसा एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, लेकिन
जब यह घटना घटी, तब वह उस निर्णय को तैयार करने में शामिल नहीं थे, जिसके

लिए
आडवाणी और पार्टी आधी सदी से प्रतिबद्ध थे। वे
केवल सूचित किया गया, परामर्श नहीं किया गया—और अंतिम समय तक उन्हें किसी भी बात से अनजान रखा गया।
वह क्षण। वाजपेयी ने 'एक अधिकारी पर भरोसा करने' का विकल्प चुना था, जैसा कि आडवाणी ने देखा था।
बृजेश मिश्रा, न कि वह, जो चार दशकों से उनके राजनीतिक साथी हैं।
खड़े हुए।
1984 के बाद, जब पार्टी के पास केवल 2 लोकसभा सीटें रह गई थीं
वाजपेयी के नेतृत्व में, पार्टी का नेतृत्व आडवाणी ने किया था। लेकिन
1998 में, भाजपा के गठन के बाद पहली बार, वह पार्टी का हिस्सा नहीं थे।
वह आंतरिक समूह जिसने परमाणु परीक्षण जैसे बड़े फैसले लिए।
आडवाणी खुद को वाजपेयी की तरह ही भाजपा का निर्माता मानते थे।
मुझे यह आभास हुआ है कि यद्यपि वे भारत के गृह मंत्री थे, अब वे
अब मैं दूसरे नंबर पर नहीं रहूंगा।
11 मई 1998 को आडवाणी का अधिक मुखर रूप सामने आया—हालांकि
उनके और वाजपेयी के बीच मतभेद तभी खुलकर सामने आने वाले थे जब...
कुछ साल बाद। जबकि 1998 के टेस्ट मैचों ने भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर पहुँचा दिया।
परमाणु हथियार संपन्न देशों की तालिका ने उनके भीतर तनाव पैदा कर दिया।
सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा—जिनके साथ वाजपेयी कम सक्षम थे
प्रबंधन करना, और जो प्रधानमंत्री के लिए समस्याएं पैदा करने वाले थे
2001-02। सबसे बढ़कर, उन्होंने वाजपेयी-अडवानी के रिश्ते को फिर से परिभाषित किया।
वर्षों की सौहार्दपूर्ण सहभागिता पर एक लंबी छाया डालते हुए,
दोनों पुरुषों के बीच हमेशा से ही सौहार्दपूर्ण संबंध रहे थे। तब तक, जब भी मतभेद होते थे,
अगर वे उठते, तो वे मिलते, बात करते और खतरे के कगार से वापस लौट आते।
11 मई 1998 को नॉर्थ ब्लॉक से निकलते समय मेरे मन में एक अवर्णनीय भावना

थी।
ऐसा आभास होता था कि आडवाणी को लगता था—हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा—कि उनका
उस 'बड़े क्षण' में योगदान को स्वीकार नहीं किया गया था
वाजपेयी।
■

जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब यह स्पष्ट था कि सभी व्यावहारिक
उद्देश्यों के लिए, ब्रजेश मिश्रा को यह पदभार ग्रहण करना होगा।
दो पदों पर। वे न केवल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।
सुरक्षा सलाहकार होने के नाते, वह सभी सुरक्षा मामलों का ध्यान रखता था और मेरा दोस्त बन गया था।
और वाजपेयी के साथी थे। वे अक्सर उनके साथ पेय साझा करते थे।
शामें।
वाजपेयी के पालक परिवार की तरह—उनकी वर्षों की साथी, राजकुमारी
कौल, दत्तक पुत्री नमिता और दत्तक दामाद रंजन
Bhattacharya, and their daughter Niharika—Brajesh Mishra started to
वाजपेयी की देखभाल करना। 'जब परिवार बाहर होता था, तो ब्रजेश या मैं'
'शाम को उसकी देखभाल करना,' अशोक सैकिया ने एक बार मुझसे कहा था। सैकिया
प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और राजकुमारी कौल के परिवार के मित्र।
वाजपेयी के लिए प्रधानमंत्री होने का मतलब था निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होना।
उन्हें आडवाणी या आरएसएस के शीर्ष नेताओं का उन पर दबाव बनाना पसंद नहीं था।
गर्दन। मिश्रा में वाजपेयी को अपनी तलवार और ढाल दोनों मिल गए थे।
इससे मिश्रा और आडवाणी के बीच टकराव और भी तेज हो गया।

that followed. Advani had wanted Vijai Kapoor, not Brajesh Mishra, to
उन्हें प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाया जाए। पार्टी के सहयोगियों ने
आडवाणी से कहा कि नंबर दो होने के नाते, निर्णयों में उनकी भी राय होनी चाहिए।
शीर्ष पर। लेकिन वाजपेयी ने कपूर को खारिज कर दिया। ब्रजेश के अनुसार।
मिश्रा ही उनके बीच समस्या की शुरुआत थी।
उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि उनके बीच 'समस्याएं' थीं। 'अडवानी
अचानक मुझे पता चला कि वाजपेयी पर मेरा काफी प्रभाव है और उन्हें यह पसंद नहीं आया।
मंत्री और सचिव ब्रजेश मिश्रा से मिलने गए, उन्हें लगा कि...
प्रधानमंत्री ने उन्हें सत्ता सौंपी थी। मिश्रा
उन्हें बताएं कि वह 'अतालजी से बात करेंगे और (फिर) देखेंगे'।
बृजेश मिश्रा ने कहा, 'अडवानी को यह पसंद नहीं आया। न ही जसवंत सिंह को।'
उन दोनों ने मिलकर अटलजी को मुझे पद से हटाने के लिए मनाने की कोशिश की।
मिश्रा ने कहा, 'इन दो पदों में से एक। या तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या प्रधान सचिव।'
आरएसएस ने भी हस्तक्षेप किया।
लेकिन अटलजी अपने रुख पर अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, 'अगर वह जाएगा तो मैं भी जाऊंगा।'
एक समय वाजपेयी ने मिश्रा को आडवाणी से मिलने और उनके बीच के मतभेदों को सुलझाने के लिए कहा था।
मतभेद। उन्होंने आडवाणी के साथ 'दो लंबी बैठकें' कीं। आडवाणी,
मिश्रा के अनुसार, उन्होंने यह कहकर शुरुआत की, 'मैं एक साधारण घर नहीं हूँ।'
मंत्री।'
मुझे पता है कि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया बताएं।
मिश्रा ने आडवाणी से कहा, 'समस्या यह है कि आप उनसे (वाजपेयी से) क्यों नहीं मिलते?'
सप्ताह में एक बार उसके साथ दोपहर का भोजन करें और बातों पर चर्चा करें। आप

जानते हैं
एक दूसरे के साथ चालीस से पचास साल तक।
आडवाणी: 'अगर हम दोपहर का भोजन करेंगे तो न तो वह बात करेंगे और न ही मैं बात करूंगा।'
आप भाजपा में इकलौते व्यक्ति हैं जो दिन में फोन उठा सकते हैं।
'या रात को उसे फोन करो,' मिश्रा ने जवाब दिया। 'ऐसा करो, यह सोचने के बजाय कि मैं
मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो आपके विचार से उचित नहीं है।
मिश्रा ने यह बातचीत वाजपेयी को बताई। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला।
मध्यस्थता के प्रयास। 1997 में हवाला मामले में बरी होने के बाद,
आडवाणी को भी लगता होगा कि शीर्ष पद पर उनका उतना ही अधिकार है जितना कि
वाजपेयी।
■

अप्रैल 1999 में, परमाणु परीक्षणों के लगभग एक साल बाद, वाजपेयी के
सरकार गिर गई। अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव में उन्हें सिर्फ 1 वोट से हार का सामना करना पड़ा।
1999 में, अक्टूबर 1999 में उन्हें फिर से सत्ता में चुना गया, उस समय उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी।
सर्वकालिक उच्च स्तर। उन्हें कारगिल युद्ध से उतना लाभ नहीं हुआ।
वोट। देश भर में यात्रा करते समय मुझे पता चला कि यह उससे कहीं अधिक था।
चुनाव, लोगों की उनके प्रति सहानुभूति। कई लोगों को लगा कि वह
सोनिया गांधी, जयललिता और अन्य लोगों द्वारा अन्याय किया गया और सत्ता से बेदखल किया गया।
सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें हराने के लिए हाथ मिलाया था।
2001 तक उत्साह धीरे-धीरे कम होने लगा था। आरएसएस के समर्थन से आडवाणी सत्ता में आए।

उच्च अधिकारियों ने प्रधानमंत्री पर दबाव बनाए रखा। स्थिति चरम पर पहुंच गई।
2002 में, दोनों नेताओं के बीच अविश्वास का स्तर लगातार बढ़ता गया।
सत्ता के गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि वाजपेयी कहीं और जा सकते हैं।
जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होने के समय राष्ट्रपति भवन मौजूद था।
2002 में आडवाणी ने उनकी जगह ली। आरएसएस के एक नेता ने उनसे मुलाकात भी की।
वाजपेयी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया—जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वर्ष 2002 में वाजपेयी की लोकप्रियता में स्पष्ट गिरावट देखी गई। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।

सत्ता को तब करारा झटका लगा जब एक प्रभावशाली और मुखर आडवाणी सत्ता में आई।
आगे आना।
उन दिनों आडवाणी जिस तरह से व्यवहार करते थे, उनके शब्द, उनका
उनका व्यवहार, शारीरिक हावभाव, उनकी हर चीज एक विशेष प्रकार की भावना को दर्शाती थी।
उन्हें पूरा भरोसा था कि वे जल्द ही प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लेंगे।
उस वर्ष के तीन प्रकरणों ने बदले हुए समीकरणों का प्रतीक प्रस्तुत किया।
दोनों व्यक्ति। फरवरी के अंत में गुजरात में गोधरा हत्याकांड के बाद और
मार्च 2002 की शुरुआत में, वाजपेयी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे राजधर्म का पालन करें, दूसरे शब्दों में, इस्तीफा दें। लेकिन आडवाणी, युवा
भाजपा नेताओं के एक समूह और आरएसएस नेतृत्व ने मोदी का समर्थन किया। वाजपेयी ने
पार्टी की राष्ट्रीय बैठक के गोवा सम्मेलन में अपने पद से पीछे हटने के लिए।
अप्रैल 2002 में कार्यकारी अधिकारी। एक हफ्ते बाद वह इसके लिए स्पष्टीकरण दे रहे थे।
मोदी के कार्यों।
जून 2002 की शुरुआत में, टाइम पत्रिका ने एलेक्स पेरी द्वारा लिखित एक लेख प्रकाशित किया।

वाजपेयी। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में 'शराबी' प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है।
सरकार। पेरी का मुखबिर कौन था, इस बारे में सच्चाई जो भी हो,
शक्ति सिन्हा के अनुसार, वाजपेयी खेमे ने इसे 'प्रतिकूल साजिश' के रूप में देखा।
आडवाणी की ओर से यह कार्य संपन्न हुआ। हालांकि गृह मंत्रालय ने एक दिखावे के तौर पर ऐसा किया।
अस्वीकृति के कारण पेरी को अपना वीजा विस्तारित करवाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा, यह
इससे वाजपेयी के लिए स्थिति और भी खराब हो गई। इससे उनकी छवि प्रतिशोधी के रूप में उभरने लगी।
लगभग उसी समय, इस बात को लेकर भी हलचल मची हुई थी कि कौन होगा
के. आर. नारायणन का कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया।
जुलाई 2002। वाजपेयी चाहते थे कि कृष्णकांत अगले राष्ट्रपति बनें।
भारत के। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कांत का समर्थन करने पर सहमति जताई थी।
दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चाओं के बाद नाम को अंतिम रूप दिया गया।
बृजेश मिश्रा और नटवर सिंह के नेतृत्व में। वाजपेयी स्वयं वहां गए थे।
कांट से मिलें। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर सूचित किया कि
एनडीए और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए उनका समर्थन करेंगे—क्योंकि
वे 6, मौलाना आजाद रोड स्थित मकान के पीछे वाले बरामदे में बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन
वाजपेयी को आडवाणी और भाजपा नेताओं के एक समूह और आंध्र प्रदेश के नेताओं ने पीछे छोड़ दिया।
जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। वाजपेयी को इस बात से बहुत ठेस पहुंची कि वे राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए।
भारत के प्रधानमंत्री को इस बात में भी कोई दखल देने का अधिकार नहीं था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा।
गणतंत्र के राष्ट्रपति।
Ten years later, Brajesh Mishra said on Krishan Kant’s tenth

death
anniversary, ‘Humne toh kar diya thaa… Yeh to Advani ne garbar kar
डी थी (हमने सब कुछ स्पष्ट कर लिया था, आडवाणी ने ही गड़बड़ की थी)
योजना)।'
2002 के मध्य में वाजपेयी ने शांति के लिए बातचीत करने का फैसला किया। उन्होंने चुना
मैंने फोन उठाया और आडवाणी को डायल किया। ‘कमलाजी को बता दीजिए, मैं दोपहर के भोजन के लिए आ रहा हूँ।’
और वे सिंधी कढ़ी खाएंगे,’ उन्होंने कहा। उनकी मुलाकात चार घंटे तक चली।
गिलाए-शिकवाए पर चर्चा हुई और अंततः एक युद्धविराम समझौता हो गया।
वाजपेयी ने 29 जून 2002 को आडवाणी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
आरएसएस काफी समय से इसकी मांग कर रहा था।
According to Brajesh Mishra, Vajpayee had deferred to the RSS—Rajju
उस समय भैया आरएसएस प्रमुख थे और उन्होंने आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया।
वाजपेयी आडवाणी और आरएसएस के सामने लगातार झुकते रहे; आखिरी हद तब पार हो गई जब...
2004 में समय से पहले आम चुनाव की घोषणा के साथ।
2003 की सर्दियों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद, जब भाजपा ने ऐसा किया
उत्तर भारतीय राज्यों में, आडवाणी ने भाजपा नेताओं के एक समूह का नेतृत्व किया।
वाजपेयी के साथ एम. वेंकैया नायडू भी थे।
Pramod Mahajan, and Ananth Kumar. Except Murli Manohar Joshi,
समूह में अधिकांश अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद थे। उन्होंने पूछा
उन्हें अगले आम चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाने के लिए कहा गया, जो होने वाले थे।
अक्टूबर 2004 में यह घटना घटी। ऐसा माना जा रहा था कि आडवाणी पदभार संभालेंगे।

चुनाव के बाद प्रधानमंत्री। वाजपेयी सहमत हो गए।
‘आप इसके लिए क्यों सहमत हुए?’ नाराज मिश्रा ने वाजपेयी से सवाल किया।
‘यह एकमात्र ऐसा समय था जब मैंने यह बात अटलजी से कही थी।’
‘पूरी पार्टी मेरे पास आई है, मैं क्या करूं?’ निराश वाजपेयी ने पूछा।
मिश्रा को बताया।
लेकिन आडवाणी की योजना उल्टी पड़ गई। भाजपा 2004 में हार गई। कांग्रेस गठबंधन सरकार का गठन किया। 'अगर आडवाणी ने इंतजार किया होता...'
बृजेश मिश्रा ने बाद में कहा, 'अक्टूबर तक (निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव के लिए)।'
'शायद हालात अलग होते।'
वाजपेयी के लिए यह अंत था। उन्होंने आडवाणी को अपना उम्मीदवार घोषित किया।
2005 में मुंबई के शिवाजी पार्क में हुई एक बैठक में उत्तराधिकारी का चयन किया गया।
उन्हीं आधारों पर आडवाणी ने वाजपेयी को भाजपा के शीर्ष नेता के रूप में पेश किया था।
दस साल पहले मंत्री पद के उम्मीदवार।
आडवाणी उस शीर्ष पद तक नहीं पहुंच पाए जिसकी उन्हें लंबे समय से चाह थी।
2009 में प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी असफल रही। हालांकि पांच वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद
वर्षों में, कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या 145 से बढ़ाकर 206 कर ली। वाजपेयी सूर्यास्त की ओर चल पड़ा। आडवाणी भी उन अंधेरों में चले गए जो थे।
तेजी से लंबाई बढ़ रही है।
वाजपेयी ने परमाणु हमले के दुष्परिणामों को सफलतापूर्वक संभाला था।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। लेकिन पोखरण द्वितीय ने उनकी सरकार और भाजपा के भीतर पहले से ही जटिल स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया।
जिसे संभालना अधिक कठिन था।
बारहवीं

क्या अटल बिहारी वाजपेयी एक अतिरंजित प्रधानमंत्री थे? कुछ लोग शायद ऐसा कहेंगे।
यदि उनके प्रधानमंत्रित्व काल की उपलब्धियों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाए तो उत्तर 'हाँ' होगा।
कार्यकाल।
वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल को निश्चित रूप से इन बातों के लिए याद किया जाएगा:
उन्होंने परमाणु परीक्षण किए, जिससे भारत परमाणु शक्ति वाले देशों की बड़ी लीग में शामिल हो गया।
'हैव' राज्यों। और फिर भी, विडंबना यह है कि वह स्वयं उन्हें ऐसा नहीं मानते थे।
उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। वास्तव में, उन्होंने परीक्षण का श्रेय खुद को दिया।
इसे नरसिम्हा राव को दिया जाना चाहिए। 'राव ने मुझे बताया था कि बम तैयार है।'
उसने कहा, 'मैंने तो बस इसे विस्फोटित किया था।'
वाजपेयी ने भी उदार आर्थिक नीतियों का पालन किया, लेकिन फिर भी वे
राव द्वारा भारतीय बाजार खोलने के दौरान दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना ही एकमात्र रास्ता है।
1991 में अर्थव्यवस्था। वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल का अधिकांश हिस्सा एक कहानी थी।
कठिन बीस-दलीय गठबंधन में निहित संघर्षों का प्रबंधन करना।
नेतृत्व किया।
वह स्पष्ट रूप से एक सक्रिय प्रशासक नहीं थे—उनकी रुचि अधिकतर इसमें थी
बड़े-बड़े फैसले लेना। उन्होंने फैसले लेने के बुनियादी पहलुओं को छोड़ दिया।
बृजेश मिश्रा को संबोधित करते हुए। दिलचस्प बात यह है कि वाजपेयी बनना चाहते थे।
कश्मीर समस्या को सुलझाने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें अधिक याद किया जाता है।
भारत-पाकिस्तान संबंधों में नरमी लाने और स्थायी संबंध स्थापित करने के उनके प्रयासों में

उपमहाद्वीप में शांति।
उन्होंने 1999 में अभूतपूर्व लाहौर यात्रा का नेतृत्व किया।
दोनों देशों के बीच सद्भावना है। लेकिन, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, पाकिस्तानी सेना ने कारगिल युद्ध के साथ जवाब दिया। उसके सैन्य नेतृत्व ने नागरिक सरकार के संबंधों को सुधारने के फैसले का समर्थन नहीं किया।
भारत। कारगिल की घटना के बावजूद, वाजपेयी ने एक और प्रयास किया ताकि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण प्रगति हुई और आगरा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
2001 में यह सफल नहीं हुआ। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे मुरासोली मारन के अनुसार,
कैबिनेट के सदस्य ने बाद में निजी तौर पर खुलासा किया कि आडवाणी ने ही इस प्रस्ताव को खारिज किया था।
अंतिम बयान जिसे अंतिम रूप देने के लिए काफी मेहनत की गई थी।
वाजपेयी ने कश्मीर विवाद को सुलझाने के प्रयास किए—एक ऐसा मुद्दा जो
यह उनके दिल के बेहद करीब था। अप्रैल 2003 में, उन्होंने तीन शब्दों की घोषणा की।
कश्मीर समस्या का समाधान—कि यह एक भावना के माध्यम से था
'Kashmiriyat, Insaniyat, Jamooriyat (Kashmiri identity, democracy, and
मानवता के नाम पर एक समाधान निकाला जा सकता है। ये शब्द उर्दू में उस पार्टी के नेता ने कहे जो अपनी हिंदू और हिंदी पहचान के लिए जानी जाती है।
यह एक ऐसा विचार था जिसे केवल वाजपेयी ही व्यक्त कर सकते थे, जिससे एक ऐसा माहौल बन गया।
वह अक्सर ऐसा करता था, लेकिन विवरणों को स्पष्ट रूप से बताए बिना।
कश्मीर पर वाजपेयी का सिद्धांत, जिसे कभी-कभी इसी नाम से पुकारा जाता था, ने कश्मीरी सतर्क हो गए और ध्यान देने लगे। लेकिन कश्मीर या इसके बाद की समस्या का कोई हल नहीं निकला।
भारत-पाकिस्तान गतिरोध उनसे दूर रहा—जैसा कि उन प्रधानमंत्रियों के साथ भी नहीं हुआ जिन्होंने

उसका पीछा किया। हालाँकि, उसने एक समस्या को हल करने के उसके अथक प्रयासों को देखा।
देश के सामने आने वाली सबसे जटिल समस्याओं में योगदान के रूप में
वह सबसे ज्यादा इसी बात के लिए याद किया जाना चाहता था।
वाजपेयी एक कुशल शतरंज खिलाड़ी थे, जो अपनी चालों की सोच-समझकर योजना बनाते थे।
अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना। हालाँकि वह हमेशा ऐसा नहीं कर पाता था।
सफल होना। मूलतः टकराव से बचने वाले व्यक्ति होने के कारण, उन्हें संघर्ष पसंद नहीं था।
परिस्थितियों के अनुसार, अक्सर दबाव बढ़ने पर पीछे हट जाते थे। अयोध्या के मामले में,
बाबरी मस्जिद के विध्वंस का कारण बनने वाली कार सेवा का विरोध करने के बाद
उन्होंने मस्जिद का बचाव अपने अनोखे, घुमावदार तरीके से किया। आगरा में,
आडवाणी के दबाव के बावजूद, उन्होंने पाकिस्तान के साथ किसी समझौते के लिए प्रयास नहीं किया।
राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ। या गोवा में, जहाँ उन्होंने पूछा था
Gujarat CM Narendra Modi to follow 'raj dharma' after the Godhra riots
उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी के सहयोगियों के दबाव में आकर उन्हें पीछे हटना पड़ा।
उन्होंने अपनी पसंद के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर बिठाने के लिए दबाव नहीं डाला।
भवन में 2002 में। एकमात्र ऐसा उदाहरण जहां उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया था, वह था
जब आरएसएस ने ब्रजेश को हटाने के लिए उन पर दबाव डाला
मिश्रा—जहां उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की धमकी दी थी।
दिल से, वाजपेयी लेन-देन में विश्वास करते थे। हालाँकि वे
आरएसएस में प्रशिक्षित होकर प्रचारक बने, यह संघर्ष का दौर था।
संसदीय राजनीति और उन्होंने जिन अनेकों संबंधों का निर्माण किया

लगभग पचास वर्षों की अवधि में संसद में विभिन्न दलों के साथ काम करने के कारण ही वह इस मुकाम पर पहुंचे।
वह एक दक्षिणपंथी पार्टी में एक उदारवादी व्यक्ति थे।
हालांकि उनकी राजनीति हिंदू ढांचे के भीतर ही सीमित थी, फिर भी उन्होंने
अल्पसंख्यकों या मुसलमानों के खिलाफ होने का आभास न हो।
विशेष रूप से। और एक उदारवादी की छवि उनसे जुड़ी रही, तमाम राजनीतिक बाधाओं के बावजूद।
उसने जीवित रहने के लिए कई कलाबाजियां कीं। लेकिन लोग
उन्होंने उसे माफ कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उसने दबाव में आकर अपनी चप्पलें बनाई थीं।
अपनी पार्टी के कट्टरपंथियों के बीच। आरएसएस संचालित जनसंघ में काम करने के बाद,
और इसके बाद के स्वरूप, भाजपा को लेकर, वाजपेयी एक हिंदू समर्थक छवि बनाना चाहते थे।
दक्षिणपंथी पार्टी जो 'समावेशी' थी और भारत की बहुलता का ध्यान रखती थी
नैतिक मूल्यों के साथ-साथ, उन्हें संघ नेतृत्व द्वारा दी जाने वाली दखलंदाजी से भी मुक्ति मिल गई थी। आरएसएस द्वारा उन पर समय-समय पर डाले जाने वाले दबाव से वे चिढ़ते थे।
लेकिन उनमें खुद को मुक्त करने और एक नया जीवन रचने का साहस या सहनशक्ति नहीं थी।
साधन।
फिर वाजपेयी को एक राजनीतिज्ञ और प्रधानमंत्री के रूप में कैसे आंका जाएगा?
मंत्री?
वाजपेयी को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उतना याद नहीं किया जाएगा—जैसे कि
जिन परमाणु परीक्षणों में उन्होंने भाग लिया। या अन्य निर्णयों के लिए जो उन्होंने लिए या लेने में असफल रहे।
ले लो। उन्हें उनके व्यक्तित्व के लिए अधिक याद किया जाएगा—एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो

वह मध्य मार्ग पर चलने में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि एक ऐसा देश जो विविधताओं से भरा हो, वह एक साथ चल सकता है।
भारत का शासन केवल आम सहमति से ही संभव हो सकता है। यह उनका ही विचार रहेगा।
अस्थाई विरासत।

अध्याय 6

कम आंका गया प्रधानमंत्री जिसने विजय प्राप्त की

मनमोहन सिंह और भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता

मैं

18 जुलाई 2005 को, व्हाइट हाउस में एक भव्य भोज का आयोजन चल रहा था।
वॉशिंगटन डीसी में स्थित एक घर। यह एक ऐसा रात्रिभोज था जिसे हमेशा याद रखा जाएगा।
मिठाई की प्लेटें और कॉन्यैक के गिलास हटा दिए जाने के काफी देर बाद तक।
वहाँ उपस्थित सभी लोग इस बात से अवगत थे कि यह आयोजन किसी नई शुरुआत की घोषणा के लिए आयोजित किया जा रहा था।
भारत और के बीच एक नई और रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत।
हम।
रात्रिभोज के लिए एक विशेष निमंत्रण पत्र चुनिंदा मेहमानों को भेजा गया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और प्रथम महिला लौरा बुश की सूची।
यह संध्या 'गणतंत्र के प्रधानमंत्री के सम्मान में' आयोजित की जानी थी।
भारत और श्रीमती गुरशरण कौर। राजकीय भोजन कक्ष में मेजें।
उस शाम वे केसरिया रंग के रेशम से ढके हुए थे और सजे हुए थे।
गुलाबी गुलाबों से बनी तुरही बजाते हाथियों की पुष्प प्रतिमाएँ। '[यह] संकेत देता है

व्हाइट हाउस में वह कोई साधारण शाम नहीं थी,' एक रिपोर्ट में यह लिखा था।
अगले दिन वाशिंगटन पोस्ट में। अखबार ने उस शाम का वर्णन 'एक
'गुलाबी हाथी जितना दुर्लभ बुश डिनर'। यह डिनर 'एक
भारत को एक तरह से सलाम। क्योंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश दावतें देने के शौकीन नहीं थे।
वह रात के 9 बजे तक बिस्तर पर जाना पसंद करता था।
इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति
बुश ने एक संयुक्त बयान जारी किया था जिसमें एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।
दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी। यह समझौता हुआ था।
आतंकवाद, सुरक्षा, व्यापार, वित्त पर भारत-अमेरिका के संयुक्त प्रयासों पर
निवेश, पर्यावरण और ऊर्जा। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा
हालांकि, समझौता 'परमाणु ऊर्जा' के बारे में था—जिससे आगे चलकर यह होना था कि...
भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता।
दस दिन पहले, मृदुभाषी सिंह और मिलनसार टेक्सास निवासी बुश
स्कॉटलैंड में एक बैठक में वे अगल-बगल बैठे थे। यह बैठक यहाँ आयोजित की गई थी।
ऑचटरार्डर में स्थित एक्सक्लूसिव ग्लेनेगल्स होटल। वे दोनों
ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित 31वें जी8 शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए
टोनी ब्लेयर। इस अवसर पर, जुलाई 2005 की शुरुआत में, दुनिया के पांच
बढ़ती आर्थिक शक्तियां—चीन, भारत, ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया
अफ्रीका (जिन्होंने खुद को जी5 कहा था) दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया था।
आठ औद्योगिक राष्ट्र। वे थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान,
ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रूस और जी8 देश जलवायु समूह का हिस्सा थे।
परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, स्वच्छ ऊर्जा और अफ्रीका को सहायता जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।
चर्चाएँ।
भव्य और विशाल होटल में स्थित ग्लेनडेवन रूम,
स्कॉटलैंड की लहरदार पहाड़ियों को उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया था।

बैठक क्षेत्र। अपनी पहली बैठक में, बुश ने सिंह की ओर मुड़कर कहा: 'अगर
तेल की कीमतें 100 डॉलर तक पहुंच जाती हैं, इससे भारत को नुकसान होता है...
लेकिन इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को भी नुकसान होता है।
राज्यों।' फिर उन्होंने आगे कहा: 'इसलिए, भारत को मदद करने के लिए हमें मिलकर
काम करना होगा।'
परमाणु सुरक्षा को उपलब्धता पर अधिक जोर देकर मजबूत करना।
परमाणु शक्ति।'
जब दोनों नेता यूनाइटेड के इतर एक कार्यक्रम में मिले थे
एक साल पहले हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा में, बुश ने अपने सीधे-सादे अंदाज में कहा
था कि
मनमोहन सिंह ने पूछा, 'मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?' सिंह ने बुश को बताया
कि
भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ऊर्जा की थी, और कीमतें बढ़ती जा रही हैं।
ऊपर'।
मनमोहन सिंह ने सबसे पहले अमेरिका के साथ सहयोग की बात कही थी।
जब उन्होंने न्यूयॉर्क में अपना पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद नागरिक परमाणु ऊर्जा
पर चर्चा की, तब वे वहीं थे।
सितंबर 2004 में प्रधानमंत्री पद से उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।
उस दिन स्कॉटलैंड में, बिना स्पष्ट रूप से कहे, बुश और सिंह
भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते को नए दृष्टिकोण के केंद्र में रखें।
वे अपने देशों के बीच जिस तरह के संबंध स्थापित करना चाहते थे। अमेरिका के
अधीन
राजनीतिक मामलों के राज्य सचिव, आर. निकोलस बर्न्स और भारतीय
विदेश सचिव श्याम सरन विशाल भवन के एक अन्य कमरे में बैठे थे।
संपत्ति। बर्न्स ने उस दिन सारन को बताया कि अमेरिका का उद्देश्य 'पुष्टि करना' था।
भारत का पूर्ण विकसित परमाणु हथियार संपन्न राज्य का दर्जा और सभी अधिकार
लेकिन दायित्वों का भी पालन करना था। हालाँकि, इसके तुरंत बाद उन्हें वापस
लौटना पड़ा।
उनके बयान के आधार पर, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व्यापार नीति के पक्षकार के रूप

में, अमेरिका
भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी जा सकी।
ग्लेनईगल्स में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मनमोहन सिंह ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया।
वह तालमेल—जिससे दोनों के बीच एक ऐसी 'केमिस्ट्री' विकसित होनी थी जो
बाद में इसकी खूब चर्चा हुई। अपनी घनिष्ठता के बावजूद, दोनों जानते थे।
यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रीय हित ने, न कि व्यक्तिगत कारकों ने, निर्णय लिया।
राष्ट्रों के बीच संबंध। फिर भी, व्यक्तिगत केमिस्ट्री ने
जब महीनों के दौरान रास्ता पथरीला हो गया तो यात्रा को सुगम बनाना।
पालन किया।
'डॉ. सिंह,' बुश को भारतीय प्रधानमंत्री से कहना था, 'आप एक
अच्छे आदमी। मुझे आपके साथ व्यापार करने की उम्मीद है।' मनमोहन
बुश से चौदह वर्ष बड़े सिंह ने भी बुश की भावनाओं का प्रतिरूपण किया।
'वह (बुश) मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं,' सिंह ने पत्रकार राज से कहा।
चेंगप्पा, 'और सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से, वह सबसे अधिक मित्रवत प्रतीत होते थे।'
भारत'।
उस दिन विशाल और खूबसूरत स्कॉटिश एस्टेट में बैठे हुए,
जब मीडिया ने इसे 'दुनिया का आठवां अजूबा' बताया था
होटल 1924 में खुला था, बुश ने सिंह से कहा, 'एक मजबूत रिश्ता है
मूल्यों के साथ-साथ (सामान्य) हित पर आधारित।' ये शब्द थे
मनमोहन सिंह के साथ लंबे समय तक संबंध बने रहे।
■

दस दिन बाद सिंह के सम्मान में बुश द्वारा आयोजित रात्रिभोज एक अश्वेत भोज था।
टाई का मामला। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण।

उस अवसर पर अतिथि के रूप में उपस्थित ऑफिस ने याद करते हुए कहा: 'वहाँ एक विशेष आयोजन हुआ था।
कार्यक्रम के साथ-साथ अतिथियों की सूची भी सोशल मीडिया पेजों पर प्रकाशित की गई थी।
अखबारों के माध्यम से, संगीत प्रदान करने के लिए विशेष रूप से चयनित एक जैज़ समूह...
आमंत्रित किए गए भारतीयों का चयन सावधानीपूर्वक किया गया था—फुटबॉलर, डॉक्टर,
व्यवसायी...' बुश ने शुरू में इस आयोजन को 'पारिवारिक' बताया था।
डिनर'। लेकिन यह एक ब्लैक-टाई कार्यक्रम बन गया, जो उस दौर का पहला बड़ा सामाजिक आयोजन था।
दो साल में व्हाइट हाउस में, और बुश द्वारा दिया गया पांचवां औपचारिक रात्रिभोज।
किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए। उच्च स्तर पर इस बात पर ध्यान गया।
अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष स्तर तक भी इसकी पहुँच थी। इसके महत्व को भी नजरअंदाज नहीं किया गया था।
वहां 134 अतिथि उपस्थित थे।
बुश टक्सीडो में आए थे; सिंह ने काला बंदगला पहना था।
और उनकी सिग्नेचर हल्के नीले रंग की पगड़ी। लौरा बुश चमकीले रंग के कपड़ों में थीं।
भारत से जुड़े रंग— नारंगी रंग के साथ पीला शिफॉन गाउन
पुष्प डिज़ाइन। श्रीमती गुरशरण कौर ने लाल बॉर्डर वाली एक परिष्कृत और सादगीपूर्ण काली रेशमी साड़ी पहनना चुना। अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक
चेनी, रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
क्लेरेंस थॉमस, विश्व बैंक के अध्यक्ष पॉल वुल्फोविट्ज़ और अमेरिकी
सीनेटर भारतीय मेहमानों के साथ घुलमिल गए, और भारतीय मूल के लोग भी।
प्रवासी व्यवसायी। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी के अलावा, भारतीय
प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री नटवर सिंह, भारतीय विदेश मंत्री शामिल थे।
अमेरिका में राजदूत रोनेन सेन, योजना समिति के उपाध्यक्ष
आयोग मोंटेक सिंह अहलूवालिया, पीएमओ में राज्य मंत्री

पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम. के. नारायणन,
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टी. के. नायर और विदेश सचिव श्याम
सरन।
अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस मेहमानों के साथ घुलमिल गईं।
उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान खिल उठी। उसे खुश होने का कारण था।
ढांचागत समझौता लगभग चौबीस घंटे में ही टूट गया था।
इससे पहले, राइस ने समय रहते स्थिति को संभालने में कामयाबी हासिल कर ली थी।
उस सुबह तड़के हस्तक्षेप किया गया।
राष्ट्रपति बुश और प्रथम महिला अपने मेहमानों को अंदर ले गए।
राजकीय भोजन कक्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने भारतीय अतिथि के सम्मान में टोस्ट उठाया।
उन्होंने कहा, 'भारत और अमेरिका के बीच आधी दुनिया की दूरी है। फिर भी आज हमारे
दो राष्ट्र पहले से कहीं अधिक करीब हैं।' भारतीय प्रधानमंत्री
वह भी उतने ही भावुक थे। उन्होंने राष्ट्रपति को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। 'मार्क'
ट्वेन ने एक बार कहा था कि एकमात्र विदेशी भूमि जिसे देखने की उन्हें दिली इच्छा थी, वह थी...
सिंह ने कहा, 'हम भारत की कहानी सीखते हुए बड़े हुए हैं।' 'हम भारत की कहानी सीखते हुए बड़े हुए हैं।'
क्रिस्टोफर कोलंबस की अधूरी यात्रा: पहुँचने के लिए रवाना होना
भारत ने अमेरिका की खोज की। अब मैं अमेरिका के लोगों को आमंत्रित करता हूँ।
उस महान अन्वेषक की यात्रा को पूरा करो।'
तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। फिर, चार प्रकार का भोजन परोसा गया। उसमें शतावरी भी शामिल थी।
सूप, हलिबूट मछली, बासमती चावल, पिस्ता और किशमिश के साथ।
भारतीय स्पर्श, और बिब्ब लेट्यूस और सिट्रस विनेगर ड्रेसिंग वाला सलाद।
इसके बाद मिठाई परोसी गई—चॉकलेट कमल के फूल आम के साथ, और

चॉकलेट-इलायची और काजू आइसक्रीम। और चुनिंदा वाइन।
भोजन की पूरक थी।
रात के खाने के बाद, मेहमान पूर्वी कमरे में चले गए जहाँ वे थे
दिग्गज कलाकार द्वारा प्रस्तुत मनोरंजन की एक शाम में 126 अन्य लोगों के साथ शामिल हुए।
प्रेज़र्वेशन हॉल जैज़ बैंड, जिसे 'वास्तविक अमेरिकी कला' माना जाता है।
'खजाना'। जॉर्ज बुश ने मनमोहन सिंह के लिए रेड कार्पेट बिछाया था।
सिंह।
माहौल खुशनुमा था। कई लोगों ने आपसी सौहार्द को महसूस किया।
सिंह और बुश के बीच। दोनों पक्ष जीत हासिल करने के बाद जोश में थे।
संयुक्त बयान को अंतिम रूप देने में बची आखिरी कुछ अड़चनें—जो पुनर्परिभाषित करेंगी
उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया। लेकिन दोनों नेताओं में से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था।
उस रात मुझे एहसास हुआ कि इसमें और उनतीस महीने की अथक मेहनत लगेगी।
दोनों पक्षों ने उस समझौते को पूरा करने के लिए दृढ़ प्रयास किया, जिसके लिए वे प्रयासरत थे।
इसे साकार करने की दिशा में काम चल रहा है।

द्वितीय

‘मैं बहुत साहसिक कदम उठाने की सोच रहा हूँ,’ अमेरिका के विदेश मंत्री ने उत्साहपूर्वक कहा।
कोंडोलीजा राइस ने मार्च 2005 में नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से कहा था।
वह भारत की संक्षिप्त यात्रा पर आई थी और बड़े उत्साह से बोल रही थी।
भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर उनके दृष्टिकोण के बारे में, जिससे एक नए युग की शुरुआत हो सकती है।
दोनों देशों के बीच साझेदारी।
ऊर्जावान और एकाग्रचित्त राइस, जो आगे चलकर प्रमुख व्यक्ति बनने वाले थे।
भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति ने

तुरंत ही इस बात को समझ लिया था।
दोनों देशों के बीच 'रणनीतिक अभिसरण' की संभावना।
उन्होंने सबसे पहले भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने में रुचि व्यक्त की थी।
अमेरिका में 2000 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान, एक व्यापक रूप से उद्धृत बयान में।
फॉरेन अफेयर्स में प्रकाशित लेख में राइस का जिक्र है, जो आगे चलकर सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक बनने वाली थीं।
आगामी बुश प्रशासन में शक्तिशाली अधिकारी (राष्ट्रीय स्तर पर)
अपने पहले कार्यकाल में सुरक्षा सलाहकार और दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्री के पद पर रहे।
(शब्द), ने लिखा कि भारत अभी तक एक महान शक्ति नहीं था। लेकिन उसके पास यह क्षमता थी।
एक बनने की क्षमता रखता है—और इसे अमेरिका के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए।
शीत युद्ध के बाद की दुनिया में गणनाएँ—ठीक वैसे ही जैसे चीन में हुआ था
चिंताएँ।
अमेरिका में डेमोक्रेट्स से रिपब्लिकन पार्टी ने सत्ता संभाली।
2000 में, राइस इस बात पर विचार कर रहे थे कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय पहचान को कैसे पुनर्परिभाषित करना चाहिए।
1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से इसमें रुचि बढ़ी।
उन्होंने जोर देकर कहा, 'महान शक्तियां सिर्फ अपने काम से काम नहीं रखतीं।'
उन्होंने उभरते हुए चीन को एक 'रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी' के रूप में देखा, न कि 'रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी' के रूप में।
'साझेदार', जैसा कि बुश के पूर्ववर्ती बिल क्लिंटन द्वारा देखा गया था। स्वागत करते हुए
अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के चलते राइस को यह देखने को मिल सकता है।
एशिया-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के लिए यह जो 'संभावित खतरा' पैदा कर सकता है

उस क्षेत्र की सैन्य शक्ति उस समय उससे कहीं अधिक थी, फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर सका।
अमेरिका की। उनके शब्द भविष्यवाणीय थे।
राइस ने अमेरिका को इस दृष्टिकोण से दूर हटने के लिए एक मजबूत तर्क प्रस्तुत किया।
भारत को संकीर्ण नजरिए से देखने के बजाय, क्षेत्रीय संतुलन में भारत की भूमिका पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'एक प्रबल प्रवृत्ति है।'
अफसोस जताते हुए कहा, 'वैचारिक रूप से भारत को पाकिस्तान से जोड़ना और सोचना
केवल कश्मीर या दोनों राज्यों के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा के बारे में ही बात हो सकती है।'
राइस द्वारा भारत के साथ 'गहन संवाद' का आह्वान करने के बाद, बुश
प्रशासन ने पिछले कुछ महीनों में नई दिल्ली से नए तरीके से संपर्क साधा।
उसने अनुसरण किया।
भारत भी उभरती हुई वैश्विक वास्तविकता की ओर देख रहा था।
1990 में सोवियत संघ का पतन और उसकी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण
1991 में, रूस कमजोर हो गया था, चीन का उदय हो रहा था। जबकि अमेरिका
चीन में अपने आर्थिक हितों को न छोड़ते हुए, इसने शुरुआत कर दी थी...
भारत को एक ‘संतुलनकारी कारक’ के रूप में देखें। भारत भी आशंकित था।
विदेश सचिव श्याम सरन को यह खुलासा करना था कि अमेरिका पतन की ओर अग्रसर है।
इससे एशिया में चीन को एक प्रमुख भूमिका मिल सकती है, जो इसके विरुद्ध हो सकती है।
भारतीय हित। एक-दूसरे के बारे में इन बदलती धारणाओं के कारण यह हुआ कि
12 जनवरी 2004 को एनएसएसपी पहल की स्थापना हुई—जब प्रधानमंत्री
मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वाशिंगटन गए थे। इसमें परिकल्पना की गई थी कि
नागरिक परमाणु क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग
ऊर्जा, अंतरिक्ष और उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी—लेकिन क्रमिक रूप से
ढंग।

■

एक दिन अमेरिका को भारत को परमाणु शक्ति से बाहर निकलने देना ही होगा।
अधोलोक।' वाजपेयी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा
जब राइस अभी भी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख थीं, तब उन्होंने एक बार उनसे कहा था।
बुश के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल (2000-04) के दौरान सलाहकार। वे शब्द।
उन्हें उसके साथ रहना था। क्योंकि, वर्षों से परमाणु मुद्दा एक
दोनों देशों के बीच प्रमुख तनाव का कारण।
भारत द्वारा 1974 में किए गए 'शांतिपूर्ण परमाणु समझौते' के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए।
'विस्फोट' ने इसे विश्व स्तर पर परमाणु अछूत बना दिया था। अमेरिका ने
तारापुर रिएक्टरों को ईंधन की आपूर्ति करने के अपने समझौते से मुकरने के मामले में,
भारत में स्थापित करने में मदद की - और भारत को पुनर्संसाधन करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया
ईंधन की खपत को रोकने के लिए अमेरिका ने एक वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने में भी मदद की थी।
भारत को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी हासिल करने या परमाणु ईंधन का व्यापार करने से रोका जा रहा है।
यहां तक कि इसके नागरिक रिएक्टरों के लिए भी—जब तक कि इसने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हों।
संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद उसने अपने परमाणु हथियार त्याग दिए। दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ।
भारत द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद देशों में आर्थिक उछाल आया। अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित होकर, भारत को दंडित किया गया।
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, दुनिया के पैंतालीस देशों का एक समूह है।

औद्योगिक राष्ट्र, जो 1974 के बाद अस्तित्व में आए थे
भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण। इनमें परमाणु हथियार रखने वाले देश शामिल थे।
इस गिरोह ने परमाणु ईंधन और उन्नत उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।
भारत को प्रौद्योगिकी प्रदान की गई। परिणामस्वरूप, भारत की नागरिक परमाणु व्यवस्था में सुधार हुआ।
ईंधन की कमी को पूरा करने और अपने मौजूदा परमाणु संयंत्रों को चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
इसमें परमाणु रिएक्टरों को अपग्रेड करने के लिए स्पेयर पार्ट्स और तकनीक की कमी थी।
पौधों पर भी प्रतिबंधों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। प्रतिबंधों ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र को भी बुरी तरह प्रभावित किया था।
कार्यक्रम और इसकी रक्षा व्यवस्था।
2004 की शुरुआत में एनएसएसपी की स्थापना के तुरंत बाद, ब्रजेश मिश्रा ने संदेश भेजा था...
उनके अमेरिकी समकक्ष कॉलिन पॉवेल (बुश के दूसरे कार्यकाल में) ने कहा कि भारत यदि वह अपने कुछ परमाणु रिएक्टरों को सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रखने को तैयार था —तो
1974 और 1998 के बाद इस पर लगाए गए ईंधन आपूर्ति प्रतिबंध को हटाया जा सकता है।
उस समय अमेरिकी पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
यह तभी हुआ जब मनमोहन सिंह ने मध्य में वाजपेयी का स्थान लिया।
2004 में अमेरिका ने भारत की मूल चिंताओं पर गौर करना शुरू किया और उन पर विचार करना शुरू किया।
इसे वास्तविक परमाणु-शस्त्र राज्य के रूप में मान्यता देने की संभावना।
उस समय अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार कर रहे अमेरिका ने यह गणना की थी कि भारत के उत्थान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना—भले ही यह
परमाणु हथियारों से लैस भारत—उसके हित में था। यह एक
एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते चीन के लिए एक प्रतिसंतुलन।

हालांकि, अमेरिका ने 2005 के दौरान चीन को नियंत्रित करने के बारे में खुलकर बात नहीं की।
2008 में, जब भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते पर बातचीत चल रही थी।
भारत ने भी ऐसा ही किया। लेकिन चीन ने इसे भारत को अपने साथ शामिल करने के लिए अमेरिका की एक चाल के रूप में देखा।
क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चीन विरोधी संगठन बनाए जा रहे हैं।
■

कोंडोलीज़ा राइस ने भारत के साथ परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि
जनवरी 2005 में विदेश मंत्री बनने के तुरंत बाद। जब वह
उन्होंने मार्च 2005 में भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की।
और विदेश मंत्री नटवर सिंह, जिन्होंने उनकी मेजबानी की, राइस ने बताया।
भारतीय नेताओं को यह बताया गया कि बुश अब एनएसपी से आगे बढ़ना चाहते हैं।
वाजपेयी के समय में तैयार किया गया। उन्होंने शीघ्र निष्कर्ष निकालने की वकालत की।
और सुझाव दिया कि इसे भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक पूरा कर लिया जाए।
मंत्री जुलाई 2005 में अमेरिका आईं। दक्षिण एशिया की यह उनकी पहली यात्रा थी और वे पाकिस्तान जा रही थीं। कुछ ही भारतीय अधिकारियों को इसकी उम्मीद थी।
अमेरिका के नए विदेश मंत्री की ओर से इस तरह की 'विस्तृत प्रस्तुति'।
उन्होंने भारतीय अधिकारियों को यह विश्वास भी दिलाया कि बुश जा रहे हैं।
पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमान बेचने की बात कही जा रही है और भारत भी इन्हें खरीद सकता है।
'उन्नत हथियार'। दस दिन बाद, व्हाइट हाउस ने घोषणा की।
पाकिस्तान को एफ-16 विमानों की बिक्री। राइस ने बुश को बिक्री में देरी करने के लिए राजी कर लिया था।

दक्षिण एशिया की यात्रा से लौटने तक यह घोषणा नहीं की गई थी।
निजी बातचीत में राइस ने ऐसा क्या कहा जिससे भारत की दिलचस्पी बढ़ी।
वॉशिंगटन डीसी लौटते समय, राइस ने एक लेख लिखा।
राष्ट्रपति बुश के लिए ज्ञापन। छह पृष्ठों में, उन्होंने मुख्य बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत किया।
उनकी दक्षिण एशियाई रणनीति। ज्ञापन में प्रस्ताव दिया गया था कि अमेरिका
प्रशासन को भारत के प्रति अपना क्रमिक दृष्टिकोण समाप्त कर देना चाहिए।
उन्हें 'पूरी तरह से जोखिम उठाना चाहिए' और एक नागरिक परमाणु समझौता कर लेना चाहिए। उनका रुख स्पष्ट था।
'व्यापक रणनीतिक लक्ष्य' के बारे में, जिसे हासिल करना है—भारत को 'बनने' की स्थिति में लाना।
संयुक्त राज्य अमेरिका के दो या तीन सबसे करीबी साझेदारों में से एक।
अगले कुछ हफ्तों में, दृढ़ निश्चयी राइस ने बुश को मना लिया, जिन्होंने
स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर भाषण देने में लगा रहता था, कि अमेरिका
भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखना चाहिए। उसे आगे बढ़ना होगा।
भारत को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के अपने रवैये से परे
क्योंकि उसने राष्ट्रीय नीति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसने एक शक्तिशाली भारत को उभरते हुए देखा।
हालांकि, अपने ज्ञापन में राइस ने चीन के प्रतिसंतुलन के रूप में इस बात का उल्लेख नहीं किया।
उसने इसे स्पष्ट रूप से कहा। उसके मन में एक समय सारिणी भी थी, विशेष रूप से इसके लिए।
नागरिक परमाणु समझौता। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने भारतीय अधिकारियों से कहा था कि
दोनों देशों को आगामी सम्मेलन में एक संयुक्त बयान जारी करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
जुलाई 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मनमोहन सिंह के बीच शिखर सम्मेलन
(जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी)। और जब बुश ने भारत का दौरा किया...

मार्च 2006 में, दोनों नेता कार्यक्रम को अंतिम रूप दे सकते थे।
समझौते का कार्यान्वयन।
उनके शब्दों से उत्साहित होकर, दोनों पक्षों के अधिकारियों ने कमर कस ली।
काम।
■

17 जुलाई 2005 को भारतीय प्रधानमंत्री वाशिंगटन डीसी पहुंचे।
वह एयर इंडिया वन में सवार थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था।
प्रधानमंत्री को उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु ऊर्जा पर सहयोग पर।
वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले, मनमोहन सिंह पहले ही
उन्होंने दो रणनीतिक निर्णय लिए। उन्होंने अनिल काकोडकर को शामिल किया था।
परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) के अध्यक्ष ने आधिकारिक तौर पर कहा
प्रतिनिधिमंडल। उन्हें आभास था कि प्रस्तावित का विरोध होगा।
संभवतः सहमति देश में एईसी से ही मिलेगी। वह यह भी जानता था।
कि यदि समझौते को देश के प्रधानमंत्री की मंजूरी मिल जाती
वैज्ञानिक निकाय (एईसी) के मामले में, इससे कुछ आलोचनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।
यह तो होना ही था, खासकर देश में वामपंथी पार्टियों की तरफ से।
अब तक, उनकी सरकार को समर्थन देने वाली वामपंथी पार्टियां एक
वे बहुत चिंतित थे। उन्होंने देखा कि भारत अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।
दस वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते की धज्जियां उड़ा दी थीं,
भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करना।
रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा तीन सप्ताह पहले हस्ताक्षरित और
अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड। वामपंथी नेताओं को आशंका थी कि
भारत अपनी स्वायत्तता का बहुत अधिक हिस्सा त्याग रहा था, और एक

अमेरिका का आश्रित राज्य।
मनमोहन सिंह को यह आशंका भी थी कि सोनिया गांधी ने शायद
उसे पता था कि वह वामपंथी दलों को अच्छी स्थिति में रखना चाहती है।
हास्यबोध; यूपीए के अस्तित्व के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण था।
सरकार। यह सिंह के लिए बेहद चिंता का विषय था क्योंकि वह अपने
सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद मिला और उन्होंने सत्ता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित किया।
शीर्ष स्तर पर निर्णय लेना।
उनका दूसरा रणनीतिक कदम विदेश मामलों के मंत्री को भेजना था।
नटवर सिंह मसौदा मंजूरी के लिए एक दिन पहले वाशिंगटन डीसी गए थे।
वह समझौता जिस पर अधिकारी काम कर रहे थे।
विदेश मंत्री होने के अलावा, नटवर सिंह पर भरोसा किया जाता था।
सोनिया गांधी। वह लंबे समय से विदेश नीति पर उनकी सलाह पर भरोसा करती रही थीं।
यूपीए के सत्ता में आने से पहले। मनमोहन सिंह अब इस पर भरोसा कर रहे थे।
नटवर सिंह को उसे नए रिश्ते की आवश्यकता के बारे में समझाने के लिए प्रयास करना होगा।
अमेरिका के साथ।
■

अमेरिकी राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद मनमोहन सिंह ने फोन किया।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक। यह समूह ब्लेयर हाउस में एकत्रित हुआ।
अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस, जहां भारतीय प्रधानमंत्री ठहरे हुए थे।
बैठक में पहले से तैयार किए गए समझौते के मसौदे पर चर्चा करना चाहते थे। बैठक में विदेश सचिव श्याम सरन भी उपस्थित थे।
जो अमेरिकी राजधानी में प्रारंभिक चर्चाओं में व्यस्त थे। सारन
और बर्न्स ने मसौदा समझौते पर काम किया था। इसके बाद यह हुआ था।
नटवर सिंह और कोंडोलीज़ा राइस द्वारा 16 जुलाई को जाँच की गई। सब कुछ

भारतीय प्रधानमंत्री के लिए तैयार था।
सिंह ने मसौदा सभी उपस्थित लोगों को वितरित करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने
मैंने कमरे में घूमकर हर किसी की राय जानने की कोशिश की। अधिकांश लोगों को लगा कि
यह समझौता संपन्न हो जाना चाहिए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के कई सदस्य आशावादी थे।
भारत और अमेरिका के बीच अभूतपूर्व साझेदारी अब एक नए मोड़ पर थी।
यह एक ऐतिहासिक अवसर था जिसे गंवाना नहीं चाहिए था।
हालांकि, कुछ लोगों को यह आशंका भी थी कि भारत को नुकसान हो सकता है।
अमेरिका के बहुत करीब। श्याम सरन के अनुसार, उनकी मुख्य आपत्ति यही है।
यह इस बारे में था कि 'ढांचागत समझौता किन प्रतिबंधों को लागू करेगा'
भारत का रणनीतिक (परमाणु) कार्यक्रम। इन बाधाओं में निम्नलिखित शामिल थे:
भारत को अपने परमाणु संयंत्रों पर कुछ ‘सुरक्षा उपाय’ लागू करने होंगे।
यह बताना होगा कि यह किन प्रतिष्ठानों के लिए खुलेगा।
संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा निरीक्षण।
अनिल काकोडकर के अनुसार, बाईस शक्तियाँ थीं
उस समय देश में मौजूद रिएक्टरों की संख्या।
एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका चाहता था कि भारत के सभी परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया जाए।
इसे आईएईए की निगरानी में लाया गया। यह भारत को स्वीकार्य नहीं था।
फिर चर्चा इस बात पर आगे बढ़ी कि किन रिएक्टरों का उपयोग किया जाएगा।
नागरिक के रूप में वर्गीकृत, निरीक्षण के लिए खुला, और जो होगा
इसे सैन्य क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और बाहरी लोगों के लिए यह प्रतिबंधित क्षेत्र है।
बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम. के. नारायणन उपस्थित थे, हालांकि
कुल मिलाकर ‘सकारात्मक’ प्रतिक्रिया देते हुए अनिल काकोडकर ने ‘सावधानी’ बरती थी।
गंभीर आपत्तियां। 'हमें परमाणु व्यापार से लाभ होगा,'
काकोडकर ने समूह को बताया। लेकिन उन्हें इसके 'प्रभाव' को लेकर चिंता थी।

भारत के परमाणु कार्यक्रम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?' उन्होंने—और विभाग ने—
परमाणु ऊर्जा (डीएई) - अमेरिका की समझ को लेकर सतर्क था
भारत के बाईस परमाणु रिएक्टरों में से किसे नागरिक रिएक्टर के रूप में परिभाषित किया जाएगा?
और इनमें से किसे रणनीतिक प्रतिष्ठान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। लेकिन
काकोडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह निर्णय केवल भारत को ही लेना चाहिए।
अंततः, भारत को अपने बिजली उत्पादन रिएक्टरों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करना था।
श्रेणियों में, चौदह को सुरक्षा उपायों के तहत रखने और आठ को रखने पर सहमति व्यक्त की गई।
रणनीतिक (सैन्य) उद्देश्यों के लिए।
काकोडकर को इस बात की भी चिंता थी कि इस समझौते का क्या प्रभाव पड़ेगा।
भारत की अपनी 'तीन-चरणीय परमाणु ईंधन चक्र' विकसित करने की योजनाओं पर
परमाणु कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था...
यूरेनियम आधारित रिएक्टरों से लेकर तीव्र गति वाले रिएक्टरों तक के कार्यक्रम
थोरियम रिएक्टर।
विदेशी निरीक्षकों की निगरानी में इसका विकास नहीं किया जा सकता।
काकोडकर ने प्रतिनिधिमंडल से कहा, 'तुम्हारी गर्दन। वे (निरीक्षक) देखेंगे।'
वे इसे बड़े संदेह से देखते हैं, जैसे कि हम कोई शरारत कर रहे हों।
भारत में थोरियम के विशाल भंडार हैं। लेकिन यूरेनियम की कमी थी।
—यही कारण था कि इसके रिएक्टर पूरी क्षमता से नहीं चल रहे थे।
तीन चरणों वाले कार्यक्रम का उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना है।
यूरेनियम की कमी को दूर करने और अपने प्रचुर थोरियम संसाधनों का उपयोग करने के लिए
पर्याप्त परमाणु ईंधन का उत्पादन करना। जैसा कि काकोडकर ने कहा, 'रणनीति यह है कि
थोरियम का पूर्णतया दोहन करना तीन-चरणीय प्रक्रिया में निहित है।
यह कार्यक्रम भारत को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेगा।

अमेरिकी तीन प्रकार के रिएक्टरों का उपयोग करने का प्रस्ताव दे रहे थे।
नागरिक श्रेणी में परमाणु ईंधन चक्र का चरण। यह काकोडकर का कहना था।
स्पष्ट रूप से, यह पूरी तरह से 'अस्वीकार्य' था। क्योंकि, तीन-चरणीय परमाणु ईंधन चक्र
इसके लिए संवेदनशील तकनीक की आवश्यकता थी। इसे 'नागरिक' श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था।
श्रेणी के अंतर्गत, इसे 'सैन्य' के अंतर्गत रखना पड़ा। 'या,' काकोडकर ने ऐसा नहीं किया।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ब्लेयर हाउस में हुई बैठक में उन्होंने अपने शब्दों को घुमा-फिराकर नहीं कहा।
मंत्री जी ने कहा, ‘भारत विकास करने के अपने ‘संप्रभु’ अधिकार का ‘बलिदान’ कर रहा होगा’।
उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी इच्छानुसार सर्वोत्तम तरीके से चलाया।
प्रधानमंत्री ने काकोडकर का समर्थन करने का विकल्प चुना। 'अगर काकोडकर खुश नहीं हैं,'
मनमोहन सिंह ने घोषणा की, ‘हम आगे नहीं बढ़ सकते... अभी और काम करने की जरूरत है।’
मसौदे पर...’ उन्होंने अधिकारियों से कहा, ‘आपको इसमें संशोधन करवाना होगा।’
समूह रात के खाने के लिए अलग हो गया। जब वे दोबारा मिले, तो हालात बदल चुके थे।
माहौल गरमा गया। हमारे समूह में अधिकांश लोगों को लगा कि "यह अवसर हाथ से निकल सकता है"।
“इसी आदमी (काकोडकर) की वजह से,” काकोडकर ने याद किया।
मुझे शक था कि वह समझौते के पक्ष में नहीं था। 'यह सच नहीं था। लेकिन (मैं
(ऐसा लगा) कि यह भारत की पूर्ण संतुष्टि और उसे सुनिश्चित करने के अधीन होना चाहिए।
नागरिक और सैन्य को अलग करने का सिद्धांत पूरी तरह से
समझौते में निहित।
प्रधानमंत्री के लिए, काकोडकर की आपत्तियां इस बात का संकेत थीं कि

भारत लौटने पर उन्हें जिस तरह की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में उन्हें चिंता थी। 'वह इस बात को लेकर चिंतित थे कि...'
श्याम सरन ने कहा, 'वामपंथी और सोनिया गांधी। ये राजनीतिक आपत्तियां थीं।'
जैसा कि प्रधानमंत्री ने बाद में नटवर सिंह से कहा: 'मैं इसे बेच नहीं पाऊंगा।'
इसे वापस घर ले आओ।
'यही उनकी चिंता थी,' नटवर सिंह ने मुझसे कहा।
जब ब्लेयर हाउस में मैराथन बैठक आखिरकार समाप्त हुई,
उस रात, प्रधानमंत्री का रुख स्पष्ट था। वह किसी भी फैसले को पलटने वाले नहीं थे।
वैज्ञानिकों की आपत्तियाँ। उन्होंने निर्णय लिया कि संयुक्त बयान द्वारा
उन्हें और जॉर्ज बुश को अगले दिन के लिए जो योजना बनानी होगी, वह यह होगी:
नागरिक परमाणु ऊर्जा पर केवल एक नीरस, दो-पंक्ति वाले सूत्र तक सीमित।
मैंने यह (मनमोहन सिंह का निर्णय) निकोलस बर्न्स को बता दिया।
श्याम सरन ने कहा, 'जो बहुत निराश थे।' बर्न्स का निधन हो गया।
राष्ट्रपति बुश और कोंडोलीज़ा राइस को जानकारी दी गई। राइस ने तब
राष्ट्रपति से बात की: 'यह काम नहीं करेगा,' उसने अपने बॉस से कहा। 'सिंह'
बस इसे संभव नहीं बना सकते।'
बुश ने दार्शनिक लहजे में जवाब दिया, 'बहुत बुरा हुआ।' उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा।
■

18 जुलाई—जिस दिन संयुक्त बयान जारी किया जाना था—की शुरुआत बहुत ही असामान्य रही।
नटवर सिंह के लिए सुबह जल्दी थी। उनके घर में अजीब समय पर फोन की घंटी बजी।
विलार्ड होटल में सुइट। वह वहां एक भारतीय के साथ ठहरे हुए थे।
प्रतिनिधिमंडल। नींद में डूबे सिंह ने रिसीवर उठाया। कोंडोलीज़ा राइस
फोन पर थी। उसने कहा, 'मैं तुमसे मिलना चाहती हूं।' नटवर सिंह वहीं थे।
वैसे भी उस दिन राइस से मिलने का कार्यक्रम तय था, लेकिन उस समय उसके

अनुरोध से वह चौंक गया।
असामान्य समय था। लेकिन उन्होंने अपना आश्चर्य नहीं दिखाया। उन्होंने बस इतना कहा कि...
वह आ जाएगा।
‘नहीं, मैं अभी आकर तुमसे मिलूंगी,’ उसने ज़िद की। नटवर
सिंह ने अनुमान लगाया कि राइस मसौदा समझौते के कारणों के बारे में बात करना चाहते थे।
मुसीबत में पड़ जाना।
कई वर्षों बाद, राइस ने घटनाओं का अपना संस्करण प्रस्तुत किया।
यह घटना 18 जुलाई की सुबह घटी। 'मैं सुबह 4:30 बजे उठा और बैठ गया।'
‘सीधे बिस्तर पर,’ राइस ने अपनी किताब, नो हायर ऑनर में लिखा। ‘मैं नहीं हूँ
मैंने सोचा, इसे ऐसे ही होने देना ठीक नहीं होगा।
मनमोहन सिंह को सुबह 10 बजे ओवल ऑफिस में बुश से मिलना था।
राइस ने सबसे पहले बर्न्स को फोन किया। उन्होंने कहा, 'मैं इसे असफल नहीं होने दूंगी।'
‘मेरे लिए प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजाम कीजिए।’ बर्न्स ने थोड़ी देर बाद वापस फोन किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उनसे मिलना नहीं चाहते थे। ‘मुझे वह चीज़ लाओ।’
उन्होंने कहा, 'विदेश मंत्री।' तभी उनकी नटवर सिंह से बात हुई। फोन करने के तुरंत बाद ही वह उनके होटल पहुंच गईं—ऐसा लग रहा था कि वह
जब उसने फोन किया तब भी वह चलने के लिए तैयार था। 'यह लगभग उसी समय हुआ होगा।'
सिंह ने कहा, 'सुबह 6:30 बजे तक मैं अभी भी अपने ड्रेसिंग गाउन में ही था।'
‘प्रधानमंत्री मुझसे मिलने से इनकार क्यों कर रहे हैं?’ राइस ने नटवार से पूछा।
सिंह।
वह आपको “ना” नहीं कहना चाहता।
उन्होंने कहा, 'मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने दीजिए और उन्हें मेरी बात सुनने दीजिए।'
मैं समझौते को बचाना चाहता हूँ... संयुक्त राज्य अमेरिका इसे लेना चाहता है

तीस साल से गले में लटके बोझ को उतार फेंको, तुम्हें ऐसा करना चाहिए... पूछो उसने आगे कहा, 'उसे फिर से।'

Natwar Singh phoned the prime minister. ‘Woh aa rahi hain (She is

coming),’ he told Manmohan Singh, ‘aap mil lo (There is no harm in

उससे मिलना।

मनमोहन सिंह ने राइस से सुबह 8 बजे ब्लेयर हाउस में मिलने पर सहमति जताई।

नटवर सिंह ने कहा, 'वह थोड़ी देर बाद उनसे जुड़ गया।' बैठक में राइस ने कहा प्रधानमंत्री से, 'आप मुझे बताइए कि इसमें क्या बाधा है... क्या है?'

समस्या बताओ और मुझे देखने दो कि क्या मैं इसे हल कर सकता हूँ।’ राइस को अधिकृत किया गया था।

राष्ट्रपति बुश द्वारा भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए - बैठक से पहले प्रधानमंत्री बुश को फोन करके उन्होंने बताया था कि वह अंतिम निर्णय ले रही हैं।

सौदे को बचाने का प्रयास।

‘श्रीमान प्रधानमंत्री...आप और राष्ट्रपति बुश अमेरिका को खतरे में डालने वाले हैं... राइस ने प्रधानमंत्री से कहा, 'भारत के साथ संबंध एक मौलिक रूप से नए आधार पर स्थापित होंगे।'

मुझे पता है कि यह आपके लिए मुश्किल है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए भी यह मुश्किल है। मैं नहीं आया था।

यहां भाषा पर बातचीत करने आए थे, लेकिन अब आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अधिकारियों को बताएं कि

इसे पूरा करो। और राष्ट्रपति से मिलने से पहले इसे पूरा कर लो।'

राइस ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने अंततः अपनी सहमति दे दी।

लोगों को दोबारा कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करें।’ मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद, उन्होंने

राष्ट्रपति को खुशखबरी सुनाने के लिए सीधे व्हाइट हाउस गए।

कि वे समझौते को एक और मौका दे रहे थे।

कोंडोलीज़ा राइस के जाने के बाद, मनमोहन सिंह ने अनिल से पूछा

काकोडकर को बुलाया गया। प्रधानमंत्री ने उनसे सीधे पूछा कि क्या होगा।
उसे स्वीकार्य होगा। नटवर सिंह प्रधानमंत्री के साथ थे। चुपचाप,
काकोडकर ने मेज पर रखे एक डिब्बे से टिशू पेपर उठाया।
उसे। वह बैठ गया और उस पर दो वाक्य लिख डाले। 'वे शब्द थे।'
इस आशय से कि हमारे तीन-चरणीय रणनीतिक कार्यक्रम की स्वायत्तता
किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।' उन्होंने यह संदेश प्रधानमंत्री को सौंप दिया। प्रधानमंत्री ने कागज देखा और उसे नटवर सिंह को दे दिया, जिन्होंने उसे रख दिया।
उसकी जेब में। फिर काकोडकर चले गए।
नटवर सिंह ने काकोडकर की मांग राइस को दिखाई। उन्होंने उसे देखा।
और उसने कहा, 'सैद्धांतिक रूप से यह ठीक रहेगा।' उसने कहा कि उसे ऐसा करना होगा।
इसे दूसरों से पूछ लें, 'लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं। मोटे तौर पर कहें तो, एक
विचारों का अभिसरण।'
हमारे दृष्टिकोण से, हम इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं चाहते थे।
'भाषा,' सारन ने मुझसे कहा। वह और बर्न्स वापस काम पर लग गए।
एक बार फिर से ड्राफ्ट तैयार करें।
इस बीच, योजना के अनुसार, मनमोहन सिंह ने ओवल में बुश से मुलाकात की।
Office at 10 a.m. Natwar Singh, Prithviraj Chavan, M. K. Narayanan,
और कोंडोलीज़ा राइस बैठक के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थीं। जब
बुश और सिंह मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आए।
'हो गया है (ऐसा हुआ था), यह स्पष्ट था,' नटवर सिंह
वापस बुला लिया गया।
हालांकि, समझौते पर काम कर रहे लोग अभी भी इसे लागू करने में लगे हुए थे।
ओवल ऑफिस से कुछ ही दूरी पर स्थित एक कमरे में दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
नटवर सिंह ने याद करते हुए कहा, 'हम वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे और मजाक कर रहे थे।'

उन्होंने कहा, 'मैंने माहौल को हल्का करने के लिए बुश को इदी अमीन के बारे में एक कहानी सुनाई।'
नटवर सिंह। अमीन, युगांडा का तानाशाह जिसने हजारों लोगों को निर्वासित कर दिया था।
अपने देशवासियों को जेल में डालने के बारे में उन्होंने एक बार अपने विदेश मंत्री से कहा था कि
युगांडा का नाम बदलकर 'इदी' कर दिया जाना चाहिए और यह निर्णय लिया जाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया गया।
युगांडा के तीखे विदेश मंत्री ने अपने प्रवक्ता से कहा, 'एक समस्या है।'
बॉस। साइप्रस के लोगों को साइप्रसवासी कहा जाता है। इदी के लोग...
उन्हें बेवकूफ कहा जाएगा।
जब अमीन ने यह विचार छोड़ दिया।
सब लोग हंस पड़े। तनाव में थोड़ी कमी आई, हालांकि...
मसौदा तैयार करने वाली टीम की ओर से अभी तक अंतिम निर्णय नहीं आया था।
अंततः, दोनों नेता उस कमरे की ओर बढ़े जिसमें प्रेस मौजूद थी।
सम्मेलन दोपहर में आयोजित होने वाला था। योजना यह थी कि
प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त बयान की घोषणा करने के लिए, लेकिन मसौदा तैयार करने के दौरान
टीमें दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहीं, प्रेस विज्ञप्ति में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
बयान जारी किया गया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद और भारतीय बाजार में आखिरी कारों के जाने के बाद
प्रतिनिधिमंडल व्हाइट हाउस से फॉगी बॉटम के लिए रवाना होने ही वाला था,
विदेश विभाग का वह कार्यालय जहाँ कॉन्डोलीज़ा राइस प्रधानमंत्री एस. जयशंकर के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन कर रही थीं, जो उस समय संयुक्त प्रधानमंत्री थे।
विदेश मंत्रालय में सचिव (अमेरिका) विदा लेने वाले व्यक्ति की ओर दौड़ते हुए आए।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सामने आकर उन्होंने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। उनकी आवाज़ में था, 'काम हो गया।'

उल्लासपूर्ण।

यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त बयान कुछ समय बाद जारी किया जाएगा।

बाद में—दोपहर के भोजन के बाद एक और बैठक में अधिकारियों द्वारा इसे और बेहतर बनाने के बाद।

सत्र। मनमोहन सिंह और उनके मीडिया सलाहकार संजय बारू,

यह निर्णय लिया गया कि इस 'सफलता' की खबर अगले व्यक्ति तक अवश्य पहुंचनी चाहिए।

भारत में सुबह के अखबार। अब तक, घर पर लगभग आधी रात हो चुकी थी।

अधिकांश दैनिक समाचार पत्र अब बंद होने की कगार पर होंगे।

प्रधानमंत्री ने अपने मीडिया सलाहकार को दो मीडियाकर्मियों को जानकारी देने का निर्देश दिया।

समझौते के बारे में उनकी कहानियां तैयार हैं। उन्हें जल्दबाजी में लागू किया जा सकता है।

अनुमति मिलने पर उन्होंने प्रिंट किया। ये पत्रकार एन थे।

द हिंदू के रवि और इंडियन एक्सप्रेस के सी. राजा मोहन। वे ऐसा कर सकते थे।

‘उनकी कहानियों को तैयार रखने के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता है, भारत में उनके संपादकों से पूछें कि वे

छपाई में देरी करें, लेकिन हरी झंडी मिलने तक खबर का खुलासा न करें।

बारू ने कहा।

■

अगली सुबह मनमोहन सिंह को एक संयुक्त सभा को संबोधित करना था।

अमेरिकी कांग्रेस के सत्र में। अपने सर्वोत्तम समय में, सिंह को माना जाता था

एक कमजोर और नीरस वक्ता, इतना मृदुभाषी कि वह अक्सर अपने शब्दों को निगल जाता था।

लेकिन उस दिन वह अलग था। उसने अपने पैंतालीस मिनट के भाषण को पढ़ा।

खचाखच भरे हॉल के लिए तैयार किया गया भाषण। 'जब जयशंकर और मैं बैठे थे...'
भाषण की प्रतियां, हाथ में कलम लेकर उन कथनों को चिह्नित करने के लिए जो
संजय बारू ने वर्षों बाद लिखा, 'तालियों की गड़गड़ाहट के बाद, हमने उसे पाया कि वह
बोलने के हर मिनट पर तालियाँ बजती रहीं।
यह मायने रखता था। क्योंकि सिंह जानते थे कि वे उन्हीं पुरुषों और महिलाओं से बात कर रहे थे।
परमाणु समझौते को मंजूरी देने के लिए किसे बुलाया जाएगा?
अखबारों में प्रमुखता से छपे संयुक्त बयान में कहा गया है कि
भारत और अमेरिका में, बुश ने अपनी कांग्रेस से पैरवी करने का वादा किया था।
और अमेरिकी सहयोगियों से—अमेरिकी कानूनों को बदलने के लिए जो रोकते थे
भारत के साथ परमाणु सहयोग न करने के कारण, क्योंकि भारत ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
परमाणु अप्रसार संधि। इसके बदले में भारत ने अपने परमाणु परमाणुओं को अलग करने का वादा किया था।
सैन्य रिएक्टरों से नागरिक रिएक्टरों को अलग करने के लिए, अपने स्थगन को जारी रखने के लिए
परीक्षण बंद करें, और केवल अपने नागरिक परमाणु रिएक्टरों को आईएईए के अधीन रखें।
निरीक्षण।
बयान में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति 'पूर्ण प्राप्ति के लिए काम करेंगे'
भारत के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग'—और ऐसा करने के लिए,
अमेरिकी कानूनों और नीतियों में बदलाव लाने के लिए कांग्रेस से सहमति प्राप्त करना।
साथ ही, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को समायोजित करने के लिए मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे।
भारत के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग और व्यापार को सक्षम बनाने के लिए।
इसमें एक 'शीघ्र' प्रक्रिया भी शामिल होगी, लेकिन यह केवल इसी तक सीमित नहीं

होगी।
सुरक्षित परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन आपूर्ति पर विचार
तारापुर।
भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से कहा कि भारत तैयार रहेगा
समान जिम्मेदारियों को ग्रहण करें और समान लाभ प्राप्त करें
उन्नत परमाणु शक्ति वाले अन्य अग्रणी देशों की तुलना में लाभ
प्रौद्योगिकी, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की।
बयान में कहा गया है कि भारत की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
नागरिक और सैन्य परमाणु सुविधाओं की पहचान करना और उन्हें अलग करना
कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से संचालित किए जाएंगे; इसके संबंध में एक घोषणा पत्र दाखिल किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ [नागरिक] सुविधाएं
(आईएईए)'; यह अपने नागरिक कर्मियों को 'स्वेच्छा से नियुक्त करने' का निर्णय लेगा।
आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत परमाणु सुविधाएं; यह एक 'अतिरिक्त' समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।
नागरिक परमाणु सुविधाओं के संबंध में 'प्रोटोकॉल'; यह जारी रहेगा
परमाणु परीक्षण पर रोक; यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा।
विखंडनीय पदार्थ कट-ऑफ संधि के बहुपक्षीय निष्कर्ष के लिए; और
यह संवर्धन और पुनर्संसाधन के हस्तांतरण से परहेज करेगा।
उन राज्यों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना जिनके पास यह नहीं है।
भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने समीक्षा करने पर सहमति जताई।
2006 में बुश की भारत यात्रा के दौरान समझौते पर हुई प्रगति का जिक्र किया गया था।
■

19 जुलाई 2005 को काकोडकर प्रधानमंत्री को विदाई देने गए थे।
मनमोहन सिंह। वे मुंबई लौट रहे थे, जहाँ वे रहते थे।

उस समय वह एयर इंडिया वन से यात्रा नहीं कर रहे थे, जैसा कि वे पहले किया करते थे।
प्रधानमंत्री की टीम के हिस्से के रूप में अमेरिका आ रहे हैं। एक पद ग्रहण करने के बाद।
बाकियों से अलग, तनावग्रस्त काकोडकर की 17 तारीख की रात खराब गुजरी थी।
जुलाई। लेकिन मनमोहन सिंह ने काकोडकर की प्रशंसा करते हुए कहा, 'उस रात आपने

राष्ट्र को बचाया।' प्रधानमंत्री ने तब काकोडकर से कहा, 'मैंने भी'
मैं उस पूरी रात सो नहीं पाया। मैं लगातार प्रार्थना करता रहा।

तृतीय

'नटवर, तुम जैसे व्यक्ति ने भला इस बात पर कैसे सहमति जताई?' सोनिया गांधी
नटवर सिंह ने कुछ तीखेपन से पूछा। वह उसे जानकारी दे रहा था।
वाशिंगटन डीसी में जो कुछ घटित हुआ था। सिंह अपने इस रवैये के लिए जाने जाते थे।
एक अमेरिकी-विरोधी रुख, जो उनकी संवेदनशीलता के दौरान विकसित हुआ था।
नेहरू के गुटनिरपेक्षता के वर्ष और शीत युद्ध।
आप जानते हैं कि देश में एक अंतर्धारा चल रही है
उन्होंने चिड़चिड़ाते हुए कहा, 'अमेरिकी नीति। यह समझौता अधिकांश लोगों को स्वीकार्य नहीं है।'
भारतीय।
उन्होंने 18 जुलाई 2005 के समझौते के लिए सरकार को 'फटकार' लगाई।
अकादमिक ज़ोया हसन के अनुसार। हसन ने नटवर सिंह का हवाला दिया था
उनकी किताब—हालांकि बाद में सोनिया गांधी ने इस बारे में अपना विचार बदल दिया था।
सौदा।
घर लौटकर उमस भरे दिल्ली में, वाशिंगटन की उमंग का माहौल छा गया।
डीसी गायब हो गया। प्रधानमंत्री को विभाजित जनमत का सामना करना पड़ा—और जॉर्ज के साथ जारी किए गए संयुक्त बयान की व्यापक आलोचना हुई।

झाड़ी।
सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं, बल्कि कई वरिष्ठ अधिकारी भी परेशान थे।
कांग्रेस नेता भी आश्वस्त नहीं थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि
इससे कांग्रेस की वामपंथी पार्टी के रूप में छवि पर पड़ने वाला प्रभाव
और रूस और चीन के साथ देश के संबंधों पर। घरेलू मामलों से संबंधित।
वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि इसका कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
वामपंथी दलों के साथ संबंध, जिन्होंने समर्थन दिया था
मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता में है।
मीडिया का एक वर्ग भी आश्वस्त नहीं प्रतीत हुआ। 'परमाणु समझौता'
'लंबे समय में महंगा साबित हो सकता है,' द हिंदू ने लिखा। 'भारत समझौता कर चुका है'
द पायनियर अखबार की हेडलाइन में भाजपा के दृष्टिकोण को दर्शाते हुए जोर-शोर से लिखा गया था। लेकिन
वहीं मीडिया में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस समझौते का स्वागत करते हुए इसे 'ऐतिहासिक' बताया।
एक 'सफलता', एक 'प्रतिमान बदलाव', जिसने देश के अलगाव को समाप्त कर दिया।
तीन दशकों से इसका सामना करना पड़ा। फिर भी कुछ अन्य लोगों ने मध्य मार्ग अपनाया और इसे कहा
एक 'शानदार सौदा'।
यह आलोचना मुख्य रूप से चार पक्षों से आई। इनमें सोनिया भी शामिल थीं।
जैसा कि उल्लेख किया गया है, गांधी और कांग्रेस के नेताओं को कुछ आपत्तियां थीं।
वहाँ वामपंथी दल भी थे, जिन्होंने संयुक्त समझौते के हर शब्द की बारीकी से जाँच की।
एक बयान जारी किया और उसकी विस्तृत आलोचना प्रस्तुत की। वैज्ञानिकों, रक्षा विश्लेषकों, पर्यावरणविदों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने इस पर और अधिक चर्चा की।
समझौते में मूलभूत समस्याएं हैं। आश्चर्यजनक रूप से, सबसे मजबूत
यह आलोचना भाजपा की ओर से आई, जिसने वाजपेयी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री रहते हुए...

अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी की पूरी प्रक्रिया शुरू की।
वाजपेयी की इस समझौते की तीखी आलोचना ने ही इसे प्रमुखता दिलाई।
अचानक मंत्री नियुक्त। वाजपेयी ने मनमोहन सिंह की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने
अमेरिकियों को 'बहुत ज्यादा दे दिया'। 'नागरिक और
उन्होंने कहा, 'सैन्य कार्रवाई बहुत मुश्किल होगी, अगर असंभव नहीं तो।' 'लागत बहुत अधिक होगी।'
इसमें शामिल होने पर भारी खर्च आएगा।' पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन वाजपेयी और ब्रजेश मिश्रा ने तीखा हमला किया।
प्रधानमंत्री। चूंकि नागरिक रिएक्टरों से निकलने वाला विखंडनीय पदार्थ
समझौते के तहत भारत को अब हथियारों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
मिश्रा ने कहा, '(यह) असल में अपने परमाणु हथियारों पर रोक लगा रहा था।
'क्षमता'। उन्हें लगा कि मनमोहन सिंह ने एक बड़ी रियायत दी है।
मिश्रा ने सरकार के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि भारत
जिसे अमेरिका या परमाणु आपूर्तिकर्ताओं में से अन्य द्वारा परमाणु आपदा प्रतिरोधी (NWS) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
समूह। अमेरिकी विदेश उप सचिव निकोलस बर्न्स ने स्पष्ट रूप से कहा था
भारत केवल परमाणु हथियार संपन्न देश था, परमाणु हथियारों से लैस देश नहीं।
उन्होंने खुलासा किया कि वाजपेयी के शासनकाल में सरकार ने राज्य में क्या किया था। उन्होंने बताया कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में सरकार ने क्या किया था।
उन्होंने केवल 'हमारे मौजूदा रिएक्टरों में से कुछ' को ही लगाने की पेशकश की थी... और हमारे सभी
सुरक्षा उपायों के तहत भविष्य के रिएक्टर। लेकिन ये न तो तेजी से प्रजनन करने वाले थे।
न तो निर्माणाधीन रिएक्टरों की बात हो रही है, न ही केवल उन रिएक्टरों की जिनकी योजना बनाई जा रही है।
भाजपा ने संसद में इस समझौते पर मतदान कराने की मांग की और समझौते के पक्ष में मतदान कराने की भी मांग की।

पुनर्विचार किया जाएगा।
इस संयुक्त बयान ने देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी थी।
परमाणु वैज्ञानिक और रक्षा विश्लेषक अपने विचारों को लेकर बुरी तरह विभाजित थे।
कई लोगों ने इस सौदे को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हुए 'भय और चिंता' जताई।
इसका विरोध करने वालों में भारत के पूर्व अध्यक्ष पी. के. अयंगर भी शामिल थे।
भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग; डॉ. ए. एन. प्रसाद, पूर्व निदेशक
ट्रॉम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के; डॉ. ए.
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से गोपालकृष्ण और रणनीतिक
विशेषज्ञ भरत कर्णद—ये सभी देश के परमाणु क्षेत्र में जाने-माने नाम हैं।
सत्ता प्रतिष्ठान। उन्होंने इस सौदे को 'रणनीतिक समझौता' करार दिया—यह
साथ ही यह उस पुस्तक का नाम भी था जिसे उन्होंने बाद में संयुक्त रूप से लिखा था।
गोपालकृष्ण ने अपनी आलोचना में तीखी टिप्पणी की: 'इसकी कोई आवश्यकता नहीं है'
भारत अमेरिका को प्रसन्न करने के लिए अपने स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बलिदान के रूप में सौंपने को तैयार है, जिसके बदले में उसे कुछ और मिलने का वादा किया गया है।
भारत के लिए व्यापक रणनीतिक गठबंधन या महाशक्ति का दर्जा।
पी. के. अयंगर ने कहा कि भारत का परमाणु कार्यक्रम एक अभिन्न अंग है।
यह संपूर्ण था और इसे सैन्य क्षेत्र की दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता था।
और नागरिक। इसमें मुख्य रूप से धन की कमी थी। 'हम केवल यही चाहते हैं
पैसा, न कि उनकी विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी या विज्ञान।
हालांकि, इस समझौते का मुख्य विरोध वामपंथी दलों से आया।
पार्टियां। वे न केवल सरकार के बारे में चिंतित थीं, बल्कि उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि सरकार के पास
बहुत जरूरी चीजें खरीदने के बदले में बहुत कुछ दे दिया गया।
भारतीय रिएक्टरों के लिए यूरेनियम। सीपीआई (एम), क्रांतिकारी समाजवादी
आरएसपी पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने संयुक्त बयान की आलोचना की।

लंबाई। सीपीआई (एम) के पोलित ब्यूरो ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने
इसने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता किया, जिससे यह एक 'रणनीतिक' देश बन गया।
अमेरिका का सहयोगी देश। इस बारे में परामर्श न किए जाने से वह बेहद नाराज था।
एक सहयोगी होने के बावजूद, इतना महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय। इसका बयान
एक अप्रत्यक्ष चेतावनी देते हुए—'सीपीआई (एम) को सरकार से यह उम्मीद नहीं है कि वह ऐसा करेगी।'
एकतरफा उपाय करना जिससे राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन हो सकता है
रुचियां।
हालांकि, इस समझौते के समर्थकों का मानना था कि इससे यह समस्या समाप्त हो जाएगी।
1974 और 1998 में हुए परीक्षणों के बाद भारत को जिस कलंक का सामना करना पड़ा था, उससे निपटने में मदद मिलेगी।
देश को परमाणु ऊर्जा उद्योग के साथ व्यापार करने में सक्षम बनाना
वैश्विक स्तर पर, जिसे प्रतिबंधों ने रोक रखा था। लेकिन कुछ लोगों को आशंका थी कि
इस समझौते को अमेरिकी पक्ष से विरोध के कारण विफल कर दिया जाएगा।
अमेरिकी कांग्रेस के भीतर। लेकिन अन्यथा, उन्होंने इसे एक कदम आगे के रूप में देखा।
एक ऐसी यात्रा जो भारत में गुणात्मक परिवर्तन लाएगी
अमेरिका के साथ संबंध। मनमोहन सिंह यही चाहते थे।
यह देश की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है।
■

1 मार्च 2006 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत पहुंचे। मौर्य जहाज
दिल्ली स्थित शेरेटन होटल अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार था;
होटल का शेड्यूल इस तरह से विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया था कि बुश

रात को जल्दी सो सकते हैं।
बुश की यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण सफलता मिली।
यह उस समझौते पर आधारित था जिसे 'पृथक्करण योजना' कहा जाता था।
यह भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते का दूसरा चरण था। जैसा कि उल्लेख किया गया है, अमेरिकियों ने शुरुआत में सभी परमाणुओं को सुरक्षित रखने की इच्छा से शुरुआत की थी।
भारतीय परमाणु रिएक्टर सुरक्षा उपायों के अंतर्गत हैं। भारतीय पक्ष ने
विरोध किया। एक बार फिर, ये बातचीत अंतिम क्षण तक चली। इसमें काफी मेहनत लगी।
भारतीय पक्ष द्वारा केवल नागरिक परमाणु रिएक्टरों के लिए सौदेबाजी करना
इसे आईएईए की निगरानी में रखा जाए, न कि सैन्य निगरानी में।
बुश के आने से ठीक पहले मनमोहन सिंह ने एक साक्षात्कार दिया था।
अमेरिकी पत्रकार चार्ली रोज़ को दिए गए उस साक्षात्कार में, प्रमुख
मंत्री ने स्वीकार किया था कि परमाणु रिएक्टरों को नागरिक क्षेत्रों में अलग करना
और रणनीतिक वाले—जिन्हें तकनीकी शब्दावली में 'आइलैंडिंग' कहा जाता था—
यह दोनों पक्षों के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे बुश को करना पड़ा था।
अमेरिकी कांग्रेस की चिंताओं पर विचार करने के लिए मनमोहन सिंह को
भारतीय संसद की चिंताओं का समाधान करें। 'मैंने हमसे वादा किया है कि हम
संसद को यह संदेश देना कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति को नुकसान पहुंचे।
कार्यक्रम।
दोनों पक्षों के बीच एक लंबा सत्र चला।
2 मार्च 2006 को दिल्ली में स्थित भव्य हैदराबाद हाउस। राष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार एम. के. नारायणन और श्याम सरन ने प्रतिनिधित्व किया।
भारतीय पक्ष। जुलाई 2005 में संयुक्त बयान के बाद, नारायणन—
सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले व्यक्ति अचानक एक महत्वपूर्ण भूमिका में उभर आए थे।
भारतीय वार्ताकार। वह समझौते के समर्थक और विरोधी पक्षों के बीच एक सेतु बन

गए।
वार्ताकार दल और अधिक सतर्क परमाणु ऊर्जा विभाग,
श्याम सरन के अनुसार, 'ऐसा प्रतीत होता था कि वे आश्वस्त थे कि हम थे'
दुकान को अमेरिकियों को बेचने वाले हैं।
अमेरिकी पक्ष में नारायणन के समकक्ष नेशनल थे।
अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार स्टीफन जे. हैडली और निकोलस बर्न्स, जो अमेरिकी सेना के अधीन हैं, ने यह जानकारी दी।
विदेश मंत्री। चारों लोग सुबह 3 बजे तक इस काम में लगे रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
वे नज़र आने ही वाले थे। वैज्ञानिक—आर. चिदंबरम, जो थे
प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और अनिल काकोडकर भी वहीं आसपास मौजूद थे।
वे पास के ही एक कमरे में धैर्यपूर्वक बैठे रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपनी सलाह दे सकें।
कुछ मुद्दों पर गतिरोध बना रहा, जिन पर कोई फैसला नहीं हो सका।
समाधान। सबसे पेचीदा मामला अमेरिका की यह मांग थी कि भारत अपने नागरिकों को तैनात करे।
रिएक्टरों को 'स्थायी रूप से' सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रखा जाएगा।
अगली सुबह, कार्य समूह की पुनः बैठक हुई। प्रधानमंत्री
सिंह और राष्ट्रपति बुश बगल के कमरे में बैठे बातचीत कर रहे थे।
वे 18 जुलाई 2005 की तरह ही गतिरोध के समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे।
अंततः एक बड़ी सफलता मिली—और यह बुश के हस्तक्षेप के बाद मिली।
व्यक्तिगत रूप से। अमेरिकियों ने भारत के साथ मिलकर प्रत्येक नागरिक रिएक्टर के जीवनकाल तक चलने वाले ईंधन भंडार बनाने का वादा किया, ताकि आपात स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके।
चाहे किसी भी कारण से व्यवधान उत्पन्न हों।
3 मार्च 2006 को दोनों नेताओं ने संयुक्त समझौते की घोषणा की।
नागरिक परमाणु सहयोग पर। उस शाम दोनों नेता खड़े थे।
एक साथ, सजे-धजे और कलात्मक रोशनी से जगमगाते पुराने किले में, जो कभी

दिल्ली का
राजधानी। ऐतिहासिक किले की पृष्ठभूमि में स्थित, एनबीसी था
जॉर्ज बुश ने ऐतिहासिक परमाणु समझौते को इस रूप में प्रस्तुत किया था।
अमेरिका के इस एक अरब लोगों के साथ नए सिरे से शुरू हुए प्रेम प्रसंग का केंद्रबिंदु लोकतंत्र'। आम तौर पर शर्मीले और शांत स्वभाव के मनमोहन सिंह में बदलाव आया। जब उन्होंने दोनों को मिलाने में बुश की भूमिका का जिक्र किया तो वे बेहद भावुक हो गए।
एक दूसरे के करीब के देश। दो साल बाद, समापन पर
2008 में हुए समझौते के अनुसार, उन्हें एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बुश से कहना था, 'भारत के लोग
'मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ—इस टिप्पणी ने विवाद को जन्म दिया।
■

2006 के शेष भाग के लिए, सारी कार्रवाई अमेरिका में स्थानांतरित हो गई। राष्ट्रपति बुश को अपने वादे को पूरा करना ही था। उन्हें अमेरिकी कानूनों में संशोधन करना ही था।
भारत के साथ परमाणु व्यापार को सक्षम बनाने के लिए, जिसने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए थे।
परमाणु अप्रसार संधि।
सबसे पहले हाइड एक्ट पारित हुआ, जिसने अमेरिकी कानूनों में संशोधन किया।
परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954—और यह आवश्यक था। अमेरिकी परमाणु ऊर्जा के लिए
ऊर्जा अधिनियम ने अमेरिका को किसी देश के साथ नागरिक परमाणु सहयोग की अनुमति दी।
केवल कुछ शर्तों के तहत—कि वह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति का सदस्य हो।
(जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे), उसने परमाणु उपकरण का विस्फोट नहीं किया था।
(जो भारत ने 1974 और 1998 में किया था), उसने अपने चल रहे प्रयासों को रोक

दिया था।
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम (जो
भारत ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसीलिए भारत को इससे छूट दी जानी थी।
ये बाध्यकारी कानूनी शर्तें।
नवंबर 2006 में, हेनरी जे. हाइड संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत शांतिपूर्ण वार्ता हुई।
परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम 2006 (पीएईसी अधिनियम) पारित किया गया।
अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 के प्रासंगिक भागों में संशोधन करना।
लेकिन
इसने भारत में राजनीतिक मत को बुरी तरह से विभाजित कर दिया। वामपंथी दल—
और अन्य आलोचकों ने तुरंत कई प्रतिबंधात्मक खंडों की ओर इशारा किया।
इस अधिनियम में भारत की संप्रभुता पर अतिक्रमण किया गया था—भले ही इसमें
प्रावधान किया गया था
अमेरिकी कानून के कुछ प्रावधानों से छूट। इन प्रावधानों ने भारत को प्रतिबंधित कर
दिया था।
यूरेनियम संवर्धन, प्रयुक्त ईंधन के पुनर्संसाधन और भारी जल उत्पादन के लिए
प्रौद्योगिकियों तक पहुंच से (अधिकतम रूप से इसने इन्हें सीमित दायरे में ही अनुमति
दी थी)।
मामले-दर-मामले आधार पर)। अधिनियम में एक शर्त थी कि अमेरिका
राष्ट्रपति कांग्रेस को प्रतिवर्ष एक 'प्रमाणन' देंगे कि
भारत ने परमाणु अप्रसार नीति और अन्य नीतियों का अनुपालन किया था।
प्रतिबद्धताएं।
मार्च में दोनों देशों द्वारा अंतिम रूप दिए गए पृथक्करण योजना के बाद
2006 में, भारत ने सोचा था कि अब बदलाव करना एक सरल मामला होगा।
अमेरिकी कानून। लेकिन हाइड अधिनियम में कुछ 'अनावश्यक' प्रावधान जोड़ दिए गए
थे।
अमेरिका में सक्रिय विभिन्न लॉबियों और हित समूहों को संतुष्ट करना।
इससे भारत में भारी आक्रोश फैल गया, क्योंकि इसने भारत की विदेश नीति में
हस्तक्षेप किया था।
ईरान के साथ उसके संबंधों को लेकर, और उसके संप्रभु अधिकार को बाधित करने

के लिए।
अपने स्वयं के निर्णय।
विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया।
उन्होंने कांग्रेस सदस्यों को पत्र लिखकर उनसे सहयोग करने का आग्रह किया।
भारत की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, नए व्यावसायिक अवसरों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
भारत में खुले बाजार, अमेरिकी व्यापार समूह, धनी इंडो-अमेरिकी
समुदाय, और भारतीय सरकार ने सदस्यों के साथ पैरवी की।
अमेरिकी कांग्रेस।
तत्कालीन सीनेटर और बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति बने बराक ओबामा थे।
इस समझौते का विरोध किया। सीनेटर जो बाइडेन भी राष्ट्रपति बनने के इच्छुक हैं।
कई वर्षों बाद, उनका रुख 'समर्थक' था। भारत के राजदूत ने कहा कि...
अमेरिका में रोनेन सेन ने भारतीय प्रवासी भारतीयों को अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए एकजुट किया।
अंततः अमेरिकी सांसदों द्वारा कुछ विधायी संशोधन किए गए।
हालांकि सांसदों ने आलोचकों, विशेषकर वामपंथियों को संतुष्ट नहीं किया, फिर भी वे सफल रहे।
पार्टियां।
■

हाइड एक्ट ने लंबी और पेचीदा प्रक्रिया के अगले चरण का मार्ग प्रशस्त किया।
समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया—123 समझौते का निर्माण।
भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते का औपचारिक नाम यही था।
दोनों पक्षों के बीच कई मतभेदों के बावजूद, यह चरण भी महत्वपूर्ण था।
27 जुलाई 2007 को सफलतापूर्वक मंजूरी मिल गई। इससे पहले कि समझौते की पुष्टि हो पाती,
अमेरिकी कांग्रेस के लिए भारतीय संसद के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी।
इस पर मतदान करें—बाधा दौड़ में अभी दो और बाधाएं पार करनी बाकी थीं।

मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश दोनों ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था।

एक विकल्प यह था कि भारत आईएईए के पास जाए और अपने लिए एक सुरक्षित स्थिति प्राप्त करे।
विशिष्ट सुरक्षा उपायों का समझौता। आईएईए के पास सुरक्षा उपायों के दो सेट थे, एक के लिए
एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को अपनी सभी सुविधाओं की गहन जांच करानी पड़ी।
एक अंतरराष्ट्रीय निकाय के लिए, और दूसरा उन देशों के लिए जिन्होंने विकल्प नहीं चुना था
एनपीटी के तहत—बाद वाला स्वेच्छा से विशिष्ट सुविधाओं को सौंप देगा।
संयुक्त राष्ट्र निकाय के सुरक्षा उपाय। भारत के मामले में, समझौता होगा
इसे भारत-विशिष्ट सुरक्षा समझौता (ISSA) कहा जाता है, क्योंकि यह
भारत राष्ट्रीय नीति समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। भारत ने इस बात पर जोर दिया था कि सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।
श्याम सरन ने कहा, 'समझौता भारत-विशिष्ट होना चाहिए।' एक बार यह समझौता भारत के लिए विशिष्ट हो जाए तो...
बाधा दूर हो जाने पर, अमेरिका भारत के लिए छूट की सुविधा प्रदान करने के लिए काम करेगा।
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से, ताकि वह ईंधन, उपकरण आदि खरीद सके।
अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री और संवेदनशील प्रौद्योगिकी।
जिसे 1974 और 1998 में हुए विस्फोटों के बाद नकार दिया गया था।
इस चरण को पार करने के बाद ही 123 समझौता आगे बढ़ेगा।
इसे अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अपनाया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे।
इसके बाद भारत और अमेरिका औपचारिक रूप से समझौते को लागू करेंगे।
भारत अंततः परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होगा (इसके विपरीत)
अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना पड़ता है।

हालांकि देश अपनी रणनीतिक परमाणु गतिविधियों को जारी रख सकता है
हथियार कार्यक्रम, नागरिक परमाणु रिएक्टरों को आईएईए के अधीन रखना
'स्थायी' सुरक्षा उपायों का एक नकारात्मक पहलू भी था। इसका मतलब यह था कि खर्च की गई सारी राशि
इन सुविधाओं पर परमाणु हथियारों के लिए ईंधन उपलब्ध नहीं होगा।
इस कार्यक्रम से देश के परमाणु भंडार के आकार को सीमित किया जा सकता है।
अमेरिका ने यह अनुमान लगाया होगा कि इससे भारत की पहुंच सीमित हो जाएगी।
परमाणु महत्वाकांक्षाएं। लेकिन देश की परमाणु ऊर्जा के प्रभारी लोगों का मानना है कि...
कार्यक्रम को लेकर आश्वस्त थे कि उनके पास अपनी रणनीतिक योजना के लिए पर्याप्त ईंधन है।
जरूरतें।
शुरू से ही, भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य इससे कहीं अधिक था।
स्वच्छ ऊर्जा और भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों के बारे में अधिक जानकारी।
कार्टर से लेकर क्लिंटन तक के राष्ट्रपतियों ने भारत की परमाणु क्षमता पर लगाम लगाने की कोशिश की थी।
आकांक्षाएँ। जैसा कि हमने पहले देखा है, 1998 के परीक्षणों के बाद, अमेरिका के पास
भारत के खिलाफ दंडात्मक प्रतिबंध लगाए गए। अप्रत्याशित रूप से, परीक्षणों ने
वाजपेयी द्वारा किए गए इस कार्य ने भारत-अमेरिका संबंधों में एक नए चरण की नींव भी रखी।
रिश्ते। शुरुआत तक अमेरिका की नजरों में भारत का महत्व बढ़ चुका था।
नए सहस्राब्दी के दौरान—जब इसने उत्तर-पूर्व में अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों पर पुनर्विचार किया—
शीत युद्ध की दुनिया। भारतीय पक्ष की ओर से, इस समझौते के मुख्य सूत्रधार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बाद में कहा कि यह समझौता
'इससे भारत के विदेश नीति विकल्पों का विस्तार हुआ'।
भारत के सतर्क और नौकरशाही प्रधान मंत्री द्वारा उठाया गया यह एक जोखिम भरा

कदम था।
मंत्री। पत्रकार शेखर गुप्ता के अनुसार, तब ऐसा हुआ था कि
शीत युद्ध के बाद के भारत का जन्म हुआ।
चतुर्थ

'वह यूजीसी का अध्यक्ष बनना चाहता है, और मैं उसे अध्यक्ष बनाना चाहता हूं।'
भारत के वित्त मंत्री,' पी.वी. नरसिम्हा राव ने टिप्पणी की।
Congressman Brij Mohan Bhama about Manmohan Singh.
मनमोहन सिंह ने राव के कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उनसे मुलाकात की थी।
राजीव गांधी की हत्या के बाद जून 1991 में वे राष्ट्रपति बने।
प्रधानमंत्री चंद्र शेखर द्वारा यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
लेकिन सरकार अपने अंतिम चरण में थी, और चंद्र शेखर भी...
कार्यवाहक प्रधानमंत्री सिंह को चिंता थी कि कहीं उन्हें यह जिम्मेदारी न उठानी पड़े।
अगर चंद्र शेखर हार जाते तो दिल्ली में कोई आवास नहीं मिलता, जो कि संभव लग रहा था।
संभवतः। नौकरशाहों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पास पर्याप्त अधिकार नहीं होते।
इस तरह की नियुक्ति करने का अधिकार किसी के पास हो सकता है, और यह अधिकार खतरे में पड़ सकता है।
मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे।
मंत्री ने चंद्र शेखर से उन्हें यूजीसी का अध्यक्ष बनाने को कहा था।
भी।
मनमोहन सिंह चाहते थे कि राव उनकी नियुक्ति को नियमित करने में मदद करें।
उनके पास यूजीसी अध्यक्ष पद की नियुक्ति का पत्र था।
भामा को, जो आर. के. धवन और सतीश शर्मा के करीबी थे, और
उस दिन राव के आवास पर, वह यह काम करने के लिए राव की मदद चाहता था। 'मैं तुम्हें जानता हूँ।'
भामा के अनुसार, सिंह ने राव से कहा, 'आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।' राव
उन्होंने सिंह को मदद का आश्वासन दिया और कहा कि वे पदभार संभालने वाले

व्यक्ति से बात करेंगे।
चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के रूप में। चुनाव परिणाम अभी घोषित नहीं हुए थे।
इसके बाद राव ने मनमोहन सिंह की ओर रुख किया और उनसे उनके विचार पूछे—
गिरवी रखे गए सोने को वापस कैसे लाया जाए
चंद्र शेखर के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान का धन विदेशों में बैंकों के सुरक्षित खातों में पड़ा हुआ था।
मनमोहन सिंह ने उनकी मदद करने पर सहमति जताई, और उन्होंने वित्तीय सहायता प्रदान की।
मंत्री।
मनमोहन सिंह, जिन्हें बाद में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में सराहा गया।
भारत के वित्त मंत्री के रूप में शुरुआती दिनों और हफ्तों में उनका रवैया संशयपूर्ण था।
राव ने ही अधिकांश कठिन निर्णय लिए थे। बाद में ही यह बात सामने आई कि
मनमोहन सिंह ने अपनी छाप छोड़ी।
■

मैं कह सकता हूं कि मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने का विचार
यह मेरा था,' तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन ने कहा।
2002 में राव ने आर.वी. (जैसा कि आर. वेंकटरामन को जाना जाता था) से संपर्क किया था।
सलाह। वेंकटरामन ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में वित्त मंत्रालय संभाला था।
गांधी (1980-82) के कार्यकाल में काम किया था और इस पद की मांगों से परिचित था। 'मैं
पीवी को दो नाम सुझाए गए थे—आई. जी. पटेल और मनमोहन सिंह।
वेंकटरमन ने कहा। आई. जी. पटेल, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर।
भारत के राष्ट्रपति मनमोहन सिंह ने पदभार संभालने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।
मनमोहन सिंह सहमत हो गए।
राव वित्त विभाग का नेतृत्व कौन कर सकता है, इसकी तलाश शुरू कर चुके थे।
जिस क्षण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला, उसी क्षण से मंत्रालय में कोई

व्यक्ति...
जो आईएमएफ जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे और
विश्व बैंक। सोवियत संघ का पतन हो गया था। एकध्रुवीय दुनिया अस्तित्व में आ गई थी।
वह सामने आया। उसे पता था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हवा किस दिशा में बह रही है।
हालांकि चुनाव परिणाम अभी घोषित नहीं हुए थे, फिर भी वह जानता था कि उसे जीत हासिल हो चुकी है।
प्रधानमंत्री बनने की अच्छी संभावना थी। जब तक वे औपचारिक रूप से निर्वाचित हुए, तब तक
सीपीपी के नेता के रूप में, उन्होंने यह तय कर लिया था कि वे किसे चाहते हैं।
इसी दौरान कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा उनसे मिलने आए।
शर्मा ने सहज भाव से पूछा, 'तो, वित्त के लिए आपके मन में कौन है?'
राव को पता था कि मामला किस ओर जा रहा है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, 'यह एक होगा।'
'टेक्नोक्रेट।' वह इस बात की आशंका को पहले ही खारिज करना चाहते थे कि शर्मा शायद
सोनिया गांधी से यह सवाल आया है कि वित्त मंत्रालय का प्रमुख कौन होना चाहिए।
मंत्रालय। राव ने पी.सी. अलेक्जेंडर को नियुक्त किया, जो अनौपचारिक रूप से सहायता कर रहे थे।
उन्हें मंत्रिमंडल गठन के बारे में सूचित किया गया, ताकि वे मनमोहन सिंह से मिल सकें।
अलेक्जेंडर ने 21 जून 1991 को सुबह 5 बजे सिंह को फोन किया और पूछा कि...
उनसे मुलाकात की—और फिर राव का प्रस्ताव लेकर उनसे मिलने गए। मनमोहन
सिंह ने नौकरी स्वीकार कर ली। पी. वी. नरसिम्हा राव ने शपथ ली।
प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में।
उस दिन दोपहर।
■

प्रधानमंत्री और उनकी नई वित्त समिति के सामने कठिन फैसले आने वाले हैं।
मंत्री जी। सबसे पहले लिए जाने वाले प्रमुख निर्णय थे अवमूल्यन के संबंध में।
रुपये और आरबीआई के सोने को गिरवी रखने जैसी घटनाएं हुईं। भारत ने पहली बार रुपये को गिरवी रखा।
संप्रभु चूक कहे जाने वाले जोखिम—यानी सक्षम न होने की स्थिति—के खतरे
अपने विदेशी ऋणों पर ब्याज चुकाने में असमर्थ। अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही थी। विकास दर में गिरावट आई थी, मुद्रास्फीति बढ़ गई थी और विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो गया था।
भंडार बेहद कम हो गया था, केवल तीन सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त भंडार बचा था।
पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न तेल संकट के चलते
इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण करने के बाद।
'अब हमें सोना गिरवी रखकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की आवश्यकता है,' एस.
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके वेंकिटारमनन ने बताया
वित्त सचिव एस. पी. शुक्ला। यह आरबीआई का सोना होना था।
इसे बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखा जाएगा; ऐसा करना आवश्यक था।
भारत को देने से पहले ही इन बैंकों के तिजोरियों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
विदेशी मुद्रा। अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद
कागजी कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को मंजूरी देनी पड़ी।
फ़ैसला।
एस. पी. शुक्ला और दीपक नैयर फाइल को मनमोहन सिंह के पास ले गए।
'हम फाइल को हाथ से ढोकर ले गए थे,' नय्यर ने याद किया।
मनमोहन सिंह ने कहा, 'मुझे इस पर हस्ताक्षर क्यों करने होंगे? प्रधानमंत्री को तो करने ही होंगे।'
इस पर हस्ताक्षर करें।'
हमने उनसे कहा कि चूंकि यह आरबीआई का (सोने का) भंडार था और इसके अंतर्गत

था।
आरबीआई अधिनियम के लिए उनकी अलग से मंजूरी की आवश्यकता थी।
उन्होंने जोर देकर कहा, 'नहीं, यह जरूरी नहीं है।'
अधिकारी मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित 9 नंबर घर के लिए रवाना हुए, जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे।
अभी भी वहीं रुके हुए थे। वे अभी तक रेसकोर्स स्थित प्रधानमंत्री आवास में नहीं गए थे।
सड़क। उन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभालने से एक दिन पहले भी उन्हें देखा था।
वे अगले दिन शपथ ग्रहण करने वाले कांग्रेस सांसदों की सूचियों का गहन अध्ययन कर रहे थे।
उन्हें अर्थव्यवस्था की स्थिति और हमारे विकल्पों के बारे में एक अत्यंत गोपनीय नोट दिया गया था।
हमारे अवसरों की बात करें तो। बस उन्हें इसकी पुष्टि करनी थी।
राव ने चुपचाप उनकी बातें सुनीं। 'मुझे हमेशा से पता था कि हम मुश्किल में हैं।'
उसने धीरे से कहा, 'लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतनी बुरी हालत में है।'
इस बार जब राव ने शुक्ला और नय्यर को देखा, तो उसने ऊपर की ओर देखा।
अधिकारियों ने जिज्ञासावश पूछा, 'सोना, दीपक?'
नैयर ने उत्तर दिया, 'यह आपके अनुमोदन के लिए है।'
उन्होंने कहा, 'लाइए।' और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए।
राव ने निर्णय लेने में जरा भी संकोच नहीं किया। चंद्र शेखर
वह हिचकिचाया था, क्योंकि उसे पता था कि गिरवी रखने के लिए उसकी निंदा की जाएगी।
country's gold. 'Ballia ke log kahenge maine unka sona bech diya (The
बलिया के लोग मुझ पर उनका सोना बेचने का आरोप लगाएंगे,' उन्होंने टिप्पणी की थी।
चिड़चिड़ाते हुए। लेकिन राव जानता था कि उस समय यही एकमात्र विकल्प था।
उसके लिए उपलब्ध।
'मनमोहन सिंह को जब पता चला कि पीवी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो वे

आए’
मैं दौड़कर अपने कमरे में गई और उसने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए।’ नय्यर ने खुलासा किया।
4 से 18 जुलाई 1991 के बीच, आरबीआई ने 46.91 टन सोना गिरवी रखा।
बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान 400 मिलियन डॉलर जुटाने जा रहे हैं।
इस अवधि के दौरान माल चार चरणों में भेजा गया। मई में
1991 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को 20 टन सोना बेचा था।
बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड 200 मिलियन डॉलर जुटाएगा।
वित्त मंत्री का पदभार संभालने के बाद शुरुआती हफ्तों में,
मनमोहन सिंह ‘घबराए हुए, झिझकते हुए और अनिर्णायक’ प्रतीत हुए।
दीपक नायर के अनुसार, बाद में ही उन्हें अपनी असली पहचान मिली।
राव वित्त मंत्रालय के कामकाज से बहुत परिचित नहीं थे,
दूसरी ओर, वह 'शांत, विनम्र लेकिन आश्चर्यजनक रूप से निर्णायक' थे।
‘बस, यही है। हम इसे करते हैं,’ वह कहते थे।
नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधार
रुपये के अवमूल्यन के साथ शुरू हुए ये घटनाक्रम, एक ऐसी स्थिति जो
विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा लगाए गए अवमूल्यन के कारण
मुद्रा सस्ती होने से असंतुलन कुछ हद तक कम होने की उम्मीद थी।
भारत के कम निर्यात और उच्च आयात के बीच, निर्यात अधिक हो गया।
प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है, जिससे भुगतान संतुलन (बीओपी) की स्थिति में सुधार होता है।
आयात के देश के निर्यात से अधिक होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ बीओपी संकट,
यह सिलसिला 1980 के दशक से चल रहा था। अवमूल्यन की बात करें तो, प्राइम मंत्री राव अधिक सतर्क थे। उन्हें पता था कि वे अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार को अपने साथ ले जाना होगा और अपने गठबंधन सहयोगियों को भी राजी करना होगा।
साथ ही वह निर्णय भी विवादास्पद था। राव बेहद सतर्क थे।
मनमोहन सिंह और नरेश सहित एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया गया

चंद्र, एस. पी. शुक्ला और दीपक नैयर राष्ट्रपति आर. से परामर्श करेंगे।
वेंकटारमन से उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि
मुद्रा अवमूल्यन कई चरणों में किया जाएगा।
'मनमोहन सिंह ने मुझे बताया कि अगर इसे कई चरणों में किया जाए,
लोगों को लगेगा कि (रुपये का) मूल्य लगातार घटता जाएगा।'
आर. वेंकटरमन ने कहा, '(लेकिन) मैं इसे कई चरणों में पूरा करना चाहता था।'
राष्ट्रपति को लगा कि 'अचानक लिया गया निर्णय' 'भयंकर मुद्रास्फीति' का कारण बनेगा।
अगर आपको ₹5 से अवमूल्यन करना ही है, तो क्यों न आप प्रतिदिन 25 पैसे का अवमूल्यन करें?
'बीस दिनों के लिए?' आर. वेंकटरमन ने मनमोहन सिंह से पूछा।
इस सुझाव से अचंभित होकर समूह ने विनम्रतापूर्वक उनसे कहा कि यह
यह इतना अच्छा विचार नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री इसका विरोध नहीं करना चाहते थे।
president, conscious as he was about heading a minority government. 'Abhi rashtrapati keh rahe hain to manana parhega (If the president is
राव ने अधिकारियों से कहा, 'ऐसा कहने पर हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी।'
हमने प्रधानमंत्री को बताया था कि यह एक बेहद बड़ी आपदा होगी।
दीपक नायर ने कहा, 'अगर हम वही करते जो आरवी चाहता था।' राव अंततः सहमत हो गए।
अंततः, अवमूल्यन 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को दो चरणों में किया गया।
पहले 9 प्रतिशत और फिर 11 प्रतिशत के लिए। सरकार ने फैसला किया कि
डॉलर के मुकाबले रुपये का 20 प्रतिशत अवमूल्यन करना और
अन्य मुद्राएँ; विश्व बैंक ने 22 प्रतिशत का सुझाव दिया था।
देश की रिपोर्ट में अवमूल्यन का उल्लेख किया गया है। इससे मुद्रास्फीति हुई। लेकिन अधिक पहुंच
अंतर्राष्ट्रीय ऋण से देश को अपने भुगतान संतुलन में मदद मिली।
संकट।

‘मुद्रा अवमूल्यन का पहला कदम स्थिति का जायजा लेने के लिए उठाया गया था।’
मनमोहन सिंह ने वर्षों बाद खुलासा किया। ‘प्रधानमंत्री नरसिम्हा
राव को इस विनिमय दर की दूसरी किस्त पर संदेह था।
समायोजन, और वास्तव में मुझे इसे रोकने के लिए कहा। लेकिन जब मैंने (सी.) को फोन किया।
रंगराजन (आरबीआई के डिप्टी गवर्नर) ने कहा कि उन्होंने पहले ही गोली चला दी थी। लक्ष्य।'
कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जो सलाहकार रह चुके थे
मनमोहन सिंह ने खुलासा किया कि सिंह—हालांकि वह
प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा 3 जुलाई 1991 की सुबह तड़के दिए गए निर्देशों के अनुसार,
अवमूल्यन के दूसरे चरण से बाहर निकलने के बाद—ऐसा सुबह 9.30 बजे ही हुआ, जब यह
बहुत देर हो चुकी थी। सुबह 9 बजे तक अवमूल्यन पहले ही हो चुका था।
जयराम रमेश ने यह नहीं बताया कि वित्त मंत्री ने इंतजार क्यों किया।
सुबह 9:30 बजे तक; प्रधानमंत्री ने उन्हें निर्देश दिए थे।
उस सुबह तड़के। साथ ही, रमेश ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्यों।
मनमोहन सिंह ने उपराज्यपाल सी. रंगराजन से बात करना बेहतर समझा।
और आरबीआई गवर्नर एस. वेंकिटारमनन को नहीं। क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था?
क्या यह कोई सोची-समझी रणनीति थी? क्या मनमोहन सिंह द्वितीय विश्व युद्ध के 'असली सितारे' थे?
अवमूल्यन का वह चरण, जिसके बारे में वह रंगराजन के साथ आश्वस्त थे।
क्या हम वित्त मंत्री की रणनीति के अनुरूप चल रहे हैं?
फिर भी, यह संकोची मनमोहन के स्वभाव के विपरीत प्रतीत होगा।
सिंह ने दो चरणों में अवमूल्यन करने का निर्णय लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने यह तय किया कि...
वित्त मंत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ देना—
बहुपक्षीय संस्थाओं को प्रसन्न करने के लिए। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि

राव,
जो विरोधाभासों को संभालने के अपने तरीके जानता था, वह दो लोगों को मारना चाहता था।
एक तीर से दो निशाने? दो चरणों में अवमूल्यन करना, जिसे वह जानता था कि वह टाल नहीं सकता, और साथ ही अपने आलोचकों को यह संकेत देना कि वह
उसे मात दे दी गई थी—और इसलिए वह असहाय था।
'राजनेताओं के बीच एक अर्थशास्त्री, और राजनेताओं के बीच एक राजनेता'
राजनीतिक जगत में मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्रियों के रूप में जाना जाता था।
जब वे वित्त मंत्री बने—और प्रधानमंत्री बने—तब वे अपने क्षेत्र में सक्रिय थे। जब वे वित्त मंत्री बने—और फिर प्रधानमंत्री बने।
2004 में उन्हें एक प्रख्यात अर्थशास्त्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन राजनीति में अनुभवहीन माना जाता था।
बाद में उन्हें भारत में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में सराहा गया।
एक समय था, जब मैं दक्षिण-दक्षिण के सचिव के रूप में कार्यरत था।
आयोग (1987-90) के दौरान, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में यह संकेत दिया था कि भारत को आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह उसके लिए हानिकारक होगा।
अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री बनने पर उन्हें अपनी राय बदलनी पड़ी।
मंत्री के इस अचानक बदलाव की आलोचना अन्य लोगों के साथ-साथ समाजवादी दलों द्वारा भी की गई।
नेता जॉर्ज फर्नांडीस, जो बाद में भारत के रक्षा मंत्री बने।
चंद्र शेखर, जिनके अधीन उन्होंने मुख्य आर्थिक अधिकारी के रूप में कार्य किया था
सलाहकार ने उन पर आरोप लगाया कि जब वे अपने चरम पर थे तब उन्होंने उनसे जानकारी छिपाकर रखी थी।
मंत्री जी, विश्व बैंक द्वारा भेजी गई भारत देश की रिपोर्टों के अनुसार
सरकार। उनमें इस बारे में निर्देश थे कि भारत को क्या करना चाहिए।
उसे अपने सामने मौजूद आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या करना चाहिए?
अपने मंत्री पद के शुरुआती वर्षों में मनमोहन सिंह राव से मार्गदर्शन लेते थे।
सलाह। 24 जुलाई 1991 को अपने पहले बजट भाषण में, सिंह ने हरी झंडी

दिखाकर शुरुआत की थी।
संरचनात्मक सुधारों के लिए पिछली सरकार को दोषी ठहराना चाहते थे।
देश की आर्थिक बदहाली के लिए। राजनीतिक रूप से चतुर राव
मैंने उनसे विनम्रता से कहा, 'हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए।' आर्थिक स्थिति को सुधारना
यह संकट 'एक सामूहिक जिम्मेदारी' थी—खासकर इसलिए क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी थी।
गठबंधन सरकार। अल्पमत सरकार चलाने का बोझ।
राव विपक्ष के साथ गलत शुरुआत नहीं करना चाहते थे।
पार्टियां।
'PV ko guru maantae thae Manmohan Singh (Manmohan Singh
वह पीवी को अपना गुरु मानता था। वह राव के पैर छुआ करता था।
राव के प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे भुवनेश चतुर्वेदी ने यह बात बताई।
लेकिन आने वाले वर्षों में मनमोहन सिंह अपने आप में एक अलग मुकाम हासिल कर चुके थे।
प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक विस्तारित अर्थव्यवस्था की अध्यक्षता की।
उनके पहले कार्यकाल के दौरान उच्च विकास पथ। वित्त के रूप में
मंत्री के रूप में उन्हें नरसिम्हा राव के अधीन जितनी स्वतंत्रता प्राप्त थी, उससे कहीं अधिक स्वतंत्रता उन्हें मंत्री के रूप में प्राप्त थी।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री।
■

मनमोहन सिंह का जन्म 1935 में गाह नामक एक पिछड़े गाँव में हुआ था।
अब पाकिस्तान में। जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, और
देश का विभाजन हुआ, उनका परिवार सीमा पार करके भारत चला गया।
उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और उनका पालन-पोषण उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया था।
दादी, जिनसे वह बहुत लगाव रखता था। गाह में बिजली नहीं थी, और भी बहुत कुछ।

स्कूल नहीं थे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थीं, और युवा मनमोहन को पैदल चलना पड़ता था।
उसे अपने उर्दू माध्यम के स्कूल तक जाने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता था। रात में वह एक चश्मदीद के सामने बैठकर पढ़ाई करता था।
मिट्टी के तेल का दीपक। उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रतिभा दिखाई—और आगे चलकर एक प्रख्यात अर्थशास्त्री बनें।
मनमोहन सिंह का साधारण पृष्ठभूमि से प्रभावशाली उत्थान था।
वह कहते थे कि इसका श्रेय गरीब छात्रों के लिए 'छात्रवृत्ति प्रणाली' को जाता है।
जो उस समय भारत में मौजूद था।
मैं कभी भी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढ़ने का खर्च नहीं उठा सकता था।
'मेरे पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर,' उन्होंने अमेरिकी पत्रकार चार्ली को बताया।
रोज़ ने कहा, 'मेरे माता-पिता मुझे भेज नहीं सके, लेकिन मैंने अच्छा प्रदर्शन किया।'
मैंने भारत में परीक्षाएं दीं, और इसलिए मुझे छात्रवृत्ति मिल गई।
और इसी तरह मैं कैम्ब्रिज गया।' उन्होंने कैम्ब्रिज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
और फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड के नफिल्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
उन्होंने 1962 में विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का फैसला किया, एक प्रयास के तहत।
यह समझने के लिए कि भारत इतना गरीब देश क्यों था।
रोज़ को दिए अपने इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि वे कैसे बने
एक पूंजीवादी और मुक्त बाजार में इतना दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति—इसके बावजूद
साधारण शुरुआत। साक्षात्कारकर्ता जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया।
समाजवाद, नियोजित अर्थव्यवस्था और राज्य-नियंत्रित उपायों को अपनाया।
देश में असमानता का समाधान करना। सिंह ने जवाब दिया कि उन्हें 'अभी भी ऐसा लगता है कि
समानता एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए।' लेकिन, उन्होंने आगे कहा, 'मैं करता हूँ।'

मेरा मानना है कि पूंजीवाद ने काफी गतिशीलता दिखाई है।
मनमोहन सिंह 1971 में सरकार में शामिल हुए और आगे चलकर...
उन्होंने भारतीय प्रशासन में उच्च सिविल सेवा पदों पर आसीन रहे।
वित्त मंत्रालय में सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर
भारत में, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। वे बने
2004 में अप्रत्याशित घटनाक्रम में प्रधानमंत्री—और
उन्होंने दस वर्षों तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का नेतृत्व किया।
लेकिन वे एकमात्र लोकसभा चुनाव नहीं जीत सके जिसमें उन्होंने भाग लिया था।
1999 में, दक्षिण दिल्ली से, हालांकि यह एक शहरी निर्वाचन क्षेत्र था।
यह उनके करियर का एक 'निम्नतम बिंदु' था जिसने उन्हें 'निराश' कर दिया था। इससे भी अधिक, क्योंकि उनके
पत्नी गुरशरण कौर ने कहा, '...वह जीवन भर विजेता रहे हैं।' कई लोगों को संदेह था कि कुछ दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने जानबूझकर ऐसा किया था।
उन्हें हराने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया गया। सिंह को एक
विद्वान लेकिन नीरस राजनेता; सड़क के बाहर वाहनों की सामान्य कतार
प्रधानमंत्री आवास या वहां आम तौर पर मिलने के लिए उमड़ने वाली भीड़
सरकार के प्रमुख, रेस कोर्स रोड स्थित 7 नंबर की सड़क के बाहर लापता थे, जब वह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने स्वयं अपने पद को कम महत्व देने का विकल्प चुना था।
राजनीतिक भूमिका।
फिर भी, जब भी उनकी राजनीति की समझ पर सवाल उठाए गए, सिंह ने
वह भड़क उठता। उसने एक व्यक्ति से कहा, 'यह सच नहीं है कि मैं राजनीतिक रूप से अनुभवहीन हूं।'
साक्षात्कारकर्ता। और फिर उन्होंने आगे कहा: 'मैं सार्वजनिक प्रणाली में तब से हूं जब से
1971...(और) मैंने हर तरह के मत वाले राजनेताओं से बातचीत की। मैंने (किया है) मैंने लगभग हर प्रधानमंत्री के साथ काम किया है... मुझे लगता है कि मेरे पास एक उचित समझ है।
राजनीतिक प्रक्रिया को प्रबंधित करने के तरीके की समझ...
यह महज एक खोखली शेखी नहीं निकली। उनकी 'प्रबंधन करने' की क्षमता

उनकी बातचीत के तरीके में 'राजनीतिक प्रक्रिया' पूरी तरह से प्रदर्शित थी।
जटिल प्रक्रिया के बावजूद, भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता सफल रहा।
एक या दो महीने के लिए नहीं, बल्कि साढ़े तीन महीने की अवधि में।
कई वर्षों तक, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल भी शामिल था।
जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया
एक मजबूत राजनीतिक नेता के लिए भी यह काफी मुश्किल होता।
भारी बहुमत, ऐसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए जो समझौतावादी विकल्प था।
देश का नेतृत्व किया—और एक कमजोर नेता के रूप में देखा गया। लेकिन फिर, परमाणु
यह सौदा एकमात्र ऐसा उदाहरण था जब सिंह ने एक तरह से अपना अधिकार जताया।
उनके पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था।
सिंह ने एक जटिल और पेचीदा विषय की समझ दिखाई।
परिस्थिति, वास्तविक राजनीति की समझ और लक्ष्य प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प
उसका लक्ष्य चाहे कितनी भी बाधा क्यों न आए, वह उसे हासिल करता रहा। साथ ही, उस दौरान
भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में जो समय लगा, उसमें उन्होंने सफलता हासिल की।
अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति और हर चीज को चकमा देकर या उससे बचकर निकल जाना—
हर विचारधारा के राजनेता, उनकी अपनी पार्टी के भीतर के विरोधी, देश में उनके आलोचक
और विदेशों में, और सबसे बढ़कर, उनके सिंहासन के पीछे की शक्ति—सोनिया Gandhi.
वी

मनमोहन सिंह की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम उनके बारे में विस्तार से न जान लें।
उनके शासनकाल के दौरान निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सोनिया गांधी द्वारा निभाई

गई भूमिका
प्रधानमंत्रित्व काल; यह जितना उनके बारे में है उतना ही उनके बारे में भी है।
13 मई 2004 को सोनिया गांधी टीवी के सामने बैठ गईं।
जनपथ, 10 बजे। सुबह के आठ बज रहे थे, जब आम चुनाव के पहले नतीजे आने शुरू हुए। जैसे ही उसने अपनी पलकें तेज़ी से झपकाईं,
स्क्रीन पर संख्याएँ चमक उठीं। वह कहा करती थी कि जब वह छोटी थी
तनावग्रस्त होने के कारण, उसे बार-बार पलकें झपकाने की आदत हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि
वह जानती थी कि चुनाव परिणाम उसके नेतृत्व को दर्शाएंगे—यह पहली बार था।
उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आगे बढ़कर किया था और खुद को समर्पित कर दिया था।
पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं।
सुबह 10:30 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो गई थी। कांग्रेस
आगे चल रही थी। भाजपा को चुनाव जीतने का इतना भरोसा था कि उसने
मतदान की तारीखें छह महीने आगे बढ़ा दी गई थीं। सोनिया गांधी की रणनीति
क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करने का फायदा मिला। कांग्रेस की सीटों की संख्या...
भाजपा की तुलना में 7 अधिक यानी 145 सीटें। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक सीटें थीं।
कांग्रेस पार्टी के लिए संकटमोचक बनकर सामने आए। राज्य ने प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की थी।
यूपीए को लोकसभा की 34 सीटें मिलीं (कांग्रेस को 29 सीटें मिलीं और
कांग्रेस की सहयोगी तेलंगाना राष्ट्र समिति के 42 सांसदों में से 5 सांसद हैं।
आंध्र प्रदेश को लोकसभा में भेजा गया। कांग्रेस एकमात्र सत्ता के रूप में उभरी।
सबसे बड़ी पार्टी।
जब उनकी बेटी प्रियंका गांधी अंदर आईं, तो आमतौर पर शांत रहने वाली महिला का चेहरा बदल गया।
सोनिया ने उत्साह से उसे गले लगाया। उसने कहा, 'हमने कर दिखाया!'
जैसे ही यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है,

घटनाएँ
सोनिया गांधी के लिए गति बढ़ने लगी। कांग्रेस एक ध्रुव पर थी।
नई सरकार बनाने की स्थिति में। परिणाम आने से पहले ही।
अंततः अंदर आने पर, सहयोगी दलों के नेता उनसे मिलने आए थे—सभी
13 और 14 मई 2004 के दौरान। चुनावों से पहले, सोनिया गांधी राष्ट्रपति थीं।
जिन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों से संपर्क किया था—उस समय उनके पास
उन्होंने उसे टालमटोल किया। अब वे उसे अपने पत्र देने के लिए दौड़ पड़े।
सहायता।
चुनाव पूर्व सहयोगियों के साथ मिलकर कांग्रेस ने 222 सीटें हासिल की थीं।
272 के जादुई मध्य बिंदु तक पहुंचने के लिए पचास और वोटों की आवश्यकता थी।
सरकार का गठन करें। चार वामपंथी दल—सीपीआई (एम), सीपीआई, आरएसपी
और
फॉरवर्ड ब्लॉक ने आश्चर्यजनक रूप से 59 सीटें जीती थीं - उनका प्रदर्शन अच्छा रहा
था।
पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में अपने तीन गढ़ों में वे काफी मजबूत स्थिति में हैं।
सोनिया गांधी की पहली पसंद उनके सहयोगी थे। उन्हें अचानक एक
उसे इस बात से राहत मिली कि अब उसे किसी की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
Samajwadi Party, the Bahujan Samaj Party, and the Rashtriya Lok Dal,
विद्रोही नेताओं के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए। वह जानती थी कि
समाजवादी पार्टी के साथ पहले उनके पति राजीव को जिन समस्याओं का सामना
करना पड़ा था,
पार्टी। सपा ने अपने समर्थन के बदले हर मोड़ पर अपना हिस्सा मांगा होगा। उत्तर
प्रदेश में सत्ता में रही सपा ने ठुकरा दिया था।
कांग्रेस द्वारा (2004) लोकसभा के समक्ष गठबंधन बनाने का प्रस्ताव
लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की सीटों में से 15 प्रतिशत सीटें हैं।
सभा में, सपा को दिल्ली में किंगमेकर के रूप में उभरने की उम्मीद थी। लेकिन
अब, भले ही कांग्रेस ने 35 सीटें जीत ली थीं, लेकिन उसे इसकी आवश्यकता नहीं
थी।

उन पर निर्भर रहें।
परिणाम घोषित होने के कुछ ही घंटों के भीतर, सीपीआई (एम) और सीपीआई के शीर्ष नेतृत्व ने
सीपीआई (एम) के नवनिर्मित भवन ए. के. गोपालन भवन में सभी लोग एक साथ जमा हुए थे।
मध्य दिल्ली में मुख्यालय का निर्माण किया। सीपीआई (एम) के महासचिव
भाजपा विरोधी गठबंधन बनाने के लिए मशहूर हरकिशन सिंह सुरजीत, उनके
पार्टी के सहयोगी सीताराम येचुरी, प्रकाश करात और सीपीआई के नेता,
ए. बी. बर्धन और डी. राजा ने नई स्थिति का जायजा लिया। वामपंथी
उन्होंने चुनाव से पहले ही धर्मनिरपेक्ष सरकार का समर्थन करने का फैसला कर लिया था।
अगर मौका मिले तो भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए। जब सोनिया गांधी
सुना है कि वामपंथी दल कांग्रेस का समर्थन करने के लिए इच्छुक हैं।
सरकार के समर्थन को मजबूत करने के लिए उन्होंने तुरंत कदम उठाए। वामपंथी
सरकार में शामिल न होने का फैसला किया, जो सोनिया गांधी के लिए संभव होता।
स्वागत है, लेकिन इसे 'बाहर से' समर्थन दें।
जब सीपीआई नेता ए. बी. बर्धन ने सरकार से पद छोड़ने का आह्वान किया
एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) के लिए सोनिया गांधी ने प्रस्ताव रखा।
उन्होंने तुरंत मनमोहन सिंह को समूह का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया।
formulate the CMP; Pranab Mukherjee, Arjun Singh, and Jairam
रमेश समिति के अन्य सदस्य थे।
सोनिया गांधी ने कांग्रेस के चुनाव पूर्व सहयोगियों से संपर्क साधा और
छोटी पार्टियों को यूनाइटेड प्रोग्रेसिव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को यूपीए गठबंधन का नाम दिया गया।
शरद पवार ने भी शुरू में उनका समर्थन किया था, हालांकि उनके पास
सोनिया गांधी की विदेश नीति के विरोध में 1999 में कांग्रेस से अलग हो गए।
और आगे चलकर उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का गठन किया।
अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए।

परिणाम घोषित होने से पहले ही, सोनिया गांधी के प्रबंधकों ने
कांग्रेस ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करना शुरू कर दिया था।
यूपीए की। 7 मई को, परिणाम घोषित होने से पहले ही, उनकी राजनीतिक
सचिव अहमद पटेल ने वी. पी. सिंह से संपर्क किया। उन्होंने आगे की कार्रवाई की।
पत्रकार संतोष भरतिया, जो उपराष्ट्रपति पटेल के करीबी थे, ने उपराष्ट्रपति से पूछताछ की।
सोनिया को प्रधानमंत्री बनाने में मदद की—भले ही यह उपराष्ट्रपति ही थीं जिन्होंने ऐसा किया था।
उन्होंने 1989 में अपने पति राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। सत्ता से बाहर होने के बावजूद, उपराष्ट्रपति को कई विपक्षी नेताओं द्वारा सम्मान दिया जाता था। 10 तारीख को
मई 2004 में, वीपी अपोलो अस्पताल से गाड़ी चलाकर निकले, जहाँ उनका इलाज होता था।
डायलिसिस के लिए सुबह 10 बजे जनपथ पर सोनिया गांधी से मिलने के लिए जाना है। अगले कुछ घंटों में
उन्होंने वामपंथी नेताओं, एच. डी. देवेगौड़ा और डीएमके प्रमुख एम. से बात की।
करुणानिधि ने सोनिया गांधी को अपना समर्थन देने के लिए उन्हें राजी किया। उन्होंने करुणानिधि को लाया।
करुणानिधि के आसपास, हालांकि डीएमके नेता ने कहा था कि उनके पास
उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने का वादा किया।
नतीजे अभी-अभी घोषित हुए हैं, और अहमद पटेल, जो आम तौर पर इससे दूर रहते थे, अब हैरान हैं।
मीडियाकर्मियों ने एक रिपोर्टर के साथ बैठने का फैसला किया। उन्होंने विस्तार से बात की।
सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्यों थीं? उद्देश्य
शीला भट्ट को दिए गए 2,000 शब्दों के साक्षात्कार का उद्देश्य इस विचार को सामने रखना था—और
पहले स्थिति का जायजा लें।
कांग्रेस प्रबंधकों ने 15 मई को सीपीपी की बैठक बुलाई।

अपने नेता का चुनाव करना था। मनमोहन सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें यह करना था।
सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित कीजिए और प्रणब मुखर्जी उसका समर्थन करेंगे।
लेकिन लोकसभा के लिए चुने गए उत्साहित मुखर्जी
पहली बार (वे इससे पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे),
उन्होंने माइक पकड़ा और उपस्थित सांसदों का सीपीपी में स्वागत किया।
'संसद के सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्य' के रूप में बैठक और फिर भी
'लोकसभा के सबसे नए सदस्यों में से एक'। सब हंस पड़े।
फिर उन्होंने सोनिया गांधी का नाम सीपीपी के नेता के रूप में प्रस्तावित किया और उन्हें
सोनिया गांधी ने माइक संभाला। एक जोशीले भाषण में उन्होंने पद स्वीकार किया;
उन्होंने कांग्रेस की जीत को भाजपा की विचारधारा की अस्वीकृति बताया।
और आरएसएस। यह एक 'समावेशी, धर्मनिरपेक्ष और एकजुट' राष्ट्र के निर्माण के लिए मतदान था।
भारत।
■

रविवार, 16 मई, सोनिया के भाग्य को बदलने वाला दिन था।
गांधी और मनमोहन सिंह के बारे में। यह वही दिन था जब उन्होंने आमंत्रित किया था।
कांग्रेस के चुनाव-पूर्व सहयोगी दलों और वामपंथी दलों के नेताओं ने
जनपथ स्थित 10 नंबर पर रात्रिभोज। यह रात्रिभोज बैठक औपचारिक स्वरूप देने के लिए आयोजित की गई थी।
यूपीए सरकार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन देना।
शाम के अंत तक गठबंधन में तेरह पार्टियां रह गई थीं।
कांग्रेस के अलावा, वे राष्ट्रीय जनता दल (24 सदस्यों के साथ) थे।
सांसद), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (16), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (9),
पट्टाली मक्कल काची (6), तेलंगाना राष्ट्र समिति (5), झारखंड मुक्ति मोर्चा (5), मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम

(एमडीएमके) (4), लोक जनशक्ति पार्टी (4), केरल कांग्रेस (1), भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग (1), जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (1), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-अथावले (1), और अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (1).

जयराम रमेश ने अंतिम प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। इसमें सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित किया गया था।

प्रधानमंत्री पद के लिए गांधी का नाम। समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह को बड़ी दयनीय स्वर में शिकायत करते हुए सुना जा सकता था कि सूची में हस्ताक्षरकर्ताओं में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं थी!

दरअसल अमर सिंह को रात्रिभोज में आमंत्रित नहीं किया गया था।

सीपीएम नेता हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ गए। सलमान खुर्शीद और अंबिका सोनी 7, जनपथ के गेट पर खड़े थे।

जब वह सुरजीत के साथ पहुंचे तो नेताओं का रात्रिभोज के लिए स्वागत कर रहे थे। उन्होंने अमर सिंह को कार से उतरते और बहस करते देखा।

सोनिया गांधी की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा समूह तैनात किया गया है। सुरक्षाकर्मियों ने अहमद पटेल को तुरंत सूचना भेजी। पटेल ने अमर को मंजूरी दे दी। सिंह का प्रवेश हुआ। कुछ मिनट बाद, आगंतुकों को अंदर भेज दिया गया।

उन दिनों अमर सिंह समाजवादी पार्टी के सुपरस्टार थे।

जैसा कि हमने देखा है, यह पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, और कांग्रेस द्वारा समर्थित। लेकिन सोनिया गांधी ने इस ओर देखा तक नहीं।

उस शाम जब अमर सिंह बैठे तो अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। सोनिया गांधी की राह पर चलते हुए, वे भी उनके प्रति उदासीन थे। अंबिका बाद में सोनी को जोर-जोर से यह कहते हुए सुना गया कि वह 'बिना अनुमति के घुस आया' था—जो उसे इससे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने इसे जानबूझकर किया गया अपमान समझा।

मुलायम सिंह यादव द्वारा सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से नाखुश रहा हूं। 2004 के चुनावों में देश भर में हुए चुनावों ने देश को नुकसान पहुंचाया था। कांग्रेस ने भाजपा को कई सीटों पर सत्ता में आने में मदद की।

उस शाम के रात्रिभोज में सोनिया गांधी असामान्य रूप से एकांतप्रिय थीं।

वह एक कोने में बैठी थी, और आश्चर्यजनक रूप से, उसने ज्यादातर वी. पी. सिंह से ही बात की।
हालांकि उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक रूप से अपने पति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन असल में वही थे जिन्होंने
राम विलास पासवान को सरकार में शामिल होने के लिए राजी कर लेंगे और
संचार मंत्रालय को स्वीकार करें, न कि इस पर जोर दें।
रेल मंत्रालय।
सोनिया गांधी द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बावजूद, लेकिन अपने साथ जोड़ने के लिए उत्सुक
सत्ता में आने के बाद, एसपी ने घोषणा की कि वे सत्ता सौंप देंगे।
सरकार को 'बाहरी' समर्थन प्राप्त था। बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों को भी यही समर्थन प्राप्त था।
राष्ट्रीय लोक दल। यूपीए के सदस्यों की संख्या, साथ ही इसे बाहरी समर्थन देने वालों की संख्या मिलाकर, प्रभावशाली 317 सीटें हो गईं।
संसद।
अगले दिन, 17 मई को, शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ शुरुआत हुई।
सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की संभावना है, जिसे समर्थन प्राप्त होगा।
वामपंथी दलों की प्रतिक्रिया बाज़ारों के लिए बिल्कुल भी आश्वस्त करने वाली नहीं थी।
यूपीए सरकार की संभावना को लेकर वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह से अनिश्चित था।
नकारात्मक, भले ही सरकार का नेतृत्व कांग्रेस को करना था।
जिस पार्टी ने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी।
सोनिया गांधी की विदेश नीति को लेकर विवाद बढ़ने लगा था।
पूर्ववृत्त। हालांकि उदास वाजपेयी, निवर्तमान प्रधानमंत्री थे,
accept the verdict philosophically—‘Kuch tajjub to hua ki kaise hogaya
ये (मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हुआ)’—भाजपा
उसने सोनिया पर निशाना साधा और उसके विदेशी पूर्वजों पर हमला करते हुए उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया।

उसे प्रधानमंत्री बनने से रोकें।
मैं केवल सफेद कपड़े पहनूंगा, नंगी ज़मीन पर सोऊंगा और केवल भुना हुआ मांस खाऊंगा।
'चना', भाजपा की तेजतर्रार नेता सुषमा स्वराज को धमकी देते हुए कहा गया, जब वह
मैंने सुना है कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। इससे भी ज्यादा
नाटकीय ढंग से, विवाहित स्वराज ने धमकी दी कि वह अपना सिर मुंडवा लेगी।
शोक में डूबी हिंदू विधवा। स्वराज ने मीडिया से कहा, 'अगर 60 साल बाद...'
स्वतंत्रता के बाद हम एक और विदेशी को सर्वोच्च पद पर बिठाते हैं, फिर यह
इसका मतलब यह होता कि 100 करोड़ लोग अक्षम थे।' एक विदेशी
उन्होंने कहा कि उन्हें 'रक्षा से जुड़े सभी रहस्यों की जानकारी होगी'। उमा भारती ने इस्तीफा दे दिया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 'गरिमा और सम्मान को बनाए रखने' के लिए।
100 करोड़ भारतीयों के लिए, के. एन. गोविंदाचार्य ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया।
'स्वाभिमान' (आत्मसम्मान) आंदोलन। अपने नाटकीय अंदाज को जारी रखते हुए
दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान, दर्जनों महिलाओं ने अपनी कलाई पर चाकू रखकर चित्र बनाए।
उन्होंने अपना ही खून बहाया—ताकि कांग्रेस को घेर सकें।
एक सरकार से दूसरी सरकार का हस्तांतरण, जो आमतौर पर बिना किसी बाधा के हो जाता था।
भारत में, अचानक हालात बिगड़ने लगे। लेकिन, राजनीति में ऐसा कम ही होता है।
यह एक पूर्वनिर्धारित स्क्रिप्ट का अनुसरण करता है।
■

विपक्ष की आवाजें उग्र होती जा रही थीं, फिर भी एक गंभीर बैठक हुई।
17 मई की दोपहर को जनपथ पर सुबह 10 बजे यह कार्यक्रम शुरू होगा।
यूपीए सरकार के स्वरूप और उसके स्वरूप में नाटकीय रूप से बदलाव लाना
नेतृत्व।

दोपहर करीब 2 बजे का समय रहा होगा। मुझे लगता है कि यह किसी मीटिंग से ठीक पहले का समय था।
वरिष्ठ नेताओं की बैठक होने वाली थी,' नटवर सिंह ने इस लेखक को बताया। 'मैं मनमोहन सिंह से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि वह 10 बजे हैं।
जनपथ... मैं उसे ढूंढने वहाँ गया था... जब मैं वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने (secretaries) said, "Aap andar jaaiye (You can go in)".' As a Gandhi
परिवार के करीबी होने के कारण, उनकी गांधी परिवार तक आसानी से पहुंच थी।
'वह (सोनिया) सोफे पर बैठी थी... मनमोहन सिंह और
प्रियंका भी वहां मौजूद थीं। सुमन दुबे भी कुछ देर बाद आईं।
सोनिया गांधी काफी परेशान दिख रही थीं... तभी राहुल आए और बोले
हम सबके सामने, "मैं तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। मेरा
मेरे पिता की हत्या कर दी गई, मेरी दादी की हत्या कर दी गई। छह महीने में, आप उन्हें मार डाला जाएगा।
राहुल ने धमकी दी कि अगर सोनिया ने उनकी बात नहीं मानी तो वह कोई चरम कदम उठाएंगे।
उसे। नटवर सिंह ने याद करते हुए कहा, 'यह कोई साधारण धमकी नहीं थी, राहुल एक
दृढ़ निश्चयी व्यक्ति। उन्होंने सोनिया को फैसला लेने के लिए 24 घंटे का समय दिया।
राहुल के यह कहने के बाद सोनिया स्पष्ट रूप से परेशान और रोती हुई दिखाई दीं।
अपनी माँ को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार।
प्रधानमंत्री पद के लिए।
कमरे में सन्नाटा छा गया।
आप क्या कह सकते थे? पंद्रह से बीस का वह समय बहुत कठिन था।
कुछ मिनटों तक वे बहुत तनाव में थे।' मनमोहन सिंह अवाक रह गए।
प्रियंका ने कुछ ऐसा कहा था, "राहुल इसके खिलाफ है, और वह सक्षम है।"
कुछ भी करने का।
हमने सोनिया को अंदर जाने के लिए कहा और कहा कि हम मामले को सुलझा लेंगे।

नटवर सिंह ने याद किया।
‘राहुल की तरफ से कुछ बड़ा कदम उठाने की धमकी ने ही सोनिया को ऐसा करने पर मजबूर किया।’
गांधी ने उनका मन बदल दिया। असल में उनके बेटे ने उनके लिए फैसला लिया।
नटवर सिंह ने कहा। उन्होंने आगे कहा, 'एक मां होने के नाते उनके लिए यह असंभव था।'
राहुल को नजरअंदाज करो।
अटल बिहारी वाजपेयी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने की सलाह भी दी थी।
मंत्री पद। सीपीपी नेता के रूप में चुने जाने के तुरंत बाद,
उनमें से दो ने आपस में बात की, और सोनिया ने उनसे आशीर्वाद मांगा।
अब उन्हें भारत की अगली प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा था।
वाजपेयी ने उन्हें बधाई दी और कहा, 'आपको मेरा आशीर्वाद है।'
प्रचुरता।’ और फिर उन्होंने आगे कहा, ‘इनाम मत लो। तुम इसे बाँट दोगे।’
इससे देश में अशांति फैल सकती है और अंततः सिविल सेवाओं की वफादारी पर भी दबाव पड़ सकता है।'
वाजपेयी सोनिया गांधी के इतने करीब थे कि उनसे बात कर सकते थे।
स्पष्ट रूप से कहें तो—और ऐसे समय में जब वह सफलता के शिखर पर थी, एक उभरती हुई कलाकार के रूप में
विजेता। हालांकि वे प्रतिद्वंद्वी थे, फिर भी उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे।
पूरे रिश्ते के दौरान। जब संसद भवन पर हमला हुआ
दिसंबर 2001 में, सोनिया ने तुरंत वाजपेयी को फोन करके पता लगाया था।
अगर वह सुरक्षित और ठीक था तो वह बाहर गया। वह उसके हावभाव से भावुक हो गया था—और
कई लोगों ने इसे इस बात का संकेत माना कि 'भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है'।
मनमोहन सिंह को राहुल गांधी के साथ बैठक में बुलाया गया था।
यह महत्वपूर्ण था। तत्काल परिवार के अलावा, वह वहां मौजूद एकमात्र व्यक्ति था।
परिवार और सुमन दुबे, जो परिवार की दोस्त थीं—जब तक नटवर
सिंह मनमोहन को खोजने के अपने मिशन पर संयोगवश वहां पहुंच गए थे।

सिंह। यह स्पष्ट था कि सोनिया गांधी चाहती थीं कि वहां मौजूद सभी लोग यह जान लें।
उसके फैसले के बारे में जानें और राहुल की भावनाओं के बारे में सीधे उससे ही पता करें।
मनमोहन सिंह की बैठक में उपस्थिति से पता चलता है कि तब तक सोनिया गांधी
उन्होंने उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने का मन बना लिया था।
जैसा कि बाद में पता चला, राहुल को अपनी माँ की जान का जो डर था, वह सच साबित हुआ।
देश के प्रधानमंत्री पद से हटने के लिए मजबूर होने के कारण, वह बहुत करीब आ गई थी।
इसकी सुलभ दूरी ने उसे पार्टी और समाज में स्वीकार्यता दिलाई।
देश—जैसा कि और कुछ नहीं कर सकता था। अपनी विदेशी उत्पत्ति के बावजूद,
वह कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली पार्टी प्रमुख बनने वाली थीं।
बाईस वर्षों तक नेतृत्व करने वाली महिला—और दल में सबसे लंबी सदस्य
उन्होंने 2022 में पद छोड़ दिया।
दुनिया भर में कई राजनीतिक वंश हैं। लेकिन एक ऐसा वंश था
नटवर सिंह का कहना था कि नेहरू-गांधी परिवार के समानांतर कोई दूसरा परिवार नहीं था।
कई वर्षों बाद। परिवार के सात सदस्यों ने शासन किया या सत्ता संभाली।
और एक विशाल देश पर अभूतपूर्व प्रकार का प्रभाव, एक वर्ष से अधिक समय तक।
सदी—मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय
Gandhi, Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi, and Rahul Gandhi, with
प्रियंका गांधी वाड्रा (लिखते समय) एक
साथ ही राजनीतिक भूमिका भी।
सोनिया गांधी द्वारा देश के प्रधानमंत्री पद को ठुकराने के फैसले ने
ट्यूरिन में जन्मी इतालवी मूल की यह महिला उस कड़ी की सबसे लंबी कड़ी है।
सरकार के कार्यकारी प्रमुख के रूप में नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में।
यह एक भव्य पुरानी पार्टी है—और मनमोहन सिंह की सत्ता के पीछे की शक्ति के रूप

में भी।
प्रीमियरशिप।
■

राहुल के साथ तीखी बहस के तुरंत बाद सोनिया वहां से चली गईं।
कमरा। उनकी मुलाकात पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से होनी थी, जिन्हें उन्होंने फोन किया था।
उस दोपहर 10 बजे जनपथ तक। उनके साथ मनमोहन भी थे।
सिंह और नटवर सिंह। उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे लोगों में प्रणब सिंह और नटवर सिंह भी शामिल थे।
मुखर्जी, शिवराज पाटिल, गुलाम नबी आज़ाद, एम. एल. फोतेदार, अहमद
पटेल और अन्य। 'मैंने डॉ. मनमोहन सिंह से कार्यभार संभालने का अनुरोध किया है।
उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा, 'प्रधानमंत्री के रूप में।'
वहां सन्नाटा छा गया।
मनमोहन सिंह ने अंत में कमजोर स्वर में कहा, “मैं आभारी हूँ। लेकिन मैं नहीं कर सकता।”
स्वीकार करता हूँ। मेरे पास इसका अधिकार नहीं है।'
यह जानते हुए कि सोनिया गांधी ने अपना मन बना लिया था, नटवर सिंह
इस बिंदु पर उन्होंने बीच में कहा, 'मनमोहन सिंह जी को 'ना' कहने का कोई अधिकार नहीं है।'
क्योंकि जिसके पास अधिकार है, वही उसे हस्तांतरित कर रहा है।'
नटवर सिंह ने आगे कहा, 'प्रणब मुखर्जी ने मुझे घूरकर देखा।'
सदन के अंदर मौजूद लोगों के अलावा, कई कांग्रेस सांसद इंतजार कर रहे थे।
बाहर। यह बात फैल गई थी कि सोनिया गांधी शायद चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी।
प्रधानमंत्री पद। 44 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में, राजनेता और सदस्य
मीडिया घंटों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिरकार, प्रणब
मुखर्जी और नटवर सिंह बंगले से बाहर निकले। उन्होंने बताया
वहाँ मौजूद सभी लोगों को पता था कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी।
अगले दिन राष्ट्रपति भवन। कई लोगों ने राहत की सांस ली; उन्होंने सोचा

उसने सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करने का फैसला कर लिया था।
■

उस सुबह सोनिया गांधी ने अहमद पटेल और अंबिका सोनी को फोन किया था।
उन्हें अलग से सूचित करने के लिए कि उन्होंने प्रधान पद न लेने का निर्णय लिया है।
मंत्री पद। पटेल और सोनी उनके राजनीतिक सचिव थे, हालांकि
अक्सर मतभेद होते रहते थे। सोनिया ने पटेल से कहा कि वह नया नहीं चाहतीं।
उसकी विदेश नीति के कड़े विरोध के कारण सरकार कमजोर पड़ जाएगी।
उत्पत्ति। पटेल, जो आने वाले वर्षों में अपार शक्ति का प्रयोग करेंगे।
इसके बाद (सोनिया उस पर बहुत अधिक निर्भर हो गई), उसने समझाने की कोशिश की।
उसने उसे भी सूचित किया—लेकिन असफल रही। उसने अपने जनार्दन द्विवेदी को भी इस बारे में बताया।
राजनीति की गहरी समझ रखने वाली हिंदी भाषण लेखिका ने अपने इस निर्णय के बारे में बताया।
अंबिका सोनी ने ऐसी भाषा में बात की जिससे सोनिया आसानी से जुड़ सकीं।
विदेश सेवा में कार्यरत उनके पति सोनी ने पहले ही दुनिया भर की यात्रा कर ली थी।
इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान उन्हें पहचान लिया और उन्हें युवा कांग्रेस का प्रमुख बना दिया। सोनिया गांधी के साथ उनका तालमेल इतना अच्छा था कि
उसके साथ यात्रा करते समय, अंबिका को बहुत आनंद आता था।
वह सोनिया के कमरे में तब भी जा सकती थी जब उसने अपने बालों में रोलर्स लगा रखे थे!
यह समझते हुए कि सोनिया को मनाना असंभव है, सोनिया ने कोशिश भी नहीं की।
उसे अपना मन बदलने के लिए मनाओ। 'आपको इसे इस तरह से करना होगा कि यह
'आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी,' उसने सोनिया से कहा।
सोनिया ने अहमद पटेल के साथ मिलकर एक 'स्पष्ट' बयान तैयार किया था।
प्रधानमंत्री न बनने के उनके निर्णय के बारे में। व्यस्त जीवनशैली को देखते हुए।
परिणामों के बाद से हुई घटनाओं के चलते, उसे यह सोचने का एक पल भी नहीं

मिला कि क्या
वह कहती थीं, 'आपको कुछ ऐसा तैयार करना चाहिए जो किसी को प्रभावित करे।'
सोनी ने सुझाव दिया, 'लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए।'
मुझे 17 तारीख की सुबह सोनिया गांधी का फोन आया—
उससे बात करने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए। जैसे ही मैंने उसे बधाई दी, उसने बोलना शुरू किया।
अगर वह सत्ता में आती हैं तो भाजपा उनके लिए क्या समस्याएं खड़ी करेगी, इस पर विस्तार से चर्चा करना।
प्रधानमंत्री, जिससे देश में हिंसा भड़क सकती है। हालांकि उनकी सटीक तारीख
मुझे शब्द नहीं सूझ रहे, उसने कुछ ऐसा कहा, 'वे मेरा
'काम करने में बहुत कठिनाई हो रही है।' जब मैंने रिसीवर नीचे रखा, तो अचानक
मुझे लगा कि उसकी आवाज़ उदास थी, उत्साहित नहीं। और मुझे आश्चर्य हुआ...
वह जीत के क्षण में आगे आने वाली कठिनाइयों का जिक्र क्यों कर रही थी?
वह बातचीत मुझे छत्तीस घंटे बाद याद आई जब
उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने का अपना निर्णय घोषित किया।
सोनिया गांधी ने कुछ लोगों से बात करने के लिए कांग्रेस पदाधिकारियों को भेजा था।
उन्होंने अपने फैसले को सार्वजनिक करने से पहले ही प्रमुख नेताओं को इसके बारे में बता दिया था। 17 तारीख को।
मई, नटवर सिंह और एम. एल. फोतेदार वी. पी. सिंह से मिलने गए थे और
लालू प्रसाद यादव। उपराष्ट्रपति चुपचाप सुनते रहे जब उन्हें बताया गया कि सोनिया
अब वे मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। 'मेरे पास कोई नहीं है'
आपत्ति,' उपराष्ट्रपति ने अपने आगंतुकों से कहा। उन्होंने मुझे एक बातचीत के दौरान बताया।
कुछ समय बाद हुई बातचीत में, 'उसके बच्चे नहीं चाहते थे कि वह'
जब वह प्रधानमंत्री बनीं, तो लोगों को उनकी जान का खतरा महसूस हुआ।
सीपीआई (एम) नेता सोमनाथ चटर्जी ने मुझे वी.पी. की बात की पुष्टि की।
सिंह ने कहा था कि सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री पद छोड़ने का निर्णय
उन्हें मंत्री पद 'उनके बच्चों की वजह से' मिला था। 'हम उनके बारे में सहमत हो गए थे।'

अगर वह प्रधानमंत्री बन जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं अगर उसके बच्चे उसके लिए चिंतित हों?
क्या आप नहीं चाहते थे कि वह प्रधानमंत्री बने?' 17 मई की उस शाम, वह
कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने वाली पार्टियों के नेताओं को 10 तारीख को आमंत्रित किया गया।
जनपथ जाकर उन्होंने अपने फैसले की जानकारी दी और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। उन्होंने वहां मौजूद नेताओं को इसका कोई कारण नहीं बताया।
उसके फैसले के लिए।
'वह बहुत कठिन बैठक थी,' नटवर सिंह ने याद किया। नेताओं
बहुत परेशान थे. राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव आक्रामक हो गये.
उन्होंने कहा, 'आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें तो टीवी से ही पता चला।'
stormed. Harkishan Singh Surjeet tried to dissuade Sonia. Ram Vilas
बिहार स्थित लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पासवान ने कहा कि उनके पास
उन्होंने सोनिया गांधी का समर्थन किया, किसी और का नहीं।
तब तक मीडिया ने आसपास फैली अनिश्चितता को उजागर कर दिया था।
सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ज्योति बसु।
जो उस दिन दिल्ली में थे, उन्होंने (उनके प्रति) निराशा व्यक्त की।
फ़ैसला)'।
प्रकाश ने कहा, 'वामपंथी दल उनसे प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद कर रहे थे।'
करत ने बाद में कहा, 'हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह मनमोहन सिंह होंगे।'
यह एक ऐसी स्थिति थी जो उनकी पार्टी, यूपीए, और के सामने प्रस्तुत की गई थी।
वामपंथी दलों का समर्थन करते हुए।
शाम की बैठक में उपस्थित लोग इतने नाराज थे कि
उन्होंने अपना निर्णय अगले दिन तक टालने का फैसला किया। हालांकि, सोनिया गांधी ने
वह अडिग रही। उसके भीतर की मातृत्व भावना प्रबल हो गई थी।
राजनीतिज्ञ।

■

18 मई की सुबह परिवार की एक निजी बैठक से शुरू हुई।
सोनिया, प्रियंका और राहुल - जनपथ स्थित 10वीं कक्षा में। उन्होंने 'सबसे महत्वपूर्ण' विषय पर चर्चा की।
उनके जीवन का कठिन निर्णय।
उसी दिन बाद में, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के साथ
उन्होंने राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम से मुलाकात की। सामान्यतः, जब
सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी के नेता को बैठक के लिए आमंत्रित किया जाता है।
राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हैं, तो वे सर्वोच्च सत्ताधारी के रूप में दिखाई देते हैं।
हालांकि, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह
सिंह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में बाहर आए और उनका सामना किया।
वहाँ मीडियाकर्मियों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने के बारे में। 'मैं मिलूंगा'
उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति कल फिर बातचीत पूरी करने के लिए मिलेंगे।'
मीडिया को अचंभित कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का गठन जल्द से जल्द किया जाएगा।
संभव।
दिल्ली में अब ये अफवाहें तेजी से फैल रही थीं कि शायद वो
देश के सर्वोच्च पद का कार्यभार नहीं संभालेंगे। कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति
उनकी विदेशी पृष्ठभूमि के कारण सरकार बनाने के उनके दावे को खारिज कर दिया गया था।
उत्पत्ति। सुब्रमण्यम स्वामी (जो उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे)
पार्टी ने इस मामले को और हवा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया था।
उन्हें सरकार का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया क्योंकि उनकी भारतीय

नागरिकता थी।
'त्रुटिपूर्ण' और उसने इतालवी भाषा छोड़ने का कोई सबूत नहीं दिया था।
नागरिकता।
आठ साल बाद आखिरकार इस अफवाह का अंत हो गया जब ए. पी. जे.
अब्दुल कलाम ने अपने संस्मरणों में सच्चाई को स्पष्ट किया। 'श्रीमती गांधी'
डॉ. मनमोहन सिंह के साथ राष्ट्रपति भवन आए थे।' कलाम
लिखा। '...औपचारिक बातचीत के बाद, उसने मुझे पत्र दिखाए।
विभिन्न दलों से समर्थन।
कलाम ने बताया कि उन्होंने उनसे कहा, 'राष्ट्रपति भवन तैयार है।'
आपके चुने हुए समय पर शपथ ग्रहण समारोह।' पत्र में
उसके लिए निमंत्रण पत्र पहले ही तैयार हो चुका था। 'तभी उसने मुझे बताया।'
कि वह डॉ मनमोहन सिंह को नामांकित करना चाहती हैं... यह
यह मेरे लिए निश्चित रूप से एक आश्चर्य की बात थी और राष्ट्रपति भवन सचिवालय के पास
पत्र को दोबारा लिखने के लिए...
अगर उसने अपने लिए कोई दावा किया होता, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता।
लेकिन उसे नियुक्त करने के लिए,' कलाम ने लिखा। क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था जो उसे ऐसा करने से रोकता।
यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिक है, तो उसे प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता है, बशर्ते कि उसके पास
सांसदों द्वारा चुने गए।
■

उस शाम सोनिया गांधी संसद के केंद्रीय हॉल में दाखिल हुईं।
वहां एकत्रित कांग्रेस सांसदों को संबोधित करने के लिए वह अंदर चली गईं।
उसके बाद उसका बेटा राहुल और बेटी प्रियंका थीं।
उनके साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी थे। तीनों गंभीर दिख रहे थे।
सोनिया लंबी, पॉलिश की हुई सागौन की मेज के पीछे बैठ गई, जिस पर

इन वर्षों में हमने कई ऐतिहासिक क्षणों को देखा है, जिनमें शामिल हैं:
उनके ससुर जवाहरलाल जवाहरलाल द्वारा दिया गया 'नियति से मिलन' भाषण
नेहरू, 14 अगस्त 1947 की आधी रात को। मनमोहन सिंह उनके बगल में बैठे थे।
सांसदों ने उन्हें बधाई देने और माला पहनाने के लिए कतार लगा दी। फिर वह
बोलने के लिए उठी। 'मुझे हमेशा यकीन था कि अगर कभी मैं खुद को ऐसी स्थिति में पाती, तो...'

आज मैं जिस स्थिति में हूँ, उसमें मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का अनुसरण करूँगा। आज,
वह आवाज मुझे बताती है कि मुझे विनम्रतापूर्वक इस पद को अस्वीकार कर देना चाहिए।'
दर्शकों में से 'नहीं, नहीं' की आवाजें गूंज उठीं। कुछ सांसद खड़े हो गए।
उन्होंने अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह था कि वे ऐसा नहीं चाहते थे।
उसकी बात स्वीकार करो।
सोनिया गांधी ने आगे कहा, 'आपने मुझे सर्वसम्मति से अपना चुना है।'
नेता। ऐसा करके आपने मुझ पर अपना विश्वास जताया है। यही विश्वास है।
जिसने मुझ पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए बहुत दबाव डाला है।
निर्णय।' एक बार फिर दर्शकों ने विरोध जताया। सोनिया ने आग्रह किया।
उन्हें बैठने के लिए कहा। 'मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप मेरी बात की ताकत को समझ सकें।'
मुझे दृढ़ विश्वास है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे निर्णय को स्वीकार करें और यह मानें कि मैं
इसे पलटा नहीं जाएगा... आपमें से एक के रूप में, और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पार्टी, मैं आपके साथ और देश के लिए काम करने का संकल्प लेती हूं।' जब वह
जैसे ही काम खत्म हुआ, उसे भीड़ ने घेर लिया। वहां मौजूद कई लोगों ने उससे विनती की कि वह...
उसने अपना मन बदल लिया। लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रही।
उनके इस फैसले की पूरे भारत में सराहना हुई। भारत और अन्य देशों के संपादकीयों

में भी इसकी चर्चा हुई।
विदेश में भी लोगों ने उनकी प्रशंसा की। द हिंदू ने लिखा, ‘अपने इस फैसले से सोनिया ने
नैतिक रूप से "उच्च स्थान" हासिल कर लिया। पाकिस्तान राष्ट्र ने इसे एक
इसे ‘समझदारी भरा’ कदम बताया गया है। इंडिया टुडे ने इसे ‘रणनीतिक त्याग’ करार दिया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे ‘राजनीतिक परिदृश्य का सुविचारित आकलन’ बताया।
उनके नामांकन के फैसले के साथ ही कई ताकतें उनके खिलाफ खड़ी हो गईं।
मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने पर, उन्होंने 'एकमात्र ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया था जो'
बिखरी हुई पार्टी को एकजुट करें...घबराए हुए मध्यम वर्ग को आश्वस्त करें और
बाहरी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश के लिए उन्हें 'बाहरी निवेशकों' के रूप में सराहा गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एकमात्र ऐसी निवेशक हैं जिन्होंने निवेश किया है।
भारतीय इतिहास में प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव ठुकराने वाले एकमात्र व्यक्ति
‘एक बार नहीं बल्कि दो बार’। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद, उन्होंने
उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालने से इनकार कर दिया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो वह
पी.वी. नरसिम्हा राव के स्थान पर, वे प्रधानमंत्री बन गए होते।
(उनसे पहले ज्योति बसु और वी. पी. सिंह दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था)
(1996 में देश का प्रधानमंत्रित्व काल।)
कांग्रेस के प्रबंधकों ने उनके 'बलिदान' की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि सोनिया गांधी ने कभी योजना नहीं बनाई थी।
सबसे पहले तो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए। और यह कि उनके पास
उन्होंने मार्च 2004 में ही मन बना लिया था कि अगर ऐसा कोई क्षण आता है तो
वह आएंगी और मनमोहन सिंह को दिल्ली की गद्दी पर बिठा देंगी।
पार्टी नेताओं ने निजी तौर पर कहा कि उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना लक्ष्य बना लिया था।
सिंह इसलिए लोकप्रिय थे क्योंकि वे एक टेक्नोक्रेट थे, जिनका कोई स्वतंत्र

राजनीतिक समर्थक वर्ग नहीं था, वे मृदुभाषी, विनम्र और दिखावटी नहीं थे।
व्यवहार या कार्यों से। सबसे बढ़कर, उसके लिए खतरा होने की संभावना नहीं थी।
या भविष्य में उसके बच्चों के लिए। इसी में उसकी स्वीकार्यता निहित थी।
सिंह परिवार में एक साधारण पंजाबी खाना पक रहा था जब
गुरशरण कौर को खबर मिली कि उनका पति अगला होगा
प्रधानमंत्री। मुस्कुराती हुई गुरशरण कौर स्वयं पानी लेकर आईं।
जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम सफदरजंग के 19वें नंबर पर पहुंची तो आगंतुकों के लिए वहां का माहौल कुछ ऐसा था जैसे वे वहां मौजूद हों।
वे लोग उनका इंटरव्यू लेने के लिए सड़क पर गए और उन्होंने उनके लिए अपना पारिवारिक एल्बम खोल दिया।
आठ दिनों के आश्चर्यजनक घटनाक्रम के बाद, सोनिया गांधी
19 मई को घोषणा की गई कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे।
मंत्री। 22 मई 2004 को, इकहत्तर वर्षीय सिंह ने शपथ ली।
भारत के तेरहवें प्रधानमंत्री के रूप में।

छठी

‘अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या आप मुझे राजनीति में आने की सलाह देते?’
सोनिया गांधी ने अपने पति के एक साल बाद पी.वी. नरसिम्हा राव से यह सवाल पूछा था।
राजीव की हत्या 1991 में हुई थी।
राव ने उससे कहा, 'अगर तुम मेरी बेटी होतीं, तो मैं मना कर देता।'
स्पष्ट रूप से।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बच्चों का पालन-पोषण करूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं उन्हें संभाल सकता हूं।
उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें अपने साथ यात्राओं पर ले जाओ।'
2004 की सोनिया गांधी उस बेफिक्र और राजनीति से दूर रहने वाली सोनिया गांधी से बिलकुल अलग थीं।
एक युवती जो 1968 में राजीव से शादी करने के लिए भारत आई थी। उनके बीच ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में छात्र के रूप में मुलाकात हुई और उन्हें प्यार हो गया। अपने

शुरुआती वर्षों में
दिल्ली में, वह एक सहज, पार्टी प्रेमी और राजनीति से दूर रहने वाली महिला थीं।
वह एक गृहिणी थीं। वह और राजीव शहर के संभ्रांत वर्ग के लोगों के साथ मेलजोल रखते थे और उनसे संबंध बनाए रखते थे।
भारतीय राजनीति की उथल-पुथल से दूर, भले ही वे
1, सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास में रहते थे। राजनीति
यह विरासत इंदिरा गांधी और उनके छोटे बेटे संजय को सौंपी गई थी।
उनकी सास और देवर की मृत्यु और उनके राज्याभिषेक के बाद
उनके पति को उनकी कड़ी आपत्तियों के बावजूद प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया।
इससे सब कुछ बदल गया। उसे राजनीति में दिलचस्पी होने लगी।
हालांकि, राजीव की हत्या के बाद, वह और भी अधिक एकांतप्रिय हो गई। लेकिन
उन अंधकारमय वर्षों के दौरान भी, उन्होंने राजनीतिक भूमिका निभाने की संभावना से इनकार नहीं किया।
न ही उन्होंने स्वयं पार्टी सदस्यों को अपनी मांगें उठाने से रोका।
समय-समय पर वह सक्रिय राजनीति में प्रवेश करती थी। यह खुद को बनाए रखने का एक तरीका था।
कांग्रेस नेता अनुमान लगा रहे हैं—और नेहरू के दक्षिणपंथी पक्ष में—
गांधी परिवार में, उस समय जब उनके पास कोई पद नहीं था। परिवार की विरासत के प्रति सचेत रहते हुए, वह शायद राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहना चाहती थीं।
यह विकल्प उनके बच्चों के लिए खुला रहेगा, अगर वे बाद में राजनीति में शामिल होने का फैसला करते हैं।
जब भी उनसे उनके प्रवेश के बारे में पूछा जाता, तो वह हमेशा एक ही रटा-रटाया जवाब देती थीं।
राजनीति: 'यह फैसला करना उन्हीं पर निर्भर है।'
अपने विकल्पों पर विचार करते हुए, उसने अर्ध-राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखा।
उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना की और कई गतिविधियों का आयोजन किया।

इंदिरा गांधी के तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
उन्होंने मेमोरियल ट्रस्ट और नेहरू मेमोरियल फंड दोनों की अध्यक्षता की।
राजीव की मृत्यु के बाद।
1995 में ही उन्होंने पहली बार सक्रिय रूप से क्रिकेट में प्रवेश करने का संकेत दिया था।
राजनीति। अमेठी के दौरे के दौरान, वह निर्वाचन क्षेत्र जो
अपने पति द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की।
राजीव गांधी हत्याकांड की जांच में धीमी प्रगति हुई है। (जैसा कि
(अध्याय 4 में उल्लेख किया गया है), राव की एक अप्रत्यक्ष आलोचना। इसे एक
यह संकेत था कि वह अब अपने लिए एक बड़ी राजनीतिक भूमिका तलाश रही थी।
8 मई 1997 को, अचानक ही उसने यह बात सबको बता दी कि उसने
कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्य बनें। जब उन्होंने पदभार संभाला
फरवरी 1998 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेसी सदस्य थे
पार्टी छोड़कर। उनके पूर्ववर्ती, सीताराम केसरी, ऐसा प्रतीत होता था कि...
पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई और उन्हें बिना किसी औपचारिकता के पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।
उस तख्तापलट में उनकी भूमिका, जिसे उसने समर्थन दिया था—और वह आगे बढ़ती गई...
उनकी जगह ले लो। हालाँकि, अब वह जिस महत्वपूर्ण पद पर आसीन थीं, उसके बावजूद,
वह अभी भी इस खेल में नई थी।
सोनिया अपनी सीमाओं और समाज में अपनी भूमिका से भलीभांति परिचित थी।
कांग्रेस की प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक। एक बार जब उनकी तुलना अन्य श्रीमती से की गई थी।
गांधी, इंदिरा, उसने धीमी आवाज़ में कहा, 'मैं नेहरू की बेटी नहीं हूँ।'
कभी-कभी उसकी घबराहट साफ तौर पर महसूस होती थी—और यह बात स्पष्ट थी
1998 में उप-प्रतिनिधि नजमा हेपतुल्ला द्वारा उनके लिए आयोजित एक चाय पार्टी
राज्यसभा की अध्यक्ष से मुलाकात का विचार था। सोनिया गांधी की मुलाकात राज्यसभा अध्यक्ष से होनी थी।

पत्रकारों से अनौपचारिक रूप से बातचीत हुई। पत्रकारों के लिए चाय का इंतजाम किया गया था।
हेपतुल्ला के अकबर रोड स्थित आवास के विशाल लॉन में सोनिया रहती थी।
उन्होंने नींबू के टुकड़े के साथ काली चाय मांगी और उन्हें वही लाकर दी गई।
वह वहां मीडियाकर्मियों से घिरी बैठी थी। उन्होंने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया।
सवाल। मैं संयोगवश उसके ठीक पीछे खड़ा था, और कर सकता था
कप पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था, और उसने सामने की ओर देखा।
सवाल। उतने ही घबराए हुए कांग्रेस नेता वहीं आसपास मंडराते रहे और
जरूरत पड़ने पर उसे याद दिलाया।
लेकिन सोनिया जल्दी सीख जाती थी। एक साल बाद, 1999 में, जब वह उड़ान भर रही थी...
बेल्लारी, जहां से उन्होंने भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था।
सुषमा स्वराज और हम कुछ पत्रकार जो उसी फ्लाइट में थे।
हम उससे बात करने के लिए उसके पास गए। इस बार हमारे सवालों से वह विचलित नहीं हुई।
उड़ान के दौरान वह स्पष्ट रूप से अपने भाषण का अभ्यास कर रही थी।
उसे यह पत्र देना था। यह उसके सामने फोल्डिंग टेबल पर पड़ा था—हिंदी का पत्र।
भाषण अंग्रेजी लिपि में बहुत बड़े फ़ॉन्ट में छपा था, यह देखने में ऐसा लग रहा था
लगभग 48 अंक। शब्दों में 'th' अक्षर रेखांकित प्रतीत हो रहा था, स्पष्ट रूप से।
यह इंगित करने के लिए कि किस बात पर जोर दिया जाना था।
सोनिया अपने भाषणों पर बहुत मेहनत करती थीं। सोनिया के हर भाषण में...
भाषण...छह से आठ घंटे तक चलते थे। कभी-कभी ये बेहद कष्टदायक होते थे।
'भाषण सत्र' आधी रात तक चलते रहे...' नटवर सिंह ने याद किया। 'वह
वे भाषण जोर से पढ़ते और मैं उसका समय नोट करता।' कांग्रेस नेताओं
वह कहती थीं कि भाषण देने के बाद ही वह आराम करेंगी।
तब तक आप उसका पूरा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते थे। वह आम तौर पर पढ़कर सुनाती थी।
उनके भाषण।
सोनिया एक अच्छी श्रोता थी। मैंने एक बार उससे पूछा था कि वह और

मायावती, जिनसे वह 2004 के चुनावों से पहले संबंध सुधारने की कोशिश कर रही थीं, ने बात की थी।
करीब ढाई घंटे तक उनकी मुलाकात मायावती के घर पर 1 तारीख को हुई।
फरवरी 2004। सोनिया ने जवाब दिया, 'मैंने ज्यादा बात नहीं की। बात तो उसने की।'
उसने गेस्ट हाउस वाली घटना का बहुत विस्तार से वर्णन किया।
सोनिया हद से ज्यादा सतर्क होने के साथ-साथ बेहद व्यावहारिक भी थी। जब
पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा।
2003 की सर्दियों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मनोबल गिर गया।
पर्यवेक्षकों ने भविष्यवाणी की कि कांग्रेस की संख्या दोगुनी हो जाएगी।
2004 के मध्य में हुए आम चुनावों में सोनिया गांधी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देने का फैसला किया।
सड़क। उन्होंने अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने का भी फैसला किया।
कांग्रेस की 6 सितंबर 1998 की 'एकल-चुनाव नीति' को पलटते हुए,
उसे पचमढ़ी में गोद लिया गया था।
एक बार जब उसने गठबंधन करने का फैसला कर लिया, तो वह उस पार चली गई।
राम विलास पासवान को देखिए, जो जनपथ नंबर 1 पर रहते थे, जो ठीक दूसरी तरफ था।
उसने अपने घर की चारदीवारी पार की और उसके साथ गठबंधन कर लिया।
उन्होंने अपनी पार्टी, लोक जनशक्ति में शरद के प्रति अपनी दुश्मनी को दरकिनार कर दिया।
पवार, जिन्होंने 1999 में उनकी विदेशी पृष्ठभूमि की आलोचना की थी और इस्तीफा दे दिया था।
कांग्रेस उनकी क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, लॉन्च करने जा रही है।
क्या वही थी जिसने उससे सहयोग मांगने के लिए संपर्क किया था, न कि दूसरा व्यक्ति?
पहले की तरह ही, उन्होंने वही रास्ता अपनाया। उन्होंने डीएमके से संपर्क साधा, वही पार्टी जिसे कांग्रेस राजीव गांधी की मौत के लिए जिम्मेदार मानती थी।

गांधी जी की हत्या। जब डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि ने मुलाकात की।
चुनाव से पहले सोनिया गांधी उनके आने का इंतजार करती थीं।
जनपथ स्थित 10 नंबर के बरामदे में जाकर, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें अंदर तक पहुंचाया।
घर। सामान्यतः ऐसा नहीं होता था, सिवाय बहुत ही विशेष परिस्थितियों में।
विशेष अतिथि। अन्यथा, आगंतुकों को एक छोटे से प्रतीक्षालय में ले जाया जाता था।
जब तक उन्हें उसके अध्ययन कक्ष में नहीं बुलाया गया, तब तक वे घर के सामने ही खड़ी रहीं। उसने उन्हें बांध भी दिया।
आरजेडी के साथ; इसके नेता लालू प्रसाद यादव पहले गैर-
जब उन पर हमले हो रहे थे तब कांग्रेस नेता उनके साथ खड़े रहे।
विदेशी पृष्ठभूमि। उनकी राजनीतिक सूझबूझ 2004 में रंग लाई—उन्होंने हराया
उन्होंने भाजपा का नेतृत्व किया और कांग्रेस को जीत दिलाई। उन्होंने मनमोहन सिंह को नियुक्त किया।
सिंह प्रधानमंत्री बनीं, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उनकी भूमिका
नई सरकार निष्क्रिय नहीं होगी। यह सोनिया गांधी ही थीं जिन्होंने
यह तय किया गया कि 2004 में मंत्रिमंडल में कौन-कौन होगा।
‘यह कोई रहस्य नहीं है,’ मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने स्वीकार किया, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं।
मनमोहन सिंह के सहयोगी, ‘यह निर्णय कि कौन (होने वाला था)’
उनके मंत्रिमंडल में केवल उन्हीं का पद नहीं होगा। उन्हें एक प्रतिनिधि के रूप में लाया गया था।
सरकार चलाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ। कांग्रेस के राजनीतिक प्रमुख।
पार्टी और यूपीए गठबंधन सोनिया गांधी की देन थी। उनके करीबी लोगों ने कोई भूमिका नहीं निभाई।
इस तथ्य का रहस्य यह था कि प्रधानमंत्री 'शासन' का काम जारी रखेंगी, जबकि वह सभी ‘राजनीतिक निर्णय’ वही लेंगे। इसके अलावा, वे यह भी तय करेंगे कि कौन क्या करेगा।
मंत्रिमंडल में होने के साथ-साथ, सरकार में उनकी बात रखने और अपनी बात मनवाने का भी उनका अधिकार था।

नियुक्तियों के संबंध में मनमोहन सिंह ज्यादातर उनकी बात मानते थे।
जो करना चाहते थे, वही किया गया। जबकि सोनिया गांधी ने प्रधान मंत्री पद पर अपना दावा छोड़ दिया।
मनमोहन सिंह की मंत्रीशिप के दौरान, उन्होंने सत्ता का प्रयोग जारी रखा।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सत्ताधारी यूपीए के अध्यक्ष।
■

17 जुलाई 2004 को सुबह 9 बजे, आत्मविश्वास से भरी सोनिया गांधी सहजता से अंदर आईं।
दिल्ली में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित 2 नंबर के कमरे में। यह कमरा कार्यालय के लिए निर्धारित था।
नवगठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी)—और वह पूरी तरह से
वह इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाली थीं। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुईं, कुछ
वहां उपस्थित एनएसी सदस्यों में से कुछ ने सम्मान के प्रतीक के रूप में खड़े होकर सम्मान व्यक्त किया।
बाकी आधे लोग उठ खड़े हुए—यह न जानते हुए कि कैसे प्रतिक्रिया दें। शेष लोग शरमाते हुए खड़े रहे।
उन्होंने उठने की कोशिश में अपने हाथ कुर्सी के आर्मरेस्ट पर रख दिए।
लेकिन उन्हें राहत मिली कि उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ा। वे बहुत विनम्र दिखना नहीं चाहते थे। लेकिन अचानक सभी सचेत हो गए थे।
सोनिया गांधी की बढ़ती प्रतिष्ठा के बारे में—जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए 'ना' कह दिया था।
वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि नए मंत्री पद का जवाब कैसे दिया जाए।
परिस्थिति।
सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संसद (एनएसी) स्थापित करने का विचार आया था।
प्रमुख पद को अस्वीकार करने के तुरंत बाद हुई चर्चाओं के दौरान यह मुद्दा उठा।

मंत्री पद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि एनएसी इसमें मदद करेगी।
यूपीए के साझा न्यूनतम कार्यक्रम को लागू करना। यह लागू हुआ।
4 जून 2004 को अस्तित्व में आया—प्रधानमंत्री के पदभार संभालने के दो सप्ताह के भीतर।
सोनिया गांधी को काम करवाने के लिए एनएसी की जरूरत नहीं थी।
सरकार। राष्ट्रपति के रूप में वह काफी शक्तिशाली थीं।
कांग्रेस पार्टी, सीपीपी के अध्यक्ष और यूपीए के अध्यक्ष को पद प्राप्त करने के लिए
किसी मंत्री से सीधे या उनके माध्यम से बात करके लिए गए निर्णय
उसके सहायकों में से।
एनएसी का असल मकसद उन्हें सरकार में प्रवेश दिलाना था।
निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में। इससे उसे काम करने के लिए एक कार्यालय और कर्मचारी मिल गए।
उसकी सहायता की—और इससे उसे कैबिनेट मंत्री का पद प्राप्त हुआ। और ऐसा ही होता रहेगा।
इससे उसे ऐसे कार्यक्रमों का सुझाव देने में मदद मिलेगी जिन्हें वह आगे भेज सकेगी।
कार्यान्वयन के लिए सरकार।
अपनी पहली बैठक में सोनिया गांधी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया।
उनमें से बारह थे—जिनमें सूचना का अधिकार (आरटीआई) भी शामिल था।
कार्यकर्ता अरुणा रॉय, पूर्व योजना आयोग सदस्य एन.सी.
विकास अर्थशास्त्री ए. के. शिव कुमार और अर्थशास्त्री जीन सक्सेना सहित अन्य अर्थशास्त्री भी शामिल हैं।
ड्रेज़ सहित अन्य लोगों में शिक्षाविद मृणाल मिती, सामाजिक कार्यकर्ता और
प्रथम के उद्यमी माधव चव्हाण और लेखक-अर्थशास्त्री सी.
एच. हनुमंथा राव उपस्थित थे। जयराम रमेश सदस्य सचिव के रूप में मौजूद थे।
अरुणा रॉय सूचना के अधिकार अभियान का नेतृत्व कर रही थीं।
कई वर्षों से; जीन ड्रेज़ एक नौकरी पर काम कर रहे थे।
सफल रहे कार्यक्रम पर आधारित गारंटी योजना
महाराष्ट्र में। आरटीआई और रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी।
यूपीए के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल वादे।

रोजगार गारंटी योजना, जिसे बाद में महात्मा गांधी नाम दिया गया,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) लगभग समाप्त होने वाला था।
सोनिया गांधी का दिल।
यह तो तय था कि पहली बैठक में इस पर चर्चा होगी।
'एनएसी की बैठक,' एक एनएसी सदस्य ने टिप्पणी की। अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई अधिकार-आधारित पहलों की अध्यक्षता की। उन्होंने राष्ट्रीय परिषद में रहते हुए कई पहलों का नेतृत्व किया।
एनएसी का गठन 1996 से शुरू हुई उनकी चर्चाओं के परिणामस्वरूप हुआ था।
शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं, इतिहासकारों, न्यायाधीशों, समाज वैज्ञानिकों और नागरिकों के साथ
समाज के समूह—जिनमें से कई वामपंथी विचारधारा वाले हैं—जो
उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में संक्षेप में बताएं। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई।
Romila Thapar, Yogendra Yadav, J. N. Dixit, and many others.
Mohit
सीपीआई के सेन जनपथ स्थित 10 नंबर मकान में अक्सर आते-जाते थे। उन महीनों में जब
इसके बाद, सोनिया की वामपंथी स्थिति संतुलन बनाने में मदद करेगी।
मनमोहन सिंह की ‘सुधारवादी’ विचारधारा।
■

‘प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे हमसे मिलेंगे,’ अरुण भटनागर ने कहा।
नव नियुक्त एनएसी सचिव, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, ने समूह को अपनी पहली बैठक में संबोधित किया।
सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का अनुरोध किया था।
मंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें अपने आवास पर चाय के लिए आमंत्रित किया था।
7, रेस कोर्स रोड। शाम 4 बजे, उन्हें एक सम्मेलन में ले जाया गया।

प्रधानमंत्री आवास में एक कमरा था। वहाँ एक आयताकार कॉन्फ्रेंस टेबल थी और मेज के सिरहाने दो कुर्सियाँ रखी हुई थीं। जब प्रधानाध्यापक ने
मंत्री जी पहुंचे, उन्होंने सोनिया गांधी को एक तस्वीर लेने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने खुद एक तस्वीर ले ली।
इस प्रकार, उसे समान दर्जा प्राप्त हो जाता है।
‘उस समय सोनिया गांधी को भगवान की तरह देखा जाता था,’ एक व्यक्ति ने टिप्पणी की।
बाद में एनएसी सदस्यों ने कहा, 'प्रधानमंत्री पद त्यागने के बाद और
मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। मणिशंकर अय्यर ने उन्हें बुलाया था।
"मदर टेरेसा"।'
प्रधानमंत्री ने समूह से कहा, 'मुझे खुशी है कि आपने काम शुरू कर दिया है।'
बातचीत के दौरान, उनसे उस सुबह हुई उनकी बैठक के बारे में पूछें।
उनमें से एक ने जवाब दिया, 'हमने एनआरईजीए पर चर्चा की।'
जी हां, यह एक अच्छा कार्यक्रम है और यह सामान्य न्यूनतम मानकों में शामिल है।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'कार्यक्रम।' फिर उन्होंने अचानक पूछा, 'इसमें कितना खर्च आएगा?'
लागत?'
किसी ने जवाब दिया, '35,000 करोड़ रुपये।'
प्रधानमंत्री ने तीखे स्वर में पूछा, 'हमें पैसा कहां से मिलेगा?'
उनमें से एक ने याद करते हुए कहा, 'मैंने मन ही मन सोचा, यह कितना अनुचित सवाल है।'
बाद में सदस्यों ने कहा, ‘मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रह चुके थे।’
आरबीआई के गवर्नर और अब प्रधानमंत्री। भले ही वे वित्त मंत्री न भी रहे होते।
या आरबीआई गवर्नर से, कोई प्रधानमंत्री ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता है?’
आखिरकार यह कोई आर्थिक सवाल नहीं बल्कि राजनीतिक सवाल था और इसका संबंध इसी से था।
सरकार द्वारा किसी चीज के लिए संसाधनों के आवंटन के साथ
कहा कि यह उसकी प्राथमिकता होगी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था, यह इसका एक हिस्सा था।

सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के प्रति यूपीए प्रतिबद्ध थी।
इसे लागू करना। 'अगर वह इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तो हम कैसे दे सकते हैं?'
'बाहरी लोग?' इस सदस्य ने सोचा।
सोनिया गांधी ने बैठक में लगभग कुछ नहीं कहा। बैठक ज्यादा देर नहीं चली।
बीस मिनट से अधिक। हालाँकि, इसने कुछ लोगों को इस बात का एहसास दिलाया कि...
एनएसी सदस्यों को यह स्वीकार करना पड़ा कि उनकी पहलों को आगे बढ़ाना उतना आसान नहीं हो सकता है।
सोनिया गांधी के प्रभाव के बावजूद, वे वैसे ही सफल हुए जैसा उन्होंने पहले सोचा था।
इस्तेमाल किया।
सरकारी हलकों में जल्द ही यह बात फैल गई कि मनमोहन
सिंह एनआरईजीए (जिसका नाम बदलकर एमजीएनआरईजीए कर दिया गया था) को लेकर उत्साहित नहीं थे।
अधिनियम में 2009 में एक संशोधन)। 'एक सच्चा मौद्रिक अर्थशास्त्री होने के नाते, उन्होंने उन परोपकारी कार्यों का समर्थन नहीं किया जिन्हें वे अनुत्पादक मानते थे।
प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक 'द कोएलिशन इयर्स' में लिखा है, 'गतिविधियां।'
सोनिया गांधी जानती थीं कि उन्हें रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। उन्हें समर्थन प्राप्त था।
वामपंथी दलों में से, जो अपने अधिकारों की रक्षा में मुखर थे
काम। जब एनएसी सदस्यों ने वामपंथी नेताओं से मुलाकात की, तो एक उत्तेजित सीपीआई नेता
ए. बी. बर्धन ने बार-बार कहा, 'हमें लड़ना ही होगा।' एनएसी के अनुसार
सदस्य ने कहा, 'उन्होंने इस शब्द का प्रयोग लगभग पच्चीस बार किया।' अंत में, लोक सभा ने 23 अगस्त 2005 को एनआरईजीए पारित किया। अगले दिन इसे मंजूरी मिल गई।
राज्यसभा द्वारा पारित। इसका उद्देश्य 'आजीविका सुरक्षा' को बढ़ाना था।
देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को कम से कम एक उपलब्ध कराकर

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों का गारंटीकृत वेतनयुक्त रोजगार
उन सभी परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं
मैनुअल काम'।
5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दे दी।
भारत में काम करना एक वैधानिक अधिकार बन गया था। सोनिया गांधी ने
उन्होंने सार्वजनिक हस्ती के रूप में अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक को अंजाम दिया।
एनआरईजीए के अलावा, एनएसी ने सरकार को निम्नलिखित मामलों में भी सुझाव दिए:
मनमोहन परिषद के लिए नीतिगत निर्णय और अनुशंसित कानून
मंत्रालय को इसे लागू करना होगा। प्रधानमंत्री या उनके वरिष्ठ अधिकारी चाहे जो भी कहें।
मंत्रियों ने एनएसी की सिफारिशों के बारे में जो भी महसूस किया हो, वे
सोनिया गांधी को 'ना' कहना मुश्किल लगा।
यूपीए ने कई अधिकार-आधारित कानून पारित किए।
सूचना का अधिकार विधेयक 15 जून 2005 को पारित हुआ। इसके बाद 2009 में शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित हुआ, और अंत में सूचना का अधिकार विधेयक पारित हुआ।
यूपीए-द्वितीय सरकार के दौरान 2013 में लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद जिस भोजन को मंजूरी मिली थी,
बातचीत।
सोनिया गांधी राष्ट्रीय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अक्सर मंत्रियों को पत्र लिखती थीं।
एनएसी सचिवालय के सदस्य मंत्रालयों के सचिवों को फोन करेंगे।
उन्हें एनएसी सदस्यों के लिए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा गया।
या उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तय करें। डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी
AIIMS ने आकर उस समूह को जानकारी दी जो इस पर काम कर रहा था।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का संविधान; एनआरएचएम

किफायती और सुलभ सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था।
ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना। अन्य लोगों ने मोंटेक के साथ बैठकें कीं।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष सिंह अहलूवालिया।
भाजपा ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें 'सुपर प्राइम' कहा।
मंत्री'—और एनएसी अध्यक्ष के रूप में उनकी स्थिति 'असंवैधानिक' है।
आलोचकों ने एनएसी को एक 'वैकल्पिक...कैबिनेट' करार दिया—इसका अस्तित्व ही
देश के संविधान के अनुरूप नहीं। सरकारी हलकों में,
एनएसी को 'अपमानजनक रूप से' 'सोनिया की झोलावाला भीड़' के रूप में संदर्भित किया गया था।
इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में नौकरशाही की एक और परत जुड़ जाती है।
लेकिन एनएसी सदस्यों के लिए, यह अभूतपूर्व अवसर था अपने पक्ष को स्थापित करने का।
भारत में अधिकार-आधारित ढांचा स्थापित करने के लिए। सोनिया गांधी को देखा गया।
दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में बिताया गया समय, उनका बन गया
'ब्रह्मास्त्र' ने उस चीज़ को संभव बना दिया जो अब तक असंभव प्रतीत होती थी।
लेकिन यह स्पष्ट था, और ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद
सिंह ने इस वास्तविकता को खुलकर व्यक्त करते हुए कहा, 'एनएसी उपयोगी है।'
इसका अर्थ तभी है जब सोनिया जी इसकी अध्यक्षता कर रही हों। अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं है।'
उन वर्षों पर विचार करते हुए, अर्थशास्त्री जीन ड्रेज़, एक प्रमुख
एनएसी के एक सदस्य ने मुझसे कहा: 'यूपीए को दोनों कारणों से याद किया जाएगा...'
उच्च आर्थिक विकास और अधिकार-आधारित ढांचे के लिए... आर्थिक
विकास ने एक अवसर पैदा किया और श्रीमती गांधी ने उसमें कदम रखा।

सामाजिक नीति के प्रति प्रतिबद्धता।' ड्रेज़ की टिप्पणी ने इस बात को संक्षेप में प्रस्तुत किया।

2004 में उत्पन्न हुई अभूतपूर्व शक्तियों के संगम के साथ
यूपीए सरकार का आगमन—एक प्रधानमंत्री जो विश्वास करते थे
उच्च आर्थिक विकास और एक समान रूप से शक्तिशाली नेता जो चाहता था
सत्ताधारी कांग्रेस को आम आदमी समर्थक संगठन के रूप में स्थापित करना।
सोनिया गांधी जानती थीं कि उन्हें लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखना होगा।
वामपंथी दलों ने यूपीए के अस्तित्व को सुनिश्चित किया। अपनी ओर से, वामपंथियों ने पार्टियाँ चाहती थीं कि सरकार गरीबों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करे— सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दे, विनिवेश से बचे और उन्हें बांधे नहीं।
स्वयं अमेरिकी हितों के बहुत करीब। यूपीए का कॉमन मिनिमम
कार्यक्रम ने 'आम आदमी' पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना था - इसने इसका उपयोग नहीं किया।
'गरीब' शब्द, जिसके अतीत में समाजवादी अर्थ निहित थे।
सोनिया गांधी अक्सर वामपंथी दलों और उनके बीच एक सेतु का काम करती थीं।
प्रधानमंत्री, यह जानते हुए कि वामपंथी विचारधारा उनसे भिन्न थी,
मनमोहन सिंह के आर्थिक दर्शन को वह सहज रूप से जानती थी।
कि कांग्रेस को काफी हद तक वामपंथी छवि बनाए रखने की जरूरत है
भारत जैसे गरीब देश में। यह उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनकी विदेशी पृष्ठभूमि। वह यह नहीं भूली थीं कि एनडीए की 2004 की 'भारत' नीति 'शाइनिंग' का चुनावी अभियान आम लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया था।
उनके बीच चाहे जो भी मतभेद रहे हों, मनमोहन सिंह इस बात का ध्यान रखते थे कि वे
सोनिया गांधी से सीधे तौर पर मुकाबला करना। हालांकि वह समय-समय पर पूछते रहते थे
एनएसी के कार्यक्रमों को कैसे वित्त पोषित किया जाएगा, इस बारे में वह आमतौर पर पूछते थे।
इसे वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और योजना मंत्री पर छोड़ दें।
आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया अपनी राय व्यक्त करेंगे।

एनएसी के सामाजिक कल्याण के वित्तीय निहितार्थों के बारे में चिंता
पहल। हालांकि, अंततः प्रधानमंत्री को बात माननी ही पड़ेगी।
सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद का दूसरा प्रमुख मुद्दा यह था।
भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता—और नई रणनीतिक
मनमोहन सिंह अमेरिका के साथ जिस तरह के संबंध बनाना चाहते थे। इस पर,
प्रधानमंत्री ने झुकने से इनकार कर दिया।

सातवीं

'ऐसा ही हो'। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ये तीन शब्द।
अगस्त 2007 में इसने दिल्ली के राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया था। सिंह ने बताया
द टेलीग्राफ की मानिनी चटर्जी ने कहा कि अगर वामपंथी पीछे हटना चाहते हैं
परमाणु समझौते को लेकर उनकी सरकार को समर्थन, 'जो भी हो'।
कोलकाता के एक अखबार ने सनसनीखेज साक्षात्कार को अपने पहले पन्ने पर छापा।
13 अगस्त 2007 को।
दिल्ली और कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालयों में इस बात को समझने की होड़ मची हुई थी कि आखिर क्या हो रहा है।
प्रधानमंत्री का मतलब था। सीपीआई (एम) नेतृत्व इस बात से स्तब्ध था कि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया।
इस लहजे में बात करें। कांग्रेस नेतृत्व इस बात से नाराज था कि सिंह
इससे यूपीए सरकार खतरे में पड़ सकती है। 'डॉक्टर साहब कौन होते हैं फैसला करने वाले?'
गठबंधन के बारे में, यह पार्टी का काम है,' अत्यंत विवेकशील अहमद ने कहा।
सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव पटेल ने शिकायत की। आखिरकार,
यूपीए शासन के राजनीतिक पक्ष की जिम्मेदारी सोनिया गांधी की थी।
गांधी और उनकी अगुवाई वाली कांग्रेस। मनमोहन सिंह को केवल शासन और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करना था।
जब वे प्रधानमंत्री बने तो यह एक अलिखित समझौता था।

‘प्रधानमंत्री इतने गैरजिम्मेदार कैसे हो सकते हैं?’ कई कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया।
निजी।
उन्होंने इस साक्षात्कार को प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया एक सुनियोजित संदेश माना।
वामपंथी दलों ने अखबार के चयन और उस पर टिप्पणी की।
जिस पत्रकार को उन्होंने साक्षात्कार दिया था। जैसा कि उल्लेख किया गया है, द टेलीग्राफ
यह कोलकाता स्थित एक अखबार था और पश्चिम बंगाल को वामपंथियों का गढ़ माना जाता था।
जागीरदारी। मानिनी चटर्जी एक पत्रकार थीं जिन्हें शायद अधिक गंभीरता से लिया जाता।
वामपंथी नेताओं, विशेषकर सीपीआई (एम) नेता प्रकाश करात द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है।
जो उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वरिष्ठ वामपंथी नेताओं के बीच उनकी विश्वसनीयता बहुत अधिक थी।
विशेषकर इसलिए क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक सीपीआई (एम) के साथ पूर्णकालिक रूप से काम किया था।
उन वर्षों के दौरान जब उन्होंने मुख्यधारा के मीडिया से ब्रेक लिया था।
‘अगस्त में मैंने संजय बारू को फोन किया,’ चटर्जी ने मुझे बताया। ‘(मैंने उनसे कहा) (उनसे) अब जब मैंने प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर ली है, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा।
उन्होंने दिल्ली में द टेलीग्राफ के रेजिडेंट एडिटर के रूप में पदभार संभाला।
मुझे संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में दोपहर 12 बजे आने के लिए कहा गया था। अगर मैं
मुझे ठीक से याद है ना, मुझे उसी दिन आने के लिए कहा गया था।
उन्होंने प्रधानमंत्री से वामपंथ के बारे में पूछकर शुरुआत की। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया।
बात करते-करते चटर्जी की कलम उनकी किताबों के पन्नों पर तेज़ी से चलने लगी।
मैंने नोटबुक में उसकी कही हर बात को लिख लिया। 'मैंने देखा...'

मैंने उनसे पूछा, “क्या मैं आपका उद्धरण दे सकता हूँ? यह पहले पन्ने की खबर है।”
वह बहुत
वामपंथियों द्वारा कही गई बातों को लेकर चिंतित थे।
'हाँ,' उन्होंने कहा। 'लेकिन पहले इसे संजय को दिखाओ।' संजय बारू, मीडिया
प्रधानमंत्री के सलाहकार प्रधानमंत्री कार्यालय में आने से पहले पत्रकार थे।
'बैठक बहुत देर तक नहीं चली, केवल 15-20 मिनट तक।'
वह संजय बारू के साथ प्रतीक्षालय में बैठी थी, और अगले दस मिनट तक
कुछ मिनटों तक उसने उसके नोट्स पर उसके साथ चर्चा की। 'मैंने मन ही मन सोचा,
मैं ऐसा नहीं कर सकती।'
'एक भी उद्धरण गलत मत करो।' बारू ने जो लिखा था उसे मंजूरी दे दी।
जब वह संसद भवन से बाहर निकली तो वह स्तब्ध सी थी।
मानिनी चटर्जी का लेख द अखबार के पहले पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था।
अगले दिन टेलीग्राफ में खबर छपी। शीर्षक में लिखा था, 'दुखी प्रधानमंत्री ने...'
बाएँ: यदि आप पीछे हटना चाहते हैं, तो ऐसा ही हो।
लेख में प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया है: 'मैंने उनसे (वामपंथियों से) कहा कि यह
है
समझौते पर पुनर्विचार करना संभव नहीं है... मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है, हम
मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। मैंने उनसे (वामपंथियों से) कहा था कि वे जो चाहें
करें।'
उन्होंने चटर्जी से कहा, 'अगर वे समर्थन वापस लेना चाहते हैं, तो ऐसा ही हो।'
घटनाक्रम को समझाते हुए बारू ने याद करते हुए कहा, 'मैं
पिछली शाम उनके (प्रधानमंत्री) साथ बैठे थे... हम टीवी देख रहे थे।
आरसीआर।’ प्रकाश करात 11 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
2007), अन्य वामपंथी नेताओं के साथ। उनके शब्दों में एक अप्रत्यक्ष चेतावनी थी।
मनमोहन सिंह मंत्रालय: “प्रधानमंत्री और
सरकार को यह समझना होगा कि यह समझौता स्वीकार्य नहीं है।
“संसद में बहुमत,” करात ने चेतावनी दी थी। “जहां तक दृष्टिकोण का सवाल है...
सरकार चिंतित है, हम अपनी सलाह खुद लेंगे।
करात भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते 123 का जिक्र कर रहे थे।

जुलाई में दोनों सरकारों द्वारा अंतिम रूप दिए गए सहयोग पर
2007, मनमोहन सिंह और जॉर्ज की मृत्यु के लगभग दो साल बाद उसी दिन, लगभग दो साल बाद।
डब्ल्यू. बुश ने सबसे पहले परमाणु समझौते को लागू करने का फैसला किया था।
123 समझौते को अंतिम रूप देना एक और महत्वपूर्ण कदम था।
जीत हासिल कर ली गई—और अब गेंद फिर से भारत के पाले में थी। प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह अगला कदम उठाने के लिए बेताब थे—आईएईए जाने के लिए।
एक 'भारत-विशिष्ट सुरक्षा समझौते' के लिए, और फिर राष्ट्रीय महासभा के समक्ष।
'छूट'। तभी अमेरिकी कांग्रेस समझौते को औपचारिक रूप देगी।
इसके तुरंत बाद, सीपीआई (एम) की केंद्रीय समिति की बैठक हुई, जिसमें
अगस्त की शुरुआत में ही उसने 'सौदे को रोकने' के लिए अपने विरोध को और कड़ा करने का फैसला किया।
सीपीआई (एम) के अनुसार, 'हमें इस समझौते को विफल करने के लिए तैयार रहना चाहिए।'
सर्वोच्च निकाय ने 'समर्थन वापस लेने' का संकल्प लिया। करात का बयान
इससे वामपंथियों के रुख में आई सख्ती झलकती है।
बारू ने याद करते हुए बताया कि जब वह और प्रधानमंत्री करात की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे,
'मैंने प्रधानमंत्री को गुस्से से लाल होते देखा। वह बहुत क्रोधित थे।' यह बात ज्ञात नहीं थी।
कई लोगों का मानना था कि सिंह को जल्दी गुस्सा आ जाता था और वे अक्सर अपना आपा खो देते थे।
निजी तौर पर। सार्वजनिक रूप से वे शांत और त्रुटिहीन व्यवहार बनाए रखते थे।
इस साक्षात्कार ने दिल्ली के राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी। इसने यह भी सुनिश्चित किया कि
कोलकाता में लहरें—जैसा कि इसका उद्देश्य था। मनमोहन सिंह ने
उन्होंने साक्षात्कार के बारे में अपनी पार्टी में किसी से सलाह नहीं ली। उन्होंने इसकी योजना केवल स्वयं बनाई थी।
अपने मीडिया सलाहकार संजय बारू के साथ। और एक बार जब यह बात सामने आ

गई, तो उन्होंने ऐसा किया।
न तो वह अपने शब्दों को वापस ले सकता था और न ही उनका खंडन कर सकता था।
स्थिति एक गंभीर मोड़ की ओर बढ़ रही थी।
वामपंथियों के साथ टकराव।
इसी समय सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया।
निर्देश दिया गया कि यूपीए के नेताओं को मिलाकर एक समिति गठित की जाए।
और वामपंथी दलों को वामपंथियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच करनी होगी।
समितियाँ समय खरीदने का एक आजमाया हुआ और कारगर तरीका थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि...
यह कदम सरकार को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उठाया गया था। प्रधानमंत्री, जो आगे बढ़ने के लिए अधीर थे,
लगाम कस ली गई। तभी सरकार और वामपंथी दोनों इस बात पर सहमत हुए कि
'पॉज़' बटन दबाएँ: 'न रोकें, न पीछे करें, केवल पॉज़ करें', एक व्यक्ति ने कहा।
शीर्षक, जो स्थिति का सारांश प्रस्तुत करता है।
■

30 अगस्त 2007 को प्रणब मुखर्जी ने इसके गठन की घोषणा की।
भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु मामलों पर यूपीए-वाम समन्वय समिति
सहयोग। विदेश मामलों के मंत्री मुखर्जी इसके प्रमुख बने।
संयोजक। समिति में कांग्रेस के पांच सदस्य थे।
मुखर्जी के अलावा, यूपीए के सहयोगी दलों से तीन और वामपंथी दलों से छह लोग शामिल हैं।
दलों में कांग्रेस के प्रतिनिधि प्रणब मुखर्जी और ए.के.
Antony, P. Chidambaram, Saifuddin Soz, Kapil Sibal, and Prithviraj
चव्हाण. शरद पवार, टी. आर. बालू और लालू यादव ने प्रतिनिधित्व किया
क्षेत्रीय दल, एनसीपी, डीएमके और आरजेडी। वामपंथी दलों के सदस्य।
इस समिति में सीपीआई (एम) के प्रकाश करात और सीताराम येचुरी शामिल थे।

सीपीआई के ए. बी. बर्धन और डी. राजा, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी के साथ।
डी. बिस्वास और टी. जे. चंद्रचूडन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। मनमोहन
सिंह और सोनिया गांधी ने समिति का हिस्सा न बनने का फैसला किया।
प्रणब मुखर्जी ने अपने घर पर समिति की पहली बैठक बुलाई।
उन्होंने साउथ ब्लॉक में अपना कार्यालय खोला। उन्होंने यूपीए के तीनों सहयोगियों से थोड़ी देर के लिए आने को कहा।
इससे पहले वह उनसे अनौपचारिक बातचीत करना चाहता था, ताकि उनकी राय जान सके।
वामपंथी नेताओं से मुलाकात से पहले के विचार।
शरद पवार उस दिन काफी चिंतित थे। 'अगर सरकार गिर गई तो'
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर परमाणु समझौते को आगे बढ़ाया गया, तो सीपीएम सरकार...'
राष्ट्रपति से समर्थन वापस ले लें।' यह भाजपा के साथ मतदान भी कर सकता है।
उन्होंने महसूस किया। चिंतित पवार ने कहा, 'हमें चुनावों के लिए तैयार रहना होगा।'
समूह।
पवार की टिप्पणियों से पता चलता है कि वामपंथी दलों के विपरीत, कांग्रेस का रुख अलग है।
सहयोगी देश परमाणु समझौते को लेकर चिंतित नहीं थे। वे चिंतित थे।
वामपंथी-कांग्रेस गतिरोध के कारण समय से पहले चुनाव होने के बारे में और अधिक जानकारी
जिसका सामना करने के लिए वे तैयार नहीं थे।
शरद पवार ने सीपीआई (एम) के महासचिव के मूड को सही ढंग से समझ लिया था।
प्रकाश करात ने अपनी पार्टी के 'साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष' को एक उच्चतर स्तर पर रखा था।
भाजपा के सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई की तुलना में इसे अधिक महत्व दिया गया है, जिसे
यूपीए सरकार जिन सिद्धांतों पर खड़ी थी, और वह सरकार को उन सिद्धांतों से मुक्त करने के लिए तैयार थे।
अगर मजबूरी हुई तो जाओ।

■

हमारे लिए, यह सब तब शुरू हुआ जब प्रणब मुखर्जी वाशिंगटन गए थे।
‘जून 2005,’ प्रकाश करात ने वर्षों बाद दस साल के उस दौर का जिक्र करते हुए कहा।
रक्षा मंत्री मुखर्जी द्वारा उल्लिखित भारत-अमेरिका रक्षा समझौता
जून 2005 में अमेरिका के साथ इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।
हमसे कोई परामर्श नहीं किया गया। किसी को भी इसके बारे में बताया नहीं गया।
यहां तक कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी नहीं... हम पूरी तरह से
'हैरान।' करात ने कहा कि वामपंथी इसे एक बड़ा नीतिगत उलटफेर मानते हैं।
जैसे ही प्रणब मुखर्जी भारत लौटे, 'बर्धन और मैं तुरंत दौड़ पड़े'
‘उनसे मिलने के लिए,’ करात ने मुझे बताया। ‘हमारी उनसे तीखी बहस हुई...’
'तुमने यह सब छुपकर, गुप्त रूप से किया है,' निराश करात ने आरोप लगाया।
मुखर्जी। ‘आपने हमें बताया था कि यह एक खोजपूर्ण दौरा था।’ बाद में, वामपंथी
विभिन्न दलों ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विरोध प्रदर्शन किया।
परमाणु समझौता एक लेन-देन था... बुश द्वारा भारत को दी गई एक लॉलीपॉप थी।
कैरेट चार्ज किया गया।
जब मनमोहन सिंह ने जॉर्ज के साथ संयुक्त बयान जारी करने की कोशिश की
18 जुलाई 2005 को बुश के खिलाफ, वामपंथियों ने फिर से विरोध प्रदर्शन किया।
इसके जवाब में,
कांग्रेस नेतृत्व ने परमाणु वैज्ञानिक राजा रामन्ना और उनसे पूछा
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम. के. नारायणन वामपंथी नेताओं को जानकारी देंगे और उनकी आशंकाओं को दूर करें। जब उन्होंने यूपीए को समर्थन देने का फैसला किया था, तब वामपंथी दल ने यूपीए का समर्थन करने का निर्णय लिया था।
उन्हें आर्थिक मुद्दों पर कांग्रेस से टकराव की उम्मीद थी।
उनके बीच मतभेद थे—लेकिन यह एक सीमा तक ही सीमित था, और इसने एक रूप ले लिया।
मुख्यतः उन नोटों के बारे में जो वे सरकार को सौंपते थे।

फरवरी 2006 में, वामपंथियों ने उन्नीस नोट प्रस्तुत किए थे।
सरकार दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) जैसे मुद्दों पर...
बीमा, बैंकिंग, प्रिंट मीडिया, खुदरा, कर्मचारियों पर दरें
भविष्य निधि, हवाई अड्डों के निजीकरण आदि के मुद्दे। उनकी ओर से,
प्रधानमंत्री स्वयं वामपंथियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई की मांग करेंगे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया। वह उन्हें खुश रखना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि...
विश्वविद्यालयों में वामपंथी नेताओं द्वारा अनुशंसित लोगों को नियुक्त किया गया,
योजना आयोग और अन्य महत्वपूर्ण निकाय।
वामपंथी नेताओं को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनके बीच तीखे मतभेद होंगे।
विदेश नीति के मुद्दे; यही साझेदारी के पतन का कारण बनने वाले थे। वामपंथियों के लिए, परमाणु समझौता बढ़ती रणनीतिक स्थिति की आधारशिला था।
अमेरिका के साथ गठबंधन, मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में, जो स्वीकार्य नहीं था
Prakash Karat.
■

जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो वह व्यक्ति जिसे वे अक्सर
मदद के लिए सीपीआई (एम) के महासचिव हरकिशन सिंह से संपर्क किया गया।
सुरजीत—प्रधानमंत्री के कम्युनिस्टों के साथ मतभेदों के बावजूद।
मनमोहन सिंह मोंटेक सिंह अहलूवालिया को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे।
मंत्री। लेकिन सोनिया गांधी ने इसे खारिज कर दिया और पी. को चुना।
Chidambaram instead. The resourceful Surjeet helped Manmohan
सिंह अहलूवालिया योजना समिति के उपाध्यक्ष बने।
उन्हें आयोग में नियुक्त किया गया और मंत्रिमंडल का दर्जा दिया गया। परिणामस्वरूप, वे उपस्थित हो सकते थे।
कैबिनेट बैठकों में भाग लें और प्रधानमंत्री की हर बात की जानकारी रखें। उनकी निकटता को देखते हुए।

प्रधानमंत्री के अनुसार, राजनेताओं और राजनयिकों की और अधिक कारें होंगी।
प्रधानमंत्री आवास के बाहर की तुलना में योजना भवन के बाहर खड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी थीं।
उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला।
अहलुवालिया ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या कोई विशेष व्यक्ति है जिसे वह संबोधित करना चाहते हैं।
उनसे मिलने के लिए। मनमोहन सिंह ने उन्हें सुरजीत से मिलने के लिए कहा। अहलूवालिया
मेरी मुलाकात अस्सी-आठ वर्षीय कॉमरेड सुरजीत से हुई, जिन्होंने मुझे चाय पिलाई और
बिस्कुटों को लेकर - 'अस्वीकृति' को लेकर नहीं। सीपीआई (एम) के नेता इससे खुश नहीं थे।
अहलुवालिया की नियुक्ति, जो पहले आईएमएफ में पद पर रह चुके थे।
उन्होंने सुरजीत से हस्तक्षेप करके इसे रोकने के लिए कहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
देर।
कांग्रेस नेताओं ने भी अहलूवालिया की ओर संदेह भरी नजरों से देखा।
नियुक्ति के बाद वे 'सरदार से सरदार' वाली सौहार्दता के बारे में मजाक करते थे।
जिसकी वजह से नियुक्ति का फैसला हुआ। तीनों—मनमोहन सिंह,
Montek Singh Ahluwalia, and Harkishan Singh Surjeet—were Bhapa
सिखों, वे ताना मारते हुए कहते थे। अहलुवालिया, मोंटेक और उनके
प्रख्यात अर्थशास्त्री की पत्नी इशर जज अहलूवालिया लंबे समय से एक दूसरे के साथ थीं।
मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर के निजी मित्र।
मनमोहन सिंह की वामपंथियों से मुश्किलें उसी क्षण से शुरू हुईं जब
Prakash Karat replaced Harkishan Singh Surjeet as general secretary of
सीपीआई (एम)। सुरजीत और ज्योति बसु, पश्चिम के पूर्व मुख्यमंत्री

बंगाल में, सीपीआई (एम) के दोनों शीर्ष नेताओं ने बार-बार आश्वासन दिया था
मनमोहन सिंह को 2004 में प्रधानमंत्री बनने पर उनके समर्थन का आश्वासन दिया गया था। वे कहते थे कि उन्हें उनसे कोई परेशानी नहीं होगी—जब तक कि...
कांग्रेस ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम का पालन किया। इसके बाद
सुरजीत ने सीपीआई (एम) के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया, करात एक
प्रधानमंत्री के लिए कांटा। जबकि करात की सार्वजनिक छवि एक
वैचारिक रूप से अडिग, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे सौम्य थे।
और एक सच्चे सज्जन व्यक्ति। करात के साथ व्यवहार करना विशेष रूप से कठिन था।
भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों पर। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें सबसे उपयुक्त पाया।
सबसे कठिन चुनौती। उनकी पैनी निगरानी में, यूपीए की कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स ने
न्यूनतम कार्यक्रम ने वामपंथियों की चिंताओं को ध्यान में रखा था—लगभग
'अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना'। जब दोनों पक्ष
सीएमपी मसौदे पर चर्चा करते हुए, कांग्रेस ने शुरू में इसके बारे में बात की थी
अमेरिका के साथ एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना। 'हमने उस वाक्य को हटा दिया।'
करत का खुलासा हुआ। इसे एक फीकी भावना से बदल दिया गया जिसमें मांग की गई थी
'एक स्वतंत्र विदेश नीति' के बाद 'अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार'।
नीति का विरोध करना और एकतरफापन के सभी प्रयासों का विरोध करना।
2007 के मध्य तक, जब प्रधानमंत्री ने अपना सनसनीखेज साक्षात्कार दिया था।
द टेलीग्राफ के अनुसार, प्रकाश करात को कई हलकों में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जो...
भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। यूपीए के भविष्य की कुंजी उन्हीं के हाथ में थी।
सरकार।
जब कांग्रेस ने सीपीआई (एम) के साथ सुलह करने की कोशिश की, प्रणब
मुखर्जी उनके लिए उस समय के सबसे चर्चित व्यक्ति बन गए—क्योंकि वे न तो प्रधानमंत्री थे और न ही

सोनिया गांधी को कट्टरपंथी करात से निपटने का तरीका बखूबी पता था।
सीपीआई (एम) नेता को अनौपचारिक स्तर पर संभालने की जिम्मेदारी मुखर्जी पर छोड़ दी गई थी।
यूपीए-वामपंथी भारत-अमेरिका समिति की बैठकों और चर्चाओं में
नागरिक परमाणु सहयोग। 'यह सिर्फ प्रणब मुखर्जी ही कर सकते थे'
खुद करात ने स्वीकार किया, 'वह वामपंथ को जानते और समझते थे।'
■

'जो होगा सो होगा' कहने के बाद प्रधानमंत्री धीरे-धीरे एकांत में सिमट गए।
अगस्त 2007 का वह साहसपूर्ण प्रयास—जब प्रणब मुखर्जी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की
परमाणु समझौते और यूपीए सरकार के संबंध में मुखर्जी ने नौ बैठकें कीं।
यूपीए-वाम समन्वय समिति। उनमें से छह हाइड में थे।
अधिनियम और भारत की विदेश नीति पर इसके प्रभाव। इसने
वामपंथियों को सबसे ज्यादा। 'हमने कहा था कि हम खुद को अमेरिका से बांध लेंगे।'
करात ने कहा, 'हमारी विदेश नीति। हाइड अधिनियम की प्रस्तावना ने इसे
यह स्पष्ट है कि हम ईरान को अलग-थलग करने के लिए काम करेंगे। भारत का ईरान के साथ एक पुराना और आजमाया हुआ रिश्ता रहा है। वामपंथियों की आलोचना के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ईरान को अलग-थलग करने के लिए काम किया है।
मंत्री ने संसद को बताया कि हाइड एक्ट भारत पर बाध्यकारी नहीं है।
हालांकि, वामपंथी दल इससे आश्वस्त नहीं हुए।
समिति की तीन बैठकें आईएईए को समर्पित थीं।
समिति की पहली चार बैठकों में काफी प्रगति हुई।
दोनों पक्षों ने विस्तृत दस्तावेज़ और प्रतिवाद प्रस्तुत किए। प्रणब
मुखर्जी ने ज्योति बसु को हर बात की जानकारी देते रहने पर विशेष ध्यान दिया। उन्हें उम्मीद थी कि...
बासु सीपीआई (एम) पर एक संयमकारी प्रभाव डालेंगे।

अक्टूबर 2007 में, हिंदुस्तान टाइम्स ने नई दिल्ली में एक 'शिखर सम्मेलन' का आयोजन किया।
12 अक्टूबर को दिल्ली में हुई घटना ने प्रधानमंत्री के विचारों की एक झलक पेश की।
सोच-विचार। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों को आमंत्रित किया गया था।
प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को टेलीविजन पर लाइव देख रहे थे।
आरसीआर स्थित उनके आवास पर। होटल जाने के लिए अपने आवास से निकलने से पहले, जहाँ
कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, वह सोनिया की बात सुनना चाहता था।
उन्होंने टेलीविजन पर सोनिया को यह कहते हुए सुना कि वामपंथी परमाणु समझौते का विरोध कर रहे हैं।
यह 'अनुचित नहीं' था। उन्होंने वादा किया कि सरकार काम करेगी।
आम सहमति के लिए।
प्रधानमंत्री समारोह के लिए रवाना हो गए। अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी।
मनमोहन सिंह अब समझ गए थे कि उन्हें अपने विरोध को कम करना होगा।
उन्होंने एचटी के श्रोताओं को बताया कि सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। और अगर
उन्होंने आगे कहा कि परमाणु समझौता नहीं हो पाया, लेकिन यह अंत नहीं होगा। ज़िंदगी'।
पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और पूछा, 'अगर वामपंथी ऐसा नहीं करते हैं तो क्या आप पद छोड़ देंगे?'
क्या वे परमाणु समझौते पर सहमत हैं?
मनमोहन सिंह हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया, 'यह है' कार्रवाई के लिए एक सुझाव।
प्रधानमंत्री पीछे हट रहे थे। और फिर भी, वे एक कदम पीछे भी हट रहे थे।
सोनिया गांधी समेत अपनी पार्टी को यह संकेत देते हुए कि उनके विकल्प ये थे:
यह खुला है—कि प्रधानमंत्री के रूप में बने रहना है या नहीं।
चिंतित सोनिया गांधी ने मोंटेक सिंह को फोन किया।
अहलुवालिया। वह जानती थी कि अहलुवालिया प्रधानमंत्री के करीबी थे।

‘प्रधानमंत्री का कहना है कि वह बहुत नाराज हैं,’ चिंतित सोनिया ने अहलूवालिया से कहा।
‘…और वह इस्तीफा देना चाहता है। यह एक आपदा होगी,’ उसने कहा। ‘कृपया
उसे समझाएं कि यह करना सही नहीं है।
अहलुवालिया ने मनमोहन सिंह को इस बातचीत की जानकारी दी। ‘मैं
अहलुवालिया ने बाद में कहा, 'मैं उससे पूरी तरह सहमत था।' वह ऐसा करने में सक्षम था।
प्रधानमंत्री को संकट उत्पन्न न करने के लिए राजी करें।
■

यूपीए-वाम समिति की पांचवीं बैठक में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया।

दोनों पक्षों ने—कई हफ्तों के रोमांचक मुकाबले के बाद। 22 अक्टूबर 2007 को,
प्रणब मुखर्जी ने वामपंथी नेताओं से कहा कि सरकार
संसद की राय के अनुसार चलने को तैयार। उन्होंने कहा, 'वोट नहीं, बल्कि (के लिए)
सदन का (अंदाजा) प्राप्त करें।
‘आपने एक महत्वपूर्ण रियायत दी है,’ बर्धन ने जवाब दिया।
सरकार का प्रस्ताव।
प्रणब मुखर्जी ने फिर अपनी गुगली गेंद फेंकी: 'जब तक कोई
आईएईए के पाठ के आधार पर, हम इस बात पर सहमत नहीं हो पाएंगे कि भारत का चिंताओं का समाधान किया जा रहा है।’ मुखर्जी आईएईए का जिक्र कर रहे थे।
सरकार को समझौते को जारी रखने के लिए जिस छूट की आवश्यकता होगी, वह इस समझौते को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगी।
आगे बढ़ते हुए। उन्होंने वामपंथी दलों से सरकार को जाने देने का आग्रह किया।
आईएईए। उन्होंने दलील दी कि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता दांव पर लगी है।
‘हम आईएईए के खिलाफ नहीं हैं’, करात ने जवाब दिया। ‘हम इसके खिलाफ हैं’
आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने धारा 123 (समझौता) और हाइड अधिनियम का हवाला देते हुए यह तर्क देने की कोशिश की।
शांति। उन्होंने कहा कि उन्हें हाइड एक्ट या '123' से कोई लेना-देना नहीं था।

‘Kripya jhagrha mat kariye (Please don’t fight),’ he said. ‘You discuss
'इस बारे में प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष से बात करें और इसका समाधान निकालें।' उन्होंने आगे कहा:
‘चुनावों के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है (यदि वामपंथी दल ऐसा करें तो)
यूपीए से अपना समर्थन वापस लेने पर सरकार गिर जाएगी)...
हमें राजनीतिक रूप से सक्रिय होना होगा। हमें एकजुट रहना होगा।'
एक भोज कार्यक्रम में दोनों पक्षों के बीच संबंधों में नरमी दिखाई दी।
कुछ हफ़्ते बाद वामपंथी नेताओं के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुने गए।
10 नवंबर 2007। प्रधानमंत्री के अलावा, इसमें सोनिया गांधी भी उपस्थित थीं।
प्रणब मुखर्जी, प्रकाश करात, और ए. बी. बर्धन। छोड़ा
राजनेताओं ने कुछ हद तक अपना रुख नरम किया। 'हम इसके विरोध में थे।'
सरकार आईएईए के पास जा रही है,’ करात ने बाद में कहा। ‘लेकिन हम उस समय सहमत हो गए थे।
उन्हें (आईएईए में) जाने देने के लिए बैठक हुई। दोनों पक्षों ने इस पर सहमति जताई।
कि आईएईए के साथ बातचीत करके तैयार किया गया पाठ पहले दिखाया जाएगा
(वामपंथी-यूपीए) समन्वय समिति। और योजना यह होगी कि
इसे तभी कार्यान्वित किया जाएगा जब समिति अपनी मंजूरी दे देगी।
‘यह (समझौता) प्रणब की सहमति से किया गया था।
मुखर्जी, जो प्रमुख वार्ताकार थे... यह हमें दिया गया था
सोनिया गांधी की सहमति से, कि वे मसौदा वापस लाएंगे
करात ने कहा, 'आईएईए से इस बारे में चर्चा करने के लिए कहा गया था। और अगर हमने मना कर दिया, तो वे आगे नहीं बढ़ेंगे... यही स्पष्ट समझौता हुआ था।'
‘वहीं उन्होंने हमें धोखा दिया… नवंबर के बीच क्या हुआ था?’
'असली कहानी 2007 और जून 2008 की है,' करात ने कहा।
■

प्रधानमंत्री फरवरी और मार्च में फिर से आक्रामक हो गए।

2008—अगस्त 2007 में उनके संक्षिप्त विरोध प्रदर्शन के बाद, और
नवंबर 2007 में उनकी पार्टी द्वारा उन पर लगाम कस दी गई थी।
फरवरी 2008 की शुरुआत में निर्णायक मोड़ आया। अमेरिकी नागरिकों के एक समूह ने
उस महीने कांग्रेस के सदस्य भारत दौरे पर गए थे। उनमें दो डेमोक्रेट भी शामिल थे, जॉन
अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष केरी और
जो बाइडेन, जो बाद में नवंबर 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने।
उनके साथ तीसरा व्यक्ति रिपब्लिकन चक हेगल था। बिडेन और उनके
सहकर्मियों ने मनमोहन सिंह को आगाह किया कि जब तक वह दबाव नहीं डालेंगे...
अगर परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का अवसर मिले तो
उसके हाथों से फिसल गया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सौदा पूरा होने की संभावना अधिक है।
रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश अभी भी पद पर हैं (जनवरी की शुरुआत तक)।
2009) और सीनेट में रिपब्लिकन बहुमत। अमेरिकी चुनाव
नवंबर 2008 के लिए निर्धारित था और अगर डेमोक्रेट जीत जाते, तो न तो
न तो बराक ओबामा और न ही हिलेरी क्लिंटन इसका सामना कर पाएंगे।
अमेरिका में परमाणु अप्रसार लॉबी। अमेरिका की तरह भारत भी इस ओर रुख करेगा।
इसके तुरंत बाद, 2009 की गर्मियों में, चुनाव हुए, और परिणाम इससे बहुत दूर थे।
हमें पूरा यकीन था कि कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी। 'हमें इस बात की जानकारी थी कि
‘समय सीमा बहुत सख्त है,’ मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने मुझसे कहा।
हालांकि, करात का मानना था कि अमेरिकियों ने अपनी भूमिका बढ़ा दी थी।
भारतीय सरकार पर दबाव। 'हमारा मानना है कि अमेरिकियों ने ऐसा किया।'
उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, संदेश यह था कि "अगर यह सौदा संभव नहीं है तो इसे भूल जाओ"।
अब हो गया।
कारण चाहे जो भी हो, मनमोहन सिंह को इस दिशा में प्रेरित किया गया।

गतिविधि। उसने एक बार फिर आक्रामक रूप से सौदे को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने किया
उन्होंने अपने पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी से समर्थन प्राप्त करने के लिए नए सिरे से संपर्क साधा,
साथ ही पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा भी। इस बार,
2005 के विपरीत, मिश्रा मनमोहन सिंह के समर्थन में सामने आए।
हालांकि, वाजपेयी राजनीति से संन्यास ले चुके थे और एल.के. आडवाणी, जो
भाजपा के प्रभारी इस समझौते के खिलाफ थे।
इसी समय मनमोहन सिंह ने संपर्क साधा।
समाजवादी पार्टी से समर्थन मांगने के लिए उन्होंने अमर सिंह से संपर्क किया, जिनके सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ शब्दों की गिनती की गई।
■

एम. के. नारायणन ने ही प्रधानमंत्री को यह विचार बेचा था कि उन्हें यह पद प्राप्त करना चाहिए।
एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने खुलासा किया, 'समाजवादी पार्टी का समर्थन।'
मुझे। 'प्रधानमंत्री पूरी तरह से इसके झांसे में आ गए।'
यह 'माइक' था, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम. के. नारायणन का यही नाम था।
सहकर्मियों द्वारा बुलाया गया, जिन्होंने मनमोहन सिंह को सलाह दी कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है।
वामपंथी दलों द्वारा बंधक बना लिया जाना।
'अमर सिंह को इस प्रोजेक्ट में शामिल करवाने में मेरी भी भूमिका थी,' एम. के. नारायणन ने कहा।
उसने मुझे बताया, 'मुलायम सिंह को साथ लाने का यही एकमात्र तरीका था।'
नारायणन ने कहा, 'मुझे कभी दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने अमर सिंह से कहा, अगर
अगर आप मनमोहन सिंह की मदद करते हैं, तो आपका नाम इतिहास में अमर हो

जाएगा।
एम. के. नारायणन को साथ लाना…“अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि
केंद्रीय स्तर पर... यह (प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया) एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय था।
मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा.
नारायणन ने आगे कहा, ‘जहाँ तक मेरा सवाल था, मुझे पता था कि सब कुछ कहाँ है।’
मोहरे शतरंज की बिसात पर रखे हुए थे।
2005 में, नारायणन को इस सौदे को लेकर कुछ आपत्तियां थीं। वह एक
सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त; वह भी इस सौदे से संतुष्ट नहीं थीं।
शुरू में तो। लेकिन तब उन्हें वामपंथ से कोई खास लगाव नहीं था, और
कुछ समय बाद उनकी स्थिति में थोड़ा बदलाव आएगा। एक कनिष्ठ खुफिया अधिकारी के रूप में
1959 में, वह बर्खास्तगी के अभियान में शामिल थे।
केरल में कम्युनिस्ट सरकार—यह इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया निर्णय था।
ऐसा माना जाता है कि उस समय राष्ट्रपति रहीं इंदिरा गांधी की नजर उन पर पड़ी थी।
उस समय कांग्रेस के नेता के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई—और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उसके बाद, सोनिया गांधी ने नारायणन के करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
जे. एन. दीक्षित की अचानक मृत्यु के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया।
मनमोहन सिंह ने 2004 में दीक्षित को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना था, नारायणन ने भी।
उस पद के लिए दावेदारी पेश की थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता दी।
दीक्षित।
इसके बजाय 'माइक' को प्रधानमंत्री कार्यालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया।
आंतरिक सुरक्षा विभाग को एनएसए से अलग करके उन्हें सौंप दिया गया था।
जिम्मेदारी। यह पद सोनिया गांधी के कहने पर विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया था। उन्हें बारह साल बाद निष्क्रियता से बाहर निकाला गया।

उनके सेवानिवृत्त होने के कई वर्षों बाद।
‘2004 में, मैंने सोनिया गांधी को उनका नाम सुझाया था, जिसमें मैंने उनकी प्रतिक्रिया देखी थी।
नटवर सिंह ने याद करते हुए कहा, 'गांधी परिवार से उनकी निकटता पर ध्यान दिया गया था।'
2005 में, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, नारायणन राष्ट्रपति बने।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। गणतंत्र दिवस की सुबह।
परेड के दौरान, उन्हें सोनिया गांधी के बैठने की जगह की ओर जाते हुए देखा गया और
‘doing an elaborate namaste to her’, recalled Sanjaya Baru.
वाशिंगटन डीसी से लौटने के तुरंत बाद, एक समिति
प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अचानक अस्तित्व में आया।
नारायणन और परमाणु विभाग के प्रख्यात व्यक्तियों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की।
ऊर्जा। विदेश सचिव श्याम सरन को आश्चर्य हुआ कि वह
उन्हें समिति से बाहर कर दिया गया। क्योंकि तब तक वे ही मुख्य भूमिका में थे।
अमेरिकियों के साथ बातचीत करने वाला व्यक्ति। परेशान सारन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
मंत्री; वह जानना चाहता था कि उसे क्यों पद से हटाया गया था—और
उन्होंने समिति में शामिल किए जाने का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री ने सरन की बात सुनी। वे सहानुभूतिपूर्ण प्रतीत हुए।
लेकिन उसने कुछ नहीं किया। सरन को संदेह था कि समिति 'आश्वस्त' थी।
कि हम दुकान अमेरिकियों को बेचने वाले थे।’ स्पष्ट रूप से, सोनिया
गांधी जी शायद प्रधानमंत्री पर लगाम लगाना चाहते थे।
नारायणन ने एक निश्चित समय पर स्वयं को प्रमुख वार्ताकार बना लिया।
'चरण,' मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने खुलासा किया। अपनी शुरुआती स्थिति के बावजूद
नारायणन ने कहीं न कहीं कुछ आरक्षणों को ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार कर लिया।
प्रधानमंत्री के लिए अपरिहार्य—एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं

परमाणु समझौते को लागू करना। नारायणन भी एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। वार्ताकार दल और डीएई के बीच मध्यस्थ।
नारायणन ने कहा, 'परमाणु ऊर्जा विभाग को मुझ पर भरोसा था। अगर मैं
अगर मैं चाहता कि वे बदलाव लाएं, तो वे मुझ पर भरोसा करेंगे।'
'माइक' ने प्रधानमंत्री को इस अभियान को राजनीतिक रूप से अंजाम देने में भी सहायता की।
हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उनका दायित्व राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा था, लेकिन
क्या वही व्यक्ति था जिसने शो के पात्रों को एक साथ लाने में मदद की थी?
जैसा कि 2005-08 के बीच घटित हुआ।
जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2 मार्च 2006 को भारत आए, और जब उन्होंने
एयरपोर्ट पर अपनी कार में बैठते समय, बुश ने नारायणन की ओर रुख किया, जो प्रधानमंत्री के पास खड़ा था। उसने अपने हाथ उन पर रखे।
नारायणन के कंधों पर हाथ रखकर, उसने इतनी जोर से कहा कि आसपास मौजूद सभी लोग सुन सकें।
सुनो, 'मुझे वह सौदा चाहिए।' वार्ता टीमों के लिए संदेश स्पष्ट था। लेकिन यह सोनिया गांधी के लिए भी था। तब तक सोनिया के
सौदे को लेकर आंतरिक हलकों में आशंकाएं जगजाहिर थीं।
नारायणन की उससे निकटता। कभी-कभी राष्ट्रपति बुश उससे पूछते थे।
एनएसए स्टीफन हैडली ने पूछा, 'स्टीव, सब कैसा चल रहा है?' हैडली के अनुसार।
'माइक' जवाब देता, 'ठीक है, सिवाय इसके कि मेरे समकक्ष (नारायणन) के पास बहुत शक्तिशाली मित्र—वह हर दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर से संवाद करता है
'दिन।' उनका तात्पर्य नारायणन द्वारा प्रतिदिन पालन की जाने वाली दिनचर्या से होगा।
चाहे कुछ भी हो रहा हो—एक घंटे की प्रार्थना से पहले
हर रात का भोजन।
इस प्रक्रिया में आए उतार-चढ़ावों को करीब से देखने के बाद
नारायणन को पूरा विश्वास था कि 'यह सौदा दोहराया नहीं जा सकता'
इसके केंद्र में जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह नहीं होने चाहिए।
बुश अक्सर अपने अधिकारियों से पूछते थे, 'मनमोहन सिंह क्या करते हैं?'

क्या चाहिए? मैं उसके प्रति समर्पित हूँ। उसकी मदद करो।'
मनमोहन सिंह की 'ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और आत्म-सम्मान' ही उनकी सफलता का कारण था।
'अपमानजनक तरीकों' ने बुश को प्रभावित किया था। किसी भी सफलता
बातचीत लेन-देन पर निर्भर करती है। लेकिन... प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
एक ही तरंगदैर्ध्य पर थे, (और) इससे निपटना आसान हो गया (एक
मुश्किल हालात।'
आठवीं

22 मई 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक रात्रिभोज का आयोजन किया।
यूपीए की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए रेस कोर्स रोड, 7 पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सरकार। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। कई
यूपीए का समर्थन करने वाले क्षेत्रीय सरदार उनके राज्य से आए थे।
राजधानियाँ। बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। सभी उपस्थित लोग
प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के विशाल लॉन में लोग घूम रहे थे।
एक सुहावनी गर्मी की शाम। राजनीतिक माहौल भी वैसा ही था।
मई के पूरे महीने में माहौल गरमाता रहा। गंभीर मतभेदों को देखते हुए।
परमाणु मुद्दे पर कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच मतभेद विकसित हो गए।
समझौते के बाद, अगर वामपंथी दल अपना समर्थन वापस ले लेते तो मध्यावधि चुनाव कराने की भी बात चल रही थी।
यूपीए को समर्थन।
कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 7 बजे पृथ्वीराज के स्वागत भाषण से हुआ।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री चव्हाण ने प्रधानमंत्री को बोलने के लिए आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री के बाईं ओर सोनिया गांधी गहरे नीले रंग की साड़ी पहने बैठी थीं, जिससे उनकी खूबसूरती और बढ़ गई।
एक नीरस मंच पर रंगों की एकमात्र छटा। मंच पर मौजूद अन्य लोग,
प्रधानमंत्री और यूपीए के अध्यक्ष के साथ-साथ शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता लालू यादव,

शरद पवार, टी. आर. बालू, राम विलास भी मौजूद थे।
Paswan, and Mufti Mohammad Sayeed.
पिछले तीन वर्षों के दौरान यूपीए की वर्षगांठ के समारोह
उन्होंने बिल्कुल उसी प्रक्रिया का पालन किया था। सिवाय इसके कि इस बार प्रधान मंत्री ने...
मंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को रात्रिभोज में आमंत्रित किया था।
उन्होंने यूपीए के बीच के मतभेदों को कम करके दिखाने की भी कोशिश की।
और वामपंथी। अपने भाषण के दौरान, प्रधानमंत्री ने उन मुद्दों पर बात की जो
वह जानता था कि इससे उन्हें प्रसन्नता होगी, जैसे कि सार्वभौमिकरण से।
रोजगार गारंटी योजना, जिसे उनकी सरकार ने शुरू किया था
परिचय दिया गया। उस शाम सीपीआई (एम) और सीपीआई के नेता सीताराम उपस्थित थे।
येचुरी, प्रकाश करात, ए.बी. बर्धन, और डी. राजा। लेकिन दो छोटे
वाम मोर्चा, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी के साझेदारों ने बहिष्कार किया था।
समारोह।
कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला।
अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट—भारत-अमेरिका परमाणु समझौते—के बारे में। स्पष्ट रूप से, उन्हें इसके बारे में पता नहीं था।
उस दिन वह एक असंगत स्वर उत्पन्न करना चाहता था। अपना भाषण समाप्त करते हुए,
मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी को सम्मान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया—और
यूपीए की रिपोर्ट कार्ड जारी करें। मंच के केंद्र में आकर, उन्होंने
उन्होंने उसे हरे रंग की पुस्तिका सौंप दी। हमेशा की तरह वही बात हुई।
मंच पर मौजूद सभी लोगों की समूह तस्वीर जिसमें वे रिपोर्ट को ऊपर उठाए हुए हैं।
अब सोनिया गांधी की बोलने की बारी थी। उन्होंने भी सबको चौंका दिया।
प्रधानमंत्री की जमकर प्रशंसा करके उपस्थित होना। मतभेद
परमाणु समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था, यह सर्वविदित था।

लगभग एक साल से रिश्ते में। 'ओह, प्रधानमंत्री और उनका परमाणु समझौता,' उसने कहा।
एक बार उसने झुंझलाकर कहा था, 'वह इसके प्रति इतना जुनूनी है।'
उनसे संकेत मिलने पर, कांग्रेस के अन्य सदस्य भी इसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।
भावनाएं। वे कहते थे, 'प्रधानमंत्री अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं।'
कांग्रेस हलकों में कहा गया कि दोनों के बीच अंतर हैं।
मामला इस हद तक बढ़ गया था कि सांसदों को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे सुलझाया जाए।
मनमोहन सिंह कब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसका अंदाजा लगाते हुए।
इस अवसर को देखते हुए, भाजपा ने सिंह को 'कमजोर' प्रधानमंत्री करार दिया था।
उस शाम के समारोह में, कई कांग्रेसी सदस्यों ने भाषण दिया।
राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद संभालने की संभावना को लेकर अप्रत्यक्ष संकेत मिल रहे हैं।
'जल्द ही मंत्री'। फिर भी, इस अवसर पर सोनिया गांधी ने एक स्पष्ट संदेश दिया।
अपने दल के सदस्यों से। नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। 'उनका (प्रधानमंत्री का)'
इसके काम करने का तरीका ऐसा है कि इसे समझने में थोड़ा समय लगता है।
(उनसे),' उसने कहा। उसका लहजा सुलह भरा था। '[लेकिन] समय ही बताएगा कि उनका नेतृत्व कितना प्रभावी है।' पर्यवेक्षकों को स्पष्ट था कि मतभेद
इन सबके अलावा, मनमोहन के अलावा कोई और व्यक्ति उन्हें शीर्ष पद के लिए इतना उपयुक्त नहीं मानता था।
सिंह ने ऐसा किया। बेशक, वहां अनुभवी प्रणब मुखर्जी भी मौजूद थे।
हाथ में। वह इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वह दूसरे नंबर पर था।
इंदिरा गांधी के समय से ही वह सरकार में थे। लेकिन इंदिरा गांधी को उन पर भरोसा नहीं था।
वह वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्य के रूप में उनके कामकाज की अनौपचारिक रूप से आलोचना करते थे।
नेता ने कहा, 'लेकिन डॉ मनमोहन सिंह ने कभी इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा।'

उसे।' सोनिया जानती थी कि उसका अपना कोई निजी मकसद नहीं था।
उन्होंने 2004 में उन्हें प्रधानमंत्री क्यों चुना था?
भाषण समाप्त होने के बाद, पृथ्वीराज चव्हाण ने घोषणा की कि
मीडियाकर्मी निकास द्वार पर रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त कर सकते थे।
और उन्होंने सभी को 'रात के खाने के लिए आगे बढ़ने' का निमंत्रण दिया। भोजन का औपचारिक भाग
शाम बीत चुकी थी। अब पत्रकार लोगों से बातचीत करने के लिए उत्सुक थे।
राजनेता उपस्थित थे। यह ठीक उसी तरह का कार्यक्रम था जिसमें इस मुद्दे को उठाया जा सकता था।
रोचक तथ्य। और बहुत कुछ घटित हो रहा था। धीरे-धीरे, सभी ने
वे लॉन में लगे बुफे डिनर की ओर बढ़े, और फिर
लोग उन मेजों की ओर आकर्षित हुए जो एक खुले स्थान में लगाई गई थीं।
बैठने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री की मेज को छोड़कर।
मनमोहन सिंह मुख्य मेज पर बैठ गए।
उस पर नाम के कार्ड लगे हुए थे। सभी मेहमान अपनी-अपनी सीटों पर बैठ गए। केवल बगल वाली जगह खाली थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय खाली रहा। समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह उपस्थित थे।
वहाँ बैठने के लिए, लेकिन वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। उस शाम,
मनमोहन सिंह बढ़ते सौहार्द को सार्वजनिक करना चाहते थे।
उनकी सरकार, अमर सिंह और समाजवादी पार्टी—जिनका उद्देश्य था
वामपंथी दलों के नेताओं सहित उपस्थित सभी लोगों के लाभ के लिए।
प्रधानमंत्री ने अनिश्चितता से चारों ओर देखा। लेकिन कोई संकेत नहीं मिला।
अमर सिंह के। कुछ मिनट बाद, करण सिंह प्रधानमंत्री की मेज पर बैठ गए।
और खाली सीट पर बैठ गए। प्रधानमंत्री की मेज पर एक रिक्ति होती तो...
इतनी बड़ी संख्या में पत्रकारों की उपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया।
इसी बीच अमर सिंह लोदी रोड स्थित अपने घर में शांतिपूर्वक बैठे रहे।
उन्होंने शाम 6.45 बजे सभी उनतीस सपा सांसदों को अपने आवास पर बुलाया था और
उन्होंने उनसे कहा कि वे प्रधानमंत्री के रात्रिभोज में एक साथ जाएंगे।

जैसे-जैसे शाम ढलती गई, सांसदों में बेचैनी बढ़ने लगी। लेकिन अमर सिंह
उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने उनसे कहा, 'हम जल्द ही निकलेंगे।' जब तक वे वहाँ पहुँचे...
7, रेस कोर्स रोड, लगभग रात के 8 बज रहे थे।
अमर सिंह ने जानबूझकर प्रधानमंत्री आवास में उनके प्रवेश में देरी की थी।
क्योंकि वह समाजवादी पार्टी के महत्व पर जोर देना चाहते थे। और वह कांग्रेस को परेशान करना चाहते थे। आखिरकार, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की अनदेखी की थी।
पिछले चार वर्षों से। हालांकि अमर सिंह ने बनाने की योजना बनाई थी।
एक शानदार प्रवेश करते हुए और शीर्ष टेबल पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए, उनका चेहरा उतर गया जब
उन्हें एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री की मेज पर सभी सीटें भरी हुई थीं।
निराश होकर वह तुरंत दूसरी मेज की ओर मुड़ गया जहाँ
वहाँ एक खाली सीट थी और वह वहीं बैठ गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने देख लिया था।
मनमोहन सिंह झटपट अपनी मेज से उठे और उसके पास गए।
अमर सिंह जहां बैठे थे, वहां तक—भले ही सपा नेता ने उन्हें अनुमति दे दी थी।
चिंताजनक क्षण। प्रधानमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके बगल में बैठ गए।
उसे।
मई 2008 में, अमर सिंह जितना महत्वपूर्ण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था।
जहां तक भारत के प्रधानमंत्री का सवाल था। प्रकाश करात और
वामपंथियों को लगा कि वे उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे।
लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह की धूर्तता को कम आंका था।
■

‘अमर सिंह हमें हर बात की जानकारी देते रहते थे,’ उन्होंने कहा।
प्रकाश करात। ‘वह हमें बताते थे कि प्रधानमंत्री उन्हें किस तरह से “लुभाने” की कोशिश कर रहे थे।’
उन्होंने सीपीआई (एम) नेता को बताया कि वह मनमोहन सिंह से छुपकर मिल रहे थे,

लेकिन
नियमित रूप से। प्रधानमंत्री ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि 'परमाणु समझौता
राष्ट्रीय हित में। और अमर सिंह को सपा को इस बात के लिए राजी करना होगा कि...
इसका समर्थन करें।
अप्रैल के अंत में ही उसने (अमर सिंह ने) ऐसा करना शुरू किया था।
'मुझे सूचित करो,' करात ने याद करते हुए कहा। 'और उसने संकेत दिया कि वे वहां से जा सकते हैं।'
(वामपंथियों से दूर)।
जब प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी को लुभाना शुरू किया, तो वे अमर सिंह को देखते थे।
वह सामान्य से अधिक बार ऐसा करेगा। प्रधानमंत्री भी ऐसा करेगा।
अक्सर उसे प्रधानमंत्री कार्यालय के किसी कनिष्ठ अधिकारी के हवाले कर दिया जाता था, जो कोशिश करता और
अमर सिंह अपने शक्तिशाली मित्रों के लिए जो करवाना चाहता था, उसे पूरा किया जाए।
2008 में मनमोहन सिंह के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन मांगना संभव नहीं था।
यह आसान होता। वह जानता था कि सोनिया गांधी ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए रखी थी।
इतनी लंबी अवधि तक—भले ही इसने 2007 तक बाहर से सरकार का समर्थन किया हो।
जब सपा अभी भी सरकार की सहयोगी थी, तब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने
सरकार में बैठे लोगों को स्थायी निर्देश दिए थे—उनका पालन करें
वे जो एहसान मांगते हैं, उनके खिलाफ मामलों में नरमी बरतें, लेकिन
उनके सिर पर तलवार लटक रही है। दूसरे शब्दों में, उन्हें अपने साथ बनाए रखें।
लेकिन उनके बहुत करीब मत जाओ।
एसपी ने 2007 में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। मतभेद
उस वर्ष के मध्य में उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान यह मुद्दा उठा। परिणामस्वरूप,

एसपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी कट्टर प्रतिद्वंद्वी मायावती की बहुजन समाज पार्टी से हार का सामना किया। 2008 में,
संसद में एसपी एक 'तीसरे मोर्चे' का नेतृत्व कर रही थी, जिसे बड़ी मुश्किलों से इकट्ठा किया गया था।
तेलुगु देशम पार्टी जैसे क्षेत्रीय समूह—यह समूह था
जिसे यूएनपीए कहा जाता था। यूपीए से अलग होने के बाद, एसपी ने शुरुआत की।
परमाणु समझौते का विरोध करें। यह वामपंथी दलों का पुराना सहयोगी था, और सीपीआई (एम)
और सीपीआई ने नाजुक समय में मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया था।
उनका राजनीतिक करियर। जब प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि उन्हें जरूरत है
अपनी सरकार को बचाने के लिए सपा के उनतीस सांसदों का समर्थन और
परमाणु समझौते को सुविधाजनक बनाने में, उनकी स्थिति डांवाडोल थी। और जबकि अमर
सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था।
मनमोहन सिंह को अंतिम आश्वासन दिया गया कि प्रधानमंत्री
वह उम्मीद कर रहा था कि एसपी इस सौदे का समर्थन करेगा और उसे संकट से उबार लेगा।
अगर वामपंथी दल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें तो सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
‘आपके विचार से परमाणु समझौते के सूत्रधार कौन हैं?’ अमर
सिंह ने इस प्रश्न को अलंकारिक शैली में पूछा।
‘आप जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह का नाम लेंगे,’ उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा।
उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए। 'मैं आपको बता दूं कि यह जॉर्ज बुश और अमर थे।'
सिंह।’ उनका सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था।
2009 में किडनी फेलियर। तब तक भारत-अमेरिका समझौता संपन्न हो चुका था।
अमर सिंह ने यह बात मजाक में नहीं कही थी। वह पूरी तरह गंभीर थे।
और वह आंशिक रूप से सही था। क्योंकि उसने बचाने में अहम भूमिका निभाई थी।
मनमोहन सिंह की सरकार ने प्रधानमंत्री को सक्षम बनाया था।

भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते को पूरा करने के लिए। अन्यथा, जिस तरह से
राजनीतिक ताकतें उनके खिलाफ एकजुट हो गईं, उनकी सरकार
या तो सौदा रद्द हो जाता या फिर उसे सौदा छोड़ना पड़ता।
■

अमर सिंह को एक राजनीतिक दलाल के रूप में देखा जाता था। लेकिन वह ऐसा नहीं था।
सत्ता के गलियारों में छुपकर काम करने वाले उन आम दलालों की तरह,
और दबाव समूहों की ओर से गुप्त रूप से पैरवी करके वे अपनी मनचाही चीज़ें हासिल करना चाहते हैं।
वे चाहते हैं। वे हर राजधानी के राजनीतिक गुप्त तंत्र का हिस्सा हैं।
दुनिया। लेकिन अमर सिंह को दलाल कहलाना पसंद नहीं था और वह खुद को उनसे कहीं बेहतर मानता था। यह बात एक से अधिक मायनों में सच थी—
वह स्वयं एक सांसद ही नहीं थे, बल्कि एक प्रभावशाली सांसद भी थे, और उन्हें यह पसंद था
वह अपने संपर्कों का दिखावा करता था और अपने कारनामों के बारे में भी शेखी बघारता था।
भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की कहानी इसके बिना अधूरी रहेगी।
अमर सिंह जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों और पैरवीकारों की भूमिका को देखते हुए—और
अमेरिका में संत चटवाल ने इसे पारित कराने में अहम भूमिका निभाई।
न्यूयॉर्क के प्रभावशाली होटल व्यवसायी चटवाल एक और रंगीन व्यक्तित्व थे।
अमर सिंह जैसे व्यक्तित्व, जिन्होंने अमेरिकियों को संगठित करने में मदद की।
समझौते का समर्थन करने के लिए सांसदों और सीनेटरों को राजी किया और उनके साथ काम किया।
अमर सिंह हर संभव तरकीब अपनाकर उन बाधाओं को पार करने की कोशिश करता है जो

मनमोहन सिंह सरकार के प्रयासों को विफल करने की धमकी दी।
उनकी भूमिका में, विद्वान मनमोहन सिंह, जो अन्यथा इतने सतर्क थे
अपनी बेदाग छवि को बनाए रखने के लिए, उन्होंने उनकी सेवाओं का उपयोग करने में संकोच नहीं किया।
उन्हें अपनी परियोजना को पूरा करने में सफलता मिले—ठीक वैसे ही जैसे उनसे पहले अन्य प्रधानमंत्रियों को मिली थी।
हो गया।
अमर सिंह की सफलता का रहस्य एहसानों के लेन-देन में निहित था।
नेटवर्किंग का उद्देश्य लोगों की जरूरतों को पहचानना था—और फिर आगे बढ़ना था।
इसे उपलब्ध कराओ।
उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी, 'जब आप लोगों से मिलते हैं, तो आपको यह सोचना होगा कि...'
आप उन्हें क्या दे सकते हैं, न कि आप उनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं।' 'प्राप्त करना' बाद में आया।
चंद्र शेखर ने राजनीतिक मंच पर पहली बार तब ध्यान आकर्षित किया जब
वह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा, 'मैंने सबसे पहले उन्हें चंद्र शेखर से मिलवाया था।'
कांग्रेस नेता हरिकेश बहादुर. 'हम चन्द्रशेखर से उनके घर पर मिले
दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित भोंडसी आश्रम में। जब चंद्र
बैठक के बाद शेखर उन्हें विदा करने के लिए बाहर आया, उसने बताया कि...
उन्होंने आश्रम में होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया और उन्हें यह भी बताया कि वहाँ क्या-क्या होता था।
अक्सर बहुत सारे लोगों के आने पर कुर्सियों की कमी हो जाती थी।
दो दिन बाद, अमर सिंह ने बड़ी संख्या में भाषण दिए।
भोंडसी को कुर्सियाँ। अमर सिंह बाद में चंद्र शेखर को मना लेंगे।
अमिताभ बच्चन के खिलाफ दायर किए गए मुकदमों को वापस लेने के लिए।
वी. पी. सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में स्थापित।
When Narasimha Rao became prime minister, Madhav Sinh
सोलंकी और माधवराव सिंधिया, दोनों उनकी सरकार में मंत्री थे।
उन्होंने राव को अमर सिंह को पार्टी में पद देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की।

‘बिल्कुल नहीं,’ राव ने उनसे कहा। ‘फिर पार्टी में दलाली शुरू हो जाएगी।’
उसके अपने कुछ गुंडे थे जिन पर वह भरोसा करता था। लेकिन वह अमर सिंह को नाराज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए, समय-समय पर वह
उसकी मदद करेगा। एक बार अमर सिंह उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था।
अमिताभ बच्चन। राव ने अपने मीडिया सलाहकार पी.वी.आर.के. प्रसाद को बताया कि
बच्चन की मदद करें ‘यदि यह संभव हो’ और ‘यदि इसे स्तर पर हल किया जा सके’
सूचना विभाग के सचिव से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन राव ने मुलाकात नहीं की।
अमर सिंह।
एच. डी. देव के शासनकाल के दौरान अमर सिंह एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती बन गए।
गौड़ा के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान, वह साउथ ब्लॉक में आते-जाते रहते थे।
उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी नामक एक अन्य प्रधानमंत्री के साथ भी काम किया।
एक बार उन्होंने उद्योगपति सुब्रतो रॉय (उनके पतन से पहले) को अपने साथ लिया था।
(कृपा करके) वाजपेयी से मुलाकात करने के लिए। रॉय प्रधानमंत्री को शादी में आमंत्रित करना चाहते थे।
उनके दो बेटे। शुरू में अनिश्चित होने के बावजूद, वाजपेयी ने जाने का फैसला किया।
हालाँकि,
जब वाजपेयी लखनऊ के राजसांसी हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो वहां
सुब्रतो रॉय उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित नहीं थे; उन्होंने अपने भाई को भेजा था।
वाजपेयी बहुत नाराज थे।
हालांकि अमर सिंह के राजनीतिक क्षेत्र में मित्र और संपर्क थे
इस स्पेक्ट्रम में, समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम के साथ उनकी निकटता ही मुख्य कारण थी।
सिंह यादव को वह असीमित शक्ति और अधिकार प्राप्त हुआ जो उनके पास था।
सत्ता संभालने आए। सपा के वरिष्ठ नेता—आजम खान, राज बब्बर, शाहिद

सिद्दीकी ने उन्हीं की वजह से पार्टी छोड़ी थी। अमर सिंह ने पार्टी का नेतृत्व किया था।
मुलायम सिंह यादव की दुनिया धन और ग्लैमर की दुनिया से परे थी।
साधारण स्वभाव वाले मुलायम सिंह ने दिल्ली में पांच सितारा पार्टियां आयोजित करना शुरू कर दिया—
उस छोटे कद के पहलवान से नेता बने व्यक्ति को देखना एक विचित्र दृश्य था।
मुलायम धोती और कुर्ते में, जो धीरे-धीरे पदोन्नति पाते हुए इस मुकाम तक पहुंचे थे।
एक जन नेता बनकर, अमीरों को खुश करने की कोशिश करना और
राजधानी के संभ्रांत वर्ग में प्रभावशाली।
अमर सिंह का अमीरों और सफल लोगों पर इतना दबदबा था कि
जुलाई 2009 के मध्य में जब उनका गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था
सिंगापुर के एक अस्पताल में, कई प्रसिद्ध हस्तियों का आगमन हुआ।
अभिनेता, उद्योगपति और राजनेता जो अपने बीमार प्रियजनों से मिलने आए थे
दोस्तों। उनमें अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या भी शामिल थे।
राय बच्चन, उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी,
और अभिनेता दोस्त संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त। मुलायम सिंह
यादव आए, साथ ही उनके बेटे अखिलेश भी आए। हिलेरी क्लिंटन ने एक संदेश भेजा।
वाशिंगटन डीसी से, उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी मांगते हुए।
दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सिंगापुर में तीन महीने बिताए।
जया बच्चन के अनुसार, वह अपने दोस्त अमर सिंह के साथ थे और उन्होंने सिंह के ठीक होने तक उनके साथ रहने के लिए एक फ्लैट किराए पर लिया था—जैसे कोई 'बड़ा भैया' उनकी देखभाल कर रहा हो।
of ‘chote bhaiya’.
समय के साथ, इस पूर्व संपर्क अधिकारी की महत्वाकांक्षाओं के अनुसार (जिसके साथ
केके बिरला समूह ने भारतीय हस्तियों की दुनिया से भी कहीं अधिक ऊंचाइयों को छुआ।
उन्होंने अमेरिका के सबसे प्रभावशाली दंपत्ति को अपना निशाना बनाया।
2000 के दशक की शुरुआत में—बिल और हिलेरी क्लिंटन।

2005 में अमर सिंह ने प्रकाश करात को फोन किया और उन्हें बताया
कि वह बिल क्लिंटन को लखनऊ में रात्रिभोज के लिए आमंत्रित करने जा रहे थे।
‘बुश ही तुम्हारा दुश्मन है, है ना?’ उसने करात से पूछा। ‘तुम्हारे पास कोई नहीं है।’
क्लिंटन से क्या समस्या है?
'यह काफी मजेदार था,' करात ने याद करते हुए कहा।
अमर सिंह ने होटल व्यवसायी संत चटवाल के माध्यम से निमंत्रण देने के लिए संपर्क किया।
क्लिंटन सितंबर 2005 में लखनऊ आए थे। जब क्लिंटन आए, तो यूपी के मुख्यमंत्री
मंत्री मुलायम सिंह यादव ने कुछ सौ लोगों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था।
उन्हें उनके आवास 5, कालिदास मार्ग पर आमंत्रित किया गया था। 'यह एक डिनर पार्टी थी जिसमें बैठकर खाना खाया गया था।'
कार्यक्रम के दौरान, शियामक दावर की टीम द्वारा नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया।
शाम के समारोह में शामिल हुई पत्रकार सुनीता आरोन ने यह बात याद दिलाई।
नर्तक हिट गाने 'सेक्सी रॉक्सी शिकागो' की धुन पर थिरक रहे थे।
'लड़की'। उत्सव शुरू होने से पहले, क्लिंटन चटवाल के साथ शामिल हो गईं, जो पहले से ही मौजूद थीं।
उनके साथ निजी बातचीत के लिए लखनऊ ले जाया गया, 'जहां वह थे'
अमर नाम के भारतीय संसद के एक गुमनाम सदस्य से उनका परिचय कराया गया।
सिंह’। वे लगभग एक घंटे तक मिले, लेकिन यह एक घनिष्ठ संबंध की शुरुआत थी।
अमर सिंह और क्लिंटन परिवार के बीच 'सहयोग'। जब हिलेरी
अगर भारत में कोई एक पुरुष विजेता होता, तो क्लिंटन ने 2006 में अपनी सीनेट सीट जीत ली होती।
जो लगभग खुशी से झूम उठे और डेमोक्रेट्स की तरह ही जमकर जश्न मनाया।
अमेरिका में, वह अमर सिंह था। उसके 'ब्रश करने' का काम खत्म होने से पहले ही।
'उसकी जैकेट से कंफ़ेटी हटाओ', अमर सिंह ने घोषणा की थी कि वह ऐसा करेगा
यदि वह 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत जाती हैं, तो उन्हें भारत आमंत्रित किया जाए।
अमर सिंह आगे चलकर मनमोहन सरकार को संकट से उबारेंगे।
जुलाई 2008 में 'वोट के बदले नकद का मामला'—जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे—

जिसके लिए वह
उन्हें 2011 में गिरफ्तार किया गया था। अपने जीवन के अंत तक, उन्होंने इस बात का अफसोस जताया कि
जब वह जेल में था तब कांग्रेस ने उसकी मदद नहीं की थी—भले ही वह
मनमोहन सिंह सरकार को बचाया था। एक कांग्रेस मंत्री
उन्होंने उससे कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह दागदार था। 'मैं नहीं था'
'जब मैंने 2008 में तुम्हारी जमानत करवाई थी, तब से तुम कलंकित हो,' अमर सिंह चिल्लाते हुए बोला।
कि यूपीए सरकार ही दागदार थी।
1 अगस्त 2020 को उनकी मृत्यु से एक महीने पहले, उन्होंने संजय बारू को फोन किया था।
और उसने उसे बताया कि उसने मनमोहन सिंह पर बारू की किताब पर आधारित फिल्म देखी है।
सिंह—अचानक बने प्रधानमंत्री। 'आप जानते हैं, मैं अपनी भूमिका निभा सकता था।'
उस फिल्म में अपनी भूमिका उस व्यक्ति से बेहतर निभाएं जिसने उसमें अभिनय किया था...
(Instead) Kisi actor ko Amar Singh bana diya aapne (Instead you made
कोई और (अमर सिंह)।
■

मनमोहन सिंह के शासनकाल में संत चटवाल हमेशा से ही सर्वोपरि नहीं थे।
दरबार—और यह बात अक्टूबर में दिल्ली में हुई एक शादी में स्पष्ट हो गई।
2004 में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सिंह ने भाग लिया था। यह एक खूबसूरत कार्यक्रम था।
देश की राजधानी में साल का वह समय। मौसम बदलने लगा था।
सुबह के समय गर्म और उमस भरी हवा की जगह ठंडी ताजगी का झोंका ले लेता है।
और शामें। बोगनविलिया के फूल गोल चक्करों और बंगलों को कालीन की तरह ढक

लेते थे।
लुटियंस के दिल्ली की समृद्ध सफेद, गुलाबी और लाल रंग की छवि, और उसकी सुगंध।
विद्वान वृक्ष (मिल्कवुड या डेविल्स ट्री) जिसे 'दिल्ली की शीतकालीन गंध' कहा जाता है।
वातावरण में एक सुगंध भर गई।
सतीश शर्मा, एक प्रभावशाली कांग्रेसी नेता जो उनके करीबी थे
भारत के दो प्रधानमंत्रियों—राजीव गांधी और पी.वी. नरसिम्हा राव
—28 तारीख को अपनी बेटी सारिका की शादी का रिसेप्शन आयोजित कर रहे थे।
अक्टूबर 2004. कैप्टन शर्मा, जो नरसिम्हा में मंत्री रह चुके थे
राव की सरकार ने देश भर की जानी-मानी हस्तियों को आमंत्रित किया था।
और विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी इस कार्यक्रम में भाग लिया गया।
यह आयोजन छतरपुर में स्थित उनके विशाल फार्महाउस में आयोजित किया गया था, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है।
दिल्ली।
सुबह शादी समारोह में मौजूद सितारे चार थे।
सोनिया गांधी के परिवार की कई पीढ़ियाँ। उनकी माँ, पाओला मैनो,
उन्हें इटली के ओर्बासानो से बुलाया गया था। उनकी बेटी प्रियंका, एक खास पोशाक में सजी हुई थीं।
खूबसूरत गुलाबी बनारसी रेशमी साड़ी उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ थी—और
उनकी बेटी, मायरा ने अपनी गर्वित दादी और परदादी दोनों को याद रखा।
दादी व्यस्त थीं। आमतौर पर कम बोलने वाले राहुल गांधी ने अनुमति दी।
किसी को उसके सिर पर बहुरंगी सफा (पगड़ी) बांधने के लिए कहा गया।
हालांकि, सबकी निगाहें सोनिया गांधी पर टिकी थीं, जो एक खास पोशाक में सजी हुई थीं।
हल्के नीले रंग की रेशमी साड़ी और ऐसे गहने पहने हुए जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलते थे।
सोनिया गांधी, जो आमतौर पर सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहनती थीं, उन्हें यह पोशाक दी गई थी।

हथकरघा वस्त्र पहनने के बारे में। उस दिन वह काफी सहज लग रही थी और लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए भी तैयार थी। यह सिर्फ चार महीने की बात थी।
इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में आई थी।
दिल्ली में सोनिया गांधी देश की सबसे शक्तिशाली हस्ती बन गईं।
प्रधानमंत्री पद का त्याग करने के बाद।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शादी के स्वागत समारोह में आए थे।
शाम को उनका स्वागत कैप्टन शर्मा और उनकी पत्नी ने किया।
प्रवेश द्वार पर स्टेरे। व्यापार जगत के प्रमुख दिग्गज।
प्रधानमंत्री का स्वागत राजनीति ने किया। अचानक बारिश शुरू हो गई और लोग आश्रय खोजने के लिए लोग दौड़ पड़े। प्रधानमंत्री को शर्मा परिवार की योजना में शामिल किया गया।
कमरा। कमरे में लगभग आठ लोग थे—प्रधानमंत्री और उनके साथी।
पत्नी, गुरशरण कौर, सतीश शर्मा और उनकी पत्नी, उनकी बेटी और
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, दामाद और एसपीजी के लोग भी इसमें शामिल थे।
राजनीतिज्ञ बी. एम. भामा। 'मैं उस समय संयोगवश कमरे में मौजूद था, और
भामा ने याद करते हुए कहा, 'मैंने अपनी आँखों से देखा कि आगे क्या हुआ।'
उस समय कप्तान शर्मा के करीबी। उस समय, संत चटवाल
वह कमरे में दाखिल हुआ और सीधे प्रधानमंत्री के पास चला गया। 'मैंने उनमें से एक को देखा।'
प्रधानमंत्री के सुरक्षा दल के जवान प्रधानमंत्री के कान में कुछ फुसफुसाते हैं।
भामा ने याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने चटवाल की ओर देखा। कुछ ही सेकंडों में...
एसपीजी तुरंत हरकत में आ गई। 'वे अत्यंत सम्मान और विनम्रता के साथ आगे बढ़े।'
चटवाल के पास जाकर मैंने कहा, “महोदय, आप इधर आइए”, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता
जो कुछ हो रहा था, उसे उन्होंने बड़ी कुशलता से कमरे से बाहर निकाल दिया।
प्रधानमंत्री को जरूर पता होगा कि वहां फोटोग्राफर मौजूद थे।
और उसने जरूर तुरंत कुछ सोचा होगा। अगर कैमरों ने उसे पकड़ लिया होता
चटवाल से बातचीत करते हुए—भारत में उनके खिलाफ सीबीआई के मामले दर्ज थे —कुछ

विपक्ष इस 'बैठक' को एक अलग ही रंग दे सकता था।
और यह प्रधानमंत्री के लिए अच्छा नहीं रहा होगा। जबकि प्रधानमंत्री ने एक
उस दिन संत चटवाल से काफी दूरी बनाए रखी गई थी, अठारह महीने बाद, 19 तारीख को।
फरवरी 2006 में, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के भारत पहुंचने से दस दिन पहले,
उन्होंने दिल्ली में होटल व्यवसायी के बेटे विक्रम की शादी में शिरकत की।
इसे 'भव्य सिख विवाह' के रूप में वर्णित किया गया था, और इसे एक भव्य समारोह में मनाया गया।
पैमाने पर। पचास हजार किलोग्राम फूल बाहर से मंगाए गए थे।
हॉलैंड, बैंकॉक और कलकत्ता; भोजन, पेय पदार्थ और अन्य सजावट
भव्य आयोजन थे। उत्सव दस दिनों तक चला। सामान्यतः,
मनमोहन सिंह को शादी समारोहों में जाने की आदत नहीं थी।
विशेषकर उन लोगों के बारे में जिन्हें वह अच्छी तरह से नहीं जानता था। इस अवसर पर, उसके पास था
उन्होंने आने का फैसला किया, हालांकि उन्हें एक सहायक द्वारा 'सलाह' दी गई थी कि यह संभव हो सकता है
दूर रहना ही समझदारी थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे अपने साथ पीले रंग के खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता लेकर आए।
फूल। अब तक, चटवाल मनमोहन सिंह के घर में प्रवेश पा चुके थे।
दरबार। कांग्रेस के एक पूर्व सांसद ने मुझे बताया: 'वहाँ बहुत कम लोग थे।
प्रधानमंत्री ने कई प्रसिद्ध सिखों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया।
जब वे दिल्ली गए (और उनसे मिलने की इच्छा जताई)।
पंजाब के फरीदकोट में छोटे व्यापारियों के एक परिवार से,
चटवाल अमेरिका पहुँच गए थे और वहाँ एक धनी होटल व्यवसायी बन गए थे।
न्यूयॉर्क। वास्तव में, न्यूयॉर्क में प्रभावशाली भारतीय आगंतुकों की संख्या बहुत कम थी।
यॉर्क, जिसका चैटवाल ने अपने पेंटहाउस में स्वागत नहीं किया था,
मैनहट्टन में इसकी फर्श से छत तक फैली कांच की खिड़कियां। आगंतुकों में शामिल थे:

हर विचारधारा के राजनेता, मीडियाकर्मी, न्यायाधीश, वरिष्ठ नौकरशाह।
उन्होंने उनके और अपने संपर्कों के बीच सेतु का काम किया।
अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान में उनका पालन-पोषण हुआ था। वे वहां के लोगों को जानते थे।
न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में जाकर पहले से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कौन कब और किस उद्देश्य से आ रहा था। बिल से उसकी निकटता और
हिलेरी क्लिंटन काफी प्रसिद्ध थीं।
2007-08 में, उन्होंने परमाणु समझौते में मदद की। और बदले में,
मनमोहन सिंह ने संत चटवाल की भूमिका को नहीं छिपाया।
भारत-अमेरिका समझौते को सफल बनाने में भारतीय सरकार का योगदान रहा।
संत चटवाल के खिलाफ कानूनी मामले वापस ले लेंगे—उन्होंने
उन्होंने 1997 में कुछ समय के लिए जेल में बिताया, उनके खिलाफ दो आरोपपत्र दायर किए गए थे, और
बैंक धोखाधड़ी का मामला—और उसे तो एक पुरस्कार भी मिल जाएगा।
उन्हें 2010 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
'सेवाओं' का प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार संत चटवाल को प्रदान किया गया।
सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री का उदाहरण
अपनी आपत्तियां व्यक्त करते हुए, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने उस समय सार्वजनिक रूप से अपनी आपत्तियां जताईं।
केंद्र के फैसले से पार्टी की नाराजगी। 'कांग्रेस चाहती है कि...'
पद्म पुरस्कार उन लोगों को दिए जाएंगे जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं।
पार्टी के प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा, 'पुरस्कार के साथ-साथ अपना भी।' 'नहीं
'दागी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए।' सत्तारूढ़ पार्टी का अप्रत्यक्ष बयान
यह आलोचना स्पष्ट रूप से सोनिया गांधी की अपनी नाखुशी को दर्शाती थी।
फ़ैसला।
अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने भी इस कदम का विरोध किया था।
अमेरिका में भारतीय राजदूत रोनेन सेन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को बताया था कि वह

ऐसा करेगा।
श्री चटवाल को पद्म पुरस्कार देना उचित नहीं होगा क्योंकि
भारत में उनके वित्तीय लेन-देन से जुड़े विवाद और
अमेरिका।' दूतावास ने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर श्री चटवाल को नामित करने से इनकार कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री
इस मामले में मनमोहन सिंह ने अपनी पार्टी और दोनों के फैसले को पलट दिया।
वाशिंगटन डीसी में भारतीय मिशन। उन्हें अवश्य ही बहुत ऋणी महसूस हुआ होगा।
चटवाल ने बताया कि उन्होंने विवादास्पद सम्मान देने का फैसला किया है।
होटल व्यवसायी। नवंबर 2008 में, भारत-
अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद मनमोहन सिंह ने संत चटवाल को एक निजी पत्र लिखा।
उन्होंने चटवाल के 'व्यक्तिगत प्रयासों' के लिए अपनी 'सच्ची प्रशंसा' व्यक्त की।
भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को साकार करने के लिए। छह साल बाद, अप्रैल में 2014 में, संत चटवाल ने इस नोट को 300 प्रशंसा पत्रों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया।
उन्हें अपनी सजा में नरमी बरतने की अपील करने का मौका मिला था। यह घटना इसके बाद हुई।
उस पर अवैध चुनाव प्रचार करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
चंदा देने के आरोप में उन्होंने अमेरिकी संघीय चुनाव नियमों का उल्लंघन करने का अपराध स्वीकार किया।
कानून।
पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर प्रसन्न चटवाल ने कहा, 'मैं
परमाणु समझौते को लागू करवाने में मैंने जो काम किया है, उस पर मुझे बहुत गर्व है।
उन्होंने कहा, 'एक साथ। अमेरिका के इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति है।'
अमेरिका में कौन 18 सीनेटरों और 50 कांग्रेस सदस्यों को एक कमरे में इकट्ठा कर सकता है?
सीनेट भवन...वहाँ मेरे चार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। मुझे इसमें समय लगा।
चार साल और लाखों डॉलर, जो मैंने अपनी जेब से चुकाए।'
उन्होंने 17 मई 2008 को अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों को एक साथ बुलाया था ताकि

'उठाया जा सके'
भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बारे में जागरूकता। हालाँकि, चटवाल से पहले
एक सफल ढंग से समाप्त हुई कहानी की चमक-दमक का आनंद ले सकते थे।
कथानक में कई उतार-चढ़ाव थे जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता थी।
नेविगेट किया।
नौवीं
जून 2008 के तीसरे सप्ताह में मनमोहन सिंह ने अपना पहला भाषण दिया था।
तुरुप का पत्ता। उन्होंने धमकी दी कि अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो वे फिर से इस्तीफा दे देंगे।
समझौते में प्रगति हुई। 17 जून की शाम को प्रधानमंत्री ने
उन्होंने सोनिया गांधी को फोन किया। उन्होंने सोनिया गांधी को बताया कि वह अपना इस्तीफा देना चाहते हैं।
इसी वजह से सोनिया उस सुबह 7, रेस कोर्स रोड पर दौड़कर पहुंची।
18 जून। उन्होंने प्रणब मुखर्जी से उनके साथ शामिल होने का अनुरोध किया।
'मेरे लिए अब आगे काम करना असंभव हो गया है,' निराश प्रधानमंत्री ने कहा।
सरकार आईएईए के साथ बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी।
भारत विशिष्ट सुरक्षा समझौता। लेकिन उन्होंने कहा कि वामपंथी दलों ने इस बात पर जोर दिया कि
आईएईए (सचिवालय) के साथ तैयार किए गए समझौते के मसौदा को प्रदर्शित किया जाए।
पहले उन्हें। 10 नवंबर 2007 को प्रधानमंत्री द्वारा वामपंथी नेताओं के लिए आयोजित दोपहर के भोजन में यही समझौता हुआ था—लेकिन अब प्रधानमंत्री
पीछे हटना।
प्रधानमंत्री ने अचानक कहा, 'वामपंथी जो चाहते हैं वह संभव नहीं है।'
सोनिया गांधी पर। एक गुप्त दस्तावेज उन लोगों को नहीं दिखाया जा सका।
उन्होंने कहा कि सरकार के बाहर। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो...
उन्होंने कहा कि अगर आईएईए ने इस्तीफा दिया तो वे 'तुरंत' इस्तीफा दे देंगे। उनके इस्तीफे की धमकी के साथ,
मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी को मुश्किल में डाल दिया। उनके पास दो ही विकल्प

थे: या तो वे चुप रहें या चुप रहें।
उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया—और वे परमाणु समझौते के साथ आए —वरना वह ऐसा करतीं
उसके बिना काम चल जाएगा। उस स्थिति में, परमाणु समझौता नहीं होगा। वह
मैंने अनुमान लगाया है कि वह प्रणब को पदोन्नत करने के प्रति अनिच्छुक होगी।
मनमोहन मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाना मनमोहन सिंह का एक सुविचारित कदम था।
सिंह. हताश सोनिया गांधी ने मोंटेक सिंह अहलूवालिया की ओर रुख किया
फिर से मदद की गुहार लगाई। इस बार अहलूवालिया ने अपनी बेबसी जाहिर की।
उन्होंने उससे कहा, 'मैंने पहले ही मान लिया था कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए।
लेकिन सच कहूं तो, एक
अब आप उनसे यह नहीं कह सकते कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका रुख बहुत ही गंभीर है।
उचित।' हालांकि, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करने का वादा किया।
मनमोहन सिंह ने अहलूवालिया से कहा, 'मैंने अपना मन बना लिया है। या तो मैं...'
इसे पूरा करो, वरना मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा।' मीडिया को खबर मिल गई थी कि
प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। क्या सरकार टिक पाएगी? दिल्ली में भीषण अशांति
फैली हुई थी।
सरकार के भविष्य को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।
प्रणब मुखर्जी ने वामपंथी नेताओं से दोबारा मुलाकात की। उन्होंने कोशिश की कि
उन्हें इस बात के लिए राजी करें कि सरकार को आईएईए बोर्ड के पास जाने दिया
जाए।
बिना किसी शर्त के राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'उसके बाद हम
देखेंगे।'
उन्हें। करात को यह बात बहुत अस्पष्ट लगी।
मुखर्जी ने शायद मन ही मन उम्मीद की होगी कि सोनिया गांधी ऐसा करेंगी।
उन्हें चुनिए और मनमोहन सिंह को जाने दीजिए। मुखर्जी बेहतर विकल्प होते।
वामपंथियों के साथ किसी भी मतभेद को छुपाने में सक्षम (अन्य बातों के अलावा,
उन्होंने पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से लोकसभा चुनाव जीता था।
2004 में उनके समर्थन से)। वैसे भी वह अधिकांश काम संभाल रहे थे।

सरकार, दर्जनों राष्ट्रीय सरकारों और ई-राष्ट्रीय सरकारों का नेतृत्व कर रही है।
हम उसे (मनमोहन सिंह को) अपना मन बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
कांग्रेस नेताओं ने वामपंथी नेताओं को निजी तौर पर यह बात बताई।
'आप जो देख रहे हैं वह एक मौन व्यक्ति का क्रोध है,' एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
कांग्रेस मंत्री ने वामपंथी नेताओं को स्पष्टीकरण देते हुए यह बात कही।
मनमोहन सिंह ने 'इस्तीफा' को एक हथियार के रूप में कई बार इस्तेमाल किया था।
अतीत में कई बार। पहली बार ऐसा 1980 के दशक में हुआ था जब वह
वह योजना आयोग के अध्यक्ष थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने योजना आयोग के सदस्यों को 'जोकरों का झुंड' कहा था।
फिर, हर्षद के बाद उन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने की धमकी दी थी।
पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में मेहता घोटाला सामने आया था।
राव के शासनकाल के दौरान उन पर उर्वरक की कीमतों को कम करने का दबाव था।
शासन के दौरान, उन्होंने फिर से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने धमकी दी थी कि...
जब वामपंथियों ने भारत-अमेरिका सैन्य अभ्यासों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
नवंबर 2005। और, ज़ाहिर है, उन्होंने पहले ही एक बार इस्तीफा देने की धमकी दे दी थी।
परमाणु समझौते को लेकर।
अंततः मनमोहन सिंह ने सही चाल चली। सोनिया गांधी
उन्होंने उसे पद से न हटाने का फैसला किया। और फिर प्रधानमंत्री को जीवनदान मिल गया। उन्हें प्राप्त हुआ
वह संदेश जिसका वह इंतजार कर रहा था। 21 जून 2008 को, अमर सिंह
प्रधानमंत्री को हरी झंडी दे दी गई है—समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी
संसद में उनकी सरकार. पीएम के मीडिया सलाहकार संजय बारू
मुझे उस दिन अमेरिका से एक कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज आई...
फोन पर उसने बताया कि वह अमर सिंह का 'दोस्त' था। जो लोग अमर को जानते थे, सिंह का मानना था कि फोन करने वाला स्वयं अमर सिंह हो सकता था।
'मेरा दोस्त अमर सिंह कोलोराडो के एक अस्पताल में भर्ती है,' दोस्त ने बताया।

बारू। 'वह चाहता है कि आप प्रधानमंत्री को बताएं कि अमेरिकी डॉक्टर
वे बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना लोग हैं।' वे अच्छी देखभाल कर रहे थे।
उसने उनकी जमकर तारीफ की। 'दोस्त' ने पूछा
यह संदेश प्रधानमंत्री को 'जितनी जल्दी हो सके' पहुँचाया जाना चाहिए। शायद, वह
सुझाव दिया गया है कि प्रधानमंत्री अमर सिंह से बात करके उन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे।
'शीघ्र स्वस्थ हों'। बारू ने तुरंत प्रधानमंत्री को यह संदेश पहुंचाया।
उस विचित्र शब्दों वाले संदेश को प्रधानमंत्री ने इस अर्थ में डिकोड किया कि यह
यह (संसद द्वारा सरकार और परमाणु ऊर्जा को दिए गए समर्थन पर) एक 'अंतिम सहमति' थी।
अमर सिंह द्वारा सौदा।
दिल्ली में हलचल मच गई। कुछ ही दिनों में, लेख प्रकाशित होने लगे।
मीडिया में यह खबरें आने लगीं कि मुलायम सिंह यादव के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।
परमाणु समझौते के प्रति अपने विरोध पर करात ने दोबारा विचार किया।
उन्हें चिंता थी कि उनकी मुलाकात यादव से हुई, जो उनके भरोसेमंद सहयोगी रहे थे।
कई वर्षों से वामपंथी रहे। वे चाहते थे कि यादव वामपंथियों के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करें।
यादव ने करात से कहा, 'मैं किसी भी बात पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जता रहा हूं।'
टालमटोल करते हुए। 'जब तक अमर सिंह वापस नहीं आ जाता, मैं कुछ नहीं कह सकता।'
अमेरिका।' करात की मुलाकात यादव से 1 जुलाई 2008 को फिर हुई। जब अमर सिंह आया।
अमेरिका से लौटने के बाद, उन्होंने मीडिया को बताया कि स्थिति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत थी।
धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होना होगा। संकेत स्पष्ट थे। वह सपा और कांग्रेस के हाथ मिलाने की वकालत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि...
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम. के. नारायणन को कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है।
2 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) ने मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह से मुलाकात की।

उन्होंने उन्हें परमाणु समझौते के बारे में जानकारी दी। मुलायम सिंह यादव को एक रास्ता खोजना पड़ा।
अपने रुख में आए बदलाव को सही ठहराने के लिए प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास। 3 जुलाई को यादव ने एक बैठक बुलाई।
संयुक्त राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन (यूएनपीए) की संसदीय
एसपी जिस समूह का हिस्सा था, उसमें ऐसे सदस्य भी शामिल थे जो न तो समूह का हिस्सा थे और न ही उसके सदस्य थे।
न तो यूपीए और न ही एनडीए। उन्हें इस बारे में अंतिम निर्णय लेना था कि क्या करना है।
परमाणु समझौते का समर्थन करें या न करें। यूएनएलपी की बैठक के तुरंत बाद, मुलायम
सिंह यादव और अमर सिंह ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से मिलने के लिए तेजी से रवाना हुए।
पूर्व राष्ट्रपति, जिनकी राष्ट्रीय मामलों से संबंधित राय अभी भी सुनी जाती थी
सुरक्षा। कलाम को पहले ही सूचना दे दी गई थी। उन्होंने तुरंत एक आदेश जारी किया।
उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता अभी भी जारी है।
राष्ट्रीय हित। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से समर्थन देने का आग्रह किया।
सरकार।
पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल को आमंत्रित करने का विचार एम.के. नारायणन का था।
कांग्रेस नेता ने बताया कि कलाम समझौते के पक्ष में बयान जारी करेंगे।
जिससे मुलायम सिंह यादव के लिए समर्थन जुटाना आसान हो गया।
सरकार। यह एक दिखावा था जिसे एसपी ने पकड़ लिया। अमर के सभी लोगों के लिए
सिंह की समझाने-बुझाने की क्षमता को लेकर मुलायम सिंह यादव चिंतित थे।
इस समझौते के प्रति उनके समर्थन का उन मुसलमानों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है जो
इसने एसपी के आधार की रीढ़ की हड्डी का गठन किया। यह समझौता इसके पर्याय

के रूप में था।
भारत का अमेरिका के करीब आना और मुसलमान इस बात को लेकर आशंकित थे।
अब सब कुछ पहले से तय स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा था। उसी दिन बाद में, एम.के.
नारायणन की अमर सिंह से एक सुरक्षित अतिथि कक्ष में एक और मुलाकात हुई।
दिल्ली में आईबी का अड्डा। इस बार अमर सिंह के साथ थे...
मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई, राम गोपाल यादव, जो एक प्रोफेसर थे।
और वे कई और सवाल पूछना चाहते थे। नारायणन ने विस्तार से बताया।
उन्होंने उनसे समझौते के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मिलकर समझौता तैयार किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किया जाने वाला बयान
सपा सांसदों द्वारा मांगे गए आश्वासन।
नारायणन फिर साउथ ब्लॉक की ओर दौड़ा। वह जल्दी से अंदर चला गया।
संजय बारू के कमरे में जाकर उन्हें एक बयान सौंपा गया, जिसे पूरा करना था।
प्रधानमंत्री के शब्दों के साथ तत्काल मीडिया को जारी किया गया।
कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता नहीं करेगा, न ही
ईरान के साथ उसके संबंधों में गड़बड़ी पैदा करना। इन प्रतिज्ञाओं का उद्देश्य आश्वस्त करना था।
मुसलमानों के साथ सभी अधूरे कामों को पूरा करने के बाद, प्रधानमंत्री ने 7 जुलाई 2008 को अधिकारियों को मसौदा प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी।
आईएईए के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। यह उनके उड़ान भरने से ठीक पहले की बात है।
जापान जी8 की बैठक में भाग लेने वाला था, जहां उसे मुलाकात करनी थी।
बुश किनारे पर थे। 'मुझे इस (आईएईए) के बारे में प्रधानमंत्री की उड़ान में पता चला।'
पत्रकार मानिनी चटर्जी ने याद करते हुए कहा, 'जापान जाते समय मैंने उनसे कहा था।'
जॉयदीप सरकार (प्रधानमंत्री के सचिव) ने कहा कि वामपंथी दल अब
अपना समर्थन वापस ले लो।' ठीक यही हुआ। कुछ घंटों बाद,
8 जुलाई को चारों वामपंथी दलों ने घोषणा की कि वे अपना नाम वापस ले रहे हैं।

मनमोहन सिंह की सरकार को उनका समर्थन। तब तक सिंह
उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने वैकल्पिक सहायता की व्यवस्था कर रखी थी।
मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ने का फैसला किया, वहीं प्रणब
मुखर्जी ने घोषणा की कि सरकार केवल आईएईए के पास ही जाएगी।
संसद में अपना बहुमत साबित करने के बाद। लेकिन प्रधानमंत्री
वह 21 जुलाई को होने वाले विश्वास मत तक इंतजार करने के मूड में नहीं थे। भले ही वह ऐसा करते भी।
यदि वह बहुमत हासिल करने में सफल नहीं हो पाता, तो वह हमेशा यह तर्क दे सकता था कि वह गया था
जब उनकी सरकार के पास बहुमत था तब आईएईए! प्रणब
अंदरूनी सूत्रों का अनुमान है कि मुखर्जी को शायद उम्मीद थी कि किसी भी स्थिति में
विश्वास मत के दौरान अंतिम क्षण में अप्रत्याशित उलटफेर—जो वैसे भी अंततः
काफी करीब होने पर—एक नए अभाज्य संख्या की संभावना हो सकती है
मंत्री का नामांकन हो रहा है। सरकार गिर जाएगी।
इसका मतलब था कि सौदा विफल हो गया। अगर ऐसा हुआ होता, तो वामपंथी शायद...
यूपीए सरकार को एक और प्रधानमंत्री के साथ जारी रखा गया।
लेकिन वह इच्छा अधूरी ही रह गई। मनमोहन सिंह आगे बढ़ते रहे।
उसकी योजना के चलते, उसके चारों ओर अराजकता उठती और गिरती रही।
भाजपा ने अचानक समाजवादी पार्टी से संपर्क साधा और उसे प्रस्ताव दिया।
यदि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिए गए अपने समर्थन पर पुनर्विचार करे तो प्रधानमंत्री पद को नुकसान हो सकता है।
इसने कहा कि यह सिंह के यूपीए का समर्थन करने को तैयार है। इसने कहा कि यह यूएनपीए के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन करने को तैयार है।
सरकार। दूसरे शब्दों में, वे मुलायम सिंह यादव का समर्थन करेंगे।
प्रधानमंत्री। इस प्रयास का नेतृत्व एल. के. आडवाणी कर रहे थे।
परमाणु समझौते के प्रति उनके विरोध को देखते हुए, एसपी अपने रुख पर अडिग रही।
मनमोहन सिंह के समर्थन में।

अमर सिंह ने अपने कर्तव्य से कहीं बढ़कर काम किया। उन्होंने हर संभव प्रयास किया।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सपा सांसद सरकार के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी सपा सांसद सरकार के पक्ष में मतदान करें। भाजपा और आरएलडी के कुछ अन्य लोगों को भी अपने पक्ष में कर लिया। इस समय तक,
कांग्रेस के प्रबंधक हरकत में आ गए थे। अब यह सिर्फ इतना ही नहीं था कि...
प्रधानमंत्री की परियोजना। इसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरकार के अस्तित्व को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अहमद पटेल, बी.एस. हुडा, आर.के. धवन और सतीश शर्मा ने इस अभियान को संभाला।
2011 में लीक हुए विकीलीक्स के दस्तावेजों से पता चला कि भारी मात्रा में धन का दुरुपयोग हुआ था।
कई सांसदों को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए 10 करोड़ रुपये से लेकर इससे भी अधिक की रकम दी गई थी।
सरकार। सीपीआई नेता ए. बी. बर्धन ने एक सभा को संबोधित किया था।
विठ्ठलभाई पटेल हाउस स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लॉन, जो कुछ ही दूरी पर हैं।
संसद भवन से। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि 25 करोड़ रुपये का गबन किया जा रहा है।
सरकार का समर्थन करने के इच्छुक सांसदों को यह प्रस्ताव दिया गया। एक गुप्त ऑपरेशन में।
पत्रकार राजदीप सरदेसाई द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, भाजपा सांसद अंदर चले गए।
22 जुलाई को लोकसभा में, उन्हें दिए गए नोटों के बंडल लहराते हुए।
पक्ष बदल लिया। उस समय कहा गया था कि यह जाल बिछाने का विचार
राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली।
आरोपों के बावजूद, मनमोहन सिंह की सरकार
22 जुलाई को संसद में विश्वास प्रस्ताव जीत लिया गया। इसका चार साल का कार्यकाल
वामपंथियों के साथ उनका गठबंधन टूट चुका था। उन्हें समाजवादी पार्टी के रूप में

एक नया सहयोगी मिल गया था।
लेकिन मुलायम सिंह यादव ने सपा के लिए कुछ शर्तें रखी थीं।
समर्थन। पहला, उसके खिलाफ मामले—उस पर आरोप लगाते हुए
अपनी आय के अनुपात से अधिक धन अर्जित करना उचित नहीं होगा।
उनका पीछा नहीं किया गया था।
मुलायम सिंह यादव ने यह भी उम्मीद जताई थी कि सपा नेता
मंत्री पद दिए गए। मनमोहन सिंह के पद दिए जाने के अगले दिन सुबह।
विश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद मुलायम सिंह और अमर सिंह पहुंचे।
रेस कोर्स रोड पर 7 नंबर पर। उन्हें मुख्य दृश्य देखने के लिए अंदर ले जाया गया।
मंत्री। जब वे उसके कमरे से बाहर आए, तो दोनों स्पष्ट रूप से गुस्से में दिख रहे थे। 'मैं
मैं वहीं खड़ा था और मैंने उन्हें अपनी बड़ी सफेद गाड़ी में बैठते हुए देखा।
'मर्सिडीज,' संजय बारू ने याद किया। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि
सपा सदस्यों के लिए मंत्रिमंडल में पद संभव नहीं थे। सोनिया गांधी,
कहा जाता है कि उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। हालाँकि मनमोहन सिंह ने ऐसा किया था।
किसी तरह टिके रहने के बावजूद, परमाणु समझौता अभी भी पूरा होने से काफी दूर था।
एक वास्तविकता। प्रधानमंत्री ने इसे प्राथमिकता देना जारी रखा।
2008 के शेष महीनों में, यदि भारत जुलाई में आईएईए के पास नहीं जाता, तो
2008 में, सचिवालय के अध्यक्ष का पद परिवर्तन होना था। अगला
संगठन का नेतृत्व करने वाला देश—ऑस्ट्रिया को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी थी—
ऐसी उम्मीद थी कि भारतीय प्रस्ताव के प्रति इतनी सहानुभूति नहीं दिखाई जाएगी।
इससे भारत-विशिष्ट दस्तावेजों की मंजूरी में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती थीं।
सुरक्षा समझौता।

एक्स

वियना—अब सारा ध्यान यहीं केंद्रित हो गया।
ऑस्ट्रिया की शांतिपूर्ण राजधानी, पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई।
शहर के बीच से बहने वाली नीली डेन्यूब नदी के साथ, कि पिछले दो
मैराथन दौड़ की बाधाओं को पार करना होगा—इससे पहले...

जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते को अमेरिका ले गए थे।
कांग्रेस को इसकी मंजूरी मिल जाएगी। भारत-विशिष्ट सुरक्षा समझौता
जिसे आईएईए द्वारा मंजूरी दी जानी थी, वह इनमें से पहला था—और यह था
बिना किसी कठिनाई के बातचीत पूरी हुई। भारत में काम कर रहे कारकों में से एक।
सबसे महत्वपूर्ण कृपा मोहम्मद अलबरादेई की थी। मिस्र के-
एल बारादेई, जिनका जन्म भारत में हुआ था, आईएईए सचिवालय के प्रमुख थे और भारत के मित्र थे।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकियों ने उन्हें इसकी आवश्यकता के बारे में आश्वस्त कर दिया था।
भारत के लिए बिना किसी शर्त के छूट प्राप्त करने हेतु। आईएईए सचिवालय ने इस पर कार्रवाई की।
कागजी कार्रवाई। दस्तावेजों को आईएईए बोर्ड को भेज दिया गया।
राज्यपालों से अनुमोदन के लिए। एल बारादेई ने सुनिश्चित किया था कि सब कुछ ठीक है।
आईएईए ने 1 अगस्त 2008 को आईएसएसए को मंजूरी दे दी।
इसके बाद यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा आया—वह छूट जो...
भारत को पैंतालीस सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता संघ द्वारा दी जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
इससे समूह को नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन खरीदने में मदद मिलेगी।
अन्य देश, परमाणु हथियार रखने के बावजूद और हस्ताक्षर न करने के बावजूद
परमाणु अप्रसार संधि। यदि एनएसजी छूट प्रदान करता है, तो यह होगा
ऐसा पहली बार हुआ था। हालाँकि अमेरिकी इसमें सहायता कर रहे थे।
भारत के लिए यह यात्रा, उन्हें जल्द ही एहसास हो गया, कि अंतिम चरण भी
यह आसान नहीं होने वाला है। उन्हें शुरुआत से ही समस्याओं का सामना करना पड़ा।
भारत के लिए छूट हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय राष्ट्रीय सभा की बैठक 21 तारीख को हुई थी।
और 22 अगस्त। लेकिन गतिरोध उत्पन्न हो गया। छोटा यूरोपीय
देशों ने खुद को 'अप्रसार के अयातुल्लाह' के रूप में देखा।
छूट में कुछ शर्तें जोड़ना चाहते थे, जैसे ईंधन की आपूर्ति बंद करना।

और प्रौद्योगिकी आपूर्ति, यदि भारत फिर से परमाणु परीक्षण करता है।
एनएसजी की एक और बैठक 5 सितंबर 2008 को निर्धारित की गई थी।
यह बैठक वियना में जर्मन मिशन में जर्मनी के साथ हुई।
अध्यक्ष। अमेरिकियों ने छूट के लिए अपना दूसरा मसौदा प्रस्तुत किया।
वियना इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में तनाव बढ़ता गया जहाँ
भारतीय प्रतिनिधिमंडल वहाँ ठहरा हुआ था। प्रतिनिधिमंडल की बैठक वहीं होनी थी।
वे दिन के समय भारतीय दूतावास में ठहरते थे। रात में वे होटल चले जाते थे।
जहां उनके लिए सुविधाएं और सम्मेलन कक्ष तैयार किए गए थे।
दूर से हो रही चर्चाओं का अनुसरण करें। भारत एनएसजी बैठक में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि यह एक राष्ट्रीय नागरिक अधिकार क्षेत्र (एनएसजी) बैठक नहीं थी।
सदस्य।
जैसे-जैसे उस शाम परछाइयाँ लंबी होती गईं, विदेश सचिव शिव
शंकर मेनन होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में इधर-उधर चहलकदमी कर रहे थे।
कभी-कभी वह अपने मंत्री प्रणब से फोन पर बात करने के लिए बाहर चले जाते थे।
मुखर्जी, नई दिल्ली में। अन्य समय में, वह बात कर रहे होते थे।
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य। वे एनएसजी के अंदर थे।
उन लोगों से मिलना, उन्हें धक्का देना, उकसाना और उन पर दबाव डालना जो सत्ता में थे।
बाहर।
दिल्ली में प्रधानमंत्री घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे थे।
बैठक आगे बढ़ने के साथ-साथ भारतीय पर्यवेक्षकों ने चीन पर सतर्क नजर रखी।
उसने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था। चीन ने पहले ही आपत्ति जताई थी।
भारत को परमाणु हथियार संपन्न देशों के बराबर दर्जा प्राप्त करने के बिना
एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के बाद। अब वे कंधों से गोली चला रहे थे।
'ग्रुप ऑफ सिक्स', यानी सामने आने के बजाय। ये टीमें थीं: आयरलैंड, न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और नीदरलैंड।
अब तक चीनी उम्मीद कर रहे थे कि यह समझौता नहीं होगा।
भारत में मौजूद आरक्षणों को देखते हुए, सोनिया के साथ

गांधी और वामपंथियों ने इसका विरोध किया।
अक्टूबर 2007 में, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह योजना बनाई थी।
बीजिंग में सोनिया गांधी के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया था। उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।
राहुल गांधी, करण सिंह और आनंद से मिलकर बनी कांग्रेस पार्टी
शर्मा और पृथ्वीराज चव्हाण—जिसके जवाब में वे एक पक्षकार थे—
चीनियों द्वारा पार्टी का निमंत्रण। मनमोहन सिंह इससे नाखुश थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री चव्हाण को शामिल करने के लिए उनकी अनुमति नहीं ली गई थी।
प्रतिनिधिमंडल में चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ ने भाग लिया।
प्रतिनिधिमंडल और उनके साथ पचास कारों का काफिला हर जगह जाता था।
वे चले गए। शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें आयोजित की गईं—साथ ही
इक्कीस कोर्स के भोज और दर्शनीय स्थलों की यात्राओं सहित,
शियान की यात्रा, जहाँ टेराकोटा सेना खड़ी है। एक विशेष राजकीय विमान।
उन्होंने उन्हें यात्रा कार्यक्रम के विभिन्न स्थानों पर हवाई यात्रा करवाई। चीनियों ने तो यहाँ तक कि
यात्रा पर बनी आधे घंटे की फिल्म। 'इसे राजकीय यात्रा के समान ही महत्व दिया गया,'
उन सदस्यों में से एक जो गए थे।
चीनी पक्ष पिछले एक दशक से भारतीय पक्ष को मनाने की कोशिश कर रहा था।
वर्ष के दौरान—वे इस सौदे के विरोध को और मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे।
कांग्रेस। वे वामपंथी दलों पर भी काम कर रहे थे, यह जानते हुए कि
भारत-अमेरिका समझौते को लेकर उनकी 'बुनियादी चिंताओं' पर विचार किया गया।
लेकिन एक साल बाद, 2008 में, सोनिया गांधी ने समझौते का विरोध करना बंद कर दिया और वामपंथी दल ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया।
अब यह कोई मायने नहीं रखता था। चीन के पास खेलने के लिए बस यही एक दांव बचा था।
वियना का उद्देश्य किसी तरह एनएसजी से भारत को मिलने वाली 'पूरी तरह से छूट'

को टालना था।
5 सितंबर 2008 की रात जैसे-जैसे बीतती गई, भारतीय राजदूत
ऑस्ट्रिया जाने वाले इक्कीस लोगों ने दूतावास में बिरयानी बनवाई और पैक करवाई।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल को पार्सल भेजे गए जो वहाँ तैनात थे।
वियना अंतरमहाद्वीपीय हवाई अड्डा। धीरे-धीरे अमेरिकियों ने देशों पर कब्जा जमा लिया।
छूट का विरोध करने वालों को एक-एक करके मना लिया।
जो लोग झुक गए वे अपनी नीतियों को जारी रखने के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर थे।
बहुत लंबे समय तक विरोध चलता रहा। अंत में केवल चीनी ही अकेले खड़े रह गए।
रात। उन्होंने बातचीत से पीछे हटने की धमकी दी थी।
इसका मतलब सौदे का अंत होता, क्योंकि एनएसजी ऐसे फैसले लेती थी
सर्वसम्मति।
मनमोहन सिंह ने बुश से बढ़ती हुई समस्या के बारे में बात की थी—लेकिन
पर्दे के पीछे—चीन के खिलाफ बढ़ता विरोध।
बुश ने उन्हें सलाह दी, 'आपको हू जिंताओ से सीधे बात करनी चाहिए।' सिंह
उन्होंने अपने कार्यालय से चीनी अधिकारियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की व्यवस्था करने को कहा।
राष्ट्रपति से सहयोग का अनुरोध करने के लिए। चीनी पक्ष का रवैया इस मामले में 'उदासीन' था।
विचार आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बार फिर कोशिश की। फिर भी, बात नहीं बनी। कुछ
कुछ महीने पहले, चीनी अधिक लचीले प्रतीत हो रहे थे, 'वापस
जुलाई 2008 में, चीनियों ने मुझे बताया था—मैं वहाँ गया था—कि हम नहीं होंगे
अगर बाकी लोग पीछे हट जाते हैं, तो जो लोग अंत तक (छूट के खिलाफ) खड़े रहेंगे, वही टिके रहेंगे।
Shivshankar Menon revealed.
उस दिन, 5 सितंबर को, प्रणब मुखर्जी ने अपने
बीजिंग में समकक्ष। चीनी टालमटोल करते रहे। अंततः, देर से ही सही।

रात में, प्रधानमंत्री ने अपनी कठिनाई के बारे में राष्ट्रपति बुश से फिर बात की।
सूत्रों ने मुझे बताया कि बुश ने फिर हू जिंताओ को व्यक्तिगत रूप से फोन किया।
परिणाम को लेकर अनिश्चितता बनी रही। दिल्ली में, प्रमुख
मंत्री जी रेस कोर्स रोड पर रात 3 बजे तक जागते रहे। वियना में आधी रात को,
एक बार फिर मुकाबला आखिरी क्षण तक खिंचता चला गया। यह एक लंबी रात होने वाली थी।
इसके बाद अमेरिकियों ने सुझाव दिया कि भारतीय विदेश मंत्री
भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बारे में एनएसजी को आश्वस्त करने के लिए एक बयान दें।
परीक्षण। इससे विरोध के अंतिम अवशेष भी मिट जाएंगे। प्रणब
मुखर्जी ने एक बयान जारी किया। उन्होंने भारत की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता को दोहराया।
परीक्षण पर रोक। भारत ने इसकी घोषणा इसके तुरंत बाद की थी।
भारत ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। लेकिन इस बार मुखर्जी के बयान से भारत
वह वैश्विक समुदाय के समक्ष यह प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा था।
सुबह 3 बजे—अब 6 सितंबर की सुबह के शुरुआती घंटे थे—विदेश मंत्रालय ने
उन्होंने दबाव बढ़ाने का फैसला किया और चीनी राजदूत को जगा दिया।
दिल्ली। भारत का संदेश अब बिल्कुल स्पष्ट था: यदि चीन ने सहयोग नहीं किया तो
और अकेले खड़े होकर उन्होंने कहा, 'इससे भारत-चीन के समग्र संबंधों पर असर पड़ेगा।'
6 सितंबर की सुबह तड़के, विदेशी अखबारों में फोन की घंटी बजी।
वियना स्थित सचिव शिवशंकर मेनन का कमरा। वे अभी भी सो रहे थे।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल तड़के ही सो गया था। तभी फोन आया।
वियना स्थित चीनी दूतावास से। 'हमने आपका समर्थन करने का निर्णय लिया है।'
उन्होंने कहा। चीनी पक्ष ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिससे आम सहमति बन सकी।
प्रबल होने के लिए। कुछ घंटों बाद, 6 सितंबर को, निर्णय की घोषणा हो गई।
एनएसजी की बैठक में मेज पर रखी मेज। इसकी जोरदार आवाज ने एनएसजी की औपचारिक शुरुआत का संकेत दिया।

भारत के लिए छूट को 6 सितंबर 2008 को अपनाया गया।
मेनन का फोन फिर बजा। यह अमेरिकी नेता का फोन था।
एनएसजी प्रतिनिधिमंडल के जॉन रूड ने कहा, 'बधाई हो।' 'हमारे पास है
कर दिया।'
शिवशंकर मेनन ने जोर देकर कहा, 'यह एक साफ माफीनामा था, इसमें कोई गलती नहीं थी।'
इसमें चेतावनी या समीक्षा प्रदान की गई है।
हालांकि, मेनन के दावे के बावजूद, छूट पूरी तरह से लागू नहीं हुई थी।
जैसा कि कुछ लोगों ने बाद में बताया, 'साफ' होने के बावजूद, इसमें प्रतिबंध बरकरार रखे गए थे।
संवेदनशील प्रौद्योगिकियों का निर्यात। नागरिक सुरक्षा पर राष्ट्रीय महासचिव का वक्तव्य।
भारत के साथ परमाणु सहयोग के लिए पूर्ण सुरक्षा उपायों को माफ कर दिया गया।
पैरा 4 में आवश्यक है, और प्रौद्योगिकियों के निर्यात की स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है।
और उपकरण, लेकिन 'पैरा 6 और 7 के अधीन'। इन दो पैरा के तहत,
आपूर्तिकर्ताओं से इन वस्तुओं के हस्तांतरण में 'संयम बरतने' का अनुरोध किया गया था।
संवेदनशील ईएनआर (यूरेनियम संवर्धन और प्रयुक्त ईंधन का पुनर्संसाधन)
प्रौद्योगिकी और उपकरण। भारत ने इसे अपने तरीके से व्याख्यायित करना चुना।
मेनन ने कहा कि ईएनआर के हस्तांतरण के बारे में पाठ अस्पष्ट था।
प्रौद्योगिकियों की बात की, और 'इसमें कुछ भी शामिल या बहिष्कृत नहीं किया गया'।
अनिल काकोडकर के अनुसार, अलग-अलग देशों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वे
ईएनआर तकनीक के हस्तांतरण पर निर्णय लें। 'ऐसे बहुत कम लोग हैं।
विभिन्न देशों के बीच ईएनआर प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के उदाहरण।
काकोडकर ने कहा, 'प्रत्येक देश अपने मुद्दे का फैसला खुद करेगा और कार्रवाई करेगा।'
अपने-अपने कानूनों के अनुसार। हमने प्रत्येक देश के साथ अलग-अलग बातचीत

की।'
भारत ने अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ समझौते किए।
समय भारत के पक्ष में रहा, क्योंकि जून 2011 में एनएसजी को अपने दिशा-निर्देशों को 'मजबूत' करना था और ईएनआर प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को अनिवार्य बनाना था।
यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समझौते (एनपीटी) पर हस्ताक्षर होने पर निर्भर है।
एनएसजी छूट और भारत-विशिष्ट आईएईए सुरक्षा उपायों के साथ
वह स्थान, जो अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 123वें विधेयक पर विचार करने के लिए आवश्यक शर्तें थीं।
समझौते पर विचार किया जा रहा था, अब अंतिम चरण के लिए मंच तैयार था।
नाटक।
■

मनमोहन सिंह अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे—क्योंकि ध्यान अब इस ओर केंद्रित हो गया था
अमेरिकी कांग्रेस जिसे 123 समझौते की पुष्टि करनी थी। प्रधानमंत्री
मतदान से ठीक पहले के उन महत्वपूर्ण दिनों में अमेरिका में रहना चाहता था।
प्रतिनिधि सभा और सीनेट। यह अंत तक होना था।
सितंबर। कुछ अधूरे काम पूरे करने थे। मनमोहन सिंह के पास
उन्होंने अपने 'रेस हॉर्स' को जुटाया। इसके अलावा अन्य समूह भी काम कर रहे थे।
भारत-अमेरिका की मित्रता और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए।
अन्य देश इस समझौते को पारित कराने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। भारतीय पक्ष के अलावा अन्य देश भी इसमें शामिल हैं।
अमेरिका स्थित दूतावास में रहते हुए अमर सिंह अपने मित्र के साथ लगातार संपर्क में थे।
संत सिंह चटवाल, जो डेमोक्रेट्स के साथ पैरवी कर रहे थे।
मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले थे।
27 सितंबर 2008 को न्यूयॉर्क में विधानसभा में। वह और राष्ट्रपति जॉर्ज

डब्ल्यू. बुश को उम्मीद थी कि डॉ. सिंह के अमेरिका में रहने के दौरान परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।
लेकिन बुश की व्यस्तता के कारण समय सारिणी कुछ दिनों के लिए गड़बड़ा गई।
हाल ही में घटी वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के साथ।
फिर भी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय निकाला।
मंत्री।
25 सितंबर को बुश और सिंह की मुलाकात ओवल ऑफिस में हुई।
शाम को उन्होंने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर हुई प्रगति का जायजा लिया।
सौदा हो गया था। हालांकि काफी काम हो चुका था और मामला अंतिम चरण तक पहुंच गया था।
यह अभी शुरुआती चरण में था, लेकिन इसे अभी अमेरिकी कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से पारित किया जाना बाकी था। नेताओं
रणनीतिक संबंध बनाने में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका से वे प्रसन्न थे।
दोनों देशों के बीच साझेदारी।
बुश ने सिंह से कहा, 'इसमें हम दोनों की ओर से काफी मेहनत लगी है।'
‘और आपकी ओर से बहुत साहस की आवश्यकता है।’ मनमोहन सिंह ने अपनी ओर से कहा।
उन्होंने हुए 'विशाल' परिवर्तन पर संतोष व्यक्त किया।
उनके साढ़े चार साल के कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों में उनकी भूमिका

प्रधानमंत्रित्व काल। उन्होंने राष्ट्रपति बुश की 'सबसे' महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा की।
'महत्वपूर्ण भूमिका'। उन्होंने कहा कि 'इतिहास' इसे 'दर्ज' करेगा।
बैठक के बाद ओल्ड फैमिली डाइनिंग में रात्रिभोज का आयोजन किया गया।
व्हाइट हाउस में बुश द्वारा आयोजित कमरा। इसे 'पारिवारिक' कार्यक्रम के रूप में प्रचारित किया गया था।
इस कार्यक्रम में बुश के अलावा दस अन्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम में शामिल अमेरिकी नागरिक बुश के अलावा दस अन्य लोगों से मिले।

रात्रिभोज में मेजबान के अलावा उपराष्ट्रपति डिक चेनी भी उपस्थित थे।
विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्टीव हेडली और उप मंत्री
विदेश मंत्री विल बर्न्स। मनमोहन सिंह के अलावा, भारतीय
इस पक्ष में विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी और विदेश मामलों के मंत्री शामिल थे।
सचिव शिवशंकर मेनन, श्याम सरन- जो अब प्रधान थे
भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के लिए मंत्री के विशेष दूत - मोंटेक सिंह
अहलुवालिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम. के. नारायणन।
मनमोहन सिंह ने उन्हें मेजबानी देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया।
अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझने के बावजूद।
बुश ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, 'यह जानकर खुशी हुई।' और फिर उन्होंने आगे कहा,
'आप एक
'मुझ पर शांत प्रभाव पड़ा।' डिनर के दौरान एक समय कोंडोलीज़ा ने कहा।
राइस ने मनमोहन सिंह की ओर मुड़कर कहा, 'श्रीमान प्रधानमंत्री, हम'
मैंने इस सौदे को पूरा करवाने के लिए (आपके लिए) काफी मेहनत की है...
आशा है कि भारत अपनी प्रतिबद्धता पूरी करेगा और परमाणु ऊर्जा खरीदेगा।
अमेरिका से रिएक्टर...' इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, बुश
उसने बात काटते हुए कहा, 'मुझे परवाह नहीं कि हम रिएक्टर बेचें या नहीं। यह मेरे बस की बात नहीं है।'
रिएक्टरों की बिक्री। यह हमारे दोनों के बीच संबंधों के बारे में है।
देश।'
रात के खाने के अंत में, बुश व्हाइट हाउस के बरामदे में आए।
प्रधानमंत्री को विदाई देने के लिए लोग घर पर जमा हुए थे। वहां सभी गाड़ियां कतार में खड़ी थीं।
चलने के लिए तैयार और प्रतीक्षारत। प्रधानमंत्री पहले से ही बैठे हुए थे।
श्याम सरन ने याद करते हुए कहा, 'उसकी कार थी। मैं अपनी कार की ओर भागा। अचानक,'
राष्ट्रपति बुश ने मुझे कंधे से पकड़ लिया। उन्होंने कहा, "यह आदमी मेरा है।"
दोस्त, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी।

27 सितंबर 2008 को हुए समझौते को अमेरिकी सीनेट ने 1 अक्टूबर को मंजूरी दे दी।
2008 में, अमेरिका द्वारा परमाणु व्यापार पर तीन दशक से लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया।
भारत। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए।
अमेरिका-भारत परमाणु सहयोग अनुमोदन और अप्रसार
8 अक्टूबर 2008 को संवर्द्धन अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम पर हस्ताक्षर करते हुए बुश ने कहा, 'यह
यह एक बड़ी बात है।'
10 अक्टूबर 2008 को प्रणब मुखर्जी और कोंडोलीज़ा राइस
बेंजामिन ने दोनों देशों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अमेरिकी विदेश विभाग का फ्रैंकलिन कक्ष। भारत में सुबह के 1:40 बज रहे थे।
जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत के साथ उत्पन्न रणनीतिक साझेदारी को देखा।
मनमोहन सिंह ने नागरिक परमाणु समझौते को अपनी विरासत का हिस्सा माना।
इस सौदे को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताया।
मंत्री।
ग्यारहवीं

2009 के चुनावों में, कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आई।
बहुमत में वृद्धि। 'काम करने के अधिकार' को सुनिश्चित करना और ऋण माफी।
75,000 करोड़ रुपये के किसानों ने इसे विरोधी लहरों को मात देने में मदद की थी।
सत्ताधारी दल ने सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा। उसे 206 सीटें मिलीं।
लोकसभा में 2004 की तुलना में 61 सीटें अधिक हो गईं। भारत-अमेरिका परमाणु समझौता।
यह सौदा चुनावों में ऐसा मुद्दा नहीं था जिसने मतदाताओं को आकर्षित किया हो।
इसे समझा गया—या इसकी परवाह की गई। लेकिन शहरी भारतीयों ने इस तरीके को पसंद किया।
जिसमें इसने भारत को अमेरिका के करीब ला दिया था, जो एक गंतव्य था।

कई भारतीयों के लिए। मनमोहन सिंह, जो आगे चलकर राष्ट्रपति बनेंगे।
यूपीए के लिए पांच और वर्षों तक उनका कार्यकाल रहा और जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसके लिए उनकी प्रशंसा की गई।
उन्होंने दृढ़तापूर्वक सौदे को आगे बढ़ाया। वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने का उनका तरीका।
2007-09 की स्थिति और 2004 के बाद से अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि के कारण
उन मध्यमवर्गीय भारतीयों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है।
चुनावी निहितार्थों को छोड़ दें तो, भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता समाप्त हो गया।
भारत को तीस वर्षों तक जिस 'परमाणु रंगभेद' का सामना करना पड़ा था।
वैश्विक स्तर पर परमाणु व्यापार पर प्रतिबंध ही नहीं थे, बल्कि
साथ ही 'तकनीकी रंगभेद' भी जो एक तरह से स्थापित हो गया था
प्रतिबंधों का परिणाम। इस समझौते ने भारत को ईंधन, रिएक्टर आदि खरीदने में सक्षम बनाया।
अन्य देशों से उपकरण और प्रौद्योगिकी की कमी थी।
देश में यूरेनियम का भंडार और कई परमाणु रिएक्टर थे।
40-55 प्रतिशत क्षमता पर चल रहा है। परमाणु व्यापार का खुलना।
इससे भारत को अपने प्रत्येक नागरिक रिएक्टर के लिए यूरेनियम का भंडार करने में मदद मिली।
उन्हें आईएईए की सुरक्षा व्यवस्था के तहत रखा गया था। समझौते के बाद, भारत को
रूस, कनाडा, कजाकिस्तान और अन्य देशों से यूरेनियम खरीदने में सक्षम।
देशों। वैज्ञानिकों के अनुसार, इससे स्थिति और बिगड़ गई है।
भारत के नागरिक और रणनीतिक दोनों प्रकार के परमाणु कार्यक्रमों के लिए यह सुविधाजनक है।
2008 से भारत ने रूस से चार परमाणु रिएक्टर भी हासिल किए हैं।

व्हाइट हाउस में आयोजित रात्रिभोज में कोंडोलीज़ा राइस की अपील के बावजूद
2008 में भारत ने अमेरिका से कोई भी परमाणु रिएक्टर नहीं खरीदा था।

आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उनकी कीमतें पर्याप्त रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं थीं, लेकिन साथ ही
क्योंकि अमेरिकी कंपनियों को परमाणु नागरिक दायित्व कानून पारित करने में कठिनाई हुई
भारत बहुत ही 'कठोर' साबित हुआ; इसने दायित्व का भार दूसरों पर डाल दिया।
परमाणु ऊर्जा बेचने वाली कंपनियां। इस सौदे में एक स्पष्ट लाभ भी था।
भारत के अन्य संबंधों पर प्रभाव। इसने यह दावा करने में कामयाबी हासिल की थी कि यह
विशेष और इस प्रकार परमाणु अप्रसार व्यवस्था को अपने पक्ष में बदल दें। अन्य
देशों ने भारत को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। भारत को एक
वास्तव में परमाणु हथियार संकटग्रस्त देश (NWS), भले ही उसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।
जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत को एक प्रतिसंतुलनकारी शक्ति के रूप में देखते थे।
एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की भूमिका। भारत के साथ यह धारणा बनी हुई है।
चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद (जिसे इस नाम से भी जाना जाता है) का हिस्सा बन गया
क्वाड (संयुक्त राष्ट्र संघ), जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य देशों के बीच एक रणनीतिक 'समूह' है।
भारत में इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इसने कई राजनयिक और सैन्य गतिविधियों में भाग लिया।
चीन द्वारा अपनी सैन्य शक्ति का बढ़ता दावा करने और
क्षेत्र की आर्थिक शक्ति और भारत की सीमाओं पर इसकी आक्रामकता।
मनमोहन सिंह की सरकार अब तक की सभी सरकारों से बिल्कुल अलग थी।
पहले या बाद में। कोई भी पूर्णकालिक, बल्कि दो कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था।
वह चारों ओर से घिरे हुए थे। सोनिया गांधी राजनीतिक निर्णय लेती थीं और
प्रमुख नीतिगत पहलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रधानमंत्री ने प्रणब मुखर्जी को यह जिम्मेदारी दी।

सरकार में एक और शक्तिशाली व्यक्ति, अधिकांश कामकाज संभालता था।
प्रशासन कई प्रमुख निर्णय लेने वाले निकायों के माध्यम से संचालित होता है, जैसे कि
जीओएम। परिणामस्वरूप, मनमोहन सिंह का अधिकार बुरी तरह प्रभावित हुआ।
काम सीमित कर दिया गया था, और उन्होंने प्रतिबंधों के तहत काम किया।
क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका को और अधिक मुखर कर सकते थे?
मंत्री पद पर रहते हुए भी, जबकि उन्हें यह पद सोनिया गांधी की बदौलत मिला था।
और उस गठबंधन के मॉडल के बारे में क्या जिसमें उनके साथ सत्ता साझा करने की बात कही गई थी?
सोनिया को उसकी उतनी ही जरूरत थी जितनी उसे सोनिया की।
लेकिन यह उनका व्यक्तित्व नहीं था। वे एक तेजतर्रार योद्धा बनना पसंद करते थे।
तूफान आने पर झुकने वाली घास, पेड़ की तरह नहीं।
सीधा खड़ा होता है और गिर जाता है। इसीलिए वह दस साल तक टिका रहा। लेकिन
इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री के अधिकार को करारा झटका लगा—और
हालांकि वे ईमानदार और सच्चे थे, फिर भी उन्हें कमजोर प्रधानमंत्रियों में गिना जाता था।
भारत में मंत्री रहे हैं। फिर भी, संसाधनशीलता, दृढ़ता और
भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने में मनमोहन सिंह द्वारा प्रदर्शित दृढ़ संकल्प ने उनके व्यक्तित्व का एक नया पहलू उजागर किया।
इस सौदे को पूरा होने में तीन साल लगे, उन्होंने कुछ लक्षण और राजनीतिक योग्यताएं प्रदर्शित कीं।
उनमें ऐसी बुद्धिमत्ता थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने दुर्जेय चुनौतियों का सामना किया।
राजनीतिक क्षेत्र में मौजूद सभी विरोधियों को पछाड़कर, उन्हें मात देने में कामयाब रहे।
या उन्हें अपने पक्ष में कर लेना। उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया, अपनी जान जोखिम में डाली।
सरकार खतरे में थी, ऐसे में राजनीतिक समझ का प्रदर्शन हुआ।

भारत में प्रचलित प्रणाली में भू-राजनीति और विदेश नीति का गहन ज्ञान प्रदर्शित किया।
नीतिगत नीति—और यह प्रदर्शित किया कि वह अपनी बात मनवा सकता है। यह कम आंका गया
प्रधानमंत्री ने अप्रत्याशित जीत हासिल कर ली। और उन्होंने
उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति—अमेरिकी राष्ट्रपति—का समर्थन प्राप्त था।
जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अगर बुश और मनमोहन सिंह नहीं होते तो...
इस घटनाक्रम के मुख्य किरदारों को देखते हुए, भारत-अमेरिका समझौते का शायद कोई खास असर नहीं हुआ होता।
सफल समापन।
भारत-अमेरिका परमाणु समझौता केवल स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में ही नहीं था।
भारत में ऊर्जा के बारे में। या फिर भारत द्वारा शुरू की गई रणनीतिक साझेदारी के बारे में भी।
बदलती वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करना।
क्षितिज पर उभरता हुआ चीन। यह सब कुछ था। लेकिन एक अमूर्त स्तर पर।
इस स्तर पर, यह कुछ और भी था—यह प्रधान मंत्री द्वारा एक घोषणा थी।
मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वह अपने फैसले खुद ले सकते हैं।

उपसंहार

अगर किसी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी की तुलना की जा सकती है, तो वह हैं...
जवाहरलाल नेहरू', करण सिंह, जिन्होंने सभी प्रमुख हस्तियों के साथ काम किया है।
भारत के मंत्रियों ने मुझे बताया। '(मुझे संदेह है) वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा लेकिन वह
मैं नेहरू जैसा बनना चाहता हूं और उनसे भी आगे निकलना चाहता हूं।'
डॉ. सिंह के बयान पर मोदी और उनके समर्थक कैसे प्रतिक्रिया देंगे?
यह अनुमान लगाना किसी के लिए भी संभव है। क्योंकि अगर भाजपा और

आरएसएस नेहरू को नीचा दिखाने में माहिर है।
और फिर भी, उनकी परस्पर विरोधी दृष्टियों में निहित सभी मतभेदों के बावजूद,
उनकी लोकप्रियता और उनके प्रभाव में समानताएं हैं।
प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में क्षण भर के लिए देखी गई समानता
दिल्ली में स्थित तीन मूर्ति भवन, मोदी के दिल के बेहद करीब की परियोजना है। यह बेहद आकर्षक है।
प्रवेश द्वार के ऊपर दीवार पर अगल-बगल दो तस्वीरें मिलीं।
स्वागत समारोह: नेहरू और मोदी।
जैसा कि मैंने प्रस्तावना में उल्लेख किया है, मैंने हित में निर्णय लिया है
निष्पक्षता और सटीकता के लिए, इसमें मौजूदा प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
पुस्तक। एक तो, उनका कार्यकाल अभी प्रगति पर है क्योंकि वे तीसरी पुस्तक की ओर काम कर रहे हैं।
कार्यकाल। और, दूसरा, अन्य प्रधानमंत्रियों के विपरीत, क्या होता
मोदी के साथ जो कमी रह गई होती, वह होती दूरदर्शिता की शक्ति।
एक प्रमुख संस्था के आंतरिक कामकाज को उजागर करने के लिए पत्रकार का एकमात्र मार्गदर्शक।
मंत्री का कार्यकाल और प्रधानमंत्री कार्यालय।
साथ ही, इस पुस्तक में इसके बारे में एक शब्द कहे बिना यह अधूरी रहेगी।
भारत के चौदहवें और संभवतः सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री—देखे गए
अपने पूर्ववर्तियों के संदर्भ में। किस प्रधानमंत्री के किस पहलू के बारे में?
क्या मोदी से तुलना करके उन्हें एक अटूट कड़ी का हिस्सा बनाया जा सकता है? और क्या
ये वो क्षेत्र हैं जिनमें मोदी अपने आप में एक अलग व्यक्ति हैं, अकेले और अद्वितीय, लगभग
अपनी तरह का?
वैचारिक रूप से नेहरू और मोदी एक दूसरे से बिलकुल विपरीत हैं। मोदी पूरी तरह से वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं।
आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करना चाहता है और इसके मूल एजेंडे को पूरा

करना चाहता है, इसे और बेहतर बनाना चाहता है।
संविधान के दायरे में एक 'सभ्यतागत राज्य', एक हिंदू राष्ट्र की संरचना। नेहरू, अपने वामपंथी और उदारवादी विचारों के साथ,
अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया।
विभाजन के बाद का स्वतंत्र भारत।
विद्वान, बुद्धिमान, कुलीन, हैरो-कैम्ब्रिज से शिक्षित
नेहरू का पालन-पोषण आलीशान आनंद भवन में विलासितापूर्ण वातावरण में हुआ था।
इलाहाबाद, जो स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। उनकी अपील का आधार यही था।
एक सुंदर, राजकुमार जैसी आकृति अपने सुख-सुविधाओं को त्यागने का निर्णय लेती है।
स्वतंत्रता संग्राम के उतार-चढ़ाव।
दूसरी ओर मोदी हैं, जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने समर्थकों की मदद की।
जब वह बच्चा था तब उसके पिता वड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे।
2014 में प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद, भारत का लोकतंत्र विकसित हो चुका था और
सत्ता का हस्तांतरण हुआ—और मोदी की लोकप्रियता उनकी साधारण शुरुआत और उनके उत्थान में निहित थी।
सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए पदक्रम में तरक्की करना।
मोदी के पास अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री कार्यालय रहा है।
नेहरू का प्रधानमंत्री कार्यालय शक्तिशाली नहीं था; केवल एक संयुक्त सचिव ही इसके प्रमुख थे। और, चूंकि
जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, नेहरू ने अपने मंत्रियों और शक्तिशाली व्यक्तियों के माध्यम से शासन किया।
अपने-अपने अधिकार से, जो स्वतंत्रता आंदोलन से गुजरे हैं,
हालांकि करिश्माई नेहरू ने अपने दम पर चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वे अपने दम पर चुनाव जीतने में सक्षम थे।

उन्होंने अपनी पार्टी के लिए चुनाव जीता। मोदी सरकार में कई मंत्री हैं,
हालांकि, वे अपने चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री पर निर्भर थे।
और उन्होंने उसे जगह सौंप दी। अक्सर, उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सूचित किया जाता था।
उन्हें क्या निर्णय लेने चाहिए।
नेहरू और मोदी दोनों के ही जनसमर्थक थे, जिनमें से एक कश्मीरी था।
पंडित, जिसका परिवार उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पलायन कर गया था,
वह नेहरू परिवार की कर्मभूमि बन गई। और दूसरी एक तेल कंपनी से थी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी घांची परिवार का जिक्र है—जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में से एक है।
गुजरात में कक्षाएं। मोदी ने उत्तर प्रदेश को अपना चुनावी अखाड़ा भी बनाया।
और वास्तव में यूपी ही वह वजह थी जिसने उन्हें 2014 और 2019 में सत्ता तक पहुंचाया।
नेहरू और मोदी दोनों के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।
1950 और 1960 के दशक में, यह गुटनिरपेक्ष तीसरे विश्व के नेता के रूप में था।
आज भारत एक उभरते बाजार और एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
तेजी से अनिश्चित होते वैश्विक परिवेश में शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी।
भूराजनीतिक परिदृश्य।
नेहरू, जो एक आदर्श शिक्षाविद थे, अपनी सार्वजनिक सभाओं का उपयोग करते थे।
नागरिकों को अनेक विषयों पर शिक्षित करना। मोदी भी इसमें अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं।
एक समाज सुधारक ने अपने मासिक रेडियो वार्ता कार्यक्रम 'मन की बात' के माध्यम से यह बात कही।
और महिलाएं अपने रेडियो सेट के आसपास इकट्ठा होकर उनकी बातें सुनती हैं—आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका से लेकर परीक्षा के दबाव से निपटने के तरीकों तक।

तनाव (उनके एग्जाम वॉरियर सेशन चाचा नेहरू के सेशन की तरह ही थे)
उपदेशों के माध्यम से या एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग बंद करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
■

अपने पिता की तरह ही, मोदी भी इंदिरा गांधी से कई समानताएं रखती हैं।
गांधी: वे दोनों प्रधानमंत्री कार्यालय के अब तक के सबसे मजबूत नेताओं में से हैं।
सत्ता उनके हाथों में केंद्रित हो गई। उनकी तरह मोदी भी बड़े हो गए।
उनकी पार्टी से भी ज्यादा। जैसे उनका मशहूर जवाब था—'वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहता हूं 'गरीबी हटाओ'—उन्होंने भी विपक्ष द्वारा दोहराए जाने वाले इस वाक्य पर जोर दिया।
उसका एकमात्र लक्ष्य उसे हराना था, यहाँ तक कि उसे एक कब्र में दफनाना भी था।
(grave). In parliament, he minced few words: 'Ek akela kitno par bhari
पड़ा, देश देख रहा है (एक अकेला ही अनेकों पर भारी पड़ गया, देश)
देख रहा है)। इंदिरा गांधी की व्यवस्था की तरह, मोदी सरकार ने भी
साथ ही, विपक्ष की आलोचना को लेकर भी वह संवेदनशील रहे हैं।
इंदिरा गांधी को अपने विरोधियों को हाशिए पर धकेलने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा—
पार्टी के अंदर और बाहर, सभी दिग्गज नेता—मोदी, 2014 से,
भाजपा के भीतर से उन्हें कोई प्रतिरोध नहीं मिला। आज वे सर्वोच्च पद पर हैं और
निर्विवाद—इसमें उदारवादी बनाम कट्टरपंथी, पुराने बनाम नए का कोई विभाजन नहीं है।
उनकी पार्टी ने 1,000 और 500 रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला लिया।
पहले कार्यकाल में पद से इस्तीफा देना और संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जो
उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
ये बेहद गोपनीय फैसले थे। उन्होंने कुछ ही राजनीतिक सहयोगियों को इसमें शामिल

किया।
आत्मविश्वास।
उनके हर फैसले पर उनकी मुहर लगी होती है—जैसे कोविड पोस्टर पर उनकी तस्वीर।
टीकाकरण प्रमाण पत्र, या मुफ्त अनाज के थैले, या प्रत्येक वंदे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना
भारत ट्रेन। छवि की राजनीति इतनी प्रभावशाली और प्रमुख कभी नहीं रही।
मंत्री अपनी छवि की पहुंच में इतने सर्वव्यापी रहे हैं—अपनी अपील के साथ
2014 में पदभार संभालने के बाद से इसमें कोई कमी नहीं आई है।
वी. पी. सिंह से लेकर मंडल संस्था तक, मोदी ने कई सबक लिए हैं।
सामाजिक न्याय को अगले स्तर तक ले जाना, अपनी 'नई भाजपा' को नया रूप देना —
यह ब्राह्मण-बनिया के उस स्वरूप से बिलकुल अलग है जो कभी हुआ करता था। उसने सिलाई की।
ओबीसी और अति पिछड़े वर्गों को एक नए राष्ट्रीय ताने-बाने में पिरोना।
उन्होंने अनुसूचित जाति (एससी) को बहाल करके दलितों और आदिवासियों तक भी इसी तरह पहुंच बनाई।
अदालत द्वारा एसटी अधिनियम को कमजोर किया गया है और आदिवासी समुदाय को उच्च दर्जा देने जैसे कदम उठाए गए हैं।
महिला द्रौपदी मुर्मू को गणतंत्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
वहीं मोदी ने पी.वी. द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों को जारी रखा।
1991 में नरसिम्हा राव ने अपनी कल्याणकारी विचारधारा को लागू किया ताकि
गरीबों के लिए एक सुरक्षा जाल (जैसा कि इंदिरा गांधी ने अपने 'गरीबी हटाओ' अभियान के तहत किया था)।
नारा, और मनमोहन सिंह ने भोजन, काम के अधिकार के साथ यही किया।
शिक्षा और सूचना।)
रणनीतिक मामलों की दुनिया में, मोदी ने अगले कदम उठाए हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई यात्रा और मनमोहन सिंह
इसके बाद, अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया

—जो कि इसका परिणाम था।
भारत-अमेरिका गृह युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए सिंह का दृढ़ संकल्प
2008 में परमाणु समझौते को हर हाल में लागू करना था।
■

मोदी अपने पूर्ववर्तियों से किन मामलों में भिन्न हैं?
यह लेख लिखे जाने के समय तक, वह पहले से ही गैर-कांग्रेसी प्रधान मंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति हैं।
मंत्री, जिन्होंने नौ वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है, और पद पर बने हुए हैं
लोकप्रियता चार्ट में उनका अपना स्थान है—जो कि दुनिया के कुछ ही लोगों के बारे में कहा जा सकता है।
आज के नेता।
राजीव गांधी तकनीकी रूप से भी काफी कुशल माने जाते थे, उनका उदय इसी दौरान हुआ था।
पर्सनल कंप्यूटर के युग के साथ। लेकिन किसी भी अन्य प्रधानमंत्री की तुलना में,
मोदी ने सोशल मीडिया, मुफ्त डेटा और नवीनतम तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है।
और संचार उपकरण, और जो कुछ भी उसे उपलब्ध था, उसका सर्वोत्तम उपयोग किया।
जनसंपर्क कंपनियों और लॉबिस्टों के माध्यम से दुनिया भर में अपने समर्थकों को लुभाने के लिए।
नेतृत्व और अपने संदेश को व्यापक बनाने के लिए। वह आज के समय में दिखावे के महत्व को जानता है।
चौबीसों घंटे, सातों दिन, साल के सातों दिन संदेश भेजने की आवश्यकता।
उनकी शैली बड़े और नाटकीय काम करने और अचानक चौंकाने वाली बातें कहने की है।
इस शैली को संक्षेप में बताने वाला एक शब्द है, वह है 'भव्य'। एक बार

एक अधिकारी ने उनसे पूछा था कि वे एक विशेष इमारत का निर्माण किस प्रकार करवाना चाहते हैं।
उन्होंने अधिकारी से कहा, 'आप जो भी करें, वह भव्य होना चाहिए।'
उन्होंने जिसे 'कल्पनिक दरिद्रा' (कल्पनाशीलता का अभाव) कहा, उससे वे बेहद नाराज थे।
देश में बड़े काम करने के लिए।
बड़े और साहसी के प्रति उनका यह झुकाव उनकी दृष्टि में परिलक्षित होता है।
राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ-साथ। इसलिए, नई संसद और केंद्रीय
विस्टा को देश के औपनिवेशिक अतीत के अंत का प्रतीक बनना था और पहचान स्थापित करनी थी।
उन्हें नई संरचना के साथ। सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा को हटाना पड़ा।
दुनिया का सबसे ऊंचा, मैडिसन स्क्वायर गार्डन मीटिंग हॉल, न्यू यॉर्क में स्थित है।
भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए यॉर्क में आयोजित यह कार्यक्रम अब तक का सबसे भव्य आयोजन होना था। काले धन को राष्ट्रीय टीवी पर प्रसारित एक आदेश के माध्यम से समाप्त किया जाना था।
दोपहर
नेहरू ने राष्ट्रीय चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई।
1952, 1957, 1962। इंदिरा गांधी ने भी 1967 और 1971 में तीन चुनाव जीते थे।
वाजपेयी ने 1980 में जीत हासिल की, लेकिन 1977 में हार गए। उन्होंने अपनी पार्टी को तीन चुनावों में जीत दिलाई।
1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनावों में, लेकिन इनमें से किसी में भी नहीं।
क्या भाजपा ने आम चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल किया? हालांकि,
वाजपेयी ने व्यक्तिगत रूप से दस लोकसभा चुनाव जीते—नहीं
छोटा रिकॉर्ड।
मोदी ने आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारा है जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ा हो। और उन्होंने केवल अपने ही चुनाव लड़े हैं।
पहला चुनाव 2002 में हुआ—जब वे मुख्यमंत्री बने थे।

Gujarat.
वास्तव में, ऐसा कोई अन्य प्रधानमंत्री नहीं है जिसने इतने चुनाव जीते हों।
नरेंद्र मोदी की तरह ही उन्होंने भी अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़े हैं। उन्होंने पांच चुनाव लड़े हैं।
और उन्होंने अपनी पार्टी को सभी चुनावों में जीत दिलाई—जिनमें से तीन चुनाव गुजरात में 2002 में हुए थे।
2007 और 2012 में, और 2014 और 2019 में दो राष्ट्रीय जीत हासिल कीं, जब उन्होंने
वे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने छठा चुनाव उपचुनाव लड़ा।
जिसे उन्होंने 2002 की शुरुआत में जीतकर गुजरात राज्य विधानसभा में प्रवेश किया था।
मुख्यमंत्री बने रहें। वे भाजपा के लिए सबसे अधिक वोट पाने वाले नेता रहे हैं।
2014 के बाद से हुए लगभग हर राज्य चुनाव में।
आरएसएस-भाजपा के विचारक के. एन. गोविंदाचार्य मोदी के बारे में कहा करते थे कि...
चुनावी सफलताएँ, 'नरेंद्र की विशेषज्ञता राजनीतिक विपणन में है...' राजनीति
सत्ता के बराबर है। सत्ता चुनावों से उत्पन्न होती है। चुनाव एक तरह की लड़ाई है।
छवियों के इर्द-गिर्द ही राजनीति घूमती है। और इसलिए राजनीति छवियों, संदेशों और छवियों के इर्द-गिर्द ही घूमती है।
संकेत देना।'
■

मोदी की लोकप्रियता को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एक विस्फोटक मिश्रण के रूप में देखा जाता है।
और राष्ट्रीय गौरव, ओबीसी सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याणवाद जो
गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सीधे लाभ प्रदान किया गया
उनके नए बनाए गए बैंक खाते। उनकी लोकप्रियता में एक और बात जुड़ जाती है, वह है उनकी छवि।

एक सशक्त और करिश्माई नेता जो कड़ी मेहनत करता है और जिसका कोई पारिवारिक साथी नहीं है।
हालांकि, यह हिंदू एकता के लिए मोदी की सांस्कृतिक परियोजना है, जो इसे इस नजरिए से देखती है।
भारत को एक सभ्यतागत इकाई के रूप में देखते हुए हर चीज का विश्लेषण किया जाता है,
उसकी योजनाओं में इसका केंद्रीय स्थान है। इसके मूल में है...
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जिसकी नींव उन्होंने स्वयं रखी थी, और काशी (वाराणसी) में उनके द्वारा निर्मित प्रभावशाली गलियारा।
और मथुरा के पुनरुद्धार के लिए चल रही योजनाएँ। ये और अन्य
इन पहलों से कई युवा भारतीयों में सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, जिनमें से कई मिलियन लोग शामिल हैं।
बाबरी मस्जिद के विध्वंस और आर्थिक संकट के बाद इनका जन्म हुआ।
सुधार।
2014 में, भाजपा की सरकार ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया।
अपने इतिहास में पहली बार—उस कांग्रेस की जगह जिसने शासन किया था
आजादी के बाद पैंतालीस वर्षों तक देश पर शासन किया। भाजपा ने आगे चलकर...
पांच साल बाद 2019 में लोकसभा में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया। यह और भी अधिक था।
किसी एक मुख्यधारा की पार्टी, कांग्रेस, से सत्ता का हस्तांतरण होने की तुलना में,
दूसरी ओर, भाजपा।
1947 में, भारत ने नेहरू को चुना था—जिन्ना को नहीं—और
आधुनिक राष्ट्र राज्य के आधार के रूप में धर्म को अस्वीकार कर दिया गया। 2023 में, यह था
हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर—अल्पसंख्यकों को पीछे छोड़ते हुए,
पूर्ण रूप से देखा जाए तो छोटी संख्या—बढ़ती असुरक्षा की भावना और
एक ऐसे देश में घिरे हुए जो अत्यधिक ध्रुवीकृत हो गया था।
विपक्षी दलों को यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि कैसे
मोदी द्वारा प्रस्तुत चुनौती का राजनीतिक रूप से मुकाबला करना। इस बारे में चिंतित

हैं कि
‘लोकतांत्रिक संस्थाओं में गिरावट’ के इस्तेमाल पर उन्होंने नाराजगी जताई।
सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय या जैसी सरकारी एजेंसियां
आयकर अधिकारियों द्वारा उन्हें नियंत्रण में लाने और उन्हें 'परेशान' करने के लिए।
एक गैर-कुलीन, गैर-अंग्रेजी भाषी, ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी
यह भारतीय राजनीति के उस अधीनीकरण का प्रतिनिधित्व करता है जो अब तक रहा था।
अभिजात वर्ग का वर्चस्व; यह छोटे शहरों के लिए एक महत्वाकांक्षी आकर्षण रखता है और
भारत का बड़ा ग्रामीण इलाका। मोदी ने लुटियंस की विचारधारा को खारिज करते हुए अभिजात वर्ग पर हमला किया है।
दिल्ली, खान मार्केट और राजनीतिक राजवंश जो एक खास तरह की सत्ता के माध्यम से शासन करते हैं
अधिकार। धर्म, वर्ग और जाति को एक साथ लाकर, वह सक्षम रहा है।
हिंदू-मुस्लिम, अमीर-गरीब, उच्च जाति के बीच मौजूदा दरारों का फायदा उठाना।
निम्न जातियां, और हकदार बनाम वंचित।
■

इस अध्ययन के अंत में मुझे दो मुख्य बातें सीखने को मिलीं।
प्रधानमंत्री पद की कहानी। प्रधानमंत्री पद के बारे में पहला उल्लेखनीय पहलू।
निर्णय लेने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती थी कि ये निर्णय कितने तदर्थ और तात्कालिक थे।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री कौन था या वह किस पार्टी का सदस्य था।
संबंधित थे। अधिकांश निर्णय, जिनका असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला था, पचास-बीस या यहाँ तक कि दस साल के परिप्रेक्ष्य से नहीं लिए गए थे। वे थे
मुख्य रूप से तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया: आग बुझाना, किसी भी आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया देना
संकट, राजनीतिक मजबूरियाँ। लक्ष्य: किसी मुद्दे को हल करना, वापस लौटना।

सत्ता हासिल करने के लिए, या सत्ता में बने रहने के लिए। यदि निर्णय आमतौर पर निर्धारित किए जाते थे
राजनीतिक अस्तित्व की आवश्यकता, जिस तरह से उन्हें ले जाया गया—
शक्तिशाली लॉबियों से प्रभावित, हर तरह की विशेषताओं से युक्त
षड्यंत्र और छल, टकराती महत्वाकांक्षाएं और गलाकाट प्रतिस्पर्धा
—यह बेहद रोमांचक और नाटकीय है।
राजनीति में बढ़ते टकराव के साथ, भारत में निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल हो गई है। यह और भी जटिल होता जा रहा है। जिस आम सहमति के आधार पर देश का गठन हुआ है, वह भी तेजी से जटिल होती जा रही है।
स्वतंत्रता के बाद पहले पंद्रह वर्षों में जो कुछ हुआ, उससे आर्थिक परेशानियां शुरू हो गईं।
नीचे की ओर, क्षेत्रीय हितों ने अन्य विचारों को पीछे छोड़ दिया। मध्य तक-
1960 के दशक में, एक आधुनिक राष्ट्र के लिए संस्थाओं का निर्माण, गरीबी उन्मूलन,
निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण और व्यापक सामूहिक हित के लिए काम करना
तमाम गलतियों के बावजूद, ये विषय अब भी प्रमुख बने हुए थे।
जब सत्ता के लिए सत्ता ही सर्वोपरि हो गई
विचार-विमर्श के दौरान, संकीर्ण हित हावी होने लगे। इंदिरा गांधी ने
वास्तविक राजनीति की एक कला और विज्ञान—यानी 'साम दाम दंड भेद' यानी हासिल करना
सत्ता। उनके बाद आने वाली कई पीढ़ियों के राजनेताओं ने उनका अनुकरण किया।
वह—दलीय सीमाओं को पार करते हुए।
राजनीति सत्ता के बारे में है। जब तक राजनेता चुनाव नहीं जीतते, तब तक कोई सत्ता नहीं होती।
प्रधानमंत्री को सुनाने के लिए एक कहानी है। लेकिन लक्ष्मण रेखा कहाँ से आती है?
अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि व्यापक परिप्रेक्ष्य के लिए दूरदर्शिता और व्यावहारिकता कहाँ एक साथ आती हैं, तो
क्या यह सिर्फ सत्ता को कायम रखने से कहीं अधिक अच्छा है? वह विशिष्ट रेखा क्या है?

धुंधला और लगभग गायब हो चुका है।
मेरा दूसरा महत्वपूर्ण सबक, जिसने मुझे नए सिरे से प्रभावित किया, जब मैं
इस पुस्तक को लिखने वाले को यह अहसास हुआ कि भारत मूलतः एक गठबंधन देश है—
और इस पर गठबंधन सरकार की तरह, आम सहमति से शासन होना चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो।
सत्ता में एक ही पार्टी हो या पार्टियों का गठबंधन, चाहे उसका नेतृत्व कोई भी कर रहा हो।
मजबूत नेता हो या कमजोर नेता।
भारत के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच के अंतराल के वर्ष—
इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी ने गठबंधन युग की शुरुआत की।
देश (राजीव गांधी के शासनकाल के पाँच वर्षों को छोड़कर)। यह एक निश्चित अवधि तक चला।
पच्चीस साल—वी. पी. सिंह, चंद्र शेखर और पी. वी. नरसिम्हा के नेतृत्व में
राव, एच. डी. देवेगौड़ा, आई. के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, और
मनमोहन सिंह। किसी भी पार्टी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं किया—उन्होंने सरकार बनाने के लिए अन्य समूहों के साथ हाथ मिलाना पड़ा। या फिर सबसे बड़ी पार्टी ने अन्य समूहों को तोड़कर सरकार का नेतृत्व किया—जैसा कि हुआ था।
नरसिम्हा राव का मामला। कांग्रेस अन्य दलों के सामने कमजोर पड़ रही थी।
राजनीतिक ताकतें, जो इसकी जगह लेने के लिए होड़ कर रही थीं। भाजपा भी उनमें से एक थी।
उस दौड़ में सबसे आगे।
विडंबना यह है कि ये निर्णय कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों द्वारा लिए गए थे।
जिससे कांग्रेस पार्टी का पतन तेज हुआ और तेजी से बदलाव आया।
भाजपा का उदय। इन निर्णयों में राजीव गांधी द्वारा अधिनियमित करने का कदम शामिल था।
मुस्लिम महिला विधेयक पारित करें और विवादित ढांचे के ताले खोलें।
अयोध्या में बाबरी मस्जिद—जिसने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को अलग-थलग कर दिया

मुसलमानों के मामले में। या पी.वी. नरसिम्हा राव के उस अनिर्णय के कारण जिसने सत्ता से बेदखल कर दिया।
बाबरी मस्जिद के निर्माण ने उनके शासनकाल के दौरान मंदिर के मुद्दे को पीछे धकेल दिया।
कार्यकाल तो मिला, लेकिन इससे हिंदू राष्ट्रवाद को बल मिला, क्योंकि भाजपा को सत्ता का स्वाद चखना पड़ा।
और इसने संवैधानिक गारंटियों में मुसलमानों के विश्वास को कमजोर कर दिया।
इसके अलावा, कांग्रेस नेता वी. पी. सिंह का विवादास्पद निर्णय भी चर्चा में रहा।
मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पार्टी से अलग हो गए।
ओबीसी को सशक्त बनाने के उनके प्रयासों ने कांग्रेस पार्टी को करारा झटका दिया।
1990 का दशक वह दशक था जिसने प्रभुत्व का अंत किया।
कांग्रेस। फिर भी उसके बाद सत्ता में आई गठबंधन सरकारें।
उन्होंने दूरगामी निर्णय लिए—जैसे कि खोलना
अर्थव्यवस्था, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सकारात्मक कार्रवाई
मंडल की कक्षाएं, जिन्होंने उत्तर भारत की राजनीति को बदल दिया, परीक्षण
परमाणु हथियारों के क्षेत्र में भारत को वैश्विक मंच पर उच्च स्थान मिला, और
देश की विदेश नीति को नया रूप दिया।
यह तो स्पष्ट है कि इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री जितनी शक्तिशाली होंगी,
गांधी हों या नरेंद्र मोदी, सत्ता का केंद्रीकरण जितना अधिक होगा,
प्रधानमंत्री कार्यालय—और अधिक संभावना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो सकता है।
संस्थाएँ। एक कमजोर प्रधानमंत्री और गठबंधन सरकार, और यह विडंबनापूर्ण है।
कई कारकों को देखते हुए, यह लोकतांत्रिक कामकाज के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान करता है।
वे हित जो सक्रिय हो जाते हैं—और अत्यधिक उपयोग पर रोक लगाते हैं
शक्ति।
निःसंदेह, गठबंधन व्यवस्था से अपनी ही तरह की चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
समस्याएं—प्रधानमंत्री की अस्थिर स्थिति, संभावना

विखंडन और अस्थिरता—और कई अन्य खिलाड़ियों द्वारा भ्रष्टाचार
दुराचार में लिप्त होना, हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि एकदलीय शासन
कम भ्रष्ट है।
आजादी के पचहत्तर साल बाद, भारत ने उन सभी बातों को साबित कर दिया है।
वे लोग गलत थे जिन्होंने यह सोचा था कि एक गरीब, पिछड़ा और अत्यधिक विविधता वाला राष्ट्र संसदीय लोकतंत्र के रूप में एकजुट नहीं रह पाएगा।
उन्होंने उन सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया, जिनमें देश के टूटने की आशंका जताई गई थी।
भारत आज भी एक लोकतंत्र है—लेकिन यह एक त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है, जिसमें कई खामियां हैं।
संसद, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का लगातार क्षरण
मीडिया और चुनाव आयोग। राजनीतिक दल इस तरह चलाए जाते हैं जैसे
उदाहरण के लिए, जागीरदारों और मंत्रियों में मंत्रिमंडल में खुलकर बोलने की क्षमता नहीं होती।
क्योंकि वे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पर निर्भर हैं।
सत्ता में बने रहने के लिए।
अंततः, मजबूत संस्थाएँ ही स्थिरता प्रदान करती हैं।
लोकतंत्र—और यह अंतिम बच्चे तक पहुँच सकता है। हम अच्छा या बुरा दोनों पा सकते हैं।
शासक तो हैं ही, लेकिन ये संस्थाएँ ही एक जीवंत समाज की प्रहरी हैं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था—और सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगा सकती है।
■

मैं इस वृत्तांत को जवाहरलाल नेहरू की कहानी के साथ समाप्त करना चाहता हूँ और
सरदार वल्लभभाई पटेल—वह प्रतिष्ठित, लेकिन विवादास्पद, पहली जोड़ी
स्वतंत्र भारत, क्योंकि यह दर्शाता है कि नेतृत्व वास्तव में क्या होता है।
ये बीते युग की बातें हैं, लेकिन आज के भारत के लिए प्रासंगिक हैं।
नेहरू और नेहरू एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे—नेहरू वामपंथी और उदारवादी थे,

और एक ऐसे व्यक्ति थे जो
पटेल विचारों के धनी, दक्षिणपंथी और व्यावहारिक, और कर्मठ व्यक्ति थे।
यह सर्वविदित है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति की पसंद नहीं थे।
नेहरू अप्रैल 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने।
महात्मा गांधी की यही पसंद थी। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वे बने।
अंतरिम अवधि में प्रधानमंत्री (कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष)
सितंबर 1946 में सरकार ने—और फिर 1947 में भी।
गांधी जी के कहने पर ही सरदार पटेल नेहरू के कार्यकाल से पीछे हट गए थे।
पक्षधर बनना, एक ऐसा निर्णय जो क्विट के नायक के लिए आसान नहीं रहा होगा।
भारत आंदोलन—और एक ऐसा आंदोलन जो कई दशकों बाद भी विवादों को जन्म देता है।
गांधी के लिए नेहरू और पटेल 'एक जुते हुए दो बैल' थे।
सरकारी गाड़ी। उसे लगा, 'एक को दूसरे की ज़रूरत होगी, और दोनों मिलकर खींचेंगे।'
एक साथ।'
जब 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तब पटेल
नेहरू के अधीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में काम करने पर सहमति व्यक्त की।
लेकिन आजादी के पांच महीने के भीतर ही उन्होंने गांधी के मंत्री को खो दिया।
30 जनवरी 1948 को एक हत्यारे की गोली के सामने एकजुट उपस्थिति।
गांधी जी के निधन से एक घंटा पहले पटेल उनके साथ थे। वे दिल्ली के बिरला हाउस में दिल खोलकर बातें कर रहे थे, और यह कहानी पटेल द्वारा सुनाई गई है।
राजमोहन गांधी ने पटेल की जीवनी में लिखा है: सरदार ने बात की। बापू
चरखा चलाते हुए उसने सुना। फिर उसने अपना शाम का भोजन किया, और
गांधी जी उत्तेजित पटेल की बातें सुनते रहे। अंत में, गांधी जी ने पटेल से कहा
उन्होंने शांतिपूर्वक कहा कि मंत्रिमंडल में उनकी और नेहरू की उपस्थिति
‘अपरिहार्य’। इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की दरार विनाशकारी होगी।
देश। उन्होंने अगले दिन नेहरू से मिलने का फैसला किया। बापू, देर से आने के कारण।
अपनी शाम 5 बजे की बैठक के बाद, वे प्रार्थना स्थल की ओर लॉन में चले गए।

हिरासत में लिया गया। पटेल घर की ओर चल पड़े। कुछ ही मिनटों में, पटेल और उनकी बेटी
मणिबेन बिरला हाउस लौट आई थीं। उन्हें बताया गया कि बापू को
गोली मारकर हत्या कर दी गई।
नेहरू वल्लभभाई के कुछ मिनट बाद पहुंचे। वे नीचे चले गए।
वह घुटनों के बल बैठ गया, अपना सिर गांधी जी के सिर के पास रखा और बच्चे की तरह रोने लगा। 'फिर
उन्होंने अपना शोकग्रस्त सिर सरदार की गोद में रख दिया। भारत के अंतिम वायसराय, लॉर्ड
माउंटबेटन को गांधी जी की कही बात याद आई—कि उनकी सबसे प्रिय इच्छा
इसका उद्देश्य नेहरू और पटेल के बीच पूर्ण सुलह कराना था।
पुरुषों ने एक-दूसरे को गले लगाया। उस रात, 30 जनवरी 1948 को, वे
नेहरू ने अंग्रेजी और हिंदी में तथा पटेल ने एक साथ राष्ट्र को संबोधित किया।
हिंदी।
तीन दिन बाद, 3 फरवरी 1948 को, द स्टेट्समैन ने एक लेख प्रकाशित किया।
गृह मंत्री पटेल की अक्षमता के कारण उनके इस्तीफे की मांग करने वाला लेख
गांधी की रक्षा करो। जयप्रकाश नारायण और अन्य समाजवादियों ने हमले का नेतृत्व किया।
पटेल के बारे में। पटेल ने प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र लिखा।
हालांकि, पत्र भेजा नहीं गया। पटेल की निजी सचिव, विद्या
शंकर ने उसे इसे रोककर रखने के लिए मना लिया—क्योंकि ऐसा करने से वह वंचित हो जाएगा
गांधी जी के संयुक्त नेतृत्व (नेहरू और पटेल के नेतृत्व) का देश
इच्छा।
संयोगवश, नेहरू ने भी उसी दिन पटेल को पत्र लिखा। ‘बापू के साथ’
मृत्यु के बाद सब कुछ बदल जाता है और हमें एक अलग और अधिक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है।
यह एक कठिन दुनिया है... मुझे लगता है कि यह मेरा कर्तव्य है और, अगर मैं कहने की हिम्मत करूं तो, आपका भी।

साथ ही, हमें दोस्तों और सहकर्मियों के रूप में मिलकर इसका सामना करना होगा। केवल इतना ही नहीं।
ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है, लेकिन एक-दूसरे के प्रति पूरी निष्ठा के साथ... मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि
वह तुम्हें मुझसे मिल जाएगा।
4 फरवरी को पहली बार सरदार पटेल ने नेहरू को 'मेरा' कहकर पुकारा।
नेता'। 'मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ,' पटेल ने अगले दिन नेहरू को लिखा, 'हम
दोनों जीवन भर एक साझा उद्देश्य में साथी रहे हैं। मुझे अच्छा अनुभव हुआ।
बापू से आखिरी बार बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी राय हम दोनों को बांधती है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हूं।
जिम्मेदारियों को...इसी भावना से निभाएं।'
नेहरू और पटेल के नेतृत्व वाली नई सरकार को एक की देखरेख करनी थी
मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रवासों में से एक, जिसने 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित किया।
उपमहाद्वीप में लोगों का पुनर्वास करना पड़ा। लाखों शरणार्थियों का पुनर्वास करना पड़ा।
जो पाकिस्तान से आए थे—और एक संविधान का निर्माण करने के लिए जो उन पर आधारित हो
वयस्क मताधिकार और उदारवादी सिद्धांत। इसे राजनीतिक रूप से एकीकृत करना था।
ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें थीं, जिनके प्रमुख शासक थे।
अपने अधिकार को लागू करने के लिए, एक संप्रभु, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए—जो
यह कार्य भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल ने बखूबी निभाया। उन्होंने मिलकर
नए देश को स्थिर करने के लिए। अंग्रेजों ने भारत को कोई अधिकार नहीं सौंपा था।
बना बनाया राष्ट्र।
ऐसा नहीं है कि पटेल ने नेहरू को हमेशा अपनी मनमानी करने दी हो।
उसके बाद के महीनों में। स्वतंत्रता के बाद के तीन वर्षों में, और तब तक जब तक वह
1950 में पटेल की मृत्यु हो गई, लेकिन कई फैसलों में उनका दबदबा रहा, जैसे कि

नियुक्ति के मामले में।
राजेंद्र प्रसाद, जो एक कट्टर हिंदू थे, को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करने के बजाय
नेहरू सी. राजगोपालाचारी को उम्मीदवार बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने उम्मीदवार को भी चुनवा लिया।
इसके विपरीत, 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए।
जे. बी. कृपलानी, जिन्हें नेहरू का समर्थन प्राप्त था।
जब पटेल टंडन के लिए समर्थन जुटाने के लिए प्रचार कर रहे थे और उन्होंने असम से पूछा
मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने,
उसका समर्थन करते हुए, फखरुद्दीन ने जवाब दिया कि वह केवल 'पंडितजी की इच्छा के अनुसार' ही करेगा। पटेल
फखरुद्दीन ने पलटवार करते हुए कहा, 'फखरुद्दीन, जो चाहो करो। लेकिन याद रखना।'
जवाहरलाल कभी किसी मित्र की मदद नहीं कर सकता और न ही कभी किसी शत्रु को हानि पहुंचा सकता है। मैं कभी नहीं।
'मित्र को भूल जाओ और शत्रु को कभी क्षमा मत करो'
नेहरू और पटेल कई मुद्दों पर एक-दूसरे से असहमत थे—जैसे कि उनके आकलन पर।
आरएसएस जैसा संगठन। नेहरू का मानना था कि यह एक फासीवादी संगठन है।
संगठन। पटेल ने इसे साहसी लेकिन गुमराह करने वाला माना और इस पर प्रतिबंध लगा दिया।
गांधी जी की हत्या के डेढ़ साल बाद।
पटेल का निधन दिसंबर 1950 में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद, नेहरू ने
उन्होंने सरकार और पार्टी दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नेहरू और
पटेल परिवार दोषरहित नहीं था। दूसरे नंबर पर रहने को स्वीकार करके, पटेल ने
दोनों बलिदानों में से बड़ा बलिदान नेहरू का था। नेहरू के लिए भी यह कठिन रहा होगा।
जब भी उनके डिप्टी द्वारा उन्हें मात दी जाती थी, तो पटेल के सामने आत्मसमर्पण कर

देना। लेकिन
उन्होंने शुरुआती वर्षों में बुद्धिमत्ता और संयम का प्रदर्शन किया।
स्वतंत्रता। गहरे मतभेदों के बावजूद, वे एकजुट रहे, ताकि भारत नामक उस नई इकाई को एकजुट रख सकें जो उन्हें दी गई थी।
हिरासत।
गांधी जी जानते थे—और नेहरू और पटेल भी जानते थे—कि वे ऐसा करेंगे
एक विशाल, जीवंत और विविधतापूर्ण राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
भारत, जहाँ जातीय, धार्मिक, जातिगत और भाषाई विविधताएँ पाई जाती हैं।
जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था—यह एक चुनौती है जो आज भी बनी हुई है।
यह आज भी उतना ही दुर्जेय है जितना उनके समय में था।
भारत की बहुलतावादी संस्कृति का प्रतीक बनकर नेहरू और पटेल ने यह दिखाया कि यह
दो भिन्न विचारधाराओं का सहअस्तित्व और सहयोग संभव है।
एक राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। उन्होंने पाया कि सत्ता सबसे सुरक्षित तब होती है जब वह
यह जानकारी साझा की जाती है, खासकर उन लोगों के साथ जो ग्राहक की बजाय एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं।
एक प्रतिध्वनि कक्ष। यह एक सबक है जिसे भारत और उसके नेतृत्व को नहीं भूलना चाहिए।
भूल जाओ।

आभार

जब मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया, तब मुझे इसके लिए आवश्यक मेहनत के बारे में बहुत कम जानकारी थी।
इसमें शामिल होगा। यह परियोजना बिना मदद के संभव नहीं होती।
और कई लोगों के समर्थन के लिए, मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए कहाँ से शुरू करूँ, यह मुझे नहीं पता।
उन्हें।

सबसे पहले, पुस्तक के मुख्य पात्रों को मेरा धन्यवाद—
मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, नौकरशाहों, वैज्ञानिकों, मेरे सहयोगियों
मीडिया—जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे जानकारी और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की।
वे पुस्तक के पन्नों पर फैले हुए हैं।
वी. पी. सिंह के साथ बिताए गए वे घंटे जब उनका ऑपरेशन चल रहा था
पद छोड़ने के बाद दिल्ली के अपोलो अस्पताल में डायलिसिस कराने वाली महिला, जिनका उत्थान हुआ
मैंने प्रतिदिन जिन विषयों पर चर्चा की थी, और जो अनेक बातचीतें मैंने की थीं, उन सभी के शीर्ष पर पहुंचने के लिए।
पी. वी. नरसिम्हा राव के साथ, मेरे करियर के दौरान लिए गए साक्षात्कार।
मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और एच. डी. देवेगौड़ा के साथ,
चंद्र शेखर और आई. के. गुजराल के साथ हुई कई स्पष्ट बातचीत,
और सोनिया गांधी और एल. के. आडवाणी से हुई मुलाकातों ने मेरी बहुत मदद की।
यह समझना कि देश को आकार देने वाले निर्णय कैसे लिए गए।
तकदीर।
पिछले कुछ वर्षों में मुझसे बात करने वाले कई लोग—उनमें से अधिकांश के पास स्पष्टवादिता—अब आसपास नहीं है—जैसे आर. वेंकटरमन, कृष्णकांत, पी. Shiv Shankar, Jaswant Singh, Harkishan Singh Surjeet, H. N. Bahuguna,
भुवनेश चतुर्वेदी, शरद यादव, राम विलास पासवान, एस जयपाल
रेड्डी, देवेंद्र द्विवेदी, अरुण नेहरू, एच. आर. भारद्वाज, एम. एल. फोतेदार,
आर.के. धवन, यूनुस सलीम, डी.पी.त्रिपाठी, ब्रजेश मिश्रा, के. Subrahmanyam, S. K. Singh, Naresh Chandra, K. Santhanam, and many
और मुझे इस बात का बेहद अफसोस रहेगा कि वे इस किताब को नहीं देख पाएंगे।
जिसे उनके सुझावों ने आकार देने में मदद की है।
मैंने दिवंगत कृष्णकांत से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिनसे मैं
मेरी पहली मुलाकात आपातकाल के वर्षों के दौरान हुई थी जब मैं उनके साथ काम

कर रहा था।
हिम्मत वीकली के लेखक और वे लोग जो वर्षों से वी.पी. सिंह से लेकर वाजपेयी तक की घटनाओं के बारे में मुझसे गोपनीय रूप से बात करते थे।
साल।
मैंने उपराष्ट्रपति पद के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चाओं को भी महत्व दिया।
सोम पाल के साथ प्रीमियरशिप।
इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक राज कमल झा को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने...
अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, उन्होंने मुझे पुस्तक के बारे में बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया।
द की पूर्व उप संपादक कल्पना शर्मा ने जिस तरह से काम किया, उसकी सराहना की गई।
एक हिंदू और उनके पुराने मित्र ने मसौदा पढ़ने के लिए समय निकाला।
उन्होंने मुझे किताब पढ़कर बहुत उपयोगी सुझाव दिए। मेरे कई सहकर्मियों ने भी इस किताब का इस्तेमाल किया।
मीडिया ने विभिन्न प्रधानमंत्रियों के अपने अनुभवों को मेरे साथ साझा किया।
वे इस पुस्तक में शामिल हैं, और मैं उनका आभारी हूं।
किताबों को सफल होने के लिए एक सहायक ढांचे की आवश्यकता होती है। मेरे दोस्तों ने ही यह काम किया।
और परिवार—जिन्होंने वह सहारा प्रदान किया और लगातार साथ दिया
मदद का हाथ बढ़ाना। शेरना घ्यारा चटर्जी, हालांकि एक मनोचिकित्सक हैं।
पेशे से यूके और भारत में रहने वाले, जरूरत पड़ने पर हर तरह से मदद करते थे।
साक्षात्कार करना, उन्हें प्रतिलेखित करना, उन्हें क्रम में लगाना, खोजना
संदर्भ—यह सब प्रेमपूर्वक किया गया है। अपर्णा खत्री ने भी इसे बड़े प्यार से लिखा है।
कई साक्षात्कार लिए, यहां तक कि कुछ हिंदी साक्षात्कारों को रोमन लिपि में टाइप भी किया।
पटकथा! कार्तिक कांत ने शोध और सामग्री को व्यवस्थित करने में मदद की।
और उनमें बारीकियों को समझने की क्षमता थी। डॉ. रवि राव, सिद्धार्थ सिंह को मेरा धन्यवाद।

और एशिया पठार (परिवर्तन की पहल) सम्मेलन में उनके सहयोगियों के साथ
पंचगनी स्थित केंद्र को लेखन के दौरान मुझे सहयोग देने के लिए धन्यवाद।
किताब।
सबसे बढ़कर, मेरे माता-पिता, सौंदर्या और गुरुदत्त चौधरी को, जिन्होंने
वे बहुत जल्दी चले गए, लेकिन हमेशा मेरे लिए मौजूद रहे। मेरी चाची, विजयलक्ष्मी।
पेशे से शिक्षाविद वधवा ने मुझे अपने घर में रहने की सुविधा दी।
जब भी मुझे दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर जाने का मौका मिलता, मैं मुंबई जाया करती थी।
शांत रहकर लेखन करो। वह चाहती थी—और उसे बताया भी गया—कि मैं
किताब लिखना खत्म कर लिया था, और कवर का डिज़ाइन देखने के लिए। कुछ दिन
पांडुलिपि प्रकाशकों को जमा करने के बाद, उसे आगे बढ़ना था।
दूर। जबकि उनके चचेरे भाई, नरेंद्र मुरकुंबी, ने हर तरह की सहायता प्रदान की।
एक अन्य चचेरी बहन, ज्योति नरूला ने रसद संबंधी सहायता प्रदान की और एक अध्याय की आलोचना की।
मुझे अपने कार्यालय का उपयोग करने की पेशकश की। मेरे अमेरिका स्थित बहनोई रविंद्र ने
जब भी ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ है, कोका हमेशा हौसला बढ़ाने वाले शब्द कहता था।
अंतहीन व्यायाम। मेरी बहन रजनी खन्ना और भतीजे जैसे कई लोग।
अमित खन्ना ने मुझे लगातार इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं किताब को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करूं।
मेरे प्रकाशक डेविड डेविडर को मेरा विशेष धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया।
मैंने पहले दिन से ही किताब पर काम करना शुरू कर दिया था—और एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का पालन किया।
उन्हें और उनकी कुशल टीम - ऐनला ओज़ुकुम और - को धन्यवाद।
कनिका प्रहारज को पुस्तक पर उनके अथक परिश्रम और अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद।
कोविड महामारी के दौरान ही इस पुस्तक का समापन हो सका।
और अंत में, मेरे जीवन के दो पुरुषों को—मेरे पति अरुण को, जिन्होंने

कम से कम दो दशकों से मुझे किताब लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा था—और कंप्यूटर/तकनीकी समस्याओं से निपटने सहित हर तरह की सहायता प्रदान करना। जो समस्याएं सामने आती थीं, और मेरा संगीतकार बेटा नकुल जो चिढ़ जाता था मेरे हर समय 'व्यस्त रहने' के खिलाफ। उनका लगातार यही कहना था: 'जब क्या यह सब खत्म हो जाएगा?
अंततः यह समाप्त हो गया।

नोट्स

परिचय
9. 'अंतिम जिम्मेदारी आपकी है...यह अद्भुत हो सकता है': वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा, अक्टूबर
1999, अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली।
ix 'जिम्मेदारी जितनी अधिक होगी, स्वतंत्रता उतनी ही कम होगी': वही।
ix 'हाँ, शिखर अकेला है': चंद्र शेखर ने लेखक से कहा।
ix 'आपके लिए कोई जगह ही नहीं है': आई. के. गुजराल ने लेखक से कहा।
ix 'जितना ऊपर जाओगे, उतना ही अकेलापन महसूस करोगे': अटल बिहारी वाजपेयी, एन. के. सिंह द्वारा उद्धृत।
'बाजों के बीच एक कबूतर', इंडिया टुडे, 31 मई 1996।
9. मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ घोटाले उजागर होने पर: 'यूपीए रिपोर्ट कार्ड'
नौ साल, नौ घोटाले', इंडिया टुडे, 22 मई 2013।
ix राजीव गांधी, जिन्हें 414 सदस्यों का अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त था: 'सांख्यिकीय आठवीं लोकसभा के लिए 1985 के आम चुनावों पर रिपोर्ट: खंड II', दिल्ली: चुनाव भारत आयोग, 1986, <https://eci.gov.in/files/file/4119-general-election-> पर उपलब्ध है
1985-खंड-i-ii/>.
ix 'जैसे ही कोई मेरे कमरे में प्रवेश करता है': इंदिरा गांधी ने कृष्णकांत से कहा।
मई 1964 में देहरादून में बिताए उनके अंतिम दिन: राज कंवर, 'देहरादू में नेहरू के

अंतिम दिन'

दून: नेहरू ने अंतिम नियुक्ति को बरकरार रखा', द सिटिजन, 26 मई 2020।

उनके बिस्तर के पास कविताओं की एक किताब पड़ी थी: गोपालकृष्ण गांधी ने लिखा, 'नेहरू एक प्रतिभाशाली नेता थे।'

सत्यता', हिंदुस्तान टाइम्स, 26 मई 2016।

उनकी जनसंपर्क एजेंसी लगातार तस्वीरें जारी करती रही: कविता उपाध्याय, 'पीएम मोदी ने रात बिताई'

केदारनाथ के पास ध्यान गुफा', इंडियन एक्सप्रेस, 19 मई 2019; महेश लांगा, 'नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" राष्ट्र को समर्पित की', द हिंदू, 31 अक्टूबर 2018; 'प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की ट्रेन यात्रा का अनुसरण किया', द ट्रिब्यून, 9 जुलाई 2016; अरजीत गर्ग, 'प्रधानमंत्री मोदी ने नए एयर इंडिया वन पर अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी: विमान के बारे में आपको जो कुछ जानने की जरूरत है', न्यूज18, 26 मार्च 2021; 'लगभग खाली दिख रही अटल सुरंग के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का विशिष्ट हाथ हिलाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है'।

Scroll.in, 4 अक्टूबर 2020।

11 'कैबिनेट में एकमात्र पुरुष': इस वाक्यांश का प्रयोग सर्वप्रथम पिलू मोदी ने किया था, जो इसके संस्थापक थे।

इंदिरा गांधी का वर्णन करने के लिए स्वतंत्र पार्टी शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका उल्लेख 'किसिंजर ने इंदिरा में "मजबूत" व्यक्ति को सलाम किया' शीर्षक वाले लेख में किया गया है, जो द टेलीग्राफ, 25 दिसंबर 2007 को प्रकाशित हुआ था। अमेरिकी दस्तावेजों के अनुसार, हेनरी किसिंजर ने 1976 में अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष मुहम्मद दाऊद से कहा था कि वह चाहते हैं कि अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा मजबूत व्यक्ति हो।

xi 'व्यापक हितों, तुच्छ दृष्टिकोणों और वास्तविक विचारों का जाल': पी. वी. नरसिम्हा राव

लेखक ने अपने पद से हटने के बाद एक लिखित प्रश्नोत्तर में यह बात कही थी। प्रश्नोत्तर पर कोई तिथि अंकित नहीं है और यह उनके निजी दस्तावेजों में भी पाया गया था। इसका उल्लेख विनय सीतापति की पुस्तक "हाफ लायन: हाउ पी.वी.

नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया", गुड़गांव: पेंगुइन रैंडम हाउस, 2016, पृष्ठ 338 में किया गया है।

xvii कांग्रेस, जिसने 1989 तक देश पर चालीस वर्षों में से उनतीस वर्षों तक शासन किया था-

दो वर्ष: देखें www.pmindia.gov.in/en/former-prime-ministers/.

xiii दोनों अवसरों पर उन्होंने तेरह दिनों तक देश पर शासन किया: सुमंत्र बोस, रूपांतरण

भारत: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, और लंदन, इंग्लैंड: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2013, पृष्ठ 79।

xiii प्रणब मुखर्जी ने इसी मानदंड का उल्लेख किया है: प्रणब मुखर्जी, द टर्बुलेंट इयर्स:

1980-1996, दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स, 2016, पृ. 70.

xiii नंदा को 27.5 हेक्टेयर के हवेली को परिवर्तित करने के लिए भी याद किया जाता है: जनार्दन ठाकुर, सभी

प्रधानमंत्री के आदमी, नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस, 1977।

xiii महात्मा गांधी द्वारा नेहरू को चुना गया: राज सिंह, 'गांधी ने नेहरू को क्यों चुना और किसी अन्य को क्यों नहीं'

'सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनें?', इंडिया टीवी, 31 अक्टूबर 2015।

xiv 'सही मार्ग के बारे में गहराई से सोचें': सी. पी. श्रीवास्तव, लाल बहादुर शास्त्री: सत्य का जीवन

राजनीति में, दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1995, पृ. 33.

xiv उन्हें अक्सर 'छोटी चिड़िया' कहा जाता था: जनार्दन ठाकुर, प्रधान मंत्री: नेहरू से वाजपेयी, मुंबई: ईश्वर, 1999, पृ. 64.

xiv 'साधारण' प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नायक बन गए: वेल्स हैंगन, नेहरू के बाद, कौन?

न्यूयॉर्क: हारकोर्ट, ब्रेस एंड वर्ल्ड, 1963, पृष्ठ 108।

xiv 'गूंगी गुड़िया': 'ए फिटफुल इम्प्रोवाइजेशन', विचार, 22 जनवरी 1966।

xiv 'this chokri': Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, and Aditya Mukherjee, India Since

स्वतंत्रता: संशोधित एवं अद्यतन, दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, 2008।

xiv ‘बुढ़िया चुड़ैल’: ‘“[इंदिरा गांधी] एक कुतिया है... भारतीय कमीने हैं”’, आउटलुक, 3
फरवरी 2022।
xiv 'दुर्गा': पुपुल जयकर, इंदिरा गांधी: एक जीवनी, नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, 1995, पी।
235.
xiv इस उछाल के परिणामस्वरूप नौ राज्य सरकारों का गठन हुआ: 1967 में, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा
पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, केरल और मद्रास (अब तमिलनाडु)। राजस्थान में इसे बहुमत नहीं मिला, लेकिन अन्य दलों की मदद से इसने सरकार बनाई।
xv ‘मम्मी की किसी न किसी तरह मदद करनी होगी’: स्टीवन आर. वेइसमैन, ‘भारत में हत्या; राजीव
गांधी: एक पुत्र जिसने जीत हासिल की, हारी और वापसी की कोशिश की’, द न्यूयॉर्क टाइम्स, 27 मई 1991।
xv विशेष रूप से अवैध रिश्वत के कथित भुगतान के संबंध में: 'बोफोर्स घोटाला मामला क्या है?'
इंडियन एक्सप्रेस, 3 फरवरी 2018।
xv ‘भारत जिस प्रधानमंत्री से वंचित रहा’: चंद्र शेखर में उद्धृत मचकुंद दुबे – द
वैचारिक राजनीति का अंतिम प्रतीक, दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स, 2019।
xv लेकिन आपातकाल के दौरान उनका उससे विमुख हो गया: हरिवंश और रवि दत्त बाजपेयी,
‘आपातकाल का वृत्तांत: जिस पार्टी को चंद्र शेखर सत्ता में लाए, उसी ने उन्हें जेल भेज दिया’, इंडियन एक्सप्रेस, 25 जून 2019।
xv अपनी चप्पलों में 4,260 किलोमीटर पैदल चलकर: वेंकटेश रामकृष्णन, 'एक विद्रोही'
जर्नी’, फ्रंटलाइन, 27 जुलाई 2007।
xv महिलाएं रास्ते में उसका इंतजार करती थीं: जैसा कि लेखिका ने देखा, जब उसने 1983 में तमिलनाडु में दो दिनों की यात्रा।

xvi ‘मृत मछली का करिश्मा’: जयराम रमेश, सीतापति, हाफ लायन, पृष्ठ 98 में उद्धृत।

xvi वाजपेयी ने चौबीस दलों के गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाई: कीथ जोन्स, ‘भारत की अगली सरकार बनाने के लिए हिंदू कट्टरपंथी नेतृत्व वाला गठबंधन’, वर्ल्ड सोशलिस्ट वेबसाइट, 9 अक्टूबर 1999।

xvi वोक्कालिगा समुदाय, एक कृषि प्रधान समुदाय, को 'पिछड़ा वर्ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया है: 'केंद्रीय सूची'

ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) संबंधी जानकारी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ncbc.nic.in पर उपलब्ध है।

xvi ‘मुख्यमंत्रियों की सरकार’: नीरजा चौधरी, ‘विश्वास रखना: राजनीतिक रिपोर्टिंग’, वी. ईश्वर आनंद और के. जयंती (संपादक), ए हैंडबुक ऑफ जर्नलिज्म: मीडिया इन द इंफॉर्मेशन एज, दिल्ली: सेज पब्लिकेशंस, 2018, पृष्ठ 129।

xvii नेहरू ‘लाहौर की भीड़ भरी सड़कों पर सफेद घोड़े पर सवार’: आई. के. गुजराल, मैटर्स

विवेकाधिकार: एक आत्मकथा, नई दिल्ली: हे हाउस पब्लिशर्स, 2011, पृष्ठ 27।

xvii ‘किचन कैबिनेट’: कैथरीन फ्रैंक, इंदिरा: इंदिरा नेहरू गांधी का जीवन, लंदन: हार्परकॉलिन्स पब्लिशर्स, 2001, पृष्ठ 299।

xvii उनके द्वारा प्रतिपादित ‘गुजराल सिद्धांत’: कंवल सिबल, ‘गुजराल सिद्धांत की स्थायी प्रासंगिकता’

'सिद्धांत', इंडिया टुडे, 16 दिसंबर 2019।

xvii ‘मैं जो कुछ भी हूँ, वह शिक्षा की वजह से हूँ,’ वे अक्सर कहते थे: पीटीआई, ‘मैं आज जो कुछ भी हूँ, वह शिक्षा के कारण हूँ’

शिक्षा के कारण: प्रधानमंत्री’, टाइम्स ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 2010।

xvii 303 सीटें, 282 से बढ़कर: '2 से 303 सीटें: वर्षों में भाजपा का विकास कैसे हुआ', टाइम्स ऑफ

भारत, 30 मई 2019।

xvii ध्रुवीकरण करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 'नई भाजपा' को आकार दिया: निरंजन साहू, 'माउंटिंग'

भारत में बहुसंख्यकवाद और राजनीतिक ध्रुवीकरण’, थॉमस कैरोथर्स और एंड्रयू

ओ'डोनोह्यू (संपादक), दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया में राजनीतिक ध्रुवीकरण: पुराने विभाजन, नए खतरे, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, पृ. 9-23।

xvii उन्होंने भाजपा के मूल, हिंदू समर्थक एजेंडे को आगे बढ़ाया: अज़ीम इब्राहिम, 'मोदी का पतन'

निरंकुशता', विदेश नीति, 13 जुलाई 2020।

xviiii मोदी, देवेगौड़ा के बाद दूसरे ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) नेता थे: सौम्या अजी, 'I

'भारत के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे: एच डी देवेगौड़ा', इकोनॉमिक टाइम्स, 13 जुलाई 2015।

xviii 'मैं...एक जाट परिवार में पैदा हुआ हूँ': ठाकुर, नेहरू ने वाजपेयी को, पृष्ठ 155। विभिन्न

जाटों के राजपूत, वैश्य या शूद्र होने को लेकर कई सिद्धांत प्रचलित हैं; अब उन्हें भारत के नौ राज्यों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) माना जाता है। वोक्कालिगा समुदाय को भी 1974 से कर्नाटक में पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, नरेंद्र मोदी घांची जाति (तेल मिल मालिक) से संबंध रखते हैं, जो गुजरात में ओबीसी हैं।

xix श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जे. आर. जयवर्धने ने एक बार कहा था: निरुपमा सुब्रमण्यम,

'स्पष्टीकरण: श्रीलंका में होने वाले संवैधानिक परिवर्तन और उसकी तमिल राजनीति की चिंता', इंडियन एक्सप्रेस, 13 सितंबर 2020।

xx 'दरअसल, नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री ही करते हैं': भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक से कहा। भारती जैन ने कहा, 'इसमें केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही शामिल हैं', 'पीएमओ के पास पूरी शक्ति है'।

नौकरशाही नियुक्तियों पर नियंत्रण', टाइम्स ऑफ इंडिया, 14 अगस्त 2014।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के लिए धन्यवाद: प्रशांत भूषण,

'सीबी और ईडी को कमजोर करने का केंद्र का कदम उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के वर्षों के प्रयासों को निष्फल करता है', द वायर, 24 नवंबर 2021।

xx 'अनौपचारिक स्तर पर बहुत सी चीजें संभव हो पाती हैं': भुवनेश चतुर्वेदी ने

लेखक से कहा।
मई 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए उसे एक
'पिंजरे में बंद तोता' और 'उसके मालिक की आवाज': रॉस कोल्विन और सतरूपा भट्टाचार्य, 'एक "पिंजरे में बंद तोता" - सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का वर्णन किया', रॉयटर्स, 10 मई 2013।
मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक अतिरिक्त साधन के रूप में शामिल किया:
सुप्रिया शर्मा और अरुणभ सैकिया, 'मोदी सरकार ने ईडी का किस प्रकार दुरुपयोग किया है'
'भारत के विपक्ष के पीछे पड़ो', स्क्रॉल डॉट इन, 5 जुलाई 2022।
xxi संविधान में आपातकाल की स्थिति लागू करने का प्रावधान भी है: अनुच्छेद 352 संविधान में असाधारण परिस्थितियों—जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह —में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, जो देश की सुरक्षा, शांति और स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं।
xxi ने कांग्रेस द्वारा संचालित नौ राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया: अरुल बी. लुईस और प्रभु चावला।
'प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नौ राज्यों में सरकारों को बर्खास्त किया, कांग्रेस को सत्ता में लाने की कोशिश', इंडिया टुडे, 15 मार्च 1980।
xxi ने 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' समझा: सुहरित पार्थसारथी, 'एक विरोधी-संवैधानिक निर्णय', द हिंदू, 30 अक्टूबर 2015।
xxi इसे 2015 में रद्द कर दिया गया था: राहेल फिलिपोस, 'कॉलेजियम बनाम एनजेएसी: नया रूप क्या है?'
न्यायाधीशों की नियुक्ति पर बहस?', इंडियन एक्सप्रेस, 17 दिसंबर 2022।
xxi 'ड्यू डिलिजेंस' करने की '360 डिग्री' प्रक्रिया: प्रणब ढाल सामंता, 'व्यू: एक नया सीजेआई'
इससे भारत सरकार को न्यायिक सुधारों में एक और प्रयास करने का मौका मिलता है, इकोनॉमिक टाइम्स, 18
नवंबर 2019; सौरव रॉय बर्मन, 'सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्तियों में "कभी

जानबूझकर" देरी नहीं की: रिजिजू', इंडियन एक्सप्रेस, 4 फरवरी 2022।
xxii न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका की मांग के साथ: रूपम जैन और
अर्पण चतुर्वेदी, 'न्यायिक नियुक्तियों में सरकार की बड़ी भूमिका की मांग से भारतीय न्यायाधीश चिंतित', रॉयटर्स, 19 जनवरी 2023।
xxii ने परिवार के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा करने वाली किताब लिखी: किताब का शीर्षक था 'रेमिनिसेंस ऑफ द'
नेहरू युग। चंद जोशी, 'पुस्तक समीक्षा: एम.ओ. मथाई द्वारा नेहरू युग की यादें', 28 फरवरी 1978, इंडिया टुडे।
xxiii मिश्रा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे, को अक्सर वास्तविक प्रमुख कहा जाता था: के.पी. नायर,
'शक्ति सिन्हा स्वभाव से राजनीतिज्ञ थे, और जिन मुद्दों पर उन्हें विश्वास था, उनके लिए वे एक जुझारू योद्धा थे।'
moneycontrol.com, 8 अक्टूबर 2021।
xxiii मनमोहन सिंह का पीएमओ 'निर्विवाद' और 'दब्बू' था: विजयराज सिंह, 'मोदी कैसे हैं'
प्रधानमंत्री कार्यालय में बदलाव किया', द स्टेट्समैन, 14 मार्च 2019।
xxiii नरेंद्र मोदी अपने पीएमओ के माध्यम से शासन करते हैं: अशोक उपाध्याय, 'पीएमओ में कितने लोग काम करते हैं?'
पीएम मोदी का कार्यालय? आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने यह कहा', इंडिया टुडे, 6 अगस्त 2021।
xxiii 'हाँ, फाइलें हैं': चंद्र शेखर ने लेखक को, 12 फरवरी 2000 को लिखा।
xxiii 'प्रधानमंत्री कार्यालय में राजनेताओं से संबंधित फाइलें हैं': भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक को 30 नवंबर को बताया
1999.
xxv Indira Gandhi used saam, daam, dand, bhed: Syed Mubin Zehra, 'Eternal Wisdom', The
सप्ताह, 27 दिसंबर 2015।
25. उन्होंने ताले खोलने में सक्षम बनाया: सनाया चंदर, 'राजीव गांधी: वह व्यक्ति

जिसने ताले खोले'
बाबरी मस्जिद में कई विवादों का पिटारा खुल गया है', क्वार्ट्ज, 9 नवंबर 2019।
xxv 'हिंदुओं के दिलों का बादशाह': साईसुरेश शिवस्वामी, 'राम मंदिर ने मोदी को पहले हिंदू के रूप में ताज पहनाया'
Hriday Samrat', Rediff.com, 4 August 2020.
xxv ने सरकार में 27 प्रतिशत नौकरियों के लिए आरक्षण की वकालत की: 'दूसरी रिपोर्ट'
पिछड़ा वर्ग आयोग', प्रथम भाग, खंड I, 1980, भारत सरकार।
xxv ओबीसी भारत की जनसंख्या का 52 प्रतिशत थे: वही।
26 क्या नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत की थी, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है?
जीवन प्रकाश शर्मा, 'प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उडुपी मठ प्रमुख ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान साजिश रची: भाजपा सांसद साक्षी महाराज', आउटलुक, 10 नवंबर 2019; सीतापति, 'बाबरी मस्जिद का पतन', हाफ लायन।
भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद के लिए प्रतीक्षारत रहे 26वें व्यक्ति: ए. बी. वाजपेयी से कृष्णकांत और रश्मि तक
कांट ने लेखक को मार्च 2021 में लिखा।
1979 में xxvi ने नरम रुख अपनाया: 'वाजपेयी ने 79 में परमाणु विकल्प का विरोध किया', फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 20
जनवरी 2004।
xxvii 'एशिया में स्थिरता का आधार': अज़ीज़ हनीफ़ा, 'भारत एशिया में स्थिरता का आधार है: अमेरिका'
विधायक', रेडिफ डॉट कॉम, 26 जुलाई 2009।
xxvii 'डॉक्टर साहब': IANS, 'मोदी ने संसद में मनमोहन सिंह पर हमला किया, कहा नोटबंदी अभूतपूर्व है'
विश्व में', बिजनेस स्टैंडर्ड, 9 फरवरी 2017।
xxvii 'आधा प्रधानमंत्री': तवलीन सिंह, 'वर्ग में जाति', इंडियन एक्सप्रेस, 15 जनवरी 2006।
xxvii गठबंधन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री भी बहुत शक्तिशाली होते हैं: 'गुजराल

का कहना है कि वह चाहते हैं...'
अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए', बिजनेस स्टैंडर्ड, 27 जनवरी 2013।

अध्याय 1: राख से उठकर प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी

वापसी का मंचन
1. 'मुझे लगता है कि मैं पहाड़ों पर जाकर वहीं रिटायर हो जाऊंगा': अनिल बाली ने लेखक से कहा।
1. 'आखिर मेरी ज़रूरतें क्या हैं?': वही।
1 वह अपने ही निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में भी हार गई थी: उसका निर्वाचन क्षेत्र, रायबरेली, था
उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित।
1 'भारत की साम्राज्ञी': डिएगो मैओरानो, 'साम्राज्ञी की दीर्घकालिक विरासतें', द हिंदू, 31
अक्टूबर 2014।
1. उत्तरी राज्यों की सभी 345 सीटों पर जीत: एस. वेंकट नारायण, 'जनता पार्टी सत्ता में'
इंडिया टुडे, 21 दिसंबर 2015।
1. 22 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था: हेनरी काम, 'सुश्री।
गांधी ने अपनी पार्टी के बहुमत खोने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया; प्रतिद्वंद्वियों ने स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली', न्यूयॉर्क टाइम्स, 22 मार्च 1977।
2. 'शायद, लेकिन फिर मेरी आत्मकथा कौन पढ़ना चाहेगा': अनिल बाली ने लेखक से कहा
2. 'हम यहां (85 में से) 70 सीटें जीत रहे हैं': अकबर अहमद 'डम्पी' ने लेखक से कहा।
2. 'मुझे वो उत्साह महसूस नहीं हो रहा जो पहले हुआ करता था': अनिल बाली ने 24 वर्षीय लेखक से कहा
नवंबर 2021, नई दिल्ली।

2 एक बार जब दिलीप कुमार चुनाव प्रचार करने आए थे: रवि नायर ने लेखक को लिखा, 23
दिसंबर 2021।
2. वह 'भ्रमित' हो गई थी: अनिल बाली ने लेखक से कहा।
2. 'घर की उपग्रह निगरानी को रोकने के लिए छत पर स्थापित उपकरण': वही।
3 'मुझे नहीं पता कि मैं अपने इन कालीनों के बारे में क्या करूँ': वही।
3. 'यह एक शिष्टाचार नहीं है जो वे पूर्व प्रधानमंत्री को दिखाएंगे': वही।
3 जनता सरकार ने आपत्ति नहीं जताई: रवि नायर ने लेखक को 1 जनवरी 2023 को लिखा।
3. 'मुझे संजय और उसकी सुरक्षा की चिंता है': अनिल बाली ने लेखक से कहा।
3 'वे उसे जीने नहीं देंगे': वही।
3. कोई ऑफिस कार नहीं थी, कोई स्टाफ कार नहीं थी: देबर्घ्य सान्याल, 'इंदिरा गांधी की झलकियाँ'
बिजनेस स्टैंडर्ड, 31 मई 2016, के. पी. माथुर द्वारा लिखित पुस्तक 'द अनसीन इंदिरा गांधी: थ्रू हर फिजिशियंस आइज', नई दिल्ली: कोनार्क पब्लिशर्स, 2015 का हवाला देते हुए।
4 'पुपुल, मैं हार गई': पुपुल जयकर, इंदिरा गांधी: एक जीवनी, नई दिल्ली: पेंगुइन पुस्तकें, 1995, पृष्ठ 320।
4 'जंगली उल्लास की रात': वही, पृष्ठ 325.
4. पांडे ने इंदिरा गांधी से इस नोट को मंजूरी दिलवाई: बी. डी. पांडे, स्वतंत्र भारत की सेवा में: संस्मरण
एक सिविल सेवक के बारे में, नई दिल्ली: स्पीकिंग टाइगर, 2021।
5. 'मैंने अपनी तरफ से जो कर सकता था वो कर लिया है। अब मैं शांति से जीना चाहता हूं': कमल नाथ ने लेखक से कहा।
5 'हाँ, हाँ, हाँ,' जट्टी ने कहा: पी. एन. धर, इंदिरा गांधी, 'आपातकाल' और भारतीय लोकतंत्र, दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000, पृष्ठ 356।
5. 'मेरे सहयोगी और मैं जनता के फैसले को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं': इंदर मल्होत्रा, 'फ्रॉम द
आर्काइव, 23 मार्च 1977: इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं', द गार्जियन, 23 मार्च

2015।
5. ‘संजय सक्रिय राजनीति से विदा लेंगे’: ए. एन. धर, ‘श्रीमती गांधी का इस्तीफा’, इंडियन एक्सप्रेस, 23
मार्च 1977।
5. ‘यदि मैंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कुछ किया हो तो मुझे खेद है’: मल्होत्रा, ‘पुरालेख से, 23 मार्च 1977:
इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं’, द गार्डियन।
5. ‘मैंने यह बात नागरकर से ही सुनी है’: रवि नायर ने लेखक से कहा, 23 दिसंबर 2021।
6 ‘इसे सावधानी से संभालना होगा’: वही।
6. ‘जेपी और प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की’: रवि नायर ने लेखक को बताया, 13 दिसंबर 2021।
6. ‘मैं हिमालय में सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ’: अनिल बाली ने लेखक से कहा।
6. 'एक माली ने हमें बताया कि संदूक [तना]': रवि नायर ने लेखक को, 13 दिसंबर 2021 को लिखा।
6 ने नौ राज्यों में कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त करने का फैसला किया: भगवान डी. दुआ, 'राष्ट्रपति चुनाव आयोग'
भारत में शासन: संकट राजनीति का एक अध्ययन’, एशियन सर्वे, खंड 19, संख्या 6, 1979, पृ. 611–26; रवि नायर, ‘भारत में तख्तापलट जो हुआ या कभी नहीं हुआ’, द लीफलेट, 12 जनवरी 2021।
6. जट्टी ने एक बार नहीं बल्कि दो बार अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया: नायर, 'भारत में हुआ तख्तापलट'
या फिर कभी था ही नहीं।
6 उसने सरकार को यह बात बता दी: विलियम बॉर्डर्स, ‘संवैधानिक संघर्ष का अंत
'कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत ने नौ राज्य विधानसभाओं को भंग करने का आदेश स्वीकार किया', न्यूयॉर्क टाइम्स, 1 मई 1977।
7. ‘चुनाव हारने की स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए नई दिल्ली में सेना भेजी जाए’: जेवियर मोरो, द
लाल साड़ी: सोनिया गांधी की एक नाटकीय जीवनी, नई दिल्ली: लोटस, 2015, पृ.

182.
7 ‘I have many armed paramilitary forces’: Jayakar, Indira Gandhi, p. 318.
7 उस दिन कई मंत्रियों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई: रवि नायर ने लेखक को बताया, 13
दिसंबर 2021।
7 उन्हें पता नहीं था कि क्या योजना बनाई जा रही है, लेकिन वे चाहते थे कि जॉर्ज 'सावधान रहे': नायर, 'द
भारत में तख्तापलट जो हुआ या कभी हुआ ही नहीं।
7. जॉर्ज फर्नांडीस ने रवि नायर को नई दिल्ली के 'सुरक्षा' क्षेत्रों का 'चक्कर' लगाने के लिए भेजा।
दिल्ली: वही।
8 वह वापस आया और जॉर्ज फर्नांडीस को ‘सब ठीक है’ की सूचना दी: वही।
8 ‘जॉर्ज को हम समाजवादी युवाओं में से 200-300 मिले’: वही।
8. इनमें से सात राज्यों में जनता पार्टी सत्ता में आई: 'जनता ने सात राज्यों में सत्ता हासिल की'
इंडियन एक्सप्रेस, 16 जून 1977।
8 देसाई आपातकाल और उसके अत्याचारों के लिए उस पर मुकदमा चलाने के लिए अनिच्छुक थे: रवि नायर
लेखक, 23 दिसंबर 2021।
8 अप्रैल 1977 तक, जनता सरकार ने आठ जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया:
क्रिस्टोफ़ जैफ़्रेलॉट और प्रतिनव अनिल, भारत की पहली तानाशाही, आपातकाल, 1975-77, नई दिल्ली: हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स, 2021, पृष्ठ 432।
8 ‘अति, कुप्रथाएं और सत्ता का दुरुपयोग’: विलियम बॉर्डर्स, ‘भारत नियोजन न्यायालय’
पदच्युत शासन के विरुद्ध सभी आरोपों की जांच करें’, न्यूयॉर्क टाइम्स, 8 अप्रैल 1977।
9 उन्होंने कहा कि यह मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी थी: जैफरेलॉट और अनिल,

भारत के पहले
तानाशाही, पृ. 434–35.
9. 'सूचना ही शक्ति है': अनिल बाली ने लेखक से कहा, 13 सितंबर 2020।
9. संजय को शाकाहारी भोजन पसंद था: अनिल बाली ने लेखक को बताया।
9 यह संजय उस किशोर से बिल्कुल अलग था जो अपने उग्र और मनमौजी स्वभाव के लिए जाना जाता था।
ways: Jayakar, Indira Gandhi, p. 294.
9 'क्या आप पियानो बजाना जानते हैं?': वही।
9 हरे और सफेद रंग की कुटिया के अंदर के कमरे: गेस्ट हाउस में अशोक मेहरोत्रा, जो
मोहन मीकिन के साथ सत्तावन वर्षों से जुड़े रहे लेखक का 26 सितंबर 2022 को सोलन में निधन हो गया।
9 'मैंने उसे बंदर टोपी पहना दी, ताकि लोग उसे पहचान न सकें': अनिल बाली ने लेखक से कहा, 6
नवंबर 2020।
9 'Log maarne ke liye taiyyar thae': Anil Bali to author, 6 November 2011.
10 'अगर जनता पार्टी ने संजय को अकेला छोड़ दिया होता': कमल नाथ ने नीरजा से कहा, 3 अगस्त 2021, न्यू
दिल्ली।
10. 'अपने चेहरे से रोने वाला भाव हटाओ': अंबिका सोनी ने लेखक से कहा, 26 सितंबर 2020।
10. मीडिया द्वारा 'सरकारी संत' कहे जाने वाले अशोक के. सिंह, 'नोटबंदी: मोदी'
लोगों को पता होना चाहिए कि वे उसे सत्ता से बाहर कर सकते हैं', डेलीओ, 14 नवंबर 2016। जैफरेलॉट और अनिल, भारत की पहली तानाशाही, पृष्ठ 26।
10 उन्होंने आपातकाल को 'अनुशासन पर्व' कहा था: जैफरेलॉट और अनिल, भारत के पहले
तानाशाही, पृष्ठ 26.
10 'मैं कभी बातचीत के लिए नहीं आया': 'चालीस साल पहले, 27 जुलाई, 1977:

मोरारजी की माफी', भारतीय
एक्सप्रेस, 27 जुलाई 2017।
10 'Morarji Desai, Charan Singh, and Jagjivan Ram are big egoists': Anil Bali to author.
11 उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनकी जीत को चुनौती दी: 'राज नारायण; एकमात्र राजनेता जो
'भारत की इंदिरा गांधी को हराओ', लॉस एंजिल्स टाइम्स, 2 जनवरी 1987।
11 जिन्हें दिग्गज-विध्वंसक के रूप में सराहा गया: जनार्दन ठाकुर, प्रधान मंत्री: नेहरू से वाजपेयी तक, मुंबई:
ईश्वर प्रकाशन, 1999, पृ. 187.
11 'श्रीमती गांधी के सत्ता से बाहर होने के बाद संजय परिपक्व हो गए थे': जगमोहन मल्होत्रा ने लेखक से कहा।
11 इसमें, इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए अन्य कदमों की तरह, संजय प्रमुख सूत्रधार थे: अनिल बाली
लेखक।
11 वह 2 फरवरी 1977 को कांग्रेस से उनके बाहर निकलने की घटना को नहीं भूल सकीं: विलियम बॉर्डर्स,
11 Jayaprakash Narayan who had called her a 'dictator': 'Indira Gandhi meets Jayaprakash
नारायण', इंडिया टुडे, 15 सितंबर 1977।
11 यह वही व्यक्ति था जिसे उसने 25 जून 1975 को जेल में डाला था: संध्या रविशंकर और
ईटी ब्यूरो, 'संडे ईटी: 'जयप्रकाश नारायण द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए कुछ अनूठे पत्रों पर एक नज़र, जब उन्हें जेल में एकांत कारावास में रखा गया था', इकोनॉमिक टाइम्स, 29 जून 2015।
12. कुछ आरएसएस नेताओं ने कपिल मोहन के माध्यम से संजय से संपर्क किया था: अनिल बाली ने लेखक से संपर्क किया था;
सुभाष आर्य ने लेखक को लिखा।
12 इंदिरा गांधी के जीवन को प्रभावित करने वाले पाँच पुरुष थे: रामचंद्र गुहा, 'द मेन

इन'
इंदिरा का जीवन', टाइम्स ऑफ इंडिया, 13 मई 2007।
12 लेकिन, उनकी मां पर सबसे अधिक शक्ति उनके पुत्र संजय गांधी के पास थी: बी.
एन. टंडन, पीएमओ डायरी।
12 वह उसका 'अंधा धब्बा' था: धर, इंदिरा गांधी, 'आपातकाल', और भारतीय लोकतंत्र, पृ.
341.
12 उसका उस पर 'बहुत कम नियंत्रण था': वही, पृष्ठ 329 और पृष्ठ 341।
12. 1950 के दशक के उत्तरार्ध में, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के प्रभाव में आकर उनका झुकाव दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर हो गया: रवि
Visvesvaraya.
13 कट्टर साम्यवाद-विरोधी संजय गांधी: 'पुरालेख से | अगर संजय गांधी होते
'रहते थे', इंडिया टुडे, 25 जून 2018।
13 'उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाले एकमात्र गुण वाले नियम हमें अधिक समाजवादी नहीं बनाते':
लोकसभा वाद-विवाद (अंग्रेजी संस्करण): आठवां सत्र (सातवीं लोकसभा)', खंड XXIV, संख्या 8, नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय, 1 मार्च 1982, पृष्ठ 382, उपलब्ध है
<https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/3447/1/
lsd_07_08_01-03-1982.pdf>.
13 'मेरी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं किसी विचारधारा में विश्वास करता हूँ': वेल्स हैंगन।
नेहरू के बाद, कौन?, लंदन: रूपर्ट हार्ट-डेविस, 1973, पृ. 181.
13. जैफ्रेलॉट के अनुसार, 'धार्मिकता और राष्ट्रवाद' उनके प्रधानमंत्रित्व काल के 'मार्गदर्शक सिद्धांत' बनने वाले थे।
और अनिल, भारत की पहली तानाशाही, आपातकाल, पृष्ठ 278।
13 'हिंदू दर्शन और भारत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता': वही।
13 यद्यपि एक 'विचारधारा-मुक्त' नेता: वही, पृष्ठ 284।

13 ‘गहरी शर्मिंदगी के कारण, इंदिरा गांधी ने खतरे का सामना करने पर फिर कभी घबराहट नहीं दिखाई’: इंदिरा गांधी, आनंद
भवन मेमोरीज, नई दिल्ली: इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, 2006, पृष्ठ 71।
14. तीन साल की इंदिरा उसकी गोद में बैठी थी जब उसने अदालत में अपना बचाव करने से इनकार कर दिया: कैथरीन
फ्रैंक, इंदिरा: इंदिरा नेहरू गांधी का जीवन, लंदन: हार्परकॉलिन्स पब्लिशर्स, 2001, पृष्ठ 21।
14 ‘हमारा मानना है कि यह भारतीय जनता का अविभाज्य अधिकार है’: जवाहरलाल नेहरू, एक
आत्मकथा, नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
पृष्ठ 612, <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.98834> पर उपलब्ध है।
14. इंदिरा को इस बात का एहसास होने लगा था कि नेहरू परिवार में उनकी मां को कितने अपमान सहने पड़ते थे:
सागरिका घोष, ‘क्रांति की संतान’, इंदिरा: भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, नई दिल्ली: जगर्नॉट, 2018।
14 ‘It was an extremely insecure childhood’: Jayakar, Indira Gandhi, p. 36.
14 ‘मैं जुलूसों और सभाओं और जो कुछ भी हुआ, उसका हिस्सा था’: वही।
14 ‘जिसने छत्तीस साल बाद एक महिला प्रधानमंत्री को संभव बनाया’: वही, पृष्ठ 35.
15 ‘अपने पति की परछाई’: प्रोमिला कल्हन, ‘एक नया रिश्ता’, कमला नेहरू: एक अंतरंग जीवनी, दिल्ली: विकास प्रकाशन गृह, 1973, पृष्ठ 45।
15 ‘वह अस्थिर थे’: फ्रैंक, इंदिरा: इंदिरा नेहरू गांधी का जीवन, पृ. 111.
15 ‘वह हमेशा मेरे लिए मौजूद था’: वही, पृष्ठ 114.
15. फिरोज 'जोरदार, उद्दंड और अपशब्दों का अत्यधिक प्रयोग करने वाला' था। नेहरू मृदुभाषी और सूक्ष्म स्वभाव के थे।
और क्रोधित होने पर भी कभी अपशब्द नहीं कहे’: फ्रैंक, इंदिरा: इंदिरा नेहरू गांधी का

जीवन, पृ.
169.
15 ‘केवल मेरी या नेहरू की नज़रों के लिए’: नारायण देसाई के बेटे अफलातून देसाई ने लेखक से टेलीफोन पर बातचीत में कहा
वाराणसी से साक्षात्कार, 17 जुलाई 2021।
15 ‘बड़ौदा स्टेशन पर मुझसे मिलो’: वही।
16 ‘यह बात आप तक पहुंचाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी’: वही।
16 इंदिरा और फ़िरोज़ का विवाह राम नवमी के दिन 26 मार्च 1942 को हुआ था: फ्रैंक, इंदिरा, पृ.
176.
16 गांधी ने प्रस्ताव को ‘एक विफल बैंक पर पोस्ट-डेटेड चेक’ कहा: वही, पृष्ठ 79।
16 ‘उन्हें उसका बगीचा, उसके शिकार के ट्राफियां, उसके मछली पकड़ने के उपकरण दिखाओ’: बर्टिल फाल्क, फिरोज गांधी:
द फॉरगॉटन गांधी, रोली बुक्स, 2016।
17 ‘संजय और राजीव…ने अपने दादा को उनके रिश्ते के टूटने के प्रमुख कारणों में गिना।
उनका पारिवारिक जीवन’: विनोद मेहता, द संजय स्टोरी: फ्रॉम आनंद भवन टू अमेठी, नई दिल्ली: हार्परकॉलिन्स, 2012, पृ. 55.
17 उसने अपने पिता की ‘उपेक्षा और मृत्यु’ के लिए अपनी माँ को दोषी ठहराया: जयकर, इंदिरा गांधी, पृ.
293.
17 ‘लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि पापू मुझ पर कितना निर्भर था’: वही, पृष्ठ 168।
17 कई लोगों ने इंदिरा को उसके पिता तक पहुँचने का एक सुविधाजनक माध्यम माना: फ्रैंक, इंदिरा, पृ. 236–37.
17 यह इंदिरा की ‘निर्दयता’ का पहला प्रदर्शन भी था: वही, पृष्ठ 253।
17 ‘केरल में अशांति…ने उसकी संवेदनशील नस को छू लिया’: वही।
17 इंदिरा ने बंबई राज्य के विभाजन को लेकर उनसे मतभेद किया था: वही, पृष्ठ 256।
18 ‘एक संत जो राजनीति में भटक गया था’: ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ. 104.

18 वह खुद को एक ‘कठोर राजनीतिज्ञ’ मानती थी: वही।
18 ‘Mera baap sant thaa, main nahin hoon’: Related by I. K. Gujral, part of Indira Gandhi’s
पत्रकार कुर्बान अली ने 12 जून 2022 को एक टेलीफोन साक्षात्कार में लेखक को बताया कि उस समय वह 'किचन कैबिनेट' हुआ करता था।
18 ने उसके विरोधियों के ‘सिंडिकेट’ के साथ हाथ मिलाया: सिंडिकेट एक ऐसा शब्द था जिसका प्रयोग किया जाता था
नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के उन नेताओं के समूह के लिए, जिन्होंने पार्टी पर अटूट पकड़ बनाए रखी और कई राज्य कांग्रेस समितियों को नियंत्रित किया, इस समूह में तमिलनाडु से के. कामराज, महाराष्ट्र से एस. के. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष, ओडिशा से बिजू पटनायक और कर्नाटक से एस. निजलिंगप्पा शामिल थे।
18 नेहरू ने हल्के ढंग से ‘अस्वीकार’ किया: फ्रैंक, इंदिरा, पृ. 250.
18 ‘क्या आपको लगता है कि यह सरकार टिक पाएगी’: वही, पृष्ठ 281.
18 ‘लाल बहादुर शास्त्री का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है’: आई. के. गुजराल, मैटर्स ऑफ
विवेक: एक आत्मकथा, नई दिल्ली: हे हाउस, 2017, पृ. 38.
18 ‘श्रीमती गांधी चाहती हैं कि आप तुरंत आएं’: वही, पृष्ठ 39.
19 ‘श्रीमती गांधी काफी उत्साहित थीं’: वही।
19 उन्होंने उससे कहा कि वह ‘प्रधानमंत्री चुनी जा सकती है’: वही।
19. इलाहाबाद से 'हैट ट्रिक' करने वाले एक व्यक्ति ने इंदिरा गांधी की ओर इशारा किया: वहाँ मौजूद एक राजनीतिक विश्लेषक ने इंदिरा गांधी की ओर इशारा किया।
गांधी ने पत्रकार निखिल चक्रवर्ती से कहा कि इलाहाबाद से 'हैट्रिक' आ गई है। फ्रैंक, इंदिरा, पृष्ठ 285 में भी देखें।
19 उसने देसाई के 169 वोटों के मुकाबले 355 वोट जीते: फ्रैंक, इंदिरा, पृ. 292.
19 ‘यह एक शानदार जनसंपर्क अभियान था’: नटवर सिंह।
19 ‘यह छोकरी’: चंद्र, मुखर्जी और मुखर्जी, स्वतंत्रता के बाद से भारत: संशोधित और
अपडेट किया गया।

19 ‘goongi gudiya’: Frank, Indira, p. 296.
19 ‘एक निर्दोष व्यक्ति’: ‘1966: मानसून के कारण भारत का खाद्य उत्पादन फिर से कम हो गया’
'विफलता', 2 जुलाई 2007, इंडिया टुडे।
20 ‘बिना मांगे भोजन और विदेशी मुद्रा दोनों प्राप्त करें’: फ्रैंक, इंदिरा, पृ.
296.
20 ‘नया, फूला हुआ हेयरस्टाइल, पूरा मेकअप और आभूषण’: वही, पृ. 296–97.
20 जॉनसन ने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि 'इस लड़की को कोई नुकसान न पहुंचे': वही, पृष्ठ 297।
20 ‘व्हाइट हाउस भोज में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ डांस फ्लोर पर चक्कर लगाना’: वही।
20 ‘उनके प्रधान सचिव एल. के. झा ने ही मुद्रा अवमूल्यन के उनके निर्णय को प्रभावित किया था’:
Natwar Singh to author.
20 ‘एक बड़े आदमी की बेटी, एक छोटे आदमी की गलती’: फ्रैंक, इंदिरा, पृ. 299.
20 उसने अमेरिका की वियतनाम नीति पर ‘साम्राज्यवादी आक्रामकता’ के रूप में हमला करना शुरू कर दिया: वही।
20 उन्होंने भारत को गेहूं की आपूर्ति को पीएल 480 कार्यक्रम के तहत रखा: 1954 में, अमेरिकी राष्ट्रपति
ड्वाइट डी. आइजनहावर ने कृषि व्यापार विकास और सहायता अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे लोकप्रिय रूप से लोक कानून 480 या शांति के लिए भोजन कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। लोक कानून 480 ने 'मित्र देशों' को अपनी मुद्रा में अमेरिका से खाद्य पदार्थ खरीदने में सक्षम बनाया, जिससे उनकी विदेशी मुद्रा की बचत हुई। इस कार्यक्रम का उपयोग विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में करने वाले अमेरिका को अपने अतिरिक्त अनाज से छुटकारा पाने में भी मदद मिली।
21 ‘नया भारतीय नेता भीख मांगने आया’: ‘1966: भारत का खाद्य उत्पादन फिर से घट गया
मानसून की विफलता के कारण’, इंडिया टुडे।
21 अंततः इसी से हरित क्रांति का जन्म हुआ: भारत में हरित क्रांति के कारण वृद्धि

हुई
खाद्य उत्पादन में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग, विशेष रूप से चावल और गेहूं के लिए, प्रतिवर्ष दोहरी फसल उगाना, और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग शामिल है।
21 'हाँ, बिल्कुल, हाँ,' पी. एन. हक्सर ने उत्तर दिया: रमेश, इंटरट्विन्ड लाइव्स।
21 वह उसके बेटों का स्थानीय संरक्षक था: वही।
21 'स्वतंत्रता के बाद देश की सबसे शक्तिशाली नौकरशाह': वसुधा वेणुगोपाल, 'इंदिरा'
Gandhi was the leader but sootradhar of 1971 was PN Haksar: Jairam Ramesh', Economic Times, 15 June 2018.
21 भुवनेश चतुर्वेदी को 'प्रधानमंत्री कार्यालय का जनक' माना जाता है: लेखक से।
21 उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में एक नोट प्रसारित किया: रमेश, आपस में जुड़े हुए
लाइव्स, पृ. 139.
21 'भारत सरकार के सबसे अच्छे गुप्त रहस्यों में से एक': नटवर सिंह का उद्धरण घोष में दिया गया है।
इंदिरा, पृष्ठ 109.
22 'अंतरात्मा का मत': रामचंद्र गुहा, गांधी के बाद भारत: विश्व का इतिहास
सबसे बड़ा लोकतंत्र, लंदन: पैन बुक्स, 2012, पृष्ठ 438।
22 'अनुशासनहीनता': फ्रैंक, इंदिरा, पृ. 316–17.
22 ये 278 राजकुमारों को दिए गए कर मुक्त विशेषाधिकार और भत्ते थे: वही, पृष्ठ 323।
22 रणनीति की मूल रूपरेखा हक्सर ने ही तैयार की थी: रमेश, इंटरट्विन्ड लाइव्स, पृष्ठ 206–207; नटवर सिंह द्वारा लेखक को, 29 मई 2022।
22 भारत ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित और समर्थन दिया: रमेश, इंटरट्विन्ड लाइव्स, पृ. 209.
22 'Kashmir mafia': Natwar Singh to author, 29 May 2022.
23 रमेश के अनुसार, वह अपने 'सर्वोत्तम जुझारू रूप' में थीं और 'निक्सन के साथ सारी बातचीत उन्होंने ही की'।

अंतर्संबंधित जीवन, पृष्ठ 228।
23 अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें 'दुर्गा' कहकर संबोधित किया: हालांकि बाद में वाजपेयी ने इस बात से इनकार किया। कांग्रेस नेता
भुवनेश चतुर्वेदी ने नई दिल्ली में मुझसे हुई बातचीत के दौरान खुलासा किया कि वह उस बैठक में मौजूद थे जहां वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को 'दुर्गा' कहा था।
23 'इंदुजी' और 'बाबूजी' के बीच का समीकरण: रमेश, इंटरट्विन्ड लाइव्स, पृ. 78, 82, 83.
23 उन्होंने मारुति का नेतृत्व किया, जो एक छोटी 'लोगों की कार' बनाने की परियोजना थी: शर्मिष्ठा मुखर्जी, '40
कुछ साल पहले...और अब: आम लोगों की कार का जन्म कैसे हुआ, और यह कैसे वैसी ही बनी रही', बिजनेस स्टैंडर्ड, 19 नवंबर 2014।
23 'आपको अपना मन बनाना होगा': नटवर सिंह ने लेखक से कहा।
23 यह दरार काफी समय से पनप रही थी: रमेश, इंटरट्विन्ड लाइव्स, पृ. 381.
23 'वह कहा करते थे कि कम्युनिस्टों को समुद्र में फेंक देना चाहिए': अनिल बाली ने लेखक से कहा।
23 'मौन आलोचक': रमेश, अंतर्संबंधित जीवन।
23 'वैचारिक दिशासूचक': वही।
24 'जैसे युद्ध में, वैसे ही शांति में, कला हमेशा शत्रु को जीतने में निहित होती है': वही, पृष्ठ 387।
24 और उन्होंने पत्र पर 'इंदिरा गांधी' के नाम से हस्ताक्षर किए: वही, पृष्ठ 388।
24 जब वह संजय के साथ गर्भवती थी तब वह वास्तव में एक लड़की चाहती थी: अनिल बाली ने लेखक को बताया।
24 वह अपने दादा के घर में गमले तोड़ा करता था: वही।
24 'राजीव विनम्र, अच्छे व्यवहार वाला और एक अच्छा छात्र था; संजय विद्रोही और विध्वंसक था':
Jayakar, Indira Gandhi, p. 294.
25 हालाँकि, उन्होंने तीन वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा नहीं किया: मेहता, संजय कहानी, पृष्ठ 65।
25. हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल ने 297 एकड़ भूमि देकर सहायता की: जे.

एंथोनी लुकास।
‘भारत वही है जो इंदिरा करती हैं’, न्यूयॉर्क टाइम्स, 4 अप्रैल 1976।
25. पचास हजार कारों का उत्पादन किया जाना था—अक्टूबर 1973 तक 10,000 और 1974 तक 25,000:
माइकल हेंडरसन, असत्य के साथ प्रयोग: आपातकाल के तहत भारत, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास: द मैकमिलन कंपनी ऑफ इंडिया, 1977, पृ. 14.
25. 14 दिसंबर 1983 को, जब एक छोटी सी सफेद मारुति 800 गुड़गांव के एक कारखाने से निकली:
अनिल सासी, ‘मारुति सुजुकी 800: बिना नाम वाली कार’, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 23 फरवरी 2014।
25 सुबह 6 बजे के कुछ देर बाद, उन्हें खबर मिली कि डी. पी. धर का निधन हो गया है: धर, इंदिरा गांधी,
‘आपातकाल’ और भारतीय लोकतंत्र, पृ. 300.
26 ‘इलाहाबाद का फैसला आ गया है और प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया है’: वही।
26. न्यायालय ने उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दोषी ठहराया: सत्य प्रकाश।
‘अदालती फैसला जिसने इंदिरा गांधी को आपातकाल घोषित करने के लिए प्रेरित किया’, हिंदुस्तान टाइम्स, 26 जून 2015।
26. इंदिरा गांधी दोनों समूहों के बीच घूमती रहीं, और 'असंवादित और एकांतप्रिय' प्रतीत हुईं:
वही, पृष्ठ 301।
26 ‘जिस दिन इलाहाबाद का फैसला आया’: करण सिंह ने लेखक से कहा।
26 ‘उसने एक शब्द भी नहीं कहा’: वही।
26 दो समूह ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि वह इस्तीफा दे: वही।
27 ‘हालांकि, न्यायमूर्ति सिन्हा की प्रबल अंतरात्मा ने उन्हें प्रलोभन में आने की अनुमति नहीं दी’: प्रकाश,
‘अदालत का वह फैसला जिसने इंदिरा गांधी को आपातकाल घोषित करने के लिए प्रेरित किया’।

27 जनता मोर्चा ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया: रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद, 12 जून 1975: वह दिन जिसने भारत को बदल दिया, इंदिरा गांधी को झकझोर दिया', ओपन, 13 जून 2022।

27 राष्ट्रपति ने रात 11.45 बजे आपातकालीन अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए: कूमी कपूर, 'केवल शासक ही है'

कोई जवाबदेह नहीं, सत्ता के आगे झुकने वाला हर व्यक्ति कम दोषी नहीं है', इंडियन एक्सप्रेस, 25 जून 2020।

27 बैठक सुबह 5 या 6 बजे आयोजित की गई थी: पांडे, स्वतंत्र भारत की सेवा में, पृष्ठ 140।

27 मंत्रिमंडल ने अगली सुबह इसकी पुष्टि कर दी: तकनीकी रूप से कहें तो, व्यावसायिक नियम, शासन करने के लिए

सरकार और उसके विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रधानमंत्री को निर्णय लेने और बाद में मंत्रिमंडल से उसे अनुमोदित कराने की अनुमति दी गई थी। भारत सरकार (कार्य संचालन) नियमों के नियम 7 के अनुसार, दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों, जिनमें आपातकाल की घोषणा से संबंधित मामले भी शामिल हैं, को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। हालांकि, कार्य संचालन नियमों के नियम 12 में कहा गया है कि 'प्रधानमंत्री किसी भी मामले या मामलों के वर्गों में, इन नियमों से विचलन की अनुमति दे सकते हैं या उसे माफ कर सकते हैं, जितनी हद तक वे आवश्यक समझते हैं।' प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय ले सकते हैं, बशर्ते कि बाद में अनुमोदन प्राप्त हो। देखें मोंटेक सिंह अहलूवालिया, 'स्वतंत्र भारत की सेवा में: स्वर्गीय बी. डी. पांडे द्वारा एक सिविल सेवक का संस्मरण', आईआईसी प्रोग्राम्स, 15 मार्च 2022, यूट्यूब पर उपलब्ध।

<https://youtu.be/qu8vAQKyuwg> पर।

27 'आपातकाल का विकल्प चुनने के उनके निर्णय में संजय का महत्वपूर्ण योगदान था': करण सिंह

लेखक को।

28 'Simhasan khali karo ki janata aati hai': '"Singhasan Khali Karo ki janata aati hai"- Dinkar

और जेपी का "पूर्ण क्रांति" का आह्वान', द लीफलेट, 26 जून 2020।

सरकार के 28 'अवैध और अनैतिक' आदेश: अमृत लाल, '40 साल बाद, वे 21 महीने'
'आपातकाल', द इंडियन एक्सप्रेस, 20 जुलाई 2015।
28 'विनाश काले विपरीत बुद्धि': ठाकुर, नेहरू से लेकर वाजपेयी तक, पृ. 105.
28 'जब मैं तानाशाह नहीं था तब भी तुम मुझे तानाशाह कहते रहे। अब हाँ, मैं तानाशाह हूँ।': हेंडरसन
असत्य के साथ प्रयोग, पृष्ठ 7।
29. हालांकि, मुखर्जी ने बाद में कहा कि आपातकाल को टाला जा सकता था: पीटीआई।
'आपातकाल को टाला जा सकता था: प्रणब मुखर्जी', इकोनॉमिक टाइम्स, 21 मई 2019।
29 'ऑल इंडिया रेडियो इंदिरा गांधी को पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं कर रहा है': आई. के. गुजराल ने लेखक को लिखा, न्यू
दिल्ली, 2 जुलाई 2003।
29 'आई एंड बी अब आपकी पसंद की चीज नहीं रही': वही।
29 'संजय आपको ऑस्ट्रेलिया में राजदूत बनाकर भेजना चाहता है': बी. एन. उनियाल ने लेखक से कहा।
29 'Youth Congress chala sakoge kya?': Tariq Anwar to author.
29 'अब हम किस रास्ते जाएं?': संतोष भारतीय ने लेखक से पूछा।
30 'कम बोलो और ज्यादा काम करो': '6 जुलाई, चालीस साल पहले: कम बोलो, ज्यादा काम करो', इंडियन एक्सप्रेस,
6 जुलाई 2015।
30 उन्होंने निर्मम 'सुंदरीकरण अभियान' शुरू किए: जॉन दयाल और अजय बोस, 'द बुलडोजर', फॉर रीजन्स ऑफ स्टेट: दिल्ली अंडर इमरजेंसी, नई दिल्ली: पेंगुइन रैंडम हाउस, 2018।
30 बुलडोजरों ने 150 पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया: वही।
30 उन्हें 24 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया: वही।
30 सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 70 लाख से अधिक पुरुषों की नसबंदी की गई:

लिन सी.
लैंडमैन, ‘भारत में जन्म नियंत्रण: गाजर और छड़ी?’, परिवार नियोजन परिप्रेक्ष्य, खंड 9, संख्या 3, 1977, पृ. 101–10.
30 किसानों को दबाव में बंध्याकरण कराने के मामले भी सामने आए: दयाल और बोस, 'द डेज़ ऑफ
'द लॉन्ग नाइफ्स', फॉर रीजन्स ऑफ स्टेट: दिल्ली अंडर इमरजेंसी।
31 ‘चुनाव कराना कितनी बड़ी गलती रही है’: अकबर अहमद ‘डम्पी’ ने लेखक से कहा, 22
जनवरी 2021।
31 ‘संजय मैटाडोर चला रहा था और मैं बैठा था’: वही।
31 ‘लेकिन इंदिरा गांधी अड़ी हुई थीं’: वही।
31 ‘मैं जनता सरकार को तीन साल नहीं देता’: वही।
रवि ने कहा, "आईबी द्वारा 340 सीटें जीतने की बात कहे जाने के बावजूद, वह जानती थी कि वह हार जाएगी।"
विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद, ‘इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में चुनाव क्यों करवाए?’, ओपन, 23 जनवरी 2022।
32 ‘मेरे पिता को अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया’: वही।
32 ‘चुनाव बुरी तरह हार गए, और वह अपने बेटे संजय गांधी को लेकर चिंतित थीं’: रवि
विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद, 'इंदिरा गांधी ने 1977 के चुनाव क्यों बुलाए, इसकी अंदरूनी कहानी', हिंदुस्तान टाइम्स, 19 मार्च 2021।
32 ‘ये गोरे लोगों से लिखवाओ’: मोहन गुरुस्वामी, जिन्होंने चंद्र के साथ मिलकर काम किया था
जनता पार्टी के शेखर ने लेखक से टेलीफोन पर साक्षात्कार लिया, 23 मई 2022।
32 विश्व बैंक उनके औद्योगिक संबंधों के प्रबंधन से प्रभावित हुआ: जैफरेलॉट और अनिल,
भारत की पहली तानाशाही, आपातकाल, पृष्ठ 415।
32 ‘Right action is necessary’: Jayakar, Indira Gandhi, p. 312.
32 ‘यह 28 अक्टूबर (1976) को था कि एक कमजोर आंदोलन’: वही।

33 ‘क्या आप अंततः फरवरी 1977 तक चुनाव कराएंगे?’: गौतम बजाज ने लेखक पौनार से पूछा
Ashram, Wardha, Maharashtra, 8 November 2022. Gautam Bajaj was the son of veteran Gandhian Radhakrishna Bajaj, related to Jamnalal Bajaj who Gandhi used to look upon as his fifth son.
33 ‘इंदिरा गांधी को विनोबाजी के प्रति आदर और स्नेह था’: वही।
33 ‘यह (संजय द्वारा) प्रधानमंत्री को दरकिनार करने का एक साहसिक प्रयास था: धर, इंदिरा गांधी,
‘आपातकाल’ और भारतीय लोकतंत्र, पृ. 329.
33 ‘ड्राइवर की सीट के लिए अधीर’: वही।
33 ‘मुझे यह स्पष्ट था…कि इंदिरा गांधी…अपने बेटे से डरती थीं’: वही।
34 ‘उसके बारे में एक भी आलोचनात्मक शब्द सुनना’: इंदर मल्होत्रा, ‘आपातकाल का अचानक अंत’, भारतीय
एक्सप्रेस, 4 अगस्त 2014।
34 ‘इस चुनावी बकवास को खत्म करो…बस हमारी बहन (इंदिरा) को आजीवन राष्ट्रपति बना दो’: ‘से
अभिलेखागार | अगर संजय गांधी जीवित होते’, इंडिया टुडे।
34 यह 5 नवंबर 1976 को हुआ था: मल्होत्रा, 'आपातकाल का अचानक अंत'।
35 ‘संविधान की आड़ में एकदलीय तानाशाही’: समर मुखर्जी ने बोलते हुए कहा लोकसभा में 1 सितंबर 1976 को दिए गए भाषण का हवाला माइकल हेंडरसन की पुस्तक 'एक्सपेरिमेंट्स विद अनट्रुथ: इंडिया अंडर इमरजेंसी', दिल्ली: मैकमिलन, 1977, पृष्ठ 181 में दिया गया है।
35 ‘तभी उन्होंने चुनावों के बारे में सोचना शुरू किया’: मल्होत्रा, ‘आपातकाल का अचानक अंत’।
35 ‘तुम्हें चरण सिंह के बगल वाली कोठरी में रखा जाएगा’: सत्यपाल मलिक ने लेखक से कहा।
35 ‘वह इस विचार के प्रति प्रतिकूल नहीं था’: वही।
35 'तो, बीजू पटनायक, पीलू मोदी, राधाकृष्णन जैसे अन्य लोग': वही।

35 केवल एक बार ही वे आवेश में आकर तीव्र भाषण देने लगे थे: वही।
मूल भाषण चरण सिंह अभिलेखागार के हिस्से के रूप में उपलब्ध है।
<www.charansingh.org/archives/historical-speech-hindi-uttar-pradesh-vidhan-sabha>.
36 चरण सिंह और उनके अलावा, ओम मेहता और मोहम्मद यूनुस भी थे: सी.जी.के. रेड्डी, 'परिशिष्ट 5', बड़ौदा डायनामाइट षड्यंत्र: विद्रोह का अधिकार, नई दिल्ली: विकास बुक्स, 1977।
36 उन्होंने 'जिम्मेदारी से व्यवहार करने' पर सहमति जताई: सत्यपाल मलिक ने लेखक से कहा।
36 वह कभी-कभी निगरानी में बाहर जा सकता था: राम बहादुर राय ने लेखक को 4 जुलाई को लिखा
2022.
37 'अफसोस जताने का कोई सवाल ही नहीं है': वही।
37 जेपी ने विपक्षी नेताओं से बार-बार एक एकीकृत पार्टी बनाने का आह्वान किया था: वही।
37 इस समय तक, आरएसएस ने सरकार के साथ सहयोग करने की पेशकश की थी: ए. जी. नूरानी, द
आरएसएस: भारत के लिए एक खतरा, नई दिल्ली: लेफ्टवर्ड बुक्स, 2019, पृ. 488–98.
37 'आइए स्पष्ट कर दें, इंदिरा गांधी ने चुनाव का विकल्प चुना': नटवर सिंह ने लेखक से कहा।
37. 1 जनवरी 1977 को, धर ने स्वामीनाथन को अपने घर आमंत्रित किया: धर, इंदिरा गांधी,
'आपातकाल' और भारतीय लोकतंत्र, पृ. 349.
37 उसी शाम उसने धर को व्हिस्की की एक बोतल भेजी: वही, पृष्ठ 350।
37 हालांकि, चुनाव की तारीख 'प्रधानमंत्री के ज्योतिषियों' द्वारा तय की गई थी: माल्होत्रा, 'आपातकाल का अचानक अंत'।
38 'ओम मेहता ने मुझे बताया था कि इंदिरा गांधी आपातकाल को वैध बनाना चाहती थीं': सत्यपाल

मलिक।
38 वह यह भी चाहती थी कि वह 'शिक्षुता की अवधि' पूरी करे: धर, इंदिरा गांधी, 'आपातकाल' और भारतीय लोकतंत्र, पृ. 329.
38 वह उन्हें 'भारत के उभरते बेटे' के रूप में प्रस्तुत करना चाहती थी: ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ. 119.
38 'हमारी प्रसिद्धि छिन गई है': धर, इंदिरा गांधी, 'आपातकाल' और भारतीय लोकतंत्र, पृष्ठ 345।
विपक्ष के चार सबसे बड़े संगठनों के 38 नेता: रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद, 'मोरारजी देसाई 1977 में प्रधानमंत्री कैसे बने', ओपन, 24 अप्रैल 2022।
39 'Jab se election announce hua hai, chaprasi theek se paani tak nahin pila rahe hain': Pran
सबहरवाल ने कुर्बान अली को यह संदेश भेजा, जिन्होंने इसे लेखक के साथ साझा किया, 12 जून 2020, नई दिल्ली।
39 'जब आप जनता तक सूचना के प्रवाह को रोकते हैं': के. एस. कोमिरेड्डी, मैलवोलेंट
गणतंत्र: नए भारत का संक्षिप्त इतिहास, चेन्नई: कॉन्टेक्स्ट, 2019, पृ. 22.
39 'कोई डीए नहीं, कोई वोट नहीं': दयाल और बोस, 'द डेन्यूमेंट', राज्य के कारणों के लिए: दिल्ली
आपातकाल।
39 'तुम्हारा बेटा कहाँ है?': वही।
39 जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, जनता पार्टी ने 298 लोकसभा सीटें जीतीं: 'सामान्य सांख्यिकी रिपोर्ट'
छठी लोकसभा के लिए 1977 के चुनाव: खंड I', दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 1978, <https://eci.gov.in/files/file/4116-general-election-1977-vol-i-ii/> पर उपलब्ध है।
39. जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी (सीएफडी), जिसने 28 सीटें जीतीं: रवि
विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद, 'कैसे मोरारजी देसाई ने जगजीवन राम और चरण सिंह को मात दी', खुला, 22 मार्च 2021।

39 इंदिरा कांग्रेस ने 154 सीटें जीतीं: 'आम चुनाव, 1977 पर सांख्यिकीय रिपोर्ट' छठी लोकसभा: खंड I'

41 जेपी शायद दो महीने से ज़्यादा टिक न पाए: संध्या रविशंकर, 'संडे ईटी: ए' 'जयप्रकाश नारायण द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए कुछ अनूठे पत्रों को देखें, जब उन्हें जेल में एकांत कारावास में रखा गया था', इकोनॉमिक टाइम्स, 29 जून 2015।

41 जब उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई, तो उनके नजरबंदी आदेश को रद्द कर दिया गया: हेंडरसन,
असत्य के साथ प्रयोग, पृष्ठ 31।

41 'मेरे कई मित्रों ने संदेह व्यक्त किया है, जिसे मैं भी साझा करता हूँ': रमा गोयल (संपादक), बचत
इंदिरा से भारत: आपातकाल की अनकही कहानी: जे. पी. गोयल के संस्मरण, नई दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स, 2019।

41 'संपूर्ण क्रांति': ललन तिवारी, लोकतंत्र और असहमति: (बिहार का एक केस स्टडी)
आंदोलन—1974–75), दिल्ली: मित्तल पब्लिकेशन्स, 1987, पृ. 260.

41 इसकी शुरुआत गुजरात के छात्रों द्वारा नव निर्माण आंदोलन के रूप में हुई थी: हेंडरसन, प्रयोग
असत्य के साथ, पृष्ठ 3.

41 'अब क्या?': छात्र युवा संघर्ष वाहिनी पर एक अप्रकाशित अध्ययन में उद्धृत,
नीरजा चौधरी, विश्व युवक केंद्र के लिए, 1980।

42 'अचानक हमें यह पोटली दिखी': कुमार प्रशांत ने लेखक को बताया, 16 जनवरी 2021
टेलीफोन पर बातचीत।

42 'I remember lines like "kuchh log apne aapko bahut superior samajhte hain"': Ibid.

42 'Tum bhagyashali ho ki tum se barabari se baat karte hain: Ibid.

43 वह इस मामले के प्रति अपनी पूर्ण उदासीनता दिखाने की कोशिश कर रही थी: वही।

43 इस बैठक में इंदिरा गांधी ने जेपी से 'उनकी मदद करने' के लिए कहा: वही।
44 'Kaise aana hua?': Kumar Prashant to author, 16 January 2021, telephonic conversation.
44 'यह कहना बकवास है कि वह पद नहीं चाहते थे': जयकर, इंदिरा गांधी, पृ. 391.
44 'प्रधानमंत्री ने श्री नारायण से कहा...कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उन्हें बताए कि वे कहाँ जा रहे हैं
wrong': Ravi Visvesvaraya Sharada Prasad, 'Nehru wanted Jayaprakash Narayan as his political successor, not Indira Gandhi', The Print, 27 May 2020.
44 'प्रधानमंत्री ने श्री नारायण से पूछा, उन्हें फुसलाया, फिर उनसे विनती की': वही।
45 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी) ने प्रस्ताव पर चर्चा की: वही।
45 बेतुल में पीएसपी की एक बैठक में—जहां उन पर सत्ता के भूखे होने का आरोप लगाया गया था: कुर्बान
अली लेखक बने।
45 'सही लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के सही साधन': धर, इंदिरा गांधी, 'आपातकाल' और भारतीय लोकतंत्र, पृष्ठ 246।
45 'confused': Jayakar, Indira Gandhi, p. 391.
45 'लेकिन इंदिरा गांधी ने सभी विपक्षी नेताओं के फोन भी टैप किए थे': कुमार प्रशांत से लेखक तक।
45 एक 'निजी' मुलाकात: '15 अगस्त, 1977, चालीस साल पहले: इंदिरा ने जेपी से मुलाकात की', इंडियन एक्सप्रेस,
15 अगस्त 2017।
45 'Jitna tumhara bhootkaal ujjwal raha hai, utna hee tumhara bhavishya bhee ujjwal ho': Ibid.
45 'Ghar aye ko dua dee jaati hai ya bad-dua deni chahiye': Kumar Prashant to author.
45 उन्होंने जनता सरकार को प्रदर्शन करने के लिए एक वर्ष का समय दिया था: अजय सिंह, 'मैं पूरी तरह से

जनता पार्टी के प्रदर्शन से निराश: जयप्रकाश नारायण', इंडिया टुडे, 31 मार्च 1978।
46 'मैं अब कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं': कुमार प्रशांत ने लेखक से टेलीफोन पर बातचीत में कहा
16 जनवरी 2021।
46 'मैंने उसे उसके कंधे पर हाथ रखते देखा': कुमार प्रशांत ने लेखक को बताया, 27 जनवरी 2021।
46 'Safalta aur vifalta ki paribhashayen bhinn hain meri': From 'Shodh ki manzilaen', a poem
यह लेख जयप्रकाश नारायण ने अगस्त 1975 में जेल में रहते हुए चंडीगढ़ में लिखा था।
46 'संजय, मैं और सुरेंद्र सिंह बैडमिंटन खेल रहे थे': अकबर अहमद 'डम्पी' ने लेखक से कहा।
47 उसे पहले ही सूचना मिल गई थी कि उसे गिरफ्तार किया जाने वाला है: रवि नायर ने लेखक को दिसंबर में लिखा पत्र।
2021.
47 'नूरेमबर्ग-शैली का परीक्षण': ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ. 158.
47 'हमें केवल कानून के अनुसार ही कार्रवाई करनी चाहिए': 'ऑपरेशन में गड़बड़ी? (31 अक्टूबर, 1977)', भारत
आज, 21 मई 2013।
47 'मुझे हथकड़ी लगाओ,' उसने पुलिस अधीक्षक पर चिल्लाया: ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ. 175.
47 'पांच राजा से चार रानी, पांच राजा से चार रानी': 'इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को जनता क्रांति के रूप में देखा जा रहा है'
पार्टी की पहली बड़ी राजनीतिक भूल', इंडिया टुडे, 2 अप्रैल 2015।
47 'मैडम...सीबीआई के लिए वारंट की प्रति देना आवश्यक नहीं है': ठाकुर, प्रधान मंत्री
मंत्रीगण, पृष्ठ 175.
47 एन. के. सिंह को गृह मंत्री चरण सिंह ने व्यक्तिगत रूप से चुना था: 'इंदिरा गांधी का

इस गिरफ्तारी को जनता पार्टी की पहली बड़ी राजनीतिक भूल के रूप में देखा जा रहा है।
48 'मैं ऐसा क्यों करूँ?' उसने पलटवार किया: ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ. 175.
48 फिर अचानक, उसका हट्टा-कट्टा, मूंछों वाला अंगरक्षक जीप के सामने लेट गया: वही।
पृष्ठ 176.
48 'सीबीआई उसे हरियाणा के भटकल (झील) की ओर ले जा रही थी': अकबर अहमद 'डम्पी'
लेखक।
48 'उन्होंने मुझे एक बार फिर धोखा दिया है': 'इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को जनता पार्टी की पहली घटना के रूप में देखा जा रहा है'
एक बड़ी राजनीतिक भूल।
48 'ये वो मामले नहीं हैं जिन पर हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए थी': वही।
49. उसे गिरफ्तार करके चरण सिंह ने सोचा कि वह हीरो बन जाएगा: ठाकुर, प्रधान मंत्री
मंत्रीगण, पृष्ठ 174.
49 'Ab aap Raj Narain se mil lo': Anil Bali to author.
49 'संजय कपिल मोहन के बहुत करीब हो गए थे': कमल नाथ ने लेखक से कहा।
49 वह अक्सर चरण सिंह के राम के लिए खुद को हनुमान कहते थे: चंदन मित्रा, ""घूमना
द्वार-प्रवेश की राजनीति भारतीय लोकतंत्र की पहचान बन गई थी", इंडिया टुडे, 26 दिसंबर 2005।
49 '1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा उन्हें एक आतंकवादी के रूप में देखा जाता था': आनंद कुमार
लेखक, टेलीफोन साक्षात्कार, 22 जून 2022।
49 'चौधरी साहब का अनुसरण करें': सुनील सेठी, 'राज नारायण होने का महत्व', इंडिया टुडे,
31 अगस्त 1979।
49 राज्य द्वारा नियुक्त मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू करना:

बिहार में मुंगेरी लाल आयोग, जिसने 1977 में अपनी रिपोर्ट दी थी, ने सुझाव दिया था कि ओबीसी को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाए: अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), जिसमें मुसलमानों के बीच कमजोर वर्ग भी शामिल थे, और पिछड़ा वर्ग।

50 'नपुंसक पुरुषों का संग्रह': इंदर मल्होत्रा, 'जनता का विघटन', भारतीय एक्सप्रेस, 15 सितंबर 2014।

50 'वे भाइयों की तरह थे': पुष्पा मोहन ने लेखक से कहा।

50 'राज नारायण अक्सर मुझे फोन करके कहते थे': वही।

51 'मेरा भविष्य क्या है?': कुर्बान अली ने लेखक से टेलीफोन पर बातचीत में पूछा, 22 अप्रैल 2022.

51 उन्होंने जानबूझकर खुद को 'निम्नवर्गीय' दिखाने के लिए एक देहाती छवि बनाई: डॉ. आनंद कुमार, पूर्व जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर, लेखक को, 22 जून 2022, टेलीफोन पर हुई बातचीत।

51 'Bol dena hum Raja Balwant Singh ke khaandan se hain': Dr Anand Kumar to author, टेलीफोन पर साक्षात्कार, 22 जून 2022। वे 1 अप्रैल 1980 को वाराणसी में एक बैठक में थे जब राज नारायण ने यह बात तब कही जब उन्हें चरण सिंह द्वारा बीएलडी से निष्कासित किए जाने की खबर मिली।

51 'तुम इत्र तो लगाते हो, लेकिन मेरे बारे में बदनामी फैलाते हो': कुर्बान अली ने लेखक से कहा, नई दिल्ली, 7 फरवरी 2023.

51 'मैं अक्सर कपिल मोहन के साथ कमरे के बाहर बैठता था': अकबर अहमद 'डम्पी' से लेखक।

52 'कपिलजी अपने मेहमानों से मिलते और उन्हें अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बातचीत करने के लिए छोड़ देते': पुष्पा मोहन से लेखक को।

52 'एक बार हमने अपने भतीजे का अन्नपराशन (बच्चे को दिया जाने वाला पहला

भोजन) समारोह किया था': वही।
52 'एक बोल्शेविक चाल': ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ. 156.
52 'क्लियोपेट्रा जैसी दुष्ट': डेविड सेलबोर्न, 'चरण सिंह और क्लियोपेट्रा', रविवार, खंड 7,
अंक 15, 2 सितंबर 1979।
52 'वह उससे नफरत करता था': सत्यपाल मलिक ने लेखक से कहा।
53 'Colonel (V. R. Mohan) bahut pareshan thae': Pushpa Mohan to author.
53 'सर्वशक्तिमान संजय' ने कपिल मोहन की 'कई तरह से' मदद की थी: सुभाष आर्य ने कहा
लेखक।
53 'मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताना चाहता': वही।
53 'मैं खुद कपिल मोहन के लिए कार लेकर आया था': अनिल बाली ने लेखक से कहा।
53 'Shri Indira Gandhi maen mati nahin hai': Anil Bali to author.
54 'उन्हें कांग्रेस (आई) का समर्थन प्राप्त होगा': जयकर, इंदिरा गांधी, पृ. 384.
54 'Aap bhi ban sakte ho PM,' Sanjay had held out a carrot: Anil Bali to author.
54 'कोई भी कानून से ऊपर नहीं है': 'गर्व और सजा, न्यूयॉर्क टाइम्स, 20 दिसंबर 1978।
55 'अब जब आप वापस आ गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपना समय दें': आनंद कुमार ने लेखक से कहा।
55 फिर उन्होंने आनंद कुमार का उनसे परिचय कराते हुए कहा कि वह अभी-अभी 'अमेरिका से लौटे हैं': वही।
55 'उन्होंने मुझसे दो बार मुलाकात की... लेकिन मैंने उनसे राजनीति पर चर्चा नहीं की': मधु लिमये, जनता
पार्टी प्रयोग: विपक्षी राजनीति का एक अंदरूनी विवरण, 1977-80, बी. आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, 1994, पृ. 498.

56 ‘महोदय, इस व्यक्ति को छोटी कारें बनाने का लाइसेंस दे दीजिए क्योंकि उसने यह काम अपनी माँ से सीखा है।’
गर्भ’: जैफ्रेलॉट और अनिल, भारत की पहली तानाशाही, पृ. 61.
56 इसमें संजय और सूचना एवं प्रसारण मंत्री वी.सी. शुक्ला पर आरोप लगाया गया: दिलीप बॉब,
‘किस्सा कुर्सी का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने संजय गांधी को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा’, इंडिया टुडे, 31 मई 1978।
56. अप्रैल 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय और शुक्ला को आरोपों से बरी कर दिया था: स्टुअर्ट
ऑरबैक, 'भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने गांधी के पुत्र को आपराधिक आरोपों से बरी किया', वाशिंगटन पोस्ट, 12 अप्रैल 1980।
56 ‘Babuji dekh laenge garhi ko’: Anil Bali to author.
57. सुरेश राम द्वारा उस दिन कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एफआईआर: फरजंद अहमद,
अरुल बी. लुईस और प्रभु चावला, ‘रक्षा मंत्री जगजीवन राम के बेटे और उसकी प्रेमिका के “अपहरण” ने देश को हिला दिया’, इंडिया टुडे, 15 सितंबर 1978।
57 सुरेश राम को इसलिए हटाया गया क्योंकि वह हर तरह की ‘कुटिल गतिविधियों’ में शामिल था: अनिल बाली
लेखक।
57 वे जानते थे कि वह 'पोलरॉइड कैमरे' से तस्वीरें लेता था: के.सी. त्यागी ने लेखक को बताया, 4
अगस्त 2020, नई दिल्ली।
57 वे तस्वीरों पर अपना हाथ डालना चाहते थे: अनिल बाली ने लेखक को बताया।
57 जैसे ही नारायण के लड़कों को तस्वीरें मिलीं: संपादक खुशवंत
भारत के पहले राजनीतिक-यौन कांड के बारे में सिंह ने कहा था—अगर कामसूत्र में 64 आसन होते हैं तो इसमें उनमें से सिर्फ नौ ही हैं। जी. प्रमोद कुमार का लेख देखें, 'मेनिका गांधी द्वारा भारत के पहले यौन कांड की तस्वीरें प्रकाशित करने के 38 साल बाद, उनके बेटे वरुण का भी ऐसा ही हाल हुआ', हफपोस्ट, 24 अक्टूबर 2016।
57 ‘Babuji Raj Narain ko manane aaye thae’: Anil Bali to

author.
57 जगजीवन राम स्पष्ट रूप से 'सौदा करना चाहता था': वही।
57 जगजीवन राम और नारायण लगभग बीस मिनट तक अंदर थे: वही।
57 'Main PM banane wala hoon, kisi ko mantri banana ho toh batana?': Ibid.
58 'ये तस्वीरें संजय को ले जाओ। अभी। तुरंत': वही।
58 'मैंने उसे दुर्घटना के बारे में बताया और उसे तस्वीरें सौंप दीं': वही।
58 'और तुम कपिल मोहन से कहो कि राज नारायण को नियंत्रण में रखें': वही।
58 'Ek aur bete nae apne baap ko duba diya.': Rashmi Kant to author, 6 August 2020, New
दिल्ली।
58 'Ab meri izzat apke haathon maen hai': Ibid.
59 'वे 6, कृष्णा मेनन मार्ग पर गुप्त बैठकें करते थे': वही।
59 'वे अपनी पिछली बैठक में मुलाकात का समय तय करेंगे': वही।
59 'बाद में उसने मुझे पूरी कहानी बताई': वही।
60 'मुझे पता है कि आप अपना काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या चर्चा की': रश्मी कांत ने लेखक से कहा।
60 'राम बहुत रो रहा था': सईद नकवी ने लेखक से 23 मई 2022 को टेलीफोन पर बातचीत की।
60 लेख का शीर्षक था, 'असली कहानी': दिलीप बॉब, 'सूर्य पत्रिका का "खुलासा" जगजीवन राम के बिगड़े हुए बेटे से जुड़ा यौन कांड', इंडिया टुडे, 31 अक्टूबर 1978।
60 अंततः अदालत ने ओम पाल सिंह और त्यागी को बरी कर दिया: समरपाल सिंह, जो काम करते थे
चरण सिंह के साथ घनिष्ठ संबंध थे और उस समय ओम पाल सिंह के साथ एक ही कमरे में रह रहे थे, लेखक को 9 अगस्त 2020 को लिखा गया।
60. चरण सिंह और उसके गुर्गे (राज नारायण) द्वारा जगजीवन राम के इकलौते बेटे को फंसाने की योजना।
सुरेश राम एक 'घिनौने यौन कांड' में फंसे: अजय बोस, 'द अनहैप्पी मीडियम', इंडिया टुडे, 5 फरवरी 2022।

61. छह दिनों तक इंदिरा गांधी की स्थिति 'अस्थिर' लग रही थी: जैफरेलॉट और अनिल, भारत के
प्रथम तानाशाही, आपातकाल, पृ. 301.
61 आईबी ने उसे बताया था कि उसे कांग्रेस के 350 सदस्यों में से केवल 191 सदस्यों का ही समर्थन प्राप्त है:
वही।
61 'इसका उद्देश्य जनता पार्टी में फूट को रोकना था': राजमोहन गांधी ने लेखक से कहा।
61 'एक चमार कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता': ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ. 132.
61 'Kissi bhi keemat par Jagjivan Ram pradhan mantri nahin banane chahiye': Anil Bali to
लेखक।
62 'मैं टूट गया हूँ': रश्मी कांत ने लेखक से कहा, 12 सितंबर 2020, नई दिल्ली। उन्होंने कहा था
यह बात उसने अपने पिता कृष्णकांत से सुनी थी, जिन्हें यह बात जगजीवन राम ने बताई थी।
62 'मेरा मानना था कि इंदिरा गांधी ने वास्तव में संजय के लिए इस धर्म का सहारा लिया था':
अनिल बाली लेखक बनेंगे।
62 ज्योतिषियों ने उसे चेतावनी दी थी कि संजय की कुंडली में 'जीवन रेखा के अचानक कट जाने' का संकेत मिलता है: वही।
62 1980 में, उन्होंने इसे भगवान के नाम पर किया: जयकर, इंदिरा गांधी, पृ. 399.
62 लेकिन राजनेताओं और धार्मिक नेताओं ने उसे मना लिया: फ्रैंक, इंदिरा, पृ. 276.
62 'पहले हिंदू और अंत में हिंदू के रूप में देखा जाता है': अनिल बाली ने लेखक से कहा।
62 सत्ता खोने के बाद, उन्होंने छोटे-बड़े सभी मंदिरों का दौरा किया: जयकर, इंदिरा गांधी, पृ. 359;

फ्रैंक, इंदिरा, पृ. 430–31.
62 अक्टूबर 1977 में, वह गुजरात के अंबाजी मंदिर गईं: घोष, इंदिरा।
62 वह वैष्णो देवी गई थीं: '18 दिसंबर, 1977, चालीस साल पहले: मारुति जांच', भारतीय
एक्सप्रेस, 18 दिसंबर 2017।
62 she took part in the Kumbh Mela in 1977: Shyamlal Yadav and Seema Chishti, 'Explained:
'इलाहाबाद के नाम में क्या रखा है?', इंडियन एक्सप्रेस, 16 अक्टूबर 2018।
62 उन्होंने कांची के सबसे वरिष्ठ शंकराचार्य परमाचार्य नम्बी से मुलाकात की।
मार्तंडम, 'इंदिरा गांधी का तमिलनाडु का दो दिवसीय दौरा एक बड़ी विफलता में समाप्त हुआ', इंडिया टुडे, 30 नवंबर 1977।
63 'मेरा परिवार संकट में है,' इंदिरा गांधी ने उनसे कहा: वही।
63 कांचीपुरम में रहने वालों का मानना था कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के पक्ष में फैसला लिया था।
प्रतीक क्योंकि परमचार्य: गीता वेंकटरमनन, 'यहां समय ठहर जाता है', टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 मार्च 2015।
63 अन्य लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी पार्टी का प्रतीक गाय और बछड़े से बदलकर हाथ कर दिया: अर्जुमंद
बानो, 'देवरिया के मतदाताओं ने 1980 में इंदिरा की जीत का श्रेय देवराहा बाबा के आशीर्वाद को दिया', टाइम्स ऑफ इंडिया, 29 मार्च 2019।
63 Anandamayi Ma gave her a rare ekmukhi rudraksh: Jayakar, Indira Gandhi, p. 341.
63. हर दिन, '108 फूलों की भेंट चढ़ाई जाती थी': अनिल बाली ने लेखक को बताया।
63 उसकी सहेली पुपुल जयकर उसे दिन-ब-दिन अधिक अंधविश्वासी होते देखकर परेशान थी:
Jayakar, Indira Gandhi, p. 418.
63 इंदिरा ने गर्भवती मेनका को अपने कमरे में जाने के लिए कहा: जयकर, इंदिरा गांधी, पृ. 399.

63 ‘Mrs Gandhi conducted a mahamrityunjay paath at her home for a month’: Satyapal Malik
लेखक को।
63 ‘श्रीमती गांधी बहुत धार्मिक थीं’: करण सिंह ने लेखक से कहा।
64 ‘Indira Gandhi bahut badi Hindu hai’: Anil Bali to author. Bali had heard this from Deoras.
64 ‘बालासाहेब देवरस और उनके भाई ने इंदिरा गांधी में हिंदुओं के एक संभावित नेता को देखा’:
वही।
64 ‘इस उपलब्धि का सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है’: ए. जी. नूरानी, आरएसएस और भाजपा: श्रम का विभाजन, खंड 3, नई दिल्ली: लेफ्टवर्ड बुक्स, 2000, पृष्ठ 40।
64. 1974 में, उन्होंने परमाणु उपकरण का विस्फोट करके एक बार फिर आरएसएस की प्रशंसा हासिल की: बर्नार्ड
वेनराउब, 'भारत परमाणु उपकरण का परीक्षण करने वाला छठा राष्ट्र बना', न्यूयॉर्क टाइम्स, 19 मई 1974।
64 वे अक्सर खुद को 'आरएसएस के भीतर एक कम्युनिस्ट' कहते थे: निलंजन मुखोपाध्याय।
आरएसएस: भारतीय दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रतीक, नई दिल्ली: ट्रांकेबार, 10 अप्रैल 2019, पृष्ठ 258।
64 बालासाहेब देवरास प्रारंभ में, इसमें निहित 'अनुशासन' से प्रभावित हुए थे: 'आरएसएस
इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन किया: पूर्व आईबी प्रमुख’, इंडिया टुडे, 21 सितंबर 2015।
64 आपातकाल के पांच दिन बाद, श्रीमती गांधी ने बालासाहेब देवरस को जेल में डाल दिया: ए.जी. नूरानी, 'आरएसएस'
'और आपातकाल', फ्रंटलाइन, 3 अगस्त 2018।
64 उन्होंने 4 जुलाई 1975 को आरएसएस और तेईस अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया: 'प्रतिबंध थोपना'

आपातकाल, 1975: द बिल्ड अप', इंडियन एक्सप्रेस, 20 जुलाई 2015।
65 यह इंदिरा गांधी के साथ 'समझौता' करने की कोशिश करेगा: रवि विश्वेश्वरैया, 'द स्टोरी'
'इंदिरा शासन के आपातकाल के दौरान आरएसएस नेताओं ने जयप्रकाश और प्रतिरोध का साथ कैसे छोड़ा', द प्रिंट, 25 जून 2020।
65 'आपका भाषण (15 अगस्त 1975 को लाल किले से दिया गया) समयोचित और संतुलित था': मधुकर
Dattatraya Deoras, Hindu Sangathan aur Sattavaadi Rajneeti, Noida: Jagriti Prakashan, 1997, p. 270, cited in Shamsul Islam, 'On 45th Anniversary of The Emergency In India: Contemporary Documents Prove RSS Leadership Kowtowed To Indira Gandhi', Frontier Weekly, 26 June 2020.
65 '(संघ का) इन (बिहार और गुजरात) आंदोलनों से कोई संबंध नहीं है': वही।
65 'मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप आरएसएस के बारे में प्रधानमंत्री की गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास करें': वही।
65 'आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के लिए हानिकारक': नूरानी, 'आरएसएस और आपातकाल'।
65 'बाल ठाकरे ने ही आरएसएस को आपातकाल का समर्थन करने के लिए राजी किया था': कमल नाथ
लेखक को, 4 अगस्त 2021।
65 'कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने पर आपातकाल हटाया जा सकता है': वही।
65 यह विवाद समय-समय पर फिर से उभरता रहता है: बालासाहेब देवरास के एस. को लिखे पत्र।
आपातकाल हटने के बाद, 18 अक्टूबर 1977 को महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बी. चव्हाण द्वारा आरएसएस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आग्रह करते हुए एक विधेयक पेश किया गया था।
66 'लेकिन श्रीमती गांधी ने इनकार कर दिया': 'आरएसएस ने इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन किया: पूर्व आईबी प्रमुख', भारत

आज, 21 सितंबर 2015। अनिल बाली ने भी लेखक को इसकी पुष्टि की, नई दिल्ली, 12
जुलाई 2021।
66 Panchjanya, the RSS mouthpiece praised him: Noorani, ‘RSS & Emergency’.
66 ‘संजय गांधी विशेष अंक’: वही।
66 ‘प्रधानमंत्री आवास से चुपचाप संपर्क स्थापित करना’: ‘आरएसएस ने इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन किया: पूर्व-
आईबी प्रमुख।
66 ‘Chunav se Sangh alag ho jaye’: K. N. Govindacharya to author, 8 December 2020.
66 ‘हम उन्हें (जनता पार्टी को) बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते’: वही।
66 'संचार की रेखा एकनाथ रानाडे से मोरोपंत पिंगले से बालासाहेब तक थी
देओरास’: वही।
67 ‘आरएसएस ने 1980 में इंदिरा गांधी को सत्ता में आने में मदद की’: अनिल बाली ने लेखक से कहा।
67 ‘वह निजी तौर पर स्वीकार करती थी कि अगर आरएसएस का समर्थन न होता’: वही।
67 ‘हो सकता है वह आरएसएस के संपर्क में रही हो’: करण सिंह ने लेखक से कहा, 4 जनवरी 2021।
67 ‘आरएसएस ने’ राजेश्वर ने कहा, ‘कांग्रेस को अपना समर्थन स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था।’
आपातकाल के बाद के चुनाव: 'आरएसएस ने इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन किया: पूर्व आईबी प्रमुख'।
67 ‘1989 के चुनावों से पहले ही…आर. के. धवन ने हमसे (आरएसएस से) मदद मांगने के लिए संदेश भेजा था’:
के. एन. गोविंदाचार्य द्वारा लेखक को, 19 जून 2022।
67. 1984 के चुनावों से पहले, आरएसएस नेता नानाजी देशमुख ने लोगों से मतदान करने का आग्रह किया था।

the Congress: Noorani, 'RSS & Emergency'.
68 'आरएसएस गैर-हिंदुओं के लिए अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलता?': ए. जी. नूरानी, 'वाजपेयी के दो
'चेहरे', फ्रंटलाइन, 19 फरवरी 2000।
68 लगभग 8 लाख किसान दिल्ली के बोट क्लब में उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए थे: अरुल बी. लुईस।
'किसान रैली: किसान उत्सव के उल्लास के साथ राजधानी में उमड़े', इंडिया टुडे, 15 जनवरी 1979।
68 'किसान अब और कुछ नहीं मांगेगा': जनार्दन ठाकुर, 'क्या किसान रैली का आयोजन मात्र के लिए किया गया था?'
क्या यह चरण सिंह के आहत अहंकार को बढ़ावा देने के लिए था?', इंडिया टुडे, 15 जनवरी 1979।
68 'मुझे अच्छा आराम मिला': विलियम बॉर्डर्स, श्रीमती गांधी को जेल से रिहा किया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स, 27
दिसंबर 1978।
68 जयंत नामक बालक का जन्म अमेरिका में हुआ था: अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी को...
2021 में अपने पिता की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया।
68 'Mrs Gandhi chai pee laengi, toh Morarji theek ho jayenge': Satyapal Malik to author.
मलिक सिंह का लेफ्टिनेंट था, और जैसा कि हमने देखा, मार्च 1976 में चौधरी साहब को जेल से रिहा कराने में उसकी अहम भूमिका थी।
69. 24 जनवरी 1979 को उन्होंने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया और उन्हें वित्त प्रदान किया।
पोर्टफोलियो: 'एचटी दिस डे: 24 जनवरी, 1979 - चरण सिंह, जे. राम आज उप प्रधानमंत्री बने', हिंदुस्तान टाइम्स, 23 जनवरी 2022।
69 'दोहरी सदस्यता': प्रणब मुखर्जी, द ड्रामेटिक डिकेड: द इंदिरा गांधी इयर्स,
नई दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स, 2015, पृष्ठ 213।

69 ‘अगर आरएसएस फासीवादी है, तो मैं भी हूँ’: विनोद कुमार, ‘जयप्रकाश नारायण की ऐतिहासिक भूल’
भाजपा के उदय का मार्ग प्रशस्त किया’, द प्रिंट, 6 अक्टूबर 2019।
70 ‘नेहरू के बाद के युग में उत्तर भारत ने दो शक्तिशाली जन नेताओं को देखा है—इंदिरा गांधी और
'चरण सिंह': जयपाल रेड्डी ने लेखक से बातचीत के दौरान कहा, नई दिल्ली, 20 अक्टूबर 2001।
70 ‘मैं चाहता हूं कि यह सरकार और पार्टी बनी रहे’: ‘जनता पार्टी के अनुभवी नेता अपनी ओर खींच रहे हैं’
'अपनी मुरझाई हुई जैतून की शाखाओं को फैलाकर', इंडिया टुडे, 31 मई 1979।
70 ‘वह केवल एक मंत्रालय के लिए समस्याएँ पैदा करेगा’: वही।
70 ‘यह (हमला करने का) समय नहीं है,’ चरण सिंह ने नाथ से टालमटोल करते हुए कहा: कमल नाथ ने लेखक से कहा।
71 इंदिरा ने यह सुनिश्चित किया था कि विशेष न्यायालयों में आगे कोई कार्यवाही न हो सके:
Jayakar, Indira Gandhi, p. 385.
72 ‘उर्स…चला गया है…और…अक्टूबर के अंत तक मुझे दोषी ठहराया जाएगा’: ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ.
149. इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अधिग्रहणकर्ता) 2 जनवरी 1978 को उनकी पहल पर दो भागों में विभाजित हो गई। 1977 में सत्ता से बाहर होने के बाद, वह कोशिश कर रही थीं...
पार्टी अध्यक्ष बनने का उनका प्रयास असफल रहा। 1 जनवरी 1978 को उनके समर्थकों ने 'कांग्रेसियों का राष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित किया और एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुना। उस समय के. ब्रह्मानंद रेड्डी पार्टी के प्रमुख थे। 54 कांग्रेस सांसद उनके साथ चले गए। लगभग 100 अन्य सांसद ब्रह्मानंद रेड्डी और वाई.बी. चव्हाण के साथ रहे, जो उस समय संसद में पार्टी के नेता थे। उनके समूह को कांग्रेस (इंदिरा) के नाम से जाना जाने लगा। चूंकि शाह आयोग के समक्ष गवाही देते हुए कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों के लिए इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया था, इसलिए ब्रह्मानंद रेड्डी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर

दिया। देवराज उर्स 1978 में इंदिरा गांधी के साथ रहे, लेकिन 1979 में उनसे अलग होकर कांग्रेस (उर्स) का गठन किया, जो बाद में कांग्रेस (एस) बन गई।

72 राजनीति 'अस्थिर गति' की स्थिति में थी: मधु लिमये, जनता पार्टी प्रयोग: एक विपक्षी राजनीति का अंदरूनी विवरण – 1977–1980, खंड II, नई दिल्ली: बी.आर. पब्लिशिंग, 1994, पृष्ठ 456।

72 'मैं उन्हें मनाने में कामयाब रहा': कमल नाथ ने लेखक से कहा।

72 'यह उन महत्वपूर्ण दिनों के दौरान था': जयकर, इंदिरा गांधी, पृष्ठ। 386.

73 यह केवल एक नाम—जॉर्ज फर्नांडीस—के सामने रुका: अनिल बाली लेखक को।

73 यह फर्नांडिस के समाजवादी सहयोगी मधु लिमये थे: लीला कबीर फर्नांडिस से लेकर लेखक तक,

1979.

73 'जनता पार्टी का पूर्ण विघटन आज ऐतिहासिक आवश्यकता है': लेखक ने कहा था

उपस्थिति।

73 'क्या हमारी वर्षों की दोस्ती आपके लिए कोई मायने नहीं रखती?': जया जेटली, लाइफ अमंग द

स्कॉर्पियन्स: भारतीय राजनीति में एक महिला के संस्मरण, नई दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स, 2017, पृष्ठ 252।

73 'जॉर्ज जानता था कि वह हारा-किरी कर रहा है': रवि नायर ने लेखक से कहा।

73 मोरारजी देसाई के पास केवल 214 सांसद बचे थे: माइकल टी. कॉफ़मैन, 'भारतीय नेता ने इस्तीफा दिया'

'सत्ताधारी दल से कई लोगों ने दल-बदल किया', न्यूयॉर्क टाइम्स, 16 जुलाई 1979।

74 'जनता संसदीय दल के नेतृत्व से इस्तीफा दें': आई.वी. चलपति राव और

P. Audinarayana Reddy, Farm House to Rashtrapati Bhavan, Hyderabad: Booklinks

कॉर्पोरेशन, 1989. प्रासंगिक अंश www.rediff.com/news/apr/12cong7.htm पर उपलब्ध है।

74 लोगों ने उनके 'बिना शर्त समर्थन' के लिए उन्हें धन्यवाद दिया: सुनीता अरोन,

'चरण सिंह - एकमात्र भारतीय'
'वह प्रधानमंत्री जिसने कभी संसद का सामना नहीं किया', द प्रिंट, 20 जुलाई 2019।
74 ‘मेरे जीवन की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई है’: ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ. 179.
75 ‘आपको उसके पास क्यों जाना चाहिए, आप तो अब प्रधानमंत्री हैं?’: सत्यपाल मलिक ने लेखक से कहा।
75 ‘उसने गुलदस्ता फेंक दिया और घर के अंदर चली गई’: वही।
75 ‘यदि इंदिराजी मेरा समर्थन करना चाहती हैं, तो कोई समझौता नहीं हो सकता’: ठाकुर, प्रधानमंत्रियों, पृ. 183.
76 ‘क्या आपको लगता है कि हम ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त कर सकते हैं जिसने इंदिराजी को झूठा कहा था?’: वही, पृष्ठ 179.
76 ‘संजय गांधी का दिमाग इतना धूर्त था कि जनता पार्टी में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था’: रवि
नैर ने लेखक को 23 दिसंबर 2021 को लिखा।
संसद में 76 अपना बहुमत साबित नहीं कर सके: एरॉन, 'चरण सिंह - एकमात्र
भारत के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया।
76 ‘आपकी माताजी मेरे सपनों में आईं’: अनिल बाली ने लेखक से कहा।
77 इंदिरा गांधी ने सितंबर 1979 में यात्रा शुरू की: एस. वेंकट नारायण, 'इंदिरा गांधी ने यात्रा शुरू की'
चुनाव प्रचार अभियान’, इंडिया टुडे, 31 दिसंबर 1979।
77 ‘मैं ही मुद्दा हूँ,’ उन्होंने जवाब दिया था: इंदर मल्होत्रा, इंदिरा गांधी: एक व्यक्तिगत और राजनीतिक
जीवनी, भारत: हे हाउस, 2014, पृ. 128.
77 उन्होंने लोगों से केवल एक ऐसी सरकार चुनने का आग्रह किया जो 'काम करती हो': इंदर मल्होत्रा, 'द रिटर्न ऑफ'
इंदिरा’, इंडियन एक्सप्रेस, 29 सितंबर 2014।
77 दर्शन ही वे सब चाहते थे: नारायण, 'इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार शुरू किया'।
78 ‘अगर श्रीमती गांधी अगले महीने सत्ता में लौटती हैं, तो यह निश्चित रूप से सबसे तेज़ वापसी होगी

हालिया राजनीतिक इतिहास': वही।
78 'Venkatji, namaskar. Main Yashpal Kapoor bol raha hoon': S. Venkat Narayan to author, 3
अगस्त 2021।
78 'यदि आप सत्ता में आते हैं, तो वी.सी. शुक्ला और संजय गांधी की क्या भूमिका होगी?': वही।
78 'मैं कूदने जा रहा हूँ, सीढ़ी आने पर आप लोग आना': वही।
फरवरी 1979 से वर्ष के अंत तक 79 20 प्रतिशत: स्टुअर्ट ऑरबैक, 'गांधी की जोरदार जीत'
'जीत ने उनके विरोधियों का सफाया कर दिया', वाशिंगटन पोस्ट, 12 जनवरी 1980।
जे. मनोर, 'पार्टियां और पार्टी': 79 ने उन्हें भाजपा से 'हिंदू-प्रथम' का मुद्दा छीनने में मदद की।
सिस्टम', अतुल कोहली (संपादक), भारत का लोकतंत्र—बदलते राज्य-समाज संबंधों का विश्लेषण, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1990, पृ. 82.
79 'क्या आपको नहीं पता, आप मुख्य मंच से हट नहीं सकते?': अंबिका सोनी ने लेखक से 26 सितंबर को कहा
2020.
79 और उनमें से 150 'संजय के कट्टर समर्थक' थे: मल्होत्रा, 'द रिटर्न ऑफ इंदिरा'।
80 इस जीत ने उन्हें 'युवराज' के रूप में वैधता प्रदान की: वही।
80 'उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता': अहमद अकबर ने लेखक से कहा, 'बेवकूफ'।
81 'उसे बता दो कि अगर वह ज़िद करता है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा': एच. आर. भारद्वाज ने लेखक से कहा।
81 'वह एक लिफाफे में पैसे रखती थी और मुझे दे देती थी': अनिल बाली ने लेखक को बताया।
82 'मैडम, आपको चामुंडा देवी जाना होगा': वही।
82 'आप इंदिरा गांधी को बताइए, यह चामुंडा है': वही।
82 'विमान में मैं लगभग दो घंटे तक चीखती-चिल्लाती रही': सिमी गरेवाल

ऑफिशियल
‘मनेका गांधी के साथ मुलाकात भाग 1 और 2’, यूट्यूब, अप्रैल 2022 में देखा गया।
83 ‘मुझे नहीं पता कि मेरा कार्यक्रम किसने रद्द किया’: अनिल बाली ने लेखक से कहा।
83 बाद में, इंदिरा ने पुपुल जयकर को बताया कि संजय की मौत उनकी गलती थी: जयकर, इंदिरा
Gandhi, p. 418.
83 ‘प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं’: अनिल बाली ने लेखक से कहा।
83 ‘जब वह पूजा कर रही थी, पंडित के हाथ कांप रहे थे’: वही।
84 ‘मैंने ऐसी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी’: वही।

अध्याय 2: धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री जिसने धर्मनिरपेक्षता को कमजोर किया:

शाह बानो को लेकर राजीव गांधी का ढुलमुल रुख
85 ‘यह सोनिया ने मेरी उपस्थिति में कहा’: डी. पी. त्रिपाठी ने लेखक से मार्च 2018 में टेप पर बातचीत की।
85 ‘आप अपनी विश्वसनीयता खो देंगे’: वही।
86 यदि राजीव आगे बढ़ते हैं, तो 'हिंदू' की प्रगति को रोकना 'बहुत मुश्किल' हो जाएगा।
कट्टरपंथी ताकतें’: डी. पी. त्रिपाठी ने लेखक को 19 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में लिखा।
86 क्योंकि इस विधेयक के बाद ‘उतना ही विनाशकारी…निर्णय’ आया: वही।
86 मीडिया ने 1985 को 'आशा का वर्ष' नाम दिया था: ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ. 222.
87 हिंदू आक्रोश को शांत करने के लिए, राजीव गांधी ने एक विशिष्ट तरीका अपनाया।
‘प्रबंधन समाधान’: डी. पी. त्रिपाठी ने लेखक को मार्च 2018 में लिखा।
87 और वह कार्य बाबरी मस्जिद के भीतर एक परिसर खोलना था: जो कि सबसे

बड़ी मस्जिदों में से एक है।

उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बाबरी मस्जिद तुगलक, लोदी और शर्की शैली में निर्मित है और दिल्ली सल्तनत की अन्य मस्जिदों की वास्तुकला की नकल करती है। बलुआ पत्थर से बनी इस मस्जिद के प्रवेश द्वार पर फारसी शिलालेखों के अनुसार, इसका निर्माण सोलहवीं शताब्दी में प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर हुआ था। मस्जिद में पश्चिम की ओर एक लीवान (प्रार्थना कक्ष) था जो तीन भागों में विभाजित था: एक केंद्रीय, बड़ा गलियारा जिसके दोनों ओर मेहराबदार प्रवेश द्वार वाली दो गलियाँ थीं और जिनके ऊपर गुंबद बने थे। मस्जिद की आंतरिक ध्वनि व्यवस्था अद्वितीय थी - 'बाबरी मस्जिद के मेहराब से की गई एक फुसफुसाहट भी 200 फीट दूर दूसरे छोर तक और केंद्रीय प्रांगण की लंबाई और चौड़ाई में स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी'। मस्जिद को एक 'निष्क्रिय पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली' माना जाता था जिसमें विभिन्न इस्लामी वास्तुशिल्प तत्वों जैसे कि ऊंची छत, गुंबद, मेहराब और इसकी छह बड़ी जालीदार खिड़कियों का उपयोग किया गया था ताकि प्राकृतिक वेंटिलेशन और दिन के उजाले को अंदर आने दिया जा सके और साथ ही इसे ठंडा रखा जा सके।

अंदर। (राधिका रवि रंजन, 'बाबरी मस्जिद: एक बीते युग की प्रतिध्वनि', स्पीकिंगट्री.इन, 6 दिसंबर 2012)

‘बाबरी मस्जिद ऊँची ज़मीन पर स्थित थी। पश्चिम की ओर (मक्का की ओर वाला भाग, जो मस्जिद का हमेशा पिछला हिस्सा होता है) एक खड़ी ढलान थी, उत्तर और दक्षिण की ओर ढलान थी, और पूर्व की ओर समतल ज़मीन थी, जो मस्जिद का प्रवेश द्वार है।’ (वलय सिंह, अयोध्या: आस्था का शहर, कलह का शहर, नई दिल्ली: अलेफ बुक कंपनी, 2018) प्रवेश द्वार पर एक मुख्य द्वार था जिसे दिसंबर 1949 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा बंद कर दिया गया था। एक दूसरा छोटा द्वार भी था, जिसका सूत्रों के अनुसार, समय-समय पर मस्जिद के भीतर अनुष्ठान करने वाले पुजारियों द्वारा गुप्त रूप से उपयोग किया जाता था। यही वह द्वार था जिसे राजीव गांधी ने 1986 में ‘छुड़ाने’ में कामयाबी हासिल की थी। बाबरी मस्जिद परिसर के भीतर, लेकिन भीतरी आंगन से एक ऊँची पत्थर की दीवार द्वारा अलग, रामचबूतरा था, जो परिसर के दक्षिण-पूर्वी कोने में $17 \times 21 \times 6$ फीट का एक ऊँचा चबूतरा था। मस्जिद के मध्य भाग में राम लल्ला के प्रकट होने तक, यहीं पर भगवान राम की पूजा की जाती थी। पश्चिम की ओर लोहे की रेलिंग थी और उत्तर की ओर एक खुला मैदान था, जिसे

1991 में निर्मित राम दीवार द्वारा घेर दिया गया था। उत्तर की ओर ही सिंह द्वार (शेर द्वार) के लिए कंक्रीट का ऊंचा चबूतरा था, जिसका निर्माण जुलाई 1992 में राम मंदिर के प्रस्तावित स्थल के रूप में किया गया था। पूर्वी दीवार पर चबूतरे से कुछ कदम उत्तर की ओर एक द्वार था, जो एक सीधी संकरी गली में खुलता था, जो कस्बे की ओर जाती थी।

'राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर तीन तरफ से हिंदू मंदिरों से घिरा हुआ था, जो कब्रिस्तानों पर बने थे।' (अयोध्या, पृष्ठ 235) ये मंदिर विवादित क्षेत्र के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि का हिस्सा थे, जिसे 'कल्याण सिंह सरकार ने 1991 में अधिग्रहित किया था' (उत्कर्ष आनंद, 'अयोध्या फैसला: भारत की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई सिर्फ 0.3 एकड़ जमीन के बारे में थी, 2.77 एकड़ के बारे में नहीं', न्यूज18, 10 नवंबर 2019) और विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया था; इन्हें अक्टूबर 1991 में ध्वस्त कर दिया गया था। मस्जिद परिसर से कुछ ही सौ मीटर की दूरी पर राम कथा कुंज स्थित था।

88 दिसंबर 1949 में, हिंदुओं के एक समूह ने चुपके से राम लल्ला देवता की मूर्ति स्थापित की:

कृष्णा झा और धीरेन्द्र के. झा, 'बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति कैसे मिली, इसकी अनकही कहानी', द वायर, 6 दिसंबर 2021।

88 लेकिन अदालत के एक फैसले ने हिंदुओं को बंद जाली के पीछे से मूर्ति की पूजा करने की अनुमति दी:

Singh, Ayodhya, p. 205.

88 'यही राजीव गांधी की सोच का सार था': डी. पी. त्रिपाठी ने लेखक को मार्च 2018 में लिखा।

88 'संसद में राजीव गांधी का प्रभावशाली बहुमत 414 से घटकर 197 रह गया': शुभोदीप

चक्रवर्ती, 'इंक्रेडिबल इंडिया: 1989 के लोकसभा चुनाव की कहानी - आपको जो कुछ जानने की जरूरत है', ज़ी न्यूज़, 7 अप्रैल 2019।

88 'इंदिरा गांधी पर हमला हुआ, तुरंत दिल्ली लौटें': मुखर्जी, द टर्बुलेंट इयर्स, पृ. 68.

89 'क्या वह इन सभी गोलियों की हकदार थी?': वही, पृष्ठ 69.

89 'वह मर चुकी है': वही, पृष्ठ 70.
89 'मैंने पूर्व उदाहरणों का हवाला दिया': वही।
89 'क्या आपको लगता है कि मैं संभाल सकता हूँ?': वही, पृष्ठ 71.
90 'हम वास्तव में इस बारे में बात नहीं कर सकते थे': टी. एन. नीनान, 'मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग शांति चाहते हैं:
राजीव गांधी', इंडिया टुडे, 31 मई 1986।
90 वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी नहीं बल्कि राजीव गांधी शपथ ग्रहण करें: अरुण
नेहरू लेखक बने।
90 नेहरू ने कई कांग्रेस नेताओं को मना लिया था: पी.सी. अलेक्जेंडर, गलियारों के माध्यम से
पावर: एन इनसाइडर्स स्टोरी, नई दिल्ली: हार्परकॉलिन्स, 2004, पृ. 217.
91 'कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता,' नेहरू ने उनसे कहा: वही, पृष्ठ 219।
91 'कोई विकल्प नहीं...वैसे भी उसकी हत्या हो ही जाती': सोनिया गांधी, राजीव, दिल्ली: वाइकिंग/पेंगुइन
भारत, 1992, पृ. 9.
91 वहीं पर मंत्रिमंडल सचिव ने राजीव से दबे स्वर में कुछ कहा: पी. सी. अलेक्जेंडर, माई इयर्स
इंदिरा गांधी के साथ, नई दिल्ली: विजन बुक्स, 1991, पृष्ठ 155।
91 उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि उन्हें राष्ट्रपति के लौटने का इंतजार करना चाहिए: अलेक्जेंडर, के माध्यम से
सत्ता के गलियारे, पृष्ठ 220।
92. नेहरू का निधन दोपहर 2 बजे हुआ था और गुलजारी लाल नंदा शाम 4 बजे तक पदभार ग्रहण कर चुके थे: सुमित मित्रा और
प्रभु चावला, 'इंदिरा गांधी की हत्या ने भारत को उसके इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया', इंडिया टुडे, 30 नवंबर 1984।
92 श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा नहीं की जानी चाहिए: मुखर्जी, द टर्बुलेंट
इयर्स, पृष्ठ 71.

92 मुखर्जी ने सुझाव दिया कि इसके बजाय, कांग्रेस संसदीय बोर्ड (सीपीबी) को गठित किया जाना चाहिए।
तुरंत बुलाया गया: वही, पृष्ठ 72।
92 उस दिन शाम 5 बजे सीपीबी की बैठक हुई: फ्रैंक, इंदिरा, पृ. 496.
92 जी. के. मूपानार, जो सीडब्ल्यूसी के सचिव थे, ने एक औपचारिक पत्र लिखा: मुखर्जी, द
अशांत वर्ष, पृष्ठ 73.
93 ने पी.वी. नरसिम्हा राव पर यह अफवाह फैलाने का संदेह जताया कि मुखर्जी बनना चाहते थे।
अंतरिम प्रधानमंत्री: प्रणब मुखर्जी के करीबी एक वरिष्ठ बंगाली पत्रकार ने नई दिल्ली में इस बारे में लिखा।
93 'उस दिन, जब मैंने राजीव को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई': एच. एस. हंसपाल, पूर्व सांसद और
पंजाब में कांग्रेस के प्रमुख का 12 सितंबर 2022 को टेलीफोन पर दिया गया साक्षात्कार।
93 समारोह में एक 'भयानक सन्नाटा' छाया रहा: मित्रा और चावला, 'इंदिरा गांधी की हत्या'
यह भारत को उसके इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा कर देता है।
94 'मैं, राजीव गांधी, पूरी गंभीरता से प्रतिज्ञा करता हूँ': वही।
94 'शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता': मुखर्जी, द टर्बुलेंट इयर्स, पृ. 76.
94 'हमें खुफिया रिपोर्ट मिली हैं कि शहर में व्यापक हिंसा होगी'
'कल': विनय सीतापति ने 22 मार्च 2022 को अमेरिका के प्रिंसटन से फोन पर लेखक को यह संदेश भेजा।
95 'पीएमओ हिंसा के जवाब में एक समन्वित प्रतिक्रिया देगा': वही। विनय सीतापति, हाफ भी देखें
लायन: हाउ पी. वी. नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, दिल्ली: पेंगुइन वाइकिंग, 2016, पृ. 63. सीतापति अपनी पुस्तक में राव को फोन करने वाले 'युवा कांग्रेस नेता' का नाम लिए बिना फोन कॉल का जिक्र करते हैं।
95 हत्या के अगले दिन, इंदिरा गांधी की करीबी दोस्त पुपुल जयकर काफी उत्तेजित

थीं।
called up Rao: Jayakar, Indira Gandhi, pp. 490–91.
95. प्रधानमंत्री के रूप में राजीव उनके लिए एक अनजान व्यक्ति थे: विनय सीतापति ने लेखक से कहा, 22
मार्च 2022, अमेरिका के प्रिंसटन से फोन पर।
96 'उस समय राव की चिंता यही रही होगी कि उनका क्या होगा': वही।
96 'यह उनका सबसे बुरा समय था': विनय सीतापति, आधा शेर: कैसे पी. वी. नरसिम्हा राव ने रूपांतरित किया
भारत, दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, 2016, पृष्ठ 65।
96 ने राव को हिंसा में किसी भी भूमिका से बरी कर दिया: वही, पृष्ठ 64।
96 'Choorhiya pehen rakhi hain kya? Maa ko maara hai': Shahid Siddiqui to author, 19 August
2021.
96 दिल्ली महानगर परिषद: दिल्ली महानगर परिषद केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन करती थी।
1966-90 के बीच दिल्ली का एक कार्यकारी पार्षद इस पद पर कार्यरत था और इसकी अध्यक्षता एक मुख्य कार्यकारी पार्षद करता था।
96 Lalit Maken, H. K. L. Bhagat, Sajjan Kumar, Jagdish Tytler, Kamal Nath: Sunil Sharan,
'1984 के घाव', टाइम्स ऑफ इंडिया, 13 मई 2019।
97 'जब हम प्रस्तुति के लिए सामग्री संकलित कर रहे थे': हरतोष सिंह बाल, 'द शैटर्ड डोम',
द कारवां, 1 मई 2014।
97 'सरकार द्वारा समुदाय के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की गई थी': वही।
सरकार का अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में दिल्ली में लगभग 2,733 सिखों की हत्या कर दी गई।
दिनों और देश भर में 3,350: गौरव विवेक भटनागर, '1984 के सिख विरोधी नरसंहार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश 2002 के गुजरात दंगों के बारे में क्या कहता है', द वायर, 17 दिसंबर 2018।

देश के चालीस शहरों में 8,000 से 17,000 लोग मारे गए: 'सिख नेताओं ने मौत का स्वागत किया'
'1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी को दी गई सजा', डीएनए, 21 नवंबर 2018; 'गुजरात दंगों का मामला भी उठाएं', हंस इंडिया, 19 दिसंबर 2018।
98 राजीव गांधी ने 'मम्मी की मदद करने' के लिए राजनीति में कदम रखा: ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ. 220.
98 'हम 12, विलिंगडन क्रिसेंट में लंच टेबल पर बैठे थे': अकबर अहमद 'डम्पी' से लेखक, 22 जनवरी 2021, टेलीफोन पर हुई बातचीत।
98 लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने व्यक्तिगत रूप से एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे: वजाहत हबीबुल्लाह, मेरे
राजीव के साथ बिताए वर्ष: विजय और त्रासदी, दिल्ली: वेस्टलैंड, 2020, पृष्ठ 43।
98 'संजय ने तुरंत आर. के. धवन को अरुण नेहरू से संपर्क करने को कहा': अकबर अहमद
लेखक से 'डम्पी' की बातचीत, 22 जनवरी 2021, टेलीफोन पर हुई।
99 'पुनः विचार करने पर, कपड़ा खरीदकर कुर्ते सिलवाना बेहतर होगा': वही।
99 'जब भी आपको रंग दिखाई दे, तो हमें याद करें': 'अरुण नेहरू और अरुण सिंह: राजीव गांधी के
सत्ता दलालों', इंडिया टुडे, 15 दिसंबर 1984।
99 लुटियंस के दिल्ली के अभिजात वर्ग में उनके अपने मित्रों का एक समूह था: तवलीन सिंह,
दरबार, दिल्ली: हैचेट, 2013।
99 'मैं संजय को कभी माफ नहीं करूंगा जिसने मम्मी को इस स्थिति में पहुंचाया': जयकर, इंदिरा
Gandhi, p. 321.
99 फोतेदार उसके पास वापस आया और कहा कि उसे तीनों नामों पर मिली प्रतिक्रिया 'अनुचित' लगी:
एम. एल. फोतेदार द्वारा लेखक को, 1 जनवरी 2005, गुड़गांव।
99 'वह मुझसे राजीव जी के राजनीति में आने के फायदे और नुकसान पर चर्चा करती थीं': एम. एल. फोतेदार ने कहा

लेखक, 1 जनवरी 2005, गुड़गांव। इसके अलावा एम. एल. फोतेदार, 'राजनीतिक सचिव, 1980-87', द चिनार लीव्स: ए पॉलिटिकल मेमॉयर, नई दिल्ली: हार्पर कॉलिन्स, 2015।

99 अरुण नेहरू ने लगभग पचास सांसदों का एक समूह संगठित किया: रशीद किदवई, 'मृत्यु पुल का काम करती है'

'परिवार में कड़वा विभाजन', द टेलीग्राफ ऑनलाइन, 27 जुलाई 2013।

29 मार्च 1982 की आधी रात को मानेका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया: चिंगखेइंगनबी

मायेंगबम, 'मेनका गांधी ने आधी रात को अपने बेटे वरुण के साथ इंदिरा गांधी के आवास को क्यों छोड़ा?', इंडिया टुडे, 20 जनवरी 2023।

100 'वह (सोनिया) मेरे राजनीति में आने के विचार के बिल्कुल खिलाफ हैं': दिलीप बॉब, 'सोनिया

राजनीति में आने के विचार के घोर विरोधी', इंडिया टुडे, 31 अगस्त 1980।

100 'एक दोपहर, 1980 के अंत में, राजीव ने मुझे चुपचाप बताया': सुमन दुबे, 'राजीव गांधी प्रवेश करते हैं'

'1981 में अमेठी से लोकसभा में पहुंचे', इंडिया टुडे, 26 दिसंबर 2005।

100 'मैं इसे इस तरह देखता हूँ,' राजीव ने कहा था, 'कि मम्मी की किसी न किसी तरह मदद करनी होगी': वही।

100 'राजीव का पदार्पण': '12 मई, 1981, चालीस वर्ष पहले: अमेठी में राजीव', इंडियन एक्सप्रेस, 12

मई 2021।

100 'Sari pehenna, teeka lagana': Habibullah, My Years with Rajiv, p. 45.

101 'मैंने बिना किसी अतिरिक्त व्यवस्था के दशहरी आम, लेमन चिकन और अरहर दाल के साथ दोपहर के भोजन का इंतजाम किया था।

'मसाला': अनिल बाली ने लेखक से कहा, 13 सितंबर 2020, नई दिल्ली।

101 राजीव रत्न बिरजीस गांधी: राजीव नाम का चुनाव उनके लिए सोच-समझकर किया गया था। राजीव का अर्थ कमल होता है।

उनका नाम उनकी दादी कमला के नाम पर रखा गया था, रत्ना नाम उनके दादा

जवाहर के नाम पर रखा गया था, और बिरजीस नाम पिता के पारसी पक्ष से आया था और फारसी में इसका अर्थ 'बृहस्पति' या 'शुभ' होता है।

101 ‘मुझे भारत के अगले प्रधानमंत्री के साथ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है’: वही।

101 19 नवंबर 1982 को हुआ उद्घाटन समारोह—जो संयोगवश इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी था—एक

भव्य आयोजन: साहिल भल्ला, 'फ्लैशबैक 1982: एशियाई खेल जिन्होंने दिल्ली को बदल दिया',

Scroll.in, 25 सितंबर 2015।

102 उस समय के अन्य पार्टी कार्यालयों के विपरीत, राजीव के कार्यालय में एक कंप्यूटर था: फ्रैंक, इंदिरा, पृ. 473.

102 ‘अंग्रेजी भाषी, दून स्कूल से शिक्षित भारतीय’: सिंह, दरबार।

103 ‘यदि व्यवस्था नहीं बनी और पंद्रह मिनट में सब कुछ खत्म नहीं हुआ, तो मैं वापस चला जाऊंगा’:

अमरनाथ के. मेनन, ‘राजीव गांधी ने हवाई अड्डे के नियमों का उल्लंघन करने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टी.एम. अंजैया को फटकार लगाई’, इंडिया टुडे, 28 फरवरी 1982।

103 उनके कठोर व्यवहार ने ‘विरोध की चीखें’ उत्पन्न कीं: वही।

जनवरी 1983 में हुए चुनावों में उन्होंने 294 सीटों में से 201 सीटें जीतीं: आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम 1983’, www.elections.in/andhra- पर उपलब्ध है।

pradesh/assembly-constituencies/1983-election-results.html >

104 वह जानती थी कि राजीव भोला और भरोसेमंद दोनों था: मणि शंकर अय्यर ने लेखक को लिखा, 16

फरवरी 2021, टेलीफोन पर हुई बातचीत।

104 उद्योगपतियों ने उन्हें 'वन विंडो क्लीयरेंस' कहा: इंदरजीत बडवार और प्रभु चावला।

‘अरुण नेहरू को सत्ता से बेदखल करने की परिस्थितियाँ रहस्य में डूबी हुई हैं’, इंडिया टुडे, 30 नवंबर 1986।

104 ‘अरुण नेहरू कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठे थे’: शाहिद सिद्दीकी ने लेखक से कहा।
105 ‘Acha, toh tu mujhe national interest sikhayega?’: Ibid.
105 ‘Main usko toh theek kar doonga’: G. S. Chawla to author.
105 प्रमुख सदस्य श्रीमती गांधी के सहयोगी एम. एल. फोतेदार थे: जी. एस. चावला, 'द गैंग हू'
पंजाब में अशांति पैदा की’, आउटलुक, 4 फरवरी 2022।
105 ने इंदिरा को अकाली दल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से रोका: वही।
105 ज़ैल सिंह ने अपने द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल भी चुकाया था।
भिंडरांवाले: मार्क टली और सतीश जैकब, अमृतसर: श्रीमती गांधी की अंतिम लड़ाई, कलकत्ता: रूपा एंड कंपनी, 1985, पृ. 60.
106 'सत्ता का कट्टरपंथी हस्तांतरण': स्वप्नजीत कुंडू, 'खालिस्तान आंदोलन: यह कैसे शुरू हुआ, कौन
'इसने और पिछले कुछ वर्षों में हुए अन्य विकासों का समर्थन किया', न्यूज़9, 12 मई 2022।
106 ज़ैल सिंह, जो अब तक राष्ट्रपति बन चुके थे—और अरुण नेहरू की मदद कर रहे थे: जी.एस.
चावला, पंजाब में रक्तपात: धोखे और तोड़फोड़ की अनकही गाथा, दिल्ली: हर-आनंद प्रकाशन, 2016।
106 ‘मैंने मम्मी को कितनी बार बताया है’: सिंह, दरबार, पृ. 144.
106 जिन्हें ‘बाबा लोग’ या ‘कंप्यूटर बॉयज़’ कहा जाता था: सुनील सेठी, ‘राजीव गांधी और
“बाबा लोग” साल’, बिजनेस स्टैंडर्ड, 24 अगस्त 2019; एस. बालकृष्णन, ‘द एंग्री लॉयलिस्ट’, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, 19 नवंबर 1989, पृ. 42.
106 'आक्रमण योजना' तैयार करने की योजना: फ्रैंक, इंदिरा, पृ. 478.
107 ‘विलंबित और प्रतिरोधी’: वही।
107 ‘वह ईश्वर के घर पर हमला करने से डरती थी’: वही।
107 कांग्रेस के बाबा लोगों ने विधिवत निर्वाचित विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने का काम किया:
भबानी सेन गुप्ता, ‘लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर कांग्रेस (आई) ने चार राज्यों के

खिलाफ राष्ट्रव्यापी “ऑपरेशन टोपल” शुरू किया’, इंडिया टुडे, 15 फरवरी 1984।
107 ‘1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, मैं कांग्रेस के लिए योजना बना रहा था’: अरुण
नेहरू ने लेखक को 16 मई 2001 को लिखा।
108 ‘उसे उन लोगों ने मार डाला जो भारत को टुकड़ों में तोड़ना चाहते थे’: सुनील सेठी, ‘राजीव’
गांधी ने भीषण चुनावी अभियान चलाया, 12 दिनों में 19,000 किलोमीटर की दूरी तय की', इंडिया टुडे, 31 दिसंबर 1984।
108 ‘जब एक बड़ा पेड़ गिरता है’: ‘राजीव गांधी का कुख्यात “बड़ा पेड़ गिरता है” भाषण देखें’
1984 के सिख विरोधी दंगों को उचित ठहराते हुए’, स्क्रॉल डॉट इन, 20 नवंबर 2015।
108 ‘Rajiv Gandhi ka ailan/nahi banega Khalistan’: Raghav Bikhchandani, ‘When ad agency
'कांग्रेस को 1984 में बड़ी जीत दिलाने में मदद मिली', द प्रिंट, 20 मार्च 2022।
108 ‘अभियान में सिखों को दुश्मन के रूप में चित्रित किया गया’: रघुनाथ एएस (असराघुनाथ), ट्वीट, 5 मई 2019,
<https://twitter.com/asraghunath/
status/1124997320251138048?s=20> पूर्व पत्रकार रघुनाथ ए.एस. ने 2019 में एक ट्विटर थ्रेड में 1984 में इस्तेमाल किए गए विज्ञापनों का दस्तावेजीकरण किया।
108 ‘हमने जो सबसे सस्ता चुनाव लड़ा’: अरुण नेहरू ने लेखक को, 16 मई 2001।
108 ‘आरामदायक सुस्ती का दौर खत्म’: सेठी, ‘राजीव गांधी एक कठिन चुनाव प्रचार अभियान पर निकल पड़े’
यात्रा के दौरान, 12 दिनों में 19,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई।
109 उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 85 में से 84 सीटें जीतीं: ‘आम चुनाव, 1984 पर सांख्यिकीय रिपोर्ट’
आठवीं लोकसभा के लिए: खंड I’, दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 1985, उपलब्ध

है
<https://eci.gov.in/files/file/4119-general-election-1985-vol-i-ii/>.
109 पार्टी ने 404 लोकसभा सीटों के अभूतपूर्व बहुमत के साथ सत्ता हासिल की: वही।
यह संख्या बढ़कर 414 हो गई: 'आठवीं लोकसभा के लिए 1985 के आम चुनावों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट'
सभा: खंड II', दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 1986, उपलब्ध है
<https://eci.gov.in/files/file/4119-general-election-1985-vol-i-ii/>.
109 'मैं क्या कहूँ?': टी. एन. नीनन, 'प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस (आई) को एक क्रूर पतन की ओर ले जा रहे हैं'
'आठवीं लोकसभा में बहुमत', इंडिया टुडे, 15 जनवरी 1985।
मैरी के अनुसार, 110 ने 'विदेश मंत्रालय के पूर्व सम्मानित अधिकारी नटवर सिंह को जमीन पर गिरा दिया'।
ऐनी वीवर, 'राजीव गांधी और "दो अरुण जो सत्ता में आने वाले हैं"—भारत चलाने का एक नया तरीका', द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, 7 जनवरी 1985।
110 'मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें प्रधानमंत्री आवास पर राजीव से मिलने आते देखा हो': विवेक भारत राम
लेखक।
110 'अरुण सिंह प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के प्रति सम्मानजनक थे, लेकिन अरुण नेहरू उनसे बिल्कुल अलग थे।
'विनम्रतापूर्ण': बी. एन. उनियाल ने लेखक से 27 फरवरी 2021 को टेलीफोन पर बातचीत में कहा, नई दिल्ली।
110 'Arunji, kuch toh umar ka lihaz kariye': Ibid.
110 'मैं कॉल का इंतजार करता रहा': मुखर्जी, द टर्बुलेंट इयर्स, पृ. 88.
111 1 जनवरी 1985 को, आर.के. धवन गाड़ी से 1 सफदरजंग रोड गए: पंकज वोहरा लेखक से, 1
अगस्त 2022, नई दिल्ली, टेलीफोन पर साक्षात्कार।

112 ‘यह सोनिया गांधी ही थीं जिन्होंने तय किया कि वे बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं’: वही।
112 ‘यह सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली’: रश्मि कांत ने लेखक से कहा, 3 अप्रैल 2018, न्यू
दिल्ली। उन्होंने यह बात अपने पिता कृष्णकांत से सुनी थी।
112 ‘आर. के. धवन जितना शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता’: पंकज वोहरा ने लेखक से कहा, 1
अगस्त 2022, नई दिल्ली, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
113 ‘आया राम, गया राम’: चिटलीन के. सेठी, ‘जैसे-जैसे दलबदलू सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, एक नज़र पीछे मुड़कर देखें’
original “Aaya Ram, Gaya Ram”’, The Print, 19 May 2018.
113 1985 के दौरान, राजीव गांधी ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए: 'एक अलग समझौता',
प्रिंट, 21 अगस्त 2010।
113 राजीव गांधी ने आगे चलकर छह प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किए: कुमार शक्ति शेखर, '5 तरीके
'राजीव गांधी ने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया', इंडिया टुडे, 20 अगस्त 2018।
113 1988 में, राजीव गांधी ने मतदान की उम्र इक्कीस से घटाकर अठारह कर दी: वही।
114 उनके कार्यकाल के दौरान हुए अत्यधिक खर्च के कारण ही भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हुआ: अंकित मित्तल।
‘1991 के आर्थिक संकट की लंबी राह’, मिंट, 8 जुलाई 2016।
114 दूसरा मामला 1987 के मध्य में बोफोर्स बंदूक सौदा था: इसमें कमीशन के आरोप लगे थे।
और स्वीडिश हथियार निर्माता एबी बोफोर्स से 155 मिमी हॉवित्जर बंदूक की खरीद में रिश्वतखोरी का मामला, जिसमें बंदूक सौदे में 64 करोड़ रुपये की रिश्वत का भुगतान किया गया था।
115 ‘आओ मेरे साथ एक कप कॉफी पियो’: अरुण नेहरू ने लेखक से कहा, 16 मई

2001, नई दिल्ली।
115 ‘शाह बानो के बारे में आपकी क्या राय है’: आरिफ मोहम्मद खान ने लेखक से 21 अगस्त 2018 को पूछा।
नई दिल्ली।
115 1937 में, अंग्रेजों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) एप्लीकेशन नामक एक कानून बनाया था।
लेख: रजिया पटेल, ‘भारतीय मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम निजी कानून की राजनीति और गरिमा एवं न्याय के साथ जीवन के लिए संघर्ष’, आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 44, अंक 44, 2009, पृष्ठ 45।
भारत में 116 मुसलमानों ने अपने आयोजन के तरीके में स्थानीय और धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन किया।
निजी जीवन: शोएब दानियाल, 'भारत में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून का संक्षिप्त इतिहास', स्क्रॉल.इन, 4 सितंबर 2017; काज़ी सारा रशीद और ए. के. शर्मा, 'भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार: संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों की आवश्यकता', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 51, अंक 37, 2016, पृष्ठ 22।
116 इस मुद्दे पर बोलने वाले सभी लोग मुसलमान थे, सिवाय जनता पार्टी के एक सांसद: मणि के।
शंकर अय्यर ने लेखक से 16 फरवरी 2021 को टेलीफोन पर बातचीत की।
116 ‘बनातवाला जो कह रहे हैं वह सब गलत है’: आरिफ मोहम्मद खान ने लेखक से कहा, 21 अगस्त 2018
नई दिल्ली।
116 ‘इसका व्यक्तिगत कानून से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून द्वारा बताया जा रहा है।
बोर्ड’: वही।
116 ‘तलाक के अवसर पर भी, जो रिश्ते के निरस्त होने की घोषणा करता है’: आरिफ
मोहम्मद खान से लेखक को, 21 अगस्त 2018, नई दिल्ली; आरिफ मोहम्मद खान, पाठ और संदर्भ: कुरान और समकालीन चुनौतियाँ, नई दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स, 2010, पृ. 1–2.

117 ‘किसी जरूरतमंद को पैसा दिए जाने पर आपत्ति करना ईशनिंदा है’: एजाज अशरफ
शाहबानो मामले पर आरिफ मोहम्मद खान: “नजमा हेपतुल्ला का राजीव पर महत्वपूर्ण प्रभाव था
Gandhi”’, Scroll.in, 30 May 2015.
117 ‘हमें यह पता नहीं था’: आरिफ मोहम्मद खान ने लेखक से कहा, 21 अगस्त 2018, नई दिल्ली।
117 ‘Baat toh sahi hai’: Ibid.
117 ‘नहीं, नहीं, हम इन लोगों की बातों से सहमत नहीं हो सकते’: वही।
117 ‘File pe toh Rajivji ne aur bhi sakht likha hai’: Ibid.
117 वह एक ‘आधुनिक’ नेता थे: शाह बानो मामले पर अशरफ, ‘आरिफ मोहम्मद खान: “नजमा
Heptullah was key influence on Rajiv Gandhi”’.
117 ‘चर्चा में सबसे पहले आरिफ हस्तक्षेप करेंगे’: आरिफ मोहम्मद खान ने लेखक को 21 अगस्त को बताया
2018, नई दिल्ली।
117 ‘हमें इन दिनों बेहतर तौर-तरीके अपनाने चाहिए’: ‘लोकसभा वाद-विवाद (अंग्रेजी संस्करण): तीसरा संस्करण’
सत्र (आठवीं लोकसभा)’, खंड 9, संख्या 23, नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय, 23 अगस्त 1985, पृष्ठ 453, उपलब्ध है
<https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/3598/1/
lsd_08_03_23-08-1985.pdf>.
117 ‘राजीव ने लोकसभा में मेरे द्वारा कही गई बातों की जमकर प्रशंसा की’: आरिफ मोहम्मद खान
लेखक को, 21 अगस्त 2018, नई दिल्ली।
118 ‘मेरे परिवार में—विस्तृत परिवार में कुछ हुआ है’: आरिफ मोहम्मद खान ने लेखक से कहा, 21
अगस्त 2018, नई दिल्ली।
118 अंततः उस महिला को किसी और से शादी करनी पड़ी: यह इस बात के अनुसार

था
‘निकाह हलाला’ रूढ़िवादी मुसलमानों में प्रचलित एक प्रथा है, जिसके अनुसार एक महिला को अपने पहले पति के पास लौटने से पहले दूसरे पुरुष से विवाह करना और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना आवश्यक होता है। ‘हलाला’ एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत, अपने पति से दोबारा विवाह करने के लिए, एक मुस्लिम महिला को दूसरे पुरुष से विवाह करना, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना और फिर उस अस्थायी पति से तलाक लेना अनिवार्य होता है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें कुछ बदनाम मुल्लाओं ने इसके बदले महिलाओं से अस्थायी विवाह कराने की पेशकश की है।’ (ग़ज़ाला वहाब, बॉर्न अ मुस्लिम, पृष्ठ 129 देखें।)
118 ‘मैं इस घटना को कभी नहीं भूला’: आरिफ मोहम्मद खान ने लेखक से कहा, 21 अगस्त 2018, नई दिल्ली।
118 संसद में आरिफ मोहम्मद खान के हस्तक्षेप के बाद: वसुधा धगमवार, 'बाद में शाह बानो फैसला – द्वितीय’, टाइम्स ऑफ इंडिया, 11 फरवरी 1986।
118 अली मियां, जैसा कि मौलाना अबुल हसन अली नदवी को लोकप्रिय रूप से कहा जाता था, ने राजीव को सौंप दिया था
memorandum: Fasihur Rahman, ‘Triple Talaaq and Shah Bano Case’, Mainstream, Vol. LVII, No. 34, 11 August 2019.
119 अली मियां को ‘पूरे इस्लामी जगत का समर्थन प्राप्त था’: शाहिद सिद्दीकी ने लेखक को 25 मार्च को बताया
2019, नई दिल्ली।
119 ‘तो, वह उससे हर महीने पैसे नहीं ले रही होगी’: वही।
119 ने फैसले के खिलाफ 'बहुत जोरदार' आवाज उठाई: वही।
119 इसने एआईएमपीएलबी पर भी अपना दबाव डाला: रहमान, 'ट्रिपल तलाक' और शाह बानो
मामला'।
119 हालांकि यह एक स्थानीय पहल थी, लेकिन इसने तीन लाख लोगों को आकर्षित किया: अशरफ, आरिफ मोहम्मद खान
शाहबानो मामला: "नजमा हेपतुल्ला का राजीव गांधी पर महत्वपूर्ण प्रभाव था"
119 दुनिया के अन्य हिस्सों के मुसलमानों की तरह, उन्होंने भी पवित्र अल-अक्सा

मस्जिद के विध्वंस के समय विरोध प्रदर्शन किया था।
यरूशलम पर हमला हुआ: अब्देल राउफ अरनाउट, 'अल-अक्सा मस्जिद में अभी भी आग लगी हुई है: फिलिस्तीनी', अनादोलू एजेंसी, 21 अगस्त 2019।
119 ‘हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन मुख्य रूप से मतदान के माध्यम से करते थे’: शाहिद सिद्दीकी
लेखक, 25 मार्च 2019, नई दिल्ली।
119 अली मियां ने उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए उन्हें पूरा श्रेय दिया: मौलाना अबुल हसन अली नदवी,
कारवां-ए-ज़िंदगी।
120 ‘नजमा हेपतुल्ला अपने हेयरड्रेसर को अदालत द्वारा आवंटित राशि से अधिक भुगतान करती है
शाह बानो!’: आरिफ मोहम्मद खान ने लेखक से 21 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में कहा।
120 ‘अगर आरिफ मोहम्मद खान, जो एक मंत्री हैं, निजी सदस्यों की बहस में बोल सकते हैं’
बिल, मैं बोल क्यों नहीं सकता?’: फसीहुर रहमान, विंग्स ऑफ डेस्टिनी: जियाउर रहमान अंसारी – ए लाइफ, नई दिल्ली: हाईब्रो स्क्राइब्स पब्लिकेशन्स, 2018।
120 अंसारी राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मुस्लिम मंत्री थे: मणि शंकर अय्यर ने लेखक को बताया, 16
फरवरी 2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
120 ‘राजीव ने त्यागपत्र लिया, उसे फाड़ दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया’: अजीज कुरैशी ने लेखक से कहा।
120 He lambasted the Shah Bano judgment as ‘prejudiced’: Rahman, ‘Triple Talaaq and Shah
बानो केस।
120 ‘यह बात निर्विवाद रूप से स्पष्ट है,’ टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक संपादकीय में लिखा: गिरिलाल जैन,
‘संपादकीय: अनुत्तरित प्रश्न’, टाइम्स ऑफ इंडिया, 6 मार्च 1986।
120 दो दिशाओं में खिंचे चले जाने के कारण, नवंबर 1985 के मध्य तक, राजीव

गांधी अभी भी अनिश्चित थे: आरिफ
मोहम्मद खान द्वारा लेखक को, 21 अगस्त 2018, नई दिल्ली।
120 ‘प्रधानमंत्री के घर से एक फोन आया था’: वही।
121 ‘उड़ान में चढ़ने के तुरंत बाद, एक अधिकारी ने मुझे बताया’: वही।
121 ‘ऐसा नहीं है कि इस गतिरोध से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता’: वही।
121 ‘Nahi, koi sawaal hi nahin inke saath samjhauta karne ka’: Ibid.
121 ‘अगर मुझे इन वार्ताओं में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने उनकी बात मान ली है’
स्थिति’: वही।
122 एम. जे. अकबर एक शिक्षित और वाक्पटु मुस्लिम थे, और एक प्रमुख पत्रकार थे जिन्होंने
प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए: वजाहत हबीबुल्लाह ने लेखक को बताया; हबीबुल्लाह, माय इयर्स विद राजीव, 2020।
122 ‘मैं अल्पसंख्यक मामलों की देखरेख कर रहा था’: वजाहत हबीबुल्लाह ने लेखक से कहा, 26 अप्रैल 2019, न्यू
दिल्ली।
122 ‘व्यक्तिगत कानून का संपूर्ण प्रश्न और भारत में इसका अनुप्रयोग’: वही।
122 उनका मानना था कि सरकार को अधिकतम यही करना चाहिए कि वह 'मामले में हस्तक्षेप न करे': वही।
122 ‘मैंने एक ही नोट भेजा था…वह अभी भी वहीं होगा’: वही।
123 ‘क्या तुम इधर आओगे?’ उसने बिना भूमिका के पूछा: वही।
123 ‘आप हम में से एक हैं’: वही।
123 ‘उन्हें लग सकता है कि वे मेरे अपनों में से नहीं हैं’: वही।
123 वे निष्कर्ष निकालेंगे कि राजीव उन्हें 'वास्तव में अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते थे': वही।
123 ‘मैंने और (या यूँ कहें कि) अकबर ने—दोनों ने 1985 में निर्णय लेने में “गलती” की थी’: वही।

124 1857 के विद्रोह के बाद से, इस्लामी धर्मगुरुओं ने स्वयं को प्रतिनिधित्व करने का दायित्व ग्रहण कर लिया था।
समुदाय: वही।
124 मामला उसके हाथ से बाहर था: वही।
124 शाह बानो फैसले पर हुई बहस ने कांग्रेस पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया: Wajahat Habibullah to author; D. P. Tripathi to author, March 2018, on tape.
124 पी. वी. नरसिम्हा राव, अर्जुन सिंह, एन. डी. तिवारी और एस. बी. चव्हाण: डी. पी. त्रिपाठी लेखक को।
19 अप्रैल 2018, नई दिल्ली; आरिफ मोहम्मद खान द्वारा लेखक को, 21 अगस्त 2018, नई दिल्ली।
124 उन्होंने बढ़ते मुस्लिम विरोध से निपटने के तरीके के बारे में उनसे सलाह ली: आरिफ मोहम्मद
खान से लेखक, 21 अगस्त 2018, नई दिल्ली; लेखक वजाहत हबीबुल्लाह, 26 अप्रैल 2019, नई दिल्ली।
124 राव ने राजीव से कहा कि 'इस मामले को लंबा खींचना': आरिफ मोहम्मद खान ने लेखक को 21 अगस्त को लिखा
2018, नई दिल्ली।
124 'यद्यपि राजीव ने मुझे पीएमएच में संसद में बोलने के लिए कहा था': वही।
125 'मुझे पता था कि राजीवजी अपना मन नहीं बदलेंगे': वही।
125 राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय इस्लामी मत का भी ध्यान रखते थे: शाहिद सिद्दीकी ने लेखक को बताया।
25 मार्च 2019, नई दिल्ली।
125 'हालांकि मैंने अपना अभियान काफी धर्मनिरपेक्ष रखा': फरज़ंद अहमद और अजय कुमार, 'उपचुनाव'
सात लोकसभा और नौ विधानसभा सीटों पर मिली हार से कांग्रेस (आई) को भारी चोट पहुंची', इंडिया टुडे, 15 जनवरी 1986।
125 'यह युवा, नेक प्रधानमंत्री, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता है, अपनी ही पार्टी को बर्बाद कर रहा है।

अपने 100वें वर्ष में': शेखर गुप्ता, 'असम गण परिषद की विजय ने असम में आशा और परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत की', इंडिया टुडे, 15 जनवरी 1986।
125 अजय ने राजीव को फैसले को पलटने के लिए विधेयक पेश करने की औचित्यता के बारे में समझाया:
कुमार, 'मुस्लिम महिला विधेयक ने तीखी बहस छेड़ दी, राजीव गांधी सरकार मुश्किल में फंस गई', इंडिया टुडे, 31 मार्च 1986।
126 राजीव ने नजमा हेपतुल्ला से इसकी जाँच करने का आग्रह किया: वही।
126 उन्होंने अशोक सेन को कानून बनाने और जियाउर रहमान और अन्य लोगों की मदद लेने का निर्देश दिया।
मुस्लिम नेता: शाहिद सिद्दीकी ने लेखक को संबोधित करते हुए 25 मार्च 2019 को नई दिल्ली में यह बात कही।
126 'आप रातोंरात प्रधानमंत्री नहीं बन गए': वही। सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें यह बताया गया था।
स्वयं राजीव गांधी द्वारा।
127 ये तीन मुद्दे भाजपा के 'मुख्य मुद्दों' के रूप में पहचाने जाने लगे थे: अनुच्छेद 44 संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर समान कानून लागू होंगे। संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और आरएसएस भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
127 'राजीव को क्या लगता है कि वह क्या कर रहा है?': वजाहत हबीबुल्लाह ने लेखक से 26 अप्रैल 2019 को पूछा, न्यू
दिल्ली। हबीबुल्लाह ने नेहरू को यह कहते हुए सुना था।
127 राजीव 'हिंदू वोट बैंक' को कैसे भूल सकते थे: नीरजा चौधरी, 'द पॉलिटिकल फॉलआउट'
द स्टेट्समैन, 20 अप्रैल 1986।
127 कुछ लोगों ने दबी आवाज़ में चर्चा की कि क्या मुस्लिम महिला विधेयक को हराया जा सकता है।

मंच पर: लेखक उस समय के कुछ सांसदों के साथ बातचीत कर रहे थे।
127 यह उनके नेतृत्व के खिलाफ हो सकता है: शाहिद सिद्दीकी ने लेखक से कहा, 25 मार्च 2019, नई दिल्ली।
यह बात राजीव गांधी ने सिद्दीकी को बताई थी।
127 'विधेयक का मसौदा तैयार है, कृपया अभी जाकर विधि मंत्री से मिलें': आरिफ मोहम्मद
खान ने लेखक को 21 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में पत्र लिखा।
128 'क्या वे (एआईएमपीएलबी और अन्य संबंधित लोग) इस पर सहमत हुए हैं?': वही।
128 'आरिफ, मैं तुमसे चुप रहने की विनती कर रहा हूँ': वही।
128 'उन्होंने यह नहीं कहा कि कृपया इसे मुस्लिम नेताओं के साथ साझा न करें': आरिफ मोहम्मद खान
लेखक, 19 अगस्त 2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
128 जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इसके सलाहकारों में कांग्रेस मंत्री सलमान खुर्शीद और अशरफ शामिल थे।
'शाहबानो मामले पर आरिफ मोहम्मद खान:' नजमा हेपतुल्ला का राजीव गांधी पर महत्वपूर्ण प्रभाव था"।
128 लेकिन तब तक सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई दबाव डाले तो: आरिफ मोहम्मद खान
लेखक को, 19 अगस्त 2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
128 एआईएमपीएलबी को तलाकशुदा लोगों के लिए वित्तीय निपटान राशि बढ़ाने में कोई समस्या नहीं थी।
महिला: कुमार, 'मुस्लिम महिला विधेयक ने तीखी बहस छेड़ दी है, जिससे राजीव गांधी सरकार मुश्किल में फंस गई है।'
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने वर्षों बाद कहा था कि 'चालाकी से गढ़े गए शब्दों'
'सेक्शन': मणि शंकर अय्यर, 'शूटिंग फ्रॉम द लिप', द वीक, 27 सितंबर 2020।
129 'राजीव गांधी और उनके कानूनी सलाहकारों' ने 'दुविधा का समाधान कर लिया था': मणि शंकर अय्यर,
'राजीव गांधी पर इस फैसले के लिए हमले हुए। मेरा मानना है कि यह एक

प्रतिभापूर्ण निर्णय था।', एनडीटीवी, 2 अगस्त 2016।

129 'Ashoke Sen did not inform Rajiv Gandhi about it': Arif Mohammad Khan to author, 19

अगस्त 2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार।

129 वे दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागार में एक सार्वजनिक सभा में बोल रहे थे: हेमंत शर्मा।

Yuddha Mein Ayodhya, Delhi: Prabhat Prakashan, 1 January 2018.

129 आरिफ ने कहा कि उसे विधेयक से ध्यान हटाने और 'संतुलन बनाने' के तरीके खोजने पड़े।

मोहम्मद खान, 'पीछे मुड़कर देखें: जब एक और मुस्लिम महिला विधेयक ने प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता को जन्म दिया', हिंदुस्तान टाइम्स, 31 जुलाई 2019।

129 उन्होंने स्वीकार किया कि शाह बानो के फैसले ने लोगों के मन में अनिश्चितता पैदा कर दी थी।

'कुछ समुदायों': कुमार, 'मुस्लिम महिला विधेयक ने तीखी बहस छेड़ दी है, राजीव गांधी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है'।

129 सीआरपीसी ने महिलाओं को केवल मामूली रकम दी: वही।

129 'मुसलमान (आम तौर पर) संसद के अपने कानूनों में संशोधन करने के अधिकार को स्वीकार नहीं करते': शाहिद सिद्दीकी

लेखक को, 25 मार्च 2019, नई दिल्ली।

129 कि यह 'सोए हुए हिंदू दिग्गज' को जगाएगा: खान, 'पीछे मुड़कर देखना: जब एक और

मुस्लिम महिला विधेयक ने प्रतिस्पर्धात्मक सांप्रदायिकता को जन्म दिया।

130 'मैं तुम्हें ढूंढ रहा था,' सिंह ने कहा: आरिफ मोहम्मद खान ने लेखक से कहा।

130 'डेढ़ घंटे तक,' खान ने याद किया, 'उन्होंने मुझ पर बहुत दबाव डाला': वही।

130 'मैं संसद में था और मैंने सदन में आरिफ को स्पष्ट रूप से परेशान देखा': अरुण नेहरू ने लेखक से कहा

विशेष, अब तक अप्रयुक्त साक्षात्कार, 16 मई 2001, नई दिल्ली।

130 'आप क्या कर रहे हैं?' उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा: वही।

131 ‘राजीव, तुमने आरिफ से पहले यह कहा था’: वही।
131 ‘आरिफ पर शारीरिक हमला होने वाला है’: वही।
131 ‘आप लोगों को इस तरह नहीं छोड़ सकते’: वही।
131 ‘Mujhe jahaan tak yaad hai’: Arif Mohammad Khan to author, 21 August 2018, New Delhi.
131 ‘Rajivji ghabraye toh usi se thae’: Ibid.
131 ‘मैं आपको वही शब्द बता रहा हूँ…जो उसने कहे थे’: वही।
131 ‘यदि मुसलमान सामाजिक सुधार नहीं चाहते’: वही।
131 ‘शाह बानो ने भी अब कहा है कि वह उसे दी जाने वाली भरण-पोषण राशि छोड़ देगी’: वही।
132 ‘प्रमुख मुस्लिम नेता सैयद शहाबुद्दीन हमारे घर आए थे’: सईद खान, ‘“मेरी माँ उनके साथ अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ”, हिंदुस्तान टाइम्स, 12 नवंबर 2011।
132 ‘इंदौर में भी एक लाख लोगों की रैली हमारे घर के सामने से गुजरी’: वही।
132 प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि स्थिति 'बहुत गंभीर' है: वही।
132 ‘राजीव ने हमसे यह घोषणा करने को कहा कि हम भरण-पोषण से इनकार कर रहे हैं’: वही।
132 उसने घोषणा की कि वह अदालत द्वारा आदेशित भरण-पोषण राशि नहीं ले रही है: तवलीन सिंह,
‘शाह बानो ने नाटकीय रूप से अपना रुख बदला, सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला वापस लेने का अनुरोध किया’, इंडिया टुडे, 15 दिसंबर 1985।
132 ‘मुझे लगा था कि मेरी माँ दो, पाँच, दस साल और जीवित रहेंगी’: खान, ‘“मेरी माँ
अन्याय किया गया, घोर अन्याय किया गया।
133 'ताला खुलवा दो,' अरुण नेहरू ने प्रधान मंत्री को सलाह दी: आरिफ मोहम्मद खान को
लेखक, 21 अगस्त 2018, नई दिल्ली। उन्हें यह बात स्वयं अरुण नेहरू ने बताई थी।
133 चिंतित राजीव ने अपने चचेरे भाई को सलाह लेने के लिए बुलाया था: शर्मा, युद्ध में अयोध्या,
पृष्ठ 263.

133 ‘Hindus khush ho jayengae,’ Nehru told Rajiv: Shahid Siddiqui to author. Siddiqui had
मैंने यह बात राजीव गांधी से सुनी।
134 टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक गिरिलाल जैन ने राजीव गांधी के खिलाफ एक तीखा लेख लिखा था।
गांधी: जैन, ‘संपादकीय: अनुत्तरित प्रश्न’।
134 एक अन्य प्रख्यात संपादक, अरुण शौरी ने भी इसी पत्रिका में दो समान रूप से आलोचनात्मक लेख लिखे थे।
लेख: कुमार द्वारा उल्लिखित, 'मुस्लिम महिला विधेयक ने गरमागरम बहस छेड़ दी, राजीव गांधी सरकार को मुश्किल में डाल दिया'।
134 ‘मैंने राजीव को मुस्लिम पर्सनल लॉ से पूरी तरह निर्दोष पाया’: अरुण शौरी ने लेखक से कहा, 12
सितंबर 2022 में, नई दिल्ली में एक टेलीफोन वार्ता में।
134 ‘एक तिहत्तर वर्षीय निर्धन महिला को प्रति माह 179.20 रुपये का भुगतान करना किस प्रकार खतरे में डाल सकता है?
इस्लाम?’: वही।
134 ‘Taala khul sakta hai kya?’: Arif Mohammad Khan to author, 21 August 2018, New Delhi.
उन्होंने कहा कि अरुण नेहरू ने स्वयं उन्हें यह बात बताई थी।
134 उन्होंने कथित तौर पर इसके बंद होने के संबंध में कोई विशिष्ट अदालती आदेश नहीं पाया: फरज़ंद अहमद, 'आदेश
अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर को फिर से खोलने से तनाव चरम पर पहुंच गया है', इंडिया टुडे, 28 फरवरी 1986।
135. 18 सितंबर 1985 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. डी. तिवारी ने अचानक राजीव गांधी को पत्र लिखा था।
गांधी: प्रभु चावला, ‘एन. डी. तिवारी ने उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह के लिए खुशी-खुशी अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया’, इंडिया टुडे, 15 अक्टूबर 1985।
135 अगली सुबह तिवारी शपथ ग्रहण करने के लिए दिल्ली के लिए उड़ान भरी: वही।

135 इंदिरा गांधी के जीवित रहते हुए उन्होंने अरुण नेहरू के इस विचार को खारिज कर दिया था: वजाहत हबीबुल्लाह
लेखक को, 12 सितंबर 2022 को, टेलीफोन पर हुई बातचीत में।
135 'मैं नहीं चाहता था कि बाद में यह कहा जाए कि अरुण नेहरू ने वीर बहादुर सिंह को निर्देश दिए थे':
आरिफ मोहम्मद खान ने लेखक को 21 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि अरुण नेहरू ने स्वयं उन्हें यह बात बताई थी।
135 'मुझे नहीं पता कि अरुण नेहरू ने मुझे जो बताया वह सही था या गलत': वही।
135 'मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अरुण नेहरू ही सारा मामला संभाल रहे थे': शर्मा, युद्ध में
Ayodhya, p. 255.
135 सिंह ने वीएचपी को एक संदेश भेजा: वही, पृष्ठ 258; के. आर. मलकानि, अयोध्या की राजनीति और
हिंदू-मुस्लिम संबंध, नई दिल्ली: हर-आनंद प्रकाशन, 1993, पृष्ठ 27।
135 'अधिकारी (यहाँ जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक का जिक्र था)
अनौपचारिक रूप से वीएचपी से आवेदन आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था: वही।
136 'वीएचपी...को ताला खोलने में दिलचस्पी थी लेकिन अदालत जाने में नहीं': वही।
136 वीएचपी से उनके संबंधों में से एक बी.पी. सिंघल थे: जी.एस. चावला ने लेखक को 21 अगस्त 2021 को लिखा।
टेलीफोन पर साक्षात्कार।
136 1986 में बी.पी. सिंघल अतिरिक्त सचिव थे: बाद में नेहरू और बी.पी. सिंघल दोनों ही
चेक पिस्तौल खरीदने के सौदे में गड़बड़ी के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया और यह मामला नेहरू की मृत्यु तक चलता रहा।
136 'अरुण नेहरू ने इस तख्तापलट की योजना बनाई': चौधरी, 'राजनीतिक परिणाम'।
136 'राजीव गांधी ने स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया था कि राम जन्मभूमि के द्वार
अवश्य खुलना चाहिए': वही।

136 यह आरएसएस ही था जिसने उसे संदेश भेजा था कि करण सिंह सबसे अच्छा हिंदू चेहरा है।
कांग्रेस को क्या प्रदर्शित करना चाहिए: अनिल बाली ने लेखक से कहा, 8 अगस्त 2019, नई दिल्ली।
137 हालांकि इंदिरा गांधी और करण सिंह के बीच शायद ही कोई संपर्क हुआ था:
कश्मीर और उससे परे 1966-84: इंदिरा गांधी और करण सिंह के बीच चयनित पत्राचार, जावेद आलम (संपादक), नई दिल्ली: पेंगुइन इंडिया, 2011, पृ. 286-87.
137 उसने 1980 के बाद उससे सुलह करने का फैसला किया: करण सिंह लेखक बने।
137 करण सिंह ने पूरे विश्व में विराट हिंदू सम्मेलनों (मेगा हिंदू सम्मेलनों) का आयोजन किया।
देश: 'अशोक सिंघल: वह व्यक्ति जिसने हिंदू वोट बैंक की अवधारणा को आकार दिया', डीएनए, 18 नवंबर 2015।
137 'एक चतुर राजनीतिज्ञ होने के नाते, उन्होंने इन सम्मेलनों का लाभ उठाया': करण
सिंह ने लेखक को 4 जनवरी 2021 को लिखा।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने 'हिंदू समाज को एकजुट करने' के उद्देश्य से 3 लाख गांवों तक पहुंचने के लिए 137 यात्राएं कीं: सुमित मित्रा, 'वीएचपी'
'एकाइमता यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 92 धार्मिक काफिले भारत भर में निकलेंगे', इंडिया टुडे, 30 नवंबर 1983।
137 'हिंदू धर्म खतरे में', और 'वोट बैंक के रूप में मुसलमानों को लाड़-प्यार करना': वही।
137 'विश्व हिंदू परिषद द्वारा 1983 में आयोजित एकात्मा यात्रा को इंदिरा गांधी ने वित्त पोषित किया था': अनिल बाली ने लेखक को बताया।
137 वह दोनों तरह से खेल खेलना जानती थी: मंजरी काटजू, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय राजनीति, नई दिल्ली: ओरिएंट लॉन्गमैन, 2003, पृ. 40.
137 वह चुपचाप उन नए हिंदू संगठनों को भी प्रोत्साहित कर रही थी जो अचानक उभर आए थे।
तेजी से फैल गया: नीरजा चौधरी, 'समुदायों को खुश करने का अदूरदर्शी कदम', द

स्टेट्समैन, 1 मई 1986।
137 शीर्ष स्तर की मंजूरी के बिना यह बैठक आयोजित नहीं की जा सकती थी: मित्रा, 'वीएचपी-
'एकाइमता यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें 92 धार्मिक काफिले भारत भर में घूमेंगे।'
138 'अयोध्या को एक चुनावी मुद्दा बनाना' एक 'उपयुक्त समय' पर: अशोक सिंघल ने लेखक से कहा;
लेखक द्वारा 20 अप्रैल और 1 मई 1986 को द स्टेट्समैन में प्रकाशित तीन लेखों में इसका उल्लेख किया गया है।
138 वह हिंदुओं की भावनाओं के प्रति पहले से कहीं अधिक सचेत हो गई थी।
मुसलमानों या सिखों में से: फ्रैंक, इंदिरा; जयकर, इंदिरा गांधी; एस. एस. गिल, द डायनेस्टी: ए पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ द प्रीमियर रूलिंग फैमिली ऑफ मॉडर्न इंडिया, नई दिल्ली: हार्परकॉलिन्स, 1996।
138 हर बार जब वह 'पीछे हट गई': हरकिशन सिंह सुरजीत ने मार्क टली और सतीश जैकब से कहा, उद्धृत
रशीद किदवई द्वारा लिखित, 'राय | इंदिरा गांधी और पंजाबी भाषी पंजाब को अलग करने में उनकी अनिच्छा', न्यूज18, 31 अक्टूबर 2018।
138 राजीव गांधी ने 1982-84 के बीच भाऊराव से तीन बार मुलाकात की, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, और एक बार
1991 के आरंभ में: सुभाष आर्य ने लेखक से 24 जुलाई 2020 को टेलीफोन पर साक्षात्कार लिया। अनिल बाली ने भी लेखक से 7 मार्च 2018 को नई दिल्ली में इसकी पुष्टि की।
138 भाऊराव और राजीव की आपस में अच्छी बनती थी और वे हर तरह के विषयों पर बात करते थे: वही।
139 'भौराव को लगता था कि राजीव के साथ हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा': अनिल बाली ने लेखक को 7 मार्च को बताया
2018, नई दिल्ली।
139 'I am an eyewitness to Rajiv Gandhi doing charan sparsh': Banwarilal Purohit to author.

139 ‘उन्होंने कहा कि यह जेपी के भूमिगत रहने के दौरान उनसे हुई उनकी मुलाकात की तरह था’: के. एन. गोविंदाचार्य
लेखक, 3 जुलाई 2018, नई दिल्ली।
139 ‘हम उनके लिए ताजे जामुन का रस जरूर लाते थे’: पुष्पा मोहन, कपिल की पत्नी
मोहन, लेखक को, 4 नवंबर 2020, टेलीफोन साक्षात्कार, नई दिल्ली।
139 अनिल बाली जब भी झंडेवालन में उनसे मिलने जाते थे, तब जामुन का रस लेकर जाते थे:
अनिल बाली ने लेखक को 7 मार्च 2018 को नई दिल्ली में पत्र लिखा।
139 ‘ताकि धवन को कुछ पता न चले’: वही।
139 ‘अगर कोई एक व्यक्ति था जिसने 1985-1985 के बीच राजीव गांधी पर हिंदूकरण का प्रभाव डाला, तो वह यही था।
89’: वही।
139 ‘राजीव से कहो कि वह खाने की मेज पर इस बारे में (आरएसएस के साथ अपनी बातचीत के बारे में) बात न करे’: एम. एल. फोतेदार ने कहा।
लेखक।
139 ‘वह जानती थी कि सोनिया आरएसएस की घोर विरोधी थीं’: अनिल बाली ने लेखक से कहा, 7 मार्च 2018, न्यू
दिल्ली।
139 ‘मुझे तो कार का रंग भी याद है—वह चॉकलेट रंग की थी: पंकज वोहरा ने लेखक से कहा,
1 अगस्त 2022, नई दिल्ली।
139 ‘Chiranjeevi Rajiv, Ramayana agar Bharat men nahin dekhi jayegi’: Anil Bali to author, 7
मार्च 2018, नई दिल्ली।
140 ‘भौराव ने जनवरी 1989 में मेरे माध्यम से राजीव को संदेश भेजा था’: अनिल बाली ने लेखक को बताया, 7
मार्च 2018, नई दिल्ली।
पंकज वोहरा ने लेखक से कहा, 140 आईबी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि पार्टी

300 सीटें जीतेगी।
अगस्त 2022, नई दिल्ली।
आरएसएस और राजीव गांधी के बीच 'शिलान्यास' को लेकर 140 'गुप्त समझौता': कांग्रेस के पूर्व सांसद का आरोप
'राजीव और आरएसएस के बीच गुप्त समझौता', टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 अप्रैल 2007।
140 'उस समय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, मैंने तत्कालीन आरएसएस के बीच एक बैठक की सुविधा प्रदान की': वही।
140 'इसके तुरंत बाद, देवरास ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह से मुलाकात की':
वही।
140 'मुझे याद है कि उन दिनों सिंह अक्सर झंडेवालन आया करते थे': सुभाष आर्य ने कहा
लेखक, 24 जुलाई 2020, टेलीफोन साक्षात्कार, नई दिल्ली।
140 राजीव गांधी को सैयद शहाबुद्दीन को बताना था कि बूटा सिंह और एन.डी. तिवारी ने 'गुमराह' किया था
सैयद शहाबुद्दीन ने लेखक को 20 जुलाई 2005 को नई दिल्ली में पत्र लिखा।
140 'मैं आपको बताऊंगा कि आरजी ने मुझे मार्च 1991 में, अपनी मृत्यु से दो महीने पहले क्या बताया था': वही।
140 'शहाबुद्दीन साहब, आप सही हैं': वही।
141 'उसने (राजीव ने) (उस दिन) स्वीकार किया कि शिलान्यास न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए किया गया था':
वही।
141 राजीव ने भाऊराव से चंद्र शेखर द्वारा विकसित फार्मूले को अस्वीकार करने का अनुरोध किया: अनिल बाली को
लेखक, 7 मार्च 2018, नई दिल्ली।
141 'उसने उन्हें सेब का एक-एक टुकड़ा दिया': वही।
141 'Bahut shaleen ladka hai': Ibid.
141 'आपको नहीं पता कि क्या बग किया गया है और क्या नहीं': वही।

141 ‘उसने तीन बार मेरी पीठ पर हाथ रखा’: वही।
142 देवरास बंधुओं, बालासाहेब और भाऊराव ने राजीव को 'निर्दोष' पाया, जबकि वास्तव में वह कौन हो सकता था?
‘ढाला गया’: पंकज वोहरा ने लेखक से कहा, 1 अगस्त 2022, नई दिल्ली।
142 उन्होंने राजनीतिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व किया जो आरएसएस को आकर्षक लगी: अनिल बाली ने लेखक को बताया, 12
सितंबर 2020, फोन पर साक्षात्कार। सुभाष आर्य ने लेखक को इसकी पुष्टि करते हुए 24 जुलाई 2020 को टेलीफोन पर साक्षात्कार दिया।
142 ‘अरुण नेहरू से एक शब्द भी नहीं,’ उन्होंने जोर देकर कहा: अनिल बाली ने लेखक से कहा, 7 मार्च 2018, न्यू
दिल्ली।
142 ‘भौराव को लगा कि ताला खोलने से राष्ट्रीय सहमति बनेगी’: गोविंदाचार्य ने कहा
लेखक, 3 जुलाई 2018, नई दिल्ली। अनिल बाली द्वारा लेखक को 12 सितंबर 2020 को टेलीफोन साक्षात्कार के माध्यम से पुष्टि की गई, नई दिल्ली।
143 ‘You have taken a historical step. Hindu Hridaya samrat bano aur rajya karo’: Anil Bali to
लेखक, 7 मार्च 2018, नई दिल्ली।
उमेश चंद्र पांडे ने तुरंत 31 तारीख को फैजाबाद जिला न्यायालय में अपील दायर की।
जनवरी: मलकानी, द पॉलिटिक्स ऑफ़ अयोध्या, पृ. 27.
144 ऐसी अफवाह थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने न्यायाधीश कृष्णा से बात की थी।
मोहन पांडे: इलियास आज़मी, 'मैं राजीव गांधी और वीर बहादुर सिंह को मौत की सजा सुनाता', उर्दू मीडिया मॉनिटर, 11 अप्रैल 2015।
144 उन्होंने तर्क दिया कि संरचना को 1949 में अदालत द्वारा प्रशासनिक रूप से बंद कर दिया गया था, न कि
न्यायिक आदेश: कुमार अंशुमन, 'सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, उस व्यक्ति का कहना है जिसकी याचिका पर 1986 में ताले खोले गए थे', इकोनॉमिक टाइम्स, 9 नवंबर 2019।

144 ‘डीएम और एसएसपी स्वयं अदालत में आए’: शर्मा, युद्ध में अयोध्या, पृ. 252; यह बात जज कृष्णा मोहन पांडे ने आरिफ मोहम्मद खान को और खान ने लेखक को 21 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में बताई थी।
जिला प्रशासन के निर्देश पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्रवाई की गई:
जब कानून को खतरा हो और पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई जाए, ताकि सार्वजनिक शांति भंग न हो, तो जिला प्रशासन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्रवाई करता है।
144 ‘हम ही मौके पर सरकार हैं, और हम ही कानून-व्यवस्था संभालेंगे’: शर्मा, युद्ध Maen Ayodhya, p. 252.
144 ‘हमने जिला न्यायाधीश को बताया कि हम स्थिति को संभालने में सक्षम होंगे’: इंदु कुमार पांडे
लेखक, 5 अगस्त 2021।
145 ‘दूरदर्शन की टीम यहां कौन भेजेगा?’: जज कृष्ण मोहन पांडे ने आरिफ से पूछा मोहम्मद खान, और खान लेखक को, 21 अगस्त 2018, नई दिल्ली।
145 ‘तब मुझे यह तसल्ली हुई कि सरकार यही चाहती थी’: वही।
145 न्यायाधीश पांडे ने प्रत्यक्ष दर्शन की अनुमति देने के लिए जिला अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर भरोसा किया।
of ‘Ram Lalla’: Sharma, Yuddh Maen Ayodhya, p. 251.
145 ‘गेट “ओ” और “पी” पर ताले खोलने से स्वर्ग नहीं गिरने वाला है’: वही।
145 इसके बाद, डीएम और एसएसपी ने जिला न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से उनके कार्यालय तक पहुँचाने का विशेष ध्यान रखा।
निवास: वही, पृष्ठ 246।
145 जंग लगे ताले शाम 5.19 बजे तोड़ दिए गए: चौधरी, 'राजनीतिक परिणाम'।
145 ‘मुझे यह बात उत्तर प्रदेश के एक कांग्रेस नेता ने बताई, जो प्रतीक्षा कक्ष में बैठे थे’: वजाहत हबीबुल्लाह
लेखक को, 12 सितंबर 2022, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
145 न तो मुंसिफ और न ही जिला न्यायाधीश को इस मामले में कोई राय देने का अधिकार था: शर्मा।

Yuddh Maen Ayodhya, p. 254.
145 वीएचपी ने ताला खोलने का श्रेय लिया: चौधरी, 'राजनीतिक परिणाम'।
146 ‘शाह बानो अब हाशिए पर चली जाएंगी’: आरिफ मोहम्मद खान 21 अगस्त 2018 को लेखक से कहेंगे।
19 अगस्त 2021 को पुनः पुष्टि की गई।
146 ‘मुझे ऐसा कोई डर नहीं है’: वही; खान, पाठ और संदर्भ, पृ. 4.
146 ‘मैंने दूसरी तरफ के संबंधित पक्षों को सतर्क कर दिया था’: वही।
146 ‘Aur bhi bahut si masjidon par gairon ka kabza hai’: Ibid.
146 ‘सब कुछ पूर्वनियोजित था,’ अधिवक्ता अब्दुल मन्नान अहमद ने टिप्पणी की: ‘पुनः खोलने का आदेश’
अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में तनाव चरम पर पहुंच गया है।
146 उन्होंने बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया:अंशुमान कुमार, ‘अयोध्या मामला: भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले संपत्ति विवाद का संक्षिप्त इतिहास’, इकोनॉमिक टाइम्स, 10 नवंबर 2019।
146 ‘धर्मनिरपेक्षता में उनकी आस्था’ को ‘कमजोर’ किया: अहमद, ‘राम जन्मभूमि मंदिर को फिर से खोलने का आदेश’
अयोध्या परिसर में तनाव चरम पर पहुंच गया है।
147 ‘यदि बाबरी मस्जिद मुसलमानों को वापस नहीं सौंपी गई, तो वे कांग्रेस (आई) से नफरत करने लगेंगे’:
नीरजा चौधरी द्वारा तीन भागों की श्रृंखला में, द स्टेट्समैन, 20 अप्रैल 1986।
147 ‘उन्हें एक यथास्थिति का सामना करना पड़ा’: वजाहत हबीबुल्लाह ने लेखक को 12 सितंबर 2022 को लिखा।
नई दिल्ली में टेलीफोन पर हुई बातचीत में।
147 हालाँकि वह अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में थे, लेकिन हबीबुल्लाह को खोलने के निर्णय में शामिल नहीं किया गया था।
ताले: वजाहत हबीबुल्लाह, 26 अप्रैल 2019, नई दिल्ली।
147 ‘किसी भी धर्म के पूजा स्थलों में हस्तक्षेप करना गलत है और ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए’: वही।
147 ‘हां, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि इसका आदेश किसने दिया था,’

राजीव ने कहा: वजाहत हबीबुल्लाह, 26 अप्रैल 2022,
नई दिल्ली।
147 ‘और जब मुझे पता चलेगा तो मुझे डर है कि मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी’: वजाहत हबीबुल्लाह, 26 अप्रैल
2019, नई दिल्ली; हबीबुल्लाह, राजीव के साथ बिताए मेरे वर्ष।
147 ‘हां, राजीव गांधी ने भी मुझे बताया था कि उन्होंने आदेश नहीं दिया था’: शाहिद सिद्दीकी ने लेखक से कहा।
7 मार्च 2020 को मुंबई से किए गए एक स्पष्टीकरणात्मक फोन कॉल में।
147 ‘मुझे नहीं लगता कि राजीव गांधी को ताले खोले जाने की जानकारी थी’: एम. के. नारायणन
लेखक, 8 अगस्त 2022, टेलीफोन साक्षात्कार, चेन्नई।
147 ‘यह संभव नहीं है कि राजीव गांधी को ताले खुलने की जानकारी न हो’:
एक अज्ञात वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने लेखक को 3 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में पत्र लिखा।
148 ‘जुलाई 1985 में, राजीव गांधी ने मुझसे कहा कि स्वीडिश लोगों के बारे में और परेशान न हों’: आर.ओ. और ए.सी.
लेखक के समक्ष, हस्ताक्षरित, हस्ताक्षर, 18-3-97, केशव मिश्रा, उप एसपी/ सीबीआई/एसपीई/एसआईजी नई दिल्ली।
148 नेहरू का स्वीडिश सरकार के साथ विवाद हो गया था: वही।
148 ‘मुझे इसमें मजबूर किया गया था’: अरुण नेहरू ने लेखक से कहा, 16 मई 2001, नई दिल्ली।
148 ‘हमने पहले दिन से ही हड़बड़ी शुरू कर दी’: वही।
148 ‘अब यह मेरी टीम है’: वही।
149 ‘जब मैं आंतरिक सुरक्षा मंत्री बना’: सीबीआई के समक्ष अरुण नेहरू का बयान मार्च 1997, नई दिल्ली।
149 ‘राजीव गांधी के पास उनसे मिलने का समय नहीं था, इसलिए वे मुझसे मिले’: वही।
149 ‘खुफिया प्रमुखों के लिए प्रधानमंत्री को रिपोर्ट न करना अकल्पनीय था’: एम. के.

नारायणन ने लेखक से 16 अगस्त 2022 को चेन्नई में टेलीफोन पर साक्षात्कार किया।
149 उस समय की खुफिया एजेंसियां 'अपनी भूमिका के सार में बदलाव होने के बावजूद भी अपने पुराने तौर-तरीकों पर अड़ी रहीं'।
'कमजोर पड़ गया था': बी. एन. उनियाल ने लेखक से 27 फरवरी 2021 को टेलीफोन पर बातचीत में कहा, नई दिल्ली।
149 'कभी-कभी वह मुझे दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करते और बातचीत करते': एम. के. नारायणन ने लेखक को 16 अगस्त को लिखा
2022, टेलीफोनिक साक्षात्कार, चेन्नई।
149 'वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा था, और यही मुख्य समस्या थी': वही।
149 'लेकिन कभी-कभी अरुण नेहरू राजीव से मिलने आते थे': बी. एन. उनियाल ने लेखक को बताया, 27
फरवरी 2021, टेलीफोन पर हुई बातचीत, नई दिल्ली।
149 'यह पार्टी के अंदर और बाहर विरोधियों को "लाइन में लाने" का एक तरीका था': वही।
149 'राजीव गांधी इस (स्थिति) से परेशान थे': सीबीआई के समक्ष अरुण नेहरू का बयान, 16
मार्च 1997।
149 'तो, वे मुझे मौखिक रिपोर्ट देते थे': वही।
149 'मेरी कार्यशैली इतनी आक्रामक थी': अरुण नेहरू ने लेखक से कहा, 16 मई 2001, नई दिल्ली।
150 'वह मुझसे पूछा करता था कि इतिहास के प्रति तुम्हारी समझ किस काम की है': वही।
150 'उसने उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों को उलट दिया': वही।
150 'मैंने उसका विरोध किया': वही।
150 '(समस्या यह है) आप टकराव चाहते हैं, मैं सुलह चाहता हूँ': वही।
150 'तब वह महारानी बन गई': वही।
150 'मुझे घरेलू लॉबी या रसोई कैबिनेट की बिल्कुल भी परवाह नहीं है': वही।

150 सोनिया को शक था कि अरुण नेहरू राजीव और उनके परिवार पर नजर रख रहे थे: शाहिद
सिद्दीकी ने 25 मार्च 2019 को नई दिल्ली में एक पत्र लिखा। साथ ही, अरुण नेहरू के करीबी रहे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने 3 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में एक पत्र लिखा।
150 'सोनिया गांधी ने राजीव को बताया था कि मैं उन पर नजर रख रहा था': अरुण नेहरू ने कहा
लेखक, 16 मई 2001, नई दिल्ली।
150 'प्रधानमंत्री के घर की सुरक्षा (अब) मेरा काम था': वही।
150 वह उद्दंड था, उसका तिरस्कार कर सकता था और यहां तक कि राजीव पर चिल्ला भी सकता था: बी. एन. उनियाल ने लेखक को बताया।
27 फरवरी 2021, टेलीफोन पर हुई बातचीत, नई दिल्ली।
151 'Mitra bhi agar Raja ho jaye toh aap usko "hey rajan" bulate hain': Ibid.
151 'अरुण नेहरू को कभी भी क्वात्रोची से परिवार की निकटता पसंद नहीं थी': दिनेश त्रिवेदी ने लेखक से कहा, 5
मई 2001, नई दिल्ली।
151 'सोनिया शायद इसे भूली नहीं होगी': लेखक को अज्ञात सूत्र।
151 'शाह बानो सिर्फ शाह बानो के बारे में नहीं थी': शाहिद सिद्दीकी ने लेखक से कहा।
151 '(अरुण नेहरू) को लगता था कि वे ही "असली" कुलीन नेहरू हैं': एक गुमनाम सदस्य
कांग्रेस द्वारा विधेयक तैयार करने का निर्देश, 3 अगस्त 2021, नई दिल्ली।
151 'Rajiv Arun Nehru se bahut ghabrate thae': G. S. Chawla to author, 21 August, 2021,
टेलीफोन पर हुई बातचीत, नई दिल्ली।
152 'कौन स्वयं को स्थापित नहीं करता?': अरुण नेहरू ने एक अप्रकाशित साक्षात्कार में लेखक से पूछा।
16 मई 2001, नई दिल्ली।

152 मई 1986 की शुरुआत में राजीव का अरुण नेहरू से आमना-सामना हुआ: जी.एस. चावला, रक्तपात
पंजाब: छल और तोड़फोड़ की अनकही गाथा, नई दिल्ली: हर-आनंद पब्लिकेशन्स, 2016।
152 31 मई 1986 को सुबह 3 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा: प्रभु चावला, 'अरुण नेहरू पीड़ित'
'दिल का दौरा, सक्रिय राजनीतिक जीवन से विराम की अटकलें तेज', इंडिया टुडे, 30 जून 1986।
152 'वह बाथरूम के दरवाजे से आया था, सामने के प्रवेश द्वार से नहीं': जी.एस. चावला ने लेखक से कहा।
21 अगस्त 2021, टेलीफोन पर हुई बातचीत, नई दिल्ली।
153 उन्होंने जुलाई 1986 में नटवर सिंह से यही बात कही थी: नटवर सिंह ने लेखक को 21 जून 2018 को लिखा।
नई दिल्ली। वजाहत हबीबुल्लाह द्वारा लेखक को 26 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में लिखा गया पत्र।
153 'उन्होंने मुझे ब्रिटेन में उच्चायुक्त के रूप में भेजने की पेशकश की': अरुण नेहरू ने लेखक को 16 मई 2001 को लिखा।
नई दिल्ली।
153 'हमारी बैठक बहुत खराब रही': वही।
153 बैठक का समापन राजीव द्वारा नेहरू से इस्तीफा देने के अनुरोध के साथ हुआ: फोतेदार, '1985 शताब्दी'
सत्र', चिनार के पत्ते।
153 'आपके साथ काम करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ': प्रभु चावला,
'कैबिनेट में फेरबदल: राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह, अरुण नेहरू जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों को पद से हटाया', इंडिया टुडे, 15 नवंबर 1986।
153 'हमें इसके परिणामों का इंतजार करना चाहिए': एम. एल. फोतेदार ने लेखक को लिखा। 1 जनवरी 2005, गुड़गांव।
154 'राजीवजी तनाव में थे': वही।

154 सोनिया के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी: फोतेदार, '1985 शताब्दी सत्र', द चिनार
पत्र; पंकज वोरा द्वारा लेखक को, 11 मार्च 2021, नई दिल्ली।
154 ‘तब मुझे समझ आया कि अरुण नेहरू को क्यों हटाया गया था’: एम. एल. फोतेदार ने लेखक से कहा।
154 ‘तब से उपराष्ट्रपति को एहसास हो गया था कि उनके लिए भी हालात बेहतर होने वाले हैं’: अरुण नेहरू ने लेखक से कहा, 16 मई
2001, नई दिल्ली।
154 बोफोर्स ने भारतीय राजनेताओं को रिश्वत दी थी: जैक सिनामन और देवन वैन डेर पोएल, 'द
बोफोर्स घोटाला’, करप्शन ट्रैकर, 7 मार्च 2023।
154 ‘बोफोर्स कांड की कहानी को स्वीडिश रेडियो को लीक करने वाले अरुण नेहरू ही थे’: एच. आर. भारद्वाज
लेखक, 26 फरवरी 2018, नई दिल्ली।
154 ‘वे आपको जो बता रहे हैं वह सब गलत है’: कुर्बान अली ने लेखक से कहा, 15 जून 2021, नई दिल्ली।
155 ‘यह अरुण नेहरू थे’: वही।
155 ‘शिलान्यास के समय भी एक औपचारिक समझौता था’: वही।
155 ‘राजीव अब उतने भोले नहीं रहे जितना लोग सोचते थे’: एच. आर. भारद्वाज ने लेखक को 20 अगस्त को लिखा
2003, नई दिल्ली।
155 एक बार फिर, राजीव दबाव में झुक गए, इस बार हिंदू समूहों के दबाव में: चौधरी, 'द
राजनीतिक परिणाम।
155 उनकी पश्चिमीकृत सोच ने उन्हें अपने करियर की सबसे बड़ी गलतियाँ करने के लिए प्रेरित किया: वजाहत
हबीबुल्लाह द्वारा लेखक को, 26 अप्रैल 2019, नई दिल्ली।
156 यह था कि ‘अदालतों का कोई महत्व नहीं था। राजनीतिक आंदोलन मायने रखते थे। चुनावी वोट बैंक भी मायने रखते थे’:

चौधरी, ‘राजनीतिक परिणाम’।

अध्याय 3: भारतीय राजनीति को नया रूप देने वाला धूर्त प्रधानमंत्री: वी. पी.

सिंह की मंडल चाल

157 रिपोर्टर सेंट्रल हॉल से तेजी से बाहर निकला: इसे यह नाम इसके बीच स्थित होने के कारण मिला था।

लोकसभा, राज्यसभा और रियासतों के सदन (पाठक कक्ष) को उन प्रतीकों से सजाया गया है जो 1947 के बाद भारत संघ में उनके विलय की घोषणा करते हैं। (सीताराम येचुरी, 'संसद का केंद्रीय हॉल: अनसुनी कहानियां', डेक्कन हेराल्ड, 21 अगस्त 2022)।

157 लेकिन, चुनाव के बाद, उन्होंने खुद शीर्ष पद के लिए दावेदारी करने का फैसला किया: हरिंदर बावेजा, 'जाट

नेता देवीलाल अजेय प्रतीत होते हैं’, इंडिया टुडे, 30 नवंबर 1989।

157 ‘राजीव गांधी ने भी राजा साहब (वी. पी. सिंह) को इस तरह अपमानित नहीं किया था’: एस. एन. सिंह

लेखक, 1 दिसंबर 1989, 28, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली।

158 जब तक राजीव गांधी ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया: 'गांधी ने पार्टी से तीन पूर्व मंत्रियों को निष्कासित किया', 16

जुलाई 1987, एसोसिएटेड प्रेस।

158 दलों ने जनता दल के गठन में योगदान दिया: 11 अक्टूबर को जनता दल बनाने के लिए विलय करने वाले दल।

1988 में जनता पार्टी (जिसमें लोक दल (ए) भी शामिल था, जो तब तक इसमें विलय हो चुका था), कांग्रेस (धर्मनिरपेक्ष), लोक दल (बी) और जन मोर्चा थे।

158 ‘मैंने उपराष्ट्रपति से दो दिन पहले (नेता के चुनाव से पहले) कहा था, इसे मुझ पर छोड़ दो और तुम इससे दूर रहो।

'यह': अरुण नेहरू ने लेखक को 16 मई 2001 को नई दिल्ली में लिखा।

158 रिकॉर्ड बहुमत वाली 414 सीटों में से इसने 217 सीटें खो दी थीं: 'सामान्य

चुनाव पर सांख्यिकीय रिपोर्ट'
नौवीं लोकसभा के लिए 1989 के चुनाव: खंड I', दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 1990, <eci.gov.in/files/file/4120-general-election-1989-vol-i-ii> पर उपलब्ध है।
29 नवंबर को राष्ट्रपति वेंकटरमन को 158 इस्तीफे: नूरुद्दीन इनामदार, '29 नवंबर' - 'जिस दिन राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया', फ्री प्रेस जर्नल, 28
नवंबर 2022।
158 राजीव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनमें गठबंधन सरकार चलाने की क्षमता नहीं है: एच. आर.
भारद्वाज द्वारा लेखक को, 20 अगस्त 2003, नई दिल्ली।
159 वी.पी. सिंह द्वारा 1988 में गठित जनता दल ने 143 लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र: 'नौवीं लोकसभा के लिए 1989 के आम चुनावों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट: खंड I'
159 पार्टी ने यूपी में 85 में से 54 सीटें जीती थीं और बिहार में 54 में से 32 सीटें हासिल की थीं: वही।
159 वामपंथी दलों ने मिलकर 52 सीटें जीतीं: सीपीआई (एम) को 33 और सीपीआई को 12 सीटें मिलीं।
क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी 4, और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक 3. इस चुनाव में असम में मतदान नहीं हुआ: रिचर्ड सिसन, '1989 में भारत: परिवर्तन की संस्कृति में चुनावों का एक वर्ष', एशियाई सर्वेक्षण, खंड 30, संख्या 2, 1990, पृष्ठ 117.
159 'विश्वनाथ, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा': चंद्र शेखर ने लेखक से कहा।
160 'मैं देवी लाल का नाम प्रस्तावित करता हूँ': वी. पी. सिंह ने लेखक को 16 अक्टूबर 1999 को अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में लिखा।
दिल्ली।
160 'VP ho gaya': Ibid.
160 'मारो, मारो, मारो, पिछली कहानी': इंदरजीत बडवार और प्रभु चावला, 'वी.पी.

सिंह बन जाते हैं’
भारत के नए प्रधानमंत्री, नेशनल फ्रंट सत्ता में आए’, इंडिया टुडे, 15 दिसंबर 1989।
161 ‘Iska anjam acha nahin hoga’: Chandra Shekhar to author, 1 December 1989, Central Hall,
संसद भवन।
161 ‘बीजू ने मुझे उड़ीसा भवन बुलाया था और बताया था कि उपराष्ट्रपति’: चंद्र शेखर ने लेखक से कहा, 20
नवंबर 2002।
161 ‘बीजू मुझसे मिलने आए और मुझे उप प्रधान मंत्री पद की पेशकश की’: वही।
161 ‘अरे बल्लिया, अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह की सरकार चलाओगे’: वही। यही स्थिति थी
दोनों के बीच ऐसा रिश्ता था कि बिजू पटनायक प्यार से चंद्र शेखर को 'बलिया' (पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका जन्मस्थान) कहकर बुलाते थे और चंद्र शेखर उन्हें 'ओडिया' (ओडिशा निवासी) कहकर संबोधित करते थे।
162 ‘मेरे बिना जनता दल क्या है?’: सोम पाल ने लेखक से कहा, नई दिल्ली।
बडवार ने कहा कि 162 देवी लाल भाजपा की हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन करने के लिए तैयार होंगे।
चावला, ‘वी.पी. सिंह भारत के नए प्रधानमंत्री बने, नेशनल फ्रंट सत्ता में आया’।
162 ‘मामाजी, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आपने बार-बार यही कहा था कि वी. पी. सिंह विजेता बनेंगे’
प्रधानमंत्री’: सोम पाल ने लेखक से कहा, नई दिल्ली।
162 ‘चंद्र शेखर के खिलाफ संख्याएँ बहुत प्रतिकूल हैं’: वही।
परिणाम घोषित होने के कुछ ही घंटों के भीतर 162 उद्योगपतियों ने अपने प्रतिनिधियों को दिल्ली भेज दिया था: बडवार और
चावला, ‘वी.पी. सिंह भारत के नए प्रधानमंत्री बने, नेशनल फ्रंट सत्ता में आया’।
163 ‘मामाजी, केंद्र सरकार चलाना हरियाणा मंत्रालय चलाने जैसा नहीं है’: वही।
163 ‘यदि आप उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन देते हैं...तो आप उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं’: वही।
163 ‘(हालाँकि) मुझे टीडीपी के पी. उपेंद्र ने सलाह दी थी कि मैं मुसीबत मोल ले

रहा हूँ': वी. पी.
सिंह से लेखक तक।
163 'अरुण नेहरू को मेरे पास भेजो': सोम पाल ने लेखक से कहा।
163 'क्या हमने राजीव गांधी से इस तरह की गड़बड़ी पैदा करने के लिए लड़ाई लड़ी थी?': कुलदीप नैयर ने लेखक से कहा।
164 'राजा की जान टोटे मैं होती है': लेखक से अश्विनी कुमार चोपड़ा।
164 Nayar, Sethi, and Chopra walked out of Haryana Bhavan together: Kuldip Nayar to author.
164 'मैं इसे देवी लाल को वापस दे देता था,' नेहरू ने बाद में कहा: अरुण नेहरू ने लेखक को 1 जून 2001 को लिखा।
नई दिल्ली।
164 'हमें देवी लाल की परवाह नहीं है,' अरुण नेहरू ने समूह से कहा: वही।
165 'क्या आप डॉक्टर हैं या क्या?': सोम पाल ने लेखक से पूछा।
165 'चंद्र शेखर चुनाव लड़ेंगे': अरुण नेहरू ने लेखक को, 16 मई 2001, नई दिल्ली।
165 'केवल बीजू ही देवी लाल को मना सकता था': चंद्र शेखर ने लेखक से कहा।
165 'किसी तरह रास्ता निकालो': अरुण नेहरू ने लेखक से कहा, 16 मई 2001, नई दिल्ली।
165 'अरुण, चीजों को इतना ज़ोर से मत खींचो कि पार्टी टूट जाए': वही।
165 'देवी लाल आक्रामक और तर्कहीन थे': अरुण नेहरू ने लेखक को 1 जून 2001 को लिखा, न्यू यॉर्क
दिल्ली।
166 'मुझे लगता है कि देवी लाल का ही यह विचार था कि उनका नाम पहले प्रस्तावित किया जाए': वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा।
166 'Hum aap ke liye kuchh bhi kar sakte hain': Ibid.
166 'Us (Chandra Shekhar) se vaada kiya hai ki main banoonga': Arun Nehru to author, 1 June
2001, नई दिल्ली।
166 'इस पर (पहले) विचार नहीं किया गया था': वही।

166 'यह अरुण नेहरू का विचार था': एस. पी. शुक्ला से नीरजा, 25 अक्टूबर 2002, नई दिल्ली।

166 अरुण नेहरू ने अंततः बिजू पटनायक को यह विश्वास दिलाया कि गतिरोध से निकलने का यही एकमात्र रास्ता था:

Santosh Bhartiya to author.

166 'We told Devi Lal that he should tell Chandra Shekhar what the samjhauta (deal) was': Arun

नेहरू ने लेखक को 1 जून 2001 को नई दिल्ली में पत्र लिखा।

167 'आप कुछ सांसदों को भी इस बारे में चुपके से बता दें,' पटनायक ने जेना से कहा: श्रीकांत जेना ने लेखक को बताया।

167 'वीपी को बनाना है': वही.

167 2 दिसंबर 1989 को दोपहर 12 बजे, राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन ने शपथ दिलाई।

कार्यालय: आर. वेंकटरमन, माई प्रेसिडेंशियल इयर्स, नई दिल्ली: इंडस (हार्परकॉलिन्स), 1994, पृ. 324–25.

167 'साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री का कार्यालय है। आपको अभी तक कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है': अश्विनी कुमार

चोपड़ा लेखक बने।

168 Suddenly Devi Lal interrupted them, 'Woh oop bhi uttar jayega': Kuldip Nayar to author, 7

जून 2002, नई दिल्ली।

168 'मेरी वजह से ही वो आज प्रधानमंत्री हैं': सोम पाल ने लेखक से कहा, नई दिल्ली, 2 मार्च

2022.

168 'तुम प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि मैंने झूठ बोला था': रविवार, 18-24 मार्च, 1990, उद्धृत

ठाकुर, प्रधानमंत्रियों, पृ. 276.

168 वे जेकेएलएफ के 'क्षेत्रीय कमांडर' शेख अब्दुल हमीद थे: बारबरा क्रॉसेट, 'अपहृत'

कश्मीर में महिला को रिहा किया गया', न्यूयॉर्क टाइम्स, 14 दिसंबर 1989।
168 'मैं (इस बारे में) प्रेस या कैबिनेट के पास नहीं गया': वी. पी. सिंह ने लेखक को, नई दिल्ली।
169 नवंबर 1989 में उत्तर प्रदेश के राज्य चुनावों में जनता दल की जीत: देबाशीष मुखर्जी, द
विघटनकारी: विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारत को कैसे हिलाया, नई दिल्ली: हार्पर कॉलिन्स, पृ. 333.
169 'Aap UP ke pachrhe maen mat parho': Som Pal to author, 13 March 2022.
169 'अगर मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया': सोम पाल ने लेखक से कहा, 3 मार्च 2022।
169 'Mayhem in Meham': Harinder Baweja, 'Haryana CM Om Prakash Chautala rigs his own
'राजनीतिक भविष्य', इंडिया टुडे, 31 मार्च 1990।
169 'एक हॉरर फिल्म और बरलेस्क थिएटर का मिश्रण': एस. निहाल सिंह, 'एक शर्मनाक
'एपिसोड', इंडिया टुडे, 15 मार्च 1990।
169 मुख्यमंत्री चौटाला पर खुलेआम डराने-धमकाने और बूथ कैप्चरिंग का आरोप: बावेजा
'Haryana CM Om Prakash Chautala rigs his own political future'.
169 चौटाला ने कथित तौर पर मेहम के गांवों में गुंडों के समूहों का नेतृत्व किया: वही।
170 'पूरी चुनाव प्रक्रिया दूषित हो गई': 'हिंसा और वोट धोखाधड़ी से प्रभावित उपचुनाव'
'रद्द किया गया', एपी न्यूज़, 8 मार्च 1990।
170 Several Janata Dal leaders—Ajit Singh, George Fernandes, Madhu Dandavate, and
Nathuram Mirdha: Baweja, 'Haryana CM Om Prakash

Chautala rigs his own political future'.
170 'अजीत सिंह को मेहम जाने के लिए किसने कहा?': वी. पी. सिंह ने लेखक को 18 अक्टूबर 1999 को अपोलो में लिखा।
अस्पताल, नई दिल्ली।
170 'Ae Pande tujhe kya pata hai iske bare maen?': Ibid.
170 'आपकी पहली सहज प्रवृत्ति अक्सर सही होती है। मैंने इंदिरा गांधी के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया था': वही।
171 'अप्रैल में (मेहम के बाद), मैं संसदीय चुनाव में भाग लेना चाहता था': वही।
171 'संभवतः वह कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देगा': वही।
171 'देवी लाल हमारे लिए एक दिव्य उपहार थे': एम. एल. फोतेदार ने लेखक को 1 जनवरी 2005 को नई दिल्ली में लिखा।
171 'उस समय आर.वी. (राष्ट्रपति आर. वेंकटरामन) भी निजी तौर पर उपराष्ट्रपति के खिलाफ थे': वही।
171 'उपराष्ट्रपति पद की सरकार को हटाओ,' शर्मा ने राजीव को सलाह दी: एन. के. शर्मा ने लेखक को 25 जनवरी को लिखा
2000, नई दिल्ली।
171 'देवी लाल ने मुझे पहले ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री उन मुद्दों पर उनकी बात नहीं सुन रहे थे जो उनसे संबंधित थे।
किसानों का: वही।
172 उन्हें आईबी द्वारा सूचना दी गई थी; कुछ अधिकारी गांधी के संपर्क में रहे थे: वही।
172 'हमें चौधरी साहब (देवी लाल) से बात करनी होगी': वही।
172 'पंडितजी, क्या आप वही दोहराएंगे जो आपने मुझे कल रात बताया था': वही।
172 अब तक भाजपा भी चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वालों की कतार में शामिल हो चुकी थी:
Inderjit Badhwar and Prabhu Chawla, 'V.P. Singh asserts himself by forcing Chautala's resignation and Jagmohan's removal', India Today, 15 June 1990.
172 इस पूरी अवधि के दौरान, देवी लाल और वी. पी. सिंह के बीच की दूरी बढ़ती

जा रही थी: एन.
के. शर्मा लेखक को।
172 ‘मैं अपने साथ एक पत्र का मसौदा ले गया था’: वही।
173 ‘मुझे बताया गया था कि मुंबई हवाई अड्डे पर कोई मेरा बोर्डिंग कार्ड लेकर मुझसे मिलने आएगा’:
वही।
173 ‘जैसे ही मैं विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरा, वहाँ एक व्यक्ति मेरा इंतज़ार कर रहा था।
बोर्डिंग कार्ड’: वही।
173 ‘वीपी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं’: सोम पाल ने लेखक से कहा।
174 ‘देवी लाल ने आज सुबह फोन किया और कहा कि वह रात के खाने से बहुत खुश थे’: वही।
174 ‘वी. पी. सिंह एक शानदार व्यक्ति हैं’: देवी लाल ने सोम पाल से कहा, जिन्होंने यह बात लेखक के साथ साझा की।
174 ‘जब मैं पहुंचा, तो उन्होंने मुझे बनारसी दास गुप्ता का दो पन्नों का बयान सौंपा’: सोम पाल ने कहा
लेखक।
175 ‘हम शाम को अरुण नेहरू के घर पर इकट्ठा हुए थे’: सत्यपाल मलिक ने लेखक से कहा।
175 प्रधानमंत्री ने उन्हें आने के लिए कहा: सीमा मुस्तफा और एच. बावेजा, 'नाटकीय घटनाक्रम जो
'लगभग राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पतन का कारण बन गया', इंडिया टुडे, 15 अगस्त 1990।
175 ‘हम रात करीब 11 बजे वीपी के घर गए थे’: सत्यपाल मलिक ने लेखक से कहा।
176 ‘वीपी एक आत्म-उपभोग लक्ष्य है’: सुरेंद्र मोहन ने लेखक को 12 सितंबर 2003 को नई दिल्ली में लिखा।
उन्हें यह बात कुलदीप नैयर ने बताई थी।
176 ‘दूसरे शब्दों में, नेहरू के लिए शीर्ष पद का रास्ता साफ हो जाएगा’: वही।

176 ‘वह (अरुण नेहरू) लगातार राजीव को (वहां क्या हो रहा था, उसके बारे में) जानकारी दे रहे थे।

जनता दल): एम. एल. फोतेदार लेखक को।

176 ‘मैंने वीपी से पूछा था कि जनता दल इतनी जल्दी क्यों ढह गया’: दिनेश त्रिवेदी ने लेखक से कहा।

176 ‘जब राजीव को एहसास हुआ कि सरकार गिर सकती है, तो उन्होंने प्रक्रिया में तेजी लाई’: वही।

176 ‘मुझे ऐसा लग रहा था कि अरुण नेहरू और आरिफ गांधी के इस्तीफे के पीछे राजीव गांधी का हाथ था।

Khan’: H. R. Bhardwaj to Neerja, 20 August 2003, New Delhi.

176 ‘उन्हें इस बात की इतनी चिंता नहीं थी कि राजीव गांधी क्या करेंगे’: गोविंदचार्य ने लेखक से कहा, 3

जुलाई 2018, नई दिल्ली।

176 ‘प्रधानमंत्री कार्यालय को यह सूचना मिली थी कि वे (भाजपा) सरकार को गिरा सकते हैं।

रथ यात्रा का अंत: प्रेम शंकर झा ने लेखक को 1 सितंबर 2021 को लिखा।

177 जून 1990 में हरिद्वार में हुई अपनी बैठक में विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही बढ़ोतरी कर दी थी।

ante and called for kar seva: यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो निस्वार्थ सेवा करते हैं—आमतौर पर आध्यात्मिक अर्थों के साथ।

177 ‘जब मैंने पदभार संभाला था, तब मैंने सोचा था कि भाजपा सत्ता से हाथ खींचने से पहले दो साल का समय लेगी’:

वी. पी. सिंह, लेखक को, नई दिल्ली।

177 ‘मैं उनसे इस्तीफा देने के लिए कहने के पक्ष में था’: वही।

177 ‘आप इसे अलग तरीके से प्रबंधित कर सकते थे’: वही, अक्टूबर 1990।

177 ‘मंडल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है’: सोम पाल ने लेखक से कहा, 13 मार्च 2022।

177 ‘यदि आप मंडल में जाते हैं, तो लाभ आपको नहीं, बल्कि दूसरों को होगा’: वही।

178 ‘मैंने (एक बार) उनसे आरक्षण पर उनके विचारों के बारे में पूछा था’: दिनेश त्रिवेदी ने लेखक से कहा।
178 ‘मंडल जनता दल की राजनीतिक अभिव्यक्ति थी’: वी. पी. सिंह ने लेखक को 20 अक्टूबर को लिखा
1999, अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली।
शरद यादव के शयनकक्ष में लगा सुरक्षित आरएएक्स फोन देर रात बजा: सुरक्षित आरएएक्स
विदेशी देशों की खुफिया एजेंसियों द्वारा फोन कॉल को इंटरसेप्ट करने से रोकने के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ नौकरशाहों को टेलीफोन सेट दिए गए थे।
178 ‘Sharad bhai, ab toh Devi Lalji ke saath kaam karna mushkil ho gaya hai’: Sharad Yadav to
लेखक, 27 दिसंबर 2005, नई दिल्ली।
179 ‘Jo Devi Lalji ki sthiti thee woh ab aapki rahegi’: Ibid.
179 ‘काफी देर हो गई है, शरद भाई, मैं आपको सुबह फोन करूंगा’: वही।
179 यह निर्णय लेने के बाद, उन्होंने प्रमुख ओबीसी नेताओं को फोन करना शुरू कर दिया: वही।
180 उनकी बैठक ‘दो घंटे’ तक चली: वही।
180 ‘यह मेरे लिए पर्याप्त संकेत था कि प्रधानमंत्री मंडल को लाने में कोई जल्दी नहीं कर रहे थे’: वही।
उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख कुर्मी नेता राम पूजन पटेल, जो बाद में उपराष्ट्रपति के मंत्रिमंडल में शामिल हुए, ने गोलीबारी की।
प्रधानमंत्री को पत्र: राम पूजन पटेल द्वारा लेखक को, नई दिल्ली, 28 फरवरी 2003।
180 ‘आपको मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के निर्णय की घोषणा करनी चाहिए’: शरद
यादव ने लेखक को लिखा।
181 ‘दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए,’ वीपी कहते थे, ‘गरीब ही स्थिरता प्रदान करते हैं, चाहे कुछ भी हो।
पार्टी’: वी. पी. सिंह ने लेखक को 20 अक्टूबर 1999 को अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में लिखा।

181 उस समय, पच्चीस राज्यों में से बारह राज्यों में पहले से ही ओबीसी के लिए कोटा निर्धारित था: मुकर्जी, द
डिसरप्टर, पृ. 396.
181 'विचार यह है,' उन्होंने एकत्रित समूह से कहा, 'कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए।': सोम पाल
लेखक।
182 बैठक में लगभग दो दर्जन सांसदों ने भाषण दिया: सोम पाल ने लेखक को 11 फरवरी 2022 को लिखा, न्यू।
दिल्ली।
182 'ऐसा करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है': सोम पाल ने लेखक को 16 फरवरी 2000 को नई दिल्ली में लिखा।
182 'जब तक कोई सवर्ण (उच्च जाति) प्रधानमंत्री रहेगा, मंडल रिपोर्ट कभी लागू नहीं होगी'
कार्यान्वित किया गया': वही।
182 'हमें संसद सत्र के पहले दिन इसकी घोषणा करनी चाहिए': वही।
182 दस वर्ष पूर्व बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल: बी. पी. मंडल पूर्व प्रमुख थे।
बिहार के मंत्री और पांच सदस्यीय नागरिक अधिकार आयोग के अध्यक्ष, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, को दिसंबर में मोरारजी देसाई द्वारा नियुक्त किया गया था
182 लेकिन उन्होंने अपने सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 'पिछड़ेपन के मुद्दे' से निपटने वाला 'अधिकारी'
उस समय बी. जी. देशमुख गृह के अतिरिक्त सचिव थे, जो बाद में मंडल आयोग की स्थापना के समय वी. पी. सिंह के प्रधान सचिव बने। वे 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग की स्थापना के समय से ही इससे संबंधित सभी कार्यों की देखरेख कर रहे थे।
183 'Saab, aap ne report par bahut mehnat ki hai. Par aaj hum iskaa visarjan kar aaye hain': S. S.
गिल द्वारा लेखक को, 26 जुलाई 2004, नई दिल्ली।
183 'इस सरकार की इस विचार के प्रति समान प्रतिबद्धता नहीं होगी': वही।
183 'रिपोर्ट का हर शब्द मैंने लिखा था,' गिल ने कहा: वही।

184 ‘यदि आप जाति को नहीं समझते हैं तो आप वास्तव में इसके परिणामों को नहीं समझ सकते…’: वही।
184 ‘जिन्होंने इसे लागू किया था उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी’: वही।
अंततः, यह ‘सामाजिक पिछड़ेपन’ पर अधिक निर्भर था: ‘दूसरी रिपोर्ट’
पिछड़ा वर्ग आयोग’, प्रथम भाग, खंड I, 1980, भारत सरकार।
सुरक्षा के लिहाज से, ओबीसी कोटा 27 प्रतिशत निर्धारित किया जाना था: 'दूसरी पिछड़ापन आयोग की रिपोर्ट'
वर्ग आयोग’।
185 हिंदुओं में अंतर्निहित जाति व्यवस्था: 'भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति', हिंदुस्तान
टाइम्स, 3 जून 2003।
186 ‘मुझे नहीं लगता कि नेहरू वास्तव में जाति को समझते थे’: एस. एस. गिल ने लेखक को, नई दिल्ली।
186 उन्होंने 2,399 जातियों को पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया, जो सहायता के पात्र हैं: नोमिता यादव, 'अन्य पिछड़ा वर्ग'
'क्लासेस: देन एंड नाउ', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 37, वॉल्यूम 44/45, 2002, पृष्ठ 4495।
186 ‘हमें ऐसा लगा कि वह इसे (कालेलकर रिपोर्ट) लागू करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा।
'इतने सीधे तौर पर': शिव शंकर ने लेखक से कहा।
186 ‘हम पंतजी से उनके कार्यालय में मिलने गए’: वही।
186 दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट के लेखक, कालेलकर, सहानुभूति रखते थे: एस. एस. गिल
लेखक।
186 हालाँकि, 1961 में इसने निर्णय लिया कि वह इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ देगा: मुकर्जी, द
डिसरप्टर, पृ. 384.
186 राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के आयोगों का गठन किया: 'द्वितीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट'

क्लासेस कमीशन', पृ. 5–11, मुकरजी में, द डिसरप्टर, पृ. 385.
187 यह 1959 में ही था, जब समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने पहली बार आरक्षित सीटों का विचार सामने रखा था।
60 प्रतिशत: पी. आर. रमेश, 'बिहार: न्यायविहीन भूमि', ओपन, 6 अगस्त 2015।
187 'Sasopa ne bandhi gaanth, pichde paanve sau maen saath': Akshaya Mukul, 'Ram Manohar
लोहिया: कोटा मार्शल', टीओआई क्रेस्ट, 3 अप्रैल 2010।
187 इससे ओबीसी आरक्षण की मात्रा प्रभावी रूप से घटकर 20 प्रतिशत हो गई: श्यामा नंद
सिंह, 'बिहार में आरक्षण विरोधी आंदोलन', द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, खंड 52, अंक 1, जनवरी-मार्च 1991, पृष्ठ 24-42।
187 इससे आरक्षण समर्थक भड़क उठे और जनता पार्टी में फूट पड़ गई: गोविंदचार्य को
लेखक, जुलाई 2018।
188 'एक बार मैं चरण सिंह के पास किसी काम से गया था जब वे गृह मंत्री थे': शिव शंकर ने कहा
लेखक।
188 यह शिव शंकर ही थे जिन्होंने चुपचाप आयोग को आर्थिक मानदंडों को न अपनाने की सलाह दी थी:
बी. जी. देशमुख, एक कैबिनेट सचिव पीछे मुड़कर देखते हैं: पूना से प्रधानमंत्री कार्यालय तक, नई दिल्ली: हार्परकॉलिन्स इंडिया, 2004, पृ. 287.
188 'Shiv Shankarji, kya karaen?': Shiv Shankar to author, 6 June 2007, New Delhi.
188 'Aisa ATR likhiye ki saamp bhi mar jaye aur laathi bhi naa toote': Ibid.
189 'मंत्रियों की समिति का नेतृत्व कौन करेगा?': वही।
189 'शिव शंकर जी, समिति में क्या चल रहा है?': वही।
189 उत्तरी राज्यों से बहुत पहले ही दक्षिणी राज्यों ने आरक्षण प्रणाली अपना ली थी: मुकर्जी, द

डिसरप्टर, पृ. 383.
189 में से 26 लोकसभा सीटें: 'छठे लोकसभा चुनाव, 1977 से 1977 तक के आम चुनावों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट'
लोकसभा: खंड I', दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 1978, उपलब्ध है <eci.gov.in/files/file/4116-general-election-1977-vol-i-ii>.
190 राजीव का मानना था कि पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए 'अन्य कदम' उठाए जाने चाहिए:
देशमुख, एक कैबिनेट सचिव पीछे मुड़कर देखते हैं, पृष्ठ 282।
190 'मंडल आयोग की रिपोर्ट विवादों का पिटारा है': इंदर मल्होत्रा, 'मंडल बनाम 'मंदिर', इंडियन एक्सप्रेस, 23 मार्च 2015।
190 उन्होंने पंचायती राज में ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया था।
संस्थाएँ: शिव शंकर से लेखक को, जून 2007; देशमुख, एक कैबिनेट सचिव पीछे मुड़कर देखते हैं, पृष्ठ 287।
190 राजीव ने अब भी उनकी आलोचना की: 'लोकसभा वाद-विवाद (अंग्रेजी संस्करण): तीसरा सत्र
(नौवीं लोकसभा)', नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय, 6 सितंबर 1990, उपलब्ध है <eparlib.nic.in/bitstream/123456789/3295/1/lsd_09_03_06-09-1990.pdf>
190 उन्होंने ढाई घंटे तक भाषण दिया—जो लोकसभा में दिया गया अब तक का सबसे लंबा भाषण है: एल.
के. आडवाणी, मेरा देश, मेरा जीवन, नई दिल्ली: रूपा एंड कंपनी, 2008, पृ. 448.
190 'मंत्री जातिगत युद्धों को भड़का रहे हैं': 'लोकसभा वाद-विवाद (अंग्रेजी संस्करण): तीसरा सत्र'
(नौवीं लोकसभा)', पृष्ठ 532.
190 मंत्रीगण दोपहर में बैठक के लिए धीरे-धीरे आने लगे थे: मुकर्जी, द
डिसरप्टर, पृ. 222.
191 नौकरशाही को एक संदेश कि वह प्रतिशोधी नहीं होने वाला था: वी. पी. सिंह ने लेखक को लिखा।

191 ‘मुझे अपने मंत्रिमंडल में कभी कोई समस्या नहीं हुई’: वही।
191 ‘हम सबसे पहले मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर चर्चा करेंगे’: देशमुख, ए
कैबिनेट सचिव ने अतीत की ओर देखा, पृष्ठ 280।
191 उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर मुड़कर स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें ‘कोई सूचना नहीं मिली’: वही।
191 उन्होंने अपने सामाजिक कल्याण मंत्री से आगे बढ़कर अपनी प्रस्तुति देने का अनुरोध किया: वही;
राम विलास पासवान ने लेखक को इसकी पुष्टि की है।
192 यह कार्य मुख्य रूप से समाज कल्याण मंत्रालय और उसके सचिव पी.एस. द्वारा किया गया था।
कृष्णा: वी. पी. सिंह लेखक को।
192 ‘मैंने राम विलास पासवान को फोन किया था और उनसे कहा था कि (पार्टी) समिति की परवाह किए बिना’:
वही।
192 जैसे-जैसे उनका भाषण आगे बढ़ा, पासवान ने मंडल आयोग के कार्यान्वयन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए।
रिपोर्ट: देशमुख, एक कैबिनेट सचिव पीछे मुड़कर देखते हैं, पृष्ठ 280।
192 यादव ने भी प्रस्ताव के पक्ष में बात की: वही।
192 उद्योग मंत्री अजीत सिंह आगे बढ़ने के पक्ष में थे: वही।
192 भारत के पहले मुस्लिम गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने और समय मांगा: वही।
192 दो लोगों ने प्रस्ताव के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त की थी: वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा था;
अरुण नेहरू द्वारा पुष्टि की गई।
तकनीकी और मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी कोटा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का विधेयक (192):
परमानंद सिंह, ‘आरक्षण, वास्तविकता और संविधान: भारत में वर्तमान संकट’, कोचीन यूनिवर्सिटी लॉ रिव्यू, खंड 11, 1987, पृष्ठ 290।

192 ‘सर, ऐसा मत कीजिए। हमने गुजरात में ऐसा किया था। इससे कई समस्याएं पैदा होंगी’: चिमनभाई मेहता ने कहा
लेखक।
192 ‘विश्वनाथ, राजनीति अंकगणित नहीं है’: अरुण नेहरू ने लेखक को, 1 जून 2001, नई दिल्ली।
193 लेकिन समाजवादी दंडवते मंडल के लंबे समय से समर्थक थे: वही; देशमुख, ए कैबिनेट सचिव ने अतीत की ओर देखा, पृष्ठ 280।
193 ‘मैंने (वीपी) के इस कदम का 100 प्रतिशत समर्थन किया’: मधु दंडवते ने लेखक से कहा।
193 दीपक नायर ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया था: दीपक नायर, 16
फरवरी 2000।
193 ‘दीपक, तुम राजनीति मुझ पर छोड़ दो’: वही।
193 ‘मैंने पूरी तरह से कोशिश नहीं की है’: राम विलास पासवान ने लेखक से कहा।
193 केवल केंद्रीय सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर लागू होना था: वही।
193वें उपाध्यक्ष ने अपने सहयोगियों की बात सुनी: दीपक नैयर लेखक होंगे। नैयर, मुख्य आर्थिक सलाहकार।
उपराष्ट्रपति सरकार के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे।
193 ‘कैबिनेट में किसी ने भी वास्तव में इसका विरोध नहीं किया’: वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा।
193 ‘तो, यही आम सहमति है’: देशमुख, ए कैबिनेट सेक्रेटरी लुक्स बैक, पृ. 281.
194 ‘क्या आप मेरे लिए एक नोट तैयार कर सकते हैं ताकि मैं संसद में निर्णय की घोषणा कर सकूँ?’
कल?’: वही।
194 देशमुख आश्चर्यचकित थे: वही।
194 लेकिन वे राजीव गांधी से मोहभंग हो गए: शिव शंकर लेखक बने; एम. एल. फोतेदार
लेखक।

194 ‘शिव शंकर ने वीपी को मंडल में जाने की सलाह दी’: एच. आर. भारद्वाज ने लेखक को, नई दिल्ली।

194 ‘यह इतनी सामान्य प्रकार की लेखन शैली थी कि यह सामाजिक न्याय के वर्णन में फिट नहीं बैठती थी’:

शिव शंकर ने लेखक को 6 जून 2007 को नई दिल्ली में पत्र लिखा।

194 वीपी ने उनके साथ उन बिंदुओं पर चर्चा की जो वे अगले दिन संसद में उठाएंगे: मुकर्जी, द

डिसरप्टर, पृ. 396.

195 ‘यह एकमात्र ऐसा समय था जब मैंने उनसे परामर्श नहीं किया,’ वीपी ने स्वीकार किया: वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा।

195 ‘यदि जनता दल मंडल कार्ड खेलने पर तुला हुआ है’: सोम पाल ने लेखक से 16 फरवरी को कहा

2000.

196 ‘देवेंद्र, इनमें से “चैन” (चालाक) कौन है?’: देवेंद्र द्विवेदी से

लेखक, 2 फरवरी 2001, नई दिल्ली। द्विवेदी संत बक्स सिंह के घनिष्ठ मित्र थे।

196 मांडा के निःसंतान राजा को गोद लेने के लिए दिया गया: मुकर्जी, द डिसरप्टर, पृ. 8.

196 उपाध्यक्षों की कुंडली जो मांडा के राजा की आवश्यकताओं से 'मेल खाती' थी: देवेंद्र द्विवेदी

लेखक, 2 फरवरी 2001, नई दिल्ली; वही, पृष्ठ 19।

197 वीपी ने वर्षों बाद याद किया कि उन्हें अभी भी इसका स्वाद याद है: वी. पी. सिंह ने लेखक को बताया।

197 संत बक्स और उनके दूसरे भाई, हर बक्स सिंह, कभी-कभी चुपके से साथ चले जाते थे।

उन्हें ‘बग्गी’ में: सीमा मुस्तफा, द लोनली प्रॉफेट: वी.पी. सिंह, एक राजनीतिक जीवनी, नई दिल्ली: न्यू एज इंटरनेशनल, 1995; वी.पी. सिंह लेखक को।

197 वीपी के इलाहाबाद जाने के एक साल बाद उनके दत्तक पिता का निधन हो गया: मुकर्जी, द डिसरप्टर, पृ. 3.

197 ‘मैं असुरक्षित था, बहुत असुरक्षित था’: वही, पृष्ठ 19.

198 ‘विद्वान और वाक्पटु’: वही, पृ. 112.
198 वीपी ने विनोबा भावे के नेतृत्व वाले भूदान आंदोलन को अपनी 200 बीघे जमीन दान में दी: इंद्र
शेखर सिंह, ‘एक पोते की श्रद्धांजलि: वीपी सिंह का भुला दिया गया आदर्शवाद’ स्क्रॉल.इन, 25 जून 2016।
198 वे रात में गांवों में जाते थे, हर कोई उम्मीदवार होने का नाटक करता था: मुकर्जी,
द डिसरप्टर, पृष्ठ 68।
198 वह इस भाव से इतना प्रभावित हुआ कि उसने घोषणा कर दी कि वीपी उसका पाँचवाँ पुत्र होगा: वी. पी. सिंह
लेखक।
199 बाद में वीपी ने स्वीकार किया कि पहचान पाने और अपनी छाप छोड़ने की इच्छा थी: मुकर्जी, द डिसरप्टर,
पृष्ठ 62.
199 उन्होंने दलित उम्मीदवार को अपने पक्ष में नाम वापस लेने के लिए राजी कर लिया: वही, पृष्ठ 84।
199 ‘मेरी जीप में ज्यादातर दलित ही सवार होते थे’: वी. पी. सिंह ने लेखक को 20 अक्टूबर 1999 को लिखा।
199 ‘मेरे स्वयं के चुनाव ने मुझे नीचे सुलग रही आग की अंतर्दृष्टि दी’: वही।
199 ‘As I entered…Bahuguna told me, “Inko andar lekar jao”’: Devendra Dwivedy to author.
200 ‘हम प्रत्येक उम्मीदवार को 1 लाख रुपये देने जा रहे हैं’: वही।
जब दिसंबर 1978 में श्रीमती गांधी को गिरफ्तार किया गया, तो वह उन लोगों में से एक थीं जिन्हें जेल भेजा गया था।
विरोध: वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा।
200 वे व्यावहारिक, विवेकशील और अपनी शांत कार्यकुशलता के लिए जाने जाते थे: देवेंद्र द्विवेदी ने लेखक को बताया।
12 फरवरी 2001, एनसीपी कार्यालय, बीडी रोड, नई दिल्ली।
200 ‘हम लखनऊ से सीधे बुलंदशहर तक जा रहे हैं’: वी. पी. सिंह ने लेखक को

अक्टूबर में लिखा।
1999.
200 ‘यदि आप स्थिति को सुधार सकते हैं, तो आइए’: वही।
201 उनके भाई को अपने पद की कीमत चुकानी पड़ी: आनंद सागर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश
कोर्ट में छपी खबर, 'डाकुओं द्वारा 15 वर्षीय बेटे की हत्या', इंडिया टुडे, 15 अप्रैल 1982।
इसके बाद के इकतालीस दिनों में, मुठभेड़ों में 299 ‘डाकुओं’ को मार गिराया गया:
Chaitanya Kalbag, ‘Dacoit menace continues to dog Uttar Pradesh’, India Today, 31 January 1982.
203 ‘स्नान करने के बाद वे दोनों अपनी कच्ची बनियान में उस पर लेट गए’: एच. आर. भारद्वाज
लेखक, 26 फरवरी 2018, नई दिल्ली।
203 इंदिरा गांधी ने आशा व्यक्त की थी कि वी. पी. सिंह राजीव गांधी की मुख्य टीम का हिस्सा होंगे:
एम. एल. फोतेदार लेखक; एच. आर. भारद्वाज लेखक; देवेंद्र द्विवेदी लेखक।
203 ‘एक दिन आधी रात को—यह 1984 के चुनावों से ठीक पहले की बात है’: वही।
203 ‘कवि और कविता’: सुरुचि मजूमदार, ‘कवि की कविता’, द इंडियन एक्सप्रेस, 22
दिसंबर 2007।
203 उस समय बच्चन परिवार 13, विलिंगडन क्रिसेंट में रह रहा था: जया बच्चन
लेखक, 2001, नई दिल्ली।
203 गांधी परिवार 1, सफदरजंग रोड में रहता था और दोनों घर काफी पास थे: 'क्या हुआ?'
'दोस्ती नंबर 1 में क्या गलत है?', टाइम्स ऑफ इंडिया, 17 अक्टूबर 2004।
203 बच्चन और गांधी परिवार के बेटे राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में एक साथ तैरते थे:
जया बच्चन द्वारा लेखक को, 2001, नई दिल्ली।

204 ‘लेकिन आपको इसे चुपचाप करना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए’: एच. आर. भारद्वाज ने लेखक से कहा।
204 ‘मुझे राजनीति का “पी” नहीं पता’: ‘दोस्ती नंबर 1 के साथ क्या गलत हुआ?’
204 ‘कोई समस्या नहीं है,’ उन्होंने राजीव गांधी से विनम्रतापूर्वक कहा: एच. आर. भारद्वाज द्वारा लेखक को।
204 लोगों ने अमिताभ और जया बच्चन को लखनऊ तक पहुंचाया: जया बच्चन ने अगस्त 2021 में लेखक को बताया।
204 ‘यह तय किया गया कि बच्चन परिवार तब गुप्त रूप से इलाहाबाद जाएगा’: एच. आर.
भारद्वाज से लेखक को।
204 ‘1,785 चुन्नियां फेंकी गईं’: डी. पी. त्रिपाठी ने लेखक से कहा।
205 वीपी अकेले नहीं थे जिन्हें बच्चन से खतरा महसूस हो रहा था: मुखर्जी, द डिसरप्टर, पृ. 248.
205. उन्होंने केवल तभी उपस्थित रहने की सहमति दी जब राजीव चुनाव प्रचार के लिए इलाहाबाद आए थे: डी. पी. त्रिपाठी।
नई दिल्ली।
205 वीपी को लगा कि उन्हें ‘इलाहाबाद से निर्वासित’ कर दिया गया है: वी. पी. सिंह ने लेखक को बताया।
205 ‘हमें पहले इन (विपक्षी) लोगों को हराना होगा’: अरुण नेहरू ने लेखक से कहा, 16 मई 2001
नई दिल्ली।
205 कुछ वर्षों बाद, 1987 के मध्य में, उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया: टी. एन. नीनन और ब्रिज खिंडारिया,
‘अमिताभ बच्चन ने लोकसभा से इस्तीफा दिया, अजीतभ स्विस संकट में फंसे’, इंडिया टुडे, 15 अगस्त 1987।
205 ‘वित्त मंत्री को बहुत सख्त होना होगा’: एम. जे. अकबर, राजीव गांधी के साथ साक्षात्कार, ‘द
'श्रीमती गांधी की हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया के लिए की गई थी', रविवार, 10-16 मार्च 1985।

205 कुछ कॉर्पोरेट नेताओं ने इसे 'स्वतंत्र भारत में अब तक का सर्वश्रेष्ठ' बताया: सुमन दुबे,
'विश्वनाथ प्रताप सिंह का बजट अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ता है', इंडिया टुडे, 15 अप्रैल 1985।
206 वह विनोद पांडे को बार-बार 'बड़ी मछली पकड़ने' के लिए कहते थे: एस. पी. शुक्ला ने लेखक से कहा, 25
दिसंबर 2002।
206 'मैंने तो बस इग्निशन चालू किया है': टी. एन. नीनन, 'टैक्स छापों से लेकर महंगाई तक, वी.पी. सिंह
कई अभिसारी तूफानों का केंद्र', इंडिया टुडे, 15 सितंबर 1985।
206 भूरे लाल और उनकी टीम ने बयासी वर्षीय उद्योगपति एस. एल. के घर पर छापा मारा।
किर्लोस्कर: मुखर्जी, द डिसरप्टर, पी. 227.
206 ललित थापर, थापर इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, को सुबह 1 बजे गिरफ्तार किया गया: वही, पृष्ठ 228।
206 थापर ने माफी मांगी और अपने खिलाफ लगाए गए अधिकांश आरोपों को स्वीकार किया: वही।
अन्य 206 प्रमुख औद्योगिक घरानों में बजाज ऑटो, वोल्टास और अन्य शामिल थे।
बच्चे: वही, पृष्ठ 226।
207 'गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों का शेयरों में रूपांतरण': वही, पृष्ठ 231.
207 'Aisa shaneechar bitha diya hai sir par': Som Pal to author.
207 'राजीव की दिवंगत मां की ओर से भारी मात्रा में धनराशि रखे हुए था और जानना चाहता था
पैसे का क्या करें': मुकर्जी, द डिसरप्टर, पृ. 238.
207 उन्होंने वीपी को गद्दार और सीआईए एजेंट कहा: वही, पृष्ठ 267।
207 यह दस्तावेज़ जाली निकला: मयंक छाया, 'पूर्व भारतीय को याद करते हुए'
'प्रधानमंत्री वी पी सिंह और सेंट किट्स गाथा', साउथ एशिया मॉनिटर, 26 जून 2021।

208 ‘Yeh jail maen nahin hain, kya itna kam soft hai?’: V. P. Singh to author.
208 देश में ‘छापेमारी राज’ शुरू हो गया था: मुकर्जी, द डिसरप्टर, पृ. 245.
208 ‘1985 में ही वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनने की संभावना नजर आने लगी थी’: सोम
मित्र से लेखक तक।
208 ‘मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके मन में यह संभावना आई होगी’:
देवेंद्र द्विवेदी ने लेखक को 27 मार्च 2001 को लिखा।
208 ‘संयम, रचना और अभिव्यक्ति बिल्कुल सही थे’: सोम पाल ने लेखक से कहा, 25
जनवरी 2000।
209 ‘यह वीपी का जनसंपर्क का पहला प्रयास था। बाद में जो हुआ वह कोई संयोग नहीं था’: वही।
प्रभु चावला, ‘फाइनेंस टू’, के अनुसार, 209 वीपी अब भारतीय राजनीति के मिस्टर क्लीन के रूप में राजीव गांधी की जगह ले रहे थे।
रक्षा: प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वी.पी. सिंह को सुर्खियों से हटाया’, इंडिया टुडे, 15 फरवरी 1987; सोम पाल ने लेखक को 25 जनवरी 2000 को लिखा।
209 ‘राजीव के साथ मेरे मतभेदों का एक कारण क्वात्रोची भी था’: वी. पी. सिंह लेखक, 18 अक्टूबर 1999, नई दिल्ली।
209 ‘या मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है’: वही।
210 ‘मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ’: सोम पाल ने लेखक से कहा।
210 ‘मुझे रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति की आवश्यकता है’: उपराष्ट्रपति ने नीरजा को 18 अक्टूबर 1999 को लिखा।
नई दिल्ली।
210 इस समय राजीव सेना प्रमुख जनरल द्वारा निभाई गई भूमिका से भी नाखुश थे।
K. Sundarji: Ibid.
210 ‘Dekhaenge. Abhi to hum machine ko study kar rahen hain’: V. P. Singh to author.

211 वीपी ने सभी जानकारी फाइल में दर्ज कर ली और विभागीय जांच का आदेश दिया: वी. पी. सिंह लेखक।
22 अक्टूबर 1999, नई दिल्ली।
211 'जांच का परिणाम क्या होगा?': वी. पी. सिंह ने लेखक को 29 मई 2003 को लिखा।
211 राजीव ने आदेश दिया कि अब से सरकार हथियारों के सौदों पर सीधे बातचीत करेगी:
हमिश मैकडॉनल्ड, अंबानी एंड संस, मुकर्जी द्वारा उद्धृत, द डिसरप्टर, पृष्ठ 257।
211 उपराष्ट्रपति ने पूरे दिन प्रधानमंत्री आवास पर संदेश छोड़े: वी. पी. सिंह ने लेखक को 22 अक्टूबर 1999 को लिखा, न्यू न्यूज़ीलैंड।
दिल्ली; एम. एल. फोतेदार लेखक को।
212 अभय, जो एक चिकित्सक थे, उन्हें अपनी मारुति 800 ओमनी में वहाँ ले गए: वी. पी. सिंह लेखक को, 22
अक्टूबर 1999, अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली।
212 वीपी ने अपना त्यागपत्र एम. एल. फोतेदार के पास छोड़ दिया: एम. एल. फोतेदार लेखक।
212 'मेरी माँ ने मुझसे कहा, "तुम्हें वी. पी. सिंह के साथ रहना चाहिए"': सोम पाल ने लेखक को 29 जनवरी को बताया
2000, 28, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली।
212 'आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे': वही।
212 'यदि आप राजीव के नेतृत्व में काम करना चाहते थे, तो आपने इस्तीफा क्यों दिया?': वही।
212 'अगर आ सकते हो तो आओ': वही।
213 'सोम पालजी, आप मुझसे उस संगठन को छोड़ने के लिए कह रहे हैं जिसमें मैंने बीस साल बिताए हैं':
वही।
213 'अब क्या किया जाना चाहिए?': वही।
213 'और, दोनों दल यह समझते हैं कि वे अपने दम पर केंद्र में सत्ता में नहीं आ सकते': वही।

213 स्वीडिश प्रसारक ने घोषणा की कि स्वीडिश हथियार कंपनी ने भुगतान कर दिया है
कमीशन: रमेश चंद्रन, 'भारतीय बंदूक सौदे में कुछ बहुत ही गड़बड़ है: स्वेरिज रेडियो', इंडिया टुडे, 15 मई 1987।
214 शाम के बाद जो संकेत मिला, वह यह था कि वी. पी. सिंह ने अरुण के साथ हाथ मिला लिया है।
नेहरू बनाम राजीव गांधी: आरिफ मोहम्मद खान ने लेखक को पत्र लिखा, नई दिल्ली, 21 अगस्त 2018।
214 The event had been crafted to get a sense of 'kaun kitne paani maen hai': Satyapal Malik, 5
मई 2001, नई दिल्ली। स्रोत का पता लगाएं।
214 'मुझे बताया गया था, आपको चाय पार्टी में अवश्य आना चाहिए': सत्यपाल मलिक ने लेखक से कहा।
215 'जब उसने मुझे पहली बार फोन किया, तो मैं यह सोचकर गया कि शायद वह मामले को सुलझाना चाहता हो।'
बाहर': वी. पी. सिंह ने लेखक को लिखा।
215 'मैंने यह मशीन तुम्हारी माँ के साथ चलाई है': वही।
215 'हम इंदिराजी से उनके विलिंगडन क्रिसेंट स्थित घर पर मिलने जाया करते थे': वही।
215 'Rajivji, if I can stand firm for three months toh main kharha reh jaunga': Ibid.
216 'aar paar ki larhai': V. P. Singh to author.
216 'मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा,' उन्होंने कहा: वही।
216 उन्होंने सबसे पहले हरिद्वार में प्रेस को यह घोषणा की: मुखर्जी, द डिसरप्टर, पृ. 274.
216 इंडियन एक्सप्रेस ने अजीतभ बच्चन के खिलाफ एक खुलासा प्रकाशित किया: नीनान और खिंडारिया,
'अमिताभ बच्चन ने लोकसभा से इस्तीफा दिया, अजीतभ स्विस संकट में फंस गए'।
वी.पी. सिंह ने तुरंत प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राजीव गांधी से इस मामले को

सुलझाने का आग्रह किया।
लेखक को, अक्टूबर 1999।
217 ‘उससे मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता’: वही।
217 ‘जब खबर आई तब मैं (रामकृष्ण) हेगड़े के घर पर था’: वही।
कांग्रेस पार्टी से निष्कासन के एक सप्ताह बाद 217: हालांकि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, फिर भी उनके पास
अभी तक घर नहीं बदला था। कुछ समय बाद ही वे सांसदों के लिए आवंटित 28 लोदी एस्टेट नामक एक बहुत छोटे घर में चले गए।
217 सड़क किनारे खड़े लोगों के समूह ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाते थे: इंदरजीत
बधवार और प्रभु चावला, 'कांग्रेस (आई) से वी.पी. सिंह और अन्य असंतुष्टों का निष्कासन एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में तब्दील होने की आशंका', इंडिया टुडे, 15 अगस्त 1987।
218 ‘VP Singh aur bhanda phorho, aur bhanda phorho’: Ibid.
218 The slogan, ‘Takht badal do, taj badal do, beimaano ka raaj badal do’: Ibid.
219 ने अकेले दम पर 60 सीटें जीती थीं, और उसके सहयोगी भाजपा को 16 सीटें मिली थीं: 'सामान्य चुनाव पर सांख्यिकीय रिपोर्ट'
हरियाणा विधानसभा के लिए 1987 के चुनाव’, नई दिल्ली: चुनाव आयोग
भारत का, 1987, <eci.gov.in/files/file/3821-haryana-1987/> पर उपलब्ध है।
219 ‘हरियाणा ने देश को रास्ता दिखाया है’: सोम पाल ने लेखक से कहा।
219 ‘मामाजी, आपने इतने कम समय में अपना मन क्यों बदल लिया?’: वही।
219 ‘मुझे अंदर बुलाया गया। मुझे बताया गया कि यूपी में कहीं एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए’: वही।
220 ‘तभी मुझे इतनी सशक्त और व्यापक प्रतिक्रिया मिलने लगी’: वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा, 18
अक्टूबर 1999।
220 ‘व्यक्तिगत रूप से मैं एक मोर्चे के रूप में जारी रहने का विकल्प चुनता’: वही।
220 ‘विपक्ष की हर पार्टी में फूट पड़ जाती’: वी. पी. सिंह ने लेखक को 16 अक्टूबर

को लिखा।
1999, अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली।
220 'उस समय अटल बिहारी वाजपेई, जसवन्त सिंह और भैरों सिंह शेखावत': वही.
220 वाजपेयी ने बाद में इस बात का खंडन किया: राजाशुक नाग, अटल बिहारी वाजपेयी: सभी के लिए एक नेता
सीजन्स, नई दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स, 2015, पृ. 103.
220 भाजपा नेता जसवंत सिंह ने उपराष्ट्रपति को मौजूदा पार्टियों को एकजुट न करने की चेतावनी दी: वी.पी. सिंह
लेखक, 16 अक्टूबर 1999, अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली।
221 'विश्वनाथ, सीमेंट एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ सकता है, लेकिन एक पत्थर को दूसरे पत्थर से नहीं जोड़ सकता।
लकड़ी का टुकड़ा': वी. पी. सिंह ने लेखक को 18 अक्टूबर 1999 को लिखा।
221 'विरोधाभासों का प्रबंधन एक कला है': वही।
221 वीपी ने कांग्रेस की ताकत को परास्त किया और शानदार जीत हासिल की: दिलीप अवस्थी, जन मोर्चा
नेता वी.पी. सिंह ने इलाहाबाद में कांग्रेस (आई) को करारी हार दी', इंडिया टुडे, 15 जुलाई 1988।
221 'राजीव ने अपनी साइकिल मेरी साइकिल से टकराई और भाग गया': वही।
222 'राष्ट्रीय मोर्चा भगवान आदित्य (सूर्य) का रथ है': प्रभु चावला, 'सात दलीय'
मद्रास में नेशनल फ्रंट का औपचारिक शुभारंभ हुआ', इंडिया टुडे, 15 अक्टूबर 1988।
222 'हीरो नहीं, ज़ीरो', देवी लाल ने बहुगुणा पर हमला किया: वही।
222 अप्रैल 1988 में जेपीसी ने सरकार को किसी भी प्रकार के गलत कार्य से बरी कर दिया: टी. एन. निनन, प्रभु
चावला, 'बोफोर्स जांच: संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में जितना छिपाया गया है उससे कहीं अधिक खुलासा हुआ है', इंडिया टुडे, 15 मई 1988।
222 सीएजी की रिपोर्ट राजीव गांधी के लिए वही थी जो इलाहाबाद का फैसला उनके लिए था।
माँ: शेखर गुप्ता, भास्कर रॉय, 'बोफोर्स बंदूक सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट से विपक्ष

को नई ऊर्जा मिली, कांग्रेस (आई) रक्षात्मक स्थिति में आ गई', इंडिया टुडे, 15 अगस्त 1989।

223 ‘सीएजी रिपोर्ट ने राजीव के लिए 1984 के जनादेश को समाप्त कर दिया है,’ वी. पी. सिंह ने गरजते हुए कहा: वही।

223 सांसदों ने उनकी योजना के साथ चलने पर सहमति जताई: वही।

223 इस कदम से वीपी ने कांग्रेस को अस्थिर करने में कामयाबी हासिल कर ली थी: इंदर मल्होत्रा, 'रियर व्यू:

'1989 में राजीव की करारी हार', इंडियन एक्सप्रेस, 2 फरवरी 2015।

223 ‘बाएँ से दाएँ तक, हम सब अब एक साझा दुश्मन को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं’: गुप्ता और

रॉय ने कहा, 'बोफोर्स बंदूक सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट ने विपक्ष को पुनर्जीवित किया है और कांग्रेस (आई) को रक्षात्मक स्थिति में डाल दिया है।'

223 ‘अब हमें कॉमरेड वाजपेयी और पंडित नंबूदिरिपाद को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि सत्ता से बेदखल किया जा सके।

राजीव!’: वही।

223 ‘Gali gali maen shor hai, Rajiv Gandhi chor hai’: Tehseen Poonawalla, ‘In my childhood, I

मैंने “गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है” सुना था, लेकिन किसी को जेल नहीं हुई। तो फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है?’, टाइम्स नाउ के साथ चर्चा, उपलब्ध है।

www.facebook.com/watch/?v=757301959372053.

224 ‘राजा से फकीर बने’ की एक झलक पाने के लिए: जैसा कि लेखक ने वी.पी. के साथ चुनाव प्रचार के दौरान देखा।

सिंह।

224 वी. पी. सिंह की चुनावी रणनीति सरल थी: राजीव गांधी पर प्रहार करो और कांग्रेस को ध्वस्त कर दो: इंदरजीत

बधवार और प्रभु चावला, 'राजीव गांधी अपना करिश्माई प्रभाव खो देते हैं, वी.पी. सिंह एक दुर्जेय प्रचारक साबित होते हैं', इंडिया टुडे, 30 नवंबर 1989।

224 And, at every rally, he would ask, ‘Bofors ka dalaal kaun hai?’: Inderjit Badhwar, ‘General

1989 के चुनाव: वी.पी. सिंह ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में अथक चुनावी अभियान चलाया', इंडिया टुडे, 30 नवंबर 1989।

224 ने विपक्ष को 'बिच्छू और लड़ाकू मुर्गे' के रूप में वर्णित किया: बडवार और चावला, 'राजीव

गांधी जी अपना करिश्माई प्रभाव खो देते हैं, वहीं वी.पी. सिंह एक दुर्जेय प्रचारक साबित होते हैं।

देश में राम राज्य की स्थापना: तपन कुमार बनर्जी, 'राजीव मंदिर बनवाते और देश को बचाते'

कांग्रेस', द स्टेट्समैन, 18 अक्टूबर 2020; हरदीप सिंह पुरी, @HardeepSPuri, '1989 में राजीव गांधी ने फैजाबाद से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया और राम राज्य का वादा किया। कांग्रेस और चयनात्मक विस्मृति का मामला', रात 9:25 बजे, 5 मई 2014।

twitter.com/HardeepSPuri/status/463346239598129152.

224 'यह वही दिन था... पहली बार... जब मुझे लगा कि हमारे पास एक मौका है': वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा।

225 क्या उसने खुद आखिरी क्षण में अपने पूरे शरीर पर केरोसिन डालने का फैसला किया था:

जनता दल के अज्ञात सूत्रों ने लेखक को यह जानकारी दी है।

225 Rajeev had told his mother the night before, 'Hum sirf tamasha karne jaa rahe hain': Nonita

कालरा, 'राजीव गोस्वामी की त्रासदी आंदोलन को एकजुट होने का अवसर प्रदान करती है', इंडिया टुडे, 15 अक्टूबर 1990।

225 'जैसे ही मैं उस जगह पहुँचा जहाँ वह था... मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा': पराग वोहरा, 'द

'अंतिम शरणस्थल', आउटलुक, 3 फरवरी 2022।

225 राजीव गोस्वामी बच तो गए, लेकिन चौदह साल बाद उनकी मृत्यु हो गई: दलीप सिंह, 'बर्नआउट इन

'अस्पष्टता - मंडल विरोधी चेहरा भुला दिया गया', द टेलीग्राफ, 24 फरवरी 2004।

226 'मुझे मंडल के विरोध की उम्मीद थी': वी. पी. सिंह ने लेखक को 16 अक्टूबर

1999 को अपोलो में लिखा।
अस्पताल, नई दिल्ली।
226 ‘लेकिन,’ उन्होंने बार-बार कहा, ‘बलिदान नहीं…’: वही।
226 राजनीतिक रूप से संबद्ध छात्र संघ, कांग्रेस से संबद्ध राष्ट्रीय छात्र संघ
India (NSUI) and the pro-BJP Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP): Vohra, ‘The Last Refuge’.
226 तिरसठ युवकों ने आत्मदाह करके अपनी जान दे दी: क्रिस्टोफ़ जैफ़्रेलॉट, भारत के मूक अभिनेता
क्रांति: उत्तर भारत में निचली जातियों का उदय, लंदन: हर्स्ट एंड कंपनी, 2003, पृ. 346.
226 अंततः, यह आंकड़ा बढ़कर 200 हो गया: गुहा, 'अधिकार', गांधी के बाद भारत।
227 ‘Mandal toh aapke manifesto maen bhi thaa, usi se prerna lee hai’: V. P. Singh to author, 16
अक्टूबर 1999, अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली।
227 ‘मैं स्पष्ट था क्योंकि भाजपा उसी कुर्सी के लिए दावेदार थी’: वही।
227 ‘हमारी लड़ाई अंततः वीपी सिंह के खिलाफ ही होगी’: के. एन. गोविंदाचार्य, 2 दिसंबर
1989, भाजपा कार्यालय, अशोक रोड, दिल्ली।
228 ‘लेकिन मैं आपके साथ मंच साझा नहीं कर सकता, कृपया इसके बारे में बुरा महसूस न करें’: के. एन.
गोविंदाचार्य से लेखक को, 2018।
228 ‘कृपया, अपने लोगों से बात करें और भाजपा के झंडे उतरवाएं’: वही।
228 ‘हम बाद में देखेंगे कि कौन किस पर हावी होता है’: वही।
228 ‘सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा आयोजित करने का निर्णय 29 तारीख को ही लिया गया था’
जून 1990’: वही।
228 ‘रथ यात्रा का विचार मेरा था’: वही।
229 ‘जब उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन का जिक्र किया, तो भीड़ चुप हो गई’:

वही।
229 'जल्दी क्या है?': वही।
229 'यद्यपि मैं छोटा था, आडवाणी जी मेरी बात सुनते थे और मेरी बातों को महत्व देते थे':
वही।
229 'यह विचार था कि आडवाणी कन्याकुमारी या कलाडी से प्रस्थान करेंगे': वही। कलाडी जन्मस्थान है
आठवीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य का स्थान।
230 'मैं इस नौटंकी में विश्वास नहीं करता': वही।
230 'तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो,' महाजन ने कहा: वही।
230 'रथ यात्रा का निर्णय (मंडल निर्णय से) बहुत पहले ही हो गया था': वही।
230 भाजपा ने रथ यात्रा को उनके निर्णय की प्रतिक्रिया के रूप में पेश किया: वही।
231 'मंडल के पीछे बहुत राजनीति थी': वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा।
231 'अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके बगल में एक मंदिर है': वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा, नई दिल्ली, 22 अक्टूबर
1999.
231 'यदि तुम कर सेवा करोगे, तो हमारे लिए करने को क्या बचेगा!': वही।
232 'अयोध्या में एक चिड़िया भी प्रवेश नहीं करेगी': नीरजा चौधरी, 'अक्टूबर 1990 ने कैसे आकार दिया'
मुलायम की 'एम-वाई' राजनीति, इंडियन एक्सप्रेस, 16 अक्टूबर 2022।
232 'उसी दिन मैंने रात 9 बजे लालू (यादव) को फोन किया और उनसे आडवाणी को गिरफ्तार करने को कहा': वी. पी. सिंह
लेखक को।
232 'Aapne Mandal kiya, toh humne Kamandal kar diya': Ibid.
232 'राजीव उतने भोले नहीं थे जितना लोग मानते थे': एच. आर. भारद्वाज।
232 अरुण नेहरू ने राजीव गांधी को संदेश भेजा: दिनेश त्रिवेदी लेखक।
232 'पड़ोसी देशों को भी सतर्क कर दिया गया था...': वही।
232 'मुझे लगता है कि यह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले था': वही।

233 ‘उन्हें वास्तव में नेहरू की कांग्रेस में वापसी की आशंका थी’: वही।
233 राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन ने ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के प्रस्ताव को खारिज किया था।
मंत्री: एम. एल. फोतेदार से लेखक को। फोतेदार द्वारा लिखित ‘1989 लोकसभा चुनाव—मंडल और कमंडल की राजनीति’, चिनार के पत्ते।
233 ‘आर.वी. (वेंकटरमन) व्यक्तिगत रूप से राजीव के खिलाफ थे’: एच. आर. भारद्वाज ने लेखक को लिखा।
233 ‘लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा’: एम. एल. फोतेदार ने लेखक से कहा।
233 ‘इस आदमी (वीपी सिंह) ने हमें खत्म करने की कोशिश की है’: वीपी सरकार के एक अज्ञात सूत्र ने यह जानकारी दी।
1 सितंबर 2021 को, उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने की इच्छा जताई।
राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस द्वारा 'बाहर से' समर्थित 234: फोतेदार, '1989 लोक चुनाव'
सभा चुनाव—मंडल और कमंडल की राजनीति’, द चिनार लीव्स।
234 ‘Jab tak samaj maen vishamta hai, tab tak samajik nyay ki avashyakata hai’: V. P. Singh to
लेखक।
234 1 अक्टूबर 1990 को, अदालत ने फैसले को 'स्थगित' कर दिया: 'कोटा पर प्रभावी रोक'
'आदेश', हिंदुस्तान टाइम्स, 2 अक्टूबर 1990।
234 दो साल बाद, 1992 में, देश की सर्वोच्च अदालत ने इसकी वैधता को बरकरार रखा।
सरकार का फैसला: अभय सिंह यादव, ‘ओबीसी आरक्षण’, टाइम्स ऑफ इंडिया, 16 अक्टूबर 2022।
235. आरएसएस ने 2015 के बिहार चुनावों के दौरान आरक्षण पर सवाल उठाने का प्रयास किया था: विवाद
आरएसएस प्रमुख की आरक्षण संबंधी टिप्पणी पर हंगामा मच गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, 22 सितंबर 2015।
235 और 2,600 में से 983 ओबीसी समुदायों को तो बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं

मिला था।
नौकरियां: 'ओबीसी के उप-वर्गीकरण और न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग को समझना', बिजनेस स्टैंडर्ड, 8 जुलाई 2022।
235 इसके बजाय, सितंबर 2022 तक, इसे दस बार एक्सटेंशन मिल चुका था: वही।
235 'मंडल ने राजनीति का व्याकरण बदल दिया': वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा।
235 इन समूहों ने अपनी संख्या के आधार पर संरक्षण की मांग करना शुरू कर दिया: जेम्स मैनर, रजनी
कोठारी, भारतीय राजनीति में जाति, दूसरा संस्करण, ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2010।
उत्तर भारत में जाति आधारित क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ: क्षेत्रीय दल पहले से ही मौजूद थे।
देश के दक्षिण और पश्चिम में इनका प्रभाव कहीं अधिक समय तक रहा। इनमें से कुछ दलों को उप-राष्ट्रवाद से अधिक बल मिला, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को 'मराठी अस्मिता' (महाराष्ट्रीयन पहचान) से, तेलंगाना राष्ट्र समिति को तेलुगु राष्ट्रवाद से और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को आंध्र गौरव से। वहीं, तमिलनाडु के द्रविड़ दल, डीएमके और एआईएडीएमके, 1930 के दशक से 'पेरियार' ई. वी. रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में ब्राह्मण-विरोधी आंदोलन से उभरे थे। उन्होंने द्रविड़ कज़गम का गठन किया था, जो बाद में डीएमके और एआईएडीएमके में विभाजित हो गया।
236 'Tilak, Tarazu, aur Talwar, Inko maro joote chaar': Amit Verma, 'For Maya, no looking
'वापस', डेक्कन क्रॉनिकल, 24 जुलाई 2016।
236 'अपना मन बना लो, क्या तुम्हें सामाजिक न्याय चाहिए या यादव राज?': जनता दल का एक बयान
नेता से लेखक को, 5 जुलाई 1991, नई दिल्ली।
236 वह पहले एमबीसी बने—वे घांची या तेल निकालने वाले की जाति से संबंध रखते हैं: 'नरेंद्र
गुजरात सरकार का कहना है कि मोदी मोध-घांची जाति से संबंध रखते हैं, जिसे 1994 में ओबीसी श्रेणियों में जोड़ा गया था।', डीएनए, 9 मई 2014।
236 वीपी बार-बार कहते थे कि मंडल का मतलब 'सत्ता में शिरकत' था: वी. पी.

सिंह ने लेखक को बताया।
237 वी. पी. सिंह ने मुझे अपनी लिखी कुछ कविताएँ पढ़कर सुनाईं: वी. पी. सिंह की कविताएँ प्रकाशित हुई थीं।
एक पुस्तक, एवरीटाइम आई वेक अप, पेंगुइन, 2006।
237 'एक ऐसा समय आता है जब आप पूछते हैं कि इन सबका अर्थ क्या है?': वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा।
अगस्त 2003।
237 'मैं अपने बचपन में कागज़ की नावों से खेला करता था': वही।
238 वीपी कई मायनों में विरोधाभास था: देवेंद्र द्विवेदी ने लेखक को 2 फरवरी 2001 को लिखा।
238 'राजनीति में वफादारी जैसी कोई चीज नहीं होती': वी. पी. सिंह ने लेखक से कहा।
238 'विचार यह था कि एक बार जब वे देश के प्रबंधन में भाग लेना शुरू कर देंगे, तो वहाँ
'विघटनकारी प्रवृत्तियाँ नहीं होंगी': वी. पी. सिंह ने लेखक को अक्टूबर 1999 में लिखा।
238 पी.वी. नरसिम्हा राव 1991 में सत्ता में आए: पी.वी. नरसिम्हा राव ने बहुमत प्राप्त किया
अन्य पार्टियों को तोड़ना।
239 'मैंने इतिहास रचा है। यह आने वाले समय में सरकारों और गठबंधनों को परिभाषित करेगा': वी. पी. सिंह
लेखक, 16 अक्टूबर 1999, अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली।

अध्याय 4: निर्णय लेने से इनकार करने वाले प्रधानमंत्री: पी. वी. नरसिम्हा

राव और बाबरी मस्जिद का विध्वंस
240 'मैंने सुना है कि आप बारह बजे के बाद पूजा कर रहे थे': राम बहादुर राय ने लेखक से कहा।

240 ‘दादा, आपको लगता है कि मुझे राजनीति की जानकारी नहीं है। मैं तो राजनीति में पैदा हुआ था’: राम बहादुर राय ने 18वीं किताब के लेखक से कहा
फरवरी 2019, नई दिल्ली, 24 जून 2020 को फोन पर पुष्टि की गई।
240 उनके साथ तीन अन्य पत्रकार भी थे: वही।
241 ‘वे राव से अक्सर मिलते थे’: वही।
241 पहले गुंबद के गिरने के बाद, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा।
मंत्री: शाहिद सिद्दीकी ने लेखक को पत्र लिखा, 25 मार्च 2019, नई दिल्ली। सिद्दीकी को लिखित पत्र दिखाया गया।
241 मंत्रिपरिषद: मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री, वरिष्ठ और कनिष्ठ, शामिल होते हैं।
सरकार में, मंत्रिमंडल के विपरीत, जिसमें कैबिनेट रैंक के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं।
241 राव ने एक अन्य आगंतुक से भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं: रश्मी कांत ने लेखक को 13 जून 2020 को लिखा।
नई दिल्ली, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
242 ‘मैंने उनसे अयोध्या के बारे में पूछकर शुरुआत की’: वही।
242 'ये तो होना ही था': वही।
242 ‘Kya karoon, saari umar clerk hee tho raha hoon’: Ibid.
242 ‘मुझे नहीं पता कि वह खुश था या दुखी’: वही।
242 ‘he said unse baat ho gayee thee ki 6 December ko aisa karenge’: Som Pal to author, 15
फरवरी 2021, नई दिल्ली। 11 सितंबर 2021 को पुनः पुष्टि की गई।
243 ‘आरएसएस प्रमुख के. सुदर्शन ने भी मुझे इसकी पुष्टि की’: वही।
243 बाबरी तूफान से उबरने के बाद, वह राजनीतिक नेताओं से परामर्श कर रहे थे: वही।
243 ‘हो सकता है कि इतिहास भविष्य में आपको अलग तरह से आंके’: वही।
243 ‘और उसने जो कुछ हुआ था उसे स्वीकार किया’: वही।
243 उनके अलग-अलग विचारों के बावजूद, उनसे 'राष्ट्रीय हित' के लिए 'सामंजस्य' में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी:
पी. वी. नरसिम्हा राव, अयोध्या: 6 दिसंबर 1992, नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स,

2006, पृष्ठ 2।
243 'संघीय संरचना में सद्भावना': वही।
243 'sarvadharma sambhav': Ibid., p. 48.
243 ने देश की राजनीति को 'धार्मिक दायरे में धकेल दिया': वही, पृष्ठ 188।
243 'केवल इसके द्वारा उत्पन्न चुनौती का मुकाबला करने के लिए': वही।
244 'Khayal rakhna. Keep in mind a Rajya Sabha seat for me, should the opportunity arise':
Janardhan Reddy to Krishan Kant to author, Hyderabad, 25 December 1995.
245 'हम सरकार बनाएंगे': एम. एल. फोतेदार ने लेखक से कहा।
245 'उन्होंने पहले कभी उस शब्द का प्रयोग नहीं किया था': वही।
245 फिर उसने स्पष्ट रूप से उसे यह कहते हुए सुना, 'मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ': जयंती नटराजन ने लेखक से कहा, 16
मार्च 2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
245 'कई लोगों ने उसे लपेट लिया, और (जी. के.) मूपानार, मैं और कुछ अन्य लोग उसे ले गए।
सामान्य अस्पताल': वही।
245 'हर कोई महत्वपूर्ण है,' नटराजन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा: वही।
246 'उसने किसी से बात नहीं की': वही।
246 'कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अब कौन करेगा?': पी.वी. नरसिम्हा राव ने भुवनेश चतुर्वेदी से पूछा
लेखक: विनय सीतापति, हाफ लायन: हाउ पी. वी. नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, 2016, पृष्ठ 90।
246 'लोग कहेंगे, आप राजनीति खेल रहे हैं': भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक से कहा, 1999, न्यू
दिल्ली।
246 उन्हें वास्तव में मुखर्जी पर भरोसा नहीं था: वही।
246 मणि शंकर अय्यर एक कोने में अकेले बैठे थे: जैसा कि लेखक ने तीन मूर्ति में उस दिन देखा था

घर।
247 ‘यह मेरे लिए पर्याप्त संकेत था कि वह तैयार था’: भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक से कहा, 7
अक्टूबर 1999, नई दिल्ली।
247 ‘जॉर्ज, अर्जुन सिंह और मैंने फैसला किया था कि हमें सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए।
कांग्रेस’: एम. एल. फोतेदार द्वारा लेखक को, 1 जुलाई 2005, गुड़गांव।
247 ‘अर्जुन सिंह, जी. के. मूपानार, सीताराम केसरी और मैं पी.वी. को देखने गए’: वही।
247 ‘महोदय, मैं उसका नाम प्रस्तावित करूँगा’: वही।
247 ‘फोतेदारजी, सोनिया गांधी के लिए माहौल अनुकूल है’: वही।
247 पवार ने प्रस्ताव का समर्थन करने पर सहमति जताई: वही।
247 लेकिन पवार ने उन्हें पीछे छोड़ दिया: राजीव देशपांडे, 'राजीव गांधी मुझे पद से हटाना चाहते थे'
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी: शरद पवार’, टाइम्स ऑफ इंडिया, 13 दिसंबर 2015।
248 ‘आइए पहले प्रस्ताव पारित करें’: वही।
248 ‘उन्हें लगा कि वे सोनिया को नियंत्रित कर पाएंगे’: भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक से कहा।
248 उन्होंने जॉर्ज से सोनिया गांधी को एक नोट भेजने का अनुरोध किया: एम. एल. फोतेदार लेखक को, नई दिल्ली।
248 ‘वह रिजर्व में एक नेता होंगी’: वही।
248 ‘आपको तय करना होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए’: नटवर सिंह ने लेखक से कहा; के.
नटवर सिंह, एक जीवन पर्याप्त नहीं है: एक आत्मकथा, नई दिल्ली: रूपा एंड कंपनी, 2014, पृ. 288–89.
248 ‘आप पी. एन. हक्सर से परामर्श क्यों नहीं करते?’: वही।
249 ‘और उन्हें बता दें कि सोनियाजी ने उनसे कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनने का अनुरोध किया है।

मंत्री’: वही।
249 ‘आपको (अरुणा आसिफ अली और नटवर को) शंकर दयाल शर्मा के पास भेजना चाहिए’: वही।
249 ‘सोनियाजी का यह प्रस्ताव देना बहुत ही उदारतापूर्ण है’: नटवर सिंह ने लेखक से कहा, 21 जून 2018
नई दिल्ली; सिंह, एक जीवन पर्याप्त नहीं है, पृ. 289.
249 ‘अब पी.वी. नरसिम्हा राव को बुलाओ,’ हक्सर ने सलाह दी: वही।
249 राव के लिए सोनिया गांधी की सहमति निर्णायक साबित हुई: राजेश रामचंद्रन, 'सोनिया
'गांधी ने 1991 में नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चुना था: आर. डी. प्रधान, पूर्व गृह सचिव', द इकोनॉमिक टाइम्स, 4 अगस्त 2014।
250 ‘नारायण दत्त तिवारी जब पीवी को यूपी में पेश कर रहे थे तब नारे लगने लगे’: भुवनेश
चतुर्वेदी द्वारा लेखक को, 26 अप्रैल 2000, नई दिल्ली।
250 ‘Maa bete ka balidan, yaad karega Hindustan’: ‘Reports from states suggest sympathy factor
आगामी चुनावों में कांग्रेस (आई) को मदद मिलने की संभावना है’, इंडिया टुडे, 15 जून 1991।
दूसरे चरण में इसने 27 में से 20 सीटें जीतीं, जबकि पहले चरण में इसे 15 में से 5 सीटें मिली थीं।
मुखर्जी, द टर्बुलेंट इयर्स, पृ. 135.
1984 के आम चुनाव में कांग्रेस ने इन राज्यों से 171 सीटें जीती थीं, जबकि अब यह संख्या 250 है, जो एक बड़ी गिरावट है।
चुनाव: ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ. 322.
कांग्रेस ने सबसे अधिक 232 सीटें जीती थीं, हालांकि उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था।
संसद: ‘दसवीं लोकसभा के लिए 1991 के आम चुनावों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट: खंड I’, दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 1992, उपलब्ध है <eci.gov.in/files/file/4121-
आम चुनाव 1991 खंड i-ii>

250 ‘शिव शंकर को छोड़कर’: भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक से कहा।
250 महाराष्ट्र के बाहुबली नेता शरद पवार ही गंभीर चुनौती बनकर उभरे:
Prithviraj Chavan to author, 19 July 2019, Mumbai.
उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों में से 38 सीटें जीती थीं:
‘दसवीं लोकसभा के लिए 1991 के आम चुनावों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट: खंड I’
250 उन्होंने देश भर में कई कांग्रेस उम्मीदवारों को भी आर्थिक सहायता दी थी: पृथ्वीराज चव्हाण को
लेखक, 19 जुलाई 2019, मुंबई।
251 साल्वे और नजमा हेपतुल्ला और सुरेश कलमदी अपने नेता के लिए समर्थन जुटा रहे थे:
वही।
251 उन्होंने नेता के चयन के लिए 'विवेक मत' का प्रस्ताव पारित किया: वही।
251 ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की और यह बताया कि वह पवार के कारनामों को उजागर करेगा।
भूमि घोटाले में संलिप्तता: एन. के. शर्मा ने लेखक को 12 जुलाई 1999 को दिल्ली में पत्र लिखा।
251 ‘सोनिया गांधी एक स्वतंत्र सोच वाले प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं करतीं’: देशपांडे, ‘राजीव
गांधी जी मुझे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे।
251 ‘कृपया साल्वे के घर जाइए और शरद पवार को पीवी के आवास 9, मोती लाल नेहरू ले आइए।’
मार्ग’: एन. के. शर्मा लेखक को।
251 ‘मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ...तुम मुझसे बहुत छोटे हो, तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे सामने है, तुम्हारा
मौका जरूर आएगा’: पवार के करीबी रहे ए. जी. कुलकर्णी ने लेखक से 1991 की सर्दियों में नई दिल्ली में यह बात कही; पी. वी. राव से यह बात सुनने वाले भुवनेश चतुर्वेदी ने भी लेखक से नई दिल्ली में यह बात कही।
252 जनपथ पर 10 बजे, जब राव सोनिया के साथ अंदर थे, 'हममें से कुछ लोग

(बाहर) बैठे थे।
'जॉर्ज का कमरा': एन. के. शर्मा ने लेखक को पत्र लिखा, नई दिल्ली।
252 21 जून 1991 को पी. वी. नरसिम्हा राव ने नौवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली: पृष्ठ भी देखें।
xiii इस बात पर कि यह पुस्तक स्वतंत्रता के बाद से देश में हुए प्रधानमंत्रियों की संख्या की गणना कैसे करती है।
252 'मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे पता है इन लोगों से कैसे निपटना है': वेद ऐथाराजू, 'पीवी को श्रद्धांजलि'
नरसिम्हा राव: "उनमें निहित ब्राह्मण और तेलंगाना को स्वीकार किया जाना चाहिए", 28 जून
2020, vedaitharaju.medium.com पर उपलब्ध है।
252 तेलुगु ब्राह्मणों को दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया था: के. एस. सिंह, पीपल ऑफ इंडिया खंड 6:
भारत के समुदाय (न्यूजीलैंड-ज़ेड), दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998।
253 'भौगोलिक रूप से उत्तर और दक्षिण के बीच एक सेतु': पी. वी. नरसिम्हा राव ने अपने
7 जुलाई, 1991 को हैदराबाद के तेलुगु विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण। पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा चयनित भाषण 1991-92, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 1991, पृष्ठ 239 में उद्धृत, सीतापति, हाफ लायन, पृष्ठ 12 में उद्धृत।
253 इस छोटी बस्ती के निवासी तेलुगु, हिंदी, मराठी, कन्नड़ और यहाँ तक कि एक अन्य भाषा भी बोलते थे।
ओडिया भाषा के कुछ अंश: सीतापति, आधा शेर, पृ. 12.
253 अध्ययन के लिए नागपुर में कई साल बिताने के कारण, वे मराठी धाराप्रवाह बोलते थे: वही, पृष्ठ 27।
253 एक बार जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ की रचना 'लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा' पढ़ी है: सागरिका
घोष, 'अब मिलिए उपन्यासकार पी.वी. से', आउटलुक, 18 अक्टूबर 1995।
दूसरी ओर राव ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया: सीतापति, हाफ लायन, पृ. 16.

254 एक साल तक वह महाराष्ट्र के चंदा में एक शिविर में तैनात रहा और हथियारों की ढुलाई करता था।
समूह: वही, पृष्ठ 21.
254 लेकिन यह हिंसा से चिह्नित था, और लगभग 40,000 मुसलमान मारे गए: वही।
254 निज़ाम-विरोधी आंदोलन ने तीन विविध धार्मिक-राजनीतिक धाराओं को एक साथ लाया था: वही।
पृष्ठ 20.
255 किसी तरह, राव किसी का पक्ष लेने से बच गए और उन्होंने ऐसा किसी को नाराज किए बिना किया: सीतापति,
हाफ लायन, पृष्ठ 22.
255 राव ने उन दिनों उच्च अधिकारियों के साथ सही संबंध बनाए रखने का महत्व भी सीखा।
कमान: उच्च कमान एक लोकप्रिय शब्द है जिसका प्रयोग किसी पार्टी के नेतृत्व के लिए किया जाता है जो अंतिम निर्णय लेता है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नेहरू-गांधी परिवार के लिए इसका प्रयोग किया जाता था।
255 कांग्रेसी जयराम रमेश के शब्दों में, 'मृत मछली' की तरह करिश्माई: वही, पृष्ठ 98।
256 एक समय तो उन्होंने उसे राष्ट्रपति भवन भेजने का भी विचार किया था: फोतेदार,
'राजनीतिक सचिव, 1980–887', चिनार के पत्ते।
256 छद्म नाम से मेनस्ट्रीम पत्रिका के लिए लिखते थे: सीतापति, आधा शेर, पृ. 77.
256 'इंदिरा गांधी कभी भी, दोहराती हूँ कभी भी, अपनी... बेहद जटिल... हीन भावना से उबर नहीं पाएंगी':
पी. वी. नरसिम्हा राव, 'अध्याय 41', द इनसाइडर, नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, 2014।
256 वे राजीव गांधी की क्षमताओं की और भी अधिक आलोचना करते थे: हालाँकि पहले यह कहा जाता था कि 'कोई भी
'नरसिम्हा राव के मन में क्या चल रहा है, यह सचमुच कोई जान सकता है', पी.वी.

राव कभी-कभी निखिल-दा से अपने दिल की बात कहते थे। 'हमारे लंबे साथ के दौरान शायद ही कोई ऐसा विषय रहा हो जिस पर उन्होंने मुझसे चर्चा न की हो', राव ने निखिल के बारे में कहा था। पी.वी. नरसिम्हा राव, 'निखिलदा: कुछ पुरानी यादें', खंड 47वीं, अंक 46, मेनस्ट्रीम, 31 अक्टूबर 2009।

257 'Kya stand loon?': Nikhil Chakravartty to Krishan Kant to author.

257 जिसका शीर्षक 'महान आत्महत्या' है, और जिसे 'कांग्रेसी' नामक छद्म नाम से लिखा गया है:

कांग्रेसी, 'द ग्रेट सुसाइड', खंड LIII, अंक 6, मेनस्ट्रीम, 31 जनवरी 2015।

257 '(विंसेंट) जॉर्ज का कहना है कि यह सोनिया गांधी की पसंद है और उन्होंने इसमें और नाम जोड़े हैं': भुवनेश

चतुर्वेदी द्वारा लेखक को, 30 नवंबर 1999, नई दिल्ली।

257 सरकार क्या कर रही थी, इसके बारे में उसे जानकारी देते रहें: वही।

258 'मैं उन्हें प्रशिक्षित करूँगा। मैं उन्हें अपने कुछ दौरों पर अपने साथ ले जाऊँगा': पी. वी. नरसिम्हा राव

लेखक, अनौपचारिक बातचीत, नई दिल्ली।

258 'उन फाइलों को छोड़कर जिन्हें वह मंजूरी नहीं देना चाहता था': पी.वी. नरसिम्हा के करीबी अज्ञात सूत्रों के अनुसार

राव से लेखक तक।

259 'क्या आप लोग एक साधारण मामले को भी नहीं संभाल सकते?': वही।

259 'कोई निर्णय न लेना भी एक निर्णय है': रवीश तिवारी, 'पीवी नरसिम्हा राव एक कुशल रणनीतिकार थे,

एक "लोमड़ी" जो "असाधारण रूप से निर्णायक" थी: जयराम रमेश, इकोनॉमिक टाइम्स, 29 अगस्त

2015.

259 'PV thanda karke khate hain': Bhuvnesh Chaturvedi to author.

259 पाउट- मीडिया ने राव को एक उपनाम दिया: संजय बारू, 'कैसे पीवी नरसिम्हा राव, भारत के

'पहले 'संयोगवश' प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने इतिहास में अपना स्थान अर्जित किया', इंडियन एक्सप्रेस, 28 जून 2021।

259 ‘जब वह कोई निर्णय नहीं लेना चाहता था, तभी वह उसे स्थगित करता था’: अज्ञात
स्रोत से लेखक को, 9 सितंबर 2019।

260 उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देश दिया था कि यदि वे कोई ‘कार्य करने’ के लिए कहें तो:
लेखक भुवनेश चतुर्वेदी।

260 ‘Na jaane kis bhesh main Narayan mil jaye’: Ibid.

श्रीनिवासा प्रसाद, 'एक रिपोर्टर की डायरी' - 260 जिन लोगों ने अपना वोट डाला उनमें से 90 प्रतिशत ने उन्हें चुना।

नंदीयाल से: 1991 में एके 477 और कच्चे बमों से लेकर 2017 में जहर के विस्फोट तक’, फर्स्टपोस्ट, 31 अगस्त 2017।

260 ‘PV bahut zaalim hain’: Bhuvnesh Chaturvedi to author.

260 मुखर्जी को वित्त मंत्रालय मिलने की उम्मीद थी: भुवनेश चतुर्वेदी लेखक बनेंगे, न्यू
दिल्ली; मुखर्जी, द टर्बुलेंट इयर्स, पृ. 138.

260 ‘यह समस्याग्रस्त होगा’: भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक को, अक्टूबर 1999।

261 ‘शायद एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपसे इस बारे में बात कर सकूंगा’: मुखर्जी, द टर्बुलेंट
इयर्स, पृ. 138.

261 ‘मैं पैंतालीस दिनों में पद छोड़ दूंगा’: एम. एल. फोतेदार ने लेखक से कहा; फोतेदार, ‘द राव इयर्स’,
चिनार के पत्ते।

261 ‘जैसे ही किसी नाम पर सहमति बन जाएगी, मैं पद छोड़ दूंगा’: एम. एल. फोतेदार ने लेखक से कहा।

261 ‘Unki meherbaani hai ki mujhe leader banaya, rakhenge tho bhi theek’: Arjun Singh to
भुवनेश चतुर्वेदी ने 7 अक्टूबर 1999 को नई दिल्ली में लेखक को बताया।

261 जब उन्होंने और शरद पवार ने कांग्रेस के कार्यकारी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की।
तिरुपति में समिति: लेखक इस सत्र में उपस्थित थे।
262 उन दिनों राव 'सोना गली में एक कमरे के छोटे से कमरे' में रहते थे: आर. के. खांडेकर ने लेखक को लिखा, 23
दिसंबर 2020।
262 'संघ की यह विशेषता है कि वह लोगों से दोस्ती करता है, उनसे चाय पर मुलाकात करता है':
गोविंदाचार्य ने लेखक को 2 अगस्त 2020 को फोन पर यह संदेश भेजा।
262 इसी दौरान संघ (आरएसएस) को आर. के. खांडेकर के बारे में भी जानकारी मिली: गोविंदचार्य
लेखक को, 4 अगस्त 2020 को, फोन पर।
262 'मैं छह साल की उम्र से स्वयंसेवक था और आरएसएस शाखाओं में जाया करता था': आर. के.
खांडेकर ने लेखक को 23 दिसंबर 2020 को लिखा।
262 खांडेकर राव के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए रेस कोर्स रोड पर आने वाले धन का भी ध्यान रखते थे।
गतिविधि: भुवनेश चतुर्वेदी द्वारा लेखक को, 27 अक्टूबर 1999, नई दिल्ली।
263 वह राव के लिए कपड़ों का एक अतिरिक्त सेट, 'यहां तक कि चश्मा भी' साथ रखते थे: आर. के. खांडेकर
लेखक को, 6 सितंबर 2020।
263 खांडेकर राव और भाजपा-आरएसएस नेताओं के बीच मध्यस्थ थे: के. एन. गोविंदचार्य लेखक को।
263. भाऊराव देवरास ने राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनसे संपर्क बनाए रखा था: सुभाष
भाऊराव के दाहिने हाथ आर्य ने लेखक को; आर. के. खांडेकर ने लेखक को।
263 'अगर आप कभी बाबरी मस्जिद को गिराने का फैसला करें तो मुझे पहले से सूचित कर दें': मलकानि, द
अयोध्या की राजनीति।

263 ‘अगर पी.वी. कुछ और समय तक सत्ता में बने रहते तो वे वास्तव में भाजपा का सफाया कर देते’:
लेखक भुवनेश चतुर्वेदी।
263 वाजपेयी ने तुरंत पलटवार करते हुए राव को 'गुरुघंटाल' कहा: सिद्धार्थ मिश्रा, 'जब
संवाद संक्षिप्त हो जाता है’, मिलेनियम पोस्ट, 31 अक्टूबर 2013।
263 ‘सबसे विद्वान प्रधानमंत्री’: आडवाणी, माई कंट्री, माई लाइफ, पृ. 391.
263 वह व्यक्ति जो ‘हिंदुओं के कष्टों और परेशानियों’ को समझता था: वही।
264 एकता यात्रा के साथ, जोशी को उम्मीद थी कि ‘मंदिर के मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सकेगा’: जफर आगा और
एन. के. सिंह, ‘भाजपा ने राष्ट्रीय एकता की खोज की’, इंडिया टुडे, 15 दिसंबर 1991।
264 उसने स्थिति को इस प्रकार संभाला कि ‘उसके इरादों के बारे में संदेह पैदा हो जाए’:
लेखक भुवनेश चतुर्वेदी।
264 प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन, जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चा (जेकेएलएफ) और हिजबुल मुजाहिदीन: फिलिप ओल्डेनबर्ग (संपादक), इंडिया ब्रीफिंग, 1993, न्यूयॉर्क और ऑक्सन: रूटलेज, 2018।
264 एक ऐसा आयोजन जिसे हजारों लोगों द्वारा देखा जाना था, उसमें केवल सड़सठ भाजपा प्रतिनिधि ही उपस्थित थे।
सदस्य: कावेरी बामज़ई, हरिंदर बावेजा और दिलीप अवस्थी, 'श्रीनगर में भाजपा का ध्वजारोहण समारोह फीका साबित हुआ, उग्रवाद को बढ़ावा मिला', इंडिया टुडे, 15 फरवरी 1992।
265 ‘अगर राजीव जीवित होते तो वे एकता यात्रा रोक देते’: भुवनेश चतुर्वेदी
लेखक।
265 राव की रणनीति शुरू से ही भाजपा को 'एक और कांग्रेस' की तरह दिखाने की रही है, न कि 'एक
एक अलग तरह की पार्टी’: वही।
265 ‘हम इसे हमेशा ऊँचा रख सकते थे। अब हम ऐसा नहीं कर सकते’: एन. के.

सिंह, ‘गुजरात प्रमुख’
'मंत्री केशूभाई पटेल की सरकार को भाजपा के 47 विधायकों के एक समूह ने बंधक बना लिया', इंडिया टुडे, 31 अक्टूबर 1995।
265 पर्दे के पीछे के ‘मास्टर कठपुतली निर्देशक’ कोई और नहीं बल्कि पी. वी. नरसिम्हा राव थे:
भुवनेश चतुर्वेदी लेखक, 30 नवंबर 1999, नई दिल्ली।
265. गुजरात के राज्यपाल नरेश चंद्र का प्रधानमंत्री से कभी सीधा संपर्क नहीं था: वही।
नरेश चंद्र ने इसकी पुष्टि की है।
265 ‘यह पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया था’: वही।
265 आरएसएस के मुखपत्र, पांचजन्य ने पीवी के पक्ष में लिखा: पांचजन्य, 7 दिसंबर 1991।
265 आरएसएस प्रमुख बालासाहेब देवरस ने उनके बारे में अच्छी बातें कही थीं: एन. के. शर्मा ने लेखक को बताया, 25
जनवरी 2000, नई दिल्ली।
266 संतों ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे उन्हें अपनी प्रस्तावित कार सेवा के बारे में व्यक्तिगत रूप से अवगत कराने आए हैं:
Hemant Sharma, Yuddha Mein Ayodhya, Delhi: Prabhat Prakashan, 1 January 2018, p. 85.
266 'मूंह जो बंद रखा है': राव भुवनेश चतुर्वेदी से जिन्होंने लेखक को बताया, 27 अक्टूबर 1999,
नई दिल्ली।
दोनों पक्षों के बीच अपने-अपने दावों के समर्थन में 267 दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया था: एल. के.
आडवाणी, मेरा देश, मेरा जीवन, नई दिल्ली: रूपा एंड कंपनी, 2008, पृ. 388.
267 अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद कार्रवाई समिति (एआईबीएमएसी) ने यह तर्क दिया था कि कहानी
रामायण पौराणिक थी, ऐतिहासिक नहीं: वही, पृष्ठ 387।
267 राव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह चंद्र शेखर के छोड़े हुए काम को आगे

बढ़ाएंगे: वही, पृष्ठ 392।
267 'Kaho, Devendra, kaise ho': Devendra Dwivedy to author, 28 February 2001, Parliament
हाउस, नई दिल्ली।
267 उसने अपने एक तीखे पत्र की 3,000 फोटोकॉपी करवाई और उन्हें पार्टी को भेज दिया।
नेता: ठाकुर, प्रधान मंत्री, पृ. 322.
268 'मुझे लगता है कि आपको भाजपा से बात करनी चाहिए': देवेंद्र द्विवेदी ने लेखक से कहा, 28 फरवरी 2001
संसद भवन, नई दिल्ली।
268 'आप भाजपा से बात करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, आपके उनके साथ अच्छे संबंध हैं': वही।
268 'मुझे याद है कि मैं वहाँ 10.07 बजे पहुँचा था': वही।
268 'प्रधानमंत्री ने वाजपेयी और मुझसे मंदिर के नेताओं को मनाने के लिए बात की।
उन्हें कुछ समय देने के लिए आंदोलन: आडवाणी, मेरा देश, मेरा जीवन, पृ. 392.
269. वेद प्रताप वैदिक ने बताया कि 26 जुलाई को कार सेवा रोक दी गई और राव को तीन महीने का समय देने का फैसला किया गया।
लेखक को, 14 सितंबर 2018, गुड़गांव।
269 'वह एक निर्मम व्यक्ति है, लेकिन वह उठा और उसने मुझे दोनों कंधों से पकड़ लिया:' देवेंद्र द्विवेदी ने कहा।
लेखक, 28 फरवरी 2001, संसद भवन, नई दिल्ली।
269 प्रधानमंत्री सहमत हो गए। 'मैं परसों बलिया जा रहा हूँ': वही। प्रधानमंत्री बलिया जा रहे थे (में
उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्र शेखर द्वारा उनकी स्मृति में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए वे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।
जयप्रकाश नारायण के। जैसा कि उल्लेख किया गया है, राव विपक्षी नेताओं को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे।
270 'इसके बाद, पीवी मुझसे बचने लगा': वही।

270 ‘यह मेरी गलती नहीं है’: नरेश चंद्र ने लेखक से पी.वी. राव द्वारा कही गई बातों के बारे में कहा
उन्हें, 25 दिसंबर 2001, नई दिल्ली।
270 ‘मैं आधिकारिक तौर पर भारत सरकार का सचिव नहीं था’: वही।
270 ‘जिस तरह से उन्होंने पोस्ट को डिजाइन किया, और यह राव के काम करने के तरीके का विशिष्ट उदाहरण था’: वही।
270 ‘मुझे पूछताछ के लिए नहीं बुला सके’: वही।
270 ‘व्यापक राष्ट्रीय हित’: वही।
270 राव ने चंद्र को विवाद से संबंधित सभी कागजात एकत्र करने को कहा: वही।
270 ‘मेरे उत्तराधिकारियों में से किसी ने भी मुझसे पांच मिनट के लिए भी इस बारे में बात नहीं की कि मैंने क्या किया था।
अयोध्या’: चंद्र शेखर ने लेखक को 12 अगस्त 2003 को नई दिल्ली में लिखा।
271 मूर्ति ने भविष्यवाणी की थी कि राव प्रधानमंत्री बनेंगे: कृष्णकांत ने लेखक को बताया, 25
दिसंबर 1995, हैदराबाद। रश्मी कांत द्वारा लेखक को 3 अप्रैल 2018, नई दिल्ली में पुष्टि की गई।
271 ‘तब से, मुझे लगता है कि उनके अंदर कहीं न कहीं’: एक अज्ञात वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा
लेखक।
271 ‘बार-बार’ नरेश चंद्र के साथ प्रमुख मील के पत्थर: नरेश चंद्र से लेखक तक,
31 मार्च 2017, नई दिल्ली।
271 का निर्माण मुगल सेनापति मीर बाकी ने सम्राट बाबर के आदेश पर 1528 में करवाया था:
Singh, Ayodhya, p. 28.
272 उन्नीसवीं शताब्दी में दोनों समुदायों के बीच कुछ झड़पें हुईं: प्रतियां
राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख, राव, अयोध्या, पृष्ठ 4 में उद्धृत।
272 1934 में, हिंदू दंगाइयों ने मस्जिद के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया; इसका पुनर्निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था:

कुमार अंशुमन, ‘अयोध्या मामला: भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले संपत्ति विवाद का संक्षिप्त इतिहास’, इकोनॉमिक टाइम्स, 10 नवंबर 2019।

272 1949 की घटना 22 दिसंबर की आधी रात को घटी: सिंह, अयोध्या, पृ. 188;

Report of the Liberhan Commission of Inquiry; Sharma, Yuddha Mein Ayodhya; Ram Bahadur Rai to author.

272 लोगों ने घंटियों, झांझों और शंखों की झंकार के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया: इसके आधार पर

भास्कर दास की गवाही, सिंह, अयोध्या, पृष्ठ 194।

272 हिंदू महासभा, जो भारतीय जनसंघ की पूर्ववर्ती संस्था थी: राम बहादुर राय

to author, 18 February 2019, Indira Gandhi Centre of Arts, New Delhi; Sharma, Yuddha Mein Ayodhya; Singh, Ayodhya, p. 187.

273 यह बात इतनी प्रसिद्ध नहीं है कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता नानाजी देशमुख ने राम बहादुर राय को लेखक बनाया था।

18 फरवरी 2019, नई दिल्ली।

273 ‘One day I had gone to meet Nanaji Deshmukh at the Deen Dayal Shodh Sansthan’: Ibid.

273 ‘Abhiram Das, Bhaiji Hanuman Prasad Poddar, Mahant Ramchandra Paramhans, and

शकुंतला नायर’: वही।

273 ‘और यह सुबह 5 बजे पाया गया’: वही।

274 नायर के अधीन कार्यरत नगर मजिस्ट्रेट गुरु दत्त सिंह ने संरचना को 'अटैच' कर लिया:

कुर्की एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय किसी देनदार की संपत्ति को लेनदार को हस्तांतरित करने के लिए नामित करता है।

274 14 अगस्त 1949 को, इसने उन सभी मंदिरों को मुक्त कराने का संकल्प लिया था जहाँ मुसलमानों ने निर्माण किया था।

mosques: Ram Bahadur Rai to author, Indira Gandhi Centre of

Arts, New Delhi, 19 February 2019. Also Sharma, Yuddh Mein Ayodhya and Singh, Ayodhya.

274 'देव के खिलाफ सांप्रदायिक रूप से कटु हमला': कृष्ण झा और धीरेंद्र के. झा, अयोध्या: द

डार्क नाइट: बाबरी मस्जिद में राम के प्रकट होने का गुप्त इतिहास, नई दिल्ली: हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया, 2016।

274 उन्होंने लोगों को अपने पक्ष में करने के अभियान के दौरान तुलसी के पत्ते भी बांटे: सिंह, अयोध्या, पृ.

186.

274 का उद्देश्य नरेंद्र देव को हाशिए पर धकेलना था, जो उत्तर प्रदेश में उनके प्रतिद्वंद्वी थे और नेहरू के विश्वासपात्र थे:

वही, पृष्ठ 185।

274 उन्होंने अपने क्षेत्र में हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया।

फेवर: झा और झा, अयोध्या: द डार्क नाइट।

274 'कांग्रेस नेताओं को मतदाताओं की हिंदू भावना को अपील करना पड़ा': वही।

275 कल्याण सिंह ने विध्वंस की अनुमति दी: रवि सिंह सिसोदिया, 'बाबरी विध्वंस' मामला: कल्याण सिंह पर आपराधिक साजिश का आरोप', टाइम्स ऑफ इंडिया, 28 सितंबर 2019; 'और सब कुछ धराशायी हो गया: बाबरी मस्जिद विध्वंस ने कल्याण सिंह सरकार को कैसे गिराया', न्यूज18, 29 सितंबर 2020।

मात्र 1,500 वर्ग गज भूमि पर 275 मामले: एम सिद्दीक (डी) थ्रू एलआरएस बनाम महंत सुरेश दास और अन्य।

9 नवंबर 2019, <indiankanoon.org/doc/107745042/> पर उपलब्ध है।

मथुरा और वाराणसी में 276 स्थलों को 'मुक्त' करने का मुद्दा: 'दक्षिणपंथी समूह काशी को 'मुक्त' करना चाहते हैं'

और मथुरा के मंदिर; आरएसएस का कहना है कि दबाव नहीं डालेंगे', द वायर, 9 सितंबर 2020।

276 बाबरी मस्जिद को लेकर पहला कानूनी मुकदमा महंत रघुबीर दास ने 1885 में

दायर किया था: सिंह,
Ayodhya, p. 28.
276 1959 में, निर्मोही अखाड़ा ने विवादित भूमि के स्वामित्व के लिए एक 'स्वामित्व मुकदमा' दायर किया: राव,
Ayodhya, p. 9.
276 उन्होंने मस्जिद के आसपास की विवादित भूमि के '2.77 एकड़' हिस्से पर कब्जा कर लिया: 'अयोध्या फैसला: भारत का
सबसे बड़ा कानूनी विवाद सिर्फ 0.3 एकड़ जमीन को लेकर था, न कि 2.77 एकड़ को लेकर', न्यूज18, 10 नवंबर 2019।
277 उन्होंने अपने कार्यों के बारे में उपराष्ट्रपति को सूचित किया और उन्होंने उनके प्रयासों का समर्थन किया: कृष्ण
कांत ने लेखक से 25 दिसंबर 1995 को हैदराबाद में एक गोपनीय बातचीत में यह बात कही थी, जिसकी पुष्टि उनके बेटे रश्मी ने की थी। कांत ने लेखक से 3 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में यह बात कही थी।
277 'मैं टेलीग्राफ लेन स्थित कृष्णकांत के घर उनसे मिलने गया था': यूनुस सलीम ने लेखक को बताया, 9
जुलाई 2003, नई दिल्ली।
277 'मैंने वार्ता के लिए आपका और अली मियां का नाम सुझाया है': वही।
277 'आप शंकराचार्य से मुलाकात तय कर लीजिए और हम साथ में उनके पास जाएंगे': वही।
277 'यदि हम कांची के शंकराचार्य से मिलने मद्रास जाते, तो अध्यक्ष
'मैंने सोचा है': कृष्णकांत ने लेखक से 25 दिसंबर 1995 को हैदराबाद में गोपनीय बातचीत में कहा।
278 'यह इस सदी की सबसे बड़ी घटना होगी': वही।
278 कृष्णकांत ने कांची के शंकराचार्य को 'कम से कम एक दर्जन बार' देखा: वही।
278 'जब मोहम्मद यूनुस सलीम और कृष्णकांत मुझसे मिले और मुझे बताया कि
शंकरचार्यों के बारे में: यूनुस सलीम ने लेखक को अली मियां द्वारा लिखित का अनुवाद करते हुए 9 जुलाई 2003 को नई दिल्ली में लिखा।
278 'मुझे याद है कि वह सीमेंट के चबूतरे पर सिकुड़कर लेटा हुआ था': कृष्णकांत ने

लेखक से कहा, 25
दिसंबर 1995, हैदराबाद।
278 ‘उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सहमति में सिर हिलाया’: यूनुस सलीम ने लेखक से 9 जुलाई को कहा
2003, नई दिल्ली।
278 सफलता के कगार पर पहुँचकर वार्ता को बाधित कर दिया गया: यूनुस सलीम और कृष्णकांत
अलग-अलग बातचीत के दौरान लेखक को।
279 ‘आप वीएचपी को मेरे भरोसे छोड़ दें’: वही।
279 कृष्णकांत को पता था कि भाजपा को किसी भी समाधान को मंजूरी देनी होगी। लेखक, 25 दिसंबर 1995, हैदराबाद।
279 ‘प्रधानमंत्री आवास पर आकर मुझसे मिलें’: चंद्र शेखर, 12 अगस्त 2003, नई दिल्ली।
279 चंद्र शेखर ने वीएचपी के साथ सीधे बातचीत करने का फैसला किया: वही।
279 उनके तिरसठ सदस्यीय जनता दल (एस) को राजीव गांधी की कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था।
पार्टी: मुकर्जी, द डिसरप्टर, पृ. 418.
279 ‘मैं एक भी ईंट गिरने नहीं दूंगा,’ चंद्र शेखर ने उनसे कहा: वही।
280 ‘क्या आप तैयार हैं?’: वही।
280 Bhairon Singh Shekhawat, Sharad Pawar, and, later, Mulayam Singh Yadav to find ‘a way
बाहर’: वही।
280 1 और 4 दिसंबर 1990 को वीएचपी और बाबरी मस्जिद के बीच बैठकें आयोजित की गईं।
नेता: राव, अयोध्या, पृ. 82.
280 ‘तांत्रिक-देवता’ चंद्रस्वामी ने ‘साधुओं को एकजुट करने’ में भी मदद की: चंद्र शेखर
लेखक को, 12 अगस्त 2003, नई दिल्ली।
280 He ‘reached out to 200 sadhus,’ including Nritya Gopal

Das: Ibid.
280 ‘Kaun mahatma hai aur kaun duratma hai, kaam zaroori hai’: Ibid.
280 Chandra Shekar told Om Prakash Chautala to keep the sadhus ‘happy’: Ibid.
280 ‘दोनों पक्षों में समाधान खोजने की तत्परता थी’: वही।
280 ‘तब हम भागीरथी और सरयू के तट पर एक भव्य मंदिर बना सकते थे’: वही।
281 ने बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति (बीएमएमसीसी) का नेतृत्व किया: फरवरी 1986 में,
सैयद शहाबुद्दीन ने बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति का गठन किया था. दिसंबर 1988 तक, यह दो भागों में विभाजित हो गया था- बीएमएमसीसी, और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद कॉन्फ्रेंस (एआईबीएमसी), जो शहाबुद्दीन का विरोधी समूह था। (पंकज पचौरी, 'बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिति नेतृत्व के लिए जॉकी', इंडिया टुडे, 31 दिसंबर 1988)।
281 ‘लेकिन मैं आपको न्यायाधीश और मध्यस्थ के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा’: सैयद शहाबुद्दीन ने लेखक से कहा, 20 जुलाई
2005, नई दिल्ली।
281 ‘वह इस कार्रवाई पर अपना राजनीतिक भविष्य बनाना चाहता था’: वही।
281 ‘काशी और मथुरा पर अपने दावे को छोड़ने के लिए सहमत होना—यदि कोई समझौता हुआ हो
अयोध्या’: चंद्र शेखर ने लेखक को 12 अगस्त 2003 को नई दिल्ली में लिखा।
282 ‘विष्णु हरि डालमिया…ने मुझे बताया कि चंद्र शेखर ने उनसे त्याग करने की विनती की थी।
Varanasi and Mathura’: Romesh Bhandari to author, 22 October 2003, New Delhi.
282 हालाँकि, दोनों पक्ष अदालत के फैसले का पालन करने पर सहमत हुए: चंद्र शेखर ने लेखक को लिखा, 12
अगस्त 2003, नई दिल्ली।
282 ‘यह अनिवार्य होना चाहिए, न कि सिफारिशी’: वही।

282 ‘युवराज इसमें शामिल थे, उनकी मदद ली गई थी, और उनके माध्यम से धार्मिक प्रमुखों को भी शामिल किया गया था।
‘बातचीत की गई’: तीन सदस्यीय वार्ताकार समिति के एक सदस्य ने लेखक को 28 फरवरी 2003 को लिखा, वही।
282 ‘हमें (भारत में) शीर्ष मुस्लिम नेताओं द्वारा जानकारी दी गई थी कि यह एक रास्ता हो सकता है, और
लड़ाई खत्म हो जाएगी’: वही।
282 विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने एआईबीएमएसी नेताओं को रात्रिभोज पर बुलाने का भी फैसला किया था: चंद्र शेखर को
लेखक, 12 अगस्त 2003, नई दिल्ली।
282 उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने यह 'नेक इरादे से' किया था: शरद पवार ने लेखक से कहा; शरद पवार, मेरी शर्तों पर:
जमीनी स्तर से लेकर सत्ता के गलियारों तक, नई दिल्ली: स्पीकिंग टाइगर बुक्स, 2015।
282 ‘राज्य की देखभाल कौन करेगा?’: शरद पवार के करीबी सूत्र ने लेखक को 28 फरवरी को बताया
2003, नई दिल्ली।
शरद पवार के अनुसार, बागी विधायकों को अंततः 210 विधायकों में से केवल 11 का ही समर्थन प्राप्त रह गया था।
लेखक को, 28 फरवरी 2003, नई दिल्ली; ऑन माई टर्म्स में भी प्रकाशित।
282 लेकिन दिल्ली के सत्ता हलकों में यह फुसफुसाहट बढ़ने लगी कि चंद्र शेखर ‘अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे’:
चंद्र शेखर द्वारा लेखक को, 12 अगस्त 2003, नई दिल्ली।
283 गुट को आशंका थी कि शरद पवार चंद्र शेखर के साथ हाथ मिला सकते हैं: वही।
283 लेकिन आखिरी क्षण में उनके पैर ठंडे पड़ गए: भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक को, नई दिल्ली।
283 ‘मैं यह नहीं कह सकता कि (समस्या का समाधान) हो पाता या नहीं’: चंद्र शेखर ने कहा

लेखक, 13 अगस्त 2003, नई दिल्ली।
283 'उन्होंने इस विषय पर मुझसे विस्तारपूर्वक चर्चा की': नरेश चंद्र ने लेखक को 31 मार्च 2017 को लिखा।
नई दिल्ली।
283 उन्होंने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक कार सेवकों को गिरफ्तार किया था: पीटीआई, 'मुलायम सिंह यादव ने अपने कृत्य को उचित ठहराया'
1990 में कार सेवकों पर पुलिस फायरिंग', टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 नवंबर 2017।
284 लेकिन 30 अक्टूबर को, उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के कर्मियों ने पहरा देते हुए
इस संरचना के कारण सुरक्षा में सेंध लग गई: सुमन चट्टोपाध्याय, 'बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का विस्तृत विवरण', डेलीओ, 15 फरवरी 2018।
284 इसे आईआईबी द्वारा फिल्माया गया था और फिल्म को दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय को भेजा गया था: नरेश
चंद्र द्वारा लेखक को, 31 मार्च 2017, नई दिल्ली।
284 'मैं स्थिति पर घंटे दर घंटे नजर रख रहा था': वही।
284 'मैंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यूपी पीएसी को कार्रवाई करनी चाहिए': वही।
284 'मृतकों की आधिकारिक संख्या बारह थी लेकिन वास्तव में अठारह लोग मारे गए थे': वही।
284 बाद में मुलायम सिंह यादव ने खुलासा किया कि अट्ठाईस लोगों की मौत हुई थी: पीटीआई, 'मुलायम'
सिंह यादव ने 1990 में कार सेवकों पर पुलिस फायरिंग को उचित ठहराया।
284 भीड़ जमा होने (और बेकाबू होने) के बाद, आपको गोली चलानी होगी: नरेश चंद्र को
लेखक, 31 मार्च 2017, नई दिल्ली।
285 उसने घोषणा की थी कि उस दिन एक भी परिंदा (पक्षी) उस संरचना में प्रवेश नहीं कर पाएगा:
Singh, Ayodhya, p. 220.
नरेश चंद्र ने लेखक को बताया, नई दिल्ली: 285 ने उन्हें 'मुल्ला मुलायम' की उपाधि

दिलाई।
285 ‘वह ऐसा होने नहीं देता’: वही।
नरेश के अनुसार, राज्यों की सीमाओं को सील करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में बल तैनात करना असंभव था।
चंद्र द्वारा लेखक को, 31 मार्च 2017, नई दिल्ली।
285 बहुत बाद में, 2007 में, राहुल गांधी ने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद नहीं गिरती:
टीएनएन, ‘अगर गांधी जी प्रधानमंत्री होते तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती: राहुल गांधी’, टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 मार्च 2007।
285 ‘Agar main hota, toh 2,000 log bhi mar jaate na, I would have protected the (Babri Masjid)
संरचना’: चंद्र शेखर ने लेखक से कहा।
285 ‘कोई पत्रकार मित्र नहीं हो सकता, यद्यपि मित्र पत्रकार हो सकता है’: पी. वी. नरसिम्हा राव
कृष्णकांत ने लेखक को यह बात बताई।
286 प्रधानमंत्री राव ने संसद में कहा कि वह 'स्थिति को शांत करना' और 'किसी भी अप्रिय स्थिति से बचना' चाहते हैं।
टकराव’, ‘समझौता लाना’: राव, अयोध्या, पृ. 199.
286 पीवी को ‘अन्य राजनीतिक दलों के साथ कठिन बातचीत का कार्य सौंपना चाहिए था’:
मुखर्जी, द टर्बुलेंट इयर्स, पृ. 154.
287 ‘प्रधानमंत्री द्वारा की गई इसी लामबंदी ने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) में दहशत पैदा कर दी’: अज्ञात सूत्र
जिन्होंने पी.वी. नरसिम्हा राव के साथ मिलकर इस पुस्तक को लिखा था, 25 सितंबर 2019, नई दिल्ली।
287 हालाँकि राव को मंदिर निर्माण की अपनी योजना का खुलासा अपने भरोसेमंद सहयोगी पी.वी.आर.के. को करना था।
Prasad: Bhuvnesh Chaturvedi to author.
287 ‘पीवी की हिंदू संत और मुस्लिम फकीरों के साथ बातचीत का मकसद भाजपा

की उन पर पकड़ को खत्म करना था’:
भुवनेश चतुर्वेदी द्वारा लेखक को, 26 अप्रैल 2000, नई दिल्ली।
287 ‘पीवी ने एक बार के.के. बिड़ला से (बाद वाले द्वारा) 2 करोड़ रुपये दान करने के बारे में बात की थी ताकि इसका निर्माण किया जा सके।
मंदिर’: वही।
287 कुछ लोगों को आशंका थी कि नरसिम्हा राव ‘किसी प्रकार का हिंदू संघ’ बनाना चाहते थे।
चर्चों के बारे में: पी. वी. नरसिम्हा राव के साथ मिलकर काम करने वाले एक अज्ञात सूत्र ने 25 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में यह जानकारी दी।
287 ‘जिस दिन कार सेवा की घोषणा हुई, पी.वी. को यह आभास हुआ कि “दाल में कुछ काला है”’: आर.के.
खांडेकर से लेखक को, 23 दिसंबर 2020, टेलीफोन पर बातचीत, नागपुर।
288 ‘तभी राव साहब को यह महसूस होने लगा कि बाबरी मस्जिद को बचाना शायद संभव न हो’:
वही।
288 ‘अर्जुन सिंह मुझसे कुशक रोड स्थित 6 नंबर पर मिलने आए थे’: एम. एल. फोतेदार ने लेखक को 1 जनवरी को लिखा
2005, गुड़गांव।
288 ‘आप मेरा इस्तीफा अभी भी ले सकते हैं और बाद में भेज सकते हैं’: वही।
288 ‘Ab toh yudh hone wala hai’: Kishore Kunal to author, Patna.
288 ‘इस बार मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है’: वही।
289 ‘Jo VHP ke saath log jude hue hain, unko kuch udhar se tod karke idhar mila dijiye’: Ibid.
289 ‘Yeh kaam maine zindagi bhar nahi kiya hai’: Ibid.
289 ‘मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त नहीं करने जा रहा हूँ। कल्याण सिंह की सरकार विधिवत निर्वाचित सरकार है’:
वही।
289 ‘आप अयोध्या, फैजाबाद और नंदीग्राम को केंद्र शासित प्रदेश बना दें’: वही।

289 ‘यह एक अच्छा सुझाव है,’ राव ने कहा: वही।
290 ‘मैंने उनसे कहा, महोदय, कृपया इसे प्रसारित करवाइए, यह स्वीकार किया जाएगा’: वही।
290 उनकी योजना में विवादित क्षेत्र के आसपास 2.77 एकड़ भूखंड पर कार सेवा की सिफारिश की गई थी: के. आर.
मलकानि, अयोध्या की राजनीति और हिंदू-मुस्लिम संबंध, अयोध्या: हर-आनंद प्रकाशन, 1993, पृ. 34.
290 ने सुझाव दिया कि वह अयोध्या में इस्तेमाल के लिए रबर की गोलियां हासिल करे: वेद प्रताप वैदिक ने लेखक को बताया, 14
सितंबर 2018, गुरुग्राम।
290 ‘आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं?’: वही।
290 ‘प्रधानमंत्री ने आखिरकार उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बलों को भेजने की मंजूरी दे दी’: माधव गोडबोले
लेखक।
291 अप्रत्याशित रूप से नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री ने कड़ा विरोध जताया: कल्याण सिंह लेखक को।
291 ‘फैसला चाहे जो भी हो, इससे मदद मिलेगी’: एल. के. आडवाणी ने कमल नाथ से और लेखक से कहा।
291 कल्याण सिंह ने न्यास परिवार को आसपास की 42 एकड़ भूमि का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में मदद की थी।
संरचना: राव, अयोध्या, पृ. 91.
292 ‘प्रस्ताव को स्वीकार्य बताने में मुझे एक मिनट भी संकोच नहीं हुआ’: आडवाणी मेरा देश, मेरा जीवन, पृष्ठ 394।
292 ‘ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है’: आडवाणी, मेरा देश, मेरा जीवन, पृ. 394.
292 पीवी ने अपने मंत्रियों को तिरस्कारपूर्वक 'हर-फन-मौला' कहा: मलकानि, राजनीति
Ayodhya, p. 32.
292 ‘अडवानी ने जो कहा वह सही था’: कमल नाथ ने लेखक से कहा, 3 अगस्त 2021, नई दिल्ली।

292 ‘अदालत से फैसला जल्द सुनाने का अनुरोध करने से प्रधानमंत्री का इनकार भी एक कारण था
वार्ता के विफल होने के कारण’: किशोर कुणाल ने लेखक को 25 अप्रैल 2017 को पटना में लिखा।
292 ‘हम एक अलग रास्ता अपनाते’: आडवाणी, माई कंट्री, माई लाइफ, पृ. 398.
292 इसने 4 नवंबर 1992 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था: वही, पृष्ठ 396।
292 इससे पहले प्रधानमंत्री ने (सिंघल को) इस बात का ‘निजी तौर पर संकेत दिया था’: मलकानि, द पॉलिटिक्स ऑफ
Ayodhya, p. 24.
292 ‘प्रधानमंत्री कार्यालय, अयोध्या प्रकोष्ठ या खुफिया ब्यूरो में प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी थी कि एक
टकराव (अब) अपरिहार्य था’: वही।
293 “‘देखते हैं”—असल में उसका मतलब “नहीं” है’: माधव गोडबोले ने लेखक से कहा, 3 फरवरी
2019, पुणे।
293 गोडबोले ने दावा किया कि उनकी योजना को उनके बॉस, गृह मंत्री चव्हाण का समर्थन प्राप्त था: वही।
293 इससे सुरक्षा बलों को परिसर पर तुरंत कब्जा करने के लिए पर्याप्त 'पूर्वानुमान' मिल जाएगा:
माधव गोडबोले, अधूरी पारी: एक सिविल सेवक की यादें और विचार, हैदराबाद: ओरिएंट ब्लैकस्वान, 1996, पृ. 356.
293 उन्हें पता था कि विपक्ष अयोध्या के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेर लेगा: वही, पृष्ठ 364।
293 लेकिन राव को यह योजना कुछ खास पसंद नहीं आई: पी.वी. नरसिम्हा राव ने करण थापर को 10 दिसंबर को लिखा।
1992, ‘बाबरी मस्जिद विध्वंस: 1992 से सबसे व्यापक वीडियो कवरेज’ (वीडियो क्रेडिट: आईविटनेस, जनवरी 1993); लिबरहान जांच आयोग की रिपोर्ट,
यह <www.mha.gov.in/about-us/commissions-committees/

liberhan-ayodhya> पर उपलब्ध है।
आयोग>; और एम. डी. नलपत, 'पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के साथ साक्षात्कार', रूट्स ऑफ पावर: एन इंडियन आई ऑन द वर्ल्ड, 28 जून 2017, उपलब्ध है
<blog.mdnalapat.com/interview-with-former-prime-minister-p-v-narasimha-rao-2f6997d2f03a>.
293 'मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि... राज्यपाल की रिपोर्ट को छोड़ा जा सकता है': माधव
गोडबोले ने लेखक को 3 फरवरी 2019 को पुणे में पत्र लिखा।
293 चंद्र शेखर ने मुझे बताया था कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है: चंद्र शेखर ने लेखक को बताया।
15 फरवरी 2000, नई दिल्ली।
293 'वह पत्र अभी भी मेरी अलमारी में कहीं रखा है': नरेश चंद्र ने लेखक को 31 मार्च को लिखा
2017, नई दिल्ली।
294 उनके बारे में कहा जाता था कि वे 'पीवी की अनुमति के बिना कुछ नहीं करते थे': अनाम उच्च अधिकारी
लेखक को विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराए गए थे। वे उस समय आंध्र प्रदेश में थे और उन्हें घटना की जानकारी थी।
294 'गृह मंत्री के साथ अपनी चर्चा के दौरान, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजने पर सहमति जताई थी': गोडबोले,
अधूरी पारी।
294 उन्होंने यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति शासन विवादित संरचना को खतरे में डाल देगा:
राव, अयोध्या, पृ. 150.
294 'सत्य नारायण रेड्डी बिना किसी अक्षर, अल्पविराम या पूर्णविराम का प्रयोग किए'
राव से पूछना: लेखक को अनाम उच्च स्तरीय सूत्रों से जानकारी मिली।

294 राष्ट्रपति ने 6 दिसंबर 1992 को फोतेदार से मुलाकात के दौरान उनसे यह बात कही थी: एम. एल. फोतेदार
लेखक को, 1 जनवरी 2005, गुड़गांव।
294 राव ने राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाई और अक्टूबर 1992 में जनार्दन रेड्डी की जगह ली: कृष्णकांत को
लेखक, 25 दिसंबर 1995, हैदराबाद।
295 'कल्याण सिंह ने अनुच्छेद 138(2) के तहत कार्रवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया है': गोडबोले, अनफिनिश्ड
इनिंग्स, पृ. 372.
295 'राष्ट्रपति शासन अब अपरिहार्य हो गया है': वही; एम. एल. फोतेदार ने लेखक को 1 जनवरी को लिखा
2005, गुड़गांव। बैठक में उपस्थित लोगों ने फोतेदार को यह बात बताई थी।
295 उन्होंने इसकी पैंतालीस प्रतियां तैयार कीं: माधव गोडबोले ने लेखक को, 3 फरवरी 2019 को लिखा।
295 राव पीछे हट गए—और ऐसा करने के लिए 'प्रक्रिया' पर भरोसा किया: वही।
295 कानूनी प्रतिबंधों से कांग्रेस में उनके सहयोगियों को यह लाभ मिलता: नरेश चंद्र, राव के विचारों को प्रतिबिंबित करते हुए, लेखक को, 31 मार्च 2017, नई दिल्ली।
296 'रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार, कम से कम 50 से 100 लोग मारे गए होंगे अयोध्या': वही।
296 यह एक अलग बात है कि मस्जिद की सुरक्षा में विफलता के कारण लगभग 1,000 लोग मारे गए।
मारे गए: 'बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूरे भारत में खूनी मंजर', इंडिया टुडे, 5 दिसंबर 2011।
296 'मान लीजिए पी. वी. नरसिम्हा राव ने मुझ जैसे मुंशी (प्रबंधकों) को पूरी छूट दे दी होती':
नरेश चंद्र द्वारा लेखक को, 31 मार्च 2017, नई दिल्ली।
296 पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी ने एक बार सीबीआई को 'विभाग' कहा था।
'गंदी चालों का विभाग': पीटीआई, '"सीबीआई को अक्सर गंदी चालों का विभाग कहा

जाता है": बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी', एनडीटीवी, 15 अप्रैल 2014।

296 'क्योंकि यह एक फिसलन भरी ढलान है': नरेश चंद्र ने लेखक से कहा, 31 मार्च 2017, नई दिल्ली।

296 'उसने इसे किसी के साथ साझा नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे साथ भी नहीं': वही।

297 रुंधे हुए स्वर में उन्होंने अयोध्या में बढ़ते तनाव के प्रति अपनी बेबसी व्यक्त की: मणि शंकर अय्यर, '"भारत एक हिंदू राष्ट्र है," पी.वी. नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा था', एनडीटीवी, 7 जुलाई 2016।

297 लेकिन केंद्र के वकील अदालत में पेश नहीं हुए: आडवाणी, माई कंट्री, माई लाइफ, पृ.
397.

297 सिंह वापस आए और प्रधानमंत्री को सूचित किया कि स्थिति 'नियंत्रण में' है: भुवनेश
चतुर्वेदी द्वारा लेखक को, 27 अक्टूबर 1999, नई दिल्ली।

297 कल्याण सिंह ने उनसे कहा कि इससे वहां जमा हुए कार सेवकों में आक्रोश फैल जाएगा: अर्जुन सिंह के साथ
अशोक चोपड़ा, समय की रेत घड़ी में एक रेत का दाना: एक आत्मकथा, नई दिल्ली: हे हाउस, 2012, पृ. 273.

297 गोडबोले, एक सीधे-सादे सरकारी कर्मचारी, 'समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है': नरेश
चंद्र द्वारा लेखक को, 31 मार्च 2017, नई दिल्ली।

298 'यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सब कुछ नियंत्रण में है': वही।

298 'परसों क्या होगा?': किशोर कुणाल ने लेखक से 25 अप्रैल 2017 को पटना में पूछा।

298 'Jaisa Supreme Court ka direction hoga, waisa hi karna hai': Ibid.

298 सर्वोच्च न्यायालय ने केवल मेरठ के एक जिला न्यायाधीश को नियुक्त किया: राव, अयोध्या।

298 ‘राज्य ने अपना अधिकार त्याग दिया है’: किशोर कुणाल ने लेखक को, 25 अप्रैल 2017, पटना।
298 ‘वहाँ इतनी बड़ी सेना तैनात है’: वही।
299 ‘Hum log usko gira karke, leepa-pothi karke, sab baraabar kar denge zameen ko’: Ibid.
299 इसे बाद में 'काला रविवार' के रूप में याद किया जाएगा: पीटीआई, 'बाबरी मस्जिद की बरसी:
“विजय दिवस” बनाम “दुःख दिवस”, डेक्कन हेराल्ड, 6 दिसंबर 2015।
299 ‘नरसिम्हा राव मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं,’ वे दावा करते थे: वेद प्रताप वैदिक ने लेखक को बताया, 14
सितंबर 2018, गुरुग्राम।
प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगियों में से 299 वरिष्ठ अधिकारियों ने राव के साथ उनकी निकटता की पुष्टि की: नरेश चंद्र
लेखक को।
299 उस सुबह, कार्यालय जाने से पहले, वैदिक ने राव को फोन किया: वेद प्रताप वैदिक लेखक को।
14 सितंबर 2018, गुरुग्राम।
299 राजेंद्र सिंह: उस समय सिंह दूसरे नंबर पर थे, लेकिन आरएसएस के वास्तविक प्रमुख थे।
सरसंघचालक बालासाहब देवरस की तबीयत खराब बनी हुई है.
299 ‘पीटीआई ने इसे हमसे लिया’: वही।
299 ‘मेरा फ़ोन तुम्हारा है’: वही।
300 ‘कार सेवा केवल प्रतीकात्मक होगी, जैसा कि हमने तय किया था’: शर्मा, युद्ध में अयोध्या, पृ.
58.
300 कटियार को फोन करने के बाद ही प्रधानमंत्री ने खुफिया ब्यूरो के प्रमुख वी. से बात की।
जी. वैद्य: आर. के. खांडेकर से लेखक।
300 ‘कार सेवा की तैयारियां चल रही हैं’: वी. जी. वैद्य ने लेखक को बताया।

300 प्रधानमंत्री ने फिर अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या का पालन किया: सीतापति, आधा शेर, पृ. 225.
300 ‘अर्जुन सिंह गुस्से में हैं,’ शर्मा ने उनसे कहा। ‘आपके वफादार उन पर हमला कर रहे हैं’: एन. के.
शर्मा से लेखक को।
सीतापति ने कहा कि 'मेरी पार्टी के पुराने नेता कंप्यूटर आयात करने की उनकी इच्छा को नहीं समझेंगे'।
हाफ लायन, पृ. 67.
300 रविवार होने के कारण प्रधानमंत्री का कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था: आर. के. खांडेकर लेखक को, 6
सितंबर 2019, टेलीफोन पर हुई बातचीत।
300 ‘उनके मन में केवल एक ही बात थी और वह थी बाबरी मस्जिद’: आर. के. खांडेकर
लेखक, 2020.
300 ‘क्या हो रहा है?’: एस. राजगोपाल ने लेखक से 10 मार्च 2019 को मुंबई में पूछा।
300 ‘मैं जाने ही वाला था और उससे मिलने जा रहा था लेकिन फिर मैंने ऑफिस जाने का फैसला किया’: वही।
301 नरेश चंद्र ने लेखक को बताया कि अयोध्या प्रकोष्ठ से 'गृह सचिव को मार्गदर्शन देने' की अपेक्षा थी।
मार्च 2017, नई दिल्ली।
301 माधव गोडबोले 'एक ईमानदार अधिकारी थे, और सर्वश्रेष्ठ अधिकारी थे', लेकिन उन्हें ढूंढ लिया गया।
‘राय रखने वाला और हठी’: वही।
301 ‘Pehla dome gir gaya hai’: V. G. Vaidik to author.
301 बाबरी मस्जिद: इस मस्जिद में एक केंद्रीय भाग था—यहीं पर राम लल्ला की मूर्ति स्थापित थी।
1949 में स्थापित इस मस्जिद के ऊपर तीन गुंबद बनाए गए थे। बाबरी मस्जिद परिसर के भीतर, लेकिन भीतरी आंगन से एक ऊंची पत्थर की दीवार द्वारा अलग

किया गया, दक्षिण-पूर्वी कोने में रामाचबूतरा था, जो $17 \times 21 \times 6$ फीट का एक ऊंचा चबूतरा था। यह मस्जिद के प्रवेश द्वार का द्वार था, जिसे राजीव गांधी ने 1986 में खुलवाया था। उत्तर की ओर सिंह द्वार के लिए कंक्रीट का ऊंचा चबूतरा था, जिसका निर्माण जुलाई 1992 में कार सेवा के दौरान राम मंदिर के प्रस्तावित स्थल के रूप में किया गया था।

301 The kar sevaks had washed the Ram Chabutra that morning: Business Standard, 'Babri

मस्जिद विध्वंस: 1992 से सबसे व्यापक वीडियो कवरेज (वीडियो क्रेडिट:

प्रत्यक्षदर्शी, जनवरी 1993), यूट्यूब, <www.youtube.com/watch?

v=k-> पर उपलब्ध है

bhAFsnv2s>, मई 2022 में एक्सेस किया गया।

दोपहर 12:20 बजे तक, भीड़ के लगभग अस्सी सदस्य गुंबदों के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए थे:

वही।

301 'फिर फावड़ों, लोहे की छड़ों और कुल्हाड़ियों से उन्मादी विध्वंस शुरू हुआ': राव, अयोध्या, पृ.

154.

301 'जैसे-जैसे कार सेवकों ने संरचना को नष्ट किया': राव, अयोध्या, पृ. 157.

301 शाम 4.55 बजे तक सब कुछ खत्म हो चुका था: बिजनेस स्टैंडर्ड, 'बाबरी मस्जिद विध्वंस: सबसे

1992 से व्यापक वीडियो कवरेज।

302 'मैं उन्हें तब से जानता था जब वे दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस में काम करने आते थे': प्रवीण

जैन ने लेखक को 2 अगस्त 2019 को लिखा।

302 'उन्होंने मुझे वीएचपी का (पहचान पत्र) कार्ड दिया...और एक पीला कार सेवक स्कार्फ': वही।

302 'उस समय किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि बाबरी मस्जिद को अगले दिन ध्वस्त किया जा सकता है':

वही।

302. 5 दिसंबर की रात को अयोध्या में एक गुप्त बैठक हुई: हेमंत शर्मा,
Ayodhya Ka Chashmadeed and Yuddha Mein Ayodhya, Delhi: Prabhat Prakashan, 1 January 2018. Sharma had covered the events for Jansatta and written in the paper Prabhat Prakashan.
302 विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की गुप्त योजना को सुबह तड़के तक अंतिम रूप दिया जा रहा था: शर्मा,
Yuddha Mein Ayodhya.
303 'मैं सबसे पहले उस मंच की ओर दौड़ा जहाँ से भाजपा नेताओं ने भीड़ को संबोधित किया था':
प्रवीण जैन से लेखक; प्रवीण जैन, 'मेरे कैमरे में मस्जिद विध्वंस के "सबूत" थे, लेकिन इसे इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया', द प्रिंट, 3 अक्टूबर 2020।
303 जब उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस मामलों में से एक में गवाही देनी पड़ी: दिसंबर में
1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गईं, एक प्रमुख भाजपा नेताओं के खिलाफ मस्जिद के विध्वंस से पहले कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में और दूसरी अज्ञात कार सेवकों के खिलाफ सोलहवीं शताब्दी की मस्जिद को ध्वस्त करने के आरोप में। देखें 'बाबरी विध्वंस मामला: दो एफआईआर की कहानी', टाइम्स ऑफ इंडिया, 30 सितंबर 2020।
303 'सूरज की धूप उतनी ही मधुर और गर्म थी जितनी हवा में हल्की ठंडक ताजगी भरी थी': मलकानि, राजनीति
अयोध्या और हिंदू-मुस्लिम संबंध, पृष्ठ 1।
303 The Kendriya Marg Darshak Mandal, the highest decision making body of the Vishwa
हिंदू परिषद: 'विश्व हिंदू परिषद के "मार्गदर्शक मंडल" ने मंदिर निर्माण के फैसले का समर्थन किया', ज़ी न्यूज़, 27 जनवरी 2002।
303 'अब हमें प्रेस नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी': मलकानि, अयोध्या की राजनीति और हिंदू-मुस्लिम
संबंध, पृष्ठ 1.

303 मलकानि ने दिन की घटनाओं को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया: वही।
303 ‘लेकिन… हम चाहते थे कि यह विधिवत कानूनी प्रक्रिया से गुजरे’: वही।
303 पार्टी ने जो कुछ हुआ उसके लिए ‘नैतिक जिम्मेदारी’ ली: राव, अयोध्या, पृ. 156.
304 ‘लगभग दस मिनट तक प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बिना हिले-डुले बैठे रहे’: पी. वी. नरसिम्हा
राव के मित्र, जो उस दिन उनके साथ थे, ने लेखक को अप्रैल 2019 में यह जानकारी दी।
304 अगले दो घंटों तक यही काम करता रहा: राव के दोस्त, जो उस सुबह उनके साथ थे, ने लेखक को बताया, 1
अक्टूबर 2022, नई दिल्ली।
304 उन्होंने केवल गृह मंत्री एस. बी. चव्हाण से बात की: माधव गोडबोले ने लेखक को 3 फरवरी को लिखा पत्र
2019, पुणे। गोडबोले ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें बताया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की थी।
305 उन्हें निर्देश मिले थे कि प्रधानमंत्री को 'परेशान नहीं किया जाना चाहिए': सिंह चोपड़ा के साथ, ए ग्रेन ऑफ
सैंड इन द ऑवरग्लास ऑफ टाइम: एन ऑटोबायोग्राफी, पृ. 277; पी. आर. कुमारमंगलम लेखक को।
305 संकट के चरम पर राव से संपर्क न हो पाने के कारण यह अफवाह फैल गई: 'क्या नरसिम्हा राव थे?'
बाबरी मस्जिद के लिए कौन जिम्मेदार है?’, इंडिया लीगल, 14 जुलाई 2016।
305 ‘Apne buddhe premi se baat hui kya?’: Ved Pratap Vaidik to author, 14 September 2018,
गुडगाँव।
305 ‘Kya chal raha hai?’: Ibid.
305 ‘मैंने दोपहर 1.40 बजे नरसिम्हा राव से बात की’: एम. एल. फोतेदार ने लेखक को, 1 जनवरी 2005, गुड़गांव।
305 ‘कांग्रेस समाप्त हो जाएगी’: वही।

305 ‘क्या हमें कैबिनेट की बैठक बुलानी चाहिए?’: वही।
305 लेकिन, अपने अन्य सहयोगियों की तरह, उन्हें नॉर्थ ब्लॉक के प्रति बेचैनी महसूस हुई: माधव
गोडबोले, अनफिनिश्ड इनिंग्स: रिकलेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ ए सिविल सर्वेंट, हैदराबाद: ओरिएंट ब्लैकस्वान, 1996, पृ. 382.
305 ‘हम नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय से स्थिति पर नजर रख रहे थे’: माधव गोडबोले ने कहा
लेखक, 3 फरवरी 2019, पुणे।
306 केंद्र सरकार ने लगभग '20,000' पुरुषों को भेजा था: राव, अयोध्या, पृ. 174.
306 वे पास के फैजाबाद में तैनात थे, राज्य सरकार की सहायता के लिए तैयार थे: सी. पाल सिंह,
'बाबरी मस्जिद विध्वंस - प्रवर्तन एजेंसियों की अप्रभावीता - संवैधानिक सीमाएं', लॉ स्ट्रीट जर्नल, 26 जून 2016।
306 वे अनेक प्रकार के ‘नरम’ हथियारों से लैस थे: डब्लू. पी. एस. सिद्धू और दिलीप अवस्थी,
‘बाबरी मस्जिद विध्वंस: जब कार सेवकों ने कानून तोड़ा तो कानून प्रवर्तक मूक दर्शक बने रहे’, इंडिया टुडे, 31 दिसंबर 1992।
306 ‘समय बर्बाद मत करो,’ उन्होंने बार-बार कहा: माधव गोडबोले ने पुणे के लेखक से कहा।
306 सुबह 11 बजे तक ‘सब कुछ ठीक लग रहा था’: वी. जी. वैद्य ने लेखक से कहा।
306 ‘कार सेवकों का एक समूह मस्जिद में घुस गया है और गुंबद के ऊपर चढ़ गया है’: वी. जी. वैद्य,
मार्च 2019, पुणे।
306 ‘प्रधानमंत्री के पास इतने सारे राजनीतिक स्रोत थे, और उन्हें तुरंत पता चल गया होगा’: वही।
306 वैद्य ने गृह मंत्री एस. बी. चव्हाण को भी सूचित किया था: माधव गोडबोले लेखक को।

306 ‘हे भगवान!’ राजगोपाल ने हैरानी से कहा। ‘ऐसा हो ही नहीं सकता’: एस. राजगोपाल ने लेखक से कहा, 10
मार्च 2019, मुंबई।
306 ‘Yeh tho nahin ho sakta’: Madhav Godbole to author.
306 ‘मैंने नहीं सोचा था कि वे मस्जिद के शीर्ष तक जाने की हद तक जाएंगे’: वही।
306 उनका यह भी मानना था कि आरएसएस और वीएचपी इस ढांचे को नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें
नरेश चंद्र ने लेखक को और माधव गोडबोले ने लेखक को बताया कि इसका उपयोग मंदिर के रूप में किया जाता रहा है।
307 कल्याण सिंह ने दस दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय को एक गंभीर आश्वासन दिया था:
मनोज मित्त, ‘जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी राष्ट्र को निराश किया’, द वायर, 6 दिसंबर 2017। बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पहले, कल्याण सिंह सरकार ने 27 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दिया था, जिसमें मस्जिद की ‘सुरक्षा और संरक्षण’ का वादा किया गया था और यह दावा किया गया था कि ‘कानून व्यवस्था’ और ‘सांप्रदायिक सद्भाव’ बनाए रखने में सरकार का ‘प्रशंसनीय’ रिकॉर्ड रहा है। हलफनामे में भाजपा सांसद स्वामी चिन्मयानंद के एक पत्र का भी हवाला दिया गया था, जो 6 दिसंबर को प्रस्तावित कार सेवा के आयोजकों में से एक थे। पत्र में कहा गया था कि कार सेवक विवादित स्थल पर किसी भी निर्माण के खिलाफ उच्च न्यायालय के पहले दिए गए आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। कल्याण सिंह सरकार के हलफनामे के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर को कुछ अनुष्ठानों के साथ एक ‘प्रतीकात्मक’ कार सेवा आयोजित करने की अनुमति दी थी।
307 ‘हमें मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी: माधव गोडबोले ने लेखक से कहा, 3 फरवरी 2019’
पुणे।
307 दोपहर लगभग 1 बजे तक, भारतीय सरकार के पांच शीर्ष अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक में थे: वही।
307 ‘हमें लगा कि हमारे विकल्प बंद हो गए हैं’: वही।
307 ‘Aap Shankar Raoji (S. B. Chavan) se baat kar lo’: Ved

Pratap Vaidik to author, 14
सितंबर 2018, गुरुग्राम।
307 वह विवादास्पद धर्मगुरु पृथ्वीराज चव्हाण के आश्रम के लिए रवाना हो गया।
307 'चव्हाण वास्तव में एक नाममात्र के गृह मंत्री थे': आर. के. खांडेकर ने लेखक को 23 दिसंबर को लिखा
2020 में नागपुर से टेलीफोन पर दिए गए एक साक्षात्कार में।
307 'Please tell him bahut bada sankat paida ho gaya ahi': Ved Pratap Vaidik to author.
308 Chavan had also spoken to Kalyan Singh at 12.25 p.m.: Sharma, Yuddha Mein Ayodhya, p.
61.
308 Both had gone to jail in 1965 for taking part in a Bharat bandh: Ved Pratap Vaidik to author,
14 सितंबर 2018, गुरुग्राम।
308 'Doctor saab, Kalyan Singh meri jaan kha raha hai': Ibid.
308 'Mera phone hi nahi le rahein. Aap unse baat keejiye': Ibid.
308 'Ab itna galat kaam kar diya': Ibid.
308 'Mere saath bahut bada dhokha hua hai': Ibid.
308 'Rao saab, Raja ko kabhi nahin kehna chahiye ke mere saath dhokha hua hai': Ibid.
309 दोपहर लगभग 3 बजे, प्रधानमंत्री ने गृह सचिव माधव गोडबोले से मुलाकात की:
लेखक, 3 फरवरी 2019, पुणे।
309 इसके बाद राव ने नरेश चंद्र से अलग से मुलाकात की: नरेश चंद्र ने लेखक को 31 मार्च 2017 को लिखा।
नई दिल्ली।
309 'इसके बजाय, कल्याण सिंह ने लिखित में यह दर्ज कराया कि पुलिस कार पर गोली नहीं चलाएगी

sevaks': Prabhat Kumar to author, 18 October 2022, Panchgani.
309 'उन्हें जो कुछ भी बताया जा रहा था, उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी': माधव गोडबोले ने लेखक से कहा, 3 फरवरी 2019
पुणे।
309 'हमें उनका इस्तीफा स्वीकार करने से पहले राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए': वही।
309 मंत्रिमंडल की बैठक शाम 6 बजे होगी और सरकार को बर्खास्त करने पर विचार किया जाएगा:
गोडबोले, अनफिनिश्ड इनिंग्स, पृ. 384.
309 कैबिनेट सचिव राजगोपाल के कार्यालय को दोपहर में प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया: एस. राजगोपाल
लेखक को।
309 प्रधानमंत्री कार्यालय ने कैबिनेट सचिवालय को कैबिनेट बैठक तय करने का निर्देश दिया: वही।
310 फोतेदार को शाम करीब 5 बजे कैबिनेट बैठक के बारे में सूचना मिली: एम. एल. फोतेदार लेखक को।
310 'उन्हें वापस यहाँ लाने में हमें समय लगा... नरसिम्हा राव बैठक शुरू नहीं करना चाहते थे।
उनकी अनुपस्थिति': नरेश चंद्र ने लेखक से कहा।
310 नरेश चंद्र 7, रेस कोर्स रोड पर 'लगभग 4.30 बजे' पहुंचे: वही।
310 'लेकिन मुझे उससे खूब खरी-खोटी सुननी पड़ी': वही।
310 'वह बहुत गुस्से में था, मुझे (उसे देखकर) थोड़ा झटका लगा': वही।
310 'हर कोई (और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे) जानता था कि स्थिति हाथ से निकल सकती है
control': Ved Pratap Vaidik to author, Pune.
311 'जैसे ही मंत्रिमंडल राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देगा, हम कागजात तुरंत राष्ट्रपति के पास भेज देंगे'
'उनके हस्ताक्षर के लिए': नरेश चंद्र ने लेखक से कहा।

311 ‘मुझे अयोध्या पुलिस नियंत्रण कक्ष से फोन आया था’: कल्याण सिंह ने लेखक को बताया, 3
सितंबर 2018, लखनऊ।
311 ‘पुलिस को भीड़ पर गोली नहीं चलानी चाहिए’: वही।
311 कल्याण सिंह ने अनुमान लगाया कि उस दिन अयोध्या में 300,000 लोग एकत्रित हुए थे: वही।
311 ‘पुलिस से गोली न चलाने का अनुरोध करके मैंने हजारों राम भक्तों की जान बचाई, हालांकि मैं
ढांचा को बचाने में असमर्थ: वही।
311 कल्याण सिंह ने भी कहा कि उन्हें ‘निराशा’ हुई: वही।
311 यदि उनका इरादा ढांचा ध्वस्त करने का था तो उन्हें उसे चेतावनी देनी चाहिए थी: शर्मा, युद्ध
Mein Ayodhya.
311 हालाँकि वे मुख्यमंत्री थे, लेकिन यह विश्व हिंदू परिषद और विनय कटियार थे: वही।
1990 के दशक में 312 मंदिर आंदोलन: कल्याण सिंह ने मंदिर के आसपास 2.77 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी।
पदभार संभालने के तीन महीने बाद ही उन्होंने मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया। मई 1992 में, उन्होंने उस ज़मीन पर बनी इमारतों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया और ज़मीन को समतल करना शुरू कर दिया। इसके चलते उन्हें रोकने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गईं। उच्च न्यायालय ने निर्माण पर रोक लगा दी।
सरकार द्वारा अधिग्रहित 2.77 एकड़ भूमि पर किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और फैसला सुनाया कि वहां कोई भी स्थायी संरचना नहीं बनाई जानी चाहिए।
312 5 दिसंबर की शाम को, विध्वंस से एक दिन पहले, कल्याण सिंह को यह महसूस होने लगा था
बेचैन: कल्याण सिंह ने लेखक को 3 सितंबर 2018 को लखनऊ में लिखा।
312 ‘कृपया सुनिश्चित करें कि आज कार सेवा सुचारू रूप से चले’: वही।

312 ‘इतिहास में यह पहली बार था कि किसी ऐसी सरकार को उखाड़ फेंका गया जो अस्तित्व में ही नहीं थी।
प्रथम स्थान’: वही।
312 बैठक कक्ष का वातावरण ‘निराशाजनक’ था: गोडबोले, अनफिनिश्ड इनिंग्स, पृ. 384; एम. एल. फोतेदार लेखक को।
312 ‘यह मंत्रिमंडल (बैठक) किसलिए है?’: एम. एल. फोतेदार ने लेखक को 1 जनवरी 2005 को गुड़गांव में लिखा।
313 फोतेदार के अनुसार, सभी आश्चर्यचकित लग रहे थे: वही।
313 ‘प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव से पूछा’: फोतेदार, चिनार लीव्स।
313 ‘शंकर दयाल शर्मा सचमुच रो रहे थे’: एम. एल. फोतेदार ने लेखक को 1 जनवरी 2005 को लिखा।
गुडगाँव।
313 ‘यह एक बहुत ही कड़ा पत्र था (जिसमें) उन्होंने प्रधानमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था।
विध्वंस’: शाहिद सिद्दीकी ने लेखक से कहा, 2019।
313 ‘मैंने उनसे कहा कि वे रेडियो पर जाएं (और राष्ट्र को संबोधित करें)’: एम. एल. फोतेदार ने लेखक से कहा।
313 ‘श्रीमान प्रधानमंत्री, इस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और इस नाजायज बच्चे (
हजरत महल पार्क में सरकार द्वारा निर्मित: वही।
313 अन्य लोगों को याद है कि फोतेदार ने प्रधानमंत्री पर चिल्लाया था: सीतापति, आधा शेर, पृ. 248.
313 एक समय पर, फोतेदार ‘रोने लगे’: सिंह, समय की रेत घड़ी में रेत का एक दाना।
313 नाराज़ सी. के. जाफ़र शरीफ़ ने चेतावनी दी कि देश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी: सी.
के. जाफर शरीफ ने संसद, नई दिल्ली में लेखक को संबोधित करते हुए कहा; सिंह, समय की रेत घड़ी में रेत का एक कण।
313 दिन के दौरान उन्होंने राव और चव्हाण से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन

उन्हें बताया गया कि वे 'आराम कर रहे हैं':
शाहिद सिद्दीकी लेखक बनेंगे।
314 ‘Usse bhi zyada,’ Rao said. ‘Sab kuch gir gaya, sab kuch gir gaya. Leken mein banaoonga
doobara. Sab kuch banaoonga’: Ibid.
314 ‘Aap banwa deejeye’: Ibid.
314 सिद्दीकी 23 नवंबर को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक का जिक्र कर रहे थे।
1992: शाहिद सिद्दीकी से लेखक, 2019; माधव गोडबोले, 'खुफिया ब्यूरो विध्वंस षड्यंत्र के बारे में प्रधानमंत्री राव को सतर्क करके बाबरी मस्जिद को बचा सकता था', द प्रिंट, 8 सितंबर 2019; 'बासु और देशपांडे लिबरहान के सामने पेश हुए', मिली गजट।
314 ‘Hindu ki toh koi aukaat hi nahi hai iss desh mein, aapki party mein’: Shahid Siddiqui, 25
मार्च 2019, नई दिल्ली।
314 ‘(आज) वहां न तो मस्जिद है और न ही मंदिर। कृपया इस यथास्थिति को न बदलें’:
वही।
315 ‘सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इसका पुनर्निर्माण हो’: प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव का बयान
संसद में दिया गया वक्तव्य, 7 दिसंबर 1992, अनुलग्नक XII के रूप में उद्धृत, राव, अयोध्या, पृष्ठ 257।
315 फोतेदार राव की आलोचना में सबसे तीखे थे: सिंह, ए ग्रेन ऑफ सैंड, पृ. 278.
315 वे बाद में हमेशा ‘विधानसभा को बहाल’ कर सकते थे: एम. एल. फोतेदार लेखक को।
315 हर बार प्रधानमंत्री वही वादा करते थे कि वे किसी भी कीमत पर मस्जिद को बचाएंगे।
लागत’: वही।
315 ‘मैंने खुले टकराव में उतरना उचित नहीं समझा’: सिंह, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द

समय की रेत घड़ी, पृष्ठ 279।
315 ‘मैं उनसे इस्तीफा देने की गुहार लगाता रहा’: अनिल बाली ने लेखक से कहा, 7 मार्च 2018, नई दिल्ली।
316 ‘Hum aapko bhi dekh lenge’: Ved Pratap Vaidik to author, 14 September 2018, Gurgaon.
316 ‘Agar main raajneeti karne laga hota, toh main aapko Delhi nahi aane deta’: Ibid.
316 ‘उन्होंने इस सुझाव को तुरंत स्वीकार कर लिया,’ सिंह ने कहा: सिंह, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द
समय की रेत घड़ी, पृष्ठ 279।
317 गोडबोले ने सलाहकारों की एक छोटी सूची पहले ही तैयार कर ली थी: गोडबोले, अनफिनिश्ड इनिंग्स, पृ. 385–
86.
317 प्रधानमंत्री से बात करने के बाद, राजगोपाल ने अशोक चंद्र और बी. के. गोस्वामी को सलाहकार के रूप में चुना:
वही।
317 उस रात खराब मौसम के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा और अगले दिन जाना पड़ा, यह एक अलग ही मामला था।
दिन: वही, पृष्ठ 386।
317 ‘Rao sahib has high fever’: Ved Pratap Vaidik to author, 14 September 2018, Gurgaon.
317 राव ने पायलट को अपनी 'गुंबद' योजना पर आगे बढ़ने के लिए कहा। 'राजेश पायलट और मैंने इस पर जी-जान से काम किया':
शाहिद सिद्दीकी लेखक के लिए; एम. एल. फोतेदार लेखक के लिए।
318 ‘यह आदेश (ऐसा न करने का) ऊपर से आया है’: शाहिद सिद्दीकी ने लेखक से कहा, 25 मार्च 2019।
318 उन पर आपराधिक साजिश और उकसाने का आरोप लगाया गया था: टीएनएन, 'बाबरी विध्वंस मामला:
दो एफआईआर की कहानी।

318 आडवाणी, जिन्होंने 6 दिसंबर को "मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन" कहा था, लेकिन इसे "एक
हिंदू जागरण का दिन': सुधींद्र कुलकर्णी, 'दरअसल, आडवाणी ने भीड़ से बाबरी मस्जिद को गिराना बंद करने को कहा था', एनडीटीवी, 20 अप्रैल 2017।
318 न्यायाधिकरण ने महसूस किया कि सरकार एक व्यापक मामला तैयार करने में विफल रही है: वी.
वेंकटेशन, 'प्रतिबंध से परे', फ्रंटलाइन, 22 जनवरी 2000।
318 आयोग ने पाया कि विध्वंस 'पूर्व नियोजित' था और इसे 'सावधानीपूर्वक' अंजाम दिया गया था।
तैयारी': 'बाबरी मस्जिद विध्वंस | लिबरहान आयोग के प्रमुख निष्कर्ष', द हिंदू, 30 सितंबर 2020।
318 जिसमें 1,200 लोग मारे गए और 4,000 घायल हुए: बॉब ड्रोगिन, 'भारत ने 3 राज्यों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया'
'कट्टरपंथी', लॉस एंजिल्स टाइम्स, 16 दिसंबर 1992।
319 इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि विवादित संरचना के नीचे एक संरचना थी, जिसमें शामिल था
मंदिर की दीवारें और स्तंभ: वी. वेंकटेशन, 'खुदाई का आदेश', द हिंदू, 30 सितंबर 2010।
319 सर्वोच्च न्यायालय ने 9 अगस्त 2011 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी: विराग
गुप्ता (संपादक), अयोध्या का राम मंदिर न्यायालयों में: निर्णय और समीक्षा, तीसरा संस्करण, सीएएससी, 2019।
319 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी गई।
मंत्री नरेंद्र मोदी: एएनआई, 'अयोध्या: सीएम योगी ने राम मंदिर के "गर्भ गृह" की आधारशिला रखी, द प्रिंट, 1 जून 2022।
320 आलोचनाओं से घिरे एक फैसले में, अदालत ने अपने 2,000 पृष्ठों के फैसले में कहा: पीटीआई,
'बाबरी मामले में विशेष अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है:

कांग्रेस', लाइवमिंट, 30 सितंबर 2020।
320 'मुझे प्रधानमंत्री के आवास पर बुलाया गया था': 'महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में वापस आने के लिए तैयार नहीं था'
1993: पवार', आउटलुक, 30 दिसंबर 2021।
320 एक सप्ताह से भी कम समय बाद, 12 मार्च को, बारह बम धमाकों की एक श्रृंखला: '1993 के धमाके कैसे
'मुंबई को हमेशा के लिए बदल दिया', बीबीसी, 30 जुलाई 2015।
320 'मैं चाहता हूं कि आप कल सुबह 8 बजे से गृह सचिव का पदभार संभाल लें': एन. एन. वोहरा ने लेखक से कहा, 24
नवंबर 2021, नई दिल्ली।
320 'मैं चाहता हूं कि आप इस बात की जांच करें कि साढ़े तीन टन विस्फोटक सामग्री मेट्रो में कैसे पहुंची'
शहर': वही।
320 'लेकिन मैंने इसे पचासी दिनों में पूरा कर लिया': वही।
321 'यह इतना गहरा बैठा हुआ था कि यह आसानी से दूर नहीं होने वाला था': वही।
321 इसके बाद के महीनों में, सरकार ने 'तेरह बार' आश्वासन दिया: वही।
321 'मैंने एक हस्तलिखित नोट छोड़ा': वही।
321 'Narasimha Raoji jahaan Ram Lallaji virajman hai, waheen Mandir banaana chahte thae':
किशोर कुणाल लेखक बनेंगे।
322 'हम भाजपा से तो लड़ सकते हैं, लेकिन भगवान राम से कैसे लड़ें?': पी. वी. आर. के. प्रसाद, व्हील्स बिहाइंड
द वेल: पीएम, सीएम और उससे आगे, विजयवाड़ा: एमेस्को बुक्स, 2010।
322 'हमारा लक्ष्य दोनों को हासिल करना होना चाहिए, न तो अदालतों के माध्यम से और न ही राजनेताओं के माध्यम से': वही।
322 उन्होंने आश्चर्यचकित प्रसाद को 'प्रतिनिधि और गैर-राजनीतिक समिति' बनाने का काम सौंपा: वही, पृष्ठ।
169.
322 और प्रसाद के अनुसार, 'यही कहानी का अंत था': वही।

322 ‘जहां हम भाजपा का सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर सकते’: नरेश चंद्र ने लेखक को 31 मार्च 2017 को लिखा।
नई दिल्ली।
322 उन्होंने परमाणु परीक्षण करने पर विचार किया, लेकिन जब इसकी जानकारी लीक हुई तो उन्होंने इसे रद्द कर दिया।
अमेरिकियों के लिए: पीटीआई, 'अमेरिका ने 1995 में पोखरण में भारतीय परमाणु परीक्षण की तैयारी का पता लगाया था', टाइम्स ऑफ इंडिया, 23 फरवरी 2013।
322 हवाला घोटाले जिनमें उनकी अपनी पार्टी के कई सहयोगी शामिल थे: जफर आगा, जैन
हवाला मामला: सीबीआई की हर गतिविधि से अवगत होने के बावजूद नरसिम्हा राव टालमटोल करते रहे’, इंडिया टुडे, 29 फरवरी 1996; शेखर गुप्ता, ‘नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद कांड को लेकर खुद को धोखा महसूस कर रहे थे, उन्होंने आडवाणी को हवाला कांड में फंसाकर इसका बदला लिया’, द प्रिंट, 6 दिसंबर 2017।
राव के भाषण शुरू होते ही 323 लोग उनकी सभाओं से उठकर चले जाते थे: लेखक उनमें से एक सभा में मौजूद थे।
ऐसी ही एक बैठक अप्रैल 1996 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुई थी।
324 वी. पी. सिंह ने नवंबर 1992 के अंत में उन्हें यह सुझाव दिया था: सोम पाल को
लेखक, 12 सितंबर 2021, गुरुग्राम।
324 लेकिन राव ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने केवल सेना को 'सतर्क' किया था: राव, अयोध्या, पृ. 253.
324 ‘बाबरी मस्जिद के साथ-साथ वे मुझे भी ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे’: वही, पृष्ठ 181।
अमिताभ तिवारी ने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ 325 मामले दर्ज किए गए थे, और उन्होंने 5 विवादों के बारे में बताया।
'नरसिम्हा राव की राजनीतिक विरासत को धूमिल कर दिया', डेलीओ, 28 जून 2016।
325 उनकी हताश बेटी वाणी देवी ने कांग्रेस नेतृत्व को संदेश भेजकर मदद की गुहार लगाई:

शिवराज पाटिल लेखक को।
325 अहमद पटेल ने पानी का गिलास उठाया और उसे पीने के लिए कहा: वही।
325 ‘मुझे उस चीज़ के लिए क्यों दोषी ठहराया जाना चाहिए जो मैंने नहीं की है?’: सीतापति, आधा शेर, पृ. 300.
325 ‘क्या मैंने जरूरत से ज्यादा बोल दिया?’: वही।
325 फूलों से सजे जुलूस को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई: लेखक 24 अकबर के समय उपस्थित थे
रोड, नई दिल्ली, 24 दिसंबर 2004। रशीद किदवई का लेख 'पीवी नरसिम्हा राव: अपना सामान पैक करने से लेकर भारत के 'आकस्मिक' प्रधानमंत्री बनने तक', इंडिया टुडे, 28 जून 2021 भी देखें।

अध्याय 5: दहाड़ने वाले शांतिप्रिय प्रधानमंत्री: ए. बी. वाजपेयी

सामरिक परमाणु उपकरणों के परीक्षण को अधिकृत करता है
328 सरकार की संयुक्त खुफिया समिति: संयुक्त खुफिया समिति थी
खुफिया ब्यूरो, आरएडब्ल्यू और सभी सैन्य खुफिया जानकारी से प्राप्त खुफिया आंकड़ों का विश्लेषण करने का कार्य सौंपा गया था और इसका सचिवालय सरकार के कैबिनेट सचिवालय में स्थित था।
भारत; देखें irp.fas.org.
328 ‘1979 में, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ रहा है’: के.
लेखक के लिए सुब्रमण्यम, वसंत कुंज, नई दिल्ली, 21 नवंबर 2004।
328 ‘अन्य किसी भी सचिव को अंदर आने की अनुमति न दें’: वही।
328 वे विशेष रूप से आमंत्रित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे: वही।
328 इसका मतलब प्रधानमंत्री के परमाणु-विरोधी रुख और उनकी नीति के खिलाफ जाना होता।
इस्लामाबाद से संपर्क स्थापित करना: योगेश जोशी, 'अहंकार, पूर्वाग्रह और अतिज्ञान: भारत द्वारा पाकिस्तान के परमाणु तख्तापलट को कैसे नजरअंदाज किया गया इसका

एक ऐतिहासिक विश्लेषण', ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ओआरएफ इश्यू ब्रीफ नंबर 513, जनवरी 2022।

328 'यह था कि हमें अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए': के. सुब्रह्मण्यम ने लेखक वसंत कुंज को लिखा।

नई दिल्ली, 21 नवंबर 2004।

329 'क्या यह चरण सिंह था?': वही।

329 और, उन्हें यह भी पता था कि वाजपेयी की मूल पार्टी, भारतीय जनसंघ: 'भारत का परमाणु

'हथियार कार्यक्रम: हथियार विकास की ओर: 1960-1967', 30 मार्च 2001, उपलब्ध है

<nuclearweaponarchive.org/India/IndiaWDevelop.html>

329 'नहीं, यह वाजपेयी थे': के. सुब्रमण्यम लेखक से, वसंत कुंज, नई दिल्ली, 21 नवंबर

2004.

329 'मोरारजी और वाजपेयी आगे बढ़ने के विरोध में थे': के. सुब्रमण्यम लेखक से, नया

दिल्ली, 13 फरवरी 2005। उन्होंने यह बात अन्य पत्रकारों को भी बताई। देखें शिवानंद कनवी।

'भारतीय प्रधानमंत्रियों ने परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर कैसी प्रतिक्रिया दी', रेडिफ डॉट कॉम, 10 फरवरी 2011; 'वाजपेयी ने 79 में परमाणु विकल्प का विरोध किया', फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 20 जनवरी 2004।

329 'उन्हें (पाकिस्तान को) नई सेंट्रीफ्यूज तकनीक मिल गई थी': के. सुब्रह्मण्यम ने लेखक को लिखा, 21

मार्च 2004, नई दिल्ली। यूरेनियम संवर्धन की एक पुरानी तकनीक गैस विसरण थी; अपकेंद्री तकनीक के आगमन के साथ इसे बंद कर दिया गया; यूरेनियम संवर्धन का नवीनतम तरीका लेजर तकनीक है (परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर ने लेखक से 2 अप्रैल 2022 को वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की)।

329 वैज्ञानिक विशेष रूप से चिंतित थे क्योंकि '1979 में हमारे पास (भी) नए सबूत

थे
ए. क्यू. खान': वही।
329 यह सितंबर 1974 की बात है, इंदिरा गांधी द्वारा भारत की 'शांतिपूर्ण' नीति का परीक्षण करने के चार महीने बाद।
परमाणु उपकरण': माइकल लॉफर, 'ए. क्यू. खान परमाणु कालक्रम', कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, 7 सितंबर 2005।
329 खान ने पाकिस्तान की स्वदेशी यूरेनियम संवर्धन क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
कहूता: वही।
329 खान को बहुत बाद में बागी होना था: वही।
329 'मैंने पाकिस्तान के कार्यक्रम का पर्दाफाश किया (1976 में)': के. संथानम ने लेखक को, नई दिल्ली, 1
दिसंबर 2004।
330 ने संथानम की बातों पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया: वही।
330 भारत द्वारा देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी: सी.
राजा मोहन ने लेखक से 3 अप्रैल 2022 को वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की।
330 वर्षों से इसका उद्देश्य पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को 'महत्वपूर्ण सहायता' प्रदान करना था।
कार्यक्रम: चार्ली गाओ, 'चीन ने इन पांच हथियारों से पाकिस्तान की सेना के निर्माण में मदद की', नेशनल इंटरेस्ट, 24 जनवरी 2022। प्रतिष्ठित रक्षा पत्रिका जेन्स डिफेंस वीकली ने खुलासा किया कि पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार मूल रूप से चीनी डिजाइन का था (शक्ति सिन्हा, वाजपेयी: द इयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, नई दिल्ली: विंटेज, पृष्ठ 120)।
330 '(जेड. ए.) भुट्टो ने परमाणु वैज्ञानिकों की एक बैठक बुलाई थी': सी. राजा मोहन ने लेखक को लिखा, 3
अप्रैल 2022, वीडियो कॉल।
330 'नहीं, नहीं, अब सबसे महत्वपूर्ण बात पाकिस्तान को बम बनाने से रोकना है':

के.
लेखक के लिए सुब्रमण्यम, 21 मई 2004, नई दिल्ली।
330 चीन ने अपने पहले परमाणु परीक्षण में 16 किलोटन का बम विस्फोट किया था: मानस तिवारी, 'द स्टोरी ऑफ'
पोखरण: भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करने वाले परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल की आधारशिला बने', फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 17 अगस्त 2018।
330 'परमाणु बम का एकमात्र जवाब परमाणु बम ही है, और कुछ नहीं': के. सुब्रह्मण्यम
लेखक।
27 नवंबर 1964 को लोकसभा में 330 सदस्यों ने एक प्रस्ताव पेश किया: 'भारत के परमाणु हथियार'
कार्यक्रम: हथियार विकास की ओर: 1960-1967'।
331 देसाई ने प्रतिज्ञा की थी कि भारत परमाणु हथियार न तो बनाएगा और न ही हासिल करेगा: जॉर्ज
पेरकोविच, भारत का परमाणु बम: वैश्विक प्रसार पर प्रभाव, बर्कले, लॉस एंजिल्स, लंदन: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 2001, पृ. 211.
331 'हिरोशिमा की पीड़ा': कविता की कोई तिथि अंकित नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह लिखी गई थी।
1950 का दशक। 1957 के बाद, जब वे बलरामपुर से लोकसभा के लिए चुने गए, वाजपेयी ने अपने कई संसदीय भाषणों में हिरोशिमा की पीड़ा का जिक्र किया (सागरिका घोष, अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका, लेखक को, 6 अप्रैल 2022)।
331 लोगों की मौत, लगभग 210,000 लोग: 'हिरोशिमा और नागासाकी बमबारी', आईसीएएन, उपलब्ध है
<icanw.org/hiroshima_and_nagasaki_bombings#:~:text=The%20two%20atomic%20bombs
%20गिराया गया, %20नागासाकी में 74%2C000%20और गिरा।
331 कभी-कभी रात में: अटल बिहारी वाजपेयी, 21 कविताएँ, अनुवाद: पवन वर्मा, नई दिल्ली: पेंगुइन

Books, 2001. The poem on Hiroshima was also found amongst Vajpayee's papers, published as Kuchh Lekh Kuchh Bhaashan, New Delhi: Kitabghar Prakashan, 1999.

332 इस मत का विवरण नहीं दिया गया: कृष्णकांत ने लेखक को 25 दिसंबर 1995 को हैदराबाद में लिखा; रश्मी
कांत द्वारा लेखक को दी गई जानकारी (2002) की पुष्टि 2021 में हुई। रश्मी कांत ने इसके बारे में अपने पिता से और कई बार सीधे के. सुब्रह्मण्यम से सुना था।

332 मोरारजी देसाई ने अपने 'निर्णायक मत' का प्रयोग किया था: कृष्णकांत लेखक से, 25 दिसंबर 1995, 1995;
हैदराबाद। रश्मी कांत द्वारा लेखक को 3 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में पुनः पुष्टि की गई। के. सुब्रह्मण्यम ने दोनों को यह बात कई बार बताई थी।

332 'कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दिया गया': वाजपेयी
1979 में परमाणु विकल्प का विरोध किया।

332 सुब्रमण्यम ने मुझे बताया कि उन्होंने कार्यवाही का विवरण 'अपने हाथ से' लिखा था: के. सुब्रमण्यम
लेखक, 21 मई 2004, नई दिल्ली।

332 'मैंने कार्यवाही की ज़ेरॉक्स प्रति ली': वही।

332 'जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं कभी भी किसी प्रयोग की अनुमति नहीं दूंगा': राज चेंगप्पा,
शांति के हथियार: भारत की परमाणु शक्ति बनने की खोज की गुप्त कहानी, दिल्ली: हार्परकॉलिन्स इंडिया, 2000, पृष्ठ 220।

332 हालाँकि, यह स्पष्ट था कि यह बम से बहुत दूर होगा: वही, पृष्ठ 221। डिज़ाइन को परिष्कृत करना
किसी उपकरण का परीक्षण करने के बाद अगला कदम उसका वजन कम करना होता है, ताकि एक ऐसा बम तैयार किया जा सके जो इतना कॉम्पैक्ट हो कि उसे मिसाइल या विमान जैसे उपयुक्त वितरण तंत्र द्वारा पहुंचाया जा सके।

333 प्रधानमंत्री, जो अपनी आत्म-धार्मिकता के लिए जाने जाते थे, ने यह बात 'जोरदार' ढंग से कही और

‘भावनात्मक रूप से’: रेजाउल एच. लस्कर, ‘मोरारजी देसाई ने अमेरिका से कहा: मुझे यकीन नहीं है कि 1974 का परमाणु परीक्षण आवश्यक था’, हिंदुस्तान टाइम्स 10 अगस्त 2019।

333 यदि भारत को अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहना था, तो एक विश्वसनीय परमाणु प्रणाली का होना आवश्यक था।

निवारक: सिन्हा, वाजपेयी, पृ. 100.

333 ‘मैं सबसे लंबे समय से प्रधानमंत्री पद की प्रतीक्षा कर रहा हूं’: ए. बी. वाजपेयी ने कृष्णकांत और रश्मिकांत से कहा

लेखक को, मार्च 2021।

333 उन्होंने वाजपेयी को सक्षम बनाने के लिए ऐसा किया: सिन्हा, वाजपेयी, पृ. 3.

333 ‘यही हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं’: शिवराज पाटिल ने लेखक से 21 फरवरी 2021 को टेलीफोन पर बातचीत में कहा।

साक्षात्कार। यह कहानी पाटिल को स्वयं वाजपेयी ने सुनाई थी।

333 उन्होंने एक बार अमेरिका में तैनात एक भारतीय राजदूत को वाजपेयी को लोगों से 'परिचय कराने' का निर्देश दिया था।

‘कौन मायने रखता था’: शिवराज पाटिल ने लेखक से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में टेलीफोन पर बातचीत में यह सवाल पूछा।

334 ‘Jisko vote dena hai toh doh, nahin dena toh mat doh’: Shivraj Patil to author, 21 February

2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार। यह कहानी वाजपेयी ने स्वयं एक सम्मेलन के दौरान पाटिल को सुनाई थी।

334 ‘क्या आपने उन्हें रैली में बोलने के लिए आमंत्रित किया था या उनकी पार्टी ने?’: शिवराज पाटिल से

लेखक, 3 नवंबर 2022, नई दिल्ली, टेलीफोन पर साक्षात्कार।

334 वाजपेयी परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश से था: सागरिका घोष, अटल बिहारी वाजपेयी, दिल्ली:

जगरनॉट बुक्स, 2021, पृ. 46.

335 वह अचानक अपनी पंक्तियाँ भूल गया और उसकी ज़बान लड़खड़ा गई: वही, पृष्ठ 48।

335 ‘ये पंक्तियाँ कविता के स्तर तक खरी नहीं उतर सकतीं’: शक्ति सिन्हा ने लेखक से कहा।

335 ‘Toote hue sapno ki, kaun sune siski’: Atal Bihari Vajpayee, Meri Ikyavan Kavitayen, New
Delhi: Kitabghar Prakashan, 1995.

335 ‘Kal agar kaal aakar mere dwar par dastak de’: Ibid.

336 ‘मुझे नहीं पता था कि उन्हें कैंसर है’: यशवंत सिन्हा ने लेखक से कहा, 11 जून 2019, नई दिल्ली।

336 उपचार के बाद, बीमारी दोबारा नहीं उभरी: शक्ति सिन्हा ने लेखक को लिखा, 11
अप्रैल 2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार।

336 ‘गुर्दा और कैंसर, दोनों आपस में संबंधित थे’: वही।

336 ‘Meri kavita jang ka elan hai, parajaya ki prastavana nahin’: Ghose, Atal Bihari Vajpayee.

336 ‘मैं इस अवसर का उपयोग अपने आवश्यक उपचार को प्राप्त करने के लिए करूंगा’: उललेख एन. पी., अनकही कहानी
वाजपेयी: राजनीतिज्ञ और विरोधाभास, नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, 2018, प्रभास के. दत्ता द्वारा उद्धृत, 'जब राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जान बचाई', इंडिया टुडे, 6 मई 2019।

336 ‘मैं न्यूयॉर्क गया था और यही एक कारण है कि मैं आज जीवित हूँ’: वही।

336 संयुक्त राष्ट्र सत्र में भाग लेने के अलावा, न्यूयॉर्क की उनकी वार्षिक यात्रा उन्हें अन्य अवसर भी प्रदान करती थी।
उनकी वार्षिक जांच: भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक को 21 मार्च 2000 को नई दिल्ली में पत्र लिखा।

336 He had once instructed Brajesh Mishra to inform journalist Rajdeep Sardesai where he
न्यूयॉर्क में सबसे बढ़िया स्टेक मिलेगा!: घोष, अटल बिहारी वाजपेयी, पृ. 354.

336 उनके दोस्त मुकुंद मोदी के अनुसार, उन्हें मैक्सिकन खाना विशेष रूप से पसंद था: सबा नकवी

भौमिक, ‘वाजपेयी ने सार्वजनिक जीवन को निजी जीवन से सफलतापूर्वक अलग किया’, इंडिया टुडे, 20 अप्रैल 1998।
337 उन्हें संयुक्त राष्ट्र में 'उच्च स्तरीय राजनीति' और 'नेताओं के आने-जाने' में रुचि थी।
'दुनिया भर में': शक्ति सिन्हा ने लेखक से 11 अप्रैल 2021 को टेलीफोन पर साक्षात्कार में कहा।
337 वाजपेयी ‘एक दिन उनसे शादी करने की उम्मीद रखते थे’: घोष, अटल बिहारी वाजपेयी।
337 इस बैठक ने वाजपेयी और राजकुमारी के बीच ‘संबंधों की लौ को फिर से प्रज्वलित कर दिया’: विनय सीतापति, ‘इन
नेहरू की छाया (1951-67)’, जुगलबंदी: मोदी से पहले भाजपा, नई दिल्ली: पेंगुइन रैंडम हाउस, 2020।
करण सिंह ने लेखक को 16 मार्च 2023 को बताया, "337 लोगों ने उन्हें 'एक उल्लेखनीय महिला' के रूप में याद किया।"
दिल्ली।
337 हालाँकि आरएसएस वाजपेयी के 'रोमांस करने, व्हिस्की पीने और मांस खाने' के रवैये को नापसंद करता था।
तरीके': घोष, अटल बिहारी वाजपेयी, पी. 114.
337 ‘राजकुमारी और वाजपेयी के बीच संबंध का मूल’: सीतापति, ‘नेहरू के Shadow (1951–67)’, Jugalbandi.
337 ‘राजकुमारी वाजपेयी से राजनीति पर बहस कर रही हैं’: वही।
338 1946 में विस्तारक (उपदेशक) बने: घोष, अटल बिहारी वाजपेयी, जगन्नाथ, पृ. 50.
338 आरएसएस प्रचारक उनकी वाक्पटुता से उत्साहित थे: घोष, अटल बिहारी वाजपेयी, पृष्ठ 54.
338 ‘वह चाट जो हम दिल्ली के बंगाली बाजार में जाकर खाते थे’: एल. के. आडवाणी ने लेखक को लिखा, 11
मई 1998, नई दिल्ली।
339 ‘हिंदू राष्ट्र से तात्पर्य भारतीय राष्ट्र से है जिसमें गैर-हिंदू भी सदस्य के रूप में

शामिल हैं':
'3 अगस्त 1979, चालीस साल पहले: आरएसएस पर वाजपेयी', इंडियन एक्सप्रेस, 3 अगस्त 2019।
339 वाजपेयी ने नवगठित भाजपा के लिए 'गांधीवादी समाजवाद' को अपना मंत्र चुना: सीतापति, कट्टरपंथी
Hindus, Moderate Vajpayee (1980–84), Jugalbandi.
339 यह 'सनातन धर्म', संस्कृति और राष्ट्रवाद के मूल्यों पर आधारित एक मॉडल था: जीके
आज, 13 नवंबर 2015।
339 न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्थानीय चुनाव को इतना महत्वपूर्ण माना कि उसके बारे में लिखा:
विलियम के. स्टीवंस, 'गांधी पार्टी ने नई दिल्ली में बड़ी जीत हासिल की', न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए विशेष लेख, 7 फरवरी 1983। कांग्रेस ने 56 में से 34 विधानसभा सीटें और 100 में से 57 निगम सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को दिल्ली में केवल 19 विधानसभा सीटें और 38 निगम सीटें ही मिलीं। (कूमी कपूर, 'दिल्ली नगर निगम चुनाव: कांग्रेस (आई) ने जोरदार वापसी की, शानदार जीत हासिल की', इंडिया टुडे, 28 फरवरी 1983)।
339 'जब तक अटलजी हैं, आडवाणी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे': गोविंदाचार्य ने लेखक से कहा
भाजपा मुख्यालय, 11 अशोक रोड, नई दिल्ली, 1 दिसंबर 1989।
339 'मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि धार्मिकता भारतीय लोगों के जीवन में इतनी गहराई से समाई हुई है': आडवाणी
मेरा देश, मेरा जीवन, पृष्ठ 377।
340 उन्होंने अपने एक भाषण में खुद को 'गुटनिरपेक्षता का समर्थक' तक कह दिया था।
संसद: घोष, अटल बिहारी वाजपेई, पृ. 137.
340 उन्हें अधिक 'उदारवादी' के रूप में देखा जाने लगा: सागरिका घोष ने लेखक से 6 अप्रैल 2022 को टेलीफोन पर बातचीत में कहा।
बातचीत।

341 ‘Yahi to dikkat hai, baniye hi baniye hain. Aur koi nahi’: Sources close to Chaudhary
राधाकृष्णन द्वारा लेखक को, 3 अप्रैल 2018, नई दिल्ली।
341 वाजपेयी पार्टी का 'मुखौटा' (मुखौटा): नीना व्यास, 'वाजपेयी 'मुखौटा', एक बार और
'हमेशा संघ का वफादार', द वायर, 17 अगस्त 2018।
341 उन्हें संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया: घोष, अटल बिहारी वाजपेयी, पृ. 105.
342 मुखर्जी को शेख अब्दुल्ला ने गिरफ्तार किया था: वाजपेयी ने वर्षों बाद 2004 में आरोप लगाया था कि
मुखर्जी की मृत्यु एक षड्यंत्र के कारण हुई थी। (शशांक भारद्वाज, 'छिपाने से लेकर हत्या की साजिश तक: कश्मीर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बारे में कुछ अनुत्तरित प्रश्न', ओपइंडिया, 23 जून 2021।)
342 वाजपेयी ने फरवरी 1978 में पाकिस्तान की यात्रा की, जिसे उन्होंने 'ऐतिहासिक' यात्रा बताया: '8 फरवरी,
1978, चालीस साल पहले: पाकिस्तान में वाजपेयी’, इंडियन एक्सप्रेस, 8 फरवरी 2018।
342 ‘वाजपेयी एक चतुर करियरवादी थे’: सागरिका घोष ने लेखक से 6 अप्रैल 2022 को टेलीफोन पर बातचीत में कहा।
साक्षात्कार।
342 वाजपेयी ने दो आवाजों में बात की: सिद्धार्थ वरदराजन, 'अटल के मंदिर पर चर्चा: बड़ा उलटफेर'
फ्लॉप’, टाइम्स ऑफ इंडिया, 4 अगस्त 2003।
342 अप्रैल 1991 में उन्होंने कहा कि एक मंदिर आवश्यक था: वही।
342 मई 1996 में, उन्होंने विध्वंस को लगभग उचित ठहराया: वही।
343 ‘राजनीति में आपका लंबा करियर बाकी है’: सोम पाल ने लेखक से कहा, 17 मार्च 2023
गुडगाँव।
343 ‘वह जो कह रही है वह सही नहीं है’: वही। सोम पाल ने कहा कि वाजपेयी ने

उन्हें यह बात 16 मई को बताई थी।
2004 में, सोनिया गांधी के कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुने जाने के एक दिन बाद।
344 ‘Yeh toh nahi chalega, yeh toh nahin chalega’: Jaswant Singh to author, 15 January 2005,
नई दिल्ली।
344 ‘आप एक खतरनाक खेल में फंसने जा रहे हैं’: बैठक में उपस्थित प्रशिक्षुओं में से एक ने कहा।
लेखक; वे 29 मार्च 2021 को नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने।
344 ‘इन कागजों को कोई नहीं देखता, कर्मचारियों को भी इसके बारे में पता नहीं है’: इंदर कुमार गुजराल ने लेखक से कहा।
345 वी. पी. सिंह ने कहा कि उन्हें राजीव गांधी द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी: वी. पी. सिंह ने लेखक को 29 मई 2002 को लिखा।
नई दिल्ली।
345 चंद्र शेखर ने शिकायत की कि उन्हें वी. पी. सिंह द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी: चंद्र शेखर ने लेखक को लिखा।
15 फरवरी 2000, नई दिल्ली।
345 नरसिम्हा राव ने नरेश चंद्र और ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को एच. डी. देवेगौड़ा को जानकारी देने के लिए भेजा:
नरेश चंद्र द्वारा लेखक को, 5 फरवरी 2004, नई दिल्ली।
345 गुजराल ने 1998 में वाजपेयी को संक्षिप्त जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें पहले ही नवीनतम जानकारी दे दी गई थी: एच. डी. देव
गौड़ा द्वारा लेखक को, 30 अक्टूबर 2003, नई दिल्ली।
345 यहां तक कि देसाई, जो शस्त्रीकरण के प्रति सबसे कम उत्साही थे, ने भी अनुसंधान एवं विकास तथा छोटे स्तर पर काम जारी रखा।
टेबल टॉप प्रयोग जारी हैं: अनिल काकोडकर ने लेखक को 15 मार्च 2023 को लिखा।
345 ‘राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह से कार्य नहीं किया जो निम्न स्तर का हो
'जिम्मेदार': आई. के. गुजराल ने लेखक को 6 अक्टूबर 2003 को नई दिल्ली में

लिखा।
345 नेहरू भारत द्वारा परमाणु विकल्प का प्रयोग करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के पूरी तरह से खिलाफ नहीं थे:
चेंगप्पा, शांति के हथियार, पृष्ठ 83-84।
345 नेहरू 'परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ थे': उद्धृत, वही, पृष्ठ 83।
345 'क्योंकि हम इससे पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते': वही।
345 उन्होंने नेहरू से संविधान में संशोधन करने की भी मांग की: कनवी, 'भारतीय प्रधानमंत्रियों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी'
परमाणु महत्वाकांक्षाएं।
345 'नहीं, नहीं,' नेहरू ने उनसे कहा। 'इतनी दूर मत जाओ': चेंगप्पा, वेपन्स ऑफ पीस, पृ. 83.
346 'वे एक शक्तिशाली तीसरी शक्ति का गठन कर सकते हैं': वही, पृष्ठ 84.
346 उन्होंने भाभा को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सक्षम बुनियादी ढांचा स्थापित करने की योजनाओं को मंजूरी दी।
हथियार: वही, पृष्ठ 83. परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना नेहरू द्वारा अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख करने और देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
होमी भाभा इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आया, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक उन्नत अनुसंधान करने हेतु होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1954 में स्थापित एक प्रमुख संस्थान था। यह मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित था और भाभा इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाने में सफल रहे। 1958 में परमाणु कार्यक्रम से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण संस्थान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की स्थापना हुई। रक्षा मंत्रालय के अधीन इस संगठन को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों पर अनुसंधान का कार्य सौंपा गया था।
346 तदनुसार, 1965 में ट्रॉम्बे में एक प्लूटोनियम पुनर्संसाधन संयंत्र शुरू किया गया: 'भारत का
परमाणु हथियार कार्यक्रम: हथियार विकास की ओर: 1960-1967'।

346 5 अप्रैल 1965 को उन्होंने परमाणु डिजाइन समूह की स्थापना को मंजूरी दी: वही।

346 'शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट' (PNE): PNE एक ऐसा परमाणु विस्फोट है जो गैर-सैन्य उद्देश्यों के लिए होता है।

(ऐसे उद्देश्यों के लिए जिनका उपयोग नहरों या बंदरगाहों की खुदाई या अंतरिक्ष यान चलाने जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।) लेकिन शास्त्री जी का निधन इसके तुरंत बाद 11 जनवरी 1966 को हो गया। उनके उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी ने आठ साल बाद एक पीएनई (सार्वजनिक परिवहन संगठन) की शुरुआत की।

347 'रामन्ना ने मुझे यह बात स्वयं (बाद में) 1978 में बताई थी': के. सुब्रह्मण्यम ने लेखक को 21 मई को लिखा।

2004, नई दिल्ली।

347 सरकार ने इस उपकरण को 'शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटक' बताया: 'परमाणु

'भारत का कार्यक्रम', <indiragandhi.in/en/milestones/index/ nuclear-program> पर उपलब्ध है।

348 उसने अंतरराष्ट्रीय अप्रसार संधि के एक प्रावधान का लाभ उठाने की उम्मीद की।

(एनपीटी): एनपीटी उन देशों के एक समूह द्वारा शुरू की गई एक संधि थी जिन्होंने सबसे पहले परमाणु हथियार विकसित किए थे। यह 1970 में लागू हुई और इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना था। भारत, इज़राइल और पाकिस्तान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि वे इसे भेदभावपूर्ण मानते हैं।

348 भारत के परीक्षण के तुरंत बाद गठित परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी): परमाणु

आपूर्तिकर्ता समूह का गठन मई 1974 में, भारत द्वारा किए गए विस्फोट के तुरंत बाद हुआ था। इसमें परमाणु प्रौद्योगिकी और कच्चे माल रखने वाले देश शामिल थे और इसका उद्देश्य परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर अंकुश लगाकर और मौजूदा सुरक्षा उपायों में सुधार करके परमाणु प्रसार को नियंत्रित करना था।

348 ये प्रतिबंध भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बड़ा 'झटका' साबित हुए, खासकर 'के लिए'

बिजली रिएक्टरों का निर्माण: के. संथानम ने लेखक को 1 दिसंबर 2004 को नई

दिल्ली में लिखा।
348 मूल रूप से हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच एक निजी संधि है: वरिष्ठ राजनयिक सौरभ कुमार
लेखक को, 29 मार्च 2021, बैंगलोर से टेलीफोन पर हुई बातचीत।
348 वे इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को बढ़ने नहीं देना चाहते थे और उन्होंने इसके समर्थन में आवाज उठाई।
पाकिस्तान: सी. राजा मोहन द्वारा लेखक को, 3 अप्रैल 2022।
349 उन्होंने तुरंत सुझाव दिया कि भारत दो हथियार डिजाइनों का परीक्षण करे: हरेश पांडी, 'राजा
रमन्ना', द गार्जियन, 1 अक्टूबर 2004।
349 1982 के मध्य तक, जिन शाफ्टों में विस्फोट होना था, उन्हें खोदकर तैयार कर लिया गया था:
चेंगप्पा, वेपन्स ऑफ पीस, पृ. 256.
349 तत्कालीन रक्षा मंत्री आर. वेंकटरमन के अनुसार, उन्होंने अपना रुख बदल लिया था।
मन: वेंकटारमन, मेरे राष्ट्रपति काल के वर्ष।
349 रसगोत्र मई 1982 में उनसे मिलने वाशिंगटन डीसी गए थे: चेंगप्पा, हथियार शांति, पृ. 256.
349 ‘फिर से ऐसा मत करो। इस बार हम तुम्हें नष्ट कर देंगे’: चेंगप्पा, शांति के हथियार, पृ. 204.
349 मंजूरी देने के कुछ ही घंटों के भीतर, उसने 'आरवी' को वी.एस. अरुणाचलम को फोन करने के लिए कहा:
पेरकोविच, भारत का परमाणु बम, पृ. 243.
349 ‘हम नहीं चाहते कि हमारी खोपड़ी तोड़ी जाए’: के. सुब्रह्मण्यम ने लेखक को, 21 मई 2004।
सुब्रह्मण्यम ने यह बात राजा रामन्ना से सुनी थी। चेंगप्पा की पुस्तक 'वेपन्स ऑफ पीस', पृष्ठ 260 में भी यही बात लिखी है।
349 राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सभा को विशेष रूप से अधिकृत किया था।

1989 में हथियार: सी. राजा मोहन ने लेखक से 3 अप्रैल 2022 को वीडियो साक्षात्कार में यह बात कही।

349 '1974 में पीएनई केवल एक उपकरण था। दूसरी ओर, एक हथियार को वेक्टर के लिए अनुकूलित किया जाता है।

डिलीवरी': के. संथानम लेखक के लिए, 1 दिसंबर 2004, नई दिल्ली।

350 'राजीव इस बात के सबूतों से आश्वस्त हो गए थे कि पाकिस्तान कुछ गलत काम कर रहा था': वही।

350 'उन्होंने पैसे में कंजूसी नहीं की': के. सुब्रह्मण्यम ने लेखक को, 13 फरवरी 2005, नई दिल्ली।

351 'पाकिस्तानी कहेंगे "भारत डर गया है और डर के मारे ऐसा कर रहा है"': वही।

351 'आप इस पर निर्णय को टालते नहीं रह सकते': वही।

351 'हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते,' उन्होंने स्पष्ट कहा, 'अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी': वही।

351 'हम चाहते हैं कि समिति की अध्यक्षता सुंदरजी करें': वही।

351 'परमाणु निवारक' की अवधारणा सबसे पहले इस रिपोर्ट में सामने आई: वही।

352 'संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के साथ संबंधों में संतुलित रुख': बर्नार्ड

वेनराउब, 'गांधी के आगमन के साथ, अमेरिका के संबंध बेहतर हुए', न्यूयॉर्क टाइम्स, 12 जून 1985।

352 'पाकिस्तान पहले ही बम बना चुका है,' रीगन ने राजीव से कहा: वरिष्ठ राजनयिक एस. के. सिंह

लेखक, 15 मार्च 2005, नई दिल्ली।

352 'सिद्धांतों की बात मत करो, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचो': वही।

352 'मुझे राजीव द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी थी': वही।

352 'हमें ब्रिटेन और अमेरिका को सबूत देना था': वही।

352 'इसने रीगन ने राजीव को जो बताया था उसकी पुष्टि की': वही।

352 'तो भारत के सामने सवाल यह था कि आप क्या करते हैं?': सी. राजा मोहन ने लेखक को 3 अप्रैल 2022 को लिखा।

वीडियो इंटरव्यू।

353 पाकिस्तान भारत को 'अस्वीकार्य क्षति' पहुँचाने की स्थिति में था: एस. के. सिंह ने लेखक को बताया।
353 फरवरी 1987 में पाकिस्तान के पास बम होने के 'अकाट्य सबूत' प्रस्तुत किए गए:
चेंगप्पा, शांति के हथियार, पीपी 330-35।
353 वह वैसे भी निरस्त्रीकरण पर अपनी पहल से निराश थे: वही, पृष्ठ 331।
353 उन्होंने ये आदेश अपने रक्षा सचिव नरेश चंद्र को दिए: वही, पृष्ठ 334।
353 नरेश चंद्र भी इस कार्यक्रम में उनके ठीक पीछे बैठे थे: चेंगप्पा, हथियार
शांति, पृ. 321.
353 'Yeh aapko karna hai': Naresh Chandra to author, 5 February 2004, New Delhi.
353 'वे दिल्ली के पास नहीं थे और भूमिगत स्थल के लिए वास्तुशिल्प योजनाएँ बनाई गई थीं':
लेखक को एस. के. सिंह।
354 'मुझे भारत के बम के बारे में औपचारिक और आधिकारिक तौर पर (केवल) जुलाई 1990 में बताया गया था': के.
लेखक के लिए सुब्रमण्यम, 13 फरवरी 2005, नई दिल्ली।
354 परमाणु बम से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करें 'अब जब हमें यह मिल गया है': के. सुब्रह्मण्यम
लेखक को, 13 फरवरी 2005, नई दिल्ली।
354 'फिर बटन कौन दबाएगा, यह सब तय हो चुका था': वही।
354 'विचार यह था कि परमाणु सिद्धांत को विस्तार से समझाया जाए, जिसे परिचालन में लाया जा सके।
विवरण': के. संथानम लेखक के लिए, 1 दिसंबर 2004, नई दिल्ली।
354 'सज्जनों, हम यहाँ इस बात पर चर्चा करने के लिए हैं कि हमारे बाद कौन जीवित रहेगा': वही।
354 इसके बाद ही वी. पी. सिंह को ठीक-ठीक पता चला कि देश की परमाणु प्रौद्योगिकी कितनी उन्नत थी।
कार्यक्रम था: लेखक के लिए के. सुब्रमण्यम, 13 फरवरी 2005, नई दिल्ली।

355 ‘प्रधानमंत्री रहते हुए, एक सक्रिय बम रखने पर जोर दिया गया था’: वी. पी. सिंह ने लेखक को लिखा, 14
अक्टूबर 1999, अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली।
355 ‘निर्णय शून्य में नहीं लिए जाते’: वही।
355 ‘क्या आपको किसी ने जानकारी नहीं दी?’: एस. के. सिंह ने लेखक से 15 मार्च 2005 को नई दिल्ली में पूछा।
355 ‘नहीं, मुझे किसी ने जानकारी नहीं दी’: चंद्र शेखर ने लेखक को 23 फरवरी 2000 को नई दिल्ली में लिखा।
चीन को 2004 में अपनी कमान नियंत्रण संरचना पूरी करनी थी। रूसियों, अंग्रेजों और अमेरिकियों ने इसे कई साल पहले ही पूरा कर लिया था।
355 ‘तो फिर तुम और मैं एक ही नाव में हैं’: एस. के. सिंह ने लेखक को, 15 मार्च 2005, नई दिल्ली।
356 ‘यह गुजराल ने किया था’: के. सुब्रह्मण्यम ने लेखक से कहा।
356 ‘जब हम देवे गौड़ा से मिलने गए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, यानी कलाम से,
चिदम्बरम, और मैं': के. संथानम लेखक के लिए, 1 दिसंबर 2004, नई दिल्ली।
356 ‘नहीं, नहीं। अभी नहीं’: वही।
356 लेकिन देवे गौड़ा ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल के अंत में एक परीक्षण मैच खेलने पर विचार किया था:
चेंगप्पा, वेपन्स ऑफ पीस, पृ. 402.
356 ‘उसी समय गुजराल ने गंभीरता से विचार किया कि क्या उसे परीक्षण कराना चाहिए’: एन.
एन. वोहरा द्वारा लेखक को 25 नवंबर 2004 को लिखा गया, जिसकी पुष्टि 24 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में हुई।
357 ‘उनके कार्यक्रम में, मैंने दोपहर 1 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच एक निजी लंच और उसके बाद आराम का समय दिखाया।
दोपहर 2 और 5 बजे: वही।
357 ‘गुजराल साहब ने परीक्षण कराने का फैसला किया’: वही।
357 मैंने उनसे कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया

शुरू हो चुकी थी': वही। इसके बाद
चुनावों की घोषणा के बाद, जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है, तो सरकार को ऐसे बड़े नीतिगत निर्णय नहीं लेने चाहिए जो सत्तारूढ़ दल को अन्य राजनीतिक दलों पर अनुचित लाभ दे सकें।
357 'अपने लड़कों द्वारा किए गए शोधों का सत्यापन प्राप्त करने के लिए उत्सुक': वही।
357 'उन्होंने परमाणु उपकरण के परीक्षण के बारे में उन संदर्भों को करना बंद कर दिया': वही।
357 'यह सब करने का यही एकमात्र तरीका था': नरेश चंद्र ने लेखक से कहा।
357 'वैज्ञानिक समुदाय अत्यधिक विश्वसनीय है, जिसमें प्रतिबद्ध लोग हैं': वही।
अनुच्छेद 358 ने अमेरिका को किसी भी अन्य राष्ट्र को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित कर दिया:
सौरभ कुमार से लेखक को, 29 मार्च 2021, टेलीफोन पर हुई बातचीत।
358 इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ: संयुक्त राष्ट्र परमाणु
ऊर्जा आयोग। यूएनएईसी को 1952 में भंग कर दिया गया था।
358 क्योंकि इससे अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है: यह तब से अमेरिकी सुरक्षा का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है।
कूटनीति। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया गया पहला प्रस्ताव (अमेरिका द्वारा) सुरक्षा परिषद को परमाणु ऊर्जा की खोज से उत्पन्न समस्याओं से निपटने और राष्ट्रीय शस्त्रागार से परमाणु हथियारों को हटाने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश देता था। हालाँकि, उनका यह प्रयास अंततः असफल रहा क्योंकि पूर्व सोवियत संघ और अन्य देशों ने यह समझ लिया कि सभी परमाणु संयंत्रों को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में रखना आवश्यक है।
358 दुनिया के पहले परमाणु हथियार संपन्न देशों - अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन - ने राष्ट्रीय परमाणु नीति संधि (एनपीटी) का मसौदा तैयार किया:
1970 में परमाणु परीक्षण नीति (एनपीटी) के लागू होने से पहले ही, 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी) हुई थी; इसने वायुमंडल और जल के भीतर परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन भूमिगत परीक्षणों पर नहीं।

पीटीबीटी पर 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह पांच परमाणु हथियार निर्माताओं द्वारा किए गए लगभग 2,000 परीक्षणों के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य पर रेडियोधर्मी मलबे के हानिकारक प्रभावों के जवाब में थी। देखें '1. मॉस्को में अगस्त में वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि।
5, 1963', अमेरिकी विदेश विभाग, <www.state.gov/limited-test-ban-treaty> पर उपलब्ध है।
358 एनपीटी ने दुनिया को परमाणु शक्ति संपन्न (एनडब्ल्यूएस) और परमाणु शक्ति से वंचित (एनएनडब्ल्यूएस) देशों में 'कानूनी तौर पर' विभाजित किया:
एनपीटी पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि ऊपर उल्लिखित पांच देशों के अलावा, अन्य सदस्यों को परमाणु हथियारों का त्याग करना होगा (न तो उनका विकास करना होगा और न ही उन्हें हासिल करना होगा)। परमाणु हथियार संपन्न देशों को अपने शस्त्रागार को समाप्त करने के लिए बाध्य करने वाला कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम नहीं था।
358 'एक अंतरराष्ट्रीय साधन, जो स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण ढंग से बनाया गया है, जिसका उद्देश्य निरस्त्रीकरण करना है
'निहत्था': सौरभ कुमार ने लेखक से 29 मार्च 2021 को नई दिल्ली में कहा।
359 इसका मतलब परमाणु हथियार हासिल करने के विकल्प को छोड़ देना होता: सैद्धांतिक रूप से
सैद्धांतिक रूप से, संधि में एक निकास खंड का प्रावधान था, जो एनपीटी के हस्ताक्षरकर्ता को कुछ परिस्थितियों में संधि से हटने में सक्षम बनाता था, लेकिन व्यवहार में, यह कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था।
359 1974 का परीक्षण, कुछ मायनों में, 1964 में चीन के परमाणु शक्ति बनने की दिशा में एक विलंबित प्रतिक्रिया थी: सी.
राजा मोहन का लेखक से 3 अप्रैल 2022 को वीडियो साक्षात्कार।
359 ऐसी चीजें जिनकी अनुमति एनपीटी द्वारा दी गई थी (हालांकि भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे) बशर्ते वे
परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए: सौरभ कुमार ने लेखक को 29 मार्च 2021 को टेलीफोन पर दिए साक्षात्कार में बताया। आज, भारत अपनी परमाणु

ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
विशाल अवसंरचना विकास कार्यक्रम। (भारत में परमाणु ऊर्जा, विश्व परमाणु)
एसोसिएशन, 31 मई 2023 को एक्सेस किया गया, <world-nuclear.org/
information-> पर उपलब्ध है
library/country-profiles/countries-g-n/india.aspx>.
359 एनपीटी का समय-समय पर विस्तार किया गया था: आज, एनपीटी लगभग सार्वभौमिक हो गया है,
अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, 191 देशों ने संधि में शामिल हुए हैं।
360 'भारत इस असमान संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, न अभी, न बाद में': रुही नियोग, 'सीटीबीटी के 20 वर्ष: क्यों'
भारत संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा', साउथ एशियन वॉइसेस, 23 सितंबर 2016।
360 इनमें से तीन—भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया—ने शुरू में इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे: 'परमाणु
'हथियार: किसके पास क्या है, एक नज़र में', शस्त्र नियंत्रण संघ, जनवरी 2022, उपलब्ध
<www.armscontrol.org/factsheets/
Nuclearweaponswhohaswhat> पर।
360 'यह 1994 में था जब पी.वी. ने पहली बार मेरे साथ यह मामला उठाया था': नरेश चंद्र ने लेखक से कहा।
360 फिर वह यह कहकर निर्णय को टाल देता था, 'बात करिन्गे फ़ुरसत से': वही।
361 'क्या आप जानते हैं कि वे (पाकिस्तान) आठ घंटे में पलटवार कर सकते हैं?': वही।
361 'संभवतः लगभग छत्तीस घंटे था': वही।
361 'मुझे परमाणु कार्यक्रम के लिए दो बार... बड़ी मात्रा में धन मिला': वही।
361 'मैंने न्यूयॉर्क से पेरिस जाने के लिए कॉनकॉर्ड विमान लिया': नरेश चंद्र ने लेखक को 8 मई 2004 को लिखा, न्यू यॉर्क
दिल्ली।
361 'मैं लूव्र में घूम रहा था, जाहिर तौर पर यह देख रहा था कि कौन सी पेंटिंग खरीदनी है': वही।

362 राव ने क्लिंटन से वादा किया था कि वह परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे: स्ट्रोब टैलबॉट,
भारत से जुड़ाव: कूटनीति, लोकतंत्र और बम, वाशिंगटन डी.सी.: ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन प्रेस, 2004, पृ. 34.
362 राष्ट्रीय संधि संधि (एनपीटी) के अनिश्चितकालीन विस्तार ने ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया: नरेश
चंद्रा से नीरजा, 8 मई, 2004, नई दिल्ली। इसके अलावा के. संथानम से नीरजा, 1 दिसंबर, 2004, नई दिल्ली।
362 भारत इस बात से भी नाराज था कि अमेरिका ने हैंक ब्राउन संशोधन पेश किया था: सुनील
दासगुप्ता, 'अमेरिकी सीनेट द्वारा पाकिस्तान को हथियार हस्तांतरण की अनुमति देने पर भारत ने इस कदम की निंदा की', इंडिया टुडे, 31 अक्टूबर 1995।
362 लेकिन अमेरिका से आ रहा संदेश स्पष्ट था—कि समय तेजी से बीत रहा था
भारत: के. संथानम से लेखक, 1 दिसंबर 2004, नई दिल्ली।
नरेश चंद्र के अनुसार, 362 राव 'केवल टालमटोल कर रहे थे': नरेश चंद्र
लेखक, 8 मई 2004, नई दिल्ली।
362 वैज्ञानिक ए. पी. जे. अब्दुल कलाम और आर. चिदंबरम हैदराबाद गए थे।
स्पष्टतः 'काम' के लिए: वही।
362 'हमने पीवी को पिच, संभावित परिणामों के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी': वही।
362 'वह बातों को इस तरह से रखता था कि बाद में कोई यह आरोप न लगा सके कि वह सक्रिय रूप से
प्रोत्साहन': वही।
362 'मैंने यह पेपर लिखा': वही।
363 इसकी केवल एक ही प्रति थी और वह कलाम के पास थी: वही।
363 'दिसंबर 1995 तक, उन्होंने (राव) विकल्प में ऑक्सीजन डालने का मन बना लिया था': के.
संथानम से लेखक, 1 दिसंबर 2004।
363 'इसके बाद इसे ज्यादा देर तक गुप्त नहीं रखा जा सकता': नरेश चंद्र ने लेखक

से कहा, 25 दिसंबर
2002, नई दिल्ली।
363 ‘यह राव के परीक्षण के सबसे करीब आने का समय था’: वही।
363 भारत का मानना है कि जो कुछ हो रहा था वह नियमित रखरखाव का काम था: भाजपा नेता जसवंत सिंह
कहा जाता था कि राव के प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मुखबिर था जिसने अमेरिकियों को जानकारी दी थी। कई वर्षों तक इस बात पर अटकलें चलती रहीं कि वह मुखबिर कौन था, लेकिन इस प्रयास से कोई पुख्ता सबूत नहीं निकला। हालांकि, अमेरिकियों ने अपनी आशंकाओं को केवल मानवीय खुफिया जानकारी पर ही आधारित नहीं किया था। उन्होंने उपग्रह तस्वीरों पर भी भरोसा किया था।
363 ‘विस्नर सबसे पहले मेरे पास आए’: नरेश चंद्र ने लेखक से कहा।
363 इतना तेज था कि विस्नर द्वारा दिखाई गई तस्वीरों के विवरण को आसानी से पहचान सका: सूत्र
परमाणु प्रतिष्ठान के करीबी लेखक को, 2021।
364 ‘नरेश चंद्र...ने मेरे पिता (जसवंत सिंह) को कहानियां सुनाई थीं कि उन्हें यह कैसे मिला था
'अमेरिकियों में से बेहतर': मानवेंद्र सिंह ने लेखक से कहा।
364 ‘हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है’: नरेश चंद्र ने लेखक को, 8 मई 2004, नई दिल्ली।
364 वर्मा को जब इसके बारे में पता चला तो वह 'बेहद गुस्से से भड़क उठे': वही।
364 ‘प्रधानमंत्री को एक बयान दें और जो प्रश्न और उत्तर आएंगे’: वही।
364 इस प्रकार अपने विकल्प खुले रखते हुए: नरेश चंद्र ने लेखक को, 5 फरवरी 2001, नई दिल्ली।
364 क्लिंटन ‘भारत के रुख की प्रशंसा करते रहे और (कहते रहे) कि वह समझते हैं’: वही।
365 'वाशिंगटन जाना था': वही।
365 ‘दूसरी बातचीत बेतरतीब थी’: वही।
366 स्थिति ‘नाजुक’ बनी रही: मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने लेखक को 29 सितंबर 2021 को लिखा।

वीडियो कॉल।
366 'निराशावादी': नरेश चंद्र ने लेखक को, 8 मई 2004, नई दिल्ली।
367 और यह कि 'अमेरिकी तब भाजपा का समर्थन करेंगे': वही।
367 सीबीआई प्रमुख विजय रामाराव ने 'हवाला लाइन' को आगे बढ़ाया: वही।
367 'हवाला उनके जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता थी': वही।
367 'परीक्षण के लिए सबसे अच्छा अवसर 1994-95 था': वही।
367 'और ज़मीनी स्तर पर परीक्षण करना अनुमेय था': के. संथानम ने लेखक को लिखा, 1
दिसंबर 2004, नई दिल्ली।
368 'जब फ्रांस और चीन ने 1994 में ऐसा किया था, तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया?': नरेश चंद्र ने लेखक से पूछा, 8
मई 2004, नई दिल्ली।
368 राव के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की संभावना तभी बेहतर होती जब कांग्रेस सत्ता में होती।
अल्पसंख्यक: नरेश चंद्र द्वारा लेखक को, 8 मई 2004, नई दिल्ली; भुवनेश चतुर्वेदी द्वारा लेखक को, 23 दिसंबर 1999, नई दिल्ली।
368 एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि वे चुनाव हार गए हैं, तो उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया: सीतापति, आधा शेर, पृ. 291.
368 'पीवी ने नियति के साथ अपना मिलन खो दिया': नरेश चंद्र ने लेखक को, 8 मई 2004, नई दिल्ली।
368 'हम अगला चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लड़ेंगे': आडवाणी
माई कंट्री माई लाइफ, पृ. 472.
369 'कि भाजपा अटलजी के प्रधानमंत्रित्व काल में अगली सरकार बनाएगी: वही।
369 'भाजपा चुनाव जीतेगी': वही, पृष्ठ 473.
369 'Atalji hi banaenge': Ibid.
369 'Kya aap maante agar humne aap se poocha hota': Ibid.
369 'आप ऐसी घोषणा कैसे कर सकते हैं?': के. एन. गोविंदाचार्य ने लेखक से 3 जुलाई को पूछा
2018, नई दिल्ली।

369 ‘अगर मैंने (दूसरों से) सलाह ली होती, तो ऐसा नहीं होता’: एल. के. आडवाणी ने लेखक से कहा।
1991 के चुनावों में 369 120 लोकसभा सीटें: 'आम चुनावों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट, 1991 से
दसवीं लोकसभा: खंड I’
369 कई लोगों को संदेह था कि 1995 में आडवाणी ने मजबूरी को अवसर में बदल दिया था: एक करीबी सूत्र के अनुसार
आडवाणी ने लेखक को इसकी पुष्टि की।
370 ‘पर्वतवी ने हवाला मामले को आगे बढ़ाकर वाजपेयी की मदद की’: भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक से कहा, 23
मार्च 2007, नई दिल्ली।
370 ‘पीवी ने इसे सिरे से नकार दिया’: वही।
370 161 लोकसभा सीटें, 1991 की तुलना में 41 सीटें अधिक: 'आम चुनाव पर सांख्यिकीय रिपोर्ट'
1996 से 11वीं लोकसभा तक: खंड I’, दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 1996, <eci.gov.in/files/file/4123-general-election-1996-vol-i-ii> पर उपलब्ध है।
371 ‘वाजपेयी स्वयं इस बात से आश्चर्यचकित थे कि उन्हें बुलाया गया था’: भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक से कहा।
21 मार्च 2000, नई दिल्ली।
371 कुछ लोगों को संदेह था कि वाजपेयी को सरकार बनाने का निमंत्रण एक खिचड़ी था: वही।
371 क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उन्हें अन्य दलों का समर्थन मिल पाएगा: वही।
371 राव अभी तक प्रधानमंत्री आवास से बाहर नहीं निकले थे: शक्ति सिन्हा ने लेखक को बताया, 11 अप्रैल 2021
टेलीफोन पर साक्षात्कार।
371 खुफिया विफलताओं की जांच करने और 'भविष्य के लिए सिफारिशें करने' का कार्य सौंपा गया: के.

लेखक के लिए सुब्रमण्यम, 13 फरवरी 2005, नई दिल्ली।
372 ‘अटलजी, जिसने मुझसे पदभार संभाला। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था’: वही।
372 ‘राव ने मुझे बताया था कि बम तैयार है। मैंने बस उसे विस्फोट किया’: विक्की नंजप्पा, ‘द लीजेंड ऑफ
पोखरण: 'राव ने मुझे बताया था कि बम तैयार है, मैंने ही उसे विस्फोट किया', वाजपेयी ने कहा, वन इंडिया, 19 अगस्त 2018। हालांकि इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि राव ने 18 मई 1996 को हुई अपनी मुलाकात के दौरान वाजपेयी को परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन पी.वी. ने वाजपेयी को परीक्षण करने का संदेश कैसे दिया, इसके कई अन्य संस्करण भी हैं। कुछ का कहना है कि राव ने 16 मई 1996 को राष्ट्रपति भवन में वाजपेयी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें एक 'चिट्ठी' भेजी थी। चिट्ठी में लिखा था, 'सामग्री तैयार है, तुम आगे बढ़ सकते हो।' (सामग्री तैयार है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं।) नरसिम्हा राव ने बाद में एक साक्षात्कार में दावा किया कि उन्होंने वाजपेयी को एक पत्र दिया था। लेकिन वाजपेयी के सबसे करीबी सलाहकार ब्रजेश मिश्रा को पत्र के अस्तित्व पर संदेह था। 'वाजपेयी ने मुझसे कभी पत्र का जिक्र नहीं किया। मुझे उनकी आधिकारिक फाइलों में कुछ भी नहीं मिला।' हालांकि, मिश्रा ने पुष्टि की कि वाजपेयी ने राव से मिलकर उन्हें जानकारी दी थी। (सीतापति, हाफ लायन, पृ. 279; प्रभाकर राव, ‘पी वी नरसिम्हा राव’, फेसबुक, 17 अगस्त 2018, 16 मई 2022 को देखा गया, उपलब्ध है)
(<www.facebook.com/SirSriPvnarasimhaRaoGaru/
photos/1132931390195999>)
372 ‘मैंने वाजपेयी को ऐसा करने को कहा था’: नरेश चंद्र ने लेखक को, 8 मई 2004, नई दिल्ली।
18 मई 1996 को वाजपेयी के साथ अपनी मुलाकात में, राव ने नए प्रधानमंत्री से दो स्तरों पर अपील की: ब्रजेश मिश्रा से लेकर लेखक तक।
372 ‘1983 से शाफ्ट सील कर दिए गए थे’: के. संथानम ने लेखक को 1 दिसंबर को लिखा
2004, नई दिल्ली।

373 कई लोगों ने दोनों के बीच 'ब्राह्मणीय संबंध' भी देखा: भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक को बताया, 23
मार्च 2007, नई दिल्ली।
373 उन्होंने वाजपेयी के अधिकांश कर्मचारियों को बरकरार रखा था: राव, 'पी वी नरसिम्हा राव', फेसबुक।
373 'Ranjishe hee sahi dil dukhane ke liye aa, Aa phir se mujhe chorhne ke liye aa': Karan
सिंह द्वारा लेखक को पत्र, 16 मार्च 2023, नई दिल्ली। राणा सफवी द्वारा अंग्रेजी अनुवाद।
<ranasafvi.com/ranjish-hi-sahi-explained>
373 'Atalji mere haal kaal ke guru rahe hain': Sachidanand Murthy, 'Clash of the titans: When
वाजपेयी और नरसिम्हा राव के बीच तीखी बहस', द वीक, 4 फरवरी 1996।
373 दरअसल, वे आमतौर पर एक दूसरे को गुरुजी कहकर संबोधित करते थे: राव, 'पी वी नरसिम्हा राव',
फेसबुक।
373 'वाजपेयी मेरे और पीवी के बीच बैठे थे': भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक को 23 मार्च 2007 को लिखा।
नई दिल्ली।
374 'Dekhte hain, governor se baat karenge': Ibid.
374 'उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए': वही।
374 जब राव 26 अक्टूबर 1995 को न्यूयॉर्क से लौटे, तो मोतीलाल वोरा उनका इंतजार कर रहे थे:
दिलीप अवस्थी, 'उत्तर प्रदेश की लड़ाई', इंडिया टुडे, 15 नवंबर 1995।
375 'वाजपेयी ने नरसिम्हा राव को बरी कराने में मदद की': भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक से कहा, 23
मार्च 2007, नई दिल्ली।
375 16 मार्च 2002 को दिल्ली उच्च न्यायालय को जेएमएम मामले में राव और बूटा सिंह को बरी करना था।

रिश्वत का मामला: 'जेएमएम रिश्वत मामले में राव, बूटा बरी', टाइम्स ऑफ इंडिया, 16 मार्च 2002।

375 'ये राजनीतिक निर्णय हैं, बाकी (कानूनी पहलू) महज मामूली बातें हैं जिन पर काम किया जाता है':
भुवनेश चतुर्वेदी लेखक, 24 दिसंबर 2008, नई दिल्ली।

375 'प्रधानमंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही करना अच्छा नहीं है': आई. के. गुजराल
लेखक, 6 अक्टूबर 2003, नई दिल्ली। गुजराल ने यह बात भुवनेश चतुर्वेदी को भी बताई, जिन्होंने यह बात लेखक को बताई।

375 एल. के. आडवाणी के नेतृत्व में कुछ भाजपा नेताओं ने विरोध जताया: नीरजा चौधरी,
'रिश्वत कांड से लेकर दानदाता घोषित करने तक, जेएमएम के लिए पूरा चक्र', द इंडियन एक्सप्रेस, 25 अप्रैल 2021।

375 'वाजपेयी ने कभी पी.वी. को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की—और इसके विपरीत भी': भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक से कहा, 23
मार्च 2007, नई दिल्ली।

375 'कृपया कलाम को बुलाइए': शक्ति सिन्हा ने लेखक से कहा, 11 अप्रैल 2021, नई दिल्ली, टेलीफोन पर बातचीत
बातचीत।

376 'प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं': वही।

376 'पटाखा चोरना है': के. संथानम लेखक से, 1 दिसंबर 2004, नई दिल्ली।

376 'हम इसे उन तेरह दिनों में कर सकते थे जब वाजपेयी ने अपना मन बना लिया था': वही।

376 कुछ लोगों को लगा कि इससे उस तरह का उत्साह पैदा हो सकता था जो कुछ लोगों को विवश कर सकता था
राजनीतिक दलों को अपना रुख बदलना होगा: नरेश चंद्र ने लेखक को 8 मई 2004 को नई दिल्ली में लिखा।

377 Vajpayee personally met Kanshi Ram: Lakhbir Singh, Secretary Kanshi Ram Foundation,

कांशी राम के भतीजे ने 13 अप्रैल 2021 को टेलीफोन पर साक्षात्कार दिया।
377 ‘मैंने खुद जॉर्ज के लिए पीवी से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया था’: भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक से कहा, 23
मार्च 2007, नई दिल्ली।
377 ‘ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है’: वही।
377 उनके प्रति अमेरिका की सतर्कता कुछ ईमेल में परिलक्षित हुई: टंडन, 'अशोक टंडन:
अटल बिहारी वाजपेयी ने तमाम बाधाओं के बावजूद भारत की परमाणु क्षमता को स्थापित करने का बीड़ा उठाया।
377 किसी नामित राजदूत के लिए विदेश जाने से पहले विपक्षी नेता से मुलाकात करना असामान्य बात थी।
एक राजनयिक कार्य: वी. जी. वैद्य, सूचना सूचना प्रमुख, लेखक, 2018, मुंबई।
377 ‘राव को यह आभास था कि अमेरिका वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से वंचित करने के लिए पैरवी करेगा’:
अशोक टंडन, ‘अशोक टंडन: अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की परमाणु साख स्थापित करने के लिए तमाम बाधाओं का सामना किया’, द इकोनॉमिक टाइम्स, 17 अगस्त 2018।
378 ‘हम दोनों जानते थे कि वह क्या कहने आ रहा है’: नरेश चंद्र ने लेखक से 8 मई 2004 को कहा, न्यू
दिल्ली।
378 ‘कि हम भारत-अमेरिका संबंधों को महत्व देते हैं’: वही।
378 विस्नर, जो वाजपेयी से मिल चुके थे, उनकी 'शारीरिक भाषा' से आश्वस्त हो गए थे। (वर्गीकृत जानकारी)
विलियम बर्र द्वारा लिखित ‘द क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट दैट डिड नॉट हैपन - 1995-1996’, एनपीआईएचपी में उद्धृत अमेरिकी दूतावास भारत से विदेश विभाग को भेजे गए पत्र।
विल्सन सेंटर, जो www.wilsoncenter.org/publication/the-clinton-administration- पर उपलब्ध है।
और भारतीय परमाणु परीक्षण 1995-1996 में नहीं हुआ।

378 ‘इस परीक्षण के भारत-अमेरिका संबंधों पर “विनाशकारी परिणाम” होंगे’: नरेश चंद्र
लेखक को, 8 मई 2004, नई दिल्ली।
378 ‘कैसा चल रहा है?’: कृष्णकांत ने 2000 में लेखक से पूछा, जिसकी पुष्टि उनके बेटे रश्मी ने की।
कांट, 24 जून 2020, टेलीफोन पर हुई बातचीत।
379 में से भाजपा ने 182 सीटें जीतीं, जो 1996 में जीती गई 161 सीटों से अधिक हैं: 'सामान्य चुनाव पर सांख्यिकीय रिपोर्ट'
1998 में 12वीं लोकसभा के चुनाव: खंड I’, दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग
1998, <eci.gov.in/files/file/4124-general-election-1998-vol-i-ii> पर उपलब्ध है।
379 वाजपेयी अपने भोजन की मेज पर बैठे और अपने सचिव शक्ति सिन्हा को एनएजी का मसौदा लिखवाया:
सिन्हा, वाजपेयी, पृ. 61.
379 उन्हें लोकसभा में 267 सांसदों का समर्थन प्राप्त था: वही, पृष्ठ 62।
379 वह चाहती थीं कि अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाया जाए: ठाकुर, प्रधानमंत्री
मंत्रीगण, पृ. 407–408.
379 सामान्यतः उदार रहने वाले वाजपेयी ने स्वामी पर अपना रुख कड़ा कर लिया: वही।
379 उनके पास एआईडीएमके और उसके सहयोगियों से तीस सांसद थे: सिन्हा, वाजपेयी, पृ. 65.
379 यह तभी हुआ जब सोनिया गांधी ने अपना दावा पेश करने से इनकार कर दिया: 'वाजपेयी शपथ ग्रहण करेंगे'
गुरुवार को दस दिनों में बहुमत साबित करना होगा’, रेडिफ डॉट कॉम, 15 मार्च 1998।
379 ‘मैंने खुद सूची टाइप की थी’: शक्ति सिन्हा ने लेखक से कहा, 11 अप्रैल 2021, टेलीफोनिक साक्षात्कार।
वाजपेयी के दत्तक दामाद, जो होटल उद्योग में थे, ने यह सुनिश्चित किया कि भोजन में

कोई अशुद्धि न हो।
कोई टमाटर: वही।
380 इसे 19 मार्च 1998 की सुबह राष्ट्रपति भवन ले जाया गया: वही।
380 वाजपेयी सुबह 7.30 बजे नाश्ते के लिए बैठे: सिन्हा, वाजपेयी, पृ. 12.
380 'अगर मैं वित्त मंत्रालय अपने पास रखूं तो क्या होगा?': शक्ति सिन्हा ने लेखक से पूछा, 11 अप्रैल 2021
टेलीफोन पर साक्षात्कार।
381 वाजपेयी को स्वयं वित्त मंत्रालय नहीं संभालना चाहिए, आडवाणी ने जवाब दिया: शक्ति सिन्हा ने लेखक को 11 अप्रैल को लिखा।
2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
381 चार घंटे के भीतर, वाजपेयी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी: नीरजा चौधरी, 'अकेलेपन का
Atal Behari Vajpayee', Indian Express, 27 April 1998.
381 'वाजपेयी यशवंत सिन्हा को लेकर उत्सुक नहीं थे': शक्ति सिन्हा ने लेखक से कहा, 11 अप्रैल 2021
टेलीफोन पर साक्षात्कार।
381 उस समय यशवंत सिन्हा आरएसएस में स्वदेशी लॉबी के करीबी माने जाते थे: शक्ति
सिन्हा, 'वाजपेयी के आर्थिक दृष्टिकोण को समझने के लिए, वित्त मंत्री के लिए उनकी पहली पसंद को देखें', द प्रिंट, 25 दिसंबर 2020।
381 उन्होंने वाजपेयी को यह भी बताया कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल में किसे रखना चाहिए: प्रभु चावला, "गठबंधन के सहयोगी चाहते हैं
वाजपेयी अपनी सत्ता स्थापित करेंगे", इंडिया टुडे, 27 अप्रैल 1998।
381 'नहीं, कृपया उन्हें नारियल पानी पिलाइए': शक्ति सिन्हा ने लेखक से कहा।
382 स्वामी ने सरकार में एक अन्य मंत्री राम जेठमलानी को 'झूठमलानी' कहा: के. एम.
थॉमस और के. गोविंदन कुट्टी, 'एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता की दबाव की रणनीति ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को पंगु बना दिया', इंडिया टुडे, 4 मई 1998।

382 ‘लोगों के पास वापस जाना’ बेहतर होगा: वही।
382 अप्रैल की शुरुआत तक, लोगों को यह आश्चर्य होने लगा था कि सरकार कितने समय तक टिकेगी: चौधरी,
‘अटल बिहारी वाजपेयी का अकेलापन’।
382 Harkishan Singh Surjeet and Jyoti Basu even dubbed his government as ‘anti-national’:
प्रभु चावला, “गठबंधन सहयोगी चाहते हैं कि वाजपेयी अपना अधिकार जताएं”, इंडिया टुडे, 27 अप्रैल 1998।
382 उनकी जगह एक अपरिचित व्यक्ति ने ले ली थी—‘कमजोर, थका हुआ, हतोत्साहित’: मणि
शंकर अय्यर, ‘बेचारे वाजपेयी पर तरस आता है: अगले 300 तो और भी बदतर होने वाले हैं’, इंडिया टुडे, 11 मई 1998।
382 ‘एक समय ऐसा आया जब हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया’: शक्ति सिन्हा
लेखक को, 11 अप्रैल 2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
382 क्या वाजपेयी में देश पर शासन करने की क्षमता है: चौधरी, 'अटल की एकांतता'
Behari Vajpayee’.
382 जिन्हें विपक्ष ने 'गलत पार्टी में सही आदमी' कहने के लिए पर्याप्त सम्मान दिया: वही।
382 टिप्पणीकारों ने उनसे कुछ 'साहसी' करने का आग्रह किया: वही।
383 ‘वह शक्ति प्राप्त करना चाहता था’: भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक को 14 अक्टूबर 1999 को लिखा, न्यू
दिल्ली।
383 वाजपेयी ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध पर वैश्विक वार्ताओं पर बारीकी से नजर रखी थी।
संधि: सिन्हा, वाजपेयी, पृ. 16.
383 ‘अटलजी ने उस विशेष समय पर परीक्षा कराने का विकल्प चुनने के पीछे अपने राजनीतिक विचार भी रखे थे’:

लेखक के रूप में ब्रजेश मिश्र, 30 नवंबर 2004, नई दिल्ली।
383 'हम इस तरह झगड़ते नहीं रह सकते': बी. रमन, 'बृजेश मिश्रा (1928-2012)', आउटलुक,
3 फरवरी 2022।
383 'हमारी कई चर्चाएँ हुईं। इससे हम एक-दूसरे के और करीब आ गए': ब्रजेश मिश्रा ने लेखक से कहा, 30
नवंबर 2004, नई दिल्ली।
383 'मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रधान सचिव बनें': ब्रजेश मिश्रा, 16 सितंबर 2005, न्यू
दिल्ली।
384 'मुझे कोई ऐसा चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ': वही।
384 'आप प्रधानमंत्री को ना नहीं कह सकते': वही।
384 प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद वाजपेयी द्वारा हस्ताक्षरित पहला आदेश मिश्रा को नियुक्त करना था।
उनके प्रधान सचिव: सिन्हा, वाजपेयी, पृ. 15.
384 'उनकी सहज प्रवृत्ति अद्भुत थी': ब्रजेश मिश्रा, 16 सितंबर 2005, नई दिल्ली।
384 'हम इस बारे में बाद में बात करेंगे': वही।
384 'मुझे वाजपेयी पसंद हैं। मुझे आडवाणी पर भरोसा नहीं है': सोनिया गांधी ने लेखक से कहा, 10, जनपथ, नई दिल्ली।
384 मिश्रा ने स्वयं प्रधानमंत्री के साथ अपने रिश्ते को 'सहजीवी' बताया: ब्रजेश मिश्रा, 16
सितंबर 2005, नई दिल्ली।
384 'प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री से किसी भी घोटाले की हल्की सी भी भनक नहीं आनी चाहिए'
'हाउस': रश्मी कांत ने लेखक को बताया। उनके पिता, कृष्ण कांत को यह बात ब्रजेश मिश्रा ने बताई थी।
385 6 अप्रैल 1998 को सुबह 7.25 बजे, पाकिस्तान ने मालूट से सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया:
हसन अख्तर, 'लक्ष्य त्रुटिरहित रूप से भेदा गया: पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने

गौरी मिसाइल का परीक्षण किया', डॉन वायर सर्विस, 11 अप्रैल 1998।
385 परीक्षण की गई मिसाइल ने उस दिन 1,100 किलोमीटर की दूरी तय की थी: ज़ाहिद हुसैन और
हरिंदर बावेजा, 'पाकिस्तान ने अपनी नवीनतम मिसाइल का परीक्षण किया, वाजपेयी सरकार इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच बढ़ते गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए आम सहमति बनाएगी', इंडिया टुडे, 20 अप्रैल 1998।
385 उन्होंने मिश्रा से वैज्ञानिकों की एक आपातकालीन बैठक बुलाने को कहा: चेंगप्पा, शांति के हथियार,
पृष्ठ 45.
385 'टकराव की पुरानी मानसिकता': बावेजा, 'पाकिस्तान ने अपनी नवीनतम मिसाइल का परीक्षण किया', वाजपेयी
सरकार को इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच बढ़ते गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए आम सहमति बनानी होगी।
385 भाजपा द्वारा भारत के परमाणु शक्ति बनने के सार्वजनिक बयान चिंता का एक बड़ा कारण हैं।
हमारे लिए': वही।
385 'घौरी के परीक्षण का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को संकेत भेजना था': वही।
385 'हमारी समझ यह है कि गौरी की जननी चीन है': मनोज जोशी, 'चीन के बावजूद'
पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों में सहायता करने के बावजूद, भारत उसे एक सौम्य शक्ति के रूप में देखता है', इंडिया टुडे, 27 अप्रैल 1998।
385 'यह मामला पाकिस्तान के साथ उठाना अमेरिका पर निर्भर है': चिंतामणि महापात्रा, 'द यूएस,
चीन और गौरी मिसाइल', आईडीएसए, <www.idsa-india.org/an-jun8-4.html> पर उपलब्ध है।
385 इसने 1992 और 1994 के बीच पाकिस्तान को पचास से अधिक एम-11 मिसाइलों की आपूर्ति की थी: जोशी, 'इसके बावजूद
चीन पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों में सहायता कर रहा है, भारत उसे एक सौम्य शक्ति के रूप में देखता है।

386 भारत को जल्द ही एहसास हो गया कि वाशिंगटन चीनी संबंधों को 'छिपाने' की कोशिश कर रहा था:
महापात्रा, 'अमेरिका, चीन और गौरी मिसाइल'।
386 'घौरी मिसाइल दागने से कोई परमाणु दौड़ शुरू नहीं होगी': वही।
गौरी मिसाइल के प्रक्षेपण के 386 घंटे बाद, चिंतित ब्रजेश मिश्रा ने सुरक्षा रणनीतिकार के. को बुलाया।
सुब्रह्मण्यम: लेखक के रूप में ब्रजेश मिश्र, 30 नवंबर 2004, नई दिल्ली।
386 'मुझे कभी यह ख्याल ही नहीं आया,' सुब्रह्मण्यम ने बाद में कहा, 'कि वे परीक्षा देने जाएंगे':
के. सुब्रह्मण्यम लेखक के लिए, 1 जून 2004, नई दिल्ली।
386 'हमने 8 अप्रैल (1998) को एक परीक्षण कराने का फैसला किया': ब्रजेश मिश्रा ने लेखक को 30 नवंबर को बताया
2004, नई दिल्ली।
386 कलाम राजनेताओं के साथ संपर्क बनाए रखने को 'एक विशेष बात' मानते थे: के. संथानम ने लेखक को बताया, 7
दिसंबर 2004, नई दिल्ली।
387 'हमें मार्च 1998 के अंत तक सक्रिय कर दिया गया था': वही।
387 'केबल बहुत ही उचित स्थिति में थे': वही।
387 'तो आप इसे कैंडललाइट डिनर के बजाय केबल बिछाने के लिए कैंडललाइट लेआउट कह सकते हैं': वही।
387 'वहाँ तीन क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए थे और उनकी तस्वीरें भेजी जाती थीं। नियंत्रण कक्ष 2 किलोमीटर दूर है': वही।
387 'यद्यपि गड्ढे उनके आराम के लिए बहुत गीले थे': वही।
387 'शाफ़्टों को भरने का काम एक ही रात में पूरा करना होगा अन्यथा परिवर्तन हो जाएगा
पता लगाया जा सकता है': वही।
388 'लेकिन जब तक अमेरिकियों को पता चला, तब तक घटना समाप्त हो चुकी थी': वही।
388 और, निश्चित रूप से, उनकी सरकार को कुछ बड़ा करने की तत्काल

आवश्यकता थी।
विश्वसनीयता: सिन्हा, वाजपेयी, पृ. 100.
388 ‘मैं चीजों को लेकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता था’: ब्रजेश मिश्रा, 30 नवंबर 2004, न्यू
दिल्ली।
388 ‘हमें अमेरिकियों को यह संकेत देना होगा कि उन्हें हमें गंभीरता से लेना होगा’: ब्रजेश
मिश्रा से लेखक को, 2009।
388 लेकिन परमाणु परीक्षणों के मामले में 'वास्तविक निर्णय लेने वाला' वही था: के. सुब्रह्मण्यम ने लेखक को बताया।
388 ‘इसका श्रेय उन्हें ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने वाजपेयी का पूरक कार्य किया’: आर. चिदंबरम ने लेखक से कहा।
31 मार्च 2021, टेलीफोन पर हुई बातचीत।
388 ‘बृजेश ने मई 1998 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई’: नरेश चंद्र ने लेखक को, नवंबर 2000।
388 विडंबना यह है कि यह एक और नौकरशाह, उनके विदेश सचिव जगत सिंह मेहता थे: के.
सुब्रह्मण्यम ने लेखक को 2004 में लिखा।
389 मेहता का मानना था कि उपमहाद्वीप का भविष्य भारत द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ शांति स्थापित करने में निहित है:
टी. पी. श्रीनिवासन, ‘राजनीतिक कांटों का ताज’, द हिंदू, 2 फरवरी 2015।
389 उन्होंने वाजपेयी को इस विचार के प्रति 'बहुत ग्रहणशील' पाया: अजय मेहता, जगत मेहता के पुत्र, लेखक को।
24 मार्च 2021।
वाजपेयी द्वारा परीक्षण का निर्णय लेने के एक सप्ताह बाद, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत बिल 389 ने कहा कि परीक्षण का निर्णय लेने के एक सप्ताह बाद, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत बिल ने कहा कि परीक्षण का निर्णय लिया गया था।
रिचर्डसन: मनोज जोशी, ‘वाजपेयी सरकार का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया’, इंडिया टुडे, 27 अप्रैल 1998।

389 ‘बिल्कुल नहीं,’ फर्नांडीस ने भावहीन चेहरे से जवाब दिया: टैलबॉट, एंगेजिंग इंडिया, पृ. 47.
389 जसवंत सिंह से ‘ऑफ़लाइन’ मिलते हैं—अर्थात निजी तौर पर: वही।
389 ‘वाशिंगटन के लिए एक विवेकपूर्ण—और यदि आवश्यक हो, तो गुप्त—चैनल’: वही।
390 इससे किसी भी तरह के ‘लीकेज’ को होने से भी रोका जा सकेगा: वही।
390 ‘बृजेश मिश्रा ने मुझे 8 मई को फोन किया था’: जनरल वी. पी. मलिक ने लेखक को अक्टूबर 2004 में लिखा।
29 मार्च 2021 को पुनः पुष्टि की गई।
390 अब समय आ गया था कि ‘तीनों प्रमुखों को बुलाया जाए और उन्हें जानकारी दी जाए’: ब्रजेश मिश्रा ने लेखक को बताया।
390 ‘जब हम पहुंचे, तो ब्रजेश मिश्रा और अब्दुल कलाम पहले से ही वहां बैठे थे’: जनरल वी.
पी. मलिक लेखक को।
390 प्रमुखों से तैयारियों के बारे में पूछने के अलावा, प्रधानमंत्री ने 'ज्यादा कुछ नहीं कहा': वही।
391 ‘हमने प्रधानमंत्री से पाकिस्तान द्वारा परीक्षण की संभावना के बारे में बात नहीं की’: जनरल वी. पी. मलिक
लेखक को।
391 ‘प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि उन्होंने परीक्षा से दो दिन पहले अपने राजनीतिक सहयोगियों को इस बारे में सूचित कर दिया था’: ब्रजेश
मिश्रा से लेखक को, 30 नवंबर 2004, नई दिल्ली।
391 ‘मुझे यकीन नहीं है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें परीक्षणों की सटीक तारीख बताई थी’: वही।
391 ‘इसमें प्रधानमंत्री आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीस और जसवंत सिंह ने भाग लिया’: शक्ति सिन्हा ने कहा
लेखक, 11 अप्रैल 2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
391 ‘पहले परमाणु हथियारों को खारिज नहीं किया गया था, अब उन्हें स्वीकार कर लिया गया है’: सिन्हा, वाजपेयी, पृ. 97.

391 चीनियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे 'बिल्कुल हास्यास्पद' बताया: वही।
391 प्रधानमंत्री के बुलावे पर वे वाजपेयी के घर पहुंचे: यशवंत सिन्हा लेखक को।
2018, 11 अप्रैल 2021 को पुनः पुष्टि की गई।
392 ‘मैं आर्थिक परिणामों और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचता रहा’: वही।
392 उसी सप्ताह, 11 मई 1998 को, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइज़र ने लिखा: 'क्या आरएसएस को इस बारे में सूचित किया गया था?'
'एन-परीक्षणों की प्रगति?', द हिंदू, 13 मई 1998।
392 ‘हम अपने परमाणु विकल्प को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते’: जॉन एफ. बर्न्स, ‘परमाणु चिंता:
संक्षिप्त विवरण: प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने दो और परमाणु परीक्षण किए’, न्यूयॉर्क टाइम्स, 14 मई 1998।
393 ‘Bhaiya, aap zara paanch number aa jaiye’: Yashwant Sinha to author 11 April 2021,
टेलीफोन पर साक्षात्कार।
393 जसवंत सिंह ने कुछ नहीं कहा। सिन्हा के अलावा उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज को भी फोन किया था:
वही।
393 वाजपेयी ने व्यक्तिगत रूप से आडवाणी को फोन किया था और उन्हें आने के लिए कहा था: ब्रजेश मिश्रा
लेखक, नई दिल्ली।
393 ‘तो, सुरक्षा संबंधी पूरी कैबिनेट समिति वहाँ मौजूद थी’: यशवंत सिन्हा 11वीं पुस्तक के लेखक बनेंगे
अप्रैल 2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
393 ‘हमें इसे सुबह 8 बजे से पहले करना था’: के. संथानम ने लेखक को 7 दिसंबर 2004 को लिखा, न्यू
दिल्ली।
393 लेकिन जब ‘हमने गड्ढा देखा तब…उत्साह उत्पन्न हुआ’: वही।

394 'सर, हमने यह कर लिया है': के. संथानम लेखक से, 1 दिसंबर 2004, नई दिल्ली; चेंगप्पा,
शांति के हथियार, पृष्ठ 432।
394 'ईश्वर आपका भला करे': चेंगप्पा, शांति के हथियार, पृ. 432.
394 वे राहत के आंसू थे, गर्व की भावना के आंसू थे, और 'आखिरकार इसे कर दिखाने' के आंसू थे: सिन्हा।
वाजपेयी, पृष्ठ 99.
394 वाजपेयी राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति भवन गए थे: चेंगप्पा, हथियार
शांति, पृष्ठ 5.
394 'ताकि वह (विदेश में रहते हुए) असहज प्रश्नों से बच सके': के. सुब्रह्मण्यम को लेखक, 13 फरवरी 2005, नई दिल्ली।
394 'मुझे इसके बारे में सबसे पहले कृष्णकांत ने बताया था': वही।
394 'Aap jo chahte rahen hain, woh hum karne jaa rahe hain': Krishan Kant to author in 2000,
रश्मी कांत द्वारा 13 जून 2020 को टेलीफोन पर हुई बातचीत में इसकी पुनः पुष्टि की गई।
394 'अभी-अभी प्रधानमंत्री ने मुझसे बात की... मैंने यह बात अभी तक किसी को नहीं बताई है': के. सुब्रह्मण्यम, 21
मई 2004, नई दिल्ली।
395 'परमाणु परीक्षण में थर्मो-परमाणु परीक्षण (उर्फ हाइड्रोजन बम) शामिल था': वही।
395 'हमें...परिणामों को कैसे प्रबंधित किया जाए और घोषणा कैसे की जाए, इस पर चर्चा करनी थी':
यशवंत सिन्हा लेखक बनेंगे।
395 Brajesh Mishra and Jaswant Singh dictated it to Shakti Sinha: Sinha, Vajpayee, p. 100.
395 उन्होंने जानबूझकर उस बयान का वर्णन करने के लिए 'संक्षिप्त' शब्द को हटा दिया जिसे उन्हें पढ़ना था:

यशवंत सिन्हा ने 11 अप्रैल 2021 को टेलीफोन पर साक्षात्कार दिया।
395 ‘आज दोपहर 3:45 बजे भारत ने पोखरण में तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण किए।
'रेंज': लेखक उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेस कोर्स रोड पर मौजूद थे।
396 पश्चिमी वैज्ञानिकों के एक समूह ने बाद में भारत के 5 किलोटन उत्पादन के दावे पर सवाल उठाया।
परमाणु परीक्षणों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया: राज चेंगप्पा, 'पश्चिमी वैज्ञानिकों के शोध ने एच-बम के सफल परीक्षण के भारत के दावों का खंडन किया', इंडिया टुडे, 12 अक्टूबर 1998।
396 ‘भारत अब एक परमाणु हथियार संपन्न देश है’: प्रभु चावला, ‘एक मजबूत और आत्मविश्वासी भारत का उदय:
अटल बिहारी वाजपेयी का मई 1998 के परमाणु परीक्षणों पर बयान, इंडिया टुडे, 25 मई 1998।
396 वाजपेयी ने सीटीबीटी या एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया क्योंकि वे
भेदभावपूर्ण: वही।
396 वे यह भी देखना चाहते थे कि आसपास की बस्तियों में बने घरों में कोई दरारें तो नहीं हैं:
लेखक के. संथानम, 7 दिसंबर 2004, नई दिल्ली।
397 'इस बात से चिंतित हैं कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण कुछ प्रदूषण हो सकता है।
परमाणु परीक्षण स्थल के आसपास के भूमिगत जलभंडार’: कल्पना शर्मा, ‘तूफान का फल भोगना’, द हिंदू, 13 नवंबर 1998।
397 लेकिन अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को 'वैज्ञानिक आधारहीन' बताकर खारिज कर दिया: श्वेता देसाई,
पोखरण परमाणु परीक्षण के चालीस साल बाद, ग्रामीण कैंसर से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या की शिकायत कर रहे हैं।
Scroll.in, 18 मई 2014।
397 ‘मैं आपको पहले पृष्ठ पर जगह दूंगा’: के. सुब्रह्मण्यम ने लेखक से कहा।

397 सुब्रमण्यम का लेख मुखपृष्ठ पर 'समाचार विश्लेषण' के रूप में प्रकाशित हुआ: के. सुब्रमण्यम,
‘भारत अब परमाणु हथियार संपन्न पांच देशों के क्लब में शामिल हो गया है’, टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 मई 1998।
397 और उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह चीन, रूस और पाकिस्तान को 'संयुक्त रूप से पहले नहीं' में शामिल होने के लिए आमंत्रित करे।
उपयोग घोषणा’: वही।
398 लेकिन ‘उन्हें यह घोषणा करने में चार महीने लग गए कि भारत इसका पहले उपयोग नहीं करेगा’: के. सुब्रह्मण्यम
लेखक को, 21 नवंबर 2004, नई दिल्ली।
398 अब उन्हें आगे के कदमों पर चर्चा करनी होगी: यशवंत सिन्हा को
लेखक, 11 अप्रैल 2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
398 ‘उसे बताओ कि परमाणु परीक्षण करने के लिए हमारे दिमाग में पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन था’: वही।
398 ‘हम आपके देश के साथ अपनी मित्रता और सहयोग को महत्व देते हैं’: जॉर्ज पेरकोविच, ‘परीक्षण और
'प्रभाव', इंडियन एक्सप्रेस, 11 मई 2018।
398 प्रधानमंत्री ने चीन को परीक्षण करने के उसके फैसले के लिए सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहराया था: शक्ति सिन्हा।
वाजपेयी, पृष्ठ 106.
398 उनके बारे में सुनकर वह 'ज्वालामुखी आवेश' में आ गए: टैलबॉट, एंगेजिंग इंडिया, पृ. 52.
398 अमेरिकी राष्ट्रपति ने परमाणु कार्यक्रमों को वापस लेने के लिए 'व्यक्तिगत पहल' की थी।
भारत और पाकिस्तान दोनों: के. पी. नायर, ‘भविष्यवाणी का रहस्य बताने का समय’, द टेलीग्राफ (कलकत्ता), 24 दिसंबर 2004।
399 चीन की प्रतिक्रिया, जो शुरू में शांत थी, वाजपेयी द्वारा चीन को इसका कारण बताए जाने के बाद तीव्र हो गई।
डी’एत्रे: सिन्हा, वाजपेयी, पृ. 102.

यदि भारत उदारीकरण और अमेरिका के साथ आर्थिक जुड़ाव जारी रखता है, तो 399
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को स्वीकार कर लेगा: लेखक मोंटेक सिंह अहलूवालिया का कहना है।
अनुच्छेद 399 में कहा गया है कि राजीव गांधी द्वारा (पर्याप्त संख्या में हथियार बनाने के लिए) लिया गया '1988 का निर्णय'
इसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया है: सिन्हा, वाजपेयी, पृ. 107.
400 वाजपेयी उनसे यह आंदोलन शुरू करने के लिए कह रहे थे कि भारत को सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए: बी. एन.
उनियाल ने लेखक से 27 फरवरी 2021 को टेलीफोन पर बातचीत की।
400 'मुझे इसके कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं': बी. एन. उनियाल ने लेखक से 4 मार्च 2021 को टेलीफोन पर साक्षात्कार में कहा।
400 'अगर भारत ने बम विस्फोट नहीं किया होता, तो पाकिस्तान ऐसा नहीं करता': '28 मई 1998-
पाकिस्तान परमाणु परीक्षण', सीटीबीटीओ, <www.ctbto.org/specials/testing-times/28-may-1998->
पाकिस्तान परमाणु परीक्षण>
400 दोनों पक्षों ने अपने देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की: जसवंत सिंह से
लेखक, 15 जनवरी 2005, नई दिल्ली।
400 दोपहर के भोजन की व्यवस्था एक महीने पहले की गई थी: हरिंदर बावेजा, 'आपसी संदेह, कठोरता'
वाजपेयी-नवाज शरीफ की मुलाकात में संभावित राजनीतिक रुख', इंडिया टुडे, 3 अगस्त 1998।
401 'कोलंबो में नवाज़ शरीफ़ के साथ हमारी एक-एक बैठक हुई': ब्रजेश मिश्रा ने लेखक को बताया,
30 नवंबर 2004, नई दिल्ली।
401 'दिल्ली से लाहौर के लिए बस क्यों नहीं होनी चाहिए?': जसवंत सिंह ने लेखक से 15 जनवरी को पूछा

2005, नई दिल्ली।
401 दोनों प्रधानमंत्रियों ने 'बस' यात्रा के विचार पर तुरंत सहमति जताई: ब्रजेश मिश्रा से
लेखक, 30 नवंबर 2004, नई दिल्ली।
401 ‘इसका उद्देश्य लोगों की कल्पना को आकर्षित करना था’: जसवंत सिंह ने लेखक से कहा, 15 जनवरी 2005, न्यू
दिल्ली।
401 भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु संबंधी चिंताओं का ध्यान रखने और अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए पर्याप्त परिपक्व थे।
मुद्दों का ‘द्विपक्षीय’ समाधान: ए. के. वर्मा, ‘अटल बिहारी की लाहौर यात्रा: सीमाएँ और उपलब्धियाँ’, शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान, 11 मार्च 1999।
401 ‘Yeh loha aur ispaat ki bus nahi hai. Yeh hamare dono mulko ke awam ke jasbaaton ke baat
है’: जसवंत सिंह ने लेखक को 5 जनवरी 2005 को नई दिल्ली में लिखा।
401 नवाज़ शरीफ ने कहा कि उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी नहीं थी, हालांकि इस बात पर विवाद है: इम्तियाज़
अहमद, “नवाज शरीफ कारगिल में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ से अनभिज्ञ थे”, हिंदुस्तान टाइम्स, 2 जून 2018।
402 ने भारत से सुरक्षा मुद्दों पर गंभीरता से बातचीत करने की इच्छा दिखाई: सी. राजा मोहन
लेखक, 3 अप्रैल 2022, वीडियो कॉल।
402 अमेरिकियों के लिए, भारतीय परीक्षण 'एक बहुत गंभीर खुफिया विफलता' के रूप में सामने आए थे: टैलबॉट,
एंगेजिंग इंडिया, पृष्ठ 50।
402 लेकिन कुछ भारतीय ऐसे भी थे जिन्हें संदेह था कि अमेरिकी विफलता 'मनगढ़ंत' थी: पल्लव
बागला ने लेखक से 21 मार्च 2021 को टेलीफोन पर साक्षात्कार लिया।
403 ‘भारत में किसी भी संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका: उसे दो परतों में लपेटना’: ब्रह्मा चेलानी,

'क्लिंटन की यात्रा: प्रचार और वास्तविकता', रेडिफ डॉट कॉम, 28 मार्च 2000।
403 यह कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कम से कम 300 सांसदों ने उनसे हाथ मिलाया होगा।
क्लिंटन: जैसा कि लेखक ने अनुमान लगाया था, जो उस दिन संसद में उपस्थित थे।
403 'कई सांसद क्लिंटन की कुर्सी बचाने के लिए कुछ दिनों तक अपने हाथ भी नहीं धोते।
स्पर्श': वही।
403 'भारत का परमाणु परीक्षण पर दांव' सफल रहा: चेलेनी, 'क्लिंटन की यात्रा: प्रचार और
वास्तविकता'।
403 हालाँकि उस समय यह 'नियामक और सुरक्षा मुद्दों' तक ही सीमित था: श्याम सरन, हाउ इंडिया
दुनिया को देखता है: कौटिल्य से मोदी तक: कौटिल्य से 21वीं सदी तक, नई दिल्ली: जगरनॉट बुक्स, 2017।
403 'केवल परमाणु शक्ति बनने से ही अमेरिकी हमारे साथ चलने को तैयार हुए': सी.
राजा मोहन द्वारा लेखक को, 3 अप्रैल 2022, नई दिल्ली।
404 वाजपेयी ने 'एक अधिकारी पर भरोसा करना' चुना था: एल. के. आडवाणी ने लेखक को बताया।
405 'जब परिवार के लोग बाहर जाते थे, तो शाम को ब्रजेश या मैं उसकी देखभाल करते थे': अशोक सैकिया
लेखक को।
405 आडवाणी विजय कपूर को चाहते थे: लेखक ब्रजेश मिश्र, 30 नवंबर 2004, नई दिल्ली।
405 'अडवानी को अचानक पता चला...वाजपेयी पर मेरा...मजबूत प्रभाव': वही।
405 'अडवानी को यह पसंद नहीं आया। न ही जसवंत सिंह को': वही।
405 'आरएसएस ने भी हस्तक्षेप किया': वही।
405 'अगर हम दोपहर का भोजन करेंगे तो न तो वह बात करेगा और न ही मैं बात करूंगा': वही।

406 कई लोगों को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें सोनिया गांधी, जयललिता और अन्य लोगों ने सत्ता से बेदखल किया है।
सुब्रमण्यम स्वामी: चुनाव कवरेज के दौरान लेखक के अनुभव पर आधारित।
406 आरएसएस के एक नेता ने वाजपेयी से मुलाकात की और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा: सीतापति, 'द स्पेक्टर ऑफ'
नरेंद्र मोदी (1999-2004)', जुगलबंदी।
406वाजपेयी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से 'राज धर्म' का पालन करने का आग्रह किया: शोभित सुजय,
'कांग्रेस ने मोदी पर हमला करने के लिए 2002 के गुजरात दंगों के बाद वाजपेयी की राजधर्म टिप्पणी का मुद्दा उठाया', इंडियन एक्सप्रेस, 11 अप्रैल 2014।
406 एक सप्ताह बाद वह मोदी के कार्यों की व्याख्या कर रहे थे: सीतापति, 'द स्पेक्टर ऑफ'
नरेंद्र मोदी (1999-2004)', जुगलबंदी।
406 जून 2002 की शुरुआत में, टाइम पत्रिका ने वाजपेयी पर एलेक्स पेरी का एक लेख प्रकाशित किया: एलेक्स पेरी,
'क्या गाड़ी चलाते समय नींद आ रही थी?', टाइम पत्रिका, 10 जून 2002।
406 वाजपेयी खेमे ने इसे आडवाणी की ओर से किया गया एक 'दुष्कर्म' माना: शक्ति सिन्हा
लेखक, 11 अप्रैल 2021, टेलीफोन पर साक्षात्कार।
406 इससे वह प्रतिशोधी प्रतीत हुआ: वही।
407 प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर सूचित किया कि एनडीए और कांग्रेस
रश्मि कांत ने लेखक को 25 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में लिखा कि वे दोनों राष्ट्रपति पद के लिए उनका समर्थन करेंगे।
407 'ये तो अडवाणी ने गरबर कर दिए थे': ब्रजेश मिश्र से रश्मी कांत, जुलाई 2012; रश्मि
कांट ने लेखक को 25 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में पत्र लिखा।
407 'कमलाजी को बता देना, मैं दोपहर के भोजन पर आ रहा हूँ और सिंधी कढ़ी खाऊँगा': अज्ञात सूत्र ने कहा

लेखक।
407 वाजपेयी ने आरएसएस के सामने झुक गए थे: ब्रजेश मिश्रा, 30 नवंबर 2004, नई दिल्ली।
407 ‘पूरी पार्टी मेरे पास आई, मैं क्या करूँ?’: वही।
407 ‘शायद चीजें अलग होतीं’: वही।
407 पांच साल सत्ता में रहने के बावजूद, कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या 145 से बढ़ाकर 206 कर ली:
क्रिस्टोफ़ जैफ़्रेलॉट और गाइल्स वर्नियर्स, 'भारत के 2009 के चुनाव: क्षेत्रवाद और जातीयता का लचीलापन', दक्षिण एशिया बहुविषयक अकादमिक जर्नल, संख्या 3, 2009।
408 वाजपेयी कश्मीर समस्या के समाधान के प्रयासों के लिए अधिक याद किया जाना चाहते थे:
वाजपेयी ने यह बात लेखक को 6 से 14 फरवरी 1999 के बीच त्रिनिदाद, टोबैगो, जमैका और मोरक्को की यात्रा के दौरान हुई बातचीत में बताई थी। उनके ये बयान लाहौर यात्रा, कारगिल और आगरा शिखर सम्मेलन से पहले एक अनौपचारिक बातचीत में दिए गए थे।
408 यह आडवाणी ही थे जिन्होंने अंतिम बयान को खारिज कर दिया था जिसे अंतिम रूप दे दिया गया था: मुरासोली
मारन ने एक निजी बातचीत में लेखक को आगरा शिखर सम्मेलन के बारे में बताया।
408 that it was through a spirit of ‘Kashmiriyat, Insaniyat, Jamooriyat’: ‘Atal Bihari Vajpayee’s
“Insaniyat, Jamhuriyat, Kashmiriyat” is the foundation for peace in Kashmir’, Firstpost, 16 August 2018.

अध्याय 6: कम आंका गया प्रधानमंत्री जिसने विजय प्राप्त की: मनमोहन

सिंह और भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता
410 ‘[इसने] संकेत दिया कि व्हाइट हाउस में यह कोई साधारण शाम नहीं थी’:

रॉक्सेन रॉबर्ट्स, 'ए बुश
'गुलाबी हाथी जितना दुर्लभ डिनर', वाशिंगटन पोस्ट, 19 जुलाई 2005।
410 अखबार ने शाम को 'गुलाबी हाथी जितना दुर्लभ बुश डिनर' के रूप में वर्णित किया: वही।
410 रात्रिभोज का उद्देश्य 'भारत के प्रति सम्मान' था: वही।
411 'अगर तेल की कीमतें 100 डॉलर तक पहुंच जाती हैं, तो इससे भारत को नुकसान होगा': प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का बयान
'चार्ली रोज शो' पर साक्षात्कार, 27 फरवरी 2006, मीडिया सेंटर, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।
411 'मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?': एम. के. नारायणन ने लेखक से 8 अगस्त 2022 को टेलीफोन पर बातचीत की।
बातचीत, चेन्नई।
411 मनमोहन सिंह ने सबसे पहले नागरिक परमाणु ऊर्जा पर अमेरिका के साथ सहयोग की बात कही थी:
'चार्ली रोज शो में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का साक्षात्कार', 21 सितंबर 2004, मीडिया सेंटर, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।
411 'भारत को पूर्ण विकसित परमाणु हथियार संपन्न राज्य के रूप में सभी अधिकारों के साथ-साथ उसकी स्थिति की पुष्टि करता है'
दायित्व': श्याम सरन, भारत दुनिया को कैसे देखता है: कौटिल्य से मोदी तक: कौटिल्य से 21वीं सदी तक, नई दिल्ली: जगर्नॉट बुक्स, 2017, पृ. 204.
411 'मैं आपके साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक हूं': राज चेंगप्पा, 27 अगस्त 2007, 'सौदे की सफलता'
'जीत हासिल कर ली गई', इंडिया टुडे।
411 'विश्व का आठवां अजूबा': 'हमारा इतिहास: वर्षों से ग्लेनेगल्स', ग्लेनेगल्स, <gleneagles.com/explore/hotel-grounds/history> पर उपलब्ध है।
411 'एक मजबूत संबंध मूल्यों के साथ-साथ (सामान्य) हितों पर भी आधारित होता है': 'प्रधानमंत्री डॉ.
मनमोहन सिंह का चार्ली रोज शो पर साक्षात्कार, 27 फरवरी 2006।

412 ‘एक विशेष उभरा हुआ कार्यक्रम था, अतिथियों की सूची प्रकाशित की गई थी’: पृथ्वीराज चव्हाण
लेखक को।
412 ‘मैं अब अमेरिका के लोगों को उस महान अन्वेषक की यात्रा पूरी करने के लिए आमंत्रित करता हूँ’: रॉबर्ट्स,
‘गुलाबी हाथी जितना दुर्लभ झाड़ी वाला भोजन’।
412 रात के खाने के बाद, मेहमान पूर्वी कमरे में चले गए जहाँ उनके साथ 126 अन्य लोग भी शामिल हो गए:
मोंटेक सिंह अहलूवालिया लेखक हैं।
413 एक ‘वास्तविक अमेरिकी कला खजाना’: राष्ट्रपति (2001-2009: बुश)। सुलेख कार्यालय।
1/20/2001-1/20/2009, ‘07/18/2005 - भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और श्रीमती गुरशरण कौर की भारत यात्रा के अवसर पर कार्यक्रम’, राष्ट्रीय अभिलेखागार सूची, 20 जून 2022 को उपलब्ध।
<catalog.archives.gov/id/148029141> पर।
413 ‘बहुत साहसिक शब्दों में सोचना’: ग्लेन केसलर, द कॉन्फिडेंट: कोंडोलीज़ा राइस और
बुश विरासत का निर्माण, न्यूयॉर्क: सेंट मार्टिन प्रेस, 2007, नूरानी द्वारा उद्धृत, 'कोंडोलीज़ा राइस और परमाणु समझौता'।
413 दोनों देशों के बीच 'रणनीतिक अभिसरण': सरन, हाउ इंडिया सीज़ द वर्ल्ड, पृ. 201.
413 भारत अभी तक एक महान शक्ति नहीं था। लेकिन इसमें महान शक्ति बनने की क्षमता थी: कोंडोलीज़ा राइस।
‘अभियान 2000: राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना’, विदेश मामले, जनवरी/फरवरी 2000।
413 ‘सिर्फ अपने काम से काम नहीं रखते’: कोंडोलीज़ा राइस, ‘राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना’,
विदेश मामले, खंड 79, अंक 1, जनवरी-फरवरी 2000, पृष्ठ 45-62।
413 ‘वैचारिक रूप से भारत को पाकिस्तान से जोड़ना और केवल कश्मीर या परमाणु

मुद्दे के बारे में सोचना’
दोनों राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा: वही।
413 राइस के ‘गहन संवाद’ के आह्वान के साथ: सरन, भारत दुनिया को कैसे देखता है।
414 भारत को एक 'संतुलन कारक' के रूप में देखना शुरू कर दिया था: श्याम सरन ने लेखक को फोन पर बताया।
नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2020।
414 भारत को भी आशंका थी, जैसा कि विदेश सचिव श्याम सरन ने खुलासा किया, कि अमेरिका की ओर से कोई कार्रवाई हो सकती है।
पतन चीन के हाथ में जा सकता है: सरन, भारत दुनिया को कैसे देखता है, पृ. 195.
414 ‘एक दिन अमेरिका को भारत को परमाणु अंधकार से बाहर निकलने देना होगा’: ए. जी. नूरानी,
‘कोंडोलीज़ा राइस और परमाणु समझौता’, फ्रंटलाइन, 18 जनवरी 2008।
414 अमेरिका ने तारापुर रिएक्टरों को ईंधन की आपूर्ति करने के अपने समझौते से मुकर गया था: चेंगप्पा,
‘यह सौदा कैसे संपन्न हुआ’।
414 जब तक कि उसने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और अपने परमाणु हथियार नहीं छोड़े: वही।
414 उस समय अमेरिकी पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई: वही।
सरन का कहना है कि 415 के तहत भारत को चीन विरोधी संगठन में शामिल किया गया है ताकि क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला किया जा सके।
भारत विश्व को किस नजरिए से देखता है।
415 कुछ भारतीय अधिकारियों को इस तरह की 'विस्तृत प्रस्तुति' की उम्मीद नहीं थी: केसलर, द
नूरानी की पुस्तक 'कोंडोलीज़ा राइस और परमाणु समझौता' में उद्धृत विश्वासपात्र।
415 भारत भी ‘उन्नत हथियार’ खरीद सकता है: ग्लेन केसलर, ‘भारत ने संभावित बिक्री का विरोध किया’
'पाकिस्तान को लड़ाकू विमान', वाशिंगटन पोस्ट, 17 मार्च 2005।
415 वह जिस 'व्यापक रणनीतिक लक्ष्य' का अनुसरण करना चाहती थी, उसके बारे

में स्पष्ट थी: केसलर, द कॉन्फिडेंट, उद्धृत
नूरानी, 'कोंडोलीज़ा राइस और परमाणु समझौता'।
415 इसे 'भारत को नियंत्रित करने' के अपने रवैये से आगे बढ़ना होगा: वही।
416 वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले, मनमोहन सिंह पहले ही दो रणनीतिक कार्य कर चुके थे।
निर्णय: मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा लेखक को, 29 सितंबर 2021।
417 'फ्रेमवर्क समझौते द्वारा भारत की रणनीतिक (परमाणु) गतिविधियों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध'
कार्यक्रम': श्याम सरन, 22 अक्टूबर 2020.
417 अनिल काकोडकर के अनुसार, बाईस बिजली उत्पादन रिएक्टर थे।
उस समय देश की स्थिति: अनिल काकोडकर ने लेखक को 21 दिसंबर 2022 को मुंबई में टेलीफोन पर साक्षात्कार दिया। इन बाईस परमाणु संयंत्रों में से चार महाराष्ट्र के तारापुर में, छह राजस्थान में, दो तमिलनाडु के कल्पक्कम में, दो उत्तर प्रदेश के नरोरा में, दो गुजरात के काकरापार में, चार कर्नाटक के कैगा में और दो तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित थे। तारापुर स्थित संयंत्रों की पहली और दूसरी इकाई अमेरिकी सहायता से बनाई गई थीं और उन्हें तुरंत सुरक्षा उपायों के तहत रखा गया था। तारापुर की शेष दो इकाइयाँ, तीसरी और चौथी, स्वदेशी रूप से निर्मित थीं। राजस्थान में पहले दो रिएक्टर कनाडा की सहायता से बनाए गए थे, लेकिन अन्य चार स्वदेशी रूप से निर्मित थे। कुडनकुलम को छोड़कर, जो रूसी सहायता से बनाए गए थे, बाकी सभी रिएक्टर भी स्वदेशी थे। इसके अतिरिक्त, भारत के पास अपने परमाणु हथियारों के लिए विखंडनीय सामग्री की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीन अनुसंधान रिएक्टर थे, और एक 500 मेगावाट का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निर्माणाधीन था। ('कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु, भारत', पावर टेक्नोलॉजी, 15 मार्च 2023; 'भारत में परमाणु ऊर्जा', उपलब्ध)
(<world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/india.aspx> पर उपलब्ध है।)
417 ने 'सावधानी' के साथ जवाब दिया: अनिल काकोडकर ने लेखक को 25 नवंबर 2022 को मुंबई में लिखा।
417 भारत की अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए 'तीन चरण परमाणु ईंधन चक्र'

विकसित करने की योजना: वही।
417 ‘वे (निरीक्षक) इसे बड़ी शंका से देखेंगे, कि हम कोई गड़बड़ी कर रहे हैं’: वही।
418 ‘थोरियम का पूर्णतया दोहन करने की रणनीति तीन चरणों में निहित है’ कार्यक्रम’: वही।
418 ‘भारत अपने ‘संप्रभु’ अधिकार का ‘बलिदान’ करेगा’: वही।
418 ‘मसौदे पर और काम करने की जरूरत है’: वही।
418 ‘यह सुनिश्चित करना कि नागरिक और सैन्य को अलग करने का सिद्धांत पूरी तरह से लागू हो’
समझौता: वही। नागरिक और सैन्य रिएक्टरों के बीच अंतर उनकी संरचना में नहीं, बल्कि उनके उपयोग और अंतरराष्ट्रीय समुदाय तथा वैश्विक नियामक संगठनों द्वारा उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार में निहित था। नागरिक रिएक्टर आईएईए निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे, साथ ही उन्हें वैश्विक स्तर पर परमाणु व्यापार का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि ईंधन का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। सैन्य रिएक्टर निरीक्षण के लिए खुले नहीं रहेंगे, और भारत सरकार यह तय करेगी कि उसके रिएक्टरों को किस श्रेणी में रखा जाएगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में मुख्य मतभेद इस बात पर था कि 'सीमा कहाँ खींची जाए'।
418 ‘ये राजनीतिक आपत्तियां थीं’: श्याम सरन ने लेखक को, 22 अक्टूबर 2020।
418 ‘मैं इसे अपने घर वापस नहीं बेच पाऊंगा’: नटवर सिंह ने लेखक से कहा।
418 उन्होंने वैज्ञानिकों की आपत्तियों को नजरअंदाज नहीं किया: कई साल बाद, तत्कालीन एनएसए एम.
के. नारायणन ने खुलासा किया कि मनमोहन सिंह ने 17 जुलाई 2005 की रात को समझौते को रद्द कर दिया था, क्योंकि अमेरिका एक 'घातक प्रस्ताव' लेकर आया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा उपायों से बाहर रखे जाने वाले भारतीय रिएक्टरों की संख्या आठ से घटाकर दो कर दी जाए। नारायणन ने बताया कि यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री को स्वीकार्य नहीं था और प्रधानमंत्री कार्यालय और अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के बीच हुई चर्चाओं में बने समझौते के विरुद्ध था। (पीटीआई, 'मनमोहन सिंह अमेरिका के घातक प्रस्तावों के बाद परमाणु समझौते को रद्द करना चाहते थे: एम.के. नारायणन', इकोनॉमिक टाइम्स, 14 जुलाई 2015।)

418 ‘मैंने यह (मनमोहन सिंह का निर्णय) निकोलस बर्न्स को बताया जो बहुत 'निराश': श्याम सरन ने लेखक से कहा।
418 ‘सिंह इसे संभव नहीं बना सकते’: कॉन्डोलीज़ा राइस, ‘एक नया रिश्ता बनाना’ इंडिया’, नो हायर ऑनर: ए मेमोइर ऑफ माई इयर्स इन वाशिंगटन, न्यूयॉर्क: पेंगुइन रैंडम हाउस, 2011।
419 ‘मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ,’ उसने कहा: नटवर सिंह ने लेखक से कहा, 9 नवंबर 2020।
419 ‘मैंने सोचा, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूँगा’: राइस, ‘भारत के साथ एक नया रिश्ता बनाना’
इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं।
419 ‘सुबह करीब 6.30 बजे होंगे, मैं अभी भी अपने ड्रेसिंग गाउन में था’: नटवर सिंह ने लेखक से कहा।
419 ‘Woh aa rahi hain’: Ibid.
419 ‘मैं उनसे थोड़ा बाद में जुड़ा’: वही।
419 बैठक में राइस ने प्रधानमंत्री से कहा, 'आप मुझे बताइए कि इसमें क्या बाधा है': Natwar Singh to author.
419 ‘और आइए राष्ट्रपति से मिलने से पहले इसे पूरा कर लें’: राइस, ‘एक नया रिश्ता बनाना’
भारत', इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं।
419 ने ‘अंततः अपने लोगों को फिर से कोशिश करने की अनुमति दे दी’: वही।
420 ‘हमारे तीन-चरणीय रणनीतिक कार्यक्रम की स्वायत्तता को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए’: नटवार
सिंह से लेखक तक।
420 ‘मोटे तौर पर कहें तो, विचारों का अभिसरण है’: वही।
420 ‘हमारे दृष्टिकोण से, हम भाषा में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं चाहते थे’: श्याम सरन
लेखक।
420 ‘Ho gaya hai, that was obvious’: Natwar Singh to author.
421 'यह हो गया,' उनकी आवाज प्रसन्न थी: संजय बारू ने लेखक से कहा।

421 वे ‘अपनी कहानियों को तैयार रखने के लिए भरोसेमंद हो सकते थे’: संजय बारू, ‘परमाणु ऊर्जा का अंत’
'रंगभेद', आकस्मिक प्रधानमंत्री: मनमोहन सिंह का निर्माण और विघटन, नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, 2014।
421 ‘हमने देखा कि उनके बोलने के हर मिनट पर तालियाँ बज रही थीं’: बारू, द एक्सीडेंटल
प्रधानमंत्री, पृष्ठ 210।
421 बयान में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति 'पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा हासिल करने के लिए काम करेंगे'
भारत के साथ सहयोग’: एलिजाबेथ रोश, ‘परमाणु समझौते ने भारत-अमेरिका संबंधों को कैसे नरम किया’, मिंट, 17 जुलाई 2015।
421 अमेरिका ‘अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को समायोजित करने के लिए मित्रों और सहयोगियों के साथ काम करेगा’: वही।
421 ‘तारापुर में संरक्षित परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन आपूर्ति पर शीघ्र विचार’: ‘डील को बढ़ावा देना’, हिंदुस्तान टाइम्स, 17 मार्च 2006।
422 ‘उन्नत परमाणु शक्ति वाले अन्य अग्रणी देशों के समान लाभ और फायदे प्राप्त करना’
प्रौद्योगिकी’: ‘व्हाइट हाउस प्रेस विज्ञप्ति: राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संयुक्त बयान’, प्रेस सचिव कार्यालय, वाशिंगटन, डीसी, 18 जुलाई 2005, <2001-2009.state.gov/p/sca/rls/pr/2005/49763.htm> पर उपलब्ध है।
बयान में कहा गया है कि भारत की जिम्मेदारियों में ‘पहचान करना और अलग करना’ शामिल होगा:
वही।
422 ‘मैं भी उस पूरी रात सो नहीं सका। मैं प्रार्थना करता रहा’: अनिल काकोडकर ने लेखक से कहा।
422 ‘नटवर, तुम जैसे व्यक्ति इस बात पर कैसे सहमत हो सकते हो?’: नटवर सिंह ने लेखक से कहा, 2018;
सिंह, एक जीवन पर्याप्त नहीं है, पृ. 341.

422 ‘आप जानते हैं कि अमेरिकी नीति को लेकर देश में एक अंतर्विरोध चल रहा है’: सिंह, वन
जीवन पर्याप्त नहीं है, पृष्ठ 341।
422 उन्होंने 18 जुलाई 2005 के समझौते के लिए सरकार को 'फटकार' लगाई: नटवर सिंह द्वारा उद्धृत
जोया हसन, इंदिरा के बाद कांग्रेस: नीति, शक्ति, राजनीतिक परिवर्तन (1984-2009), नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012।
422 हालाँकि बाद में सोनिया गांधी ने अपना विचार बदल दिया: नटवर सिंह लेखक को, 2018।
423 ‘परमाणु समझौता दीर्घकाल में महंगा साबित हो सकता है’: सिद्धार्थ वरदराजन, ‘परमाणु समझौता’
'दीर्घकाल में महंगा साबित हो सकता है', द हिंदू, 20 जुलाई 2005।
423 ‘भारत समझौता’ शीर्षक से द पायनियर अखबार में खबर छपी: वही।
423 ‘ऐतिहासिक सफलता’: सीमा सिरोही, ‘भारत-अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक सफलता’, बीबीसी
समाचार, 19 जुलाई 2005।
423 ‘प्रतिमान बदलाव’: आर. रामचंद्रन, ‘सौदे के पीछे’, फ्रंटलाइन, 12 अगस्त 2005।
423 ‘नागरिक और सैन्य क्षेत्रों को अलग करना बहुत मुश्किल होगा, अगर असंभव नहीं तो’: पीटीआई, वाजपेयी
'परमाणु समझौतों का उपहास करता है', फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 20 जुलाई 2005।
423 मिश्रा ने सरकार के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि भारत को राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई है:
बृजेश मिश्रा का शीला भट्ट के साथ साक्षात्कार: 'भारत की रणनीतिक क्षमता पर एक सीमा है'
कार्यक्रम’, रेडिफ डॉट कॉम, 21 मार्च 2006।
423 ‘और हमारे सभी भविष्य के रिएक्टर सुरक्षा उपायों के तहत’: वही।
424 उन्होंने इस सौदे को ‘रणनीतिक समझौता’ करार दिया: पी. के. अयंगर एट अल., रणनीतिक समझौता: भारतीय–

अमेरिकी परमाणु समझौता, नई दिल्ली: पेंटागन प्रेस, 2009।
424 ‘भारत को अपने स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है’: ए.
गोपालकृष्णन, टी.वी. जयन द्वारा उद्धृत, 'नो बुलिंग', डाउन टू अर्थ, 28 फरवरी 2006।
424 ‘हमें केवल पैसा चाहिए, उनकी विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी या विज्ञान नहीं’: वही।
424 ‘सीपीआई (एम) को उम्मीद है कि सरकार ऐसे एकतरफा उपाय नहीं करेगी जो राष्ट्रीय हितों से समझौता’: ‘भारत-अमेरिका संयुक्त बयान’, 21 जुलाई 2005, उपलब्ध है
<www.cpim.org/content/indo-us-joint-statement-0>.
425 एक बार फिर, ये बातचीत ‘अंतिम क्षण तक चली’: अनिल काकोडकर ने लेखक को बताया।
425 ‘मैंने हमारी संसद को यह आश्वासन दिया है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति को नुकसान पहुंचे।
कार्यक्रम: ‘प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का चार्ली रोज शो पर साक्षात्कार’, 27 फरवरी 2006।
425 ‘हमें पूरा यकीन था कि हम दुकान अमेरिकियों को बेचने वाले थे’: सरन, भारत इसे कैसे देखता है
दुनिया।
425 भारत ने अपने नागरिक रिएक्टरों को 'स्थायी रूप से' सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रखा: सरन, भारत इसे कैसे देखता है
दुनिया।
425 अंततः, एक सफलता मिली—और यह बुश के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद आई: वही।
3 मार्च 2006 को दोनों नेताओं ने नागरिक परमाणु सुरक्षा पर संयुक्त समझौते की घोषणा की।
सहयोग: पीटीआई, 'भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का कालक्रम', इकोनॉमिक टाइम्स, 9 अक्टूबर 2008।
425 ‘एक अरब मजबूत लोकतंत्र के साथ नया रोमांस’: एसोसिएटेड प्रेस, ‘बुश:

भारत एक
'रोजगार के अवसर, बाधा नहीं', एनबीसी न्यूज, 3 मार्च 2006।
425 ‘भारत की जनता आपसे बेहद प्यार करती है’: ‘भारत की जनता आपसे बेहद प्यार करती है’, आउटलुक, 3
फरवरी 2022।
426 सबसे पहले हाइड अधिनियम पारित हुआ, जिसने अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन किया।
1954: सरन, भारत दुनिया को कैसे देखता है।
426 लेकिन विभिन्न गुटों को संतुष्ट करने के लिए हाइड अधिनियम में 'अनावश्यक' प्रावधान शामिल किए गए थे:
वही, पृष्ठ 216।
426 सीनेटर जो बाइडन, जो कुछ वर्षों बाद राष्ट्रपति भी बनेंगी, ने 'समर्थन' व्यक्त किया:
वही, पृष्ठ 215।
427 ‘भारत ने जोर दिया था कि सुरक्षा उपाय भारत-विशिष्ट होने चाहिए’: श्याम सरन ने लेखक को बताया।
428 ‘भारत के विदेश नीति विकल्पों का विस्तार किया’: वही।
428 ‘शीत युद्ध के बाद भारत का जन्म हुआ’: शेखर गुप्ता, ‘कैसे एक बड़े भारत-अमेरिका समझौते ने हमें छह
'वामपंथियों का सफाया सहित बड़ी उपलब्धियां खुशी का कारण हैं', द प्रिंट, 22 फरवरी 2020।
428 ‘मैं उन्हें भारत का वित्त मंत्री बनाना चाहता हूँ’: पी.वी. राव ने बी.एम. भामा से लेखक को कहा।
428 ‘मनमोहन सिंह चाहते थे कि राव उनकी नियुक्ति को नियमित करने में मदद करें: वही।
428 ‘मुझे पता है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे’: बी.एम. भामा ने लेखक से कहा। भामा राव के यहाँ थे।
उस दिन निवास स्थान पर मौजूद था और बाद वाले ने उसे यह बात बताई।
428 ‘मैं कह सकता हूँ कि मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने का विचार मेरा था’:

आर.
वेंकटारमन द्वारा लेखक को, 22 अगस्त 2022, दिल्ली; भुवनेश चतुर्वेदी द्वारा लेखक को पुष्टि की गई।
429 उन्होंने तुरंत जवाब दिया, 'यह एक टेक्नोक्रेट होगा': कांग्रेस नेता हरिकेश बहादुर ने लेखक से कहा।
सतीश शर्मा ने बहादुर को घटना के बारे में बताया था।
429 अलेक्जेंडर 21 जून 1991 को सुबह 5 बजे सिंह से मिले: अलेक्जेंडर, गलियारों के माध्यम से
पॉवर, पृ. 409.
429 पी. वी. नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली: सीतापति, आधा शेर, पृ. 103.
429 विकास दर में गिरावट आई थी: विकास दर घटकर 5 प्रतिशत (1990-91) हो गई थी।
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 11.9 प्रतिशत था (1991-92 में यह घटकर शून्य प्रतिशत हो गया था); मुद्रास्फीति की दर 1990-2001 में बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई थी और 1991-92 में और बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई थी; केंद्र और राज्यों को मिलाकर राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 11.9 प्रतिशत था। (अरुण कुमार, स्वतंत्रता के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था: निरंतर औपनिवेशिक व्यवधान, नई दिल्ली: विजन बुक्स, 2013, पृष्ठ 234)।
429 ‘अब हमें सोना गिरवी रखकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की आवश्यकता है’: गायत्री नायक, ‘जब 47
'सड़क के बीच में टन सोना पड़ा था', इकोनॉमिक टाइम्स, 5 जुलाई 2017; सी. रंगराजन, 'चंद्र शेखर सरकार और आरबीआई ने 1991 में भारत के सोने को गिरवी रखने की योजना कैसे बनाई', 26 नवंबर 2022।
430 ‘मुझे इस पर हस्ताक्षर क्यों करने होंगे?’: दीपक नैयर ने लेखक से 9 सितंबर 2001 को नई दिल्ली में पूछा।
उस समय नय्यर मुख्य आर्थिक सलाहकार थे।
430 ‘अर्थव्यवस्था की स्थिति पर, हमारे विकल्पों पर, हमारे अवसरों पर’: वही।
430 ‘लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतनी गड़बड़ है’: वही।

430 ‘मनमोहन सिंह को जैसे ही पता चला कि पी.वी. ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, वह दौड़ते हुए आए’: वही।

430 4 से 18 जुलाई 1991 के बीच, आरबीआई ने 46.91 टन सोना गिरवी रखा: शाजी विक्रम, 'इन

तथ्य: सरकारों ने अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए सोने का वादा कैसे किया’, इंडियन एक्सप्रेस, 5 अप्रैल 2017।

430 ‘बस, यही है। हम इसे करते हैं,’ वे कहते थे: दीपक नायर ने लेखक को 9 सितंबर 2001 को लिखा, न्यू

दिल्ली।

431 ‘मनमोहन सिंह…ने मुझे बताया कि अगर इसे कई चरणों में किया जाए’: आर. वेंकटरामन ने लेखक को लिखा।

431 ‘यदि आपको 5 रुपये का अवमूल्यन करना ही है, तो आप 25 पैसे प्रतिदिन बीस दिनों तक क्यों नहीं अवमूल्यन करते’:

वही।

431 ‘हमने प्रधानमंत्री से कहा कि अगर हमने वही किया जो आरवी ने कहा था तो यह एक भीषण आपदा होगी।

'चाहिए': दीपक नैयर ने लेखक को 9 सितंबर 2001 को नई दिल्ली में लिखा।

431 ‘अवमूल्यन का पहला कदम स्थिति का जायजा लेने के लिए उठाया गया था’: शाजी विक्रम, ‘25 साल बाद,

मनमोहन सिंह को इस बात का अफसोस है: संकट में हम कार्रवाई करते हैं। संकट समाप्त होते ही, स्थिति फिर से पहले जैसी हो जाती है।’, द इंडियन एक्सप्रेस, 24 जुलाई 2016।

431 सुबह 9 बजे तक अवमूल्यन पहले ही किया जा चुका था: जयराम रमेश, टू द ब्रिंक एंड

बैक, इंडियाज 1991 स्टोरी, नई दिल्ली: रूपा पब्लिकेशंस, 2015।

431 क्या मनमोहन सिंह अवमूल्यन के दूसरे चरण के 'असली सितारे' थे: बीएस रिपोर्टर, 'कौन'

'1991 में रुपये के दो चरणों में अवमूल्यन का असली सितारा वही था', बिजनेस स्टैंडर्ड, 31 अगस्त 2015।

432 वित्त मंत्री बनने पर उन्होंने अपनी राय बदल दी—उनका यह बदलाव
आलोचना: जॉर्ज फर्नांडीस, 'औद्योगिक नीति पर एक वक्तव्य', लोकायन बुलेटिन, नवंबर-दिसंबर 1991, खंड 9.6, 1991, पृष्ठ 24।
432 चंद्र शेखर, जिनके अधीन उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था, ने उन पर आरोप लगाया कि
उनसे जानकारी छिपाना: जुलाई 1991 में संसद में बजट पर बहस के दौरान चंद्र शेखर बोल रहे थे।
432 'हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए': दीपक नैयर ने लेखक को, 9 सितंबर 2001, नई दिल्ली।
432 'वह राव के पैर छुआ करते थे': भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक से कहा।
433 उस समय भारत में गरीब छात्रों के लिए मौजूद 'छात्रवृत्ति प्रणाली': 'साक्षात्कार' प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 'चार्ली रोज शो' में, 21 सितंबर 2004, मीडिया सेंटर, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।
433 'मेरे पास जो संसाधन थे, उनके आधार पर मैं कभी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढ़ने का खर्च नहीं उठा सकता था।
निपटान': वही।
433 'मेरा मानना है कि पूंजीवाद ने बहुत अधिक गतिशीलता दिखाई है': वही।
433 'वह जीवन भर विजेता रहे हैं': रितु सरीन, 'श्रीमती सिंह ने अपने दिल की बात कही और अपना एल्बम साझा किया'
इंडियन एक्सप्रेस, 20 मई 2004।
434 'यह सच नहीं है कि मैं राजनीतिक रूप से अनुभवहीन हूँ': प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का साक्षात्कार
चार्ली रोज शो पर, 21 सितंबर 2004।
434 वह कहा करती थीं कि जब वह तनाव में होती थीं, तो वह अधिक बार पलकें झपकाती थीं: सोनिया गांधी
लेखक 2004 में एक बातचीत के दौरान।
कांग्रेस को 145 सीटें मिलीं, जो भाजपा से 7 अधिक थीं: 'सांख्यिकीय रिपोर्ट'
14वीं लोकसभा के लिए 2004 के आम चुनाव: खंड I', दिल्ली: चुनाव आयोग
भारत, 2004, <eci.gov.in/files/file/4126-general-election-2004-

vol-i-ii-iii > पर उपलब्ध है।

435 ‘हमने कर दिखाया,’ उसने कहा: रशीद किदवई, सोनिया: एक जीवनी, नई दिल्ली: पेंगुइन
पुस्तकें, 2011।

435 चुनाव पूर्व सहयोगियों के साथ कांग्रेस ने 222 सीटें हासिल की थीं: ई. श्रीधरन, 'चुनावी'
2004 के आम चुनावों में गठबंधन: सिद्धांत और साक्ष्य’, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 39, संख्या 51, 2004, पृष्ठ 5419।

435 वामपंथी दलों—सीपीआई (एम), सीपीआई, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक—ने आश्चर्यजनक रूप से 59 सीटें जीती थीं।

सीटें: ‘14वीं लोकसभा के लिए 2004 के आम चुनावों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट: खंड I’

उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 15 प्रतिशत सीटें होने के कारण, सपा को उम्मीद थी कि वह विजयी होकर उभरेगी।

दिल्ली में किंगमेकर: सुनीता अरोन, अखिलेश यादव: बदलाव की हवाएँ, ट्रांकेबार, 2013, पृष्ठ 312। साथ ही ‘भारत: छोटी पार्टियाँ चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद करती हैं—2004-04-
13’, voanews.com, 29 अक्टूबर 2009.

435 नतीजों की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर, सीपीआई (एम) और सीपीआई के शीर्ष नेता एक साथ इकट्ठा हुए।
ए.के. गोपालन भवन: ज़ी न्यूज़, 14 मई 2004।

435 वामपंथी दलों ने चुनाव से पहले ही धर्मनिरपेक्ष सरकार का समर्थन करने का फैसला कर लिया था: प्रकाश
करात ने लेखक को दिसंबर 2020 में लिखा।

435 इसे 'बाहर से' समर्थन देते हैं: 'बाहर से' समर्थन का अर्थ है किसी सरकार को किसी बाहरी ताकत द्वारा दिया गया समर्थन।
किसी भी दल या दलों के समूह में शामिल हुए बिना मंत्रालय में शामिल होना और उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार होना।

436 उन्होंने सीएमपी तैयार करने के लिए गठित समूह का नेतृत्व करने के लिए

मनमोहन सिंह को नियुक्त किया: 'सीएमपी इस प्रकार होगी'
मनमोहन सिंह पवार के शासनकाल में तैयार किया गया', ज़ी न्यूज़, 14 मई 2004।
436 उन्होंने पत्रकार संतोष भरतिया के माध्यम से संपर्क साधा, जो सिंह के करीबी थे: संतोष भरतिया, उपाध्यक्ष
Singh, Chandra Shekhar, Sonia Gandhi aur Main, Warriors Victory, 2021, pp. 460–62.
436 उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्यों बताया, इस बारे में विस्तार से बात की: शीला
भट्ट, 'सोनिया गांधी के पक्ष में तर्क', रेडिफ डॉट कॉम, 14 मई 2004।
436 'संसद में कांग्रेस के सबसे पुराने सदस्य' और फिर भी 'संसद में सबसे नए सदस्यों में से एक'
लोकसभा': प्रणब मुखर्जी, गठबंधन के वर्ष: 1996-2012, दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स, 2017, पृष्ठ 68।
436 यह एक 'समावेशी, धर्मनिरपेक्ष और एकजुट' भारत बनाने के लिए मतदान था: रणदीप रमेश, 'सोनिया'
गांधी ने "धर्मनिरपेक्ष" शासन का वादा किया', द गार्जियन, 16 मई 2004।
437 वे राष्ट्रीय जनता दल (24 सांसदों के साथ) थे: 'आम चुनावों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट,
2004 से 14वीं लोकसभा तक: खंड I'
437 पटेल ने अमर सिंह की प्रविष्टि को मंजूरी दी: अंबिका सोनी लेखक होंगी।
437 लेकिन उस शाम जब अमर सिंह बैठे तो सोनिया गांधी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं: विनोद
शर्मा, 'अमर ने सोनिया के साथ डिनर टेबल कैसे साझा की', हिंदुस्तान टाइम्स, 18 मई 2004।
437 सोनिया गांधी उस शाम के रात्रिभोज में असामान्य रूप से एकांतप्रिय थीं: ए. बी. बरधान ने लेखक को लिखा।
437 यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने राम विलास पासवान को सरकार में शामिल होने के लिए राजी किया था: सोनिया गांधी
लेखक को, 2004।

438 ‘Kuch tajjub toh hua ki kaise hogaya yeh’: Ritu Sarin, ‘Manmohan returned my call past 11
प्रधानमंत्री ने मेरे काम की प्रशंसा की और कहा कि वे इसे आगे बढ़ाएंगे’, इंडियन एक्सप्रेस, 21 मई 2004।
438 ‘मैं केवल सफेद कपड़े पहनूंगा, नंगी ज़मीन पर सोऊंगा और केवल भुने हुए चने खाऊंगा’: ‘जब
'सुषमा स्वराज ने अपना सिर मुंडवाने की धमकी दी', इंडिया टुडे, 7 अगस्त 2019।
438 ‘यदि स्वतंत्रता के 60 वर्षों के बाद हम शीर्ष पद के लिए एक और विदेशी को ताज पहनाते हैं’: वही।
438 एक विदेशी को ‘रक्षा के सभी रहस्यों की जानकारी होगी’: पीटीआई, ‘स्वराज ने विरोध जताने के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात की’
गांधी के प्रधानमंत्री बनने की खबर’, द ट्रिब्यून, 18 मई 2004।
438 उमा भारती ने मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, 'राज्य की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए'।
'100 करोड़ भारतीयों का सम्मान': अशोक दामोदरन, 'विपक्ष ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुनी गई सोनिया गांधी को पदभार ग्रहण करने से रोकने के लिए विदेशी मूल का कार्ड खेला', इंडिया टुडे, 31 मई 2004।
दिल्ली में 438 महिलाओं ने अपनी कलाई पर चाकू रखकर अपना खून निकाला: वही।
438 ‘यह दोपहर लगभग 2 बजे का समय रहा होगा’: नटवर सिंह ने लेखक को, 21 जून 2018, नई दिल्ली।
439 ‘छह महीनों में, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी’: वही।
439 ‘उन्होंने सोनिया को फैसला करने के लिए 24 घंटे का समय दिया’: सिंह, वन लाइफ इज नॉट इनफ, पृ. 319.
439 ‘सोनिया स्पष्ट रूप से परेशान और रो रही थी’: वही; नटवर सिंह ने लेखक को 21 जून 2018 को लिखा।
29 मई 2022 को पुनः पुष्टि की गई।
439 ‘आप क्या कह सकते थे? यह पंद्रह से बीस मिनट बहुत मुश्किल थे’: वही, पुनः पुष्टि की गई

2020. सिंह की पुस्तक, वन लाइफ इज नॉट इनफ, पृष्ठ 319 में भी इस पर चर्चा की गई है।

439 'प्रियंका ने कुछ ऐसा कहा था कि "राहुल इसके खिलाफ है": नटवर सिंह ने लेखक को 21 जून को बताया

2018 में पुष्टि हुई, 2022 में पुनः पुष्टि की गई।

439 'हमने सोनिया को अंदर जाने के लिए कहा': वही।

439 'असल में उसके बेटे ने उसके लिए फैसला किया': वही।

439 'एक माँ के रूप में उसके लिए राहुल को नज़रअंदाज़ करना असंभव था': सिंह, एक जीवन पर्याप्त नहीं है।

439 सोनिया गांधी ने वाजपेयी को फोन करके उनका आशीर्वाद मांगा था: के. सुब्रमण्यम

लेखक, 13 फरवरी 2005, नई दिल्ली।

439 'आप देश को विभाजित कर देंगे और अंततः सिविल सेवाओं की निष्ठा पर दबाव डाल सकते हैं':

वही।

439 वह उसके इस हावभाव से भावुक हो गया—और कई लोगों ने इसे इस बात का संकेत माना कि 'भारत का लोकतंत्र

सुरक्षित': वही।

परिवार के सात सदस्यों ने अभूतपूर्व स्तर पर शासन किया या सत्ता एवं प्रभाव का प्रयोग किया।

एक सदी से भी अधिक समय तक एक विशाल देश पर दयालुता का परिचय देते हुए नटवर सिंह ने लेखक को 29 मई 2022 को नई दिल्ली में लिखा।

440 'मैंने डॉ मनमोहन सिंह से प्रधानमंत्री पद संभालने का अनुरोध किया है': नटवर सिंह

लेखक, 21 जून 2018, 2022 में पुनः पुष्टि की गई, नई दिल्ली।

440 'मनमोहन सिंह जी को "ना" कहने का कोई अधिकार नहीं है': वही।

440 'मुझे प्रणब मुखर्जी से गंदी निगाहें मिलीं': वही।

441 'आपको इसे इस तरह से करना चाहिए कि यह भावी पीढ़ियों द्वारा याद रखा जाए': अंबिका सोनी ने लेखक से कहा।

441 ‘आपको कुछ ऐसा तैयार करना चाहिए जो लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव पैदा करे’:
अंबिका सोनी लेखिका को।
441 ‘उनके बच्चे नहीं चाहते थे कि वह प्रधानमंत्री बनें, उन्हें उनकी जान का खतरा था’: वी. पी.
सिंह से लेखक तक।
441 ‘अगर उसके बच्चों को उसकी जान का खतरा हो और वे उसे प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते हों तो हम क्या कर सकते हैं?’
सोमनाथ चटर्जी लेखक को।
442 ‘आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें इसके बारे में टीवी से पता चला’: नटवर सिंह ने लेखक से कहा।
21 जून 2018, 2022 में पुनः पुष्टि की गई, नई दिल्ली।
442 उन्होंने सोनिया गांधी को अपना समर्थन दिया था, किसी और को नहीं: सिंह, वन लाइफ इज नॉट
पर्याप्त, पृ. 330–31.
442 पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु, जो उस दिन दिल्ली में थे, ने अपनी राय व्यक्त की।
‘उनके फैसले से निराशा’: प्रकाश करात ने लेखक से 4 दिसंबर 2020 को कहा।
442 ‘यह उनकी पार्टी, यूपीए और सहयोगी वामपंथी पार्टियों के सामने प्रस्तुत किया गया एक यथार्थ था’: वही।
442 उन्होंने ‘अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय’ पर चर्चा की: शीला भट्ट ने कहा, ‘अहमद पटेल के पास एक
कांग्रेस के इतिहास की समझ और भविष्य की चुनौतियां', इंडियन एक्सप्रेस, 26 नवंबर 2020।
442 ‘मैं कल राष्ट्रपति से फिर मिलूंगा ताकि वार्ता पूरी हो सके’: लेखक इसका हिस्सा थे
उस दिन राष्ट्रपति भवन के बाहर मीडिया मौजूद थी।
442 ‘श्रीमती गांधी डॉ. मनमोहन सिंह के साथ राष्ट्रपति भवन आईं’: ए. पी. जे. अब्दुल

कलाम, टर्निंग पॉइंट्स: ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस, नई दिल्ली: हार्परकॉलिन्स, 2011।
443 'यह मेरे लिए वाकई एक आश्चर्य की बात थी और राष्ट्रपति भवन सचिवालय को इस पर दोबारा काम करना पड़ा।
पत्र': वही।
443 'अगर उसने अपने लिए कोई दावा किया होता, तो मेरे पास उसे नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता': वही।
443 'मुझे हमेशा से यकीन था कि अगर मैं कभी खुद को उस स्थिति में पाता हूँ जिसमें मैं आज हूँ': '"मेरा
अपनी आंतरिक आवाज का उपयोग करें", आउटलुक, 3 फरवरी 2022।
443 'सोनिया ने नैतिक रूप से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया था': 'अद्भुत राजनीतिक बलिदान', द हिंदू, 19
मई 2004।
443 पाकिस्तान राष्ट्र ने इसे एक 'समझदारी भरा' कदम बताया: राजीव शर्मा, 'विश्व प्रेस सलाम करता है'
सोनिया', द ट्रिब्यून, 19 मई 2004।
443 इंडिया टुडे ने इसे 'रणनीतिक त्याग' बताया: प्रभु चावला, 'सोनिया गांधी ने इनकार किया'
'प्रधानमंत्री पद, मनमोहन सिंह को सरकार का मुखिया नियुक्त किया गया', इंडिया टुडे, 31 मई 2004।
443 'उसके खिलाफ खड़ी राजनीतिक ताकतों का सुविचारित आकलन': 'वह महिला गायब हो जाती है',
द टाइम्स, 19 मई 2004।
444 भारतीय इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को 'एक बार नहीं बल्कि दो बार' ठुकराया:
'संपादकीय', हिंदुस्तान टाइम्स, 19 मई 2004, 'द गार्जियन', 20 मई 2004 में 'द एडिटर प्रेस रिव्यू इंडिया' में उद्धृत। हालांकि सोनिया गांधी एकमात्र ऐसी राजनीतिज्ञ थीं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के प्रस्ताव को दो बार ठुकराया, भारतीय राजनीति के इतिहास में अन्य भी थे जिन्होंने इसे अस्वीकार किया था—ज्योति बसु ने 1996 में ऐसा किया था और उसी वर्ष वी. पी. सिंह ने भी, जब संयुक्त मोर्चा, सरकार बनाने

की स्थिति में था, ने उन दोनों से बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करने का अनुरोध किया था; दोनों ने इनकार कर दिया था।
444 कांग्रेस के प्रबंधकों ने उनके 'बलिदान' की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी: एम. एल. फोतेदार ने लेखक को बताया।
444 उस दिन सिंह परिवार में एक साधारण पंजाबी भोजन पक रहा था: सारिन, 'श्रीमती सिंह'
वह अपने दिल की बात कहती है और अपना एल्बम खोलती है।
444 'अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या आप मुझे राजनीति में आने की सलाह देते?': पी.वी. राव ने लेखक से पूछा।
अनौपचारिक बातचीत।
445 लेकिन उन अंधकारमय वर्षों के दौरान भी, उन्होंने अपने लिए एक राजनीतिक भूमिका निभाने की संभावना को खारिज नहीं किया: फोतेदार,
चिनार के पत्ते, पृष्ठ 296।
445 'यह फैसला करना उन्हीं पर निर्भर है': सोनिया गांधी ने 2003 में नई दिल्ली में हुई बातचीत में लेखक से कहा।
445 जिनमें से दोनों की अध्यक्षता उन्होंने राजीव की मृत्यु के बाद की: किदवई, सोनिया।
445 उन्होंने राजीव गांधी परियोजना में धीमी प्रगति पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।
हत्या की जांच: भुवनेश चतुर्वेदी ने लेखक से बात की।
445 'मैं नेहरू की बेटी नहीं हूँ': सोनिया गांधी ने लेखक से कहा। नीरजा चौधरी द्वारा भी उद्धृत।
'थर्ड मैन', द कारवां, 1 अप्रैल 2014।
446 'वह भाषण जोर से पढ़ती और मैं समय नोट करता': सिंह, वन लाइफ इज नॉट इनफ, पृ.
312.
446 'मैं ज्यादा नहीं बोलती। बोलती तो वो होती है': सोनिया गांधी ने लेखक से कहा। कुख्यात 'अतिथि'
1995 में लखनऊ में हुई 'गेस्ट हाउस' घटना, जब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने एक गेस्ट हाउस को घेर लिया और मायावती को कमरे में बंद होने के लिए मजबूर कर

दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर उन्हें बचाया न जाता तो वे उन्हें मार डालते। इस घटना ने उन्हें वर्षों तक मानसिक आघात पहुँचाया। (रविश तिवारी, 'द स्टोरी ऑफ द गेस्ट हाउस', इंडियन एक्सप्रेस, 16 जनवरी 2019)

446 कांग्रेस की 6 सितंबर 1998 की 'एकल-चुनाव नीति' को पलटते हुए: कांग्रेस की एकल-चुनाव नीति

पचमढ़ी में हुए पार्टी अधिवेशन में अपनाई गई नीति को जुलाई 2003 में शिमला में हुई बैठक में त्याग दिया गया। लेकिन कई लोगों का मानना था कि सत्ता के लिए गठबंधन में शामिल होने से कांग्रेस का पतन हुआ। (सिद्धार्थ मिश्रा, 'कांग्रेस को अपने चुनावी अवसरों को मजबूत करने के लिए पचमढ़ी और शिमला की ओर क्यों देखना चाहिए', फर्स्टपोस्ट, 11 मई 2022।)

447 उनके करीबी लोगों ने इस बात को छिपाया नहीं कि प्रधानमंत्री 'शासन' पर ध्यान केंद्रित करेंगी: अहमद

पटेल लेखक को।

447 'उनके मंत्रिमंडल में कौन होगा, इसका निर्णय केवल उनका ही नहीं होगा':

मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया द्वारा 29 सितंबर 2021 को लेखक के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की गई, और 2022 में इसकी पुष्टि हुई। मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया की पुस्तक "बैकस्टेज: द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ इयर्स", नई दिल्ली: रूपा पब्लिकेशंस, 2020 भी देखें।

447 वे बहुत विनम्र दिखना नहीं चाहते थे: शिव कुमार ने लेखक से कहा।

448 'यह तो स्पष्ट था कि एनएसी की पहली बैठक में इस पर चर्चा होगी':

लेखक: एनएसी का एक गुमनाम सदस्य।

448 'प्रधानमंत्री आज दोपहर 4 बजे हमसे मिलेंगे': वही।

448 'उस समय सोनिया गांधी को भगवान की तरह देखा जाता था': वही।

449 'भले ही वह वित्त मंत्री या आरबीआई गवर्नर न भी रहे हों, फिर भी एक प्रधानमंत्री ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं':

वही।

449 इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना था: मंत्रालय

विधि एवं न्याय, 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005', भारत का

राजपत्र, 7 सितंबर 2005, 23 जून 2022 को देखा गया, उपलब्ध है
<rural.nic.in/sites/default/files/nrega/Library/
Books/1_MGNREGA_Act.pdf>
449 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दी: वही। बाद में, फरवरी में
2008 में, सोनिया गांधी के बेटे और सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर एनआरईजीए को पूरे देश में लागू करने के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने 29 फरवरी 2008 को कुछ युवा सांसदों के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कार्यक्रम को सार्वभौमिक बनाने की मांग की। प्रधानमंत्री राहुल को मना नहीं कर सकीं, और इस लेखक की राय में, संभवतः सोनिया गांधी की भी इसमें सहमति थी।
450 वह अक्सर एनएसी अध्यक्ष के रूप में मंत्रियों को पत्र लिखती थीं: एनएसी के एक अनाम सदस्य को
लेखक।
भाजपा ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें 'सुपर प्राइम मिनिस्टर' कहा: पीटीआई, 'एनएसी'
'असंवैधानिक, सोनिया गांधी सुपर पीएम: भाजपा', टाइम्स ऑफ इंडिया, 18 जुलाई 2004।
450 आलोचकों ने एनएसी को 'वैकल्पिक...कैबिनेट' करार दिया: रशीद किदवई, 24 अकबर रोड: ए
कांग्रेस के पतन और उत्थान के पीछे के लोगों का संक्षिप्त इतिहास, दिल्ली: हैचेट, 2011।
450 एनएसी को 'अपमानजनक रूप से' 'सोनिया की झोलावाला भीड़' कहा जाता था: प्रिया सहगल, 'सोनिया
गांधी ने एनएसी प्रमुख पद से इस्तीफा दिया, सरकार ने 11 सदस्यीय निकाय को बिना प्रमुख के छोड़ दिया', इंडिया टुडे, 17 अप्रैल 2006।
450 'एनएसी तभी उपयोगी है जब सोनियाजी इसकी अध्यक्षता कर रही हों। अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं है': वही।
450 'आर्थिक विकास ने एक अवसर पैदा किया और श्रीमती गांधी ने अपनी प्रतिबद्धता के साथ इसमें कदम रखा।

'सामाजिक नीति': जीन ड्रेज़ ने लेखक को 9 नवंबर 2020 को लिखा।
451 'ऐसा ही हो': मानिनी चटर्जी '"दुखी" प्रधानमंत्री ने वामपंथियों से कहा: अगर आप पीछे हटना चाहते हैं, तो ऐसा ही हो'
द टेलीग्राफ, 11 अगस्त 2007।
451 'गठबंधन के बारे में फैसला करने वाले डॉक्टर साहब कौन होते हैं, यह पार्टी का काम है': अहमद पटेल
लेखक।
451 'प्रधानमंत्री इतने गैरजिम्मेदार कैसे हो सकते हैं?': वही।
452 'मुझे संसद भवन में उनके कार्यालय में 12 बजे आने के लिए कहा गया था': मानिनी चटर्जी ने लेखक से कहा।
452 बारू ने जो नोट किया था उसे ठीक कर दिया: संजय बारू ने लेखक को।
452 'मैंने उनसे (वामपंथियों से) कहा था कि समझौते पर पुनर्विचार करना संभव नहीं है': चटर्जी '"दुखी" प्रधानमंत्री
बाईं ओर: यदि आप पीछे हटना चाहते हैं, तो ऐसा ही हो।
452 'मैं पिछली शाम उनके (प्रधानमंत्री) साथ बैठा था': संजय बारू ने लेखक से कहा, 25
सितंबर 2020।
452 'जहां तक सरकार से संपर्क करने का सवाल है, हम अपनी सलाह खुद लेंगे।'
'प्रधानमंत्री के बयान पर प्रकाश करात', 11 अगस्त 2007, उपलब्ध है
<www.cpim.org/content/prakash-karat-pms-statement>.
अनुच्छेद 452 के तहत 'भारत विशिष्ट सुरक्षा समझौते' के लिए आईएईए के पास और फिर एनएसजी के पास जाने का प्रस्ताव है।
'छूट': 'प्रधानमंत्री 123 कहने के लिए जुलाई के मध्य की समय सीमा पर विचार कर रहे हैं', इकोनॉमिक टाइम्स, 23 जून 2008।
452 'हमें इस सौदे को विफल करने के लिए तैयार रहना चाहिए,' सीपीएम की सर्वोच्च संस्था ने संकल्प लिया, 'भले ही
समर्थन वापस लेने के लिए: सीपीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 19 जून 2008।
453 जब वह और प्रधानमंत्री करात की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, तब बारू ने याद करते हुए कहा, 'मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मुड़ गए।'

रेड': संजय बारू लेखक से।
453 उन्होंने इसकी योजना केवल अपने मीडिया सलाहकार संजय बारू के साथ बनाई थी: वही।
453 'कोई रुकना नहीं, कोई पीछे जाना नहीं... गठबंधन को सांस लेने का मौका मिला': स्मिता गुप्ता,
'ब्लिंकमैनशिप', आउटलुक, 10 सितंबर 2007।
454 'हमारे लिए, यह सब जून 2005 में प्रणब मुखर्जी के वाशिंगटन जाने से शुरू हुआ': प्रकाश
करात ने लेखक को 4 दिसंबर 2020 को लिखा।
454 'आपने हमें बताया था कि यह एक खोजपूर्ण यात्रा थी': वही।
454 'परमाणु समझौता एक quid pro quo था': वही।
454 कांग्रेस नेतृत्व ने परमाणु वैज्ञानिक राजा रामन्ना से पूछा: वही।
455 मनमोहन सिंह मोंटेक सिंह अहलूवालिया को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे: अज्ञात कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार।
455 'मुझे चाय और बिस्कुट पेश किए': अहलूवालिया, बैकस्टेज, पृ. 236.
455 'सरदार से सरदार' की सौहार्दता जिसने नियुक्ति को प्रभावित किया: अज्ञात सूत्रों के अनुसार
कांग्रेस।
455 व्यक्तिगत रूप से वे विनम्र और सच्चे सज्जन थे: डी. पी. त्रिपाठी ने लेखक किशोर को लिखा;
चंद्र देव लेखक को।
455 'अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में न जाने' के बारे में: प्रकाश करात ने लेखक से कहा।
455 'अमेरिका के साथ एक रणनीतिक साझेदारी': इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस, 21 मई 2008
455 'हमने वह वाक्य हटा दिया': प्रकाश करात ने लेखक को, 4 दिसंबर 2020।
456 'वह वामपंथ को जानता था, और उसे समझता था': वही।
456 'हाइड अधिनियम की प्रस्तावना ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम ईरान को अलग-थलग करने के लिए काम करेंगे': वही।
456 वामपंथियों की आलोचना के जवाब में, प्रधानमंत्री ने संसद को बताया कि हाइड

अधिनियम
बाध्यकारी नहीं: ए. बी. बर्धन, 'गतिरोध क्यों?', मेनस्ट्रीम, खंड XLV, संख्या 37, 4 सितंबर 2007।
456 वामपंथियों द्वारा परमाणु समझौते का विरोध, जैसा कि उन्होंने सोनिया गांधी को टेलीविजन पर कहते सुना, 'नहीं था'
'अतार्किक': वर्गीस के जॉर्ज, 'पुस्तक के अनुसार सोनिया शुरू में परमाणु समझौते के खिलाफ थीं', हिंदुस्तान टाइम्स, 20 अक्टूबर 2012।
456 उन्होंने वादा किया कि सरकार 'आम सहमति' के लिए काम करेगी: "टकराव नहीं है"
"गठबंधन धर्म", हिंदुस्तान टाइम्स, 12 अक्टूबर 2007।
456 और अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ, तो उन्होंने आगे कहा, 'यह जीवन का अंत नहीं होगा': पीटीआई, 'एन-
'समझौते की विफलता जीवन का अंत नहीं होगी: प्रधानमंत्री', टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 अक्टूबर 2007।
456 'यह कार्रवाई के लिए एक सुझाव है': वही।
457 'मैं उससे पूरी तरह सहमत था': मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने लेखक से कहा, 29 सितंबर 2021।
457 'हम सरकार के आईएईए जाने के विरोध में थे': प्रकाश करात ने लेखक से कहा।
458 'वहीं उन्होंने हमें धोखा दिया... नवंबर 2007 और जून 2008 के बीच क्या हुआ?'
यही असली कहानी है': वही।
458 प्रधानमंत्री फरवरी और मार्च 2008 में फिर से मुखर हो गए: वही।
458 बाइडन और उनके सहयोगियों ने मनमोहन सिंह को आगाह किया कि जब तक वे गति नहीं बढ़ाएंगे:
संजय बारू ने लेखक को लिखा।
458 'हमें (कठिन) समय सारिणी की जानकारी थी': मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने लेखक को 29 सितंबर को लिखा
2021.

458 ‘हमारा मानना है कि अमेरिकियों ने कड़ा विरोध किया’: प्रकाश करात ने लेखक से कहा।
459 ‘प्रधानमंत्री पूरी तरह से इसके झांसे में आ गए’: एक गुमनाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने लेखक से कहा।
459 ‘मैंने अमर सिंह से कहा, अगर तुम मनमोहन सिंह की मदद करोगे, तो तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा’: एम. के.
नारायणन से लेखक को, 8 अगस्त 2022, टेलीफोन पर बातचीत, चेन्नई।
459 ‘एम.के. नारायणन को साथ लाना…“न कि केवल अप्रत्यक्ष रूप से बल्कि केंद्रीय रूप से”… बहुत महत्वपूर्ण था।
रणनीतिक निर्णय’: मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने लेखक को 29 सितंबर 2021 को लिखा।
459 ‘मुझे पता था कि शतरंज की बिसात पर सभी मोहरे कहाँ हैं’: वही।
459 ‘2004 में, मैंने सोनिया गांधी को उनका नाम सुझाया था, और उनकी निकटता की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था।
गांधी परिवार को’: नटवर सिंह ने लेखक से कहा।
459 ‘doing an elaborate namaste to her’: Sanjaya Baru to author.
460 व्यथित सारन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की; वह जानना चाहता था कि उसे क्यों पद से हटाया गया था:
सरन, भारत दुनिया को कैसे देखता है।
460 ‘हमें पूरा यकीन था कि हम दुकान अमेरिकियों को बेचने वाले थे’: सरन, भारत इसे कैसे देखता है
दुनिया।
460 ‘नारायणन ने एक निश्चित चरण में स्वयं को प्रमुख वार्ताकार बना लिया’: मोंटेक सिंह
अहलुवालिया ने लेखक को 29 सितंबर 2021 को लिखा।
460 ‘अगर मैं चाहता कि वे बदलाव लाएं, तो वे मुझ पर भरोसा करेंगे’: एम. के. नारायणन ने लेखक से 8 अगस्त को कहा
2022, टेलीफोन पर हुई बातचीत, चेन्नई।

460 ‘मुझे वह सौदा चाहिए’: बारू, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पृ. 217.
460 ‘वह प्रतिदिन सर्वशक्तिमान ईश्वर से संवाद करता है’: एम. के. नारायणन ने लेखक को 8 अगस्त को लिखा
2022, टेलीफोन पर हुई बातचीत, चेन्नई।
460 ‘जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह के बिना यह समझौता दोहराया नहीं जा सकता था’: वही।
460 ‘मैं उसके प्रति प्रतिबद्ध हूँ। उसकी मदद करो’: वही।
460 ‘लेकिन… प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही सोच रखते थे, (और) इससे चीजें आसान हो गईं
किसी कठिन परिस्थिति से निपटना’: वही।
461 ‘ओह, प्रधानमंत्री और उनका परमाणु समझौता’: एक गुमनाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने लेखक से कहा।
462 भाजपा ने मनमोहन सिंह को 'कमजोर नेता' करार दिया था: पीटीआई, 'प्रधानमंत्री कमजोर नेता हैं, सहयोगी
भाजपा का कहना है कि ये अवसरवादी हैं’, रेडिफ डॉट कॉम, 22 मई 2008।
462 राहुल गांधी के ‘जल्द ही प्रधानमंत्री बनने की संभावना’: एक अज्ञात वरिष्ठ अधिकारी
कांग्रेस नेता लेखक बनेंगे।
462 ‘[लेकिन] समय ही बताएगा कि उनका नेतृत्व कितना प्रभावी है’: पीटीआई, ‘सोनिया ने यूपीए डिनर में पीएम की प्रशंसा की’
रेडिफ डॉट कॉम, 22 मई 2008।
462 ‘लेकिन डॉ मनमोहन सिंह ने उनके खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं कहा’: शीर्ष कांग्रेस नेता
लेखक ने गुमनाम रहना चुना।
462 ‘हम जल्द ही जाएंगे,’ उन्होंने उनसे कहा: एसपी सांसद जिन्होंने लेखक के लिए गुमनाम रहना चुना।
463 लेकिन उन्होंने ‘मनमोहन सिंह की धूर्तता को कम करके आंका था’: मानिनी चटर्जी ने लेखक से कहा।
463 ‘अमर सिंह हमें चल रही घटनाओं के बारे में सूचित करते रहते थे’: प्रकाश

करात ने लेखक से कहा।
463 प्रधानमंत्री ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की थी कि ‘परमाणु समझौता राष्ट्रीय हित में था’: वही।
463 ‘और उन्होंने संकेत दिया कि वे आगे बढ़ सकते हैं’: वही।
464 ‘मैं आपको बता दूं कि यह जॉर्ज बुश और अमर सिंह थे’: संजय बारू ने लेखक से कहा, 25
सितंबर 2020।
464 ‘आपको यह सोचना होगा कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं, न कि आप उनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं’: अमर
सिंह ने यह जानकारी हरिकेश बहादुर को दी, जिन्होंने इसे लेखक के साथ साझा किया।
465 ‘मैं सबसे पहले उसे चंद्र शेखर से मिलवाने ले गया था’: हरिकेश बहादुर ने लेखक से कहा।
465 अमर सिंह ने बाद में चंद्र शेखर को अमिताभ के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए राजी किया।
बच्चन: वीर संघवी, 'अमर सिंह का उदय और पतन', हिंदुस्तान टाइम्स, 5 अगस्त 2020। इसके कई वर्षों बाद तक, अमर सिंह यह कहानी सुनाते रहे कि कैसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बच्चन परिवार के खिलाफ एक मामले से संबंधित सरकारी फाइल को तब तक अपने साथ रखा जब तक कि चंद्र शेखर उस पर हस्ताक्षर करने और मामले को बंद करने के लिए सहमत नहीं हो गए।
465 ‘इसके बाद पार्टी में दलाली शुरू हो जाएगी’: बी. एम. भामा ने लेखक से कहा।
465 एक बार अमर सिंह अमिताभ बच्चन की मदद करने की कोशिश कर रहे थे: प्रसाद, पहिए पीछे
परदा।
465 वरिष्ठ सपा नेताओं—आजम खान, राज बब्बर, शाहिद सिद्दीकी—ने पार्टी छोड़ दी क्योंकि
हिम: ‘मुलायम का मुस्लिम समर्थन पुनः प्राप्त करने का प्रयास’, मिल्ली गजट, 4 दिसंबर 2012।
466 like ‘bade bhaiya’ taking care of ‘chote bhaiya’: Jaya

Bachchan to author.
466 अमर सिंह ने प्रकाश करात को फोन किया और उन्हें बताया कि वह बिल को आमंत्रित करने जा रहे हैं।
क्लिंटन डिनर पर: प्रकाश करात लेखक के साथ डिनर पर।
466 'यह काफी हास्यास्पद था': वही।
466 'यह खुले में बैठकर किया गया रात्रिभोज था': पीटर श्वित्ज़र, क्लिंटन कैश: अनकही कहानी
विदेशी सरकारों और व्यवसायों ने बिल और हिलेरी को अमीर बनाने में कैसे और क्यों मदद की, न्यूयॉर्क: हार्परकॉलिन्स, 2015।
466 'जहां उनकी मुलाकात भारतीय संसद के एक गुमनाम सदस्य अमर सिंह से हुई':
वही।
466 'अपनी जैकेट से कॉन्फेटी झाड़ते हुए': आरती आर. जेरथ, 'अमर सिंह बड़े सपने देखता है', डीएनए, 19
नवंबर 2013।
466 अमर सिंह ने 'वोट के बदले पैसे' मामले में मनमोहन सरकार को बचाया:
अमर सिंह को 2011 में सांसदों को सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए रिश्वत के तौर पर भारी रकम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
466 यह यूपीए सरकार थी जो दागदार थी: अमर सिंह ने लेखक को फरवरी 2020 में लिखा।
सिंगापुर में टेलीफोन पर हुई बातचीत।
467 'आप जानते हैं, उस फिल्म में मैं अपनी भूमिका उस व्यक्ति से बेहतर निभा सकता था जिसे आपने लिया था':
संजय बारू ने लेखक को लिखा।
467 उनकी बेटी सारिका का विवाह समारोह: सारिका नाम इंदिरा ने सुझाया था।
गांधी परिवार की कश्मीर की 'कुलदेवी' के नाम पर यह नाम रखा गया था। श्रीमती गांधी अपनी पोती का नाम सारिका रखना चाहती थीं, लेकिन राजीव और सोनिया ने प्रियंका नाम तय कर लिया था। (लेखक बी. एम. भामा (अब भाजपा में) हैं। वे कभी आर. के. धवन और बाद में कप्तान सतीश शर्मा के बहुत करीबी थे। अनिल बाली ने

भी लेखक को इसकी पुष्टि की है।)
468 ‘मैं उस समय संयोगवश कमरे में मौजूद थी’: बी. एम. भामा ने लेखक से कहा, 17 अक्टूबर 2020
टेलीफोन पर बातचीत।
468 प्रधानमंत्री को अवश्य ही पता होगा कि वहां फोटोग्राफर मौजूद थे: पीएमओ सूत्रों ने लेखक को बताया।
भारत में उनके खिलाफ सीबीआई के मामले दर्ज थे: 'सीबीआई ने चटवाल को क्लीन चिट कैसे दी', गवर्नेंस
अब, 30 जनवरी 2010।
468 उन्होंने दिल्ली में होटल व्यवसायी के बेटे विक्रम की शादी में शिरकत की: डेबोरा शोनेमैन।
‘विक्रम की भव्य सिख शादी’, न्यूयॉर्क, 2 मार्च 2006।
468 लेकिन प्रधानमंत्री ने इस सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया: अज्ञात सूत्रों के अनुसार
Manmohan Singh.
468 ‘ऐसे कुछ ही प्रसिद्ध सिख थे जिन्हें प्रधानमंत्री ने नियुक्ति नहीं दी’:
गुमनाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से लेखक, संजय बारू भी लेखक।
469 भारतीय सरकार संत चटवाल के खिलाफ कानूनी मामले वापस ले लेगी: 'कैसे' सीबीआई ने चटवाल को क्लीन चिट दे दी।
469 लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जाएगा:
वीर संघवी, ‘इस आदमी को पद्म पुरस्कार कैसे मिला?’, हिंदुस्तान टाइम्स, 31 जनवरी 2010।
469 प्रधानमंत्री के अनुरोध पर संत चटवाल को यह प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया।
मंत्री: टीएनएन, 'पीएमओ ने संत चटवाल के लिए पद्मा का बचाव किया', इकोनॉमिक टाइम्स, 28 जनवरी 2010।
469 ‘किसी भी दागी व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए’: कांग्रेस ने चटवाल के पुरस्कार का विरोध जताया

पद्म पुरस्कार, हिंदुस्तान टाइम्स, 27 जनवरी 2010।
469 ‘श्री चटवाल को पद्म पुरस्कार देना उचित नहीं होगा’: सिद्धार्थ
वरदराजन, ‘चटवाल को सम्मानित न करें, भारतीय राजदूत ने पीएमओ को बताया’, द हिंदू, 1 फरवरी 2010।
469 उन्होंने चटवाल के ‘व्यक्तिगत प्रयासों’ के लिए अपनी ‘सच्ची सराहना’ व्यक्त की: पीटीआई, ‘300 से अधिक
चटवाल के समर्थन में अमेरिकी अदालत में पत्र प्रस्तुत किए गए’, टाइम्स ऑफ इंडिया, 27 अक्टूबर 2014।
469 ‘भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए’: सारा जैकब, ‘मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने क्या किया है’
'चैटवाल ने एनडीटीवी को बताया', एनडीटीवी डॉट कॉम, 13 फरवरी 2010।
470 ‘मेरे लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया है’: बरू, ‘सिंह इज़ किंग’, द एक्सीडेंटल प्राइम
मंत्री।
470 ‘वामपंथी जो चाहते हैं वह संभव नहीं है’: वही।
470 ‘क्योंकि उनका रुख बहुत तर्कसंगत है’: मोंटेक सिंह अहलूवालिया, 29 सितंबर 2021।
470 ‘या तो मैं इसे पूरा कर लूँ, या मैं इसे पूरा नहीं करूँ’: वही।
470 ‘उसके बाद हम देखेंगे,’ उन्होंने उनसे कहा: प्रकाश करात ने लेखक से कहा।
470 ‘हम उसे (मनमोहन सिंह को) अपना मन बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते’: वही।
470 ‘(जो आप देख रहे हैं) वह एक मौन व्यक्ति का क्रोध है’: वही।
470 ‘इस्तीफा’ एक ऐसा हथियार था जिसे मनमोहन सिंह ने अतीत में कई बार इस्तेमाल किया था:
‘क्या प्रधानमंत्री से फिर से सिर्फ डॉ. सिंह बन जाएंगे?’, आउटलुक, 29 अक्टूबर 2007।
471 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने योजना आयोग के सदस्यों को 'जोकरों का झुंड' कहा था:
शिवानी सिंह, ‘वास्तव में ‘मजाकिया लोगों का समूह’, टाइम्स ऑफ इंडिया, 18

जुलाई 2004।
471 प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने तब इस्तीफा देने की धमकी दी थी जब वामपंथियों ने भारत-अमेरिका सैन्य अभ्यासों को रोकने की कोशिश की थी:
'क्या प्रधानमंत्री से फिर से सिर्फ डॉ. सिंह की भूमिका होगी?'
471 फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई कि वह अमर सिंह का 'दोस्त' है: संजय बारू
लेखक को। बारू उस 'मित्र' की पहचान के बारे में और कुछ कहने को तैयार नहीं थे।
471 कॉल करने वाला स्वयं अमर सिंह हो सकता था: बी.एम. भामा ने लेखक को लिखा।
471 प्रधानमंत्री अमर सिंह से बात करके उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर सकते हैं: संजय बारू
लेखक को।
471 'अमर सिंह के अमेरिका से वापस आने तक मैं कुछ नहीं कह सकता': प्रकाश करात ने लेखक से कहा।
471 जब अमर सिंह अमेरिका से लौटे, तो उन्होंने मीडिया को बताया कि स्थिति सभी के लिए आवश्यक है।
धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने के लिए: बारू, 'सिंह इज किंग', द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर।
471 'उन्हें परमाणु समझौते के बारे में जानकारी दी': वही।
472 पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से एक विज्ञप्ति जारी करवाने का विचार एम.के. नारायणन का था।
समझौते के पक्ष में बयान: गुमनाम कांग्रेस नेता ने लेखक को लिखा।
472 वह जल्दी से संजय बारू के कमरे में गया और उसे एक बयान सौंपा जिसे जारी किया जाना था।
मीडिया को तत्काल संबोधित करते हुए: बारू, संयोगवश प्रधानमंत्री बने।
472 'मैंने जॉयदीप सरकार (प्रधानमंत्री के सचिव) से कहा कि वामपंथी दल अब अपने बयान वापस ले लेंगे।
'समर्थन': मानिनी चटर्जी ने लेखिका को बताया।
473 दूसरे शब्दों में, वे मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन देंगे:

जसवंत सिंह
लेखक।
473 अहमद पटेल, बी.एस. हुडा, आर.के. धवन और सतीश शर्मा ने ऑपरेशन संभाला: बी.एम.
Bhama to author.
2011 में लीक हुए विकिलीक्स के 473 केबलों से पता चला कि भारी मात्रा में धन: 'अमेरिकी दूतावास'
केबल: परमाणु वोट से पहले भारतीय सांसदों को कांग्रेस पार्टी ने रिश्वत दी', द गार्जियन, 18
मार्च 2011; 'विश्वास मत विवाद पर विकीलीक्स केबल का पूरा पाठ', NDTV.com, 17 मार्च 2011।
473 उस समय कहा गया था कि यह स्टिंग ऑपरेशन अरुण जेटली की सोच का नतीजा था: शांतनु गुहा राय,
'वोट के बदले नकद घोटाला: स्टिंग सिंह के घातक रहस्य', इंडिया टुडे, 15 अगस्त 2011।
मुलायम सिंह यादव ने सपा के समर्थन के लिए दो शर्तें रखी थीं: संजय बारू को समर्थन देना होगा।
लेखक, 25 सितंबर 2020।
अनाम पीएमओ सूत्रों ने लेखक को बताया कि 473 पर 'आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी'।
473 'मैं वहीं खड़ा था और मैंने उन्हें अपनी बड़ी सफेद मर्सिडीज में बैठते हुए देखा': संजय बारू
लेखक को, 25 सितंबर 2020।
भारत के पक्ष में काम करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक मोहम्मद अल-बरादेई थे:
लेखक को पीएमओ के अज्ञात सूत्रों से जानकारी मिली।
474 छोटे यूरोपीय देशों ने खुद को 'अप्रसार के अयातुल्लाह' के रूप में देखा:
मोंटेक सिंह अहलूवालिया लेखक हैं।
475 प्रतिनिधिमंडल दिन के दौरान भारतीय दूतावास में मुलाकात करेगा: शिवशंकर

मेनन
लेखक, 10 अक्टूबर 2021।
475 इससे पहले चीन ने भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश के बराबर दर्जा दिए जाने पर आपत्ति जताई थी।
एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने वाले राज्य: विजय गोखले, '123 डील: द बिग टर्नअबाउट', द लॉन्ग गेम: हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, नई दिल्ली: पेंगुइन रैंडम हाउस, 2011।
475 'इसे राजकीय यात्रा के बराबर माना गया': लेखक को कांग्रेस के अनाम सूत्रों से जानकारी मिली।
भारत-अमेरिका समझौते के बारे में 475 'बुनियादी चिंताएँ': गोखले, द लॉन्ग गेम, पृ. 100.
5 सितंबर 2008 की रात जैसे-जैसे बीतती गई, ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत ने बिरयानी खाई।
दूतावास में पकाया और पैक किया गया: वियना स्थित भारतीय दूतावास के अज्ञात सूत्रों ने लेखक को यह जानकारी दी।
476 'आपको हू जिंताओ से सीधे बात करनी चाहिए,' बुश ने उन्हें सलाह दी: विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार।
लेखक।
476 चीनी पक्ष इस विचार के प्रति 'उदासीन' था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बार फिर कोशिश की: वही।
476 'जुलाई 2008 में, चीनियों ने मुझसे कहा था—मैं वहाँ गया था—कि हम आखिरी नहीं होंगे
'यदि अन्य लोग पीछे हट जाते हैं तो (छूट के खिलाफ) खड़े रहना': शिवशंकर मेनन ने लेखक को 10 अक्टूबर 2021 को लिखा।
476 बुश ने तब हू जिंताओ को व्यक्तिगत रूप से फोन किया: मोंटेक सिंह अहलूवालिया लेखक को।
476 'इससे भारत-चीन संबंधों पर समग्र रूप से असर पड़ेगा': गोखले, '123 डील: द बिग टर्नअबाउट',
लंबी अवधि की रणनीति।

477 ‘बधाई हो,’ उन्होंने कहा। ‘हमने कर दिखाया’: शिवशंकर मेनन ने लेखक से कहा, 10 अक्टूबर
2021.
477 ‘कुछ भी शामिल या बहिष्कृत नहीं किया’: वही।
477 ‘हमने प्रत्येक देश के साथ अलग-अलग बातचीत की’: अनिल काकोडकर ने लेखक से कहा।
477 अपने दिशा-निर्देशों को 'मजबूत' करे और ईएनआर प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को इस पर निर्भर बनाए
राष्ट्रीय संधि समझौते पर हस्ताक्षर: सिद्धार्थ वरदराजन, 'एनएसजी ने भारत की "स्पष्ट" छूट समाप्त की', द हिंदू, 24 जून 2011।
477 वह और राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उम्मीद थी कि डॉ. सिंह के कार्यकाल के दौरान परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।
यूएस: श्याम सरन लेखक, 22 अक्टूबर 2020।
478 ‘इसमें हम दोनों की ओर से काफी मेहनत लगी है’: प्रेस सचिव कार्यालय, राष्ट्रपति
बुश ने भारत के प्रधानमंत्री सिंह से मुलाकात की’, व्हाइट हाउस, 25 सितंबर 2008।
26 जून 2022 को एक्सेस किया गया, <georgewbush-> पर उपलब्ध है
whitehouse.archives.gov/news/
releases/2008/09/20080925-11.html>.
478 बैठक के बाद ओल्ड फैमिली डाइनिंग रूम में रात्रिभोज हुआ: पीटीआई, 'बुश ने मेजबानी की'
मनमोहन सिंह के लिए रात्रिभोज’, इंडिया टुडे, 26 सितंबर 2008।
478 ‘आप मुझ पर शांत प्रभाव डालते हैं’: मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने लेखक से कहा, 29 सितंबर
2021; लेखक के रूप में श्याम सरन, 22 अक्टूबर 2020।
478 ‘श्रीमान प्रधानमंत्री जी, इस समझौते को पूरा करवाने के लिए हमने आपके लिए काफी मेहनत की है’:
श्याम सरन द्वारा लेखक को, 22 अक्टूबर 2020; सरन, हाउ इंडिया सीज़ द वर्ल्ड, पृ. 239.

478 'यह रिएक्टरों की बिक्री से कहीं बढ़कर है। यह हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों से संबंधित है':
वही।
478 उन्होंने कहा, "यह आदमी मेरा दोस्त है। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना": वही।
अधिनियम पर हस्ताक्षर करते हुए बुश ने कहा, 'यह एक बड़ी बात है': प्रेस सचिव का कार्यालय।
'राष्ट्रपति बुश ने एच.आर. 7081, संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत परमाणु सहयोग अनुमोदन और अप्रसार संवर्धन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए', व्हाइट हाउस, 8 अक्टूबर 2008, एक्सेस 24
जून 2022, <georgewbush-> पर उपलब्ध है
whitehouse.archives.gov/news/
releases/2008/10/20081008-4.html>.
479 मनमोहन सिंह ने इस समझौते को अपने कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना: मोंटेक
सिंह अहलूवालिया ने लेखक को 29 सितंबर 2021 को लिखा।
479 वर्ष 2009 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी बढ़ी हुई बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई:
'राष्ट्रीय दलों का प्रदर्शन', दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 2009, उपलब्ध है
<eci.gov.in/files/file/2881-performance-of-national-
parties>.
प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप शुरू हुआ 479 'तकनीकी रंगभेद': मोंटेक सिंह
अहलुवालिया ने लेखक को 29 सितंबर 2021 को लिखा।
479 2008 से, भारत ने रूस से चार परमाणु रिएक्टर भी हासिल किए हैं: अनिल काकोडकर
लेखक, 14 अक्टूबर 2021।
480 अन्य देशों ने भारत को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया: : शिवशंकर मेनन से लेखक को, 10
अक्टूबर 2021।

उपसंहार

482 ‘वह यह बात कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वह नेहरू जैसा बनना चाहता है और उनसे आगे निकलना चाहता है’: करण
सिंह द्वारा लेखक को, 16 मार्च 2023, नई दिल्ली।
482 ‘सभ्यतावादी राज्य’ की वास्तुकला: ‘प्रधानमंत्री मोदी: भारत के उदय में अग्रणी’ 'सभ्यतावादी राज्य', इंडिया नैरेटिव, 12 दिसंबर 2021।
483 अक्सर, उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के बारे में सूचित किया जाता था: मधुपरना
दास, ‘मोदी पीएमओ हर चीज को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति रखता है, मंत्री प्रेस मीट के लिए भी मंजूरी मांगते हैं, अनिल स्वरूप कहते हैं’, द प्रिंट, 30 मई 2022।
483 विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य उसे हराना था, यहाँ तक कि उसे एक 'कब्र' में 'दफ़नाना' भी था:
हिंदुस्तान टाइम्स, ‘“मोदी की कब्र…”: बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे को लेकर जारी श्रेय की होड़ में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा | देखें’, यूट्यूब, 12 मार्च 2023, उपलब्ध है
<www.youtube.com/watch?v=e2JsLTTexqI>.
483 ‘Ek akela kitno par bhari pada’: AajTak HD, PM Modi Speech in parliament: “‘Desh Dekh
Raha Ek Akela Kitno Par Bhari Hai”, Jab Seena Thokkar Bole PM Modi’, YouTube, 9
फरवरी 2023, <www.youtube.com/watch?v=NqMSagf3Qmo> पर उपलब्ध है।
484 अपनी ‘नई भाजपा’ को नया रूप दे रहे हैं: वाल्टर एंडरसन लिखते हैं: नरेंद्र मोदी कैसे
भाजपा को नया रूप दिया, इंडियन एक्सप्रेस, 23 जुलाई 2022।
जनसंपर्क कंपनियों और लॉबिस्टों के माध्यम से 484 लोगों ने उनके नेतृत्व को बढ़ावा देने और उनके संदेश को व्यापक बनाने के लिए काम किया:

बिनॉय प्रभाकर, ‘कैसे एक अमेरिकी लॉबिंग कंपनी एपको वर्ल्डवाइड नरेंद्र मोदी को दुनिया के सामने पेश करती है’, इकोनॉमिक टाइम्स, 9 जुलाई 2012; मितुल ठक्कर और बिनॉय
प्रभाकर, ‘नरेंद्र मोदी 2014 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली स्थित एक जनसंपर्क एजेंसी को नियुक्त करेंगे’, इकोनॉमिक टाइम्स, 4 जुलाई 2013।
485 ‘आप जो भी करें,’ उन्होंने अधिकारी से कहा, ‘वह भव्य होना चाहिए’: लेखक को अज्ञात सूत्र।
485 ‘नरेंद्र की विशेषज्ञता राजनीतिक विपणन में है’: प्रशांत झा की पुस्तक ‘हाउ’ में के. एन. गोविंदाचार्य का उद्धरण।
भाजपा की जीत: भारत की सबसे बड़ी चुनावी मशीन के अंदर, दिल्ली: जगरनॉट, 2017।
485 ‘और इसलिए राजनीति छवियों, संदेशों और संकेतों के इर्द-गिर्द घूमती है’: वही।
489 ‘और दोनों मिलकर काम करेंगे’: गांधी ने सरदार पटेल के बजाय नेहरू को चुना था—कई कारणों से
कारण। हालांकि पटेल एक कुशल वार्ताकार और बेहतर आयोजक थे, गांधीजी का मानना था कि नेहरू ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की ओर संक्रमण की समस्याओं को बेहतर ढंग से संभाल सकेंगे। उन्होंने हैरो, कैम्ब्रिज और लंदन में शिक्षा प्राप्त की थी, अंग्रेजी भाषा का सहज उपयोग करते थे, अंग्रेजों के साथ उनका अच्छा तालमेल था और वे पटेल की तुलना में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बेहतर समझते थे। नेहरू जनता के बीच अधिक लोकप्रिय थे और मुसलमानों के साथ उनके बेहतर संबंध थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधीजी जानते थे कि 'जवाहर कभी दूसरे स्थान पर नहीं रहेंगे।' (दुर्गा दास, इंडिया फ्रॉम कर्ज़न टू नेहरू एंड आफ्टर, लंदन: कॉलिन्स, 1969, पृष्ठ 230, राजमोहन गांधी द्वारा उद्धृत, पटेल: ए लाइफ, अहमदाबाद: नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1991)। पटेल के जीवनीकार राजमोहन गांधी ने उल्लेख किया कि 15 में से 12 राज्य कांग्रेस समितियों ने पटेल को पार्टी अध्यक्ष के रूप में पसंद किया था। किसी भी पीसीसी ने अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था। हालांकि, पटेल के सबसे कट्टर समर्थक और महाकोशल पीसीसी के सदस्य डी. पी. मिश्रा ने खुलासा किया कि 'हमारा नेहरू को भविष्य में प्रधानमंत्री पद से वंचित करने का कोई इरादा नहीं था'। (डी. पी. मिश्रा, लिविंग एन एरा, खंड 2, नई दिल्ली: विकास,

1978, गांधी, पटेल: ए लाइफ में उद्धृत।)
489 गांधी ने पटेल से शांत भाव से कहा कि मंत्रिमंडल में उनकी और नेहरू की उपस्थिति
'अपरिहार्य': गांधी, पटेल: एक जीवन, पृ. 467.
489 कुछ ही मिनटों में पटेल और उनकी बेटी मणिबेन बिरला हाउस वापस आ गए: वही।
489 'तब उसने अपना शोकग्रस्त सिर सरदार की गोद में रख दिया': वही, पृ. 468.
489 उस रात, 30 जनवरी 1948 को, उन्होंने एक साथ राष्ट्र को संबोधित किया: वही।
489 क्योंकि ऐसा करने से वह देश को नेहरू और पटेल के संयुक्त नेतृत्व से वंचित कर देगा।
गांधी की इच्छा: वही, पृष्ठ 469।
489 'मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपको वह मुझसे मिलेगा': वही, पृष्ठ 470.
490 'मैं अपनी जिम्मेदारियों को इसी भावना से निभाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हूँ': वही।
490 ने उपमहाद्वीप में 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित किया: शिवानी सिंह, 'पूंजीगत लाभ: 1947 कैसे'
'एक नई पहचान, एक नई महत्वाकांक्षा, एक नए दिल्ली को जन्म दिया', हिंदुस्तान टाइम्स, 24 अप्रैल 2018।
490 'मैं कभी किसी मित्र को नहीं भूलता और कभी किसी शत्रु को क्षमा नहीं करता': इंदर मल्होत्रा, 'एक मूलभूत सिद्धांत'
असहमति', इंडियन एक्सप्रेस, 3 अप्रैल 2009।
490 नेहरू का मानना था कि यह एक फासीवादी संगठन था: आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी, और
सुचेता महाजन, आरएसएस, स्कूल पाठ्यपुस्तकें और महात्मा गांधी की हत्या: हिंदू सांप्रदायिक परियोजना, दिल्ली: सेज, 2008, पृ. 69-70.
490 Patel saw it as patriotic but misguided: Neerja Singh, 'Sardar Vallabhai Patel aur Rashtriya

Swayam Sevak Sangh (RSS): Ek Vivechan', Samajik Vimarsh, Vol. 3, No. 2, 2020, p. 149.
गांधी जी की हत्या के बाद 490 ने इसे डेढ़ साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया: 'आरएसएस और सरदार पटेल: ए'
भाजपा की चयनात्मक अंधता का विचित्र मामला', द टेलीग्राफ, 31 अक्टूबर 2018।

ग्रंथ सूची

आलम, जावेद (संपादक), कश्मीर और उससे आगे 1966-84: इंदिरा गांधी और उनके बीच चयनित पत्राचार
गांधी और करण सिंह, नई दिल्ली: पेंगुइन इंडिया, 2011।
आनंद, ईश्वर वी., और जयथी, के. (संपादक), पत्रकारिता की एक पुस्तिका: सूचना में मीडिया
एज, नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स, 2018।
Andersen, Walter and Shridhar D. Damle, The Brotherhood in Saffron: The Rashtriya
स्वयंसेवक संघ और हिंदू पुनरुत्थानवाद, नई दिल्ली: पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, 2019।
बारू, संजय, 1991: हाउ पी. वी. नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री, नई दिल्ली: एलेफ़ बुक कंपनी, 2016.
———आकस्मिक प्रधानमंत्री: मनमोहन सिंह का बनना और बिगड़ना, न्यू
दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, 2014।
बोस, सुमात्रा, भारत का रूपांतरण: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ, कैम्ब्रिज,
मैसाचुसेट्स और लंदन, इंग्लैंड: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2013।
कैरास, मैरी सी., इंदिरा गांधी: नेतृत्व की कसौटी पर, मुंबई: जैको पब्लिशिंग हाउस, 1980।
Chandra, Bipan, Mukherjee, Mridula, and Mukherjee, Aditya, India Since Independence:

संशोधित एवं अद्यतन, दिल्ली: इंडिया पेंगुइन, 2008।
चंद्र, बिपन, लोकतंत्र के नाम पर: जेपी आंदोलन और आपातकाल, नई दिल्ली: भारत पेंगुइन, 2017.
चेंगप्पा, राज, शांति के हथियार: भारत की परमाणु शक्ति बनने की खोज की गुप्त कहानी,
नई दिल्ली: हार्पर कॉलिन्स इंडिया, 2000।
दास, दुर्गा, इंडिया फ्रॉम कर्ज़न टू नेहरू एंड आफ्टर, न्यूयॉर्क: जॉन डे पब्लिकेशन्स, 1970। दयाल, जॉन और बोस, अजय, फॉर रीजन्स ऑफ स्टेट: दिल्ली अंडर इमरजेंसी, नई दिल्ली: पेंगुइन।
रैंडम हाउस, 2018।
धर, पी. एन., इंदिरा गांधी, आपातकाल और भारतीय लोकतंत्र, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड
यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000।
दत्त, रवि बाजपेयी और हरिवंश, चंद्र शेखर—वैचारिक राजनीति के अंतिम प्रतीक, न्यू दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स, 2019।
फाल्क, बर्टिल, फ़िरोज़ गांधी: द फ़ॉरगॉटन गांधी, नई दिल्ली: रोली बुक्स, 2016। फ्रैंक, कैथरीन, इंदिरा: द लाइफ ऑफ़ इंदिरा नेहरू गांधी, न्यूयॉर्क: हार्पर पेरिनियल, 2005। फ्रीडमैन, थॉमस एल., द लेक्सस एंड द ऑलिव ट्री, न्यूयॉर्क: फर्रार, स्ट्रॉस, एंड गिरौक्स।
1999.
गांधी, राजमोहन, पटेल: एक जीवन, अहमदाबाद: नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1991। जेनोवेस, माइकल ए., और स्टेकेनराइडर, जेनी एस. (संपादक), राजनीतिक नेताओं के रूप में महिलाएं: अध्ययन
लिंग और शासन, नई दिल्ली: रूटलेज, 2013।
घोष, सागरिका, इंदिरा: भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री। नई दिल्ली: जगर्नॉट, 2018। गुहा, रामचंद्र (संपादक), मेकर्स ऑफ मॉडर्न एशिया, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स और लंदन।
इंग्लैंड: द बेल्कनैप प्रेस ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2014।
गुहा, रामचंद्र, गांधी के बाद भारत: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का इतिहास, न्यू

यॉर्क: हार्पर पेरिनियल, 2008।
गुप्ता, विराग (संपादक), अयोध्या के राम मंदिर पर न्यायालयों में: निर्णय और समीक्षा, तीसरा संस्करण, न्यू यॉर्क
दिल्ली: सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज, 2019।
हबीबुल्लाह, वजाहत, राजीव के साथ मेरे वर्ष: विजय और त्रासदी, दिल्ली: वेस्टलैंड, 2020। हैंगन, वेल्स, नेहरू के बाद कौन?, लंदन: रूपर्ट हार्ट-डेविस, 1973। हेंडरसन, माइकल, असत्य के साथ प्रयोग: आपातकाल के तहत भारत, दिल्ली, बॉम्बे।
कलकत्ता, मद्रास: द मैकमिलन कंपनी ऑफ इंडिया, 1977।
जैफ्रेलॉट, क्रिस्टोफर, भारत में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन, न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998।
जयकर, पुपुल, इंदिरा गांधी: एक जीवनी, नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, 1995। झा, कृष्णा और झा, धीरेंद्र के., अयोध्या: द डार्क नाइट: द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ रामाज बाबरी मस्जिद में उपस्थिति, नई दिल्ली: हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया, 2016।
जॉनसन, रिचर्ड एल., और गांधी, मोहनदास करमचंद, गांधी के सत्य के साथ प्रयोग: महात्मा गांधी द्वारा और उनके बारे में आवश्यक लेखन, लैनहैम, एमडी: लेक्सिंगटन बुक्स, 2006।
कलाम, ए. पी. जे. अब्दुल, टर्निंग पॉइंट्स, नई दिल्ली: हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया, 2014। कल्हन, प्रोमिला, कमला नेहरू: एक अंतरंग जीवनी, नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस।
1973.
कर, देव, भारत: अभी भी जंजीरों में जकड़ा हुआ विशालकाय, नई दिल्ली: पेंगुइन पोर्टफोलियो, 2019। कासिपथी, कपिला, नियति के साथ मिलन, हैदराबाद: के.वी. राव, 1970। कौल, टी.एन., राज से स्वराज तक के मेरे वर्ष, नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस, 1995। खुर्शीद, सलमान, अयोध्या पर सूर्योदय: हमारे समय में राष्ट्रवाद, नई दिल्ली: विंटेज बुक्स।
2021.
किदवई, रशीद, 24 अकबर रोड: पतन और उत्थान के पीछे के लोगों का संक्षिप्त इतिहास
कांग्रेस, नई दिल्ली: हैचेट, 2011।
सोनिया: एक जीवनी, नया भारत: वाइकिंग (पेंगुइन बुक्स इंडिया), 2009। मल्होत्रा,

इंदर, इंदिरा गांधी: एक व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवनी, नई दिल्ली: हे हाउस।
2014.
मलकानि, के. आर., अयोध्या की राजनीति और हिंदू-मुस्लिम संबंध, फैजाबाद: हर आनंद
प्रकाशन, 1993।
मेहता, विनोद, द संजय स्टोरी: फ्रॉम आनंद भवन टू अमेठी, नई दिल्ली: हार्पर कॉलिन्स,
2012.
मुखर्जी, प्रणब, नाटकीय दशक: इंदिरा गांधी के वर्ष, नई दिल्ली: रूपा
प्रकाशन, 2015।
———गठबंधन के वर्ष: 1996–2012, नई दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स, 2017।
———अशांतिपूर्ण वर्ष: 1980–1996, नई दिल्ली: रूपा पब्लिकेशन्स, 2016।
मुखर्जी, देबाशीष, द डिसरप्टर: हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शूक इंडिया, नई दिल्ली:
हार्पर कॉलिन्स इंडिया, 2021।
मुखोपाध्याय, निलंजन, द आरएसएस: आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट, नई दिल्ली: ट्रांकेबार प्रेस,
2019.
नाग, किंगशुक, अटल बिहारी वाजपेयी: ए मैन फॉर ऑल सीजन्स, नई दिल्ली: रूपा प्रकाशन,
2017.
नायर, कुलदीप, द जजमेंट: इनसाइड द स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया, नई दिल्ली: विकास
प्रकाशन, 1977।
नेहरू, जवाहरलाल, आत्मकथा, लंदन: बॉडली हेड, 1936। नूरानी, ए.जी., भारत के मुसलमान: एक दस्तावेजी रिकॉर्ड, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय।
प्रेस, 2003.
पाण्डे, बी.डी., स्वतंत्र भारत की सेवा में: एक सिविल सेवक का संस्मरण, नई दिल्ली: स्पीकिंग टाइगर,
2021.
प्रसाद, पी. वी. आर. के., व्हील्स बिहाइंड द वेल: पीएम, सीएम और उससे आगे,

विजयवाड़ा: एमेस्को बुक्स,
2010.
रमेश, जयराम, इंटरट्वाइंड लाइव्स: पी.एन. हक्सर और इंदिरा गांधी, नई दिल्ली: साइमन और
शूस्टर, 2018.
राव, पी. वी. नरसिम्हा, अयोध्या: 6 दिसंबर 1992, नई दिल्ली: इंडिया पेंगुइन, 2019. राइस, कोंडोलीज़ा, नो हायर ऑनर: ए मेमोइर ऑफ माई इयर्स इन वाशिंगटन, न्यूयॉर्क:
पेंगुइन रैंडम हाउस, 2011।
सहगल, नयनतारा, इंदिरा गांधी—सत्ता के साथ मिलन, नई दिल्ली: इंडिया पेंगुइन, 2012। संघवी, वीर, एक असभ्य जीवन: संस्मरण, नई दिल्ली: इंडिया वाइकिंग, 2021। सरन, श्याम, भारत दुनिया को कैसे देखता है: कौटिल्य से 21वीं सदी तक, नई दिल्ली: जगर्नोट।
2017.
Sharma, Chandrika Prasad, Poet Politician Atal Bihari Vajpayee: A Biography, New Delhi: Kitab
Ghar Prakashan, 1998.
सिंह, कुमार सुरेश, भारत के लोग खंड 6: भारत के समुदाय (न्यू न्यूजीलैंड), नई दिल्ली:
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998।
सिंह, वलय, अयोध्या: आस्था का शहर, कलह का शहर, नई दिल्ली: अलेफ बुक कंपनी, 2018। सिन्हा, शक्ति, वाजपेयी: वे वर्ष जिन्होंने भारत को बदल दिया, नई दिल्ली: विंटेज बुक्स, 2020। सीतापति, विनय, आधा शेर: कैसे पी.वी. नरसिम्हा राव ने भारत को रूपांतरित किया, नई दिल्ली: इंडिया
वाइकिंग, 2016.
———जुगलबंदी: मोदी से पहले भाजपा, नई दिल्ली: पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, 2020। श्रीवास्तव, सी. पी., लाल बहादुर शास्त्री: राजनीति में सत्य का जीवन, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय
प्रेस, 1995।
श्रीवास्तव, सुशील, विवादित मस्जिद: एक ऐतिहासिक जांच, नई दिल्ली: विस्तार

प्रकाशन,
1992.
टैलबॉट, स्ट्रोब, भारत से जुड़ाव: कूटनीति, लोकतंत्र और बम, वाशिंगटन डी.सी. ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन प्रेस, 2004।
ठाकुर, जनार्दन, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन, नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस, 1977। ———प्रधानमंत्री: नेहरू से वाजपेयी तक, मुंबई: ईश्वर, 1999। थारूर, शशि, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर: नरेंद्र मोदी और उनका भारत, नई दिल्ली: एलेफ बुक कंपनी, 2018।
उललेख, एन. पी., अनकही वाजपेयी कथा: राजनीतिज्ञ और विरोधाभास। नई दिल्ली: पेंगुइन रैंडम
हाउस इंडिया, 2018।
वैष्णव, मिलन, व्हेन क्राइम पेज: मनी एंड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स, नई दिल्ली: हार्पर
कॉलिन्स पब्लिशर्स, 2017।
से

ज्ञान और संस्कृति का आपका प्रवेश द्वार। सभी के लिए सुलभ।